CUET UG

NTA द्वारा जारी पाठ्यक्रम के अनुसार

EXAM 2026

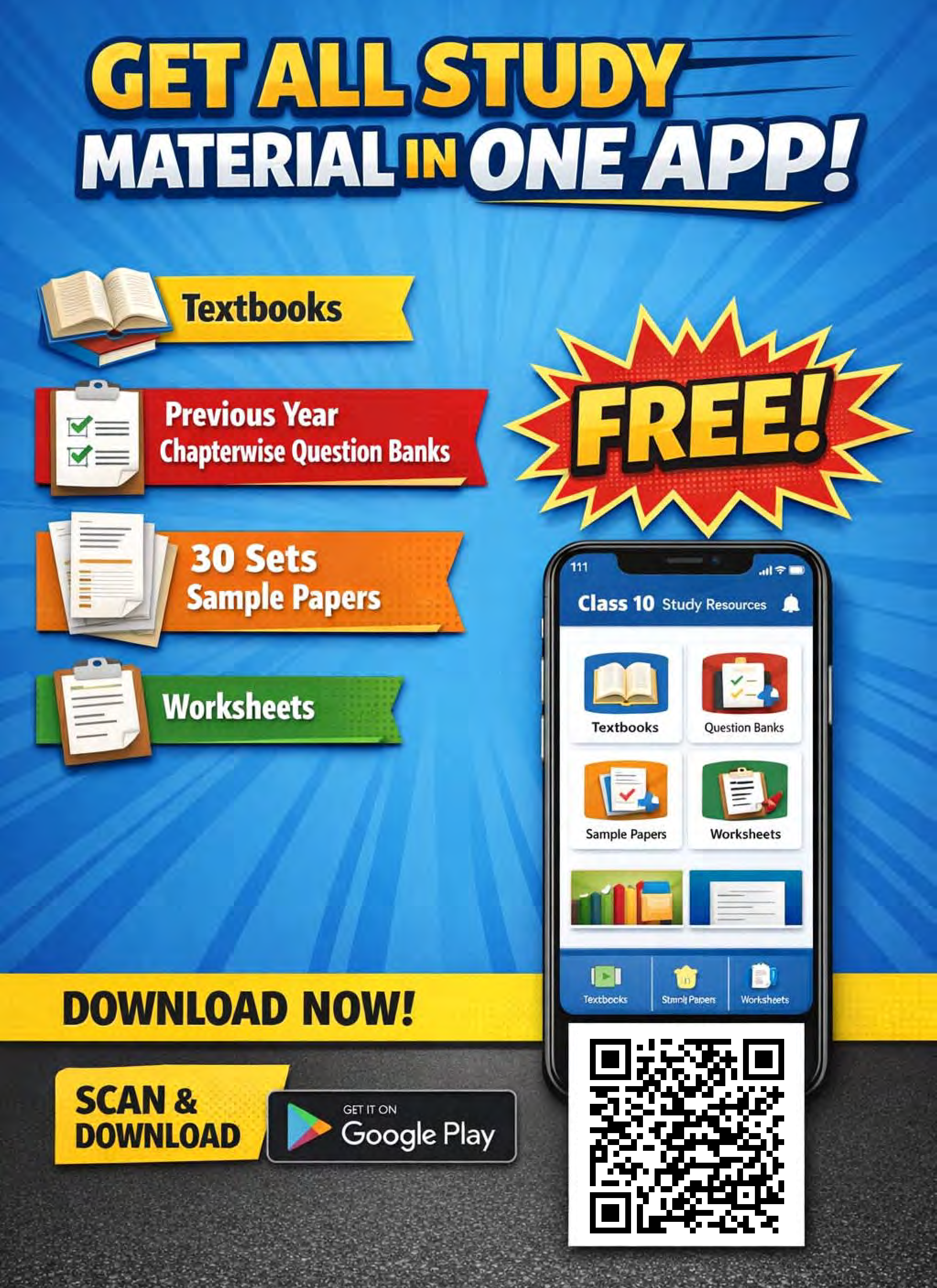
राजनीति विज्ञान

POLITICAL SCIENCE

अध्यायवार MCQs

Nodia

Scan QR Code
for Demo PDF


GET ALL STUDY MATERIAL IN ONE APP!
Textbooks
Previous Year Chapterwise Question Banks
30 Sets Sample Papers
Worksheets
FREE!
Class 10 Study Resources
Textbooks
Question Banks
Sample Papers
Worksheets
DOWNLOAD NOW!
SCAN & DOWNLOAD
GET IT ON Google Play

CUET UG 2026

राजनीति विज्ञान
POLITICAL SCIENCE

अध्यायवार MCQ
NTA द्वारा जारी पाठ्यक्रम के अनुसार

NODIA

CUET UG POLITICAL SCIENCE
Edition March 2026
Published by :NODIA
An Imprint of Nodia EDITIONS LLP

MRP ₹560.00

NODIA EDITIONS LLP
125, Sector 6, Vidyadhar Nagar, Jaipur 302039
Phone :+91 9024037387
email : mail@nodia.in

CONTENTS

समकालीन विश्व राजनीति

अध्याय 1 दो ध्रुवीयता का अंत 7-42

अध्याय 2 सत्ता के समकालीन केंद्र 43-77

अध्याय 3 समकालीन दक्षिण एशिया 78-114

अध्याय 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन 115-150

अध्याय 5 समकालीन विश्व में सुरक्षा 151-186

अध्याय 6 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन 187-223

अध्याय 7 वैश्वीकरण 224-262

भारत में स्वतंत्रता के बाद की राजनीति

अध्याय 8 राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ 263-298

अध्याय 9 एक दल के प्रभुत्व का दौर 299-334

अध्याय 10 नियोजित विकास की राजनीति 335-373

अध्याय 11 भारत के विदेश संबंध 374-410

अध्याय 12 कांग्रेस प्रणाली : चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना 411-445

अध्याय 13 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट 446-482

अध्याय 14 क्षेत्रीय आकांक्षाएँ 483-517

अध्याय 15 भारतीय राजनीति : नए बदलाव 518-552

For the Year 2026

Political Science – 323 Syllabus for CUET(UG)

Political in India Since Independence.

Course Content

1. **Era of One-Party Dominance**: First three general elections, nature of Congress dominance at the National level, uneven dominance at the state level, coalitional nature of Congress. Major opposition parties.

2. **Nation** - Building and Its Problems: Nehru's approach to nation-building: Legacy of partition: challenge of 'refugee' resettlement, the Kashmir problem. Organisation and reorgansation of states; Political conflicts over language.

3. **Politics of Planned Development**: Five year plans, expansion of state sector and the rise of new economic interest.

4. **India's External Relation**: Nehru's foreign policy. Sino-Indian war of 1962, Indo-Pak war of 1965 and 1971. India's nuclear programme and shifting alliance in world politics.

5. **Challenge to and Restoration of Congress System**: Political succession after Nehru. NonCongressism and electoral upset of 1967, Congress split and reconstitution, Congress' victory in 1971 elections, politics of 'garibi hatao'.

6. **Crises of the Constitutional Order**: Search for 'committed' bureaucracy and judiciary. Navnirman movement in Gujarat and the Bihar movement. Emergency: context, constitutional and extra-constitutional dimensions, resistance to emergency. 1977 elections and the formation of Janata Party. Rise of civil liberties organisations.

7. **Regional Aspiration and Conflicts:** Rise of regional parties. Punjab crisis and the anti-Sikh riots of 1984. The Kashmir situation. Challenges and responses in the North East.

8. **Democratic Upsurge and Coalition Politics:** Participatory upsurge in 1990s. Rise of the JD and the BJP. Increasing role of regional parties and coalition politics. UF and NDA governments. Elections 2004-2019 and UPA government with addition of NDA government.

9. **Recent Issues and Challenges:** Challenge of and responses to globalization: new economic policy and its opposition. Rise of OBCs in North Indian politics. Dalit politics in electoral and non-electoral arena. Challenge of communalism: Ayodhya issue.

Contemporary World Politics.

Course Content

1. **Disintegration of the 'Second World' and the Collapse of Bipolarity:** New entities in world politics: Russia, Balkan states and, Central Asian states, Introduction of democratic politics and capitalism in post-communist regimes. India's relations with Russia and other post-communist countries.

2. **Alternative Centers of Economic and Political Power**: Rise of China as an economic power in post-Mao era, creation and expansion of European Union, ASEAN. India's changing relations with China, Japan and South Korea.

3. **South Asia in the Post Cold War Era:** Democratisation and its reversals in Pakistan and Nepal. Ethnic conflict in Sri Lanka. Impact of economic globalization on the region. Conflicts and efforts for peace in South Asia. India's relation with its neighbours.

4. **International Organisations in a Unipolar World:** Restructuring and the future of the UN. India's position in the restructured UN. Rise of new international actors: new international economic organisations, NGOs. How democratic and accountable are the new institution of global governance?

5. **Security in Contemporary World:** Traditional concerns of security and politics of disarmament. Non-traditional of human security: global poverty, health and education. Issues of human rights and migration.

6. **Environment and Natural Resources in Global Politics**: Environment movement and evolution of global environmental norms. Conflicts over traditional and common property resources. Right of indigenous people. India's stand in global environmental debates.

7. **Globalisation and its critics:** Economic, cultural and political manifestations. Debates on the nature of consequences of globalization. Anti-globalisation movements. India as an arena of globalization and struggles against it.

अध्याय 01
दो ध्रुवीयता का अंत

1. बर्लिन की दीवार को किसका प्रतीक माना जाता था?
(A) प्रथम विश्वयुद्ध का
(B) शीतयुद्ध का
(C) जर्मनी के एकीकरण का
(D) गुटनिरपेक्ष आंदोलन का

2. समाजवादी सोवियत गणराज्य (यू.एस.एस.आर.) किस क्रांति के बाद अस्तित्व में आया?
(A) 1917 की समाजवादी क्रांति
(B) 1789 की फ्रांसीसी क्रांति
(C) 1949 की चीनी क्रांति
(D) 1857 का भारतीय विद्रोह

3. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी।
कथन II: सोवियत प्रणाली में, कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा अन्य राजनीतिक दलों और विपक्ष के लिए पर्याप्त जगह थी।
उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

4. 'दूसरी दुनिया' का प्रयोग किन देशों के लिए किया जाता था?
(A) पश्चिमी यूरोप के पूँजीवादी देश
(B) एशिया और अफ्रीका के नव-स्वतंत्र देश
(C) अमरीकी गुट के देश
(D) पूर्वी यूरोप के समाजवादी खेमे के देश

5. सोवियत प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह पूँजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी।
2. इसमें निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने की कोशिश की गई।
3. अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी।
4. इसमें नागरिकों को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1, 2 और 3
(C) केवल 3 और 4
(D) सभी 1, 2, 3 और 4

6. सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की विशेषता के बारे में कौन सा कथन गलत है?
(A) सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी।
(B) उपभोक्ता उद्योग उन्नत और पश्चिमी देशों से बेहतर था।
(C) इसके पास विशाल ऊर्जा-संसाधन उपलब्ध थे।
(D) सरकार ने नागरिकों हेतु न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित किया।

7. सोवियत प्रणाली में मुख्य नियंत्रक संस्था कौन सी थी?
(A) न्यायपालिका
(B) नौकरशाही
(C) सेना
(D) कम्युनिस्ट पार्टी

8. सूची-I का सूची-II से मिलान करें:
सूची I: (सोवियत नेता)
P. व्लादिमीर लेनिन
Q. जोजेफ स्टालिन
R. निकिता ख्रुश्चेव
S. मिखाइल गोर्बाचेव

सूची II: (प्रमुख योगदान/नीति)
1. पेरेस्त्रोइका और ग्लासनोस्त
2. 1917 की रूसी क्रांति के नायक
3. खेती का बलपूर्वक सामूहिकीकरण
4. पश्चिम के साथ 'शांतिपूर्ण सहअस्तित्व' का सुझाव

(A) P-2, Q-3, R-4, S-1
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

9. सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में किस वर्ष हस्तक्षेप किया था?
(A) 1975
(B) 1985
(C) 1979
(D) 1989

10. सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में मिखाइल गोर्बाचेव का चुनाव किस दशक में हुआ?
(A) 1980 के दशक के मध्य में

(B) 1970 के दशक के मध्य में
(C) 1990 के दशक के आरम्भ में
(D) 1960 के दशक के अंत में

11. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में आर्थिक-राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण की नीति चलायी।
कारण (R): 1980 के दशक में पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी और सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार आवश्यक थे।
उपरोक्त आलोक में उत्तर चुनें:
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

12. पूर्वी यूरोप के देशों में सोवियत नियंत्रण के विरुद्ध हुए प्रदर्शनों के प्रति गोर्बाचेव की क्या नीति थी?
(A) उन्होंने सैन्य हस्तक्षेप कर विद्रोहों को कुचल दिया।
(B) उन्होंने अतीत की तरह कोई हस्तक्षेप नहीं किया।
(C) उन्होंने स्थानीय साम्यवादी सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की।
(D) उन्होंने प्रदर्शनकारियों के साथ सीधी बातचीत की।

13. 1991 में सोवियत संघ में हुए तख्तापलट का विरोध करने में किस नेता ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई और नायक के रूप में उभरे?
(A) मिखाइल गोर्बाचेव
(B) लिओनिड ब्रेझनेव
(C) बोरिस येल्तसिन
(D) व्लादिमीर लेनिन

14. निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें:
1. बर्लिन की दीवार का गिरना
2. रूसी क्रांति
3. सोवियत संघ का विघटन
4. अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप
उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है?
(A) 1, 2, 3, 4
(B) 2, 4, 1, 3
(C) 4, 3, 2, 1
(D) 3, 1, 4, 2

15. दिसंबर 1991 में किन तीन बड़े गणराज्यों ने येल्तसिन के नेतृत्व में सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की?
(A) रूस, यूक्रेन और बेलारूस
(B) रूस, कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान
(C) एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया
(D) जॉर्जिया, आर्मेनिया और अज़रबैजान

16. सोवियत संघ के विघटन के बाद उसके उत्तराधिकारी राज्य के रूप में किसे स्वीकार किया गया?
(A) यूक्रेन
(B) रूस
(C) बेलारूस
(D) कज़ाकिस्तान

17. सोवियत संघ के विघटन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. सोवियत संघ की राजनीतिक-आर्थिक संस्थाएँ अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकीं।
2. अर्थव्यवस्था कई वर्षों तक गतिरुद्ध रही, जिससे उपभोक्ता-वस्तुओं की कमी हो गई।
3. सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का बड़ा हिस्सा परमाणु हथियारों और सैन्य साजो-सामान पर खर्च किया।
4. गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों का व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
5. राष्ट्रवाद और संप्रभुता के भावों का उभार विघटन का एक तात्कालिक कारण बना।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 4
(B) केवल 3, 4 और 5
(C) केवल 1, 2, 3 और 5
(D) सभी कथन सही हैं।

18. सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया?
(A) 70 वर्ष
(B) 50 वर्ष
(C) 60 वर्ष
(D) 80 वर्ष

19. सोवियत संघ के विघटन का एक परिणाम नहीं है?
(A) शीतयुद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति।
(B) विश्व राजनीति में शक्ति-संबंधों में बदलाव।
(C) मध्य-पूर्व में नए संकटों का उदय।
(D) नए देशों का उदय और एकध्रुवीय विश्व की शुरुआत।

20. सूची-I का सूची-II से मिलान करें:
सूची I: (घटना)
P. सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत
Q. बर्लिन की दीवार का गिरना
R. लिथुआनिया द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा
S. सोवियत संघ का अंत
सूची II: (वर्ष)
1. 1989
2. 1990

3. 1991
4. 1985

(A) P-4, Q-1, R-2, S-3
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-2, R-1, S-3
(D) P-2, Q-4, R-3, S-1

21. 'शॉक थेरेपी' का मॉडल किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा निर्देशित था?

(A) संयुक्त राष्ट्र और यूनिसेफ
(B) विश्व व्यापार संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन
(C) विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
(D) नाटो और यूरोपीय संघ

22. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:

अभिकथन (A): शॉक थेरेपी से पूर्व सोवियत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो गई।

कारण (R): शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रुप निजी स्वामित्व होगा और राज्य की संपत्ति का निजीकरण किया जाना चाहिए।

उपरोक्त आलोक में उत्तर चुनें:

(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

23. 'इतिहास की सबसे बड़ी गराज-सेल' किस घटना को कहा गया है?

(A) बर्लिन की दीवार के टुकड़ों की बिक्री
(B) सोवियत सैन्य उपकरणों का निस्तारण
(C) सामूहिक फार्मों का निजी फार्मों में परिवर्तन
(D) रूसी उद्योगों को औने-पौने दामों में बेचा जाना

24. शॉक थेरेपी के परिणामों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. रूसी मुद्रा रुबल के मूल्य में नाटकीय गिरावट आई।
2. समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया।
3. खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित हुई और आयात समाप्त हो गया।
4. अमीर और गरीब के बीच तीखा विभाजन हो गया।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(A) केवल 1 और 4
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) सभी 1, 2, 3 और 4

25. किस देश के राष्ट्रपति ने पहले 10 वर्षों के लिए और फिर अगले 10 वर्षों के लिए अपना कार्यकाल बढ़ाया?

(A) रुस और यूक्रेन
(B) बेलारुस और कज़ाकिस्तान
(C) तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान
(D) जॉर्जिया और आर्मेनिया

26. रुस के किन दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले?

(A) चेचन्या और दागिस्तान
(B) साइबेरिया और यूराल
(C) क्रीमिया और डोनबास
(D) तातारस्तान और बशकोर्तोस्तान

27. चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक किन दो देशों में विभक्त हुआ?

(A) सर्बिया और क्रोएशिया
(B) बोस्निया और हर्जेगोविना
(C) लिथुआनिया और लातविया
(D) चेक और स्लोवाक गणराज्य

28. शीतयुद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंधों के बारे में कौन सा कथन असत्य है?

(A) सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों में मदद की।
(B) भारत सोवियत संघ द्वारा बनाए गए सैन्य गठबंधन 'वारसा संधि' का सदस्य था।
(C) सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र में भारत का समर्थन किया।
(D) हिंदी फिल्में और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में लोकप्रिय थीं।

29. नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए हैं, लेकिन रुस के साथ उसके संबंध सबसे गहरे हैं।

कथन II: भारत और रुस दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:

(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

30. 2001 के भारत-रुस सामरिक समझौते के अंग के रूप में लगभग कितने द्विपक्षीय दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर हुए?

(A) 50
(B) 100
(C) 120
(D) 80

31. निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें:

1. मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के

महासचिव बने।
2. बोरिस येल्तसिन रूस के राष्ट्रपति बने।
3. रूस, बेलारूस और उक्रेन द्वारा सोवियत संघ को समाप्त करने का निर्णय।
4. गोर्बाचेव द्वारा राष्ट्रपति पद से इस्तीफा।

उपरोक्त का सही कालानुक्रम क्या है?
(A) 1, 2, 3, 4
(B) 2, 1, 4, 3
(C) 1, 3, 2, 4
(D) 4, 3, 2, 1

32. रूस के लिए भारत की क्या महत्ता है?
(A) भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीददार देश है।
(B) उपरोक्त सभी।
(C) भारत रूस को ऊर्जा-आयात करता है।
(D) भारत रूस की परमाण्विक योजना में सहायता करता है।

33. सोवियत प्रणाली में नागरिकों को अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए किन माध्यमों का प्रयोग करना पड़ता था?
(A) सार्वजनिक प्रदर्शनों और रैलियों का
(B) चुटकुलों और कार्टूनों का
(C) समाचार पत्रों में लेखों का
(D) विपक्षी दलों के मंचों का

34. सोवियत संघ के विघटन के कारणों पर विचार करें:
1. प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से व्यवस्था का गतिरुद्ध होना।
2. कम्युनिस्ट पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह न होना।
3. देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीकृत होना।
4. पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिक से ज्यादा विशेषाधिकार मिलना।
5. राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार।

उपरोक्त में से कौन से कारण सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 4
(B) केवल 3 और 5
(C) केवल 1, 2, 4 और 5
(D) उपरोक्त सभी 1, 2, 3, 4 और 5

35. बाल्टिक गणराज्य कौन-कौन से हैं?
(A) पोलैंड, हंगरी और रोमानिया
(B) रूस, यूक्रेन और बेलारूस
(C) एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया
(D) जॉर्जिया, आर्मेनिया और अज़रबैजान

36. सूची-I का सूची-II से मिलान करें:
सूची I: (अवधारणा)
P. शॉक थेरेपी
Q. दूसरी दुनिया
R. सीआईएस (CIS)
S. वारसा संधि

सूची II: (विवरण)
1. सोवियत खेमे का सैन्य गठबंधन
2. आघात पहुँचाकर उपचार करना
3. स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल
4. समाजवादी खेमे के देश

(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-4, R-3, S-1
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

37. सोवियत संघ के पतन के बाद कौन सी व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था बन गई?
(A) समाजवादी अर्थव्यवस्था
(B) मिश्रित अर्थव्यवस्था
(C) पूँजीवादी अर्थव्यवस्था
(D) साम्यवादी अर्थव्यवस्था

38. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): सोवियत संघ के विघटन के बाद, रूस के दो गणराज्यों चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले।
कारण (R): मध्य-एशियाई गणराज्यों में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उभार सबसे दमदार था क्योंकि वे धार्मिक और नस्ली रूप से रूस से अलग थे।
उपरोक्त आलोक में उत्तर चुनें:
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

39. 'पेरेस्त्रोइका' और 'ग्लासनोस्त' की नीतियां किस सोवियत नेता ने शुरु कीं?
(A) जोजेफ स्तालिन
(B) लिओनिड ब्रेझनेव
(C) बोरिस येल्तसिन
(D) मिखाइल गोर्बाचेव

40. सोवियत प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
(A) भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर राज्य का स्वामित्व था।
(B) यह निजी संपत्ति के अधिकार का समर्थन करती थी।
(C) इसमें बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था थी।
(D) अर्थव्यवस्था बाजार की ताकतों द्वारा नियंत्रित होती थी।

41. सोवियत संघ के विघटन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें:
1. सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप

में मिखाइल गोर्बाचेव का चुनाव।
2. बर्लिन की दीवार का गिरना।
3. बोरिस येल्तसिन द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा।
4. रूस, यूक्रेन और बेलारूस द्वारा सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा।

इन घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है?
(A) 1, 2, 3, 4
(B) 2, 1, 4, 3
(C) 1, 3, 2, 4
(D) 3, 1, 2, 4

42. 1991 के बाद युगोस्लाविया के विखंडन से कौन से देश बने?
(A) बोस्निया-हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया
(B) चेक और स्लोवाक गणराज्य
(C) एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया
(D) पोलैंड और हंगरी

43. 'शॉक थेरेपी' की सर्वोपरि मान्यता क्या थी?
(A) राज्य-नियंत्रित समाजवाद को बढ़ावा देना।
(B) एक वैकल्पिक 'तीसरे रुख' को अपनाना।
(C) सोवियत खेमे के बीच व्यापारिक गठबंधनों को मजबूत करना।
(D) मिल्कियत का सबसे प्रभावी रुप निजी स्वामित्व है।

44. शॉक थेरेपी के अंतर्गत, सामूहिक 'फार्म' को किसमें बदलने का प्रावधान था?
(A) राजकीय 'फार्म'
(B) निजी 'फार्म'
(C) सहकारी 'फार्म'
(D) सामुदायिक 'फार्म'

45. सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे?
(A) बोरिस येल्तसिन
(B) लिओनिड ब्रेझनेव
(C) मिखाइल गोर्बाचेव
(D) निकिता ख्रुश्चेव

46. सोवियत संघ के विघटन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध हो गई थी।
2. सोवियत संघ के आम नागरिकों को पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में जानकारी नहीं थी।
3. सोवियत राजव्यवस्था पश्चिम के पूँजीवाद से बेहतर है, यह सच्चाई थी।
4. गोर्बाचेव के सुधारों ने लोगों की आकांक्षाओं का ज्वार पैदा किया।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 4
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) सभी 1, 2, 3 और 4

47. सूची-I का सूची-II से मिलान करें:
सूची I: (देश/गणराज्य)
P. चेचन्या
Q. ताजिकिस्तान
R. युगोस्लाविया
S. चेकोस्लोवाकिया

सूची II: (घटना)
1. गृहयुद्ध और बगावत
2. शांतिपूर्ण विभाजन
3. हिंसक अलगाववादी आंदोलन
4. दस वर्षों तक गृहयुद्ध

(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-3, R-2, S-1
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

48. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद, अमरीका अकेली महाशक्ति बन बैठा।
कथन II: विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएँ विभिन्न देशों की ताकतवर सलाहकार बन गईं।
उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

49. सोवियत संघ के विघटन के बाद, रूस के साथ भारत के संबंधों के क्या लाभ हैं?
(A) कश्मीर मामले पर समर्थन
(B) उपरोक्त सभी
(C) ऊर्जा-आपूर्ति
(D) चीन के साथ संबंधों में संतुलन

50. 'स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल' (CIS) का गठन कब हुआ?
(A) 1991
(B) 1989
(C) 1990
(D) 1993

51. शॉक थेरेपी के परिणामों पर विचार करें:
1. लगभग 90 प्रतिशत उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेचा गया।
2. रूसी मुद्रा रुबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से वृद्धि हुई।
3. समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को क्रम से नष्ट किया गया।
4. निजीकरण ने नई विषमताओं को जन्म दिया।
5. संविधान हड़बड़ी में तैयार किए गए और संसद कमजोर संस्था रह गई।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(A) केवल 1, 2 और 4
(B) केवल 1, 3, 4 और 5
(C) केवल 2, 3 और 5
(D) सभी कथन सही हैं।

52. 'ग्लासनोस्त' का शाब्दिक अर्थ क्या है?
(A) पुनर्रचना
(B) समाजवाद
(C) निजीकरण
(D) खुलेपन

53. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): सोवियत संघ के यूरोपीय और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्यों में राष्ट्रवादी असंतोष सबसे प्रबल नजर आया।
कारण (R): इन गणराज्यों के लोगों में यह भाव घर कर गया था कि ज्यादा पिछड़े इलाकों को संघ में शामिल रखने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है।
उपरोक्त आलोक में उत्तर चुनें:
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

54. सोवियत अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए गोर्बाचेव द्वारा उठाए गए कदमों में से एक नहीं था?
(A) पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाना
(B) अर्थव्यवस्था को और अधिक केंद्रीकृत करना
(C) सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देना
(D) प्रशासनिक ढाँचे में ढील देना

55. रूस के अलावा, पूर्व सोवियत संघ के कौन से देश तेल और गैस के बड़े उत्पादक हैं?
(A) एस्टोनिया और लातविया
(B) यूक्रेन और बेलारूस
(C) जॉर्जिया और आर्मेनिया
(D) कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अज़रबैजान

56. सोवियत नेता लिओनिड ब्रेझनेव किस घटना से संबद्ध नहीं थे?
(A) सोवियत संघ का विघटन
(B) एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव
(C) चेकोस्लोवाकिया के जन-विद्रोह का दमन
(D) अफगानिस्तान पर आक्रमण

57. सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन क्या कहलाता था?
(A) नाटो (NATO)
(B) सीटो (SEATO)
(C) वारसा संधि (Warsaw Pact)
(D) सेंटो (CENTO)

58. 1917 की समाजवादी क्रांति का नेतृत्व किसने किया?
(A) व्लादिमीर लेनिन
(B) जोजेफ स्टालिन
(C) निकिता ख्रुश्चेव
(D) मिखाइल गोर्बाचेव

59. बर्लिन की दीवार का निर्माण किस वर्ष हुआ था?
(A) 1945
(B) 1951
(C) 1989
(D) 1961

60. सूची-I का सूची-II से मिलान करें:
सूची I: (भारतीय सहयोग)
P. भिलाई इस्पात कारखाना
Q. बोकारो इस्पात कारखाना
R. 1971 का युद्ध
S. कश्मीर मामला
सूची II: (सोवियत भूमिका)
1. संयुक्त राष्ट्र में समर्थन
2. आर्थिक और तकनीकी सहायता
3. सैन्य सहायता
4. राजनीतिक समर्थन
(A) P-2, Q-2, R-3, S-1
(B) P-1, Q-2, R-4, S-3
(C) P-2, Q-3, R-1, S-4
(D) P-3, Q-1, R-2, S-4

61. सोवियत संघ के पतन के तात्कालिक कारण की पहचान करें।
(A) आर्थिक गतिरोध
(B) पश्चिमी देशों से तकनीकी पिछड़ापन
(C) राष्ट्रवाद और संप्रभुता के भावों का उभार
(D) अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप

62. सोवियत प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. सरकार बुनियादी जरूरत की चीजें रियायती दर पर मुहैया कराती थी।
2. मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व था।
3. लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी।
4. कम्युनिस्ट पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह थी।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2 और 4
(C) केवल 1, 2 और 3

(D) सभी 1, 2, 3 और 4

63. सोवियत संघ के विघटन के बाद, सुरक्षा परिषद् में उसकी स्थायी सीट किसे मिली?
(A) रूसी गणराज्य को
(B) यूक्रेन को
(C) संयुक्त राष्ट्र को
(D) स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल को

64. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): 1990 के दशक में अपनाई गई 'शॉक थेरेपी' जनता को उपभोग के उस 'आनंदलोक' तक नहीं ले गई जिसका उसने वादा किया था।
कारण (R): शॉक थेरेपी के परिणामस्वरुप, सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो गई और लोगों की खाद्यान्न सुरक्षा नष्ट हो गई।
उपरोक्त आलोक में उत्तर चुनें:
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

65. जोजेफ स्टालिन के शासनकाल (1924-1953) की एक प्रमुख विशेषता क्या थी?
(A) लोकतंत्रीकरण और खुलेपन की नीति
(B) औद्योगीकरण को तेजी से बढ़ावा और खेती का बलपूर्वक सामूहिकीकरण
(C) पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व
(D) सोवियत संघ का विघटन

66. निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करें:
1. मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने।
2. लिथुआनिया में आजादी के लिए आंदोलन शुरू।
3. गोर्बाचेव ने बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की।
4. येल्तसिन रूस के राष्ट्रपति बने।
5. गोर्बाचेव ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया।
उपरोक्त का सही कालानुक्रम क्या है?
(A) 1, 2, 3, 4, 5
(B) 2, 1, 3, 5, 4
(C) 1, 3, 2, 4, 5
(D) 3, 1, 4, 2, 5

67. 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में सोवियत व्यवस्था के लड़खड़ाने का क्या कारण था?
(A) उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में पश्चिम से पीछे छूटना
(B) उपभोक्ता वस्तुओं की कमी
(C) उपरोक्त सभी
(D) खाद्यान्न का बढ़ता आयात

68. 'पेरेस्त्रोइका' का अर्थ क्या है?
(A) खुलापन
(B) लोकतंत्र
(C) स्वतंत्रता
(D) पुनर्रचना

69. स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य कौन सा था?
(A) यूक्रेन
(B) जॉर्जिया
(C) लिथुआनिया
(D) रूस

70. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: सोवियत संघ का पतन के बाद, बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश 'यूरोपीय संघ' से जुड़ना चाहते थे।
कथन II: मध्य एशियाई देश अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर रूस और पश्चिमी देशों, दोनों के साथ संबंध बनाए रखना चाहते थे।
उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

71. सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सी एक परिणति नहीं हुई?
(A) एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय।
(B) हथियारों की होड़ की समाप्ति।
(C) विचारधारात्मक विवाद का अंत।
(D) द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।

72. सूची-I का सूची-II से मिलान करें:
सूची I: (नेता)
P. बोरिस येल्तसिन
Q. लिओनिड ब्रेझनेव
R. निकिता ख्रुश्चेव
S. व्लादिमीर लेनिन
सूची II: (पद/भूमिका)
1. क्यूबा मिसाइल संकट में शामिल
2. रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति
3. बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक
4. एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव
(A) P-1, Q-3, R-2, S-4
(B) P-2, Q-4, R-1, S-3
(C) P-3, Q-2, R-4, S-1
(D) P-4, Q-1, R-3, S-2

73. रूस में 'माफिया वर्ग' के उदय का प्रमुख कारण क्या था?
(A) लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण
(B) समाज कल्याण की व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण
(C) निजीकरण की प्रक्रिया और आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण
(D) खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि

74. सोवियत प्रणाली की विशेषताओं पर विचार करें:
1. न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी।
2. बेरोजगारी का न होना।
3. राज्य का स्वामित्व उत्पादन के साधनों पर।
4. उन्नत उपभोक्ता उद्योग।
5. नागरिकों को राजनीतिक अधिकार।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 2, 4 और 5
(C) केवल 1, 3 और 5
(D) सभी कथन सही हैं।

75. 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमरीका ने किस क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनाना चाहा?
(A) पूर्वी यूरोप
(B) बाल्टिक क्षेत्र
(C) बाल्कन क्षेत्र
(D) मध्य एशिया

76. पूर्व सोवियत संघ के किस गणराज्य में गृहयुद्ध दस वर्षों (2001 तक) तक चला?
(A) अज़रबैजान
(B) ताजिकिस्तान
(C) जॉर्जिया
(D) उज़्बेकिस्तान

77. शीतयुद्ध के दौरान, भारत की विदेश नीति के सोवियत संघ का समर्थन करने का एक अप्रत्यक्ष तरीका क्या था?
(A) भारत ने वारसा संधि पर हस्ताक्षर किए।
(B) भारत ने खुले तौर पर अमेरिकी नीतियों की निंदा की।
(C) भारत ने सोवियत संघ की विदेश नीति का अप्रत्यक्ष समर्थन किया।
(D) भारत ने सोवियत सैन्य अड्डों की अनुमति दी।

78. 'बहुध्रुवीय विश्व' से रूस और भारत का क्या आशय है?
(A) अंतर्राष्ट्रीय फलक पर केवल दो शक्तियों का होना।
(B) अंतर्राष्ट्रीय फलक पर एक ही शक्ति का प्रभुत्व।
(C) किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का न होना।
(D) अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियों का मौजूद होना।

79. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): भारत-रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास है।
कारण (R): भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है और रूस ने तेल संकट की घड़ी में भारत की मदद की है।
उपरोक्त आलोक में उत्तर चुनें:
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

80. 'अनिर्धारित सीमा' (Undetermined Boundary) का उल्लेख किन देशों के बीच की स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है?
(A) अज़रबैजान, अर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान
(B) रूस और चीन
(C) कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान
(D) पाकिस्तान और अफगानिस्तान

81. बर्लिन की दीवार लगभग कितने किलोमीटर लंबी थी?
(A) 50 किलोमीटर
(B) 150 किलोमीटर से ज्यादा
(C) 100 किलोमीटर
(D) 200 किलोमीटर

82. सोवियत संघ के पतन के बाद की घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें:
1. युगोस्लाविया का विखंडन शुरु हुआ।
2. जॉर्जिया राष्ट्रकुल का सदस्य बना।
3. बाल्टिक गणराज्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने।
4. बाल्टिक गणराज्य नाटो में शामिल हुए।
उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है?
(A) 1, 3, 2, 4
(B) 3, 1, 4, 2
(C) 2, 4, 1, 3
(D) 4, 2, 3, 1

83. 'दूसरी दुनिया' के पतन का एक परिणाम क्या था?
(A) समाजवादी प्रणाली का विस्तार
(B) गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अंत
(C) शीतयुद्ध के संघर्ष की समाप्ति
(D) संयुक्त राष्ट्र की स्थापना

84. शॉक थेरेपी के अंतर्गत, व्यापार के संबंध में किस नीति को अपनाना महत्वपूर्ण माना गया?
(A) संरक्षणवाद की नीति
(B) आयात प्रतिस्थापन की नीति
(C) राज्य-नियंत्रित व्यापार की नीति
(D) मुक्त व्यापार की नीति

85. सोवियत संघ के विघटन के कारणों पर विचार करें:

1. कम्युनिस्ट पार्टी का 70 साल का शासन।
2. शासन में ज्यादा खुलापन लाने की अनिच्छा।
3. गोर्बाचेव के सुधारों की धीमी गति।
4. सोवियत राजव्यवस्था का पश्चिम के पूँजीवाद से बेहतर होने का भ्रम टूटना।

उपरोक्त में से कौन से कारण सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3 और 4
(C) केवल 1, 2 और 4
(D) उपरोक्त सभी

86. सोवियत प्रणाली की किस एक विशेषता ने नागरिकों का जीवन कठिन बना दिया था?
(A) न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी
(B) लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी का न होना
(C) स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता
(D) रियायती दर पर शिक्षा की सुविधा

87. सूची-I का सूची-II से मिलान करें:
सूची I: (क्षेत्र/गणराज्य)
P. नगरनो-कराबाख
Q. जॉर्जिया
R. यूक्रेन
S. बेलारुस

सूची II: (विवाद/स्थिति)
1. स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य
2. दो प्रांत स्वतंत्रता चाहते हैं और गृहयुद्ध लड़ रहे हैं
3. स्थानीय अर्मेनियाई लोगों का अलगाववादी आंदोलन
4. यहाँ भी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे हैं

(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-3, Q-2, R-4, S-1
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

88. सोवियत संघ के किस नेता को "1930 के दशक के भयानक आतंक" के लिए जिम्मेदार ठहराया गया?
(A) जोजेफ स्टालिन
(B) व्लादिमीर लेनिन
(C) निकिता ख्रुश्चेव
(D) लिओनिड ब्रेझनेव

89. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): सोवियत संघ ने समय-समय पर हथियारों की होड़ में अमरीका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी।
कारण (R): सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका।
उपरोक्त आलोक में उत्तर चुनें:
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

90. रुस में आर्थिक पुनर्जीवन का प्रमुख कारण क्या था?
(A) खनिज, तेल, प्राकृतिक गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात
(B) कृषि उत्पादन में वृद्धि
(C) विदेशी सहायता
(D) सेवा क्षेत्र का विकास

91. सोवियत संघ के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल (CIS) का गठन किन गणराज्यों के लिए विशेष रुप से आश्चर्यचकित करने वाला था?
(A) बाल्टिक गणराज्यों
(B) पूर्वी यूरोप के देशों
(C) बाल्कन गणराज्यों
(D) मध्य एशियाई गणराज्यों

92. शॉक थेरेपी के बाद रुस सहित अधिकांश देशों में संविधान निर्माण की प्रक्रिया में राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बनाने का क्या परिणाम हुआ?
(A) संसद ने स्वयं को एक अत्यंत शक्तिशाली और स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया।
(B) राष्ट्रपति अत्यधिक शक्तिशाली हो गए और संसद कमजोर संस्था बन गई।
(C) प्रधानमंत्री को शासन के सभी मुख्य क्षेत्रों में व्यापक अधिकार प्राप्त हुए।
(D) स्वतंत्र न्यायपालिका को प्रशासन के सबसे शक्तिशाली अंग के रूप में मान्यता मिली।

93. भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 1971 की भारत-सोवियत मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए, जब सोवियत संघ ने पाकिस्तान से युद्ध के दौरान भारत की मदद की?
(A) जवाहरलाल नेहरु
(B) लाल बहादुर शास्त्री
(C) इंदिरा गांधी
(D) राजीव गांधी

94. सोवियत संघ में शामिल कुल गणराज्यों की संख्या कितनी थी?
(A) 10
(B) 12
(C) 20
(D) 15

95. सोवियत संघ के पतन के बाद विश्व राजनीति में हुए परिवर्तनों पर विचार करें:
1. शीतयुद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति हुई।

2. एकध्रुवीय विश्व का उदय हुआ जिसमें अमरीका का दबदबा था।
3. पूँजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था बन गई।
4. उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा।
5. अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक और मुद्रा कोष की भूमिका घटी।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 4
(B) केवल 3, 4 और 5
(C) केवल 1, 2, 3 और 4
(D) सभी कथन सही हैं।

96. सोवियत संघ के पतन का वह कौन सा कारण था जिसे इतिहास की अनिवार्यता के रूप में देखा जा सकता है?
(A) गोर्बाचेव के सुधार
(B) राष्ट्रीयता की भावना और तड़प का जारी रहना
(C) आर्थिक ठहराव
(D) कम्युनिस्ट पार्टी का भ्रष्टाचार

97. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता-उद्योग बहुत उन्नत था और पिन से लेकर कार तक सभी चीजों का उत्पादन करता था।
कथन II: सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली वस्तुएँ गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर की थीं।
उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

98. सूची-I का सूची-II से मिलान करें:
सूची I: (पदनाम)
P. बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक
Q. सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति
R. रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति
S. लेनिन के उत्तराधिकारी

सूची II: (नेता)
1. मिखाइल गोर्बाचेव
2. बोरिस येल्तसिन
3. जोजेफ स्टालिन
4. व्लादिमीर लेनिन

(A) P-4, Q-1, R-2, S-3
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-3, R-1, S-2
(D) P-2, Q-4, R-3, S-1

99. निकिता ख्रुश्चेव किस प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संकट में शामिल थे?
(A) स्वेज नहर संकट
(B) कोरियाई युद्ध
(C) क्यूबा का मिसाइल संकट
(D) वियतनाम युद्ध

100. भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट तकनीक प्रदान करने में किस देश ने मदद की है?
(A) अमरीका
(B) फ्रांस
(C) इज़राइल
(D) रूस

101. सोवियत संघ के विघटन के बाद, पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा किसे मिला?
(A) यूक्रेन
(B) कज़ाकिस्तान
(C) रूस
(D) बेलारूस

102. सोवियत संघ के विघटन के कालानुक्रम को व्यवस्थित करें:
1. बर्लिन की दीवार का गिरना
2. सोवियत संघ द्वारा बहुदलीय राजनीति को अपनाना
3. रूसी संसद द्वारा सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा
4. कम्युनिस्ट पार्टी के गरमपंथियों द्वारा असफल तख्तापलट

उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है?
(A) 1, 2, 3, 4
(B) 2, 1, 4, 3
(C) 1, 3, 2, 4
(D) 3, 2, 1, 4

103. गोर्बाचेव के सुधारों के प्रति कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों और व्यवस्था से लाभान्वित लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी?
(A) उन्होंने सुधारों का पूर्ण समर्थन किया।
(B) वे चाहते थे कि सुधार और तेज गति से लागू किए जाएं।
(C) वे सुधारों के प्रति पूरी तरह से उदासीन थे।
(D) वे मानते थे कि गोर्बाचेव बहुत जल्दबाजी दिखा रहे थे और उनके विशेषाधिकार कम हो रहे थे।

104. भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स (BHEL) की स्थापना में किस देश ने आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान की?
(A) सोवियत संघ
(B) संयुक्त राज्य अमरीका
(C) ब्रिटेन
(D) जर्मनी

105. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): शॉक थेरेपी अपनाने वाले देशों में, एक 'माफिया वर्ग' उभरा और उसने अधिकतर आर्थिक गतिविधियों

को अपने नियंत्रण में ले लिया।
कारण (R): आर्थिक बदलाव को बड़ी प्राथमिकता दी गई लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सका।
उपरोक्त आलोक में उत्तर चुनें:
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

106. सोवियत राजनीतिक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह समाजवाद और समतामूलक समाज के आदर्शों से प्रेरित थी।
2. इसमें राज्य और 'पार्टी की संस्था' को प्राथमिक महत्त्व दिया गया।
3. अर्थव्यवस्था राज्य के नियंत्रण में थी।
4. इसमें विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 4
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) उपरोक्त सभी

107. "तो फिर, आलू के पहाड़ भी नहीं होते!" यह चुटकुला सोवियत व्यवस्था की किस खामी पर व्यंग्य करता है?
(A) अर्थव्यवस्था की विफलता
(B) कृषि का सामूहिकीकरण
(C) नौकरशाही का भ्रष्टाचार
(D) ईश्वर और धर्म पर राज्य का नियंत्रण

108. बाल्कन क्षेत्र का कौन सा गणराज्य 1991 के बाद कई प्रांतों में टूट गया और वहाँ गृहयुद्ध छिड़ गया?
(A) रोमानिया
(B) युगोस्लाविया
(C) बुल्गारिया
(D) अल्बानिया

109. सोवियत संघ के पतन के बाद, भारत और रूस ने जिस साझा दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया, वह क्या था?
(A) एकध्रुवीय विश्व
(B) द्विध्रुवीय विश्व
(C) बहुध्रुवीय विश्व
(D) गैर-ध्रुवीय विश्व

110. सोवियत संघ के किस नेता ने स्टालिन की नेतृत्व-शैली की आलोचना की और 1956 में कुछ सुधार लागू किए?
(A) लिओनिड ब्रेझनेव
(B) मिखाइल गोर्बाचेव
(C) व्लादिमीर लेनिन
(D) निकिता ख्रुश्चेव

111. सोवियत संघ के विघटन के बाद, पूर्व सोवियत गणराज्यों में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित करने का प्रयास किया गया?
(A) लोकतांत्रिक पूँजीवादी व्यवस्था
(B) सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था
(C) राजतंत्रीय व्यवस्था
(D) सैन्य तानाशाही

112. सूची-I का सूची-II से मिलान करें:
सूची I: (नेता)
P. मिखाइल गोर्बाचेव
Q. बोरिस येल्तसिन
R. व्लादिमीर लेनिन
S. जोजेफ स्टालिन

सूची II: (कार्यकाल/भूमिका)
1. 1917-1924
2. 1924-1953
3. 1985-1991
4. 1991-1999

(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-3, R-2, S-1
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

113. 'दूसरी दुनिया' के विघटन के परिणामों पर विचार करें:
1. शीतयुद्ध के संघर्ष की समाप्ति।
2. अमरीका का अकेली महाशक्ति बनना।
3. नए देशों का उदय।
4. उदारवादी लोकतंत्र का प्रभुत्व।
5. समाजवादी विचारधारा का वैश्विक प्रसार।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 5
(B) केवल 3, 4 और 5
(C) केवल 1, 2, 3 और 4
(D) सभी कथन सही हैं।

114. गोर्बाचेव द्वारा शुरू किए गए सुधारों का विरोध किसने किया?
(A) कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गरमपंथियों ने
(B) आम जनता ने
(C) पश्चिमी देशों ने
(D) मध्य एशियाई गणराज्यों ने

115. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): सोवियत संघ के विघटन के बाद, मध्य एशियाई गणराज्यों ने तुरंत स्वतंत्रता की मांग नहीं की।
कारण (R): मध्य एशियाई गणराज्य आर्थिक रूप से पिछड़े थे और उन्हें डर था कि वे स्वतंत्र रूप से अपना निर्वाह नहीं कर

पाएंगे, इसलिए वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे।
उपरोक्त आलोक में उत्तर चुनें:
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

116. किस भारतीय अभिनेता का नाम रूस और पूर्व सोवियत गणराज्यों में घर-घर जाना जाता है?
(A) दिलीप कुमार
(B) देव आनंद
(C) राजेश खन्ना
(D) राज कपूर

117. 'शॉक थेरेपी' की एक तात्कालिक परिणति क्या थी?
(A) उद्योगों का तेजी से विकास
(B) मुद्रास्फीति पर नियंत्रण
(C) पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का तहस-नहस होना
(D) सामाजिक समानता में वृद्धि

118. बर्लिन की दीवार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
(A) यह पूँजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी।
(B) दीवार का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के तुरंत बाद हुआ था।
(C) यह 28 वर्षों तक खड़ी रही।
(D) इसे 9 नवंबर, 1989 को तोड़ा गया।

119. सोवियत संघ के पतन के बाद हुए संघर्षों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है?
(A) चेचन्या - शांतिपूर्ण अलगाव
(B) चेकोस्लोवाकिया - हिंसक विभाजन
(C) युगोस्लाविया - शांतिपूर्ण समझौता
(D) ताजिकिस्तान - दस साल का गृहयुद्ध

120. भारत और सोवियत संघ के बीच सांस्कृतिक संबंधों का एक उदाहरण है:
(A) भारतीय लेखकों और कलाकारों की सोवियत संघ की यात्रा
(B) दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास
(C) संयुक्त राष्ट्र में एक-दूसरे का समर्थन
(D) व्यापार के लिए रुपये का माध्यम के रूप में प्रयोग

121. निम्नलिखित सोवियत नेताओं को उनके कार्यकाल के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करें:
1. जोजेफ स्टालिन
2. निकिता ख्रुश्चेव
3. लिओनिड ब्रेझनेव
4. मिखाइल गोर्बाचेव
उपरोक्त नेताओं का सही कालानुक्रम क्या है?
(A) 1, 2, 3, 4
(B) 2, 1, 4, 3
(C) 1, 3, 2, 4
(D) 4, 3, 2, 1

122. सोवियत संघ में शामिल किस गणराज्य का हर मामले में प्रभुत्व था?
(A) रूस
(B) यूक्रेन
(C) कज़ाकिस्तान
(D) बेलारूस

123. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: गोर्बाचेव के सुधारों के कारण लोगों की आकांक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा जिसका अनुमान लगाना मुश्किल था।
कथन II: जनता का एक तबका चाहता था कि गोर्बाचेव और तेजी से कदम उठाएं, जबकि दूसरा तबका (कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य) मानता था कि वह बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं।
उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

124. सोवियत संघ के विघटन के बाद, किस विचारधारा को राजनीतिक जीवन की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में देखा जाने लगा?
(A) समाजवाद
(B) उदारवादी लोकतंत्र
(C) साम्यवाद
(D) फासीवाद

125. भारत-रूस संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत, रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है।
2. रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में मदद की है।
3. दोनों देश विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में साझीदार हैं।
4. दोनों देशों का सपना एकध्रुवीय विश्व का है।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 4
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) सभी 1, 2, 3 और 4

126. सोवियत संघ के विघटन का आरोप किस नेता पर लगा?
(A) बोरिस येल्तसिन
(B) लिओनिड ब्रेझनेव

(C) जोजेफ स्टालिन
(D) मिखाइल गोर्बाचेव

127. सूची-I का सूची-II से मिलान करें:
सूची I: (शब्द)
P. पेरेस्त्रोइका
Q. ग्लासनोस्त
R. शॉक थेरेपी
S. दूसरी दुनिया
सूची II: (अर्थ)
1. खुलापन
2. पुनर्रचना
3. समाजवादी खेमा
4. आघात पहुँचाकर उपचार
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-1, R-4, S-3
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

128. पूर्व साम्यवादी देशों में 'शॉक थेरेपी' अपनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था?
(A) समाजवादी व्यवस्था को मजबूत करना
(B) पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण
(C) एक मिश्रित अर्थव्यवस्था स्थापित करना
(D) सैन्य शक्ति में वृद्धि करना

129. सोवियत संघ के पतन के बाद, किन देशों ने 1922 की सोवियत संघ के निर्माण से संबद्ध संधि को समाप्त करने का फैसला किया?
(A) रूस, पोलैंड, हंगरी
(B) रूस, बेलारूस, उक्रेन
(C) एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया
(D) कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिजिस्तान

130. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीतयुद्ध समाप्त हो गया।
कारण (R): विघटन ने 'समाजवादी प्रणाली पूँजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं' - इस विचारधारात्मक विवाद को समाप्त कर दिया।
उपरोक्त आलोक में उत्तर चुनें:
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सही है।

131. सोवियत संघ के विघटन के कारणों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. अर्थव्यवस्था का गतिरुद्ध होना।
2. नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा करने में व्यवस्था की विफलता।
3. हथियारों की होड़ में संसाधनों का अत्यधिक व्यय।
4. राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार।
5. कम्युनिस्ट पार्टी का अलोकतांत्रिक और सत्तावादी चरित्र।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 5
(B) केवल 3, 4 और 5
(C) केवल 1, 2, 4 और 5
(D) उपरोक्त सभी 1, 2, 3, 4 और 5

132. 'वारसा समझौते' के सदस्यों को अपना भविष्य तय करने की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई?
(A) मार्च 1985
(B) जून 1988
(C) फरवरी 1990
(D) अक्टूबर 1989

133. सोवियत संघ के पतन के बाद, उसकी विदेश नीति के दायित्वों (अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियाँ) को निभाने का जिम्मा किसने लिया?
(A) संयुक्त राष्ट्र
(B) यूक्रेन
(C) रूस
(D) सीआईएस (CIS)

134. सोवियत प्रणाली की आलोचना का एक मुख्य बिंदु क्या था?
(A) अत्यधिक औद्योगीकरण
(B) सत्ता का सत्तावादी होते जाना और नौकरशाही का शिकंजा
(C) कृषि पर अत्यधिक ध्यान
(D) अत्यधिक लोक कल्याणकारी योजनाएं

135. साम्यवाद के पतन के बाद पूर्वी और मध्य यूरोप के देशों के संक्रमण का वर्णन करने के लिए किस पद का उपयोग किया गया था?
(A) ग्लासनोस्त
(B) पेरेस्त्रोइका
(C) नई आर्थिक नीति
(D) शॉक थेरेपी

136. बोरिस येल्तसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
(A) उन्होंने 1991 के तख्तापलट का समर्थन किया था।
(B) वे रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति थे।
(C) वे गोर्बाचेव द्वारा मास्को के मेयर बनाए गए थे।
(D) उन्होंने सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाई।

137. शॉक थेरेपी के आर्थिक परिणामों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राज्य-नियंत्रित औद्योगिक ढाँचा चरमरा उठा।
2. उद्योगों को कम कीमत पर बेचा गया।
3. रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय गिरावट आई।
4. मुद्रास्फीति बहुत बढ़ गई।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(A) केवल 1 और 4
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) उपरोक्त सभी

138. सोवियत संघ द्वारा अपने संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा पूर्वी यूरोप के अपने पिछलग्गू देशों पर खर्च करने का क्या उद्देश्य था?

(A) उन्हें सोवियत नियंत्रण में बनाए रखना।
(B) उन देशों में लोकतंत्र स्थापित करना।
(C) उन देशों में आर्थिक समृद्धि लाना।
(D) उन्हें नाटो में शामिल होने से रोकना।

139. सूची-I का सूची-II से मिलान करें:

सूची I: (घटना)

P. रूसी क्रांति
Q. बर्लिन दीवार का निर्माण
R. सोवियत संघ का विघटन
S. बर्लिन दीवार का गिरना

सूची II: (वर्ष)

1. 1961
2. 1989
3. 1917
4. 1991

(A) P-3, Q-1, R-4, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-3, R-2, S-1
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

140. किस घटना को शीतयुद्ध के अंत का प्रतीक माना जाता है?

(A) क्यूबा मिसाइल संकट
(B) बर्लिन की दीवार का गिरना
(C) वियतनाम युद्ध का अंत
(D) कोरियाई युद्ध का अंत

141. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:

अभिकथन (A): भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए हैं।

कारण (R): भारतीय हिन्दी फिल्मों के नायक रूस और पूर्व सोवियत संघ के बाकी गणराज्यों में घर-घर जाने जाते हैं।

उपरोक्त आलोक में उत्तर चुनें:

(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

142. सोवियत संघ में 72 वर्षों से चला आ रहा किस पार्टी का एकाधिकार फरवरी 1990 में समाप्त हुआ?

(A) सोशलिस्ट पार्टी
(B) डेमोक्रेटिक पार्टी
(C) लेबर पार्टी
(D) कम्युनिस्ट पार्टी

143. सोवियत संघ के पतन से जुड़ी घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें:

1. रूस, बेलारूस और यूक्रेन द्वारा 1922 की संधि को समाप्त करना
2. मिखाइल गोर्बाचेव का राष्ट्रपति पद से इस्तीफा
3. सोवियत संघ का अंत
4. बाल्टिक गणराज्यों का संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनना

उपरोक्त का सही कालानुक्रम क्या है?

(A) 1, 4, 3, 2
(B) 4, 1, 2, 3
(C) 2, 3, 1, 4
(D) 4, 2, 1, 3

144. शीतयुद्ध के दौरान, भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी, तब सोवियत संघ ने किस माध्यम से भारत के साथ व्यापार किया?

(A) डॉलर
(B) रुपया
(C) स्वर्ण
(D) वस्तु-विनिमय

145. सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा के बाद मध्य एशियाई गणराज्यों को क्या दर्जा दिया गया?

(A) उन्हें राष्ट्रकुल से बाहर रखा गया।
(B) उन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बनाया गया।
(C) उन्हें पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया।
(D) उन्हें यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए कहा गया।

146. शॉक थेरेपी के सामाजिक परिणामों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई।
2. सरकारी रियायतों के खात्मे से ज्यादातर लोग गरीबी में पड़ गए।
3. मध्य वर्ग समाज के हाशिए पर आ गया।
4. 'माफिया वर्ग' का उदय हुआ।
5. धनी और निर्धन लोगों के बीच गहरी आर्थिक असमानता पैदा हुई।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(A) केवल 1, 2 और 5
(B) केवल 3, 4 और 5
(C) केवल 1, 2, 4 और 5
(D) उपरोक्त सभी 1, 2, 3, 4 और 5

147. सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?
(A) सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी।
(B) उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व/नियंत्रण था।
(C) जनता को पूर्ण आर्थिक आजादी थी।
(D) अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था।

148. सूची-I का सूची-II से मिलान करें:
सूची I: (देश/समूह)
P. रूस, बेलारूस, उक्रेन
Q. एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया
R. चेक और स्लोवाक गणराज्य
S. चेचन्या, दागिस्तान
सूची II: (विशेषता/घटना)
1. शांतिपूर्ण विभाजन
2. रूस के भीतर अलगाववादी आंदोलन
3. CIS के संस्थापक सदस्य
4. बाल्टिक गणराज्य
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-3, R-2, S-1
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

149. सोवियत संघ ने अपने संसाधन किन दो प्रमुख क्षेत्रों पर लगाए जिससे उस पर गहरा आर्थिक दबाव बना?
(A) कृषि और उपभोक्ता उद्योग
(B) स्वास्थ्य और शिक्षा
(C) परमाणु हथियार/सैन्य साजो-सामान और पूर्वी यूरोप के पिछलग्गू देश
(D) अंतरिक्ष अनुसंधान और सूचना प्रौद्योगिकी

150. उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:
कथन I: शॉक थेरेपी के अंतर्गत, सोवियत खेमे के देशों के बीच मौजूद व्यापारिक गठबंधनों को समाप्त कर दिया गया।
कथन II: इन देशों को एक-दूसरे से जोड़ने की जगह सीधे पश्चिमी मुल्कों से जोड़ा गया ताकि वे पश्चिमी अर्थतंत्र में समाहित हो सकें।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं तथा कथन II, कथन I की सही व्याख्या करता है।
(B) कथन I और कथन II दोनों सही हैं लेकिन कथन II, कथन I की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
सोवियत प्रणाली, जिसे 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद स्थापित किया गया, एक अद्वितीय आर्थिक और राजनीतिक संरचना पर आधारित थी। इस प्रणाली का मूल आधार 'आदेशात्मक अर्थव्यवस्था' (commऔर economy) थी, जहाँ उत्पादन, वितरण और मूल्य निर्धारण के सभी प्रमुख निर्णय केंद्रीय योजना प्राधिकरणों, विशेष रूप से 'गोस्प्लान' (राज्य योजना समिति) द्वारा लिए जाते थे। इसका उद्देश्य तीव्र औद्योगिकीकरण और सामाजिक समानता प्राप्त करना था। प्रारंभ में, इस मॉडल ने भारी उद्योगों, सैन्य प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के विकास में प्रभावशाली सफलताएँ हासिल कीं, जिससे सोवियत संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा। हालाँकि, इस प्रणाली में अंतर्निहित कमजोरियाँ थीं। केंद्रीय योजना की कठोरता नवाचार और उद्यमशीलता को हतोत्साहित करती थी। उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में गंभीर अभाव था, क्योंकि प्राथमिकता हमेशा भारी उद्योग और रक्षा को दी जाती थी। गुणवत्ता नियंत्रण एक सतत समस्या थी, और अर्थव्यवस्था बाजार की माँगों और तकनीकी परिवर्तनों के प्रति अनुकूलन करने में धीमी थी। धीरे-धीरे, इन संरचनात्मक खामियों ने आर्थिक गतिरोध को जन्म दिया, जिससे नागरिकों में असंतोष बढ़ा और अंततः 1980 के दशक के अंत तक यह प्रणाली अस्थिर हो गई।
उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

151. सोवियत आर्थिक प्रणाली में 'गोस्प्लान' की क्या भूमिका थी?
(A) विदेशी व्यापार का प्रबंधन करना
(B) केंद्रीय योजना बनाना और आर्थिक निर्णय लेना
(C) कृषि का सामूहिकीकरण करना
(D) राजनीतिक विरोध का दमन करना

152. स्रोत के अनुसार, सोवियत 'आदेशात्मक अर्थव्यवस्था' की एक प्रमुख कमजोरी क्या थी?
(A) नवाचार और बाजार की माँगों के प्रति अनुकूलन में धीमी गति
(B) भारी उद्योगों के विकास में विफलता
(C) वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरने में असमर्थता
(D) सामाजिक समानता के लक्ष्य को पूरी तरह से त्याग देना

153. निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सोवियत योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त करता था?
(A) उपभोक्ता वस्तुएँ और सेवाएँ
(B) कृषि और खाद्य उत्पादन
(C) भारी उद्योग और रक्षा
(D) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार

154. अनुच्छेद से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सोवियत संघ में आर्थिक गतिरोध का एक मुख्य कारण था:
(A) अत्यधिक विदेशी ऋण।
(B) प्राकृतिक संसाधनों की कमी।

(C) पड़ोसी देशों के साथ निरंतर सैन्य संघर्ष।
(D) केंद्रीय योजना की संरचनात्मक खामियाँ और कठोरता।

155. सोवियत मॉडल ने प्रारंभ में किन क्षेत्रों में सफलता प्रदर्शित की?
(A) केवल उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में
(B) केवल कृषि उत्पादकता में
(C) तीव्र औद्योगिकीकरण और सैन्य क्षमता के निर्माण में
(D) राजनीतिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों में

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
1985 में मिखाइल गोर्बाचेव के सोवियत संघ के कम्युस्ट पार्टी के महासचिव बनने के बाद, उन्होंने देश की बिगड़ती आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए दोहरी नीति की शुरुआत की: 'पेरेस्त्रोइका' (पुनर्रचना) और 'ग्लासनोस्त' (खुलापन)। पेरेस्त्रोइका का उद्देश्य सोवियत अर्थव्यवस्था में सुधार करना था, जिसमें उद्यमों को अधिक स्वायत्तता देना, कुछ हद तक निजी व्यवसाय की अनुमति देना और केंद्रीय योजना के कठोर नियंत्रण में ढील देना शामिल था। इसका लक्ष्य आर्थिक ठहराव को समाप्त कर उत्पादकता को बढ़ाना था। वहीं दूसरी ओर, ग्लासनोस्त एक राजनीतिक सुधार था जिसका उद्देश्य सरकार और समाज में अधिक पारदर्शिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लाना था। इसके तहत, मीडिया पर सेंसरशिप कम की गई, राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया और स्टालिनवादी युग के अत्याचारों पर सार्वजनिक चर्चा की अनुमति दी गई। गोर्बाचेव का मानना था कि आर्थिक सुधारों की सफलता के लिए राजनीतिक खुलापन आवश्यक है। हालाँकि, इन सुधारों के अनपेक्षित परिणाम हुए। ग्लासनोस्त ने दशकों से दमित राष्ट्रवादी भावनाओं को उजागर कर दिया, जिससे विभिन्न गणराज्यों में स्वतंत्रता आंदोलनों को बल मिला। पेरेस्त्रोइका आर्थिक समस्याओं को तुरंत हल करने में विफल रहा, जिससे वस्तुओं की कमी और बढ़ गई और लोगों में निराशा फैल गई। इस प्रकार, जो सुधार सोवियत संघ को बचाने के लिए शुरू किए गए थे, उन्होंने अनजाने में उसके विघटन की प्रक्रिया को तेज कर दिया।
उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

156. मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा शुरु की गई 'पेरेस्त्रोइका' की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था?
(A) सोवियत संघ में बहुदलीय प्रणाली स्थापित करना
(B) अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन और उसमें सुधार करना
(C) सोवियत संघ का सैन्यीकरण करना
(D) वारसॉ संधि को मजबूत करना

157. 'ग्लासनोस्त' की नीति के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया गया?
(A) केंद्रीय योजना को और अधिक कठोर बनाना
(B) मीडिया पर सेंसरशिप बढ़ाना
(C) निजी संपत्ति को पूरी तरह से समाप्त करना
(D) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पारदर्शिता को बढ़ावा देना

158. स्रोत के अनुसार, गोर्बाचेव के सुधारों का एक अनपेक्षित परिणाम क्या था?
(A) राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार और स्वतंत्रता आंदोलनों को बल मिलना
(B) सोवियत अर्थव्यवस्था का तत्काल पुनरुद्धार
(C) कम्युनिस्ट पार्टी पर लोगों का विश्वास बढ़ना
(D) संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों में पूर्ण अलगाव

159. गोर्बाचेव का यह क्यों मानना था कि आर्थिक सुधारों के लिए राजनीतिक खुलापन आवश्यक है?
(A) क्योंकि वे पश्चिमी देशों को प्रभावित करना चाहते थे।
(B) क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथियों ने इसकी माँग की थी।
(C) क्योंकि उनका मानना था कि पारदर्शिता और चर्चा से आर्थिक सुधारों को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकता है।
(D) क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र की एक शर्त थी।

160. अनुच्छेद का केंद्रीय तर्क यह है कि गोर्बाचेव के सुधार...
(A) एक विरोधाभासी प्रभाव रखते थे, जिससे अनजाने में विघटन तेज हो गया।
(B) सोवियत संघ को बचाने में पूरी तरह सफल रहे।
(C) केवल आर्थिक क्षेत्र तक सीमित थे।
(D) सोवियत नागरिकों द्वारा पूरी तरह से अस्वीकार कर दिए गए थे।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
सोवियत संघ के विघटन के बाद, रूस और कई पूर्वी यूरोपीय देशों ने साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के लिए एक कट्टरपंथी आर्थिक कार्यक्रम अपनाया, जिसे 'शॉक थेरेपी' के नाम से जाना गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक जैसे पश्चिमी वित्तीय संस्थानों द्वारा समर्थित, इस मॉडल का आधार यह विश्वास था कि एक धीमी, क्रमिक संक्रमण प्रक्रिया विफल हो जाएगी। इसलिए, एक तीव्र और व्यापक परिवर्तन आवश्यक माना गया। 'शॉक थेरेपी' के तहत, राज्य-नियंत्रित अर्थव्यवस्था की लगभग सभी संरचनाओं को समाप्त करने का प्रयास किया गया। इसमें राज्य की संपत्ति का बड़े पैमाने पर निजीकरण, मूल्य नियंत्रण को हटाना, व्यापार बाधाओं को समाप्त करना और सरकारी सब्सिडी को खत्म करना शामिल था। इसका उद्देश्य एक झटके में बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना था। हालाँकि, इसके सामाजिक और आर्थिक परिणाम विनाशकारी थे। रूस में, औद्योगिक उत्पादन लगभग ध्वस्त हो गया, जिससे "इतिहास की सबसे बड़ी गैराज-सेल" की स्थिति उत्पन्न हुई, जहाँ मूल्यवान औद्योगिक उद्यमों को औने-पौने दामों पर बेच दिया गया। मुद्रास्फीति आसमान छू गई, जिससे आम नागरिकों की बचत का सफाया हो गया। पुरानी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के ढहने से गरीबी और असमानता में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई और एक नए 'ओलिगार्क' (कुलीनतंत्र) वर्ग का उदय हुआ, जिसने अपार संपत्ति और राजनीतिक शक्ति हासिल कर ली।
उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर

दीजिए।

161. 'शॉक थेरेपी' की अवधारणा का मूल आधार क्या था?
(A) साम्यवाद से पूंजीवाद में एक धीमा और क्रमिक संक्रमण
(B) अर्थव्यवस्था पर राज्य के नियंत्रण को मजबूत करना
(C) पश्चिमी देशों के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को समाप्त करना
(D) एक तीव्र, झटके के साथ बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण

162. स्रोत में "इतिहास की सबसे बड़ी गैराज-सेल" वाक्यांश का उपयोग किस संदर्भ में किया गया है?
(A) पुराने सैन्य उपकरणों की बिक्री के लिए
(B) मूल्यवान राज्य के औद्योगिक उद्यमों की औने-पौने दामों पर बिक्री के लिए
(C) सामूहिक खेतों को किसानों को सौंपने के लिए
(D) उपभोक्ता वस्तुओं के लिए नए शॉपिंग मॉल खोलने के लिए

163. 'शॉक थेरेपी' को लागू करने में किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई?
(A) संयुक्त राष्ट्र और यूनिसेफ
(B) विश्व स्वास्थ्य संगठन और रेड क्रॉस
(C) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक
(D) नाटो और वारसॉ संधि

164. निम्नलिखित में से कौन सा 'शॉक थेरेपी' का एक विनाशकारी सामाजिक परिणाम था?
(A) पूर्ण रोजगार की उपलब्धि
(B) सभी के लिए समान धन का वितरण
(C) औद्योगिक उत्पादन में भारी वृद्धि
(D) गरीबी, असमानता में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा का पतन

165. 'शॉक थेरेपी' के परिणामस्वरूप रूस में किस नए शक्तिशाली वर्ग का उदय हुआ?
(A) 'ओलिगार्क' नामक एक धनी कुलीनतंत्र का
(B) एक मजबूत श्रमिक संघ का
(C) छोटे किसानों के एक संगठन का
(D) बुद्धिजीवियों और शिक्षाविदों के एक समूह का

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
सोवियत संघ के विघटन में राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार एक निर्णायक और अंतिम कारक साबित हुआ। यह विडंबना ही है कि शीत युद्ध के दौरान कई पश्चिमी विश्लेषकों का मानना था कि राष्ट्रवादी उभार मध्य एशिया के मुस्लिम गणराज्यों में सबसे मजबूत होगा, जो धार्मिक और जातीय रूप से रूस से भिन्न थे। हालाँकि, वास्तविकता इसके विपरीत थी। राष्ट्रवादी असंतोष की सबसे मजबूत लहर यूरोपीय और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्यों- बाल्टिक राज्यों (एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया), यूक्रेन, जॉर्जिया और स्वयं रूस में उठी। इन गणराज्यों के लोगों को यह महसूस होने लगा था कि वे सोवियत संघ के कम विकसित, विशेष रूप से मध्य एशियाई, क्षेत्रों को बनाए रखने के लिए एक भारी आर्थिक कीमत चुका रहे हैं। उन्हें लगा कि उनका केंद्रीयकृत सोवियत प्रणाली द्वारा दमन किया रहा है और वे अपनी राष्ट्रीय पहचान और राजनीतिक संप्रभुता को पुनः प्राप्त करना चाहते थे। बाल्टिक राज्यों ने स्वतंत्रता की घोषणा करने में सबसे पहले पहल की। अंततः, दिसंबर 1991 में रूस, यूक्रेन और बेलारूस के नेताओं ने स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल (CIS) का गठन करके सोवियत संघ को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया, जिसने विघटन पर अंतिम मुहर लगा दी।
उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

166. सोवियत संघ के विघटन का सबसे तात्कालिक और निर्णायक कारण क्या था?
(A) आर्थिक मंदी
(B) राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार
(C) बाहरी सैन्य दबाव
(D) अफगानिस्तान में सैन्य विफलता

167. स्रोत के अनुसार, शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी विश्लेषकों की क्या धारणा थी जो गलत साबित हुई?
(A) कि सोवियत संघ कभी नहीं टूटेगा।
(B) कि राष्ट्रवादी उभार मध्य एशियाई गणराज्यों में सबसे मजबूत होगा।
(C) कि गोर्बाचेव के सुधार सफल होंगे।
(D) कि सोवियत अर्थव्यवस्था पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं से आगे निकल जाएगी।

168. किन गणराज्यों में राष्ट्रवादी असंतोष सबसे प्रबल रूप से उभरा?
(A) यूरोपीय और समृद्ध गणराज्यों जैसे बाल्टिक राज्यों और यूक्रेन में
(B) केवल मध्य एशियाई गणराज्यों में
(C) केवल साइबेरियाई क्षेत्रों में
(D) केवल उन गणराज्यों में जिनकी सीमा चीन से लगती थी

169. समृद्ध गणराज्यों के लोगों को यह क्यों महसूस हुआ कि वे आर्थिक कीमत चुका रहे हैं?
(A) क्योंकि उन्हें अपनी सारी संपत्ति सेना पर खर्च करनी पड़ रही थी।
(B) क्योंकि उन्हें पश्चिमी देशों को भारी कर देना पड़ता था।
(C) क्योंकि उन्हें लगा कि वे संघ के कम विकसित क्षेत्रों का समर्थन कर रहे हैं।
(D) क्योंकि उनके प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो गए थे।

170. दिसंबर 1991 में किन तीन गणराज्यों ने स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल (CIS) का गठन कर सोवियत संघ को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया?
(A) एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया

(B) कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान
(C) जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान
(D) रुस, यूक्रेन, बेलारुस

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

सोवियत संघ के पतन ने शीत युद्ध की द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था को समाप्त कर दिया और एकध्रुवीय विश्व के उदय का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा। इस नए युग में, शक्ति-संतुलन नाटकीय रूप से अमेरिका के पक्ष में झुक गया। राजनीतिक और सैन्य रुप से, अमेरिका का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं रहा, जिससे उसे वैश्विक मामलों में अभूतपूर्व प्रभाव और हस्तक्षेप की क्षमता मिली। आर्थिक रुप से, पूंजीवादी मॉडल को सार्वभौमिक विजय के रूप में देखा गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं, जो अमेरिकी प्रभाव में थीं, पूर्व साम्यवादी देशों में आर्थिक परिवर्तन को निर्देशित करने वाली प्रमुख सलाहकार बन गईं। उन्होंने ऋण और सहायता के बदले में उदारवादी आर्थिक सुधारों (शॉक थेरेपी) को बढ़ावा दिया। वैचारिक रुप से, उदारवादी लोकतंत्र को शासन का एकमात्र वैध रुप माना जाने लगा, जिसे कुछ विश्लेषकों ने 'इतिहास का अंत' (End of History) कहा। इस एकध्रुवीय क्षण ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति को बदल दिया। जहाँ एक ओर इसने महाशक्तियों के बीच परमाणु युद्ध के खतरे को कम किया, वहीं दूसरी ओर इसने अमेरिका को अपनी नीतियों को लागू करने के लिए अधिक स्वतंत्रता प्रदान की, जिसे कभी-कभी बहुपक्षीय संस्थानों की अवहेलना करके भी अंजाम दिया गया।

उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

171. सोवियत संघ के पतन का विश्व राजनीति पर सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था?
(A) एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय
(B) संयुक्त राष्ट्र का विघटन
(C) एकध्रुवीय विश्व का उदय, जिसमें अमेरिका एकमात्र महाशक्ति था
(D) चीन का एकमात्र महाशक्ति के रुप में उभरना

172. 'इतिहास का अंत' की अवधारणा किस विचार को संदर्भित करती है?
(A) कि सभी ऐतिहासिक संघर्ष समाप्त हो गए हैं
(B) कि उदारवादी लोकतंत्र शासन के अंतिम और सार्वभौमिक रुप के रुप में विजयी हुआ है
(C) कि दुनिया का अंत निकट है
(D) कि इतिहास का अध्ययन अब प्रासंगिक नहीं रहा

173. सोवियत संघ के पतन के बाद विश्व बैंक और आईएमएफ की भूमिका कैसे बढ़ी?
(A) उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर नियंत्रण कर लिया।
(B) उन्होंने वैश्विक स्तर पर साम्यवादी सिद्धांतों को बढ़ावा दिया।
(C) उन्होंने सभी विकासशील देशों को बिना शर्त ऋण प्रदान किया।
(D) वे पूर्व साम्यवादी देशों में पूंजीवादी संक्रमण को निर्देशित करने वाले प्रमुख सलाहकार बन गए।

174. अनुच्छेद के अनुसार, एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था का एक नकारात्मक पहलू क्या हो सकता है?
(A) अमेरिका द्वारा अपनी नीतियों को लागू करने के लिए बहुपक्षीय संस्थानों की अवहेलना
(B) महाशक्तियों के बीच परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ना
(C) वैश्विक व्यापार में कमी आना
(D) लोकतांत्रिक मूल्यों का पूरी तरह पतन

175. एकध्रुवीय व्यवस्था में संयुक्त राज्य अमेरिका को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त हुई?
(A) केवल आर्थिक शक्ति
(B) केवल सैन्य शक्ति
(C) राजनीतिक, सैन्य, और वैचारिक क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रभाव
(D) केवल सांस्कृतिक प्रभाव

ANSWERS

1. (B) शीतयुद्ध का
बर्लिन की दीवार को शीतयुद्ध का प्रमुख प्रतीक माना जाता था। यह दीवार 1961 में बनाई गई थी और इसने बर्लिन शहर को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया था। इसका गिरना न केवल जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि इसने सोवियत खेमे के अंत और शीतयुद्ध की समाप्ति की शुरुआत को भी स्पष्ट रूप से दर्शाया।

2. (A) 1917 की समाजवादी क्रांति
समाजवादी सोवियत गणराज्य 1917 की रुसी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया था। यह क्रांति पूँजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और पूरी तरह से समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरुरत से प्रेरित थी। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के आधार पर रचने का सबसे बड़ा प्रयास था।

3. (C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
सोवियत राजनीतिक प्रणाली में कम्युनिस्ट पार्टी का केंद्रीय स्थान था और किसी अन्य दल या विपक्ष के लिए कोई राजनीतिक जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से राज्य द्वारा नियोजित और नियंत्रित थी। सोवियत व्यवस्था में पार्टी की संस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, जिससे यह प्रणाली समय के साथ अत्यधिक सत्तावादी और अलोकतांत्रिक हो गई थी।

4. (D) पूर्वी यूरोप के समाजवादी खेमे के देश
दूसरी दुनिया का शब्द उन देशों के लिए उपयोग किया जाता था जो पूर्वी यूरोप में स्थित थे और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के नियंत्रण में आए थे। इन देशों में समाजवादी और साम्यवादी शासन व्यवस्था लागू की गई थी। इनका राजनीतिक और आर्थिक ढाँचा सोवियत संघ की तर्ज पर बनाया गया था, जिसे सामूहिक रूप से समाजवादी खेमा भी कहा जाता था।

5. (B) केवल 1, 2 और 3
सोवियत प्रणाली समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी और पूँजीवाद के विरोध में खड़ी थी। इसमें निजी संपत्ति की व्यवस्था को समाप्त कर राजकीय स्वामित्व पर बल दिया गया था। अर्थव्यवस्था पूरी तरह राज्य के नियंत्रण में और योजनाबद्ध थी। हालांकि, इस व्यवस्था में नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी और वे अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों के माध्यम से अपना विरोध व्यक्त करते थे।

6. (B) उपभोक्ता उद्योग उन्नत और पश्चिमी देशों से बेहतर था।
सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में एक विशाल संचार प्रणाली और ऊर्जा संसाधनों की प्रचुरता थी। यद्यपि इसने पिन से लेकर कार तक सभी वस्तुओं का उत्पादन किया, लेकिन इसका उपभोक्ता उद्योग पश्चिमी देशों की तुलना में काफी पीछे था। गुणवत्ता के मामले में सोवियत निर्मित वस्तुएँ पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थीं, जिसके कारण धीरे-धीरे वहां आर्थिक संकट गहराने लगा।

7. (D) कम्युनिस्ट पार्टी
सोवियत राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली में कम्युनिस्ट पार्टी ही मुख्य नियंत्रक संस्था थी। यह पार्टी पूरे देश के शासन और अर्थव्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण रखती थी। सोवियत संघ में कोई अन्य राजनीतिक दल मौजूद नहीं था, और यह पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। इस एकदलीय शासन व्यवस्था के कारण सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण हुआ, जिसने अंततः सोवियत व्यवस्था को कमजोर किया।

8. (A) P-2, Q-3, R-4, S-1
व्लादिमीर लेनिन ने 1917 की रुसी क्रांति का नेतृत्व किया था। जोजेफ स्टालिन ने खेती के बलपूर्वक सामूहिकीकरण की नीति अपनाई थी। निकिता ख्रुश्चेव ने पश्चिमी देशों के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सुझाव दिया था और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की स्थिति मजबूत की थी। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत प्रणाली में सुधार लाने के लिए पेरेस्त्रोइका और ग्लासनोस्त जैसी प्रसिद्ध नीतियों की शुरुआत की थी।

9. (C) 1979
सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में अपना सैन्य हस्तक्षेप किया था। इस घटना के कारण सोवियत व्यवस्था पर भारी आर्थिक दबाव पड़ा और उसकी सैन्य शक्ति में कमजोरी आई। इस हस्तक्षेप के बाद सोवियत संघ की अंतरराष्ट्रीय छवि खराब हुई और देश के भीतर भी संसाधनों की कमी महसूस की जाने लगी। इस युद्ध ने सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुँचाया था।

10. (A) 1980 के दशक के मध्य में
मिखाइल गोर्बाचेव को 1980 के दशक के मध्य में, विशेष रूप से 1985 में, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव चुना गया था। उन्होंने सोवियत व्यवस्था को आधुनिक बनाने और पश्चिम के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए सुधारों की आवश्यकता महसूस की थी। उनके कार्यकाल के दौरान शुरु किए गए आर्थिक और राजनीतिक सुधारों ने अंततः सोवियत संघ के भीतर राष्ट्रवादी भावनाओं को उभारा और विघटन को गति दी।

11. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ को पश्चिमी देशों की तकनीकी और सूचना क्रांति के बराबर लाने के लिए आर्थिक-राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण की नीति अपनाई थी।

1980 के दशक में पश्चिम में हो रही प्रगति की तुलना में सोवियत व्यवस्था पिछड़ रही थी। इन सुधारों का उद्देश्य प्रशासनिक ढांचे को लचीला बनाना और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना था ताकि व्यवस्था को मजबूत किया जा सके।

12. (B) उन्होंने अतीत की तरह कोई हस्तक्षेप नहीं किया।
पूर्वी यूरोप के देशों में सोवियत नियंत्रण के विरुद्ध जब प्रदर्शन हुए, तो मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ की पारंपरिक सैन्य हस्तक्षेप की नीति का त्याग किया। उन्होंने इन देशों में चल रहे जन-विद्रोहों को कुचलने के लिए सेना नहीं भेजी। उनकी इस उदारवादी और अहिंसक नीति के कारण ही पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक-एक करके गिर गईं, जिससे अंततः शीतयुद्ध का दौर समाप्त हो गया।

13. (C) बोरिस येल्तसिन
1991 में सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी के गरमपंथियों द्वारा किए गए तख्तापलट का विरोध करने में बोरिस येल्तसिन ने केंद्रीय भूमिका निभाई थी। उन्होंने जनता के बीच जाकर इस विद्रोह को विफल करने का आह्वान किया और एक नायक के रूप में उभरे। इस घटना के बाद सत्ता गोर्बाचेव के हाथों से फिसलकर येल्तसिन और उनके समर्थित राज्यों के पास चली गई, जिससे विघटन की प्रक्रिया तेज हुई।

14. (B) 2, 4, 1, 3
सोवियत इतिहास की प्रमुख घटनाओं का क्रम रूसी क्रांति से शुरू होता है। इसके बाद 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप किया, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1989 में बर्लिन की दीवार का गिरना शीतयुद्ध के अंत का एक महत्वपूर्ण संकेत था। अंततः 1991 में सोवियत संघ का आधिकारिक रूप से विघटन हो गया और विश्व राजनीति का स्वरूप बदल गया।

15. (A) रूस, यूक्रेन और बेलारूस
दिसंबर 1991 में बोरिस येल्तसिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के तीन सबसे शक्तिशाली गणराज्यों—रूस, यूक्रेन और बेलारूस—ने सोवियत संघ की समाप्ति की औपचारिक घोषणा की। इन देशों ने साम्यवाद को त्यागकर पूँजीवाद और लोकतंत्र को अपनाने का निर्णय लिया। इस घोषणा के साथ ही स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का गठन हुआ और सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में रूस को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली।

16. (B) रूस
सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को उसके उत्तराधिकारी राज्य के रूप में वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया गया। रूस ने ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की स्थायी सीट हासिल की और पूर्ववर्ती सोवियत संघ द्वारा की गई सभी अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों को निभाने की जिम्मेदारी ली। वह सोवियत परमाणु हथियारों का एकमात्र मालिक बना और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सोवियत संघ की जगह ली।

17. (C) केवल 1, 2, 3 और 5
सोवियत संघ का विघटन आंतरिक कमजोरियों और राजनीतिक-आर्थिक संस्थाओं की विफलता का परिणाम था। लंबे समय तक अर्थव्यवस्था में आए ठहराव के कारण उपभोक्ता वस्तुओं की भारी कमी हो गई थी। संघ ने अपने संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा सैन्य शक्ति बढ़ाने और अंतरिक्ष अनुसंधान पर खर्च किया। अंततः रूस और बाल्टिक क्षेत्रों में उभरी राष्ट्रवादी और संप्रभुता की तीव्र भावनाओं ने विघटन को अपरिहार्य बना दिया।

18. (A) 70 वर्ष
सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने लगभग 70 वर्षों तक निरंतर शासन किया। 1917 की रूसी क्रांति के बाद से लेकर 1991 में इसके विघटन तक, यह पार्टी राजनीतिक शक्ति की मुख्य धुरी बनी रही। इस लंबी अवधि के दौरान पार्टी का शासन अलोकतांत्रिक और सत्तावादी हो गया था, जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रही। अंततः व्यवस्था की अंदरूनी कमजोरियों ने इसका अंत किया।

19. (C) मध्य-पूर्व में नए संकटों का उदय।
सोवियत संघ के विघटन के कारण शीतयुद्ध के लंबे दौर के संघर्ष की समाप्ति हुई और विश्व राजनीति के शक्ति संबंधों में बुनियादी बदलाव आए। इसके फलस्वरूप कई नए स्वतंत्र देशों का उदय हुआ और एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था की शुरुआत हुई। हालांकि, मध्य-पूर्व में संकटों का उदय सोवियत विघटन का सीधा परिणाम नहीं था, बल्कि वहां की जटिलताएं विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीतिक कारणों से पहले से विद्यमान थीं।

20. (A) P-4, Q-1, R-2, S-3
सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव के महासचिव बनने के साथ हुई थी। बर्लिन की दीवार का गिरना 1989 की एक युगांतकारी घटना थी जिसने साम्यवाद के अंत की घोषणा की। लिथुआनिया ने 1990 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बनकर इतिहास रचा। अंततः 1991 में सोवियत संघ का पूर्ण विघटन हुआ, जिससे द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अंत हो गया।

21. (C) विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
पूर्व सोवियत देशों में अपनाई गई शॉक थेरेपी का मॉडल विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा निर्देशित था। इस मॉडल का उद्देश्य साम्यवादी अर्थव्यवस्थाओं को पूरी तरह से पूँजीवादी व्यवस्था में बदलना था। इसके अंतर्गत राज्य की संपत्तियों का निजीकरण और मुक्त व्यापार जैसी नीतियों पर जोर दिया गया, जिससे इन देशों के आर्थिक और सामाजिक ढांचे में बड़ा परिवर्तन हुआ।

22. (B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
शॉक थेरेपी ने पूर्व सोवियत संघ के देशों की अर्थव्यवस्थाओं को गहराई से प्रभावित किया और उन्हें लगभग तहस-नहस कर

दिया। इस मॉडल की मुख्य धारणा यह थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व ही हो सकता है। यद्यपि निजीकरण का उद्देश्य विकास लाना था, लेकिन व्यावहारिक रूप से इसने भारी मुद्रास्फीति और आर्थिक विषमता को जन्म दिया। ये दोनों तथ्य सही हैं, लेकिन कारण कथन नहीं है।

23. (D) रूसी उद्योगों को औने-पौने दामों में बेचा जाना
शॉक थेरेपी के कारण रूस में औद्योगिक ढांचा पूरी तरह चरमरा गया, जिसे 'इतिहास की सबसे बड़ी गराज-सेल' कहा जाता है। इस प्रक्रिया में रूस के लगभग 90 प्रतिशत सरकारी उद्योगों को निजी कंपनियों या व्यक्तियों को औने-पौने दामों पर बेच दिया गया। चूंकि औद्योगिक संपत्तियों का मूल्य बहुत कम आँका गया था, इसलिए आम नागरिकों को दिए गए अधिकार पत्रों को उन्होंने अपनी जरूरतों के लिए बेच दिया।

24. (A) केवल 1 और 4
शॉक थेरेपी के परिणामों ने रूसी समाज और अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। इसके कारण रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में भारी गिरावट आई, जिससे लोगों की जमा पूँजी और बचत पूरी तरह खत्म हो गई। साथ ही, इसने समाज में अमीर और गरीब के बीच एक बहुत ही गहरी खाई पैदा कर दी। पुरानी समाज कल्याण व्यवस्था के नष्ट होने से बड़ी आबादी गरीबी में आ गई और विषमता बढ़ी।

25. (C) तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान
मध्य एशियाई देशों में तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं के अभाव का लाभ उठाते हुए अपने कार्यकाल को पहले दस वर्षों के लिए और फिर अगले दस वर्षों के लिए बढ़ा दिया। इन देशों में राष्ट्रपति के पास असीमित शक्तियां केंद्रित हो गईं और उन्होंने विपक्ष के प्रति बहुत ही कठोर रवैया अपनाया। इस प्रवृत्ति ने इन गणराज्यों में लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास को बुरी तरह बाधित किया।

26. (A) चेचन्या और दागिस्तान
रूस के दो गणराज्यों, चेचन्या और दागिस्तान में, सोवियत संघ के विघटन के बाद लंबे समय तक हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। इन क्षेत्रों में रूस से अलग होने की मांग को लेकर विद्रोहियों और रूसी सेना के बीच भारी संघर्ष हुआ। रूस द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन और विद्रोहियों द्वारा की गई बमबारी की घटनाओं ने इन क्षेत्रों को काफी समय तक अशांत रखा। सैन्य बल से इस पर नियंत्रण पाया गया।

27. (D) चेक और स्लोवाक गणराज्य
चेकोस्लोवाकिया का विभाजन सोवियत संघ के पतन के बाद हुए शांतिपूर्ण विभाजनों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह देश दो स्वतंत्र भागों—चेक और स्लोवाक गणराज्यों—में बिना किसी हिंसा या बड़े विवाद के विभाजित हो गया। जहां एक ओर युगोस्लाविया जैसे देशों में विभाजन के कारण भयानक जातीय संघर्ष और गृहयुद्ध हुए, वहीं चेकोस्लोवाकिया के नेताओं ने आपसी सहमति से अलग होने का रास्ता चुनकर राजनीतिक परिपक्वता दिखाई।

28. (B) भारत सोवियत संघ द्वारा बनाए गए सैन्य गठबंधन 'वारसा संधि' का सदस्य था।
शीतयुद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के बीच संबंध बहुत मजबूत थे। सोवियत संघ ने भारत के प्रमुख इस्पात कारखानों की स्थापना और कश्मीर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हमेशा समर्थन दिया। हालांकि, यह कहना गलत है कि भारत वारसा संधि का सदस्य था। भारत ने हमेशा गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया और किसी भी सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनने से पूरी तरह इनकार किया।

29. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
भारत ने पूर्व साम्यवादी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं, लेकिन रूस के साथ उसके संबंध ऐतिहासिक रूप से सबसे गहरे और भरोसेमंद रहे हैं। दोनों देशों का एक साझा सपना 'बहुध्रुवीय विश्व' व्यवस्था का है, जहां अंतरराष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियों का अस्तित्व हो। वे सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं को मजबूत करने और संप्रभुता के सम्मान पर बल देते हैं।

30. (D) 80
भारत और रूस के बीच 2001 में एक महत्वपूर्ण सामरिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसके तहत लगभग 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया गया। यह समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा और आतंकवाद विरोधी सहयोग जैसे विविध क्षेत्रों में साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले गया। इस विस्तृत समझौते ने भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे भरोसे को मजबूत किया।

31. (A) 1, 2, 3, 4
सोवियत संघ के विघटन के घटनाक्रम की शुरुआत 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव के महासचिव बनने से हुई। इसके बाद जून 1991 में बोरिस येल्तसिन रूस के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, जो सत्ता के केंद्र के रूप में उभरे। दिसंबर 1991 में रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने सोवियत संघ की समाप्ति की औपचारिक घोषणा की। अंततः, 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया।

32. (B) उपरोक्त सभी।
रूस के लिए भारत एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक साझेदार है, क्योंकि भारत रूसी हथियारों का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए भी रूस से तेल और प्राकृतिक गैस का आयात करता है, जो रूस की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, भारत और रूस अंतरिक्ष अभियानों और परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में एक-दूसरे का निरंतर तकनीकी सहयोग करते हैं।

33. (B) चुटकुलों और कार्टूनों का
सोवियत प्रणाली में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी का अभाव था, जिसके कारण नागरिकों के पास सीधे तौर पर अपनी असहमति व्यक्त करने के अवसर सीमित थे। वे अपनी शिकायतों और व्यवस्था के प्रति गुस्से को व्यक्त करने के लिए अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों जैसे रचनात्मक माध्यमों का

सहारा लेते थे। ये चुटकुले नौकरशाही के भ्रष्टाचार और सरकारी विफलता पर व्यंग्य करते थे, जो आम जनता की दबी भावनाएं थी।

34. (D) उपरोक्त सभी 1, 2, 3, 4 और 5
सोवियत संघ के विघटन के पीछे कई गहरे प्रशासनिक और राजनीतिक कारण थे। कम्युनिस्ट पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रही थी और शासन का स्वरूप अत्यधिक केंद्रीकृत हो गया था। सरकारी अधिकारियों को मिलने वाले विशेषाधिकारों ने आम नागरिकों में असंतोष पैदा किया। इसके साथ ही, रूस और बाल्टिक क्षेत्रों में उभरी राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की तीव्र इच्छा ने इस विशाल संघ को टूटने की ओर धकेल दिया।

35. (C) एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया
एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को सामूहिक रुप से बाल्टिक गणराज्य कहा जाता है क्योंकि ये बाल्टिक सागर के तट पर स्थित हैं। इन देशों ने सोवियत संघ के विघटन की प्रक्रिया में अग्रणी भूमिका निभाई थी। लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला गणराज्य था। इन तीनों देशों ने सोवियत संघ से अलग होने के बाद जल्द ही संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ली और नाटो जैसे संगठनों में शामिल हुए।

36. (B) P-2, Q-4, R-3, S-1
शॉक थेरेपी का अर्थ आघात पहुँचाकर उपचार करना है, जो साम्यवाद से पूँजीवाद की ओर संक्रमण की एक प्रक्रिया थी। दूसरी दुनिया उन देशों को कहा जाता था जो समाजवादी खेमे का हिस्सा थे। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का गठन सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्व गणराज्यों के बीच समन्वय के लिए किया गया था। वारसा संधि सोवियत खेमे का एक सैन्य गठबंधन था जिसे नाटो के जवाब में बनाया गया था।

37. (C) पूँजीवादी अर्थव्यवस्था
सोवियत संघ के पतन और साम्यवाद की विफलता के बाद, पूँजीवादी अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे शक्तिशाली और प्रभुत्वशाली व्यवस्था बन गई। पश्चिमी देशों का आर्थिक मॉडल वैश्विक मानक के रुप में उभरा और विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं आर्थिक नीतियों की मार्गदर्शक बन गईं। उदारवादी लोकतंत्र और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को विकास का एकमात्र विश्वसनीय मार्ग माना जाने लगा, जिससे पूरी दुनिया बदल गई।

38. (C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
रूस के भीतर चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले, जहां विद्रोहियों ने रूस से अलग होने के लिए सशस्त्र संघर्ष किया। सोवियत संघ के विघटन के दौरान राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार सबसे अधिक रूस, बाल्टिक गणराज्यों और यूक्रेन में देखा गया, न कि मध्य एशियाई गणराज्यों में। मध्य एशियाई गणराज्य शुरुआत में सोवियत संघ के साथ ही बने रहना चाहते थे, वे रूस से धार्मिक रुप से भिन्न थे।

39. (D) मिखाइल गोर्बाचेव
मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ की पिछड़ती अर्थव्यवस्था और जर्जर राजनीतिक व्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए पेरेस्त्रोइका और ग्लासनोस्त की नीतियां शुरू की थीं। इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य सोवियत समाज का लोकतंत्रीकरण करना और प्रशासनिक ढांचे में पारदर्शिता लाना था। हालांकि, गोर्बाचेव की इन सुधारवादी कोशिशों ने अनजाने में राष्ट्रवादी भावनाओं को तीव्र कर दिया और ऐसी ताकतों को सक्रिय कर दिया, जिससे अंततः विघटन हुआ।

40. (A) भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर राज्य का स्वामित्व था।
सोवियत प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि वहां भूमि और अन्य सभी उत्पादक संपदाओं पर निजी स्वामित्व के बजाय राज्य का पूर्ण नियंत्रण और स्वामित्व था। इस व्यवस्था में निजी संपत्ति की अवधारणा को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था और अर्थव्यवस्था का संचालन राज्य द्वारा नियोजित तरीके से किया जाता था। सोवियत मॉडल संसाधनों के समान वितरण और उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक नियंत्रण पर आधारित था।

41. (A) 1, 2, 3, 4
सोवियत संघ के पतन की घटनाओं का क्रम मिखाइल गोर्बाचेव के महासचिव बनने से शुरु हुआ। 1989 में बर्लिन की दीवार का गिरना साम्यवाद के पतन का स्पष्ट संकेत था। जुलाई 1991 में बोरिस येल्तसिन ने कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिससे पार्टी का दबदबा कमजोर हुआ। अंततः दिसंबर 1991 में रुस, यूक्रेन और बेलारुस ने सोवियत संघ की समाप्ति की औपचारिक घोषणा की। इस प्रकार महाशक्ति का अंत हुआ।

42. (A) बोस्निया-हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया
1991 के बाद युगोस्लाविया के विखंडन के परिणामस्वरूप बोस्निया-हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया जैसे नए देशों का उदय हुआ। यह विखंडन बहुत ही हिंसक और दर्दनाक था क्योंकि वहां विभिन्न जातीय समूहों के बीच भीषण संघर्ष और गृहयुद्ध छिड़ गया था। विशेष रुप से बोस्निया में सर्बों और गैर-सर्बों के बीच हुए संघर्ष ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचा और नाटो को वहां हस्तक्षेप करना पड़ा। यह संघर्ष काफी लंबा चला।

43. (D) मिल्कियत का सबसे प्रभावी रुप निजी स्वामित्व है।
शॉक थेरेपी के मॉडल की सर्वोपरि मान्यता यह थी कि संपत्ति का सबसे प्रभावी रुप केवल निजी स्वामित्व ही हो सकता है। इसीलिए इस मॉडल के तहत राज्य की संपत्तियों के तेजी से निजीकरण और खेती के सामूहिक फार्मों को निजी फार्मों में बदलने पर जोर दिया गया था। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सोवियत काल के ढांचे को खत्म करना और उसकी जगह एक मुक्त बाजार आधारित व्यवस्था स्थापित करना था।

44. (B) निजी 'फार्म'
शॉक थेरेपी के आर्थिक सुधारों के अंतर्गत सोवियत काल के सामूहिक फार्मों की प्रणाली को समाप्त कर उन्हें निजी फार्मों

में बदलने का प्रावधान किया गया था। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वामित्व और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना था ताकि उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सके। हालांकि, इस अचानक हुए बदलाव और सरकारी सहायता की कमी के कारण कृषि क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ और रुस में खाद्यान्न सुरक्षा का संकट पैदा हुआ।

45. (C) मिखाइल गोर्बाचेव
मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे जिन्होंने 1985 से 1991 तक देश का नेतृत्व किया। उन्होंने सोवियत व्यवस्था में सुधार के लिए पेरेस्त्रोइका और ग्लासनोस्त जैसी महत्वपूर्ण नीतियां लागू कीं। उनकी उदारवादी नीतियों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति प्रयासों के कारण शीतयुद्ध का अंत हुआ। 25 दिसंबर 1991 को उनके पद से इस्तीफा देने के साथ ही सोवियत संघ का आधिकारिक रूप से अंत हो गया और रुस उत्तराधिकारी बना।

46. (A) केवल 1 और 4
सोवियत संघ का विघटन अनिवार्य रूप से उसकी आर्थिक गतिहीनता और राजनीतिक विफलता का परिणाम था। लंबे समय तक अर्थव्यवस्था में ठहराव के कारण संसाधनों का अभाव हो गया और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई। इसके साथ ही, मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों ने जनता की दबी हुई आकांक्षाओं को अचानक बाहर आने का मौका दिया। जब लोगों ने महसूस किया कि उनके अधिकार कम हैं, तो असंतोष विद्रोह में बदल गया।

47. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
चेचन्या में सोवियत विघटन के बाद लंबे समय तक हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। ताजिकिस्तान में लगभग दस वर्षों तक भीषण गृहयुद्ध की स्थिति बनी रही, जो 2001 में जाकर समाप्त हुई। युगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया जहां विभिन्न समुदायों के बीच गृहयुद्ध और बगावत देखी गई। इसके विपरीत, चेकोस्लोवाकिया एक ऐसा उदाहरण था जहां चेक और स्लोवाक गणराज्यों के बीच शांतिपूर्ण विभाजन हुआ। ये सभी घटनाएं पतन के बाद की अस्थिरता दर्शाती हैं।

48. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
शीतयुद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन के बाद वैश्विक शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल गया और संयुक्त राज्य अमरीका दुनिया की एकमात्र महाशक्ति बन गया। इस नए दौर में विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं विभिन्न विकासशील और पूर्व साम्यवादी देशों के लिए शक्तिशाली सलाहकार बन गईं। इन संस्थाओं ने इन देशों को पूँजीवादी नीतियों और आर्थिक सुधारों को अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था बदल गई।

49. (B) उपरोक्त सभी
सोवियत संघ के विघटन के बाद भी रुस के साथ भारत के संबंध अत्यंत लाभप्रद बने रहे हैं। रुस ने कश्मीर जैसे संवदेनशील मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हमेशा भारत का पक्ष लिया है। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में रुस भारत को तेल और प्राकृतिक गैस की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, रुस के साथ मजबूत साझेदारी भारत को चीन के साथ अपने क्षेत्रीय संबंधों में संतुलन बनाए रखने में भी काफी मदद करती है।

50. (A) 1991
स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल (सीआईएस) का गठन दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के तुरंत बाद किया गया था। इसकी स्थापना रुस, बेलारुस और यूक्रेन जैसे प्रमुख गणराज्यों द्वारा की गई थी ताकि पूर्व सोवियत देशों के बीच आर्थिक और सामरिक समन्वय बना रहे। बाद में मध्य एशियाई गणराज्य भी इसमें शामिल हो गए। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ के अंत के बाद पैदा हुई राजनीतिक शून्यता को भरना था।

51. (B) केवल 1, 3, 4 और 5
शॉक थेरेपी के कारण रुस का औद्योगिक ढांचा पूरी तरह तबाह हो गया क्योंकि लगभग 90 प्रतिशत उद्योगों को बहुत कम दामों पर निजी हाथों में बेच दिया गया। रुसी मुद्रा रुबल के मूल्य में भारी गिरावट आई और समाज कल्याण की पुरानी सरकारी व्यवस्था नष्ट हो गई। इस प्रक्रिया ने समाज में गहरी आर्थिक विषमताओं और माफिया वर्ग को जन्म दिया। साथ ही, हड़बड़ी में तैयार किए गए संविधानों ने संसद को कमजोर बना दिया।

52. (D) खुलेपन
ग्लासनोस्त का शाब्दिक अर्थ 'खुलापन' है, जिसे मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में राजनीतिक सुधारों के हिस्से के रूप में पेश किया था। इस नीति का उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना और नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करना था ताकि वे व्यवस्था की खामियों पर खुलकर चर्चा कर सकें। गोर्बाचेव का मानना था कि इस खुलेपन से भ्रष्टाचार कम होगा और जनता का विश्वास पुनः प्राप्त किया जा सकेगा, जिससे शासन सुधरेगा।

53. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
सोवियत संघ के यूरोपीय और तुलनात्मक रूप से समृद्ध गणराज्यों जैसे रुस, बाल्टिक क्षेत्र और यूक्रेन में राष्ट्रवादी असंतोष सबसे अधिक देखा गया। इन क्षेत्रों के लोगों में यह प्रबल भाव था कि उन्हें संघ के पिछड़े इलाकों को साथ रखने के लिए बहुत भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ रही है। उन्हें लगा कि संघ का हिस्सा बने रहने से उनकी अपनी प्रगति बाधित हो रही है। इसी कारण इन समृद्ध हिस्सों में स्वतंत्रता की मांग उठी।

54. (B) अर्थव्यवस्था को और अधिक केंद्रीकृत करना
मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत व्यवस्था में सुधार के लिए पश्चिम के साथ संबंधों को सामान्य बनाने और प्रशासनिक ढांचे में ढील देने जैसे कदम उठाए थे। उन्होंने सोवियत संघ को अधिक लोकतांत्रिक रूप देने और पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश की थी। हालांकि, अर्थव्यवस्था को और अधिक केंद्रीकृत करना उनके सुधारों का हिस्सा नहीं था। इसके विपरीत, उन्होंने पेरेस्त्रोइका के माध्यम से अत्यधिक केंद्रीकरण को कम करने और अर्थव्यवस्था में लचीलापन लाने का प्रयास किया था।

55. (D) कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अज़रबैजान
सोवियत संघ के विघटन के बाद उभरे देशों में रुस के अतिरिक्त कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अज़रबैजान तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार वाले प्रमुख उत्पादक देश हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों के कारण इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं में पिछले कुछ दशकों में तेजी से सुधार हुआ है। इन संसाधनों पर नियंत्रण के लिए वैश्विक शक्तियों और अंतरराष्ट्रीय तेल कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। इन देशों की भौगोलिक स्थिति रणनीतिक है।

56. (A) सोवियत संघ का विघटन
लिओनिड ब्रेझनेव सोवियत संघ के एक प्रभावशाली नेता थे जिन्होंने 1964 से 1982 तक शासन किया। उनके कार्यकाल के दौरान एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया गया और चेकोस्लोवाकिया के जन-विद्रोह को सैन्य बल से दबाया गया। उनके शासन के अंत में ही अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण हुआ था। हालांकि, सोवियत संघ का आधिकारिक विघटन 1991 में हुआ, जो उनके निधन के काफी वर्षों बाद की घटना है। अतः वे इससे असंबद्ध थे।

57. (C) वारसा संधि (Warsaw Pact)
सोवियत संघ के नेतृत्व में बनाया गया सैन्य गठबंधन 'वारसा संधि' या वारसा पैक्ट कहलाता था। इसकी स्थापना 1955 में पश्चिमी देशों के सैन्य गठबंधन 'नाटो' के जवाब में की गई थी। इस गठबंधन में पूर्वी यूरोप के समाजवादी देश शामिल थे और इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना था। शीतयुद्ध के दौरान इस संधि ने समाजवादी खेमे की सैन्य शक्ति को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

58. (A) व्लादिमीर लेनिन
1917 की ऐतिहासिक रुसी क्रांति का नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन ने किया था, जो बोल्शेविक पार्टी के संस्थापक और सोवियत संघ के पहले प्रमुख थे। इस क्रांति ने रुस में सदियों पुरानी जारशाही का अंत किया और दुनिया के पहले समाजवादी राज्य की स्थापना की। लेनिन के विचार और उनके द्वारा अपनाई गई नीतियां ही सोवियत संघ के राजनीतिक और आर्थिक ढांचे का मुख्य आधार बनीं। उन्होंने साम्यवादी विचारधारा को वैश्विक स्तर पर प्रसारित किया।

59. (D) 1961
बर्लिन की दीवार का निर्माण 1961 में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन के बीच लोगों की आवाजाही को रोकना था। यह दीवार शीतयुद्ध के चरम पर होने और विश्व के दो विचारधारात्मक गुटों में विभाजित होने का सबसे बड़ा भौतिक प्रतीक थी। लगभग 28 वर्षों तक खड़ी रहने वाली यह दीवार न केवल एक शहर को बल्कि दो अलग-अलग राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों को अलग करती थी। 1989 में इसे तोड़ा गया।

60. (A) P-2, Q-2, R-3, S-1
सोवियत संघ ने भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए भिलाई और बोकारो के इस्पात कारखानों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान की। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने भारत को महत्वपूर्ण सैन्य और राजनयिक सहायता दी थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, सोवियत संघ ने कश्मीर के संवेदनशील मुद्दे पर हमेशा भारत के रुख का पुरजोर समर्थन किया। यह गहरी दोस्ती का प्रमाण है।

61. (C) राष्ट्रवाद और संप्रभुता के भावों का उभार
सोवियत संघ के पतन के कई दीर्घकालिक कारण थे, लेकिन इसका सबसे तात्कालिक कारण रुस और बाल्टिक गणराज्यों में उभरी राष्ट्रवाद और संप्रभुता की तीव्र भावना थी। इन गणराज्यों के लोगों में अपनी अलग पहचान बनाने और सोवियत नियंत्रण से बाहर निकलने की तड़प अचानक बहुत बढ़ गई थी। इस राष्ट्रवादी लहर ने गोर्बाचेव के सुधारों के दौरान मिली छूट का लाभ उठाकर सोवियत संघ के ढांचे को भीतर से हिला दिया और उसे विखंडित कर दिया।

62. (A) केवल 1 और 3
सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह थी कि सरकार अपने नागरिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा और बच्चों की देखभाल जैसी बुनियादी जरूरत की चीजें रियायती दरों पर उपलब्ध कराती थी। इस व्यवस्था में बेरोजगारी लगभग नहीं थी, लेकिन नागरिकों को राजनीतिक आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। सत्ता पर कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार था, जो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। व्यक्तिगत अधिकारों के अभाव ने आम जनता के जीवन को कठिन बनाया।

63. (A) रुसी गणराज्य को
सोवियत संघ के आधिकारिक विघटन के बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र ने सर्वसम्मति से रुसी गणराज्य को सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य के रूप में मान्यता दी। इसके परिणामस्वरूप, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की स्थायी सीट रुस को मिल गई। रुस ने ही पूर्ववर्ती संघ द्वारा की गई अंतरराष्ट्रीय संधियों के पालन की जिम्मेदारी ली। इस प्रकार, रुस ने वैश्विक मंच पर सोवियत संघ की राजनीतिक और राजनयिक विरासत को संभाला।

64. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
1990 के दशक में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता के लिए खुशहाली लाने के अपने वादों में पूरी तरह विफल रही और इसने लोगों के जीवन को और अधिक कठिन बना दिया। इसका मुख्य कारण सामूहिक खेती की पुरानी और सुरक्षित प्रणाली का अचानक समाप्त होना था, जिससे खाद्यान्न सुरक्षा का संकट पैदा हो गया। सरकारी सहायता और सब्सिडी खत्म होने से आम लोग भुखमरी के कगार पर पहुँच गए। इस आर्थिक प्रयोग ने व्यापक उथल-पुथल मचाई।

65. (B) औद्योगीकरण को तेजी से बढ़ावा और खेती का बलपूर्वक सामूहिकीकरण
जोजेफ स्टालिन का शासनकाल सोवियत संघ को एक औद्योगिक महाशक्ति बनाने के प्रयासों के लिए जाना जाता

है। उन्होंने देश में औद्योगीकरण को अत्यधिक गति से बढ़ावा दिया और कृषि क्षेत्र में खेती के बलपूर्वक सामूहिकीकरण की कठोर नीति लागू की। उनके शासन की अन्य प्रमुख विशेषता राजनीतिक विरोधियों का दमन और सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण था। हालांकि उनके नेतृत्व में सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध में विजय प्राप्त की, लेकिन जनता को कष्ट हुआ।

66. (A) 1, 2, 3, 4, 5
सोवियत संघ के अंतिम वर्षों की घटनाओं का सही क्रम मिखाइल गोर्बाचेव के महासचिव बनने से शुरू होता है। इसके बाद 1988 में लिथुआनिया में आजादी के लिए सशक्त जन-आंदोलन की शुरुआत हुई। 1990 के आरंभ में गोर्बाचेव ने सोवियत राजनीति में बहुदलीय व्यवस्था को अनुमति दी। जून 1991 में बोरिस येल्तसिन रूस के राष्ट्रपति बने और उन्होंने सोवियत सत्ता को चुनौती दी। अंततः दिसंबर 1991 में गोर्बाचेव के इस्तीफे के साथ ही सोवियत संघ के इतिहास का अंत हुआ।

67. (C) उपरोक्त सभी
1970 के दशक के उत्तरार्ध में सोवियत व्यवस्था कई मोर्चों पर कमजोर होने लगी थी। प्रौद्योगिकी और उत्पादकता के मामले में यह पश्चिमी देशों से काफी पीछे छूट गई थी, जिससे देश के भीतर उपभोक्ता वस्तुओं की भारी कमी हो गई। इसके अलावा, कृषि क्षेत्र की विफलता के कारण सोवियत संघ को हर साल भारी मात्रा में खाद्यान्न का आयात करना पड़ रहा था। इन आर्थिक समस्याओं के साथ-साथ प्रशासनिक भ्रष्टाचार ने सोवियत व्यवस्था को पूरी तरह से गतिहीन बनाया।

68. (D) पुनर्रचना
पेरेस्त्रोइका का अर्थ 'पुनर्रचना' है, जो मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा सोवियत संघ की ठप पड़ी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को सुधारने के लिए शुरू किया गया एक व्यापक कार्यक्रम था। इसका उद्देश्य सोवियत ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन लाकर उसे अधिक कुशल, प्रतिस्पर्धी और आधुनिक बनाना था। इस नीति के तहत आर्थिक गतिविधियों में कुछ हद तक विकेंद्रीकरण और निजी उद्यमों को प्रोत्साहन देने की कोशिश की गई थी ताकि सोवियत अर्थव्यवस्था को गति मिल सके।

69. (C) लिथुआनिया
लिथुआनिया वह पहला सोवियत गणराज्य था जिसने मार्च 1990 में सोवियत संघ से अपनी पूर्ण स्वतंत्रता की औपचारिक घोषणा की थी। यह बाल्टिक गणराज्य सोवियत शासन के खिलाफ प्रतिरोध का मुख्य केंद्र बन गया था और इसकी साहसी घोषणा ने अन्य गणराज्यों के लिए भी मिसाल पेश की। लिथुआनिया के इस कदम ने सोवियत संघ के नेतृत्व को हिलाकर रख दिया और इसके बाद एक-एक करके अन्य गणराज्यों ने भी अपनी संप्रभुता का दावा करना शुरू कर दिया।

70. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
सोवियत संघ के पतन के बाद, बाल्टिक गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देश अपनी सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि के लिए 'यूरोपीय संघ' और नाटो का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक थे। दूसरी ओर, मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति को समझते हुए एक संतुलित विदेश नीति अपनाई। वे रूस के साथ अपने पुराने संबंधों को बनाए रखने के साथ-साथ अमरीका, चीन और अन्य पश्चिमी देशों के साथ भी मजबूत आर्थिक और सामरिक रिश्ते विकसित करना चाहते थे।

71. (D) द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।
सोवियत संघ के विघटन के कारण अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कई युगांतकारी परिवर्तन हुए, जिनमें हथियारों की होड़ की समाप्ति और विचारधारात्मक संघर्ष का अंत प्रमुख था। इसके परिणामस्वरूप द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो गई और एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ, जिसमें संयुक्त राज्य अमरीका का वर्चस्व स्थापित हुआ। इसलिए, यह कहना कि द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था सुदृढ़ हुई, पूरी तरह गलत है क्योंकि सोवियत संघ के अंत के साथ ही संरचना बिखर गई थी।

72. (B) P-2, Q-4, R-1, S-3
बोरिस येल्तसिन रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने जिन्होंने सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का नेतृत्व किया। लिओनिड ब्रेझनेव ने एशिया के लिए सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का प्रस्ताव दिया था और अपने लंबे शासनकाल में सैन्य शक्ति पर जोर दिया। निकिता ख्रुश्चेव के समय में ही प्रसिद्ध क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था जिसने दुनिया को परमाणु युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया था। व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जिन्होंने सोवियत संघ की नींव रखी थी।

73. (C) निजीकरण की प्रक्रिया और आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण
रूस में माफिया वर्ग का उदय मुख्य रूप से शॉक थेरेपी के तहत शुरू की गई निजीकरण की जल्दबाज प्रक्रिया का परिणाम था। सरकारी उद्योगों और संसाधनों के निजी हाथों में जाने के दौरान कानून-व्यवस्था और नियामक संस्थाओं की कमजोरी का लाभ उठाकर ताकतवर समूहों ने आर्थिक गतिविधियों पर अपना अवैध नियंत्रण स्थापित कर लिया। इन समूहों ने संसाधनों की लूट के माध्यम से भारी धन अर्जित किया। लोकतांत्रिक संस्थाओं के अभाव में इस वर्ग ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया।

74. (A) केवल 1, 2 और 3
सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं में सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी देना और बेरोजगारी का पूरी तरह अभाव होना शामिल था। उत्पादन के सभी प्रमुख साधनों पर राज्य का स्वामित्व था, जो समाज में समानता लाने का प्रयास करता था। हालांकि, यह व्यवस्था उपभोक्ता उद्योगों के मामले में पिछड़ी हुई थी और नागरिकों को बुनियादी राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। इन आंतरिक विरोधाभासों ने, जहां एक ओर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की, वहीं नवाचार को अवरुद्ध किया।

75. (D) मध्य एशिया
11 सितंबर 2001 को हुए आतंकी हमलों के बाद, अमरीका ने अफगानिस्तान और इराक में अपनी सैन्य कार्रवाइयों को

सुविधाजनक बनाने के लिए मध्य एशिया के देशों में सैनिक ठिकाने बनाना चाहा। अमरीका ने इन गणराज्यों की सरकारों को बड़ी मात्रा में धन दिया और उनसे अपने विमानों को वहां से उड़ान भरने की अनुमति मांगी। मध्य एशिया की रणनीतिक स्थिति और वहां के विशाल ऊर्जा संसाधनों ने भी अमरीका को इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए काफी आकर्षित किया।

76. (B) ताजिकिस्तान
पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य ताजिकिस्तान में 1991 के बाद एक भीषण और लंबा गृहयुद्ध चला जो लगभग दस वर्षों तक यानी 2001 तक जारी रहा। यह संघर्ष विभिन्न क्षेत्रीय और धार्मिक समूहों के बीच सत्ता पर नियंत्रण को लेकर हुआ था। इस युद्ध के कारण देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो गई और हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ताजिकिस्तान की यह अशांति उस व्यापक अस्थिरता का हिस्सा थी जो विघटन के बाद कई क्षेत्रों में सुरक्षा शून्यता के कारण पैदा हुई।

77. (C) भारत ने सोवियत संघ की विदेश नीति का अप्रत्यक्ष समर्थन किया।
शीतयुद्ध के दौरान भारत ने आधिकारिक रूप से गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी, लेकिन कई मौकों पर उसने सोवियत संघ की विदेश नीति का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया। भारत ने सोवियत संघ के साथ 1971 में एक महत्वपूर्ण मित्रता संधि की थी, जो संकट के समय सुरक्षा की गारंटी प्रदान करती थी। हालांकि भारत ने खुले तौर पर किसी सैन्य गठबंधन में शामिल होने से इनकार किया, लेकिन सोवियत संघ के साथ गहरे संबंधों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोनों देशों को काफी करीब ला दिया था।

78. (D) अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियों का मौजूद होना।
'बहुध्रुवीय विश्व' से रूस और भारत का स्पष्ट आशय अंतरराष्ट्रीय फलक पर कई शक्तिशाली देशों और संगठनों की मौजूदगी से है, ताकि दुनिया किसी एक महाशक्ति के पूर्ण वर्चस्व के अधीन न रहे। इस व्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय विवादों का समाधान आपसी बातचीत और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। बहुध्रुवीयता का अर्थ यह भी है कि प्रत्येक देश की संप्रभुता का सम्मान हो और वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में अधिक लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, जिससे शांति बनी रहे।

79. (B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
भारत और रूस के बीच संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझा रणनीतिक हितों पर आधारित रहा है, जो दशकों से अडिग बना हुआ है। भारत आज भी रूस के लिए हथियारों का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है और रूस ने तेल संकट के समय हमेशा भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद की है। यद्यपि ये दोनों तथ्य सही हैं, लेकिन केवल व्यापारिक और सैन्य सौदे ही इस गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध की पूरी व्याख्या नहीं करते, यह बहुआयामी है।

80. (A) अज़रबैजान, अर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान
'अनिर्धारित सीमा' शब्द का प्रयोग अक्सर अज़रबैजान, अर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान जैसे क्षेत्रों के बीच उत्पन्न सीमा विवादों को दर्शाने के लिए किया जाता है। सोवियत संघ के विघटन के बाद, इन नए स्वतंत्र गणराज्यों के बीच सीमाओं का सीमांकन स्पष्ट नहीं था, जिससे कई जातीय संघर्ष और युद्ध हुए। नागोर्नो-काराबाख जैसे क्षेत्रों को लेकर अर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच दशकों से चला आ रहा विवाद इसी विवादित सीमाओं का परिणाम है, जिसने शांति और स्थिरता को खतरे में डाला।

81. (B) 150 किलोमीटर से ज्यादा
बर्लिन की दीवार की लंबाई 150 किलोमीटर से भी अधिक थी और यह 28 वर्षों तक शीतयुद्ध के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में खड़ी रही। इस विशाल दीवार ने बर्लिन शहर को दो विचारधारात्मक गुटों में विभाजित कर दिया था, जहां एक ओर पूँजीवादी पश्चिम बर्लिन था और दूसरी ओर साम्यवादी पूर्वी बर्लिन। 1989 में आम जनता द्वारा इस दीवार को तोड़ा जाना एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसने न केवल जर्मनी के पुनर्मिलन की राह खोली बल्कि पूरे साम्यवादी शासन के पतन की शुरुआत की।

82. (A) 1, 3, 2, 4
सोवियत संघ के पतन के बाद की घटनाओं का क्रम युगोस्लाविया के विखंडन और वहां शुरू हुए हिंसक संघर्षों से शुरू होता है। इसके तुरंत बाद 1991 में बाल्टिक गणराज्य—एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया—संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्ण सदस्य बन गए। 1993 में जॉर्जिया भी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में शामिल हो गया। अंततः 2004 में इन बाल्टिक गणराज्यों ने पश्चिमी सैन्य गठबंधन नाटो की सदस्यता ग्रहण की, जो इस क्षेत्र के भू-राजनीतिक परिदृश्य में सोवियत प्रभाव के समाप्त होने का संकेत था।

83. (C) शीतयुद्ध के संघर्ष की समाप्ति
दूसरी दुनिया यानी सोवियत खेमे के पतन का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक परिणाम शीतयुद्ध के लंबे दौर के संघर्ष की समाप्ति था। इससे न केवल हथियारों की होड़ रुकी बल्कि वह विचारधारात्मक विवाद भी खत्म हो गया कि समाजवादी प्रणाली बेहतर है या पूँजीवादी। इस पतन के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संबंधों का स्वरूप बदल गया, जिससे एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हुआ और उदारवादी लोकतंत्र को शासन की सबसे प्रभावी पद्धति के रूप में वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली।

84. (D) मुक्त व्यापार की नीति
शॉक थेरेपी के आर्थिक मॉडल के अंतर्गत व्यापार के क्षेत्र में मुक्त व्यापार की नीति को अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पूर्व साम्यवादी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक बाजार से जोड़ना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना था। इसके तहत मुद्राओं की परिवर्तनीयता और आयात-निर्यात पर से सरकारी नियंत्रण हटाने पर जोर दिया गया। यह माना गया कि पश्चिमी देशों के साथ सीधा व्यापारिक जुड़ाव

ही पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्थाओं में नई जान फूंकने का एकमात्र उपाय है।

85. (D) उपरोक्त सभी
सोवियत संघ के विघटन के पीछे कई प्रमुख कारण उत्तरदायी थे, जिनमें कम्युनिस्ट पार्टी का 70 वर्षों का निरंकुश शासन और प्रशासन में पारदर्शिता की कमी मुख्य थी। गोर्बाचेव द्वारा शुरू किए गए सुधारों की गति जनता की तीव्र आकांक्षाओं की तुलना में बहुत धीमी थी, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ा। इसके साथ ही, जब नागरिकों को यह अहसास हुआ कि सोवियत राजव्यवस्था पश्चिम के पूँजीवाद से बेहतर होने के दावों में खोखली है, तो व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास पूरी तरह टूट गया।

86. (B) लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी का न होना
सोवियत प्रणाली की जिस एक प्रमुख विशेषता ने नागरिकों का जीवन सबसे अधिक कठिन बना दिया था, वह वहां लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी का पूरी तरह अभाव था। यद्यपि सरकार बुनियादी सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती थी, लेकिन लोग अपनी राय रखने या सरकार की आलोचना करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। भ्रष्टाचार और नौकरशाही के बढ़ते शिकंजे ने आम जनता की आवाज को दबा दिया था। अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए उन्हें चुटकुलों और कार्टूनों का सहारा लेना पड़ता था।

87. (C) P-3, Q-2, R-4, S-1
नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र में स्थानीय अर्मेनियाई लोगों ने अज़रबैजान से अलग होने के लिए एक लंबा अलगाववादी आंदोलन चलाया है। जॉर्जिया में दो प्रमुख प्रांत अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, जिसके कारण वहां भीषण गृहयुद्ध की स्थिति बनी हुई है। यूक्रेन में भी समय-समय पर मौजूदा शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए बड़े पैमाने पर जन-आंदोलन और प्रदर्शन होते रहे हैं। बेलारूस सोवियत संघ के विघटन के बाद बने स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का एक संस्थापक सदस्य रहा है।

88. (A) जोजेफ स्टालिन
जोजेफ स्टालिन को 1930 के दशक के उस भयानक आतंक और दमन के लिए जिम्मेदार माना जाता है, जिसमें लाखों लोगों को पार्टी और सरकार के प्रति वफादारी न दिखाने के संदेह में मार दिया गया या निर्वासित कर दिया गया। उनके शासनकाल में राजनीतिक विरोधियों का सफाया करने के लिए क्रूर नीतियां अपनाई गईं। स्टालिन ने सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण किया और समाज के हर पहलू पर राज्य का कड़ा नियंत्रण स्थापित किया। यद्यपि उन्होंने औद्योगीकरण किया, लेकिन इसकी मानवीय कीमत बहुत अधिक और विनाशकारी थी।

89. (B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
सोवियत संघ ने शीतयुद्ध के दौरान हथियारों की होड़ में संयुक्त राज्य अमरीका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन सैन्य शक्ति पर अत्यधिक खर्च करने के कारण उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो गई। संसाधनों का बड़ा हिस्सा सेना और अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर लगाने से आम जनता की बुनियादी जरूरतों की अनदेखी हुई। यद्यपि सोवियत व्यवस्था नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रही, लेकिन यह विफलता सैन्य खर्च के बोझ के साथ-साथ प्रशासनिक भ्रष्टाचार का भी संयुक्त परिणाम थी।

90. (A) खनिज, तेल, प्राकृतिक गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात
2000 के दशक में रूस के आर्थिक पुनर्जीवन और स्थिरता का सबसे प्रमुख कारण उसके विशाल प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और धातुओं का बड़े पैमाने पर निर्यात था। वैश्विक बाजार में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों ने रूस की अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक दी और उसे एक बार फिर वैश्विक मंच पर एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में स्थापित किया। इसके साथ ही, तेल और गैस की पाइपलाइनों के लिए पारगमन शुल्क से भी रूस और उसके पड़ोसी देशों को काफी आर्थिक लाभ हुआ।

91. (D) मध्य एशियाई गणराज्यों
दिसंबर 1991 में सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का गठन मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए बहुत आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित था। ये गणराज्य, रूस और बाल्टिक देशों के विपरीत, सोवियत संघ से अलग होने के लिए सक्रिय रूप से आंदोलन नहीं कर रहे थे और संघ का हिस्सा बने रहना चाहते थे। उन्हें डर था कि स्वतंत्रता के बाद उनकी आर्थिक स्थिति और सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। हालांकि, बाद में उन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बनाकर व्यवस्था में शामिल किया गया।

92. (B) राष्ट्रपति अत्यधिक शक्तिशाली हो गए और संसद कमजोर संस्था बन गई।
शॉक थेरेपी के बाद रूस और कई मध्य एशियाई देशों में जिस प्रकार के संविधान बनाए गए, उनमें राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बनाकर उन्हें असीमित और व्यापक अधिकार दिए गए। इसके परिणामस्वरूप, इन देशों में राष्ट्रपति अत्यधिक शक्तिशाली हो गए और संसद जैसी लोकतांत्रिक संस्थाएं बहुत कमजोर और प्रभावहीन बनकर रह गईं। उदाहरण के लिए, तुर्कमेनिस्तान में राष्ट्रपतियों ने अपने कार्यकाल को मनमाने ढंग से बढ़ाया और विपक्ष को कुचल दिया। इस केंद्रीकृत सत्ता ने लोकतंत्र की स्थापना में बाधा डाली।

93. (C) इंदिरा गांधी
1971 में पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव और बांग्लादेश संकट के दौरान, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भारत और सोवियत संघ के बीच ऐतिहासिक 20-वर्षीय मित्रता और शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि ने भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत सामरिक सुरक्षा कवच प्रदान किया और पाकिस्तान के खिलाफ सोवियत संघ की सैन्य और कूटनीतिक सहायता सुनिश्चित की। यह संधि भारत की विदेश नीति का एक निर्णायक मोड़ थी, जिसने क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को भारत के पक्ष में मोड़ने में मदद की।

94. (D) 15
सोवियत संघ कुल 15 अलग-अलग गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया एक विशाल संघ था, जिसमें रूस सबसे बड़ा और प्रभावशाली गणराज्य था। इन गणराज्यों की अपनी सांस्कृतिक और भाषाई विविधता थी, लेकिन राजनीतिक रूप से ये सभी मॉस्को स्थित कम्युनिस्ट पार्टी के कड़े नियंत्रण में थे। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, ये सभी 15 गणराज्य स्वतंत्र देशों के रूप में उभरे। इस विशाल संघ के टूटने से दुनिया का राजनीतिक मानचित्र बदल गया और एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का अंत हुआ जिसने 20वीं सदी को प्रभावित किया।

95. (C) केवल 1, 2, 3 और 4
सोवियत संघ के पतन ने विश्व राजनीति में बुनियादी बदलाव लाए, जिससे शीतयुद्ध के विचारधारात्मक संघर्ष का अंत हुआ और एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में प्रभुत्वशाली बन गई और उदारवादी लोकतंत्र को राजनीतिक जीवन को व्यवस्थित करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में स्वीकार किया गया। इसके साथ ही, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं की वैश्विक भूमिका बढ़ गई, क्योंकि वे अब पूर्व साम्यवादी देशों के आर्थिक संक्रमण की मुख्य मार्गदर्शक बन गई थीं।

96. (B) राष्ट्रीयता की भावना और तड़प का जारी रहना
सोवियत संघ के पतन को इतिहास की एक अनिवार्यता के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि विभिन्न गणराज्यों के भीतर दबी हुई राष्ट्रीयता की भावना और संप्रभुता की तीव्र तड़प को लंबे समय तक दबाकर रखना संभव नहीं था। गोर्बाचेव के सुधारों ने इस भावना को केवल अभिव्यक्ति का रास्ता दिया, जो पहले से ही व्यवस्था के भीतर मौजूद थी। रूस और बाल्टिक गणराज्यों में उभरा यह राष्ट्रवाद इतना शक्तिशाली था कि उसने सोवियत संघ के ढांचे और कम्युनिस्ट विचारधारा के बंधनों को पूरी तरह तोड़ दिया, जिससे विघटन हुआ।

97. (C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग काफी व्यापक और विकसित था, जो पिन से लेकर बड़ी कारों तक लगभग हर आवश्यक वस्तु का उत्पादन स्वयं करता था। हालांकि, यह भी एक कड़वी सच्चाई थी कि सोवियत कारखानों में बनने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता पश्चिमी देशों के उत्पादों के स्तर की नहीं थी। गुणवत्ता के इस बड़े अंतर और उत्पादकता में कमी के कारण सोवियत नागरिकों में धीरे-धीरे असंतोष पनपने लगा। अंततः, तकनीकी पिछड़ापन सोवियत अर्थव्यवस्था के पतन और उसके लड़खड़ाने का एक प्रमुख कारण बनी।

98. (A) P-4, Q-1, R-2, S-3
व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जिन्होंने 1917 की क्रांति का नेतृत्व किया। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे जिनके कार्यकाल में संघ का विघटन हुआ। बोरिस येल्तसिन रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने जिन्होंने सोवियत सत्ता को चुनौती दी। जोजेफ स्टालिन को लेनिन का उत्तराधिकारी माना जाता है जिन्होंने सोवियत संघ को एक औद्योगिक और सैन्य महाशक्ति बनाने के लिए कठोर नीतियां लागू की थीं। इन नेताओं ने सोवियत इतिहास के विभिन्न चरणों को प्रभावित किया।

99. (C) क्यूबा का मिसाइल संकट
निकिता ख्रुश्चेव 1962 के उस प्रसिद्ध क्यूबा मिसाइल संकट में मुख्य रूप से शामिल थे, जिसने शीतयुद्ध के दौरान दुनिया को परमाणु महायुद्ध के अत्यंत करीब ला खड़ा किया था। उन्होंने अमरीका के पास स्थित क्यूबा में सोवियत परमाणु मिसाइलें तैनात करने का साहसिक निर्णय लिया था, जिसका अमरीका ने कड़ा विरोध किया। ख्रुश्चेव को स्टालिन की क्रूर नीतियों की आलोचना करने और सोवियत संघ में कुछ सुधार लागू करने के लिए भी याद किया जाता है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के प्रयासों ने तनाव को कम करने में मदद की।

100. (D) रूस
भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में रूस ने एक अत्यंत विश्वसनीय साझेदार की भूमिका निभाई है और विशेष रूप से क्रायोजेनिक रॉकेट तकनीक प्रदान करने में भारत की महत्वपूर्ण मदद की है। जब पश्चिमी देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाए थे और यह तकनीक देने से इनकार कर दिया था, तब रूस ने भारत का साथ दिया। यह तकनीकी सहयोग भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में आत्मनिर्भर बनाने और भारी उपग्रहों को लॉन्च करने की क्षमता विकसित करने में निर्णायक साबित हुआ। यह साझेदारी रणनीतिक भरोसे का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

101. (C) रूस
सोवियत संघ के विघटन के समय परमाणु हथियार कई गणराज्यों जैसे यूक्रेन, बेलारूस और कज़ाकिस्तान में भी तैनात थे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत यह तय किया गया कि रूस ही सोवियत संघ का एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न उत्तराधिकारी राज्य होगा। अन्य सभी गणराज्यों ने स्वेच्छा से अपने परमाणु हथियार रूस को सौंप दिए और स्वयं को परमाणु मुक्त राष्ट्र घोषित किया। इस प्रक्रिया ने रूस को वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में सोवियत संघ की सामरिक विरासत और जिम्मेदारी प्रदान की, जिससे वह महाशक्ति बना रहा।

102. (A) 1, 2, 3, 4
सोवियत संघ के पतन के घटनाक्रम की शुरुआत 1989 में बर्लिन की दीवार गिरने से हुई, जो साम्यवाद के पतन का वैश्विक प्रतीक बन गई। इसके बाद फरवरी 1990 में सोवियत संघ ने अपनी 72 साल पुरानी एकदलीय व्यवस्था को त्यागकर बहुदलीय राजनीति को अपनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इसके तुरंत बाद विभिन्न गणराज्यों की संसदों ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणाएं करना शुरु कर दिया। अंततः अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के गरमपंथियों द्वारा किया गया असफल तख्तापलट विघटन का कारण बना।

103. (D) वे मानते थे कि गोर्बाचेव बहुत जल्दबाजी दिखा रहे थे और उनके विशेषाधिकार कम हो रहे थे।
मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा शुरु किए गए सुधारों के प्रति कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर और व्यवस्था से लाभान्वित होने वाले अधिकारियों में काफी नाराजगी और विरोध था। उनका मानना

था कि गोर्बाचेव बहुत अधिक जल्दबाजी दिखा रहे थे और उनके द्वारा लाए जा रहे बदलावों से पार्टी की पकड़ ढीली हो रही थी और उनके पारंपरिक विशेषाधिकार छिन रहे थे। इस असंतोष ने पार्टी के भीतर एक गहरा विभाजन पैदा कर दिया, जहां एक ओर कट्टरपंथी इन सुधारों को रोकना चाहते थे, वहीं दूसरी ओर जनता को ये सुधार बहुत धीमे लग रहे थे।

104. (A) सोवियत संघ
भारत की आजादी के बाद औद्योगिक आधार को मजबूत करने के लिए सोवियत संघ ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी कंपनियों की स्थापना में महत्वपूर्ण आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान की। उस समय जब पश्चिमी देश भारत को भारी उद्योगों के लिए तकनीक देने में संकोच कर रहे थे, सोवियत संघ ने भिलाई और बोकारो के इस्पात संयंत्रों सहित ऊर्जा और मशीनरी निर्माण के क्षेत्र में भारत का भरपूर सहयोग किया। यह सहायता न केवल औद्योगिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि रणनीतिक साझेदारी की नींव भी थी।

105. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
शॉक थेरेपी के दौरान आर्थिक सुधारों को इतनी हड़बड़ी में लागू किया गया कि इस प्रक्रिया में लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण और कानूनी ढांचे को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। इसी प्रशासनिक और विधिक शून्यता के कारण एक शक्तिशाली 'माफिया वर्ग' का उदय हुआ, जिसने कौड़ियों के भाव बिक रहे सरकारी उद्योगों और संसाधनों पर अपना अवैध नियंत्रण कर लिया। चूंकि बाजार को नियंत्रित करने वाली निष्पक्ष संस्थाएं मौजूद नहीं थीं, इसलिए इस वर्ग ने पूरी अर्थव्यवस्था को अपने हितों के अनुसार संचालित किया।

106. (D) उपरोक्त सभी
सोवियत राजनीतिक प्रणाली समाजवाद के आदर्शों और एक समतामूलक समाज के निर्माण के महान लक्ष्य से प्रेरित थी, लेकिन व्यवहार में इसमें 'पार्टी की संस्था' को राज्य के सभी अंगों से ऊपर प्राथमिकता दी गई। पूरी अर्थव्यवस्था राज्य के कड़े नियंत्रण और नियोजन में थी, जहां निजी संपत्ति के लिए कोई स्थान नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस एकदलीय व्यवस्था में किसी भी प्रकार के राजनीतिक विपक्ष या स्वतंत्र मत के लिए कोई जगह नहीं थी। इन विशेषताओं ने व्यवस्था को अत्यधिक सत्तावादी और अलोकतांत्रिक बना दिया।

107. (D) ईश्वर और धर्म पर राज्य का नियंत्रण
सोवियत संघ में प्रचलित यह चुटकुला उस व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य करता है जहां राज्य ने न केवल संसाधनों पर बल्कि ईश्वर और धर्म पर भी अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की थी। यह इस सोच को दर्शाता है कि यदि सब कुछ राज्य के नियंत्रण में होगा, तो प्राकृतिक चीजें भी सरकारी आदेशों और नौकरशाही की अकुशलता की भेंट चढ़ जाएंगी। यह चुटकुला सोवियत नागरिकों की उस छिपी हुई हताशा को प्रकट करता है जो वे हर चीज के सरकारीकरण और व्यक्तिगत विश्वासों पर राज्य के हस्तक्षेप के कारण महसूस कर रहे थे।

108. (B) युगोस्लाविया
बाल्कन क्षेत्र का महत्वपूर्ण देश युगोस्लाविया 1991 के बाद गंभीर आंतरिक जातीय संघर्षों के कारण कई स्वतंत्र प्रांतों में टूट गया। यह विखंडन अत्यंत हिंसक था, जहां सर्ब, क्रोएट और बोस्नियाई समुदायों के बीच भीषण गृहयुद्ध छिड़ गया। स्लोवेनिया और क्रोएशिया जैसे गणराज्यों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, जिसका केंद्रीय नेतृत्व ने विरोध किया। इस गृहयुद्ध ने यूरोप के इस हिस्से में बड़े पैमाने पर मानवीय संकट पैदा किया और हजारों लोगों के विस्थापन और मौत का कारण बना, जिसने अंततः इस बहुजातीय संघ को समाप्त कर दिया।

109. (C) बहुध्रुवीय विश्व
सोवियत संघ के पतन और शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद, भारत और रूस ने वैश्विक राजनीति के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित किया जिसे 'बहुध्रुवीय विश्व' कहा जाता है। दोनों देशों का मानना है कि दुनिया में किसी एक महाशक्ति का वर्चस्व नहीं होना चाहिए, बल्कि कई महत्वपूर्ण शक्तियां मौजूद होनी चाहिए जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करें। यह दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान, संयुक्त राष्ट्र की मजबूती और सभी देशों की संप्रभुता के सम्मान पर आधारित है, जिससे वैश्विक स्तर पर संतुलन बना रहे।

110. (D) निकिता ख्रुश्चेव
निकिता ख्रुश्चेव ने 1956 में कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस के दौरान एक 'गुप्त भाषण' में जोजेफ स्टालिन की तानाशाही नेतृत्व-शैली और उनके द्वारा किए गए दमन की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने सोवियत व्यवस्था में 'वि-स्टालिनीकरण' की प्रक्रिया शुरु की और कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार लागू किए। ख्रुश्चेव ने पश्चिम के साथ 'शांतिपूर्ण सहअस्तित्व' की नीति अपनाई और सोवियत संघ के भीतर अभिव्यक्ति की थोड़ी अधिक स्वतंत्रता देने का प्रयास किया, हालांकि वे व्यवस्था के बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सके।

111. (A) लोकतांत्रिक पूँजीवादी व्यवस्था
सोवियत संघ के विघटन के बाद, पूर्ववर्ती गणराज्यों में दशकों पुरानी साम्यवादी व्यवस्था को त्यागकर 'लोकतांत्रिक पूँजीवादी व्यवस्था' स्थापित करने का व्यापक प्रयास किया गया। इस परिवर्तन को 'शॉक थेरेपी' के माध्यम से लागू करने की कोशिश की गई, जिसका उद्देश्य राज्य-नियंत्रित अर्थव्यवस्था को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में बदलना था। हालांकि, यह संक्रमण बहुत कठिन साबित हुआ, क्योंकि कई देशों में लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत नहीं हो सकीं और आर्थिक विषमताएं तेजी से बढ़ीं। फिर भी, पश्चिमी उदारवादी मॉडल को ही विकास का एकमात्र विकल्प माना गया।

112. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
व्लादिमीर लेनिन ने 1917 से 1924 तक सोवियत संघ के प्रारंभिक और क्रांतिकारी दौर का नेतृत्व किया। जोजेफ स्टालिन

का लंबा शासनकाल 1924 से 1953 तक रहा, जिसमें उन्होंने सोवियत संघ को एक औद्योगिक शक्ति बनाया। मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में महासचिव बने और 1991 तक पद पर रहे, उनके सुधारों ने अंततः विघटन का मार्ग प्रशस्त किया। बोरिस येल्तसिन ने 1991 से 1999 तक रूस के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और साम्यवाद के बाद रूस के आर्थिक संक्रमण के दौर का नेतृत्व किया। यह कालक्रम सोवियत इतिहास का मुख्य आधार है।

113. (C) केवल 1, 2, 3 और 4
दूसरी दुनिया के विघटन के कारण अंतरराष्ट्रीय राजनीति में युगांतकारी परिवर्तन हुए, जिनमें शीतयुद्ध के लंबे विचारधारात्मक और सैन्य संघर्ष की समाप्ति सबसे प्रमुख थी। संयुक्त राज्य अमरीका दुनिया की एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा और विश्व राजनीति एकध्रुवीय हो गई। इस प्रक्रिया में सोवियत संघ से अलग होकर कई नए स्वतंत्र देशों का जन्म हुआ, जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। साथ ही, उदारवादी लोकतंत्र को शासन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति के रूप में वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली, जिससे साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव तेजी से कम हुआ।

114. (A) कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गरमपंथियों ने
मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा शुरू किए गए सुधारों का सबसे तीव्र विरोध कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर मौजूद कट्टरपंथी या गरमपंथियों ने किया था। इन नेताओं और अधिकारियों को डर था कि गोर्बाचेव के सुधारों से पार्टी की सत्ता पर पकड़ कमजोर हो जाएगी और सदियों से चले आ रहे उनके विशेषाधिकार समाप्त हो जाएंगे। इसी विरोध के परिणामस्वरूप अगस्त 1991 में इन कट्टरपंथियों ने एक असफल तख्तापलट की कोशिश की थी। यद्यपि यह विद्रोह विफल रहा, लेकिन इसने सोवियत संघ के भीतर चल रही गहरी राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष को पूरी तरह उजागर कर दिया।

115. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
सोवियत संघ के विघटन के दौरान, मध्य एशियाई गणराज्यों ने बाल्टिक राज्यों या रूस की तरह तुरंत स्वतंत्रता की मांग नहीं की थी। इसका मुख्य कारण उनका आर्थिक रूप से पिछड़ा होना और संघ पर उनकी अत्यधिक निर्भरता थी। इन गणराज्यों के नेताओं को यह भय सता रहा था कि सोवियत संघ से अलग होने के बाद वे अपने संसाधनों का प्रबंधन और सुरक्षा स्वयं नहीं कर पाएंगे, इसलिए वे संघ के भीतर ही बने रहने के पक्षधर थे। इसी कारण जब रूस ने संघ की समाप्ति की घोषणा की, तो यह मध्य एशिया के लिए काफी चौंकाने वाला था।

116. (D) राज कपूर
भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता राज कपूर का नाम रूस और पूर्व सोवियत संघ के सभी गणराज्यों में आज भी घर-घर में अत्यंत सम्मान और प्यार के साथ लिया जाता है। उनकी फिल्में जैसे 'आवारा' और 'श्री 420' वहां इतनी लोकप्रिय हुईं कि उनके गीतों को आज भी रूसी लोग गुनगुनाते हैं। राज कपूर ने अपनी कला के माध्यम से भारत और सोवियत संघ के बीच सांस्कृतिक सेतु का काम किया और आम जनता के स्तर पर भारत की एक बहुत ही सकारात्मक छवि बनाई। यह लगाव आज भी दोनों देशों के लोगों के बीच भावनात्मक जुड़ाव का एक आधार है।

117. (C) पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का तहस-नहस होना
शॉक थेरेपी की सबसे बड़ी और तात्कालिक परिणति पूरे सोवियत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से तहस-नहस हो जाना था। जिस खुशहाली का वादा किया गया था, उसके विपरीत औद्योगिक उत्पादन में भारी गिरावट आई और सरकारी सब्सिडी खत्म होने से लाखों लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए। मुद्रास्फीति इतनी अधिक बढ़ गई कि लोगों की जीवन भर की जमा पूँजी और बचत की कीमत कौड़ियों के बराबर रह गई। इस आर्थिक प्रयोग ने रूस जैसे देशों को एक गहरे संकट में धकेल दिया, जिससे उबरने में उन्हें कई दशक लग गए और भारी असंतोष पैदा हुआ।

118. (B) दीवार का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के तुरंत बाद हुआ था।
बर्लिन की दीवार को पूँजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। यह दीवार लगभग 28 वर्षों तक खड़ी रही और इसे अंततः 1989 में जन-आंदोलन के द्वारा तोड़ा गया। हालांकि, यह कहना गलत है कि इस दीवार का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद हुआ था। वास्तव में, इस दीवार का निर्माण 1961 में किया गया था, जब शीतयुद्ध अपने चरम पर पहुँच गया था। युद्ध के बाद बर्लिन का विभाजन तो हो गया था, लेकिन भौतिक रूप से दीवार खड़ी करने का निर्णय बहुत बाद में लिया गया था।

119. (D) ताजिकिस्तान - दस साल का गृहयुद्ध
सोवियत संघ के पतन के बाद ताजिकिस्तान में दस वर्षों तक भीषण गृहयुद्ध चला, जो वहां की राजनीतिक स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुआ। यह गृहयुद्ध 2001 में जाकर समाप्त हुआ और इसने देश के सामाजिक ढांचे को काफी नुकसान पहुँचाया। इसके विपरीत, चेचन्या में अलगाववादी आंदोलन अत्यंत हिंसक था, जबकि चेकोस्लोवाकिया का विभाजन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। युगोस्लाविया में हुआ विखंडन भी भयानक जातीय संघर्षों और गृहयुद्ध का गवाह बना। अतः केवल ताजिकिस्तान के गृहयुद्ध की प्रकृति का मिलान सटीक और सही है।

120. (A) भारतीय लेखकों और कलाकारों की सोवियत संघ की यात्रा
भारत और सोवियत संघ के बीच सांस्कृतिक संबंधों की गहराई का सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय लेखकों और कलाकारों की नियमित रूप से सोवियत संघ की यात्राएं और वहां उनका भव्य स्वागत होना था। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान के कार्यक्रमों ने आम जनता को एक-दूसरे की परंपराओं और जीवनशैली को समझने का अवसर दिया। सोवियत संघ में भारतीय फिल्मों, संगीत और साहित्य के प्रति जो जबरदस्त दीवानगी देखी गई, उसने दोनों देशों के बीच एक

मजबूत भावनात्मक रिश्ता कायम किया। यह जुड़ाव किसी भी राजनीतिक संधि से अधिक स्थायी था।

121. (A) 1, 2, 3, 4
सोवियत संघ के शीर्ष नेताओं का सही कालानुक्रम जोजेफ स्टालिन से शुरु होता है, जिन्होंने लेनिन के बाद सत्ता संभाली। उनके बाद निकिता ख्रुश्चेव ने नेतृत्व किया और स्टालिन की नीतियों की आलोचना की। 1960 के दशक के मध्य में लिओनिड ब्रेझनेव सत्ता में आए और उन्होंने लंबे समय तक शासन किया। अंततः 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव महासचिव बने, जिनके सुधारों के दौरान सोवियत संघ का विघटन हुआ। इन नेताओं के अलग-अलग दृष्टिकोणों ने सोवियत संघ के उदय, विस्तार, ठहराव और अंततः उसके पतन की कहानी को ऐतिहासिक आकार प्रदान किया।

122. (A) रूस
सोवियत संघ भले ही 15 गणराज्यों का एक संघ था, लेकिन वास्तविकता में रूस का ही हर मामले में पूर्ण प्रभुत्व और दबदबा बना हुआ था। सोवियत संघ की अधिकांश महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक संस्थाएं रूस में ही केंद्रित थीं और निर्णयों में रुसी नेताओं की ही मुख्य भूमिका रहती थी। इसके कारण अन्य गणराज्यों के लोगों के भीतर अक्सर यह भाव पैदा होता था कि उनकी अपनी संस्कृति की उपेक्षा की जा रही है। रूस का यह वर्चस्व सोवियत संघ की अंदरूनी दरारों का एक बड़ा कारण बना, जिसने अंततः विघटन के दौरान राष्ट्रवादी विरोध को हवा दी।

123. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा शुरु किए गए सुधारों ने सोवियत जनता के भीतर दबी हुई आकांक्षाओं का एक ऐसा शक्तिशाली ज्वार पैदा किया, जिसका अंदाजा स्वयं गोर्बाचेव या पार्टी के नेताओं को नहीं था। जनता के एक बड़े हिस्से को लगता था कि गोर्बाचेव बहुत धीरे चल रहे हैं और उन्हें और भी अधिक क्रांतिकारी और तेज कदम उठाने चाहिए। वहीं दूसरी ओर, कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथी सदस्य यह मान रहे थे कि गोर्बाचेव बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं और उनकी नीतियां सोवियत व्यवस्था को ही नष्ट कर रही हैं। इस दोहरे दबाव ने उनकी स्थिति को कमजोर किया।

124. (B) उदारवादी लोकतंत्र
सोवियत संघ के विघटन और साम्यवादी विचारधारा की विफलता के बाद, उदारवादी लोकतंत्र को राजनीतिक जीवन को व्यवस्थित करने की दुनिया की सबसे श्रेष्ठ धारणा के रूप में वैश्विक मान्यता मिली। यह माना गया कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ही विकास और मानवाधिकारों की सुरक्षा का एकमात्र विश्वसनीय मार्ग है। इस बदलाव ने पूरी दुनिया के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया और कई पूर्व साम्यवादी देशों ने अपनी पुरानी व्यवस्था को त्यागकर बहुदलीय चुनाव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित इसी उदारवादी मॉडल को अपनाया।

125. (C) केवल 1, 2 और 3
भारत और रूस के बीच संबंध अत्यंत गहरे और सामरिक महत्व के हैं, जहां भारत रूसी हथियारों का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग की शैशवावस्था में तकनीकी मदद की है और दोनों देश आज भी कई जटिल वैज्ञानिक परियोजनाओं में एक-दूसरे के प्रमुख साझेदार हैं। हालांकि, यह कहना गलत है कि दोनों का सपना एकध्रुवीय विश्व का है; इसके विपरीत, भारत और रूस दोनों ही एक 'बहुध्रुवीय विश्व' व्यवस्था के प्रबल पक्षधर हैं, जहां अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का केंद्रीकरण न होकर संतुलित भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

126. (D) मिखाइल गोर्बाचेव
सोवियत संघ के विघटन का सबसे बड़ा आरोप अक्सर मिखाइल गोर्बाचेव पर लगाया जाता है, क्योंकि उनकी सुधारवादी नीतियों ने ही व्यवस्था के भीतर मौजूद राष्ट्रवादी ताकतों को सक्रिय किया। यद्यपि उनका उद्देश्य सोवियत संघ को आधुनिक बनाना और उसे पतन से बचाना था, लेकिन उनकी उदारवादी पहुंच ने पार्टी की पकड़ को इतना ढीला कर दिया कि वे बाद में विघटन की प्रक्रिया को नियंत्रित नहीं कर सके। कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथी आज भी उन्हें एक ऐसी शक्ति के रुप में देखते हैं जिसने अपनी अदूरदर्शिता से दुनिया की एक महाशक्ति का अंत कर दिया।

127. (B) P-2, Q-1, R-4, S-3
पेरेस्त्रोइका का अर्थ सोवियत व्यवस्था की पुनर्रचना करना था ताकि अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जा सके। ग्लासनोस्त का उद्देश्य प्रशासन में खुलेपन और पारदर्शिता को बढ़ावा देना था। शॉक थेरेपी उस आर्थिक मॉडल को कहा जाता है जिसके तहत साम्यवाद से पूँजीवाद की ओर संक्रमण के लिए 'आघात पहुँचाकर उपचार' करने की रणनीति अपनाई गई थी। दूसरी दुनिया उन देशों का समूह था जो सोवियत संघ के नेतृत्व वाले समाजवादी खेमे का हिस्सा थे। ये सभी शब्द सोवियत संघ के पतन और उसके बाद के आर्थिक एवं राजनीतिक बदलावों की मौलिक अवधारणाएं हैं।

128. (B) पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण
पूर्व साम्यवादी देशों में शॉक थेरेपी अपनाने का मुख्य और सर्वोपरि उद्देश्य राज्य-नियंत्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से एक मुक्त बाजार आधारित पूँजीवादी व्यवस्था में बदलना था। इस मॉडल के तहत यह माना गया कि निजी स्वामित्व ही उत्पादकता बढ़ाने का सबसे प्रभावी साधन है। इसके लिए राजकीय संपत्तियों का बड़े पैमाने पर निजीकरण किया गया और बाहरी दुनिया के साथ मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित किया गया। यह एक प्रकार का आर्थिक प्रयोग था जिसका लक्ष्य सोवियत काल के ढांचे को खत्म करके इन देशों को पश्चिमी तंत्र का हिस्सा बनाना था।

129. (B) रूस, बेलारुस, उक्रेन
दिसंबर 1991 में रूस, बेलारुस और यूक्रेन के नेताओं ने एक ऐतिहासिक बैठक में 1922 की उस संधि को समाप्त करने का औपचारिक निर्णय लिया जिसके तहत सोवियत संघ का गठन

हुआ था। इन तीनों गणराज्यों ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की और साम्यवाद को पूरी तरह से त्याग दिया। इस युगांतकारी निर्णय ने सोवियत संघ के अस्तित्व को कानूनी और राजनीतिक रूप से हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसके बाद ही स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का उदय हुआ, जिसने पूर्व सोवियत गणराज्यों के बीच संबंधों की एक नई और स्वायत्त संरचना की आधारशिला रखी थी।

130. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीतयुद्ध का लंबा और तनावपूर्ण दौर समाप्त हो गया क्योंकि इस घटना ने उस मौलिक विचारधारात्मक विवाद को ही खत्म कर दिया कि समाजवादी प्रणाली पूँजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं। साम्यवाद की विफलता और सोवियत खेमे के बिखराव ने यह सिद्ध कर दिया कि उदारवादी लोकतंत्र और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था ही अधिक टिकाऊ और प्रभावी हैं। इस प्रकार, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था के एक स्तंभ के गिर जाने से महाशक्तियों के बीच का वह दशकों पुराना संघर्ष शांत हो गया और राजनीति नए दौर में पहुँची।

131. (D) उपरोक्त सभी 1, 2, 3, 4 और 5
सोवियत संघ का विघटन कई जटिल कारकों का परिणाम था, जिनमें आर्थिक गतिरोध और आम जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में व्यवस्था की विफलता प्रमुख थी। सोवियत संघ ने हथियारों की होड़ में अपने संसाधनों का इतना अधिक व्यय किया कि घरेलू अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। इसके अलावा, कम्युनिस्ट पार्टी का सत्तावादी चरित्र जनता में गहरे असंतोष का कारण बना। अंततः, विभिन्न गणराज्यों में उभरी राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की तीव्र इच्छा ने इस विशाल संघ के ढांचे को अंदर से तोड़ दिया, जिससे उसका पतन ऐतिहासिक रूप से अवश्यंभावी हो गया।

132. (D) अक्टूबर 1989
अक्टूबर 1989 में सोवियत संघ के नेतृत्व ने एक ऐतिहासिक घोषणा की जिसमें वारसा संधि के सदस्य देशों को अपना भविष्य स्वयं तय करने और अपनी इच्छानुसार राजनीतिक प्रणाली चुनने की पूरी स्वतंत्रता दी गई। यह घोषणा गोर्बाचेव की उदारवादी विदेश नीति का हिस्सा थी, जिसने पूर्वी यूरोप में सोवियत नियंत्रण को स्वेच्छा से ढीला कर दिया। इस घोषणा के तुरंत बाद ही पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों में जन-क्रांतियां शुरु हो गईं और साम्यवादी सरकारें गिरने लगीं। इसने बर्लिन की दीवार के गिरने और समाजवादी खेमे के बिखरने का मार्ग प्रशस्त किया।

133. (C) रूस
सोवियत संघ के आधिकारिक रूप से समाप्त होने के बाद, उसकी अंतरराष्ट्रीय विदेश नीति के सभी दायित्वों, करारों और महत्वपूर्ण संधियों को निभाने की पूरी जिम्मेदारी रूस ने संभाली। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भी रूस को सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य के रूप में मान्यता दी, जिससे उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त हुई। रूस ने ही परमाणु निरस्त्रीकरण से जुड़ी सभी द्विपक्षीय संधियों और पूर्ववर्ती संघ द्वारा किए गए अन्य अंतरराष्ट्रीय वादों को पूरा करने का संकल्प लिया। इस प्रकार, रूस ने वैश्विक स्थिरता बनाए रखी।

134. (B) सत्ता का सत्तावादी होते जाना और नौकरशाही का शिकंजा
सोवियत प्रणाली की आलोचना का सबसे प्रमुख और बुनियादी बिंदु सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकृत और सत्तावादी होना था, जिसके कारण प्रशासन पर नौकरशाही का शिकंजा बहुत कस गया था। सरकारी और पार्टी के अधिकारियों के पास असीमित अधिकार थे, जबकि आम नागरिकों के पास अपनी आवाज उठाने या व्यवस्था में बदलाव लाने का कोई प्रभावी लोकतांत्रिक जरिया नहीं था। नौकरशाही की अकुशलता और भ्रष्टाचार ने न केवल आर्थिक विकास को बाधित किया, बल्कि आम जनता के दैनिक जीवन को भी बहुत कठिन बना दिया था। इसी जड़ता ने जनता का विश्वास पूरी तरह खत्म किया।

135. (D) शॉक थेरेपी
साम्यवाद के पतन के बाद पूर्वी और मध्य यूरोप के देशों में समाजवादी व्यवस्था से पूँजीवादी व्यवस्था की ओर होने वाले तेज और कठिन संक्रमण का वर्णन करने के लिए 'शॉक थेरेपी' पद का उपयोग किया गया है। यह मॉडल विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सुझाया गया था, जिसका उद्देश्य इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं में आमूल-चूल परिवर्तन लाना था। इसमें राज्य की संपत्ति के निजीकरण, मुक्त व्यापार और विदेशी निवेश पर जोर दिया गया। हालांकि इस प्रक्रिया ने देशों को बाजार से जोड़ा, लेकिन इसकी सामाजिक और आर्थिक कीमत बहुत अधिक थी।

136. (A) उन्होंने 1991 के तख्तापलट का समर्थन किया था।
बोरिस येल्तसिन रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति थे और उन्होंने सोवियत संघ के विघटन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और केंद्रीय भूमिका निभाई थी। यद्यपि वे मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा ही मास्को के मेयर बनाए गए थे, लेकिन बाद में वे उनके कट्टर प्रतिद्वंद्वी बन गए। यह कहना पूरी तरह गलत है कि उन्होंने 1991 के तख्तापलट का समर्थन किया था; वास्तव में, उन्होंने इस तख्तापलट का डटकर विरोध किया और जनता का नेतृत्व करते हुए इसे विफल कर दिया। इसी विरोध के कारण वे एक जननायक के रूप में उभरे और सोवियत सत्ता के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुए।

137. (D) उपरोक्त सभी
शॉक थेरेपी के आर्थिक परिणाम रूस और अन्य पूर्व सोवियत देशों के लिए अत्यंत विनाशकारी साबित हुए। वर्षों से बना राज्य-नियंत्रित औद्योगिक ढांचा पूरी तरह चरमरा उठा और अधिकांश उद्योगों को बहुत कम दामों पर निजी हाथों में बेच दिया गया। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय रूप से गिरावट आई, जिससे आम नागरिकों की जमा पूँजी की कीमत लगभग शून्य हो गई। मुद्रास्फीति इतनी अधिक बढ़ गई कि दैनिक आवश्यकताओं की चीजें आम लोगों की पहुँच से बाहर हो गईं। इस आर्थिक उथल-पुथल ने समाज में भारी विषमता पैदा की और गहरा संकट आया।

138. (A) उन्हें सोवियत नियंत्रण में बनाए रखना।
सोवियत संघ ने अपने सीमित आर्थिक संसाधनों का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा पूर्वी यूरोप के अपने पिछलग्गू देशों की अर्थव्यवस्थाओं और सरकारों को सहारा देने पर खर्च किया। इसका एकमात्र मुख्य उद्देश्य इन देशों को अपने राजनीतिक और सामरिक नियंत्रण में बनाए रखना और उन्हें पश्चिमी प्रभाव या नाटो में शामिल होने से रोकना था। सोवियत संघ इन्हें एक सुरक्षित क्षेत्र के रूप में देखता था। हालांकि, इन बाहरी देशों पर अत्यधिक खर्च करने की इस नीति ने सोवियत संघ की अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाला, जिससे वह कमजोर हुआ।

139. (A) P-3, Q-1, R-4, S-2
1917 की रूसी क्रांति ने सोवियत संघ की नींव रखी, जो मानव इतिहास की एक युगांतकारी घटना थी। बर्लिन की दीवार का निर्माण 1961 में शीतयुद्ध के चरम पर होने के दौरान किया गया था, जो विश्व के दो गुटों में बंटने का प्रतीक बनी। 1989 में जन-आंदोलन के कारण बर्लिन की दीवार का गिरना साम्यवाद के अंत की शुरुआत थी। अंततः, 1991 में सोवियत संघ का आधिकारिक विघटन हुआ, जिसने द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का हमेशा के लिए अंत कर दिया। इन चार महत्वपूर्ण वर्षों ने न केवल सोवियत संघ के भाग्य का फैसला किया, बल्कि वैश्विक राजनीति को भी नया आकार दिया।

140. (B) बर्लिन की दीवार का गिरना
बर्लिन की दीवार का गिरना शीतयुद्ध के अंत का सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त प्रतीक माना जाता है। 9 नवंबर 1989 को जब आम जनता ने इस दीवार को तोड़ दिया, तो इसने न केवल एक शहर के भौतिक विभाजन को समाप्त किया, बल्कि यूरोप में साम्यवादी प्रभाव के ढहने की स्पष्ट घोषणा भी कर दी। इस घटना के बाद ही जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका और पूर्वी यूरोप के अन्य देशों में भी साम्यवादी शासन के खिलाफ आंदोलनों को जबरदस्त गति मिली। इस ऐतिहासिक मोड़ ने दुनिया को दशकों पुराने तनाव और विचारधारात्मक संघर्ष से मुक्ति दिलाई।

141. (B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
भारत ने सोवियत संघ के विघटन के बाद बने सभी नए और पूर्व साम्यवादी देशों के साथ बहुत ही अच्छे और दोस्ताना संबंध स्थापित किए हैं। इसका एक प्रमुख सांस्कृतिक आधार यह है कि भारतीय हिन्दी फिल्मों और उनके नायकों की लोकप्रियता इन सभी देशों में बहुत अधिक है। यद्यपि यह सांस्कृतिक लगाव संबंधों को मधुर बनाने में मदद करता है, लेकिन केवल फिल्मी लोकप्रियता ही भारत की व्यापक विदेश नीति के सभी पहलुओं की व्याख्या नहीं करती। भारत के इन देशों के साथ संबंध ऊर्जा, सुरक्षा और व्यापार जैसे अन्य कई रणनीतिक हितों पर भी मजबूती से आधारित हैं।

142. (D) कम्युनिस्ट पार्टी
सोवियत संघ में लगभग 72 वर्षों से चला आ रहा कम्युनिस्ट पार्टी का एकदलीय राजनीतिक एकाधिकार फरवरी 1990 में समाप्त हुआ, जब पार्टी ने अपनी सत्ता की पकड़ ढीली करने और बहुदलीय राजनीति की अनुमति देने का निर्णय लिया। यह सोवियत इतिहास का एक बड़ा संवैधानिक बदलाव था, जिसने विपक्ष के अस्तित्व के लिए कानूनी रास्ता साफ कर दिया। इस निर्णय के बाद सोवियत संघ की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक बदलावों की प्रक्रिया तेज हो गई। हालांकि, पार्टी के इस ढीले पड़ते नियंत्रण ने अंततः राष्ट्रवादी आंदोलनों को और अधिक बल दिया।

143. (B) 4, 1, 2, 3
सोवियत संघ के पतन के अंतिम चरणों का सही क्रम सितंबर 1991 में बाल्टिक गणराज्यों के संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने से शुरू होता है। इसके बाद दिसंबर 1991 की शुरुआत में रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने 1922 की संधि को समाप्त कर सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके साथ ही सोवियत संघ का आधिकारिक रूप से अंत हो गया। इन घटनाओं ने कुछ ही महीनों के भीतर दुनिया की एक महाशक्ति के दशकों पुराने अस्तित्व को पूरी तरह से समाप्त कर दिया।

144. (B) रुपया
शीतयुद्ध के दौरान जब भारत को अपने विकास के लिए विदेशी मुद्रा, विशेष रूप से डॉलर, की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा था, तब सोवियत संघ ने भारत के साथ व्यापार के लिए भारतीय रुपये को माध्यम के रूप में स्वीकार किया। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था, जिसने भारत को बिना किसी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के संकट के भारी मशीनरी और रक्षा उपकरण खरीदने की सुविधा दी। इस 'रुपया व्यापार' व्यवस्था ने भारत की आर्थिक संप्रभुता को बनाए रखने और उसके औद्योगिक आधार को मजबूत करने में निर्णायक भूमिका निभाई। यह गहरे आपसी सहयोग का उदाहरण था।

145. (B) उन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बनाया गया।
सोवियत संघ के विघटन और रूस, यूक्रेन तथा बेलारूस द्वारा इसकी समाप्ति की घोषणा के बाद, मध्य एशियाई गणराज्यों की स्थिति को लेकर काफी अनिश्चितता पैदा हो गई थी। इस समस्या के समाधान के लिए, उन्हें स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बनाया गया और उन्हें रूस के बराबर का दर्जा दिया गया। यह निर्णय इन गणराज्यों को नई व्यवस्था में शामिल करने और उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए लिया गया था कि सोवियत संघ के अंत के बावजूद उनके आर्थिक हित सुरक्षित रहेंगे। इस प्रकार, वे इस नए राष्ट्रकुल के अभिन्न हिस्से के रूप में स्वीकार किए गए।

146. (D) उपरोक्त सभी 1, 2, 3, 4 और 5
शॉक थेरेपी के सामाजिक परिणाम आम जनता के लिए अत्यंत पीड़ादायक रहे क्योंकि इसके कारण सोवियत काल की समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो गई। सरकारी रियायतों के खात्मे ने मध्यम वर्ग को समाज के हाशिए पर धकेल दिया और बड़ी आबादी को गरीबी के गहरे गर्त में धकेल दिया। इसी अराजकता के बीच एक शक्तिशाली 'माफिया वर्ग'

का उदय हुआ जिसने आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण कर लिया। समाज में धनी और निर्धन लोगों के बीच एक ऐसी गहरी खाई पैदा हो गई जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी, जिससे अपराधों में भारी वृद्धि हुई।

147. (C) जनता को पूर्ण आर्थिक आजादी थी।
सोवियत अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी, जहां उत्पादन के सभी प्रमुख साधनों पर राज्य का पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण होता था। अर्थव्यवस्था के हर पहलू, जैसे उत्पादन, वितरण और मूल्य निर्धारण, का नियोजन राज्य द्वारा बहुत ही बारीकी से किया जाता था ताकि समाज में समानता बनी रहे। इसलिए, यह कहना पूरी तरह गलत है कि वहां की जनता को पूर्ण आर्थिक आजादी प्राप्त थी। वास्तव में, निजी उद्यम के लिए सोवियत मॉडल में कोई स्थान नहीं था, और नागरिकों को राज्य द्वारा निर्धारित आर्थिक ढांचे में रहना पड़ता था।

148. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
रुस, बेलारूस और यूक्रेन वे प्रमुख गणराज्य थे जिन्होंने सोवियत संघ के विघटन की पहल की और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल के संस्थापक सदस्य बने। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को बाल्टिक गणराज्य कहा जाता है जिन्होंने सबसे पहले स्वतंत्रता की राह पकड़ी। चेक और स्लोवाक गणराज्य का उदाहरण चेकोस्लोवाकिया के उस शांतिपूर्ण विभाजन को दर्शाता है जो बिना किसी हिंसा के संपन्न हुआ। दूसरी ओर, चेचन्या और दागिस्तान रुस के वे हिस्से हैं जहां लंबे समय तक हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। ये घटनाएं विखंडन के विविध रुपों को स्पष्ट करती हैं।

149. (C) परमाणु हथियार/सैन्य साजो-सामान और पूर्वी यूरोप के पिछलग्गू देश
सोवियत संघ ने अपनी विशाल आय और संसाधनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा परमाणु हथियारों के विकास, सैन्य साजो-सामान के आधुनिकीकरण और पूर्वी यूरोप के अपने पिछलग्गू देशों को अपने नियंत्रण में बनाए रखने पर खर्च किया। अमरीका के साथ हथियारों की होड़ में बने रहने की इस निरंतर कोशिश ने सोवियत खजाने पर असहनीय बोझ डाला। इसके परिणामस्वरूप, देश के भीतर उपभोक्ता उद्योग और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की घोर उपेक्षा हुई, जिससे अर्थव्यवस्था पूरी तरह गतिहीन हो गई। सैन्य शक्ति पर इस अत्यधिक खर्च ने अंततः सोवियत संघ की आर्थिक नींव को कमजोर कर दिया।

150. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं तथा कथन II, कथन I की सही व्याख्या करता है।
शॉक थेरेपी के तहत सोवियत खेमे के देशों के बीच दशकों से चले आ रहे पारंपरिक व्यापारिक गठबंधनों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। इन देशों को एक-दूसरे के साथ सहयोग करने के बजाय सीधे पश्चिमी देशों के आर्थिक तंत्र से जोड़ने की नीति अपनाई गई ताकि वे पूरी तरह पूँजीवादी व्यवस्था में समाहित हो सकें। इस बदलाव का उद्देश्य साम्यवादी काल के उस आर्थिक ढांचे को जड़ से उखाड़ना था जिसने इन देशों को एक-दूसरे पर निर्भर बनाया था। अब वे पश्चिमी मुल्कों के लिए नए बाजारों के रूप में विकसित होने लगे, जिससे उनकी पुरानी व्यापारिक एकता खत्म हो गई।

151. (B) केंद्रीय योजना बनाना और आर्थिक निर्णय लेना
गोस्प्लान सोवियत संघ की राज्य योजना समिति थी, जो देश की आदेशात्मक अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए उत्तरदायी थी। इसका मुख्य कार्य उत्पादन लक्ष्यों को निर्धारित करना, संसाधनों का आवंटन करना और वितरण के संबंध में केंद्रीय स्तर पर योजनाएं बनाना था। इस संस्था ने सोवियत संघ के आर्थिक ढांचे को नियंत्रित करने और विकास नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

152. (A) नवाचार और बाजार की माँगों के प्रति अनुकूलन में धीमी गति
सोवियत अर्थव्यवस्था में केंद्रीय नियोजन की कठोरता ने नवाचार और व्यक्तिगत उद्यमशीलता के लिए बहुत कम स्थान छोड़ा था। इससे तकनीकी परिवर्तनों को अपनाने और बाजार की बदलती माँगों के अनुसार समायोजन करने में काफी समय लगता था। उपभोक्ता वस्तुओं की कमी और उत्पाद की गुणवत्ता में गिरावट इस प्रणाली की अक्षमता के परिणाम थे, जिसने अंततः दीर्घकालिक आर्थिक गतिरोध उत्पन्न किया।

153. (C) भारी उद्योग और रक्षा
सोवियत संघ की केंद्रीय योजना ने हमेशा भारी उद्योगों और सैन्य शक्ति के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इसका उद्देश्य देश को एक वैश्विक महाशक्ति बनाना और पश्चिमी देशों के साथ सामरिक संतुलन बनाए रखना था। बुनियादी ढांचे और रक्षा क्षेत्र में अत्यधिक निवेश के कारण उपभोक्ता वस्तुओं और कृषि जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की अक्सर उपेक्षा हुई, जिससे अर्थव्यवस्था में असंतुलन पैदा हुआ।

154. (D) केंद्रीय योजना की संरचनात्मक खामियाँ और कठोरता।
सोवियत संघ में आर्थिक ठहराव का मुख्य कारण केंद्रीय नियोजन की अंतर्निहित संरचनात्मक खामियाँ और इसकी अत्यधिक कठोर प्रकृति थी। निर्णय लेने की प्रक्रिया पूरी तरह से केंद्रीकृत थी, जिससे जमीनी स्तर की समस्याओं को सुलझाने में लचीलेपन की कमी रही। नवाचार की कमी और संसाधनों के अकुशल आवंटन ने अर्थव्यवस्था की गति को धीमा कर दिया, जिससे वह प्रणाली समय के साथ अस्थिर हो गई।

155. (C) तीव्र औद्योगिकीकरण और सैन्य क्षमता के निर्माण में
सोवियत मॉडल ने अपने शुरुआती चरणों में विशेष रूप से भारी उद्योगों, बुनियादी ढांचे के विकास और सैन्य प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की थी। इस प्रणाली ने सोवियत संघ को एक कृषि प्रधान समाज से एक औद्योगिक शक्ति में बदलने में मदद की। तीव्र औद्योगिकीकरण और सामरिक मजबूती के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक वैश्विक महाशक्ति बनकर उभर सका।

156. (B) अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन और उसमें सुधार करना
पेरेस्त्रोइका का शाब्दिक अर्थ अर्थव्यवस्था और समाज का पुनर्गठन करना था। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत अर्थव्यवस्था

को सुधारने के लिए इस नीति को लागू किया था ताकि केंद्रीय नियंत्रण को कम किया जा सके। इसके तहत उद्यमों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना और आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए बाजार-उन्मुख तत्वों को शामिल करना था, जिससे निरंतर आर्थिक ठहराव को समाप्त किया जा सके।

157. (D) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पारदर्शिता को बढ़ावा देना
ग्लासनोस्त की नीति का उद्देश्य सोवियत समाज में पारदर्शिता लाना और नागरिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना था। इसके माध्यम से मिखाइल गोर्बाचेव ने सूचनाओं के मुक्त प्रवाह की अनुमति दी और सरकारी कामकाज की सार्वजनिक आलोचना का द्वार खोला। मीडिया पर से सेंसरशिप कम की गई और राजनीतिक कैदियों की रिहाई जैसे कदमों ने नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया।

158. (A) राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार और स्वतंत्रता आंदोलनों को बल मिलना
गोर्बाचेव के सुधारों ने अनपेक्षित रूप से विभिन्न सोवियत गणराज्यों के भीतर दबी हुई राष्ट्रवादी आकांक्षाओं और संप्रभुता की इच्छा को जगा दिया। जब राजनीतिक वातावरण में खुलापन आया, तो एस्टोनिया, लातविया और यूक्रेन जैसे गणराज्यों में स्वतंत्रता आंदोलनों ने जोर पकड़ लिया। इन सुधारों ने नागरिकों को अपनी पहचान और अधिकारों की माँग करने के लिए मंच दिया, जिससे सोवियत संघ का विघटन अपरिहार्य हो गया।

159. (C) क्योंकि उनका मानना था कि पारदर्शिता और चर्चा से आर्थिक सुधारों को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकता है।
मिखाइल गोर्बाचेव का मानना था कि जब तक जनता को बोलने और सुधारों में भाग लेने की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तब तक आर्थिक बदलाव सफल नहीं होंगे। राजनीतिक खुलेपन या पारदर्शिता से भ्रष्टाचार कम होने और नीतियों के कार्यान्वियन में सुधार होने की उम्मीद थी। उन्होंने महसूस किया कि समाज में चर्चा और आलोचना के बिना अर्थव्यवस्था की जड़ता को तोड़ना और उत्पादकता बढ़ाना असंभव है।

160. (A) एक विरोधाभासी प्रभाव रखते थे, जिससे अनजाने में विघटन तेज हो गया।
सोवियत संघ को आधुनिक बनाने और आर्थिक गिरावट को रोकने के लिए शुरू किए गए सुधारों ने अंततः विपरीत परिणाम दिए। यद्यपि सुधारों का उद्देश्य प्रणाली को बचाना था, लेकिन उन्होंने नौकरशाही के प्रतिरोध और जनता की बढ़ती अपेक्षाओं के बीच एक संघर्ष पैदा कर दिया। राजनीतिक ढील ने राष्ट्रवादी ताकतों को सक्रिय कर दिया, जिससे संघ की संरचना चरमरा गई और अनजाने में विघटन की प्रक्रिया बहुत तेज हो गई।

161. (D) एक तीव्र, झटके के साथ बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण
शॉक थेरेपी एक ऐसी आर्थिक पद्धति थी जिसका लक्ष्य साम्यवादी व्यवस्था से पूंजीवाद की ओर तत्काल और पूर्ण परिवर्तन करना था। इसका मूल सिद्धांत यह था कि क्रमिक सुधारों के बजाय एक झटके में बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को लागू किया जाए। इसमें राज्य के नियंत्रण को समाप्त करना, कीमतों को मुक्त करना और निजीकरण को बढ़ावा देना शामिल था ताकि आर्थिक स्थिति सुधारी जा सके।

162. (B) मूल्यवान राज्य के औद्योगिक उद्यमों की औने-पौने दामों पर बिक्री के लिए
शॉक थेरेपी के दौरान रूस के विशाल और मूल्यवान सरकारी उद्योगों को बहुत कम कीमतों पर निजी हाथों में बेच दिया गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज-सेल कहा जाता है। चूंकि यह प्रक्रिया जल्दबाजी में की गई थी, इसलिए संसाधनों का उचित मूल्यांकन नहीं हो पाया। इसके परिणामस्वरूप देश की महत्वपूर्ण आर्थिक संपत्तियां कुछ ही प्रभावशाली व्यक्तियों और निजी कंपनियों के नियंत्रण में चली गईं।

163. (C) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक
सोवियत संघ के पतन के बाद रूस और पूर्वी यूरोप में आर्थिक बदलाव लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन पश्चिमी वित्तीय संस्थानों ने आर्थिक सहायता के बदले में उदारवादी नीतियों और बाजार सुधारों को अपनाने की शर्त रखी थी। उनके द्वारा समर्थित मॉडल ने राज्य के स्वामित्व वाली संपत्तियों के निजीकरण और मुक्त व्यापार को अनिवार्य बना दिया था।

164. (D) गरीबी, असमानता में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा का पतन
शॉक थेरेपी के कारण सोवियत संघ की पुरानी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई, जिससे आम जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सब्सिडी खत्म होने और मुद्रास्फीति बढ़ने से गरीबी और आर्थिक असमानता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। मध्यम वर्ग की बचत समाप्त हो गई और कल्याणकारी कार्यक्रमों के अभाव में समाज के कमजोर वर्ग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हो गए, जिससे अराजकता पैदा हुई।

165. (A) 'ओलिगार्क' नामक एक धनी कुलीनतंत्र का
शॉक थेरेपी की प्रक्रिया के दौरान रूस में 'ओलिगार्क' नामक एक नए अत्यंत धनी और शक्तिशाली वर्ग का उदय हुआ। इन लोगों ने सरकारी संपत्तियों के अनियोजित निजीकरण का लाभ उठाते हुए प्रमुख उद्योगों और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। इस वर्ग के पास न केवल अपार धन था, बल्कि उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव डाला, जिससे आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण हुआ।

166. (B) राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार
सोवियत संघ के पतन का सबसे महत्वपूर्ण और तात्कालिक कारण विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रवादी भावनाओं का तीव्र उभार था। संप्रभुता की इच्छा और अपनी सांस्कृतिक पहचान को स्वतंत्र रूप से बनाए रखने की भावना ने केंद्रीय नियंत्रण को चुनौती दी। जब बाल्टिक राज्यों और अन्य गणराज्यों ने स्वतंत्रता की घोषणा की, तो सोवियत संघ की एकता को बनाए रखना पूर्णतः असंभव हो गया।

167. (B) कि राष्ट्रवादी उभार मध्य एशियाई गणराज्यों में सबसे मजबूत होगा।
शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी विद्वानों का अनुमान था कि सोवियत संघ में सबसे अधिक विद्रोह मध्य एशियाई मुस्लिम बहुल गणराज्यों में होगा। उनका मानना था कि सांस्कृतिक और धार्मिक भिन्नता के कारण ये क्षेत्र पहले अलग होंगे। हालांकि, वास्तविकता इसके विपरीत रही और विद्रोह की सबसे मजबूत लहर रूस, यूक्रेन और बाल्टिक राज्यों जैसे अपेक्षाकृत समृद्ध यूरोपीय गणराज्यों में देखी गई।

168. (A) यूरोपीय और समृद्ध गणराज्यों जैसे बाल्टिक राज्यों और यूक्रेन में
सोवियत संघ के विघटन के दौरान राष्ट्रवादी असंतोष और विरोध की लहर सबसे पहले एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और यूक्रेन जैसे यूरोपीय गणराज्यों में प्रबल हुई। इन क्षेत्रों के लोग अपनी संप्रभुता के प्रति अधिक जागरूक थे और उन्हें लगा कि वे संघ का हिस्सा रहकर अपनी प्रगति को रोक रहे हैं। इन समृद्ध गणराज्यों की स्वतंत्रता की माँग ने ही सोवियत संघ के अंत की नींव रखी।

169. (C) क्योंकि उन्हें लगा कि वे संघ के कम विकसित क्षेत्रों का समर्थन कर रहे हैं।
सोवियत संघ के समृद्ध और विकसित गणराज्यों के निवासियों को यह महसूस होने लगा था कि उनकी आर्थिक उन्नति का बड़ा हिस्सा कम विकसित क्षेत्रों की मदद में खर्च हो रहा है। उन्हें लगा कि केंद्रीयकृत व्यवस्था उनके संसाधनों का उपयोग मध्य एशियाई क्षेत्रों के विकास के लिए कर रही है, जिससे उनके अपने विकास की गति धीमी हो गई है। इसी असंतोष ने उनमें अलगाववाद की भावना जगाई।

170. (D) रूस, यूक्रेन, बेलारूस
दिसंबर 1991 में रूस, यूक्रेन और बेलारूस के राष्ट्राध्यक्षों ने एक ऐतिहासिक बैठक में स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल (CIS) की स्थापना की घोषणा की। इस महत्वपूर्ण कदम ने सोवियत संघ के औपचारिक अस्तित्व को समाप्त कर दिया और 1922 की संघ संधि को रद्द कर दिया। इन तीन प्रमुख गणराज्यों द्वारा लिया गया यह निर्णय सोवियत संघ के विघटन की प्रक्रिया का अंतिम चरण था।

171. (C) एकध्रुवीय विश्व का उदय, जिसमें अमेरिका एकमात्र महाशक्ति था
सोवियत संघ के विघटन ने वैश्विक राजनीति में शक्ति के संतुलन को पूरी तरह बदल दिया और शीत युद्ध की द्विध्रुवीय व्यवस्था का अंत कर दिया। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा, जिससे एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना हुई। अब वैश्विक निर्णयों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सुरक्षा नीतियों पर अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया और उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं रहा।

172. (B) कि उदारवादी लोकतंत्र शासन के अंतिम और सार्वभौमिक रुप के रूप में विजयी हुआ है
'इतिहास का अंत' की अवधारणा का तात्पर्य है कि वैचारिक विकास के क्रम में उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद ने साम्यवाद पर अंतिम विजय प्राप्त कर ली है। इसका अर्थ यह है कि अब शासन के किसी अन्य नए वैकल्पिक रुप के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। सोवियत संघ के पतन को लोकतांत्रिक मूल्यों की सार्वभौमिक स्वीकार्यता और मानव समाज के अंतिम राजनीतिक गंतव्य के रूप में देखा गया।

173. (D) वे पूर्व साम्यवादी देशों में पूंजीवादी संक्रमण को निर्देशित करने वाले प्रमुख सलाहकार बन गए।
सोवियत संघ के विघटन के पश्चात, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पूर्व साम्यवादी देशों के लिए प्रमुख आर्थिक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। इन संस्थाओं ने उन देशों को वित्तीय सहायता प्रदान की जो अपनी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी ढांचे में बदलने के लिए सहमत थे। उन्होंने मुक्त बाजार सुधारों, व्यापार उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों को लागू करने के लिए आवश्यक तकनीकी और वित्तीय सलाह दी।

174. (A) अमेरिका द्वारा अपनी नीतियों को लागू करने के लिए बहुपक्षीय संस्थानों की अवहेलना
एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था में एकमात्र महाशक्ति होने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका को अपनी वैश्विक नीतियों को बिना किसी प्रभावी विरोध के लागू करने की छूट मिल गई। इसका एक नकारात्मक प्रभाव यह हुआ कि अमेरिका ने कभी-कभी अपनी इच्छा थोपने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय संधियों की अनदेखी की। इससे वैश्विक शासन में शक्ति का दुरुपयोग होने और सामूहिक निर्णयों की उपेक्षा का अंदेशा बढ़ा।

175. (C) राजनीतिक, सैन्य, और वैचारिक क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रभाव
सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका को न केवल सैन्य और आर्थिक क्षेत्र में, बल्कि राजनीतिक और वैचारिक रूप से भी अपार शक्ति प्राप्त हुई। अमेरिकी संस्कृति, भाषा और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रभाव पूरी दुनिया में फैल गया। वैश्विक वित्त प्रणालियों पर नियंत्रण और उन्नत सैन्य तकनीक ने अमेरिका को एक ऐसी महाशक्ति बना दिया जो दुनिया के किसी भी हिस्से में हस्तक्षेप करने की क्षमता रखती थी।

अध्याय 02

सत्ता के समकालीन केंद्र

1. 1990 के दशक के आरम्भ में किस व्यवस्था के टूटने के बाद राजनैतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों का उदय हुआ?
(A) एक-ध्रुवीय व्यवस्था
(B) दो-ध्रुवीय व्यवस्था
(C) बहु-ध्रुवीय व्यवस्था
(D) उपनिवेशवादी व्यवस्था

2. मार्शल योजना के तहत 1948 में किस संगठन की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद देना था?
(A) यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन
(B) यूरोपीय परिषद्
(C) उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो)
(D) यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय

3. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को तर्क (R) के रुप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर अधिकाधिक राजनीतिक रूप लेता गया है।
तर्क (R): यूरोपीय संघ का अपना झंडा, गान, स्थापना-दिवस और अपनी मुद्रा है, तथा इसकी साझी विदेश और सुरक्षा नीति भी है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

4. यूरोपीय संघ के झंडे में सोने के रंग के सितारों का घेरा किसका प्रतीक है?
(A) सदस्य देशों की कुल संख्या का प्रतीक
(B) यूरोपीय संघ की आर्थिक शक्ति का आधार
(C) संस्थापक बारह सदस्य देशों की पहचान
(D) यूरोप की एकता और मेलमिलाप

5. निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का संस्थापक सदस्य नहीं था?
(A) गणराज्य फ्रांस
(B) पश्चिम जर्मनी
(C) ब्रिटेन
(D) इटली गणराज्य

6. नीचे दी गई सूचियों को सुमेलित कीजिए:
सूची I: (घटना)
P. यूरोपीय संघ की स्थापना
Q. यूरो मुद्रा को अपनाना
R. यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन
S. शांगेन संधि
सूची II: (वर्ष)
1. 1957
2. 1985
3. 1992
4. 2002
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

7. यूरोपीय संघ की आर्थिक शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
(A) 2024 में इसका सकल घरेलू उत्पादन लगभग 19.35 खरब डॉलर होने का अनुमान है।
(B) विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमरीका से तीन गुनी ज़्यादा है।
(C) यह विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्त्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है।
(D) इसकी मुद्रा यूरो, अमरीकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए कोई खतरा नहीं है।

8. 1957 में रोम की संधि के माध्यम से किन दो समुदायों का गठन हुआ?
(A) EEC और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय (यूरेटम)
(B) यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय परिषद् संगठन
(C) यूरोपीय कोयला-इस्पात और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समूह
(D) यूरोपीय संघ और निर्वाचित यूरोपीय संसद संस्था

9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है।
2. यूरोपीय संघ का कुल रक्षा बजट अमरीका के बाद सबसे अधिक है।
3. यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देश सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य हैं।
4. अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है।

उपरोक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2 सही हैं।
(B) केवल 1, 2 और 4 सही हैं।
(C) केवल 3 और 4 सही हैं।
(D) सभी कथन सही हैं।

10. डेनमार्क और स्वीडन ने किस संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा को मानने का प्रतिरोध किया?
(A) मास्ट्रिच संधि और यूरो
(B) पेरिस संधि और फ्रैंक
(C) रोम संधि और मार्क
(D) लिस्बन संधि और पाउंड

11. इराक पर अमरीकी हमले के संदर्भ में यूरोपीय संघ के देशों के बीच मतभेद का क्या उदाहरण था?
(A) समस्त यूरोपीय देशों ने हमले का पूर्ण समर्थन किया
(B) ब्रिटेन हमले के पक्ष में था, जर्मनी-फ्रांस खिलाफ थे
(C) जर्मनी-फ्रांस ने नेतृत्व किया, ब्रिटेन ने विरोध किया
(D) ब्रिटेन हमले के पक्ष में था, जर्मनी-फ्रांस खिलाफ थे

12. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को तर्क (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों ने आसियान बनाकर एक वैकल्पिक पहल की।
तर्क (R): बांडुंग सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से एकता कायम करने के प्रयास अनौपचारिक स्तर पर कारगर नहीं हो रहे थे।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

13. 1967 में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना करने वाले पाँच संस्थापक देश कौन थे?
(A) भारत, चीन, जापान, कोरिया, और वियतनाम
(B) इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, और कंबोडिया
(C) इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपींस, सिंगापुर, और थाईलैंड
(D) मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, और ऑस्ट्रेलिया

14. आसियान के प्रतीक चिह्न में धान की दस बालियाँ किसे इंगित करती हैं?
(A) आसियान के दस प्रमुख मूलभूत और संस्थापक सिद्धांत
(B) एशिया की दस प्रमुख और उभरती आर्थिक शक्तियां
(C) क्षेत्र के दस प्रमुख और महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद
(D) मित्रता से बंधे दक्षिण-पूर्व एशिया के दस देश

15. निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF) की स्थापना
2. बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर
3. आसियान समुदाय की स्थापना
4. भारत द्वारा 'लुक ईस्ट' नीति अपनाना
(A) 2, 4, 1, 3
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 1, 4, 3
(D) 4, 2, 1, 3

16. 'आसियान शैली' (ASEAN way) की मुख्य विशेषता क्या है?
(A) सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्णय थोपना
(B) अनौपचारिक, टकरावरहित और सहयोगात्मक मेल-मिलाप
(C) एक साझा मुद्रा और विदेश नीति अपनाना
(D) सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में सैन्य हस्तक्षेप

17. 2003 में आसियान ने किन तीन स्तम्भों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए?
(A) सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय, और राजनीतिक समुदाय
(B) सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय, और सामाजिक-सांस्कृतिक समुदाय
(C) आर्थिक समुदाय, सामाजिक-सांस्कृतिक समुदाय, और शैक्षिक समुदाय
(D) सैन्य समुदाय, व्यापार समुदाय, और सांस्कृतिक समुदाय

18. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी।
2. इसका उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तेज करना था।
3. बाद में ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया इसमें शामिल हुए।
4. आसियान ने यूरोपीय संघ की तरह एक अधिराष्ट्रीय संगठन बनने का लक्ष्य रखा।
5. आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना महत्त्वपूर्ण है।
उपरोक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2, और 3
(B) केवल 1, 2, 3, और 5
(C) केवल 4 और 5
(D) उपरोक्त सभी

19. आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF) की स्थापना 1994 में क्यों की गई?
(A) सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए
(B) एक साझा मुद्रा लागू करने के लिए
(C) सदस्य देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए
(D) सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए

20. भारत ने किस वर्ष 'एक्ट ईस्ट' नीति अपनाई, जो 'लुक ईस्ट' नीति का विस्तार थी?
(A) 1991
(B) 2003
(C) 2018
(D) 2014

21. नीचे दी गई सूचियों को सुमेलित कीजिए:
सूची I: (नीति/संगठन)
P. खुले द्वार की नीति
Q. आसियान
R. यूरोपीय संघ
S. मार्शल योजना
सूची II: (संबंधित देश/क्षेत्र)
1. यूरोप
2. चीन
3. दक्षिण-पूर्व एशिया
4. अमरीका
(A) P-2, Q-3, R-1, S-4
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-2, Q-1, R-4, S-3
(D) P-4, Q-3, R-1, S-2

22. आसियान आर्थिक समुदाय का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(A) सदस्य देशों के लिए एक साझा सैन्य बल बनाना
(B) आसियान देशों का साझा बाज़ार और उत्पादन आधार तैयार करना
(C) सभी सदस्य देशों में एक ही प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था लागू करना
(D) यूरोपीय संघ के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक राजनीतिक गुट बनाना

23. 1978 में चीन में आर्थिक सुधारों और 'खुले द्वार की नीति' की घोषणा किस नेता ने की?
(A) माओ त्से-तुंग
(B) चाऊ एनलाई
(C) शी जिनपिंग
(D) देंग श्याओपेंग

24. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को तर्क (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): 1949 की क्रांति के बाद चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ लिए।
तर्क (R): चीन की आर्थिकी सोवियत मॉडल पर आधारित थी और उसके पास अपने ही संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई चारा नहीं था।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

25. 1973 में प्रधानमंत्री चाऊ एनलाई द्वारा प्रस्तावित 'चार आधुनिकीकरण' के प्रस्तावों में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था?
(A) कृषि
(B) उद्योग
(C) शिक्षा
(D) सेना

26. चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए 'शॉक थेरेपी' के बजाय कौन सा तरीका अपनाया?
(A) अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला।
(B) पूरी अर्थव्यवस्था को एक साथ निजी हाथों में सौंप दिया।
(C) केवल कृषि क्षेत्र में सुधार किए।
(D) विदेशी निवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया।

27. चीन में खेती का निजीकरण कब किया गया?
(A) 1978
(B) 1998
(C) 2001
(D) 1982

28. 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' (SEZ) की स्थापना का चीन पर क्या प्रभाव पड़ा?
(A) विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय कमी आई।
(B) विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
(C) केवल घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिला।
(D) चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बंद हो गई।

29. चीन विश्व व्यापार संगठन (WTO) में कब शामिल हुआ?
(A) 1991
(B) 1998
(C) 2001
(D) 2008

30. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. चीन में आर्थिक सुधारों के बाद बेरोजगारी बढ़ी है।
2. सुधारों के कारण पर्यावरण को नुकसान और भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है।
3. गाँव और शहर के लोगों के बीच आर्थिक फासला बढ़ा है।
4. चीन में सुधारों का लाभ सभी को समान रुप से मिला है।
उपरोक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2 सही हैं।
(B) केवल 1, 2 और 3 सही हैं।
(C) केवल 4 गलत है।
(D) उपरोक्त सभी कथन सही हैं।

31. 1997 के वित्तीय संकट के बाद किस देश के आर्थिक उभार ने आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में मदद की?
(A) चीन

(B) जापान
(C) भारत
(D) दक्षिण कोरिया

32. शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद भारत-चीन संबंधों में क्या महत्त्वपूर्ण बदलाव आया है?
(A) दोनों देशों के संबंध केवल रणनीतिक स्तर तक सीमित हैं
(B) रणनीतिक के साथ आर्थिक पहलू का जुड़ना
(C) दोनों देशों के मध्य का व्यापार अब पूर्णतः समाप्त हो चुका है
(D) दोनों राष्ट्र एक-दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से उदासीन हैं

33. नीचे दी गई सूचियों को सुमेलित कीजिए:
सूची I: (नेता)
P. राजीव गांधी
Q. चाऊ एनलाई
R. देंग श्याओपेंग
S. मार्गरेट थैचर
सूची II: (संबंधित नीति/कार्य)
1. 'चार आधुनिकीकरण' का प्रस्ताव
2. 'खुले द्वार' की नीति
3. ब्रिटेन को यूरोपीय बाज़ार से अलग रखा
4. 1988 में चीन का दौरा किया
(A) P-4, Q-1, R-2, S-3
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-2, R-1, S-3
(D) P-3, Q-1, R-2, S-4

34. 1950 में किस घटना के कारण भारत और चीन के बीच संबंध एकदम गड़बड़ हो गए?
(A) चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने के फैसले से
(B) कोरियाई युद्ध में चीन की भागीदारी से
(C) भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता अपनाने से
(D) चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने से

35. 1962 का भारत-चीन युद्ध किन क्षेत्रों पर प्रतिस्पर्धी दावों के चलते हुआ?
(A) सिक्किम और भूटान के विवादित सीमावर्ती क्षेत्र
(B) कश्मीर और पंजाब के अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र
(C) अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख का अक्साई चिन
(D) तिब्बत और नेपाल के मध्यवर्ती हिमालयी क्षेत्र

36. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को तर्क (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): 1976 तक भारत और चीन के बीच कूटनैतिक संबंध समाप्त ही रहे।
तर्क (R): 1962 के युद्ध में भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी और इसका भारत-चीन संबंधों पर दीर्घकालिक असर हुआ।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

37. किस भारतीय प्रधानमंत्री के 1988 के चीन दौरे से भारत-चीन संबंधों को सुधारने के प्रयासों को बढ़ावा मिला?
(A) इंदिरा गांधी
(B) अटल बिहारी वाजपेयी
(C) राजीव गांधी
(D) पी. वी. नरसिम्हा राव

38. हाल के वर्षों में भारत और चीन के बीच तनाव के कारणों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है?
(A) सीमा-विवाद
(B) विश्व व्यापार संगठन जैसे मंचों पर सहयोग
(C) चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा
(D) चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का समर्थन

39. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. चीन और भारत के बीच 1999 से व्यापार 30 फीसदी सालाना की दर से बढ़ रहा है।
2. दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान और विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के समझौते किए हैं।
3. भारत ने अपने 1998 के परमाणु परीक्षण को चीन से खतरे के मद्देनज़र उचित ठहराया था।
4. पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में चीन को मददगार माना जाता है।
5. बांग्लादेश और म्यांमार से चीन के सैनिक संबंध भारतीय हितों के खिलाफ माने जाते हैं।
उपरोक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3, 4 और 5
(C) केवल 1, 2 और 4
(D) उपरोक्त सभी

40. एशिया के देशों में अकेला कौन सा देश समूह-7 (G7) का सदस्य है?
(A) जापान
(B) चीन
(C) भारत
(D) दक्षिण कोरिया

41. जापान के संविधान का कौन सा अनुच्छेद युद्ध के त्याग की घोषणा करता है?
(A) अनुच्छेद 5
(B) अनुच्छेद 11
(C) अनुच्छेद 9
(D) अनुच्छेद 21

42. निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जापान की शक्ति का परिचायक नहीं है?
(A) इसके पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं।
(B) यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है (2017)।
(C) यह संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में 10 प्रतिशत का योगदान करता है।
(D) सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में इसका सातवाँ स्थान है।

43. दक्षिण कोरिया के तीव्र आर्थिक विकास को क्या कहा जाता है?
(A) यांग्ज़ी नदी पर चमत्कार
(B) मेकांग डेल्टा का विकास
(C) सियोल का उभार
(D) हान नदी पर चमत्कार

44. नीचे दी गई सूचियों को सुमेलित कीजिए:
सूची I: (देश)
P. चीन
Q. जापान
R. दक्षिण कोरिया
S. जर्मनी
सूची II: (विशेषता/घटना)
1. हान नदी पर चमत्कार
2. यूरोपीय संघ का प्रमुख देश
3. खुले द्वार की नीति
4. समूह-7 का एशियाई सदस्य
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

45. दक्षिण कोरिया किस वर्ष आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (OECD) का सदस्य बना?
(A) 1964
(B) 1991
(C) 1996
(D) 2017

46. भारत में प्रसिद्ध सैमसंग, एलजी और हुंडई जैसे ब्रांड किस देश के हैं?
(A) जापान
(B) चीन
(C) ताइवान
(D) दक्षिण कोरिया

47. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को तर्क (R) के रुप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई।
तर्क (R): मास्ट्रिच संधि पर हस्ताक्षर के परिणामस्वरुप यूरोपीय संघ का गठन हुआ।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

48. यूरोपीय एकता के निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण पड़ावों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. लिस्बन संधि लागू हुई
2. क्रोएशिया 28वां सदस्य बना
3. जर्मनी का एकीकरण
4. डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन की सदस्यता
(A) 4, 3, 1, 2
(B) 3, 4, 1, 2
(C) 4, 1, 3, 2
(D) 3, 1, 4, 2

49. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसका एक संविधान बनाने की कोशिश असफल हो गई।
2. इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है जो कई बार एक-दूसरे के खिलाफ होती है।
3. यूरो को लागू करने को लेकर कुछ सदस्य देशों में नाराजगी है।
4. ब्रिटेन जनमत संग्रह के बाद संघ से बाहर हो गया (ब्रेक्जिट)।
उपरोक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3 और 4
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) उपरोक्त सभी

50. 1972 में किस देश से संबंध बनाकर चीन ने अपने राजनैतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया?
(A) अमरीका
(B) सोवियत संघ
(C) भारत
(D) जापान

51. आसियान विजन दस्तावेज़ 2020 में किस बात को प्रमुखता दी गई है?
(A) सदस्य देशों के मध्य एक सशक्त सैन्य गठबंधन बनाना
(B) सम्पूर्ण एशियाई क्षेत्र के लिए एक साझा मुद्रा बनाना
(C) अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक बहिर्मुखी भूमिका
(D) आंतरिक-केंद्रित आर्थिक और सामाजिक विकास मॉडल

52. नीचे दी गई सूचियों को सुमेलित कीजिए:
सूची I: (संगठन/नीति)
P. आसियान
Q. यूरोपीय संघ
R. खुले द्वार की नीति
S. एक्ट ईस्ट नीति

सूची II: (स्थापना/घोषणा वर्ष)
1. 1978
2. 1992
3. 2014
4. 1967
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-2, R-1, S-3
(C) P-2, Q-4, R-1, S-3
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

53. 'आसियान शैली' के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इसकी कार्यप्रणाली का हिस्सा है?
(A) औपचारिकता और कठोर नियम
(B) टकराव और सैन्य दबाव
(C) सहयोग और निरंतर संवाद
(D) अधिराष्ट्रीय सत्ता का प्रयोग

54. यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) का नाम बदलकर यूरोपीय समुदाय (EC) किस वर्ष किया गया?
(A) 1992
(B) 1993
(C) 2002
(D) 2009

55. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. चीन ने 'शॉक थेरेपी' पर अमल किया।
2. चीन ने 1982 में उद्योगों का निजीकरण किया।
3. चीन में व्यापार संबंधी अवरोधों को केवल 'विशेष आर्थिक क्षेत्रों' के लिए ही हटाया गया।
4. चीन में कृषि के निजीकरण से ग्रामीण आय में कमी आई।
5. चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ।

उपरोक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 3 और 5
(B) केवल 1, 2 और 4
(C) केवल 2, 3 और 5
(D) केवल 1 और 5

56. चीन की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(A) चीन विदेशी निवेश के लिए सर्वाधिक आकर्षक देश बना
(B) 1949 की क्रांति के बाद चीन ने पूंजीवादी मॉडल अपनाया
(C) माओ के काल में चीन ने अभूतपूर्व औद्योगिक विकास किया
(D) चीन ने अर्थव्यवस्था हेतु 'शॉक थेरेपी' मॉडल अपनाया

57. दक्षिण और उत्तरी कोरिया को किस समानांतर रेखा पर विभाजित किया गया था?
(A) 17वीं समानांतर
(B) 49वीं समानांतर
(C) 38वीं समानांतर
(D) 10वीं समानांतर

58. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को तर्क (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है।
तर्क (R): आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति, खास तौर से भारत और चीन जैसे देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में उसकी प्रासंगिकता ने इसे और भी आकर्षक बना दिया है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

59. यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन 1951 में किन छह देशों ने किया था?
(A) फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, स्पेन, पुर्तगाल और ग्रीस
(B) जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया
(C) स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया
(D) फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग

60. 'शांगेन वीजा' का क्या अर्थ है?
(A) यह केवल किसी एक विशेष देश में प्रवेश की अनुमति है
(B) यूरोपीय देशों में मुक्त यात्रा की अनुमति
(C) यह केवल व्यापारिक और व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु है
(D) यह यूरोपीय संघ के सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य है

61. निम्नलिखित में से किस देश ने मास्ट्रिच संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध किया?
(A) फ्रांस और जर्मनी
(B) इटली और स्पेन
(C) डेनमार्क और स्वीडन
(D) बेल्जियम और नीदरलैंड

62. नीचे दी गई सूचियों को सुमेलित कीजिए:
सूची I: (देश/संगठन)
P. आसियान
Q. जापान
R. चीन
S. यूरोपीय संघ

सूची II: (मुख्यालय/संबंधित शहर)
1. ब्रुसेल्स (अघोषित मुख्यालय)
2. जकार्ता (सचिवालय)
3. टोक्यो
4. बीजिंग

(A) P-2, Q-3, R-4, S-1
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4

(C) P-2, Q-4, R-3, S-1
(D) P-4, Q-3, R-1, S-2

63. चीन की 1949 की साम्यवादी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था?
(A) माओ त्से-तुंग
(B) देंग श्याओपेंग
(C) चाऊ एनलाई
(D) शी जिनपिंग

64. चीन के आर्थिक सुधारों के नकारात्मक परिणामों में से एक क्या है?
(A) प्रति व्यक्ति औसत आय में उल्लेखनीय कमी
(B) बेरोजगारी और पर्यावरण को गंभीर नुकसान
(C) विदेशी व्यापार और निर्यात में भारी गिरावट
(D) औद्योगिक उत्पादन और विकास में ठहराव

65. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यूरोपीय संघ का एक सदस्य फ्रांस सुरक्षा परिषद् का स्थायी सदस्य है।
2. यूरोपीय संघ के पास परमाणु हथियार नहीं हैं।
3. यूरोपीय संघ को 2012 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला।
4. क्रोएशिया 2013 में यूरोपीय संघ का सदस्य बना।

उपरोक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 3 और 4 सही हैं।
(B) केवल 1 और 2 सही हैं।
(C) केवल 2 और 4 सही हैं।
(D) सभी कथन सही हैं।

66. 'ब्रेक्ज़िट' (Brexit) से क्या तात्पर्य है?
(A) ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर होना
(B) ब्रिटेन का यूरोपीय संघ में शामिल होना
(C) ब्रिटेन द्वारा यूरो मुद्रा को अपनाना
(D) ब्रिटेन का नाटो से अलग होना

67. निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का संस्थापक सदस्य है?
(A) वियतनाम
(B) म्यांमार
(C) थाईलैंड
(D) लाओस

68. भारत-चीन संबंधों के संदर्भ में, 'हिंदी-चीनी भाई-भाई' का नारा किस दौर में लोकप्रिय हुआ?
(A) 1962 के प्रसिद्ध भारत-चीन युद्ध के दौरान
(B) 21वीं सदी के आरम्भिक और आधुनिक दौर में
(C) 1988 में राजीव गांधी के ऐतिहासिक चीन दौरे बाद
(D) 1950 के दशक में आजादी के बाद

69. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को तर्क (R) के रूप में अंकित किया गया है।

अभिकथन (A): जापान के पास प्राकृतिक संसाधन कम हैं और वह ज्यादातर कच्चे माल का आयात करता है।
तर्क (R): इसके बावजूद, जापान उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पाद बनाने में विश्व में अग्रणी है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

70. आसियान के बाद के वर्षों में शामिल होने वाले देशों का सही समूह कौन सा है?
(A) भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल देश
(B) ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया
(C) ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, पापुआ न्यू गिनी और फिजी
(D) चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया और ताइवान

71. निम्नलिखित में से कौन सा कथन आसियान के बारे में सही नहीं है?
(A) यह बुनियादी रूप से एक आर्थिक संगठन है।
(B) इसका विकास अमरीका और यूरोपीय संघ से अधिक तेजी से हो रहा है।
(C) इसने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र (FTA) बनाने पर ध्यान दिया है।
(D) इसकी अर्थव्यवस्था का आकार अमरीका और यूरोपीय संघ से बड़ा है।

72. निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. चीन का विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश
2. चीन में खेती का निजीकरण
3. 'खुले द्वार' की नीति की घोषणा
4. प्रधानमंत्री चाऊ एनलाई द्वारा 'चार आधुनिकीकरण' का प्रस्ताव

(A) 4, 3, 2, 1
(B) 3, 4, 2, 1
(C) 4, 2, 3, 1
(D) 3, 2, 4, 1

73. 1951 की पेरिस संधि द्वारा किस समुदाय का गठन किया गया था?
(A) यूरोपीय आर्थिक समुदाय
(B) यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय
(C) यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय
(D) यूरोपीय संघ

74. यूरोपीय संघ के संदर्भ में कौन सा कथन इसकी राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव को इंगित करता है?
(A) अमरीका सहित अन्य देशों की नीतियों पर प्रभाव
(B) इसका प्रभाव केवल इसके पड़ोसी देशों तक सीमित

रहता है
(C) यह केवल क्षेत्रीय आर्थिक और व्यापारिक मामलों में है
(D) यह मानवाधिकार और पर्यावरण के मुद्दों पर मौन है

75. नीचे दी गई सूचियों को सुमेलित कीजिए:
सूची I: (घटना)
P. ब्रेक्जिट जनमत संग्रह
Q. लिस्बन संधि लागू हुई
R. यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार
S. क्रोएशिया का प्रवेश
सूची II: (वर्ष)
1. 2009
2. 2012
3. 2013
4. 2016
(A) P-4, Q-1, R-2, S-3
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-2, R-1, S-3
(D) P-3, Q-1, R-2, S-4

76. निम्नलिखित में से किसने 'खुले द्वार' की नीति अपनाई?
(A) यूरोपीय संघ
(B) चीन
(C) आसियान
(D) जापान

77. आसियान सुरक्षा समुदाय का आधार क्या है?
(A) सदस्य देशों पर एक बाहरी हमले का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त सेना।
(B) चीन के खिलाफ एक रक्षात्मक गठबंधन।
(C) क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति।
(D) सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में सामूहिक हस्तक्षेप।

78. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत आसियान का संस्थापक सदस्य है।
2. भारत ने 1991 में 'लुक ईस्ट' नीति अपनाई।
3. भारत ने मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है।
4. भारत 2010 में आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था का हिस्सा बना।
5. भारत आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF) का सदस्य नहीं है।
उपरोक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 2, 3 और 4
(B) केवल 1, 2 और 5
(C) केवल 1, 3 और 5
(D) उपरोक्त सभी

79. चीन ने अपने आर्थिक मॉडल में खेती से निकाली गई पूँजी का उपयोग किसलिए किया?
(A) सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योगों की स्थापना
(B) विभिन्न सामाजिक कल्याण और जनहित योजनाओं के लिए
(C) ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और कुटीर उद्योगों हेतु
(D) विशाल विदेशी मुद्रा भंडार और स्वर्ण संचय के लिए

80. 1970 के दशक में चीन के नेतृत्व ने कौन से बड़े नीतिगत निर्णय लिए?
(A) सोवियत संघ के साथ अपने सभी रणनीतिक संबंध तोड़ना
(B) अमरीका से संबंध बनाकर एकांतवास समाप्त करना
(C) गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सक्रिय सदस्य के रूप में जुड़ना
(D) समस्त निजी उद्योगों का पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण करना

81. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को तर्क (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): 1988 में राजीव गांधी के चीन दौरे से भारत-चीन संबंधों में सुधार को बढ़ावा मिला।
तर्क (R): इसके बाद दोनों देशों ने टकराव टालने और सीमा पर शांति बनाए रखने के उपायों की शुरुआत की।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

82. जापान के आर्थिक विकास के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है?
(A) यह 1964 में OECD का सदस्य बना।
(B) यह अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर है।
(C) यह G7 समूह का सदस्य नहीं है।
(D) इसकी अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे बड़ी है।

83. दक्षिण कोरिया के उच्च मानव विकास के लिए जिम्मेदार कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है?
(A) सफल भूमि सुधार
(B) ग्रामीण विकास
(C) आयात उन्मुखीकरण
(D) मजबूत पुनर्वितरण नीतियां

84. यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ?
(A) 1957
(B) 1973
(C) 1992
(D) 1979

85. नीचे दी गई सूचियों को सुमेलित कीजिए:
सूची I: (ब्रांड)
P. सोनी, पैनासोनिक
Q. सैमसंग, हुंडई
R. देंग श्याओपेंग

S. आसियान

सूची II: (देश/अवधारणा)

1. दक्षिण कोरिया
2. जापान
3. बैंकॉक घोषणा
4. खुले द्वार की नीति

(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-1, R-4, S-3
(C) P-2, Q-1, R-3, S-4
(D) P-1, Q-2, R-4, S-3

86. चीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई।
2. इसने विकास का जो मॉडल अपनाया उसमें राज्य-नियंत्रित बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर था।
3. बढ़ती आबादी विकास के लाभ में बाधक बन रही थी।
4. 1970 के दशक तक चीन में प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक थी।

उपरोक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही हैं?

(A) केवल 1 और 2 सही हैं।
(B) केवल 1, 2 और 3 सही हैं।
(C) केवल 4 गलत है।
(D) सभी कथन सही हैं।

87. 1962 के युद्ध के बाद भारत और चीन के बीच कूटनीतिक संबंध कब तक समाप्त रहे?

(A) 1965
(B) 1971
(C) 1980
(D) 1976

88. यूरोपीय संघ को एक अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर क्या करने में सक्षम बनाता है?

(A) आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक मामलों में दखल
(B) केवल सदस्य देशों के आर्थिक और वित्तीय मामलों में
(C) केवल सदस्य देशों के सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों में
(D) सभी सदस्य देशों पर अपनी एकल मुद्रा यूरो थोपने में

89. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को तर्क (R) के रूप में अंकित किया गया है।

अभिकथन (A): चीन की अर्थव्यवस्था का बाहरी दुनिया से जुड़ाव और पारस्परिक निर्भरता ने इसे अपने व्यावसायिक साझेदारों पर प्रभावशाली बना दिया है।

तर्क (R): जापान, अमरीका, आसियान और रूस जैसे देश चीन के साथ अपने व्यापारिक हितों के कारण अन्य विवादों को भुला देते हैं।

(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

90. आसियान के संस्थापक सदस्य देशों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है?

(A) वियतनाम
(B) इंडोनेशिया
(C) मलेशिया
(D) फिलिपींस

91. निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत-चीन संबंधों में हालिया तनाव का एक कारण है?

(A) दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि
(B) सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम
(C) जलवायु परिवर्तन पर सहयोग
(D) चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC)

92. निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:

1. भारत-चीन युद्ध
2. चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा
3. राजीव गांधी का चीन दौरा
4. चीन में 'खुले द्वार' की नीति की घोषणा

(A) 2, 1, 4, 3
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 4, 1, 3
(D) 4, 2, 1, 3

93. परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश कौन सा है?

(A) जर्मनी
(B) चीन
(C) जापान
(D) वियतनाम

94. यूरोपीय संघ के गठन की प्रक्रिया में सबसे पहला कदम क्या था?

(A) मास्ट्रिच संधि
(B) यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना
(C) रोम की संधि
(D) यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन

95. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया 1991 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने।
2. दक्षिण कोरिया 1996 में OECD का सदस्य बना।
3. 2017 में दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था दुनिया में ग्यारहवीं सबसे बड़ी थी।
4. "हान नदी पर चमत्कार" जापान के आर्थिक विकास को संदर्भित करता है।
5. सैमसंग और एलजी चीनी ब्रांड हैं।

उपरोक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2, और 3
(B) केवल 4 और 5
(C) केवल 1, 4, और 5
(D) उपरोक्त सभी

96. 'आसियान विज़न 2020' का संबंध किससे है?
(A) सदस्य देशों के लिए एक संयुक्त साझा सेना बनाने से
(B) टकराव के स्थान पर संवाद को प्रोत्साहन देना
(C) यूरोपीय संघ की तरह एक अधिराष्ट्रीय संगठन बनाने से
(D) चीन के साथ एक विशाल क्षेत्रीय आर्थिक संघ बनाने से

97. चीन में उद्योगों का निजीकरण कब शुरू हुआ?
(A) 1982
(B) 1998
(C) 1988
(D) 2001

98. नीचे दी गई सूचियों को सुमेलित कीजिए:
सूची I: (अवधि)
P. 1951
Q. 1957
R. 1992
S. 2002
सूची II: (यूरोपीय एकता में घटना)
1. रोम की संधि (EEC का गठन)
2. पेरिस संधि (ECSC का गठन)
3. यूरो का प्रचलन
4. मास्ट्रिच संधि (EU का गठन)
(A) P-2, Q-1, R-4, S-3
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-2, Q-4, R-1, S-3
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

99. 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल-मिलाप को किससे मदद मिली?
(A) सोवियत संघ के विस्तार से
(B) उपनिवेशों के पतन से
(C) शीतयुद्ध से
(D) संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से

100. यूरोपीय संघ की साझी विदेश और सुरक्षा नीति की एक सीमा क्या है?
(A) यह नीति सदैव सभी की पूर्ण सर्वसम्मति से बनती है
(B) यह नीति केवल महाद्वीप के यूरोपीय देशों पर लागू है
(C) इस विदेश और सुरक्षा नीति का कोई सैन्य आयाम नहीं है
(D) सदस्य देशों की परस्पर विरोधी व्यक्तिगत नीतियां

101. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को तर्क (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): आसियान ने यूरोपीय संघ की तरह खुद को अधिराष्ट्रीय संगठन बनाने का लक्ष्य नहीं रखा।
तर्क (R): आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना बहुत ही महत्त्वपूर्ण रहा है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

102. आसियान ने किन दो संकटों के समाधान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई?
(A) कोरियाई संकट और वियतनाम युद्ध
(B) कंबोडिया के टकराव और पूर्वी तिमोर के संकट
(C) खाड़ी युद्ध और अफगान संकट
(D) कश्मीर मुद्दा और फिलीस्तीन विवाद

103. चीन के आर्थिक उभार के संबंध में 2040 तक क्या अनुमान लगाया गया है?
(A) यह भविष्य में भी एक विकासशील देश ही बना रहेगा
(B) इसकी अर्थव्यवस्था भविष्य में अमेरिका से छोटी होगी
(C) यह भविष्य में विश्व व्यापार संगठन से बाहर हो जाएगा
(D) दुनिया की सबसे बड़ी और प्रमुख आर्थिक शक्ति बनना

104. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. चीन की विशाल आबादी, बड़ा भू-भाग और संसाधन इसकी शक्ति के स्रोत हैं।
2. आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन पूर्व एशिया के विकास का इंजन-जैसा बना हुआ है।
3. चीन का प्रभाव केवल उसके पड़ोसी देशों तक सीमित है।
4. चीन में आर्थिक वृद्धि ने उसके राजनीतिक प्रभाव को कम कर दिया है।

उपरोक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2 सही हैं।
(B) केवल 3 और 4 सही हैं।
(C) केवल 1, 2 और 4 सही हैं।
(D) सभी कथन सही हैं।

105. 1950 के दशक में चीन को किस देश से थोड़े समय के लिए मदद और सलाह मिली थी?
(A) संयुक्त राज्य अमेरिका
(B) जापान
(C) सोवियत संघ
(D) भारत

106. नीचे दी गई सूचियों को सुमेलित कीजिए:
सूची I: (वर्ष)
P. 1967
Q. 1991
R. 1994
S. 2014
सूची II: (घटना/नीति)

1. 'लुक ईस्ट' नीति
2. 'एक्ट ईस्ट' नीति
3. आसियान की स्थापना
4. आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF) की स्थापना

(A) P-3, Q-1, R-4, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

107. 1960 से 1980 के दशक के बीच किस देश के तीव्र आर्थिक विकास को "हान नदी पर चमत्कार" कहा गया?
(A) चीन
(B) जापान
(C) ताइवान
(D) दक्षिण कोरिया

108. जापान की सैन्य शक्ति के बारे में क्या अद्वितीय है?
(A) इसके पास वर्तमान में दुनिया की सबसे विशाल सैन्य सेना है
(B) संविधान द्वारा युद्ध त्याग, फिर भी सातवां सैन्य व्यय
(C) इसका सैन्य बजट कुल सकल घरेलू उत्पाद का 10 प्रतिशत है
(D) इसके पास अपनी सुरक्षा हेतु वर्तमान में कोई सेना नहीं है

109. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को तर्क (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद से भारत-चीन संबंधों का आर्थिक पहलू भी महत्त्वपूर्ण हो गया है।
तर्क (R): 1992 के 33 करोड़ डॉलर की तुलना में 2017 में भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार 84 अरब डॉलर का हो गया।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

110. यूरोपीय संघ की मुद्रा 'यूरो' के लिए क्या सही है?
(A) यह सभी सदस्य देशों द्वारा अपनाई गई है।
(B) यह केवल सांकेतिक मुद्रा है, वास्तविक प्रचलन में नहीं।
(C) इसे 2010 में पेश किया गया था।
(D) यह अमरीकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है।

111. आसियान के कामकाज में 'टकरावरहित और सहयोगात्मक मेल-मिलाप' की नीति को क्या कहा जाता है?
(A) आसियान शैली
(B) आसियान संधि
(C) बैंकॉक घोषणा
(D) आसियान चार्टर

112. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यूरोपीय संघ का अपना झंडा, गान और स्थापना-दिवस है।
2. यूरोपीय संघ के सभी सदस्यों को यूरो मुद्रा अपनाना अनिवार्य है।
3. यूरोपीय संघ का एक साझा संविधान 2003 में सफलतापूर्वक बनाया गया था।
4. डेनमार्क और स्वीडन ने यूरो को मानने का प्रतिरोध किया।
5. ब्रिटेन ने जनमत संग्रह के माध्यम से यूरोपीय संघ छोड़ने का फैसला किया।

उपरोक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 4, और 5
(B) केवल 1, 2, और 3
(C) केवल 2 और 3
(D) उपरोक्त सभी

113. 1978 से पहले चीन की अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता थी?
(A) बाजार-उन्मुख और खुली हुई
(B) राज्य-नियंत्रित और बंद
(C) कृषि-प्रधान और निजी
(D) सेवा-उन्मुख और विदेशी-निवेश आधारित

114. चीन ने आर्थिक सुधारों के लिए 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' (SEZ) क्यों स्थापित किए?
(A) विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से
(B) विशेष रूप से केवल घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देने हेतु
(C) विभिन्न कृषि उत्पादों के आधुनिक और सुरक्षित भंडारण हेतु
(D) विदेशी सैन्य अड्डों के रूप में गुप्त रूप से उपयोग हेतु

115. यूरोपीय परिषद् का गठन कब हुआ और इसका क्या उद्देश्य था?
(A) 1948, आर्थिक सहयोग
(B) 1957, आर्थिक एकीकरण
(C) राजनैतिक सहयोग (1949)
(D) 1992, सैन्य सहयोग

116. नीचे दी गई सूचियों को सुमेलित कीजिए:
सूची I: (संकल्पना)
P. ब्रेक्जिट
Q. SEZ
R. ARF
S. ECSC

सूची II: (संबंधित देश/संगठन)
1. चीन
2. आसियान
3. यूरोपीय संघ
4. यूनाइटेड किंगडम

(A) P-4, Q-1, R-2, S-3
(B) P-1, Q-4, R-2, S-3
(C) P-4, Q-2, R-1, S-3

(D) P-3, Q-1, R-2, S-4

117. 1998 में भारत के परमाणु हथियार परीक्षण को कुछ लोगों ने किस खतरे को ध्यान में रखते हुए उचित ठहराया था?
(A) पाकिस्तान
(B) अमरीका
(C) चीन
(D) आतंकवाद

118. निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया का सदस्य नहीं है, लेकिन उसके साथ चीन के सैनिक संबंधों को भारत अपने हितों के खिलाफ मानता है?
(A) नेपाल
(B) म्यांमार
(C) भूटान
(D) मालदीव

119. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को तर्क (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): यूरोपीय संघ का सैनिक प्रभाव भी जबरदस्त है।
तर्क (R): यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है और इसका कुल रक्षा बजट अमरीका के बाद सबसे अधिक है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

120. यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे क्यों हैं?
(A) 12 संख्या पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक है
(B) क्योंकि इसके आरम्भ में कुल 12 संस्थापक सदस्य देश थे
(C) क्योंकि यह वर्ष के 12 महीनों का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं
(D) क्योंकि इस झंडे को औपचारिक रूप से 12 दिसंबर को अपनाया

121. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. आसियान की स्थापना पाँच देशों ने की थी।
2. वर्तमान में इसके दस सदस्य देश हैं।
3. भारत आसियान का एक सदस्य देश है।
4. इसका सचिवालय जकार्ता में है।
उपरोक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 4 सही हैं।
(B) केवल 1 और 2 सही हैं।
(C) केवल 3 और 4 सही हैं।
(D) सभी कथन सही हैं।

122. माओ के समय के चीनी आर्थिक मॉडल की एक बड़ी समस्या क्या थी?
(A) खेती से उद्योगों हेतु पर्याप्त अधिशेष की कमी
(B) चीन का विदेशी व्यापार और निर्यात बहुत अधिक था
(C) देश की जनसंख्या वृद्धि दर उस समय नकारात्मक रही
(D) माओ के काल में प्रति व्यक्ति आय बहुत ही अधिक थी

123. चीन की अर्थव्यवस्था में सुधारों के बावजूद कौन सी समस्या बनी हुई है?
(A) पूरी तरह से बंद और नियंत्रित अर्थव्यवस्था की समस्या
(B) देश में पर्याप्त विदेशी निवेश और पूंजी की भारी कमी
(C) तकनीकी रूप से पिछड़ापन और नवाचार का पूर्ण अभाव
(D) भ्रष्टाचार और अमीर-गरीब के बीच बढ़ती खाई

124. निम्नलिखित में से कौन सा संगठन 'अधिराष्ट्रीय संगठन' का एक उदाहरण है जो अपने सदस्य देशों के आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है?
(A) आसियान
(B) यूरोपीय संघ
(C) सार्क
(D) नाटो

125. 1970 के दशक के उत्तरार्द्ध में चीन की नीति में क्या वैचारिक बदलाव आया?
(A) व्यावहारिक मुद्दों की जगह वैचारिक मुद्दे प्रमुख हो गए।
(B) माओवादी विचारधारा और मजबूत हो गई।
(C) वैचारिक मुद्दों की जगह व्यावहारिक मुद्दे प्रमुख हो गए।
(D) चीन ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपना ली।

126. भारत और चीन द्वारा हाल के वर्षों में सहयोग के लिए सहमति जताए गए मुद्दों में से एक क्या है?
(A) सीमा विवादों को सैन्य रूप से हल करना।
(B) एक दूसरे के पड़ोसियों के साथ संबंध तोड़ना।
(C) पाकिस्तान के मुद्दे पर एक समान नीति अपनाना।
(D) विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने का मसला।

127. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 1962 के युद्ध का भारत-चीन संबंधों पर कोई दीर्घकालिक असर नहीं हुआ।
2. 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनैतिक संबंध समाप्त रहे।
3. 1981 में सीमा विवादों को दूर करने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला शुरु हुई।
4. राजीव गांधी के 1988 के चीन दौरे से संबंधों को सुधारने में मदद मिली।
5. शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद संबंधों में कोई बदलाव नहीं आया।
उपरोक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2, और 3
(B) केवल 2, 3, और 4
(C) केवल 1 और 5

(D) उपरोक्त सभी

128. जापान किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का सदस्य है जिसमें एशिया का कोई और देश शामिल नहीं है?
(A) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्
(B) जी-7 (समूह-7)
(C) आसियान
(D) सार्क

129. आसियान ने अपनी स्थापना के समय मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित किया?
(A) सैन्य सुरक्षा
(B) आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक विकास
(C) राजनीतिक प्रभुत्व
(D) मानवाधिकार संरक्षण

130. यूरोपीय संघ के उस सदस्य देश का नाम बताइए जिसके पास परमाणु हथियार हैं और जो सुरक्षा परिषद् का स्थायी सदस्य भी है?
(A) फ्रांस
(B) जर्मनी
(C) इटली
(D) स्पेन

131. भारत द्वारा 1991 में अपनाई गई 'लुक ईस्ट' नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था?
(A) पश्चिमी विकसित देशों के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत करना
(B) अफ्रीका महाद्वीप के विकासशील देशों के साथ व्यापार बढ़ाना
(C) पूर्वी एशियाई देशों से आर्थिक संबंधों में वृद्धि
(D) रूस के साथ एक स्थायी और मजबूत सैन्य गठबंधन बनाना

132. चीन ने अपनी बाज़ारमूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया?
(A) एक ही बार में सभी क्षेत्रों को खोल दिया।
(B) केवल सेवा क्षेत्र में सुधार किए।
(C) सोवियत संघ के मॉडल का पूरी तरह से पालन किया।
(D) चरणबद्ध ढंग से, पहले कृषि फिर उद्योग।

133. आसियान समुदाय के तीन स्तंभ कौन-कौन से हैं?
(A) आसियान राजनीतिक समुदाय, आसियान सैन्य समुदाय, व्यापार समुदाय
(B) आसियान एकता समुदाय, आसियान विकास समुदाय, शांति समुदाय
(C) सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक समुदाय
(D) आसियान मानवाधिकार समुदाय, पर्यावरण समुदाय, प्रौद्योगिकी समुदाय

134. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यूरोपीय संघ का 2024 में अनुमानित सकल घरेलू उत्पादन अमरीका से अधिक है।
2. यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो, अमरीकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है।
3. विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी अमरीका से तीन गुनी ज़्यादा है।
4. यूरोपीय संघ विश्व व्यापार संगठन में एक नगण्य शक्ति है।

उपरोक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2 सही हैं।
(B) केवल 2 और 3 सही हैं।
(C) केवल 1, 2 और 3 सही हैं।
(D) सभी कथन सही हैं।

135. दक्षिण कोरिया ने आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (OECD) की सदस्यता कब प्राप्त की?
(A) 1988
(B) 2001
(C) 2010
(D) 1996

136. 'समाजवादी रास्ता ही सबसे व्यापक रास्ता है' - यह नारा किस देश और किस समय की विचारधारा को दर्शाता है?
(A) क्रांति के तत्काल बाद का चीन
(B) 1990 के दशक का रूस
(C) 1950 का भारत
(D) 1960 का क्यूबा

137. 2003 में यूरोपीय संघ ने क्या बनाने की एक असफल कोशिश की थी, जिसे एक कार्टून में टाइटैनिक जहाज के रूप में दर्शाया गया?
(A) एक साझा सेना
(B) एक साझा बैंक
(C) एक साझा संविधान
(D) एक साझा अंतरिक्ष एजेंसी

138. मास्ट्रिच संधि (1992) का सबसे महत्त्वपूर्ण परिणाम क्या था?
(A) यूरोपीय संघ की स्थापना
(B) यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन
(C) यूरो मुद्रा का अवमूल्यन
(D) नाटो का विस्तार

139. आसियान का कौन सा सदस्य देश संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं था और बाद में शामिल हुआ?
(A) थाईलैंड
(B) सिंगापुर
(C) मलेशिया
(D) वियतनाम

140. 2017 के आंकड़ों के अनुसार, अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से विश्व में जापान और दक्षिण कोरिया का क्रमशः क्या स्थान था?
(A) दूसरा और दसवां
(B) तीसरा और ग्यारहवां
(C) चौथा और बारहवां
(D) पहला और पांचवां

141. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के नेता चाहते थे कि यूरोप अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करे।
2. मार्शल योजना के तहत अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन में मदद की।
3. नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया गया।
4. 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई।
5. 1949 में यूरोपीय परिषद् का गठन राजनीतिक सहयोग की दिशा में एक अगला कदम था।

उपरोक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2, और 3
(B) केवल 2, 3, IV, और 5
(C) केवल 1 और 5
(D) उपरोक्त सभी

142. चीन के आर्थिक सुधारों से पहले, चीन की अर्थव्यवस्था की तुलना सोवियत संघ की राज्य-नियंत्रित आर्थिकी से क्यों की जा सकती है?
(A) क्योंकि दोनों ही बाजार-उन्मुख थीं।
(B) क्योंकि दोनों ही विदेशी निवेश पर बहुत अधिक निर्भर थीं।
(C) क्योंकि दोनों को ही औद्योगिक उत्पादन में तीव्र वृद्धि और उच्च प्रति व्यक्ति आय की समस्या का सामना करना पड़ा।
(D) क्योंकि दोनों को ही औद्योगिक उत्पादन में अपर्याप्त तेजी और कम प्रति व्यक्ति आय जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा।

143. आसियान के प्रतीक चिह्न में वृत्त (गोला) किसका प्रतीक है?
(A) आसियान की एकता का
(B) सदस्य देशों की संख्या का
(C) धान की खेती का
(D) आर्थिक विकास की गति का

144. यूरोपीय संघ के कौन से दो सदस्य देशों ने यूरो को लागू करने के कार्यक्रम का विरोध किया?
(A) फ्रांस और जर्मनी
(B) डेनमार्क और स्वीडन
(C) स्पेन और पुर्तगाल
(D) इटली और ग्रीस

145. 2012 में यूरोपीय संघ को किसलिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
(A) इसके असाधारण और उत्कृष्ट आर्थिक प्रदर्शन के लिए
(B) यूरोप में शांति, लोकतंत्र और मानवाधिकारों हेतु
(C) इसकी विशाल और अत्यधिक प्रभावशाली सैन्य शक्ति हेतु
(D) इसकी महान और ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए

146. आसियान द्वारा कंबोडिया के टकराव को समाप्त करने और पूर्वी तिमोर के संकट को संभालने के लिए किस नीति का उपयोग किया गया?
(A) टकराव के स्थान पर निरंतर बातचीत की नीति
(B) क्षेत्र में सीधे सैन्य हस्तक्षेप करने की सक्रिय नीति
(C) विभिन्न आर्थिक प्रतिबंधों को कड़ाई से लागू करने की नीति
(D) बाहरी महाशक्तियों से प्रत्यक्ष सैन्य मदद मांगने की नीति

147. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 1962 में भारत और चीन के बीच सीमावर्ती लड़ाई हुई।
2. 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध बहाल नहीं हुए।
3. 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया।
4. 1992 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 84 अरब डॉलर का था।

उपरोक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 3 सही हैं।
(B) केवल 1 और 4 सही हैं।
(C) केवल 3 और 4 सही हैं।
(D) सभी कथन सही हैं।

148. चीन ने 1998 में किस क्षेत्र में एक बड़ा सुधार किया?
(A) कृषि का निजीकरण
(B) शिक्षा प्रणाली का उदारीकरण
(C) अपनी मुद्रा का अवमूल्यन
(D) उद्योगों का निजीकरण

149. 2004 में यूरोपीय संघ में शामिल होने वाले दस नए सदस्य मुख्य रूप से किस समूह से थे?
(A) भूतपूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश
(B) उत्तरी अमेरिकी देश
(C) भूतपूर्व सोवियत खेमे के देश
(D) दक्षिण एशियाई देश

150. आसियान, भारत के लिए क्यों महत्त्वपूर्ण है?
(A) क्योंकि भारत वर्तमान में आसियान का एक पूर्ण सदस्य है
(B) एक्ट ईस्ट नीति के तहत व्यापार और निवेश बढ़ाना
(C) क्योंकि आसियान ने भारत को पूर्ण सैन्य सहायता का वादा किया
(D) क्योंकि आसियान के लगभग सभी सदस्य देश हिंदी

बोलते हैं

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
यूरोपीय संघ का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की उस आकांक्षा से प्रेरित था जिसमें यूरोप को स्थायी शांति और समृद्धि के एक क्षेत्र के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी। यह प्रक्रिया आर्थिक एकीकरण से प्रारंभ हुई, जिसका मानना था कि आर्थिक रूप से परस्पर-निर्भर राष्ट्र युद्ध में संलग्न नहीं होंगे। 1957 की रोम की संधि द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) की स्थापना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। तथापि, यूरोपीय संघ के इतिहास में सबसे परिवर्तनकारी क्षण 1992 में मास्ट्रिच संधि के लागू होने के साथ आया। इस संधि ने केवल एक साझा बाजार से आगे बढ़कर एक राजनीतिक संघ की नींव रखी। इसने तीन-स्तंभीय संरचना की स्थापना की: पहला स्तंभ यूरोपीय समुदायों (आर्थिक मामलों को कवर करते हुए), दूसरा स्तंभ साझा विदेश और सुरक्षा नीति (CFSP), और तीसरा स्तंभ न्याय और गृह मामलों में सहयोग। मास्ट्रिच संधि ने ही यूरोपीय नागरिकता की अवधारणा पेश की, जिससे सदस्य देशों के नागरिकों को पूरे संघ में स्वतंत्र रूप से आने-जाने, रहने और काम करने का अधिकार मिला। इस संधि ने आर्थिक और मौद्रिक संघ (EMU) की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त किया, जिसकी परिणति अंततः एकल मुद्रा, यूरो, को अपनाने में हुई। यह आर्थिक से राजनीतिक संघ में परिवर्तन यूरोपीय एकीकरण की गहराई और महत्वाकांक्षा को दर्शाता है।
उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

151. मास्ट्रिच संधि के अनुसार, यूरोपीय संघ की तीन-स्तंभीय संरचना में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था?
(A) साझा विदेश और सुरक्षा नीति
(B) एक एकीकृत यूरोपीय सेना
(C) न्याय और गृह मामलों में सहयोग
(D) यूरोपीय समुदाय

152. स्रोत के अनुसार, यूरोपीय एकीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभिक प्रेरक बल क्या था?
(A) स्थायी शांति और समृद्धि प्राप्त करना
(B) सोवियत संघ के विस्तार का मुकाबला करना
(C) अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देना
(D) एक साझा सांस्कृतिक पहचान बनाना

153. मास्ट्रिच संधि द्वारा प्रस्तुत 'यूरोपीय नागरिकता' की अवधारणा ने नागरिकों को क्या अधिकार प्रदान किया?
(A) अपने मूल राष्ट्र की सीमाओं के भीतर ही मतदान और राजनीतिक भागीदारी का अधिकार
(B) संघ के सभी सदस्य देशों के युवाओं के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा का कठोर प्रावधान
(C) पूरे संघ में स्वतंत्र रूप से आने-जाने, निवास करने और रोजगार प्राप्त करने का अधिकार
(D) यूरोपीय संसद के चुनावों में मतदान करने अथवा चुनाव लड़ने पर कानूनी प्रतिबंध

154. अनुच्छेद के अनुसार, यूरोपीय संघ के संस्थापकों का यह क्यों मानना था कि आर्थिक परस्पर-निर्भरता से शांति स्थापित होगी?
(A) क्योंकि इससे सदस्य राष्ट्रों के वार्षिक सैन्य और रक्षा बजट में भारी कटौती सुनिश्चित होगी
(B) क्योंकि इससे भविष्य में एक एकीकृत यूरोपीय सरकार और साझा सैन्य बल का निर्माण होगा
(C) क्योंकि यह विभिन्न सदस्य राष्ट्रों के बीच आपसी सांस्कृतिक और भाषाई आदान-प्रदान को बढ़ाएगा
(D) क्योंकि आर्थिक रूप से परस्पर-निर्भर राष्ट्रों के लिए युद्ध में शामिल होना तर्कहीन होगा

155. किस संधि ने यूरोपीय संघ को एक साझा बाजार से एक राजनीतिक संघ में परिवर्तित करने की नींव रखी?
(A) रोम की संधि
(B) पेरिस की संधि
(C) मास्ट्रिच संधि
(D) लिस्बन संधि

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन (आसियान) अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया और कूटनीतिक शैली के लिए जाना जाता है, जिसे 'आसियान वे' (ASEAN Way) कहा जाता है। यह दृष्टिकोण यूरोपीय संघ के औपचारिक, कानून-आधारित और अधिराष्ट्रीय मॉडल के विपरीत है। 'आसियान वे' की जड़ें मलय संस्कृति की 'मुशावरा' (विचार-विमर्श) और 'मुफाकत' (सर्वसम्मति) की अवधारणाओं में हैं। इसका सार अनौपचारिक परामर्श और सर्वसम्मति-आधारित निर्णय लेने में निहित है, जहां किसी भी सदस्य द्वारा वीटो का प्रयोग किए बिना आम सहमति बनने तक चर्चा जारी रहती है। इस पद्धति का एक महत्वपूर्ण पहलू 'अहस्तक्षेप' का सिद्धांत है, जिसके अनुसार सदस्य देश एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते। यह सिद्धांत सदस्य राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान करता है, जो संगठन के लिए सर्वोपरि है, विशेष रूप से औपनिवेशिक अतीत को देखते हुए। हालांकि इस दृष्टिकोण की धीमी और कभी-कभी अनिर्णायक होने के लिए आलोचना की जाती है, लेकिन इसके समर्थकों का तर्क है कि इसने क्षेत्र में विश्वास का निर्माण किया है, संघर्षों को बढ़ने से रोका है और अत्यधिक विविध राजनीतिक प्रणालियों और आर्थिक विकास के स्तर वाले देशों के बीच एकता बनाए रखी है। यह टकराव से बचने और सहकारी संबंधों को प्राथमिकता देने पर जोर देता है।
उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

156. 'आसियान वे' की निर्णय लेने की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस पर आधारित है?
(A) बहुमत के मतदान पर
(B) विचार-विमर्श और सर्वसम्मति पर
(C) सबसे शक्तिशाली सदस्य के निर्देशों पर

(D) अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसलों पर

157. स्रोत के अनुसार 'आसियान वे' के संदर्भ में 'अहस्तक्षेप' के सिद्धांत का क्या अर्थ है?
(A) सदस्य देशों को एक-दूसरे के साथ व्यापार नहीं करना चाहिए
(B) सदस्य देश बाहरी शक्तियों से सैन्य सहायता स्वीकार नहीं कर सकते
(C) आसियान अपने सदस्य देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड की निगरानी नहीं करता है
(D) सदस्य देश एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से बचते हैं

158. अनुच्छेद 'आसियान वे' की तुलना यूरोपीय संघ के मॉडल से किस प्रकार करता है?
(A) यह आसियान को अनौपचारिक-परामर्श आधारित और यूरोपीय संघ को औपचारिक मॉडल बताता है
(B) यह दोनों ही क्षेत्रीय संगठनों की कार्यप्रणाली और कूटनीतिक शैली को पूर्णतः समान बताता है
(C) यह आसियान के दृष्टिकोण को यूरोपीय संघ से अधिक औपचारिक और कानून-आधारित बताता है
(D) यह स्पष्ट करता है कि अब यूरोपीय संघ ने पूरी तरह से 'आसियान वे' की कार्यप्रणाली अपना ली है

159. 'मुशावरा' और 'मुफाकत' की सांस्कृतिक अवधारणाएं, जो 'आसियान वे' का आधार हैं, का क्या अर्थ है?
(A) शक्ति और अधिकार
(B) युद्ध और शांति
(C) विचार-विमर्श और सर्वसम्मति
(D) व्यापार और वाणिज्य

160. स्रोत में 'आसियान वे' की संभावित आलोचना के रूप में किस बिंदु का उल्लेख किया गया है?
(A) यह प्रक्रिया धीमी और कभी-कभी अनिर्णायक हो सकती है
(B) यह बहुत महंगा है
(C) यह प्रक्रिया बहुत तेज और जल्दबाजी वाली है
(D) यह सदस्य देशों की संप्रभुता को कमजोर करता है

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

1978 में देंग श्याओपिंग द्वारा शुरू की गई 'खुले द्वार' की नीति के बाद चीन का आर्थिक परिवर्तन विश्व इतिहास में अभूतपूर्व रहा है। इस परिवर्तन की एक प्रमुख विशेषता 'विशेष आर्थिक क्षेत्रों' (Special Economic Zones - SEZs) की स्थापना थी। सोवियत ब्लॉक में अपनाई गई 'शॉक थेरेपी' के विपरीत, जिसने तेज और व्यापक उदारीकरण की वकालत की, चीन ने एक क्रमिक और प्रयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाया। SEZs इस दृष्टिकोण के प्रतीक थे। ये तटीय क्षेत्रों में स्थित छोटे, भौगोलिक रूप से सीमांकित क्षेत्र थे, जैसे कि शेन्ज़ेन, जिन्हें वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए नियंत्रित खिड़कियों के रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इन क्षेत्रों के भीतर, सरकार ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने, बाजार-उन्मुख उद्यमों को प्रोत्साहित करने और नई आर्थिक नीतियों का परीक्षण करने के लिए विशेष नियम और उदार प्रोत्साहन प्रदान किए। यह रणनीति 'पत्थरों को महसूस करके नदी पार करने' के समान थी, जिससे अधिकारियों को बड़े पैमाने पर राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन से पहले नीतियों की प्रभावशीलता का आकलन और समायोजन करने का अवसर मिला। शेन्ज़ेन, जो कभी एक छोटा मछली पकड़ने वाला गाँव था, का एक विशाल महानगर में परिवर्तन SEZ मॉडल की सफलता का सबसे शक्तिशाली प्रमाण है। इन क्षेत्रों ने चीन के वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने और बाद में विश्व व्यापार संगठन (WTO) में इसके सफल एकीकरण की नींव रखी।

उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

161. चीन की आर्थिक सुधार रणनीति सोवियत ब्लॉक की 'शॉक थेरेपी' से किस प्रकार भिन्न थी?
(A) चीन ने पूर्ण आर्थिक अलगाव की नीति चुनी, जबकि सोवियत ब्लॉक ने अपने व्यापारिक द्वार खोले
(B) चीन ने विशेष रूप से केवल कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया, जबकि सोवियत ब्लॉक ने उद्योग को चुना
(C) चीन ने तत्काल अपनी संपूर्ण अर्थव्यवस्था को मुक्त कर दिया, जबकि सोवियत ब्लॉक ने इसे मंद किया
(D) चीन ने एक क्रमिक और प्रयोगात्मक मार्ग चुना, जबकि शॉक थेरेपी तीव्र और व्यापक सुधार थी

162. स्रोत में उल्लिखित 'पत्थरों को महसूस करके नदी पार करने' की उपमा का क्या तात्पर्य है?
(A) जोखिम लेने और अनिश्चितता से बचने की इच्छा।
(B) एक सतर्क, क्रमिक और प्रयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाना।
(C) तेजी से और निर्णायक रूप से कार्य करने की रणनीति।
(D) पारंपरिक तरीकों पर पूरी तरह से निर्भर रहना।

163. चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था?
(A) चीन की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन हेतु सुरक्षित और संरक्षित करना
(B) सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तटीय क्षेत्रों में आधुनिक सैन्य ठिकानों का सुदृढ़ीकरण करना
(C) आर्थिक नीतियों के परीक्षण और विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु नियंत्रित क्षेत्रों के रूप में कार्य करना
(D) बढ़ती हुई ग्रामीण आबादी को रोजगार हेतु नियोजित तरीके से बड़े शहरों की ओर स्थानांतरित करना

164. अनुच्छेद के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सा शहर SEZ मॉडल की सफलता का एक प्रमुख उदाहरण है?
(A) बीजिंग
(B) शंघाई
(C) हांगकांग
(D) शेन्ज़ेन

165. चीन के विशेष आर्थिक क्षेत्र मुख्य रूप से कहाँ स्थित थे और क्यों?
(A) तटीय क्षेत्रों में, वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव को सुविधाजनक बनाने के लिए।
(B) भीतरी इलाकों में, कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए।
(C) उत्तरी सीमा के पास, रूस के साथ व्यापार के लिए।
(D) पूरे देश में समान रूप से, संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
आसियान समुदाय के तीन स्तंभों में से एक, आसियान सुरक्षा समुदाय (ASEAN Security Community - ASC), इस क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए संगठन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ASC एक सैन्य गठबंधन नहीं है, जैसे नाटो। इसके बजाय, यह व्यापक सुरक्षा की अवधारणा पर आधारित है, जिसमें सैन्य पहलुओं के अलावा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे भी शामिल हैं। इसका मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सदस्य देशों के बीच विवाद शांतिपूर्ण ढंग से हल हों और बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप के बिना क्षेत्रीय शांति बनी रहे। ASC के संचालन का मुख्य साधन 1976 में हस्ताक्षरित मैत्री और सहयोग की संधि (Treaty of Amity और Cooperation - TAC) है, जो सदस्य राज्यों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाले प्रमुख सिद्धांतों, जैसे संप्रभुता का सम्मान और बल प्रयोग का त्याग, को निर्धारित करती है। इसके अतिरिक्त, आसियान क्षेत्रीय मंच (ASEAN Regional Forum - ARF), जिसमें आसियान के दस सदस्यों के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस और यूरोपीय संघ जैसी प्रमुख शक्तियां शामिल हैं, विश्वास-निर्माण उपायों और निवारक कूटनीति पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है, जिससे व्यापक एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा संवाद को बढ़ावा मिलता है।
उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

166. आसियान सुरक्षा समुदाय (ASC) और नाटो के बीच मुख्य अंतर क्या है?
(A) ASC एक सैन्य गठबंधन है, जबकि नाटो नहीं है।
(B) ASC एक सैन्य गठबंधन नहीं है, जबकि नाटो है।
(C) ASC में यूरोपीय देश शामिल हैं, जबकि नाटो में एशियाई देश।
(D) ASC और नाटो के बीच कोई अंतर नहीं है।

167. स्रोत के अनुसार, आसियान सुरक्षा समुदाय द्वारा अपनाई गई 'व्यापक सुरक्षा' की अवधारणा में क्या शामिल है?
(A) सदस्य राष्ट्रों की पारंपरिक केवल सैन्य और सीमा सुरक्षा
(B) समग्र सुरक्षा जिसमें सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दे शामिल हैं
(C) सदस्य देशों के बीच केवल आर्थिक और व्यापारिक सुरक्षा
(D) सदस्य राष्ट्रों की केवल आंतरिक पुलिस और कानून व्यवस्था

168. कौन सी संधि आसियान सुरक्षा समुदाय के संचालन के लिए मूलभूत सिद्धांतों को निर्धारित करती है?
(A) मैत्री और सहयोग की संधि (TAC)
(B) बैंकॉक घोषणा
(C) मास्ट्रिच संधि
(D) पेरिस शांति समझौते

169. आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF) की भूमिका क्या है?
(A) एक संयुक्त सैन्य बल बनाना।
(B) सदस्य देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना।
(C) क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर संवाद और विश्वास-निर्माण को बढ़ावा देना।
(D) आसियान देशों के बीच व्यापार विवादों का निपटारा करना।

170. आसियान सुरक्षा समुदाय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(A) बाहरी देशों पर आक्रमण करना।
(B) एक एकल क्षेत्रीय सरकार की स्थापना करना।
(C) सदस्य देशों के लिए एक समान मुद्रा बनाना।
(D) यह सुनिश्चित करना कि विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से हो।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
1999 में यूरो की शुरुआत और 2002 में भौतिक मुद्रा के रूप में इसका प्रचलन, यूरोपीय एकीकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण क्षण था। एकल मुद्रा, जिसे 27 में से 20 सदस्य देशों (जिन्हें सामूहिक रूप से यूरोजोन कहा जाता है) द्वारा अपनाया गया है, ने अमेरिकी डॉलर के वैश्विक प्रभुत्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती पेश की है। यूरो को अपनाने का आर्थिक तर्क सदस्य देशों के बीच लेनदेन लागत को खत्म करना, मूल्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना और व्यापार तथा निवेश को प्रोत्साहित करना था। इसने यूरोजोन को दुनिया के सबसे बड़े एकल बाजारों में से एक बना दिया। फ्रैंकफर्ट में स्थित यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) द्वारा प्रबंधित यूरो, जल्दी ही दुनिया की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण आरक्षित मुद्रा बन गया, जिसका उपयोग दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा किया जाता है। हालांकि, यूरो को गंभीर चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है, विशेष रूप से 2009 के बाद के यूरोजोन संप्रभु ऋण संकट के दौरान। इस संकट ने एक मौद्रिक संघ के भीतर विभिन्न राजकोषीय नीतियों (बजट और कर नीतियां) के अंतर्निहित तनाव को उजागर किया। इस संकट ने दिखाया कि यूरोजोन के कुछ देशों की आर्थिक कमजोरियां पूरे मुद्रा क्षेत्र की स्थिरता को खतरे में डाल सकती हैं। इन चुनौतियों के बावजूद, यूरो अंतरराष्ट्रीय वित्त में एक प्रमुख शक्ति बना हुआ है, जो वैश्विक मंच पर यूरोपीय संघ के आर्थिक वजन का प्रतीक है।
उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

171. स्रोत के अनुसार, यूरो को अपनाने का प्राथमिक आर्थिक तर्क क्या था?
(A) सदस्य देशों के बीच राष्ट्रीय गौरव बढ़ाना।
(B) संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक व्यापार युद्ध शुरु करना।
(C) लेनदेन लागत को खत्म करना और व्यापार को प्रोत्साहित करना।
(D) सदस्य देशों को अपनी स्वतंत्र मौद्रिक नीति बनाए रखने की अनुमति देना।

172. 'यूरोजोन' शब्द का क्या अर्थ है?
(A) यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य देश।
(B) वे यूरोपीय संघ के सदस्य देश जिन्होंने यूरो को अपनी मुद्रा के रुप में अपनाया है।
(C) वे देश जो यूरोपीय संघ में शामिल होना चाहते हैं।
(D) यूरोपीय महाद्वीप पर स्थित सभी देश।

173. यूरो का प्रबंधन किस संस्था द्वारा किया जाता है?
(A) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)
(B) विश्व बैंक
(C) अमेरिकी फेडरल रिजर्व
(D) यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB)

174. यूरोजोन संप्रभु ऋण संकट ने यूरो के बारे में किस अंतर्निहित तनाव को उजागर किया?
(A) एकल मौद्रिक नीति और विविध राष्ट्रीय राजकोषीय नीतियों के बीच का अंतर्निहित तनाव
(B) सदस्य देशों के बीच एक साझा आधिकारिक भाषा और सांस्कृतिक एकता का अभाव
(C) सदस्य राष्ट्रों के बीच ऐतिहासिक संघर्षों से उत्पन्न गहरे भाषाई और सांस्कृतिक मतभेद
(D) यूरोजोन के स्थायी सदस्यों और गैर-यूरोजोन सदस्यों के बीच निरंतर चलने वाले व्यापारिक संघर्ष

175. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में यूरो की क्या स्थिति है?
(A) यह अमेरिकी डॉलर को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर चुका है।
(B) इसका उपयोग केवल यूरोपीय संघ के भीतर ही किया जाता है।
(C) यह दुनिया की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण आरक्षित मुद्रा है।
(D) यह एक अस्थिर और महत्वहीन मुद्रा मानी जाती है।

ANSWERS

1. (B) दो-ध्रुवीय व्यवस्था
1990 के दशक के आरम्भ में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीतयुद्धकालीन दो-ध्रुवीय व्यवस्था का अंत हो गया। इसके परिणामस्वरूप वैश्विक राजनीति में यूरोपीय संघ और आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठन आर्थिक और राजनैतिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों के रूप में उभरे। ये संगठन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शक्ति के संतुलन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

2. (A) यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप के देशों की जर्जर अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए अमेरिका ने मार्शल योजना के माध्यम से भारी आर्थिक सहायता प्रदान की। इसी योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। इस संगठन का प्राथमिक उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देकर विकास सुनिश्चित करना था।

3. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
यूरोपीय संघ ने अपनी यात्रा एक आर्थिक संगठन के रूप में शुरु की थी, लेकिन समय के साथ यह अधिक राजनीतिक होता गया। इसका अपना झंडा, गान और साझा विदेश नीति इसके राजनीतिक स्वरूप को दर्शाते हैं। ये सभी तत्व स्पष्ट करते हैं कि संघ अब केवल व्यापारिक समूह न रहकर एक राजनीतिक और राजनयिक इकाई के रूप में कार्य कर रहा है।

4. (D) यूरोप की एकता और मेलमिलाप
यूरोपीय संघ के झंडे में नीले धरातल पर सोने के रंग के बारह सितारों का घेरा बना हुआ है। बारह की संख्या को पारंपरिक रूप से यूरोप में पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। यह घेरा यूरोप के विभिन्न देशों के लोगों के बीच आपसी मेलमिलाप, एकता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की भावना को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करता है।

5. (C) ब्रिटेन
यूरोपीय संघ की नींव रखने वाले 1951 के पेरिस समझौते और 1957 की रोम संधि में फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग शामिल थे। ब्रिटेन उस समय इन शुरुआती संगठनों का हिस्सा नहीं था और उसने 1973 में यूरोपीय समुदाय की सदस्यता प्राप्त की थी। अतः ब्रिटेन को इस संगठन का संस्थापक सदस्य नहीं माना जा सकता है।

6. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
यूरोपीय एकता के ऐतिहासिक क्रम में 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन हुआ और 1985 में सीमाओं को खोलने हेतु शांगेन संधि हुई। इसके बाद 1992 में मास्ट्रिच संधि के जरिए यूरोपीय संघ की औपचारिक स्थापना की गई। अंततः 2002 में सदस्य देशों ने यूरो को साझी मुद्रा के रूप में अपनाया, जो क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर था।

7. (D) इसकी मुद्रा यूरो, अमरीकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए कोई खतरा नहीं है।
यूरोपीय संघ विश्व की एक अत्यंत शक्तिशाली आर्थिक इकाई है, जिसका वैश्विक व्यापार में हिस्सा अमेरिका से भी अधिक है। इसकी साझा मुद्रा यूरो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पैठ बना रही है और भविष्य में अमेरिकी डॉलर के वैश्विक प्रभुत्व को गंभीर चुनौती दे सकती है। संघ की यह आर्थिक मजबूती इसे विश्व व्यापार संगठन के भीतर एक प्रभावशाली समूह के रूप में स्थापित करती है।

8. (A) EEC और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय (यूरेटम)
वर्ष 1957 में हस्ताक्षरित रोम की संधि यूरोपीय एकीकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। इस संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय (यूरेटम) नामक दो महत्वपूर्ण संगठनों का गठन हुआ। इन समुदायों का मुख्य लक्ष्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को गहरा करना और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए साझा नीतियां बनाना था।

9. (B) केवल 1, 2 और 4 सही हैं।
यूरोपीय संघ वर्तमान में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति होने के साथ-साथ रक्षा बजट के मामले में भी अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। विज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी इसकी स्थिति वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है। हालांकि, इसके केवल फ्रांस के पास ही सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और परमाणु हथियार हैं, सभी सदस्य देशों के पास नहीं।

10. (A) मास्ट्रिच संधि और यूरो
यूरोपीय संघ के भीतर गहरे एकीकरण के प्रयासों का कुछ सदस्य देशों ने विरोध भी किया है। डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिच संधि की कुछ शर्तों को स्वीकार करने और अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के स्थान पर साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को अपनाने का कड़ा प्रतिरोध किया। यह विरोध सदस्य देशों की अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और आर्थिक स्वायत्तता को बनाए रखने की इच्छा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

11. (D) ब्रिटेन हमले के पक्ष में था, जर्मनी-फ्रांस खिलाफ थे
अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच अक्सर गहरे मतभेद दिखाई देते हैं। इराक पर अमेरिकी हमले के दौरान ब्रिटेन ने सक्रिय रूप से सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और अमेरिका का साथ दिया। इसके विपरीत, जर्मनी और फ्रांस जैसे प्रभावशाली यूरोपीय देशों ने इस हमले का कड़ा

विरोध किया। यह उदाहरण दर्शाता है कि संघ की कोई एक साझी विदेश नीति नहीं है।

12. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों ने क्षेत्रीय सहयोग को नया आयाम देने के लिए आसियान की स्थापना की। बांडुंग सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से एकता के शुरुआती प्रयास अनौपचारिक थे और वे इस क्षेत्र की विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने में प्रभावी नहीं रहे। इसलिए, इन देशों ने एक अधिक संरचित और औपचारिक आर्थिक संगठन बनाकर अपनी साझा विकास संबंधी चुनौतियों का मुकाबला करने का निर्णय लिया।

13. (C) इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपींस, सिंगापुर, और थाईलैंड
अगस्त 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) अस्तित्व में आया। इसके पांच मूल संस्थापक देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थे। इन राष्ट्रों का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में आर्थिक विकास की गति को तेज करना और साझा हितों के आधार पर सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिरता को मजबूती प्रदान करना था।

14. (D) मित्रता से बंधे दक्षिण-पूर्व एशिया के दस देश
आसियान के प्रतीक चिह्न में दिखाई गई धान की दस बालियां इस संगठन की एकता और शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये बालियां दक्षिण-पूर्व एशिया के उन दस देशों को इंगित करती हैं जो मित्रता और एकजुटता के अटूट बंधन में बंधे हुए हैं। चिह्न का बाहरी घेरा इन सभी सदस्य राष्ट्रों की अखंडता और सामूहिक क्षेत्रीय सहयोग की भावना का एक सशक्त प्रतीक माना जाता है।

15. (A) 2, 4, 1, 3
इन क्षेत्रीय घटनाओं का क्रम 1967 में बैंकॉक घोषणा से शुरु होता है। इसके बाद भारत ने 1991 में आर्थिक सुधारों के साथ 'लुक ईस्ट' नीति अपनाई। 1994 में सुरक्षा सहयोग हेतु आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF) की स्थापना हुई और अंत में 2003 में सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक स्तंभों के साथ आसियान समुदाय बनाने की दिशा में औपचारिक और ठोस कदम उठाए गए।

16. (B) अनौपचारिक, टकरावरहित और सहयोगात्मक मेल-मिलाप
'आसियान शैली' इस संगठन की कार्यप्रणाली का सबसे विशिष्ट पहलू है, जो इसे यूरोपीय संघ जैसे अन्य समूहों से अलग बनाती है। यह शैली सदस्य देशों के बीच अनौपचारिक बातचीत, आपसी सहयोग और किसी भी प्रकार के सैन्य या राजनीतिक टकराव से बचने की नीति पर आधारित है। इसमें सदस्य देशों की राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लेने पर विशेष जोर दिया जाता है।

17. (B) सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय, और सामाजिक-सांस्कृतिक समुदाय
वर्ष 2003 में आसियान ने अपनी भूमिका का विस्तार करते हुए तीन प्रमुख स्तंभों के आधार पर 'आसियान समुदाय' की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। इनमें सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय शांति सुनिश्चित करने के लिए, आर्थिक समुदाय साझा बाजार बनाने के लिए और सामाजिक-सांस्कृतिक समुदाय आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए गठित किए गए। यह कदम संगठन को अधिक प्रभावी और व्यापक क्षेत्रीय शक्ति बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण था।

18. (B) केवल 1, 2, 3, और 5
आसियान एक सफल क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1967 में हुई और बाद में इसमें ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया शामिल हुए। इसका प्राथमिक लक्ष्य आर्थिक विकास है और यह सदस्य देशों की संप्रभुता का पूरा सम्मान करता है। यूरोपीय संघ के विपरीत, आसियान ने कभी भी खुद को एक अधिराष्ट्रीय संगठन बनाने या साझी मुद्रा लागू करने का लक्ष्य नहीं रखा है।

19. (C) सदस्य देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए
वर्ष 1994 में स्थापित आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF) इस संगठन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों और उनके सहयोगी राष्ट्रों के बीच सुरक्षा और विदेश नीति के मुद्दों पर तालमेल बिठाना है। यह मंच क्षेत्रीय विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाने और विश्वास बहाली के उपायों के माध्यम से दक्षिण-पूर्व एशिया में दीर्घकालिक स्थिरता और शांति बनाए रखने का कार्य करता है।

20. (D) 2014
भारत ने वर्ष 2014 में अपनी पुरानी 'लुक ईस्ट' नीति को नया स्वरुप देते हुए 'एक्ट ईस्ट' नीति की घोषणा की। इस नीति का मुख्य लक्ष्य दक्षिण-पूर्व एशियाई और पूर्वी एशियाई देशों के साथ केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि रणनीतिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा संबंधी संबंधों को और अधिक गहन बनाना है। यह भारत की बदलती वैश्विक प्राथमिकताओं और क्षेत्रीय जुड़ाव की सक्रियता को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करता है।

21. (A) P-2, Q-3, R-1, S-4
विभिन्न नीतियों और क्षेत्रों के संबंधों को देखें तो चीन ने 1978 में 'खुले द्वार की नीति' अपनाई। आसियान दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रमुख क्षेत्रीय संगठन है, जबकि यूरोपीय संघ पूरे यूरोप की एकता का प्रतिनिधित्व करता है। मार्शल योजना अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए शुरु की गई एक महत्वपूर्ण और दूरगामी सहायता कार्यक्रम की पहल थी।

22. (B) आसियान देशों का साझा बाज़ार और उत्पादन आधार तैयार करना
आसियान आर्थिक समुदाय का मुख्य लक्ष्य इस पूरे क्षेत्र में एक साझा बाजार और उत्पादन आधार विकसित करना है। इससे

सदस्य देशों के बीच माल, सेवाओं, निवेश और कुशल श्रम का मुक्त प्रवाह संभव हो सकेगा। यह आर्थिक एकीकरण इस क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती प्रदान करेगा और विकास के नए अवसर सृजित करेगा, जिससे पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया की समृद्धि में व्यापक वृद्धि होगी।

23. (D) देंग श्याओपेंग
चीन के आर्थिक कायाकल्प का श्रेय मुख्य रूप से देंग श्याओपेंग को दिया जाता है, जिन्होंने 1978 में 'खुले द्वार की नीति' की आधिकारिक घोषणा की थी। उन्होंने माओवादी बंद अर्थव्यवस्था के स्थान पर बाजार आधारित सुधारों को अपनाया। इन सुधारों के माध्यम से चीन ने विदेशी निवेश के लिए अपने दरवाजे खोले और अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक व्यापार की मुख्यधारा से जोड़कर अभूतपूर्व विकास हासिल किया।

24. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
1949 की साम्यवादी क्रांति के बाद चीन ने सोवियत मॉडल को अपनाते हुए पूंजीवादी दुनिया से अपने आर्थिक संबंध विच्छेद कर लिए थे। उस समय चीन के पास सीमित संसाधन थे, इसलिए उसने आत्मनिर्भरता की नीति अपनाई और अपने घरेलू संसाधनों से ही औद्योगिक आधार तैयार करने का प्रयास किया। यह मॉडल शुरुआती दौर में सफल रहा लेकिन बढ़ती आबादी के कारण आगे चलकर अपर्याप्त साबित हुआ।

25. (C) शिक्षा
वर्ष 1973 में चीनी प्रधानमंत्री चाऊ एनलाई ने देश के आधुनिकीकरण के लिए चार प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने का प्रस्ताव रखा था। ये क्षेत्र कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी थे। शिक्षा को इन चार विशिष्ट आधुनिकीकरण लक्ष्यों की सूची में शामिल नहीं किया गया था, हालांकि बाद के वर्षों में चीन ने अपनी पूरी शैक्षिक और शोध प्रणाली में व्यापक सुधार और विस्तार किया।

26. (A) अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला।
चीन ने सोवियत संघ की तरह अचानक 'शॉक थेरेपी' अपनाने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे और चरणबद्ध तरीके से खोलने का विवेकपूर्ण निर्णय लिया। उसने सबसे पहले कृषि क्षेत्र में सुधार किए, उसके बाद व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों को विदेशी निवेश के लिए खोला। इस क्रमिक प्रक्रिया ने चीन को आर्थिक अस्थिरता से बचाया और उसे निरंतर विकास की ओर अग्रसर करने में सफलता दिलाई।

27. (D) 1982
चीन में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के तहत वर्ष 1982 में खेती का निजीकरण किया गया। इस महत्वपूर्ण सुधार ने सामूहिक खेती की पुरानी प्रणाली को समाप्त कर दिया और किसानों को अपनी उपज का प्रबंधन करने की अधिक स्वायत्तता दी। इसके सकारात्मक परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय में भारी वृद्धि हुई और कृषि उत्पादन के क्षेत्र में चीन ने उल्लेखनीय और ऐतिहासिक प्रगति दर्ज की।

28. (B) विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
चीन ने विदेशी पूंजी और आधुनिक प्रौद्योगिकी को आकर्षित करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' (SEZ) स्थापित किए। इन क्षेत्रों में विदेशी निवेशकों को विशेष कर रियायतें और बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गईं। इसके परिणामस्वरूप चीन के विदेशी व्यापार और निर्यात में जबरदस्त उछाल आया, जिससे चीन बहुत ही कम समय में दुनिया की एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक और औद्योगिक शक्ति बन गया।

29. (C) 2001
वर्ष 2001 में चीन का विश्व व्यापार संगठन (WTO) में शामिल होना इसकी आर्थिक यात्रा का एक निर्णायक मोड़ था। इस सदस्यता के साथ चीन वैश्विक व्यापार नियमों के दायरे में आ गया और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक उसकी पहुंच और अधिक सुगम हो गई। इससे चीन ने दुनिया भर में अपने उत्पादों का निर्यात बढ़ाया और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति को अत्यंत सुदृढ़ और अपरिहार्य बना लिया।

30. (B) केवल 1, 2 और 3 सही हैं।
चीन के आर्थिक सुधारों ने जहां एक ओर विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए, वहीं इसके कुछ नकारात्मक सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव भी पड़े हैं। देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है और पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंची है। साथ ही, आर्थिक लाभ का वितरण समान नहीं रहा है, जिससे शहरों और गांवों के बीच आय की खाई गहरी हुई है और भ्रष्टाचार में भी निरंतर वृद्धि हुई है।

31. (A) चीन
वर्ष 1997 के दक्षिण-पूर्वी एशियाई वित्तीय संकट के दौरान चीन ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन न करने का साहसिक निर्णय लिया, जिससे इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं को और अधिक गिरने से बचाया जा सका। चीन के निरंतर आर्थिक विकास और निवेश ने आसियान देशों की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्थाओं को सहारा दिया। इससे क्षेत्र में चीन की आर्थिक साख बढ़ी और पड़ोसी देशों के साथ उसके व्यापारिक संबंधों में अधिक प्रगाढ़ता आई।

32. (B) रणनीतिक के साथ आर्थिक पहलू का जुड़ना
शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद भारत और चीन के संबंधों में एक नया और महत्वपूर्ण आयाम जुड़ा है। अब दोनों देशों के बीच संबंधों का आधार केवल सीमा विवाद या रणनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं रह गया है, बल्कि आर्थिक सहयोग भी एक प्रमुख स्तंभ बन गया है। दोनों राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिसने राजनीतिक तनाव के बावजूद संबंधों में निरंतरता और संवाद बनाए रखा है।

33. (A) P-4, Q-1, R-2, S-3
नेताओं और उनकी नीतियों का सही मिलान करने पर स्पष्ट होता है कि राजीव गांधी ने 1988 में चीन का ऐतिहासिक दौरा किया था। चाऊ एनलाई ने चार आधुनिकीकरणों का प्रस्ताव दिया, जबकि देंग श्याओपेंग ने 'खुले द्वार की नीति' की शुरुआत की

थी। मार्गरेट थैचर के कार्यकाल के दौरान ब्रिटेन के यूरोपीय बाजार के प्रति सख्त और अलग रहने की नीति भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में काफी चर्चा का विषय रही थी।

34. (A) चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने के फैसले से
वर्ष 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर अधिकार करने के निर्णय ने भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक मैत्रीपूर्ण संबंधों में दरार पैदा कर दी। भारत ने तिब्बत को एक बफर स्टेट के रूप में देखा था, लेकिन चीन के इस कदम से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सीधे तौर पर उभरकर सामने आ गए। इसके बाद ही दलाई लामा को भारत में शरण देनी पड़ी, जिससे तनाव और बढ़ गया।

35. (C) अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख का अक्साई चिन
भारत और चीन के बीच 1962 का युद्ध मुख्य रूप से दो भौगोलिक क्षेत्रों पर प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय दावों के कारण हुआ था। चीन ने लद्दाख के अक्साई चिन क्षेत्र और उस समय के नेफ़ा (वर्तमान अरुणाचल प्रदेश) के बड़े हिस्से पर अपना अधिकार जताया था। इन क्षेत्रों में चीन की सैन्य घुसपैठ ने एक पूर्ण युद्ध का रूप ले लिया, जिसने दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों को दशकों तक प्रभावित किया।

36. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
1962 के युद्ध में भारत की सैन्य पराजय ने दोनों देशों के बीच गहरे अविश्वास की स्थिति पैदा कर दी थी। इस युद्ध के परिणामस्वरूप आपसी बातचीत का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया और कूटनीतिक संबंध लगभग समाप्त हो गए। संबंधों में यह गतिरोध 1976 तक बना रहा, जब दोनों देशों ने अंततः अपने राजदूतों को पुनः एक-दूसरे की राजधानियों में भेजने और संवाद बहाली का निर्णय लिया।

37. (C) राजीव गांधी
दिसंबर 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा ने दोनों देशों के बीच जमे हुए संबंधों को पिघलाने में अहम भूमिका निभाई। 1962 के युद्ध के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला चीन दौरा था। इस यात्रा के दौरान सीमा विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह बनाने पर सहमति बनी, जिससे संबंधों में सुधार हुआ।

38. (B) विश्व व्यापार संगठन जैसे मंचों पर सहयोग
भारत और चीन के बीच सीमा विवाद, चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का चीनी समर्थन तनाव के मुख्य कारण रहे हैं। हालांकि, विश्व व्यापार संगठन और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर दोनों देश अक्सर विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए एक-दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। यह सहयोग दोनों देशों के बीच मौजूद व्यापक और जटिल संबंधों के सकारात्मक पहलू को दर्शाता है।

39. (D) उपरोक्त सभी
भारत और चीन के संबंध अत्यंत जटिल और बहुआयामी हैं। जहां एक ओर दोनों देशों के बीच व्यापार में 30 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बरकरार हैं। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में चीन की मदद और पड़ोसी देशों म्यांमार एवं बांग्लादेश के साथ चीन के बढ़ते सैन्य संबंध भारतीय हितों के दृष्टिकोण से हमेशा से ही संवेदनशील विषय रहे हैं।

40. (A) जापान
जी-7 विश्व की सात सबसे विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक समूह है। पूरे एशिया महाद्वीप से केवल जापान ही इस विशिष्ट समूह का एकमात्र सदस्य देश है। यह तथ्य जापान की वैश्विक आर्थिक शक्ति और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उसके उच्च स्थान को प्रमाणित करता है। जापान लंबे समय से इस मंच के माध्यम से वैश्विक आर्थिक नीतियों के निर्धारण में अहम भूमिका निभा रहा है।

41. (C) अनुच्छेद 9
जापान का संविधान अपनी विशिष्ट शांतिवादी नीतियों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसके अनुच्छेद 9 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जापानी जनता न्याय और व्यवस्था पर आधारित अंतरराष्ट्रीय शांति की कामना करती है और युद्ध को राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में हमेशा के लिए त्यागती है। यह अनुच्छेद जापान को अपनी सुरक्षा के अलावा किसी भी अन्य सैन्य अभियान से प्रतिबंधित करता है।

42. (A) इसके पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं।
जापान की वास्तविक शक्ति उसके प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों में नहीं, बल्कि उसकी उच्च प्रौद्योगिकी और कुशल मानव श्रम में निहित है। वास्तव में जापान अपनी ऊर्जा और कच्चे माल की जरूरतों के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। इसके बावजूद, जापान विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और संयुक्त राष्ट्र के बजट में भी इसका आर्थिक योगदान वैश्विक स्तर पर काफी अधिक और महत्वपूर्ण माना जाता है।

43. (D) हान नदी पर चमत्कार
दक्षिण कोरिया ने 1960 के दशक से 1980 के दशक के बीच जो अभूतपूर्व और तीव्र आर्थिक प्रगति की, उसे वैश्विक स्तर पर 'हान नदी पर चमत्कार' के नाम से जाना जाता है। इस अवधि के दौरान दक्षिण कोरिया ने एक गरीब कृषि प्रधान देश से बदलकर खुद को एक आधुनिक औद्योगिक और तकनीकी शक्ति के रूप में स्थापित किया। यह नाम सियोल से गुजरने वाली प्रमुख नदी हान से प्रेरित है।

44. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
विभिन्न देशों की विशेषताओं को देखें तो चीन ने 'खुले द्वार की नीति' से आर्थिक सुधार किए, जबकि जापान जी-7 का एकमात्र एशियाई सदस्य है। दक्षिण कोरिया की प्रगति को 'हान नदी पर चमत्कार' कहा जाता है और जर्मनी वर्तमान में यूरोपीय संघ का सबसे शक्तिशाली और आर्थिक रूप से संपन्न सदस्य राष्ट्र है। ये

सभी देश अपने-अपने क्षेत्रों में नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहे हैं और वैश्विक शक्ति केंद्र हैं।

45. (C) 1996
वर्ष 1996 में दक्षिण कोरिया को आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (OECD) की सदस्यता मिलना इसकी आर्थिक सफलता का एक बड़ा प्रमाण था। यह संगठन दुनिया के विकसित और अमीर देशों का एक समूह है। इस मंच में शामिल होने के साथ ही दक्षिण कोरिया की गिनती विश्व के सर्वाधिक विकसित देशों में होने लगी। यह उपलब्धि दक्षिण कोरिया द्वारा दशकों तक किए गए कठोर आर्थिक परिश्रम का ही परिणाम थी।

46. (D) दक्षिण कोरिया
भारत के घरेलू बाजारों में अत्यंत लोकप्रिय और प्रतिष्ठित ब्रांड जैसे सैमसंग, एलजी और हुंडई मूल रूप से दक्षिण कोरिया की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। इन कंपनियों ने इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में अपनी उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकों के माध्यम से वैश्विक पहचान बनाई है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच बढ़ते व्यापारिक संबंधों में इन ब्रांडों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली रहा है।

47. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
यूरोपीय संघ का गठन एक क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम था जो 1992 में अपनी परिणति पर पहुंचा। इस वर्ष मास्ट्रिच संधि पर सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए, जिसने पुराने यूरोपीय समुदायों को एक नई और अधिक व्यापक राजनैतिक और आर्थिक पहचान प्रदान की। इसी संधि के माध्यम से साझी विदेश नीति, सुरक्षा और न्याय जैसे विषयों पर सहयोग के नए ढांचों का निर्माण सफलतापूर्वक किया गया था।

48. (A) 4, 3, 1, 2
यूरोपीय एकीकरण की घटनाओं को देखें तो ब्रिटेन ने 1973 में सदस्यता ली, जिसके बाद 1990 में जर्मनी का ऐतिहासिक एकीकरण हुआ। इसके पश्चात 2009 में लिस्बन संधि लागू हुई जिसने संघ की कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाया। अंत में, 2013 में क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बना। यह कालक्रम दर्शाता है कि यूरोपीय संघ ने निरंतर विस्तार और सुधार के माध्यम से अपनी शक्ति को संगठित किया है।

49. (D) उपरोक्त सभी
यूरोपीय संघ के सामने कई गंभीर चुनौतियां और आंतरिक मतभेद मौजूद हैं। संघ का एक साझा संविधान बनाने का प्रयास जनता के विरोध के कारण विफल हो गया और ब्रिटेन ने ब्रेक्जिट के माध्यम से संघ ही छोड़ दिया। इसके अतिरिक्त, सदस्य देशों के बीच विदेश नीति और यूरो मुद्रा को अपनाने को लेकर भी अक्सर गहरी असहमति दिखाई देती है, जो इसकी राजनीतिक अखंडता को निरंतर प्रभावित करती रहती है।

50. (A) अमरीका
1949 की क्रांति के बाद चीन लंबे समय तक शेष विश्व से कटा रहा, जिसे उसका 'एकांतवास' कहा जाता है। इस अलगाव को समाप्त करने के लिए चीन ने 1972 में अमेरिका के साथ अपने राजनैतिक संबंध बहाल करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इस कदम ने चीन के लिए वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था के नए द्वार खोल दिए और उसे एक उभरती हुई विश्व शक्ति के रूप में स्थापित किया।

51. (C) अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक बहिर्मुखी भूमिका
आसियान विजन 2020 का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अंतरराष्ट्रीय समुदाय में इस संगठन की एक सक्रिय और 'बहिर्मुखी' भूमिका को बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने के लिए संवाद को प्राथमिकता देना और वैश्विक मंचों पर एक संगठित आवाज के रूप में उभरना है। यह विजन आसियान को केवल एक क्षेत्रीय समूह से बदलकर एक प्रभावी वैश्विक हितधारक बनाने की दिशा में केंद्रित है।

52. (B) P-4, Q-2, R-1, S-3
क्षेत्रीय संगठनों और नीतियों का समय काल देखें तो आसियान 1967 में और यूरोपीय संघ 1992 में स्थापित हुए। चीन की 'खुले द्वार की नीति' 1978 में शुरु हुई, जबकि भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति की घोषणा 2014 में की गई थी। ये सभी वर्ष अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नए सत्ता केंद्रों के उभरने और क्षेत्रीय सहयोग के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण मील के पत्थर माने जाते हैं।

53. (C) सहयोग और निरंतर संवाद
आसियान की सफलता का मुख्य आधार 'आसियान शैली' है, जो कठोर नियमों के बजाय आपसी सहयोग और निरंतर संवाद पर जोर देती है। यह संगठन किसी भी प्रकार के सैन्य टकराव के स्थान पर कूटनीतिक समाधान खोजने में विश्वास रखता है। सदस्य देशों की संप्रभुता का सम्मान करना और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना इसकी कार्यप्रणाली का एक अनिवार्य और अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।

54. (B) 1993
1 नवंबर 1993 को मास्ट्रिच संधि के प्रभावी होने के साथ ही 'यूरोपीय आर्थिक समुदाय' का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से 'यूरोपीय समुदाय' कर दिया गया। यह केवल नाम का बदलाव नहीं था, बल्कि यह संगठन के उद्देश्यों में व्यापक विस्तार का प्रतीक था। अब यह समुदाय केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें सामाजिक, राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी साझा नीतियों को भी समाहित किया गया।

55. (A) केवल 3 और 5
चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत ही सूझ-बूझ के साथ चरणबद्ध तरीके से खोला, जिसमें 2001 में विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता लेना एक बड़ा कदम था। व्यापारिक बाधाओं को हटाने के लिए विशिष्ट रूप से 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' (SEZ) बनाए गए जहां विदेशी निवेशकों को विशेष सुविधाएं दी गईं। चीन ने कभी भी अचानक 'शॉक थेरेपी' नहीं अपनाई और न ही कृषि के निजीकरण से ग्रामीण आय घटी।

56. (A) चीन विदेशी निवेश के लिए सर्वाधिक आकर्षक देश बना
1978 के बाद चीन ने बाजार आधारित सुधारों और अपनी 'खुले द्वार की नीति' के माध्यम से दुनिया भर के निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित किया। अपनी विशाल श्रम शक्ति, बेहतर बुनियादी ढांचे और सरकार की सहायक नीतियों के कारण चीन विदेशी निवेश के लिए दुनिया का सबसे पसंदीदा गंतव्य बन गया। इसी निवेश के बल पर चीन ने अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति की और वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बन गया।

57. (C) 38वीं समानांतर
द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कोरियाई प्रायद्वीप को दो हिस्सों में विभाजित करने के लिए 38वीं समानांतर रेखा को आधार बनाया गया था। इसके उत्तर में सोवियत प्रभाव वाला उत्तर कोरिया और दक्षिण में अमेरिकी प्रभाव वाला दक्षिण कोरिया अस्तित्व में आया। 1950-53 के कोरियाई युद्ध के बाद भी यह रेखा दोनों देशों के बीच एक स्थायी और दुनिया की सबसे अधिक सुरक्षित सीमा बनी हुई है।

58. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
आसियान वर्तमान समय में दुनिया के सबसे तेजी से विकसित होने वाले क्षेत्रीय संगठनों में से एक है। इसकी बढ़ती आर्थिक ताकत और रणनीतिक महत्व ने चीन और भारत जैसे बड़े देशों को इसके साथ मुक्त व्यापार समझौते करने के लिए प्रेरित किया है। आसियान की यह बढ़ती प्रासंगिकता ही उसे वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मंच पर एक अत्यंत आकर्षक और शक्तिशाली सत्ता केंद्र के रूप में स्थापित करती है।

59. (D) फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग
यूरोपीय एकीकरण की औपचारिक शुरुआत 1951 में हुई जब छह देशों ने मिलकर यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय (ECSC) का गठन किया। इन देशों में फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग शामिल थे। इन राष्ट्रों का मुख्य उद्देश्य इन दो महत्वपूर्ण संसाधनों के उत्पादन को साझा नियंत्रण में लाकर भविष्य में किसी भी युद्ध की संभावना को पूरी तरह समाप्त करना और आर्थिक सहयोग बढ़ाना था।

60. (B) यूरोपीय देशों में मुक्त यात्रा की अनुमति
शांगेन वीजा यूरोपीय संघ के एक बड़े ऐतिहासिक समझौते का परिणाम है, जो इसके सदस्य देशों के बीच सीमाओं को समाप्त करता है। इस वीजा के माध्यम से पर्यटक और नागरिक बिना किसी पासपोर्ट जांच के शांगेन क्षेत्र में शामिल दर्जनों यूरोपीय देशों में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते हैं। यह व्यवस्था यूरोप में लोगों के सुगम आवागमन, पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई है।

61. (C) डेनमार्क और स्वीडन
यूरोपीय संघ के भीतर पूर्ण आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण का मार्ग हमेशा निष्कंटक नहीं रहा है। डेनमार्क और स्वीडन जैसे देशों ने अपनी राष्ट्रीय पहचान और आर्थिक स्वायत्तता को सुरक्षित रखने के लिए मास्ट्रिच संधि के कुछ प्रावधानों का कड़ा विरोध किया। इन दोनों देशों ने अपनी स्वयं की मुद्रा को बनाए रखने का निर्णय लिया और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को अपनाने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया था।

62. (A) P-2, Q-3, R-4, S-1
विभिन्न संगठनों और देशों के प्रशासनिक केंद्रों को देखें तो आसियान का सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो और चीन की बीजिंग प्रमुख सत्ता केंद्र हैं। यूरोपीय संघ की अधिकांश महत्वपूर्ण संस्थाएं और आयोग ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित हैं, जिसे इस संघ का अघोषित मुख्यालय माना जाता है। ये शहर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और वैश्विक आर्थिक निर्णयों के मुख्य केंद्र के रूप में कार्य करते हैं।

63. (A) माओ त्से-तुंग
चीन में 1949 की सफल साम्यवादी क्रांति का नेतृत्व माओ त्से-तुंग ने किया था, जिसके बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। माओ के शासनकाल के दौरान चीन ने सोवियत मॉडल पर आधारित एक बंद और राज्य-नियंत्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। हालांकि इस दौरान चीन ने बुनियादी ढांचा खड़ा किया, लेकिन बाद में विकास की धीमी गति ने उनके उत्तराधिकारियों को आर्थिक सुधारों और बाज़ारवादी नीतियों की ओर मोड़ा।

64. (B) बेरोजगारी और पर्यावरण को गंभीर नुकसान
चीन के आर्थिक सुधारों ने जहां देश को धनवान बनाया, वहीं इसके गंभीर नकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। औद्योगीकरण की अंधी दौड़ ने चीन के पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है, जिससे वहां प्रदूषण की समस्या विकराल हो गई है। इसके साथ ही, सरकारी उद्यमों के पुनर्गठन के कारण बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है और भ्रष्टाचार ने देश के सामाजिक और प्रशासनिक ढांचे को काफी नुकसान पहुंचाया है।

65. (A) केवल 1, 3 और 4 सही हैं।
यूरोपीय संघ वैश्विक राजनीति में एक प्रभावशाली शक्ति है, जिसका सदस्य फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। संघ की शांति स्थापना की कोशिशों के लिए उसे 2012 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था और क्रोएशिया 2013 में इसका सदस्य बना। यह कहना गलत है कि संघ के पास परमाणु हथियार नहीं हैं, क्योंकि इसके सदस्य फ्रांस के पास परमाणु हथियारों का विशाल भंडार है।

66. (A) ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर होना
'ब्रेक्ज़िट' शब्द 'ब्रिटेन' और 'एग्ज़िट' के मेल से बना है, जो यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की ऐतिहासिक प्रक्रिया को दर्शाता है। जून 2016 में एक जनमत संग्रह के माध्यम से ब्रिटेन की जनता ने संघ छोड़ने का फैसला किया। यह घटना यूरोपीय एकीकरण के इतिहास में एक बड़ा धक्का थी, जिसने भविष्य में यूरोपीय संघ की स्थिरता और प्रभावशीलता पर कई सवाल खड़े कर दिए।

67. (C) थाईलैंड
वर्ष 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पांच मूल राष्ट्रों में थाईलैंड एक प्रमुख संस्थापक सदस्य था। वियतनाम, म्यांमार और लाओस जैसे देश शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद और क्षेत्रीय स्थिरता आने पर काफी बाद में इस संगठन का हिस्सा बने। थाईलैंड ने शुरू से ही आसियान के भीतर एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ और नेतृत्वकारी भूमिका निभाई है, जिससे इस संगठन को मजबूती मिली है।

68. (D) 1950 के दशक में आजादी के बाद
भारत की आजादी और चीन की क्रांति के बाद 1950 के दशक में दोनों देशों के बीच संबंधों का एक सुनहरा दौर था। इसी समय 'हिंदी-चीनी भाई-भाई' का प्रसिद्ध नारा पूरे भारत में गूंजा था। दोनों देशों ने पंचशील के सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किए थे और एशिया की दो महान सभ्यताओं के रूप में मिलकर काम करने का संकल्प लिया था, हालांकि 1962 के युद्ध ने इस दोस्ती को समाप्त कर दिया।

69. (B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
जापान अपनी प्राकृतिक संसाधनों की कमी को अपनी उच्च तकनीकी कुशलता और नवाचार से पूरा करता है। यह सच है कि जापान कच्चे माल के लिए विदेशों पर निर्भर है, लेकिन उसकी आर्थिक सफलता का मुख्य कारण उसका मजबूत औद्योगिक ढांचा और शोध एवं विकास पर निवेश है। संसाधन की कमी होना सीधे तौर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का कारण नहीं है, बल्कि यह उसकी प्रतिकूल परिस्थितियों का हिस्सा है।

70. (B) ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया
आसियान के पांच संस्थापक सदस्यों के बाद संगठन का विस्तार हुआ और पांच अन्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देश इसमें शामिल हुए। ब्रुनेई 1984 में, वियतनाम 1995 में, लाओस और म्यांमार 1997 में और अंततः कंबोडिया 1999 में इसका सदस्य बना। इन देशों के शामिल होने से आसियान की भौगोलिक सीमा पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया में फैल गई और यह एक अधिक समावेशी और शक्तिशाली क्षेत्रीय संगठन के रूप में स्थापित हुआ।

71. (D) इसकी अर्थव्यवस्था का आकार अमरीका और यूरोपीय संघ से बड़ा है।
आसियान एक बहुत ही गतिशील और तेजी से बढ़ता हुआ आर्थिक संगठन है, लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था का कुल आकार अभी भी अमेरिका या यूरोपीय संघ जैसी वैश्विक महाशक्तियों की तुलना में काफी छोटा है। आसियान का मुख्य बल साझा बाजार बनाने, निवेश आकर्षित करने और सेवाओं के मुक्त व्यापार पर है। इसकी प्रगति की दर भले ही तेज हो, लेकिन समग्र आर्थिक भार में यह अभी पीछे है।

72. (A) 4, 3, 2, 1
चीन के आर्थिक विकास के चरणों का सही क्रम चाऊ एनलाई के 1973 के चार आधुनिकीकरण प्रस्तावों से शुरू होता है। इसके बाद 1978 में देंग श्याओपेंग ने 'खुले द्वार की नीति' अपनाई। 1982 में कृषि का निजीकरण हुआ, जिससे ग्रामीण समृद्धि आई। अंततः 2001 में विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश के साथ चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक व्यापार की मुख्यधारा में पूरी तरह से शामिल कर लिया।

73. (C) यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय
वर्ष 1951 में हस्ताक्षरित पेरिस की संधि यूरोपीय एकता की दिशा में पहला औपचारिक और संस्थागत कदम था। इस संधि के माध्यम से 'यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय' (ECSC) की स्थापना की गई। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य यूरोप के इन दो बुनियादी औद्योगिक संसाधनों के उत्पादन को छह देशों के साझा नियंत्रण में लाना था, ताकि भविष्य में युद्ध की संभावनाओं को कम किया जा सके और आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाई जा सके।

74. (A) अमरीका सहित अन्य देशों की नीतियों पर प्रभाव
यूरोपीय संघ की शक्ति केवल आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव भी वैश्विक है। संघ की सामूहिक आवाज और उसकी साझा नीतियां अक्सर अमेरिका और चीन जैसे बड़े देशों के निर्णयों को प्रभावित करती हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार वार्ता, मानवाधिकार और पर्यावरण सुरक्षा जैसे मुद्दों पर यूरोपीय संघ एक निर्णायक भूमिका निभाता है, जिससे इसकी कूटनीतिक धाक पूरी दुनिया में मजबूती से जमी हुई है।

75. (A) P-4, Q-1, R-2, S-3
यूरोपीय संघ के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं का मिलान करने पर स्पष्ट है कि 2009 में लिस्बन संधि लागू हुई थी। 2012 में संघ को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसके अगले ही साल 2013 में क्रोएशिया ने इसकी सदस्यता ली। अंततः, 2016 में ब्रिटेन में हुए ऐतिहासिक ब्रेक्जिट जनमत संग्रह ने पूरे यूरोपीय और वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य को एक नया और चुनौतीपूर्ण मोड़ प्रदान किया था।

76. (B) चीन
'खुले द्वार की नीति' (Open Door Policy) का संबंध मुख्य रूप से चीन से है, जिसकी घोषणा 1978 में की गई थी। इस नीति का उद्देश्य चीन की बंद अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश और तकनीक के लिए खोलना था। इस क्रांतिकारी बदलाव ने चीन को वैश्विक व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बना दिया और इसके फलस्वरूप चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था में कई दशकों तक दो अंकों की वृद्धि दर हासिल करने में सफलता पाई।

77. (C) क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति।
आसियान सुरक्षा समुदाय का मुख्य उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखना है। यह समुदाय इस सिद्धांत पर आधारित है कि सदस्य देशों के बीच कोई भी क्षेत्रीय या राजनीतिक विवाद सैन्य संघर्ष का रूप नहीं लेना चाहिए। यह समुदाय आपसी बातचीत और कूटनीतिक माध्यमों से

समस्याओं को सुलझाने पर बल देता है, जिससे इस क्षेत्र में पिछले कई दशकों से कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ है।

78. (A) केवल 2, 3 और 4
भारत और आसियान के संबंध 1991 की 'लुक ईस्ट' नीति के बाद से काफी मजबूत हुए हैं। भारत ने इस क्षेत्र के प्रमुख देशों जैसे सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। भारत 2010 में आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र का हिस्सा भी बना। हालांकि, भारत आसियान का सदस्य नहीं बल्कि एक संवाद साझेदार है और वह आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF) का भी एक सक्रिय सदस्य है।

79. (A) सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योगों की स्थापना
चीन के शुरुआती आर्थिक मॉडल में कृषि क्षेत्र से प्राप्त होने वाले अधिशेष और पूंजी का उपयोग भारी उद्योगों के निर्माण के लिए किया गया था। सरकार ने इस पूंजी को राज्य-नियंत्रित बड़े कल-कारखानों की स्थापना में निवेश किया ताकि देश औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। यह रणनीति सोवियत विकास मॉडल से प्रेरित थी, जिसका उद्देश्य तेजी से एक मजबूत औद्योगिक आधार तैयार करना था जो भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सके।

80. (B) अमरीका से संबंध बनाकर एकांतवास समाप्त करना
वर्ष 1972 में चीन के नेतृत्व ने वैश्विक राजनीति में एक बड़ा बदलाव करते हुए अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाने की पहल की। इस ऐतिहासिक निर्णय ने चीन के कई दशकों से चले आ रहे राजनैतिक और आर्थिक एकांतवास को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। इसी कदम ने भविष्य में होने वाले बड़े आर्थिक सुधारों और चीन के वैश्विक व्यापारिक मंच पर उदय की ठोस और व्यावहारिक आधारशिला रखी थी।

81. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
1962 के युद्ध के बाद भारत और चीन के बीच जमे हुए बर्फ जैसे संबंधों को पिघलाने में 1988 की राजीव गांधी की यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण रही। इस यात्रा के बाद दोनों देशों ने सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए विश्वास बहाली के उपायों पर काम करना शुरू किया। व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ने से दोनों देशों के बीच तनाव कम हुआ और सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान की गई।

82. (A) यह 1964 में OECD का सदस्य बना।
जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के विनाश के बाद बहुत ही कम समय में अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया। 1964 में विकसित देशों के संगठन OECD की सदस्यता मिलना इसकी आर्थिक प्रगति की एक अंतरराष्ट्रीय मान्यता थी। जापान ऊर्जा के लिए विदेशों पर निर्भर होने के बावजूद अपनी तकनीक और औद्योगिक कुशलता के बल पर दुनिया की एक शीर्ष आर्थिक शक्ति बना हुआ है और वह जी-7 का भी सदस्य है।

83. (C) आयात उन्मुखीकरण
दक्षिण कोरिया की असाधारण प्रगति का राज उसके निर्यात उन्मुखीकरण (Export Orientation) में छिपा है, न कि आयात उन्मुखीकरण में। कोरिया ने अपनी अर्थव्यवस्था को बाहरी दुनिया के लिए खोलकर निर्यात पर विशेष ध्यान दिया। साथ ही, सफल भूमि सुधारों, प्रभावी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और मजबूत पुनर्वितरण नीतियों ने वहां के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और उच्च मानव विकास सूचकांक प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

84. (D) 1979
यूरोपीय संघ में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में 1979 का वर्ष एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसी वर्ष यूरोपीय संसद के सदस्यों के चुनाव के लिए पहली बार सीधे और प्रत्यक्ष मतदान कराए गए। इस व्यवस्था ने यूरोपीय नागरिकों को संघ की नीति निर्धारण प्रक्रिया में सीधे भाग लेने का अवसर दिया और यूरोपीय संघ की संस्थाओं को अधिक लोकतांत्रिक वैधता और जन समर्थन प्रदान करने का कार्य किया।

85. (B) P-2, Q-1, R-4, S-3
विभिन्न तकनीकी ब्रांडों और राजनैतिक संकल्पनाओं को देखें तो सोनी और पैनासोनिक जापान की दिग्गज कंपनियां हैं, जबकि सैमसंग और हुंडई दक्षिण कोरिया की पहचान हैं। चीनी नेता देंग श्याओपेंग ने 'खुले द्वार की नीति' की नींव रखी थी, वहीं आसियान का जन्म 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ हुआ था। ये सभी तत्व एशियाई देशों की प्रगति और उनकी विशिष्ट पहचान को वैश्विक स्तर पर दर्शाते हैं।

86. (B) केवल 1, 2 और 3 सही हैं।
1949 में माओ के नेतृत्व में चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के बाद देश ने राज्य-नियंत्रित विकास मॉडल अपनाया। हालांकि इस दौरान अर्थव्यवस्था में कुछ वृद्धि हुई, लेकिन तेजी से बढ़ती आबादी ने विकास के लाभों को जनता तक पहुंचने से रोक दिया। उस समय चीन में प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम थी, जिसके कारण 1970 के दशक के उत्तरार्द्ध में चीन को अपने पुराने मॉडल में बदलाव करना पड़ा।

87. (D) 1976
1962 के युद्ध ने भारत और चीन के बीच अविश्वास की एक गहरी खाई पैदा कर दी थी, जिसके कारण दोनों देशों ने अपने राजदूत वापस बुला लिए थे। यह कूटनैतिक गतिरोध लगभग 14 वर्षों तक बना रहा। अंततः, 1976 में दोनों देशों ने पुनः राजदूत स्तर के संबंधों को बहाल करने का निर्णय लिया। इसके बाद ही दोनों पड़ोसी देशों के बीच संवाद और सामान्य कूटनैतिक गतिविधियां धीरे-धीरे फिर से शुरु हो पाई थीं।

88. (A) आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक मामलों में दखल
यूरोपीय संघ एक 'अधिराष्ट्रीय संगठन' के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है क्योंकि इसकी शक्तियां केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं। यह संगठन अपने सदस्य देशों के लिए साझा कानून बनाता है जो आर्थिक नीतियों के साथ-साथ राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को भी प्रभावित करते हैं। संघ के पास अपनी संसद और न्यायालय हैं, जो सदस्य देशों की संप्रभुता के साथ तालमेल बिठाते हुए क्षेत्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हैं।

89. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
चीन की वैश्विक आर्थिक शक्ति का सबसे बड़ा आधार उसकी व्यापारिक निर्भरता है। दुनिया के लगभग सभी बड़े देश चीन के साथ अपने गहरे व्यापारिक हितों के कारण उसके साथ बड़े विवादों में उलझने से बचते हैं। अमेरिका, जापान और रूस जैसे राष्ट्र चीन के साथ आर्थिक सहयोग बनाए रखने के लिए अक्सर राजनीतिक और कूटनीतिक मतभेदों को पीछे छोड़ देते हैं, जो चीन की अंतरराष्ट्रीय सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाता है।

90. (A) वियतनाम
आसियान की स्थापना 1967 में मुख्य रूप से पांच देशों - इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा की गई थी। वियतनाम इस संगठन का संस्थापक सदस्य नहीं है; वह शीतयुद्ध के बाद और कंबोडिया संकट के समाधान के बाद 1995 में इसका सातवां सदस्य बना। वियतनाम के शामिल होने से आसियान की पहुंच और प्रभाव हिंद-चीन के साम्यवादी देशों तक भी फैल गया, जो एक महत्वपूर्ण बदलाव था।

91. (D) चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC)
हाल के वर्षों में भारत और चीन के बीच तनाव का एक प्रमुख कारण चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है। भारत इस परियोजना का कड़ा विरोध करता है क्योंकि यह पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरती है, जिसे भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन मानता है। यह रणनीतिक परियोजना दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को प्रभावित करती है, जिससे दोनों देशों के बीच अविश्वास और सुरक्षा संबंधी चिंताएं काफी बढ़ गई हैं।

92. (A) 2, 1, 4, 3
भारत-चीन संबंधों के ऐतिहासिक पड़ावों में सबसे पहले 1950 में चीन ने तिब्बत पर अधिकार किया। इसके बाद 1962 में दोनों देशों के बीच सीमा युद्ध हुआ। 1978 में चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए 'खुले द्वार की नीति' की घोषणा की। संबंधों को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम 1988 में उठाया गया, जब तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण यात्रा की थी।

93. (C) जापान
जापान विश्व का एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसने परमाणु बम की भीषण तबाही और उसके दीर्घकालिक दुष्परिणामों को झेला है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर किए गए परमाणु हमलों ने जापान के सामाजिक और राजनैतिक दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया। इसी त्रासदी के बाद जापान ने एक शांतिवादी संविधान अपनाया और युद्ध को राष्ट्र के अधिकार के रूप में हमेशा के लिए त्याग दिया।

94. (D) यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन
यूरोपीय संघ के निर्माण की लंबी प्रक्रिया की पहली ठोस शुरुआत 1951 में यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय (ECSC) की स्थापना से हुई थी। पेरिस की संधि द्वारा गठित इस संगठन ने यूरोप के दो प्रमुख औद्योगिक संसाधनों पर साझा नियंत्रण स्थापित किया। यह कदम देशों के बीच आर्थिक निर्भरता बढ़ाने और भविष्य के युद्धों को रोकने के लिए उठाया गया था, जिसने आगे चलकर एक एकीकृत यूरोप का आधार तैयार किया।

95. (A) केवल 1, 2, और 3
कोरियाई प्रायद्वीप के दोनों देश 1991 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने, जो उनके कूटनैतिक इतिहास की एक बड़ी घटना थी। दक्षिण कोरिया ने 1996 में OECD में शामिल होकर अपनी आर्थिक शक्ति का लोहा मनवाया और आज वह दुनिया की ग्यारहवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हालांकि, 'हान नदी पर चमत्कार' दक्षिण कोरिया से संबंधित है और सैमसंग तथा एलजी भी दक्षिण कोरियाई ब्रांड हैं, न कि जापानी या चीनी।

96. (B) टकराव के स्थान पर संवाद को प्रोत्साहन देना
'आसियान विजन 2020' इस संगठन का एक दूरदर्शी दस्तावेज है जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक सक्रिय और शांतिपूर्ण भूमिका की परिकल्पना करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए सैन्य बल के स्थान पर निरंतर बातचीत और कूटनीति का उपयोग करना है। यह विजन आसियान को एक ऐसे समूह के रूप में देखता है जो पूरी दुनिया में शांति और सहयोग का संदेश फैलाता है।

97. (B) 1998
चीन ने अपने आर्थिक सुधारों के दूसरे बड़े चरण में वर्ष 1998 में उद्योगों के निजीकरण की प्रक्रिया शुरु की थी। इससे पहले 1982 में कृषि का निजीकरण किया जा चुका था। उद्योगों के निजीकरण ने चीनी अर्थव्यवस्था को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया और विदेशी निवेश के लिए नए अवसर पैदा किए। इस बदलाव ने चीन को सरकारी नियंत्रण वाली सुस्त अर्थव्यवस्था से निकालकर एक गतिशील और बाज़ार-उन्मुख वैश्विक शक्ति में बदल दिया।

98. (A) P-2, Q-1, R-4, S-3
यूरोपीय एकता के पड़ावों को देखें तो 1951 की पेरिस संधि ने ECSC की नींव रखी और 1957 की रोम संधि ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय बनाया। 1992 में मास्ट्रिच संधि के साथ यूरोपीय संघ का उदय हुआ। अंततः 2002 में यूरो मुद्रा के वास्तविक प्रचलन ने सदस्य देशों के बीच आर्थिक एकीकरण को एक ठोस और दृश्य स्वरुप प्रदान किया। यह पूरी प्रक्रिया यूरोप के देशों के बीच बढ़ते गहरे जुड़ाव की कहानी है।

99. (C) शीतयुद्ध से
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देश गंभीर विनाश और राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहे थे। इसी समय शीतयुद्ध की स्थिति ने पश्चिमी यूरोपीय देशों को आपसी सहयोग और मेल-मिलाप के लिए प्रेरित किया। सोवियत संघ के प्रभाव के भय ने उन्हें एकजुट होकर राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए प्रेरित किया, जिससे यूरोप में सहयोग और एकता की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला।

100. (D) सदस्य देशों की परस्पर विरोधी व्यक्तिगत नीतियां
यूरोपीय संघ की एक बड़ी कमजोरी यह है कि इसके सदस्य देश अक्सर महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर एकमत नहीं हो पाते। प्रत्येक देश की अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और राष्ट्रीय हित होते हैं, जो कई बार संघ की साझी विदेश और सुरक्षा नीति के विपरीत चले जाते हैं। इराक युद्ध जैसे संकटों के समय यह विरोधाभास स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आता है, जिससे संघ की सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता काफी प्रभावित होती है।

101. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
आसियान ने जानबूझकर यूरोपीय संघ के विपरीत स्वयं को एक अधिराष्ट्रीय संगठन नहीं बनाया है। आसियान के लिए अपने सदस्य देशों की राष्ट्रीय संप्रभुता और उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यही कारण है कि आसियान ने साझी मुद्रा या साझा कानून थोपने के बजाय अनौपचारिक सहयोग और सर्वसम्मति के आधार पर काम करने का रास्ता चुना है, जिसे 'आसियान शैली' के रूप में जाना जाता है।

102. (B) कंबोडिया के टकराव और पूर्वी तिमोर के संकट
आसियान ने दक्षिण-पूर्व एशिया में शांति स्थापित करने की दिशा में अत्यंत सराहनीय और प्रभावशाली भूमिका निभाई है। इस संगठन ने कंबोडिया में चल रहे लंबे गृहयुद्ध को समाप्त करने के लिए सफल मध्यस्थता की और पूर्वी तिमोर के गंभीर संकट को भी कुशलतापूर्वक संभाला। यह उपलब्धियां दर्शाती हैं कि आसियान केवल एक आर्थिक समूह नहीं है, बल्कि वह क्षेत्रीय सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए एक अनिवार्य मंच बन गया है।

103. (D) दुनिया की सबसे बड़ी और प्रमुख आर्थिक शक्ति बनना
चीन जिस तीव्र गति से आर्थिक प्रगति कर रहा है, उसे देखते हुए अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि 2040 तक वह अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। चीन की विशाल श्रम शक्ति, आधुनिक बुनियादी ढांचा और निर्यात आधारित विकास मॉडल इस दावे को मजबूती प्रदान करते हैं। चीन का यह आर्थिक उभार उसे आने वाले दशकों में विश्व की एकमात्र महाशक्ति के रूप में भी स्थापित कर सकता है।

104. (A) केवल 1 और 2 सही हैं।
चीन की अपार शक्ति का मुख्य स्रोत उसकी विशाल आबादी, समृद्ध संसाधन और बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। चीन वर्तमान में न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए विकास के एक इंजन की तरह कार्य कर रहा है, जिससे उसके पड़ोसी देश भी आर्थिक रूप से जुड़े हुए हैं। हालांकि, चीन का आर्थिक प्रभाव केवल उसके पड़ोसियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसने अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे महाद्वीपों में भी अपनी गहरी पैठ बना ली है।

105. (C) सोवियत संघ
1949 की क्रांति के बाद के शुरुआती वर्षों में चीन को अपने औद्योगिक ढांचे को खड़ा करने के लिए सोवियत संघ से महत्वपूर्ण आर्थिक और तकनीकी सहायता मिली थी। सोवियत विशेषज्ञों ने चीन में भारी उद्योगों की स्थापना और पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में अपनी अहम सलाह दी थी। हालांकि 1960 के दशक के आते-आते दोनों साम्यवादी देशों के बीच वैचारिक और सीमा संबंधी मतभेद इतने बढ़ गए कि उनका यह सहयोग समाप्त हो गया।

106. (A) P-3, Q-1, R-4, S-2
दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रति भारत के जुड़ाव और आसियान के विकास को देखें तो आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। भारत ने अपनी 'लुक ईस्ट' नीति 1991 में और 'एक्ट ईस्ट' नीति 2014 में शुरु की। सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच का गठन हुआ। यह घटनाक्रम दर्शाता है कि समय के साथ भारत और आसियान के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंध कितने गहरे और व्यापक होते गए हैं।

107. (D) दक्षिण कोरिया
1960 से 1980 के दशक के बीच दक्षिण कोरिया ने जिस तीव्र गति से आर्थिक और औद्योगिक प्रगति की, उसे 'हान नदी पर चमत्कार' की संज्ञा दी जाती है। सियोल शहर के बीच से बहने वाली हान नदी के नाम पर पड़ा यह मुहावरा कोरिया के एक गरीब राष्ट्र से एक विकसित वैश्विक शक्ति बनने के सफर को दर्शाता है। इस दौरान दक्षिण कोरिया ने शिक्षा, बुनियादी ढांचे और निर्यात आधारित उद्योगों में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक निवेश किया था।

108. (B) संविधान द्वारा युद्ध त्याग, फिर भी सातवां सैन्य व्यय
जापान की सैन्य स्थिति वैश्विक राजनीति में अत्यंत अद्वितीय है। यद्यपि इसके संविधान का अनुच्छेद 9 अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए युद्ध के प्रयोग का त्याग करता है, फिर भी अपनी सुरक्षा जरूरतों के कारण जापान का रक्षा बजट दुनिया में सातवें स्थान पर है। जापान के पास अपनी एक आधुनिक 'आत्मरक्षा सेना' है जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस है, जिससे वह अपनी सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम और सुदृढ़ है।

109. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
शीतयुद्ध के बाद भारत और चीन के संबंधों में आर्थिक हितों ने एक प्रमुख स्थान ले लिया है। दोनों देशों के बीच व्यापार में जो जबरदस्त उछाल आया है, वह इनके सुधरते संबंधों का सबसे बड़ा प्रमाण है। 1992 में महज कुछ मिलियन डॉलर का व्यापार 2017 तक 84 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यह व्यापारिक जुड़ाव दोनों देशों को एक-दूसरे पर निर्भर बनाता है, जिससे राजनीतिक तनाव के बावजूद सहयोग बना रहता है।

110. (D) यह अमरीकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है।
यूरो यूरोपीय संघ की सामूहिक आर्थिक शक्ति का एक जीवंत प्रतीक है। यह मुद्रा न केवल संघ के भीतर व्यापार को सुगम बनाती है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में भी इसकी साख बहुत ऊंची है। यूरो की मजबूती और व्यापक स्वीकार्यता इसे अमेरिकी डॉलर के एकमात्र वास्तविक वैश्विक विकल्प के

रूप में पेश करती है। भविष्य में यूरो की बढ़ती भूमिका वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डॉलर के दशकों पुराने एकछत्र प्रभुत्व को चुनौती दे सकती है।

111. (A) आसियान शैली
आसियान के सदस्य देशों के बीच काम करने के विशेष और लचीले तरीके को 'आसियान शैली' कहा जाता है। इसमें औपचारिक समझौतों के स्थान पर अनौपचारिक चर्चाओं और सर्वसम्मति पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यह शैली सदस्य देशों के बीच किसी भी संभावित टकराव को टालने और निरंतर सहयोग बनाए रखने में अत्यंत सफल रही है। इसी के कारण आसियान ने क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखते हुए अपनी आर्थिक प्रगति को निरंतर और सुचारू रूप से जारी रखा है।

112. (A) केवल 1, 4, और 5
यूरोपीय संघ के पास अपना ध्वज, गान और विशेष स्थापना दिवस है, जो इसकी साझा पहचान के प्रतीक हैं। हालांकि, यूरो को अपनाना सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य नहीं है और डेनमार्क तथा स्वीडन जैसे देशों ने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा बनाए रखने के लिए इसका विरोध किया है। ब्रिटेन का जनमत संग्रह के जरिए संघ से बाहर होना (ब्रेक्जिट) इस संगठन के इतिहास की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनकर उभरा है।

113. (B) राज्य-नियंत्रित और बंद
1978 के आर्थिक सुधारों से पहले चीनी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में थी और बाहरी दुनिया के लिए लगभग बंद थी। चीन ने सोवियत मॉडल का पालन करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को घरेलू संसाधनों पर आधारित किया था। उस समय विदेशी निवेश और अंतरराष्ट्रीय व्यापार बहुत ही नगण्य था। राज्य ही सभी उत्पादन लक्ष्यों और कीमतों का निर्धारण करता था, जिससे अर्थव्यवस्था में नवाचार और प्रतिस्पर्धा की भारी कमी देखी जाती थी।

114. (A) विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से
चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए देश के तटीय क्षेत्रों में 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' (SEZ) स्थापित किए। इन क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य विदेशी पूंजी, तकनीक और प्रबंधन कौशल को आकर्षित करना था। यहाँ विदेशी कंपनियों को कम करों और सरल नियमों जैसी विशेष सुविधाएं दी गईं। SEZ की सफलता ने चीन को वैश्विक निर्यात का केंद्र बना दिया और उसके विदेशी मुद्रा भंडार में अभूतपूर्व वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

115. (C) राजनैतिक सहयोग (1949)
1949 में यूरोपीय परिषद का गठन यूरोपीय एकीकरण की प्रक्रिया में राजनीतिक सहयोग की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण और शुरुआती कदम था। मार्शल योजना द्वारा शुरु किए गए आर्थिक सहयोग के बाद, इस परिषद की स्थापना का लक्ष्य साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकारों और कानून के शासन को बढ़ावा देना था। इसने यूरोपीय देशों को एक साझा राजनीतिक मंच प्रदान किया, जिसने आगे चलकर यूरोपीय संघ जैसी संस्थाओं के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया।

116. (A) P-4, Q-1, R-2, S-3
विभिन्न अंतरराष्ट्रीय विषयों का मिलान करने पर स्पष्ट है कि ब्रेक्जिट यूनाइटेड किंगडम के संघ से अलग होने की घटना है। विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) चीन की सफल आर्थिक नीति का हिस्सा हैं। आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF) दक्षिण-पूर्व एशिया में सुरक्षा संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जबकि यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय (ECSC) यूरोपीय संघ के पूर्ववर्ती संगठनों में से एक है जिसने यूरोप में एकता की शुरुआती और ठोस नींव रखी थी।

117. (C) चीन
वर्ष 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किए, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी काफी आलोचना हुई थी। उस समय भारत सरकार और कई विशेषज्ञों ने तर्क दिया था कि चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति और परमाणु क्षमता भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। इसलिए, अपनी न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन परीक्षणों को भारत के दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक और उचित ठहराया गया था।

118. (B) म्यांमार
म्यांमार दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। भारत के लिए चिंता का विषय यह है कि म्यांमार के साथ चीन के बढ़ते सैन्य और व्यापारिक संबंध भारतीय सुरक्षा हितों को प्रभावित कर सकते हैं। चीन का हिंद महासागर तक पहुंच बनाने का प्रयास और म्यांमार में उसके द्वारा विकसित किए जा रहे बुनियादी ढांचे को भारत अपनी घेराबंदी के रूप में देखता है, जो दोनों देशों के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है।

119. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
यूरोपीय संघ न केवल एक आर्थिक शक्ति है, बल्कि इसका सैन्य प्रभाव भी बहुत व्यापक और प्रभावशाली है। संघ के पास सामूहिक रूप से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है और इसका रक्षा बजट अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे अधिक है। सदस्य देशों की आधुनिक सैन्य तकनीक और उनके पास मौजूद परमाणु हथियार इसे एक ऐसी वैश्विक शक्ति बनाते हैं जिसे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के किसी भी बड़े मामले में नजरअंदाज करना असंभव है।

120. (A) 12 संख्या पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक है
यूरोपीय संघ के ध्वज में बारह सितारों का होना सदस्य देशों की संख्या पर आधारित नहीं है। यूरोपीय संस्कृति में बारह की संख्या को आध्यात्मिक और पारंपरिक रूप से पूर्णता और एकता का प्रतीक माना जाता है। ये सितारे घेरे के रूप में व्यवस्थित हैं, जो यूरोप के लोगों के बीच आपसी सद्भाव, अखंडता और शांतिपूर्ण मेल-मिलाप को प्रदर्शित करते हैं। यह झंडा पूरे यूरोप की सामूहिक पहचान और साझा भविष्य का एक अत्यंत सशक्त प्रतीक है।

121. (A) केवल 1, 2 और 4 सही हैं।
आसियान की स्थापना 1967 में पांच देशों द्वारा की गई थी और वर्तमान में इसके दस सदस्य देश हैं जो पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका मुख्य सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है जहां से इसकी गतिविधियों का संचालन होता है। भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है, बल्कि वह इसके साथ एक संवाद साझेदार के रूप में जुड़ा हुआ है और कई मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से आर्थिक सहयोग करता है।

122. (A) खेती से उद्योगों हेतु पर्याप्त अधिशेष की कमी
माओ के शासनकाल में चीनी अर्थव्यवस्था को जिस सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, वह कृषि क्षेत्र से पर्याप्त पूंजी न मिल पाना था। चूंकि चीन एक बंद अर्थव्यवस्था थी, उसे औद्योगिक विकास के लिए धन की व्यवस्था घरेलू स्तर पर ही करनी थी। खेती की पुरानी और अकुशल तकनीक के कारण इतना अधिशेष पैदा नहीं हो पा रहा था जो तेजी से बढ़ते उद्योगों की जरूरतों और बढ़ती आबादी की मांगों को एक साथ पूरा कर सके।

123. (D) भ्रष्टाचार और अमीर-गरीब के बीच बढ़ती खाई
चीन ने भले ही जबरदस्त आर्थिक वृद्धि हासिल की है, लेकिन उसके समाज में भ्रष्टाचार एक गहरी और गंभीर समस्या बन गया है। इसके अलावा, विकास का लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंचा है, जिससे अमीर और गरीब के बीच का फासला बहुत बढ़ गया है। तटीय शहरों और आंतरिक ग्रामीण इलाकों के बीच आय और सुविधाओं की यह असमानता चीन के भविष्य की स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती और चिंता का विषय बनी हुई है।

124. (B) यूरोपीय संघ
यूरोपीय संघ दुनिया के सबसे विकसित और प्रभावशाली 'अधिराष्ट्रीय संगठनों' का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह संगठन अपने सदस्य देशों के लिए साझी नीतियां और कानून बनाता है जो सीधे तौर पर उनके आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं। सार्क या आसियान जैसे अन्य संगठनों की तुलना में यूरोपीय संघ के पास अधिक संस्थागत शक्ति है, जो इसे सदस्य राष्ट्रों की संप्रभुता के कुछ हिस्सों पर निर्णय लेने में सक्षम और प्रभावी बनाती है।

125. (C) वैचारिक मुद्दों की जगह व्यावहारिक मुद्दे प्रमुख हो गए।
1970 के दशक के अंत में चीन के नेतृत्व ने अपनी कट्टर माओवादी विचारधारा को पीछे छोड़कर व्यावहारिकता (Pragmatism) को अपनाना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि केवल नारों से देश का विकास नहीं हो सकता। इसके बाद ही आर्थिक लाभ और आधुनिक तकनीक प्राप्त करने के लिए बाजार सुधारों की शुरुआत की गई। अब नीतियों का आधार यह नहीं था कि वे कितनी साम्यवादी हैं, बल्कि यह था कि वे चीन की अर्थव्यवस्था को कितना मजबूत और प्रतिस्पर्धी बना सकती हैं।

126. (D) विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने का मसला
भारत और चीन दोनों ही दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं और दोनों को अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारी मात्रा में तेल और गैस की जरूरत है। हाल के वर्षों में दोनों देशों ने विदेशों में ऊर्जा संसाधनों के लिए एक-दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय आपसी सहयोग करने पर सहमति जताई है। यह सहयोग दोनों राष्ट्रों के आर्थिक हितों को सुरक्षित करने और वैश्विक ऊर्जा बाजार में अपनी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने के लिए किया गया है।

127. (B) केवल 2, 3, और 4
भारत-चीन संबंधों के इतिहास को देखें तो 1962 के युद्ध का बहुत गहरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिससे 1976 तक दोनों के बीच राजदूत स्तर के संबंध पूरी तरह समाप्त रहे। संबंधों को पुनः पटरी पर लाने के लिए 1981 में सीमा वार्ताएं शुरु हुईं और 1988 में राजीव गांधी की यात्रा ने इस प्रक्रिया को नई गति दी। शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद संबंधों में और भी सकारात्मक बदलाव आए, विशेषकर व्यापारिक और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर खुले।

128. (B) जी-7 (समूह-7)
जी-7 विश्व की शीर्ष विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली समूह है। पूरे एशिया महाद्वीप में केवल जापान ही इस समूह का एकमात्र सदस्य राष्ट्र है, जो इसे वैश्विक आर्थिक नीतियों के निर्धारण में एक अद्वितीय और नेतृत्वकारी स्थान प्रदान करता है। चीन या भारत जैसे बड़े देश अभी तक इस समूह का हिस्सा नहीं बन पाए हैं, जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय और राजनीतिक व्यवस्था में जापान की विशेष और प्रभावशाली स्थिति को स्पष्ट रूप से उजागर करता है।

129. (B) आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक विकास
आसियान की स्थापना के समय सदस्य देशों का प्राथमिक ध्यान सुरक्षा या सैन्य गठबंधन बनाने पर नहीं था। उनका मुख्य लक्ष्य क्षेत्र में आर्थिक विकास की दर को तेज करना और सदस्य राष्ट्रों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना था। उन्होंने माना कि गरीबी को दूर करके और साझा हितों पर काम करके ही दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता लाई जा सकती है। इसी उद्देश्य ने आसियान को एक सफल आर्थिक समूह के रूप में विकसित किया।

130. (A) फ्रांस
फ्रांस यूरोपीय संघ का एक ऐसा प्रमुख सदस्य देश है जो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति के मामले में बहुत ही उच्च स्थान रखता है। यह न केवल परमाणु हथियारों से लैस है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति रखने वाला एक स्थायी सदस्य भी है। फ्रांस की यह वैश्विक स्थिति यूरोपीय संघ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक कूटनीतिक वजन और रणनीतिक गहराई प्रदान करती है, जिससे संघ की बात को पूरी दुनिया में गंभीरता से सुना और माना जाता है।

131. (C) पूर्वी एशियाई देशों से आर्थिक संबंधों में वृद्धि
भारत ने 1991 में शीतयुद्ध की समाप्ति और अपनी अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के समय 'लुक ईस्ट' नीति की शुरुआत की थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों और पूर्वी एशिया के विकसित देशों के साथ आर्थिक, व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूती प्रदान करना था। भारत चाहता था कि वह इस क्षेत्र के तेजी से बढ़ते बाजारों का लाभ उठाए और अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक आर्थिक केंद्रों के साथ जोड़कर विकास की नई गति प्राप्त करे।

132. (D) चरणबद्ध ढंग से, पहले कृषि फिर उद्योग।
चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को बाज़ार के अनुकूल बनाने के लिए एक अत्यंत सतर्क और क्रमिक रास्ता अपनाया। उसने सोवियत संघ की तरह अचानक बदलाव करने के बजाय धीरे-धीरे सुधार लागू किए। सबसे पहले 1982 में कृषि क्षेत्र में व्यक्तिगत जिम्मेदारी प्रणाली लागू की गई, और जब यह सफल रही, तब 1998 में उद्योगों के निजीकरण की दिशा में कदम बढ़ाए गए। इस चरणबद्ध तरीके ने चीन को आर्थिक झटकों से बचाया और उसे निरंतर विकास की ओर बढ़ने में मदद की।

133. (C) सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक समुदाय
वर्ष 2003 में आसियान ने अपनी भावी दिशा तय करते हुए तीन प्रमुख स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय के निर्माण का संकल्प लिया। इसमें सुरक्षा समुदाय का लक्ष्य क्षेत्रीय शांति बनाए रखना, आर्थिक समुदाय का लक्ष्य एक साझा बाजार विकसित करना और सामाजिक-सांस्कृतिक समुदाय का लक्ष्य लोगों के बीच आपसी जुड़ाव बढ़ाना है। ये तीन स्तंभ सामूहिक रूप से आसियान को एक अधिक एकीकृत, आत्मनिर्भर और विश्व मंच पर प्रभावशाली क्षेत्रीय इकाई बनाने के लिए समर्पित और प्रयासरत हैं।

134. (B) केवल 2 और 3 सही हैं।
यूरोपीय संघ विश्व व्यापार के क्षेत्र में अमेरिका से तीन गुना अधिक हिस्सेदारी रखता है, जो इसे एक अत्यंत शक्तिशाली आर्थिक समूह बनाता है। इसकी साझा मुद्रा यूरो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी मजबूत है और यह अमेरिकी डॉलर के दशकों पुराने वर्चस्व को चुनौती देने की पूरी क्षमता रखती है। वर्तमान में यूरोपीय संघ विश्व व्यापार संगठन के भीतर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक शक्ति के रूप में कार्य करता है, जिसकी आर्थिक नीतियों का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है।

135. (D) 1996
दक्षिण कोरिया को 1996 में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (OECD) की सदस्यता मिलना उसकी शानदार आर्थिक यात्रा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवशाली पड़ाव था। यह संगठन दुनिया के सबसे विकसित और अमीर देशों का एक विशेष क्लब माना जाता है। इस सदस्यता ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह प्रमाणित कर दिया कि दक्षिण कोरिया अब एक विकसित औद्योगिक राष्ट्र बन चुका है। यह उपलब्धि दक्षिण कोरिया की सरकार और उसकी जनता के दशकों के कठिन परिश्रम और दूरदर्शी आर्थिक नीतियों का सफल परिणाम थी।

136. (A) क्रांति के तत्काल बाद का चीन
'समाजवादी रास्ता ही सबसे व्यापक रास्ता है' यह नारा 1949 की साम्यवादी क्रांति के बाद के प्रारंभिक वर्षों के चीन की राजनीतिक विचारधारा का मुख्य स्वर था। उस समय चीन का नेतृत्व यह मानता था कि केवल सोवियत संघ द्वारा दिखाए गए समाजवादी और राज्य-नियंत्रित आर्थिक मॉडल से ही देश का कायाकल्प किया जा सकता है। इसी विचारधारा के तहत चीन ने अपनी पूरी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को संगठित किया था, जो कई दशकों तक वहां की नीतियों का मुख्य आधार बना रहा।

137. (C) एक साझा संविधान
वर्ष 2003 में यूरोपीय संघ ने सदस्य देशों के बीच राजनीतिक एकता को और अधिक गहरा करने के लिए एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की थी। हालांकि, यह प्रयास तब पूरी तरह विफल हो गया जब फ्रांस और नीदरलैंड जैसे प्रमुख सदस्य देशों की जनता ने जनमत संग्रह के माध्यम से इस संविधान को अपनाने से इनकार कर दिया। इस विफलता को दर्शाने के लिए अक्सर कार्टूनों में इसे डूबते हुए टाइटैनिक जहाज के रूप में चित्रित किया जाता है, जो संघ के भीतर के आंतरिक विरोध को उजागर करता है।

138. (A) यूरोपीय संघ की स्थापना
1992 में हस्ताक्षरित मास्ट्रिच संधि यूरोपीय एकीकरण के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और दूरगामी संधि मानी जाती है। इसी संधि के माध्यम से पुराने 'यूरोपीय समुदायों' का विलय कर औपचारिक रूप से 'यूरोपीय संघ' का गठन किया गया था। इस संधि ने संघ के लिए साझी विदेश और सुरक्षा नीति, नागरिकता और न्याय के क्षेत्र में सहयोग के नए आयाम स्थापित किए। इसी ऐतिहासिक संधि ने आधुनिक यूरोपीय संघ के राजनैतिक और कानूनी ढांचे की मजबूत नींव रखने का कार्य सफलतापूर्वक किया था।

139. (D) वियतनाम
वियतनाम आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है; वह काफी समय बाद जुलाई 1995 में इस संगठन का हिस्सा बना था। 1967 में स्थापना के समय केवल पांच देश इसके सदस्य थे, जबकि वियतनाम का शामिल होना शीतयुद्ध की समाप्ति और क्षेत्रीय कूटनीतिक बदलावों का एक बड़ा परिणाम था। वियतनाम के प्रवेश ने आसियान को हिंद-चीन क्षेत्र में विस्तार करने और एक अधिक व्यापक क्षेत्रीय संगठन के रूप में उभरने में मदद की, जो इसकी सफलता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था।

140. (B) तीसरा और ग्यारहवां
वर्ष 2017 के वैश्विक आर्थिक आंकड़ों के अनुसार, जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति मजबूत बनाए हुए था। वहीं दूसरी ओर, दक्षिण कोरिया ने अपनी तीव्र औद्योगिक प्रगति और तकनीकी निर्यात के बल पर विश्व की ग्यारहवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का गौरव हासिल किया था। ये दोनों देश न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया के आर्थिक परिदृश्य में अत्यंत प्रभावशाली और

निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जो इनकी मजबूत औद्योगिक बुनियाद को दर्शाता है।

141. (B) केवल 2, 3, IV, और 5
दूसरे विश्व युद्ध के विनाश के बाद यूरोप के नेताओं ने आपसी दुश्मनी को खत्म कर सहयोग का रास्ता चुना। अमेरिका ने मार्शल योजना के जरिए आर्थिक मदद दी और नाटो ने सामूहिक सुरक्षा का ढांचा तैयार किया। इसके बाद 1948 में OEEC और 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन हुआ, जिसने आर्थिक और राजनैतिक सहयोग की ठोस नींव रखी। इन संस्थाओं ने ही भविष्य के एकीकृत यूरोप और यूरोपीय संघ के निर्माण की दिशा में क्रमिक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए थे।

142. (D) क्योंकि दोनों को ही औद्योगिक उत्पादन में अपर्याप्त तेजी और कम प्रति व्यक्ति आय जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा।
सुधारों से पहले चीनी अर्थव्यवस्था पूरी तरह सोवियत मॉडल पर आधारित थी, जो राज्य-नियंत्रित और बाहरी दुनिया के लिए बंद थी। इस व्यवस्था के कारण दोनों ही देशों में औद्योगिक उत्पादन की गति धीमी हो गई थी और तकनीकी रूप से पिछड़ापन घर कर गया था। जनता की प्रति व्यक्ति आय भी वैश्विक औसत की तुलना में काफी कम थी। इसी आर्थिक गतिरोध और बढ़ती बेरोजगारी ने अंततः दोनों देशों के नेतृत्व को अपनी आर्थिक नीतियों में बुनियादी बदलाव करने के लिए मजबूर किया था।

143. (A) आसियान की एकता का
आसियान के आधिकारिक प्रतीक चिह्न में धान की दस बालियों के चारों ओर बना हुआ घेरा (वृत्त) अत्यंत प्रतीकात्मक है। यह वृत्त इस संगठन के सभी सदस्य देशों के बीच अटूट एकता और अखंडता को प्रदर्शित करता है। यह इस बात का संकेत है कि सभी सदस्य राष्ट्र अपनी विविधता के बावजूद एक साझा उद्देश्य और क्षेत्रीय पहचान के साथ एकजुट हैं। यह घेरा आसियान की उस सामूहिक शक्ति और एकजुटता को दर्शाता है जो इस पूरे क्षेत्र की शांति और समृद्धि का मुख्य आधार है।

144. (B) डेनमार्क और स्वीडन
यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देश साझी मुद्रा यूरो को अपनाने के लिए राजी नहीं हुए हैं। डेनमार्क और स्वीडन दो ऐसे प्रमुख देश हैं जिन्होंने अपनी राष्ट्रीय पहचान और आर्थिक संप्रभुता को प्राथमिकता देते हुए यूरो को लागू करने का विरोध किया और अपनी स्वयं की मुद्राओं को बनाए रखा। यह उदाहरण दर्शाता है कि यूरोपीय एकीकरण की प्रक्रिया में सदस्य देशों के बीच अपनी राष्ट्रीय स्वायत्तता और संघ के सामूहिक हितों के बीच एक निरंतर और जटिल संतुलन की स्थिति बनी रहती है।

145. (B) यूरोप में शांति, लोकतंत्र और मानवाधिकारों हेतु
वर्ष 2012 में यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना इसके दशकों लंबे प्रयासों की एक बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय मान्यता थी। यह पुरस्कार संघ द्वारा यूरोप में छह दशकों से अधिक समय तक शांति बनाए रखने, लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने और मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए दिया गया था। इसने यह प्रमाणित किया कि संघ ने पुराने दुश्मनों को करीब लाकर यूरोप को युद्ध के महाद्वीप से बदलकर शांति और सहयोग के क्षेत्र में सफलतापूर्वक बदल दिया है।

146. (A) टकराव के स्थान पर निरंतर बातचीत की नीति
आसियान ने कंबोडिया के गृहयुद्ध और पूर्वी तिमोर के संकट जैसे जटिल मुद्दों को सुलझाने के लिए 'आसियान शैली' का प्रभावी उपयोग किया। इस नीति के तहत सैन्य हस्तक्षेप या कठोर प्रतिबंधों के बजाय सभी संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संवाद और कूटनीतिक मध्यस्थता को प्राथमिकता दी गई। इस दृष्टिकोण ने न केवल इन संकटों को शांत करने में मदद की, बल्कि क्षेत्र में शांति और विश्वास का वातावरण भी बनाया, जिससे यह संगठन विवादों को सुलझाने का एक विश्वसनीय और प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय मंच बना।

147. (A) केवल 1, 2 और 3 सही हैं।
भारत-चीन संबंधों के इतिहास के मुख्य बिंदुओं में 1962 का युद्ध और उसके बाद 1976 तक कूटनीतिक संबंधों का पूरी तरह निलंबित रहना शामिल है। 1988 में राजीव गांधी की चीन यात्रा ने दोनों देशों के बीच संवाद का एक नया युग शुरु किया था। हालांकि 2017 में द्विपक्षीय व्यापार 84 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, लेकिन 1992 में यह राशि बहुत कम थी। यह कालक्रम दर्शाता है कि राजनीतिक तनाव के बावजूद दोनों देशों ने धीरे-धीरे आर्थिक सहयोग के रास्ते तलाशे हैं।

148. (D) उद्योगों का निजीकरण
चीन ने अपने आर्थिक सुधारों के क्रम में 1982 में कृषि का निजीकरण करने के बाद, वर्ष 1998 में उद्योगों के निजीकरण की दिशा में एक बहुत ही साहसिक और महत्वपूर्ण कदम उठाया था। इस सुधार के माध्यम से राज्य-नियंत्रित उद्यमों को बाज़ार की प्रतिस्पर्धा के लिए खोला गया और निजी निवेश को प्रोत्साहित किया गया। इसने चीन की औद्योगिक दक्षता को बढ़ाने और उसे वैश्विक बाजार का एक शक्तिशाली खिलाड़ी बनाने में अहम भूमिका निभाई, जिससे चीन की आर्थिक विकास दर को नई और लंबी ऊंचाई मिली।

149. (C) भूतपूर्व सोवियत खेमे के देश
वर्ष 2004 में यूरोपीय संघ का अब तक का सबसे बड़ा विस्तार हुआ जब इसमें दस नए सदस्य देश एक साथ शामिल हुए। इनमें से अधिकांश देश पूर्वी यूरोप के थे और पूर्व में सोवियत संघ के प्रभाव वाले साम्यवादी खेमे का हिस्सा रहे थे। इन देशों का शामिल होना शीतयुद्ध की कड़वाहट को भुलाकर पूरे यूरोप के एकीकरण की दिशा में एक महान ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इसने संघ की भौगोलिक सीमा और उसकी बाजार शक्ति को और अधिक विस्तार प्रदान किया, जिससे संघ वैश्विक मंच पर और मजबूत हुआ।

150. (B) एक्ट ईस्ट नीति के तहत व्यापार और निवेश बढ़ाना
आसियान भारत की विदेश नीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है, विशेषकर 'एक्ट ईस्ट' नीति के संदर्भ में। भारत के लिए आसियान देशों के साथ गहरे आर्थिक और रणनीतिक

संबंध बनाना अनिवार्य है ताकि व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सके। आसियान के साथ मजबूत साझेदारी भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया के गतिशील बाजारों तक पहुंच प्रदान करती है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और शक्ति संतुलन बनाए रखने में भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और नेतृत्वकारी भूमिका निभाने में सक्षम बनाती है।

151. (B) एक एकीकृत यूरोपीय सेना
मास्ट्रिच संधि ने यूरोपीय संघ के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने आर्थिक एकीकरण से परे एक राजनीतिक संघ की नींव रखी। इस संधि के तहत तीन मुख्य स्तंभ स्थापित किए गए थे: यूरोपीय समुदाय, साझा विदेश और सुरक्षा नीति, तथा न्याय और गृह मामलों में सहयोग। इसमें एक एकीकृत यूरोपीय सेना के गठन का कोई प्रावधान शामिल नहीं था।

152. (A) स्थायी शांति और समृद्धि प्राप्त करना
द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका के बाद, यूरोपीय राष्ट्रों ने एक ऐसे क्षेत्र के निर्माण की आकांक्षा की जहाँ भविष्य में युद्धों की संभावना समाप्त हो सके। एकीकरण की इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से परस्पर-निर्भर राष्ट्रों के माध्यम से स्थायी शांति और समृद्धि सुनिश्चित करना था। इसी दृष्टिकोण ने यूरोपीय देशों को सहयोग के पथ पर अग्रसर किया।

153. (C) पूरे संघ में स्वतंत्र रूप से आने-जाने, निवास करने और रोजगार प्राप्त करने का अधिकार
मास्ट्रिच संधि ने यूरोपीय नागरिकता की एक नई और क्रांतिकारी अवधारणा को जन्म दिया, जिसने सदस्य देशों के निवासियों की पहचान को व्यापक बनाया। इसके अंतर्गत नागरिकों को यह विशेष अधिकार प्राप्त हुआ कि वे संघ के किसी भी सदस्य देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर बिना किसी बाधा के आवाजाही कर सकते हैं, वहाँ स्थायी रूप से रह सकते हैं और रोजगार पा सकते हैं।

154. (D) क्योंकि आर्थिक रूप से परस्पर-निर्भर राष्ट्रों के लिए युद्ध में शामिल होना तर्कहीन होगा
यूरोपीय एकीकरण के पीछे का आर्थिक तर्क यह था कि जब राष्ट्र व्यापार और संसाधनों के लिए एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो उनके बीच सैन्य संघर्ष के आर्थिक परिणाम विनाशकारी होते हैं। ऐसी स्थिति में युद्ध एक तर्कहीन विकल्प बन जाता है। इस परस्पर-निर्भरता ने राष्ट्रों के बीच साझा हितों को बढ़ावा दिया, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और शांति सुनिश्चित हुई।

155. (C) मास्ट्रिच संधि
यूरोपीय संघ के इतिहास में 1992 की मास्ट्रिच संधि को सबसे परिवर्तनकारी क्षण माना जाता है। इससे पहले यूरोप मुख्य रूप से एक आर्थिक समुदाय के रूप में कार्य कर रहा था, लेकिन इस संधि ने इसे एक व्यापक राजनीतिक संघ में बदल दिया। इसने एकल मुद्रा के मार्ग को प्रशस्त किया और विदेश नीति तथा न्याय जैसे क्षेत्रों में सहयोग को औपचारिक रूप दिया।

156. (B) विचार-विमर्श और सर्वसम्मति पर
दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन की कार्यप्रणाली अपनी अनूठी कूटनीतिक शैली के लिए प्रसिद्ध है। यह मॉडल औपचारिक नियमों के बजाय अनौपचारिक चर्चाओं और आपसी रजामंदी को महत्व देता है। इसमें किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुँचने के लिए तब तक विचार-विमर्श किया जाता है जब तक कि सभी सदस्य राष्ट्र एक साझा बिंदु पर सहमत न हो जाएँ, जिससे क्षेत्रीय एकता बनी रहती है।

157. (D) सदस्य देश एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से बचते हैं
आसियान की सफलता का एक प्रमुख आधार 'अहस्तक्षेप' का सिद्धांत है, जो प्रत्येक सदस्य राष्ट्र की संप्रभुता का पूर्ण सम्मान करता है। इसके अनुसार, संगठन का कोई भी देश दूसरे सदस्य की घरेलू राजनीति या आंतरिक समस्याओं में दखल नहीं देता है। यह दृष्टिकोण औपनिवेशिक अतीत वाले इन देशों के बीच विश्वास को मजबूत करने और अनावश्यक क्षेत्रीय तनाव को रोकने में सहायक होता है।

158. (A) यह आसियान को अनौपचारिक-परामर्श आधारित और यूरोपीय संघ को औपचारिक मॉडल बताता है
क्षेत्रीय सहयोग के दो प्रमुख मॉडलों के बीच कूटनीतिक शैली का स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। जहाँ यूरोपीय संघ एक कानून-आधारित और औपचारिक संरचना का पालन करता है, वहीं आसियान का दृष्टिकोण अधिक अनौपचारिक और परामर्श पर आधारित है। आसियान में सदस्य राष्ट्रों के बीच आपसी संबंधों को संप्रभुता के सम्मान और सर्वसम्मति के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है, जो यूरोपीय मॉडल से भिन्न है।

159. (C) विचार-विमर्श और सर्वसम्मति
'आसियान वे' की जड़ें मलय संस्कृति की दो अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणाओं में गहराई से समाहित हैं। 'मुशावरा' का तात्पर्य सामूहिक रूप से गहन चर्चा और विचार-विमर्श करने से है, जबकि 'मुफाकत' का अर्थ आपसी सहमति या सर्वसम्मति प्राप्त करना है। ये दोनों अवधारणाएँ मिलकर एक ऐसी निर्णय प्रक्रिया का निर्माण करती हैं जहाँ टकराव के बजाय सहयोग और कूटनीतिक संवाद को प्राथमिकता दी जाती है।

160. (A) यह प्रक्रिया धीमी और कभी-कभी अनिर्णायक हो सकती है
यद्यपि सर्वसम्मति आधारित कूटनीति आसियान की शक्ति है, परंतु इसकी कुछ कमियाँ भी उजागर होती हैं। आलोचकों का तर्क है कि जब तक सभी सदस्य किसी निर्णय पर सहमत नहीं होते, तब तक प्रक्रिया बहुत लंबी खिंच जाती है। इस धीमी गति के कारण संगठन आपातकालीन स्थितियों या जटिल क्षेत्रीय संकटों के समय तत्काल और निर्णायक कार्रवाई करने में अक्सर संघर्ष करता हुआ प्रतीत होता है।

161. (D) चीन ने एक क्रमिक और प्रयोगात्मक मार्ग चुना, जबकि शॉक थेरेपी तीव्र और व्यापक सुधार थी
आर्थिक सुधारों के मामले में चीन और सोवियत ब्लॉक ने विपरीत रास्ते अपनाए। सोवियत ब्लॉक की 'शॉक थेरेपी' ने

अचानक और व्यापक निजीकरण की वकालत की, जिससे वहां आर्थिक अस्थिरता पैदा हुई। इसके विपरीत, चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे और चरणबद्ध तरीके से खोला। उन्होंने पूरी अर्थव्यवस्था को एक साथ बदलने के बजाय पहले छोटे क्षेत्रों में सफल प्रयोग किए और फिर उन्हें विस्तार दिया।

162. (B) एक सतर्क, क्रमिक और प्रयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाना।
चीन के आर्थिक परिवर्तन की रणनीति को 'पत्थरों को महसूस करके नदी पार करने' की उपमा से परिभाषित किया जाता है। इसका अर्थ है कि सरकार ने सुधारों को लागू करते समय अत्यधिक सावधानी बरती। किसी भी बड़ी नीति को पूरे देश में लागू करने से पहले छोटे स्तर पर उसका परीक्षण किया गया। इस प्रायोगिक दृष्टिकोण ने चीन को अपनी नीतियों में आवश्यक सुधार और समायोजन करने का मौका दिया।

163. (C) आर्थिक नीतियों के परीक्षण और विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु नियंत्रित क्षेत्रों के रूप में कार्य करना
विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) की स्थापना चीन की 'खुले द्वार' की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। ये क्षेत्र विदेशी पूंजी, उन्नत तकनीक और आधुनिक प्रबंधन तकनीकों को आकर्षित करने के लिए बनाए गए थे। यहाँ उदार नियमों और कर लाभों के माध्यम से बाजार-उन्मुख प्रयोग किए गए। इन क्षेत्रों ने एक प्रयोगशाला के रूप में कार्य किया, जिससे चीन को वैश्विक अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे एकीकृत होने में मदद मिली।

164. (D) शेन्ज़ेन
चीन के आर्थिक चमत्कार का सबसे जीवंत उदाहरण शेन्ज़ेन शहर है। 1980 के दशक की शुरुआत में यह केवल एक छोटा और साधारण मछली पकड़ने वाला गाँव था। SEZ मॉडल के सफल कार्यान्वयन के माध्यम से, यह बहुत कम समय में एक विशाल वैश्विक महानगर और विनिर्माण केंद्र में बदल गया। इसकी तीव्र वृद्धि और औद्योगिक सफलता चीन की क्रमिक आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता को सिद्ध करती है।

165. (A) तटीय क्षेत्रों में, वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव को सुविधाजनक बनाने के लिए।
चीन ने अपने पहले विशेष आर्थिक क्षेत्रों को रणनीतिक रूप से तटीय क्षेत्रों में स्थापित किया। इसका मुख्य कारण वैश्विक समुद्री व्यापार मार्गों के साथ सुगम संपर्क सुनिश्चित करना था। तटीय स्थिति ने विदेशी निवेशकों के लिए पहुँच को आसान बनाया और निर्यात-उन्मुख विनिर्माण को बढ़ावा दिया। इन क्षेत्रों ने चीन की मुख्य भूमि और शेष विश्व के बीच एक नियंत्रित प्रवेश द्वार के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य किया।

166. (B) ASC एक सैन्य गठबंधन नहीं है, जबकि नाटो है।
आसियान सुरक्षा समुदाय और नाटो की प्रकृति में मौलिक अंतर है। नाटो एक पारंपरिक सैन्य गठबंधन है जो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके विपरीत, आसियान सुरक्षा समुदाय किसी सैन्य गुट के रूप में कार्य नहीं करता है। इसका मुख्य जोर कूटनीति, आपसी संवाद और शांतिपूर्ण समाधानों पर है, न कि सदस्य देशों के बीच एक एकीकृत सेना बनाने या सैन्य विस्तार करने पर।

167. (B) समग्र सुरक्षा जिसमें सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दे शामिल हैं
आसियान सुरक्षा समुदाय केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह 'व्यापक सुरक्षा' की अवधारणा को अपनाता है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत सुरक्षा को एक बहुआयामी विषय माना जाता है, जिसमें सैन्य शक्ति के साथ-साथ राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास और सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं को समान महत्व दिया जाता है। यह मानता है कि क्षेत्रीय शांति तभी संभव है जब सुरक्षा के इन सभी आयामों को एक साथ संबोधित किया जाए।

168. (A) मैत्री और सहयोग की संधि (TAC)
1976 में हस्ताक्षरित मैत्री और सहयोग की संधि आसियान देशों के बीच संबंधों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज है। यह संधि सदस्य राष्ट्रों के आचरण को नियंत्रित करने वाले मूलभूत सिद्धांतों को परिभाषित करती है। इसमें विशेष रूप से संप्रभुता के सम्मान, एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और विवादों के समाधान के लिए बल प्रयोग को त्यागने पर बल दिया गया है, जो क्षेत्रीय स्थिरता का आधार है।

169. (C) क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर संवाद और विश्वास-निर्माण को बढ़ावा देना।
आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF) एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण बहुपक्षीय मंच है। इसमें आसियान सदस्यों के अलावा दुनिया की प्रमुख महाशक्तियाँ भी शामिल हैं। इसका प्राथमिक कार्य सदस्य देशों के बीच विश्वास-निर्माण के उपायों को लागू करना और निवारक कूटनीति के माध्यम से संघर्षों को टालना है। यह मंच जटिल सुरक्षा चुनौतियों पर खुली चर्चा के लिए एक समावेशी वातावरण प्रदान करता है।

170. (D) यह सुनिश्चित करना कि विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से हो।
आसियान सुरक्षा समुदाय का मुख्य लक्ष्य दक्षिण-पूर्व एशिया में एक शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सदस्य देशों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी क्षेत्रीय विवाद को सैन्य संघर्ष के बजाय बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल किया जाए। यह बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप के बिना क्षेत्रीय समस्याओं के स्वदेशी समाधान खोजने और साझा सुरक्षा चिंताओं पर सहयोग करने पर केंद्रित है।

171. (C) लेनदेन लागत को खत्म करना और व्यापार को प्रोत्साहित करना।
यूरोपीय संघ द्वारा एकल मुद्रा यूरो को अपनाने के पीछे सशक्त आर्थिक कारण थे। विभिन्न राष्ट्रीय मुद्राओं के स्थान पर एक साझा मुद्रा आने से देशों के बीच व्यापार करते समय मुद्रा विनिमय और लेनदेन पर होने वाला अतिरिक्त खर्च समाप्त हो गया। इससे कीमतों में पारदर्शिता आई और निवेश के लिए एक स्थिर वातावरण तैयार हुआ, जिससे यूरोजोन दुनिया के सबसे गतिशील और एकीकृत बाजारों में से एक बन गया।

172. (B) वे यूरोपीय संघ के सदस्य देश जिन्होंने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाया है।
यद्यपि यूरोपीय संघ में कुल 27 सदस्य देश शामिल हैं, लेकिन उन सभी की मुद्रा यूरो नहीं है। 'यूरोजोन' विशेष रूप से उन सदस्य देशों के समूह को संदर्भित करता है जिन्होंने आधिकारिक तौर पर अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं को त्यागकर यूरो को अपनाया है। वर्तमान में 20 देश इस मौद्रिक संघ का हिस्सा हैं, जो एक साझा मौद्रिक नीति और यूरोपीय सेंट्रल बैंक के दिशा-निर्देशों के तहत अपनी अर्थव्यवस्था संचालित करते हैं।

173. (D) यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB)
यूरो मुद्रा का कुशल प्रबंधन और यूरोजोन के भीतर मूल्य स्थिरता बनाए रखने की जिम्मेदारी यूरोपीय सेंट्रल बैंक की है। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में स्थित यह संस्था एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करती है। यह यूरोजोन के लिए मौद्रिक नीति निर्धारित करती है, ब्याज दरों को नियंत्रित करती है और मुद्रा की आपूर्ति का प्रबंधन करती है। इसकी भूमिका वैश्विक वित्तीय प्रणाली में यूरो की साख बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

174. (A) एकल मौद्रिक नीति और विविध राष्ट्रीय राजकोषीय नीतियों के बीच का अंतर्निहित तनाव
यूरोजोन ऋण संकट ने एक गंभीर संरचनात्मक चुनौती को उजागर किया। जहाँ सभी सदस्य देश यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा निर्धारित एक ही मौद्रिक नीति का पालन करते हैं, वहीं उनके पास अपनी स्वतंत्र राजकोषीय नीतियां, जैसे कर और बजट, होती हैं। संकट के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि कुछ देशों की कमजोर वित्तीय स्थिति पूरे संघ की स्थिरता को प्रभावित कर सकती है, जिससे एक साझा मुद्रा और भिन्न राष्ट्रीय बजटों के बीच का विरोधाभास प्रकट हुआ।

175. (C) यह दुनिया की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण आरक्षित मुद्रा है।
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय परिदृश्य में यूरो ने अपनी एक मजबूत और विश्वसनीय पहचान बनाई है। यह वर्तमान में अमेरिकी डॉलर के बाद दुनिया की दूसरी सबसे प्रमुख आरक्षित मुद्रा के रूप में स्वीकार की जाती है। विश्व भर के केंद्रीय बैंक और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान अपने विदेशी मुद्रा भंडार के एक बड़े हिस्से के रूप में यूरो को रखते हैं। यह वैश्विक मंच पर यूरोपीय संघ की संयुक्त आर्थिक शक्ति और वित्तीय स्थिरता का एक प्रमुख संकेतक है।

अध्याय 03
समकालीन दक्षिण एशिया

1. 'दक्षिण एशिया' पद का व्यवहार सामान्यतः किन देशों को इंगित करने के लिए किया जाता है?
   (A) बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और चीन
   (B) बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका
   (C) भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल और भूटान
   (D) भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और म्यांमार

2. निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशिष्टता का सबसे सटीक वर्णन करता है?
   (A) यह क्षेत्र उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा है।
   (B) यह क्षेत्र उत्तर में हिमालय, दक्षिण में अरब सागर, पश्चिम में बंगाल की खाड़ी और पूर्व में हिंद महासागर से घिरा है।
   (C) यह क्षेत्र उत्तर की पर्वत श्रेणियों, दक्षिण के रेतीले मैदानों और पूर्व-पश्चिम के पठारी भागों से मिलकर बना है।
   (D) यह क्षेत्र उत्तर में पर्वतों, दक्षिण में महासागरों और चारों ओर से विभिन्न देशों की राजनीतिक सीमाओं से घिरा है।

3. नीचे दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें:
   अभिकथन (A): दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक-सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है।
   कारण (R): भारत और श्रीलंका में लोकतंत्र सफलतापूर्वक कायम है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के शासन रहे हैं।
   (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
   (B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
   (C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
   (D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

4. 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद कौन सा देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा?
   (A) भूटान
   (B) मालदीव
   (C) श्रीलंका
   (D) नेपाल

5. निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें:
   सूची I: (देश)
   P. मालदीव
   Q. भूटान
   R. पाकिस्तान
   S. नेपाल
   सूची II: (राजनीतिक घटना)
   1. 2008 से लोकतांत्रिक शासन
   2. 1968 तक सल्तनत
   3. 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बना
   4. 2008 में राजतंत्र को खत्म किया
   (A) P-2, Q-3, R-1, S-4
   (B) P-1, Q-2, R-3, S-4
   (C) P-3, Q-1, R-4, S-2
   (D) P-4, Q-3, R-2, S-1

6. मालदीव में किस वर्ष बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में संसद ने एकमत से मतदान किया?
   (A) 1968
   (B) 2005
   (C) 2008
   (D) 2018

7. नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें:
   1. दक्षिण एशिया के देशों में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला-जुला रहा है।
   2. इस क्षेत्र के पाँच बड़े देशों में हुए सर्वेक्षण से पता चला कि लोकतंत्र को व्यापक जन-समर्थन हासिल है।
   3. यह माना जाता रहा है कि लोकतंत्र सिर्फ विश्व के धनी देशों में फल-फूल सकता है।
   4. दक्षिण एशिया के अनुभवों से लोकतंत्र की वैश्विक कल्पना का दायरा कम हुआ है।
   दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
   (A) केवल 1 और 2
   (B) केवल 1, 2 और 3
   (C) केवल 2, 3 और 4
   (D) 1, 2, 3 और 4 सभी

8. 1947 से 1971 तक बांग्लादेश किस देश का अंग था?
   (A) पाकिस्तान
   (B) भारत
   (C) म्यांमार

(D) यह एक स्वतंत्र देश था

9. पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाई नहीं है?
(A) सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा।
(B) भारत के साथ निरंतर तनातनी।
(C) एक मजबूत और स्वतंत्र न्यायपालिका की उपस्थिति।
(D) अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कमी।

10. नीचे दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें:
अभिकथन (A): पाकिस्तान में सेना-समर्थक समूह अक्सर यह दलील देते हैं कि राजनीतिक दलों के स्वार्थ साधन से पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।
कारण (R): भारत के साथ पाकिस्तान की तनातनी ने सेना-समर्थक समूहों को अधिक मजबूत बनाया है, जो सैनिक शासन को जायज ठहराते हैं।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

11. पाकिस्तान में 1999 में हुए सैनिक तख्तापलट का नेतृत्व किसने किया था?
(A) जनरल जियाउल-हक
(B) जनरल अयूब खान
(C) जनरल याहिया खान
(D) जनरल परवेज़ मुशर्रफ़

12. निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें:
1. भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता
2. भारत-पाक युद्ध और बांग्लादेश की मुक्ति
3. भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला-समझौता
4. जनरल जियाउल-हक द्वारा भुट्टो सरकार का तख्तापलट
(A) 1, 2, 3, 4
(B) 2, 1, 3, 4
(C) 1, 3, 2, 4
(D) 4, 3, 2, 1

13. पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान में जन-संघर्ष का नेतृत्व किसने किया?
(A) जनरल याहिया खान
(B) जुल्फिकार अली भुट्टो
(C) शेख मुजीबुर्रहमान
(D) जियाउर्रहमान

14. नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें:
1. शेख मुजीबुर्रहमान ने 1975 में संविधान में संशोधन कराकर संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मान्यता दी।
2. शेख मुजीब ने अपनी पार्टी अवामी लीग को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया।
3. 1975 के अगस्त में सेना ने शेख मुजीब के खिलाफ बगावत की और उनकी हत्या कर दी।
4. जियाउर्रहमान ने बांग्लादेश National Party बनाई और 1979 के चुनाव में विजयी रहे।
5. 1991 से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 5
(B) केवल 1, 3, 4 और 5
(C) केवल 2, 3 और 4
(D) उपरोक्त सभी

15. नेपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(A) नेपाल में माओवादी कभी भी अपना प्रभाव जमाने में कामयाब नहीं हुए।
(B) नेपाल अतीत में एक हिन्दू-राज्य था।
(C) 1990 में एक मजबूत लोकतंत्र-समर्थक आंदोलन के बाद राजा ने नए लोकतांत्रिक संविधान की माँग मान ली।
(D) 2008 में नेपाल राजतंत्र को खत्म करने के बाद एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया।

16. नेपाल में 2006 के देशव्यापी लोकतंत्र-समर्थक प्रदर्शन का नेतृत्व किसने किया था?
(A) राजा ज्ञानेन्द्र के समर्थक और शाही सेना के उच्च अधिकारी
(B) सात दलों का गठबंधन, माओवादी और सामाजिक नागरिक कार्यकर्ता
(C) केवल सशस्त्र माओवादी विद्रोही और उनके राजनीतिक विंग
(D) भारतीय शांति सेना और अन्य बाहरी सुरक्षा सलाहकार एजेंसियां

17. निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें:
सूची I: (घटना)
P. 'सिएटो' और 'सेंटो' में पाकिस्तान का शामिल होना
Q. सिंधु नदी जल समझौता
R. ताशकंद समझौता
S. भारत द्वारा परमाणु परीक्षण
सूची II: (वर्ष)
1. 1966
2. 1974
3. 1954-55
4. 1960
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4

(C) P-4, Q-3, R-2, S-1
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

18. श्रीलंका (तत्कालीन सिलोन) को ब्रिटेन से आजादी कब मिली?
(A) 1948
(B) 1947
(C) 1971
(D) 1987

19. नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें:
1. श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक सिंहली समुदाय का दबदबा रहा है।
2. सिंहली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई 'रियायत' नहीं बरती जानी चाहिए।
3. 1983 के बाद से उग्र तमिल संगठन 'लिट्टे' ने श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष किया।
4. लिट्टे ने 'तमिल ईलम' यानी सिंहली लोगों के लिए एक अलग देश की मांग की।

दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1, 2 और 3
(C) केवल 3 और 4
(D) 1, 2, 3 और 4 सभी

20. भारत ने किस वर्ष श्रीलंका में शांति सेना भेजी?
(A) 1983
(B) 1985
(C) 1989
(D) 1987

21. नीचे दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें:
अभिवथन (A): श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बावजूद, इसने अच्छी आर्थिक वृद्धि और विकास के उच्च स्तर को हासिल किया।
कारण (R): गृहयुद्ध से गुजरने के बावजूद, श्रीलंका का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है और इसने लोकतांत्रिक राजव्यवस्था को कायम रखा है।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

22. 1948 के युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर के दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा 'पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर' कहलाया, जबकि दूसरा हिस्सा भारत का क्या प्रान्त बना?
(A) पंजाब प्रान्त
(B) जम्मू-कश्मीर प्रान्त
(C) हिमाचल प्रान्त
(D) दिल्ली प्रान्त

23. भारत और पाकिस्तान ने 1960 में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था की मदद से 'सिंधु जल संधि' पर हस्ताक्षर किए?
(A) संयुक्त राष्ट्र संघ
(B) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
(C) विश्व व्यापार संगठन
(D) विश्व बैंक

24. निम्नलिखित में से कौन सा भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष का एक मसला नहीं है?
(A) गंगा नदी जल बंटवारा
(B) कश्मीर विवाद
(C) सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण
(D) सरक्रिक की सीमारेखा

25. नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें:
1. दोनों देशों के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी को लेकर कोई मतभेद नहीं है।
2. भारतीय सरकार बांग्लादेश से भारत में अवैध आप्रवास से नाखुश है।
3. बांग्लादेश भारत की 'लुक ईस्ट' और 'एक्ट ईस्ट' नीति का हिस्सा है।
4. 2015 में दोनों देशों ने कुछ परिक्षेत्रों (एन्क्लेव) का आदान-प्रदान किया।
5. आपदा-प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर दोनों देशों में कोई सहयोग नहीं है।

दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 2, 3 और 4
(C) केवल 1, 4 और 5
(D) केवल 2, 3 और 5

26. वह कौन सी संधि है जिसके तहत भारत और नेपाल के नागरिक एक-दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट और वीजा के आ-जा सकते हैं?
(A) भारत-नेपाल शांति और मैत्री संधि
(B) शिमला समझौता
(C) सार्क चार्टर
(D) साफ्टा समझौता

27. भारत सरकार नेपाल के किन तत्वों को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती है?
(A) नेपाल की राजशाही
(B) नेपाली कांग्रेस पार्टी
(C) नेपाल का पर्यटन उद्योग
(D) नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन

28. निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें:
सूची I: (संधि/समझौता)

P. भारत-सोवियत मैत्री संधि
Q. शिमला-समझौता
R. दक्षेस की स्थापना
S. साफ्टा पर हस्ताक्षर
सूची II: (वर्ष)
1. 1972
2. 1985
3. 2004
4. 1971
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-1, R-2, S-3
(C) P-2, Q-3, R-4, S-1
(D) P-3, Q-4, R-1, S-2

29. 'लिट्टे' (LTTE) का पूरा नाम क्या है?
(A) लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल टेरिटरी
(B) लिबरल टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम
(C) लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम
(D) लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलायंस

30. निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण सबसे पहले किया?
(A) भारत
(B) पाकिस्तान
(C) बांग्लादेश
(D) श्रीलंका

31. निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें:
1. 'दक्षेस' के पहले सम्मेलन में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर
2. भारत-श्रीलंका समझौता
3. भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण
4. करगिल-युद्ध
(A) 1, 2, 3, 4
(B) 2, 1, 4, 3
(C) 1, 3, 2, 4
(D) 3, 4, 1, 2

32. भारत और पाकिस्तान ने क्रमशः पोखरण और चगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किस वर्ष किए?
(A) 1996
(B) 1998
(C) 1999
(D) 2001

33. नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें:
1. भारत सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार और प्रशिक्षण देता है।
2. पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर भारत-विरोधी अभियानों में संलग्न होने का आरोप है।
3. पाकिस्तान की सरकार भारतीय सरकार पर सिंध और बलूचिस्तान में समस्या को भड़काने का आरोप लगाती है।
4. 1960 में विश्व बैंक की मदद से हुई सिंधु-जल संधि कई सैन्य संघर्षों के बावजूद अब भी कायम है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3 और 4
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) 1, 2, 3 और 4 सभी

34. दक्षिण एशिया के किस देश के साथ भारत के संबंध सबसे मधुर और शांतिपूर्ण माने जाते हैं, जहाँ कोई बड़ा झगड़ा नहीं है?
(A) भूटान
(B) पाकिस्तान
(C) बांग्लादेश
(D) नेपाल

35. नीचे दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें:
अभिकथन (A): छोटे देशों को लगता है कि भारत दक्षिण एशिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है।
कारण (R): भारत का आकार बड़ा है और वह शक्तिशाली है, इसकी वज़ह से अपेक्षाकृत छोटे देशों का भारत के इरादों को लेकर शक करना लाजिमी है।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

36. 1988 में मालदीव पर हुए हमले को नाकाम करने में किस देश ने सहायता की थी?
(A) श्रीलंका
(B) पाकिस्तान
(C) संयुक्त राज्य अमेरिका
(D) भारत

37. 'दक्षेस' (SAARC) का पूर्ण रूप क्या है?
(A) साउथ एशियन अलायन्स फॉर रीजनल कोऑपरेशन
(B) साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉमर्स
(C) साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन
(D) साउथ एशियन अलायन्स फॉर रेलवे कोऑपरेशन

38. दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
(A) 1980
(B) 1985
(C) 1991
(D) 2002

39. दक्षेस के सदस्य देशों ने 'दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार-क्षेत्र समझौते' (SAFTA) पर किस वर्ष हस्ताक्षर किये?
(A) 1985
(B) 2004
(C) 2006
(D) 2002

40. 'साफ्टा' (SAFTA) समझौता कब से प्रभावी हुआ?
(A) 1 जनवरी 2006
(B) 1 जनवरी 2004
(C) 1 दिसंबर 2002
(D) 1 दिसंबर 2005

41. दक्षिण एशिया की राजनीति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दो बाहरी देश कौन से हैं?
(A) चीन और जापान
(B) रूस और जर्मनी
(C) चीन और संयुक्त राज्य अमरीका
(D) ब्रिटेन और फ्रांस

42. शीतयुद्ध के बाद दक्षिण एशिया में किस बाहरी शक्ति का प्रभाव तेजी से बढ़ा है?
(A) अमरीका
(B) रूस
(C) चीन
(D) यूरोपीय संघ

43. निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
(A) चीन की रणनीतिक साझेदारी पाकिस्तान के साथ है।
(B) 1991 के बाद भारत और चीन के आर्थिक संबंध मजबूत हुए हैं।
(C) अमरीका ने शीतयुद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों से अपने संबंध बेहतर किए हैं।
(D) दक्षिण एशिया में अमरीकी भागीदारी का मुख्य कारण केवल वहां के प्राकृतिक संसाधन हैं।

44. नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें:
1. यह क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से खतरे की आशंका वाला क्षेत्र माना जाता है।
2. इस क्षेत्र के देशों के बीच सीमा और नदी जल के बँटवारे को लेकर विवाद कायम हैं।
3. इस क्षेत्र के देश अगर आपस में सहयोग करें तो यह क्षेत्र विकास करके समृद्ध बन सकता है।
4. इन देशों की घरेलू राजनीति का आपसी झगड़ों या सहयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

दिए गए कथनों में से कौन-से सही नहीं हैं?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 4
(C) केवल 2 और 4
(D) केवल 1, 2 और 3

45. निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें:
सूची I: (देश)
P. बांग्लादेश
Q. नेपाल
R. श्रीलंका
S. पाकिस्तान
सूची II: (राजनीतिक विशेषता/घटना)
1. जातीय संघर्ष और लिट्टे
2. सैनिक और लोकतांत्रिक शासन का बारी-बारी आना
3. धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक देश घोषित
4. संवैधानिक राजतंत्र
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-1, R-2, S-3
(D) P-2, Q-3, R-4, S-1

46. पाकिस्तान के पहले संविधान बनने के बाद शासन की बागडोर किसने अपने हाथों में ली?
(A) जनरल याहिया खान
(B) जनरल जियाउल-हक
(C) जुल्फिकार अली भुट्टो
(D) जनरल अयूब खान

47. नीचे दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें:
अभिकथन (A): 1971 के युद्ध के परिणामस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान टूटकर एक स्वतंत्र देश बना जिसे बांग्लादेश कहा गया।
कारण (R): भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आजादी की माँग का समर्थन किया और उन्हें वित्तीय और सैन्य सहायता दी, जिससे भारत-पाकिस्तान युद्ध हुआ।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

48. शेख मुजीबुर्रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान की स्वायत्तता के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा था?
(A) चार-सूत्री प्रस्ताव
(B) छः-सूत्री प्रस्ताव
(C) आठ-सूत्री प्रस्ताव
(D) दस-सूत्री प्रस्ताव

49. नेपाल के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें:
1. नए लोकतांत्रिक संविधान की माँग का स्वीकार किया जाना।
2. राजा द्वारा संसद को भंग करना।
3. देशव्यापी लोकतंत्र-समर्थक प्रदर्शन।

4. राजतंत्र का अंत और लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना।
(A) 1, 2, 3, 4
(B) 2, 1, 3, 4
(C) 1, 3, 2, 4
(D) 3, 1, 2, 4

50. 1970 के चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान की सभी सीटों पर किस पार्टी ने विजय प्राप्त की?
(A) अवामी लीग
(B) पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी
(C) मुस्लिम लीग
(D) बांग्लादेश नेशनल पार्टी

51. नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें:
1. 1975 में शेख मुजीबुर्रहमान की हत्या के बाद देश में सैनिक शासन स्थापित हुआ।
2. जियाउर्रहमान की हत्या के बाद लेफ्टिनेंट जेनरल एच. एम. इरशाद ने सैनिक शासन का नेतृत्व किया।
3. 1990 में व्यापक जनविरोध के बाद जेनरल इरशाद को पद छोड़ना पड़ा।
4. 1991 के बाद से बांग्लादेश में एकदलीय शासन प्रणाली कायम है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1, 2 और 3
(C) केवल 3 और 4
(D) 1, 2, 3 और 4 सभी

52. नेपाल में 1990 के दशक में राजा, लोकतंत्र-समर्थकों और किनके बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ?
(A) भू-स्वामियों
(B) उद्योगपतियों
(C) भारतीय शांति सेना
(D) माओवादियों

53. श्रीलंका में संघर्ष समाप्त करने के लिए किन स्कैंडिनेवियाई देशों ने मध्यस्थ के रूप में भूमिका निभाई?
(A) स्वीडन और डेनमार्क
(B) फिनलैंड और स्वीडन
(C) नार्वे और आइसलैंड
(D) डेनमार्क और नार्वे

54. भारत-नेपाल संबंधों के संदर्भ में क्या सही नहीं है?
(A) दोनों देशों के बीच एक विशेष संधि है जिससे नागरिकों को बिना पासपोर्ट-वीजा के आने-जाने की सुविधा है।
(B) भारत सरकार नेपाल की चीन से दोस्ती को लेकर हमेशा प्रसन्न रही है।
(C) नेपाल में माओवादी आंदोलन को भारत अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है।
(D) विभेदों के बावजूद दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग आदि में एक साथ हैं।

55. निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें:
सूची I: (नेता)
P. शेख मुजीबुर्रहमान
Q. बेनजीर भुट्टो
R. परवेज़ मुशर्रफ़
S. राजा ज्ञानेन्द्र

सूची II: (देश/पार्टी)
1. नेपाल
2. पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी
3. अवामी लीग
4. सैनिक तख्तापलट (1999)

(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-2, R-4, S-1
(C) P-2, Q-3, R-1, S-4
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

56. 1971-77 तक पाकिस्तान में किसके नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार बनी?
(A) जुल्फिकार अली भुट्टो
(B) बेनजीर भुट्टो
(C) नवाज़ शरीफ़
(D) परवेज़ मुशर्रफ़

57. नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें:
1. चीन को दक्षिण एशिया का अंग माना जाता है।
2. इस क्षेत्र में सद्भाव, शत्रुता, आशा, और निराशा साथ-साथ बसते हैं।
3. यह क्षेत्र भू-राजनीतिक धरातल पर एक क्षेत्र है।
4. इस उप-महाद्वीपीय क्षेत्र में भाषाई, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अनूठापन है।
5. अफगानिस्तान और म्यांमार को इस क्षेत्र की चर्चा में कभी शामिल नहीं किया जाता है।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2, 3
(B) केवल 2, 3, 4
(C) केवल 1, 3, 5
(D) केवल 2, 4, 5

58. 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को किसने गिराया था?
(A) जेनरल जियाउल-हक
(B) जेनरल परवेज़ मुशर्रफ़
(C) जेनरल अयूब खान
(D) नवाज शरीफ

59. नीचे दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें:
अभिवथन (A): 1987 में भारत सरकार श्रीलंका के तमिल मसले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई।
कारण (R): भारत की तमिल जनता का भारत सरकार पर भारी दबाव था कि वह श्रीलंकाई तमिलों के हितों की रक्षा करे।

(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

60. भारत ने अपनी 'शांति सेना' (IPKF) श्रीलंका से कब वापस बुलाई?
(A) 1987
(B) 1990
(C) 1988
(D) 1989

61. भारत और बांग्लादेश के बीच मतभेद का एक प्रमुख कारण क्या है?
(A) क्रिकेट में प्रतिद्वंद्विता
(B) ऐतिहासिक स्मारक
(C) नदी-जल में हिस्सेदारी
(D) भाषाई भिन्नता

62. दक्षिण एशियाई देशों के घटनाक्रम को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें:
1. श्रीलंका को आजादी
2. पाकिस्तान का 'सिएटो' में शामिल होना
3. भारत और चीन के बीच सीमा-विवाद
4. बांग्लादेश के नेताओं द्वारा आजादी की उद्घोषणा
(A) 1, 2, 3, 4
(B) 2, 3, 1, 4
(C) 1, 3, 2, 4
(D) 3, 1, 4, 2

63. 'साफ्टा' (SAFTA) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(A) सदस्य देशों के बीच व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को कम करना।
(B) सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सैन्य सहयोग और सुरक्षा को बढ़ाना।
(C) क्षेत्र के लिए एक साझा मुद्रा और एकीकृत बैंकिंग व्यवस्था बनाना।
(D) आतंकवाद के खिलाफ एक सशक्त और संयुक्त सुरक्षा मोर्चा तैयार करना।

64. भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के संदर्भ में कौन सा दक्षिण एशियाई देश महत्वपूर्ण है?
(A) पाकिस्तान
(B) बांग्लादेश
(C) श्रीलंका
(D) मालदीव

65. नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें:
1. इसकी शुरुआत 1985 में हुई।
2. यह आपसी सहयोग करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
3. विभेदों की मौजूदगी के कारण दक्षेस को बहुत ज्यादा सफलता मिली है।
4. अफगानिस्तान 2007 में इसका सदस्य बना।
उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1, 2 और 4
(C) केवल 3 और 4
(D) 1, 2, 3 और 4 सभी

66. 1999 के करगिल-युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे?
(A) अटल बिहारी वाजपेयी
(B) मनमोहन सिंह
(C) आई. के. गुजराल
(D) पी. वी. नरसिम्हा राव

67. निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें:
सूची I: (समझौता/घटना)
P. फरक्का संधि
Q. आगरा-बैठक
R. 12वां दक्षेस सम्मेलन
S. 18वां दक्षेस सम्मेलन
सूची II: (स्थान/वर्ष)
1. काठमांडू (2014)
2. इस्लामाबाद (2004)
3. 1996
4. 2001
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-3, R-4, S-1
(C) P-3, Q-4, R-2, S-1
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

68. भारत और पाकिस्तान के बीच 'सरक्रिक' विवाद किस क्षेत्र से संबंधित है?
(A) सियाचिन ग्लेशियर
(B) कश्मीर घाटी
(C) पंजाब का सीमावर्ती क्षेत्र
(D) कच्छ के रन

69. नीचे दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें:
अभिकथन (A): कुछ छोटे देश मानते हैं कि 'साफ्टा' की ओट लेकर भारत उनके बाज़ार में सेंध मारना चाहता है।
कारण (R): भारत सोचता है कि 'साफ्टा' से इस क्षेत्र के हर देश को फायदा होगा और मुक्त व्यापार से राजनीतिक सहयोग बेहतर होगा।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

70. दक्षिण एशिया में केवल भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच ही झगड़े नहीं हैं। इसका उदाहरण कौन सा है?
(A) भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहा कश्मीर का दीर्घकालिक सीमा विवाद।
(B) नेपाल-भूटान के बीच जातीय मूल के नेपालियों के आप्रवास का मसला।
(C) भारत-बांग्लादेश के बीच होने वाला गंगा-ब्रह्मपुत्र नदी जल विवाद।
(D) भारत-श्रीलंका के मध्य गहराता हुआ तमिलों का जातीय संघर्ष।

71. नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें:
1. यहाँ सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा है।
2. भारत के साथ तनातनी के कारण सेना-समर्थक समूह मजबूत हैं।
3. अमरीका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थों से सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है।
4. पाकिस्तान में कभी भी स्वतंत्र और साहसी प्रेस नहीं रहा।
5. यहाँ मानवाधिकार आंदोलन कभी भी मजबूत नहीं रहे।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2, 3
(B) केवल 3, 4, 5
(C) केवल 1, 4, 5
(D) उपरोक्त सभी

72. दक्षिण एशिया का वह कौन-सा द्वीपीय देश है जो 1968 तक एक सल्तनत था?
(A) मालदीव
(B) श्रीलंका
(C) इंडोनेशिया
(D) फिलीपींस

73. दक्षिण एशिया के किस देश में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था?
(A) भूटान
(B) मालदीव
(C) नेपाल
(D) श्रीलंका

74. 'लिबर्टी लीडिंग द पीपल' नामक प्रसिद्ध पेंटिंग किसने बनाई थी?
(A) येगेनी डेलाक्रो
(B) सुभाष राय
(C) पाब्लो पिकासो
(D) विन्सेंट वैन गॉग

75. निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें:

सूची I: (देश)
P. भारत
Q. पाकिस्तान
R. बांग्लादेश
S. नेपाल

सूची II: (एक राजनीतिक घटना)
1. 1971 में मुक्ति
2. 2015 में नया संविधान अपनाया
3. 1947 में स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय
4. 1999 में सैनिक तख्तापलट

(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-3, R-2, S-1
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

76. निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्षिण एशिया के बारे में गलत है?
(A) बांग्लादेश और भारत ने नदी-जल की हिस्सेदारी के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
(B) दक्षिण एशिया में सिर्फ़ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है।
(C) 'साफ्टा' पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें सार्क-सम्मेलन में हुए।
(D) दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमरीका महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

77. 1971 में भारत और सोवियत संघ ने कितने वर्षों के लिए मैत्री संधि पर दस्तखत किए थे?
(A) 10 वर्ष
(B) 15 वर्ष
(C) 20 वर्ष
(D) 25 वर्ष

78. निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें:
1. भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए।
2. वाजपेयी-मुशर्रफ के बीच आगरा-बैठक।
3. अफगानिस्तान दक्षेस का सदस्य बना।
4. 18वां दक्षेस सम्मेलन काठमांडू में हुआ।

(A) 1, 2, 3, 4
(B) 2, 1, 3, 4
(C) 1, 3, 2, 4
(D) 3, 1, 2, 4

79. 1988 में पाकिस्तान में किसके नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी थी?
(A) बेनजीर भुट्टो
(B) नवाज शरीफ
(C) परवेज मुशर्रफ
(D) जुल्फिकार अली भुट्टो

80. नीचे दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें:
अभिकथन (A): पूर्वी पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ थे।
कारण (R): पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद ही बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध शुरु हो गया था।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

81. 2001 में परवेज़ मुशर्रफ़ ने अपना निर्वाचन किस रुप में कराया?
(A) प्रधानमंत्री
(B) राष्ट्रपति
(C) सेना प्रमुख
(D) मुख्य न्यायाधीश

82. नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें:
1. भारत के भूटान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं।
2. भूटानी सरकार के साथ भारत का कोई बड़ा झगड़ा नहीं है।
3. भूटान ने पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों को अपने क्षेत्र से खदेड़ भगाया।
4. भारत भूटान में पनबिजली की बड़ी परियोजनाओं में हाथ बँटा रहा है।
5. भूटान के विकास कार्यों के लिए अधिकांश अनुदान चीन से हासिल होता है।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2, 3, 4
(B) केवल 2, 3, 4, 5
(C) केवल 1, 3, 4, 5
(D) उपरोक्त सभी

83. बांग्लादेश के किस नेता की 1975 में सैन्य बगावत में हत्या कर दी गई थी?
(A) जियाउर्रहमान
(B) एच. एम. इरशाद
(C) शेख मुजीबुर्रहमान
(D) खालिदा जिया

84. 1990 में किस बांग्लादेशी नेता को जनता के व्यापक विरोध के कारण राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ा?
(A) जियाउर्रहमान
(B) शेख मुजीबुर्रहमान
(C) अताउर्रहमान खान
(D) लेफ्टिनेंट जेनरल एच. एम. इरशाद

85. निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें:
सूची I: (घटना)
P. भारत-पाक युद्ध, बांग्लादेश मुक्ति
Q. भारत-श्रीलंका समझौता
R. करगिल युद्ध
S. वाजपेयी की लाहौर बस यात्रा
सूची II: (वर्ष)
1. 1987
2. 1999 (जून-जुलाई)
3. 1971
4. 1999 (फरवरी)
(A) P-3, Q-1, R-2, S-4
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

86. नेपाल में 2002 में संसद को किसने भंग कर दिया था?
(A) प्रधानमंत्री
(B) राजा
(C) सेना प्रमुख
(D) माओवादी नेता

87. श्रीलंका में लिट्टे को किस वर्ष पूर्ण रुप से समाप्त कर दिया गया?
(A) 2006
(B) 2007
(C) 2008
(D) 2009

88. नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें:
1. इस क्षेत्र के देशों के बीच केवल सीमा विवाद ही संघर्ष का कारण है।
2. विद्रोह, जातीय संघर्ष और संसाधनों का बँटवारा भी संघर्ष के प्रमुख कारण हैं।
3. विशेषज्ञों का मानना है कि यह क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से खतरे की आशंका वाला क्षेत्र है।
4. इस क्षेत्र के सभी देश केवल आपस में लड़ते रहते हैं, उनमें सहयोग की कोई भावना नहीं है।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 4
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) केवल 2, 3 और 4

89. पाकिस्तान ने शीतयुद्धकालीन सैन्य गुट 'सिएटो' और 'सेंटो' में कब शामिल हुआ?
(A) 1948 में
(B) 1962 में
(C) 1954-55 में
(D) 1965 में

90. नीचे दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें:
अभिकथन (A): दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का अनुभव इस धारणा को चुनौती देता है कि लोकतंत्र केवल धनी देशों में ही फल-फूल सकता है।
कारण (R): दक्षिण एशिया के पांच बड़े देशों में हुए सर्वेक्षणों से यह बात जाहिर हुई कि इन देशों में लोकतंत्र को व्यापक जन-समर्थन हासिल है और लोग किसी भी अन्य शासन प्रणाली से लोकतंत्र को बेहतर मानते हैं।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

91. 2018 में मालदीव में हुए चुनावों में किस पार्टी ने जीत हासिल की?
(A) मालदीवियन पीपुल्स पार्टी
(B) मालदीवियन रिपब्लिकन पार्टी
(C) मालदीवियन सोशलिस्ट पार्टी
(D) मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी)

92. 1987 में जेनरल इरशाद के खिलाफ लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन के दौरान मारे गए नूर हुसैन की याद में किस शहर के विश्वविद्यालय में चित्रमाला बनाई गई थी?
(A) चटगांव
(B) ढाका
(C) कराची
(D) काठमांडू

93. बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर स्वयं को कैसा देश घोषित नहीं किया?
(A) धर्मनिरपेक्ष
(B) लोकतांत्रिक
(C) राजशाही
(D) समाजवादी

94. नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें:
1. 1971 के युद्ध ने कश्मीर मसले को पूरी तरह सुलझा दिया।
2. 1990 के दशक में दोनों देशों ने परमाणु हथियार हासिल कर लिए।
3. भारत का आरोप है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पूर्वोत्तर भारत में भारत-विरोधी अभियानों में संलग्न है।
4. दोनों देशों के बीच नदी-जल के बँटवारे को लेकर कभी कोई समझौता नहीं हुआ।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं हैं?
(A) केवल 1 और 4
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1, 2 और 4
(D) केवल 1, 3 और 4

95. निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें:
सूची I: (क्षेत्र/विवाद)
P. सियाचिन ग्लेशियर
Q. सरक्रिक
R. तमिल ईलम
S. चटगांव पर्वतीय क्षेत्र
सूची II: (संबंधित देश)
1. श्रीलंका
2. बांग्लादेश
3. भारत-पाकिस्तान
4. भारत-पाकिस्तान (कच्छ का रन)
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-1, R-2, S-3
(D) P-2, Q-3, R-4, S-1

96. चारों तरफ से जमीन से घिरे देश (Landlocked country) का उदाहरण है
(A) श्रीलंका
(B) नेपाल
(C) मालदीव
(D) बांग्लादेश

97. भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग के क्षेत्र कौन से हैं?
(A) केवल आर्थिक संबंध
(B) उपरोक्त सभी
(C) केवल आपदा-प्रबंधन
(D) केवल पर्यावरण

98. नीचे दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें:
अभिकथन (A): भारत सरकार को अक्सर महसूस होता है कि उसके पड़ोसी देश उसका बेजा फायदा उठा रहे हैं।
कारण (R): भारत नहीं चाहता कि पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो क्योंकि ऐसी स्थिति में बाहरी ताकतों को इस क्षेत्र में प्रभाव जमाने में मदद मिलेगी।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

99. दक्षेस के 8वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ?
(A) म्यांमार
(B) चीन
(C) अफगानिस्तान
(D) थाईलैंड

100. नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें:
1. चीन
2. संयुक्त राज्य अमरीका
3. रुस
4. यूरोपीय संघ
5. जापान

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1, 2 और 3
(C) केवल 3, 4 और 5
(D) केवल 1, 4 और 5

101. 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल में हिस्सेदारी को लेकर फरक्का संधि पर हस्ताक्षर हुए?
(A) ब्रह्मपुत्र
(B) तीस्ता
(C) गंगा
(D) यमुना

102. 2007 में दक्षेस का 8वां सदस्य कौन बना?
(A) चीन
(B) अफगानिस्तान
(C) म्यांमार
(D) ईरान

103. 'सार्क' (दक्षेस) की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था?
(A) एक सैन्य गठबंधन बनाना।
(B) एक साझा बाजार का निर्माण करना।
(C) बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप को रोकना।
(D) दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करना।

104. भारत-चीन संबंधों के बारे में कौन सा कथन सही है?
(A) चीन की पाकिस्तान के साथ रणनीतिक साझेदारी भारत-चीन संबंधों में एक बड़ी कठिनाई है।
(B) 1991 के बाद से दोनों देशों के आर्थिक संबंध कमजोर हुए हैं।
(C) वैश्वीकरण के कारण दोनों देश एक-दूसरे से दूर हुए हैं।
(D) दोनों देशों के बीच कोई सीमा विवाद नहीं है।

105. निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें:
सूची I: (देश)
P. बांग्लादेश
Q. भूटान
R. मालदीव
S. पाकिस्तान

सूची II: (विवरण)
1. 1968 तक सल्तनत
2. संवैधानिक राजतंत्र
3. सैनिक और लोकतांत्रिक शासन
4. ग्रामीण बैंक द्वारा गरीबी कम करने में मदद

(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-3, R-4, S-1
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-4, Q-2, R-1, S-3

106. भारत के किस प्रधानमंत्री ने बस-यात्रा कर लाहौर में शांति के एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए थे?
(A) अटल बिहारी वाजपेयी
(B) इंदिरा गांधी
(C) राजीव गांधी
(D) मनमोहन सिंह

107. 2001 में आगरा-बैठक किन दो नेताओं के बीच हुई थी?
(A) अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ
(B) मनमोहन सिंह और परवेज मुशर्रफ
(C) नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ
(D) अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ

108. दक्षिण एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(A) इस क्षेत्र में केवल सद्भाव और सहयोग है।
(B) यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सद्भाव और शत्रुता, आशा और निराशा साथ-साथ बसते हैं।
(C) इस क्षेत्र में कोई आंतरिक संघर्ष नहीं है, केवल सीमा विवाद हैं।
(D) यह क्षेत्र पूरी तरह से बाहरी शक्तियों के प्रभाव से मुक्त है।

109. नीचे दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें:
अभिकथन (A): शीतयुद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमरीकी प्रभाव तेजी से बढ़ा है।
कारण (R): इस क्षेत्र में आर्थिक सुधारों और उदार नीतियों के अपनाए जाने से दक्षिण एशिया में अमरीकी भागीदारी ज़्यादा गहरी हुई है।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

110. 'SAPTA' का पूर्ण रुप क्या है, जिस पर 1993 में दक्षेस के सातवें सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए थे?
(A) साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट
(B) साउथ एशिया प्राइमरी ट्रेड एग्रीमेंट
(C) सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट
(D) दक्षेस के देशों को वरीयता देने की संधि

111. नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें:
1. नेपाल आधुनिक काल में कई सालों तक संवैधानिक

राजतंत्र रहा।
2. 1990 में राजा ने लोकतांत्रिक संविधान की माँग को स्वीकार कर लिया।
3. 2002 में राजा ने संसद को भंग कर सरकार को गिरा दिया।
4. अप्रैल 2006 में देशव्यापी लोकतंत्र-समर्थक प्रदर्शन हुए।
5. 2015 में नेपाल ने राजशाही पर आधारित नया संविधान अपनाया।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2, 3 और 4
(B) केवल 2, 3, 4 और 5
(C) केवल 1, 3, 4 और 5
(D) उपरोक्त सभी

112. "लोकतंत्र तो खैर पाकिस्तान में पूरी तरह सफल नहीं हो सका है लेकिन इस देश में लोकतंत्र का जज़्बा बहुत मज़बूती के साथ कायम रहा है।" इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क दिया जा सकता है?
(A) यहाँ सेना का शासन पर पूर्ण नियंत्रण है।
(B) यहाँ अपेक्षाकृत स्वतंत्र और साहसी प्रेस मौजूद है।
(C) यहाँ कोई मानवाधिकार आंदोलन नहीं है।
(D) यहाँ राजनीतिक दलों में पूर्ण एकता है।

113. 1971 के भारत-पाक युद्ध के समय पाकिस्तान पर किसका सैनिक शासन था?
(A) जनरल अयूब खान
(B) जनरल याहिया खान
(C) जनरल जिया-उल-हक
(D) जनरल परवेज मुशर्रफ

114. निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें:
सूची I: (वर्ष)
P. 1948
Q. 1965
R. 1971
S. 1999
सूची II: (घटना)
1. भारत-पाक युद्ध
2. करगिल युद्ध
3. कश्मीर को लेकर भारत-पाक लड़ाई
4. भारत-पाक युद्ध, बांग्लादेश की मुक्ति
(A) P-3, Q-1, R-4, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-3, R-2, S-1
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

115. श्रीलंका में जातीय संघर्ष का मुख्य कारण क्या था?
(A) देश के विभिन्न समुदायों के बीच मौजूद गंभीर आर्थिक असमानता।
(B) विभिन्न भाषाई समूहों के मध्य होने वाले तीव्र धार्मिक मतभेद।
(C) सिंहली और तमिल समुदायों के बीच राजनीतिक प्रभुत्व का संघर्ष।
(D) बाहरी शक्तियों द्वारा देश की आंतरिक राजनीति में किया गया हस्तक्षेप।

116. किस घटना के बाद दक्षिण एशिया क्षेत्र अचानक पूरे विश्व की नजर में महत्त्वपूर्ण हो गया था?
(A) 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद
(B) दक्षेस (सार्क) की स्थापना के बाद
(C) सोवियत संघ के विघटन के बाद
(D) भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण करने के बाद

117. नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें:
1. यह 1947 से 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था।
2. यहाँ के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे के खिलाफ थे।
3. शेख मुजीबुर्रहमान ने इस संघर्ष का नेतृत्व किया।
4. भारत ने बांग्लादेश की मुक्ति का कभी समर्थन नहीं किया।

उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1, 2 और 3
(C) केवल 3 और 4
(D) 1, 2, 3 और 4 सभी

118. भारत-पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सा समझौता हुआ था?
(A) ताशकंद समझौता
(B) शिमला-समझौता
(C) लाहौर घोषणापत्र
(D) आगरा-समझौता

119. नीचे दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें:
अभिकथन (A): पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने का एक प्रमुख कारण भारत के साथ उसकी तनातनी है।
कारण (R): भारत के साथ तनातनी के कारण पाकिस्तान में सेना-समर्थक समूह ज्यादा मजबूत हैं, जो लोकतंत्र को कमजोर करते हैं।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

120. नेपाल में 2008 में राजतंत्र समाप्त होने के बाद पहला मुख्य परिवर्तन क्या था?
(A) यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया।

(B) यह एक हिंदू राज्य बना रहा।
(C) सेना ने शासन पर कब्जा कर लिया।
(D) यह भारत में विलीन हो गया।

121. नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें:
1. दक्षिण एशिया के देश केवल एक-दूसरे से लड़ते हैं, सहयोग नहीं करते।
2. शांति के प्रयास केवल द्विपक्षीय स्तर पर हुए हैं।
3. दक्षेस (SAARC) की स्थापना सहयोग की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है।
4. साफ्टा (SAFTA) का उद्देश्य पूरे दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना है।
5. सभी छोटे देश साफ्टा को लेकर उत्साहित हैं और उन्हें भारत से कोई भय नहीं है।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3 और 4
(C) केवल 1, 3 और 5
(D) केवल 2, 4 और 5

122. दक्षिण एशिया का वह कौन सा देश है जिसने ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था के कारण गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण सफलता पाई है?
(A) बांग्लादेश
(B) भारत
(C) पाकिस्तान
(D) नेपाल

123. श्रीलंका के जातीय संघर्ष के संदर्भ में 'तमिल ईलम' से क्या तात्पर्य है?
(A) श्रीलंका के सभी निवासियों के लिए एक संयुक्त देश
(B) सिंहली लोगों के लिए एक अलग देश
(C) एक सांस्कृतिक संगठन
(D) श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश

124. भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंधों के बारे में क्या सत्य है?
(A) भारत और नेपाल के बीच हमेशा तनावपूर्ण संबंध रहे हैं।
(B) भारत के भूटान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं।
(C) बांग्लादेश और भारत के बीच कोई मतभेद नहीं है।
(D) मालदीव के साथ भारत के संबंध शत्रुतापूर्ण हैं।

125. निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें:
सूची I: (देश)
P. पाकिस्तान
Q. बांग्लादेश
R. नेपाल
S. श्रीलंका

सूची II: (राजधानी)
1. काठमांडू
2. कोलंबो/श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे
3. इस्लामाबाद
4. ढाका

(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-2, Q-1, R-4, S-3
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

126. दक्षिण एशिया के किस देश के बारे में यह कहा जाता है कि उसकी सीमाएँ दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों से मिलती हैं और उसकी स्थिति केंद्रीय है?
(A) पाकिस्तान
(B) बांग्लादेश
(C) नेपाल
(D) भारत

127. 1971 के भारत-पाक युद्ध का तात्कालिक परिणाम क्या था?
(A) पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश के रूप में उदय।
(B) कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय।
(C) शिमला समझौते पर हस्ताक्षर।
(D) पाकिस्तान में सैनिक शासन की समाप्ति।

128. नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें:
1. भारत में आज़ादी के बाद से हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था रही है।
2. पाकिस्तान में कभी भी लोकतांत्रिक सरकार नहीं बनी।
3. 2008 में भूटान संवैधानिक राजतंत्र बन गया।
4. नेपाल में अभी भी राजतंत्र कायम है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2 और 4
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) केवल 2, 3 और 4

129. रोहिंग्या लोगों के म्यांमार से प्रवास का मसला किन दक्षिण एशियाई देशों के बीच मतभेद का कारण रहा है?
(A) भारत और नेपाल
(B) भारत और बांग्लादेश
(C) बांग्लादेश और पाकिस्तान
(D) नेपाल और भूटान

130. 2014 में दक्षेस का 18वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था?
(A) काठमांडू, नेपाल
(B) ढाका, बांग्लादेश
(C) थिम्पू, भूटान
(D) नई दिल्ली, भारत

131. भारत द्वारा 1987 में श्रीलंका में सैन्य हस्तक्षेप (शांति सेना भेजना) का क्या परिणाम हुआ?
(A) लिट्टे का तत्काल समर्पण हो गया।
(B) श्रीलंका में स्थायी शांति स्थापित हो गई।
(C) भारतीय सेना लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई।

(D) भारत और श्रीलंका के संबंध हमेशा के लिए टूट गए।

132. दक्षिण एशिया क्षेत्र की सुरक्षा के संबंध में विशेषज्ञों का क्या मानना है?
(A) विश्व का सबसे सुरक्षित और स्थिर क्षेत्र है।
(B) इस क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी कोई चिंता नहीं है।
(C) केवल बाहरी शक्तियां ही इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा हैं।
(D) यह क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से खतरे की आशंका वाला क्षेत्र है।

133. नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें:
1. जनरल अयूब खान ने निर्वाचित सरकार को हटाकर सत्ता संभाली।
2. जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार 1971 से 1977 तक कायम रही।
3. 1988 में बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी।
4. 1999 में जेनरल परवेज़ मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ़ को हटा दिया।
5. 2008 से पाकिस्तान में लगातार सैनिक शासन रहा है।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2, 3
(B) केवल 2, 3, 4
(C) केवल 1, 2, 3, 4
(D) उपरोक्त सभी

134. दक्षिण एशिया के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है?
(A) यह भौगोलिक दृष्टि से एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र है।
(B) चीन को इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश और अंग माना जाता है।
(C) इस क्षेत्र में भाषाई, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अनूठापन है।
(D) यह हर अर्थ में विविधताओं से भरा-पूरा इलाका है।

135. नीचे दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें:
अभिकथन (A): दक्षेस अपनी स्थापना के बाद बहुत अधिक सफल नहीं हो पाया है।
कारण (R): सदस्य देशों के बीच मौजूद राजनीतिक विभेदों और आपसी झगड़ों ने इसकी सफलता को सीमित कर दिया है।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

136. भारत के पड़ोसियों के संदर्भ में, चटगांव पर्वतीय क्षेत्र किस देश में स्थित है?
(A) बांग्लादेश
(B) नेपाल
(C) भूटान
(D) म्यांमार

137. 1990 के दशक में नेपाल में हुए त्रिकोणीय संघर्ष में कौन से तीन पक्ष शामिल थे?
(A) राजतंत्र-समर्थक, लोकतंत्र-समर्थक और कम्युनिस्ट
(B) भारत, चीन और राजा की सेना
(C) माओवादी, राजा की सेना और लोकतंत्र-समर्थक
(D) लोकतंत्र-समर्थक, माओवादी और भारत

138. 1988 में भारत ने मालदीव में किस प्रकार की सैन्य सहायता प्रदान की थी?
(A) भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए।
(B) गृहयुद्ध को दबाने के लिए।
(C) सुनामी राहत कार्यों के लिए।
(D) एक लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने के लिए।

139. दक्षिण एशिया के भविष्य के बारे में कौन सा कथन सही है?
(A) यह क्षेत्र हमेशा संघर्षों की आशंका वाला बना रहेगा।
(B) इसका भविष्य पूरी तरह से बाहरी शक्तियों जैसे चीन और अमरीका पर निर्भर है।
(C) इस क्षेत्र का कोई भविष्य नहीं है।
(D) यह एक क्षेत्रीय गुट के रूप में उभरेगा या नहीं, यह यहाँ के लोगों और सरकारों पर अधिक निर्भर है।

140. भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के लिए किए जाने वाले "विश्वास बहाली के उपाय" का क्या अर्थ है?
(A) दोनों देशों द्वारा एक-दूसरे पर हमला करने की तैयारी।
(B) युद्ध के जोखिम को कम करने और आपसी समझ बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम।
(C) केवल व्यापारिक संबंध स्थापित करना।
(D) तीसरे पक्ष को मध्यस्थता के लिए आमंत्रित करना।

141. नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें:
1. श्रीलंका ब्रिटेन से आजाद होने के बाद से ही एक सफल लोकतंत्र रहा है।
2. बांग्लादेश में शीतयुद्ध के बाद के सालों में लोकतंत्र कायम रहा है।
3. 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था।
4. भूटान 2008 में एकदलीय तानाशाही बन गया।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1, 2 और 3
(C) केवल 3 और 4
(D) 1, 2, 3 और 4 सभी

142. पाकिस्तान ने 1977 में हुए सैनिक तख्तापलट का नेतृत्व किसने किया था?
(A) अयूब खान
(B) याहिया खान
(C) परवेज मुशर्रफ
(D) जियाउल-हक

143. भारत के किस पड़ोसी देश को "हिमालयी देश" के रूप में वर्णित किया गया है जहाँ संवैधानिक राजतंत्र है?
(A) भूटान
(B) नेपाल
(C) बांग्लादेश
(D) म्यांमार

144. शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ किस देश ने अपने संबंध बेहतर किए हैं और वह भारत-पाक के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है?
(A) चीन
(B) अमरीका
(C) रूस
(D) जापान

145. दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियाँ कैसे प्रभावित करती हैं?
(A) बाहरी शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
(B) चीन की पाकिस्तान से साझेदारी और क्षेत्र में अमरीकी हित जैसी बाहरी शक्तियाँ यहाँ के संबंधों को प्रभावित करती हैं।
(C) केवल यूरोपीय संघ ही संबंधों को प्रभावित करता है।
(D) बाहरी शक्तियां हमेशा शांति स्थापित करने में ही सफल होती हैं।

146. नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें:
1. इस क्षेत्र की जनता लोकतंत्र की आकांक्षाओं में सहभागी है।
2. इस क्षेत्र के लोग तानाशाही को लोकतंत्र से बेहतर मानते हैं।
3. प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का यहाँ के नागरिक समर्थन करते हैं।
4. यहाँ यह माना जाता है कि लोकतंत्र केवल धनी देशों के लिए है।
5. दक्षिण एशिया के अनुभवों ने लोकतंत्र की वैश्विक कल्पना के दायरे को बढ़ाया है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(A) केवल 1, 2, 3
(B) केवल 1, 3, 5
(C) केवल 2, 3, 4
(D) केवल 3, 4, 5

147. 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिलने पर उसका तत्कालीन नाम क्या था?
(A) सिंहल
(B) ईलम
(C) सिलोन
(D) लंका

148. पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का संबंध किस नेता से है?
(A) नवाज शरीफ
(B) परवेज मुशर्रफ
(C) इमरान खान
(D) बेनजीर भुट्टो

149. बांग्लादेश ने 1991 के बाद किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया है?
(A) एकदलीय शासन
(B) सैनिक तानाशाही
(C) बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र
(D) अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली

150. 'विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद' के डर से किन देशों ने पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया?
(A) रूस और चीन
(B) अमरीका तथा अन्य पश्चिमी देश
(C) भारत और ईरान
(D) सऊदी अरब और तुर्की

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) की स्थापना 1985 में इस उम्मीद के साथ की गई थी कि यह सदस्य देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय एकीकरण का एक शक्तिशाली माध्यम बनेगा। इसके चार्टर में गरीबी उन्मूलन, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना, और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य शामिल थे। हालाँकि, अपनी स्थापना के लगभग चार दशकों के बाद भी, सार्क अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में विफल रहा है। इसका मुख्य कारण सदस्य देशों, विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच गहरे राजनीतिक और सैन्य विवाद हैं। सार्क का एक अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि द्विपक्षीय और विवादास्पद मुद्दों को मंच पर नहीं उठाया जाएगा, लेकिन व्यवहार में, इन अनसुलझे विवादों की छाया हमेशा संगठन की कार्यप्रणाली पर पड़ती रही है। परिणामस्वरूप, सार्क शिखर सम्मेलन अक्सर स्थगित या रद्द होते रहे हैं, जिससे महत्वपूर्ण पहलों पर प्रगति रुक जाती है। 2004 में हस्ताक्षरित दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) समझौता भी गैर-टैरिफ बाधाओं और आपसी अविश्वास के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाया है। विशेषज्ञों का तर्क है कि जब तक सदस्य राष्ट्र, विशेषकर भारत और पाकिस्तान, अपने द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, तब तक सार्क एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन के बजाय एक प्रतीकात्मक मंच बना रहेगा।

उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर

दीजिए।

151. सार्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था?
(A) केवल सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना
(B) आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना
(C) सदस्य देशों के बीच सैन्य गठबंधन बनाना
(D) केवल गरीबी उन्मूलन के लिए नीतियां बनाना

152. स्रोत के अनुसार, सार्क की विफलता का सबसे प्रमुख कारण क्या है?
(A) भारत और पाकिस्तान के बीच गहरे राजनीतिक और सैन्य विवाद
(B) सदस्य देशों के बीच भाषाई भिन्नता
(C) अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी
(D) संगठन के चार्टर में स्पष्ट लक्ष्यों का अभाव

153. सार्क के सिद्धांत के अनुसार, किस प्रकार के मुद्दों को मंच पर नहीं उठाया जाना चाहिए?
(A) आर्थिक सहयोग से संबंधित मुद्दे
(B) सांस्कृतिक आदान-प्रदान के मुद्दे
(C) द्विपक्षीय और विवादास्पद मुद्दे
(D) पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दे

154. दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) समझौते के अपेक्षित परिणाम न दे पाने का क्या कारण बताया गया है?
(A) सदस्य देशों की भौगोलिक दूरी
(B) वैश्विक आर्थिक मंदी का प्रभाव
(C) समझौते में केवल कुछ ही वस्तुओं का शामिल होना
(D) गैर-टैरिफ बाधाएं और आपसी अविश्वास

155. अनुच्छेद का क्या निष्कर्ष है?
(A) सार्क एक अत्यंत सफल क्षेत्रीय संगठन बन गया है।
(B) सार्क की सफलता केवल आर्थिक कारकों पर निर्भर करती है।
(C) राजनीतिक इच्छाशक्ति, विशेषकर भारत-पाकिस्तान संबंधों में सुधार, सार्क की प्रभावशीलता के लिए महत्वपूर्ण है।
(D) सार्क को समाप्त कर एक नया संगठन बनाया जाना चाहिए।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

श्रीलंका में जातीय संघर्ष की जड़ें औपनिवेशिक काल और उसके बाद की राजनीतिक प्रक्रियाओं में गहरी हैं। 1948 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, बहुसंख्यक सिंहली समुदाय के नेताओं ने एक ऐसी राष्ट्र-निर्माण की परियोजना शुरू की जिसने तमिल अल्पसंख्यक समुदाय को हाशिए पर धकेल दिया। 1956 का 'सिंहला ओनली एक्ट' इसका एक प्रमुख उदाहरण था, जिसने सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा बना दिया और तमिल भाषा की स्थिति को कम कर दिया। इस अधिनियम ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में तमिल भाषी नागरिकों के अवसरों को गंभीर रूप से सीमित कर दिया। इसके अतिरिक्त, सरकार ने बौद्ध धर्म को प्रमुखता दी, जो कि अधिकांश सिंहलियों का धर्म है, जिससे तमिल, जो मुख्य रूप से हिंदू या ईसाई हैं, और भी अलग-थलग महसूस करने लगे। इन भेदभावपूर्ण नीतियों के जवाब में, शुरुआत में तमिल राजनीतिक दलों ने संघीय ढांचे के भीतर स्वायत्तता और समान अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अभियान चलाया। हालाँकि, जब इन मांगों को लगातार नजरअंदाज किया गया और राज्य प्रायोजित हिंसा की घटनाएँ बढ़ीं, तो तमिल युवाओं का एक वर्ग उग्रवाद की ओर मुड़ गया। इसी पृष्ठभूमि में, 1980 के दशक की शुरुआत में 'लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम' (लिट्टे) जैसे सशस्त्र समूहों का उदय हुआ, जिन्होंने एक स्वतंत्र तमिल राज्य 'तमिल ईलम' की स्थापना के लिए एक हिंसक संघर्ष शुरू कर दिया, जिसने श्रीलंका को दशकों तक चलने वाले गृहयुद्ध में झोंक दिया।

उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

156. स्रोत के अनुसार, श्रीलंका में जातीय संघर्ष का मूल कारण क्या था?
(A) विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप
(B) स्वतंत्रता के बाद की राष्ट्र-निर्माण परियोजना जिसने तमिल समुदाय को हाशिए पर डाला
(C) आर्थिक संसाधनों का असमान वितरण
(D) सिंहली और तमिल समुदायों के बीच केवल भाषाई मतभेद

157. 'सिंहला ओनली एक्ट' का तमिल समुदाय पर क्या तात्कालिक प्रभाव पड़ा?
(A) इससे तमिलों के लिए व्यापार के नए अवसर खुले।
(B) इसने तमिल भाषा को भी राजभाषा का दर्जा दिया।
(C) इसने तमिल समुदाय को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया।
(D) इसने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में तमिलों के अवसरों को सीमित कर दिया।

158. अनुच्छेद के अनुसार, तमिल राजनीतिक दलों की प्रारंभिक मांग क्या थी?
(A) संघीय ढांचे के भीतर स्वायत्तता और समान अधिकार
(B) एक पूर्णतः स्वतंत्र तमिल राज्य का निर्माण
(C) सिंहली भाषा को पूरी तरह से समाप्त करना
(D) सभी तमिलों के लिए विदेशों में प्रवास की सुविधा

159. 'लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम' (लिट्टे) के उदय का मुख्य कारण क्या था?
(A) पड़ोसी देशों से वित्तीय सहायता का वादा
(B) सिंहली समुदाय के नेताओं के साथ व्यक्तिगत दुश्मनी
(C) सरकार द्वारा शांतिपूर्ण राजनीतिक मांगों की लगातार अनदेखी और राज्य प्रायोजित हिंसा
(D) अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का दबाव

160. यह अनुच्छेद श्रीलंका के जातीय संघर्ष के बारे में क्या मुख्य तर्क प्रस्तुत करता है?
(A) भेदभावपूर्ण राज्य नीतियों ने शांतिपूर्ण राजनीतिक प्रतिरोध को सशस्त्र संघर्ष में बदल दिया।
(B) संघर्ष पूरी तरह से आर्थिक प्रकृति का था।
(C) संघर्ष केवल कुछ वर्षों तक ही चला।
(D) संघर्ष का श्रीलंका की राजनीति पर कोई दीर्घकालिक प्रभाव नहीं पड़ा।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में लोकतंत्र की अस्थिरता और बार-बार सैन्य हस्तक्षेप एक जटिल परिघटना है जिसके मूल में कई संस्थागत और संरचनात्मक कारक हैं। यहाँ की राजनीति को अक्सर 'ट्रोइका' या तीन शक्तिशाली स्तंभों - सेना, नौकरशाही और भूस्वामी अभिजात वर्ग - के प्रभाव से समझा जाता है। इनमें सेना सबसे प्रमुख और निर्णायक भूमिका निभाती रही है। भारत के साथ निरंतर तनाव और राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा ने सेना को एक ऐसा विशेषाधिकार प्राप्त स्थान दिया है जहाँ वह राष्ट्रीय हितों की संरक्षक के रूप में खुद को प्रस्तुत करती है। सेना ने अपने व्यापक वाणिज्यिक हितों का भी विकास किया है, जिसे 'मिलबस' (मिलिट्री बिजनेस) कहा जाता है, जिससे वह देश की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख हितधारक बन गई है। यह आर्थिक शक्ति उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को और मजबूत करती है। इसके अलावा, राजनीतिक दलों की कमजोरी, भ्रष्टाचार के आरोप, और आंतरिक कलह ने भी सेना को हस्तक्षेप करने का अवसर और औचित्य प्रदान किया है। जब भी नागरिक सरकारें लोकप्रिय समर्थन खोने लगती हैं या सेना के हितों को चुनौती देती हैं, तो सैन्य तख्तापलट की संभावना बढ़ जाती है। हालाँकि पाकिस्तान में एक जीवंत नागरिक समाज, स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया मौजूद है, लेकिन सेना के संस्थागत प्रभुत्व को निर्णायक रूप से चुनौती देना अभी भी एक बड़ी बाधा बना हुआ है, जिससे लोकतंत्र की जड़ें गहरी नहीं हो पाती हैं।
उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

161. स्रोत में उल्लिखित 'ट्रोइका' में कौन से तीन स्तंभ शामिल हैं?
(A) सेना, न्यायपालिका और मीडिया
(B) राजनेता, उद्योगपति और धार्मिक नेता
(C) नौकरशाही, media और भूस्वामी अभिजात वर्ग
(D) सेना, नौकरशाही और भूस्वामी अभिजात वर्ग

162. अनुच्छेद के अनुसार, सेना को पाकिस्तान की राजनीति में विशेषाधिकार प्राप्त स्थान क्यों मिला है?
(A) देश के संविधान में इसके लिए विशेष प्रावधान होने के कारण
(B) भारत के साथ निरंतर तनाव और राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा के कारण
(C) देश की सभी चुनावी प्रक्रियाओं का संचालन करने के कारण
(D) जनता के बीच इसके नेताओं की अत्यधिक लोकप्रियता के कारण

163. 'मिलबस' (मिलिट्री बिजनेस) शब्द का क्या अर्थ है?
(A) सेना द्वारा संचालित गुप्त सैन्य अभियान
(B) सेना और राजनेताओं के बीच व्यापारिक समझौते
(C) सेना के व्यापक वाणिज्यिक और व्यावसायिक हित
(D) पाकिस्तान का वार्षिक सैन्य बजट

164. अनुच्छेद के अनुसार, कौन सी परिस्थितियाँ सेना को राजनीतिक हस्तक्षेप का अवसर प्रदान करती हैं?
(A) जब नागरिक सरकारें अत्यधिक लोकप्रिय हो जाती हैं
(B) जब देश में आर्थिक समृद्धि चरम पर होती है
(C) जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सैन्य शासन का समर्थन करता है
(D) जब राजनीतिक दल कमजोर होते हैं और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करते हैं

165. स्रोत का केंद्रीय तर्क क्या है?
(A) पाकिस्तान में लोकतंत्र की अस्थिरता का मुख्य कारण सेना का संस्थागत प्रभुत्व और राजनीतिक दलों की कमजोरी है।
(B) पाकिस्तान में लोकतंत्र पूरी तरह से सफल और स्थिर है।
(C) पाकिस्तान की सारी राजनीतिक समस्याएँ केवल बाहरी शक्तियों द्वारा उत्पन्न की गई हैं।
(D) पाकिस्तान में न्यायपालिका और मीडिया पूरी तरह से सेना के नियंत्रण में हैं।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका एक जटिल और विरोधाभासी आयाम प्रस्तुत करती है। अपने विशाल आकार, जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और सैन्य क्षमता के कारण, भारत इस क्षेत्र में एक निर्विवाद रूप से प्रभावशाली शक्ति है। यह असंतुलित शक्ति संरचना एक ऐसी स्थिति को जन्म देती है जिसे अक्सर 'BIG BROTHER' सिंड्रोम के रूप में वर्णित किया जाता है। एक ओर, क्षेत्र के छोटे देश सुरक्षा, आर्थिक सहायता और आपदा के समय तत्काल सहायता के लिए भारत की ओर देखते हैं। 1988 में मालदीव में तख्तापलट के प्रयास को विफल करने के लिए भारतीय सैन्य हस्तक्षेप ('ऑपरेशन कैक्टस') या नेपाल और भूटान को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता इसके उदाहरण हैं। दूसरी ओर, यही प्रभुत्व पड़ोसी देशों में भय और संदेह भी उत्पन्न करता है। उन्हें अक्सर यह आशंका रहती है कि भारत उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है और उनकी संप्रभुता को कम कर सकता है। भारत की जल-बंटवारा नीतियों, व्यापार असंतुलन और सीमा विवादों को अक्सर इसी नजरिए से देखा जाता है। उदाहरण के लिए, नेपाल में कुछ समूह भारत पर उसके जल संसाधनों का अनुचित लाभ उठाने का आरोप लगाते हैं, जबकि बांग्लादेश में तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर असंतोष है। इस प्रकार, भारत को एक साथ एक आवश्यक भागीदार और एक संभावित आधिपत्यवादी शक्ति के रूप में देखा जाता है, और नई दिल्ली के लिए इस दोहरी धारणा को संतुलित करना

एक निरंतर कूटनीतिक चुनौती बनी रहती है।
उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

166. 'बिग ब्रदर' सिंड्रोम का क्या अर्थ है, जैसा कि अनुच्छेद में वर्णित है?
(A) भारत के सभी पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं।
(B) भारत का प्रभुत्व पड़ोसियों में प्रशंसा और भय दोनों उत्पन्न करता है।
(C) भारत अपने पड़ोसी देशों के मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता।
(D) छोटे देश हमेशा भारत के नेतृत्व को बिना किसी संदेह के स्वीकार करते हैं।

167. अनुच्छेद में भारत की सकारात्मक भूमिका के उदाहरण के रूप में किसका उल्लेख किया गया है?
(A) श्रीलंका में जातीय संघर्ष को बढ़ावा देना
(B) 1988 में मालदीव में तख्तापलट के प्रयास को विफल करना
(C) पाकिस्तान के साथ सभी विवादों को हल करना
(D) नेपाल के साथ व्यापार पूरी तरह से बंद करना

168. स्रोत के अनुसार, पड़ोसी देश भारत से क्यों आशंकित रहते हैं?
(A) उन्हें डर है कि भारत उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है और उनकी संप्रभुता को कम कर सकता है।
(B) क्योंकि भारत उन्हें कोई आर्थिक सहायता नहीं देता।
(C) क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश नहीं है।
(D) उन्हें डर है कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को अन्य देशों के लिए बंद कर देगा।

169. अनुच्छेद में भारत और उसके पड़ोसियों के बीच तनाव के स्रोत के रूप में किन मुद्दों का उल्लेख है?
(A) खेल प्रतिस्पर्धा और सांस्कृतिक मतभेद
(B) समान भाषा और धर्म का अभाव
(C) जल-बंटवारा, व्यापार असंतुलन और सीमा विवाद
(D) ऐतिहासिक स्मारकों पर स्वामित्व के दावे

170. भारत के लिए मुख्य कूटनीतिक चुनौती क्या है, जैसा कि स्रोत में बताया गया है?
(A) दुनिया की अन्य महाशक्तियों के साथ संबंध बनाना
(B) अपनी सैन्य शक्ति को और अधिक बढ़ाना
(C) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट प्राप्त करना
(D) एक आवश्यक भागीदार और एक संभावित आधिपत्यवादी शक्ति की दोहरी धारणा को संतुलित करना

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
दक्षिण एशिया में जल की राजनीति तेजी से क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बनती जा रही है। इस क्षेत्र की अधिकांश प्रमुख नदियाँ, जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, एक से अधिक देशों से होकर बहती हैं, जिससे वे स्वाभाविक रूप से सहयोग और संघर्ष दोनों का स्रोत बन जाती हैं। हालाँकि 1960 की सिंधु जल संधि (भारत और पाकिस्तान के बीच) को अक्सर एक सफल उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन यह एक अपवाद है। हाल के दशकों में, जनसंख्या वृद्धि, तेजी से शहरीकरण, और कृषि के लिए बढ़ती मांग ने जल संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डाला है। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जैसे ग्लेशियरों का पिघलना और मानसून के पैटर्न में अप्रत्याशितता, इस समस्या को और गंभीर बना रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर लंबे समय से चला आ रहा विवाद इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। इसी तरह, चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र (यारलुंग त्सांगपो) नदी पर ऊपरी क्षेत्रों में बनाए जा रहे बड़े बांधों ने निचले तटीय राज्यों, विशेष रूप से भारत और बांग्लादेश में चिंता पैदा कर दी है। इन विवादों को अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के रूप में देखा जाता है, जिससे तकनीकी समाधान के बजाय राजनीतिक तनाव बढ़ता है। यदि इन मुद्दों का प्रबंधन पारदर्शी और न्यायसंगत डेटा-साझाकरण, संयुक्त बेसिन प्रबंधन और प्रभावी विवाद समाधान तंत्र के माध्यम से नहीं किया गया, तो भविष्य में 'जल युद्ध' की आशंका को खारिज नहीं किया सकता।
उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

171. दक्षिण एशिया में जल विवादों के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है?
(A) नदियों में पानी की मात्रा में अप्रत्याशित वृद्धि
(B) देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग की कमी
(C) जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, और कृषि की बढ़ती मांग
(D) विदेशी शक्तियों द्वारा जल संसाधनों का उपयोग

172. अनुच्छेद में किस संधि को जल-साझाकरण में एक सफल अपवाद के रूप में वर्णित किया गया है?
(A) गंगा जल संधि
(B) सिंधु जल संधि
(C) तीस्ता जल संधि
(D) ब्रह्मपुत्र जल संधि

173. चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर बांधों के निर्माण से किन देशों में चिंता उत्पन्न हुई है?
(A) पाकिस्तान और नेपाल
(B) श्रीलंका और मालदीव
(C) भूटान और म्यांमार
(D) भारत और बांग्लादेश

174. अनुच्छेद के अनुसार, जल विवादों को अक्सर किस रूप में देखा जाता है, जिससे तनाव बढ़ता है?
(A) एक राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के रूप में
(B) एक आर्थिक अवसर के रूप में
(C) एक पर्यावरणीय अवसर के रूप में
(D) एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान के मुद्दे के रूप में

175. स्रोत जल विवादों को हल करने के लिए क्या समाधान सुझाता है?

(A) नदियों पर सैन्य नियंत्रण स्थापित करना
(B) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सभी मामलों को ले जाना
(C) पारदर्शी डेटा-साझाकरण, संयुक्त बेसिन प्रबंधन और प्रभावी विवाद समाधान तंत्र
(D) नदियों के प्रवाह को पूरी तरह से रोक देना

ANSWERS

1. (B) बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका
दक्षिण एशिया शब्द का प्रयोग सामान्यतः उन देशों के समूह के लिए किया जाता है जो भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा हैं। इसमें मुख्य रूप से सात देश शामिल हैं जो भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। उत्तर में हिमालय पर्वतमाला और दक्षिण में हिंद महासागर इस क्षेत्र की प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारण करते हैं। यह विविधतापूर्ण क्षेत्र साझा इतिहास और चुनौतियों को दर्शाता है।

2. (A) यह क्षेत्र उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा है।
दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति इसे दुनिया के अन्य क्षेत्रों से अलग और विशिष्ट बनाती है। इसके उत्तरी भाग में गगनचुंबी हिमालय की श्रेणियां रक्षक के रूप में स्थित हैं। दक्षिणी भाग विशाल हिंद महासागर से घिरा है, जबकि पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। यह प्राकृतिक घेरा इस क्षेत्र की विशिष्ट सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को सुरक्षित रखने में सहायक रहा है।

3. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
दक्षिण एशिया के देशों में शासन की प्रणालियाँ एक समान नहीं रही हैं। भारत और श्रीलंका ने अपनी आजादी के बाद से ही लोकतंत्र को सफलतापूर्वक बनाए रखा है। इसके विपरीत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में समय-समय पर लोकतांत्रिक शासन और सैनिक तानाशाही के बीच सत्ता का परिवर्तन होता रहा है। यह विविधता इस क्षेत्र की जटिल राजनीतिक यात्रा और आंतरिक चुनौतियों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

4. (D) नेपाल
नेपाल एक लंबे समय तक हिंदू राजतंत्र के रूप में जाना जाता रहा था। वहां दशकों तक चले लोकतंत्र-समर्थक आंदोलनों और माओवादी विद्रोह के परिणामस्वरूप शासन प्रणाली में भारी बदलाव आया। अंततः वर्ष 2008 में नेपाल में सदियों पुरानी राजशाही को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वैश्विक पटल पर एक नई पहचान के साथ उभरा।

5. (A) P-2, Q-3, R-1, S-4
मालदीव 1968 तक एक सल्तनत था और बाद में वहां गणतंत्र की स्थापना हुई। भूटान वर्ष 2008 में एक संवैधानिक राजतंत्र बना, जबकि नेपाल ने उसी वर्ष राजशाही को पूरी तरह समाप्त कर दिया। पाकिस्तान में 2008 के बाद से निरंतर लोकतांत्रिक शासन बना हुआ है। यह क्षेत्रीय घटनाक्रम दक्षिण एशिया के देशों में राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर बढ़ते झुकाव और राजनीतिक परिवर्तन को दर्शाता है।

6. (B) 2005
मालदीव के राजनीतिक इतिहास में वर्ष 2005 एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस दौरान देश की संसद ने एकमत होकर बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। इससे पहले वहां राष्ट्रपति शासन के तहत एक दलीय व्यवस्था का प्रभाव था। इस निर्णय ने मालदीव में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया और विपक्षी दलों को सक्रिय राजनीति में भाग लेने का अवसर प्रदान किया।

7. (B) केवल 1, 2 और 3
दक्षिण एशिया के पांच बड़े देशों में किए गए व्यापक सर्वेक्षणों से यह स्पष्ट हुआ है कि यहां के लोग लोकतंत्र को अत्यधिक महत्व देते हैं। सामान्य धारणा के विपरीत कि लोकतंत्र केवल विकसित और धनी देशों में सफल हो सकता है, इस क्षेत्र के नागरिकों ने लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति गहरी आस्था दिखाई है। यह अनुभव लोकतंत्र की वैश्विक स्वीकार्यता और इसकी समावेशी क्षमता को दृढ़ता प्रदान करता है।

8. (A) पाकिस्तान
वर्ष 1947 में विभाजन के समय बांग्लादेश 'पूर्वी पाकिस्तान' के रूप में अस्तित्व में आया था। यह 1971 तक पाकिस्तान का एक हिस्सा रहा, लेकिन भाषाई और सांस्कृतिक भेदभाव के कारण वहां जन-असंतोष बढ़ता गया। पश्चिमी पाकिस्तान के सैन्य प्रभुत्व के खिलाफ चले लंबे संघर्ष और भारत के हस्तक्षेप के बाद दिसंबर 1971 में बांग्लादेश एक संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ।

9. (C) एक मजबूत और स्वतंत्र न्यायपालिका की उपस्थिति।
पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थिरता के मार्ग में सेना, कट्टरपंथी धार्मिक समूहों और शक्तिशाली भूस्वामी अभिजनों का अत्यधिक प्रभाव एक बड़ी बाधा रहा है। इसके अतिरिक्त, भारत के साथ निरंतर बनी रहने वाली तनातनी सैन्य शासन को उचित ठहराने का आधार प्रदान करती है। हालांकि, वहां एक स्वतंत्र न्यायपालिका और सक्रिय प्रेस की मौजूदगी लोकतंत्र की बहाली और रक्षा के लिए एक सकारात्मक कारक मानी जाती है।

10. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
पाकिस्तान में सेना का राजनीति में हस्तक्षेप अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किया जाता है। वहां के सैन्य समर्थक समूह यह तर्क देते हैं कि राजनीतिक दलों के आपसी कलह और भ्रष्टाचार से देश की अखंडता खतरे में पड़ सकती है। भारत के

साथ लंबे समय से चले आ रहे विवाद ने इस धारणा को और मजबूती दी है, जिससे सैनिक शासन को जनता के बीच वैधता प्राप्त करने में मदद मिली।

11. (D) जनरल परवेज़ मुशर्रफ़
पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर सैन्य शासन स्थापित करने की घटनाएँ कई बार हुई हैं। वर्ष 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्तापलट कर सत्ता पर अधिकार कर लिया। उन्होंने स्वयं को मुख्य कार्यकारी और बाद में राष्ट्रपति के रूप में स्थापित किया। यह घटना पाकिस्तान में नागरिक शासन की कमजोरी और सेना के राजनीतिक वर्चस्व का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उदाहरण मानी जाती है।

12. (A) 1, 2, 3, 4
दक्षिण एशिया के इतिहास में 1966 का ताशकंद समझौता एक महत्वपूर्ण शांति प्रयास था। इसके बाद 1971 में भारत-पाक युद्ध के परिणामस्वरूप बांग्लादेश अस्तित्व में आया। 1972 में दोनों देशों के बीच शिमला समझौता हुआ, जिसका उद्देश्य शांति स्थापित करना था। अंततः 1977 में जनरल जियाउल-हक ने ज़ुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार का तख्तापलट कर सत्ता संभाली। ये घटनाएँ क्षेत्र की बदलती राजनीति को दर्शाती हैं।

13. (C) शेख मुजीबुर्रहमान
पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान के राजनीतिक और भाषाई प्रभुत्व के विरुद्ध चले जन-आंदोलन का नेतृत्व शेख मुजीबुर्रहमान ने किया था। उनकी पार्टी अवामी लीग ने स्वायत्तता की माँग की और 1970 के चुनावों में भारी जीत हासिल की। हालांकि, उन्हें जेल में डाल दिया गया, जिससे जनता का विद्रोह और तेज हो गया। अंततः उनके नेतृत्व और संघर्ष के कारण 1971 में स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण संभव हुआ।

14. (D) उपरोक्त सभी
बांग्लादेश का प्रारंभिक राजनीतिक काल उथल-पुथल भरा रहा। शेख मुजीब ने 1975 में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई, लेकिन जल्द ही उनकी सैन्य हत्या कर दी गई। इसके बाद जियाउर्रहमान और फिर जनरल इरशाद के तहत सैन्य शासन रहा। 1990 के व्यापक जन-आंदोलन ने लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त किया। 1991 से बांग्लादेश में बहुदलीय संसदीय लोकतंत्र सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, जो वहां की जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को दर्शाता है।

15. (A) नेपाल में माओवादी कभी भी अपना प्रभाव जमाने में कामयाब नहीं हुए।
नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य में माओवादियों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने देश के कई हिस्सों में अपना मजबूत प्रभाव कायम किया और राजशाही के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष छेड़ा। माओवादियों की माँग थी कि संविधान सभा का गठन हो और राजतंत्र को समाप्त किया जाए। अंततः वे मुख्यधारा की राजनीति में शामिल हुए और नेपाल को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाई।

16. (B) सात दलों का गठबंधन, माओवादी और सामाजिक नागरिक कार्यकर्ता
नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के लिए अप्रैल 2006 में एक ऐतिहासिक देशव्यापी आंदोलन हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व सात राजनीतिक दलों के गठबंधन (एसपीए) ने किया था, जिसे माओवादियों और नागरिक समाज के विभिन्न वर्गों का व्यापक समर्थन प्राप्त था। राजा द्वारा संसद भंग किए जाने के विरोध में हुए इस जबरदस्त प्रदर्शन ने राजशाही को झुकने पर मजबूर कर दिया और अंततः लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई।

17. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
पाकिस्तान 1954-55 में सिएटो और सेंटो जैसे सैन्य गुटों का हिस्सा बना। इसके बाद 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक सिंधु नदी जल समझौता हुआ। वर्ष 1966 में ताशकंद समझौता हुआ, जिसने 1965 के युद्ध को समाप्त किया। अंततः 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया। ये घटनाएं दक्षिण एशिया की बदलती सुरक्षा और रणनीतिक स्थिति को दर्शाती हैं।

18. (A) 1948
श्रीलंका, जिसे उस समय सिलोन कहा जाता था, ने 4 फरवरी 1948 को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। आजादी के बाद से ही श्रीलंका ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक बनाए रखा है। हालांकि, देश को लंबे समय तक जातीय संघर्ष की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वहां की लोकतांत्रिक संस्थाएं निरंतर कार्य करती रहीं। यह दक्षिण एशिया में लोकतंत्र के स्थायित्व का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

19. (B) केवल 1, 2 और 3
श्रीलंका में आजादी के बाद बहुसंख्यक सिंहली समुदाय का राजनीति पर प्रभुत्व रहा, जिससे अल्पसंख्यक तमिल समुदाय में असंतोष पैदा हुआ। सिंहली राष्ट्रवादियों ने तमिलों के प्रति सख्त रुख अपनाया, जिसके परिणामस्वरूप 1983 में उग्रवादी संगठन लिट्टे का उदय हुआ। लिट्टे ने तमिलों के लिए एक अलग राज्य 'तमिल ईलम' की माँग करते हुए सशस्त्र संघर्ष किया। यह जातीय संघर्ष दशकों तक श्रीलंका की शांति और प्रगति में बाधक रहा।

20. (D) 1987
श्रीलंका में बढ़ते जातीय संघर्ष और हिंसा को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1987 में श्रीलंका सरकार के साथ एक समझौता किया। इस समझौते के तहत भारतीय शांति सेना (आईपीकेएफ) को वहां भेजा गया था। हालांकि, भारतीय सेना को लिट्टे के साथ संघर्ष करना पड़ा और श्रीलंकाई जनता ने भी इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना। अंततः 1989 में वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई और 1990 में पूरी हुई।

21. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
श्रीलंका ने भीषण जातीय गृहयुद्ध का सामना करने के बावजूद आर्थिक मोर्चे पर उल्लेखनीय प्रगति की है। यह दक्षिण एशिया का पहला देश था जिसने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण और मानव विकास सूचकांकों में इसका प्रदर्शन सराहनीय रहा है। निरंतर जारी युद्ध के बावजूद वहां लोकतांत्रिक राजव्यवस्था बनी रही और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के मामले में यह क्षेत्र में अग्रणी रहा।

22. (B) जम्मू-कश्मीर प्रान्त
1947 के विभाजन के तुरंत बाद कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। 1948 के युद्धविराम के बाद कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया, जिसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) कहा जाता है। दूसरा बड़ा हिस्सा भारत का अभिन्न अंग बना और जम्मू-कश्मीर राज्य के रूप में स्थापित हुआ। यह विवाद आज भी दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव का मुख्य कारण बना हुआ है।

23. (D) विश्व बैंक
भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के जल बँटवारे को लेकर लंबे समय तक विवाद रहा। इस कठिन समस्या को सुलझाने के लिए विश्व बैंक ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। अंततः 1960 में दोनों देशों ने 'सिंधु जल संधि' पर हस्ताक्षर किए। कई युद्धों और तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद, यह संधि आज भी प्रभावी ढंग से काम कर रही है, जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग और कूटनीति की एक बड़ी सफलता मानी जाती है।

24. (A) गंगा नदी जल बंटवारा
भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के कई ऐतिहासिक मुद्दे रहे हैं, जिनमें कश्मीर विवाद और सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण प्रमुख हैं। इसके अलावा सरक्रिक की सीमा रेखा को लेकर भी दोनों देशों में मतभेद हैं। हालांकि, गंगा नदी के जल बँटवारे का मुद्दा भारत और बांग्लादेश के बीच का विषय है, न कि पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ मुख्य जल विवाद सिंधु नदी तंत्र से संबंधित रहा है।

25. (B) केवल 2, 3 और 4
भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में सहयोग और विवाद दोनों मौजूद हैं। अवैध आप्रवास का मुद्दा भारत के लिए चिंता का विषय रहा है। हालांकि, 2015 में दोनों देशों ने ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौते के तहत परिक्षेत्रों का आदान-प्रदान किया। बांग्लादेश भारत की 'लुक ईस्ट' और 'एक्ट ईस्ट' नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। दोनों देश आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग करते हैं।

26. (A) भारत-नेपाल शांति और मैत्री संधि
भारत और नेपाल के बीच संबंध अत्यंत अनूठे और घनिष्ठ हैं। दोनों देशों के बीच हुई एक विशेष संधि के तहत नागरिकों को एक-दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट और वीजा के आने-जाने और काम करने की अनुमति है। यह खुली सीमा दोनों देशों के बीच गहरे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों का आधार है। हालांकि समय-समय पर कुछ विवाद उठते हैं, लेकिन यह संधि आपसी विश्वास का प्रतीक है।

27. (D) नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन
भारत सरकार नेपाल में बढ़ते माओवादी प्रभाव को अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती मानती रही है। भारत को यह डर था कि नेपाल के माओवादी तत्वों और भारत के विभिन्न राज्यों में सक्रिय नक्सली समूहों के बीच संपर्क स्थापित हो सकता है। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी। यह चिंता दोनों देशों के बीच रणनीतिक चर्चाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है।

28. (B) P-4, Q-1, R-2, S-3
भारत और सोवियत संघ के बीच 1971 में एक ऐतिहासिक मैत्री संधि हुई थी। इसके बाद 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) की स्थापना 1985 में हुई, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था। अंततः 2004 में सदस्य देशों ने दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) पर हस्ताक्षर किए, ताकि आर्थिक संबंधों को और अधिक मजबूती दी जा सके।

29. (C) लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम
लिट्टे (LTTE) श्रीलंका का एक प्रमुख उग्रवादी संगठन था जिसने तमिलों के लिए एक अलग राष्ट्र 'तमिल ईलम' की माँग को लेकर सशस्त्र संघर्ष किया। यह संगठन श्रीलंका की सेना के साथ लंबे समय तक छापामार युद्ध में शामिल रहा। इसने श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में अपना प्रभाव कायम किया था। अंततः 2009 में श्रीलंकाई सेना की एक बड़ी कार्रवाई में इस संगठन का खात्मा हुआ और गृहयुद्ध समाप्त हुआ।

30. (D) श्रीलंका
श्रीलंका ने दक्षिण एशिया में आर्थिक सुधारों के मामले में अग्रणी भूमिका निभाई है। इसने क्षेत्र के अन्य देशों की तुलना में बहुत पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कर दिया था। इस नीति के कारण श्रीलंका ने विदेशी निवेश आकर्षित किया और व्यापार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की। गृहयुद्ध की गंभीर आंतरिक चुनौतियों के बावजूद, श्रीलंका ने अपनी आर्थिक वृद्धि दर और मानव विकास के उच्च स्तर को सफलतापूर्वक बनाए रखा।

31. (A) 1, 2, 3, 4
दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की शुरुआत 1985 में दक्षेस के पहले सम्मेलन से हुई। इसके बाद 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच शांति समझौता हुआ। क्षेत्र में सुरक्षा का माहौल तब बदला जब 1998 में भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए। अंततः 1999 में दोनों देशों के बीच करगिल का भीषण युद्ध हुआ। ये घटनाएँ इस क्षेत्र में शांति प्रयासों और संघर्षों के उतार-चढ़ाव को दर्शाती हैं।

32. (B) 1998
वर्ष 1998 दक्षिण एशिया के सामरिक इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मई 1998 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण कर अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। इसके कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने चगाई की पहाड़ियों में परमाणु परीक्षण कर इसका जवाब दिया। इन परीक्षणों के बाद यह क्षेत्र परमाणु हथियारों से लैस हो गया, जिससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंताएं और इस क्षेत्र की सुरक्षा संवेदनशीलता बढ़ गई।

33. (D) 1, 2, 3, 4 सभी
भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में आपसी अविश्वास और आरोपों का लंबा इतिहास रहा है। भारत पाकिस्तान पर कश्मीरी उग्रवादियों की मदद और आईएसआई के जरिए अशांति फैलाने का आरोप लगाता है। दूसरी ओर, पाकिस्तान भारत पर सिंध और बलूचिस्तान में हस्तक्षेप का आरोप लगाता है। इन तनावों के बावजूद, 1960 की सिंधु जल संधि जैसी व्यवस्थाएं आज भी कायम हैं, जो सहयोग की संभावनाओं को दर्शाती हैं।

34. (A) भूटान
भारत के अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों में भूटान के साथ संबंध सबसे मधुर और शांतिपूर्ण माने जाते हैं। दोनों देशों के बीच कोई बड़ा सीमा विवाद या राजनीतिक झगड़ा नहीं है। भूटान ने अपनी धरती से भारत-विरोधी उग्रवादियों को हटाने में सक्रिय मदद की है। भारत भी भूटान के विकास और पनबिजली परियोजनाओं में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है। यह दोस्ती दक्षिण एशिया में आपसी विश्वास और सहयोग का एक आदर्श उदाहरण है।

35. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
भारत का विशाल भौगोलिक आकार, बड़ी जनसंख्या और मजबूत अर्थव्यवस्था इसे दक्षिण एशिया में एक प्रभावी शक्ति बनाती है। इस प्राकृतिक प्रभुत्व के कारण पड़ोसी छोटे देशों में अक्सर यह आशंका बनी रहती है कि भारत उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। हालांकि भारत का इरादा क्षेत्रीय स्थिरता और विकास का है, लेकिन शक्ति असंतुलन के कारण छोटे देशों का शक करना एक स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है।

36. (D) भारत
नवंबर 1988 में जब श्रीलंका से आए कुछ तमिल भाड़े के सैनिकों ने मालदीव पर हमला किया और वहां तख्तापलट की कोशिश की, तब मालदीव सरकार ने भारत से सहायता माँगी। भारत ने तुरंत अपनी वायुसेना और नौसेना के जरिए 'ऑपरेशन कैक्टस' चलाकर हस्तक्षेप किया। भारतीय सेना ने घुसपैठियों को खदेड़ दिया और मालदीव की सत्ता को सुरक्षित रखा। इस घटना ने भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता की भूमिका को मजबूत किया।

37. (C) साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) की स्थापना सात दक्षिण एशियाई देशों ने मिलकर की थी। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना और सामूहिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है। यह संगठन क्षेत्रीय समस्याओं को आपसी संवाद और शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाने का एक मंच प्रदान करता है। दक्षिण एशिया के विकास और स्थिरता के लिए इस संगठन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।

38. (B) 1985
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) की औपचारिक स्थापना दिसंबर 1985 में ढाका, बांग्लादेश में हुई थी। इसकी शुरुआत दक्षिण एशियाई देशों के बीच आपसी सहयोग और विश्वास बढ़ाने के एक प्रयास के रूप में की गई थी। इस संगठन का सचिवालय काठमांडू में स्थित है। स्थापना के बाद से इसने क्षेत्रीय व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए अनेक शिखर सम्मेलनों और कार्ययोजनाओं का आयोजन किया है।

39. (D) 2002
दक्षिण एशियाई देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं को कम करने और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए 'साफ्टा' की रूपरेखा तैयार की गई थी। वर्ष 2002 में दक्षेस के सदस्य देशों ने इस महत्वपूर्ण समझौते की दिशा में कदम बढ़ाए। इसका मुख्य लक्ष्य पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना था। यह समझौता क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और सदस्य देशों की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए किया गया था।

40. (A) 1 जनवरी 2006
दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) समझौता आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ। इस समझौते पर 2004 में इस्लामाबाद में आयोजित 12वें दक्षेस शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को कम करना और आपसी व्यापार को सुगम बनाना है। यह दक्षिण एशिया में आर्थिक विकास और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने की एक बड़ी पहल है।

41. (C) चीन और संयुक्त राज्य अमरीका
दक्षिण एशिया की राजनीति केवल इसके सदस्य देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बाहरी शक्तियां भी यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका इस क्षेत्र के रणनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को गहराई से प्रभावित करते हैं। चीन का पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध और भारत के साथ सीमा विवाद है, जबकि अमेरिका के भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंध हैं जो क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करते हैं।

42. (A) अमरीका
शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद दक्षिण एशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव और सक्रियता काफी बढ़ गई है। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की नीति अपनाई है। आर्थिक सुधारों और उदारवाद के दौर में अमेरिका इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा व्यापारिक साझेदार और निवेश का स्रोत बनकर उभरा है। क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भी अमेरिका की भूमिका निर्णायक रही है।

43. (D) दक्षिण एशिया में अमरीकी भागीदारी का मुख्य कारण केवल वहां के प्राकृतिक संसाधन हैं।
दक्षिण एशिया में अमेरिकी भागीदारी के कारण विविध और रणनीतिक हैं, जो केवल प्राकृतिक संसाधनों तक सीमित नहीं हैं। अमेरिका के लिए यह क्षेत्र आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई, परमाणु सुरक्षा और बड़े बाजारों तक पहुंच के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, भारत और पाकिस्तान के बीच संतुलन बनाए रखना और चीन के बढ़ते प्रभाव पर नजर रखना भी अमेरिकी विदेश नीति के प्रमुख रणनीतिक लक्ष्यों में शामिल हैं।

44. (B) केवल 4
दक्षिण एशिया के देशों की घरेलू राजनीति का उनके आपसी संबंधों और क्षेत्रीय सहयोग पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अक्सर आंतरिक राजनीतिक दबावों और राष्ट्रीय भावनाओं के कारण देशों के बीच विवाद सुलझाना कठिन हो जाता है। इसके विपरीत, यदि घरेलू नेतृत्व सहयोग के पक्ष में हो, तो जटिल समस्याओं का समाधान भी संभव हो पाता है। इसलिए यह मानना गलत है कि घरेलू राजनीति का अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

45. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
बांग्लादेश ने स्वयं को एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया है, जहां विकास के नए मॉडल अपनाए गए हैं। नेपाल लंबे समय तक संवैधानिक राजतंत्र रहा और बाद में लोकतांत्रिक गणराज्य बना। श्रीलंका को लंबे समय तक लिट्टे और जातीय संघर्ष की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में सत्ता का स्वरूप अस्थिर रहा है, जहां सैनिक शासन और निर्वाचित सरकारों के बीच निरंतर बदलाव होते रहे हैं।

46. (D) जनरल अयूब खान
पाकिस्तान के प्रारंभिक वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। पहले संविधान के निर्माण के बाद, जनरल अयूब खान ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। उनके शासनकाल में सैन्य शक्ति का प्रभाव बढ़ा और नागरिक प्रशासन कमजोर हुआ। हालांकि उनके खिलाफ बढ़ते जन-असंतोष के कारण उन्हें अंततः पद छोड़ना पड़ा, लेकिन इसने पाकिस्तान में भविष्य के सैन्य हस्तक्षेपों के लिए एक मार्ग प्रशस्त कर दिया, जो वहां की राजनीति की विशेषता बन गई।

47. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
1971 का वर्ष दक्षिण एशिया के मानचित्र को बदलने वाला साबित हुआ। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने पश्चिमी पाकिस्तान के भेदभावपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध विद्रोह किया। भारत ने मानवीय आधार पर और अपनी सुरक्षा चिंताओं के कारण पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया। इसके परिणामस्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का जन्म हुआ।

48. (B) छः-सूत्री प्रस्ताव
शेख मुजीबुर्रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के अधिकारों और स्वायत्तता की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक 'छह-सूत्री प्रस्ताव' पेश किया था। इस प्रस्ताव में पूर्वी पाकिस्तान के लिए अधिक राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता की माँग की गई थी। पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों ने इस माँग को देश की अखंडता के लिए खतरा माना और इसे दबाने का प्रयास किया। इसी संघर्ष ने अंततः बांग्लादेश की आजादी के आंदोलन को एक निर्णायक दिशा प्रदान की।

49. (A) 1, 2, 3, 4
नेपाल में राजनीतिक परिवर्तन की प्रक्रिया चरणों में हुई। 1990 में राजा ने पहली बार लोकतांत्रिक संविधान की माँग स्वीकार की। हालांकि, 2002 में राजा ने संसद भंग कर सत्ता फिर से अपने हाथ में ले ली। इसके विरोध में 2006 में देशव्यापी भीषण जन-प्रदर्शन हुए, जिसने राजा को झुकने पर मजबूर किया। अंततः 2008 में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और नेपाल एक पूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ।

50. (A) अवामी लीग
1970 के चुनावों में शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान की लगभग सभी सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस जीत ने अवामी लीग को पूरे पाकिस्तान की संसद में बहुमत प्रदान कर दिया। हालांकि, पश्चिमी पाकिस्तान के नेतृत्व और जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस जनादेश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सत्ता हस्तांतरण में इस विफलता ने पूर्वी पाकिस्तान में भारी असंतोष और अंततः गृहयुद्ध की स्थिति पैदा कर दी।

51. (B) केवल 1, 2 और 3
बांग्लादेश की आजादी के बाद का राजनीतिक इतिहास सैन्य हस्तक्षेपों से भरा रहा है। शेख मुजीब की हत्या के बाद जियाउर्रहमान ने सत्ता संभाली, लेकिन उनकी भी हत्या कर दी गई। इसके बाद जनरल एच.एम. इरशाद ने लंबे समय तक सैनिक शासन चलाया। 1990 में हुए व्यापक छात्र और जन-आंदोलनों के कारण इरशाद को पद छोड़ना पड़ा। 1991 से वहां बहुदलीय लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई, जिसने राजनीतिक स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

52. (D) माओवादियों
नेपाल में लंबे समय तक एक त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बनी रही। इस संघर्ष में एक ओर राजशाही की सेना थी, दूसरी ओर लोकतंत्र के समर्थक राजनीतिक दल और तीसरी ओर सशस्त्र माओवादी विद्रोही थे। माओवादी देश की शासन प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन और राजतंत्र की समाप्ति चाहते थे। इन तीनों पक्षों के बीच चलने वाले इस तनाव ने नेपाल की राजनीति को लंबे समय तक अस्थिर रखा, जिसका अंत 2006 के शांति समझौते के साथ हुआ।

53. (C) नार्वे और आइसलैंड
श्रीलंका के भीषण जातीय गृहयुद्ध को समाप्त करने और शांति बहाल करने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में स्कैंडिनेवियाई देशों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। नार्वे और आइसलैंड ने सरकार और लिट्टे के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य किया। उन्होंने दोनों पक्षों को वार्ता की मेज पर लाने और युद्धविराम समझौतों को लागू करने के लिए निरंतर प्रयास किए। हालांकि पूर्ण शांति प्राप्त करने में अनेक बाधाएं आईं, लेकिन इन देशों की कूटनीतिक कोशिशों ने संघर्ष को कम करने में मदद की।

54. (B) भारत सरकार नेपाल की चीन से दोस्ती को लेकर हमेशा प्रसन्न रही है।
भारत और नेपाल के संबंधों में चीन एक संवेदनशील कारक रहा है। भारत अक्सर नेपाल की चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों और सुरक्षा समझौतों को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करता रहा है। भारत का मानना है कि नेपाल की भौगोलिक स्थिति उसकी सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि दोनों देशों के बीच व्यापार, संस्कृति और जन-स्तर पर गहरे संबंध हैं, लेकिन रणनीतिक मामलों में चीन का प्रभाव अक्सर द्विपक्षीय तनाव का कारण बनता है।

55. (B) P-3, Q-2, R-4, S-1
शेख मुजीबुर्रहमान ने बांग्लादेश की आजादी में अवामी लीग का नेतृत्व किया। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की प्रमुख नेता और वहां की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट कर सत्ता हथिया ली। राजा ज्ञानेन्द्र नेपाल के अंतिम शासक थे, जिनके शासनकाल में लोकतंत्र के लिए भीषण संघर्ष हुआ। ये सभी व्यक्तित्व दक्षिण एशिया के राजनीतिक इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली रहे हैं।

56. (A) जुल्फिकार अली भुट्टो
1971 के युद्ध में पाकिस्तान की हार और बांग्लादेश के अलग होने के बाद वहां सैन्य शासन का अंत हुआ। इसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित नागरिक सरकार का गठन हुआ। भुट्टो ने पाकिस्तान को एक नया संविधान दिया और देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने का प्रयास किया। उनकी सरकार 1977 तक चली, जब एक सैन्य तख्तापलट के माध्यम से जनरल जियाउल-हक ने उन्हें सत्ता से हटा दिया।

57. (B) केवल 2, 3, 4
दक्षिण एशिया एक ऐसा विशिष्ट क्षेत्र है जहाँ परस्पर विरोधी भावनाएँ जैसे सद्भाव और शत्रुता साथ-साथ मौजूद हैं। यह भौगोलिक रूप से एक संगठित उपमहाद्वीप है जिसकी एक साझा सांस्कृतिक और भाषाई विरासत है। हालांकि चीन इस क्षेत्र की राजनीति को गहराई से प्रभावित करता है, लेकिन इसे दक्षिण एशिया का भौगोलिक अंग नहीं माना जाता। अफगानिस्तान और म्यांमार को भी अक्सर इस क्षेत्र की व्यापक चर्चाओं और सहयोग संगठनों में शामिल किया जाता है।

58. (A) जेनरल जियाउल-हक
पाकिस्तान में 1977 का सैन्य तख्तापलट जनरल जियाउल-हक के नेतृत्व में हुआ था। उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को बर्खास्त कर दिया और देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया। जियाउल-हक ने पाकिस्तान की राजनीति और समाज का इस्लामीकरण करने की नीति अपनाई। उनके शासनकाल ने पाकिस्तान की न्यायपालिका और नागरिक प्रशासन पर सेना के नियंत्रण को और अधिक गहरा और स्थायी बना दिया, जिसका प्रभाव लंबे समय तक रहा।

59. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
श्रीलंका में तमिलों के विरुद्ध हो रही हिंसा और मानवाधिकारों के उल्लंघन का भारत पर सीधा असर पड़ा। भारत के तमिलनाडु राज्य की जनता का अपनी सरकार पर भारी दबाव था कि वह श्रीलंकाई तमिलों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए। इसी जन-दबाव और क्षेत्रीय स्थिरता की चिंता के कारण भारत सरकार ने 1987 में श्रीलंका के साथ शांति समझौता किया और अपनी सेना वहां भेजी। यह भारत की पड़ोस नीति का एक कठिन निर्णय था।

60. (B) 1990
भारत ने अपनी शांति सेना (IPKF) को 1987 में श्रीलंका भेजा था, लेकिन उसे वहां अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारतीय सेना का लिट्टे के साथ सशस्त्र संघर्ष शुरू हो गया और श्रीलंकाई सरकार के साथ भी संबंधों में खटास आने लगी। श्रीलंका में भारतीय सेना की उपस्थिति का व्यापक विरोध हुआ। अंततः बिना अपने लक्ष्यों को पूरी तरह प्राप्त किए, भारत ने 1990 में अपनी सेना को वापस बुलाने का निर्णय लिया, जिससे यह मिशन समाप्त हुआ।

61. (C) नदी-जल में हिस्सेदारी
भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी साझा नदियों के जल का बँटवारा एक संवेदनशील और पुराना विवाद रहा है। विशेष रूप से सूखे के मौसम में पानी की उपलब्धता को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद पैदा होते हैं। हालांकि 1996 में फरक्का संधि के जरिए गंगा जल के बँटवारे पर एक समझौता हुआ, लेकिन अन्य नदियों जैसे तीस्ता के जल को लेकर अभी भी बातचीत और असहमति बनी हुई है।

62. (A) 1, 2, 3, 4
दक्षिण एशिया का घटनाक्रम विविध परिवर्तनों का गवाह रहा है। सबसे पहले 1948 में श्रीलंका को आजादी मिली। इसके बाद 1954 में पाकिस्तान शीतयुद्ध के सैन्य गुट सिएटो में शामिल हुआ। 1962 में भारत और चीन के बीच हिमालयी सीमा को लेकर भीषण युद्ध हुआ। अंततः 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के नेताओं ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, जिससे बांग्लादेश का उदय हुआ। यह क्रम इस क्षेत्र की ऐतिहासिक और रणनीतिक यात्रा को स्पष्ट करता है।

63. (A) सदस्य देशों के बीच व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को कम करना।
दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) का प्राथमिक लक्ष्य इस क्षेत्र के देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं को दूर करना है। इसके माध्यम से सदस्य देशों ने सीमा शुल्क और अन्य व्यापारिक करों को चरणबद्ध तरीके से कम करने की प्रतिबद्धता जताई है। मुक्त व्यापार को बढ़ावा देकर यह समझौता पूरे दक्षिण एशिया को एक एकीकृत बाजार बनाने का प्रयास करता है, जिससे क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि और आपसी निर्भरता बढ़ेगी, जिससे अंततः राजनीतिक शांति भी संभव होगी।

64. (B) बांग्लादेश
भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति का मुख्य उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है, और इस दृष्टि से बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और म्यांमार के बीच एक सेतु का कार्य करता है। बेहतर कनेक्टिविटी और व्यापारिक समझौतों के माध्यम से बांग्लादेश इस नीति की सफलता में अहम भूमिका निभाता है। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भी अनिवार्य हैं।

65. (B) केवल 1, 2 और 4
दक्षेस की स्थापना 1985 में क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से की गई थी, और 2007 में अफगानिस्तान इसका आठवां सदस्य बना। हालांकि यह संगठन सहयोग की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच निरंतर तनाव और आपसी अविश्वास के कारण इसे अब तक बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल सकी है। राजनीतिक विवादों ने इस संगठन की आर्थिक और सामाजिक क्षमता को काफी हद तक सीमित कर दिया है, जिससे यह पिछड़ गया है।

66. (A) अटल बिहारी वाजपेयी
1999 में जब पाकिस्तान की सेना और घुसपैठियों ने करगिल क्षेत्र में भारतीय सीमा का उल्लंघन किया, तब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। उनके नेतृत्व में भारत ने 'ऑपरेशन विजय' चलाया और पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर किया। यह युद्ध उस समय हुआ जब वाजपेयी जी ने बस-यात्रा के जरिए शांति की पहल की थी। इस युद्ध के बाद भारत ने अपनी सुरक्षा नीतियों को और अधिक कड़ा किया और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में सफलता पाई।

67. (C) P-3, Q-4, R-2, S-1
भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बँटवारे को लेकर 1996 में फरक्का संधि हुई। 2001 में आगरा शिखर वार्ता हुई जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच शांति के प्रयास किए गए। 2004 में इस्लामाबाद में 12वां दक्षेस सम्मेलन आयोजित किया गया जहाँ साफ्टा पर हस्ताक्षर हुए। अंततः 2014 में काठमांडू में 18वां दक्षेस सम्मेलन हुआ। ये घटनाएँ दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों के विकास के महत्वपूर्ण पड़ावों को दर्शाती हैं।

68. (D) कच्छ के रन
सरक्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच गुजरात के कच्छ के रन क्षेत्र में स्थित एक समुद्री जलधारा की सीमा रेखा को लेकर है। दोनों देश इस समुद्री सीमा के बँटवारे के बारे में अलग-अलग दावे करते हैं। यह विवाद न केवल क्षेत्रीय सीमा से जुड़ा है, बल्कि यह उस क्षेत्र में मौजूद संभावित खनिज और मछली पकड़ने के संसाधनों के नियंत्रण के लिए भी महत्वपूर्ण है। कई दौर की वार्ताओं के बावजूद यह मसला अब तक नहीं सुलझा है।

69. (B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या है नहीं है।
साफ्टा को लेकर दक्षिण एशिया के छोटे देशों में एक तरह का डर बना हुआ है कि भारत उनके घरेलू बाजारों पर कब्जा कर लेगा। उनका मानना है कि मुक्त व्यापार का लाभ केवल बड़े देशों को मिलेगा। दूसरी ओर, भारत का तर्क है कि मुक्त व्यापार से सभी देशों को लाभ होगा और आर्थिक सहयोग से राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलेगी। ये दोनों विचार इस क्षेत्र में मौजूद आर्थिक असुरक्षा और सहयोग की संभावनाओं के द्वंद्व को दर्शाते हैं।

70. (B) नेपाल-भूटान के बीच जातीय मूल के नेपालियों के आप्रवास का मसला।
दक्षिण एशिया में अक्सर यह धारणा बनी रहती है कि सभी विवादों के केंद्र में भारत है, लेकिन इस क्षेत्र के अन्य देशों के बीच भी गंभीर मतभेद हैं। इसका एक स्पष्ट उदाहरण नेपाल और भूटान के बीच नेपाली मूल के लोगों के निर्वासन और नागरिकता को लेकर चल रहा विवाद है। हजारों लोग भूटान छोड़कर नेपाल के शिविरों में रहने को मजबूर हुए, जिससे दोनों देशों के संबंधों में तनाव पैदा हुआ। यह क्षेत्रीय जटिलता का एक महत्वपूर्ण गैर-भारतीय उदाहरण है।

71. (A) केवल 1, 2, 3
पाकिस्तान में लोकतंत्र की जड़ों के कमजोर होने के पीछे कई सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय कारण हैं। वहां की सेना, कट्टरपंथी धर्मगुरुओं और प्रभावशाली भूस्वामी समूहों का समाज पर गहरा नियंत्रण है, जो अक्सर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में बाधा डालते हैं। इसके अलावा, भारत के साथ जारी तनाव सैन्य शासन को वैधता प्रदान करता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी, शीतयुद्ध के दौरान और बाद में पश्चिमी शक्तियों ने अपने स्वार्थों के लिए वहां अक्सर सैन्य तानाशाही का समर्थन किया है।

72. (A) मालदीव
मालदीव का राजनीतिक इतिहास काफी रोचक रहा है। यह हिंद महासागर में स्थित एक महत्वपूर्ण द्वीपीय देश है जो 1968 तक एक सल्तनत के रूप में शासित था। 1968 में वहां राजशाही को समाप्त कर दिया गया और देश को एक गणतंत्र घोषित किया गया। इसके बाद वहां राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था अपनाई गई। मालदीव में लोकतंत्र की यात्रा कई चुनौतियों से गुजरी है, जिसमें हाल के वर्षों में बहुदलीय प्रणाली और चुनावों का सफल आयोजन शामिल है।

73. (C) नेपाल
नेपाल आधुनिक समय तक दुनिया के उन गिने-चुने देशों में शामिल था जहां संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था कायम थी। राजा की सर्वोच्च शक्ति और राजनीतिक दलों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के बीच लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। 2006 में हुए प्रचंड जन-आंदोलन ने राजा को विवश कर दिया और राजशाही के अधिकारों को सीमित कर दिया गया। इसके बाद 2008 में नेपाल ने आधिकारिक रूप से राजतंत्र का अंत कर दिया और एक पूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में नई शुरुआत की।

74. (A) येगेनी डेलाक्रो
'लिबर्टी लीडिंग द पीपल' फ्रांसीसी कलाकार येगेनी डेलाक्रो द्वारा 1830 में बनाई गई एक सुप्रसिद्ध पेंटिंग है। यह कृति स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए किए जाने वाले जन-संघर्ष का एक शक्तिशाली प्रतीक मानी जाती है। हालांकि यह पेंटिंग फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है, लेकिन इसका संदेश वैश्विक है और दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्रों में भी लोकतंत्र के लिए होने वाले आंदोलनों के संदर्भ में इसे अक्सर प्रेरणा के रूप में देखा जाता है।

75. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
भारत 1947 में एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में उभरा। पाकिस्तान में 1999 में जनरल मुशर्रफ द्वारा सैन्य तख्तापलट किया गया। बांग्लादेश ने 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर अपनी स्वतंत्रता हासिल की। नेपाल ने एक लंबे संघर्ष और राजतंत्र की समाप्ति के बाद 2015 में अपना नया लोकतांत्रिक संविधान अपनाया। ये घटनाएँ दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों की अपनी-अपनी राजनीतिक यात्रा और लोकतंत्र की दिशा में बढ़ते कदमों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती हैं।

76. (B) दक्षिण एशिया में सिर्फ़ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है।
दक्षिण एशिया अपनी राजनीतिक विविधता के लिए जाना जाता है, जहाँ एक समान प्रणाली का अभाव है। भारत और श्रीलंका में जहाँ स्थिर लोकतंत्र है, वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैन्य और लोकतांत्रिक शासन के बीच उतार-चढ़ाव देखा गया है। नेपाल और भूटान राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर बढ़े हैं, जबकि मालदीव भी विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनों से गुजरा है। यह विविधता इस क्षेत्र के देशों की अलग-अलग ऐतिहासिक परिस्थितियों और सामाजिक संरचनाओं का परिणाम है।

77. (C) 20 वर्ष
1971 के बांग्लादेश संकट के दौरान, अपनी सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक संतुलन के लिए भारत ने सोवियत संघ के साथ एक महत्वपूर्ण मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए। यह संधि 20 वर्षों के लिए की गई थी, जिसने भारत को पाकिस्तान और उसके सहयोगियों के खिलाफ एक मजबूत रणनीतिक आधार प्रदान किया। इस संधि के माध्यम से भारत को सैन्य सहायता और राजनयिक समर्थन का आश्वासन मिला, जिसने 1971 के युद्ध के परिणाम को निर्णायक रूप से प्रभावित किया।

78. (A) 1, 2, 3, 4
दक्षिण एशिया में कूटनीतिक प्रयासों का एक लंबा सिलसिला रहा है। 1998 में भारत और श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार संधि हुई, जिससे आर्थिक संबंध मजबूत हुए। 2001 में आगरा शिखर वार्ता के माध्यम से भारत-पाक तनाव कम करने की कोशिश की गई। 2007 में अफगानिस्तान दक्षेस का नया सदस्य बना, जिससे संगठन का विस्तार हुआ। अंततः 2014 में काठमांडू में दक्षेस सम्मेलन हुआ। यह क्रम क्षेत्र में आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है।

79. (A) बेनजीर भुट्टो
जनरल जिया-उल-हक के सैन्य शासन की समाप्ति के बाद, 1988 में पाकिस्तान में लोकतंत्र की वापसी हुई। बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने चुनाव जीता और वे किसी मुस्लिम राष्ट्र की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं। उनके शासनकाल ने पाकिस्तान में नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक संस्थाओं को पुनर्जीवित करने की उम्मीद जगाई। हालांकि, उन्हें बाद के वर्षों में सैन्य और राजनीतिक अस्थिरता के कारण अनेक चुनौतियों और सत्ता परिवर्तन का सामना करना पड़ा।

80. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
पाकिस्तान के निर्माण के बाद से ही इसके दोनों हिस्सों के बीच सांस्कृतिक और भाषाई मतभेद गहरे थे। पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों ने पूर्वी पाकिस्तान पर जबरन उर्दू भाषा थोपने का प्रयास किया और वहां की समृद्ध बंगाली संस्कृति को दबाने की कोशिश की। इसके विरोध में पूर्वी पाकिस्तान में तीव्र आंदोलन शुरू हुए, जिन्होंने धीरे-धीरे राजनीतिक स्वायत्तता और फिर पूर्ण स्वतंत्रता की माँग का रूप ले लिया। यही सांस्कृतिक टकराव बांग्लादेश की आजादी का मुख्य कारण बना।

81. (B) राष्ट्रपति
1999 के सफल सैन्य तख्तापलट के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने शासन की बागडोर संभाली। वर्ष 2001 में उन्होंने स्वयं को पाकिस्तान का राष्ट्रपति घोषित किया। उन्होंने अपनी सत्ता को संवैधानिक रूप देने के लिए एक जनमत संग्रह भी कराया, जिसे काफी विवादित माना गया। राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल में पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध अमेरिकी युद्ध में भागीदारी की, लेकिन घरेलू स्तर पर लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों के हनन के कारण उनका निरंतर विरोध होता रहा।

82. (A) केवल 1, 2, 3, 4
भारत और भूटान के बीच संबंध अत्यधिक सहयोगात्मक और विश्वास पर आधारित हैं। भूटान ने अपनी सुरक्षा की चिंता करते हुए अपने क्षेत्र में सक्रिय भारतीय विद्रोही समूहों के खिलाफ कड़ी सैन्य कार्रवाई की। भारत भी भूटान के आर्थिक विकास में सबसे बड़ा भागीदार है और वहां की विशाल पनबिजली परियोजनाओं के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भूटान की विकास योजनाओं के लिए अनुदान मुख्य रूप से भारत से आता है, न कि किसी अन्य विदेशी शक्ति से।

83. (C) शेख मुजीबुर्रहमान
बांग्लादेश के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर्रहमान की अगस्त 1975 में एक भीषण सैन्य तख्तापलट के दौरान हत्या कर दी गई थी। उन्होंने देश की शासन प्रणाली में बड़े बदलाव करने की कोशिश की थी, जिससे सेना के एक वर्ग में भारी असंतोष पैदा हो गया था। उनकी हत्या के बाद बांग्लादेश में लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता और सैनिक शासन का दौर शुरू हुआ। यह घटना बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास का सबसे दुखद और महत्वपूर्ण मोड़ मानी जाती है।

84. (D) लेफ्टिनेंट जेनरल एच. एम. इरशाद
बांग्लादेश में जनरल एच.एम. इरशाद ने 1982 में सत्ता हथिया ली थी और लंबे समय तक राष्ट्रपति के रूप में शासन किया। हालांकि उन्होंने कुछ लोकतांत्रिक दिखावा किया, लेकिन उनके शासन के खिलाफ जनता का आक्रोश बढ़ता गया। 1990 में छात्र संगठनों और सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने मिलकर एक व्यापक आंदोलन चलाया। इस जन-दबाव के आगे झुकते हुए इरशाद को पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे देश में पुनः लोकतंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ।

85. (A) P-3, Q-1, R-2, S-4
दक्षिण एशिया में संघर्ष और शांति के प्रयासों का एक मिला-जुला इतिहास रहा है। 1971 में भारत-पाक युद्ध के बाद बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली। 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच महत्वपूर्ण शांति समझौता हुआ। फरवरी 1999 में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने शांति के लिए लाहौर की ऐतिहासिक बस यात्रा की। लेकिन इसके तुरंत बाद जून-जुलाई 1999 में करगिल का युद्ध छिड़ गया। ये घटनाएँ दर्शाती हैं कि इस क्षेत्र में शांति और संघर्ष की स्थितियाँ कितनी अनिश्चित रही हैं।

86. (B) राजा
नेपाल में लोकतंत्र की प्रक्रिया को तब गहरा झटका लगा जब 2002 में राजा ज्ञानेन्द्र ने निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर दिया और संसद को भंग कर दिया। राजा ने देश में बढ़ती माओवादी हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का बहाना बनाकर सत्ता के सभी अधिकार अपने हाथों में केंद्रित कर लिए। इस कदम ने नेपाल में राजशाही और लोकतंत्र-समर्थक शक्तियों के बीच टकराव को चरम पर पहुँचा दिया, जिसके कारण अंततः राजतंत्र का पूरी तरह से पतन हुआ।

87. (D) 2009
श्रीलंका में लगभग तीन दशकों से चल रहा भीषण गृहयुद्ध वर्ष 2009 में समाप्त हुआ। श्रीलंकाई सेना ने एक व्यापक सैन्य अभियान के माध्यम से उग्रवादी संगठन लिट्टे (LTTE) के अंतिम ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और इसके प्रमुख नेताओं का सफाया कर दिया। इस सैन्य जीत के साथ ही देश में सक्रिय सशस्त्र उग्रवाद का अंत हुआ। हालांकि युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन इसके बाद तमिलों के पुनर्वास और राजनीतिक समाधान की चुनौतियां आज भी श्रीलंका के सामने बनी हुई हैं।

88. (B) केवल 2 और 3
दक्षिण एशिया के देशों के बीच संघर्ष के कारण अत्यंत जटिल हैं। केवल सीमा विवाद ही नहीं, बल्कि आंतरिक विद्रोह, जातीय तनाव और जल संसाधनों का बँटवारा भी अशांति के प्रमुख कारक हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में संघर्ष की गहरी जड़ें हैं जो कभी भी बड़े संकट का रूप ले सकती हैं। हालांकि विवाद मौजूद हैं, लेकिन इन देशों के बीच सहयोग के भी अनेक प्रयास और साझा मंच हैं जो सकारात्मक भविष्य की उम्मीद जगाते हैं।

89. (C) 1954-55 में
पाकिस्तान ने अपनी सुरक्षा और सैन्य मजबूती के लिए शीतयुद्ध के दौरान अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गुटों में शामिल होने का निर्णय लिया। वह 1954 में सिएटो (SEATO) और 1955 में सेंटो (CENTO) का सदस्य बना। इन समझौतों के माध्यम से पाकिस्तान को अमेरिका से भारी सैन्य सहायता और हथियार प्राप्त हुए। इस कदम ने दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को प्रभावित किया और भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया, जिससे क्षेत्र में शीतयुद्ध की प्रतिस्पर्धा का प्रवेश हुआ।

90. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
दक्षिण एशिया में लोकतंत्र की सफलता ने इस पश्चिमी धारणा को गलत साबित कर दिया है कि यह शासन प्रणाली केवल विकसित देशों के लिए उपयुक्त है। इस क्षेत्र के विकासशील और विविध समाजों में भी लोकतंत्र के प्रति गहरा जन-समर्थन पाया गया है। यहाँ के लोग मतदान में उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं और तानाशाही के मुकाबले लोकतंत्र को बेहतर विकल्प मानते हैं। यह अनुभव लोकतंत्र की वैश्विक स्वीकार्यता और मानवीय गरिमा के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को और अधिक पुख्ता करता है।

91. (D) मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी)
मालदीव में लोकतंत्र की मजबूती के लिए 2018 के चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण थे। इन चुनावों में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) ने शानदार जीत हासिल की। यह जीत वहां की जनता द्वारा लोकतंत्र के प्रति विश्वास और सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण का प्रतीक थी। मालदीव में पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक स्थिरता और लोकतांत्रिक संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस चुनावी परिणाम ने भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंधों को भी एक नई ऊर्जा प्रदान की है।

92. (B) ढाका
बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली के लिए हुए संघर्ष में अनेक लोगों ने अपना बलिदान दिया। 1987 में जनरल इरशाद के शासन के विरुद्ध हुए प्रदर्शनों में नूर हुसैन नामक युवक शहीद हो गया, जिसकी पीठ पर लोकतंत्र के पक्ष में नारे लिखे थे। उनकी स्मृति को जीवंत रखने के लिए ढाका विश्वविद्यालय में सुंदर चित्रमालाएं बनाई गई हैं। यह कलात्मक श्रद्धांजलि बांग्लादेश की जनता के उस साहस और जज्बे को दर्शाती है जिसने अंततः सैन्य शासन को उखाड़ फेंकने में सफलता प्राप्त की।

93. (C) राजशाही
1971 में अपनी स्वतंत्रता के तुरंत बाद, बांग्लादेश ने एक आधुनिक संविधान अपनाया जिसमें देश के आधारभूत मूल्यों को परिभाषित किया गया। बांग्लादेश ने स्वयं को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी राष्ट्र घोषित किया। इन आदर्शों का उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जो भेदभाव से मुक्त हो और जहाँ सत्ता जनता के हाथ में हो। राजशाही या तानाशाही के किसी भी स्वरूप को नकारते हुए, बांग्लादेश ने संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से अपनी नई यात्रा शुरू करने का संकल्प लिया था।

94. (A) केवल 1 और 4
भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध जटिल चुनौतियों से भरे रहे हैं। 1971 के युद्ध ने बांग्लादेश को जन्म दिया, लेकिन कश्मीर मुद्दा अनसुलझा ही रहा। 1990 के दशक में दोनों देशों द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने से सुरक्षा जोखिम बढ़ गया। भारत निरंतर यह आरोप लगाता रहा है कि पाकिस्तानी एजेंसियां पूर्वोत्तर में अशांति फैलाती हैं। इसके बावजूद, 1960 की सिंधु जल संधि एक सफल उदाहरण है जो दिखाती है कि तनाव के बीच भी जल बँटवारे जैसे समझौते प्रभावी रह सकते हैं।

95. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
दक्षिण एशिया में कई क्षेत्रीय विवाद संघर्ष का केंद्र रहे हैं। सियाचिन ग्लेशियर और सरक्रिक सीमा विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के प्रमुख मुद्दे हैं। श्रीलंका में 'तमिल ईलम' की माँग को लेकर भीषण जातीय संघर्ष हुआ जिसने देश की शांति को प्रभावित किया। बांग्लादेश में चटगांव पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों और सरकार के बीच अधिकारों को लेकर विवाद रहा है। ये सभी मुद्दे इस क्षेत्र की जटिल सुरक्षा और राजनीतिक चुनौतियों के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं।

96. (B) नेपाल
नेपाल एक भू-आबद्ध (lऔर-locked) देश है, जिसका अर्थ है कि इसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। यह चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है, जिसके उत्तर में चीन और शेष तीन दिशाओं में भारत स्थित है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण नेपाल अपने अंतरराष्ट्रीय व्यापार और पारगमन के लिए काफी हद तक भारत पर निर्भर रहता है। यह निर्भरता अक्सर दोनों देशों के बीच व्यापारिक संधियों और कूटनीतिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

97. (B) उपरोक्त सभी
भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग के क्षेत्र अत्यंत विस्तृत और बहुआयामी हैं। दोनों देश न केवल आर्थिक व्यापार और कनेक्टिविटी में सुधार कर रहे हैं, बल्कि आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर भी मिलकर काम करते हैं। वे अक्सर बाढ़ नियंत्रण, चक्रवात की पूर्व सूचना और सुंदरवन जैसे साझा पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए सूचनाएँ साझा करते हैं। यह समग्र सहयोग क्षेत्र की स्थिरता और साझा विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जाता है।

98. (B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
भारत और उसके पड़ोसियों के बीच एक जटिल मनोवैज्ञानिक संबंध है। भारत को अक्सर यह लगता है कि उसके पड़ोसी देश उसकी उदारता का अनुचित लाभ उठाते हैं। वहीं, भारत की एक प्रमुख कूटनीतिक चिंता यह है कि पड़ोसियों में अस्थिरता होने पर बाहरी शक्तियां इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा सकती हैं, जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ये दोनों स्थितियाँ अलग-अलग चिंताओं को दर्शाती हैं जो क्षेत्रीय संबंधों के उतार-चढ़ाव को प्रभावित करती रहती हैं।

99. (C) अफगानिस्तान
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) के विस्तार में 2007 का वर्ष ऐतिहासिक रहा जब अफगानिस्तान को इसके आठवें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अफगानिस्तान को शामिल करने का उद्देश्य इस युद्धग्रस्त देश को क्षेत्रीय विकास की मुख्यधारा से जोड़ना और दक्षिण एशिया में सुरक्षा व व्यापारिक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना था। इस कदम से दक्षेस का भौगोलिक दायरा बढ़ गया और मध्य एशिया के साथ इस क्षेत्र के संबंधों की नई संभावनाएँ भी तलाशने के अवसर पैदा हुए।

100. (A) केवल 1 और 2
दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दो सबसे प्रभावशाली बाहरी शक्तियां मानी जाती हैं। चीन की सीमाएं इस क्षेत्र से लगती हैं और वह पाकिस्तान का करीबी सहयोगी होने के साथ-साथ अन्य पड़ोसी देशों में भी भारी निवेश कर रहा है। वहीं, अमेरिका की रुचि इस क्षेत्र की परमाणु सुरक्षा और आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में रही है। इन दोनों शक्तियों की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और गतिविधियां दक्षिण एशिया के देशों के आपसी संबंधों और क्षेत्रीय संतुलन को गहराई से प्रभावित करती हैं।

101. (C) गंगा
भारत और बांग्लादेश के बीच जल संसाधनों के बँटवारे को लेकर चल रहे विवादों को सुलझाने की दिशा में 1996 में एक बड़ा कदम उठाया गया। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने ऐतिहासिक 'फरक्का संधि' पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य गंगा नदी के जल का न्यायसंगत बँटवारा सुनिश्चित करना था। यह संधि विशेष रूप से सूखे के महीनों में पानी की उपलब्धता को नियमित करती है। इस समझौते ने दोनों देशों के बीच

आपसी विश्वास बढ़ाने और दीर्घकालिक विवाद को काफी हद तक कम करने में मदद की।

102. (B) अफगानिस्तान
वर्ष 2007 में नई दिल्ली में आयोजित 14वें दक्षेस शिखर सम्मेलन के दौरान अफगानिस्तान आधिकारिक तौर पर इस संगठन का आठवां सदस्य बना। यह संगठन के इतिहास में अब तक का एकमात्र विस्तार है। अफगानिस्तान के शामिल होने से दक्षेस की पहचान और प्रभाव में वृद्धि हुई है। हालांकि अफगानिस्तान में निरंतर जारी आंतरिक संघर्ष और अस्थिरता ने क्षेत्रीय सहयोग की योजनाओं को लागू करने में चुनौतियां भी पेश की हैं, लेकिन इसकी सदस्यता क्षेत्र के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।

103. (D) दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करना।
दक्षेस (सार्क) की स्थापना के पीछे मुख्य दर्शन यह था कि दक्षिण एशिया के देश एक साझा मंच पर आकर अपनी सामूहिक शक्ति और संसाधनों का उपयोग कर सकें। यह संगठन आर्थिक विकास, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सामाजिक प्रगति के बहुस्तरीय साधनों के माध्यम से सहयोग बढ़ाने का प्रयास करता है। इसका लक्ष्य आपसी अविश्वास को दूर करना और एक ऐसा वातावरण बनाना है जहाँ क्षेत्रीय विवादों को सुलझाते हुए जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके और साझा समृद्धि प्राप्त की जा सके।

104. (A) चीन की पाकिस्तान के साथ रणनीतिक साझेदारी भारत-चीन संबंधों में एक बड़ी कठिनाई है।
भारत और चीन के संबंधों में जटिलता का एक मुख्य कारण चीन और पाकिस्तान के बीच गहराता रणनीतिक और सैन्य सहयोग है। भारत को लगता है कि चीन पाकिस्तान को समर्थन देकर इस क्षेत्र में भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा, सीमा विवाद और व्यापारिक असंतुलन भी दोनों देशों के बीच तनाव पैदा करते हैं। हालांकि 1991 के बाद से दोनों के बीच व्यापार में भारी वृद्धि हुई है, लेकिन रणनीतिक अविश्वास और प्रतिद्वंद्विता आज भी द्विपक्षीय संबंधों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है।

105. (D) P-4, Q-2, R-1, S-3
दक्षिण एशिया के देशों की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। बांग्लादेश ने ग्रामीण बैंकों के माध्यम से सूक्ष्म ऋण प्रदान कर गरीबी उन्मूलन में वैश्विक स्तर पर सफलता पाई है। भूटान एक संवैधानिक राजतंत्र है जहां शांतिपूर्वक शासन चलता है। मालदीव का इतिहास 1968 तक एक सल्तनत के रूप में रहा है। पाकिस्तान में शासन का स्वरूप बदलता रहा है, जहाँ कभी सेना का शासन रहा तो कभी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारें सत्ता में रहीं।

106. (A) अटल बिहारी वाजपेयी
फरवरी 1999 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारने के लिए एक अत्यंत साहसी और ऐतिहासिक पहल की। उन्होंने दिल्ली से लाहौर तक की बस यात्रा की और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ 'लाहौर घोषणापत्र' पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच शांति, विश्वास और भाईचारे का एक नया युग शुरू करना था। हालांकि इसके तुरंत बाद करगिल युद्ध ने इस शांति प्रक्रिया को भारी क्षति पहुँचाई।

107. (D) अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ
करगिल युद्ध के बाद उपजे तनाव को कम करने के लिए 2001 में आगरा में एक महत्वपूर्ण शिखर बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने भाग लिया। हालांकि इस वार्ता में कश्मीर सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन अंततः किसी ठोस समझौते पर सहमति नहीं बन सकी। फिर भी, यह बैठक दोनों देशों के बीच संवाद बनाए रखने की दिशा में एक गंभीर कूटनीतिक प्रयास मानी जाती है।

108. (B) यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सद्भाव और शत्रुता, आशा और निराशा साथ-साथ बसते हैं।
दक्षिण एशिया एक विरोधाभासों से भरा क्षेत्र है, जहाँ के देशों के बीच एक ओर गहरी शत्रुता और संघर्ष की स्थिति रहती है, तो दूसरी ओर सहयोग और शांति की तीव्र आकांक्षा भी देखी जाती है। यहाँ की राजनीति में कभी युद्ध के बादल मंडराते हैं, तो कभी साझा व्यापार और सांस्कृतिक एकता की बातें होती हैं। यह क्षेत्र अपनी विविधताओं, साझा इतिहास और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के कारण वैश्विक राजनीति में एक अत्यंत दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण स्थान रखता है।

109. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
शीतयुद्ध के बाद के वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण एशिया में अपनी सक्रियता काफी बढ़ा दी है। इसका मुख्य कारण इस क्षेत्र में अपनाए गए आर्थिक सुधार और उदारवादी नीतियां हैं, जिन्होंने अमेरिकी कंपनियों के लिए बड़े बाजार खोले हैं। इसके अलावा, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और पाकिस्तान दोनों अमेरिका के रणनीतिक सहयोगी बन गए हैं। इस बढ़ती भागीदारी ने अमेरिका को इस क्षेत्र की राजनीति और सुरक्षा मामलों में एक प्रभावी मध्यस्थ की भूमिका प्रदान की है।

110. (D) दक्षेस के देशों को वरीयता देने की संधि
'साप्टा' (SAPTA) का पूरा नाम सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट है, जिसे हिंदी में 'दक्षेस के देशों को वरीयता देने की संधि' कहा जाता है। 1993 में कोलंबो में हुए सातवें दक्षेस शिखर सम्मेलन के दौरान इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार में विशेष रियायतें और वरीयता देना था ताकि क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा मिले। यह साफ्टा (SAFTA) की दिशा में उठाया गया प्रारंभिक और महत्वपूर्ण कदम था, जिसने आर्थिक एकीकरण का आधार तैयार किया।

111. (A) केवल 1, 2, 3 और 4
नेपाल का राजनीतिक इतिहास अत्यंत नाटकीय रहा है, जहाँ वह लंबे समय तक संवैधानिक राजतंत्र रहा। 1990 के दशक में हुए आंदोलनों ने राजा को लोकतांत्रिक संविधान बनाने पर मजबूर किया। हालांकि, 2002 में राजा ज्ञानेन्द्र ने निरंकुशता दिखाते हुए चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद 2006 में हुए प्रचंड जन-आंदोलन ने लोकतंत्र की वापसी सुनिश्चित की। 2015 में नेपाल ने एक नया धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक संविधान अपनाया, जिसने राजशाही की जगह गणतंत्र को पूरी तरह स्थापित किया।

112. (B) यहाँ अपेक्षाकृत स्वतंत्र और साहसी प्रेस मौजूद है।
पाकिस्तान में बार-बार होने वाले सैन्य हस्तक्षेपों के बावजूद वहां की जनता में लोकतंत्र के प्रति गहरी निष्ठा देखी गई है। इस जज्बे का सबसे बड़ा प्रमाण वहां मौजूद स्वतंत्र और निडर प्रेस है, जो कठिन परिस्थितियों में भी सरकार और सेना की आलोचना करने का साहस रखती है। इसके अलावा, वहां सक्रिय मानवाधिकार संगठन और नागरिक समाज भी निरंतर लोकतंत्र की बहाली और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहे हैं, जो वहां लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती को दर्शाता है।

113. (B) जनरल याहिया खान
1971 के भारत-पाक युद्ध और बांग्लादेश संकट के दौरान पाकिस्तान में जनरल याहिया खान का सैन्य शासन था। उनके कार्यकाल में पूर्वी पाकिस्तान में दमनकारी नीतियां अपनाई गईं, जिससे वहां भारी विद्रोह हुआ। याहिया खान ने लोकतांत्रिक जनादेश को स्वीकार करने के बजाय सैन्य बल का प्रयोग किया, जिसके परिणामस्वरुप लाखों लोग विस्थापित होकर भारत आए। उनकी इसी अदूरदर्शिता और भारत के साथ हुए युद्ध में पराजय के कारण अंततः उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी और पाकिस्तान का विभाजन हुआ।

114. (A) P-3, Q-1, R-4, S-2
भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धों का एक लंबा और दुखद इतिहास रहा है। सबसे पहले 1948 में कश्मीर को लेकर पहली लड़ाई हुई। इसके बाद 1965 में दोनों देशों के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ा। 1971 का युद्ध बांग्लादेश की मुक्ति का कारण बना और पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। अंततः 1999 में करगिल की चोटियों पर दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ। ये युद्ध इस क्षेत्र की अस्थिरता और जटिल सुरक्षा चुनौतियों के गवाह रहे हैं।

115. (C) सिंहली और तमिल समुदायों के बीच राजनीतिक प्रभुत्व का संघर्ष।
श्रीलंका में जातीय संघर्ष की जड़ें सत्ता और अधिकारों के असमान वितरण में छिपी थीं। आजादी के बाद बहुसंख्यक सिंहली समुदाय ने राजनीति और सरकारी नौकरियों में अपना दबदबा बनाया, जिससे अल्पसंख्यक तमिलों को लगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। तमिलों ने अपनी पहचान और स्वायत्तता की रक्षा के लिए आंदोलन किया, जो बाद में सशस्त्र विद्रोह में बदल गया। यह संघर्ष केवल भाषाई नहीं था, बल्कि यह राज्य की शक्ति में हिस्सेदारी और सम्मानपूर्ण सह-अस्तित्व का प्रश्न था।

116. (D) भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण करने के बाद
मई 1998 में जब भारत और उसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए, तो पूरा विश्व स्तब्ध रह गया। इन परीक्षणों ने दक्षिण एशिया को अचानक वैश्विक राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह डर सताने लगा कि इन दो पड़ोसी और प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच का कोई भी विवाद परमाणु युद्ध में बदल सकता है। इस घटना के बाद से इस क्षेत्र की सुरक्षा और शांति बनाए रखना वैश्विक महाशक्तियों की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हो गया है।

117. (B) केवल 1, 2 और 3
बांग्लादेश का इतिहास पाकिस्तान के साथ जुड़े संघर्षों से शुरु होता है। 1947 से 1971 तक यह पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के राजनीतिक और आर्थिक शोषण ने यहाँ विद्रोह की आग सुलगा दी। शेख मुजीबुर्रहमान ने इस स्वायत्तता आंदोलन का नेतृत्व किया और जनता को एकजुट किया। भारत ने इस न्यायपूर्ण संघर्ष का न केवल नैतिक समर्थन किया, बल्कि सैन्य सहायता भी प्रदान की, जिसने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई।

118. (B) शिमला-समझौता
1971 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने के लिए जुलाई 1972 में ऐतिहासिक 'शिमला समझौता' हुआ। इस पर भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य युद्ध के बाद उपजे विवादों को द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना था। इसमें यह भी तय किया गया कि दोनों देश भविष्य में किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बिना अपने मसले सुलझाएंगे।

119. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न होने के पीछे सुरक्षा की चिंताएं एक प्रमुख कारण रही हैं। भारत के साथ लगातार बनी रहने वाली शत्रुता और तनातनी का लाभ उठाकर वहां की सेना स्वयं को देश का असली रक्षक साबित करती रही है। सैन्य समर्थक समूह यह तर्क देते हैं कि राजनेता देश की सुरक्षा के साथ समझौता कर सकते हैं, इसलिए सेना का नियंत्रण आवश्यक है। इसी असुरक्षा की भावना ने वहां लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया और सैनिक शासन को फलने-फूलने का मौका दिया।

120. (A) यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया।
वर्ष 2008 नेपाल के इतिहास का सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। सदियों पुरानी राजशाही को समाप्त करते हुए नेपाल को आधिकारिक तौर पर एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। यह परिवर्तन दशकों के जन-संघर्ष और माओवादी आंदोलन का परिणाम था। राजा की शक्तियों को पूरी तरह खत्म कर दिया गया और जनता द्वारा

निर्वाचित प्रतिनिधियों ने देश के नए भविष्य का निर्माण शुरु किया। इस ऐतिहासिक कदम ने नेपाल को आधुनिक लोकतांत्रिक विश्व की मुख्यधारा में मजबूती से स्थापित कर दिया।

121. (B) केवल 3 और 4
दक्षिण एशिया में केवल संघर्ष ही नहीं, बल्कि सहयोग के भी ठोस प्रयास हुए हैं। दक्षेस (SAARC) की स्थापना आपसी विश्वास और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल थी। इसी क्रम में साफ्टा (SAFTA) पर हस्ताक्षर किए गए ताकि पूरे क्षेत्र को एक मुक्त व्यापार क्षेत्र में बदलकर आर्थिक समृद्धि लाई जा सके। हालांकि कुछ छोटे देश भारत के प्रभुत्व से डरते हैं, लेकिन यह सच है कि ये संगठन सहयोग के लिए एक आवश्यक संस्थागत ढांचा प्रदान करते हैं।

122. (A) बांग्लादेश
बांग्लादेश ने ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया है। यहाँ के 'ग्रामीण बैंक' मॉडल ने छोटी बचत और बिना किसी बड़ी गारंटी के दिए जाने वाले सूक्ष्म ऋण (micro-credit) के माध्यम से लाखों गरीब लोगों, विशेषकर महिलाओं, के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। इस मॉडल की सफलता के कारण बांग्लादेश ने मानव विकास सूचकांकों में उल्लेखनीय सुधार किया है। इस पहल के प्रणेता मोहम्मद यूनुस को इसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

123. (D) श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश
श्रीलंका में जातीय संघर्ष के दौरान 'तमिल ईलम' शब्द एक अलग और संप्रभु राष्ट्र की माँग का प्रतीक बन गया था। अल्पसंख्यक तमिल समुदाय के अधिकारों की अनदेखी और बहुसंख्यक सिंहली प्रभुत्व के विरोध में लिट्टे जैसे उग्रवादी संगठनों ने इस पृथक राज्य की अवधारणा को जन्म दिया। वे श्रीलंका के उत्तर और पूर्व के उन हिस्सों में अपना स्वतंत्र शासन चाहते थे जहाँ तमिल जनसंख्या अधिक थी। इस माँग ने देश को दशकों लंबे खूनी गृहयुद्ध की आग में झोंक दिया था।

124. (B) भारत के भूटान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं।
भारत और भूटान के संबंध दक्षिण एशिया में आपसी विश्वास और मैत्री का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। दोनों देशों के बीच कोई विवाद नहीं है और वे सुरक्षा तथा आर्थिक विकास के मामलों में एक-दूसरे का पूरा सहयोग करते हैं। भूटान ने भारत की सुरक्षा चिंताओं का सम्मान करते हुए अपनी जमीन से उग्रवादियों को खदेड़ा है, जबकि भारत ने भूटान के बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण निवेश किया है। यह संबंध पूरी तरह शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक रहे हैं।

125. (B) P-3, Q-4, R-1, S-2
दक्षिण एशिया के प्रमुख देशों की राजधानियाँ उनके राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों के केंद्र हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, जबकि बांग्लादेश का प्रशासनिक केंद्र ढाका है। नेपाल की राजधानी काठमांडू हिमालय की गोद में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। श्रीलंका की राजधानियाँ कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे हैं। ये शहर न केवल शासन के केंद्र हैं, बल्कि अपने-अपने देशों की सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान का प्रतिनिधित्व भी करते हैं और क्षेत्रीय कूटनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

126. (D) भारत
दक्षिण एशिया के मानचित्र को देखने पर भारत की स्थिति अत्यंत केंद्रीय और महत्वपूर्ण दिखाई देती है। भारत इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है और इसकी सीमाएं दक्षिण एशिया के लगभग हर अन्य देश से मिलती हैं। केवल श्रीलंका और मालदीव को छोड़कर, जो समुद्री पड़ोसी हैं, अन्य सभी देशों के साथ भारत की थल सीमाएं जुड़ी हुई हैं। इस विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण क्षेत्र की स्थिरता और किसी भी प्रकार के क्षेत्रीय सहयोग में भारत की भूमिका अनिवार्य और निर्णायक हो जाती है।

127. (A) पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश के रूप में उदय।
1971 के भारत-पाक युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण और तात्कालिक परिणाम विश्व मानचित्र पर एक नए संप्रभु राष्ट्र, बांग्लादेश का जन्म था। इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना की करारी हार हुई और उसने बड़े पैमाने पर आत्मसमर्पण किया। यह दक्षिण एशिया के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था जिसने द्वि-राष्ट्र सिद्धांत की सीमाओं को उजागर कर दिया। इस जीत के साथ ही पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे मानवाधिकारों के हनन का अंत हुआ और एक नई लोकतांत्रिक यात्रा की शुरुआत हुई।

128. (A) केवल 1 और 3
भारत अपनी आजादी के बाद से ही एक अटूट और जीवंत लोकतंत्र बना हुआ है, जो विश्व स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि है। पड़ोसी देश भूटान ने भी अपनी राजशाही व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 2008 में सफलतापूर्वक संवैधानिक राजतंत्र को अपनाया और लोकतंत्र की दिशा में कदम बढ़ाए। इसके विपरीत, पाकिस्तान और नेपाल की राजनीतिक यात्रा अधिक उतार-चढ़ाव वाली रही है, जहाँ सैनिक शासन और राजतंत्र को समाप्त करने के लिए लंबे समय तक जनता को कड़ा संघर्ष करना पड़ा है।

129. (B) भारत और बांग्लादेश
रोहिंग्या शरणार्थियों का म्यांमार से पलायन भारत और बांग्लादेश के बीच एक संवेदनशील कूटनीतिक और सुरक्षा मुद्दा रहा है। लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों ने बांग्लादेश में शरण ली, जिससे वहां के संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा। भारत को भी अपनी सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों में होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चिंता सताती रही है। इस समस्या के समाधान के लिए दोनों देश म्यांमार पर दबाव बनाने और शरणार्थियों की सुरक्षित वापसी के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और संवाद करते रहे हैं।

130. (A) काठमांडू, नेपाल
वर्ष 2014 में दक्षेस का 18वां शिखर सम्मेलन नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में सदस्य देशों के बीच कनेक्टिविटी, ऊर्जा सहयोग और क्षेत्रीय

व्यापार को बढ़ाने पर गहन चर्चा हुई। सम्मेलन के दौरान 'सार्क फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर एनर्जी कोऑपरेशन' जैसे महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह बैठक दक्षिण एशियाई देशों के बीच आपसी विश्वास को मजबूत करने और क्षेत्रीय विकास के साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रयास थी।

131. (C) भारतीय सेना लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई।
1987 में श्रीलंका में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से भेजी गई भारतीय शांति सेना (IPKF) को अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारतीय सेना का सीधा टकराव उग्रवादी संगठन लिट्टे से हो गया, जिससे वह एक जटिल और लंबे गुरिल्ला युद्ध में उलझ गई। इस हस्तक्षेप का न केवल लिट्टे ने बल्कि श्रीलंकाई जनता ने भी विरोध किया, क्योंकि वे इसे अपने संप्रभुता के हनन के रूप में देख रहे थे। अंततः भारी जान-माल के नुकसान के बाद भारतीय सेना को वापस लौटना पड़ा।

132. (D) यह क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से खतरे की आशंका वाला क्षेत्र है।
अंतरराष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञ दक्षिण एशिया को विश्व के सबसे संवेदनशील और खतरनाक क्षेत्रों में से एक मानते हैं। इसके पीछे प्रमुख कारण दो परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसियों, भारत और पाकिस्तान, के बीच का दीर्घकालिक तनाव और कश्मीर विवाद है। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में सक्रिय आतंकवाद, सीमा पार संघर्ष और बढ़ती सैन्य प्रतिस्पर्धा सुरक्षा जोखिमों को और बढ़ा देती है। किसी भी छोटी सी घटना के बड़े युद्ध में बदलने की संभावना हमेशा यहाँ बनी रहती है।

133. (C) केवल 1, 2, 3, 4
पाकिस्तान का राजनीतिक इतिहास निर्वाचित सरकारों और सैनिक तख्तापलट के बीच झूलता रहा है। जनरल अयूब खान और जनरल परवेज मुशर्रफ जैसे सैन्य अधिकारियों ने कई बार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को दरकिनार कर सत्ता संभाली। हालांकि, जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में नागरिक सरकारों ने भी शासन किया है। यह उतार-चढ़ाव दर्शाता है कि वहां लोकतांत्रिक संस्थाएं अभी भी पूरी तरह मजबूत नहीं हो पाई हैं और सेना का राजनीति पर प्रभाव निरंतर बना हुआ है, जिससे अस्थिरता बनी रहती है।

134. (B) चीन को इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश और अंग माना जाता है।
दक्षिण एशिया भौगोलिक रूप से एक सुस्पष्ट और एकीकृत क्षेत्र है जिसमें भारत और उसके पड़ोसी देश शामिल हैं। हालांकि चीन की सीमाएं इस क्षेत्र से मिलती हैं और वह यहाँ की राजनीति में गहरा हस्तक्षेप करता है, लेकिन उसे दक्षिण एशिया का भौगोलिक या सांस्कृतिक हिस्सा नहीं माना जाता। यह क्षेत्र हिमालय और महासागरों जैसी प्राकृतिक सीमाओं से घिरा हुआ है, जो इसे एक अनूठी पहचान प्रदान करता है। चीन को इस क्षेत्र के बाहर की एक महाशक्ति माना जाता है।

135. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
दक्षेस (SAARC) को जिस उद्देश्य के साथ बनाया गया था, वह उसमें पूरी तरह सफल नहीं हो सका है। इसका मुख्य कारण सदस्य देशों, विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान, के बीच गहरे राजनीतिक मतभेद और अविश्वास हैं। द्विपक्षीय झगड़ों की छाया अक्सर बहुपक्षीय बैठकों पर पड़ती है, जिससे महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक परियोजनाओं पर सहमति बनाना कठिन हो जाता है। जब तक पड़ोसी देशों के बीच बुनियादी राजनीतिक विवाद नहीं सुलझते, तब तक क्षेत्रीय सहयोग की गति धीमी रहने की आशंका है।

136. (A) बांग्लादेश
चटगांव पर्वतीय क्षेत्र बांग्लादेश के दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित है। यह क्षेत्र अपनी जातीय विविधता और पहाड़ी भूगोल के लिए जाना जाता है। लंबे समय तक यहाँ के स्थानीय चकमा और अन्य जनजातीय समूहों और बांग्लादेश सरकार के बीच स्वायत्तता और अधिकारों को लेकर संघर्ष चला। हालांकि 1997 में एक शांति समझौते के माध्यम से हिंसा को काफी हद तक कम किया गया, लेकिन इस क्षेत्र के निवासियों के हितों की रक्षा और विकास के मुद्दे आज भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं।

137. (C) माओवादी, राजा की सेना और लोकतंत्र-समर्थक
1990 के दशक में नेपाल में एक जटिल त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस संघर्ष के तीन प्रमुख केंद्र थे: निरंकुश सत्ता को बनाए रखने की कोशिश करने वाली राजा की सेना, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए संघर्ष करने वाले राजनीतिक दल, और सशस्त्र क्रांति के माध्यम से राजतंत्र का अंत करने की कोशिश करने वाले माओवादी। इन तीनों पक्षों के बीच चलने वाले इस तनावपूर्ण मुकाबले ने नेपाल की सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता को लंबे समय तक अस्थिर और संकटपूर्ण बनाए रखा।

138. (A) भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए।
1988 में जब मालदीव में कुछ विदेशी भाड़े के सैनिकों ने राष्ट्रपति गयूम की सरकार का तख्तापलट करने की कोशिश की, तब मालदीव ने भारत से सहायता माँगी। भारत ने तुरंत अपनी 'शांति सेना' और नौसेना को भेजकर हस्तक्षेप किया। भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक विद्रोहियों को पकड़ा और मालदीव की लोकतांत्रिक सत्ता को सुरक्षित रखा। इस त्वरित सहायता ने न केवल मालदीव की रक्षा की, बल्कि दक्षिण एशिया में भारत की एक विश्वसनीय सुरक्षा प्रदाता की छवि को भी मजबूत किया।

139. (D) यह एक क्षेत्रीय गुट के रूप में उभरेगा या नहीं, यह यहाँ के लोगों और सरकारों पर अधिक निर्भर है।
दक्षिण एशिया का भविष्य बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप से अधिक यहाँ के अपने देशों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग पर निर्भर करता है। यदि यहाँ की सरकारें अपने ऐतिहासिक विवादों को पीछे छोड़कर आर्थिक एकीकरण और साझा विकास को प्राथमिकता दें, तो यह क्षेत्र एक शक्तिशाली

वैश्विक गुट बन सकता है। यहाँ की विशाल जनसंख्या और संसाधन इसके विकास की अपार संभावनाएँ प्रदान करते हैं, लेकिन इसके लिए एक सकारात्मक राजनीतिक इच्छाशक्ति और क्षेत्रीय एकजुटता की अत्यंत आवश्यकता है।

140. (B) युद्ध के जोखिम को कम करने और आपसी समझ बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम।
"विश्वास बहाली के उपाय" (Confidence Building Measures) भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव को कम करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत दोनों देश अपनी सेनाओं की गतिविधियों की पूर्व सूचना साझा करते हैं और हॉटलाइन जैसी संचार व्यवस्थाएं स्थापित करते हैं ताकि किसी भी गलतफहमी से युद्ध न छिड़ जाए। इन उपायों का मुख्य उद्देश्य आपसी संदेह को कम करना और एक ऐसा वातावरण बनाना है जहाँ विवादों को शांतिपूर्ण और कूटनीतिक तरीकों से सुलझाया जा सके।

141. (B) केवल 1, 2 और 3
दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का सफर अलग-अलग देशों में भिन्न रहा है। श्रीलंका आजादी के बाद से ही एक स्थिर लोकतंत्र बना हुआ है, जो इसकी राजनीतिक परिपक्वता का उदाहरण है। बांग्लादेश में भी 1991 के बाद से लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं काफी मजबूत हुई हैं। नेपाल ने 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र का पालन किया, लेकिन बाद में वह गणतंत्र बन गया। इसके विपरीत भूटान ने भी तानाशाही के बजाय 2008 में संवैधानिक राजतंत्र अपनाकर लोकतांत्रिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

142. (D) जियाउल-हक
पाकिस्तान में 1977 का सैन्य तख्तापलट जनरल जिया-उल-हक द्वारा किया गया था। उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो की लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर मार्शल लॉ लागू कर दिया। उनके शासनकाल में पाकिस्तान की शासन व्यवस्था का तीव्र इस्लामीकरण हुआ और नागरिक अधिकारों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। जिया-उल-हक ने लंबे समय तक पाकिस्तान पर शासन किया और वहां की राजनीति में सेना के प्रभाव को गहराई से संस्थागत बना दिया, जिसके प्रभाव आज भी पाकिस्तान के राजनीतिक ढांचे में महसूस किए जाते हैं।

143. (A) भूटान
भूटान हिमालय की गोद में स्थित एक छोटा और शांत देश है जहाँ लंबे समय से राजशाही की व्यवस्था रही है। हालांकि, भूटान के राजाओं ने समय के साथ अपनी शक्तियों को जनता के साथ साझा करने की प्रगतिशील नीति अपनाई। 2008 में भूटान ने अपनी स्वेच्छा से संवैधानिक राजतंत्र को अपनाया और पहले लोकतांत्रिक चुनाव आयोजित किए। यह परिवर्तन बिना किसी हिंसा या बड़े विद्रोह के हुआ, जो इसे दक्षिण एशिया में राजनीतिक परिवर्तन का एक अत्यंत शांतिपूर्ण और सकारात्मक उदाहरण बनाता है।

144. (B) अमरीका
शीतयुद्ध की समाप्ति और 9/11 की घटनाओं के बाद दक्षिण एशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका का रणनीतिक महत्व बढ़ गया है। अमेरिका ने अपनी पुरानी नीतियों को बदलते हुए भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ समान रूप से घनिष्ठ संबंध बनाने का प्रयास किया है। वह अक्सर दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए एक पर्दे के पीछे के मध्यस्थ की भूमिका भी निभाता है। आर्थिक और सैन्य दृष्टि से अमेरिका की इस क्षेत्र में मौजूदगी अब एक अनिवार्य और प्रभावशाली वास्तविकता बन चुकी है।

145. (B) चीन की पाकिस्तान से साझेदारी और क्षेत्र में अमरीकी हित जैसी बाहरी शक्तियाँ यहाँ के संबंधों को प्रभावित करती हैं।
दक्षिण एशिया के देशों के आपसी संबंध केवल उनके आंतरिक मुद्दों से ही तय नहीं होते, बल्कि बाहरी महाशक्तियों के हित भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। चीन का पाकिस्तान को दिया जाने वाला भारी सैन्य और आर्थिक समर्थन भारत के साथ उसके संबंधों को प्रभावित करता है। इसी तरह, अमेरिका की रणनीतिक भागीदारी भी क्षेत्रीय संतुलन को बदलती है। ये बाहरी कारक अक्सर द्विपक्षीय विवादों को जटिल बना देते हैं, जिससे क्षेत्रीय सहयोग की दिशा और गति काफी हद तक प्रभावित होती है।

146. (B) केवल 1, 3, 5
दक्षिण एशिया के आम नागरिकों में लोकतंत्र के प्रति गहरी और व्यापक आकांक्षा पाई जाती है। यहाँ के लोग न केवल मतदान में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, बल्कि वे प्रतिनिधिमूलक लोकतांत्रिक संस्थाओं का भी मजबूती से समर्थन करते हैं। यह जन-समर्थन उन देशों में भी देखा गया है जहाँ बार-बार सैनिक शासन या राजतंत्र रहा है। दक्षिण एशिया के इन अनुभवों ने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र की मांग वैश्विक है और यह किसी विशेष आर्थिक स्थिति या भूगोल की मोहताज नहीं है।

147. (C) सिलोन
वर्ष 1948 में जब श्रीलंका को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तब इसे आधिकारिक तौर पर 'सिलोन' के नाम से जाना जाता था। यह नाम काफी समय तक प्रचलन में रहा जब तक कि 1972 में देश ने एक नया संविधान अपनाकर अपना नाम बदलकर 'श्रीलंका' नहीं कर लिया। सिलोन के रूप में इस द्वीप राष्ट्र ने अपनी चाय और मसालों के लिए विश्व भर में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। आजादी के बाद से ही सिलोन ने अपनी लोकतांत्रिक पहचान को अक्षुण्ण रखा।

148. (D) बेनजीर भुट्टो
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) की स्थापना जुल्फिकार अली भुट्टो ने की थी, लेकिन इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान और मजबूती बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में मिली। वे इस पार्टी की लंबे समय तक अध्यक्ष रहीं और दो बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री चुनी गईं। बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान में नागरिक स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकारों के लिए कड़ा संघर्ष किया। उनकी पार्टी आज भी पाकिस्तान की राजनीति में एक प्रमुख और प्रभावशाली

लोकतांत्रिक आवाज के रूप में सक्रिय है, जो प्रगतिशील मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है।

149. (C) बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र
1990 के दशक की शुरुआत बांग्लादेश के लिए एक नई राजनीतिक सुबह लेकर आई। लंबे सैन्य शासन के अंत के बाद, 1991 में बांग्लादेश ने संसदीय और प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की व्यवस्था को पुनः अपनाया। इसके बाद से वहां नियमित रूप से बहुदलीय चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनल पार्टी (बीएनपी) जैसी प्रमुख पार्टियां सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था ने बांग्लादेश को आर्थिक विकास और सामाजिक सुधारों के मार्ग पर आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है।

150. (B) अमरीका तथा अन्य पश्चिमी देश
पाकिस्तान में लोकतंत्र की विफलता के पीछे अंतरराष्ट्रीय कारकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अमरीका और अन्य पश्चिमी देशों ने समय-समय पर अपने सामरिक हितों और वैश्विक सुरक्षा चिंताओं के कारण वहां सैन्य शासन को मौन समर्थन दिया है। विशेष रूप से इस्लामी आतंकवाद के भय ने इन शक्तियों को पाकिस्तान में स्थिरता के नाम पर सेना के प्रभुत्व को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया है। इन शक्तियों के लिए अक्सर लोकतंत्र की तुलना में एक मजबूत सैन्य शासक अधिक विश्वसनीय सहयोगी साबित हुआ है।

151. (B) आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना का प्राथमिक लक्ष्य सदस्य राष्ट्रों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को तेज करने का प्रयास किया जाता है। क्षेत्रीय एकीकरण को सुदृढ़ करके सदस्य देशों के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार करना और आपसी विश्वास बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है।

152. (A) भारत और पाकिस्तान के बीच गहरे राजनीतिक और सैन्य विवाद
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की कार्यप्रणाली में सबसे बड़ी बाधा भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनावपूर्ण संबंध हैं। इन द्विपक्षीय विवादों के कारण संगठन के महत्वपूर्ण निर्णय और शिखर सम्मेलन बार-बार प्रभावित होते रहते हैं। आपसी अविश्वास और सुरक्षा संबंधी चिंताओं ने इस मंच को अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने से रोक रखा है।

153. (C) द्विपक्षीय और विवादास्पद मुद्दे
संगठन के चार्टर में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि सामूहिक सहयोग के वातावरण को बनाए रखने के लिए केवल क्षेत्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसके अंतर्गत सदस्य देशों को निर्देश दिया गया है कि वे आपसी विवादों या द्विपक्षीय राजनीतिक मुद्दों को इस मंच पर न उठाएं। इस सिद्धांत का उद्देश्य विवादों को दरकिनार कर विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना है।

154. (D) गैर-टैरिफ बाधाएं और आपसी अविश्वास
दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते की विफलता के पीछे व्यापारिक प्रतिबंधों के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक कारण भी उत्तरदायी हैं। सदस्य देशों के बीच व्याप्त गहरे अविश्वास के कारण वे एक-दूसरे के सामान पर कड़े गैर-टैरिफ प्रतिबंध लगाते हैं। इससे व्यापार की लागत बढ़ जाती है और मुक्त व्यापार की अवधारणा व्यावहारिक रूप से सफल नहीं हो पाती, जिससे क्षेत्रीय व्यापार सीमित रह जाता है।

155. (C) राजनीतिक इच्छाशक्ति, विशेषकर भारत-पाकिस्तान संबंधों में सुधार, सार्क की प्रभावशीलता के लिए महत्वपूर्ण है। सार्क की भविष्य की सफलता काफी हद तक दक्षिण एशिया की दो प्रमुख शक्तियों के बीच शांति और सहयोग पर टिकी हुई है। जब तक सदस्य देशों के नेतृत्व में द्विपक्षीय समस्याओं को सुलझाने के लिए दृढ़ राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं होगी, तब तक यह संगठन सक्रिय नहीं हो पाएगा। प्रभावी क्षेत्रीय सहयोग के लिए विवादों को सुलझाना और आपसी विश्वास की बहाली करना अनिवार्य शर्त है।

156. (B) स्वतंत्रता के बाद की राष्ट्र-निर्माण परियोजना जिसने तमिल समुदाय को हाशिए पर डाला
श्रीलंका में गृहयुद्ध की जड़ें उन सरकारी नीतियों में निहित हैं जिन्होंने सिंहली वर्चस्व को बढ़ावा दिया। स्वतंत्रता के पश्चात सत्ता में आए नेताओं ने तमिल अल्पसंख्यकों की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी को नजरअंदाज किया। इस बहिष्करण की भावना ने तमिलों के भीतर असुरक्षा पैदा की, जिससे वे अपनी पहचान और अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करने के लिए मजबूर हो गए।

157. (D) इसने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में तमिलों के अवसरों को सीमित कर दिया।
1956 में लागू किए गए भाषाई कानून ने तमिल भाषी नागरिकों के लिए व्यवस्था में गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दीं। सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने से उन लोगों को बहुत नुकसान हुआ जो इस भाषा में निपुण नहीं थे। इसके कारण सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों और उच्च शिक्षा में तमिलों का प्रतिनिधित्व तेजी से घटा, जिससे उनमें भारी असंतोष और अन्याय की भावना पैदा हुई।

158. (A) संघीय ढांचे के भीतर स्वायत्तता और समान अधिकार
प्रारंभ में तमिल नेतृत्व ने देश की अखंडता के भीतर ही अपने अधिकारों की मांग की थी। उनकी मुख्य मांग एक ऐसी संघीय व्यवस्था की थी जहाँ वे अपने क्षेत्रों में स्वशासन कर सकें और उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा में बराबरी का स्थान मिले। वे शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों से तमिलों के लिए भाषाई और सांस्कृतिक समानता सुनिश्चित करना चाहते थे, न कि अलग देश।

159. (C) सरकार द्वारा शांतिपूर्ण राजनीतिक मांगों की लगातार अनदेखी और राज्य प्रायोजित हिंसा
जब तमिलों के लोकतांत्रिक आंदोलनों को दमनकारी नीतियों और हिंसा के माध्यम से कुचल दिया गया, तो संघर्ष ने हिंसक रुप ले लिया। राजनीतिक समाधान न निकलने के कारण तमिल युवाओं का मोहभंग हो गया, जिससे उग्रवादी गुटों का उदय हुआ। लिट्टे जैसे संगठनों ने हथियारों के बल पर अपनी मांगे मनवाने का रास्ता चुना क्योंकि उन्हें लगा कि शांतिपूर्ण वार्ता अब संभव नहीं है।

160. (A) भेदभावपूर्ण राज्य नीतियों ने शांतिपूर्ण राजनीतिक प्रतिरोध को सशस्त्र संघर्ष में बदल दिया।
श्रीलंका का जातीय संकट यह दर्शाता है कि कैसे समावेशी राजनीति का अभाव देश को विनाशकारी गृहयुद्ध की ओर धकेल सकता है। जब राज्य एक विशेष समुदाय को प्राथमिकता देता है और दूसरों के अधिकारों का हनन करता है, तो राजनीतिक संवाद विफल हो जाता है। इस संघर्ष का मुख्य निष्कर्ष यही है कि स्थायी शांति के लिए सभी समुदायों को समान न्याय और सम्मान मिलना चाहिए।

161. (D) सेना, नौकरशाही और भूस्वामी अभिजात वर्ग
पाकिस्तान की शासन व्यवस्था पर तीन विशिष्ट समूहों का अत्यधिक नियंत्रण रहा है, जिन्हें सामूहिक रुप से ट्रोइका के नाम से जाना जाता है। इसमें शक्तिशाली सैन्य बल, प्रशासनिक ढांचे को चलाने वाली नौकरशाही और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभाव रखने वाला जमींदार वर्ग शामिल है। ये तीनों घटक मिलकर देश की राजनीतिक दिशा और नीतियों को इस प्रकार प्रभावित करते हैं कि सत्ता उनके इर्द-गिर्द ही सिमटी रहती है।

162. (B) भारत के साथ निरंतर तनाव और राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा के कारण
पाकिस्तान में सेना की सर्वोच्चता का एक बड़ा कारण पड़ोसी देश भारत के साथ उसके जटिल संबंध और सुरक्षात्मक मानसिकता है। बाहरी खतरे के डर ने सेना को खुद को राष्ट्र के रक्षक के रूप में पेश करने का मौका दिया है। इस स्थिति ने सेना के बजट और राजनीतिक प्रभाव को जनमानस में वैध बना दिया है, जिससे वह देश के लोकतांत्रिक संस्थानों से भी अधिक शक्तिशाली हो गई है।

163. (C) सेना के व्यापक वाणिज्यिक और व्यावसायिक हित
मिलबस शब्द सेना के उन आर्थिक उपक्रमों को दर्शाता है जो विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में फैले हुए हैं। पाकिस्तान की सेना केवल रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि वह बड़े उद्योगों, रियल एस्टेट और व्यापारिक संस्थानों का भी संचालन करती है। यह व्यापक आर्थिक आधार सेना को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाता है और उसे राजनीति में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए अतिरिक्त संसाधन प्रदान करता है।

164. (D) जब राजनीतिक दल कमजोर होते हैं और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करते हैं
पाकिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप के लिए अक्सर नागरिक सरकारों की विफलताएं जिम्मेदार रही हैं। जब भी निर्वाचित सरकारें आंतरिक कलह या भ्रष्टाचार के कारण अपनी विश्वसनीयता खो देती हैं, तो सेना को सत्ता हथियाने का नैतिक आधार मिल जाता है। कमजोर राजनीतिक नेतृत्व और लोकतांत्रिक संस्थानों की अस्थिरता सेना के लिए तख्तापलट करने या पर्दे के पीछे से शासन चलाने का मार्ग प्रशस्त करती है।

165. (A) पाकिस्तान में लोकतंत्र की अस्थिरता का मुख्य कारण सेना का संस्थागत प्रभुत्व और राजनीतिक दलों की कमजोरी है।
पाकिस्तान का राजनीतिक इतिहास नागरिक और सैन्य शासन के बीच झूलता रहा है। सेना की मजबूत संस्थागत पकड़ ने लोकतंत्र की जड़ों को कभी मजबूत नहीं होने दिया। राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की कमी और भ्रष्टाचार ने इस स्थिति को और खराब किया है। निष्कर्षतः, जब तक सेना की भूमिका सीमित नहीं होती और दल मजबूत नहीं होते, तब तक वहां लोकतंत्र अस्थिर ही रहेगा।

166. (B) भारत का प्रभुत्व पड़ोसियों में प्रशंसा और भय दोनों उत्पन्न करता है।
दक्षिण एशिया में भारत की विशाल भौगोलिक और आर्थिक स्थिति उसे एक स्वाभाविक नेतृत्वकर्ता बनाती है। हालांकि, यही शक्ति पड़ोसी देशों के लिए चिंता का विषय भी बन जाती है क्योंकि वे अपनी स्वायत्तता को लेकर सशंकित रहते हैं। वे भारत को संकट के समय सहायक तो मानते हैं, परंतु साथ ही उसके प्रभाव को अपनी संप्रभुता के लिए एक संभावित खतरे के रुप में भी देखते हैं।

167. (B) 1988 में मालदीव में तख्तापलट के प्रयास को विफल करना
भारत ने क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता के रूप में समय-समय पर अपनी जिम्मेदारी निभाई है, जिसका प्रमाण मालदीव में किया गया सैन्य हस्तक्षेप है। जब मालदीव की निर्वाचित सरकार संकट में थी, तब भारत ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां स्थिरता बहाल की। यह घटना दर्शाती है कि भारत अपने पड़ोसियों की संप्रभुता और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए सैन्य और रणनीतिक सहयोग प्रदान करने में हमेशा तत्पर रहा है।

168. (A) उन्हें डर है कि भारत उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है और उनकी संप्रभुता को कम कर सकता है।
छोटे देशों की यह धारणा है कि भारत अपनी शक्ति का उपयोग उनकी घरेलू राजनीति को प्रभावित करने के लिए कर सकता है। उन्हें यह आशंका सताती है कि बड़े आकार के कारण भारत उनकी स्वतंत्र विदेश नीति या आंतरिक निर्णयों को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। यही मनोवैज्ञानिक दबाव उनके और भारत के बीच विश्वास की कमी का एक प्रमुख कारण बनता है, जो संबंधों को प्रभावित करता है।

169. (C) जल-बंटवारा, व्यापार असंतुलन और सीमा विवाद
भारत और उसके पड़ोसियों के बीच मतभेद केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि संसाधनों और सीमाओं से भी जुड़े हैं। नदियों के पानी के बँटवारे को लेकर होने वाले विवाद और बढ़ते व्यापारिक घाटे ने अक्सर कूटनीतिक तनाव को जन्म दिया है।

इसके अलावा, अनसुलझी सीमाएं और घुसपैठ जैसी समस्याएं भी आपसी संबंधों में खटास पैदा करती हैं। इन व्यावहारिक मुद्दों का समाधान द्विपक्षीय सहयोग के लिए अत्यंत आवश्यक है।

170. (D) एक आवश्यक भागीदार और एक संभावित आधिपत्यवादी शक्ति की दोहरी धारणा को संतुलित करना
भारतीय विदेश नीति के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी छवि को सुधारने की है। उसे एक तरफ पड़ोसी देशों को यह विश्वास दिलाना होता है कि वह उनकी प्रगति में सहायक है, और दूसरी तरफ अपनी सुरक्षा चिंताओं को भी सुरक्षित रखना होता है। सहयोग और वर्चस्व के बीच एक महीन रेखा बनाए रखना जरूरी है ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे और भारत का नेतृत्व स्वीकार्य हो।

171. (C) जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, और कृषि की बढ़ती मांग
दक्षिण एशियाई देशों में बढ़ती आबादी के कारण पानी की खपत में भारी इजाफा हुआ है। औद्योगिक विकास और आधुनिक कृषि पद्धतियों ने सीमित जल संसाधनों पर दबाव को कई गुना बढ़ा दिया है। जब मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है, तो साझा जल स्रोतों के उपयोग को लेकर देशों के बीच प्रतिस्पर्धा और तनाव बढ़ना स्वाभाविक है। यह समस्या आने वाले समय में और भी जटिल होने वाली है।

172. (B) सिंधु जल संधि
भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सिंधु जल संधि को विश्व स्तर पर एक सफल कूटनीतिक उपलब्धि माना जाता है। विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई इस संधि ने कई युद्धों और अत्यधिक राजनीतिक तनाव के बावजूद जल साझाकरण की व्यवस्था को अटूट बनाए रखा है। यह संधि इस बात का प्रतीक है कि जटिल तकनीकी और विवादित मुद्दों पर भी स्थाई सहयोग समझौता करना संभव है।

173. (D) भारत और बांग्लादेश
ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी प्रवाह पर चीन की गतिविधियों ने निचले देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। बांधों के निर्माण से भारत और बांग्लादेश को डर है कि उनके क्षेत्रों में पानी की कमी हो सकती है या अचानक पानी छोड़े जाने से बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। यह स्थिति जल सुरक्षा के साथ-साथ इन देशों की खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी एक बड़ी चुनौती है।

174. (A) एक राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के रूप में
जल संसाधनों को अब केवल पर्यावरणीय या आर्थिक मुद्दा नहीं माना जाता, बल्कि इसे देश की सुरक्षा से जोड़कर देखा जाता है। जब सरकारें पानी के अधिकार को संप्रभुता का प्रतीक बना लेती हैं, तो तकनीकी समाधान मुश्किल हो जाते हैं। इससे जल-बंटवारा एक संवेदनशील राजनीतिक प्रश्न बन जाता है, जहाँ एक देश का लाभ दूसरे के लिए सुरक्षा खतरे के रूप में देखा जाने लगता है।

175. (C) पारदर्शी डेटा-साझाकरण, संयुक्त बेसिन प्रबंधन और प्रभावी विवाद समाधान तंत्र
जल संकट के समाधान के लिए देशों को आपसी अविश्वास त्यागकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। नदियों के बहाव और उपयोग से संबंधित सटीक जानकारी साझा करना विवादों को कम करने में सहायक हो सकता है। साथ ही, संपूर्ण नदी बेसिन के संयुक्त प्रबंधन और स्वतंत्र कानूनी मंचों की स्थापना के माध्यम से ही भविष्य के संभावित जल युद्धों को रोका जा सकता है और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है।

अध्याय 04
अंतर्राष्ट्रीय संगठन

1. संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रतीक चिह्न में जैतून की पत्तियाँ किसका संकेत करती हैं?
(A) सदस्य देशों की शक्ति का
(B) विश्व शांति का
(C) आर्थिक समृद्धि का
(D) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का

2. संयुक्त राष्ट्रसंघ का गठन किस उद्देश्य से हुआ था?
(A) मानवता को नरक से बचाने के लिए
(B) मानवता को स्वर्ग पहुँचाने के लिए
(C) सदस्य देशों पर सैन्य नियंत्रण स्थापित करने के लिए
(D) एक वैश्विक सरकार बनाने के लिए

3. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के बारे में सही है?
(A) यह वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था की विस्तृत देखरेख और मार्गदर्शन करता है।
(B) इसके सभी सदस्य देशों के मतदान का कुल वज़न पूरी तरह बराबर होता है।
(C) यह वैश्विक वित्त-व्यवस्था की देखरेख और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
(D) इसका मुख्यालय प्रमुख यूरोपीय शहर जेनेवा में पूर्णतः स्थित है।

4. अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों आवश्यक हैं?
(A) वे एक शक्तिशाली राज्य के रूप में कार्य करते हैं।
(B) वे केवल विकसित देशों के हितों की रक्षा करते हैं।
(C) वे हमेशा अपने सदस्यों पर अपनी इच्छा थोपते हैं।
(D) वे युद्ध और शांति के मामलों में मदद करते हैं।

5. निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर
2. संयुक्त राष्ट्रसंघ की घोषणा पर हस्ताक्षर
3. याल्टा सम्मेलन
4. संयुक्त राष्ट्रसंघ चार्टर पर 50 देशों के हस्ताक्षर
5. संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना

(A) 1, 2, 3, 4, 5
(B) 2, 1, 4, 3, 5
(C) 1, 3, 2, 5, 4
(D) 3, 1, 4, 5, 2

6. 'लीग ऑफ नेशंस' के उत्तराधिकारी के रूप में किस संगठन की स्थापना हुई?
(A) विश्व व्यापार संगठन
(B) संयुक्त राष्ट्रसंघ
(C) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
(D) विश्व बैंक

7. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में मदद करते हैं।
कारण (R): देश अपने वैर-विरोध के कारण हमेशा एक-दूसरे से युद्ध ठान लेते हैं और बातचीत नहीं करते।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

8. 1945 में संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणापत्र पर कितने देशों ने दस्तखत किए थे?
(A) 51
(B) 26
(C) 50
(D) 193

9. निम्नलिखित में से कौन-सा संयुक्त राष्ट्रसंघ का प्रमुख अंग नहीं है?
(A) सुरक्षा-परिषद्
(B) आम सभा
(C) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
(D) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय

10. निम्नलिखित में से कौन सा कथन शीतयुद्ध के बाद के बदलावों को सही ढंग से नहीं दर्शाता है?
(A) रूस-अमरीका संबंध अधिक तनावपूर्ण हुए।
(B) सोवियत संघ पूर्णतः बिखर गया।
(C) अमरीका वैश्विक महाशक्ति बना।
(D) चीन तेज़ी से महाशक्ति बन रहा है।

11. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (संयुक्त राष्ट्र अंग)

P. सुरक्षा-परिषद्
Q. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
R. आम सभा
S. सचिवालय

सूची II: (कार्य/विशेषता)

1. सभी सदस्यों को एकसमान मत
2. 15 न्यायाधीश, 9 वर्षों के लिए
3. महासचिव इसका प्रधान होता है
4. पाँच स्थायी सदस्य

(A) P-4, Q-2, R-1, S-3
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-3, R-2, S-1
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

12. संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा-परिषद् में कितने स्थायी और अस्थायी सदस्य हैं?
(A) 10 स्थायी और 5 अस्थायी
(B) 5 स्थायी और 10 अस्थायी
(C) 7 स्थायी और 8 अस्थायी
(D) 15 स्थायी और 0 अस्थायी

13. सुरक्षा-परिषद् के स्थायी सदस्यों को प्राप्त 'वीटो' का अधिकार क्या है?
(A) एक सकारात्मक शक्ति जो किसी प्रस्ताव को पारित करने में मदद करती है।
(B) महासचिव की नियुक्ति करने की शक्ति।
(C) एक नकारात्मक शक्ति जिससे वे किसी भी फैसले को रोक सकते हैं।
(D) अस्थायी सदस्यों के चुनाव में मतदान करने की शक्ति।

14. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संयुक्त राष्ट्रसंघ की आम सभा में हरेक सदस्य को एक वोट हासिल है।
2. सुरक्षा परिषद् में पाँच स्थायी सदस्य हैं।
3. दूसरे विश्वयुद्ध के विजेता देशों को स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया।
4. संयुक्त राष्ट्रसंघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा उसका महासचिव होता है।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3 और 4
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) 1, 2, 3 और 4

15. संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश से हैं?
(A) पुर्तगाल
(B) नॉर्वे
(C) घाना
(D) दक्षिण कोरिया

16. शीतयुद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्रसंघ में सुधारों की मांग क्यों उठी?
(A) पुराना संगठन काफी हद तक अप्रभावी हो गया था।
(B) विश्व राजनीति की समकालीन सच्चाइयाँ बदल गई थीं।
(C) सदस्य देशों की कुल संख्या में काफी कमी आई थी।
(D) अमरीका ने स्वयं इसकी सक्रिय रूप से मांग की थी।

17. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): सुरक्षा-परिषद् में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग की जा रही है।
कारण (R): यह माना जाता है कि मौजूदा सुरक्षा-परिषद् समकालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताओं की बेहतर नुमाइंदगी नहीं करती है।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

18. 1992 में संयुक्त राष्ट्रसंघ की आम सभा में स्वीकृत प्रस्ताव में किन मुख्य शिकायतों का जिक्र था?
(A) उपरोक्त सभी।
(B) सुरक्षा परिषद् राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती।
(C) इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है।
(D) इसमें बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है।

19. सुरक्षा-परिषद् की स्थायी सदस्यता के लिए सुझाए गए मानदंडों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है?
(A) बड़ी आर्थिक ताकत होना।
(B) बड़ी सैन्य ताकत होना।
(C) एक राजतंत्रीय शासन व्यवस्था होना।
(D) आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र होना।

20. संयुक्त राष्ट्रसंघ के बजट में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है?
(A) चीन
(B) जापान
(C) जर्मनी
(D) संयुक्त राज्य अमेरिका

21. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई।
2. इसकी गतिविधियाँ प्रमुख रूप से विकसित देशों से संबंधित हैं।
3. यह अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है।
4. यह केवल आधारभूत ढाँचे के लिए काम करता है।
5. यह संस्था समकालीन वैश्विक अर्थ-व्यवस्था को

प्रभावित नहीं करती है।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2 और 4
(C) केवल 1, 2 और 5
(D) केवल 3 और 4

22. सुरक्षा-परिषद् में अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं?

(A) एक वर्ष
(B) दो वर्ष
(C) चार वर्ष
(D) पाँच वर्ष

23. 'वीटो पावर' के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है?

(A) यह सुरक्षा-परिषद् के सिर्फ स्थायी सदस्यों को प्राप्त है।
(B) यह एक तरह की नकारात्मक शक्ति है।
(C) एक वीटो से भी सुरक्षा-परिषद् का प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है।
(D) महासचिव भी इसका प्रयोग कर सकता है।

24. 2005 में संयुक्त राष्ट्रसंघ की 60वीं सालगिरह पर सदस्य देशों ने किन कदमों को उठाने का फैसला किया?

(A) उपरोक्त सभी
(B) शांति संस्थापक आयोग का गठन
(C) मानवाधिकार परिषद् की स्थापना
(D) सहस्राब्दि विकास लक्ष्य को प्राप्त करने पर सहमति

25. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची I: (महासचिव)

P. ट्राइग्व ली
Q. डेग हैमरशोल्ड
R. यू थांट
S. कोफी अन्नान

सूची II: (देश)

1. बर्मा (म्यांमार)
2. घाना
3. नॉर्वे
4. स्वीडन

(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

26. 'सतत विकास लक्ष्य' (Sustainable Development Goals) का उद्देश्य क्या है?

(A) विकास संबंधी महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करना
(B) केवल पर्यावरण की रक्षा करना
(C) केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देना
(D) केवल सैन्य निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित करना

27. भारत के अनुसार, संयुक्त राष्ट्रसंघ के एजेंडे में कौन सा मामला प्रमुख होना चाहिए?

(A) सैन्य हस्तक्षेप
(B) अंतरिक्ष अन्वेषण
(C) वीटो पावर का विस्तार
(D) विकास

28. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:

अभिकथन (A): भारत सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता का दावेदार है।

कारण (R): भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति है और उसने संयुक्त राष्ट्रसंघ की पहलकदमियों में सक्रिय भाग लिया है।

(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

29. सुरक्षा परिषद् की सदस्य संख्या को 1965 में 11 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था?

(A) 12
(B) 20
(C) 15
(D) 21

30. निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सुरक्षा-परिषद् में स्थायी सदस्यता का स्पष्ट रूप से विरोध नहीं करता है?

(A) पाकिस्तान
(B) ब्राजील
(C) जर्मनी
(D) संयुक्त राज्य अमेरिका

31. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन विश्व व्यापार संगठन (WTO) के बारे में गलत है?

(A) इसकी कार्यविधि पूरी तरह पारदर्शी है।
(B) इसकी स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी।
(C) यह 'गैट' का उत्तराधिकारी संगठन है।
(D) फैसला सर्वसम्मति से ही लिया जाता है।

32. एक-ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्रसंघ के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है?

(A) चीन का बढ़ता प्रभाव
(B) अमरीकी प्रभुत्व
(C) रूस का सैन्य विस्तार
(D) यूरोपीय संघ का एकीकरण

33. संयुक्त राष्ट्रसंघ के भीतर अमरीका के विशेष प्रभाव का क्या कारण है?

(A) वह संयुक्त राष्ट्रसंघ के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाला देश है।
(B) उपरोक्त सभी।
(C) संयुक्त राष्ट्रसंघ का मुख्यालय अमरीकी भू-क्षेत्र में स्थित है।
(D) संयुक्त राष्ट्रसंघ के कई नौकरशाह अमरीकी नागरिक हैं।

34. संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव के चयन में किस देश की बात बहुत वज़न रखती है?
(A) अमरीका
(B) चीन
(C) रूस
(D) फ्रांस

35. निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में रखें:
1. मानवाधिकार परिषद् की स्थापना
2. 'एन अजेंडा फॉर पीस' रिपोर्ट जारी होना
3. एंटोनियो गुटेरेस का महासचिव बनना
4. यू थांट का महासचिव बनना

(A) 4, 2, 1, 3
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 4, 1, 3
(D) 4, 1, 2, 3

36. एमनेस्टी इंटरनेशनल किस क्षेत्र में काम करने वाला एक स्वयंसेवी संगठन है?
(A) पर्यावरण संरक्षण
(B) आर्थिक विकास
(C) वैश्विक व्यापार
(D) मानवाधिकारों की रक्षा

37. ह्यूमन राइट्स वॉच के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
(A) यह एक सरकारी संगठन है।
(B) यह केवल बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने के लिए काम करता है।
(C) यह अमरीका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है।
(D) इसका मुख्यालय जेनेवा में है।

38. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): एक-ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्रसंघ अमरीका की ताकत पर अंकुश लगाने में खास सक्षम नहीं है।
कारण (R): अमरीका अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बूते संयुक्त राष्ट्रसंघ की अनदेखी कर सकता है और उसके पास 'वीटो' की शक्ति भी है।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

39. अंतर्राष्ट्रीय आण्विक ऊर्जा एजेंसी (IAEA) का मुख्य कार्य क्या है?
(A) परमाण्विक ऊर्जा के सैन्य उपयोग को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना।
(B) विश्व के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को स्थायी रूप से बंद करवाना।
(C) परमाणु हथियार विकसित करने में विभिन्न सदस्य देशों की मदद करना।
(D) परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना।

40. 'पारस्परिक निर्भरता' की अवधारणा का क्या अर्थ है?
(A) विभिन्न समाजों और मसलों के बीच आपसी जुड़ाव।
(B) सभी देशों का एक-दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र होना।
(C) केवल आर्थिक और वित्तीय मसलों पर एक-दूसरे पर निर्भर होना।
(D) दो मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय सैन्य सुरक्षा संधि होना।

41. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. IAEA की स्थापना 1957 में हुई।
2. यह संगठन परमाण्विक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है।
3. इसके अधिकारी विश्व की परमाण्विक सुविधाओं की नियमित जाँच करते हैं।
4. इसका मुख्य उद्देश्य सैन्य उद्देश्यों के लिए परमाणु संयंत्रों के उपयोग को प्रोत्साहित करना है।
5. यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के अधीन काम नहीं करता है।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2, 3
(B) केवल 2, 3, 4
(C) केवल 1, 4, 5
(D) केवल 1, 2, 3, 5

42. सुरक्षा-परिषद् के फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होने की शिकायत का क्या अर्थ है?
(A) पश्चिमी देशों के हितों को प्राथमिकता देना।
(B) फैसले पूर्णतः केवल पश्चिमी देशों द्वारा लिए जाते हैं।
(C) फैसले सदैव गैर-पश्चिमी देशों के हितों के खिलाफ होते हैं।
(D) फैसलों में मानवाधिकारों की पूरी तरह अनदेखी की जाती है।

43. संयुक्त राष्ट्रसंघ में सुधार के अंतर्गत दो तरह के बुनियादी सुधार कौन से हैं?
(A) बजट में वृद्धि और कर्मचारियों की संख्या में कमी।
(B) मुख्यालय को बदलना और स्थायी सदस्यों को हटाना।
(C) केवल सैन्य अभियानों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित

करना।
(D) संगठन की बनावट और प्रक्रियाओं में सुधार।

44. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (एजेंसी/कार्यक्रम)
P. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)
Q. संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (UNDP)
R. संयुक्त राष्ट्रसंघ शरणार्थी उच्चायोग (UNHCR)
S. संयुक्त राष्ट्रसंघ बाल कोष (UNICEF)
सूची II: (मुख्य कार्यक्षेत्र)
1. बच्चों के लिए
2. शरणार्थियों के लिए
3. विकास के लिए
4. स्वास्थ्य के लिए
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-4, Q-1, R-3, S-2
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

45. संयुक्त राष्ट्रसंघ का कौन सा अंग सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से बनता है?
(A) सुरक्षा परिषद्
(B) आर्थिक और सामाजिक परिषद्
(C) आम सभा
(D) सचिवालय

46. आम सभा में प्रमुख निर्णयों के लिए कितने बहुमत की ज़रूरत होती है?
(A) सामान्य बहुमत
(B) तीन-चौथाई बहुमत
(C) सर्वसम्मति
(D) दो-तिहाई बहुमत

47. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
(A) हेग
(B) न्यूयॉर्क
(C) जेनेवा
(D) पेरिस

48. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): भारत सुरक्षा परिषद् के पुनर्गठन की मांग करता है।
कारण (R): भारत का मानना है कि परिषद् के विस्तार से वह ज़्यादा प्रतिनिधिमूलक होगी और उसे विश्व-बिरादरी का ज़्यादा समर्थन मिलेगा।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

49. विश्व व्यापार संगठन (WTO) किसका उत्तराधिकारी है?
(A) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)
(B) जेनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ (GATT)
(C) विश्व बैंक
(D) संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (UNDP)

50. किस देश ने 'वीटो पावर' का सबसे अधिक बार इस्तेमाल किया है?
(A) सोवियत संघ/रूस
(B) अमरीका
(C) चीन
(D) फ्रांस

51. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सुरक्षा परिषद् के अस्थायी सदस्य दो साल की अवधि के बाद तत्काल पुनः नहीं चुने जा सकते।
2. अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं है।
3. अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन इस तरह से होता है कि विश्व के सभी महादेशों का प्रतिनिधित्व हो सके।
4. स्थायी सदस्यों में से कोई एक भी वीटो का प्रयोग करके किसी फैसले को रोक सकता है।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3 और 4
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) 1, 2, 3 और 4

52. संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव 'बान की मून' किस देश के नागरिक थे?
(A) चीन
(B) जापान
(C) पुर्तगाल
(D) दक्षिण कोरिया

53. संयुक्त राष्ट्रसंघ के पहले महासचिव थे?
(A) डेग हैमरशोल्ड
(B) यू थांट
(C) कुर्त वाल्डहीम
(D) ट्राइग्व ली

54. संयुक्त राष्ट्रसंघ के संस्थापक चार्टर (अटलांटिक चार्टर) पर अगस्त 1941 में किन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किए?
(A) रूजवेल्ट और स्टालिन
(B) रूजवेल्ट और चर्चिल
(C) चर्चिल और स्टालिन
(D) रूजवेल्ट और द गॉल

55. निम्नलिखित महासचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:

1. बान की मून
2. कोफी अन्नान
3. बुतरस बुतरस घाली
4. जेवियर पेरेज द कूइयार

(A) 4, 3, 2, 1
(B) 3, 4, 1, 2
(C) 4, 2, 3, 1
(D) 2, 3, 4, 1

56. 'एन अजेंडा फॉर पीस' नामक रिपोर्ट किस महासचिव ने जारी की थी?
(A) बुतरस बुतरस घाली
(B) कोफी अन्नान
(C) बान की मून
(D) जेवियर पेरेज द कूइयार

57. आर्थिक और सामाजिक परिषद् के सदस्यों का चुनाव कौन करता है?
(A) सुरक्षा परिषद्
(B) महासचिव
(C) आम सभा
(D) स्थायी सदस्य देश

58. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): वीटो को समाप्त करने की मुहिम चली है।
कारण (R): यह माना जाता है कि वीटो लोकतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों के बीच बराबरी की धारणा से मेल नहीं खाता।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

59. न्यासिता परिषद् (Trusteeship Council) को कब से स्थगित कर दिया गया?
(A) 1991
(B) 2000
(C) 2005
(D) 1994

60. 2001 का नोबेल शांति पुरस्कार किस महासचिव को प्रदान किया गया था?
(A) बान की मून
(B) कोफी अन्नान
(C) बुतरस बुतरस घाली
(D) डेग हैमरसोल्ड (मरणोपरांत)

61. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (संगठन)
P. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)
Q. विश्व व्यापार संगठन (WTO)
R. अंतर्राष्ट्रीय आण्विक ऊर्जा एजेंसी (IAEA)
S. ह्यूमन राइट्स वॉच

सूची II: (कार्य/मुख्यालय)
1. वैश्विक व्यापार नियम
2. मानवाधिकार उल्लंघन पर नजर
3. वैश्विक वित्त-व्यवस्था की देखरेख
4. परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग

(A) P-1, Q-3, R-2, S-4
(B) P-3, Q-1, R-4, S-2
(C) P-3, Q-2, R-1, S-4
(D) P-4, Q-1, R-3, S-2

62. सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश उसका उत्तराधिकारी राज्य बना?
(A) यूक्रेन
(B) बेलारूस
(C) कजाकिस्तान
(D) रूस

63. 'समूह-7' (G-7) के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है?
(A) चीन
(B) अमरीका
(C) जापान
(D) जर्मनी

64. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. शीतयुद्ध के बाद रूस और अमरीका के बीच संबंध अधिक सहयोगात्मक हो गए।
2. एशिया की अर्थव्यवस्था में अप्रत्याशित दर से तरक्की हुई है।
3. पूर्वी यूरोप के कई भूतपूर्व साम्यवादी देश संयुक्त राष्ट्रसंघ में शामिल हुए।
4. विश्व के सामने जनसंहार, गृहयुद्ध और आतंकवाद जैसी नई चुनौतियाँ मौजूद हैं।
5. शीतयुद्ध के अंत के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता समाप्त हो गई।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2, 3
(B) केवल 1, 2, 3, 4
(C) केवल 3, 4, 5
(D) सभी कथन सही हैं

65. भारत संयुक्त राष्ट्रसंघ में कब शामिल हुआ?
(A) 24 अक्टूबर 1945
(B) 30 अक्टूबर 1945
(C) 26 जून 1945
(D) 15 अगस्त 1947

66. संयुक्त राष्ट्रसंघ के किस अंग को 'बतकही की चौपाल' भी कहा जाता है?
(A) आम सभा
(B) सुरक्षा परिषद्
(C) सचिवालय
(D) आर्थिक और सामाजिक परिषद्

67. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): संयुक्त राष्ट्रसंघ अमरीका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मसलों पर बातचीत कायम कर सकता है।
कारण (R): संयुक्त राष्ट्रसंघ एक ऐसा मंच है जहाँ अमरीकी रवैये और नीतियों पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है और आलोचना की सुनवाई होती है।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

68. निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार मिला?
(A) ट्राइग्व ली
(B) यू थांट
(C) कुर्त वाल्डहीम
(D) डेग हैमरशोल्ड

69. संयुक्त राष्ट्रसंघ के बजट में भारत का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है?
(A) 2.64%
(B) 1.1%
(C) 0.8%
(D) 2.2%

70. संयुक्त राष्ट्रसंघ की संरचना में, कौन सी एजेंसी आम सभा और सुरक्षा-परिषद् दोनों के प्रति उत्तरदायी है?
(A) विश्व व्यापार संगठन (डबल्यूटीओ)
(B) अंतर्राष्ट्रीय आण्विक ऊर्जा एजेंसी
(C) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)
(D) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)

71. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (संगठन)
P. UNCTAD
Q. UNEP
R. UNDP
S. UNHCR
सूची II: (पूरा नाम/कार्यक्षेत्र)
1. विकास कार्यक्रम
2. शरणार्थी उच्चायोग
3. पर्यावरण कार्यक्रम
4. व्यापार एवं विकास सम्मेलन
(A) P-4, Q-3, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-1, R-2, S-3
(D) P-3, Q-4, R-1, S-2

72. सुरक्षा-परिषद् के पुनर्गठन की योजना में किस महाद्वीप के देशों को शामिल करने पर विशेष बल दिया जा रहा है?
(A) एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमरीका
(B) केवल एशिया और अफ्रीकी महाद्वीप
(C) यूरोप और उत्तरी अमरीका के देश
(D) ऑस्ट्रेलिया और एशियाई महाद्वीप

73. क्यूबा के मिसाइल-संकट के समाधान में किस महासचिव ने प्रयास किए थे?
(A) ट्राइग्व ली
(B) डेग हैमरशोल्ड
(C) यू थांट
(D) कुर्त वाल्डहीम

74. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत संयुक्त राष्ट्रसंघ के जन्म से ही उसका सदस्य है।
2. भारत सुरक्षा परिषद् के स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोत्तरी का समर्थक है।
3. भारत का मानना है कि सुरक्षा-परिषद् का विस्तार करने पर वह ज़्यादा प्रतिनिधिमूलक होगी।
4. भारत स्वयं सुरक्षा परिषद् का स्थायी सदस्य नहीं बनना चाहता।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1, 2 और 3
(C) केवल 3 और 4
(D) 1, 2, 3 और 4

75. मानवाधिकारों की रक्षा में सक्रिय दो स्वयंसेवी संगठन कौन से हैं?
(A) विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनेस्को
(B) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक
(C) ग्रीनपीस और रेड क्रॉस
(D) एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच

76. कांगो-संकट को सुलझाने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए किस महासचिव की आलोचना हुई?
(A) ट्राइग्व ली
(B) डेग हैमरशोल्ड
(C) यू थांट
(D) कोफी अन्नान

77. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:

अभिकथन (A): कुछ देश भारत को सुरक्षा परिषद् का स्थायी सदस्य बनाने का विरोध करते हैं।
कारण (R): कुछ देश भारत के परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित हैं और कुछ का मानना है कि अन्य उभरती ताकतों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

78. संयुक्त राष्ट्रसंघ की किस विशेष एजेंसी का संबंध शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति से है?
(A) यूनिसेफ (UNICEF)
(B) यूएनडीपी (UNDP)
(C) डब्ल्यूएचओ (WHO)
(D) यूनेस्को (UNESCO)

79. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं और उनका कार्यकाल कितना होता है?
(A) 15 न्यायाधीश, 9 वर्ष
(B) 10 न्यायाधीश, 5 वर्ष
(C) 9 न्यायाधीश, 15 वर्ष
(D) 20 न्यायाधीश, 10 वर्ष

80. संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है?
(A) केवल सुरक्षा परिषद्
(B) सुरक्षा-परिषद् की सलाह पर आम सभा
(C) केवल आम सभा
(D) सदस्य देशों के सीधे मतदान द्वारा

81. निम्नलिखित में से कौन-सा देश सुरक्षा परिषद् का स्थायी सदस्य नहीं है?
(A) चीन
(B) जर्मनी
(C) फ्रांस
(D) ब्रिटेन

82. संयुक्त राष्ट्रसंघ के घटनाक्रम को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें:
1. याल्टा सम्मेलन
2. सेन फ्रांसिस्को सम्मेलन
3. भारत संयुक्त राष्ट्रसंघ में शामिल हुआ
4. संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना
(A) 1, 2, 4, 3
(B) 2, 1, 4, 3
(C) 1, 4, 2, 3
(D) 4, 1, 2, 3

83. 'शांति संस्थापक आयोग' (Peacebuilding Commission) का गठन कब किया गया?
(A) 1992
(B) 1997
(C) 2005
(D) 2015

84. विश्व बैंक की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन से देश हैं?
(A) विकसित देश
(B) साम्यवादी देश
(C) सभी देश समान रूप से
(D) विकासशील देश

85. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अंतर्राष्ट्रीय संगठन हर मर्ज की दवा नहीं हैं लेकिन वे महत्त्वपूर्ण हैं।
2. वे देशों की सहायता करते हैं ताकि बेहतर जीवन-स्थितियाँ कायम हों।
3. अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण विभिन्न राज्य ही करते हैं और यह उनके मामलों के लिए जवाबदेह होता है।
4. एक बार निर्माण हो जाने पर, ये समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान में मदद करते हैं।
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमेशा सदस्य देशों पर अपनी इच्छा थोपते हैं।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2, 5
(B) केवल 3, 4, 5
(C) केवल 1, 2, 3, 4
(D) सभी कथन सही हैं

86. निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विश्व बैंक का नहीं है?
(A) मानवीय विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य)
(B) वैश्विक मौद्रिक नीति का निर्धारण करना
(C) कृषि और ग्रामीण विकास
(D) आधारभूत ढाँचे (सड़क, बिजली)

87. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): शीतयुद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्रसंघ की भूमिका में बदलाव की उम्मीद की जा रही थी।
कारण (R): अमरीका और उसके खेमे के देश विजेता बनकर उभरे थे, जिससे अमरीकी ताकत पर अंकुश लगाने के लिए एक संगठन की आवश्यकता महसूस की गई।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

88. सुरक्षा परिषद् के सुधार के संदर्भ में, प्रतिनिधित्व के मसले को हल करने के लिए किन आधारों पर विचार किया जा रहा है?
(A) उपरोक्त सभी
(B) भौगोलिक बराबरी
(C) आर्थिक विकास
(D) संस्कृति या सभ्यता

89. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के कितने सदस्य देश हैं?
(A) 51
(B) 193
(C) 190
(D) 164

90. संयुक्त राष्ट्रसंघ चार्टर पर हस्ताक्षर किस शहर में संपन्न हुए सम्मेलन में हुए?
(A) सेन फ्रांसिस्को
(B) याल्टा
(C) वाशिंगटन
(D) न्यूयॉर्क

91. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (एजेंसी)
P. FAO
Q. IMO
R. ITU
S. ILO
सूची II: (पूरा नाम/ कार्यक्षेत्र)
1. अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ
2. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
3. खाद्य एवं कृषि संगठन
4. अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

92. किस महासचिव के दोबारा चुने जाने का चीन ने विरोध किया था?
(A) कुर्त वाल्डहीम
(B) जेवियर पेरेज द कूइयार
(C) ट्राइग्व ली
(D) यू थांट

93. किस महासचिव के दोबारा चुने जाने का अमरीका ने विरोध किया था?
(A) कोफी अन्नान
(B) बान की मून
(C) बुतरस बुतरस घाली
(D) यू थांट

94. संयुक्त राष्ट्रसंघ के किस अंग को 1 नवम्बर 1994 से स्थगित कर दिया गया है?
(A) आर्थिक और सामाजिक परिषद्
(B) सचिवालय
(C) सुरक्षा परिषद्
(D) न्यासिता परिषद्

95. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन संयुक्त राष्ट्रसंघ के बारे में असत्य है?
(A) आम सभा में प्रत्येक सदस्य को दो वोट हासिल हैं।
(B) इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना है।
(C) यह सामाजिक-आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए काम करता है।
(D) 2011 तक इसके सदस्य देशों की संख्या 193 थी।

96. निम्नलिखित महासचिवों को उनके देश के साथ सुमेलित करने वाला सही जोड़ा पहचानें:
(A) एंटोनियो गुटेरेस - स्पेन
(B) कोफी अन्नान - घाना
(C) बान की मून - जापान
(D) यू थांट - थाईलैंड

97. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): विकासशील देशों की शिकायत रहती है कि विश्व व्यापार संगठन की कार्यविधि पारदर्शी नहीं है।
कारण (R): बड़ी आर्थिक ताकतें जैसे अमरीका, यूरोपीय संघ और जापान व्यापार के नियमों को अपने हितों के अनुसार बनाने में कामयाब हो जाती हैं।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

98. संयुक्त राष्ट्रसंघ के ढांचे के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेष एजेंसी (Specialized Agency) है?
(A) विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)
(B) यूएनडीपी
(C) यूनिसेफ
(D) यूएनईपी

99. सुरक्षा परिषद् के निर्णयों की क्या प्रकृति होती है?
(A) वे केवल सलाहकारी होते हैं।
(B) वे केवल स्थायी सदस्यों पर बाध्यकारी होते हैं।
(C) वे सभी सदस्यों पर बाध्यकारी होते हैं।
(D) वे केवल अस्थायी सदस्यों पर बाध्यकारी होते हैं।

100. 'ग्लोबल वार्मिंग' (विश्वव्यापी तापवृद्धि) की समस्या से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्यों आवश्यक है?

(A) क्योंकि यह केवल औद्योगिक देशों की समस्या है।
(B) क्योंकि इसके समाधान के लिए केवल वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।
(C) क्योंकि यह एक स्थानीय समस्या है।
(D) क्योंकि कोई एक देश इसे अकेले हल नहीं कर सकता।

101. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सुरक्षा-परिषद् में पाँच स्थायी सदस्य हैं।
2. जर्मनी और जापान सुरक्षा-परिषद् के स्थायी सदस्य हैं।
3. स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार है।
4. भारत सुरक्षा-परिषद् का एक स्थायी सदस्य है।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 4
(D) केवल 3 और 4

102. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में किस देश के पास सबसे अधिक मताधिकार प्रतिशत है?
(A) चीन
(B) अमरीका
(C) जापान
(D) जर्मनी

103. 'लीग ऑफ नेशंस' किस बड़ी घटना को रोकने में असफल रहा?
(A) पहला विश्वयुद्ध
(B) शीतयुद्ध
(C) कोरिया युद्ध
(D) दूसरा विश्वयुद्ध

104. संयुक्त राष्ट्रसंघ दिवस कब मनाया जाता है?
(A) 24 अक्टूबर
(B) 26 जून
(C) 30 अक्टूबर
(D) 1 जनवरी

105. संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव के कार्यकाल की अवधि सामान्यतः कितनी होती है?
(A) चार साल
(B) छह साल
(C) पाँच साल
(D) नौ साल

106. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (मुद्दा/अवधारणा)
P. मानवाधिकार परिषद् की स्थापना
Q. अटलांटिक चार्टर
R. न्यासिता परिषद् का स्थगन
S. एमनेस्टी इंटरनेशनल का कार्यक्षेत्र

सूची II: (वर्ष/विवरण)
1. मानवाधिकारों की रक्षा
2. 1994
3. 2006
4. 1941

(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-4, R-2, S-1
(C) P-3, Q-2, R-4, S-1
(D) P-4, Q-3, R-1, S-2

107. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सुरक्षा परिषद् के निर्णयों पर पश्चिमी मूल्यों की छाप होती है।
2. सुरक्षा परिषद् में बराबर का प्रतिनिधित्व है।
3. सुरक्षा परिषद् अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी करती है।
4. 1997 में सुधारों के लिए जाँच शुरु करवाई गई।
5. सुरक्षा परिषद् के फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है।

उपरोक्त में से कौन से कथन गलत हैं?
(A) केवल 2 और 3
(B) केवल 1, 4 और 5
(C) केवल 2, 3 और 4
(D) केवल 1 और 5

108. यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए, तो इसका उत्तरदायित्व लेने की स्वीकृति किस बैठक में दी गई?
(A) 1992 की आयोजित आम सभा में
(B) 2005 की 60वीं सालगिरह की बैठक में
(C) ऐतिहासिक याल्टा सम्मेलन में
(D) प्रसिद्ध सेन फ्रांसिस्को सम्मेलन में

109. ह्यूमन राइट्स वॉच ने किन मुद्दों के लिए अभियान चलाने में मदद की है?
(A) बारूदी सुरंगों पर रोक लगाना
(B) बाल सैनिकों का प्रयोग रोकना
(C) उपरोक्त सभी
(D) अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करना

110. अमरीकी राष्ट्रपति रुजवेल्ट और ब्रितानी प्रधानमंत्री चर्चिल ने किस चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे?
(A) संयुक्त राष्ट्र चार्टर
(B) मानवाधिकार चार्टर
(C) पेरिस चार्टर
(D) अटलांटिक चार्टर

111. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित रिपोर्टें अक्सर सरकारों को नागवार लगती हैं।
कारण (R): क्योंकि एमनेस्टी का ज़्यादा जोर सरकारों द्वारा

किए जा रहे दुर्व्यवहार पर होता है।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

112. संयुक्त राष्ट्रसंघ से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें:
1. संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना।
2. संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्य संख्या 11 से बढ़ाकर 15 की गई।
3. मानवाधिकार परिषद् की स्थापना।
4. कोफी अन्नान को नोबेल शांति पुरस्कार मिला।

(A) 1, 2, 4, 3
(B) 1, 4, 2, 3
(C) 2, 1, 3, 4
(D) 4, 3, 2, 1

113. संयुक्त राष्ट्रसंघ की वह कौन सी एजेंसी है जो आपातकाल में आश्रय तथा चिकित्सीय सहायता मुहैया कराती है?
(A) संयुक्त राष्ट्रसंघ शरणार्थी उच्चायोग
(B) विश्व व्यापार संगठन (WTO)
(C) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)
(D) विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)

114. निम्नलिखित में से कौन सा देश 'समूह-7' का सदस्य है?
(A) कनाडा
(B) भारत
(C) चीन
(D) रूस

115. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत संयुक्त राष्ट्रसंघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान देता है।
2. भारत कभी भी अपने भुगतान से चूका नहीं है।
3. सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता का एक प्रतीकात्मक महत्त्व भी है।
4. किसी देश की बढ़ी हुई हैसियत का फायदा उसकी विदेश नीति में मिलता है।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2 और 4
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) 1, 2, 3 और 4

116. संयुक्त राष्ट्रसंघ का कौन सा अंग स्थगित कर दिया गया क्योंकि उसकी देखरेख में आने वाला अंतिम क्षेत्र (पलाउ) आजाद हो गया था?
(A) आर्थिक और सामाजिक परिषद्
(B) सैन्य समिति
(C) निरस्त्रीकरण समिति
(D) न्यासिता परिषद्

117. संयुक्त राष्ट्रसंघ के नौवें महासचिव कौन हैं?
(A) बान की मून
(B) कोफी अन्नान
(C) एंटोनियो गुटेरेस
(D) बुतरस बुतरस घाली

118. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (वीटो प्रयोग की संख्या, 1 जून 2018 तक)
P. सोवियत संघ/रूस
Q. अमरीका
R. यू.के.
S. चीन

सूची II: (संख्या)
1. 84
2. 11
3. 135
4. 32

(A) P-3, Q-1, R-4, S-2
(B) P-1, Q-3, R-2, S-4
(C) P-3, Q-2, R-1, S-4
(D) P-4, Q-1, R-3, S-2

119. सुरक्षा-परिषद् के अस्थायी सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है?
(A) 3 वर्ष
(B) 5 वर्ष
(C) स्थायी
(D) 2 वर्ष

120. संयुक्त राष्ट्रसंघ का कौन सा अंग सदस्य देशों के बीच मौजूद विवादों का निपटारा करता है?
(A) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
(B) आम सभा
(C) सचिवालय
(D) आर्थिक और सामाजिक परिषद्

121. संयुक्त राष्ट्रसंघ के मामलों का समायोजन और प्रशासन किस अंग का कार्य है?
(A) सचिवालय
(B) सुरक्षा-परिषद्
(C) आम सभा
(D) न्यासिता परिषद्

122. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत का मानना है कि बदले हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्रसंघ की मज़बूती ज़रूरी है।
2. भारत चाहता है कि विकास का मामला संयुक्त राष्ट्रसंघ

के एजेंडे में प्रमुख हो।
3. भारत सुरक्षा परिषद् की संरचना में बदलाव का विरोधी है।
4. भारत का तर्क है कि सुरक्षा-परिषद् के विस्तार से वह कम प्रतिनिधिमूलक होगी।
5. भारत केवल स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने का समर्थक है।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3, 4 और 5
(C) केवल 1, 2 और 5
(D) सभी कथन सही हैं

123. 'जेनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ' (GATT) कब अस्तित्व में आया था?
(A) पहले विश्वयुद्ध के बाद
(B) शीतयुद्ध के बाद
(C) 1995 में
(D) दूसरे विश्वयुद्ध के बाद

124. अमरीका के किस महासचिव के दोबारा निर्वाचन का सोवियत संघ ने विरोध किया था?
(A) डेग हैमरशोल्ड
(B) ट्राइग्व ली
(C) यू थांट
(D) कुर्त वाल्डहीम

125. आर्थिक और सामाजिक परिषद् में कितने सदस्य होते हैं?
(A) 15
(B) 51
(C) 54
(D) 193

126. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (क्षेत्रीय आयोग)
P. अफ्रीका के लिए आर्थिक आयोग
Q. यूरोप के लिए आर्थिक आयोग
R. एशिया-प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग
S. दक्षिण अमरीका और कैरेबियाई देश के लिए आर्थिक आयोग

सूची II: (संबंधित अंग)
1. आर्थिक और सामाजिक परिषद्

(A) P, Q, R, और S सभी का संबंध 1 से है।
(B) P-1, Q-1, R-1, S-1 (अलग-अलग इकाइयों के रूप में)
(C) P और Q का 1 से, R और S का 1 से
(D) सभी संयुक्त राष्ट्र के अंग नहीं हैं

127. विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सदस्यों की संख्या कितनी है?
(A) 164
(B) 51
(C) 193
(D) 190

128. संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणापत्र पर 26 जून 1945 को कितने देशों ने हस्ताक्षर किए?
(A) 51
(B) 50
(C) 26
(D) 193

129. 15 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर करने वाला 51वाँ मूल संस्थापक सदस्य देश कौन सा था?
(A) चीन
(B) पोलैंड
(C) भारत
(D) फ्रांस

130. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी को सबसे ज़्यादा वज़नदार बनाता है?
(A) बढ़ती आर्थिक शक्ति और स्थिर लोकतांत्रिक राजनीतिक ढांचा।
(B) देश के पास उच्च स्तरीय परमाणु हथियार क्षमता का होना।
(C) भारत का भौगोलिक दृष्टिकोण से विशाल एशियाई क्षेत्र होना।
(D) संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना से ही इसका सक्रिय सदस्य होना।

131. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. विश्व बैंक मानवीय विकास के लिए काम करता है।
2. यह अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है।
3. ज्यादा गरीब देशों को ये अनुदान वापिस नहीं चुकाने पड़ते।
4. यह संस्था समकालीन वैश्विक अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित करती है।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3 और 4
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) 1, 2, 3 और 4

132. परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघ की एजेंसी का नाम क्या है?
(A) संयुक्त राष्ट्रसंघ निरस्त्रीकरण समिति
(B) संयुक्त राष्ट्रसंघ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति
(C) विश्व व्यापार संगठन
(D) अंतर्राष्ट्रीय आण्विक ऊर्जा एजेंसी

133. संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा-परिषद् में निषेधाधिकार (वीटो) का अधिकार किन्हें प्राप्त है?
(A) सभी सदस्यों को
(B) महासचिव को
(C) केवल स्थायी सदस्यों को
(D) केवल अस्थायी सदस्यों को

134. संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा के संबंध में कौन सा कथन सही है?
(A) इसके सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्रसंघ के बाकी प्रमुख अंगों के स्वतः सदस्य हो जाते हैं।
(B) इसमें प्रत्येक सदस्य देश को एक वोट प्राप्त है।
(C) इसमें सुरक्षा और शांति से जुड़े सभी मसलों का निपटारा होता है।
(D) इसके निर्णय सभी सदस्यों पर बाध्यकारी नहीं होते हैं।

135. सुरक्षा परिषद् के कार्य क्या हैं?
(A) सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की चिंता।
(B) वैश्विक मामलों पर बहस-मुबाहिसा।
(C) सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार की राह आसान बनाना।
(D) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण।

136. 'सहस्राब्दि विकास लक्ष्य' (Millennium Development Goals) को प्राप्त करने पर सहमति कब बनी?
(A) 2005 में
(B) 1992 में
(C) 1997 में
(D) 2015 में

137. संयुक्त राष्ट्रसंघ के कामकाज के बारे में कौन सा कथन गलत है?
(A) सुरक्षा और शांति से जुड़े सभी मसलों का निपटारा सुरक्षा-परिषद् में होता है।
(B) मानवतावादी नीतियों का क्रियान्वयन विभिन्न एजेंसियों के मार्फत होता है।
(C) सुरक्षा के किसी मसले पर पाँचों स्थायी सदस्य देशों का सहमत होना ज़रूरी नहीं है।
(D) संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा के सदस्य बाकी प्रमुख अंगों के स्वतः सदस्य नहीं होते।

138. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संयुक्त राष्ट्रसंघ में केवल लोकतांत्रिक नेताओं को ही अपने देश की नुमाइंदगी का हक होना चाहिए।
2. अंतर्राष्ट्रीय संगठन नियमों और नौकरशाही की एक रुपरेखा दे सकता है।
3. अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग करने के उपाय और सूचनाएँ जुटाने में मदद कर सकता है।
4. अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई शक्तिशाली राज्य नहीं होता जिसकी अपने सदस्यों पर धौंस चलती हो।
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण विभिन्न राज्य ही करते हैं।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2, 3
(B) केवल 2, 3, 4, 5
(C) केवल 1, 3, 5
(D) उपरोक्त सभी कथन प्रासंगिक हैं

139. संयुक्त राष्ट्रसंघ का सबसे जाना-पहचाना पद किसका है?
(A) आम सभा के अध्यक्ष का
(B) सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष का
(C) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का
(D) महासचिव का

140. वैश्विक वित्त-व्यवस्था की देखरेख का कार्य कौन सी संस्था करती है?
(A) विश्व व्यापार संगठन
(B) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
(C) विश्व बैंक
(D) संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम

141. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (महासचिव)
P. बुतरस बुतरस घाली
Q. जेवियर पेरेज द कूइयार
R. कुर्त वाल्डहीम
S. बान की मून

सूची II: (देश)
1. पेरु
2. ऑस्ट्रिया
3. कोरिया गणराज्य
4. मिस्र

(A) P-4, Q-1, R-2, S-3
(B) P-1, Q-4, R-3, S-2
(C) P-4, Q-2, R-1, S-3
(D) P-2, Q-3, R-4, S-1

142. संयुक्त राष्ट्रसंघ का कौन सा मुख्य अंग सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की चिंता करता है?
(A) सुरक्षा परिषद्
(B) आम सभा
(C) सचिवालय
(D) आर्थिक एवं सामाजिक परिषद्

143. अमरीकी नेतृत्व में इराक पर हुए हमले को किस महासचिव ने अवैध करार दिया था?
(A) कोफी अन्नान
(B) बुतरस बुतरस घाली
(C) बान की मून
(D) एंटोनियो गुटेरेस

144. शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद विश्व राजनीति में आए बदलावों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है?
(A) सोवियत संघ का बिखरना
(B) जर्मनी का दो भागों में एकीकरण
(C) अमरीका का सबसे ताकतवर देश बनना
(D) चीन का एक महाशक्ति के रूप में उभरना

145. संयुक्त राष्ट्रसंघ में 'वीटो' का क्या अर्थ है?
(A) मैं अनुमति देता हूँ
(B) मैं निषेध करता हूँ
(C) मैं समर्थन करता हूँ
(D) मैं तटस्थ हूँ

146. सुरक्षा-परिषद् की स्थायी सदस्यता के लिए सुझाए गए मानदंडों में से एक है 'लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान'। इस मानदंड को लागू करने में क्या व्यावहारिक कठिनाई आ सकती है?
(A) चयन प्रक्रिया में व्यावहारिक कठिनाइयाँ।
(B) लोकतंत्र की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है।
(C) कई शक्तिशाली देश इस मानदंड पर खरे नहीं उतरेंगे।
(D) यह आर्थिक ताकत से काफी कम महत्वपूर्ण मानदंड है।

147. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है।
2. यह पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है।
3. यह मानवाधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करता है।
4. इसकी रिपोर्टें हमेशा सरकारों द्वारा प्रशंसित की जाती हैं।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1, 2 और 3
(C) केवल 4
(D) 1, 2, 3 और 4

148. संयुक्त राष्ट्रसंघ के ढांचे में 'यूएन वीमेन' (UN Women) के निर्माण के लिए किस महासचिव ने काम किया?
(A) कोफी अन्नान
(B) एंटोनियो गुटेरेस
(C) बुतरस बुतरस घाली
(D) बान की मून

149. एक-ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्रसंघ की भूमिका के संबंध में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है?
(A) यह अमरीकी प्रभुत्व को पूरी तरह संतुलित कर सकता है।
(B) संगठन अब वर्तमान में पूरी तरह अप्रासंगिक हो गया है।
(C) अमरीका और शेष विश्व के बीच संवाद मंच।
(D) यह केवल अमरीकी हितों की पूर्ति के लिए काम करता है।

150. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (संगठन/निकाय)
P. सुरक्षा-परिषद्
Q. आम सभा
R. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
S. विश्व व्यापार संगठन

सूची II: (कार्य)
1. वैश्विक मामलों पर बहस-मुबाहिसा
2. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण
3. सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार की राह आसान बनाना
4. वैश्विक वित्त-व्यवस्था की देखरेख

(A) P-2, Q-1, R-4, S-3
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-3, R-2, S-1
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में व्यवस्था और शांति बनाए रखने का एक मूलभूत आधार है, जिसे विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र (यूएन) चार्टर के माध्यम से संस्थागत रूप दिया गया है। यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि 'एक के विरुद्ध आक्रमण सभी के विरुद्ध आक्रमण' माना जाएगा, और सभी राष्ट्र मिलकर उस आक्रामक राज्य के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। यह व्यवस्था पारंपरिक सैन्य गठबंधनों से भिन्न है, जो विशिष्ट बाहरी खतरों के विरुद्ध बनाए जाते हैं। सामूहिक सुरक्षा का उद्देश्य किसी भी राज्य द्वारा, चाहे वह सदस्य हो या न हो, की जाने वाली आक्रामकता को रोकना और उसका प्रतिकार करना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इस सिद्धांत को लागू करने का प्राथमिक अधिकार और जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुरक्षा परिषद आर्थिक प्रतिबंधों से लेकर सैन्य हस्तक्षेप तक के उपायों को अधिकृत कर सकती है। हालांकि, शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के बीच वीटो पावर के उपयोग ने सामूहिक सुरक्षा की प्रभावशीलता को गंभीर रूप से बाधित किया। राष्ट्र संघ (लीग ऑफ नेशंस) की विफलता का एक प्रमुख कारण भी एक प्रभावी सामूहिक सुरक्षा तंत्र को लागू करने में उसकी अक्षमता थी, क्योंकि उसके पास न तो सार्वभौमिक सदस्यता थी और न ही अपने निर्णयों को लागू करने के लिए बाध्यकारी शक्ति थी। संयुक्त राष्ट्र का निर्माण इसी ऐतिहासिक कमी को दूर करने के एक प्रयास के रूप में देखा जा सकता है, यद्यपि यह आज भी महाशक्तियों के राजनीतिक हितों से प्रभावित होता है।

उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

151. सामूहिक सुरक्षा का मूल सिद्धांत क्या है?
(A) राष्ट्रों को विशिष्ट सैन्य गठबंधनों में संगठित करना।
(B) किसी एक राज्य पर हुए आक्रमण को सभी राज्यों पर आक्रमण मानना।
(C) केवल आर्थिक प्रतिबंधों के माध्यम से विवादों का समाधान करना।
(D) महाशक्तियों को विश्व व्यवस्था बनाए रखने का विशेष

अधिकार देना।

152. संयुक्त राष्ट्र के किस अंग को सामूहिक सुरक्षा लागू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी दी गई है?
(A) सुरक्षा परिषद
(B) महासभा
(C) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
(D) सचिवालय

153. शीत युद्ध के दौरान सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत की प्रभावशीलता में मुख्य बाधा क्या थी?
(A) संयुक्त राष्ट्र के पास वित्तीय संसाधनों की भारी कमी होना।
(B) महासभा के सदस्य राष्ट्रों के बीच राजनीतिक सहमति का अभाव।
(C) सुरक्षा परिषद में महाशक्तियों द्वारा वीटो पावर का प्रयोग।
(D) एक स्थायी और सक्रिय संयुक्त राष्ट्र सैन्य बल का न होना।

154. स्रोत के अनुसार, राष्ट्र संघ (लीग ऑफ नेशंस) की विफलता का एक प्रमुख कारण क्या था?
(A) इसने आक्रामक और विस्तारवादी राज्यों को सदस्य के रूप में शामिल किया था।
(B) यह संगठन केवल प्रमुख यूरोपीय शक्तियों के हितों पर ही केंद्रित रहा था।
(C) इस संस्था का आधिकारिक मुख्यालय किसी तटस्थ देश में स्थित नहीं था।
(D) इसके पास एक प्रभावी सामूहिक सुरक्षा तंत्र लागू करने की क्षमता नहीं थी।

155. पारंपरिक सैन्य गठबंधन और सामूहिक सुरक्षा में मुख्य अंतर क्या है?
(A) पारंपरिक गठबंधन गुप्त होते हैं, जबकि सामूहिक सुरक्षा की प्रक्रिया सार्वजनिक होती है।
(B) पारंपरिक रक्षात्मक गठबंधनों में किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई की अनुमति नहीं है।
(C) पारंपरिक गठबंधन विशिष्ट खतरों हेतु हैं, जबकि सामूहिक सुरक्षा किसी भी आक्रमण हेतु है।
(D) सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में केवल उदारवादी लोकतांत्रिक राष्ट्र ही सम्मिलित हो सकते हैं।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना (पीसकीपिंग) अभियानों की भूमिका में समय के साथ एक महत्वपूर्ण विकास हुआ है। प्रारंभ में, जिन्हें 'प्रथम पीढ़ी' के शांति स्थापना अभियान कहा जाता है, वे मुख्य रूप से युद्धविराम की निगरानी और दो संप्रभु राज्यों के बीच एक बफर ज़ोन बनाने तक सीमित थे। इन अभियानों में हल्के हथियारों से लैस सैनिक शामिल होते थे और वे आत्मरक्षा को छोड़कर बल का प्रयोग नहीं करते थे। उनकी तैनाती के लिए संघर्षरत पक्षों की सहमति अनिवार्य थी। हालांकि, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, आंतरिक संघर्षों, गृहयुद्धों और राज्य के विघटन की बढ़ती संख्या ने शांति स्थापना की प्रकृति को बदल दिया। 'बहुआयामी' या 'दूसरी पीढ़ी' के शांति स्थापना अभियान अधिक जटिल और व्यापक हो गए। इनके कार्यों में अब मानवाधिकारों की निगरानी, चुनावों का आयोजन, पुलिस बलों का प्रशिक्षण, निरस्त्रीकरण, विसैन्यीकरण और संघर्ष के बाद के समाजों का पुनर्निर्माण (जिसे 'पीस-बिल्डिंग' या शांति-निर्माण भी कहा जाता है) शामिल हो गया। इन नए अभियानों को अक्सर शत्रुतापूर्ण वातावरण में काम करना पड़ता है, जहाँ संघर्षरत पक्षों की स्पष्ट सहमति हमेशा नहीं होती और बल प्रयोग के नियम भी अधिक मजबूत हो जाते हैं। यह विकास संयुक्त राष्ट्र के सामने आने वाली नई चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बदलती परिभाषा को दर्शाता है।

उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

156. 'प्रथम पीढ़ी' के शांति स्थापना अभियानों की मुख्य विशेषता क्या थी?
(A) भारी हथियारों से लैस सैनिकों की आक्रामक तैनाती करना।
(B) मुख्य रूप से युद्धविराम की निगरानी और बफर ज़ोन बनाना।
(C) संबंधित संघर्षरत पक्षों की सहमति के बिना सीधा हस्तक्षेप।
(D) लोकतांत्रिक चुनावों का आयोजन और मानवाधिकारों की निगरानी।

157. शीत युद्ध के बाद शांति स्थापना अभियानों के कार्यों में विस्तार क्यों हुआ?
(A) संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक बजट में होने वाली निरंतर वृद्धि के कारण।
(B) प्रमुख महाशक्तियों के बीच आपसी सहयोग में अचानक आई कमी के कारण।
(C) एक स्थायी और प्रभावी अंतरराष्ट्रीय सेना के विधिवत गठन के कारण।
(D) आंतरिक संघर्षों और गृहयुद्धों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण।

158. 'बहुआयामी' शांति स्थापना अभियानों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शामिल नहीं है?
(A) केवल आत्मरक्षा के लिए बल का प्रयोग करना।
(B) मानवाधिकारों की निरंतर निगरानी करना।
(C) निष्पक्ष चुनावों का सफल आयोजन करना।
(D) स्थानीय पुलिस बलों का पेशेवर प्रशिक्षण।

159. 'पीस-बिल्डिंग' (शांति-निर्माण) की अवधारणा का क्या अर्थ है?
(A) दो शत्रु देशों के बीच एक स्थायी और अभेद्य दीवार का निर्माण करना।
(B) केवल अल्पकालिक युद्धविराम समझौतों की शर्तों पर

विस्तृत बातचीत करना।
(C) संघर्ष के बाद समाजों का पुनर्निर्माण और स्थायी शांति हेतु संस्थानों की स्थापना।
(D) आक्रामक देश पर कड़े आर्थिक और राजनयिक प्रतिबंधों को लागू करना।

160. पारंपरिक और बहुआयामी शांति स्थापना के बीच एक प्रमुख अंतर क्या है?
(A) बहुआयामी अभियानों का दायरा व्यापक होता है और उनमें अक्सर शांति-निर्माण के तत्व शामिल होते हैं।
(B) पारंपरिक अभियानों को महासभा द्वारा अधिकृत किया जाता था, जबकि बहुआयामी अभियानों को सुरक्षा परिषद द्वारा।
(C) पारंपरिक अभियानों में नागरिक कर्मी शामिल नहीं थे।
(D) बहुआयामी अभियानों के लिए संघर्षरत पक्षों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। जबकि उनका घोषित लक्ष्य आर्थिक विकास में सहायता करना और सदस्य देशों को वित्तीय संकट से उबारना है, उनकी कार्यप्रणाली, विशेष रूप से विकासशील देशों के संदर्भ में, अक्सर विवाद का विषय रही है। इन संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले ऋण सामान्यतः कुछ शर्तों के साथ आते हैं, जिन्हें 'संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम' (Structural Adjustment Programmes - SAPs) के रूप में जाना जाता है। इन शर्तों में अक्सर सरकारी खर्च में कटौती (विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों में), व्यापार का उदारीकरण, सरकारी उद्यमों का निजीकरण और वित्तीय बाजारों का अविनियमन शामिल होता है। आलोचकों का तर्क है कि ये शर्तें प्राप्तकर्ता देशों की राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करती हैं, क्योंकि वे उन्हें अपनी आर्थिक नीतियों को स्वतंत्र रूप से निर्धारित करने से रोकती हैं। यह भी तर्क दिया जाता है कि इन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप अक्सर गरीबी और असमानता में वृद्धि होती है, क्योंकि सामाजिक कल्याण योजनाओं में कटौती से सबसे कमजोर वर्ग प्रभावित होता है। इस प्रकार, ये संस्थाएँ वैश्विक आर्थिक प्रशासन के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, लेकिन उनकी वैधता और प्रभावशीलता पर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं।
उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

161. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना किस समझौते के तहत हुई थी?
(A) पेरिस समझौता
(B) याल्टा सम्मेलन
(C) जेनेवा कन्वेंशन
(D) ब्रेटन वुड्स समझौता

162. 'संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम' (SAPs) क्या हैं?
(A) विकासशील देशों को दिए जाने वाले बिना शर्त के आर्थिक अनुदान।
(B) ऋण के लिए लगाई जाने वाली अनिवार्य आर्थिक नीतिगत शर्तें।
(C) विभिन्न देशों के बीच आयोजित सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम।
(D) संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाए जाने वाले वैश्विक साक्षरता कार्यक्रम।

163. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की आलोचना का एक मुख्य कारण क्या है?
(A) वे ऋण की सुविधा केवल विकसित औद्योगिक राष्ट्रों को प्रदान करती हैं।
(B) वे ऋण राशि पर अत्यंत उच्च और दंडात्मक ब्याज दरें वसूल करती हैं।
(C) उनकी ऋण शर्तें प्राप्तकर्ता राष्ट्रों की राष्ट्रीय संप्रभुता को कमजोर करती हैं।
(D) वे केवल रणनीतिक सैन्य और रक्षा परियोजनाओं हेतु वित्त प्रदान करती हैं।

164. संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों की शर्तों में सामान्यतः क्या शामिल नहीं होता है?
(A) व्यापार का व्यापक उदारीकरण।
(B) सरकारी उद्यमों का निजीकरण।
(C) वित्तीय बाजारों का अविनियमन।
(D) सामाजिक क्षेत्रों में सरकारी खर्च में वृद्धि।

165. आलोचकों के अनुसार, संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का सामाजिक प्रभाव क्या होता है?
(A) वे अक्सर गरीबी और असमानता में वृद्धि करते हैं।
(B) वे हमेशा गरीबी को कम करते हैं।
(C) वे समाज के सभी वर्गों को समान रूप से लाभ पहुँचाते हैं।
(D) उनका सामाजिक कल्याण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग दशकों से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक केंद्रीय विषय रही है। सुधार की यह मांग इस तथ्य पर आधारित है कि परिषद की वर्तमान संरचना 1945 की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को दर्शाती है, न कि आज की दुनिया को। सुधार पर बहस मुख्य रूप से दो प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित है: स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि, और वीटो के अधिकार का प्रश्न। इस बहस में कई देशों के समूह बन गए हैं। एक ओर 'जी-4' राष्ट्र (भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील) हैं, जो एक-दूसरे के स्थायी सदस्यता के दावों का समर्थन करते हैं और वीटो अधिकार के साथ स्थायी सीटों में विस्तार की वकालत करते हैं। दूसरी ओर, 'एकजुटता के लिए आम सहमति' (Uniting for Consensus - UfC) समूह है, जिसे 'कॉफी क्लब' भी कहा जाता है, जिसमें पाकिस्तान, इटली, अर्जेंटीना और दक्षिण कोरिया जैसे देश शामिल हैं। यह समूह स्थायी सीटों

की संख्या में किसी भी वृद्धि का विरोध करता है और केवल अस्थायी सीटों की संख्या बढ़ाने का पक्षधर है। उनका तर्क है कि नई स्थायी सीटों के निर्माण से असमानता और बढ़ेगी। सुधार की राह में सबसे बड़ी बाधा पांच स्थायी सदस्यों (पी-5) की अपनी स्थिति को लेकर है, जो अपने वीटो के विशेषाधिकार को कमजोर करने या साझा करने के लिए अनिच्छुक हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसी भी संशोधन के लिए पी-5 सहित दो-तिहाई सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है, जिससे यह प्रक्रिया अत्यंत कठिन हो जाती है।

उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

166. सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग का मुख्य आधार क्या है?
(A) सुरक्षा परिषद अपने आवंटित बजट से अधिक व्यय कर रही है।
(B) परिषद की संरचना आज की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं है।
(C) सुरक्षा परिषद की आधिकारिक बैठकें बहुत कम अंतराल पर होती हैं।
(D) इसके अस्थायी सदस्य राष्ट्र वर्तमान में अत्यधिक शक्तिशाली हो गए हैं।

167. निम्नलिखित में से कौन सा देश 'जी-4' समूह का सदस्य नहीं है?
(A) भारत
(B) इटली
(C) जर्मनी
(D) ब्राजील

168. 'एकजुटता के लिए आम सहमति' (UfC) समूह का सुरक्षा परिषद सुधार पर क्या रुख है?
(A) वे स्थायी सीटों में वृद्धि का विरोध करते हैं और केवल अस्थायी सीटें बढ़ाना चाहते हैं।
(B) वे परिषद की स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों की सीटों में वृद्धि चाहते हैं।
(C) वे भू-राजनीतिक संतुलन हेतु केवल स्थायी सीटों की संख्या में वृद्धि का पक्ष लेते हैं।
(D) वे परिषद के सभी स्थायी सदस्यों के वीटो अधिकार को समाप्त करने की मांग करते हैं।

169. सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा क्या है?
(A) महासभा में स्पष्ट बहुमत का पूर्णतः अभाव।
(B) सुधार प्रक्रिया की वित्तीय लागत का बहुत अधिक होना।
(C) चार्टर संशोधन की कठिन प्रक्रिया और पी-5 देशों की अनिच्छा।
(D) छोटे विकासशील देशों द्वारा किसी भी सुधार का विरोध करना।

170. 'कॉफी क्लब' किस समूह का दूसरा नाम है?
(A) जी-4 राष्ट्र
(B) पांच स्थायी सदस्य (पी-5)
(C) सात का समूह (जी-7)
(D) एकजुटता के लिए आम सहमति (UfC)

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

समकालीन वैश्विक प्रशासन में राज्य एकमात्र कर्ता नहीं हैं। गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), बहुराष्ट्रीय निगमों और अन्य गैर-राज्य कर्ताओं का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, जिससे एक 'वैश्विक नागरिक समाज' (ग्लोबल सिविल सोसाइटी) की अवधारणा को बल मिला है। ये संगठन पारंपरिक राज्य-केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के बाहर या उसके समानांतर काम करते हैं। मानवाधिकार संगठन जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच, राज्यों द्वारा किए जाने वाले उल्लंघनों की निगरानी और रिपोर्टिंग करके वैश्विक मानवाधिकार मानदंडों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण संगठन जैसे ग्रीनपीस और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) अंतर्राष्ट्रीय संधियों और नीतियों के लिए पैरवी करते हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसी मानवीय संस्थाएँ संघर्ष और आपदा क्षेत्रों में सीधे सहायता प्रदान करती हैं, जहाँ राज्य या तो असमर्थ होते हैं या अनिच्छुक। इन गैर-राज्य कर्ताओं का प्रभाव उनकी विशेषज्ञता, सूचना नेटवर्क और सार्वजनिक राय को लामबंद करने की क्षमता से उत्पन्न होता है। वे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेते हैं, सरकारों पर दबाव डालते हैं और वैश्विक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाते हैं। हालांकि उनके पास राज्यों की तरह संपरभु शक्ति नहीं होती, लेकिन वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एजेंडे को प्रभावित करने और वैश्विक मानदंडों के विकास में योगदान देने में एक अनिवार्य शक्ति बन गए हैं।

उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

171. 'वैश्विक नागरिक समाज' की अवधारणा में मुख्य रूप से कौन शामिल हैं?
(A) केवल संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश।
(B) केवल बहुराष्ट्रीय निगम।
(C) गैर-सरकारी संगठन और अन्य गैर-राज्य कर्ता।
(D) विश्व की सभी राष्ट्रीय सरकारें।

172. स्रोत के अनुसार, मानवाधिकार एनजीओ वैश्विक मानदंडों को कैसे आकार देते हैं?
(A) सैन्य हस्तक्षेप करके।
(B) राज्यों द्वारा किए गए उल्लंघनों की निगरानी और रिपोर्टिंग करके।
(C) अन्य संपरभु राष्ट्रों पर कड़े आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध लगाकर।
(D) राजनीतिक चुनाव लड़कर विभिन्न देशों में अपनी सरकारें बनाकर।

173. निम्नलिखित में से कौन एक मानवीय सहायता प्रदान करने वाला गैर-सरकारी संगठन है?

(A) ग्रीनपीस
(B) एमनेस्टी इंटरनेशनल
(C) वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ)
(D) डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स

174. गैर-राज्य कर्ताओं का प्रभाव मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है?
(A) उनकी विशेषज्ञता, सूचना नेटवर्क और जनमत को लामबंद करने की क्षमता पर।
(B) उनकी सैन्य शक्ति और संप्रभुता पर।
(C) कर लगाने और आधिकारिक कानून बनाने के उनके संप्रभु अधिकार पर।
(D) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उनके प्रत्यक्ष स्थायी प्रतिनिधित्व पर।

175. वैश्विक प्रशासन में गैर-राज्य कर्ताओं की भूमिका के संबंध में क्या सत्य है?
(A) वे राज्य-केंद्रित व्यवस्था को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर चुके हैं।
(B) उनका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एजेंडे पर कोई प्रभाव नहीं है।
(C) वे वैश्विक जागरूकता बढ़ाकर और सरकारों पर दबाव डालकर प्रभाव डालते हैं।
(D) वे केवल अपने विशिष्ट स्थानीय समुदायों के भौगोलिक दायरे में काम करते हैं।

ANSWERS

1. (B) विश्व शांति का
संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रतीक चिह्न में जैतून की शाखाएं पूरी दुनिया में शांति और मित्रता का संदेश देने के लिए शामिल की गई हैं। यह विश्व मानचित्र के चारों ओर स्थित हैं जो वैश्विक भाईचारे और सुरक्षा की आवश्यकता को दर्शाती हैं। संगठन का मुख्य लक्ष्य भी यही है कि सदस्य देश आपसी विवादों को युद्ध के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा सकें।

2. (A) मानवता को नरक से बचाने के लिए
संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना का मूल लक्ष्य मानवता को भयानक युद्धों और सामूहिक विनाश की परिस्थितियों से बचाना था। इसके चार्टर के अनुसार यह संगठन देशों के बीच शांतिपूर्ण संबंध विकसित करने का कार्य करता है। संगठन का अस्तित्व यह सुनिश्चित करता है कि अंतरराष्ट्रीय विवादों का समाधान केवल कूटनीति से हो ताकि दुनिया को विनाशकारी हिंसा से सुरक्षित रखा जा सके।

3. (C) यह वैश्विक वित्त-व्यवस्था की देखरेख और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक प्रमुख वैश्विक संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौद्रिक प्रणाली और वित्तीय स्थिरता की देखरेख करता है। यह उन सदस्य देशों को ऋण और तकनीकी सहायता प्रदान करता है जो भुगतान संतुलन के संकट या आर्थिक मंदी का सामना कर रहे होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखना और सदस्य राष्ट्रों के आर्थिक विकास में सहयोग करना है।

4. (D) वे युद्ध और शांति के मामलों में मदद करते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय संगठन विभिन्न देशों के बीच विवादों को सुलझाने और युद्ध को टालने के लिए एक औपचारिक मंच प्रदान करते हैं। ये संगठन शांति स्थापना, सुरक्षा और आर्थिक विकास जैसे साझा हितों पर सहयोग को बढ़ावा देते हैं। इनकी मौजूदगी से देशों के बीच संवाद बना रहता है, जिससे वैश्विक समस्याओं जैसे महामारी और पर्यावरण परिवर्तन का समाधान मिलकर निकालना बहुत आसान हो जाता है।

5. (A) 1, 2, 3, 4, 5
संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना की दिशा में अगस्त 1941 में सबसे पहले अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे। इसके पश्चात जनवरी 1942 में घोषणापत्र जारी हुआ और 1945 में याल्टा सम्मेलन तथा सैन फ्रांसिस्को में चार्टर पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया संपन्न हुई। अंततः 24 अक्टूबर 1945 को इस संगठन की औपचारिक स्थापना हुई, जो वैश्विक इतिहास में शांति व्यवस्था की दिशा में एक बड़ा कदम था।

6. (B) संयुक्त राष्ट्रसंघ
प्रथम विश्वयुद्ध के बाद स्थापित 'लीग ऑफ नेशंस' दूसरे विश्वयुद्ध को रोकने में असफल रहा था, जिसके कारण उसकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई थी। इसी असफलता के बाद भविष्य में युद्धों को टालने के लिए 1945 में संयुक्त राष्ट्रसंघ को एक सशक्त उत्तराधिकारी के रूप में गठित किया गया। यह नया संगठन अधिक समावेशी था और इसे वैश्विक स्तर पर शांति बनाए रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई।

7. (C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
अंतर्राष्ट्रीय संगठन वास्तव में युद्ध और शांति के जटिल मामलों को सुलझाने में सहायता करते हैं क्योंकि वे देशों के बीच संचार की कड़ियाँ जोड़ते हैं। हालाँकि यह कहना गलत है कि देश हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहते हैं और संवाद नहीं करते। अधिकांश राष्ट्र बातचीत के माध्यम से ही अपने हितों की रक्षा करना चाहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच उन्हें ऐसा करने का सुलभ अवसर प्रदान करते हैं।

8. (A) 51
संयुक्त राष्ट्रसंघ के संस्थापक चार्टर पर जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के दौरान कुल 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। पोलैंड इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं था लेकिन उसने 15 अक्टूबर 1945 को इस चार्टर पर हस्ताक्षर करके अपनी सदस्यता सुनिश्चित की। इस प्रकार कुल 51 देशों को संयुक्त राष्ट्र के मूल संस्थापक सदस्यों के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिन्होंने इसकी नींव रखी थी।

9. (C) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
संयुक्त राष्ट्र के संगठनात्मक ढांचे में छह प्रमुख अंग शामिल हैं, जिनमें सुरक्षा परिषद्, महासभा, आर्थिक और सामाजिक परिषद्, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यासिता परिषद् मुख्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रुप में कार्य करता है, परंतु यह मुख्य अंगों की श्रेणी में नहीं आता। मुख्य अंग संगठन की नीति निर्धारण और प्रशासनिक संचालन के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी होते हैं।

10. (A) रूस-अमरीका संबंध अधिक तनावपूर्ण हुए।
शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद रूस और अमरीका के बीच संबंधों में सुधार हुआ और पुराने वैचारिक मतभेद काफी हद तक समाप्त हो गए। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अमरीका विश्व की एकमात्र महाशक्ति बना, जबकि चीन ने एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इस कालखंड में वैश्विक राजनीति का ढांचा पूरी तरह बदल गया और नए प्रकार के अंतरराष्ट्रीय संबंध विकसित हुए।

11. (A) P-4, Q-2, R-1, S-3
संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों के विशिष्ट कार्य और संरचनाएँ निर्धारित हैं। सुरक्षा परिषद् में पाँच स्थायी सदस्य होते हैं जिन्हें वीटो शक्ति प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पंद्रह न्यायाधीश नौ वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। महासभा में सभी सदस्यों को समान मताधिकार मिलता है और सचिवालय का नेतृत्व महासचिव करता है। यह विभाजन संगठन के सुचारू संचालन और न्यायसंगत निर्णय लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।

12. (B) 5 स्थायी और 10 अस्थायी
सुरक्षा परिषद् की कुल सदस्य संख्या पंद्रह है, जिसमें पाँच स्थायी और दस अस्थायी सदस्य होते हैं। पाँच स्थायी सदस्यों के पास वीटो का विशेष अधिकार होता है, जो किसी भी प्रस्ताव को रोकने की शक्ति रखता है। दस अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा केवल दो वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। यह संरचना विश्व में शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने का प्रमुख तंत्र है।

13. (C) एक नकारात्मक शक्ति जिससे वे किसी भी फैसले को रोक सकते हैं।
वीटो की शक्ति सुरक्षा परिषद् के पाँच स्थायी सदस्यों को दी गई एक विशेष नकारात्मक शक्ति है। इसका अर्थ है कि यदि कोई स्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव के विरुद्ध अपना मत देता है, तो वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। भले ही अन्य सभी सदस्य उसके पक्ष में हों, एक वीटो पूरे निर्णय को प्रभावी रूप से रोक सकता है। यह शक्ति अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इन देशों के दबदबे को बनाए रखती है।

14. (D) 1, 2, 3 और 4
संयुक्त राष्ट्र की महासभा में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को एक वोट का अधिकार प्राप्त है जो समानता दर्शाता है। सुरक्षा परिषद् के पाँच स्थायी सदस्य दूसरे विश्वयुद्ध के विजेता देश हैं और उन्हें विशेष विशेषाधिकार दिए गए हैं। महासचिव संगठन का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी और इसका सबसे प्रमुख सार्वजनिक चेहरा होता है। ये सभी बिंदु संगठन की मूलभूत कार्यप्रणाली और शक्ति के संतुलन को सही ढंग से परिभाषित करते हैं।

15. (A) पुर्तगाल
एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के नौवें महासचिव हैं और वे पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने महासचिव का पद संभालने से पहले संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग के रूप में भी महत्वपूर्ण कार्य किया था। एक अनुभवी राजनेता के रूप में, वे वैश्विक शांति, मानवाधिकारों की सुरक्षा और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठन का नेतृत्व और प्रतिनिधित्व करते हैं।

16. (B) विश्व राजनीति की समकालीन सच्चाइयाँ बदल गई थीं।
शीतयुद्ध के अंत के बाद वैश्विक परिदृश्य पूरी तरह बदल गया और पुरानी व्यवस्था अब वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए अपर्याप्त महसूस होने लगी। सोवियत संघ के पतन और नए राष्ट्रों के उदय के कारण संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई। इसके सदस्य चाहते थे कि संगठन समकालीन वास्तविकताओं और बदलती हुई आर्थिक तथा सैन्य शक्तियों के प्रभाव को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करे।

17. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
वर्तमान समय में सुरक्षा परिषद् की संरचना में बदलाव की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि यह 1945 की विश्व व्यवस्था पर आधारित है। अब विश्व राजनीति में नए शक्ति केंद्र उभरे हैं जो इसे अधिक लोकतांत्रिक और प्रतिनिधिमूलक बनाना चाहते हैं। भारत जैसे देश मानते हैं कि सदस्यों की संख्या बढ़ाकर ही इस संस्था की वैधता और प्रभावशीलता को भविष्य की वैश्विक चुनौतियों के लिए बढ़ाया जा सकता है।

18. (A) उपरोक्त सभी।
महासभा द्वारा पारित प्रस्तावों में सुरक्षा परिषद् की कार्यप्रणाली के प्रति असंतोष व्यक्त किया गया था। शिकायतों में प्रमुख रूप से यह उल्लेख था कि परिषद् वर्तमान राजनीतिक स्थितियों का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती और इसके निर्णयों पर पश्चिमी देशों का अत्यधिक प्रभाव है। सदस्य देशों का मानना है कि इसमें भौगोलिक असंतुलन है और विकासशील देशों की आवाज़ को पर्याप्त रूप से महत्व नहीं दिया जाता है।

19. (C) एक राजतंत्रीय शासन व्यवस्था होना।
सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता के लिए प्रस्तावित मानदंडों में आर्थिक और सैन्य शक्ति, जनसंख्या तथा मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता जैसे कारक शामिल हैं। हालाँकि, राजतंत्रीय शासन व्यवस्था होना इसमें कोई मानदंड नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। इन सुझावों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नया सदस्य वैश्विक स्तर पर उत्तरदायित्व निभाने और संगठन को मजबूत करने में सक्षम हो।

20. (D) संयुक्त राज्य अमेरिका
संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के नियमित और शांति मिशन बजट में सबसे अधिक आर्थिक योगदान देने वाला देश है। इसकी विशाल अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव के कारण यह संगठन के वित्तीय संसाधनों का मुख्य स्रोत बना हुआ है। भारी बजटीय योगदान के कारण ही संयुक्त राष्ट्र के निर्णयों और प्रशासनिक नीतियों में अमेरिका का प्रभाव अन्य सदस्य राष्ट्रों की तुलना में काफी अधिक और प्रभावी देखा जाता है।

21. (A) केवल 1 और 3
विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी और यह मुख्य रूप से विकासशील देशों के आर्थिक सुधार के लिए कार्य करता है। यह संगठन स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए आसान ऋण और अनुदान प्रदान करता है। इसका उद्देश्य गरीब राष्ट्रों में गरीबी को कम करना और उनके बुनियादी ढांचे के विकास में सहायता करना है, जिससे वे वैश्विक अर्थव्यवस्था में सक्रिय भागीदार बन सकें।

22. (B) दो वर्ष
सुरक्षा परिषद् के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा द्वारा दो वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए किया जाता है। इन सदस्यों का चयन भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है ताकि विश्व के सभी क्षेत्रों की आवाज़ परिषद् में सुनी जा सके। कोई भी देश अपना कार्यकाल पूरा करने के तुरंत बाद दोबारा नहीं चुना जा सकता। यह प्रक्रिया परिषद् के भीतर विविधता और नई भागीदारी को निरंतर सुनिश्चित करती है।

23. (D) महासचिव भी इसका प्रयोग कर सकता है।
वीटो शक्ति केवल सुरक्षा परिषद् के पाँच स्थायी सदस्यों को दी गई है और महासचिव के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता। महासचिव संगठन का प्रशासनिक प्रधान होता है, जबकि वीटो एक राजनीतिक शक्ति है जिसका उपयोग केवल अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन ही कर सकते हैं। यह नकारात्मक शक्ति किसी भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को पारित होने से रोकने की क्षमता रखती है, जिससे निर्णय प्रक्रिया प्रभावित होती है।

24. (A) उपरोक्त सभी
वर्ष 2005 में संगठन की 60वीं वर्षगांठ पर सदस्य देशों ने व्यापक सुधारों का निर्णय लिया था। इसके तहत शांति संस्थापक आयोग का गठन और मानवाधिकार परिषद् की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। साथ ही, सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की प्राप्ति और सामूहिक सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई गई। इन सुधारों का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र को नई सदी की चुनौतियों के प्रति अधिक संवेदनशील और प्रभावी संस्था बनाना था।

25. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
संयुक्त राष्ट्र के महासचिवों का संबंध विभिन्न देशों से रहा है, जो संगठन की वैश्विक प्रकृति को दर्शाता है। ट्राइग्व ली नॉर्वे से थे, जबकि डेग हैमरशोल्ड स्वीडन के नागरिक थे। यू थांट का संबंध म्यांमार से था और कोफी अन्नान घाना के निवासी थे। इस विविधतापूर्ण नेतृत्व ने अलग-अलग कालखंडों में अंतरराष्ट्रीय शांति और विकास के मुद्दों पर संगठन का कुशलतापूर्वक संचालन और मार्गदर्शन करने का प्रयास किया है।

26. (A) विकास संबंधी महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करना
सतत विकास लक्ष्य 2030 तक गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सुधार और पर्यावरण संरक्षण जैसे व्यापक उद्देश्यों को प्राप्त करने की एक वैश्विक योजना है। ये लक्ष्य सभी देशों के लिए एक समान दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं ताकि विकास की प्रक्रिया न्यायसंगत और सुरक्षित बनी रहे। इसका मुख्य उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना और एक बेहतर दुनिया का निर्माण करना है।

27. (D) विकास
भारत का हमेशा से यह तर्क रहा है कि संयुक्त राष्ट्र को अंतरराष्ट्रीय शांति के साथ-साथ विकास के मुद्दों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विकासशील देशों के लिए गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी समस्याएँ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनका समाधान किए बिना वैश्विक स्थिरता संभव नहीं है। भारत के अनुसार, यदि विकास का एजेंडा प्राथमिकता पर रहता है, तो इससे दुनिया के पिछड़े क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा की स्थिति स्वतः ही बेहतर हो जाएगी।

28. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
भारत सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता के लिए एक सशक्त दावेदार है क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और एक उभरती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में हमेशा सक्रिय भूमिका निभाई है और इसके सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है। इन सभी योग्यताओं के कारण भारत को लगता है कि उसे परिषद् के भीतर निर्णय लेने वाली उच्च स्तरीय भूमिका मिलनी चाहिए।

29. (C) 15
संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय सुरक्षा परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या ग्यारह थी, जिसे बाद में बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप बढ़ाने का निर्णय लिया गया। 1965 में एक संशोधन के माध्यम से इसकी सदस्य संख्या को बढ़ाकर पंद्रह कर दिया गया। इसमें पाँच स्थायी सदस्यों के अलावा अस्थायी सदस्यों की संख्या छह से बढ़ाकर दस कर दी गई ताकि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों को अधिक प्रतिनिधित्व मिल सके।

30. (D) संयुक्त राज्य अमेरिका
संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई अवसरों पर भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन किया है, हालांकि यह प्रक्रिया जटिल और कई शर्तों के अधीन है। पाकिस्तान जैसे कुछ देश क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा के कारण भारत की दावेदारी का खुला विरोध करते हैं। वहीं ब्राजील और जर्मनी जैसे अन्य देश स्वयं भी इस दावेदारी में शामिल हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आम सहमति बनाना वर्तमान में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

31. (A) इसकी कार्यविधि पूरी तरह पारदर्शी है।
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में गेट के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी ताकि वैश्विक व्यापार को सुव्यवस्थित किया जा सके। इसके निर्णयों में बड़ी आर्थिक शक्तियों जैसे अमेरिका और यूरोपीय संघ का दबदबा रहता है, जिसके कारण विकासशील देश अक्सर इसकी पारदर्शिता पर सवाल उठाते हैं। इस संगठन का मुख्य कार्य व्यापार नियमों का निर्धारण करना है, लेकिन इसकी प्रक्रियाएँ अक्सर विवादों और असंतुलन से घिरी रहती हैं।

32. (B) अमरीकी प्रभुत्व
शीतयुद्ध के बाद दुनिया एक-ध्रुवीय हो गई है, जहाँ अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में कार्य कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका के इस असीमित प्रभाव और दबदबे को संतुलित करना है। अमेरिका अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति के बल पर अक्सर अंतरराष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी कर देता है। ऐसे में संगठन की प्रभावशीलता इस

बात पर निर्भर करती है कि वह महाशक्ति के विरुद्ध कितनी स्वायत्तता रख पाता है।

33. (B) उपरोक्त सभी।
संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का विशेष प्रभाव कई भौतिक और वित्तीय कारकों का परिणाम है। संगठन का मुख्यालय अमेरिकी धरती पर स्थित है और वहाँ काम करने वाले कई कर्मचारी और नौकरशाह अमेरिकी नागरिक हैं। इसके अलावा, अमेरिका का वित्तीय योगदान सबसे अधिक है और उसके पास वीटो की अजेय शक्ति भी है। ये सभी स्थितियाँ मिलकर अमेरिका को संगठन के भीतर एक अत्यंत प्रभावशाली और निर्णायक भूमिका प्रदान करती हैं।

34. (A) अमरीका
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की चयन प्रक्रिया में सुरक्षा परिषद् के पाँच स्थायी सदस्यों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। अमेरिका अपनी वैश्विक शक्ति और आर्थिक दबदबे के कारण इस चयन में बहुत अधिक वज़न रखता है। किसी भी उम्मीदवार के लिए अमेरिका की सहमति अनिवार्य मानी जाती है क्योंकि वह अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करके किसी भी नाम को रोक सकता है। इसी प्रभाव के कारण महासचिव का चयन अक्सर महाशक्तियों की पसंद पर आधारित होता है।

35. (A) 4, 2, 1, 3
संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सबसे पहले यू थांट 1961 में महासचिव बने, उसके बाद 1992 में 'एन अजेंडा फॉर पीस' रिपोर्ट आई। मानवाधिकार परिषद् की स्थापना 2006 के सुधारों के दौरान हुई और अंत में एंटोनियो गुटेरेस ने 2017 में महासचिव का पद संभाला। यह कालक्रम दर्शाता है कि संगठन ने समय के साथ कैसे अपनी प्राथमिकताओं को बदला और नए संस्थानों एवं नेतृत्व के माध्यम से खुद को अद्यतन किया है।

36. (D) मानवाधिकारों की रक्षा
एमनेस्टी इंटरनेशनल एक प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है जो पूरी दुनिया में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है। यह संगठन जेलों में बंद कैदियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और सरकारों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाता है। इसकी रिपोर्टें वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की स्थिति को उजागर करने में बहुत विश्वसनीय मानी जाती हैं, जिससे सरकारों पर नैतिक दबाव बनाकर न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है।

37. (C) यह अमरीका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है।
ह्यूमन राइट्स वॉच अमेरिका में स्थित एक प्रभावशाली गैर-सरकारी संगठन है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के हनन की निगरानी करता है। यह संगठन दुनिया भर की मीडिया का ध्यान मानवाधिकारों के मुद्दों की ओर खींचने में सफल रहता है। इसने बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने, बाल सैनिकों के उपयोग को समाप्त करने और अंतरराष्ट्रीय दंड न्यायालय की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण अभियानों में सराहनीय योगदान दिया है, जिससे वैश्विक न्याय प्रणाली मजबूत हुई है।

38. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
एक-ध्रुवीय विश्व में अमेरिका की शक्ति इतनी अधिक है कि वह संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों की परवाह किए बिना अपनी नीतियाँ लागू कर सकता है। उसके पास वीटो की शक्ति है और वह संगठन के बजट का मुख्य हिस्सा प्रदान करता है, जिससे उसकी उपेक्षा करना कठिन होता है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र अक्सर अमेरिकी सैन्य और आर्थिक शक्ति पर प्रभावी अंकुश लगाने में खुद को असहाय और काफी हद तक सीमित महसूस करता है।

39. (D) परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना।
अंतर्राष्ट्रीय आण्विक ऊर्जा एजेंसी का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग केवल शांतिपूर्ण और सुरक्षित कार्यों के लिए हो। यह संगठन यह निगरानी करता है कि परमाणु तकनीक का उपयोग हथियारों के निर्माण जैसे सैन्य उद्देश्यों के लिए न किया जाए। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी और यह नियमित रूप से दुनिया भर की परमाणु सुविधाओं की जाँच करके सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करता है।

40. (A) विभिन्न समाजों और मसलों के बीच आपसी जुड़ाव।
पारस्परिक निर्भरता का अर्थ है कि आज के वैश्वीकृत युग में देश और समाज एक-दूसरे से इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि कोई भी अकेले नहीं रह सकता। आर्थिक, सुरक्षा और पर्यावरणीय मसले अब किसी एक राष्ट्र की सीमा तक सीमित नहीं हैं। इस अवधारणा के तहत देशों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आपसी सहयोग और सामूहिक प्रयास करने पड़ते हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त होता है।

41. (A) केवल 1, 2, 3
अंतर्राष्ट्रीय आण्विक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित और नागरिक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। इसके विशेषज्ञ दल सदस्य देशों की परमाणु इकाइयों की नियमित जाँच करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि परमाणु सामग्री का कोई दुरुपयोग सैन्य कार्यों में न हो। यह संगठन वैश्विक परमाणु सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है और सुरक्षा परिषद् को अपनी गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है।

42. (A) पश्चिमी देशों के हितों को प्राथमिकता देना।
सुरक्षा परिषद् के निर्णयों पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि वे पश्चिमी देशों की विचारधारा और उनके आर्थिक हितों के पक्ष में होते हैं। चूँकि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश इसके स्थायी सदस्य हैं, इसलिए उनकी नीतियों का प्रभाव वैश्विक निर्णयों पर स्पष्ट रूप से झलकता है। इसका परिणाम यह होता है कि विकासशील और कम विकसित देशों की आवश्यकताओं और दृष्टिकोणों को कई बार पर्याप्त महत्व या स्थान नहीं मिल पाता है।

43. (D) संगठन की बनावट और प्रक्रियाओं में सुधार।
संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की मांग मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में केंद्रित है: पहला, इसकी बनावट जैसे सुरक्षा परिषद् का विस्तार और दूसरा, इसकी कार्यप्रणाली एवं प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाना। सदस्य देश चाहते हैं कि संगठन की निर्णय लेने वाली इकाइयों में अधिक प्रतिनिधित्व हो ताकि वे समकालीन विश्व व्यवस्था को सही ढंग से दर्शा सकें। इन सुधारों का उद्देश्य संगठन की प्रभावशीलता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी वैधता को और अधिक मजबूत करना है।

44. (B) P-4, Q-3, R-2, S-1
संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियाँ अपने विशिष्ट क्षेत्रों में मानवीय कल्याण के लिए काम करती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक स्वास्थ्य मानकों की देखरेख करता है, जबकि यूएनडीपी विकास कार्यक्रमों का संचालन करता है। शरणार्थियों की सुरक्षा और पुनर्वास का कार्य यूएनएचसीआर द्वारा किया जाता है और यूनिसेफ बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देता है। यह विशिष्ट कार्य विभाजन संगठन को अपनी वैश्विक जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने में सक्षम बनाता है।

45. (C) आम सभा
आम सभा संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र ऐसा अंग है जिसमें सभी 193 सदस्य देशों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसे अक्सर विश्व की 'बतकही की चौपाल' भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर अंतरराष्ट्रीय मसले पर खुली चर्चा होती है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को एक वोट देने का अधिकार होता है, जिससे छोटे और बड़े देशों के बीच समानता बनी रहती है। यह संगठन के सबसे महत्वपूर्ण विमर्शकारी और नीति-निर्माता मंच के रूप में कार्य करता है।

46. (D) दो-तिहाई बहुमत
आम सभा में शांति और सुरक्षा, नए सदस्यों के प्रवेश तथा बजटीय मामलों जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। सामान्य विषयों पर निर्णय साधारण बहुमत के माध्यम से लिए जाते हैं। दो-तिहाई बहुमत का प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि बड़े और विवादास्पद फैसलों के लिए सदस्य देशों के बीच एक व्यापक और मजबूत सहमति हो, जिससे उन फैसलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक स्वीकार्यता प्राप्त हो सके।

47. (A) हेग
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है, जिसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र ऐसा मुख्य अंग है जो न्यूयॉर्क से बाहर स्थित है। इसका कार्य सदस्य देशों के बीच उत्पन्न होने वाले कानूनी विवादों को सुलझाना और संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न शाखाओं को कानूनी सलाह देना है। यह वैश्विक स्तर पर न्याय और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन को सुनिश्चित करने वाली सर्वोच्च संस्था है।

48. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
भारत का मानना है कि सुरक्षा परिषद् की वर्तमान संरचना पुराने समय की है और यह आज की बदलती हुई विश्व व्यवस्था का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती। परिषद् के विस्तार से विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे इसके निर्णयों को अधिक लोकतांत्रिक समर्थन मिलेगा। भारत के अनुसार, एक अधिक समावेशी और प्रतिनिधिमूलक सुरक्षा परिषद् ही वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को अधिक कुशलता से निभाने में सक्षम हो सकती है।

49. (B) जेनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ (GATT)
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को 'जेनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ' के उत्तराधिकारी के रूप में हुई थी। गेट का गठन दूसरे विश्वयुद्ध के बाद व्यापारिक बाधाओं को दूर करने के लिए किया गया था। नए संगठन के रूप में विश्व व्यापार संगठन का कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक है, जिसमें सेवाओं और बौद्धिक संपदा जैसे आधुनिक व्यापारिक मुद्दे भी शामिल हैं। यह वैश्विक व्यापार को सुचारु और न्यायसंगत बनाने के लिए नियमों का निर्धारण करता है।

50. (A) सोवियत संघ/रूस
सुरक्षा परिषद् के इतिहास में सोवियत संघ और बाद में रूस ने वीटो की शक्ति का उपयोग सबसे अधिक बार किया है। शीतयुद्ध के दौरान, उसने पश्चिमी देशों द्वारा लाए गए कई प्रस्तावों को रोकने के लिए अपनी इस विशेष शक्ति का बार-बार इस्तेमाल किया। रूस द्वारा वीटो का व्यापक प्रयोग अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उसके रणनीतिक हितों की रक्षा करने और सुरक्षा परिषद् के भीतर अपनी प्रभावी स्थिति और संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता रहा है।

51. (D) 1, 2, 3 और 4
सुरक्षा परिषद् की कार्यप्रणाली में अस्थायी सदस्यों का चुनाव दो वर्ष के लिए होता है और वे तत्काल दोबारा नहीं चुने जा सकते। उनके पास वीटो की कोई शक्ति नहीं होती, जो केवल स्थायी सदस्यों का विशेषाधिकार है। अस्थायी सदस्यों के चयन में भौगोलिक संतुलन का ध्यान रखा जाता है ताकि पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व हो सके। वहीं, किसी भी प्रस्ताव को रोकने के लिए एक ही स्थायी सदस्य का वीटो पर्याप्त और अत्यंत शक्तिशाली होता है।

52. (D) दक्षिण कोरिया
बान की मून संयुक्त राष्ट्र के आठवें महासचिव थे और उनका संबंध दक्षिण कोरिया से है। उन्होंने 2007 से 2016 तक दो कार्यकालों के लिए इस पद पर सेवा दी। उनके कार्यकाल के दौरान जलवायु परिवर्तन, वैश्विक सुरक्षा और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया। एक अनुभवी राजनयिक के रूप में, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संघर्षों को कम करने और संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय भूमिका निभाई।

53. (D) ट्राइग्व ली
नॉर्वे के ट्राइग्व ली संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे, जिन्होंने 1946 से 1952 तक इस पद पर कार्य किया। उनके कार्यकाल के दौरान शीतयुद्ध की शुरुआत हुई और कश्मीर एवं कोरिया जैसे गंभीर अंतरराष्ट्रीय संकट उभरे। उन्होंने एक नए संगठन की नींव रखने और उसकी प्रशासनिक संरचना को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महासचिव के रूप में उन्होंने वैश्विक स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए प्रारंभिक कूटनीतिक प्रयास किए थे।

54. (B) रूजवेल्ट और चर्चिल
अगस्त 1941 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। यह ऐतिहासिक दस्तावेज भविष्य में एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के गठन की नींव बना। इसमें युद्ध के बाद की दुनिया के लिए सिद्धांतों और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की रूपरेखा तय की गई थी। इसी चार्टर से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसका उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना था।

55. (A) 4, 3, 2, 1
संयुक्त राष्ट्र के महासचिवों का कार्यकाल एक निश्चित क्रम में रहा है। जेवियर पेरेज द कूइयार ने 1980 के दशक में सेवा दी, उनके बाद बुतरस बुतरस घाली और फिर कोफी अन्नान महासचिव बने। बान की मून ने 2007 में पद संभाला। यह कालक्रम दर्शाता है कि संगठन ने विभिन्न वैश्विक चुनौतियों और राजनीतिक परिवर्तनों के बीच किस प्रकार अपने नेतृत्व को बदलते हुए शांति और विकास की दिशा में अपना निरंतर सफर जारी रखा है।

56. (A) बुतरस बुतरस घाली
बुतरस बुतरस घाली ने 1992 में 'एन अजेंडा फॉर पीस' नामक एक ऐतिहासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में शीतयुद्ध के बाद की दुनिया में संयुक्त राष्ट्र की बदलती भूमिका और शांति स्थापना के नए तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य संगठन को अधिक सक्रिय बनाना और संघर्षों को रोकने के लिए निवारक कूटनीति तथा शांति-निर्माण की प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी और सुदृढ़ ढंग से स्थापित करना था।

57. (C) आम सभा
आर्थिक और सामाजिक परिषद् के सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा किया जाता है। इसके कुल 54 सदस्य होते हैं जिन्हें तीन वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। महासभा यह सुनिश्चित करती है कि परिषद् में विभिन्न क्षेत्रों का संतुलित और न्यायसंगत प्रतिनिधित्व बना रहे। यह परिषद् संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कार्यों के समन्वय के लिए उत्तरदायी है और महासभा के मार्गदर्शन में अपनी महत्वपूर्ण गतिविधियों का सुचारु संचालन करती है।

58. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
वीटो की शक्ति को समाप्त करने की मांग वैश्विक स्तर पर अक्सर उठती रहती है क्योंकि इसे अलोकतांत्रिक और असमानता का प्रतीक माना जाता है। आलोचकों का तर्क है कि यह शक्ति केवल कुछ देशों को विशेष अधिकार प्रदान करती है, जो संप्रभु राष्ट्रों की समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। इसी कारण कई छोटे और विकासशील देश मानते हैं कि वीटो के हटने से संयुक्त राष्ट्र अधिक प्रतिनिधिमूलक और न्यायपूर्ण संस्था के रूप में उभर सकता है।

59. (D) 1994
न्यासिता परिषद् को 1 नवंबर 1994 से औपचारिक रूप से स्थगित कर दिया गया है। इसका मुख्य कार्य उन क्षेत्रों की देखरेख करना था जो अभी तक स्वतंत्र नहीं हुए थे। जब पलाउ, जो अंतिम ट्रस्ट क्षेत्र था, स्वतंत्र हो गया, तो इस परिषद् का मुख्य उद्देश्य पूर्ण हो गया। हालांकि यह अभी भी संयुक्त राष्ट्र का एक मुख्य अंग बना हुआ है, लेकिन अब यह सक्रिय रूप से कार्य नहीं करता और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही बैठक करता है।

60. (B) कोफी अन्नान
वर्ष 2001 में संयुक्त राष्ट्र और इसके महासचिव कोफी अन्नान को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। उन्हें यह सम्मान विश्व शांति की स्थापना और मानवाधिकारों के संरक्षण में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट प्रयासों के लिए मिला। अन्नान ने संगठन में कई महत्वपूर्ण सुधार किए और वैश्विक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के मुद्दों पर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। उनके नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र ने नई सदी की चुनौतियों का डटकर सामना किया।

61. (B) P-3, Q-1, R-4, S-2
विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठन अपने विशिष्ट क्षेत्रों में वैश्विक व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए कार्यरत हैं। आईएमएफ वित्तीय स्थिरता देखता है, जबकि विश्व व्यापार संगठन व्यापारिक नियमों का निर्धारण करता है। इसी तरह आईएईए परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की निगरानी करता है और ह्यूमन राइट्स वॉच मानवाधिकारों के उल्लंघन पर नजर रखता है। यह विविधतापूर्ण व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए एक समर्पित संस्था मौजूद रहे।

62. (D) रूस
1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को उसके उत्तराधिकारी राज्य के रूप में मान्यता दी गई। इसके परिणामस्वरूप, सोवियत संघ को प्राप्त सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता और वीटो की शक्ति रूस को हस्तांतरित कर दी गई। रूस ने सोवियत संघ द्वारा की गई सभी अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों का दायित्व भी अपने ऊपर लिया। इस बदलाव के बावजूद, रूस विश्व राजनीति में एक प्रमुख और निर्णायक शक्ति के रूप में अपनी उपस्थिति बनाए रखने में सफल रहा।

63. (A) चीन
समूह-7 या जी-7 विश्व की सात सबसे बड़ी उन्नत और औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा शामिल हैं। हालांकि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसे इस समूह में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि जी-7 के सदस्य मुख्य रूप से विकसित और लोकतांत्रिक देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। चीन को अभी भी कई मानकों पर एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में ही देखा जाता है।

64. (B) केवल 1, 2, 3, 4
शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद विश्व राजनीति में कई सकारात्मक और चुनौतीपूर्ण बदलाव आए। रूस और अमेरिका के बीच सहयोग बढ़ा और एशियाई अर्थव्यवस्थाओं ने अभूतपूर्व प्रगति की। कई नए स्वतंत्र राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने, लेकिन साथ ही आतंकवाद और गृहयुद्ध जैसी नई वैश्विक समस्याएँ भी पैदा हुईं। इन परिवर्तनों के कारण अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि वे इन जटिल चुनौतियों का समाधान करने में सहयोग प्रदान करते हैं।

65. (B) 30 अक्टूबर 1945
भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है और वह 30 अक्टूबर 1945 को औपचारिक रूप से इसमें शामिल हुआ था। आजादी से पहले ही भारत ने अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया था। संस्थापक सदस्य के रूप में, भारत ने संगठन के चार्टर और उसके उद्देश्यों के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा व्यक्त की। तब से लेकर आज तक भारत संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न गतिविधियों और शांति अभियानों में निरंतर एक सक्रिय और महत्वपूर्ण भागीदार रहा है।

66. (A) आम सभा
महासभा को अक्सर 'बतकही की चौपाल' या विश्व की संसद कहा जाता है क्योंकि यहाँ दुनिया भर के सदस्य देश एकत्रित होकर अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर व्यापक विचार-विमर्श करते हैं। यहाँ हर देश को अपनी बात रखने का समान अवसर मिलता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। हालांकि महासभा के प्रस्ताव अनिवार्य नहीं होते, लेकिन वे अंतरराष्ट्रीय समुदाय की राय और नैतिक दबाव को प्रभावी रूप से व्यक्त करते हैं, जिससे वैश्विक नीतियाँ प्रभावित होती हैं।

67. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
संयुक्त राष्ट्र एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहाँ दुनिया के देश अमेरिका जैसी महाशक्ति के साथ संवाद कर सकते हैं और उसके फैसलों पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यहाँ अमेरिकी नीतियों की आलोचना संभव है, जिससे उस पर कुछ हद तक नैतिक अंकुश लगता है। हालांकि अमेरिका का प्रभाव बहुत अधिक है, फिर भी संयुक्त राष्ट्र शेष विश्व के देशों को एकजुट होने और अपने साझा हितों के लिए आवाज उठाने का एक महत्वपूर्ण अवसर देता है।

68. (D) डेग हैमरशोल्ड
डेग हैमरशोल्ड संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव थे, जिन्हें 1961 में मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी मृत्यु कांगो संकट के दौरान एक विमान दुर्घटना में हुई थी। उन्हें अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापना के सिद्धांतों को विकसित करने और शीतयुद्ध के दौरान संगठन की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए याद किया जाता है। उनके साहसिक कूटनीतिक प्रयासों ने संयुक्त राष्ट्र को एक सशक्त और प्रभावी अंतरराष्ट्रीय संस्था के रूप में स्थापित करने में मदद की थी।

69. (C) 0.8%
संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में प्रत्येक सदस्य देश का योगदान उसकी आर्थिक क्षमता और सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर निर्धारित किया जाता है। भारत का योगदान लगभग 0.8 प्रतिशत के आसपास है, जो उसकी अर्थव्यवस्था के आकार के अनुरूप है। हालांकि यह विकसित देशों की तुलना में कम लग सकता है, लेकिन भारत बजट का भुगतान करने में हमेशा नियमित रहा है। यह वित्तीय योगदान संगठन के प्रशासनिक कार्यों और विभिन्न वैश्विक परियोजनाओं के संचालन में सहयोग प्रदान करता है।

70. (B) अंतर्राष्ट्रीय आण्विक ऊर्जा एजेंसी
अंतर्राष्ट्रीय आण्विक ऊर्जा एजेंसी एक विशिष्ट स्वायत्त संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद् दोनों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसका मुख्य कार्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना है कि इसका उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए न हो। सुरक्षा परिषद् के प्रति इसकी जवाबदेही अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और परमाणु अप्रसार के मामले में इसकी महत्वपूर्ण और संवेदनशील भूमिका को दर्शाती है, जिससे वैश्विक शांति बनी रहती है।

71. (A) P-4, Q-3, R-1, S-2
संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न संस्थाएँ अपने विशेष कार्यक्षेत्रों में वैश्विक चुनौतियों का सामना करती हैं। अंकटाड व्यापार और विकास के मुद्दों को देखता है, जबकि यूएनईपी पर्यावरण संरक्षण के लिए नीतियां बनाता है। यूएनडीपी दुनिया भर में विकास कार्यक्रमों का वित्तपोषण और प्रबंधन करता है, और यूएनएचसीआर युद्ध या उत्पीड़न के कारण विस्थापित हुए शरणार्थियों को सुरक्षा प्रदान करता है। ये सभी संस्थाएँ मिलकर एक संतुलित और सुरक्षित वैश्विक समाज के निर्माण की दिशा में निरंतर प्रयासरत रहती हैं।

72. (A) Asia, Africa और South America
सुरक्षा परिषद् के पुनर्गठन की चर्चाओं में एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे महाद्वीपों को अधिक प्रतिनिधित्व देने पर जोर दिया जा रहा है। वर्तमान संरचना में इन क्षेत्रों की उपेक्षा की गई है, जबकि यहाँ विश्व की अधिकांश जनसंख्या और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं निवास करती हैं। इन महाद्वीपों के देशों को शामिल करने से परिषद् अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण बनेगी, जिससे इसके निर्णयों की वैश्विक स्वीकार्यता और प्रभावशीलता में व्यापक वृद्धि होने की संभावना प्रबल हो जाएगी।

73. (C) यू थांट
1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन महासचिव यू थांट ने शांति स्थापना में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मध्यस्थता की और दोनों महाशक्तियों को सीधे सैन्य संघर्ष से बचने के लिए प्रेरित किया। उनके संयमित कूटनीतिक प्रयासों ने दुनिया को एक संभावित परमाणु युद्ध के कगार से पीछे हटाने में मदद की। इस संकट के समाधान ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर महासचिव के पद की गरिमा और प्रभाव को और बढ़ाया।

74. (B) केवल 1, 2 और 3
भारत संयुक्त राष्ट्र का एक संस्थापक सदस्य है और वह सुरक्षा परिषद् की वर्तमान संरचना में आमूल-चूल बदलाव का पुरजोर समर्थन करता है। भारत का तर्क है कि स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए ताकि यह संस्था अधिक प्रतिनिधिमूलक बन सके। भारत स्वयं भी स्थायी सदस्यता का एक प्रबल दावेदार है क्योंकि उसकी आर्थिक और सैन्य हैसियत में काफी वृद्धि हुई है। भारत मानता है कि ऐसे विस्तार से ही परिषद् की प्रभावशीलता बनी रहेगी।

75. (D) एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच
एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच दो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन हैं जो पूरी दुनिया में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित हैं। ये संगठन सरकारों द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न, अन्याय और नागरिक स्वतंत्रताओं के हनन के खिलाफ आवाज उठाते हैं। उनकी विस्तृत रिपोर्टें और वैश्विक अभियान अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान महत्वपूर्ण मानवाधिकार मुद्दों की ओर खींचते हैं, जिससे पीड़ितों को न्याय मिलने की संभावना बढ़ती है और लोकतांत्रिक मूल्यों को वैश्विक स्तर पर मजबूती मिलती है।

76. (B) डेग हैमरशोल्ड
1960 के दशक के दौरान कांगो संकट को सुलझाने के प्रयासों के कारण महासचिव डेग हैमरशोल्ड को सोवियत संघ की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा था। सोवियत संघ ने उन पर पश्चिमी देशों के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया और उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए। इस विवाद के कारण सोवियत संघ ने महासचिव के पद को समाप्त कर तीन सदस्यीय समिति (ट्रोइका) बनाने की मांग भी की थी, जिससे उस समय संगठन के भीतर काफी तनाव पैदा हो गया था।

77. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
भारत की सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता की राह में कई चुनौतियाँ मौजूद हैं, जिनमें कुछ देशों का विरोध प्रमुख है। पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ने के डर से इसका विरोध करते हैं, जबकि कुछ अन्य देश भारत की परमाणु क्षमताओं को लेकर चिंतित रहते हैं। इसके अलावा, अन्य उभरती शक्तियों को भी शामिल करने की बहस के कारण आम सहमति बनाना मुश्किल हो जाता है, जिससे भारत की दावेदारी की प्रक्रिया काफी लंबी और जटिल हो गई है।

78. (D) यूनेस्को (UNESCO)
यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। यह संस्था दुनिया भर में सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण, साक्षरता बढ़ाने और वैज्ञानिक सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करती है। यूनेस्को का मानना है कि चूंकि युद्धों की शुरुआत मनुष्य के मस्तिष्क में होती है, इसलिए शांति की रक्षा की नींव भी मनुष्य के विचारों और शिक्षा के माध्यम से ही रखी जानी चाहिए।

79. (A) 15 न्यायाधीश, 9 वर्ष
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल पंद्रह न्यायाधीश होते हैं, जिनका चयन महासभा और सुरक्षा परिषद् द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल नौ वर्ष का होता है और उन्हें दोबारा चुना जा सकता है। यह न्यायालय अंतरराष्ट्रीय कानूनों की व्याख्या करता है और सदस्य देशों के बीच कानूनी विवादों पर निष्पक्ष निर्णय देता है। इसके न्यायाधीशों का चयन इस प्रकार किया जाता है कि दुनिया की प्रमुख कानूनी प्रणालियों और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का न्यायसंगत प्रतिनिधित्व बना रहे।

80. (B) सुरक्षा-परिषद् की सलाह पर आम सभा
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुरक्षा परिषद् और महासभा दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सुरक्षा परिषद् किसी एक नाम की सिफारिश करती है, जिसे बाद में महासभा द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित किया जाता है। इस प्रक्रिया में सुरक्षा परिषद् के पाँच स्थायी सदस्यों की सहमति अनिवार्य है क्योंकि वे वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। यह नियुक्ति सामान्यतः पाँच वर्ष के कार्यकाल के लिए होती है और महासचिव को दोबारा चुने जाने का विकल्प भी मिलता है।

81. (B) जर्मनी
वर्तमान में सुरक्षा परिषद् के केवल पाँच स्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। जर्मनी एक बड़ी आर्थिक शक्ति होने के बावजूद वर्तमान में स्थायी सदस्य नहीं है, हालांकि वह लंबे समय से इस पद की मांग कर रहा है। परिषद् की यह स्थायी सदस्यता दूसरे विश्वयुद्ध के बाद के शक्ति संतुलन को दर्शाती है। जर्मनी जैसे देशों को शामिल करने की बहस अक्सर उठती है, लेकिन इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संशोधन की एक अत्यंत कठिन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।

82. (A) 1, 2, 4, 3
संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के क्रम में सबसे पहले फरवरी 1945 में याल्टा सम्मेलन हुआ, जहाँ संगठन के ढांचे पर चर्चा की गई। इसके बाद अप्रैल-जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन आयोजित हुआ और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक स्थापना हुई। भारत 30 अक्टूबर 1945 को इसमें शामिल हुआ। यह ऐतिहासिक कालक्रम दर्शाता है कि दूसरे विश्वयुद्ध के अंतिम दिनों में किस तरह दुनिया के प्रमुख देशों ने

मिलकर एक स्थायी शांति संगठन के निर्माण की प्रक्रिया पूरी की थी।

83. (C) 2005
शांति संस्थापक आयोग का गठन वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित विश्व शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य संघर्ष के बाद की स्थितियों में देशों को फिर से खड़ा करने और वहां शांति बनाए रखने में मदद करना है। यह आयोग विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करता है ताकि युद्धग्रस्त क्षेत्रों में विकास और पुनर्निर्माण के कार्य प्रभावी ढंग से हो सकें और दोबारा हिंसा की स्थिति पैदा होने से रोकी जा सके।

84. (D) विकासशील देश
विश्व बैंक अपनी अधिकांश विकास गतिविधियों और ऋण कार्यक्रमों को विकासशील देशों पर केंद्रित करता है। इसका उद्देश्य इन देशों में गरीबी कम करना, शिक्षा का स्तर सुधारना और बुनियादी ढांचे का विकास करना है। हालांकि इसकी नीतियां अक्सर विकसित देशों के हितों से प्रभावित मानी जाती हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह गरीब और मध्यम आय वाले राष्ट्रों को ही वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। यह संस्था वैश्विक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सदस्य देशों को विशेष अनुदान भी देती है।

85. (C) केवल 1, 2, 3, 4
अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूरी तरह से दोषरहित नहीं होते, लेकिन वे देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और जीवन स्तर सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संगठन सदस्य देशों की सहमति से बनते हैं और उनकी समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह कहना गलत है कि ये संगठन हमेशा अपनी इच्छा थोपते हैं, क्योंकि वे केवल उतनी ही शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं जितनी सदस्य देश उन्हें देते हैं। वे सामूहिक प्रयासों के लिए एक आवश्यक मंच के रूप में कार्य करते हैं।

86. (B) वैश्विक मौद्रिक नीति का निर्धारण करना
विश्व बैंक मुख्य रूप से मानवीय विकास, ग्रामीण विकास और आधारभूत ढांचे जैसे क्षेत्रों में दीर्घकालिक निवेश और ऋण प्रदान करने का कार्य करता है। वैश्विक मौद्रिक नीति का निर्धारण करना और विनिमय दरों की निगरानी करना इसका कार्य नहीं है, बल्कि यह जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की है। विश्व बैंक का प्राथमिक लक्ष्य विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और सामाजिक कल्याण की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देकर गरीबी उन्मूलन की दिशा में ठोस और सार्थक कदम उठाना है।

87. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका दुनिया की एकमात्र महाशक्ति बनकर उभरा, जिससे वैश्विक शक्ति संतुलन में भारी बदलाव आया। ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई ताकि वह किसी एक देश के मनमाने व्यवहार पर कुछ अंकुश लगा सके। सदस्य देशों को उम्मीद थी कि संगठन नए दौर की राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप खुद को बदलेगा और अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए एक न्यायसंगत और अधिक प्रभावी माध्यम के रूप में कार्य करेगा।

88. (A) उपरोक्त सभी
सुरक्षा परिषद् के पुनर्गठन में प्रतिनिधित्व के मुद्दे को हल करने के लिए कई आधारों पर विचार किया जा रहा है, जिनमें भौगोलिक समानता, आर्थिक हैसियत और सांस्कृतिक विविधता शामिल हैं। आलोचकों का तर्क है कि वर्तमान परिषद् में दुनिया की विविधता की कमी है, इसलिए इसमें विभिन्न महाद्वीपों और सभ्यताओं को जगह मिलनी चाहिए। इन मानदंडों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिषद् के निर्णय अधिक लोकतांत्रिक हों और उन्हें पूरी दुनिया के राष्ट्रों का व्यापक और ठोस नैतिक समर्थन प्राप्त हो सके।

89. (C) 190
वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों की कुल संख्या 190 है। यह संगठन वैश्विक स्तर पर वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देता है और सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक नीतियों की निगरानी करता है। इसके सदस्यों में दुनिया के लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल हैं, जो वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के साझा लक्ष्य के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। आईएमएफ में प्रत्येक सदस्य का प्रभाव उसके आर्थिक योगदान और कोटे पर निर्भर करता है, जिससे निर्णय प्रक्रिया में कुछ बड़े देशों का दबदबा बना रहता है।

90. (A) सेन फ्रांसिस्को
संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर की ऐतिहासिक प्रक्रिया सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के दौरान संपन्न हुई थी, जो अप्रैल से जून 1945 तक चला था। इस सम्मेलन में दुनिया के 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अंतरराष्ट्रीय शांति की नई रुपरेखा तैयार की। इसी सम्मेलन के अंत में चार्टर को स्वीकार किया गया, जिसके आधार पर संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ। यह सम्मेलन वैश्विक कूटनीति के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है, जिसने भविष्य की सामूहिक सुरक्षा प्रणाली की ठोस नींव रखी।

91. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियां विभिन्न मानवीय और तकनीकी क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर विशेषज्ञता प्रदान करती हैं। एफएओ कृषि और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि आईएमओ अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान और समुद्री सुरक्षा से जुड़े कार्यों को देखता है। आईटीयू दूरसंचार के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय मानक तय करता है और आईएलओ श्रमिकों के अधिकारों और कार्यस्थल की सुरक्षा के लिए वैश्विक नीतियां बनाता है। ये संस्थाएं संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों को धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका निभाती हैं।

92. (A) कुर्त वाल्डहीम
ऑस्ट्रिया के कुर्त वाल्डहीम ने 1972 से 1981 तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में दो कार्यकाल पूरे किए थे। जब उन्होंने तीसरे कार्यकाल के लिए दावेदारी पेश की, तो चीन

ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करके उनके नाम का कड़ा विरोध किया। चीन का मानना था कि अब किसी विकासशील देश के प्रतिनिधि को यह पद मिलना चाहिए। इस विरोध के परिणामस्वरूप वाल्डहीम दोबारा नहीं चुने जा सके और अंततः पेरू के जेवियर पेरेज द कूइयार को नया महासचिव नियुक्त किया गया था।

93. (C) बुतरस बुतरस घाली
मिस्र के बुतरस बुतरस घाली ने 1992 से 1996 तक महासचिव के रूप में कार्य किया। जब वे दूसरे कार्यकाल के लिए खड़े हुए, तो अमेरिका ने उनके दोबारा चुने जाने का तीव्र विरोध किया और वीटो का प्रयोग किया। अमेरिका उनकी कुछ स्वायत्त नीतियों और कार्यप्रणाली से असंतुष्ट था। इस कड़े विरोध के कारण वे दोबारा महासचिव नहीं बन सके, और उनके स्थान पर कोफी अन्नान को चुना गया। यह घटना महासचिव के चयन में महाशक्तियों के गहरे प्रभाव और दखल को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

94. (D) न्यासिता परिषद्
न्यासिता परिषद् संयुक्त राष्ट्र का वह मुख्य अंग है जिसने उन क्षेत्रों के प्रशासन की देखरेख की जो दूसरे विश्वयुद्ध के बाद भी स्वतंत्र नहीं हुए थे। 1994 में पलाउ के स्वतंत्र होने के साथ ही इस परिषद् के पास कोई नया कार्य शेष नहीं बचा, जिसके कारण इसकी गतिविधियों को स्थगित कर दिया गया। हालांकि यह तकनीकी रूप से अभी भी अस्तित्व में है, लेकिन अब इसकी नियमित बैठकें नहीं होती हैं। यह परिषद् उपनिवेशवाद की समाप्ति और राष्ट्रों की स्वतंत्रता की दिशा में एक सफल प्रयास मानी जाती है।

95. (A) आम सभा में प्रत्येक सदस्य को दो वोट हासिल हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के नियमों के अनुसार, प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को केवल एक वोट का अधिकार प्राप्त है, चाहे वह देश कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न हो। यह सिद्धांत 'एक राष्ट्र, एक मत' की अवधारणा पर आधारित है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों की समानता को सुनिश्चित करता है। महासभा का मुख्य उद्देश्य वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करना और शांतिपूर्ण समाधान ढूंढना है। 2011 में दक्षिण सूडान के शामिल होने के बाद से इसकी सदस्य संख्या 193 हो गई है।

96. (B) कोफी अन्नान - घाना
कोफी अन्नान संयुक्त राष्ट्र के सातवें महासचिव थे और उनका संबंध अफ्रीकी देश घाना से था। वे संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों के बीच से ही इस शीर्ष पद तक पहुँचने वाले पहले महासचिव थे। उनके कार्यकाल के दौरान संगठन ने मानवाधिकारों और वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की। उन्हें दुनिया भर में एक सम्मानित राजनयिक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने अफ्रीका और शेष विश्व के बीच सहयोग के नए पुल बनाने और शांति स्थापना में ऐतिहासिक योगदान दिया था।

97. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
विश्व व्यापार संगठन की कार्यप्रणाली अक्सर विवादों के केंद्र में रहती है क्योंकि विकासशील देशों का मानना है कि यहाँ निर्णय लेने की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियां अक्सर बंद कमरों में चर्चा करके व्यापार के नियम अपने पक्ष में बना लेती हैं। इसके परिणामस्वरूप गरीब और विकासशील देशों को वैश्विक बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा और नुकसान का सामना करना पड़ता है, जिससे व्यापारिक असंतुलन और आर्थिक असमानता की समस्या निरंतर और गंभीर बनी रहती है।

98. (A) विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)
विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख विशेष एजेंसी है, जो अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। यह स्वायत्त रूप से कार्य करती है और इसका अपना बजट तथा सदस्य देश होते हैं। यूएनडीपी, यूनिसेफ और यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम और कोष हैं, जो महासभा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में काम करते हैं। विशेष एजेंसियां तकनीकी और विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्रदान करती हैं और संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधियों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के साथ औपचारिक रूप से जुड़ी होती हैं।

99. (C) वे सभी सदस्यों पर बाध्यकारी होते हैं।
सुरक्षा परिषद् के निर्णयों की प्रकृति महासभा के प्रस्तावों से भिन्न होती है क्योंकि वे कानूनी रूप से सभी सदस्य देशों पर बाध्यकारी होते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 25 के अनुसार, सभी सदस्य देश सुरक्षा परिषद् के फैसलों को स्वीकार करने और उन्हें लागू करने के लिए सहमत होते हैं। यदि कोई देश इन निर्णयों का उल्लंघन करता है, तो परिषद् उसके विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध या सैन्य कार्रवाई जैसे कड़े कदम उठा सकती है ताकि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे।

100. (D) क्योंकि कोई एक देश इसे अकेले हल नहीं कर सकता।
ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक पर्यावरणीय समस्या किसी एक देश की सीमा तक सीमित नहीं है, इसलिए इसका समाधान भी किसी एक राष्ट्र के प्रयास से संभव नहीं है। वायुमंडल में बढ़ती कार्बन गैसें पूरी पृथ्वी को प्रभावित करती हैं, जिससे निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सामूहिक जिम्मेदारी अनिवार्य है। संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन विभिन्न देशों को एक साथ लाकर ऐसी संधियां और नियम बनाने में मदद करते हैं जिनसे पर्यावरण का संरक्षण सुनिश्चित हो सके और भविष्य सुरक्षित रहे।

101. (A) केवल 1 और 3
सुरक्षा परिषद् की संरचना में पाँच स्थायी सदस्य—अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन—शामिल हैं, जिन्हें वीटो की विशेष शक्ति प्राप्त है। जर्मनी, जापान और भारत जैसे देश वर्तमान में स्थायी सदस्य नहीं हैं, हालांकि वे इस पद के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। स्थायी सदस्यों का वीटो अधिकार उन्हें किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रस्ताव को अकेले रोकने की अभूतपूर्व शक्ति प्रदान करता है। यह व्यवस्था दूसरे विश्वयुद्ध के बाद के

राजनीतिक वास्तविकताओं को दर्शाती है जिसे अब सुधारने की मांग हो रही है।

102. (B) अमरीका
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मतदान की शक्ति 'एक देश, एक वोट' के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक देश के वित्तीय योगदान या कोटे पर निर्भर करती है। अमेरिका इस संगठन में सबसे अधिक वित्तीय योगदान देने वाला देश है, जिसके कारण उसके पास सबसे अधिक मताधिकार प्रतिशत है। यह स्थिति अमेरिका को आईएमएफ के नीतिगत निर्णयों और ऋण संबंधी शर्तों पर एक निर्णायक और अत्यंत प्रभावशाली नियंत्रण प्रदान करती है, जिससे वैश्विक वित्तीय व्यवस्था पर उसका दबदबा बना रहता है।

103. (D) दूसरा विश्वयुद्ध
'लीग ऑफ नेशंस' की स्थापना प्रथम विश्वयुद्ध के बाद विश्व शांति सुनिश्चित करने के लिए की गई थी, लेकिन यह राष्ट्रों के बीच बढ़ते तनाव और आक्रामकता को रोकने में विफल रहा। इसकी सबसे बड़ी असफलता 1939 में दूसरे विश्वयुद्ध की शुरुआत थी, जिसे यह संगठन नहीं रोक सका। इसी विफलता के कारण युद्ध के बाद एक अधिक शक्तिशाली और प्रभावी संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की आवश्यकता महसूस की गई, ताकि भविष्य में इस तरह के महाविनाश को टाला जा सके।

104. (A) 24 अक्टूबर
प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर आधिकारिक रूप से प्रभावी हुआ था। यह दिन संगठन के उद्देश्यों, जैसे अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और मानवाधिकारों के प्रति दुनिया भर के लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। इस अवसर पर विभिन्न देशों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो वैश्विक सहयोग की भावना को मजबूत करते हैं और संगठन की अब तक की उपलब्धियों को याद दिलाते हैं।

105. (C) पाँच साल
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल सामान्यतः पाँच वर्ष की अवधि के लिए होता है। उन्हें सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। यदि उनके कार्य संतोषजनक रहते हैं, तो उन्हें दूसरे पाँच वर्षीय कार्यकाल के लिए भी चुना जा सकता है। महासचिव का मुख्य कार्य संगठन के प्रशासनिक तंत्र का संचालन करना और अंतरराष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थ की भूमिका निभाना है। यह कार्यकाल उन्हें वैश्विक शांति और सुरक्षा की परियोजनाओं को लागू करने का पर्याप्त समय देता है।

106. (B) P-3, Q-4, R-2, S-1
संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएँ विशिष्ट वर्षों से जुड़ी हुई हैं। अटलांटिक चार्टर 1941 में आया, जिसने संगठन की नींव रखी। 1994 में न्यासिता परिषद् को स्थगित किया गया और 2006 में मानवाधिकार परिषद् की स्थापना हुई। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठन लंबे समय से मानवाधिकारों की रक्षा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। ये सभी विकास यह दर्शाते हैं कि समय के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था ने कैसे नई चुनौतियों के अनुसार खुद को ढाला और संस्थानों का निर्माण किया है।

107. (A) केवल 2 और 3
सुरक्षा परिषद् के बारे में यह कहना गलत है कि इसमें वर्तमान में बराबर का प्रतिनिधित्व है या यह पूरी तरह से समकालीन राजनीतिक वास्तविकताओं को दर्शाती है। वास्तव में, परिषद् की संरचना आज भी 1945 के शक्ति संतुलन पर आधारित है, जिसके कारण विकासशील देशों को उचित स्थान नहीं मिल पाया है। आलोचकों का मानना है कि इसके निर्णयों पर चंद विकसित राष्ट्रों का ही दबदबा रहता है, जिससे यह वैश्विक स्तर पर पूर्णतः प्रतिनिधिमूलक और न्यायसंगत संस्था नहीं बन पाई है।

108. (B) 2005 की 60वीं सालगिरह की बैठक में
वर्ष 2005 के विश्व शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने 'संरक्षण की जिम्मेदारी' (Responsibility to Protect) के सिद्धांत को स्वीकार किया। इसके तहत यह तय किया गया कि यदि कोई देश अपने नागरिकों को जनसंहार, युद्ध अपराधों या जातीय सफाए से बचाने में विफल रहता है, तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय को हस्तक्षेप करने का अधिकार और उत्तरदायित्व होगा। यह निर्णय मानवाधिकारों की रक्षा की दिशा में एक बड़ा और क्रांतिकारी कदम था, जिसने राष्ट्रीय संप्रभुता के साथ मानवीय सुरक्षा को भी जोड़ा।

109. (C) उपरोक्त सभी
ह्यूमन राइट्स वॉच ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण मानवीय मुद्दों को उठाया है। इसने युद्धों में बारूदी सुरंगों के घातक उपयोग पर रोक लगाने, बच्चों को सैनिक बनाने की प्रथा को समाप्त करने और युद्ध अपराधियों को दंडित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दंड न्यायालय की स्थापना के लिए व्यापक अभियान चलाए हैं। इन प्रयासों के माध्यम से संगठन ने मानवाधिकारों के प्रति वैश्विक चेतना जागृत करने और अंतरराष्ट्रीय न्याय प्रणाली को अधिक मानवीय और जवाबदेह बनाने में अत्यंत सराहनीय और निर्णायक भूमिका निभाई है।

110. (D) अटलांटिक चार्टर
द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अगस्त 1941 में राष्ट्रपति रुजवेल्ट और प्रधानमंत्री चर्चिल के बीच हुई वार्ता के बाद अटलांटिक चार्टर जारी किया गया था। इस चार्टर में उन आदर्शों की घोषणा की गई थी जिन पर युद्ध के बाद की विश्व व्यवस्था आधारित होनी चाहिए थी। इसने सामूहिक सुरक्षा, राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के अधिकार और आर्थिक सहयोग की नींव रखी। हालांकि यह औपचारिक संधि नहीं थी, लेकिन इसने संयुक्त राष्ट्र के गठन के लिए आवश्यक वैचारिक और राजनीतिक आधारशिला मजबूती से तैयार की थी।

111. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल सरकारों द्वारा किए जाने वाले मानवाधिकार उल्लंघनों की निष्पक्ष जांच करती है और अपनी

रिपोर्टों के माध्यम से उन्हें सार्वजनिक करती है। अक्सर ये रिपोर्टें सरकारों की दमनकारी नीतियों और तानाशाही रवैये को उजागर करती हैं, जिससे उनकी अंतरराष्ट्रीय छवि धूमिल होती है। इसी कारण कई सरकारें इस संगठन की आलोचना करती हैं और उसकी रिपोर्टों को पक्षपाती बताती हैं। फिर भी, यह संगठन बिना किसी दबाव के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अपना वैश्विक अभियान जारी रखता है।

112. (A) 1, 2, 4, 3
संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख घटनाओं का क्रम संगठन की विकास यात्रा को दर्शाता है। 1945 में इसकी स्थापना हुई, जिसके बाद 1965 में सुरक्षा परिषद् के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। 2001 में कोफी अन्नान को उनकी सेवाओं के लिए नोबेल पुरस्कार मिला और अंत में 2006 में मानवाधिकार परिषद् का गठन हुआ। यह कालक्रम स्पष्ट करता है कि संयुक्त राष्ट्र ने समय की माँग के अनुसार अपने अंगों में सुधार किया और वैश्विक शांति एवं सुरक्षा के प्रति अपनी भूमिका को निरंतर और व्यापक बनाया है।

113. (A) संयुक्त राष्ट्रसंघ शरणार्थी उच्चायोग
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग या यूएनएचसीआर एक प्रमुख एजेंसी है जो युद्ध, हिंसा या उत्पीड़न के कारण अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए लोगों की सहायता करती है। यह संस्था आपातकालीन स्थितियों में शरणार्थियों को सुरक्षित आश्रय, भोजन, पानी और चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करती है। इसका मुख्य कार्य शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके लिए सुरक्षित पुनर्वास के अवसर तलाशना है, जिससे विस्थापित समुदायों को मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का सहारा मिल सके।

114. (A) कनाडा
कनाडा समूह-7 का एक संस्थापक सदस्य है, जो विश्व की सात सबसे बड़ी और विकसित औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जी-7 के अन्य सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं। यह समूह वैश्विक आर्थिक शासन, सुरक्षा और ऊर्जा नीतियों पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से बैठकें करता है। भारत, चीन और रूस वर्तमान में इसके पूर्ण सदस्य नहीं हैं, हालांकि कई बार उन्हें विशेष अतिथि के रूप में सम्मेलनों में आमंत्रित किया जाता है।

115. (D) 1, 2, 3 और 4
भारत संयुक्त राष्ट्र का एक अत्यंत जिम्मेदार सदस्य है जो अपने वित्तीय अंशदान का भुगतान समय पर और नियमित रूप से करता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का यह रिकॉर्ड उसकी विश्वसनीयता को बढ़ाता है। सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता का दावा केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह देश की वैश्विक हैसियत और विदेश नीति को भी मजबूती प्रदान करता है। भारत जैसे बड़े और विकासशील देश के लिए यह सदस्यता अंतरराष्ट्रीय निर्णय प्रक्रिया में एक निर्णायक और गौरवशाली भूमिका सुनिश्चित करेगी।

116. (D) न्यासिता परिषद्
न्यासिता परिषद् को औपचारिक रूप से तब स्थगित किया गया जब उसके अधीन आने वाला अंतिम क्षेत्र पलाउ 1994 में स्वतंत्र हो गया। इस अंग का निर्माण ग्यारह ऐसे ट्रस्ट क्षेत्रों की देखरेख के लिए किया गया था जो अभी तक स्वशासन के लिए तैयार नहीं थे। जैसे-जैसे ये क्षेत्र आजाद होते गए, परिषद् का कार्य कम होता गया। पलाउ की स्वतंत्रता के साथ ही इसका मूल उद्देश्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने इसकी नियमित गतिविधियों को अनिश्चित काल के लिए विराम दे दिया।

117. (C) एंटोनियो गुटेरेस
एंटोनियो गुटेरेस ने 1 जनवरी 2017 को संयुक्त राष्ट्र के नौवें महासचिव के रूप में अपना पदभार संभाला। वे पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और उनके पास अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का लंबा अनुभव है। उनके नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौती, वैश्विक संघर्षों के समाधान और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। वे संगठन को आधुनिक बनाने और इसे 21वीं सदी की जटिल आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने के लिए निरंतर प्रयासरत और समर्पित हैं।

118. (A) P-3, Q-1, R-4, S-2
सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों ने अलग-अलग समय पर अपने हितों और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार वीटो शक्ति का प्रयोग किया है। जून 2018 तक के आंकड़ों के अनुसार सोवियत संघ/रूस ने सबसे अधिक बार (135) वीटो का इस्तेमाल किया है, उसके बाद अमेरिका का स्थान आता है। ब्रिटेन और चीन ने इसकी तुलना में कम बार वीटो का उपयोग किया है। यह डेटा दर्शाता है कि महाशक्तियों ने परिषद् के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए इस नकारात्मक शक्ति का कितना व्यापक प्रयोग किया है।

119. (D) 2 वर्ष
सुरक्षा परिषद् के दस अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा केवल दो वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। प्रत्येक वर्ष पाँच नए अस्थायी सदस्यों का चयन होता है ताकि निरंतरता बनी रहे। कोई भी देश अपना कार्यकाल समाप्त होने के तुरंत बाद दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता। यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के देशों को बारी-बारी से परिषद् का हिस्सा बनने और वैश्विक सुरक्षा के मामलों में भागीदारी करने का समान अवसर मिले।

120. (A) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का वह अंग है जो सदस्य देशों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है। जब दो देश किसी संधि या सीमा विवाद पर एकमत नहीं होते, तो वे इस न्यायालय की शरण ले सकते हैं। न्यायालय अंतरराष्ट्रीय कानूनों के आधार पर अपने फैसले सुनाता है, जो संबंधित देशों के लिए मान्य होते हैं। यह वैश्विक स्तर पर न्याय व्यवस्था को बनाए रखने और शक्ति के प्रयोग के बजाय कानूनी माध्यम से संघर्षों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

121. (A) सचिवालय
सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का मुख्य प्रशासनिक अंग है जो संगठन के दैनिक कार्यों और कार्यक्रमों का संचालन करता है। इसका नेतृत्व महासचिव करते हैं, जिन्हें दुनिया भर के हजारों कर्मचारियों का सहयोग मिलता है। सचिवालय का कार्य सम्मेलनों का आयोजन करना, शोध रिपोर्टें तैयार करना और महासभा तथा सुरक्षा परिषद् द्वारा लिए गए निर्णयों को धरातल पर लागू करना है। यह अंग संयुक्त राष्ट्र की निरंतरता और उसके प्रशासनिक ढांचे को सुचारु रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक आधार प्रदान करता है।

122. (A) केवल 1 और 2
भारत की विदेश नीति में संयुक्त राष्ट्र को मजबूत बनाना एक प्रमुख प्राथमिकता रही है क्योंकि यह वैश्विक स्थिरता के लिए आवश्यक है। भारत का मानना है कि गरीबी उन्मूलन और विकास जैसे मुद्दे संयुक्त राष्ट्र के प्राथमिक एजेंडे में होने चाहिए। भारत सुरक्षा परिषद् की वर्तमान संरचना को पुराना मानता है और इसमें स्थायी एवं अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार का कट्टर समर्थक है। भारत का तर्क है कि विस्तार से परिषद् अधिक समावेशी और प्रतिनिधिमूलक बनेगी, जिससे उसकी निर्णय क्षमता बेहतर होगी।

123. (D) दूसरे विश्वयुद्ध के बाद
'जेनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ' का गठन 1948 में दूसरे विश्वयुद्ध के बाद किया गया था ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुव्यवस्थित और उदार बनाया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापारिक करों (टैरिफ) को कम करना और भेदभावपूर्ण व्यापार नीतियों को समाप्त करना था। गेट ने कई दशकों तक वैश्विक व्यापार के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया, जिसे बाद में 1995 में अधिक शक्तिशाली और व्यापक विश्व व्यापार संगठन (डबल्यूटीओ) में बदल दिया गया था।

124. (B) ट्राइग्व ली
संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव ट्राइग्व ली को सोवियत संघ के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था। विशेष रूप से कोरिया युद्ध के दौरान, सोवियत संघ ने उन पर अमेरिकी हितों का पक्ष लेने का आरोप लगाया था। जब उनके दोबारा निर्वाचन की बात आई, तो सोवियत संघ ने उनके नाम का तीव्र विरोध किया और उन्हें महासचिव मानने से इनकार कर दिया। इस राजनीतिक दबाव और असहयोग के कारण ट्राइग्व ली को अंततः 1952 में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

125. (C) 54
आर्थिक और सामाजिक परिषद् में वर्तमान में 54 सदस्य देश होते हैं। इन सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। परिषद् के एक-तिहाई सदस्य हर साल सेवानिवृत्त होते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होता है। यह परिषद् संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों के समन्वय के लिए उत्तरदायी है और विभिन्न विशेष एजेंसियों के कार्यों की निगरानी भी करती है, जिससे वैश्विक विकास सुनिश्चित होता है।

126. (A) P, Q, R, और S सभी का संबंध 1 से है।
अफ्रीका, यूरोप, एशिया-प्रशांत और लैटिन अमेरिका के लिए बनाए गए क्षेत्रीय आर्थिक आयोग सीधे तौर पर संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद् के अधीन कार्य करते हैं। ये आयोग अपने संबंधित क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग बढ़ाने और विकास संबंधी समस्याओं का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान खोजने के लिए जिम्मेदार हैं। परिषद् इन क्षेत्रीय निकायों के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं और वैश्विक नीतियों के बीच एक प्रभावी तालमेल स्थापित करती है, जिससे संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यों को जमीनी मजबूती मिलती है।

127. (A) 164
विश्व व्यापार संगठन में वर्तमान में 164 सदस्य देश शामिल हैं, जो वैश्विक व्यापार का लगभग 98 प्रतिशत हिस्सा नियंत्रित करते हैं। यह संगठन सदस्य देशों के बीच व्यापारिक विवादों को सुलझाने और नए व्यापार समझौतों पर बातचीत के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इसके नियम सभी सदस्यों पर बाध्यकारी होते हैं, हालांकि निर्णय अक्सर सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। विकासशील देशों की इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद, संगठन के भीतर बड़ी आर्थिक शक्तियों का प्रभाव और दबदबा हमेशा अधिक रहता है।

128. (B) 50
26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के समापन के अवसर पर कुल 50 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। इन देशों ने मिलकर एक ऐसी नई वैश्विक संस्था की रूपरेखा तैयार की जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की गारंटी दे सके। पोलैंड उस समय सम्मेलन में उपस्थित नहीं हो पाया था, लेकिन बाद में उसने हस्ताक्षर करके संस्थापक सदस्यों में अपनी जगह बनाई। इन 50 देशों की सहमति ने ही आधुनिक संयुक्त राष्ट्र के वैधानिक और राजनीतिक अस्तित्व की शुरुआत की थी।

129. (B) पोलैंड
पोलैंड को संयुक्त राष्ट्र का 51वाँ मूल संस्थापक सदस्य माना जाता है क्योंकि उसने 15 अक्टूबर 1945 को चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि पोलैंड ने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, लेकिन चार्टर में उसके लिए स्थान सुरक्षित रखा गया था। पोलैंड के हस्ताक्षर के साथ ही संस्थापक सदस्यों की कुल संख्या पूरी हो गई। यह घटना दर्शाती है कि युद्ध के बाद की नई विश्व व्यवस्था में सभी महत्वपूर्ण मित्र राष्ट्रों को शामिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र कितना गंभीर और प्रतिबद्ध था।

130. (A) बढ़ती आर्थिक शक्ति और स्थिर लोकतांत्रिक राजनीतिक ढांचा।
भारत की सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता की दावेदारी का सबसे मजबूत आधार इसकी विशाल और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था एवं सुदृढ़ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, भारत अंतरराष्ट्रीय कानूनों

और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का हमेशा समर्थक रहा है। इसके अलावा, भारत की जनसंख्या और अंतरराष्ट्रीय शांति अभियानों में उसका विशाल योगदान उसे एक अनिवार्य वैश्विक शक्ति बनाता है। इन सभी कारकों के कारण भारत का मानना है कि उसे परिषद् में निर्णय लेने की मुख्य भूमिका मिलनी चाहिए।

131. (D) 1, 2, 3 और 4
विश्व बैंक की भूमिका वैश्विक विकास में अत्यंत व्यापक है, क्योंकि यह मानवीय विकास से लेकर आधारभूत ढांचे तक के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह सदस्य देशों को कम ब्याज पर ऋण देता है और गरीब देशों को ऐसे अनुदान प्रदान करता है जिन्हें वापस नहीं चुकाना पड़ता। यह संस्था अंतरराष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। इसके माध्यम से विकासशील देशों को आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञता हासिल करने में मदद मिलती है, जिससे वैश्विक गरीबी कम होती है।

132. (D) अंतर्राष्ट्रीय आण्विक ऊर्जा एजेंसी
अंतर्राष्ट्रीय आण्विक ऊर्जा एजेंसी परमाणु तकनीक के सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने वाली दुनिया की प्रमुख संस्था है। यह सदस्य देशों को परमाणु ऊर्जा के वैज्ञानिक लाभों का उपयोग करने में मदद करती है, लेकिन साथ ही यह भी निगरानी करती है कि इस ऊर्जा का उपयोग घातक परमाणु हथियारों के निर्माण के लिए न हो। आईएईए की निरीक्षण प्रणाली अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो दुनिया को परमाणु प्रसार के खतरों से बचाने और सुरक्षा मानकों को लागू करने में मदद करती है।

133. (C) केवल स्थायी सदस्यों को
निषेधाधिकार या वीटो की शक्ति केवल सुरक्षा परिषद् के पाँच स्थायी सदस्यों—अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस—को ही प्राप्त है। यह एक असाधारण शक्ति है जिसके माध्यम से कोई भी एक स्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव को अकेले ही रोक सकता है, भले ही बाकी सभी सदस्य उसके समर्थन में हों। अस्थायी सदस्यों या महासभा के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है। यह व्यवस्था सुरक्षा परिषद् के भीतर शक्ति के एक बड़े असंतुलन और महाशक्तियों के विशेष दबदबे को स्पष्ट रूप से उजागर करती है।

134. (B) इसमें प्रत्येक सदस्य देश को एक वोट प्राप्त है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के भीतर 'एक राष्ट्र, एक मत' का सिद्धांत लागू होता है, जो सभी सदस्य देशों की संप्रभुता और समानता का प्रतीक है। महासभा में किसी भी देश का आकार या शक्ति उसके मताधिकार को प्रभावित नहीं करती है। यह अंग अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और सहयोग के हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने का अधिकार रखता है। महासभा के माध्यम से ही दुनिया के छोटे देश भी वैश्विक मंच पर अपनी आवाज उठा सकते हैं और अंतरराष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं।

135. (D) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण।
सुरक्षा परिषद् का प्राथमिक उत्तरदायित्व विश्व भर में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। यह अंग अंतरराष्ट्रीय विवादों की जांच करता है और उनके शांतिपूर्ण समाधान के लिए मध्यस्थता या सिफारिशें करता है। यदि आवश्यक हो, तो यह आक्रामक देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगा सकता है या शांति बनाए रखने के लिए सैन्य बल के प्रयोग की अनुमति दे सकता है। इसकी महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका के कारण इसे संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली और प्रभावी अंग माना जाता है, जो वैश्विक स्थिरता का संरक्षक है।

136. (A) 2005 में
वर्ष 2000 में घोषित सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता को सदस्य देशों ने 2005 के विश्व शिखर सम्मेलन में पुनः दोहराया। इन लक्ष्यों में गरीबी उन्मूलन, भुखमरी की समाप्ति, शिक्षा का प्रसार और लैंगिक समानता जैसे आठ महत्वपूर्ण उद्देश्य शामिल थे। 2005 की बैठक में इन लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और उन्हें 2015 तक पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने पर एक व्यापक और ठोस सहमति बनी थी।

137. (C) सुरक्षा के किसी मसले पर पाँचों स्थायी सदस्य देशों का सहमत होना ज़रूरी नहीं है।
सुरक्षा परिषद् की कार्यप्रणाली में किसी भी महत्वपूर्ण या प्रक्रियात्मक विषय से इतर मामले पर निर्णय लेने के लिए पाँचों स्थायी सदस्यों की सहमति अनिवार्य होती है। यदि कोई एक भी स्थायी सदस्य असहमत होकर वीटो का प्रयोग करता है, तो वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। यह नियम यह सुनिश्चित करता है कि बड़े निर्णय केवल तभी लिए जाएं जब दुनिया की प्रमुख महाशक्तियों के बीच एक न्यूनतम सहमति हो। बिना स्थायी सदस्यों की एकजुटता के सुरक्षा संबंधी कोई भी प्रभावी कार्रवाई संभव नहीं होती।

138. (B) केवल 2, 3, 4, 5
अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई स्वतंत्र संप्रभु राज्य नहीं होते, बल्कि वे सदस्य देशों के सहयोग से निर्मित एक साझा मंच हैं। इनका मुख्य कार्य देशों को बातचीत के लिए नियम और एक संगठित ढांचा प्रदान करना है। ये संगठन सूचनाएं जुटाने और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए उपाय सुझाने में अत्यंत सहायक होते हैं। वे अपने सदस्यों पर कोई बात थोप नहीं सकते, बल्कि सदस्य देशों के बीच समन्वय और सामूहिक कार्रवाई के लिए एक आवश्यक एवं उपयोगी साधन के रूप में कार्य करते हैं।

139. (D) महासचिव का
महासचिव संयुक्त राष्ट्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और इसका सबसे जाना-पहचाना सार्वजनिक चेहरा होता है। वह न केवल संगठन के सचिवालय का नेतृत्व करता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय विवादों में एक महत्वपूर्ण राजनयिक और मध्यस्थ के रूप में भी कार्य करता है। महासचिव की भूमिका पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र के आदर्शों और शांति के संदेश को पहुँचाने की होती है। उनके पास अपनी बुद्धिमत्ता और कूटनीतिक कौशल से

वैश्विक राजनीति को प्रभावित करने और संघर्षों को टालने की व्यापक नैतिक शक्ति होती है।

140. (B) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वह प्रमुख वैश्विक संस्था है जो दुनिया भर की वित्त-व्यवस्था की देखरेख और स्थिरता सुनिश्चित करती है। यह सदस्य देशों की विनिमय दरों और भुगतान संतुलन की स्थिति पर नजर रखती है। जब किसी देश के पास विदेशी मुद्रा का संकट होता है, तो आईएमएफ उसे वित्तीय सहायता और नीतिगत सलाह प्रदान करता है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी को रोकना और सदस्य राष्ट्रों के बीच सुदृढ़ मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना है, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था स्थिर बनी रहे।

141. (A) P-4, Q-1, R-2, S-3
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव विभिन्न महाद्वीपों से चुने जाते हैं ताकि नेतृत्व में विविधता बनी रहे। बुतरस बुतरस घाली मिस्र से थे, जबकि जेवियर पेरेज द कूइयार पेरु के राजनयिक थे। कुर्त वाल्डहीम का संबंध ऑस्ट्रिया से था और बान की मून दक्षिण कोरिया के निवासी थे। इन सभी नेताओं ने अपने-अपने कार्यकाल में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता को मजबूत किया और वैश्विक राजनीति में संयुक्त राष्ट्र की गरिमा और प्रभाव को बनाए रखने का निरंतर प्रयास किया।

142. (D) आर्थिक एवं सामाजिक परिषद्
आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् संयुक्त राष्ट्र का वह अंग है जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य संबंधी मामलों की देखरेख करता है। यह परिषद् महासभा और सुरक्षा परिषद् के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न विशेष एजेंसियों के कार्यों का समन्वय करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों में जीवन स्तर को ऊँचा उठाना, पूर्ण रोजगार सुनिश्चित करना और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान बढ़ाना है। यह वैश्विक विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में संगठन का सबसे महत्वपूर्ण कार्यात्मक अंग है।

143. (A) कोफी अन्नान
2003 में जब अमेरिका ने सुरक्षा परिषद् की स्पष्ट अनुमति के बिना इराक पर आक्रमण किया, तो तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नान ने इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताते हुए 'अवैध' करार दिया था। अन्नान का मानना था कि किसी भी देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई केवल अंतरराष्ट्रीय कानूनों और सामूहिक सहमति के आधार पर ही होनी चाहिए। उनके इस कड़े स्टैंड ने एक ओर जहाँ संगठन की निष्पक्षता को सिद्ध किया, वहीं दूसरी ओर महाशक्तियों के साथ उनके संबंधों में तनाव भी पैदा कर दिया था।

144. (B) जर्मनी का दो भागों में एकीकरण
शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था, लेकिन यह दो भागों में नहीं बल्कि पूर्व और पश्चिम जर्मनी के मिलकर एक होने की प्रक्रिया थी। शीतयुद्ध के अंत के अन्य बड़े परिणामों में सोवियत संघ का पूर्ण विघटन, अमेरिका का एकमात्र महाशक्ति के रूप में उदय और चीन की आर्थिक शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि शामिल थे। जर्मनी का पुनः एकीकरण यूरोप के राजनीतिक मानचित्र के लिए एक युगांतकारी घटना थी, जिसने महाद्वीप में पुराने वैचारिक विभाजनों को समाप्त कर दिया था।

145. (B) मैं निषेध करता हूँ
'वीटो' एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है 'मैं मना करता हूँ' या 'मैं निषेध करता हूँ'। संयुक्त राष्ट्र में यह एक ऐसी नकारात्मक शक्ति है जो सुरक्षा परिषद् के किसी भी स्थायी सदस्य को किसी प्रस्ताव को रोकने का अधिकार देती है। यदि कोई स्थायी सदस्य इस शक्ति का प्रयोग करता है, तो वह प्रस्ताव गिर जाता है, चाहे उसे बहुमत प्राप्त हो। यह शक्ति दर्शाती है कि बिना महाशक्तियों की सहमति के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी बड़ा सुरक्षा संबंधी निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

146. (A) चयन प्रक्रिया में व्यावहारिक कठिनाइयाँ।
सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता के लिए 'लोकतंत्र और मानवाधिकार' को मानदंड बनाने में मुख्य समस्या इसके व्यावहारिक कार्यान्वयन की है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय में लोकतंत्र के विभिन्न रूप प्रचलित हैं, और किसी एक देश की लोकतांत्रिक साख को मापने का कोई सर्वमान्य पैमाना नहीं है। इसके अलावा, वर्तमान में वीटो रखने वाले कुछ स्थायी सदस्यों पर भी मानवाधिकारों के हनन के आरोप लगते रहते हैं। ऐसे में इन मानदंडों को निष्पक्ष रूप से लागू करना और आम सहमति बनाना एक अत्यंत जटिल राजनयिक चुनौती है।

147. (B) केवल 1, 2 और 3
एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वतंत्र वैश्विक स्वयंसेवी संगठन है जो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। यह दुनिया भर में होने वाले अत्याचारों पर विस्तृत रिपोर्टें तैयार करता है ताकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इन मुद्दों पर लाया जा सके। चूंकि इसकी रिपोर्टें अक्सर सरकारों की खामियों और दुर्व्यवहार को उजागर करती हैं, इसलिए सरकारें हमेशा इसकी सराहना नहीं करतीं, बल्कि कई बार इसे संदेह की दृष्टि से देखती हैं। फिर भी, इसकी रिपोर्टें मानवाधिकार आंदोलनों के लिए एक विश्वसनीय आधार प्रदान करती हैं।

148. (D) बान की मून
'यूएन वीमेन' की स्थापना वर्ष 2010 में महासचिव बान की मून के कार्यकाल के दौरान की गई थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करना है। बान की मून ने महिलाओं के अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के मुख्य एजेंडे में लाने के लिए विशेष प्रयास किए थे। यह संस्था दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने और उनके राजनीतिक एवं आर्थिक अवसरों को बढ़ाने के लिए एक समर्पित निकाय के रूप में कार्य करती है।

149. (C) अमरीका और शेष विश्व के बीच संवाद मंच।
एक-ध्रुवीय विश्व में, जहाँ अमेरिका की सैन्य और आर्थिक शक्ति सर्वोपरि है, संयुक्त राष्ट्र उसे पूरी तरह नियंत्रित तो नहीं कर सकता, लेकिन एक महत्वपूर्ण संवाद मंच के रूप में कार्य अवश्य करता है। यहाँ शेष दुनिया के देश अमेरिकी नीतियों पर बहस कर सकते हैं और उस पर कुछ नैतिक दबाव बना सकते हैं। यह संगठन अमेरिका को भी अपनी नीतियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैध बनाने का अवसर देता है। इस प्रकार, संयुक्त राष्ट्र महाशक्ति और अन्य राष्ट्रों के बीच संवाद की एक अनिवार्य कड़ी बना हुआ है।

150. (A) P-2, Q-1, R-4, S-3
संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संगठन विभिन्न भूमिकाओं के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को संचालित करते हैं। सुरक्षा परिषद् का मुख्य कार्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है, जबकि महासभा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक बड़ा लोकतांत्रिक मंच प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वैश्विक वित्त-व्यवस्था की देखरेख करता है और विश्व व्यापार संगठन सदस्य देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं को दूर कर मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है। यह संस्थागत ढांचा वैश्विक शासन को अधिक संगठित और प्रभावी बनाता है।

151. (B) किसी एक राज्य पर हुए आक्रमण को सभी राज्यों पर आक्रमण मानना।
सामूहिक सुरक्षा का मूल सिद्धांत इस विचार पर टिका है कि किसी एक सदस्य देश पर किया गया हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। यह व्यवस्था सभी राष्ट्रों को एकजुट होकर आक्रामक राज्य के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे वैश्विक स्तर पर सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

152. (A) सुरक्षा परिषद
संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद को सौंपी गई है। यह अंग सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांतों को लागू करने के लिए अधिकृत है। सुरक्षा परिषद के पास विवादों को सुलझाने के लिए आर्थिक प्रतिबंध लगाने या आवश्यकता पड़ने पर सैन्य हस्तक्षेप की अनुमति देने की शक्ति होती है, जो इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है।

153. (C) सुरक्षा परिषद में महाशक्तियों द्वारा वीटो पावर का प्रयोग।
शीत युद्ध के दौरान, सामूहिक सुरक्षा की प्रभावशीलता में सबसे बड़ी बाधा सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों द्वारा वीटो पावर का बार-बार उपयोग करना था। महाशक्तियों के बीच वैचारिक और राजनीतिक मतभेदों के कारण परिषद अक्सर महत्वपूर्ण निर्णयों पर सहमत नहीं हो पाती थी। इस वीटो शक्ति ने सामूहिक सुरक्षा तंत्र को कई अंतरराष्ट्रीय संकटों के दौरान निष्क्रिय और अप्रभावी बना दिया था।

154. (D) इसके पास एक प्रभावी सामूहिक सुरक्षा तंत्र लागू करने की क्षमता नहीं थी।
राष्ट्र संघ की असफलता का एक मुख्य कारण एक प्रभावी सामूहिक सुरक्षा तंत्र का अभाव था। इस संस्था के पास अपने निर्णयों को लागू करने के लिए पर्याप्त बाध्यकारी शक्ति और सार्वभौमिक सदस्यता नहीं थी। इसके कारण, यह आक्रामक देशों की गतिविधियों को रोकने और विश्व शांति बनाए रखने में विफल रही, जिससे अंततः द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई और संस्था अप्रासंगिक हो गई।

155. (C) पारंपरिक गठबंधन विशिष्ट खतरों हेतु हैं, जबकि सामूहिक सुरक्षा किसी भी आक्रमण हेतु है।
पारंपरिक सैन्य गठबंधन और सामूहिक सुरक्षा के बीच मौलिक अंतर उनके उद्देश्यों में निहित है। सैन्य गठबंधन आम तौर पर किसी विशिष्ट बाहरी खतरे या शत्रु देश के विरुद्ध बनाए जाते हैं। इसके विपरीत, सामूहिक सुरक्षा एक व्यापक प्रणाली है जो किसी भी राज्य द्वारा की जाने वाली आक्रामकता को रोकने के लिए डिज़ाइन की गई है, चाहे वह आक्रमणकारी संगठन का सदस्य हो या नहीं।

156. (B) मुख्य रूप से युद्धविराम की निगरानी और बफर ज़ोन बनाना।
प्रथम पीढ़ी के शांति स्थापना अभियानों का मुख्य केंद्र दो संप्रभु राज्यों के बीच युद्धविराम की निगरानी करना और एक बफर ज़ोन स्थापित करना था। इन मिशनों में सैनिकों को केवल आत्मरक्षा के लिए बल प्रयोग की अनुमति थी और वे हल्के हथियारों से लैस होते थे। इन अभियानों की सफलता के लिए संबंधित संघर्षरत पक्षों की पूर्व सहमति अनिवार्य मानी जाती थी।

157. (D) आंतरिक संघर्षों और गृहयुद्धों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण।
शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व राजनीति का परिदृश्य बदल गया और विभिन्न क्षेत्रों में आंतरिक संघर्षों तथा गृहयुद्धों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। इन जटिल परिस्थितियों ने संयुक्त राष्ट्र को अपनी शांति स्थापना भूमिका का विस्तार करने के लिए मजबूर किया। अब केवल युद्धविराम ही काफी नहीं था, बल्कि राज्य के विघटन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए नई रणनीतियों की आवश्यकता थी।

158. (A) केवल आत्मरक्षा के लिए बल का प्रयोग करना।
बहुआयामी शांति स्थापना अभियानों का दायरा अत्यंत व्यापक होता है, जिसमें मानवाधिकारों की निगरानी, चुनावों का संचालन और स्थानीय पुलिस का प्रशिक्षण जैसे कार्य शामिल हैं। केवल आत्मरक्षा के लिए बल प्रयोग करना प्रथम पीढ़ी के अभियानों की सीमित विशेषता थी। आधुनिक बहुआयामी अभियानों में शांति बनाए रखने और नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बल प्रयोग के नियम अधिक कड़े और विस्तृत होते हैं।

अध्याय 05
समकालीन विश्व में सुरक्षा

1. सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है?
(A) खतरों से स्वतंत्रता
(B) खतरों से आज़ादी
(C) खतरों से मुक्ति
(D) खतरों से बचाव

2. सुरक्षा विषयक अध्ययन करने वाले विद्वानों के अनुसार, किन चीज़ों को सुरक्षा से जुड़ी चीज़ों का विषय बनाया जाना चाहिए?
(A) जिनसे जीवन के 'केंद्रीय मूल्यों' को गहरा खतरा हो
(B) जिनसे राष्ट्र अथवा राज्य के संपूर्ण अस्तित्व को बड़ा खतरा हो
(C) जिनसे देश के प्रत्येक आम नागरिक के दैनिक जीवन को खतरा हो
(D) जिनसे संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था को खतरा हो

3. नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन (A) और एक कारण (R) दिया गया है। सही विकल्प का चयन करें:
अभिकथन (A): सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में सैन्य ख़तरे को किसी देश के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक माना जाता है।
कारण (R): इस ख़तरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है जो सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देता है।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

4. युद्ध की स्थिति में किसी सरकार के पास निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प नहीं होता है?
(A) आत्मसमर्पण करना
(B) दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना
(C) शत्रु को युद्ध के भारी नुकसान का संकेत देकर हमले से रोकना
(D) बिना किसी पूर्व शर्त के विपक्षी पर अचानक हमला करना

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. सुरक्षा-नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे 'अपरोध' कहा जाता है।
2. सुरक्षा-नीति का संबंध युद्ध को सीमित रखने अथवा उसको समाप्त करने से होता है, जिसे 'रक्षा' कहा जाता है।
3. परंपरागत सुरक्षा-नीति का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व शक्ति-संतुलन है।
4. परंपरागत सुरक्षा-नीति में गठबंधन बनाना शामिल नहीं है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2 सही हैं।
(B) केवल 1, 2 और 3 सही हैं।
(C) केवल 3 और 4 सही हैं।
(D) सभी कथन सही हैं।

6. 'शक्ति-संतुलन' को बनाए रखने के लिए सरकारें किस पर ख़ास तौर पर जोर देती हैं?
(A) अपनी आर्थिक शक्ति बढ़ाने पर
(B) अपनी सैन्य-शक्ति बढ़ाने पर
(C) अपनी प्रौद्योगिकी क्षमता बढ़ाने पर
(D) अपनी सांस्कृतिक प्रभाव बढ़ाने पर

7. सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के अनुसार, किसी देश की सुरक्षा को ज़्यादातर ख़तरा कहाँ से होता है?
(A) देश की सीमा के भीतर से
(B) पड़ोसी देशों से
(C) अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से
(D) देश की सीमा के बाहर से

8. निम्नलिखित मदों का मिलान कीजिए:
सूची I: (संधि/समझौता)
P. जैविक हथियार संधि (BWC)
Q. रासायनिक हथियार संधि (CWC)
R. एंटी-बैलेस्टिक मिसाइल संधि (ABM)
S. परमाणु अप्रसार संधि (NPT)
सूची II: (वर्ष)
1. 1997
2. 1968
3. 1972
4. 1972

कूट:
(A) P-3, Q-1, R-4, S-2
(B) P-1, Q-3, R-2, S-4
(C) P-4, Q-2, R-1, S-3
(D) P-2, Q-4, R-3, S-1

अनिच्छुक हैं, जिससे सुधार की दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हो पाती है।

170. (D) एकजुटता के लिए आम सहमति (UfC)
कॉफी क्लब वास्तव में एकजुटता के लिए आम सहमति समूह का एक अनौपचारिक नाम है। इस समूह में पाकिस्तान, इटली और मेक्सिको जैसे देश शामिल हैं जो जी-4 देशों की स्थायी सदस्यता की मांगों का विरोध करते हैं। यह समूह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सुरक्षा परिषद के लोकतांत्रिक विस्तार के लिए केवल अस्थायी सीटों की संख्या बढ़ाने की वकालत करने के लिए जाना जाता है।

171. (C) गैर-सरकारी संगठन और अन्य गैर-राज्य कर्ता।
वैश्विक नागरिक समाज की अवधारणा में मुख्य रूप से गैर-सरकारी संगठन, बहुराष्ट्रीय निगम और विभिन्न नागरिक समूह शामिल होते हैं। ये संस्थाएं किसी राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण के बिना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रहती हैं। वे सामाजिक, पर्यावरणीय और मानवीय मुद्दों पर काम करती हैं और पारंपरिक राज्य-केंद्रित व्यवस्था के पूरक के रूप में उभरकर वैश्विक शासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

172. (B) राज्यों द्वारा किए गए उल्लंघनों की निगरानी और रिपोर्टिंग करके।
मानवाधिकारों से जुड़े गैर-सरकारी संगठन विभिन्न राष्ट्रों द्वारा किए जाने वाले मानवाधिकार उल्लंघनों की निष्पक्ष निगरानी और उनकी विस्तृत रिपोर्टिंग करते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से वे वैश्विक स्तर पर जनमत तैयार करते हैं और सरकारों पर अंतरराष्ट्रीय मानकों के पालन हेतु दबाव बनाते हैं। उनकी रिपोर्टें और अभियान अक्सर नई अंतरराष्ट्रीय संधियों और सुरक्षात्मक कानूनों के निर्माण के लिए आधार प्रदान करते हैं।

173. (D) डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स
डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मानवीय सहायता संगठन है जो युद्ध, आपदा और महामारी से प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता प्रदान करता है। यह संस्था राजनीतिक सीमाओं और पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर निष्पक्ष रूप से पीड़ितों की सेवा करती है। जहाँ सरकारी तंत्र पहुँचने में असमर्थ या अनिच्छुक होता है, वहां यह संगठन जीवन रक्षक सेवाएं प्रदान कर अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराता है।

174. (A) उनकी विशेषज्ञता, सूचना नेटवर्क और जनमत को लामबंद करने की क्षमता पर।
गैर-राज्य कर्ताओं का प्रभाव उनकी किसी सैन्य शक्ति पर नहीं, बल्कि उनकी तकनीकी विशेषज्ञता और सूचना के विशाल नेटवर्क पर आधारित होता है। वे वैश्विक मुद्दों पर जनता की राय को लामबंद करने और जागरूकता फैलाने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। उनकी विश्वसनीयता और वैज्ञानिक डेटा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में महत्वपूर्ण स्थान दिलाते हैं, जिससे वे वैश्विक नीति-निर्माण की दिशा को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं।

175. (C) वे वैश्विक जागरूकता बढ़ाकर और सरकारों पर दबाव डालकर प्रभाव डालते हैं।
वैश्विक शासन के संदर्भ में यह सत्य है कि गैर-राज्य कर्ता अंतरराष्ट्रीय राजनीति के एजेंडे को प्रभावित करने में अनिवार्य शक्ति बन गए हैं। वे अपनी सक्रियता, शोध और जन-जागरूकता अभियानों के माध्यम से सरकारों पर नैतिक दबाव डालते हैं। यद्यपि उनके पास संप्रभु शक्ति नहीं होती, फिर भी वे नए वैश्विक मानदंडों के विकास और अंतरराष्ट्रीय संधियों के क्रियान्वयन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

159. (C) संघर्ष के बाद समाजों का पुनर्निर्माण और स्थायी शांति हेतु संस्थानों की स्थापना।
शांति-निर्माण या पीस-बिल्डिंग का अर्थ संघर्ष के समाप्त होने के बाद समाज का पुनर्निर्माण करना है। इसका मुख्य लक्ष्य उन संस्थाओं और ढांचों की स्थापना करना है जो भविष्य में युद्ध को रोकने और स्थायी शांति सुनिश्चित करने में सहायक हों। इसमें अक्सर राजनीतिक स्थिरता, बुनियादी ढांचे का विकास और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देने वाली विभिन्न विकासात्मक गतिविधियाँ शामिल होती हैं।

160. (A) बहुआयामी अभियानों का दायरा व्यापक होता है और उनमें अक्सर शांति-निर्माण के तत्व शामिल होते हैं।
पारंपरिक और बहुआयामी शांति स्थापना के बीच प्रमुख अंतर उनके कार्यक्षेत्र की व्यापकता में है। जहाँ पारंपरिक अभियान केवल युद्धविराम और सैन्य निगरानी तक सीमित थे, वहीं बहुआयामी अभियानों में शांति-निर्माण के विभिन्न तत्व शामिल होते हैं। इन आधुनिक अभियानों का उद्देश्य केवल युद्ध को रोकना ही नहीं, बल्कि संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करते हुए एक स्थिर शासन प्रणाली स्थापित करना भी है।

161. (D) ब्रेटन वुड्स समझौता
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वर्ष 1944 में आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान की गई थी। इस समझौते का उद्देश्य युद्ध से प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण करना और भविष्य में वैश्विक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना था। इन संस्थाओं को वैश्विक वित्तीय प्रणाली के प्रबंधन और विकासशील देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का उत्तरदायित्व दिया गया।

162. (B) ऋण के लिए लगाई जाने वाली अनिवार्य आर्थिक नीतिगत शर्तें।
संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम वे आर्थिक नीतिगत शर्तें होती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण प्रदान करते समय प्राप्तकर्ता देशों पर लागू की जाती हैं। इन शर्तों का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करना होता है, जिसमें अक्सर राजकोषीय अनुशासन और बाजार सुधारों पर जोर दिया जाता है। हालांकि, ये शर्तें अक्सर संबंधित देश की घरेलू नीतियों में हस्तक्षेप के रूप में देखी जाती हैं।

163. (C) उनकी ऋण शर्तें प्राप्तकर्ता राष्ट्रों की राष्ट्रीय संप्रभुता को कमजोर करती हैं।
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की कड़ी आलोचना का एक मुख्य कारण यह है कि उनकी ऋण शर्तें प्राप्तकर्ता राष्ट्रों की संप्रभुता को प्रभावित करती हैं। ऋण के बदले थोपी गई आर्थिक नीतियां देशों को अपनी प्राथमिकताएं स्वतंत्र रूप से निर्धारित करने से रोकती हैं। आलोचकों का मानना है कि इससे बाहरी शक्तियों का घरेलू मामलों में हस्तक्षेप बढ़ता है और राष्ट्रीय नीति-निर्माण की स्वतंत्रता समाप्त होती है।

164. (D) सामाजिक क्षेत्रों में सरकारी खर्च में वृद्धि।
संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों की शर्तों में सामान्यतः उदारीकरण, निजीकरण और विनियंत्रण जैसे उपाय शामिल होते हैं। इन कार्यक्रमों के तहत सरकारी खर्च में कटौती, विशेष रुप से शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों में, एक प्रमुख शर्त होती है। इसलिए, सामाजिक क्षेत्रों में सरकारी खर्च में वृद्धि करना इन कार्यक्रमों के उद्देश्यों और शर्तों के बिल्कुल विपरीत माना जाता है, जो विवाद का विषय है।

165. (A) वे अक्सर गरीबी और असमानता में वृद्धि करते हैं।
आलोचकों के अनुसार, संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का समाज के कमजोर वर्गों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सामाजिक कल्याण योजनाओं और सार्वजनिक सेवाओं के बजट में कटौती करने से अक्सर गरीबी और आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है। यह स्थिति विकासशील देशों में मानव विकास सूचकांकों को प्रभावित करती है, क्योंकि स्वास्थ्य और बुनियादी शिक्षा तक आम जनता की पहुँच कठिन और महंगी हो जाती है।

166. (B) परिषद की संरचना आज की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग मुख्य रूप से इस तर्क पर आधारित है कि इसकी वर्तमान संरचना पुरानी हो चुकी है। यह 1945 के उत्तर-युद्ध काल की भू-राजनीतिक स्थितियों को दर्शाती है, जबकि वर्तमान विश्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। दुनिया के नए उभरते हुए शक्ति केंद्रों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए परिषद के ढांचे में बदलाव लाना अनिवार्य माना जाता है।

167. (B) इटली
जी-4 राष्ट्रों के समूह में भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील शामिल हैं, जो एक-दूसरे की स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन करते हैं। इटली इस समूह का सदस्य नहीं है, बल्कि वह एकजुटता के लिए आम सहमति समूह का हिस्सा है। इटली जैसे देश सुरक्षा परिषद की स्थायी सीटों में विस्तार का विरोध करते हैं और केवल अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने के पक्षधर हैं।

168. (A) वे स्थायी सीटों में वृद्धि का विरोध करते हैं और केवल अस्थायी सीटें बढ़ाना चाहते हैं।
एकजुटता के लिए आम सहमति या कॉफी क्लब समूह का रुख यह है कि सुरक्षा परिषद की स्थायी श्रेणियों में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए। वे तर्क देते हैं कि नई स्थायी सीटें बनाने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर असमानता बढ़ेगी। इसके बजाय, यह समूह केवल अस्थायी सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव देता है ताकि अधिक से अधिक देशों को बारी-बारी से प्रतिनिधित्व का अवसर मिल सके।

169. (C) चार्टर संशोधन की कठिन प्रक्रिया और पी-5 देशों की अनिच्छा।
सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन की अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। किसी भी बदलाव के लिए पांच स्थायी सदस्यों सहित दो-तिहाई देशों की सहमति आवश्यक है। स्थायी सदस्य अपने वीटो पावर और विशेष स्थिति को साझा करने या कमजोर करने के प्रति

9. शीतयुद्ध के दौरान, संयुक्त राज्य अमरीका के नेतृत्व वाले पश्चिमी गुट और सोवियत संघ की अगुआई वाले साम्यवादी गुट को एक-दूसरे से किस प्रकार का भय था?
(A) आर्थिक पतन का
(B) राजनीतिक अस्थिरता का
(C) सैन्य हमले का
(D) सांस्कृतिक प्रभुत्व का

10. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में असत्य है?
(A) 1946 से 1991 के बीच गृह युद्धों की संख्या में कमी आई।
(B) दूसरे विश्वयुद्ध के बाद ताकतवर देशों ने आंतरिक सुरक्षा पर कम ध्यान दिया।
(C) नव-स्वतंत्र देशों को अंदरूनी सैन्य-संघर्ष की चिंता करनी थी।
(D) अलग राष्ट्र बनाने पर तुले अलगाववादी आंदोलनों से देशों को खतरा था।

11. निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें:
1. ब्रिटेन को केन्या में जूझना पड़ा।
2. फ्रांस को वियतनाम में जूझना पड़ा।
3. उपनिवेशों का आज़ाद होना शुरु हुआ।
4. दूसरा विश्वयुद्ध समाप्त हुआ।
इन घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
(A) 4, 3, 2, 1
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 4, 2, 1, 3
(D) 3, 4, 1, 2

12. एशिया और अफ्रीका के नव- स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की चुनौतियाँ यूरोपीय देशों के मुकाबले किन मायनों में विशिष्ट थीं?
(A) केवल दूसरे देशों से होने वाले बाहरी सैन्य हमले की प्रबल आशंका
(B) बाहरी सैन्य हमले और अंदरुनी सैन्य-संघर्ष की दोहरी चिंता
(C) केवल राष्ट्र की सीमा के भीतर होने वाले आंतरिक सैन्य-संघर्ष की चिंता
(D) न तो बाहरी हमला और न ही अंदरुनी संघर्ष की कोई विशेष चिंता

13. सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में 'न्याय-युद्ध' की परंपरा के अनुसार किसी देश को युद्ध कब करना चाहिए?
(A) केवल राष्ट्र के आर्थिक लाभ और संसाधनों की प्राप्ति के लिए
(B) केवल अपने भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार और आधिपत्य करने के लिए
(C) केवल आत्म-रक्षा या जनसंहार से दूसरों को बचाने के लिए
(D) केवल वैश्विक स्तर पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए

14. निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा का पारंपरिक तरीका नहीं है?
(A) निरस्त्रीकरण
(B) अस्त्र-नियंत्रण
(C) विश्वास की बहाली
(D) मानवीय हस्तक्षेप

15. जैविक हथियार संधि (BWC) किस वर्ष हुई और इसमें क्या प्रतिबंधित किया गया?
(A) 1972; जैविक हथियारों के निर्माण और उनके भंडारण पर प्रतिबंध
(B) 1997; रासायनिक हथियारों के उत्पादन और उनके संचयन पर रोक
(C) 1968; वैश्विक स्तर पर परमाणु हथियारों के प्रसार पर नियंत्रण
(D) 1972; बैलेस्टिक मिसाइलों के रक्षा-कवच के रूप में प्रयोग पर रोक

16. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. रासायनिक हथियार संधि (CWC) पर 193 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं।
2. जैविक हथियार संधि (BWC) पर 155 से ज़्यादा देशों ने हस्ताक्षर किए हैं।
3. दोनों संधियों पर सभी महाशक्तियों ने हस्ताक्षर किए हैं।
4. इन संधियों के बाद महाशक्तियों ने परमाण्विक हथियारों का विकल्प छोड़ दिया।
5. अमरीका तथा सोवियत संघ ने अस्त्र-नियंत्रण का सहारा लिया।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 3 सही हैं।
(B) केवल 1, 2, 3 और 5 सही हैं।
(C) केवल 4 और 5 सही हैं।
(D) सभी कथन सही हैं।

17. एंटी-बैलेस्टिक मिसाइल (ABM) संधि (1972) ने किन दो देशों को बैलेस्टिक मिसाइलों को रक्षा-कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका?
(A) अमरीका और चीन
(B) अमरीका और सोवियत संघ
(C) सोवियत संघ और चीन
(D) ब्रिटेन और फ्रांस

18. परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
(A) इसने 1967 से पूर्व परीक्षण करने वालों को हथियार रखने दिए।
(B) यह संधि आधिकारिक तौर पर वर्ष 1972 में संपन्न हुई थी।
(C) यह विश्व के सभी राष्ट्रों को परमाणु शक्ति बनने का हक देती है।
(D) इसने दुनिया से परमाण्विक आयुधों को पूरी तरह समाप्त कर दिया।

है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(A) केवल 1 और 2 सही हैं।
(B) केवल 3 और 4 सही हैं।
(C) केवल 1, 2 और 4 सही हैं।
(D) केवल 1 और 4 सही हैं।

60. 'अपरोध' (Deterrence) की अवधारणा का क्या अर्थ है?

(A) युद्ध को जीतने की क्षमता
(B) युद्ध की आशंका को रोकना
(C) दुश्मन को पराजित करना
(D) आत्मसमर्पण करना

61. सुरक्षा की परंपरागत धारणा के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शामिल है?

1. बाहरी सुरक्षा
2. आंतरिक सुरक्षा
3. मानवता की सुरक्षा
4. विश्व सुरक्षा

(A) केवल 1
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 3 और 4
(D) उपरोक्त सभी

62. गठबंधन बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है?

(A) विभिन्न राष्ट्रों के मध्य सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना
(B) सदस्य देशों के बीच आपसी आर्थिक व्यापार की वृद्धि करना
(C) वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास में निरंतर सहयोग करना
(D) दूसरे देशों की तुलना में अपनी सैन्य ताकत का असर बढ़ाना

63. नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन (A) और एक कारण (R) दिया गया है। सही विकल्प का चयन करें:

अभिकथन (A): गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं और राष्ट्रीय हितों के बदलने पर गठबंधन भी बदल जाते हैं।

कारण (R): संयुक्त राज्य अमरीका ने 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन दिया, लेकिन बाद में उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।

(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

64. 1946 से 1991 के बीच गृह युद्धों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई?

(A) दोगुनी
(B) बारहगुनी
(C) पाँचगुनी
(D) दसगुनी

65. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन 'अस्त्र-नियंत्रण' को सही ढंग से परिभाषित करता है?

(A) विश्व के सभी प्रकार के घातक हथियारों को पूरी तरह समाप्त करना
(B) हथियारों के उपार्जन हेतु निश्चित कायदे-कानूनों का पालन करना
(C) केवल खतरनाक परमाणु हथियारों के प्रयोग पर वैश्विक प्रतिबंध लगाना
(D) केवल विश्व की बड़ी महाशक्तियों को आधुनिक हथियार रखने की अनुमति

66. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. आतंकवाद
2. मानवाधिकारों का हनन
3. वैश्विक निर्धनता
4. महामारियाँ
5. प्रवासन

इनमें से कौन से खतरे के नए स्रोत माने जाते हैं?

(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 1, 3 और 4
(C) केवल 2, 4 और 5
(D) उपरोक्त सभी

67. संयुक्त राष्ट्रसंघ के भूतपूर्व महासचिव कोफ़ी अन्नान के अनुसार 'मानवता की सुरक्षा' का क्या आशय है?

(A) व्यक्तियों और समुदायों को बाहरी हमलों से बचाना
(B) राज्यों को आर्थिक संकट से बचाना
(C) व्यक्तियों और समुदायों को अंदरूनी खून-खराबा से बचाना
(D) पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना

68. 11 सितंबर 2001 को आतंकवादियों ने अमरीका के किस स्थान पर हमला बोला था?

(A) पेंटागन
(B) व्हाइट हाउस
(C) स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी
(D) वर्ल्ड ट्रेड सेंटर

69. अधिकारों की तीसरी कोटि में किनके अधिकार आते हैं?

(A) राष्ट्र के सभी नागरिकों को प्राप्त होने वाले सामान्य अधिकार
(B) समाज के केवल कमजोर वर्गों जैसे महिलाओं और बच्चों के अधिकार
(C) उपनिवेशीकृत जनता अथवा जातीय और अल्पसंख्यक समूहों के अधिकार
(D) केवल समाज के अत्यंत धनी और प्रभावशाली व्यक्तियों के विशेष अधिकार

(B) 'अभाव से मुक्ति' और 'भय से मुक्ति'
(C) 'शक्ति-संतुलन' और 'गठबंधन निर्माण'
(D) 'निरस्त्रीकरण' और 'अस्त्र-नियंत्रण'

29. निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें:
1. संयुक्त राज्य अमरीका पर 11 सितंबर का हमला।
2. फ्रांस का वियतनाम में युद्ध।
3. संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन।
4. कुवैत पर इराक का हमला।

उपरोक्त घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
(A) 2, 3, 4, 1
(B) 3, 2, 1, 4
(C) 1, 4, 3, 2
(D) 2, 4, 3, 1

30. वैश्विक तापवृद्धि (ग्लोबल वार्मिंग) से यदि समुद्रतल दो मीटर ऊँचा उठता है तो बांग्लादेश का कितना प्रतिशत हिस्सा डूब जाएगा?
(A) 10 प्रतिशत
(B) 30 प्रतिशत
(C) 50 प्रतिशत
(D) 20 प्रतिशत

31. अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की क्या विशेषता है?
(A) यह एक से ज़्यादा देशों में व्याप्त है और उसके निशाने पर कई देशों के नागरिक होते हैं।
(B) यह एक ही देश में व्याप्त होता है।
(C) इसका उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ होता है।
(D) यह केवल सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाता है।

32. मानवाधिकारों की पहली कोटि में कौन-से अधिकार शामिल हैं?
(A) आर्थिक और सामाजिक अधिकार
(B) राजनीतिक अधिकार जैसे अभिव्यक्ति और सभा करने की आज़ादी
(C) उपनिवेशीकृत जनता के अधिकार
(D) जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार

33. निम्नलिखित मदों का मिलान कीजिए:
सूची I: (खतरे का स्रोत)
P. वैश्विक निर्धनता
Q. आतंकवाद
R. महामारी
S. प्रवासन

सूची II: (उदाहरण/प्रकार)
1. एचआईवी-एड्स, बर्ड फ्लू
2. उत्तरी गोलार्द्ध में प्रवासन
3. प्रति व्यक्ति निम्न आय और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि
4. विमान-अपहरण, बम विस्फोट

कूट:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-2, Q-1, R-4, S-3
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

34. 1990 के दशक में किन घटनाओं के कारण यह बहस चल पड़ी कि संयुक्त राष्ट्रसंघ को मानवाधिकारों के हनन की स्थिति में हस्तक्षेप करना चाहिए?
(A) रवांडा में जनसंहार और कुवैत पर इराक का हमला
(B) वियतनाम युद्ध और कोरियाई युद्ध
(C) शीतयुद्ध की समाप्ति
(D) बर्लिन की दीवार का गिरना

35. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. विश्व की कुल जनसंख्या-वृद्धि का 50 फीसदी सिर्फ 6 देशों में घटित हो रहा है।
2. ये देश भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया हैं।
3. अगले 50 सालों में दुनिया के सबसे गरीब देशों में जनसंख्या तीन गुनी बढ़ेगी।
4. इसी अवधि में अनेक धनी देशों की जनसंख्या घटेगी।
5. विश्वस्तर पर यह असमानता उत्तरी गोलार्द्ध के देशों को दक्षिणी गोलार्द्ध के देशों से अलग करती है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 3 सही हैं।
(B) केवल 3, 4 और 5 सही हैं।
(C) केवल 1, 2, 4 और 5 सही हैं।
(D) सभी कथन सही हैं।

36. दुनिया में सबसे ज़्यादा सशस्त्र संघर्ष किस क्षेत्र में होते हैं?
(A) दक्षिण एशिया का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र
(B) लैटिन अमरीका के विकासशील देशों का समूह
(C) मध्य पूर्व के अस्थिर और तनावपूर्ण इलाके
(D) अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देश

37. अंतर्राष्ट्रीय कायदे-कानून आप्रवासी और शरणार्थी में क्या भेद करते हैं?
(A) शरणार्थी अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं, जबकि आप्रवासी मजबूरी में छोड़ते हैं।
(B) दोनों ही अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं।
(C) आप्रवासी अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं, जबकि शरणार्थी मजबूरी में छोड़ते हैं।
(D) दोनों को ही स्वदेश छोड़ने पर मजबूर किया जाता है।

38. 'आंतरिक रूप से विस्थापित जन' किन्हें कहा जाता है?
(A) जो लोग हिंसा के कारण दूसरे देश में चले जाते हैं।
(B) जो लोग अपना घर-बार छोड़ चुके हैं परंतु राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही हैं।
(C) जो लोग बेहतर आर्थिक अवसरों के लिए प्रवास करते हैं।
(D) जो लोग युद्ध के कारण शरणार्थी शिविरों में रहते हैं।

19. नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन (A) और एक कारण (R) दिया गया है। सही विकल्प का चयन करें:
अभिकथन (A): परमाणु अप्रसार संधि (NPT) ने परमाण्विक आयुधों को समाप्त तो नहीं किया लेकिन इन्हें हासिल कर सकने वाले देशों की संख्या ज़रूर कम की।
कारण (R): यह एक अर्थ में अस्त्र-नियंत्रण संधि थी क्योंकि इसने परमाण्विक हथियारों के उपार्जन को कायदे-कानून के दायरे में ला खड़ा किया।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

20. 'विश्वास बहाली' की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(A) प्रतिद्वंद्वी देशों को अचानक सैन्य टकराव के लिए तैयार करना
(B) विभिन्न देशों के मध्य आपसी आर्थिक सहयोग को निरंतर बढ़ावा देना
(C) समान विचारधारा वाले देशों को गठबंधन बनाने हेतु प्रेरित करना
(D) गलतफहमी के कारण होने वाले युद्ध की आशंका को दूर करना

21. निम्नलिखित मदों का मिलान कीजिए:
सूची I: (संकल्पना)
P. अपरोध
Q. रक्षा
R. शक्ति-संतुलन
S. गठबंधन
सूची II: (विवरण)
1. सैन्य हमले को रोकने या उससे रक्षा के लिए समवेत कदम
2. युद्ध की आशंका को रोकना
3. दूसरे देश से अपने शक्ति-संतुलन का पलड़ा अपने पक्ष में बैठाना
4. युद्ध को सीमित रखना या समाप्त करना
कूट:
(A) P-2, Q-4, R-3, S-1
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-2, R-1, S-3
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

22. सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में 'सुरक्षा किसको चाहिए?' इस प्रश्न के जवाब में संदर्भी किसे माना जाता है?
(A) केवल संप्रभु राष्ट्र अथवा राज्य की सीमाओं को
(B) राज्य, व्यक्तियों, समुदायों और संपूर्ण मानवता को
(C) सिर्फ भौगोलिक भूक्षेत्र और शासन करने वाली संस्थाओं को
(D) केवल बड़े और प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को

23. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. मानवता की सुरक्षा
2. विश्व-रक्षा
3. राष्ट्रीय सुरक्षा
4. सामूहिक सुरक्षा
सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को और किन नामों से जाना जाता है?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3 और 4
(C) केवल 1 और 3
(D) केवल 2 और 4

24. 'मानवता की सुरक्षा' का विचार जनता-जनार्दन की सुरक्षा को किससे बढ़कर मानता है?
(A) राज्यों की सुरक्षा से
(B) अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से
(C) सैन्य शक्ति से
(D) आर्थिक समृद्धि से

25. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. सुरक्षित राज्य का मतलब हमेशा सुरक्षित जनता नहीं होता।
2. पिछले 100 वर्षों में जितने लोग विदेशी सेना के हाथों मारे गए उससे कहीं ज़्यादा लोग खुद अपनी ही सरकारों के हाथों मारे गए।
3. मानवता की सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तियों की संरक्षा है।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2 सही हैं।
(B) केवल 2 और 3 सही हैं।
(C) केवल 1 और 3 सही हैं।
(D) 1, 2 और 3 सभी सही हैं।

26. 'मानवता की सुरक्षा' का संकीर्ण अर्थ लेने वाले पैरोकार किस पर जोर देते हैं?
(A) व्यक्तियों को हिंसक खतरों यानी खून-खराबे से बचाने पर
(B) व्यक्तियों को अकाल और महामारी से बचाने पर
(C) व्यक्तियों को आर्थिक असुरक्षा से बचाने पर
(D) व्यक्तियों को मानवीय गरिमा के हनन से बचाने पर

27. 'मानवता की सुरक्षा' का व्यापक अर्थ लेने वाले पैरोकार खतरों की सूची में किन्हें शामिल करने का तर्क देते हैं?
(A) केवल युद्ध और जन-संहार
(B) केवल आतंकवाद
(C) केवल आर्थिक मंदी
(D) अकाल, महामारी और प्राकृतिक आपदाएँ

28. मानवता की रक्षा के व्यापकतम नज़रिए में किन अवधारणाओं पर जोर दिया जाता है?
(A) 'संप्रभुता की रक्षा' और 'क्षेत्रीय अखंडता'

(C) 2, 1, 3, 4
(D) 1, 2, 3, 4

50. भारत की सुरक्षा नीति का दूसरा घटक क्या है?
(A) अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को अधिक सुदृढ़ बनाना
(B) अपने सभी पड़ोसी देशों को सैन्य रूप से बहुत कमजोर करना
(C) विश्व की महाशक्तियों के साथ एक मजबूत सैन्य गठबंधन बनाना
(D) सुरक्षा की दृष्टि से अपनी अर्थव्यवस्था को हमेशा बंद रखना

51. भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु ने किन प्रयासों की हिमायत की थी?
(A) सैन्य गठबंधन, उपनिवेशवाद और शस्त्रों की होड़
(B) अलगाववाद, संरक्षणवाद और परमाणु प्रसार
(C) एशियाई एकता, विउपनिवेशीकरण और निरस्त्रीकरण
(D) साम्यवाद का प्रसार, साम्राज्यवाद और गुप्त कूटनीति

52. नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन (A) और एक कारण (R) दिया गया है। सही विकल्प का चयन करें:
अभिकथन (A): भारत ने गुटनिरपेक्षता के रूप में विश्व-शांति का तीसरा विकल्प सामने रखा।
कारण (R): भारत दो महाशक्तियों की खेमेबाजी से अलग रहना चाहता था।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

53. क्योटो प्रोटोकॉल (1997) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(A) वैश्विक स्तर पर परमाणु हथियारों के प्रसार को प्रभावी ढंग से रोकना
(B) जैविक हथियारों के निर्माण और प्रयोग पर कड़ा प्रतिबंध लगाना
(C) ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर तापवृद्धि रोकना
(D) अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध सदस्य देशों का सहयोग बढ़ाना

54. भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक किससे संबंधित है?
(A) वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निरंतर बढ़ावा देना
(B) देश की आंतरिक सुरक्षा-चुनौतियों से निबटने की तैयारी
(C) पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय सैन्य समझौते सुनिश्चित करना
(D) स्वदेशी सैन्य प्रौद्योगिकी का अन्य देशों को बड़े पैमाने पर निर्यात

55. निम्नलिखित में से कौन भारत में उग्रवादी समूहों से प्रभावित क्षेत्र नहीं रहा है?
(A) नगालैंड
(B) मिजोरम
(C) पंजाब
(D) केरल

56. भारत ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए किस व्यवस्था का पालन किया है?
(A) लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था
(B) तानाशाही राजनीतिक व्यवस्था
(C) एक-दलीय प्रणाली
(D) सैन्य शासन

57. निम्नलिखित मदों का मिलान कीजिए:
सूची I: (भारत की सुरक्षा रणनीति के घटक)
P. पहला घटक
Q. दूसरा घटक
R. तीसरा घटक
S. चौथा घटक
सूची II: (विवरण)
1. अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करना
2. अंदरुनी सुरक्षा समस्याओं से निपटना
3. अर्थव्यवस्था का विकास
4. सैन्य-क्षमता को मजबूत करना
कूट:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-1, R-2, S-3
(C) P-2, Q-3, R-4, S-1
(D) P-4, Q-2, R-1, S-3

58. भारत की सुरक्षा रणनीति का चौथा घटक, अर्थव्यवस्था को विकसित करने का प्रयास, किस उद्देश्य से प्रेरित है?
(A) नागरिकों को गरीबी और अभाव की स्थिति से मुक्त करना
(B) भारत को अल्प समय में एक महान आर्थिक महाशक्ति बनाना
(C) विश्व के विशाल अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों पर पूर्ण कब्ज़ा करना
(D) अपने सभी पड़ोसी देशों को बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता देना

59. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत की लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था विभिन्न समुदायों को अपनी शिकायतें खुलकर रखने का मौका देती है।
2. भारत में लोकतांत्रिक रीति से निर्वाचित सरकार पर आर्थिक संवृद्धि को मानवीय विकास का सहगामी बनाने का दबाव होता है।
3. लोकतंत्र सिर्फ एक राजनीतिक आदर्श है, इसका सुरक्षा से कोई लेना-देना नहीं है।
4. भारत गरीबी और असमानता पर पूरी तरह काबू पा चुका

39. नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन (A) और एक कारण (R) दिया गया है। सही विकल्प का चयन करें:
अभिकथन (A): दक्षिणी गोलार्द्ध के देशों में सशस्त्र संघर्ष और युद्ध के कारण लाखों लोग शरणार्थी बने।
कारण (R): विश्व का शरणार्थी-मानचित्र विश्व के संघर्ष-मानचित्र से लगभग हू-ब-हू मेल खाता है।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

40. 2003 तक पूरी दुनिया में कितने लोग एचआईवी-एड्स से संक्रमित हो चुके थे?
(A) 4 करोड़
(B) 2 करोड़
(C) 3 करोड़
(D) 5 करोड़

41. एचआईवी-एड्स से संक्रमित लोगों में से दो-तिहाई किस महाद्वीप में रहते हैं?
(A) एशिया
(B) यूरोप
(C) अफ्रीका
(D) दक्षिण अमरीका

42. निम्नलिखित मदों का मिलान कीजिए:
सूची I: (देश/क्षेत्र)
P. फ्रांस
Q. ब्रिटेन
R. बोत्सवाना
S. मालदीव
सूची II: (सुरक्षा चिंता)
1. वियतनाम में युद्ध
2. केन्या में संघर्ष
3. वैश्विक तापवृद्धि से डूबने का खतरा
4. एचआईवी-एड्स का गंभीर खतरा
कूट:
(A) P-4, Q-3, R-2, S-1
(B) P-1, Q-2, R-4, S-3
(C) P-2, Q-1, R-3, S-4
(D) P-3, Q-4, R-1, S-2

43. 1994 में रवांडा की किस जनजाति के अस्तित्व पर खतरा मंडराया था?
(A) हुतु
(B) ज़ुलु
(C) योरुबा
(D) तुत्सी

44. सहयोगमूलक सुरक्षा में सैन्य-बल के प्रयोग के संदर्भ में क्या दृष्टिकोण है?
(A) सैन्य-बल का प्रयोग किसी भी स्थिति में बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
(B) सैन्य-बल का प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में सामूहिक रूप से हो
(C) सैन्य-बल का प्रयोग हमेशा प्राथमिक और मुख्य उपाय के रूप में हो।
(D) कोई भी संप्रभु देश अपनी सुरक्षा के लिए स्वतंत्र बल-प्रयोग करे

45. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत को पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों तरह के खतरों का सामना करना पड़ा है।
2. ये खतरे केवल सीमा के बाहर से उभरे हैं।
3. भारत की सुरक्षा-नीति के चार बड़े घटक हैं।
4. भारत की रणनीति समय के साथ स्थिर रही है, उसमें कोई हेर-फेर नहीं हुआ।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 3 सही हैं।
(B) केवल 2 और 4 सही हैं।
(C) केवल 1, 2 और 3 सही हैं।
(D) सभी कथन सही हैं।

46. भारत की सुरक्षा-नीति का पहला घटक क्या है?
(A) अंतर्राष्ट्रीय कायदों को मज़बूत करना
(B) अंदरुनी सुरक्षा-समस्याओं से निपटना
(C) आर्थिक विकास करना
(D) सैन्य-क्षमता को मज़बूत करना

47. भारत ने किन देशों के हमलों का सामना किया है?
(A) पाकिस्तान और चीन
(B) चीन और नेपाल
(C) पाकिस्तान और बांग्लादेश
(D) श्रीलंका और म्यांमार

48. भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण को किस आधार पर उचित ठहराया?
(A) आर्थिक विकास
(B) राष्ट्रीय सुरक्षा
(C) वैज्ञानिक प्रगति
(D) अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा

49. निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें:
1. भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण
2. चीन का भारत पर हमला
3. भारत का पहला परमाणु परीक्षण
4. भारत-पाकिस्तान का कारगिल युद्ध
इन घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
(A) 2, 3, 1, 4
(B) 3, 2, 1, 4

70. निम्नलिखित मदों का मिलान कीजिए:
सूची I: (क्षेत्र/देश)
P. सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देश
Q. बांग्लादेश
R. थाईलैंड
S. अफ्रीका
सूची II: (खतरा/समस्या)
1. दुनिया के सबसे ज़्यादा सशस्त्र संघर्ष
2. समुद्र तल बढ़ने पर 20% हिस्से के डूबने का खतरा
3. एचआईवी-एड्स के दो-तिहाई संक्रमित लोग
4. समुद्र तल बढ़ने पर 50% आबादी को खतरा
कूट:
(A) P-1, Q-2, R-4, S-3
(B) P-2, Q-1, R-3, S-4
(C) P-1, Q-3, R-4, S-2
(D) P-3, Q-4, R-2, S-1

71. 1990 से 1995 के बीच सत्तर देशों के मध्य हुए 93 युद्धों में लगभग कितने लोग मारे गए?
(A) 15 लाख
(B) 25 लाख
(C) 75 लाख
(D) 55 लाख

72. ब्रिटेन को 1990 के दशक के उत्तरार्द्ध में किस महामारी के कारण अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा?
(A) मैड-काऊ
(B) बर्ड फ्लू
(C) सार्स
(D) स्वाइन फ्लू

73. निम्नलिखित युद्धों पर विचार करें:
1. 1965 का भारत-पाकिस्तान युद्ध
2. 1999 का कारगिल युद्ध
3. 1947-48 का भारत-पाकिस्तान युद्ध
4. 1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध
इन युद्धों को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
(A) 3, 1, 4, 2
(B) 1, 3, 2, 4
(C) 3, 4, 1, 2
(D) 4, 1, 3, 2

74. सहयोगमूलक सुरक्षा में कौन-कौन शामिल हो सकते हैं?
(A) राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ, स्वयंसेवी संगठन और अन्य कर्ता
(B) केवल विश्व के विभिन्न संप्रभु राष्ट्र और उनकी सरकारें
(C) केवल प्रभावशाली वैश्विक और क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन
(D) केवल सामाजिक कार्यों में संलग्न अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन

75. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. 'रक्षा' का अर्थ युद्ध को सीमित रखना या समाप्त करना है।
2. 'अपरोध' का अर्थ युद्ध की आशंका को रोकना है।
3. ' शक्ति-संतुलन' का अर्थ है दूसरे देशों पर पूर्ण सैन्य प्रभुत्व स्थापित करना।
4. 'गठबंधन' राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 4 सही हैं।
(B) केवल 1, 3 और 4 सही हैं।
(C) केवल 2 और 3 सही हैं।
(D) सभी कथन सही हैं।

76. भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया?
(A) 1962
(B) 1974
(C) 1971
(D) 1998

77. सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के उदय का एक प्रमुख कारण क्या था?
(A) वैश्विक स्तर पर लंबे समय से चले आ रहे शीत युद्ध की समाप्ति
(B) द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक स्थापना
(C) तापवृद्धि और आतंकवाद जैसे विश्वव्यापी नए खतरों का उदय
(D) विकासशील देशों द्वारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रभावी गठन

78. नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन (A) और एक कारण (R) दिया गया है। सही विकल्प का चयन करें:
अभिकथन (A): सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में सैन्य-बल के प्रयोग से अधिकांश मसलों का हल नहीं हो सकता।
कारण (R): गरीबी मिटाने, आप्रवासियों के प्रबंधन तथा महामारी के नियंत्रण में सैन्य-बल से ख़ास मदद नहीं मिलती, बल्कि मामला और बिगड़ सकता है।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

79. 'सुरक्षा' की अवधारणा के बारे में कौन-सा कथन सबसे उपयुक्त है?
(A) यह एक विवादग्रस्त और भुलैयादार धारणा है।
(B) यह एक सरल और स्पष्ट अवधारणा है।
(C) इसका अर्थ सभी समाजों में एक समान है।
(D) यह केवल सैन्य मामलों तक सीमित है।

80. निम्नलिखित मदों का मिलान कीजिए:

157. 'अभाव से मुक्ति' (freedom from want) की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा खतरा शामिल है?
(A) राज्य प्रायोजित दमन।
(B) आतंकवाद और संगठित अपराध।
(C) युद्ध के कारण विस्थापन।
(D) भुखमरी और बीमारी।

158. निम्नलिखित में से कौन सा यूएनडीपी द्वारा पहचाना गया मानव सुरक्षा का एक घटक नहीं है?
(A) सैन्य सुरक्षा।
(B) स्वास्थ्य सुरक्षा।
(C) पर्यावरणीय सुरक्षा।
(D) राजनीतिक सुरक्षा।

159. 'भय से मुक्ति' (freedom from fear) और 'अभाव से मुक्ति' (freedom from want) के बीच मुख्य अंतर क्या है?
(A) 'भय से मुक्ति' केवल दीर्घकालिक संरचनात्मक खतरों पर और 'अभाव से मुक्ति' केवल तात्कालिक हिंसा पर केंद्रित है।
(B) 'भय से मुक्ति' केवल संप्रभु राज्यों के लिए है और 'अभाव से मुक्ति' केवल निजी व्यक्तियों के लाभ के लिए है।
(C) 'भय से मुक्ति' प्रत्यक्ष हिंसा से संरक्षण पर और 'अभाव से मुक्ति' संरचनात्मक अभावों से संरक्षण पर केंद्रित है।
(D) 'भय से मुक्ति' विशुद्ध रूप से आर्थिक है जबकि 'अभाव से मुक्ति' विशुद्ध रूप से राजनीतिक और वैचारिक है।

160. स्रोत का समग्र निष्कर्ष क्या है?
(A) मानव सुरक्षा एक व्यापक और एकीकृत अवधारणा है जो व्यक्ति की गरिमा और भलाई पर केंद्रित है।
(B) मानव सुरक्षा केवल सैन्य हस्तक्षेप और बल प्रयोग के माध्यम से ही सफलतापूर्वक प्राप्त की जा सकती है।
(C) मानव सुरक्षा एक अत्यंत संकीर्ण और सीमित अवधारणा है जो केवल युद्ध की परिस्थितियों से संबंधित है।
(D) पारंपरिक राज्य सुरक्षा का मॉडल मानव सुरक्षा की आधुनिक अवधारणा से कहीं अधिक व्यावहारिक और महत्वपूर्ण है।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

सहयोगमूलक सुरक्षा का विचार अंतर्राष्ट्रीय 'व्यवस्थाओं' (regimes) की अवधारणा से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत में, एक व्यवस्था को किसी विशेष मुद्दे-क्षेत्र में सिद्धांतों, मानदंडों, नियमों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके चारों ओर अभिनेताओं की अपेक्षाएँ परिवर्तित होती हैं। ये व्यवस्थाएँ उन समस्याओं का प्रबंधन करने के लिए बनाई जाती हैं जो प्रकृति में वैश्विक या पार-राष्ट्रीय हैं, जैसे परमाणु अप्रसार, व्यापार, या पर्यावरण संरक्षण, और जिन्हें कोई एक राज्य अकेले हल नहीं कर सकता। परमाणु अप्रसार संधि (NPT) या क्योटो प्रोटोकॉल जैसी व्यवस्थाएँ इसका उदाहरण हैं। इन व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता एक केंद्रीय प्रवर्तन प्राधिकरण के अभाव में पारस्परिकता और साझा हितों पर निर्भर करती है। राज्य इन नियमों का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि अन्य राज्य भी ऐसा ही करेंगे, और व्यवस्था के बाहर रहने की तुलना में सहयोग करने से अधिक लाभ होगा। यह स्व-हित और सामूहिक कार्रवाई का एक नाजुक संतुलन है। हालांकि ये व्यवस्थाएँ हमेशा सफल नहीं होती हैं, फिर भी वे अंतर्राष्ट्रीय अराजकता को कम करने और साझा खतरों के प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण प्रदान करती हैं, जो सहयोगमूलक सुरक्षा के व्यावहारिक कार्यान्वयन को दर्शाती हैं।

उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

161. अंतर्राष्ट्रीय 'व्यवस्था' (regime) को कैसे परिभाषित किया गया है?
(A) राज्यों के बीच सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए गठित एक औपचारिक वैश्विक सैन्य गठबंधन के रूप में।
(B) सभी देशों की संप्रभुता को समाप्त कर स्थापित की गई एक एकल और सर्वशक्तिमान विश्व सरकार के रूप में।
(C) दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों द्वारा अपने हितों की रक्षा हेतु बनाए गए एक अनौपचारिक क्लब के रूप में।
(D) एक विशिष्ट मुद्दे पर सिद्धांतों, मानदंडों, नियमों और प्रक्रियाओं के समूह के रूप में।

162. स्रोत के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(A) राज्यों पर अपनी विशिष्ट विचारधारा थोपना।
(B) वैश्विक या पार-राष्ट्रीय समस्याओं का प्रबंधन करना।
(C) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना।
(D) कमजोर देशों को नियंत्रित करना।

163. अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता किस पर निर्भर करती है?
(A) एक शक्तिशाली वैश्विक पुलिस बल पर।
(B) सभी राज्यों पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों पर।
(C) पारस्परिकता और साझा हितों पर।
(D) केवल नैतिक अनुनय पर।

164. निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का उदाहरण है?
(A) एक देश की संसद।
(B) एक बहुराष्ट्रीय निगम का निदेशक मंडल।
(C) एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल।
(D) परमाणु अप्रसार संधि (NPT)।

165. स्रोत से यह क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का पालन क्यों करते हैं?
(A) क्योंकि उन्हें विश्वास है कि सहयोग उनके स्व-हित में है और इससे सामूहिक लाभ होता है।
(B) क्योंकि उन्हें एक केंद्रीय विश्व सरकार द्वारा वैश्विक कानूनों के माध्यम से मजबूर किया जाता है।
(C) क्योंकि वे विशुद्ध रूप से केवल नैतिक, परोपकारी और

91. दक्षिण एशियाई इलाके में भारत के चारों तरफ कैसे देश हैं?
(A) गैर-परमाणु हथियार वाले देश
(B) आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े देश
(C) सैन्य तानाशाही वाले देश
(D) परमाणु हथियारों से लैस देश

92. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत ने 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।
2. भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में संयुक्त राष्ट्रसंघ को अंतिम पंच मानने पर जोर दिया है।
3. भारत ने हथियारों के अप्रसार के संबंध में एक सार्वभौम और बिना भेदभाव वाली नीति की पहलकदमी की है।
4. भारत ने नव-अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की माँग उठायी।
5. भारत हमेशा से एक प्रमुख सैन्य गठबंधन का सदस्य रहा है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 3 सही हैं।
(B) केवल 1, 2, 3 और 4 सही हैं।
(C) केवल 3, 4 और 5 सही हैं।
(D) सभी कथन सही हैं।

93. किस देश में एचआईवी-एड्स से गंभीर खतरा है, जहाँ हर 6 वयस्क व्यक्तियों में से एक इस रोग से पीड़ित है?
(A) दक्षिण अफ्रीका
(B) नाइजीरिया
(C) बोत्सवाना
(D) केन्या

94. आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को मानवाधिकारों की किस कोटि में रखा गया है?
(A) पहली कोटि
(B) तीसरी कोटि
(C) इन्हें मानवाधिकार नहीं माना जाता
(D) दूसरी कोटि

95. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. अपरोध
2. रक्षा
3. शक्ति-संतुलन
4. गठबंधन बनाना

सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के मुख्य तत्त्वों में क्या शामिल है?
(A) केवल 1, 2 और 4
(B) केवल 1, 3 और 4
(C) केवल 1 और 2
(D) उपरोक्त सभी

96. पारंपरिक सुरक्षा-नीति में सैन्य-शक्ति का आधार किसे माना जाता है?
(A) केवल सैनिकों की संख्या को
(B) आर्थिक और प्रौद्योगिकी की ताकत को
(C) केवल हथियारों की गुणवत्ता को
(D) देश के भौगोलिक आकार को

97. 1950 के दशक में फ्रांस को किस देश में संघर्ष करना पड़ा?
(A) केन्या
(B) वियतनाम
(C) अल्जीरिया
(D) भारत

98. निम्नलिखित मदों का मिलान कीजिए:
सूची I: (संगठन/व्यक्ति)
P. एमनेस्टी इंटरनेशनल
Q. रेड क्रॉस
R. नेल्सन मंडेला
S. विश्व स्वास्थ्य संगठन

सूची II: (प्रकार/श्रेणी)
1. अंतर्राष्ट्रीय संगठन
2. स्वयंसेवी संगठन
3. जानी-मानी हस्ती
4. स्वयंसेवी संगठन

कूट:
(A) P-2, Q-4, R-3, S-1
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-2, Q-1, R-4, S-3
(D) P-4, Q-3, R-1, S-2

99. 'अभाव से मुक्ति' की अवधारणा का संबंध किससे है?
(A) राजनीतिक स्वतंत्रता से
(B) सैन्य हमलों से सुरक्षा से
(C) आर्थिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा से
(D) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से

100. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन आतंकवाद के बारे में सही नहीं है?
(A) यह राजनीतिक खून-खराबे से संबंधित है।
(B) यह जान-बूझकर नागरिकों को निशाना बनाता है।
(C) यह नागरिकों के असंतोष का इस्तेमाल कर सकता है।
(D) यह एक नई परिघटना है जो 2001 के बाद ही शुरु हुई।

101. सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा पारंपरिक धारणा के किन तत्त्वों पर सवाल उठाती है?
(A) केवल सुरक्षा के तरीकों पर अपनाए जाने वाले सैन्य विकल्पों पर
(B) केवल भविष्य में आने वाले विभिन्न प्रकार के बाहरी खतरों पर
(C) सुरक्षा के संदर्भों, खतरों के प्रकार और सुरक्षा के तरीकों पर
(D) केवल राज्य की संप्रभुता और अखंडता के प्राचीन सिद्धांतों पर

122. किसी मसले को सुरक्षा का मसला कहलाने के लिए सर्व स्वीकृत न्यूनतम मानक क्या है?
(A) अगर मसले से संदर्भी राष्ट्र या जनसमूह के अस्तित्व को खतरा हो
(B) अगर मसले से संप्रभु राष्ट्र अथवा राज्य की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को खतरा हो
(C) अगर किसी विशेष मसले से तत्कालीन केंद्र सरकार के गिरने का गंभीर खतरा हो
(D) अगर किसी मसले से देश के सतत आर्थिक विकास में कोई बड़ी बाधा आ रही हो

123. निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें:
1. रासायनिक हथियार संधि (CWC)
2. परमाणु अप्रसार संधि (NPT)
3. क्योटो प्रोटोकॉल
4. जैविक हथियार संधि (BWC)
इन घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
(A) 2, 4, 1, 3
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 4, 3, 1, 2
(D) 2, 1, 4, 3

124. 'शांति-सेना' का होना स्वयं में एक विरोधाभासी बात क्यों लग सकती है?
(A) क्योंकि शांति-सेना हमेशा युद्ध में विफल रहती है।
(B) क्योंकि शांति और सेना के उद्देश्य परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं।
(C) क्योंकि शांति-सेना का कोई कानूनी आधार नहीं है।
(D) क्योंकि सेना केवल युद्ध के लिए होती है, शांति के लिए नहीं।

125. 1950 और 1960 के दशक में ब्रिटेन को कहाँ जूझना पड़ा?
(A) वियतनाम में
(B) क्यूबा में
(C) केन्या में
(D) मिस्र में

126. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. सैन्य-क्षमता को मजबूत करना।
2. अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करना।
3. देश की अंदरुनी सुरक्षा-समस्याओं से निपटना।
4. अर्थव्यवस्था का विकास कर गरीबी और अभाव से निजात दिलाना।
5. एक प्रमुख सैन्य गठबंधन का नेतृत्व करना।
भारत की सुरक्षा रणनीति के घटकों में इनमें से क्या-क्या शामिल है?
(A) केवल 1, 2, 3 और 5
(B) केवल 2, 3, 4 और 5
(C) केवल 1, 2, 3 और 4
(D) उपरोक्त सभी

127. आज लगभग पूरा विश्व क्यों मानता है कि किसी देश को युद्ध केवल उचित कारणों से करना चाहिए?
(A) क्योंकि यह 'न्याय-युद्ध' की यूरोपीय परंपरा का परवर्ती विस्तार है।
(B) क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यह अनिवार्य कर दिया है।
(C) क्योंकि युद्ध बहुत महंगे हो गए हैं।
(D) क्योंकि आधुनिक हथियार बहुत विनाशकारी हैं।

128. नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन (A) और एक कारण (R) दिया गया है। सही विकल्प का चयन करें:
अभिकथन (A): नव-स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की चुनौतियाँ दोहरी थीं।
कारण (R): उन्हें अपने पड़ोसी देश से सैन्य हमले की आशंका और अंदरुनी सैन्य-संघर्ष, दोनों की चिंता करनी थी।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

129. सुरक्षा की कौन सी धारणा में 'संदर्भ' और 'स्थितियों' को ध्यान में रखना विशेष रुप से ज़रुरी माना जाता है?
(A) केवल पारंपरिक धारणा में
(B) पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों धारणाओं में
(C) केवल अपारंपरिक धारणा में
(D) किसी भी धारणा में नहीं

130. सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में सबसे महत्त्वपूर्ण सहयोग के तरीके कौन से हैं?
(A) निरस्त्रीकरण, अस्त्र-नियंत्रण और आपसी विश्वास की बहाली
(B) सदस्य देशों के मध्य आर्थिक सहायता, व्यापार और प्रत्यक्ष निवेश
(C) सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आदान-प्रदान और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन
(D) पीड़ित राष्ट्रों में मानवीय हस्तक्षेप और कड़े आर्थिक प्रतिबंध

131. निम्नलिखित मदों का मिलान कीजिए:
सूची I: (मानवाधिकार कोटि)
P. पहली कोटि
Q. दूसरी कोटि
R. तीसरी कोटि
S. सार्वभौम मानवाधिकार
सूची II: (अधिकार का प्रकार)
1. आर्थिक और सामाजिक अधिकार
2. उपनिवेशीकृत जनता के अधिकार
3. राजनीतिक अधिकार
4. सभी कोटियों पर आम सहमति का अभाव

5. तमिलनाडु

भारत के किन राज्यों से उग्रवादी समूहों ने अलगाव की कोशिश की है?

(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 1, 2, 3 और 4
(C) केवल 3, 4 और 5
(D) उपरोक्त सभी

113. 1975 में क्यूबा की आयु-प्रत्याशा 70 वर्ष थी, जबकि उसकी निजी आय केवल 540 डॉलर थी। यह क्या दर्शाता है?

(A) राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय और जन-स्वास्थ्य में कोई संबंध नहीं है।
(B) आय और सेवाओं का वितरण समाज के स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है।
(C) क्यूबा उस समय के विश्व का एक अत्यंत समृद्ध और अमीर देश था।
(D) कम राष्ट्रीय आय हमेशा समाज के खराब जन-स्वास्थ्य का कारण बनती है।

114. निम्नलिखित में से कौन-सा अपारंपरिक खतरे से निपटने के लिए एक प्रभावी तरीका होगा?

(A) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से रणनीतियाँ बनाना
(B) सैन्य-संघर्ष
(C) आर्थिक प्रतिबंध
(D) राजनीतिक अलगाव

115. पारंपरिक सुरक्षा की धारणा के अनुसार, सैन्य कार्रवाई से किन्हें खतरा होता है?

(A) केवल युद्ध के मैदान में लड़ रहे सक्रिय और पेशेवर सैनिकों को
(B) केवल देश का संचालन कर रही तत्कालीन केंद्र अथवा राज्य सरकार को
(C) संप्रभुता, अखंडता और आम नागरिकों के बहुमूल्य जीवन को
(D) केवल देश की संपूर्ण औद्योगिक और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को

116. नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन (A) और एक कारण (R) दिया गया है। सही विकल्प का चयन करें:

अभिवथन (A): दूसरे विश्वयुद्ध के बाद, दुनिया के अधिकांश ताकतवर देश अपनी अंदरुनी सुरक्षा के प्रति कमोबेश आश्वस्त थे।

कारण (R): इन देशों के सामने अपनी सीमा के भीतर बसे समुदायों अथवा वर्गों से कोई गंभीर खतरा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना ध्यान सीमापार के खतरों पर केंद्रित किया।

(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

117. विश्व के सशस्त्र संघर्षों में से कितने प्रतिशत अब आंतरिक युद्ध के अंतर्गत हैं?

(A) 50 प्रतिशत
(B) 75 प्रतिशत
(C) 95 प्रतिशत
(D) 100 प्रतिशत

118. महाशक्तियों द्वारा परमाणु हथियारों का विकल्प न छोड़ने के कारण उन्होंने किसका सहारा लिया?

(A) निरस्त्रीकरण
(B) अस्त्र-नियंत्रण
(C) विश्वास की बहाली
(D) सामूहिक सुरक्षा

119. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. पारंपरिक सुरक्षा की धारणा मुख्य रुप से सैन्य बल के प्रयोग की आशंका से संबद्ध है।
2. इस धारणा में माना जाता है कि सैन्य बल से सुरक्षा को खतरा पहुँचता है।
3. इस धारणा में माना जाता है कि सैन्य बल से ही सुरक्षा को कायम रखा जा सकता है।
4. यह धारणा मानती है कि हिंसा का इस्तेमाल असीमित होना चाहिए।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(A) केवल 1 और 2 सही हैं।
(B) केवल 1, 2 और 3 सही हैं।
(C) केवल 3 और 4 सही हैं।
(D) सभी कथन सही हैं।

120. 'भय से मुक्ति' की अवधारणा का संबंध किससे है?

(A) व्यक्तियों का हिंसक खतरों से बचाव
(B) गरीबी और भुखमरी से मुक्ति
(C) राजनीतिक दमन से आज़ादी
(D) प्राकृतिक आपदाओं से बचाव

121. निम्नलिखित मदों का मिलान कीजिए:

सूची I: (खतरा)

P. पारंपरिक बाहरी खतरा
Q. पारंपरिक आंतरिक खतरा
R. अपारंपरिक खतरा
S. खतरे की अनुपस्थिति

सूची II: (उदाहरण)

1. गरीबी और महामारी
2. पड़ोसी देश से सैन्य हमला
3. सहयोगमूलक सुरक्षा
4. अलगाववादी आंदोलन

कूट:

(A) P-2, Q-4, R-1, S-3
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-2, R-1, S-3
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

सूची I: (अवधारणा)
P. मानवता की सुरक्षा (संकीर्ण अर्थ)
Q. मानवता की सुरक्षा (व्यापक अर्थ)
R. आंतरिक रूप से विस्थापित जन
S. शरणार्थी
सूची II: (उदाहरण/परिभाषा)
1. कश्मीरी पंडित
2. युद्ध के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर
3. अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति
4. खून-खराबे से बचाव
कूट:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-3, R-1, S-2
(C) P-3, Q-4, R-2, S-1
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

81. सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में, किसी सरकार द्वारा आत्मसमर्पण करने को उसकी देश-नीति के रूप में प्रचारित क्यों नहीं किया जाता?
(A) क्योंकि यह एक गोपनीय रणनीति है।
(B) क्योंकि यह एक अलोकप्रिय और अस्वीकार्य नीति मानी जाएगी।
(C) क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विरुद्ध है।
(D) क्योंकि यह केवल अंतिम विकल्प के रूप में होता है।

82. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. विश्व-राजनीति में कोई केंद्रीय ताकत नहीं है जो देशों के व्यवहार पर अंकुश रख सके।
2. संयुक्त राष्ट्रसंघ अपने सदस्य देशों से स्वतंत्र एक सर्वोच्च सत्ता है।
3. विश्व-राजनीति में हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी होती है।
4. किसी देश के भीतर हिंसा से निपटने के लिए सरकार नामक एक जानी-पहचानी व्यवस्था होती है।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 3 सही हैं।
(B) केवल 2 और 4 सही हैं।
(C) केवल 1, 3 और 4 सही हैं।
(D) सभी कथन सही हैं।

83. शीतयुद्ध के बाद नव-स्वतंत्र देशों को अपने यूरोपीय औपनिवेशिक शासकों से किस बात का डर था?
(A) आर्थिक प्रतिबंधों का
(B) सांस्कृतिक प्रभुत्व का
(C) कहीं वे उन पर दोबारा हमला न बोल दें
(D) राजनीतिक अलगाव का

84. 'न्याय-युद्ध' की परंपरा के अनुसार, युद्धरत् सेना को किनके प्रति हिंसा से बचना चाहिए?
(A) केवल संघर्षविमुख शत्रु
(B) केवल निहत्थे व्यक्ति
(C) केवल आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु
(D) उपरोक्त सभी

85. SALT-II का पूरा नाम क्या है?
(A) सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि
(B) सामरिक आक्रामक शस्त्र कटौती संधि
(C) सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता-2
(D) सामरिक रक्षा पहल

86. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है?
(A) इसमें मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरे शामिल हैं।
(B) सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा सिर्फ सैन्य खतरों से संबद्ध है।
(C) इसे 'मानवता की सुरक्षा' भी कहा जाता है।
(D) यह व्यक्तियों और समुदायों को भी सुरक्षा का संदर्भी मानती है।

87. निम्नलिखित में से कौन सी एक नई महामारी है जिसके बारे में जानकारी भी कुछ खास नहीं है?
(A) टीबी
(B) मलेरिया
(C) हैजा
(D) एबोला वायरस

88. सहयोगमूलक सुरक्षा में निम्नलिखित में से कौन-सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था शामिल नहीं है?
(A) नाटो (NATO)
(B) विश्व स्वास्थ्य संगठन
(C) विश्व बैंक
(D) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

89. भारत ने अपनी सेना संयुक्त राष्ट्रसंघ के किन मिशनों में भेजी है?
(A) आक्रामक युद्धों में
(B) उपनिवेश स्थापित करने में
(C) शांतिबहाली के मिशनों में
(D) गृह युद्धों में हस्तक्षेप करने में

90. नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन (A) और एक कारण (R) दिया गया है। सही विकल्प का चयन करें:
अभिकथन (A): भारत में लोकतांत्रिक शासन जनता को ज़्यादा सुरक्षा मुहैया कराने का साधन है।
कारण (R): लोकतंत्र में गरीब और वंचित नागरिक अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और निर्वाचित सरकार पर मानवीय विकास के लिए दबाव बना सकते हैं।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

कूट:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-1, R-2, S-4
(C) P-2, Q-3, R-1, S-4
(D) P-3, Q-2, R-4, S-1

132. विश्व की जनसंख्या 21वीं सदी के मध्य तक कितनी हो जाने का अनुमान है?
(A) 800 करोड़
(B) 900 करोड़
(C) 1200 करोड़
(D) 1000 करोड़

133. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन 'शरणार्थी' और 'आप्रवासी' के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है?
(A) राज्यों द्वारा प्रवासियों को स्वीकार करना अनिवार्य है, शरणार्थियों को नहीं
(B) संप्रभु राष्ट्रों को दोनों श्रेणियों के लोगों को स्वीकार करना अनिवार्य होता है
(C) राज्यों द्वारा शरणार्थियों को स्वीकार करना अनिवार्य है, प्रवासियों को नहीं
(D) संप्रभु राष्ट्रों को इनमें से किसी को भी स्वीकार करना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं

134. महामारियाँ जैसे एचआईवी-एड्स, बर्ड फ्लू और सार्स तेजी से विभिन्न देशों में कैसे फैली हैं?
(A) केवल भारी संख्या में होने वाले अवैध आप्रवास की प्रक्रियाओं के जरिए
(B) आप्रवास, व्यवसाय, पर्यटन और सैन्य-अभियानों की प्रक्रियाओं के जरिए
(C) केवल विभिन्न देशों द्वारा संचालित किए जाने वाले सैन्य-अभियानों के जरिए
(D) केवल प्राकृतिक हवा के प्रवाह और पर्यावरणीय परिवर्तनों के माध्यम से

135. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. पुरानी महामारियाँ जैसे टीबी और मलेरिया ने औषधि-प्रतिरोधक रूप धारण कर लिया है।
2. जानवरों में महामारी फैलने के भारी आर्थिक दुष्प्रभाव होते हैं।
3. महामारियाँ बताती हैं कि देशों के बीच पारस्पारिक निर्भरता बढ़ रही है।
4. राष्ट्रीय सीमाएँ अब पहले की तुलना में अधिक सार्थक हो गई हैं।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2 सही हैं।
(B) केवल 1, 2 और 3 सही हैं।
(C) केवल 3 और 4 सही हैं।
(D) सभी कथन सही हैं।

136. सुरक्षा की धारणा में विस्तार का क्या यह मतलब है कि हम हर तरह के कष्ट या बीमारी को सुरक्षा का मसला मान लें?
(A) नहीं, ऐसा करने से सुरक्षा की धारणा में संगति नहीं रह जाएगी।
(B) हाँ, हर कष्ट एक सुरक्षा समस्या है।
(C) केवल गंभीर कष्ट ही सुरक्षा समस्या हैं।
(D) केवल संक्रामक बीमारियाँ ही सुरक्षा समस्या हैं।

137. 1990 के दशक में हिंसा से बचने के लिए कश्मीर घाटी छोड़ने वाले कश्मीरी पंडित किसका उदाहरण हैं?
(A) शरणार्थी
(B) आप्रवासी
(C) आंतरिक रूप से विस्थापित जन
(D) अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक

138. नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन (A) और एक कारण (R) दिया गया है। सही विकल्प का चयन करें:
अभिकथन (A): भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया।
कारण (R): भारतीय सरकार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया क्योंकि भारत के चारों तरफ परमाणु हथियारों से लैस देश हैं।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

139. 'विउपनिवेशीकरण' (Decolonisation) का भारत की सुरक्षा नीति से क्या संबंध है?
(A) यह भारत की सुरक्षा के लिए एक खतरा था।
(B) भारत ने इसका विरोध किया था।
(C) इसका भारत की नीति से कोई संबंध नहीं था।
(D) प्रधानमंत्री नेहरु ने इसकी हिमायत की थी।

140. भारत ने हथियारों के अप्रसार के संबंध में कैसी नीति चलाने की पहलकदमी की?
(A) एक भेदभावपूर्ण नीति जिसमें केवल कुछ देशों को अधिकार हों।
(B) एक सार्वभौम और बिना भेदभाव वाली नीति।
(C) केवल परमाणु हथियारों पर केंद्रित नीति।
(D) केवल जैविक हथियारों पर केंद्रित नीति।

141. निम्नलिखित में से कौन सहयोगमूलक सुरक्षा में एक गैर-राज्य कर्ता का उदाहरण है?
(A) संयुक्त राष्ट्रसंघ
(B) विश्व बैंक
(C) एमनेस्टी इंटरनेशनल
(D) भारत सरकार

102. नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन (A) और एक कारण (R) दिया गया है। सही विकल्प का चयन करें:
अभिकथन (A): वैश्विक तापवृद्धि जैसे विश्वव्यापी खतरों का समाधान कोई भी देश अकेले नहीं कर सकता।
कारण (R): इन समस्याओं की प्रकृति वैश्विक है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाता है।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

103. 'निरस्त्रीकरण' की माँग क्या होती है?
(A) केवल छोटे राज्यों का हथियारों से बाज आना
(B) केवल महाशक्तियों का हथियारों से बाज आना
(C) केवल परमाणु हथियारों का त्याग करना
(D) कुछ खास किस्म के हथियारों से सभी राज्यों का बाज आना

104. START संधि का संबंध किससे है?
(A) सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण
(B) जैविक हथियारों पर रोक
(C) रासायनिक हथियारों पर रोक
(D) आतंकवाद विरोधी सहयोग

105. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. दूसरे विश्वयुद्ध के बाद शीतयुद्ध का दौर चला।
2. इस दौर में पश्चिमी और साम्यवादी गुट एक-दूसरे के आमने-सामने थे।
3. कुछ यूरोपीय देशों को अपने उपनिवेशों में उपनिवेशीकृत जनता से खून-खराबे की चिंता थी।
4. उपनिवेशों ने 1940 के दशक के उत्तरार्द्ध से आजाद होना शुरु किया।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 3 सही हैं।
(B) केवल 2, 3 और 4 सही हैं।
(C) केवल 1 और 4 सही हैं।
(D) उपरोक्त सभी सही हैं।

106. प्रति व्यक्ति उच्च आय और जनसंख्या की कम वृद्धि का लाभ किन देशों को मिलता है?
(A) धनी देशों को
(B) गरीब देशों को
(C) विकासशील देशों को
(D) सभी देशों को समान रुप से

107. निम्नलिखित में से कौन-सा देश उन 6 देशों में शामिल नहीं है जहाँ विश्व की 50% जनसंख्या वृद्धि हो रही है?
(A) भारत
(B) चीन
(C) पाकिस्तान
(D) जापान

108. 'सुरक्षा' को एक भुलैयादार धारणा क्यों माना जाता है?
(A) क्योंकि इसका अर्थ सभी समाजों और सभी समयों में एक समान रहता है।
(B) क्योंकि विभिन्न संदर्भ और स्थितियों में इसका अर्थ बदल जाता है।
(C) क्योंकि यह केवल सैन्य विशेषज्ञों द्वारा समझी जा सकती है।
(D) क्योंकि इस पर कोई अकादमिक अध्ययन नहीं हुआ है।

109. निम्नलिखित मदों का मिलान कीजिए:
सूची I: (युद्ध/संघर्ष)
P. भारत-चीन युद्ध
Q. भारत-पाकिस्तान युद्ध
R. कुवैत पर इराक का हमला
S. अमरीका पर 9/11 हमला

सूची II: (वर्ष)
1. 1999
2. 1962
3. 2001
4. 1990

कूट:
(A) P-2, Q-1, R-4, S-3
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-2, Q-4, R-1, S-3
(D) P-3, Q-1, R-2, S-4

110. 'दक्षिणी गोलार्द्ध' और 'उत्तरी गोलार्द्ध' के बीच की असमानता का मुख्य कारण क्या है?
(A) सैन्य शक्ति में अंतर
(B) सांस्कृतिक मूल्यों में अंतर
(C) भौगोलिक स्थिति में अंतर
(D) प्रति व्यक्ति आय और जनसंख्या वृद्धि दर में अंतर

111. 1990 के दशक में 'विश्व-सुरक्षा' की धारणा क्यों उभरी?
(A) ग्लोबल वार्मिंग और आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्याओं के कारण
(B) पारंपरिक प्रकृति के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सैन्य खतरों के कारण
(C) महाशक्तियों के मध्य चले आ रहे शीत युद्ध के पूर्ण अंत के कारण
(D) संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक स्तर पर अत्यंत कमजोर होने के कारण

112. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. नगालैंड
2. मिजोरम
3. पंजाब
4. कश्मीर

एक राज्य को इतना शक्तिशाली होने से रोकना था कि वह दूसरों पर हावी हो सके। 19वीं शताब्दी में, वियना कांग्रेस के बाद स्थापित 'यूरोप की संगीत-सभा' (Concert of Europe) ने एक बहुध्रुवीय शक्ति संतुलन का प्रबंधन किया, जहाँ प्रमुख शक्तियाँ राजनयिक वार्ताओं के माध्यम से स्थिरता बनाए रखती थीं। शीत युद्ध के दौरान, यह अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक द्विध्रुवीय संरचना में रूपांतरित हो गई, जहाँ परमाणु हथियारों ने 'आतंक के संतुलन' को जन्म दिया। इस प्रणाली में, शक्ति का संतुलन केवल सैन्य क्षमता पर ही नहीं, बल्कि वैचारिक गठबंधनों पर भी आधारित था। समकालीन विश्व में, शक्ति संतुलन अधिक जटिल और बहुध्रुवीय हो गया है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस और यूरोपीय संघ जैसी कई शक्तियाँ तथा क्षेत्रीय शक्तियाँ भी शामिल हैं। यह संतुलन अब केवल सैन्य शक्ति से ही नहीं, बल्कि आर्थिक प्रभाव, तकनीकी नवाचार और राजनयिक कौशल से भी निर्धारित होता है, जो इसे पहले से कहीं अधिक गतिशील और अप्रत्याशित बनाता है।
उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

151. शक्ति संतुलन की अवधारणा का मूल उद्देश्य क्या है?
(A) राज्यों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना।
(B) किसी एक राज्य के प्रभुत्व को रोकना।
(C) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना।
(D) मानवाधिकारों की सार्वभौमिक रक्षा करना।

152. शीत युद्ध के दौरान शक्ति संतुलन की विशेषता क्या थी?
(A) एक द्विध्रुवीय संरचना जो 'आतंक के संतुलन' पर आधारित थी।
(B) एक बहुध्रुवीय प्रणाली जिसमें कई समान और प्रतिस्पर्धी शक्तियाँ थीं।
(C) एकध्रुवीय विश्व जहाँ केवल एक महाशक्ति का पूर्ण वैश्विक प्रभुत्व था।
(D) राजनयिक वार्ताओं पर आधारित एक औपचारिक सामूहिक सुरक्षा प्रणाली।

153. 'यूरोप की संगीत-सभा' (Concert of Europe) ने शक्ति संतुलन को कैसे प्रबंधित किया?
(A) एक शक्तिशाली और एकीकृत वैश्विक सरकार की औपचारिक स्थापना करके।
(B) परमाणु हथियारों के वैश्विक प्रसार और सैन्य उपयोग को प्रभावी ढंग से रोककर।
(C) प्रमुख शक्तियों के बीच राजनयिक वार्ताओं के माध्यम से।
(D) राज्यों के बीच व्यापक और उदार मुक्त व्यापार समझौतों को लागू करके।

154. समकालीन विश्व में शक्ति संतुलन को क्या निर्धारित करता है?
(A) केवल सैन्य क्षमता, हथियारों की कुल संख्या और रक्षा बजट का पूर्ण नियंत्रण।
(B) केवल वैचारिक गठबंधनों, राजनीतिक व्यवस्था और सांस्कृतिक मूल्यों का वैश्विक प्रसार।
(C) केवल संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का कड़ाई से पालन।
(D) सैन्य शक्ति, आर्थिक प्रभाव, तकनीकी नवाचार और राजनयिक कौशल का मिश्रण।

155. स्रोत के अनुसार, शक्ति संतुलन की अवधारणा के ऐतिहासिक विकास का सही क्रम क्या है?
(A) द्विध्रुवीय संरचनात्मक संतुलन → बहुध्रुवीय कूटनीतिक संतुलन → वेस्टफेलियन संप्रभुता आधारित संतुलन।
(B) 'यूरोप की संगीत-सभा' का प्रबंधन → शीत युद्ध का परमाणु संतुलन → वेस्टफेलियन संधि का आधारभूत संतुलन।
(C) वेस्टफेलियन संतुलन → 'यूरोप की संगीत-सभा' का बहुध्रुवीय संतुलन → शीत युद्ध का द्विध्रुवीय संतुलन।
(D) बहुध्रुवीय प्रणाली का संतुलन → एकध्रुवीय प्रभुत्व का संतुलन → द्विध्रुवीय वैचारिक गठबंधनों का संतुलन।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा का एक महत्वपूर्ण आयाम 'मानव सुरक्षा' है, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की 1994 की मानव विकास रिपोर्ट में प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया था। यह दृष्टिकोण राज्य-केंद्रित सुरक्षा के पारंपरिक मॉडल को चुनौती देता है और व्यक्ति को सुरक्षा का मुख्य केंद्र मानता है। रिपोर्ट के अनुसार, मानव सुरक्षा के दो प्रमुख पहलू हैं: 'भय से मुक्ति' (freedom from fear) और 'अभाव से मुक्ति' (freedom from want)। 'भय से मुक्ति' व्यक्तियों को प्रत्यक्ष हिंसा, जैसे कि युद्ध, अपराध, आतंकवाद और राज्य प्रायोजित दमन से बचाने पर केंद्रित है। वहीं, 'अभाव से मुक्ति' का संबंध उन दीर्घकालिक, संरचनात्मक खतरों से है जो मानव की भलाई को कमजोर करते हैं, जैसे कि गरीबी, भुखमरी, बीमारी और पर्यावरणीय क्षरण। इस व्यापक ढांचे के तहत, यूएनडीपी ने मानव सुरक्षा के सात मुख्य घटकों की पहचान की: आर्थिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, सामुदायिक सुरक्षा और राजनीतिक सुरक्षा। यह वर्गीकरण स्पष्ट करता है कि मानव सुरक्षा केवल शारीरिक हिंसा की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक अवसरों और क्षमताओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करती है। यह दृष्टिकोण सुरक्षा को एक समग्र और एकीकृत अवधारणा के रूप में देखता है।
उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

156. 1994 की यूएनडीपी रिपोर्ट के अनुसार, मानव सुरक्षा का मुख्य केंद्र कौन है?
(A) राज्य और उसकी संप्रभुता।
(B) व्यक्ति और उसकी गरिमा।
(C) अंतर्राष्ट्रीय संगठन।
(D) सैन्य गठबंधन और समझौते।

142. पारंपरिक सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में, युद्ध में आम स्त्री-पुरुष को निशाना क्यों बनाया जाता है?
(A) क्योंकि वे युद्ध के मैदान में सबसे आसान और कमजोर लक्ष्य होते हैं।
(B) यह आधुनिक युद्धों का एक दुखद और पूर्णतः अनपेक्षित परिणाम होता है।
(C) क्योंकि वे अक्सर महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों और छावनियों के समीप रहते हैं।
(D) जनता और उनकी चुनी हुई सरकार का मनोबल तोड़ने के उद्देश्य से।

143. निम्नलिखित मदों का मिलान कीजिए:
सूची I: (देश)
P. पाकिस्तान
Q. चीन
R. भारत
S. संयुक्त राज्य अमरीका
सूची II: (संबंधित घटना/नीति)
1. 1962 में भारत पर हमला
2. गुटनिरपेक्षता की नीति
3. 1971 में भारत से युद्ध
4. 11 सितंबर 2001 का हमला
कूट:
(A) P-3, Q-1, R-2, S-4
(B) P-1, Q-3, R-4, S-2
(C) P-3, Q-2, R-4, S-1
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

144. शीतयुद्ध काल में नव-स्वतंत्र देशों द्वारा किसी एक गुट में शामिल होने का क्या परिणाम होता था?
(A) उन्हें तत्काल आर्थिक समृद्धि प्राप्त हो जाती थी।
(B) उन्हें दूसरे खेमे के देशों से दुश्मनी ठाननी पड़ती थी।
(C) वे पूरी तरह से सुरक्षित हो जाते थे।
(D) उनकी संप्रभुता समाप्त हो जाती थी।

145. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. युद्ध के साधन सीमित होने चाहिए।
2. युद्धरत् सेना को निहत्थे व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए।
3. बल प्रयोग तभी किया जाय जब बाकी उपाय असफल हो गए हों।
4. युद्ध किसी भी कारण से किया जा सकता है।
5. 'न्याय-युद्ध' की अवधारणा आधुनिक विश्व में अप्रासंगिक है।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 3 सही हैं।
(B) केवल 1, 2 और 4 सही हैं।
(C) केवल 3, 4 और 5 सही हैं।
(D) सभी कथन सही हैं।

146. सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा का केंद्रीय तर्क क्या है?
(A) मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों पर ध्यान केंद्रित करना।
(B) राज्यों की सुरक्षा सर्वोपरि है।
(C) केवल सैन्य खतरे ही वास्तविक खतरे हैं।
(D) अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को बदलना असंभव है।

147. भारत द्वारा लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को अपनाने का उसकी आंतरिक सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है?
(A) इसके कारण देश के विभिन्न हिस्सों में अलगाववादी आंदोलनों को बल मिला है।
(B) इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का आंतरिक सुरक्षा की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
(C) इसने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने और समूहों को मंच प्रदान करने में मदद की है।
(D) इसके कारण देश में निरंतर राजनीतिक अस्थिरता और द्वेष की स्थिति बढ़ी है।

148. नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन (A) और एक कारण (R) दिया गया है। सही विकल्प का चयन करें:
अभिकथन (A): पारंपरिक सुरक्षा की धारणा में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को एक निर्मम मैदान माना जाता है।
कारण (R): इस धारणा के अनुसार, विश्व-राजनीति में ऐसी कोई केंद्रीय ताकत नहीं है जो देशों के व्यवहार-बरताव पर अंकुश रखने में सक्षम हो।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

149. यदि किसी देश के भीतर रक्तपात हो रहा हो, तो पारंपरिक सुरक्षा की दृष्टि से वह देश सुरक्षित क्यों नहीं माना जा सकता?
(A) क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है।
(B) क्योंकि इससे उसकी आर्थिक प्रगति रुक जाती है।
(C) क्योंकि वह बाहरी हमलों से निपटने की तैयारी नहीं कर सकता।
(D) क्योंकि इससे पड़ोसी देशों से संबंध खराब हो जाते हैं।

150. अंतिम उपाय के रूप में बल-प्रयोग की अनुमति देते समय सहयोगमूलक सुरक्षा की धारणा किस बात पर जोर देती है?
(A) बल-प्रयोग कोई भी एक शक्तिशाली देश कर सकता है।
(B) बल-प्रयोग सामूहिक स्वीकृति से और सामूहिक रूप से किया जाए।
(C) बल-प्रयोग केवल संयुक्त राष्ट्र की सेना द्वारा किया जाए।
(D) बल-प्रयोग की अनुमति कभी नहीं दी जानी चाहिए।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में 'शक्ति संतुलन' एक केंद्रीय स्तंभ रहा है, जिसका ऐतिहासिक विकास अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति को दर्शाता है। वेस्टफेलिया की संधि (1648) के बाद उभरी आधुनिक राज्य-प्रणाली में, इसका उद्देश्य किसी

मानवीय आधार पर ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
(D) क्योंकि वे अन्य शक्तिशाली देशों द्वारा किए जाने वाले संभावित सैन्य आक्रमण या दंड से डरते हैं।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

अपारंपरिक सुरक्षा खतरों के दायरे में, 'पर्यावरणीय सुरक्षा' एक तेजी से उभरता हुआ और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह अवधारणा इस बात पर जोर देती है कि पर्यावरण क्षरण और संसाधनों की कमी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। पारंपरिक रूप से, सुरक्षा को सैन्य खतरों के संदर्भ में देखा जाता था, लेकिन अब यह स्पष्ट है कि पर्यावरणीय तनाव भी संघर्षों को जन्म दे सकते हैं और मानव कल्याण को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जल जैसे साझा संसाधनों की कमी, विशेषकर नदी घाटियों में जो कई देशों से होकर गुजरती हैं, राज्यों के बीच तनाव और यहाँ तक कि संघर्ष का कारण बन सकती है, जिसे 'जल युद्ध' की संज्ञा दी जाती है। इसी तरह, जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि, मरुस्थलीकरण और चरम मौसम की घटनाओं से बड़े पैमाने पर विस्थापन हो सकता है, जिससे 'जलवायु शरणार्थी' (climate refugees) की एक नई श्रेणी उत्पन्न हो रही है। इन विस्थापित आबादी का दबाव मेजबान देशों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर सकता है। इसके अतिरिक्त, सीमा-पार प्रदूषण, जैसे कि एसिड रेन या औद्योगिक कचरे का नदियों में बहाव, पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को खराब कर सकता है। इस प्रकार, पर्यावरणीय सुरक्षा पारंपरिक राज्य-केंद्रित सुरक्षा मॉडल को चुनौती देती है और यह मानती है कि एक स्वस्थ पर्यावरण मानव अस्तित्व और राजनीतिक स्थिरता दोनों के लिए आधारभूत है।

उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

166. 'पर्यावरणीय सुरक्षा' की अवधारणा का केंद्रीय तर्क क्या है?
(A) पर्यावरण संरक्षण एक विशुद्ध रूप से आर्थिक मुद्दा है जिसका राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई सीधा संबंध नहीं है।
(B) पर्यावरण क्षरण और संसाधनों की कमी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे पैदा कर सकते हैं।
(C) केवल उन्नत सैन्य बल और तकनीकी शक्ति ही आधुनिक पर्यावरणीय समस्याओं का पूर्ण समाधान कर सकती है।
(D) पर्यावरण की सुरक्षा करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल विकसित और औद्योगिक देशों की मुख्य जिम्मेदारी है।

167. स्रोत में 'जल युद्ध' की संभावना को किस संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है?
(A) खुले समुद्र और समुद्री मार्गों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए होने वाले नौसैनिक संघर्ष के रूप में।
(B) साझा जल संसाधनों की कमी से उत्पन्न होने वाले राज्य-स्तरीय संघर्ष के रूप में।
(C) स्थानीय क्षेत्रों में वर्षा जल के निजी संग्रहण और वितरण पर होने वाले नागरिक विवाद के रूप में।
(D) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोतलबंद पानी के बढ़ते व्यापारिक बाजार पर एकाधिकार स्थापित करने के रूप में।

168. 'जलवायु शरणार्थी' शब्द से क्या तात्पर्य है?
(A) वे लोग जिन्हें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है।
(B) वे संपन्न लोग जो अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में लंबी छुट्टी बिताने के उद्देश्य से अस्थायी प्रवास करते हैं।
(C) वे वैज्ञानिक जो विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का वैज्ञानिक और अकादमिक अध्ययन करते हैं।
(D) वे सामाजिक कार्यकर्ता जो जलवायु परिवर्तन की समस्याओं के खिलाफ सार्वजनिक मंचों पर विरोध प्रदर्शन करते हैं।

169. पर्यावरणीय सुरक्षा की अवधारणा पारंपरिक सुरक्षा मॉडल को कैसे चुनौती देती है?
(A) यह तर्क देकर कि वर्तमान वैश्विक परिवेश में पारंपरिक सैन्य खतरे अब किसी भी रूप में मौजूद नहीं हैं।
(B) यह व्यावहारिक सुझाव देकर कि सभी संप्रभु राष्ट्रों को अपनी नियमित सेनाओं को तुरंत भंग कर देना चाहिए।
(C) यह प्रदर्शित करके कि गैर-सैन्य, पर्यावरणीय कारक भी संघर्ष और अस्थिरता का कारण बन सकते हैं।
(D) यह कहकर कि केवल अनियंत्रित आर्थिक विकास और औद्योगीकरण ही राष्ट्र की वास्तविक और सच्ची सुरक्षा है।

170. स्रोत के अनुसार, सीमा-पार प्रदूषण का एक संभावित परिणाम क्या हो सकता है?
(A) देशों के बीच आर्थिक सहयोग में वृद्धि।
(B) वैश्विक पर्यटन में वृद्धि।
(C) प्रौद्योगिकी के विकास में तेजी।
(D) पड़ोसी देशों के बीच संबंधों में तनाव।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

भारत की सुरक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ इसकी परमाणु नीति है, जो 'विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध' (Credible Minimum Deterrence) के सिद्धांत पर आधारित है। 1998 में परमाणु परीक्षणों के बाद, भारत ने औपचारिक रूप से अपनी परमाणु सिद्धांत की घोषणा की, जिसका एक प्रमुख तत्व 'पहले उपयोग नहीं' (No First Use - NFU) की नीति है। इस नीति के अनुसार, भारत किसी भी देश के खिलाफ परमाणु हथियारों का प्रयोग करने वाला पहला पक्ष नहीं बनेगा। हालाँकि, यह स्पष्ट किया गया है कि यदि भारतीय क्षेत्र या भारतीय सेना पर कहीं भी परमाणु, रासायनिक या जैविक हमला होता है, तो भारत बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई करेगा जो दुश्मन के लिए असहनीय क्षति सुनिश्चित करेगी। 'न्यूनतम प्रतिरोध' का पहलू इस बात पर जोर देता है कि भारत हथियारों की अंधी दौड़ में शामिल नहीं होगा और केवल उतनी ही परमाणु क्षमता बनाए रखेगा जो एक विश्वसनीय जवाबी हमले के लिए आवश्यक हो। यह सिद्धांत रक्षात्मक प्रकृति का है, जिसका उद्देश्य परमाणु ब्लैकमेल या हमले को रोकना है, न कि आक्रामक उद्देश्यों के लिए इनका उपयोग करना।

11. (A) 4, 3, 2, 1
इन घटनाओं का सही कालक्रम दूसरे विश्वयुद्ध की समाप्ति (1945) से शुरू होता है। इसके उपरांत 1940 के दशक के उत्तरार्द्ध से विभिन्न उपनिवेशों का आजाद होना प्रारंभ हुआ। फ्रांस को 1950 के दशक के दौरान वियतनाम में गंभीर सैन्य संघर्षों का सामना करना पड़ा। अंत में 1950 के दशक के उत्तरार्द्ध और 1960 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में ब्रिटेन को केन्या में औपनिवेशिक विद्रोहों और संघर्षों से जूझना पड़ा था।

12. (B) बाहरी सैन्य हमले और अंदरूनी सैन्य-संघर्ष की दोहरी चिंता
एशिया और अफ्रीका के नव-स्वतंत्र देशों की सुरक्षा चुनौतियाँ यूरोपीय देशों से भिन्न और अधिक जटिल थीं। इन देशों को न केवल पड़ोसी देशों से बाहरी सैन्य हमले की आशंका रहती थी, बल्कि उन्हें अपने ही देश की सीमाओं के भीतर होने वाले आंतरिक सैन्य संघर्षों और अलगाववादी आंदोलनों की भी चिंता थी। इस प्रकार इन राष्ट्रों को बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के दोहरे मोर्चे पर निरंतर संघर्ष करना पड़ा था।

13. (C) केवल आत्म-रक्षा या जनसंहार से दूसरों को बचाने के लिए
पारंपरिक सुरक्षा धारणा के अंतर्गत 'न्याय-युद्ध' की परंपरा यह स्पष्ट करती है कि युद्ध केवल उचित कारणों से ही किया जाना चाहिए। इसके अनुसार किसी देश को सैन्य बल का प्रयोग केवल अपनी आत्म-रक्षा के लिए या दूसरों को जनसंहार से बचाने के उद्देश्य से करना चाहिए। यह विचार संसाधनों पर कब्जे या क्षेत्रीय विस्तार के लिए युद्ध करने की कड़ी निंदा करता है और उसे पूर्णतः अनैतिक मानता है।

14. (D) मानवीय हस्तक्षेप
सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों में निस्त्रीकरण, अस्त्र-नियंत्रण और विश्वास की बहाली जैसे उपाय शामिल हैं जो मुख्य रूप से राज्यों के बीच सैन्य टकराव को रोकने पर केंद्रित होते हैं। इसके विपरीत मानवीय हस्तक्षेप सुरक्षा की एक अपारंपरिक धारणा है। इसमें मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बाहरी शक्तियों द्वारा किसी देश के आंतरिक मामलों में दखल दिया जाता है, जो संप्रभुता के पारंपरिक सैन्य-केंद्रित सिद्धांतों से पूरी तरह मेल नहीं खाता है।

15. (A) 1972; जैविक हथियारों के निर्माण और उनके भंडारण पर प्रतिबंध
जैविक हथियार संधि वर्ष 1972 में संपन्न हुई थी। इस अंतरराष्ट्रीय समझौते का मुख्य उद्देश्य जैविक हथियारों के निर्माण, विकास और उनके भंडारण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना था। इस संधि के माध्यम से सदस्य देशों ने घातक जैविक एजेंटों के युद्ध में प्रयोग को रोकने की प्रतिबद्धता जताई। यह संधि सामूहिक विनाश के हथियारों को नियंत्रित करने की दिशा में पारंपरिक सुरक्षा नीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।

16. (B) केवल 1, 2, 3 और 5 सही हैं।
रासायनिक और जैविक हथियार संधियों पर दुनिया के अधिकांश देशों और महाशक्तियों ने हस्ताक्षर किए हैं। यद्यपि इन देशों ने जैविक और रासायनिक हथियारों को प्रतिबंधित किया, परंतु उन्होंने परमाणु हथियारों का विकल्प कभी नहीं छोड़ा। इसके बजाय अमरीका और सोवियत संघ जैसे देशों ने अस्त्र-नियंत्रण का सहारा लिया ताकि परमाणु हथियारों के प्रसार और उपयोग को कायदे-कानून के दायरे में रखकर सैन्य स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

17. (B) अमरीका और सोवियत संघ
एंटी-बैलेस्टिक मिसाइल संधि वर्ष 1972 में संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ के बीच हुई थी। इस संधि का मुख्य उद्देश्य दोनों महाशक्तियों को बैलेस्टिक मिसाइलों के खिलाफ रक्षा-कवच तैयार करने से रोकना था। इसका तर्क यह था कि यदि दोनों पक्ष असुरक्षित रहेंगे, तो कोई भी युद्ध शुरू करने की हिम्मत नहीं करेगा। यह संधि शीतयुद्ध के दौरान अस्त्र-नियंत्रण की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावी रणनीतिक कदम थी।

18. (A) इसने 1967 से पूर्व परीक्षण करने वालों को हथियार रखने दिए।
परमाणु अप्रसार संधि एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो दुनिया में परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकने का प्रयास करता है। इस संधि की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसने केवल उन्हीं देशों को परमाणु हथियार रखने की अनुमति दी जिन्होंने 1967 से पहले इनका परीक्षण कर लिया था। अन्य देशों के लिए परमाणु तकनीक और हथियारों को हासिल करने पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़े कानूनी प्रतिबंध लगाए गए हैं।

19. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
परमाणु अप्रसार संधि ने दुनिया से परमाणु हथियारों को पूरी तरह समाप्त नहीं किया, बल्कि उन्हें हासिल करने वाले देशों की संख्या को सीमित कर दिया। यह एक महत्वपूर्ण अस्त्र-नियंत्रण संधि थी क्योंकि इसने परमाणु हथियारों के उपार्जन और उपयोग को अंतरराष्ट्रीय नियमों के दायरे में ला खड़ा किया। इस प्रकार इस संधि ने परमाणु शक्ति के विस्तार को नियंत्रित करने और उसे विनियमित करने में एक निर्णायक भूमिका निभाई।

20. (D) गलतफहमी के कारण होने वाले युद्ध की आशंका को दूर करना
विश्वास बहाली की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच व्याप्त संदेह और असुरक्षा की भावना को कम करना है। इसके माध्यम से देश अपनी सैन्य गतिविधियों और योजनाओं की जानकारी साझा करते हैं ताकि किसी गलतफहमी के कारण युद्ध न छिड़ जाए। यह प्रक्रिया संचार के खुले रास्ते सुनिश्चित करती है, जिससे अचानक होने वाले सैन्य टकराव की आशंका दूर होती है और सीमा पर स्थिरता बनी रहती है।

21. (A) P-2, Q-4, R-3, S-1
सुरक्षा नीति के विभिन्न अंगों के विशिष्ट अर्थ हैं। अपरोध का अर्थ युद्ध की आशंका को रोकना है, जबकि रक्षा का संबंध जारी युद्ध को सीमित या समाप्त करने से है। शक्ति-संतुलन के तहत देश अपनी शक्ति प्रतिद्वंद्वी के बराबर रखने का प्रयास करते हैं। गठबंधन सैन्य हमलों को रोकने या उनसे रक्षा के लिए

ANSWERS

1. (B) खतरों से आज़ादी
सुरक्षा का बुनियादी और सामान्य अर्थ खतरों से आज़ादी है। यद्यपि मानव जीवन में पग-पग पर अनेक छोटे-मोटे जोखिम और खतरे विद्यमान रहते हैं, किंतु सुरक्षा के अध्ययन में केवल उन्हीं गंभीर खतरों को शामिल किया जाता है जो जीवन के केंद्रीय मूल्यों के लिए बड़ा संकट पैदा करते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य समाज या राष्ट्र के अस्तित्व को सुरक्षित रखना और स्थिरता सुनिश्चित करना होता है।

2. (A) जिनसे जीवन के 'केंद्रीय मूल्यों' को गहरा खतरा हो
सुरक्षा विषयक अध्ययन करने वाले विद्वानों के अनुसार केवल उन्हीं चुनौतियों को सुरक्षा का विषय बनाया जाना चाहिए जिनसे जीवन के 'केंद्रीय मूल्यों' को गहरा खतरा हो। यदि समाज की हर छोटी समस्या को सुरक्षा की श्रेणी में रख दिया जाएगा, तो इसकी व्यापकता बहुत बढ़ जाएगी और मुख्य खतरों पर ध्यान केंद्रित करना कठिन होगा। अतः अस्तित्व को संकट में डालने वाले गंभीर मुद्दे ही इसमें शामिल हैं।

3. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में सैन्य ख़तरे को किसी भी देश के लिए सर्वाधिक खतरनाक माना जाता है। इस संकट का मुख्य स्रोत प्रायः कोई अन्य देश होता है जो सैन्य बल के माध्यम से किसी राष्ट्र की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता को सीधी चुनौती देता है। ऐसे हमले न केवल सरकार बल्कि आम नागरिकों के जीवन और उनके अस्तित्व को भी गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं।

4. (D) बिना किसी पूर्व शर्त के विपक्षी पर अचानक हमला करना
युद्ध की स्थिति में सरकारों के पास मुख्य रूप से तीन विकल्प होते हैं। पहला विकल्प आत्मसमर्पण करना है, दूसरा शत्रु को युद्ध के भारी नुकसान का संकेत देकर उसे हमले से रोकना है, और तीसरा हमला होने पर अपनी रक्षा करना है। बिना किसी पूर्व शर्त के विपक्षी पर अचानक हमला करना पारंपरिक सुरक्षा नीति के अंतर्गत सरकार के एक सामान्य और नैतिक विकल्प के रूप में शामिल नहीं होता है।

5. (B) केवल 1, 2 और 3 सही हैं।
पारंपरिक सुरक्षा नीति के तीन प्रमुख अंग अपरोध, रक्षा और शक्ति-संतुलन हैं। अपरोध का मुख्य उद्देश्य शत्रु को युद्ध शुरू करने से रोकना होता है, जबकि रक्षा का संबंध युद्ध शुरू होने के बाद उसे सीमित या समाप्त करने से है। शक्ति-संतुलन के माध्यम से देश प्रतिद्वंद्वी के मुकाबले स्वयं को सैन्य रूप से सक्षम रखते हैं। गठबंधन बनाना भी इस पारंपरिक सुरक्षा नीति का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है।

6. (B) अपनी सैन्य-शक्ति बढ़ाने पर
शक्ति-संतुलन बनाए रखने के लिए सरकारें अपनी सैन्य-शक्ति को बढ़ाने पर विशेष बल देती हैं। इसके तहत आधुनिक हथियारों का संचय, सेना का सुदृढ़ीकरण और रक्षा प्रणालियों में निरंतर सुधार किया जाता है। यद्यपि आर्थिक और तकनीकी प्रगति भी महत्वपूर्ण है, परंतु मुख्य उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी देशों के मुकाबले स्वयं को सैन्य रूप से सशक्त बनाना है ताकि कोई भी देश दूसरे पर हावी न हो सके और संतुलन बना रहे।

7. (D) देश की सीमा के बाहर से
सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के अनुसार किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा उसकी सीमाओं के बाहर से उत्पन्न होता है। यह दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि संप्रभु राज्यों को अन्य राष्ट्रों की सैन्य कार्रवाइयों से निरंतर सावधान रहना चाहिए। बाहरी सैन्य हमले देश की अखंडता और स्वतंत्रता को सीधे प्रभावित करते हैं, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतियाँ मुख्य रूप से बाहरी खतरों को रोकने पर केंद्रित होती हैं।

8. (A) P-3, Q-1, R-4, S-2
वैश्विक सुरक्षा के लिए विभिन्न संधियाँ महत्वपूर्ण हैं। जैविक हथियार संधि वर्ष 1972 में संपन्न हुई थी, जबकि रासायनिक हथियार संधि 1997 में लागू हुई। एंटी-बैलेस्टिक मिसाइल संधि पर भी 1972 में हस्ताक्षर किए गए थे ताकि मिसाइल रक्षा प्रणालियों को सीमित किया जा सके। अंततः परमाणु अप्रसार संधि 1968 में लाई गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में परमाणु हथियारों के विस्तार को प्रभावी ढंग से रोकना था।

9. (C) सैन्य हमले का
शीतयुद्ध के दौरान अमरीका के नेतृत्व वाले पश्चिमी गुट और सोवियत संघ के नेतृत्व वाले साम्यवादी गुट के बीच भारी तनाव व्याप्त था। दोनों ही पक्षों को एक-दूसरे से सैन्य हमले का गहरा भय रहता था। इसी डर के कारण उन्होंने विशाल सैन्य गठबंधन बनाए और हथियारों की भीषण होड़ में शामिल हुए। सैन्य हमले की इसी आशंका ने उस दौर की अंतरराष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा नीतियों को निर्धारित किया था।

10. (A) 1946 से 1991 के बीच गृह युद्धों की संख्या में कमी आई।
ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार वर्ष 1946 से 1991 के बीच विश्व स्तर पर गृह युद्धों की संख्या में भारी वृद्धि हुई थी, न कि कमी। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद जहाँ ताकतवर देश अपनी बाहरी सुरक्षा पर ध्यान दे रहे थे, वहीं एशिया और अफ्रीका के नव-स्वतंत्र देश आंतरिक सैन्य संघर्षों और अलगाववादी आंदोलनों से जूझ रहे थे। यह कहना बिल्कुल गलत है कि इस कालखंड में आंतरिक संघर्षों की संख्या कम हुई थी।

76. (B) 1974
भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण वर्ष 1974 में राजस्थान के पोखरण में किया था। इस परीक्षण को 'स्माइलिंग बुद्धा' का कूट नाम दिया गया था। यद्यपि भारत ने इसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया गया परीक्षण बताया था, परंतु इसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की वैज्ञानिक और रणनीतिक क्षमता का लोहा मनवाया। यह कदम भारत की सुरक्षा नीति में अपनी सैन्य और तकनीकी ताकत को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक पड़ाव था।

77. (C) तापवृद्धि और आतंकवाद जैसे विश्वव्यापी नए खतरों का उदय
सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के उदय का मुख्य कारण वैश्विक तापवृद्धि (ग्लोबल वार्मिंग), अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और महामारियों जैसे नए प्रकार के खतरों का सामने आना है। ये खतरे केवल किसी एक देश की सीमा तक सीमित नहीं हैं और न ही इन्हें सैन्य बल से पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। इन चुनौतियों की वैश्विक प्रकृति ने सुरक्षा के दायरे को बढ़ाकर उसमें मानवीय अस्तित्व और वैश्विक सहयोग को शामिल करना अनिवार्य बना दिया है।

78. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा यह मानती है कि सैन्य बल हर समस्या का समाधान नहीं हो सकता। गरीबी उन्मूलन, महामारियों के नियंत्रण और प्रवासन जैसी जटिल समस्याओं को सेना के जरिए हल नहीं किया जा सकता है। वास्तव में इन मामलों में सैन्य हस्तक्षेप स्थिति को और अधिक बिगाड़ सकता है। इन चुनौतियों के लिए आर्थिक सुधारों, स्वास्थ्य सेवाओं और अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक सहयोग की आवश्यकता होती है, जो सैन्य-शक्ति के दायरे से बिल्कुल बाहर के विषय हैं।

79. (A) यह एक विवादग्रस्त और भुलैयादार धारणा है।
सुरक्षा की अवधारणा को एक विवादग्रस्त और भुलैयादार धारणा माना जाता है क्योंकि इसका अर्थ संदर्भ और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। अलग-अलग समाजों और राष्ट्रों के लिए सुरक्षा की प्राथमिकताएं भिन्न हो सकती हैं। जहाँ एक देश के लिए बाहरी सैन्य हमला सबसे बड़ा खतरा है, वहीं दूसरे के लिए गरीबी या पर्यावरण संकट मुख्य चुनौती हो सकती है। इसी विविधता के कारण सुरक्षा की कोई एक सार्वभौमिक परिभाषा देना अत्यंत कठिन कार्य है।

80. (B) P-4, Q-3, R-1, S-2
मानवता की सुरक्षा का संकीर्ण अर्थ खून-खराबे से बचाव है, जबकि व्यापक अर्थ अभाव और भय से मुक्ति है। कश्मीर घाटी से विस्थापित हुए कश्मीरी पंडित आंतरिक रूप से विस्थापित जन का सटीक उदाहरण हैं क्योंकि उन्होंने अपनी राष्ट्रीय सीमा नहीं छोड़ी थी। वहीं युद्ध के कारण मजबूरी में अपना देश छोड़कर अन्यत्र जाने वाले लोग शरणार्थी कहलाते हैं। यह मिलान सुरक्षा के विभिन्न मानवीय और विस्थापन संबंधी आयामों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।

81. (B) क्योंकि यह एक अलोकप्रिय और अस्वीकार्य नीति मानी जाएगी।
सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में किसी सरकार द्वारा शत्रु के सामने आत्मसमर्पण करने को कभी भी आधिकारिक देश-नीति के रूप में प्रचारित नहीं किया जाता है। इसका कारण यह है कि किसी भी संप्रभु राष्ट्र की जनता के लिए अपनी सरकार का झुकना और संप्रभुता का त्याग करना एक अपमानजनक, अलोकप्रिय और पूर्णतः अस्वीकार्य कृत्य माना जाता है। सरकारें सदैव अपनी रक्षा और संघर्ष करने की क्षमता को ही अपनी मुख्य नीति के रूप में प्रदर्शित करती हैं।

82. (C) केवल 1, 3 और 4 सही हैं।
विश्व-राजनीति में कोई ऐसी केंद्रीय सर्वोच्च सत्ता नहीं है जो देशों के व्यवहार पर अंकुश लगा सके, इसलिए हर देश को अपनी सुरक्षा का जिम्मा स्वयं उठाना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र अपने सदस्य देशों से स्वतंत्र कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रों का एक संगठन मात्र है। इसके विपरीत किसी देश के भीतर सरकार नामक व्यवस्था आंतरिक हिंसा से निपटने में सक्षम होती है। अतः विकल्प 1, 3 और 4 अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की यथार्थवादी स्थिति दर्शाते हैं।

83. (C) कहीं वे उन पर दोबारा हमला न बोल दें
शीतयुद्ध के दौरान और उसके बाद भी एशिया और अफ्रीका के नव-स्वतंत्र देशों के मन में अपने पुराने यूरोपीय औपनिवेशिक शासकों को लेकर गहरा संदेह व्याप्त था। उन्हें निरंतर यह भय सताता रहता था कि कहीं उनके पूर्व आका अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग कर उन पर दोबारा हमला न कर दें और उन्हें फिर से गुलाम न बना लें। इस असुरक्षा की भावना ने इन देशों को अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।

84. (D) उपरोक्त सभी
'न्याय-युद्ध' की प्राचीन और आधुनिक परंपरा यह मानती है कि युद्ध के साधन हमेशा सीमित होने चाहिए। इसके अनुसार युद्धरत् सेना को उन लोगों के प्रति हिंसा करने से बचना चाहिए जो सीधे युद्ध में शामिल नहीं हैं। इसमें संघर्षविमुख शत्रु, निहत्थे नागरिक और आत्मसमर्पण करने वाले सैनिक शामिल हैं। यह विचार इस नैतिक सिद्धांत पर टिका है कि युद्ध केवल आवश्यक सैन्य लक्ष्यों तक ही सीमित रहना चाहिए और निरपराधों को नहीं मारना चाहिए।

85. (C) सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता-2
SALT-II का पूरा नाम 'सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता-2' (Strategic Arms Limitation Talks-II) है। यह अमरीका और सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों की होड़ को नियंत्रित करने के लिए की गई वार्ताओं का दूसरा चरण था। वर्ष 1979 में इस पर हस्ताक्षर हुए थे। इसका मुख्य उद्देश्य लंबी दूरी के परमाणु प्रक्षेपास्त्रों और हथियारों की संख्या को सीमित करना था ताकि शीतयुद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के बीच खतरनाक परमाणु तनाव को कम किया जा सके।

विभिन्न देशों द्वारा मिलकर उठाए गए सामूहिक और समन्वित सैन्य कदमों को कहा जाता है।

22. (B) राज्य, व्यक्तियों, समुदायों और संपूर्ण मानवता को
सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में सुरक्षा का संदर्भी केवल राज्य की सीमाओं तक सीमित नहीं है। इसमें व्यक्तियों, समुदायों और संपूर्ण मानवता की सुरक्षा को केंद्र में रखा जाता है। इस दृष्टिकोण का तर्क है कि यदि जनता ही सुरक्षित नहीं है, तो राज्य की सुरक्षा का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः यह विचारधारा मानवीय अस्तित्व और गरिमा को प्रभावित करने वाले व्यापक वैश्विक खतरों पर ध्यान केंद्रित करती है।

23. (A) केवल 1 और 2
सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को 'मानवता की सुरक्षा' और 'विश्व-रक्षा' जैसे नामों से भी जाना जाता है। ये अवधारणाएँ इस बात पर जोर देती हैं कि आज के युग में खतरे केवल सीमाओं तक सीमित नहीं हैं। वैश्विक तापवृद्धि और महामारियों जैसे संकट पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। इसलिए सुरक्षा का दायरा बढ़ाकर इसमें केवल राष्ट्रों के बजाय संपूर्ण मानव जाति और वैश्विक हितों को शामिल किया गया है।

24. (A) राज्यों की सुरक्षा से
मानवता की सुरक्षा का विचार इस तर्क पर आधारित है कि जनता की सुरक्षा राज्यों की सुरक्षा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इस अवधारणा के समर्थकों का मानना है कि केवल सीमाओं को सुरक्षित कर लेने से नागरिक सुरक्षित नहीं हो जाते। कई बार सरकारों की अपनी नीतियां ही लोगों के लिए खतरा बन जाती हैं, इसलिए व्यक्ति की सुरक्षा को राज्य की संप्रभुता से ऊपर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

25. (D) 1, 2 और 3 सभी सही हैं।
मानवता की सुरक्षा से जुड़े ये तीनों कथन पूरी तरह सत्य हैं। एक सुरक्षित राज्य का यह अर्थ कदापि नहीं है कि वहाँ की जनता भी सुरक्षित है। पिछले सौ वर्षों के आंकड़े दर्शाते हैं कि विदेशी सेनाओं की तुलना में लोगों को अपनी ही सरकारों से अधिक खतरा रहा है। इसीलिए मानवता की सुरक्षा का मुख्य लक्ष्य व्यक्तियों की संरक्षा सुनिश्चित करना है ताकि वे हर भय से मुक्त रहें।

26. (A) व्यक्तियों को हिंसक खतरों यानी खून-खराबे से बचाने पर
मानवता की सुरक्षा का संकीर्ण अर्थ रखने वाले विद्वान केवल हिंसक खतरों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। उनका मुख्य जोर व्यक्तियों को युद्ध, जनसंहार और आपसी खून-खराबे से बचाने पर होता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार सुरक्षा का प्राथमिक कार्य लोगों को शारीरिक हिंसा और मृत्यु के तात्कालिक भय से मुक्त करना है। वे अन्य सामाजिक समस्याओं को सुरक्षा के इस सीमित दायरे से बाहर रखने का तर्क देते हैं।

27. (D) अकाल, महामारी और प्राकृतिक आपदाएँ
मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ रखने वाले पैरोकार खतरों की सूची में अकाल, महामारी और प्राकृतिक आपदाओं जैसे विषयों को भी शामिल करते हैं। उनका तर्क है कि ये आपदाएं युद्धों की तुलना में कहीं अधिक जनहानि करती हैं। इसलिए व्यक्तियों को केवल हिंसक झड़पों से ही नहीं, बल्कि भूख, बीमारी और प्राकृतिक प्रकोपों से बचाना भी सुरक्षा की अवधारणा का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग होना चाहिए।

28. (B) 'अभाव से मुक्ति' और 'भय से मुक्ति'
मानवता की रक्षा के व्यापकतम दृष्टिकोण में 'अभाव से मुक्ति' और 'भय से मुक्ति' की अवधारणाओं पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। 'भय से मुक्ति' का संबंध व्यक्तियों को हिंसा और खून-खराबे से बचाने से है, जबकि 'अभाव से मुक्ति' का तात्पर्य गरीबी, भुखमरी और बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करना है। ये दोनों मिलकर एक ऐसे वातावरण के निर्माण पर जोर देते हैं जहाँ मानवीय गरिमा पूरी तरह सुरक्षित रहे।

29. (A) 2, 3, 4, 1
इन घटनाओं का सही कालक्रम फ्रांस के वियतनाम संघर्ष (1950 का दशक) से शुरू होता है। इसके बाद 1980 के दशक में अमरीका द्वारा सोवियत संघ के खिलाफ इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन देने की घटना हुई। फिर 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया। अंत में 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमरीका पर बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। अतः घटनाओं का सही ऐतिहासिक क्रम विकल्प 2, 3, 4, 1 है।

30. (D) 20 प्रतिशत
वैश्विक तापवृद्धि के कारण समुद्र तल का बढ़ना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि समुद्र का जलस्तर दो मीटर बढ़ता है, तो बांग्लादेश का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब जाएगा। यह स्थिति करोड़ों लोगों के विस्थापन और भारी आर्थिक नुकसान का कारण बनेगी, जो यह दर्शाता है कि जलवायु परिवर्तन मानवता की सुरक्षा के लिए एक अत्यंत गंभीर चुनौती है।

31. (A) यह एक से ज़्यादा देशों में व्याप्त है और उसके निशाने पर कई देशों के नागरिक होते हैं।
अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की मुख्य विशेषता यह है कि यह एक से अधिक देशों में सक्रिय रहता है। इसके निशाने पर किसी एक देश के नहीं, बल्कि विभिन्न राष्ट्रों के निर्दोष नागरिक होते हैं। आतंकवादी समूह अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का लाभ उठाकर अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं और वैश्विक स्तर पर भय का वातावरण पैदा करते हैं। इस खतरे से निपटने के लिए सभी देशों के बीच आपसी सहयोग अनिवार्य है।

32. (B) राजनीतिक अधिकार जैसे अभिव्यक्ति और सभा करने की आज़ादी
मानवाधिकारों की पहली कोटि में मुख्य रूप से राजनीतिक अधिकारों को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत नागरिकों को प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की आज़ादी और संगठन बनाने जैसे मौलिक अधिकार आते हैं। ये अधिकार व्यक्ति को राज्य के दमनकारी कार्यों से सुरक्षा प्रदान करते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं। यह मानवाधिकारों की सबसे बुनियादी श्रेणी है।

55. (D) केरल
भारत में राष्ट्रीय एकता को चुनौती देने वाले उग्रवादी और अलगाववादी आंदोलन विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रहे हैं। नगालैंड, मिजोरम और पंजाब जैसे राज्यों ने अतीत में भीषण उग्रवाद का सामना किया है। इसके विपरीत केरल में इस तरह के कोई भी संगठित अलगाववादी या उग्रवादी समूह सक्रिय नहीं रहे हैं जिन्होंने भारत से अलग होने की कोशिश की हो। अतः आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में केरल इन विकल्पों में अपवाद है।

56. (A) लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था
भारत ने अपनी विशाल विविधता और राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का पालन किया है। लोकतंत्र विभिन्न समुदायों और समूहों को अपनी शिकायतों और आकांक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से रखने का मौका प्रदान करता है। यह व्यवस्था सत्ता में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करती है जिससे अलगाववाद की भावना कम होती है। भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में इस लोकतांत्रिक ढांचे की भूमिका महत्वपूर्ण है।

57. (B) P-4, Q-1, R-2, S-3
भारत की सुरक्षा रणनीति के चार प्रमुख अंग हैं। पहला घटक सैन्य-क्षमता को मजबूत करने पर केंद्रित है। दूसरा घटक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और कानूनों को सुदृढ़ बनाने की वकालत करता है। तीसरा घटक देश के भीतर व्याप्त अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं और अलगाववाद से निपटने से संबंधित है। चौथा घटक देश की अर्थव्यवस्था के विकास और गरीबी उन्मूलन पर जोर देता है। ये चारों घटक मिलकर भारत की समग्र सुरक्षा का आधार तैयार करते हैं।

58. (A) नागरिकों को गरीबी और अभाव की स्थिति से मुक्त करना
भारत की सुरक्षा रणनीति का चौथा घटक अर्थव्यवस्था को विकसित करने पर केंद्रित है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को गरीबी, भूख और अभाव की स्थिति से पूरी तरह मुक्त करना है। भारतीय नेतृत्व का मानना है कि आर्थिक पिछड़ापन और असमानता ही अक्सर आंतरिक संघर्षों को जन्म देते हैं। अतः जब जनता आर्थिक रूप से समृद्ध होगी तभी राष्ट्र सुरक्षित बन पाएगा। यह दृष्टिकोण मानवीय विकास को राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा मानता है।

59. (A) केवल 1 और 2 सही हैं।
भारत के संदर्भ में पहले दो कथन पूर्णतः सत्य हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था विभिन्न समुदायों को अपनी आवाज उठाने का मंच प्रदान करती है जिससे असंतोष को कम करने में मदद मिलती है। साथ ही चुनी हुई सरकार पर विकास को मानवीय चेहरा देने का दबाव रहता है। यह कहना गलत है कि लोकतंत्र का सुरक्षा से संबंध नहीं है या भारत ने गरीबी पर पूरी तरह जीत पा ली है, क्योंकि ये चुनौतियां आज भी विद्यमान हैं।

60. (B) युद्ध की आशंका को रोकना
'अपरोध' (Deterrence) सुरक्षा नीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका मुख्य अर्थ युद्ध की आशंका को रोकना है। इसके तहत कोई देश अपनी सैन्य शक्ति को इस प्रकार प्रदर्शित करता है कि शत्रु हमला करने का साहस न करे। इसका मूल विचार यह है कि संभावित हमलावर को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि युद्ध के परिणाम उसके लिए अत्यंत विनाशकारी और महंगे होंगे जिससे वह आक्रमण करने का विचार त्याग दे।

61. (B) केवल 1 और 2
सुरक्षा की परंपरागत धारणा मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित है। पहली श्रेणी बाहरी सुरक्षा की है जिसमें किसी राष्ट्र को पड़ोसी देशों या अन्य शक्तियों के सैन्य हमलों से सुरक्षित रखना शामिल है। दूसरी श्रेणी आंतरिक सुरक्षा की है जिसका उद्देश्य देश की सीमाओं के भीतर कानून-व्यवस्था बनाए रखना और अलगाववाद को रोकना है। मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा जैसे विषय सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा का हिस्सा माने जाते हैं।

62. (D) दूसरे देशों की तुलना में अपनी सैन्य ताकत का असर बढ़ाना
गठबंधन बनाने का मुख्य उद्देश्य समान हितों वाले देशों के साथ मिलकर अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना है। इसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्र एक संयुक्त सैन्य मोर्चा तैयार करते हैं ताकि किसी बाहरी हमले को रोका जा सके या प्रतिद्वंद्वी देशों के मुकाबले अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत की जा सके। यह पारंपरिक सुरक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो शक्ति-संतुलन बनाए रखने में राज्यों की सहायता करता है।

63. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
अंतरराष्ट्रीय राजनीति में गठबंधन हमेशा देशों के राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं। जब राष्ट्रीय हित बदलते हैं तो पुराने गठबंधन टूट जाते हैं और नए बन जाते हैं। इसका सटीक उदाहरण अमरीका है जिसने 1980 के दशक में सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए इस्लामी उग्रवादियों का साथ दिया था। किंतु बाद में जब इन्हीं उग्रवादियों ने अमरीकी हितों को चोट पहुँचाई तो अमरीका ने उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया।

64. (B) बारहगुनी
शीतयुद्ध के कालखंड (1946 से 1991) के दौरान दुनिया भर में आंतरिक संघर्षों और गृह युद्धों की स्थिति बहुत भयावह हो गई थी। ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में गृह युद्धों की संख्या में लगभग बारहगुनी वृद्धि हुई थी। यह तथ्य दर्शाता है कि उस दौर में बाहरी सैन्य खतरों के साथ-साथ देशों की आंतरिक सुरक्षा भी अत्यंत नाजुक और चुनौतीपूर्ण थी जिससे अनेक राष्ट्रों की स्थिरता को गंभीर खतरा पैदा हुआ।

65. (B) हथियारों के उपार्जन हेतु निश्चित कायदे-कानूनों का पालन करना
अस्त्र-नियंत्रण का अर्थ हथियारों को पूरी तरह समाप्त करना नहीं है बल्कि उनके निर्माण और उपार्जन को निश्चित कायदे-कानूनों के दायरे में लाना है। इसका मुख्य उद्देश्य खतरनाक हथियारों की होड़ को सीमित करना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सैन्य स्थिरता बनाए रखना है। इसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्र इस

44. (B) सैन्य-बल का प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में सामूहिक रूप से हो
सहयोगमूलक सुरक्षा की धारणा में सैन्य-बल के प्रयोग को पूरी तरह नकारा नहीं गया है, परंतु इसके लिए कुछ शर्तें अनिवार्य हैं। इसके अनुसार सैन्य-बल का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब बातचीत और अन्य सभी शांतिपूर्ण उपाय विफल हो गए हों। साथ ही यह कार्रवाई किसी एक देश की मर्जी से नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सामूहिक स्वीकृति और भागीदारी के साथ अंतिम विकल्प के रूप में होनी चाहिए।

45. (A) केवल 1 और 3 सही हैं।
भारत की सुरक्षा नीति के संदर्भ में पहला और तीसरा कथन सही है। भारत को पारंपरिक सैन्य खतरों और अपारंपरिक संकटों, दोनों का सामना करना पड़ा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत ने एक व्यापक रणनीति अपनाई है जिसके चार मुख्य घटक हैं। यह कहना गलत होगा कि खतरे केवल सीमा के बाहर से हैं या रणनीति में कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि समय के साथ चुनौतियां बदली हैं।

46. (D) सैन्य-क्षमता को मज़बूत करना
भारत की सुरक्षा रणनीति का पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण घटक अपनी सैन्य-क्षमता को निरंतर मजबूत करना है। पड़ोसी देशों के साथ हुए पिछले युद्धों और क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए भारत के लिए एक शक्तिशाली सैन्य बल अनिवार्य है। इसके तहत आधुनिक हथियारों का विकास और सेना का सुदृढ़ीकरण किया जाता है ताकि किसी भी बाहरी आक्रमण का प्रभावी ढंग से जवाब दिया जा सके और राष्ट्र की अखंडता अक्षुण्ण रहे।

47. (A) पाकिस्तान और चीन
स्वतंत्रता के बाद से भारत को मुख्य रूप से पाकिस्तान और चीन के सैन्य हमलों का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान के साथ भारत के कई युद्ध हुए हैं, जबकि 1962 में चीन के साथ एक बड़ा सीमा संघर्ष हुआ था। इन कड़वे अनुभवों ने भारत को अपनी सैन्य शक्ति और सीमा सुरक्षा को सर्वोपरि प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया है। आज भी ये दोनों देश भारत की सुरक्षा चिंताओं के केंद्र में बने हुए हैं।

48. (B) राष्ट्रीय सुरक्षा
भारत ने वर्ष 1998 में किए गए अपने परमाणु परीक्षणों का मुख्य आधार राष्ट्रीय सुरक्षा को बताया था। तत्कालीन सरकार का तर्क था कि पड़ोस में परमाणु हथियारों की मौजूदगी और क्षेत्रीय अस्थिरता को देखते हुए भारत के लिए परमाणु सक्षम होना अनिवार्य है। इस कदम का उद्देश्य किसी भी संभावित हमले को रोकना और अपनी संप्रभुता की रक्षा करना था। यह परीक्षण भारत की रक्षा रणनीति में एक मील का पत्थर साबित हुआ।

49. (A) 2, 3, 1, 4
इन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का सही कालक्रम 1962 के भारत-चीन युद्ध से शुरु होता है। इसके पश्चात भारत ने 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। फिर 1998 में भारत ने दूसरी बार परमाणु परीक्षण कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। अंत में 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ। अतः घटनाओं का सही तार्किक और ऐतिहासिक क्रम विकल्प 2, 3, 1, 4 के अनुसार बिल्कुल सटीक है।

50. (A) अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को अधिक सुदृढ़ बनाना
भारत की सुरक्षा नीति का दूसरा महत्वपूर्ण घटक अंतरराष्ट्रीय कायदों, कानूनों और संस्थाओं को अधिक सुदृढ़ बनाना है। भारत का विश्वास है कि एक न्यायपूर्ण और नियम-आधारित विश्व व्यवस्था ही राष्ट्रों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। इसी उद्देश्य से भारत संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर सक्रिय रहा है और अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करता रहा है। यह नीति वैश्विक शांति को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

51. (C) एशियाई एकता, विउपनिवेशीकरण और निरस्त्रीकरण
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एशियाई एकता, विउपनिवेशीकरण और निरस्त्रीकरण के प्रयासों की पुरजोर हिमायत की थी। वे चाहते थे कि नव-स्वतंत्र देश महाशक्तियों की गुटबाजी से दूर रहकर अपने विकास पर ध्यान दें। उनका मानना था कि विश्व शांति के लिए उपनिवेशवाद का अंत और हथियारों की होड़ पर लगाम लगाना अत्यंत आवश्यक है। नेहरु के इन विचारों ने भारत की सुरक्षा नीति को आकार दिया।

52. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
भारत ने गुटनिरपेक्षता के माध्यम से विश्व को शांति का एक तीसरा विकल्प प्रदान किया जो उस समय की दो महाशक्तियों के बीच बँटी दुनिया के लिए नया था। इसका मुख्य कारण यह था कि भारत किसी भी सैन्य गुट में शामिल होकर अपनी स्वतंत्रता को गिरवी नहीं रखना चाहता था। वह दोनों खेमों से समान दूरी बनाकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना चाहता था ताकि वैश्विक स्थिरता बनी रहे।

53. (C) ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर तापवृद्धि रोकना
वर्ष 1997 में अपनाए गए क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य लक्ष्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना है ताकि वैश्विक तापवृद्धि (ग्लोबल वार्मिंग) को नियंत्रित किया जा सके। यह संधि इस वैज्ञानिक समझ पर आधारित है कि बढ़ता तापमान पूरी मानवता और पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा है। अतः पर्यावरण की रक्षा के माध्यम से वैश्विक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय का एक महत्वपूर्ण सामूहिक प्रयास है।

54. (B) देश की आंतरिक सुरक्षा-चुनौतियों से निबटने की तैयारी
भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक देश की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों और समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने की तैयारी करना है। भारत के कई हिस्सों जैसे नगालैंड, मिजोरम और कश्मीर में अलगाववादी आंदोलनों ने राष्ट्रीय एकता को चुनौती दी है। इन खतरों से निपटने के लिए भारत ने सैन्य कार्रवाई और लोकतांत्रिक बातचीत का सहारा लिया है। आंतरिक शांति बनाए रखना भारत की संप्रभुता के लिए अत्यंत अनिवार्य है।

33. (B) P-3, Q-4, R-1, S-2
वैश्विक गरीबी का संबंध प्रति व्यक्ति निम्न आय और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से है। आतंकवाद के अंतर्गत विमान-अपहरण और बम विस्फोट जैसी हिंसक घटनाएँ आती हैं। महामारियों के उदाहरणों में एचआईवी-एड्स और बर्ड फ्लू जैसी घातक बीमारियाँ शामिल हैं। प्रवासन का एक प्रमुख रूप दक्षिणी गोलार्द्ध के लोगों का बेहतर जीवन की तलाश में उत्तरी गोलार्द्ध के धनी देशों की ओर जाना है। ये सभी सुरक्षा के नए स्रोत हैं।

34. (A) रवांडा में जनसंहार और कुवैत पर इराक का हमला
1990 के दशक में रवांडा में हुए भीषण जनसंहार और कुवैत पर इराक के हमले जैसी घटनाओं ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी बहस को जन्म दिया। इन संकटों ने यह सवाल खड़ा किया कि क्या मानवाधिकारों के व्यापक हनन की स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप करना चाहिए। इन घटनाओं ने स्पष्ट किया कि केवल राज्य की संप्रभुता का सम्मान करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मानवीय जीवन की रक्षा भी सर्वोपरि है।

35. (D) सभी कथन सही हैं।
विश्व की जनसंख्या वृद्धि से जुड़े ये सभी कथन सत्य हैं। दुनिया की आधी वृद्धि केवल छह प्रमुख देशों में हो रही है। आगामी दशकों में गरीब देशों की आबादी में भारी इजाफा होगा, जबकि धनी देशों की जनसंख्या घटेगी। यह असंतुलन उत्तरी और दक्षिणी गोलार्द्ध के बीच आर्थिक और सामाजिक खाई को और गहरा करता है, जो भविष्य में वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा के लिए नई चुनौतियाँ पैदा करेगा।

36. (D) अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देश
विश्व में सर्वाधिक सशस्त्र संघर्ष अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों (सब-सहारा अफ्रीका) में होते हैं। इस क्षेत्र के अनेक राष्ट्र आंतरिक युद्धों, जातीय संघर्षों और राजनीतिक अस्थिरता से ग्रसित हैं। इन निरंतर होने वाली लड़ाइयों के कारण यहाँ बड़े पैमाने पर जनहानि और विस्थापन होता है। यह क्षेत्र वैश्विक सुरक्षा और मानवीय सहायता की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए एक अत्यंत चिंताजनक इलाका बना हुआ है।

37. (C) आप्रवासी अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं, जबकि शरणार्थी मजबूरी में छोड़ते हैं।
अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार आप्रवासी और शरणार्थी के बीच एक स्पष्ट अंतर है। आप्रवासी वे लोग होते हैं जो स्वेच्छा से बेहतर आर्थिक अवसरों या जीवन स्तर की तलाश में अपना देश छोड़ते हैं। इसके विपरीत शरणार्थी वे हैं जिन्हें युद्ध, प्राकृतिक आपदा या उत्पीड़न के कारण मजबूरी में अपना घर और देश छोड़ना पड़ता है। शरणार्थियों को अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत विशेष संरक्षण और सहायता प्राप्त करने का अधिकार होता है।

38. (B) जो लोग अपना घर-बार छोड़ चुके हैं परंतु राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही हैं।
'आंतरिक रूप से विस्थापित जन' उन लोगों को कहा जाता है जिन्हें हिंसा, संघर्ष या आपदा के कारण अपना घर छोड़ना पड़ा है, परंतु वे अपने देश की सीमाओं से बाहर नहीं गए हैं। ये लोग अपने ही राष्ट्र के भीतर सुरक्षित स्थानों की तलाश में भटकते हैं। शरणार्थियों के विपरीत ये अंतरराष्ट्रीय सीमा पार नहीं करते, फिर भी इन्हें सुरक्षा, भोजन और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भारी संघर्ष करना पड़ता है।

39. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
दक्षिणी गोलार्द्ध के देशों में होने वाले सशस्त्र संघर्षों ने लाखों लोगों को शरणार्थी बनने पर विवश किया है। यह एक कड़वा सच है कि विश्व का शरणार्थी-मानचित्र और संघर्ष-मानचित्र एक-दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हैं। जहाँ भी युद्ध या हिंसा होती है, वहाँ से लोग अपनी जान बचाने के लिए पलायन करते हैं। अतः अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और संघर्ष ही सामूहिक विस्थापन का प्राथमिक कारण है।

40. (A) 4 करोड़
वर्ष 2003 तक पूरी दुनिया में लगभग 4 करोड़ लोग एचआईवी-एड्स से संक्रमित हो चुके थे। यह आंकड़ा इस बीमारी की भयावहता और इसके व्यापक वैश्विक प्रसार को दर्शाता है। इस महामारी ने न केवल स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव डाला, बल्कि अनेक देशों की अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिरता को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया। यह वैश्विक स्वास्थ्य संकट सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के तहत एक विनाशकारी खतरे के रूप में उभरा।

41. (C) अफ्रीका
एचआईवी-एड्स महामारी का सबसे भीषण प्रभाव अफ्रीका महाद्वीप पर पड़ा है। वैश्विक स्तर पर इस वायरस से संक्रमित कुल लोगों में से लगभग दो-तिहाई अकेले अफ्रीका में रहते हैं। इस उच्च संक्रमण दर ने यहाँ के समाज और अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया है। यह स्थिति दर्शाती है कि कुछ क्षेत्र महामारियों के प्रति कितने संवेदनशील हैं और वहाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष स्वास्थ्य सहायता की कितनी आवश्यकता है।

42. (B) P-1, Q-2, R-4, S-3
विभिन्न देशों की अपनी विशिष्ट सुरक्षा चिंताएं रही हैं। फ्रांस को वियतनाम में और ब्रिटेन को केन्या में औपनिवेशिक संघर्षों का सामना करना पड़ा। बोत्सवाना जैसे देशों के लिए एचआईवी-एड्स एक गंभीर स्वास्थ्य और सामाजिक संकट बना हुआ है। वहीं मालदीव जैसे द्वीप राष्ट्रों के लिए वैश्विक तापवृद्धि और समुद्र तल का बढ़ना अस्तित्व का खतरा है क्योंकि उनके डूबने की प्रबल आशंका है। ये सभी सुरक्षा के विविध आयाम हैं।

43. (D) तुत्सी
वर्ष 1994 में रवांडा में तुत्सी जनजाति के अस्तित्व पर भारी संकट मंडराया था। यहाँ हुए भीषण जनसंहार में अल्पसंख्यक तुत्सी समुदाय के लाखों लोगों को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया था। यह घटना अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मानवाधिकारों की रक्षा और बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता पर एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। इस त्रासदी ने दुनिया को सिखाया कि केवल राज्यों की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि समुदायों की सुरक्षा भी अनिवार्य है।

बात पर सहमत होते हैं कि वे किस प्रकार के हथियार और कितनी मात्रा में रख सकते हैं ताकि अचानक युद्ध की आशंका कम रहे।

66. (D) उपरोक्त सभी
सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में खतरे के अनेक नए स्रोतों को पहचान मिली है। इनमें आतंकवाद, मानवाधिकारों का व्यापक हनन, वैश्विक निर्धनता, घातक महामारियाँ और बड़े पैमाने पर होने वाला अनियंत्रित प्रवासन शामिल हैं। ये सभी चुनौतियाँ किसी एक देश की सैन्य शक्ति से हल नहीं हो सकतीं। इनके समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता होती है क्योंकि इनका प्रभाव संपूर्ण मानवता और वैश्विक स्थिरता पर पड़ता है।

67. (C) व्यक्तियों और समुदायों को अंदरुनी खून-खराबा से बचाना
संयुक्त राष्ट्रसंघ के भूतपूर्व महासचिव कोफ़ी अन्नान ने 'मानवता की सुरक्षा' को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया था। उनके अनुसार इसका मुख्य आशय व्यक्तियों और समुदायों को केवल बाहरी हमलों से ही नहीं बल्कि उनके अपने देश के भीतर होने वाले खून-खराबे, हिंसा और दमन से बचाना है। यह विचार राज्य की संप्रभुता से अधिक व्यक्ति की गरिमा और उसके सुरक्षित जीवन जीने के अधिकार को प्राथमिकता प्रदान करता है।

68. (D) वर्ल्ड ट्रेड सेंटर
11 सितंबर 2001 को आतंकवादियों ने संयुक्त राज्य अमरीका के न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आत्मघाती हमला किया था। इस घटना में अपहृत विमानों का उपयोग इमारतों से टकराने के लिए किया गया जिससे हजारों बेगुनाह लोग मारे गए। इस भीषण हमले ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया और पूरी दुनिया को यह अहसास कराया कि कोई भी देश इस तरह के घातक खतरों से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है।

69. (C) उपनिवेशीकृत जनता अथवा जातीय और अल्पसंख्यक समूहों के अधिकार
मानवाधिकारों की तीसरी कोटि के अंतर्गत उन अधिकारों को रखा जाता है जो सामूहिक रूप से किसी विशेष समूह या समुदाय को प्राप्त होते हैं। इसमें मुख्य रूप से उपनिवेशों में रहने वाली जनता के अधिकार और जातीय या अल्पसंख्यक समूहों के हितों की रक्षा शामिल है। यह श्रेणी इस बात पर जोर देती है कि केवल व्यक्तिगत अधिकार ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि समुदायों की पहचान और उनकी सांस्कृतिक स्वायत्तता की रक्षा करना भी आवश्यक है।

70. (A) P-1, Q-2, R-4, S-3
विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा के अलग-अलग संकट विद्यमान हैं। सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में सर्वाधिक सशस्त्र संघर्ष होते हैं। बांग्लादेश के लिए समुद्र तल बढ़ने से उसका 20% हिस्सा डूबने का खतरा है, जबकि थाईलैंड की 50% आबादी पर इसका असर पड़ सकता है। पूरे अफ्रीका महाद्वीप में एचआईवी-एड्स से संक्रमित लोगों की संख्या सर्वाधिक है। ये आंकड़े वैश्विक स्तर पर व्याप्त असमान सुरक्षा चुनौतियों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।

71. (D) 55 लाख
1990 से 1995 के बीच की अवधि वैश्विक सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत अशांत रही थी। इस दौरान सत्तर देशों के मध्य हुए लगभग 93 युद्धों में 55 लाख के करीब लोग मारे गए थे। यह भयावह संख्या दर्शाती है कि शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद भी दुनिया भर में क्षेत्रीय और आंतरिक संघर्ष कम नहीं हुए थे। इन युद्धों ने बड़े पैमाने पर विस्थापन और मानवीय संकट पैदा किया जिसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचा।

72. (A) मैड-काऊ
1990 के दशक के उत्तरार्द्ध में ब्रिटेन को 'मैड-काऊ' नामक महामारी के कारण भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा था। इस बीमारी के फैलने से पशुधन को बहुत हानि हुई और अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रिटिश मांस के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस संकट ने अरबों डॉलर का आर्थिक बोझ डाला और यह साबित किया कि पशुओं में फैलने वाली महामारियाँ भी किसी देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती हैं।

73. (A) 3, 1, 4, 2
भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्धों का सही कालक्रम इस प्रकार है: सबसे पहले 1947-48 में कश्मीर मुद्दे पर संघर्ष हुआ। इसके बाद 1965 में दोनों देशों के बीच बड़ा युद्ध लड़ा गया। फिर 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान तीसरा युद्ध हुआ। अंत में 1999 में कारगिल की पहाड़ियों पर दोनों सेनाओं के बीच सशस्त्र संघर्ष हुआ। अतः ऐतिहासिक दृष्टि से सही तार्किक क्रम विकल्प 3, 1, 4, 2 के अनुसार है।

74. (A) राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ, स्वयंसेवी संगठन और अन्य कर्ता
सहयोगमूलक सुरक्षा एक व्यापक अवधारणा है जिसमें केवल संप्रभु राष्ट्र ही शामिल नहीं होते। इसमें अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ (जैसे संयुक्त राष्ट्र), गैर-सरकारी स्वयंसेवी संगठन (जैसे रेड क्रॉस), और विभिन्न अन्य नागरिक कर्ता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका मूल विचार यह है कि वर्तमान युग के वैश्विक खतरों से निपटने के लिए सभी स्तरों पर आपसी सहयोग और तालमेल आवश्यक है क्योंकि कोई भी अकेला देश इन चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता है।

75. (A) केवल 1, 2 और 4 सही हैं।
सुरक्षा के संदर्भ में रक्षा का अर्थ युद्ध को सीमित या समाप्त करना है, जबकि अपरोध का उद्देश्य युद्ध की आशंका को रोकना है। गठबंधन भी राष्ट्रीय हितों पर ही आधारित होते हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि शक्ति-संतुलन का अर्थ सैन्य प्रभुत्व स्थापित करना नहीं, बल्कि अपनी शक्ति प्रतिद्वंद्वी के समान रखना है ताकि कोई हमला न कर सके। ये सिद्धांत पारंपरिक सुरक्षा नीति के आधारभूत स्तंभ माने जाते हैं।

यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने और एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में अपनी छवि पेश करने के दोहरे उद्देश्यों को संतुलित करने का प्रयास करता है।

उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

171. भारत की परमाणु नीति का आधारभूत सिद्धांत क्या है?
(A) व्यापक प्रथम प्रहार क्षमता (Massive First Strike Capability)।
(B) पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण (Complete Nuclear Disarmament)।
(C) विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध (Credible Minimum Deterrence)।
(D) असीमित हथियारों का संग्रह (Unlimited Arms Stockpiling)।

172. 'पहले उपयोग नहीं' (No First Use - NFU) की नीति का क्या अर्थ है?
(A) भारत किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेगा।
(B) भारत परमाणु हथियारों का उपयोग करने वाला पहला देश नहीं बनेगा।
(C) भारत केवल गैर-परमाणु संपन्न देशों के खिलाफ पहले उपयोग करेगा।
(D) भारत केवल अपने क्षेत्र के भीतर परमाणु हथियारों का उपयोग करेगा।

173. भारत की परमाणु नीति के अनुसार, भारत किस स्थिति में जवाबी परमाणु हमला कर सकता है?
(A) केवल पारंपरिक सैन्य हमले की स्थिति में।
(B) आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने की स्थिति में।
(C) किसी भी प्रकार के सीमा विवाद की स्थिति में।
(D) यदि उस पर परमाणु, रासायनिक या जैविक हमला होता है।

174. 'न्यूनतम प्रतिरोध' की अवधारणा का क्या तात्पर्य है?
(A) भारत जवाबी हमले के लिए आवश्यक विश्वसनीय क्षमता बनाए रखेगा बिना हथियारों की दौड़ में शामिल हुए।
(B) भारत अपने परमाणु शस्त्रागार में केवल एक सक्रिय परमाणु बम रखने की नीति अपनाएगा।
(C) भारत अपने परमाणु हथियारों की संख्या को निरंतर कम करते हुए उन्हें न्यूनतम संभव स्तर पर लाने का प्रयास करेगा।
(D) भारत वैश्विक स्तर पर सबसे कमजोर और सीमित परमाणु शस्त्रागार रखने वाला एकमात्र जिम्मेदार राष्ट्र बनेगा।

175. स्रोत के अनुसार, भारत की परमाणु नीति किन दोहरे उद्देश्यों को संतुलित करने का प्रयास करती है?
(A) क्षेत्रीय आक्रामक विस्तार और तीव्र आर्थिक विकास की नीतियों को।
(B) पूर्ण वैश्विक प्रभुत्व और व्यापक सांस्कृतिक प्रभाव के लक्ष्यों को।
(C) रणनीतिक स्वायत्तता और एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति की छवि।
(D) पूर्ण कूटनीतिक अलगाव और सैन्य आत्मनिर्भरता की योजनाओं को।

86. (B) सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा सिर्फ सैन्य खतरों से संबद्ध है।
सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के बारे में यह कहना गलत है कि यह सिर्फ सैन्य खतरों से संबद्ध है। वास्तव में यह धारणा सैन्य खतरों से कहीं आगे जाकर मानवीय अस्तित्व को प्रभावित करने वाले अभाव, महामारी, गरीबी और पर्यावरणीय संकटों पर ध्यान केंद्रित करती है। इसे 'मानवता की सुरक्षा' भी कहा जाता है क्योंकि यह राज्य के बजाय व्यक्तियों और समुदायों के कल्याण और उनकी गरिमापूर्ण रक्षा को सर्वोपरि मानती है।

87. (D) एबोला वायरस
एबोला वायरस एक ऐसी नई और घातक महामारी है जिसके बारे में अभी भी चिकित्सा जगत को बहुत अधिक जानकारी नहीं है। यह वायरस अत्यंत संक्रामक है और इसकी मृत्यु दर बहुत ऊँची होती है। टीबी, मलेरिया और हैजा जैसी पुरानी बीमारियों का इलाज उपलब्ध है, परंतु एबोला जैसी उभरती बीमारियाँ अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक नई और गंभीर चुनौती पेश करती हैं क्योंकि इनके प्रसार को रोकना और इलाज ढूंढना अत्यंत कठिन है।

88. (A) नाटो (NATO)
सहयोगमूलक सुरक्षा में विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएँ शामिल होती हैं क्योंकि ये स्वास्थ्य और आर्थिक संकटों के समाधान में मदद करती हैं। इसके विपरीत नाटो (NATO) एक सैन्य संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य सामूहिक सैन्य रक्षा है। सहयोगमूलक सुरक्षा का दायरा सैन्य गठबंधन से कहीं अधिक व्यापक होता है और इसमें गैर-सैन्य खतरे जैसे गरीबी और महामारियों से लड़ने वाले संगठन मुख्य भूमिका निभाते हैं।

89. (C) शांतिबहाली के मिशनों में
भारत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रबल समर्थक रहा है। इसी प्रतिबद्धता के तहत भारत ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के विभिन्न शांतिबहाली मिशनों में अपनी सेनाएँ भेजी हैं। भारतीय सैनिकों ने दुनिया के अशांत क्षेत्रों में हिंसा को रोकने, चुनाव संपन्न कराने और मानवीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह नीति भारत के उस विश्वास को दर्शाती है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से ही वैश्विक संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान संभव है।

90. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने का एक प्रभावी माध्यम है। लोकतंत्र गरीब और वंचित वर्गों को अपनी आवाज उठाने का मंच प्रदान करता है। चुनाव के माध्यम से जनता सरकार पर दबाव बना सकती है कि वह केवल सैन्य सुरक्षा पर ही नहीं बल्कि मानवीय विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे। इस प्रकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुरक्षा को अधिक समावेशी और जन-केंद्रित बनाने का कार्य करती है।

91. (D) परमाणु हथियारों से लैस देश
दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति अत्यंत संवेदनशील है। भारत के पड़ोस में ऐसे देश स्थित हैं जो परमाणु हथियारों से लैस हैं। इस क्षेत्रीय परमाणु होड़ और तनावपूर्ण पड़ोसी संबंधों ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को सदैव बढ़ाए रखा है। इसी कारण भारत को अपनी रक्षा तैयारियों और परमाणु नीति को इस प्रकार तैयार करना पड़ा है कि वह किसी भी संभावित परमाणु खतरे के प्रति प्रभावी अवरोध उत्पन्न कर सके।

92. (B) केवल 1, 2, 3 और 4 सही हैं।
भारत की सुरक्षा नीति के संदर्भ में पहले चार कथन सही हैं। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं और संयुक्त राष्ट्र को महत्व दिया है। साथ ही भारत ने भेदभावहीन परमाणु नीति और नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की वकालत की है। कथन 5 गलत है क्योंकि भारत कभी किसी सैन्य गठबंधन का सदस्य नहीं रहा, बल्कि उसने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया है। यह भारत की स्वतंत्र और शांतिपूर्ण नीति को दर्शाता है।

93. (C) बोत्सवाना
बोत्सवाना एक ऐसा देश है जहाँ एचआईवी-एड्स का खतरा अत्यंत गंभीर रूप ले चुका है। वहाँ की स्थिति इतनी भयावह है कि हर 6 वयस्क व्यक्तियों में से एक इस जानलेवा बीमारी से संक्रमित है। इस महामारी ने बोत्सवाना की सामाजिक संरचना और आर्थिक प्रगति को भारी चोट पहुँचाई है। यह उदाहरण स्पष्ट करता है कि कैसे एक स्वास्थ्य संकट किसी राष्ट्र की समग्र सुरक्षा और भविष्य के लिए युद्ध से भी अधिक खतरनाक साबित हो सकता है।

94. (D) दूसरी कोटि
मानवाधिकारों की दूसरी कोटि के अंतर्गत आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को शामिल किया जाता है। इनमें रोजगार का अधिकार, भोजन, स्वास्थ्य सेवाएँ और शिक्षा जैसे बुनियादी अधिकार आते हैं। यह श्रेणी इस तर्क पर आधारित है कि बिना आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के व्यक्ति अपने राजनीतिक अधिकारों का सही उपयोग नहीं कर सकता है। अतः मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए इन अधिकारों को सुरक्षित करना किसी भी समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए।

95. (D) उपरोक्त सभी
सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के मुख्य तत्वों में अपरोध, रक्षा, शक्ति-संतुलन और गठबंधन बनाना शामिल हैं। ये सभी उपाय मुख्य रूप से सैन्य खतरों से निपटने और राज्य की संप्रभुता की रक्षा करने पर केंद्रित होते हैं। अपरोध युद्ध को रोकता है, रक्षा युद्ध के नुकसान को कम करती है, शक्ति-संतुलन प्रतिद्वंद्वियों को नियंत्रण में रखता है और गठबंधन सामूहिक सैन्य शक्ति प्रदान करते हैं। ये तत्व पारंपरिक राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का आधार बनते हैं।

96. (B) आर्थिक और प्रौद्योगिकी की ताकत को
पारंपरिक सुरक्षा नीति में किसी देश की सैन्य-शक्ति का वास्तविक आधार उसकी आर्थिक और प्रौद्योगिकी की ताकत

उनके लिए सुरक्षा का अर्थ केवल विदेशी हमले से बचाव था। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं क्योंकि आंतरिक स्थिरता ने उन्हें बाहरी मोर्चे पर ध्यान लगाने की सुविधा दी।

117. (C) 95 प्रतिशत
वर्तमान समय में वैश्विक युद्धों और संघर्षों के स्वरूप में बड़ा बदलाव आया है। आंकड़े बताते हैं कि आज विश्व में होने वाले कुल सशस्त्र संघर्षों में से लगभग 95 प्रतिशत आंतरिक युद्ध या गृह युद्ध की श्रेणी में आते हैं। इसका अर्थ यह है कि अब देशों को बाहरी आक्रमण की तुलना में अपनी ही सीमाओं के भीतर होने वाले जातीय, धार्मिक या राजनीतिक संघर्षों से कहीं अधिक खतरा है। यह आंतरिक सुरक्षा के बढ़ते महत्व को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

118. (B) अस्त्र-नियंत्रण
शीतयुद्ध के दौरान जब महाशक्तियों ने यह महसूस किया कि वे परमाणु हथियारों को पूरी तरह नहीं त्याग सकतीं, तो उन्होंने 'अस्त्र-नियंत्रण' का मार्ग चुना। इसके माध्यम से उन्होंने हथियारों की होड़ को सीमित करने और कुछ खास किस्म के मिसाइल परीक्षणों पर रोक लगाने के लिए संधियाँ कीं। इसका उद्देश्य परमाणु युद्ध के खतरे को कम करना और हथियारों के उपार्जन को नियमों के दायरे में लाना था, ताकि पूर्ण विनाश की स्थिति से बचा जा सके।

119. (B) केवल 1, 2 और 3 सही हैं।
पारंपरिक सुरक्षा की धारणा मुख्य रूप से सैन्य बल के खतरों पर केंद्रित है। इसमें माना जाता है कि सैन्य बल ही सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है और सैन्य शक्ति के माध्यम से ही राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। यह धारणा हिंसा के असीमित उपयोग का समर्थन नहीं करती, बल्कि 'न्याय-युद्ध' और युद्ध के सीमित साधनों के उपयोग पर जोर देती है ताकि मानवता को होने वाले नुकसान को न्यूनतम रखा जा सके।

120. (A) व्यक्तियों का हिंसक खतरों से बचाव
'भय से मुक्ति' की अवधारणा का मूल उद्देश्य व्यक्तियों को प्रत्यक्ष हिंसक खतरों और शारीरिक नुकसान से बचाना है। इसमें युद्ध, जनसंहार, आतंकवाद और नागरिक हिंसा जैसी स्थितियाँ शामिल हैं जहाँ व्यक्ति की जान को खतरा होता है। सुरक्षा के संकीर्ण नजरिए में इसे ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका तर्क है कि जब तक व्यक्ति मृत्यु और हिंसा के डर से मुक्त नहीं होगा, तब तक किसी अन्य प्रकार के विकास का कोई महत्व नहीं रह जाएगा।

121. (A) P-2, Q-4, R-1, S-3
खतरों और सुरक्षा के उपायों का सही मिलान इस प्रकार है: पड़ोसी देश का हमला पारंपरिक बाहरी खतरा है, जबकि अलगाववादी आंदोलन आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती है। गरीबी और महामारियाँ सुरक्षा के अपारंपरिक खतरों की श्रेणी में आते हैं। इन खतरों की अनुपस्थिति और सामूहिक सुरक्षा की भावना ही सहयोगमूलक सुरक्षा का आधार बनती है। यह मिलान सुरक्षा के विविध पहलुओं और उनके समाधान के तरीकों को स्पष्ट रूप से वर्गीकृत करता है।

122. (A) अगर मसले से संदर्भी राष्ट्र या जनसमूह के अस्तित्व को खतरा हो
किसी भी मुद्दे को सुरक्षा का मुद्दा मानने का न्यूनतम और सर्व स्वीकृत मानक यह है कि उस मसले से संबंधित राष्ट्र, समाज या जनसमूह के अस्तित्व को सीधा खतरा होना चाहिए। यदि कोई चुनौती इतनी गंभीर है कि वह जीवन के केंद्रीय मूल्यों या राष्ट्र की संप्रभुता को नष्ट कर सकती है, तभी उसे सुरक्षा की श्रेणी में रखा जाता है। सामान्य समस्याओं और सुरक्षा संबंधी मसलों के बीच यही अस्तित्वगत संकट ही मुख्य विभाजक रेखा है।

123. (A) 2, 4, 1, 3
इन अंतरराष्ट्रीय संधियों का सही कालक्रम इस प्रकार है: सबसे पहले परमाणु अप्रसार संधि (NPT) 1968 में आई। इसके बाद जैविक हथियार संधि (BWC) 1972 में संपन्न हुई। रासायनिक हथियार संधि (CWC) पर प्रक्रिया काफी बाद में हुई और यह 1993 में हस्ताक्षर के लिए खुली और 1997 में प्रभावी हुई। अंत में जलवायु परिवर्तन से जुड़ा क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अपनाया गया। यह क्रम वैश्विक सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को दर्शाता है।

124. (B) क्योंकि शांति और सेना के उद्देश्य परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं।
'शांति-सेना' की अवधारणा अक्सर विरोधाभासी लगती है क्योंकि सामान्यतः सेना का संबंध युद्ध, लड़ाई और बल-प्रयोग से होता है, जबकि शांति का अर्थ अहिंसा और सौहार्द है। सेना का उपयोग शांति स्थापित करने के लिए करना एक अनूठा प्रयोग है। संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों द्वारा इन सेनाओं का उपयोग युद्धरत क्षेत्रों में संघर्ष विराम लागू कराने और शांति बनाए रखने के लिए किया जाता है, जो सैन्य शक्ति के रचनात्मक और सुरक्षात्मक उपयोग का एक उदाहरण है।

125. (C) केन्या में
1950 और 1960 के दशक के दौरान ब्रिटेन को अपने उपनिवेश केन्या में भारी उग्रवाद और संघर्ष का सामना करना पड़ा था। वहां के स्थानीय 'माऊ-माऊ' विद्रोहियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। ब्रिटेन ने इस विद्रोह को दबाने के लिए कड़े सैन्य कदम उठाए, परंतु अंततः बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव और स्थानीय प्रतिरोध के कारण उसे केन्या को आजाद करना पड़ा। यह संघर्ष औपनिवेशिक काल की सुरक्षा चुनौतियों का एक प्रमुख उदाहरण है।

126. (C) केवल 1, 2, 3 और 4
भारत की सुरक्षा रणनीति के चार मुख्य स्तंभ हैं: अपनी सैन्य-क्षमता को आधुनिक और मजबूत बनाना, अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संस्थाओं का समर्थन करना, देश के भीतर व्याप्त अलगाववादी और उग्रवादी समस्याओं को सुलझाना, और आर्थिक विकास के जरिए गरीबी को खत्म करना। भारत कभी किसी सैन्य गठबंधन का सदस्य या नेतृत्वकर्ता नहीं रहा है, बल्कि उसने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया है। अतः विकल्प 1, 2, 3 और 4 ही भारत की वास्तविक सुरक्षा रणनीति का हिस्सा हैं।

के सामने निरंतर नई बाधाएँ खड़ी करती हैं जिससे वैश्विक असमानता और अधिक बढ़ती है।

107. (D) जापान
विश्व की कुल जनसंख्या वृद्धि का 50% हिस्सा केवल 6 देशों में केंद्रित है, जिनमें भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया शामिल हैं। जापान इस सूची में नहीं है क्योंकि वहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर अत्यंत कम है और वास्तव में वहाँ की आबादी घट रही है। यह अंतर दर्शाता है कि जनसंख्या का दबाव मुख्य रूप से विकासशील और गरीब देशों पर है, जो उनके भविष्य की सुरक्षा और संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती है।

108. (B) क्योंकि विभिन्न संदर्भ और स्थितियों में इसका अर्थ बदल जाता है।
सुरक्षा को एक भुलैयादार धारणा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका अर्थ सभी के लिए एक समान नहीं होता है। अलग-अलग संदर्भों, समय और स्थितियों में खतरे की परिभाषा बदल जाती है। एक युद्धग्रस्त देश के लिए सुरक्षा का अर्थ सैन्य विजय हो सकता है, जबकि एक शांतिपूर्ण किंतु गरीब देश के लिए इसका अर्थ भोजन और स्वास्थ्य की उपलब्धता हो सकता है। इसी लचीलेपन और व्यक्तिपरकता के कारण सुरक्षा को समझना एक जटिल कार्य माना जाता है।

109. (A) P-2, Q-1, R-4, S-3
इन महत्वपूर्ण युद्धों और हमलों का सही मिलान इस प्रकार है: भारत और चीन के बीच युद्ध 1962 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का संघर्ष 1999 में लड़ा गया। इराक ने कुवैत पर आक्रमण 1990 में किया था, जिसके बाद खाड़ी युद्ध शुरू हुआ। संयुक्त राज्य अमरीका पर भीषण 9/11 आतंकवादी हमला वर्ष 2001 में हुआ था। यह मिलान आधुनिक इतिहास की प्रमुख रणनीतिक घटनाओं और उनकी समय-सीमा को स्पष्ट रूप से उजागर करता है।

110. (D) प्रति व्यक्ति आय और जनसंख्या वृद्धि दर में अंतर
उत्तरी और दक्षिणी गोलार्द्ध के देशों के बीच बढ़ती आर्थिक और सामाजिक असमानता का मुख्य कारण प्रति व्यक्ति आय और जनसंख्या वृद्धि दर में व्यापक अंतर है। उत्तरी गोलार्द्ध के धनी देशों में आय अधिक और जनसंख्या स्थिर है, जबकि दक्षिणी गोलार्द्ध के गरीब देशों में आय कम और आबादी तेजी से बढ़ रही है। यह असंतुलन संसाधनों के वितरण को प्रभावित करता है और वैश्विक स्तर पर गरीबी, प्रवासन और अस्थिरता जैसी सुरक्षा चुनौतियाँ पैदा करता है।

111. (A) ग्लोबल वार्मिंग और आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्याओं के कारण
1990 के दशक में 'विश्व-सुरक्षा' की नई धारणा उभरी क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और महामारियों जैसे खतरों ने वैश्विक रूप धारण कर लिया था। ये ऐसी समस्याएँ हैं जिनसे कोई भी देश अकेले नहीं लड़ सकता और न ही ये किसी एक राष्ट्र की सीमा तक सीमित हैं। यदि पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या कोई संक्रामक बीमारी फैलती है, तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, जिससे सामूहिक सुरक्षा की आवश्यकता महसूस हुई।

112. (B) केवल 1, 2, 3 और 4
भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए अलगाववादी आंदोलन एक बड़ी चुनौती रहे हैं। नगालैंड, मिजोरम, पंजाब और कश्मीर जैसे राज्यों में विभिन्न उग्रवादी समूहों ने समय-समय पर भारत से अलग होने की कोशिशें की हैं। सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए सैन्य बल और लोकतांत्रिक संवाद, दोनों का उपयोग किया है। तमिलनाडु में भाषाई और सांस्कृतिक आंदोलन तो हुए, परंतु वहाँ पंजाब या कश्मीर की तरह सशस्त्र अलगाववादी संघर्ष की स्थिति व्यापक रूप से नहीं रही है।

113. (B) आय और सेवाओं का वितरण समाज के स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है।
1975 में क्यूबा का उदाहरण यह स्पष्ट करता है कि केवल उच्च प्रति व्यक्ति आय ही बेहतर स्वास्थ्य की गारंटी नहीं है। यद्यपि क्यूबा की आय कम थी, परंतु वहाँ सेवाओं और संसाधनों का वितरण इतना बेहतर था कि लोगों की आयु-प्रत्याशा बहुत अधिक थी। यह तथ्य दर्शाता है कि मानवीय सुरक्षा के लिए आर्थिक संवृद्धि के साथ-साथ सामाजिक न्याय और स्वास्थ्य सुविधाओं तक सभी की समान पहुँच होना अत्यंत आवश्यक है, जो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है।

114. (A) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से रणनीतियाँ बनाना
सुरक्षा के अपारंपरिक खतरों जैसे कि वैश्विक तापवृद्धि, महामारियाँ और आतंकवाद से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सामूहिक रणनीतियाँ बनाना है। इन समस्याओं की प्रकृति सीमापार है, इसलिए कोई भी देश अपने दम पर इन्हें हल नहीं कर सकता है। सैन्य शक्ति या आर्थिक प्रतिबंध इन मामलों में उतने कारगर नहीं होते जितने कि साझा सूचना, संयुक्त अनुसंधान और वैश्विक समझौतों के माध्यम से किए गए सामूहिक प्रयास होते हैं।

115. (C) संप्रभुता, अखंडता और आम नागरिकों के बहुमूल्य जीवन को
पारंपरिक सुरक्षा की धारणा के अनुसार सैन्य कार्रवाई सीधे तौर पर किसी राष्ट्र की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा पैदा करती है। इसके अलावा आधुनिक युद्धों में केवल सैनिक ही नहीं, बल्कि निर्दोष आम नागरिकों के जीवन को भी भारी नुकसान पहुँचता है। युद्ध की विभीषिका पूरे देश के सामाजिक और ढांचागत स्वरूप को नष्ट कर सकती है, इसलिए सैन्य खतरों को राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए सबसे गंभीर और प्रत्यक्ष संकट माना जाता है।

116. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
दूसरे विश्वयुद्ध के बाद पश्चिमी और शक्तिशाली देश अपनी आंतरिक सुरक्षा के प्रति काफी आश्वस्त थे क्योंकि उनके भीतर कोई बड़ा अलगाववादी आंदोलन नहीं था। इसी कारण उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपनी सीमाओं के बाहर से आने वाले सैन्य खतरों और शीतयुद्ध की रणनीतियों पर केंद्रित किया।

137. (C) आंतरिक रूप से विस्थापित जन
1990 के दशक में कश्मीर घाटी में बढ़ती हिंसा और आतंकवाद के कारण वहां से पलायन करने वाले कश्मीरी पंडित 'आंतरिक रूप से विस्थापित जन' का सबसे सटीक उदाहरण हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने हिंसा के डर से अपना घर और क्षेत्र तो छोड़ दिया, परंतु वे भारत की राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही रहे। उन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार शरणार्थी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन्होंने सुरक्षा की तलाश में कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा पार नहीं की थी।

138. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
भारत ने वर्ष 1998 में किए गए पोखरण-II परमाणु परीक्षणों को राष्ट्रीय सुरक्षा के तर्क के आधार पर पूरी तरह उचित ठहराया था। सरकार का स्पष्ट मानना था कि भारत के पड़ोस में परमाणु हथियारों से लैस देशों की मौजूदगी और क्षेत्रीय अस्थिरता को देखते हुए एक मजबूत परमाणु अवरोध (Deterrence) विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। यह कदम भारत की संप्रभुता की रक्षा और बाहरी दबावों से मुक्त रहने की उसकी सामरिक आवश्यकता का परिणाम था।

139. (D) प्रधानमंत्री नेहरू ने इसकी हिमायत की थी।
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 'विउपनिवेशीकरण' (Decolonisation) के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि जब तक दुनिया में उपनिवेशवाद रहेगा, तब तक वास्तविक अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संभव नहीं है। उन्होंने एशिया और अफ्रीका के देशों की आजादी की हिमायत की और इसे भारत की सुरक्षा नीति के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखा। नेहरू का तर्क था कि स्वतंत्र राष्ट्रों का समूह ही एक न्यायपूर्ण और सुरक्षित विश्व व्यवस्था का आधार बन सकता है।

140. (B) एक सार्वभौम और बिना भेदभाव वाली नीति।
भारत ने हथियारों के अप्रसार और विशेषकर परमाणु हथियारों के संदर्भ में हमेशा एक सार्वभौम और बिना भेदभाव वाली नीति की वकालत की है। भारत का विरोध 'परमाणु अप्रसार संधि' (NPT) जैसी भेदभावपूर्ण व्यवस्थाओं से रहा है जो कुछ देशों को हथियार रखने की अनुमति देती हैं और बाकी को रोकती हैं। भारत का मानना है कि संपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के नियम सभी देशों पर समान रूप से लागू होने चाहिए ताकि वैश्विक सुरक्षा वास्तव में सुनिश्चित हो सके।

141. (C) एमनेस्टी इंटरनेशनल
एमनेस्टी इंटरनेशनल सहयोगमूलक सुरक्षा में एक प्रमुख गैर-राज्य कर्ता (Non-state actor) का उदाहरण है। यह एक अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है जो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए दुनिया भर में अभियान चलाता है। सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर यह संगठन उन क्षेत्रों में कार्य करता है जहाँ मानवीय गरिमा खतरे में होती है। ऐसे संगठनों की सक्रियता दर्शाती है कि सुरक्षा अब केवल राज्यों का नहीं, बल्कि वैश्विक नागरिक समाज का भी विषय बन चुका है।

142. (D) जनता और उनकी चुनी हुई सरकार का मनोबल तोड़ने के उद्देश्य से।
पारंपरिक सुरक्षा और युद्धों के इतिहास में अक्सर आम निर्दोष स्त्री-पुरुषों को जान-बूझकर निशाना बनाया जाता रहा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य शत्रु देश की आम जनता और वहां की चुनी हुई सरकार के मनोबल को पूरी तरह तोड़ना होता है। हमलावर पक्ष का मानना होता है कि यदि नागरिक आबादी डरी और असुरक्षित होगी, तो सरकार पर युद्ध समाप्त करने या आत्मसमर्पण करने का दबाव बढ़ जाएगा। यह रणनीति युद्ध की अत्यंत क्रूर और अमानवीय सच्चाई को उजागर करती है।

143. (A) P-3, Q-1, R-2, S-4
भारत और उसके पड़ोसी देशों तथा महाशक्तियों के बीच की प्रमुख घटनाओं का मिलान इस प्रकार है: पाकिस्तान के साथ भारत का भीषण युद्ध 1971 में हुआ था। चीन ने भारत पर हमला 1962 में किया। भारत ने अपनी विदेश और सुरक्षा नीति के रूप में गुटनिरपेक्षता को अपनाया। वहीं संयुक्त राज्य अमरीका पर 11 सितंबर 2001 को भयानक आतंकवादी हमला हुआ था। यह मिलान दक्षिण एशिया और वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को सही ढंग से जोड़ता है।

144. (B) उन्हें दूसरे खेमे के देशों से दुश्मनी ठाननी पड़ती थी।
शीतयुद्ध के दौरान जब कोई नव-स्वतंत्र देश अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति (अमरीका या सोवियत संघ) के गुट में शामिल होता था, तो उसे अनिवार्य रूप से दूसरे खेमे के देशों से दुश्मनी मोल लेनी पड़ती थी। इससे उस देश की सुरक्षा बढ़ने के बजाय अक्सर वह महाशक्तियों के बीच चलने वाले वैश्विक संघर्ष और प्रतिद्वंद्विता का अखाड़ा बन जाता था। इसी खतरे से बचने के लिए भारत जैसे अनेक देशों ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाना बेहतर समझा था।

145. (A) केवल 1, 2 और 3 सही हैं।
'न्याय-युद्ध' की परंपरा के अनुसार युद्ध के साधन सदैव सीमित होने चाहिए और सेना को निहत्थे नागरिकों या संघर्षविमुख शत्रुओं पर हमला नहीं करना चाहिए। साथ ही सैन्य बल का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब बातचीत के सभी शांतिपूर्ण रास्ते बंद हो गए हों। कथन 4 और 5 गलत हैं क्योंकि युद्ध किसी भी तुच्छ कारण से नहीं किया जा सकता और यह परंपरा आज के मानवाधिकारों के युग में पहले से अधिक प्रासंगिक हो गई है।

146. (A) मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों पर ध्यान केंद्रित करना।
सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा का केंद्रीय और सबसे सशक्त तर्क यह है कि आज के युग में हमें मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह विचार राज्यों की पारंपरिक सैन्य सुरक्षा से आगे बढ़कर गरीबी, भुखमरी, महामारियों और मानवाधिकारों के हनन जैसे विषयों को सुरक्षा का हिस्सा मानता है। इसका मानना है कि यदि व्यक्ति और समाज सुरक्षित नहीं हैं, तो केवल भौगोलिक सीमाओं की रक्षा करने का कोई अर्थ नहीं है।

127. (A) क्योंकि यह 'न्याय-युद्ध' की यूरोपीय परंपरा का परवर्ती विस्तार है।
आधुनिक अंतरराष्ट्रीय संबंधों में यह मान्यता कि युद्ध केवल उचित और नैतिक कारणों से होना चाहिए, वास्तव में 'न्याय-युद्ध' की प्राचीन यूरोपीय परंपरा का विस्तार है। आज लगभग पूरा विश्व इस बात पर सहमत है कि आत्म-रक्षा या दूसरों को जनसंहार से बचाने जैसे 'उचित' कारणों के बिना किया गया युद्ध अनैतिक है। इसी विचार के आधार पर संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में भी केवल आत्म-रक्षा के लिए ही बल-प्रयोग को वैध माना गया है।

128. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
एशिया और अफ्रीका के नव-स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की चुनौतियाँ अत्यंत जटिल थीं क्योंकि उन्हें एक साथ दो मोर्चों पर लड़ना था। एक तरफ उन्हें पड़ोसी देशों से संभावित बाहरी हमले का डर था, वहीं दूसरी तरफ उनके भीतर अनेक जातीय और अलगाववादी सैन्य-संघर्ष चल रहे थे। यह दोहरी चिंता उन्हें विकसित यूरोपीय देशों से अलग करती थी जिनकी आंतरिक सीमाएँ अपेक्षाकृत अधिक स्थिर थीं। अतः अभिकथन और कारण दोनों सही हैं।

129. (B) पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों धारणाओं में
सुरक्षा की अवधारणा चाहे पारंपरिक हो या अपारंपरिक, उसमें संदर्भ और स्थितियों को ध्यान में रखना अत्यंत अनिवार्य होता है। सुरक्षा कभी भी एक स्थिर विचार नहीं है; यह इस बात पर निर्भर करती है कि खतरा किसे है, किस समय है और उसकी प्रकृति क्या है। एक शांतिपूर्ण देश के लिए जो बात सामान्य हो सकती है, वही बात युद्ध की कगार पर खड़े देश के लिए एक गंभीर सुरक्षा चुनौती बन सकती है। अतः संदर्भ ही सुरक्षा की व्याख्या निर्धारित करता है।

130. (A) निरस्त्रीकरण, अस्त्र-नियंत्रण और आपसी विश्वास की बहाली
पारंपरिक सुरक्षा की धारणा के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए तीन प्रमुख सहयोगमूलक तरीके अपनाए जाते हैं: निरस्त्रीकरण, जिसके तहत खतरनाक हथियारों को खत्म किया जाता है; अस्त्र-नियंत्रण, जो हथियारों की होड़ और उनके प्रकारों को विनियमित करता है; और विश्वास की बहाली, जिसके माध्यम से देश अपनी सैन्य योजनाओं को साझा कर गलतफहमियों को दूर करते हैं। ये उपाय सैन्य टकराव की आशंका को कम करने और स्थिरता बढ़ाने में मदद करते हैं।

131. (B) P-3, Q-1, R-2, S-4
मानवाधिकारों की विभिन्न कोटियों का मिलान इस प्रकार है: पहली कोटि में राजनीतिक अधिकार आते हैं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। दूसरी कोटि में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को रखा जाता है। तीसरी कोटि में उन लोगों के सामूहिक अधिकार आते हैं जो उपनिवेशों में रहते थे या अल्पसंख्यक समूहों का हिस्सा हैं। सार्वभौम मानवाधिकारों के मामले में अभी भी पूरी दुनिया में सभी श्रेणियों पर आम सहमति का अभाव बना हुआ है।

132. (D) 1000 करोड़
वर्तमान जनसंख्या वृद्धि की दर और जनसांख्यिकीय अनुमानों के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या 21वीं सदी के मध्य, यानी वर्ष 2050 तक लगभग 1000 करोड़ (10 अरब) हो जाने की प्रबल संभावना है। जनसंख्या में यह भारी वृद्धि संसाधनों पर दबाव बढ़ाएगी, पर्यावरण को प्रभावित करेगी और गरीबी जैसी समस्याओं को जन्म देगी। यह तीव्र वृद्धि वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि इससे संसाधनों के लिए देशों के बीच संघर्ष बढ़ सकता है।

133. (C) राज्यों द्वारा शरणार्थियों को स्वीकार करना अनिवार्य है, प्रवासियों को नहीं
अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संधियों के तहत संप्रभु राज्यों के लिए यह कानूनी रूप से अनिवार्य है कि वे शरणार्थियों को स्वीकार करें और उन्हें सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि वे मजबूरी में अपनी जान बचाकर आते हैं। इसके विपरीत प्रवासियों को स्वीकार करना किसी राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि आप्रवासी स्वेच्छा से आर्थिक लाभ के लिए आते हैं। यही कारण है कि दुनिया भर में शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं।

134. (B) आप्रवास, व्यवसाय, पर्यटन और सैन्य-अभियानों की प्रक्रियाओं के जरिए
वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में एचआईवी-एड्स, बर्ड फ्लू और सार्स जैसी महामारियाँ बहुत तेजी से एक देश से दूसरे देश में फैली हैं। इसका मुख्य कारण लोगों की बढ़ती आवाजाही है, जो व्यवसाय, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन, बड़े पैमाने पर होने वाले आप्रवास और विभिन्न देशों द्वारा संचालित किए जाने वाले सैन्य-अभियानों के माध्यम से होती है। इन प्रक्रियाओं ने सीमाओं को पारगम्य बना दिया है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी खतरे अब स्थानीय न रहकर वैश्विक सुरक्षा का मसला बन गए हैं।

135. (B) केवल 1, 2 और 3 सही हैं।
महामारियों के संदर्भ में पहले तीन कथन पूर्णतः सत्य हैं। पुरानी बीमारियों ने अब दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है और पशुओं में फैलने वाली बीमारियों का गहरा आर्थिक प्रभाव पड़ता है। ये घटनाएँ बताती हैं कि आज के दौर में देश एक-दूसरे पर अधिक निर्भर हैं और बीमारियाँ सीमाओं को नहीं मानतीं। कथन 4 गलत है क्योंकि महामारियों के सामने राष्ट्रीय सीमाएँ अब पहले की तुलना में कम सार्थक और प्रभावी रह गई हैं।

136. (A) नहीं, ऐसा करने से सुरक्षा की धारणा में संगति नहीं रह जाएगी।
सुरक्षा की धारणा का विस्तार आवश्यक है, परंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि हर मानवीय कष्ट या साधारण बीमारी को सुरक्षा का मसला मान लिया जाए। यदि ऐसा किया गया तो सुरक्षा की अवधारणा अपनी विशिष्टता और गहराई खो देगी। सुरक्षा के दायरे में केवल उन्हीं मुद्दों को रखा जाना चाहिए जो समाज के अस्तित्व या उसके केंद्रीय मूल्यों के लिए प्रत्यक्ष और गंभीर खतरा पैदा करते हों, ताकि नीतिगत समाधान संभव हो सकें।

सुरक्षित रहें, जो व्यक्ति की गरिमा और भलाई के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

157. (D) भुखमरी और बीमारी।
मानव सुरक्षा में 'अभाव से मुक्ति' उन संरचनात्मक खतरों को संबोधित करती है जो प्रत्यक्ष हिंसा नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता को बाधित करते हैं। इसमें गरीबी, भुखमरी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं शामिल हैं क्योंकि ये कारक मानव अस्तित्व हेतु युद्ध जितने ही घातक हैं। यह अवधारणा सामाजिक और आर्थिक विकास को सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा मानती है ताकि व्यक्ति बुनियादी संसाधनों की कमी से पूरी तरह मुक्त रहे।

158. (A) सैन्य सुरक्षा।
यूएनडीपी द्वारा प्रस्तावित मानव सुरक्षा के सात घटकों में आर्थिक, खाद्य, स्वास्थ्य, पर्यावरण, व्यक्तिगत, सामुदायिक और राजनीतिक सुरक्षा शामिल हैं। सैन्य सुरक्षा इसमें शामिल नहीं है क्योंकि यह ढांचा राज्य-केंद्रित सैन्य शक्ति के बजाय गैर-सैन्य मानवीय खतरों पर केंद्रित है। यह वर्गीकरण स्पष्ट करता है कि सुरक्षा का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा की अनुपस्थिति नहीं बल्कि मानवीय गरिमा हेतु आवश्यक अवसरों की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

159. (C) 'भय से मुक्ति' प्रत्यक्ष हिंसा से संरक्षण पर और 'अभाव से मुक्ति' संरचनात्मक अभावों से संरक्षण पर केंद्रित है।
मानव सुरक्षा के ये दो स्तंभ अलग-अलग खतरों को लक्षित करते हैं। 'भय से मुक्ति' युद्ध और आतंकवाद जैसी प्रत्यक्ष शारीरिक हिंसा से बचाव पर बल देती है। 'अभाव से मुक्ति' का ध्यान उन आर्थिक और सामाजिक कारकों पर है जो संसाधनों की कमी पैदा करते हैं। दोनों आयाम मिलकर व्यक्ति की सुरक्षा हेतु एक ऐसा समग्र ढांचा तैयार करते हैं जो प्रत्यक्ष और संरचनात्मक खतरों को एक साथ सम्मिलित करता है।

160. (A) मानव सुरक्षा एक व्यापक और एकीकृत अवधारणा है जो व्यक्ति की गरिमा और भलाई पर केंद्रित है।
स्रोत का निष्कर्ष है कि सुरक्षा अब केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है। मानव सुरक्षा एक व्यापक दृष्टिकोण है जो व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं को समाहित करता है। यह पारंपरिक राज्य-केंद्रित मॉडल को चुनौती देते हुए विकास और व्यक्तिगत गरिमा के मध्य गहरा संबंध स्थापित करती है। यह सुरक्षा को एक एकीकृत अवधारणा मानती है जहाँ व्यक्ति की भलाई और गरिमा ही सर्वोपरि और अंतिम लक्ष्य है।

161. (D) एक विशिष्ट मुद्दे पर सिद्धांतों, मानदंडों, नियमों और प्रक्रियाओं के समूह के रूप में।
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में 'व्यवस्था' उन सिद्धांतों और नियमों का समूह है जो राज्यों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। ये व्यवस्थाएँ साझा मानदंडों के माध्यम से विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग की रुपरेखा प्रदान करती हैं। इनका उद्देश्य अराजकता कम करना और देशों की अपेक्षाओं में एकरूपता लाना है। इससे वैश्विक समस्याओं का सामूहिक समाधान संभव होता है और राष्ट्रों के मध्य आपसी विश्वास और स्थिरता बढ़ती है।

162. (B) वैश्विक या पार-राष्ट्रीय समस्याओं का प्रबंधन करना।
अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएँ उन वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करती हैं जो सीमाओं तक सीमित नहीं होतीं। परमाणु प्रसार और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों हेतु सामूहिक कार्रवाई अनिवार्य है। ये व्यवस्थाएँ राष्ट्रों को सहयोग हेतु प्रेरित करती हैं ताकि वे उन साझा जोखिमों को कम कर सकें जिन्हें अकेले संभालना असंभव है। यह तंत्र अराजकता कम कर साझा खतरों के प्रबंधन हेतु एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावी उपकरण प्रदान करता है।

163. (C) पारस्परिकता और साझा हितों पर।
केंद्रीय वैश्विक सत्ता के अभाव में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएँ पारस्परिकता और साझा हितों पर टिकी होती हैं। राज्य इन नियमों का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वे इसमें अपना दीर्घकालिक लाभ देखते हैं। विश्वास और साझा लक्ष्यों की प्राप्ति ही इन व्यवस्थाओं की स्थिरता का मुख्य आधार है। जब राष्ट्रों को विश्वास होता है कि दूसरे भी नियमों का पालन करेंगे, तभी सहयोग की प्रभावशीलता और निरंतरता संभव होती है।

164. (D) परमाणु अप्रसार संधि (NPT)।
परमाणु अप्रसार संधि एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है जो परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने हेतु नियम और मानदंड निर्धारित करती है। यह संधि सदस्य राष्ट्रों के लिए स्पष्ट उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। ऐसी व्यवस्थाएँ वैश्विक सुरक्षा हेतु आवश्यक संरचना प्रदान करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि तकनीकी प्रतिस्पर्धा विनाशकारी मोड़ न ले। यह साझा वैश्विक खतरों को प्रबंधित करने का सटीक उदाहरण है।

165. (A) क्योंकि उन्हें विश्वास है कि सहयोग उनके स्व-हित में है और इससे सामूहिक लाभ होता है।
राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का पालन यथार्थवादी गणनाओं के आधार पर करते हैं। वे समझते हैं कि व्यवस्था के भीतर सहयोग करना अकेले चलने की तुलना में अधिक लाभप्रद है। यह तर्क इस विचार पर आधारित है कि साझा नियमों से प्राप्त स्थिरता और सामूहिक लाभ किसी भी स्वतंत्र कार्रवाई से अधिक मूल्यवान हैं। स्व-हित और सामूहिक कल्याण का संतुलन ही राज्यों को इन नियमों का अनुकरण हेतु प्रेरित करता है।

166. (B) पर्यावरण क्षरण और संसाधनों की कमी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे पैदा कर सकते हैं।
पर्यावरणीय सुरक्षा का तर्क है कि पारिस्थितिक क्षरण और संसाधनों की कमी राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु गंभीर खतरा हैं। जब संसाधन कम होते हैं, तो संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। यह अवधारणा सुरक्षा को सैन्य शक्ति से आगे बढ़ाकर स्वस्थ पर्यावरण को स्थिरता की अनिवार्य शर्त मानती है। यह स्पष्ट करता है कि पर्यावरणीय तनाव सीधे तौर पर मानव कल्याण और शांति को प्रभावित करते हैं।

167. (B) साझा जल संसाधनों की कमी से उत्पन्न होने वाले राज्य-स्तरीय संघर्ष के रूप में।
जल एक सीमित संसाधन है जो सीमाओं के पार बहता है, जिससे यह भू-राजनीतिक तनाव का कारण बनता है। जब कई देश एक ही नदी पर निर्भर होते हैं, तो पानी के बंटवारे को

147. (C) इसने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने और समूहों को मंच प्रदान करने में मदद की है।
भारत द्वारा अपनाई गई लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था ने उसकी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में निर्णायक भूमिका निभाई है। इस व्यवस्था ने विभिन्न जातीय, भाषाई और क्षेत्रीय समूहों को अपनी माँगें और शिकायतें शांतिपूर्ण ढंग से रखने के लिए एक मंच प्रदान किया है। जब लोगों को महसूस होता है कि उनकी बात सुनी जा रही है और वे सत्ता में भागीदार हैं, तो अलगाववादी प्रवृत्तियाँ कमजोर होती हैं। इस प्रकार लोकतंत्र ने विविधतापूर्ण भारत को एकजुट रखने का कार्य किया है।

148. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
पारंपरिक सुरक्षा की धारणा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को एक निर्मम मैदान मानती है जहाँ शक्ति का ही बोलबाला है। इसका मुख्य कारण यह है कि विश्व-राजनीति में ऐसी कोई भी केंद्रीय सर्वोच्च सत्ता या 'वैश्विक सरकार' नहीं है जो देशों के व्यवहार पर नियंत्रण रख सके या विवादों का अंतिम निपटारा कर सके। इसी कारण प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार होना पड़ता है और हथियारों पर निर्भर रहना पड़ता है। अभिकथन और कारण दोनों इस यथार्थवादी स्थिति को स्पष्ट करते हैं।

149. (C) क्योंकि वह बाहरी हमलों से निपटने की तैयारी नहीं कर सकता।
पारंपरिक सुरक्षा की दृष्टि से यदि किसी देश के भीतर भीषण रक्तपात या गृह युद्ध हो रहा हो, तो वह देश सुरक्षित नहीं माना जा सकता है। इसका मुख्य रणनीतिक कारण यह है कि आंतरिक हिंसा में उलझा हुआ देश अपनी पूरी शक्ति और संसाधनों को बाहरी हमलों से निपटने के लिए तैयार नहीं कर पाता है। आंतरिक अस्थिरता देश की सैन्य क्षमता को कमजोर करती है और पड़ोसी देशों को हस्तक्षेप या आक्रमण करने का मौका प्रदान करती है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा संकट में पड़ जाती है।

150. (B) सैन्य-बल का प्रयोग सामूहिक स्वीकृति से और सामूहिक रूप से किया जाए
सहयोगमूलक सुरक्षा की धारणा यह मानती है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सैन्य-बल का प्रयोग अत्यंत दुर्लभ और केवल अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए। जब अन्य सभी शांतिपूर्ण और कूटनीतिक रास्ते पूरी तरह विफल हो जाएं, तभी बल-प्रयोग किया जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी कोई भी सैन्य कार्रवाई किसी एक देश की व्यक्तिगत इच्छा से नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सामूहिक स्वीकृति और भागीदारी के साथ होनी चाहिए, ताकि उसकी वैधता बनी रहे और वह न्यायपूर्ण हो।

151. (B) किसी एक राज्य के प्रभुत्व को रोकना।
शक्ति संतुलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता सुनिश्चित करना है ताकि कोई राज्य दूसरों पर हावी न हो सके। वेस्टफेलिया संधि के बाद उभरी यह प्रणाली राज्यों को सैन्य और राजनीतिक क्षमताओं को संतुलित करने हेतु प्रेरित करती है। यह आक्रामक शक्तियों की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं को हतोत्साहित करने हेतु सुरक्षा का एक रक्षात्मक तंत्र प्रदान कर प्रभुत्व को प्रभावी ढंग से रोकती है।

152. (A) एक द्विध्रुवीय संरचना जो 'आतंक के संतुलन' पर आधारित थी।
शीत युद्ध काल में वैश्विक व्यवस्था अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य द्विध्रुवीय थी। परमाणु हथियारों ने दोनों महाशक्तियों के बीच सीधा युद्ध असंभव बनाया जिसे 'आतंक का संतुलन' कहा गया। दोनों पक्ष जानते थे कि हमले का परिणाम पूर्ण विनाश होगा। इस संरचना ने वैचारिक गतिरोध के माध्यम से एक लंबी लेकिन तनावपूर्ण वैश्विक शांति बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य किया।

153. (C) प्रमुख शक्तियों के बीच राजनयिक वार्ताओं के माध्यम से।
वियना कांग्रेस के बाद स्थापित 'यूरोप की संगीत-सभा' ने बहुध्रुवीय शक्ति संतुलन हेतु सामूहिक दृष्टिकोण अपनाया। इसमें प्रमुख शक्तियों ने आपसी विवाद सुलझाने और क्षेत्रीय अस्थिरता रोकने हेतु नियमित राजनयिक वार्ताओं का उपयोग किया। यह व्यवस्था सीधे सैन्य संघर्ष के स्थान पर आपसी सहयोग और कूटनीतिक संवाद के माध्यम से शांति बनाए रखने के व्यावहारिक तंत्र पर आधारित थी जिसने स्थिरता सुनिश्चित की।

154. (D) सैन्य शक्ति, आर्थिक प्रभाव, तकनीकी नवाचार और राजनयिक कौशल का मिश्रण।
समकालीन वैश्विक व्यवस्था में शक्ति केवल पारंपरिक सेना तक सीमित नहीं है। राष्ट्रों का प्रभाव अब आर्थिक मजबूती, तकनीकी नवाचार और प्रभावी कूटनीति से मापा जाता है। बहुध्रुवीय विश्व में प्रमुख शक्तियाँ इन विविध कारकों द्वारा शक्ति संतुलन को आकार देती हैं। यह जटिलता वर्तमान अंतरराष्ट्रीय संबंधों को पहले से अधिक गतिशील बनाती है जहाँ सुरक्षा के सैन्य और गैर-सैन्य पहलू आपस में गुंथे हुए हैं।

155. (C) वेस्टफेलियन संतुलन → 'यूरोप की संगीत-सभा' का बहुध्रुवीय संतुलन → शीत युद्ध का द्विध्रुवीय संतुलन।
शक्ति संतुलन का विकास वेस्टफेलिया संधि से शुरू हुआ जिसने संप्रभु राज्य प्रणाली की नींव रखी। इसके बाद 19वीं सदी में बहुध्रुवीय कूटनीतिक प्रबंधन आया। शीत युद्ध काल में यह प्रणाली द्विध्रुवीय परमाणु संतुलन में बदल गई। यह क्रमिक विकास दर्शाता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बदलती प्रकृति के साथ शक्ति संतुलन बनाए रखने के तरीके और रणनीतियाँ भी समय के साथ निरंतर विकसित होती रही हैं।

156. (B) व्यक्ति और उसकी गरिमा।
यूएनडीपी की 1994 की रिपोर्ट ने सुरक्षा की अवधारणा को राज्य की सीमाओं से हटाकर व्यक्ति पर केंद्रित किया। मानव सुरक्षा का यह प्रतिमान व्यक्ति को प्राथमिक इकाई मानता है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों को हिंसा से बचाने के साथ-साथ एक गरिमापूर्ण वातावरण प्रदान करना है। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि मानवीय अधिकार और मूलभूत आवश्यकताएं

अध्याय 06
पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन

1. 1960 के दशक के बाद से वैश्विक मामलों में पर्यावरण को लेकर चिंता क्यों बढ़ने लगी?
(A) क्योंकि विकसित देशों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के वैश्विक मानकों को लागू करने हेतु दबाव डाला गया।
(B) क्योंकि विकास के पर्यावरणीय प्रभावों ने राजनीतिक स्वरूप ग्रहण करना शुरु कर दिया।
(C) क्योंकि सोवियत संघ के पतन के बाद वैश्विक राजनीति में सत्ता समीकरणों का पूर्ण बदलाव हुआ।
(D) क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण सुरक्षा को अनिवार्य रूप से एक वैश्विक नियम बनाया गया।

2. 1972 में 'लिमिट्स टू ग्रोथ' शीर्षक से पुस्तक किस विद्वत् समूह ने प्रकाशित की थी?
(A) क्लब ऑफ रोम
(B) ग्रीनपीस
(C) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)
(D) वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड (WWF)

3. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (पर्यावरणीय समस्या)
P. कृषि-योग्य भूमि
Q. मत्स्य-भंडार
R. जलराशि
S. ओज़ोन परत
सूची II: (प्रभाव)
1. प्रदूषण बढ़ना और मात्रा में कमी
2. क्षय होना
3. उर्वरता में कमी
4. घटना
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-3, R-2, S-1
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

4. संयुक्त राष्ट्र संघ की 2016 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, विकासशील देशों की कितनी आबादी को साफ़-सफाई की सुविधा से वंचित बताया गया है?
(A) 66.3 करोड़
(B) 30 लाख
(C) 170 करोड़
(D) दो अरब चालीस करोड़

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्राकृतिक वन जलवायु को संतुलित रखने में मदद करते हैं।
2. वनों से जलचक्र भी संतुलित बना रहता है।
3. वनों में धरती की जैव-विविधता का भंडार होता है।
4. वनों की कटाई और लोगों के विस्थापन से जैव-विविधता की हानि नहीं होती है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2 सही हैं।
(B) केवल 1, 2 और 3 सही हैं।
(C) केवल 4 गलत है।
(D) सभी कथन सही हैं।

6. 'पृथ्वी सम्मेलन' के रूप में जाना जाने वाला 1992 का संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन किस शहर में हुआ था?
(A) क्योटो
(B) रियो डी जनेरियो
(C) स्टॉकहोम
(D) जोहान्सबर्ग

7. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): पर्यावरण से जुड़े मसले गहरे अर्थों में राजनीतिक होते हैं।
कारण (R): पर्यावरण को कौन नुकसान पहुँचाता है और इस पर रोक लगाने की जिम्मेदारी किसकी है, यह बहुधा इस बात से निर्धारित होता है कि कौन देश कितना ताकतवर है।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

8. पृथ्वी सम्मेलन (1992) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(A) इस सम्मेलन का मुख्य ध्यान केवल विकसित देशों के आर्थिक विकास पर था।
(B) इसमें 170 देशों, हज़ारों स्वयंसेवी संगठनों और अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया।
(C) इसे 'अर्थ समिट' भी कहा जाता है।
(D) इसमें 'एजेंडा-21' के रूप में विकास के कुछ तौर-तरीके सुझाए गए।

लेकर असहमति गंभीर राज्य-स्तरीय संघर्ष पैदा कर सकती है। स्रोत स्पष्ट करता है कि संसाधनों की कमी कैसे पारंपरिक सैन्य संघर्षों के नए स्रोतों को जन्म देती है, जिन्हें 'जल युद्ध' कहा जाता है।

168. (A) वे लोग जिन्हें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है।
जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली प्राकृतिक आपदाएँ समुदायों को अपना घर छोड़ने पर विवश करती हैं। 'जलवायु शरणार्थी' वे व्यक्ति हैं जिनका निवास स्थान अब रहने योग्य नहीं रह गया है। यह विस्थापन न केवल मानवीय संकट है, बल्कि मेजबान क्षेत्रों में संसाधनों पर दबाव और सामाजिक-राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर सुरक्षा हेतु गंभीर खतरा है। यह पर्यावरणीय संकट के प्रत्यक्ष मानवीय परिणामों को दर्शाता है।

169. (C) यह प्रदर्शित करके कि गैर-सैन्य, पर्यावरणीय कारक भी संघर्ष और अस्थिरता का कारण बन सकते हैं।
पर्यावरणीय सुरक्षा पारंपरिक मॉडल को चुनौती देती है क्योंकि यह दर्शाती है कि गैर-सैन्य कारक भी संघर्ष का कारण बन सकते हैं। जहाँ पारंपरिक मॉडल केवल बाहरी सैन्य हमले पर ध्यान देता है, वहीं यह दृष्टिकोण प्रदूषण और संसाधन क्षरण को अस्थिरता का स्रोत मानता है। यह सुरक्षा की परिभाषा को व्यापक बनाकर उन खतरों को पहचानता है जिनका समाधान केवल सैन्य शक्ति द्वारा संभव नहीं है।

170. (D) पड़ोसी देशों के बीच संबंधों में तनाव।
प्रदूषण सीमाओं का सम्मान नहीं करता और एक देश की गतिविधियाँ पड़ोसी के पर्यावरण को नुकसान पहुँचा सकती हैं। नदियों या वायु का प्रदूषण अक्सर तीव्र राजनयिक विवादों का कारण बनता है। स्रोत के अनुसार, यह स्थिति अंतरराष्ट्रीय संबंधों को जटिल बनाती है और सुरक्षा हेतु चुनौती पेश करती है। सीमा-पार पर्यावरणीय क्षति राष्ट्रों के मध्य अविश्वास पैदा कर द्विपक्षीय संबंधों में गहरा तनाव बढ़ाती है।

171. (C) विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध (Credible Minimum Deterrence)।
भारत की परमाणु रणनीति विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध पर आधारित है जो हमला रोकने हेतु पर्याप्त शक्ति बनाए रखने पर बल देती है। 'विश्वसनीय' का अर्थ है कि जवाबी क्षमता वास्तविक होनी चाहिए, जबकि 'न्यूनतम' का अर्थ अनावश्यक हथियारों से बचना है। यह दृष्टिकोण भारत की सुरक्षा आवश्यकताओं और वैश्विक उत्तरदायित्वों के मध्य सामंजस्य स्थापित कर एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति की छवि प्रस्तुत करता है।

172. (B) भारत परमाणु हथियारों का उपयोग करने वाला पहला देश नहीं बनेगा।
भारत की 'पहले उपयोग नहीं' की नीति इसके रक्षात्मक परमाणु चरित्र को दर्शाती है। इसका तात्पर्य है कि भारत किसी भी संघर्ष में परमाणु हथियारों का उपयोग करने वाला पहला पक्ष कभी नहीं बनेगा। यह नीति वैश्विक समुदाय को भारत के शांतिपूर्ण इरादों का आश्वासन देती है। साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि भारत केवल अपनी संप्रभुता और अखंडता की सुरक्षा हेतु ही इन हथियारों को निवारक रूप में रखता है।

173. (D) यदि उस पर परमाणु, रासायनिक या जैविक हमला होता है।
भारत की नीति 'पहले उपयोग नहीं' की है, किंतु यह परमाणु, जैविक या रासायनिक हमले के विरुद्ध कठोर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देती है। यदि भारतीय क्षेत्र या सेना पर ऐसे हथियारों से हमला होता है, तो भारत बड़े पैमाने पर जवाबी परमाणु प्रहार करेगा। यह रणनीति दुश्मन हेतु असहनीय क्षति सुनिश्चित करने और परमाणु ब्लैकमेल या किसी भी आक्रामक हमले को रोकने के लिए अनिवार्य है।

174. (A) भारत जवाबी हमले के लिए आवश्यक विश्वसनीय क्षमता बनाए रखेगा बिना हथियारों की दौड़ में शामिल हुए।
न्यूनतम प्रतिरोध का सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि भारत परमाणु शस्त्रागार के मामले में किसी अनावश्यक प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं होगा। भारत केवल उतना शस्त्रागार रखता है जो शत्रु को असहनीय क्षति पहुँचाने और हमले को रोकने में सक्षम हो। यह नीति संसाधनों के उचित उपयोग और परमाणु अप्रसार के प्रति भारत के जिम्मेदार व्यवहार को वैश्विक मंच पर दृढ़ता से प्रदर्शित करने में मदद करती है।

175. (C) रणनीतिक स्वायत्तता और एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति की छवि।
भारत की परमाणु नीति रणनीतिक स्वायत्तता और उत्तरदायी परमाणु शक्ति की छवि में संतुलन बनाती है। यह बाहरी दबावों के बिना राष्ट्रीय हितों की रक्षा की स्वतंत्रता देने के साथ ही वैश्विक नियमों का पालन सुनिश्चित करती है। यह नीति भारत को अपनी सुरक्षा बनाए रखने और परमाणु अप्रसार के अंतरराष्ट्रीय मानकों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दिखाने में निरंतर महत्वपूर्ण मदद करती है।

को माना जाता है। केवल बड़ी संख्या में सैनिक होना पर्याप्त नहीं है; आधुनिक युद्धों में जीत के लिए उन्नत हथियार, संचार प्रणाली और एक मजबूत अर्थव्यवस्था की आवश्यकता होती है जो लंबे समय तक संघर्ष का भार सह सके। अतः जो देश आर्थिक और तकनीकी रूप से समृद्ध हैं, वे सैन्य रूप से भी अधिक शक्तिशाली और सुरक्षित माने जाते हैं।

97. (B) वियतनाम
1950 के दशक में फ्रांस को वियतनाम में एक भीषण और लंबे सैन्य संघर्ष का सामना करना पड़ा था। उस समय वियतनाम फ्रांस का एक उपनिवेश था और वहाँ की जनता अपनी आजादी के लिए लड़ रही थी। फ्रांस ने अपनी औपनिवेशिक सत्ता बचाए रखने की कोशिश की, परंतु उसे वियतनामी सेनाओं के कड़े प्रतिरोध और गुरिल्ला युद्ध के कारण अंततः हार माननी पड़ी और वहाँ से हटना पड़ा। यह औपनिवेशिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

98. (A) P-2, Q-4, R-3, S-1
सहयोगमूलक सुरक्षा में विभिन्न कर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और रेड क्रॉस अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्वयंसेवी संगठन हैं जो मानवाधिकारों और मानवीय सहायता के लिए कार्य करते हैं। नेल्सन मंडेला जैसी जानी-मानी हस्तियों ने शांति और सुरक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर प्रभाव डाला है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो महामारियों जैसी वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रों के बीच सहयोग सुनिश्चित करता है।

99. (C) आर्थिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा से
'अभाव से मुक्ति' की अवधारणा का सीधा संबंध व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा और उसकी मानवीय गरिमा से है। इसका तात्पर्य यह है कि सुरक्षा केवल बंदूकों और सीमाओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रत्येक मनुष्य को गरीबी, भूख और बेरोजगारी जैसे अभावों से भी छुटकारा मिलना चाहिए। जब तक समाज का हर व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा, तब तक उसे वास्तव में सुरक्षित नहीं माना जा सकता है।

100. (D) यह एक नई परिघटना है जो 2001 के बाद ही शुरु हुई।
आतंकवाद के बारे में यह कहना बिल्कुल गलत है कि यह एक नई परिघटना है जो केवल 2001 के बाद शुरु हुई। यद्यपि 9/11 के हमले के बाद इसका अंतरराष्ट्रीय स्वरूप अधिक मुखर हुआ है, परंतु आतंकवाद दशकों से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक खून-खराबे और नागरिकों को निशाना बनाने के साधन के रूप में मौजूद रहा है। यह एक पुरानी समस्या है जिसने समय के साथ नए और अधिक घातक रूप धारण कर लिए हैं।

101. (C) सुरक्षा के संदर्भी, खतरों के प्रकार और सुरक्षा के तरीकों पर
सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा पारंपरिक धारणा के तीन बुनियादी तत्त्वों पर सवाल उठाती है: सुरक्षा का संदर्भी कौन हो (सिर्फ राज्य या व्यक्ति), खतरे किस प्रकार के हों (सिर्फ सैन्य या गरीबी-महामारी भी), और सुरक्षा के तरीके क्या हों (सिर्फ सैन्य बल या अंतरराष्ट्रीय सहयोग)। यह विस्तार दर्शाता है कि आज की बदलती दुनिया में पुराने सैन्य-केंद्रित सुरक्षा मॉडल पर्याप्त नहीं हैं और इनमें व्यापक बदलाव की आवश्यकता है।

102. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
वैश्विक तापवृद्धि जैसे खतरों की प्रकृति ऐसी है कि कोई भी देश अपनी सीमाओं के भीतर रहकर अकेले इसका समाधान नहीं कर सकता। यदि समुद्र का स्तर बढ़ता है तो उससे सभी तटीय देश प्रभावित होंगे। इसलिए ऐसी वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सामूहिक रणनीतियाँ बनाना अत्यंत अनिवार्य हो जाता है। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं क्योंकि समस्या की व्यापकता ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलकर काम करने की माँग करती है।

103. (D) कुछ खास किस्म के हथियारों से सभी राज्यों का बाज आना
निरस्त्रीकरण का अर्थ दुनिया से सभी हथियारों को खत्म करना नहीं है, बल्कि कुछ खास किस्म के अत्यंत घातक हथियारों के निर्माण और प्रयोग से सभी राज्यों का बाज आना है। इसमें मुख्य रूप से सामूहिक विनाश के हथियार जैसे जैविक और रासायनिक हथियारों को प्रतिबंधित करना शामिल है। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना और हथियारों की उस होड़ को रोकना है जो संपूर्ण मानवता के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकती है।

104. (A) सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण
START (Strategic Arms Reduction Treaty) का संबंध सामरिक हथियारों के न्यूनीकरण से है। यह अमरीका और सोवियत संघ (बाद में रूस) के बीच की गई संधियों की एक श्रृंखला है जिसका मुख्य लक्ष्य परमाणु हथियारों और उनके प्रक्षेपास्त्रों की संख्या में बड़ी कटौती करना था। यह अस्त्र-नियंत्रण के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है क्योंकि इसने दुनिया को परमाणु महाविनाश की आशंका से थोड़ा दूर ले जाने में मदद की है।

105. (D) उपरोक्त सभी सही हैं।
दूसरे विश्वयुद्ध के बाद का समय अत्यंत जटिल था। शीतयुद्ध के दौरान दुनिया दो गुटों में बँट गई थी और महाशक्तियों के बीच निरंतर तनाव बना रहता था। उसी समय अनेक यूरोपीय देशों को अपने उपनिवेशों में बढ़ते विद्रोहों और हिंसा का सामना करना पड़ा। 1940 के दशक के अंत से शुरु हुए स्वतंत्रता आंदोलनों ने इन उपनिवेशों को आज़ाद कराया। ये सभी तथ्य उस दौर की अंतरराष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को सही ढंग से दर्शाते हैं।

106. (A) धनी देशों को
प्रति व्यक्ति उच्च आय और जनसंख्या की कम वृद्धि दर का सीधा लाभ धनी विकसित देशों को मिलता है। इन देशों में संसाधनों की प्रचुरता और कम आबादी के कारण जीवन स्तर बहुत ऊँचा होता है और वे स्वास्थ्य, शिक्षा तथा तकनीक में अधिक निवेश कर पाते हैं। इसके विपरीत गरीब देशों में तेजी से बढ़ती जनसंख्या और कम आय उनकी सुरक्षा और विकास

9. निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के क्रम में व्यवस्थित करें:
1. 'अवर कॉमन फ्यूचर' शीर्षक बर्टलैंड रिपोर्ट का प्रकाशन
2. 'लिमिट्स टू ग्रोथ' पुस्तक का प्रकाशन
3. पृथ्वी सम्मेलन (रियो सम्मेलन)
4. क्योटो प्रोटोकॉल पर सहमति
5. अंटार्कटिका संधि

(A) 5, 2, 1, 3, 4
(B) 2, 1, 3, 4, 5
(C) 1, 2, 5, 3, 4
(D) 5, 1, 2, 4, 3

10. 'टिकाऊ विकास' की अवधारणा का क्या अर्थ है?
(A) पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए आर्थिक विकास करने का संतुलित तरीका।
(B) तीव्र आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना, भले ही पर्यावरण को भारी कीमत चुकानी पड़े।
(C) केवल पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना और विकास को रोकना।
(D) विकसित देशों द्वारा थोपे गए विकास के पश्चिमी मॉडलों को पूर्णतः अपनाना।

11. 'वैश्विक संपदा' या 'मानवता की साझी विरासत' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष शामिल हैं।
2. इन पर किसी एक देश का संप्रभु क्षेत्राधिकार नहीं होता है।
3. इनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है।
4. केवल विकसित देश ही इनके प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हैं।
5. 'वैश्विक संपदा' की सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आसानी से कायम हो जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1, 2 और 3 सही हैं।
(B) केवल 4 और 5 सही हैं।
(C) केवल 1, 3 और 5 सही हैं।
(D) उपरोक्त सभी सही हैं।

12. 1987 में प्रकाशित 'अवर कॉमन फ्यूचर' शीर्षक रिपोर्ट में क्या मुख्य चेतावनी दी गई थी?
(A) विश्व स्तर पर बढ़ते हुए शीत युद्ध के खतरों और संभावित परमाणु संघर्ष के बारे में।
(B) वर्तमान आर्थिक विकास के तरीकों के भविष्य में गैर-टिकाऊ होने के बारे में।
(C) विकासशील देशों में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाले खतरों के बारे में।
(D) आधुनिक समाज में परमाणु हथियारों के प्रसार और उनकी बढ़ती हुई होड़ के बारे में।

13. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (संधि/प्रोटोकॉल)
P. अंटार्कटिका संधि
Q. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
R. अंटार्कटिका पर्यावरणीय प्रोटोकॉल
S. क्योटो प्रोटोकॉल

सूची II: (वर्ष)
1. 1987
2. 1997
3. 1959
4. 1991

(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-1, R-4, S-2
(C) P-2, Q-4, R-1, S-3
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

14. 'साझी परंतु अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ' के सिद्धांत के संबंध में विकासशील देशों का क्या तर्क है?
(A) विश्व स्तर पर सभी देशों की पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी और जवाबदेही पूर्णतः बराबर हो।
(B) विकासशील देशों को पर्यावरण संरक्षण की सभी वैश्विक बाध्यताओं से पूर्ण छूट मिले।
(C) केवल गैर-सरकारी संगठनों को ही पर्यावरण के संरक्षण हेतु पूर्ण ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए।
(D) विकसित देशों के औद्योगिक विकास से हुए नुकसान के कारण उनकी ज़िम्मेदारी अधिक है।

15. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों को क्योटो-प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से अलग रखा गया।
कारण (R): ऐतिहासिक रूप से और मौजूदा समय में भी ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा हिस्सा विकसित देशों का है और विकासशील देशों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम है।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

16. अंटार्कटिक महादेश के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है?
(A) यह विश्व के निर्जन क्षेत्र का 26% हिस्सा है।
(B) इस पर केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस का संप्रभु अधिकार है।
(C) यहाँ स्थलीय हिम का 90% और स्वच्छ जल का 70% हिस्सा मौजूद है।
(D) इसका समुद्री पारिस्थितिकी-तंत्र क्रिल मछली के कारण अत्यंत उर्वर है।

जाने वाले वैश्विक अभियान।
(D) स्वच्छ जल संसाधनों के अधिकार हेतु होने वाले हिंसक संघर्ष।

79. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): ब्रितानी औपनिवेशिक शासन कायम होने के बाद से भारत के जनजातीय समुदायों का सामना बाहरी लोगों से हुआ।
कारण (R): ब्रितानी शासन से पहले आदिवासी समुदाय पूरी तरह से अलग-थलग और आत्मनिर्भर थे और उनका किसी से संपर्क नहीं था।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

80. 'वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल' को संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन सा दर्जा दिया गया?
(A) स्थायी सदस्य का
(B) परामर्शदायी परिषद् का
(C) वीटो शक्ति प्राप्त सदस्य का
(D) पर्यवेक्षक राज्य का

81. 1992 के पृथ्वी सम्मेलन का एक प्रमुख परिणाम क्या था?
(A) क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर।
(B) टिकाऊ विकास और 'एजेंडा-21' का सर्वसम्मत अनुमोदन।
(C) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की स्थापना।
(D) पेरिस समझौते पर सहमति।

82. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (व्यक्ति/संगठन)
P. क्लब ऑफ रोम
Q. संयुक्त राष्ट्र संघ
R. बर्टलैंड रिपोर्ट
S. भारत सरकार
सूची II: (पहल/प्रकाशन)
1. ऊर्जा-संरक्षण अधिनियम, 2001
2. अवर कॉमन फ्यूचर
3. पृथ्वी सम्मेलन, 1992
4. लिमिट्स टू ग्रोथ
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-1, R-4, S-3
(C) P-4, Q-3, R-2, S-1
(D) P-3, Q-4, R-1, S-2

83. 'विजनपन' (Wilderness) का दृष्टिकोण, जिसमें पर्यावरण को मनुष्य से दूर की चीज माना जाता है, किन क्षेत्रों में अधिक प्रभावी है?
(A) भारत और चीन
(B) लैटिन अमेरिका और अफ्रीका
(C) ऑस्ट्रेलिया, स्कैंडिनेविया, उत्तरी अमरीका
(D) पश्चिम एशिया

84. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. दक्षिणी गोलार्द्ध के देशों में 'विजनपन' का अभियान एकदम नदारद है।
2. भारत में 'बंगाल-टाइगर' को बचाने की मुहिम चल रही है।
3. विजनपन से जुड़े अनेक मसलों को हाल में जैव-विविधता के मसलों का रूप दिया गया है।
4. दक्षिणी गोलार्ध के देशों में विजनपन की अवधारणा को आसानी से स्वीकृति मिल गई है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 2 और 3 सही हैं।
(B) केवल 1 और 4 गलत हैं।
(C) केवल 1, 2 और 4 सही हैं।
(D) सभी कथन गलत हैं।

85. 'साझी संपदा' के आकार में गिरावट, गुणवत्ता में कमी और गरीबों के लिए उसकी उपलब्धता कम होने का क्या कारण है?
(A) निजीकरण और गहनतर खेती
(B) आबादी की वृद्धि
(C) उपरोक्त सभी
(D) पारिस्थितिकी तंत्र की गिरावट

86. भारत का यह तर्क कि उत्सर्जन-दर में कमी करने की सबसे ज़्यादा ज़िम्मेवारी विकसित देशों की है, किस सिद्धांत पर आधारित है?
(A) साझी विरासत
(B) साझी परंतु अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ
(C) टिकाऊ विकास
(D) वैश्विक संपदा

87. भारत में बायोडीजल से संबंधित राष्ट्रीय मिशन का लक्ष्य क्या है?
(A) 2030 तक सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक बनाना।
(B) पेट्रोल और डीजल का आयात बंद करना।
(C) प्राकृतिक गैस का उपयोग बढ़ाना।
(D) 2011-12 तक बायोडीजल तैयार करना।

88. 1997 में भारत द्वारा पृथ्वी-सम्मेलन के समझौतों के क्रियान्वयन के पुनरावलोकन का मुख्य निष्कर्ष क्या था?
(A) विकासशील देशों को रियायती शर्तों पर नई प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने में कोई सार्थक प्रगति नहीं हुई है।
(B) विकासशील देशों को पर्यावरण सुरक्षा हेतु पर्याप्त

(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-2, Q-3, R-4, S-1

26. UNFCCC (1992) के नियमाचार के अनुसार, पर्यावरण संरक्षण के लिए देशों की ज़िम्मेदारियाँ किस आधार पर तय होती हैं?
(A) अपनी क्षमता और पर्यावरण क्षय में अपनी हिस्सेदारी के आधार पर।
(B) प्रत्येक संबंधित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर।
(C) संबंधित राष्ट्र की कुल जनसंख्या के दबाव और आकार के आधार पर।
(D) संबंधित राष्ट्र की वैश्विक सैन्य शक्ति और सामरिक प्रभाव के आधार पर।

27. भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों में क्या शामिल नहीं है?
(A) नेशनल ऑटो-फ्यूल पॉलिसी के तहत स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य करना।
(B) 2001 में ऊर्जा-संरक्षण अधिनियम पारित करना।
(C) 2003 के बिजली अधिनियम में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना।
(D) सभी औद्योगिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना।

28. भारत ने पेरिस जलवायु समझौते को कब अनुमोदित किया?
(A) 15 अगस्त 1947
(B) 2 अक्टूबर 2016
(C) 26 जनवरी 1950
(D) 5 जून 1992

29. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. दक्षिणी देशों के वन-आंदोलन उत्तरी देशों के वन-आंदोलनों से भिन्न हैं।
2. उत्तरी गोलार्ध के देशों में वन को प्रायः निर्जन प्रांत के रूप में देखा जाता है।
3. दक्षिणी देशों में पर्यावरण के अधिकांश मसले इस मान्यता पर आधारित हैं कि लोग वनों में भी रहते हैं।
4. 'विजनपन' (wilderness) का दृष्टिकोण मनुष्य को प्रकृति का हिस्सा मानता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 4 सही हैं।
(B) केवल 1, 2 और 3 सही हैं।
(C) केवल 3 और 4 सही हैं।
(D) सभी कथन सही हैं।

30. फिलीपिन्स में किस ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी के खिलाफ कई समूहों ने मिलकर अभियान चलाया?
(A) वेस्टर्न माइनिंग कारपोरेशन
(B) रियो टिंटो
(C) बीएचपी बिलिटन
(D) वेस्टर्न माइनिंग कारपोरेशन

31. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): 1980 के दशक में चले बाँध-विरोधी आंदोलन को अब नदियों को बचाने के आंदोलनों के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है।
कारण (R): ऐसे आंदोलनों में नदियों और नदी-घाटियों के ज़्यादा टिकाऊ तथा न्यायसंगत प्रबंधन की बात उठायी जाती है।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

32. विश्व का पहला बाँध-विरोधी आंदोलन 1980 के दशक में कहाँ चला?
(A) उत्तरी गोलार्ध में (भारत)
(B) दक्षिणी गोलार्ध में (ऑस्ट्रेलिया)
(C) उत्तरी गोलार्ध में (संयुक्त राज्य अमेरिका)
(D) दक्षिणी गोलार्ध में (ब्राज़ील)

33. 'संसाधनों की भू-राजनीति' किन सवालों से जूझती है?
(A) संसाधन कैसे बनते हैं।
(B) किसे, क्या, कब, कहाँ और कैसे हासिल होता है।
(C) संसाधनों का विनाश कैसे होता है।
(D) केवल संसाधनों का भंडारण कैसे करें।

34. 17वीं सदी के बाद यूरोपीय शक्तियों की प्राथमिकताओं में जहाजों के लिए इमारती लकड़ियों की आपूर्ति क्यों महत्वपूर्ण थी?
(A) क्योंकि उस काल में समुद्री नौवहन पूर्णतः इमारती लकड़ियों पर ही आधारित था।
(B) क्योंकि यूरोपीय शक्तियाँ लकड़ी से विशेष प्रकार के विलासी फर्नीचर बनाना चाहती थीं।
(C) क्योंकि इमारती लकड़ी एक अत्यंत मूल्यवान और स्थायी नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है।
(D) क्योंकि उन्हें विशाल स्तर पर कागज़ के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रियाओं को पूर्ण करना था।

35. शीतयुद्ध के दौरान उत्तरी गोलार्ध के विकसित देशों ने संसाधनों की सतत् आपूर्ति के लिए क्या कदम उठाए?
1. संसाधन-दोहन के इलाकों में सेना की तैनाती।
2. महत्वपूर्ण संसाधनों का भंडारण।
3. उत्पादक देशों में मनपसंद सरकारों की बहाली।
4. बहुराष्ट्रीय निगमों को समर्थन।
5. विकासशील देशों के साथ प्रौद्योगिकी साझा करना।

उपरोक्त में से सही विकल्प चुनें:
(A) केवल 1, 2, 3 और 5

(B) केवल 1, 2, 3 और 4
(C) केवल 2, 3, 4 और 5
(D) उपरोक्त सभी

36. वैश्विक रणनीति में आज भी सबसे महत्त्वपूर्ण संसाधन कौन सा बना हुआ है?
(A) कोयला
(B) जल
(C) यूरेनियम
(D) तेल

37. निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के क्रम में व्यवस्थित करें:
1. 'वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल' का गठन
2. संयुक्त राष्ट्र द्वारा मूलवासियों की शुरुआती परिभाषा देना
3. फिलीपिन्स में 'वेस्टर्न माइनिंग कारपोरेशन' के खिलाफ अभियान
4. ऑस्ट्रेलिया में फ्रैंकलिन नदी को बचाने का आंदोलन

(A) 1, 4, 2, 3
(B) 4, 1, 2, 3
(C) 1, 2, 4, 3
(D) 2, 1, 4, 3

38. विश्व के कुल तेल-उत्पादन का लगभग 30 प्रतिशत और ज्ञात तेल-भंडार का 64 प्रतिशत हिस्सा किस क्षेत्र में मौजूद है?
(A) लैटिन अमेरिका
(B) पश्चिम एशिया (खाड़ी-क्षेत्र)
(C) उत्तरी अमेरिका
(D) दक्षिण-पूर्व एशिया

39. विश्व में तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश और सऊदी अरब के बाद दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश कौन है?
(A) ईरान और सऊदी अरब
(B) वेनेज़ुएला और कुवैत
(C) रुस और संयुक्त राज्य अमेरिका
(D) सऊदी अरब और इराक

40. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रुप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): साझे जल-संसाधन को लेकर देशों के बीच हिंसक संघर्ष होने की संभावना है।
कारण (R): विश्व के कुछ भागों में साफ पानी की कमी हो रही है और स्वच्छ जल हर हिस्से में समान मात्रा में मौजूद नहीं है।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

41. 1950 और 1960 के दशक में किन देशों के बीच जॉर्डन और यारमुक नदियों के जल बहाव को मोड़ने को लेकर संघर्ष हुआ?
(A) तुर्की, सीरिया और इराक
(B) भारत और पाकिस्तान
(C) इज़रायल, सीरिया तथा जॉर्डन
(D) मिस्र और सूडान

42. संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में 'मूलवासी' (Indigenous People) को किस प्रकार परिभाषित किया?
(A) किसी क्षेत्र के वे मूल निवासी जिन पर बाद में बाहरी संस्कृतियाँ हावी हो गईं।
(B) वे लोग जो किसी राष्ट्र के आधुनिक महानगरीय क्षेत्रों में प्राचीन काल से निवास करते हैं।
(C) वे लोग जो हाल के आर्थिक कारणों से अन्य देशों में समूह बनाकर प्रवास कर गए हों।
(D) किसी भी राष्ट्र के समस्त सामान्य नागरिक जिन्हें समान कानूनी और सामाजिक अधिकार प्राप्त हैं।

43. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (मूलवासी समूह/क्षेत्र)
P. कोरडिलेरा क्षेत्र
Q. मापुशे
R. चटगांव पर्वतीय क्षेत्र
S. कुना
सूची II: (देश/स्थान)
1. चिले
2. बांग्लादेश
3. पनामा नहर के पूरब में
4. फिलीपिन्स

(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-1, R-2, S-3
(C) P-2, Q-3, R-4, S-1
(D) P-3, Q-4, R-1, S-2

44. भारत में 'मूलवासी' के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है और वे कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हैं?
(A) अप्रवासी, 10 प्रतिशत
(B) अनुसूचित जनजाति या आदिवासी, 8 प्रतिशत
(C) अल्पसंख्यक, 15 प्रतिशत
(D) शहरी गरीब, 5 प्रतिशत

45. 'वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल' का गठन कब हुआ था?
(A) 1972
(B) 1992
(C) 1975
(D) 1985

46. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. विकास की परियोजनाओं से विस्थापित होने वालों में

मूलवासी समुदाय सबसे बड़ा है।
2. भारत में मूलवासियों को संवैधानिक सुरक्षा हासिल नहीं है।
3. मूलवासियों के अधिकारों से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हाल ही में उभरे हैं।
4. मूलवासी अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाना चाहते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 4 सही हैं।
(B) केवल 2 और 3 गलत हैं।
(C) केवल 1, 3 और 4 सही हैं।
(D) सभी कथन सही हैं।

47. पर्यावरण से जुड़े सरोकारों का राजनीतिक चरित्र ग्रहण करना कब शुरू हुआ?
(A) 1960 के दशक के बाद से
(B) 1990 के दशक से
(C) 2000 के दशक से
(D) 1945 से पहले

48. पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में कमी होने को 'ओज़ोन परत में छेद' कहा जाता है?
(A) ऑक्सीजन
(B) ओज़ोन
(C) नाइट्रोजन
(D) carbon डाइऑक्साइड

49. 'अवर कॉमन फ्यूचर' शीर्षक बर्टलैंड रिपोर्ट किस वर्ष छपी थी?
(A) 1972
(B) 1987
(C) 1992
(D) 1997

50. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): विकासशील देश चाहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण में उन पर वे प्रतिबंध न लगें जो विकसित देशों पर लगाये जाने हैं।
कारण (R): विकासशील देश अभी औद्योगीकरण की प्रक्रिया से गुज़र रहे हैं।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

51. अंटार्कटिक महादेश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दावा गलत है?
(A) ब्रिटेन और अर्जेन्टीना ने इस पर संप्रभु अधिकार का दावा किया।
(B) कई देशों का मानना है कि यह विश्व की साझी संपदा है।
(C) यहाँ केवल पर्यटन और मत्स्य आखेट की ही अनुमति है, वैज्ञानिक अनुसंधान की नहीं।
(D) यह पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र पर्यावरण-सुरक्षा के विशेष नियमों के अंतर्गत आता है।

52. निम्नलिखित में से क्या 'वैश्विक संपदा' का हिस्सा नहीं है?
(A) पृथ्वी का वायुमंडल
(B) अंटार्कटिका
(C) बाहरी अंतरिक्ष
(D) किसी देश का राष्ट्रीय उद्यान

53. निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें:
1. भारत द्वारा पेरिस समझौते का अनुमोदन
2. भारत द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल का अनुमोदन
3. भारत में ऊर्जा-संरक्षण अधिनियम का पारित होना
4. पृथ्वी सम्मेलन, रियो

(A) 4, 2, 3, 1
(B) 2, 3, 4, 1
(C) 4, 3, 2, 1
(D) 3, 4, 1, 2

54. रियो घोषणापत्र में किस सिद्धांत को माना गया?
(A) सभी की बराबर ज़िम्मेदारी
(B) साझी परंतु अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ
(C) केवल विकसित देशों की ज़िम्मेदारी
(D) केवल विकासशील देशों की ज़िम्मेदारी

55. भारत सरकार की 2005 में की गई घोषणा के अनुसार, विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों की ग्रीन हाउस गैसों की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर कैसी है?
(A) नाममात्र है
(B) बहुत ज़्यादा है
(C) लगभग बराबर है
(D) बहुत ज़्यादा है

56. निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण आंदोलन नहीं है?
(A) वनों की व्यावसायिक कटाई का समर्थन करने वाला एक संगठित आंदोलन।
(B) हानिकारक खनिज-उद्योग के विस्तार के विरुद्ध वैश्विक आंदोलन।
(C) पारिस्थितिकी को नुकसान पहुँचाने वाले बड़े बाँधों के खिलाफ संघर्ष।
(D) नदियों के अस्तित्व और उनके प्रदूषण मुक्त बहाव को बचाने का आंदोलन।

57. पर्यावरण आंदोलनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ये आज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जीवंत, विविधतापूर्ण तथा ताकतवर सामाजिक आंदोलनों में शुमार किए जाते

हैं।
2. इन आंदोलनों से नए विचार निकलते हैं।
3. ये आंदोलन केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही सक्रिय हैं, स्थानीय स्तर पर नहीं।
4. ये आंदोलन केवल सरकारों द्वारा ही चलाए जाते हैं।
5. दक्षिणी देशों में वन-आंदोलनों पर कोई दबाव नहीं है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3, 4 और 5
(C) केवल 1, 2 और 5
(D) उपरोक्त सभी

58. ऑस्ट्रेलिया में चला फ्रैंकलिन नदी का आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था?
(A) वन, विजनपन और बाँध-विरोधी, तीनों
(B) केवल वन और विजनपन की पैरोकारी करने वाला
(C) केवल बाँध-विरोधी आंदोलन
(D) केवल खनिज-उद्योग के विरुद्ध

59. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद भी सरकारों की चिंता तेल की सुरक्षित आपूर्ति बनाए रखने की है।
कारण (R): बीसवीं सदी के अधिकांश समय में विश्व की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर रही है और यह आज भी वैश्विक रणनीति में महत्त्वपूर्ण बना हुआ है।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

60. तुर्की, सीरिया और इराक के बीच किस नदी पर बाँध के निर्माण को लेकर तनातनी है?
(A) जॉर्डन नदी
(B) फरात नदी
(C) नील नदी
(D) यारमुक नदी

61. भारत की अधिकांश आदिवासी जनता अपने जीवन-यापन के लिए किस पर निर्भर है?
(A) शहरी नौकरियों पर
(B) औद्योगिक कार्यों पर
(C) खेती पर
(D) विदेशी सहायता पर

62. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (अवधारणा/रिपोर्ट)
P. लिमिट्स टू ग्रोथ
Q. अवर कॉमन फ्यूचर
R. एजेंडा-21
S. साझी परंतु अलग-अलग जिम्मेदारियाँ

सूची II: (संबंधित/परिणाम)
1. बर्टलैंड रिपोर्ट
2. रियो सम्मेलन
3. क्लब ऑफ रोम
4. UNFCCC का सिद्धांत

(A) P-3, Q-1, R-2, S-4
(B) P-1, Q-2, R-4, S-3
(C) P-4, Q-3, R-1, S-2
(D) P-2, Q-4, R-3, S-1

63. विकासशील देशों की 66.3 करोड़ जनता को कौन सी बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं है, जैसा कि 2016 की मानव विकास रिपोर्ट में कहा गया है?
(A) स्वच्छ जल
(B) बिजली
(C) इंटरनेट
(D) पक्के मकान

64. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पृथ्वी सम्मेलन में जलवायु-परिवर्तन, जैव-विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित हुए।
2. 'एजेंडा-21' के आलोचकों का कहना है कि इसका झुकाव आर्थिक वृद्धि की ओर है।
3. 'टिकाऊ विकास' पर अमल कैसे किया जाएगा, यह एक अनसुलझी समस्या बनी रही।
4. पृथ्वी सम्मेलन में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देश सभी मुद्दों पर पूरी तरह सहमत थे।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 4 सही हैं।
(B) केवल 4 गलत है।
(C) केवल 1, 2 और 3 सही हैं।
(D) सभी कथन सही हैं।

65. अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज किस दशक के मध्य में हुई?
(A) 1970 के दशक
(B) 1980 के दशक
(C) 1990 के दशक
(D) 1960 के दशक

66. भारत की 'नेशनल ऑटो-फ्यूल पॉलिसी' का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(A) वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य करना।
(B) वाहनों का उत्पादन बढ़ाना।
(C) वाहनों पर कर बढ़ाना।
(D) इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रतिबंध लगाना।

67. 'देवस्थान' की व्यवस्था की विशेषताएँ किससे मिलती-जुलती हैं?

(A) निजी संपत्ति के संरक्षण की व्यवस्था से
(B) सरकारी संपत्ति के संरक्षण की व्यवस्था से
(C) साझी संपदा के संरक्षण की व्यवस्था से
(D) बहुराष्ट्रीय निगमों की संपत्ति से

68. भारत में कौन सा बाँध-विरोधी आंदोलन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है?
(A) टिहरी बाँध आंदोलन
(B) भाखड़ा नांगल आंदोलन
(C) सरदार सरोवर आंदोलन
(D) नर्मदा आंदोलन

69. विश्व-राजनीति के लिए पानी एक महत्त्वपूर्ण संसाधन क्यों है?
(A) क्योंकि यह प्रकृति द्वारा असीमित मात्रा में हर स्थान पर सहज उपलब्ध है।
(B) क्योंकि सभी राष्ट्र वर्तमान में पानी की ज़रूरतों के मामले में पूर्णतः आत्मनिर्भर हैं।
(C) क्योंकि विश्व के कुछ भागों में स्वच्छ जल की कमी और वितरण असमान है।
(D) क्योंकि इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करना अन्य संसाधनों की तुलना में आसान है।

70. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): मूलवासियों की भूमि की हानि उनके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है।
कारण (R): भूमि की हानि का अर्थ है, आर्थिक-संसाधनों के एक आधार की हानि।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

71. निम्नलिखित में से कौन-सा देश अंटार्कटिक क्षेत्र पर अपने संप्रभु अधिकार का दावा करने वालों में शामिल नहीं है?
(A) ब्रिटेन
(B) नॉर्वे
(C) फ्रांस
(D) भारत

72. पर्यावरण के वैश्विक अपक्षय में विभिन्न राज्यों के योगदान के बारे में रियो-घोषणापत्र क्या कहता है?
(A) विभिन्न राज्यों का योगदान अलग-अलग है।
(B) सभी राज्यों का योगदान बराबर है।
(C) केवल विकासशील देशों का योगदान है।
(D) योगदान का आकलन करना असंभव है।

73. निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें:
1. अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार (प्रोटोकॉल)
2. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
3. अंटार्कटिका संधि
4. क्योटो प्रोटोकॉल
(A) 3, 2, 1, 4
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 3, 4, 1
(D) 4, 1, 2, 3

74. क्योटो प्रोटोकॉल किन देशों के लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करता है?
(A) औद्योगिक (विकसित) देशों के लिए
(B) केवल विकासशील देशों के लिए
(C) सभी देशों के लिए समान रूप से
(D) केवल G-8 देशों के लिए

75. पर्यावरण आंदोलनों के संबंध में क्या असत्य है?
(A) ये सामाजिक चेतना के दायरे में राजनीतिक कार्रवाई के नए रूप खोजते हैं।
(B) ये वैयक्तिक और सामूहिक जीवन के लिए दृष्टि प्रदान करते हैं।
(C) दक्षिणी देशों में वन-आंदोलनों पर बहुत दबाव है।
(D) ये केवल विकसित देशों तक ही सीमित हैं।

76. 'संसाधनों की भू-राजनीति' के पश्चिमी चिंतन के मूल में क्या था?
(A) पर्यावरण का वैश्विक संरक्षण।
(B) विदेशी संसाधनों की उपलब्धता और नौवहन दक्षता।
(C) बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा।
(D) व्यापक सांस्कृतिक आदान-प्रदान।

77. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पेट्रोलियम का history युद्ध और संघर्षों का भी इतिहास है।
2. सऊदी अरब के पास विश्व के कुल तेल-भंडार का एक चौथाई हिस्सा मौजूद है।
3. इराक का ज्ञात तेल-भंडार सऊदी अरब से ज़्यादा है।
4. जल को लेकर देशों के बीच कभी कोई संघर्ष नहीं हुआ है।
5. तेल की वैश्विक राजनीति में कोई खास भूमिका नहीं है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2 सही हैं।
(B) केवल 3, 4 और 5 सही हैं।
(C) केवल 1, 2 और 5 सही हैं।
(D) उपरोक्त सभी गलत हैं।

78. 'जलयुद्ध' शब्द का प्रयोग विद्वान किस संदर्भ में करते हैं?
(A) अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापारिक मार्गों पर पूर्ण नियंत्रण हेतु किए जाने वाले युद्ध।
(B) विभिन्न देशों की नौसेनाओं के मध्य समुद्र में होने वाले प्रत्यक्ष सैन्य युद्ध।
(C) जल प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के विरुद्ध चलाए

17. रियो-सम्मेलन में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बीच मुख्य मतभेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. उत्तरी देश ओज़ोन परत की छेद और वैश्विक तापवृद्धि को लेकर चिंतित थे।
2. दक्षिणी देश आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्ते को सुलझाने के लिए ज़्यादा चिंतित थे।
3. उत्तरी देश टिकाऊ विकास के पूरी तरह खिलाफ थे।
4. दक्षिणी देश पर्यावरण संरक्षण की कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1 और 2 सही हैं।
(B) केवल 3 और 4 सही हैं।
(C) केवल 1 और 3 सही हैं।
(D) केवल 2 और 4 सही हैं।

18. UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है?

(A) यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज
(B) यूनाइटेड नेशंस फ़्लड एंड क्लाइमेट कमीशन
(C) यूनियन of नार्थ एंड फ़ॉरेस्ट कंजर्वेशन कमिटी
(D) यूनाइटेड नॉर्म्स फॉर क्लाइमेट कंट्रोल

19. 'साझी संपदा' के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?

(A) इस पर किसी एक का नहीं, बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है।
(B) इसके उदाहरणों में संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारागाह, या मैदान शामिल हैं।
(C) निजीकरण और आबादी की वृद्धि से साझी संपदा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
(D) इसके रख-रखाव में समूह के हर सदस्य को समान अधिकार और उत्तरदायित्व निभाने होते हैं।

20. क्योटो प्रोटोकॉल क्या है?

(A) केवल विकासशील देशों हेतु निर्धारित पर्यावरण सुरक्षा संबंधी एक अनिवार्य समझौता।
(B) जल प्रदूषण को वैश्विक स्तर पर नियंत्रित करने से संबंधित एक प्रमुख समझौता।
(C) संकटग्रस्त प्रजातियों की जैव-विविधता के संरक्षण पर केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता।
(D) औद्योगिक देशों हेतु ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता।

21. भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल (1997) पर हस्ताक्षर और अनुमोदन कब किया?

(A) 1997
(B) 2005
(C) 2002
(D) 2016

22. निम्नलिखित में से कौन सी गैसें ग्रीनहाउस गैसें मानी जाती हैं, जिनकी वैश्विक तापवृद्धि में भूमिका होती है?

1. कार्बन डाइऑक्साइड
2. मीथेन
3. हाइड्रो-फ्लोरो कार्बन
4. ऑक्सीजन
5. नाइट्रोजन

उपरोक्त में से सही विकल्प चुनें:

(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 4 और 5
(C) केवल 1, 2 और 4
(D) उपरोक्त सभी

23. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।

अभिकथन (A): बाहरी अंतरिक्ष के प्रबंधन पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बीच मौजूद असमानता का असर पड़ा है।

कारण (R): बाहरी अंतरिक्ष में दोहन-कार्य प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास पर निर्भर करते हैं, जिसमें उत्तरी देश आगे हैं।

(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

24. भारत के 'पावन वन-प्रांतर' या 'देवस्थान' के बारे में क्या सही है?

(A) धार्मिक कारणों से संरक्षित वन क्षेत्र जिन्हें काटा नहीं जाता है।
(B) सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में विकसित किए गए आधुनिक वनस्पति उद्यान।
(C) औद्योगिक कंपनियों द्वारा प्रबंधित विशेष संसाधन युक्त आरक्षित वन क्षेत्र।
(D) ये वन केवल भारत के राजस्थान और केरल राज्यों में ही पाए जाते हैं।

25. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:

सूची I: ('देवस्थान' के स्थानीय नाम)

P. वानी, केंकड़ी, ओरान
Q. जहेरा थान, सरना
R. लिंगदोह
S. काव

सूची II: (राज्य)

1. झारखंड
2. मेघालय
3. केरल
4. राजस्थान

(A) P-4, Q-1, R-2, S-3

वित्तीय और आधुनिक प्रौद्योगिकी सहायता प्राप्त हुई है।
(C) विकसित देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर की गई अपनी सभी पुरानी प्रतिबद्धताओं को पूर्ण रूप से पूरा कर दिया है।
(D) वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की वर्तमान स्थिति में विगत वर्षों की तुलना में कोई गिरावट दर्ज नहीं की गई है।

89. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): खनिज-उद्योग पृथ्वी पर मौजूद सबसे ताकतवर उद्योगों में से एक है।
कारण (R): यह धरती के भीतर मौजूद संसाधनों को बाहर निकालता है, रसायनों का उपयोग करता है, और भूमि-जलमार्गों को प्रदूषित करता है, जिससे जन-समुदायों का विस्थापन होता है।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

90. मूलवासी समुदायों की एक प्रमुख मांग क्या है?
(A) मूलवासी कौम के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखना।
(B) आधुनिक शहरी क्षेत्रों में सामूहिक रूप से बसने का पूर्ण कानूनी अधिकार।
(C) सभी नागरिकों के लिए एक समान वैश्विक नागरिक संहिता लागू करना।
(D) बिना किसी रोक-टोक के अन्य विकसित देशों में अनियंत्रित प्रवास की स्वतंत्रता।

91. 1970 के दशक में अफ्रीका की सबसे बड़ी विपदाओं में से एक क्या थी, जिसके कारण 'पर्यावरणीय शरणार्थी' जैसा शब्द प्रचलित हुआ?
(A) बाढ़
(B) भूकंप
(C) ज्वालामुखी विस्फोट
(D) अनावृष्टि (सूखा)

92. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. विकासशील देशों की पहली और अपरिहार्य प्राथमिकता आर्थिक तथा सामाजिक विकास की है।
2. भारत इस बात के खिलाफ है कि उस पर ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की बाध्यता आयद की जाए।
3. भारत का 2030 तक प्रति व्यक्ति उत्सर्जन विश्व के 2000 के औसत से अधिक हो जाएगा।
4. भारत दक्षेस देशों के साथ मिलकर पर्यावरण के मसलों पर एक समान राय बनाने का पक्षधर है।
5. भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई घरेलू नीति नहीं अपनाई है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1, 2 और 4 सही हैं।
(B) केवल 3 और 5 गलत हैं।
(C) केवल 1, 2, 3 और 4 सही हैं।
(D) सभी कथन सही हैं।

93. भारत में बाँध विरोधी तथा पर्यावरण-बचाव के अन्य आंदोलन किस एक बात में समानधर्मी हैं?
(A) वे हिंसा पर आधारित हैं।
(B) वे केवल शहरी क्षेत्रों में सक्रिय हैं।
(C) वे अहिंसा पर आधारित हैं।
(D) उन्हें विदेशी ताकतों से समर्थन मिलता है।

94. संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोप, जापान, चीन और भारत जैसे देश तेल के लिए किस क्षेत्र पर बहुत अधिक निर्भर हैं?
(A) लैटिन अमेरिका
(B) रूस
(C) अफ्रीका
(D) पश्चिम एशिया (खाड़ी-क्षेत्र)

95. मूलवासियों के निवास स्थान वाले क्षेत्रों में कौन सा शामिल नहीं है?
(A) पश्चिमी यूरोप
(B) मध्य और दक्षिण अमरीका
(C) अफ्रीका, दक्षिणपूर्व एशिया
(D) भारत

96. पर्यावरण के नुकसान से जुड़े मसलों को विश्व-राजनीति का हिस्सा क्यों माना जाता है?
(A) क्योंकि ये केवल एक ही विशिष्ट देश की सीमाओं को प्रभावित करते हैं।
(B) क्योंकि इनका समाधान कोई एक देश अकेले नहीं कर सकता।
(C) क्योंकि ये शुद्ध रूप से केवल भौगोलिक और भू-शास्त्रीय मुद्दे हैं।
(D) क्योंकि इन पर केवल प्रशिक्षित वैज्ञानिक ही प्रभावी कार्य कर सकते हैं।

97. 'एजेंडा-21' के बारे में कुछ आलोचकों की क्या राय है?
(A) यह पूरी तरह से केवल पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों पर ही केंद्रित है।
(B) इसका झुकाव पर्यावरण सुरक्षा के बजाय आर्थिक वृद्धि की ओर अधिक है।
(C) यह केवल विकसित राष्ट्रों के हितों के लिए ही पूर्णतः फायदेमंद है।
(D) इसे वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में लागू करना अत्यंत आसान कार्य है।

98. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (आंदोलन/अभियान)
P. 'बंगाल-टाइगर' बचाओ
Q. वेस्टर्न माइनिंग कारपोरेशन के विरुद्ध

R. नर्मदा आंदोलन
S. फ्रैंकलिन नदी बचाओ

सूची II: (देश)
1. फिलीपिन्स
2. भारत
3. ऑस्ट्रेलिया
4. भारत

(A) P-4, Q-1, R-2, S-3
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-2, Q-3, R-4, S-1
(D) P-3, Q-4, R-1, S-2

99. निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए:
1. क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर
2. रियो पृथ्वी सम्मेलन
3. 'लिमिट्स टू ग्रोथ' का प्रकाशन
4. 'अवर कॉमन फ्यूचर' रिपोर्ट का प्रकाशन

(A) 3, 4, 2, 1
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 4, 3, 2, 1
(D) 2, 1, 4, 3

100. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।

अभिकथन (A): 1990 के दशक से वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार बन गए हैं।

कारण (R): 1992 के पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के प्रमुख मुद्दों में शामिल करा दिया और वैश्विक चेतना बढ़ी।

(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

101. 'अंटार्कटिका पर किसका स्वामित्व है?' इस प्रश्न के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कुछ देशों (जैसे ब्रिटेन, अर्जेंटीना आदि) ने इस पर अपने संप्रभु अधिकार का दावा किया।
2. अन्य अधिकांश देशों ने इसे विश्व की साझी संपदा माना।
3. इस पर केवल संयुक्त राष्ट्र का अधिकार है।
4. यह पूरी तरह से मानव गतिविधियों के लिए बंद है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3 और 4
(C) केवल 1 और 3
(D) केवल 2 और 4

102. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड (WWF) जैसे संगठनों ने किस प्रकार के अभियानों की शुरुआत और वित्तीय मदद की है?

(A) मुख्य रूप से केवल शहरी विकास और महानगरीय विस्तार से जुड़े अभियान।
(B) जंतु-प्रजातियों के संरक्षण हेतु 'विजनपन' से जुड़े अनेक वैश्विक अभियान।
(C) केवल राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक चुनाव और सत्ता परिवर्तन संबंधी अभियान।
(D) केवल औद्योगिक विस्तार और संसाधनों के व्यावसायिक दोहन के वैश्विक अभियान।

103. 'संसाधनों की भू-राजनीति' के संबंध में कौन सा कथन गलत है?

(A) यूरोपीय ताकतों के विश्वव्यापी प्रसार का एक मुख्य साधन और मकसद संसाधन रहे हैं।
(B) पहले और दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान तेल की निर्बाध आपूर्ति का महत्त्व उजागर हुआ।
(C) शीतयुद्ध के दौरान विकसित देशों ने संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए।
(D) संसाधनों को लेकर राज्यों के बीच कभी तनातनी नहीं हुई है।

104. भारत सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों में मौजूद लगभग 30 करोड़ मूलवासियों के सर्वसामान्य हित विश्व-राजनीति के संदर्भ में क्या हैं?

(A) अपने मूल वासस्थान पर हक और स्वतंत्र पहचान को बनाए रखना।
(B) अपनी पारंपरिक जीवन शैली को पूर्णतः त्यागकर आधुनिक बनना।
(C) बेहतर आर्थिक अवसरों हेतु विकसित देशों में स्थायी प्रवास करना।
(D) सभी प्रकार की वैश्विक पर्यावरणीय संधियों का सामूहिक विरोध करना।

105. विकास की बड़ी कीमत किन्हें चुकानी पड़ी है?

(A) समाज के आधुनिक शहरी अभिजात वर्ग को।
(B) बड़े स्तर के व्यावसायिक बहुराष्ट्रीय निगमों को।
(C) विस्थापित होने वाले मूलवासी समुदायों को।
(D) विकसित देशों की शक्तिशाली सरकारों को।

106. निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 'देवस्थान' का स्थानीय नाम नहीं है?

(A) नेशनल पार्क
(B) सरना
(C) काव
(D) देव रहतिस

107. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'देवस्थान' की मान्यता से जैव-विविधता और सांस्कृतिक वैविध्य को कायम रखने में मदद मिलती है।
2. हाल के सालों में मनुष्यों की बसाहट के विस्तार ने

'देवस्थानों' पर अपना कब्ज़ा कर लिया है।
3. नयी राष्ट्रीय वन-नीतियों के आने से इन परंपरागत वनों की पहचान और मज़बूत हुई है।
4. 'देवस्थान' के प्रबंधन में कोई समस्या नहीं आती है।
5. 'देवस्थान' का कानूनी स्वामित्व और व्यावहारिक नियंत्रण हमेशा एक ही संस्था के पास होता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2 सही हैं।
(B) केवल 3, 4 और 5 सही हैं।
(C) केवल 1, 2 और 5 सही हैं।
(D) उपरोक्त सभी सही हैं।

108. भारत का 2000 तक प्रति व्यक्ति carbon उत्सर्जन कितना था और 2030 तक इसके कितना होने का अनुमान है?
(A) 0.9 टन; 1.6 टन
(B) 0.9 टन; 1.6 टन
(C) 3.8 टन; 5.0 टन
(D) 1.6 टन; 0.9 टन

109. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): वैश्विक पर्यावरण आंदोलनों को आज सबसे ज़्यादा जीवंत, विविधतापूर्ण तथा ताकतवर सामाजिक आंदोलनों में शुमार किया जाता है।
कारण (R): ये आंदोलन केवल कुछ विशिष्ट देशों और केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही सक्रिय हैं।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

110. तेल के बाद विश्व-राजनीति के लिए दूसरा महत्त्वपूर्ण संसाधन कौन सा है जिसके लिए संघर्ष की आशंका जताई जाती है?
(A) कोयला
(B) लोहा
(C) सोना
(D) पानी

111. 'काला सोना' किस संसाधन को संदर्भित करता है?
(A) पेट्रोलियम (तेल)
(B) कोयला
(C) लोहा अयस्क
(D) मैंगनीज

112. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (क्षेत्र/देश)
P. खाड़ी-क्षेत्र
Q. ऑस्ट्रेलिया
R. भारत
S. फिलीपिन्स

सूची II: (संबंधित पर्यावरणीय मुद्दा/आंदोलन)
1. फ्रैंकलिन नदी आंदोलन
2. वेस्टर्न माइनिंग कारपोरेशन का विरोध
3. नर्मदा आंदोलन
4. विश्व का 64% तेल-भंडार

(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-1, R-3, S-2
(C) P-2, Q-3, R-1, S-4
(D) P-3, Q-4, R-2, S-1

113. 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था?
(A) जैव-विविधता का संरक्षण।
(B) ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना।
(C) जल प्रदूषण को रोकना।
(D) वनों की कटाई पर रोक लगाना।

114. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'साझी परंतु अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ' का सिद्धांत पृथ्वी सम्मेलन (1992) में मान लिया गया।
2. UNFCCC (1992) के अनुसार, विकसित देशों का ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में ऐतिहासिक और मौजूदा हिस्सा ज़्यादा है।
3. क्योटो प्रोटोकॉल एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं है।
4. भारत और चीन को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं के अंतर्गत रखा गया था।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2 सही हैं।
(B) केवल 3 और 4 गलत हैं।
(C) केवल 1, 2 और 4 सही हैं।
(D) सभी कथन गलत हैं।

115. दक्षिणी देशों के वन-आंदोलन उत्तरी देशों से किस अर्थ में भिन्न हैं?
(A) दक्षिणी देशों के वन पूर्णतः जनविहीन हैं, जबकि उत्तरी देशों के वनों में घनी आबादी है।
(B) दक्षिणी देशों में वन निर्जन माने जाते हैं, जबकि उत्तरी देशों के वनों में स्थानीय लोग रहते हैं।
(C) उत्तरी देशों के वन निर्जन माने जाते हैं, जबकि दक्षिणी देशों के वनों में लोग निवास करते हैं।
(D) दोनों क्षेत्रों के वन-आंदोलनों की प्रकृति और उद्देश्यों में वर्तमान में कोई भिन्नता नहीं है।

116. भारत का यह मानना क्यों है कि विकासशील देशों को स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकसित देशों द्वारा मुहैया कराई जानी चाहिए?
(A) क्योंकि विकासशील देशों के पास वर्तमान में अत्यधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं।
(B) क्योंकि विकसित देशों के पास कोई भी स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी वर्तमान में नहीं है।
(C) क्योंकि यह विकासशील देशों द्वारा की गई एक अत्यंत

पहली बार पर्यावरण को एक गंभीर वैश्विक मुद्दे के रूप में स्थापित किया और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद, 1980 के दशक में 'सतत विकास' की अवधारणा का उदय हुआ, जिसे ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट 'हमारा साझा भविष्य' (1987) द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। इस अवधारणा ने विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एकीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया। इस विचार को 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में संस्थागत रूप दिया गया, जिसने जलवायु परिवर्तन (UNFCCC) और जैव विविधता (CBD) पर प्रमुख ढाँचागत समझौतों को जन्म दिया। इस पूरी प्रक्रिया में, गैर-राज्य कर्ताओं, जैसे कि पर्यावरण गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और वैज्ञानिक निकायों (जैसे IPCC) की भूमिका तेजी से बढ़ी है। इन कर्ताओं ने जन जागरूकता बढ़ाने, सरकारों पर दबाव बनाने और नीति-निर्माण के लिए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डेटा प्रदान करने में केंद्रीय भूमिका निभाई है, जिससे वैश्विक पर्यावरण शासन का परिदृश्य अधिक बहुआयामी और जटिल हो गया है।

उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

171. स्रोत के अनुसार, 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन का मुख्य महत्व क्या था?
(A) इसने सतत विकास की अवधारणा को जन्म दिया।
(B) इसने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करवाए।
(C) इसने पहली बार पर्यावरण को एक गंभीर वैश्विक मुद्दे के रूप में स्थापित किया।
(D) इसने केवल समुद्री प्रदूषण पर ध्यान केंद्रित किया।

172. 'सतत विकास' की अवधारणा किस बात पर जोर देती है?
(A) केवल तीव्र आर्थिक विकास पर।
(B) विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एकीकरण पर।
(C) केवल पर्यावरण संरक्षण पर।
(D) औद्योगिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध पर।

173. वैश्विक पर्यावरण शासन के विकास में गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की क्या भूमिका रही है?
(A) उनकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही है।
(B) उन्होंने केवल वित्तीय सहायता प्रदान की है।
(C) उन्होंने केवल स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है।
(D) उन्होंने जागरूकता बढ़ाकर और सरकारों पर दबाव बनाकर एक केंद्रीय भूमिका निभाई है।

174. अनुच्छेद के अनुसार, समय के साथ वैश्विक पर्यावरण शासन में क्या प्रवृत्ति देखी गई है?
(A) यह अधिक संस्थागत, बहुआयामी और जटिल हो गया है।
(B) यह कम महत्वपूर्ण हो गया है।
(C) यह केवल कुछ देशों तक ही सीमित रहा है।
(D) यह पूरी तरह से सरकारों के नियंत्रण में आ गया है।

175. 1992 का रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस अवधारणा को संस्थागत रूप देने के लिए महत्वपूर्ण था?
(A) राष्ट्रीय संप्रभुता।
(B) साझा की त्रासदी।
(C) सतत विकास।
(D) शीत युद्ध की राजनीति।

(A) जल
(B) कोयला
(C) इमारती लकड़ी
(D) तेल

127. 'हम यहाँ अनंत काल से रहते चले आ रहे हैं' - यह जुमला किनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है?
(A) विश्वभर के मूलनिवासियों द्वारा
(B) विकसित देशों द्वारा
(C) बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा
(D) पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा

128. भारत ने 'दक्षेस' (SAARC) के मंच पर पर्यावरण के मुद्दे को क्यों उठाना चाहा?
(A) ताकि दक्षेस देशों पर दबाव बनाया जा सके।
(B) ताकि इस क्षेत्र की आवाज़ वैश्विक मंच पर वज़नी हो सके।
(C) ताकि दक्षेस को भंग किया जा सके।
(D) ताकि विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा की जा सके।

129. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में सबसे बड़ा समुदाय आदिवासियों का है।
2. 1975 में 'वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल' का गठन हुआ।
3. संयुक्त राष्ट्र ने इस परिषद् को कोई मान्यता नहीं दी।
4. भारत में आदिवासियों को कोई संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2 सही हैं।
(B) केवल 3 और 4 गलत हैं।
(C) केवल 1, 2 और 4 सही हैं।
(D) सभी कथन गलत हैं।

130. 1970 के दशक में विश्व के विभिन्न भागों के मूलवासियों के नेताओं के बीच संपर्क बढ़ने का क्या परिणाम हुआ?
(A) उनके साझे अनुभवों और सरोकारों को एक शक्ल मिली।
(B) उनके बीच संघर्ष बढ़ गया।
(C) उन्होंने अपनी पारंपरिक पहचान खो दी।
(D) उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से खुद को अलग कर लिया।

131. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): रियो-सम्मेलन में यह बात खुलकर सामने आयी कि विश्व के धनी और गरीब देश पर्यावरण के अलग-अलग अजेंडे के पैरोकार हैं।
कारण (R): उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओज़ोन परत और वैश्विक तापवृद्धि थी जबकि दक्षिणी देश आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के रिश्ते को सुलझाने में चिंतित थे।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

132. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (जलमार्ग/नदी)
P. जॉर्डन और यारमुक नदी
Q. फरात नदी
R. नर्मदा नदी
S. फ्रैंकलिन नदी

सूची II: (संबंधित देश/क्षेत्र)
1. ऑस्ट्रेलिया
2. भारत
3. तुर्की, सीरिया, इराक
4. इज़रायल, सीरिया, जार्डन

(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-1, R-4, S-3
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

133. अराल सागर की समस्या के बारे में क्या सच है?
(A) पानी के विषाक्त होने से मत्स्य-उद्योग नष्ट हो गया।
(B) पानी में नमक की सांद्रता बढ़ने से पैदावार कम हो गई।
(C) उपरोक्त सभी।
(D) इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका।

134. "धरती के पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता और गुणवत्ता की बहाली, सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए विभिन्न देश विश्व-बंधुत्व की भावना से आपस में सहयोग करेंगे।" - यह कथन किस दस्तावेज़ का हिस्सा है?
(A) क्योटो प्रोटोकॉल
(B) रियो-घोषणापत्र
(C) पेरिस समझौता
(D) अंटार्कटिका संधि

135. वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाले किस विद्वत् समूह ने 1972 में 'लिमिट्स टू ग्रोथ' पुस्तक प्रकाशित की?
(A) ग्रीनपीस
(B) एमनेस्टी इंटरनेशनल
(C) रेड क्रॉस
(D) क्लब ऑफ रोम

136. भारत में 2003 के बिजली अधिनियम का एक प्रमुख उद्देश्य क्या था?
(A) नवीकरणीय (Renewable) ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना।
(B) परमाणु ऊर्जा को प्रतिबंधित करना।
(C) कोयले के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करना।
(D) बिजली का निजीकरण करना।

(D) अलगाववाद और तटस्थता।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
सीमा-पारीय जल संसाधन, विशेष रूप से नदियाँ और भूमिगत जलभृत, राष्ट्रों के बीच सहयोग और संघर्ष दोनों के संभावित स्रोत हैं। इस भू-राजनीति का केंद्र 'ऊपरी तटीय' (अपस्ट्रीम) और 'निचले तटीय' (डाउनस्ट्रीम) राज्यों के बीच का संबंध है। ऊपरी तटीय देश, जहाँ से नदी का उद्गम होता है या जो उसके प्रवाह पथ में पहले आते हैं, जल प्रवाह पर महत्वपूर्ण नियंत्रण रखते हैं। वे बांधों का निर्माण कर, कृषि के लिए बड़े पैमाने पर पानी का मार्ग बदलकर, या औद्योगिक कचरे से नदी को प्रदूषित कर निचले तटीय देशों के लिए पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप, निचले तटीय देश जल की कमी, कृषि उत्पादकता में गिरावट और पर्यावरणीय क्षरण जैसी समस्याओं का सामना कर सकते हैं, जिससे भू-राजनीतिक तनाव उत्पन्न होता है। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय जल कानून, जैसे कि 1997 का संयुक्त राष्ट्र जलमार्ग समझौता, जल के न्यायसंगत और तर्कसंगत उपयोग का आह्वान करता है, परन्तु इन कानूनों को लागू करने के लिए एक मजबूत प्रवर्तन तंत्र का अभाव है। इसलिए, जल संसाधनों का प्रबंधन अक्सर द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संधियों के माध्यम से किया जाता है, जिनकी सफलता राजनीतिक इच्छाशक्ति और आपसी विश्वास पर बहुत अधिक निर्भर करती है।
उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

156. ऊपरी तटीय (अपस्ट्रीम) और निचले तटीय (डाउनस्ट्रीम) देशों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या है?
(A) सांस्कृतिक मतभेद।
(B) जल प्रवाह पर असंतुलित नियंत्रण और उसका उपयोग।
(C) राजनीतिक विचारधाराओं में भिन्नता।
(D) व्यापारिक मार्गों पर विवाद।

157. स्रोत के अनुसार, एक 'निचले तटीय' देश को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है?
(A) अत्यधिक वर्षा और बाढ़।
(B) राजनीतिक अस्थिरता।
(C) तकनीकी पिछड़ापन।
(D) जल की कमी और प्रदूषण।

158. अनुच्छेद के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय जल कानून को लागू करने में मुख्य चुनौती क्या है?
(A) एक मजबूत प्रवर्तन तंत्र का अभाव है।
(B) संधियों की भाषा बहुत जटिल है।
(C) ऊपरी तटीय देश इन कानूनों को नहीं पहचानते हैं।
(D) यह कानून केवल भूमिगत जल पर लागू होता है।

159. किसी ऊपरी तटीय देश की कौन सी गतिविधि निचले तटीय देश के लिए भू-राजनीतिक तनाव पैदा कर सकती है?
(A) अपने क्षेत्र में वनीकरण को बढ़ावा देना।
(B) शिक्षा प्रणाली में सुधार करना।
(C) नदी पर एक बड़े बांध का निर्माण करना।
(D) सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन करना।

160. स्रोत यह क्या इंगित करता है कि सीमा-पारीय जल विवादों का सफल समाधान किस पर निर्भर करता है?
(A) संबंधित देशों के बीच राजनीतिक इच्छाशक्ति और आपसी विश्वास पर।
(B) सैन्य शक्ति के उपयोग पर।
(C) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के हस्तक्षेप पर।
(D) तीसरे पक्ष के देशों द्वारा मध्यस्थता पर।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
स्वदेशी समुदाय और पर्यावरण के बीच का संबंध केवल संसाधन उपयोग से कहीं बढ़कर है; यह सांस्कृतिक पहचान, आध्यात्मिकता और अस्तित्व का मामला है। दुनिया भर में, स्वदेशी लोगों ने पीढ़ियों से 'पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान' (Traditional Ecological Knowledge - TEK) का विकास और संरक्षण किया है। यह ज्ञान स्थानीय पारिस्थितिक तंत्रों की एक गहन समझ पर आधारित है और इसमें टिकाऊ कृषि, स्थायी कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की प्रथाएँ शामिल हैं। यह ज्ञान जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके विपरीत, संरक्षण का 'किला संरक्षण' (fortress conservation) मॉडल, जो मानव गतिविधियों को बाहर करने के लिए संरक्षित क्षेत्र बनाता है, अक्सर इन स्वदेशी समुदायों को उनकी पारंपरिक भूमि से विस्थापित कर देता है। यह न केवल उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है, बल्कि यह उस पारंपरिक ज्ञान को भी नष्ट कर देता है जो पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए, स्वदेशी भूमि अधिकारों को मान्यता देना और उन्हें संरक्षण प्रयासों में भागीदार बनाना केवल सामाजिक न्याय का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह एक प्रभावी पर्यावरण संरक्षण रणनीति भी है। उनका समग्र विश्वदृष्टिकोण, जो मानव और प्रकृति को अविभाज्य मानता है, आधुनिक संरक्षण विज्ञान को मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है।
उपर्दोक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

161. 'पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान' (TEK) क्या है?
(A) आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में विकसित ज्ञान।
(B) पश्चिमी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाने वाला पर्यावरण विज्ञान।
(C) औद्योगिक कृषि के लिए विकसित तकनीकें।
(D) पीढ़ियों से संचित स्थानीय पारिस्थितिक तंत्रों का गहन ज्ञान।

162. संरक्षण का 'किला संरक्षण' मॉडल स्वदेशी समुदायों को कैसे प्रभावित करता है?
(A) यह उन्हें संरक्षण प्रयासों में प्रमुख भागीदार बनाता है।
(B) यह उन्हें उनकी पारंपरिक भूमि से अक्सर विस्थापित कर

(C) केवल 1, 2 और 3 सही हैं।
(D) सभी कथन सही हैं।

147. बांग्लादेश के चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में कितने आदिवासी बसे हैं?
(A) 10 लाख
(B) 20 लाख
(C) 6 लाख
(D) 50 हजार

148. अंटार्कटिका महादेश की अंदरूनी हिमानी परत किसका महत्वपूर्ण सूचना-स्रोत है?
(A) भविष्य के मौसम का
(B) समुद्री जीवन का
(C) तेल भंडारों का
(D) ग्रीन हाऊस गैस के जमाव का

149. निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में रखें:
1. भारत में ऊर्जा-संरक्षण अधिनियम पारित हुआ
2. भारत ने पेरिस जलवायु समझौते को अनुमोदित किया
3. भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल को अनुमोदित किया
4. भारत में बिजली अधिनियम पारित हुआ

(A) 1, 4, 3, 2
(B) 3, 1, 4, 2
(C) 1, 3, 4, 2
(D) 4, 1, 2, 3

150. 'एजेंडा-21' में किस प्रकार के विकास के तौर-तरीके सुझाए गए थे?
(A) तीव्र औद्योगीकरण
(B) टिकाऊ विकास
(C) कृषि-आधारित विकास
(D) सेवा क्षेत्र आधारित विकास

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

पर्यावरणीय न्याय और 'साझी परंतु विभेदित जिम्मेदारियों' (CBDR) का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के आधारभूत स्तंभों में से एक है। इस सिद्धांत की जड़ें इस मान्यता में निहित हैं कि वैश्विक पर्यावरणीय क्षरण, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन, में सभी देशों का योगदान समान नहीं है। ऐतिहासिक रूप से, उत्तरी गोलार्ध के औद्योगिक रूप से विकसित देशों ने अपनी आर्थिक प्रगति के लिए जीवाश्म ईंधनों का बड़े पैमाने पर दोहन किया है, जिसके परिणामस्वरूप वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों का अधिकांश संचयन हुआ है। इसके विपरीत, दक्षिणी गोलार्ध के विकासशील देश अभी भी अपनी आबादी को गरीबी से बाहर निकालने और बुनियादी ढाँचे का विकास करने की प्रक्रिया में हैं, और उनका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन ऐतिहासिक रूप से और वर्तमान में भी बहुत कम है। CBDR सिद्धांत इस ऐतिहासिक उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है और तर्क देता है कि पर्यावरण संरक्षण का बोझ सभी पर समान रूप से नहीं डाला जा सकता। यह मानता है कि विकसित देशों को उत्सर्जन कम करने में नेतृत्व करना चाहिए और विकासशील देशों को टिकाऊ विकास पथ अपनाने में मदद करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए। यह सिद्धांत केवल जिम्मेदारी का विभाजन नहीं करता, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में समता और न्याय को स्थापित करने का एक प्रयास भी है।

उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

151. 'साझी परंतु विभेदित जिम्मेदारियों' (CBDR) का सिद्धांत किस मूल मान्यता पर आधारित है?
(A) सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण के लिए समान योगदान देना चाहिए।
(B) पर्यावरण क्षरण में सभी देशों का ऐतिहासिक योगदान असमान रहा है।
(C) विकासशील देशों को पर्यावरण की चिंता किए बिना विकास करना चाहिए।
(D) केवल उत्तरी गोलार्ध के देश ही पर्यावरण क्षरण के लिए जिम्मेदार हैं।

152. स्रोत के अनुसार, वैश्विक पर्यावरणीय क्षरण का सबसे बड़ा बोझ किसे उठाना चाहिए?
(A) वे देश जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से सबसे अधिक उत्सर्जन किया है।
(B) वे देश जिनका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन सबसे कम है।
(C) दक्षिणी गोलार्ध के सभी विकासशील देश।
(D) संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण शाखा।

153. यह सिद्धांत विकासशील देशों को विभेदित जिम्मेदारियाँ क्यों सौंपता है?
(A) क्योंकि उनके पास बेहतर तकनीक है।
(B) क्योंकि उनकी जनसंख्या कम है।
(C) क्योंकि उनकी विकासात्मक आवश्यकताएँ और निम्न प्रति व्यक्ति उत्सर्जन है।
(D) क्योंकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है।

154. स्रोत के अनुसार, उत्तरी गोलार्ध के देशों ने वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों के संचयन में सबसे अधिक योगदान क्यों दिया है?
(A) अपनी उच्च जनसंख्या के कारण।
(B) अपने कृषि पद्धतियों के कारण।
(C) वनों की कटाई की नीतियों के कारण।
(D) अपनी औद्योगिक प्रगति के लिए जीवाश्म ईंधन के व्यापक उपयोग के कारण।

155. CBDR सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किन नैतिक मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास करता है?
(A) प्रतिस्पर्धा और संप्रभुता।
(B) राष्ट्रीय सुरक्षा और शक्ति।
(C) समता और न्याय।

अनावश्यक सामरिक मांग है।
(D) क्योंकि यह 'UNFCCC' की वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने हेतु आवश्यक है।

117. 'जलयुद्ध' की संभावना का एक प्रचलित उदाहरण क्या है?
(A) दो राष्ट्रों के मध्य होने वाला नियमित और सामान्य नौसैनिक सैन्य अभ्यास।
(B) समुद्री खाद्य संसाधनों के व्यापारिक वितरण पर होने वाला एक छोटा विवाद।
(C) नदी के उद्गम पर बाँध बनाकर दूसरे देश हेतु जल प्रवाह को बाधित करना।
(D) ध्रुवीय क्षेत्रों में होने वाली प्राकृतिक बर्फबारी की दरों पर होने वाला विवाद।

118. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): मूलवासी अपनी ज़मीन और उस पर आधारित जीवन-प्रणालियों के बारे में एक जैसी विश्वदृष्टि रखते हैं, भले ही वे भौगोलिक रूप से अलग-अलग हों।
कारण (R): वे अपने मूल वासस्थान पर हक की दावेदारी के लिए 'हम यहाँ अनंत काल से रहते चले आ रहे हैं' जैसे जुमले का इस्तेमाल करते हैं।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

119. अंटार्कटिका में 1959 के बाद किन गतिविधियों की अनुमति रही है?
(A) सैन्य अड्डा बनाना और हथियार परीक्षण
(B) औद्योगिक खनन और शहरीकरण
(C) कृषि और पशुपालन
(D) वैज्ञानिक अनुसंधान, मत्स्य आखेट और पर्यटन

120. 'देवस्थान' या 'पावन वन-प्रांतर' का प्रबंधन परंपरागत रूप से कौन करता आया है?
(A) ग्रामीण समुदाय
(B) केंद्र सरकार
(C) राज्य सरकार
(D) निजी कंपनियाँ

121. निम्नलिखित में से कौन सा कथन 'साझी संपदा' की सही परिभाषा है?
(A) ऐसी संपदा जिस पर किसी व्यक्ति का निजी स्वामित्व हो।
(B) ऐसी संपदा जिस पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो।
(C) ऐसी संपदा जिस पर किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व हो।
(D) ऐसी संपदा जिसका कोई स्वामी न हो।

122. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (जनसंख्या/डेटा)
P. पृथ्वी सम्मेलन में भागीदार देश
Q. फिलीपिन्स के कोरडिलेरा क्षेत्र में मूलवासी
R. चिले में मापुशे मूलवासी
S. भारत में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत
सूची II: (संख्या)
1. 20 लाख
2. 10 लाख
3. 8%
4. 170
(A) P-4, Q-1, R-2, S-3
(B) P-1, Q-4, R-3, S-2
(C) P-3, Q-2, R-1, S-4
(D) P-2, Q-3, R-4, S-1

123. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अराल सागर के विषाक्त होने से मत्स्य-उद्योग नष्ट हो गया।
2. दुनिया भर में कृषि-योग्य भूमि में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है।
3. प्राकृतिक वन जलवायु को असंतुलित करते हैं।
4. पूरे विश्व में समुद्रतटीय क्षेत्रों का प्रदूषण घट रहा है।
5. विकासशील देशों की 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 5 सही हैं।
(B) केवल 2, 3 और 4 सही हैं।
(C) केवल 1, 2 और 5 सही हैं।
(D) उपरोक्त सभी गलत हैं।

124. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था?
(A) संपूर्ण विश्व में मुक्त व्यापार और आर्थिक विकास को निरंतर बढ़ावा देना।
(B) पर्यावरणीय समस्याओं पर अधिक प्रभावी और सुलझी हुई पहलकदमियां शुरू करना।
(C) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल सैन्य शांति और सामरिक सुरक्षा को बनाए रखना।
(D) वैश्विक स्तर पर उभरती हुई स्वास्थ्य समस्याओं का पूर्ण समाधान करना।

125. दक्षिणी गोलार्ध के देशों की अर्थव्यवस्था किसके कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खुल चुकी है?
(A) शीत युद्ध की समाप्ति के कारण
(B) संयुक्त राष्ट्र के दबाव के कारण
(C) वैश्विक अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के कारण
(D) जनसंख्या वृद्धि के कारण

126. पहला और दूसरा विश्वयुद्ध के दौरान किस सामरिक संसाधन का महत्त्व उजागर हुआ?

देता है।
(C) यह उनके पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देता है।
(D) यह उनके लिए आर्थिक अवसर पैदा करता है।

163. अनुच्छेद के अनुसार, स्वदेशी भूमि अधिकारों को मान्यता देना एक प्रभावी पर्यावरण रणनीति क्यों है?
(A) क्योंकि स्वदेशी लोग आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं।
(B) क्योंकि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है।
(C) क्योंकि यह उनके पारंपरिक ज्ञान के उपयोग को सक्षम बनाता है जो संरक्षण में मदद करता है।
(D) क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग को आकर्षित करता है।

164. स्वदेशी समुदायों का विश्वदृष्टिकोण मानव और प्रकृति के बीच किस प्रकार के संबंध को दर्शाता है?
(A) मानव को प्रकृति से श्रेष्ठ मानता है।
(B) मानव और प्रकृति को एक-दूसरे से अलग मानता है।
(C) प्रकृति को केवल एक आर्थिक संसाधन के रूप में देखता है।
(D) मानव और प्रकृति को अविभाज्य और परस्पर जुड़ा हुआ मानता है।

165. 'किला संरक्षण' मॉडल को लागू करने का एक अनपेक्षित नकारात्मक परिणाम क्या हो सकता है?
(A) पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण पारंपरिक ज्ञान की हानि।
(B) जैव विविधता में वृद्धि।
(C) स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास।
(D) प्रदूषण के स्तर में कमी।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
वैश्विक साझा संसाधन (Global Commons) वे क्षेत्र और संसाधन हैं जो किसी एक राष्ट्र के संप्रभु अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थित हैं। इनमें उच्च समुद्र, वायुमंडल, अंटार्कटिका और बाहरी अंतरिक्ष शामिल हैं। इन साझा संसाधनों का प्रबंधन एक अनूठी चुनौती प्रस्तुत करता है जिसे अक्सर 'साझा की त्रासदी' की अवधारणा के माध्यम से समझा जा सकता है। चूँकि इन पर किसी एक सत्ता का स्वामित्व नहीं है, इसलिए प्रत्येक देश अपने व्यक्तिगत अल्पकालिक लाभ को अधिकतम करने के लिए इन संसाधनों का अति-दोहन करने के लिए प्रेरित हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक देश अंतर्राष्ट्रीय जल में मछली पकड़ने की अपनी दर बढ़ा सकता है या बिना किसी रोक-टोक के वायुमंडल में प्रदूषक उत्सर्जित कर सकता है। जब कई देश इसी तरह का व्यवहार करते हैं, तो इसका परिणाम संसाधन का क्षय या विनाश होता है, जिससे अंततः सभी को सामूहिक रूप से दीर्घकालिक हानि होती है। इस समस्या का मूल कारण एक प्रभावी केंद्रीय शासन तंत्र का अभाव है जो उपयोग को विनियमित कर सके और नियमों को लागू कर सके। इन साझा संसाधनों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों की आवश्यकता होती है, लेकिन इन पर सहमति बनाना और इनका अनुपालन सुनिश्चित करना अक्सर मुश्किल होता है, क्योंकि यह राष्ट्रीय हितों पर अंकुश लगाने की मांग करता है।
उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

166. निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत के अनुसार एक 'वैश्विक साझा संसाधन' का उदाहरण है?
(A) किसी देश की राष्ट्रीय नदी।
(B) अंटार्कटिका महाद्वीप।
(C) अमेज़ॅन वर्षावन।
(D) साइबेरिया के जंगल।

167. अनुच्छेद में वर्णित 'साझा की त्रासदी' का मुख्य संकट क्या है?
(A) विकसित और विकासशील देशों के बीच तकनीकी अंतर।
(B) व्यक्तिगत, अल्पकालिक लाभ और सामूहिक, दीर्घकालिक हानि के बीच का संघर्ष।
(C) विभिन्न संस्कृतियों के बीच संचार की कमी।
(D) संसाधनों के वितरण में भौगोलिक असमानताएँ।

168. वैश्विक साझा संसाधनों के प्रबंधन में सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
(A) उपयोग को विनियमित करने के लिए एक प्रभावी केंद्रीय शासन तंत्र का अभाव।
(B) इन संसाधनों तक पहुँचने के लिए प्रौद्योगिकी की कमी।
(C) इन संसाधनों के अस्तित्व के बारे में जानकारी का अभाव।
(D) इन संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होना।

169. वैश्विक साझा संसाधन अति-दोहन के प्रति संवेदनशील क्यों होते हैं?
(A) क्योंकि वे बहुत तेजी से नवीनीकृत होते हैं।
(B) क्योंकि वे केवल कुछ ही देशों के लिए सुलभ हैं।
(C) क्योंकि वे किसी एक राष्ट्र के संप्रभु अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं।
(D) क्योंकि उनका कोई पारिस्थितिक महत्व नहीं है।

170. यदि कई देश अंतर्राष्ट्रीय जल में बिना किसी सीमा के मछली पकड़ते हैं, तो अनुच्छेद के अनुसार इसका संभावित दीर्घकालिक परिणाम क्या होगा?
(A) मछली की कीमतें बहुत कम हो जाएँगी।
(B) मछली पकड़ने की तकनीक में सुधार होगा।
(C) केवल एक देश को ही सारी मछलियाँ मिलेंगी।
(D) मत्स्य भंडार का क्षय हो जाएगा, जिससे सभी को नुकसान होगा।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
वैश्विक पर्यावरण शासन की यात्रा 20वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरु हुई, जब पर्यावरण संबंधी चिंताएँ धीरे-धीरे राष्ट्रीय सीमाओं से परे जाकर वैश्विक मंच पर स्थापित होने लगीं। इस विकास में 1972 का स्टॉकहोम में हुआ संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन (UNCHE) एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने

137. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'देवस्थान' की व्यवस्था केवल वन-संरक्षण तक सीमित है।
2. हिंदू समवेत रूप से प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा करते हैं जिसमें पेड़ और वन-प्रान्तर भी शामिल हैं।
3. 'देवस्थान' के महत्त्व का परंपरागत आधार क्षेत्र की आध्यात्मिक अथवा सांस्कृतिक विशेषताएँ हैं।
4. हाल के वर्षों में 'देवस्थान' का विस्तार हुआ है।
5. 'देवस्थान' के प्रबंधन में तब कठिन समस्या आती है जब कानूनी स्वामित्व और व्यावहारिक नियंत्रण अलग-अलग हाथों में हो।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1, 4 और 5 सही हैं।
(B) केवल 2, 3 और 5 सही हैं।
(C) केवल 1, 2 और 3 सही हैं।
(D) सभी कथन सही हैं।

138. खनिज उद्योग की आलोचना के क्या कारण हैं?
(A) उपरोक्त सभी।
(B) यह जन-समुदायों को विस्थापित करता है।
(C) यह भूमि और जलमार्गों को प्रदूषित करता है।
(D) यह स्थानीय वनस्पतियों का विनाश करता है।

139. शीतयुद्ध के दौरान पश्चिमी देशों के राजनीतिक चिंतन का केंद्रीय सरोकार क्या था?
(A) पर्यावरण की सुरक्षा।
(B) विकासशील देशों का विकास।
(C) मानवाधिकारों का संरक्षण।
(D) संसाधनों तक पहुँच अबाध रूप से बनी रहे।

140. 'मूलवासी' शब्द से क्या अभिप्राय है?
(A) किसी विशिष्ट राष्ट्र में रहने वाले अप्रवासी नागरिक।
(B) किसी क्षेत्र के वे वंशज जिन पर बाद में बाहरी संस्कृतियाँ हावी हुईं।
(C) वे लोग जो अपनी पारंपरिक जीवन शैली को पूर्णतः छोड़ चुके हैं।
(D) किसी भी राष्ट्र का वर्तमान में शासन करने वाला आधुनिक वर्ग।

141. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (शब्द/अवधारणा)
P. वैश्विक तापवृद्धि
Q. टिकाऊ विकास
R. पर्यावरणीय शरणार्थी
S. पावन वन-प्रांतर

सूची II: (विवरण)
1. विकास का वह तरीका जो पर्यावरण को क्षति न पहुंचाए
2. ग्रीनहाउस गैसों के कारण विश्व के तापमान में वृद्धि
3. धार्मिक कारणों से संरक्षित वन क्षेत्र
4. पर्यावरणीय आपदा के कारण विस्थापित लोग

(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-1, R-4, S-3
(C) P-3, Q-4, R-2, S-1
(D) P-4, Q-3, R-1, S-2

142. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): भारत इस बात का ज़ोरदार विरोध करता है कि उस पर ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की बाध्यता लागू की जाए।
कारण (R): भारत का मानना है कि यह UNFCCC की मूल भावना के विरुद्ध है और उसका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

143. 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था?
(A) 170
(B) 50
(C) 100
(D) 193

144. निम्नलिखित में से कौन-सा आंदोलन, वन और विजनपन की पैरोकारी के साथ-साथ बाँध-विरोधी आंदोलन भी था?
(A) चिपको आंदोलन
(B) ऑस्ट्रेलिया का फ्रैंकलिन नदी आंदोलन
(C) नर्मदा आंदोलन
(D) फिलीपिन्स का खनन-विरोधी आंदोलन

145. विश्व के कुल तेल उत्पादन का कितना प्रतिशत पश्चिम एशिया (खाड़ी-क्षेत्र) मुहैया कराता है?
(A) 10%
(B) 30%
(C) 50%
(D) 64%

146. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. दक्षिणी गोलार्द्ध के देशों जैसे तुर्की से लेकर थाईलैंड और दक्षिण अफ्रीका तक बड़े बाँधों को बनाने की होड़ लगी है।
2. भारत में बाँध-विरोधी आंदोलन अहिंसा पर आधारित हैं।
3. बाँध-विरोधी आंदोलनों को अब नदियों को बचाने के आंदोलनों के रूप में भी देखा जा रहा है।
4. विश्व का पहला बाँध-विरोधी आंदोलन भारत में शुरु हुआ था।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 4 गलत है।
(B) केवल 1 और 2 सही हैं।

ANSWERS

1. (B) क्योंकि विकास के पर्यावरणीय प्रभावों ने राजनीतिक स्वरूप ग्रहण करना शुरु कर दिया।
वैश्विक स्तर पर साठ के दशक के बाद से पर्यावरण के प्रति चिंता में व्यापक वृद्धि दर्ज की गई है। तीव्र आर्थिक विकास की निरंतर प्रक्रिया ने प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जिससे गंभीर पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न हुआ। विकास के इन नकारात्मक प्रभावों ने धीरे-धीरे राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया जिससे पर्यावरण सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी।

2. (A) क्लब ऑफ रोम
क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रकाशित 'लिमिट्स टू ग्रोथ' पुस्तक ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वैश्विक चेतना को जागृत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह ऐतिहासिक पुस्तक वर्ष उन्नीस सौ बहत्तर में प्रकाशित हुई थी जिसमें बढ़ती जनसंख्या और तीव्र औद्योगीकरण के कारण संसाधनों के सीमित होने की स्पष्ट चेतावनी दी गई थी। इसने सतत विकास और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर बल दिया।

3. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
पर्यावरणीय समस्याओं का उनके विशिष्ट प्रभावों के साथ सीधा संबंध होता है। कृषि-योग्य भूमि की गुणवत्ता में कमी उसकी उर्वरता घटने के कारण होती है जबकि मत्स्य-भंडार में कमी उनके अत्यधिक दोहन के परिणाम स्वरूप देखी जाती है। इसी प्रकार जलराशि में प्रदूषण और कमी एक गंभीर संकट है तथा ओजोन परत का क्षय होने से हानिकारक पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी तक पहुँचती हैं।

4. (D) दो अरब चालीस करोड़
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी वर्ष दो हजार सोलह की मानव विकास रिपोर्ट विकासशील राष्ट्रों की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डालती है। इस रिपोर्ट के अनुसार इन देशों की लगभग दो अरब चालीस करोड़ आबादी बुनियादी साफ-सफाई की सुविधाओं से वंचित है। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में लोगों को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता भी नहीं है जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का प्रमुख कारण है।

5. (B) केवल 1, 2 और 3 सही हैं।
प्राकृतिक वन पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का आधार हैं जो जलवायु को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनों के माध्यम से ही जलचक्र नियमित रहता है और यह धरती की विशाल जैव-विविधता का सुरक्षित भंडार होते हैं। वनों की कटाई और इसके कारण होने वाले लोगों के विस्थापन से जैव-विविधता की भारी हानि होती है इसलिए चौथा कथन पूरी तरह गलत माना जाता है।

6. (B) रियो डी जनेरियो
वर्ष उन्नीस सौ बाणवे में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। ब्राजील के रियो डी जनेरियो शहर में हुए इस वृहद् सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें विश्व के एक सौ सत्तर देशों और हजारों स्वयंसेवी संगठनों ने पर्यावरण सुरक्षा हेतु विस्तृत चर्चा की थी।

7. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
पर्यावरण से जुड़े मुद्दे वैश्विक राजनीति में गहराई से समाहित हैं क्योंकि संसाधनों के उपयोग और संरक्षण के नियम राजनीतिक हितों से प्रभावित होते हैं। कौन सा देश पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुँचाता है और उस पर रोक लगाने की जिम्मेदारी किसकी है, यह अक्सर उस देश की अंतरराष्ट्रीय शक्ति और प्रभाव द्वारा निर्धारित होता है। अतः पर्यावरणीय जिम्मेदारियों का आवंटन पूर्णतः राजनीतिक प्रक्रिया है।

8. (A) इस सम्मेलन का मुख्य ध्यान केवल विकसित देशों के आर्थिक विकास पर था।
पृथ्वी सम्मेलन का उद्देश्य केवल विकसित देशों के आर्थिक हितों की रक्षा करना नहीं था बल्कि वैश्विक पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाना था। इसमें जैव-विविधता, जलवायु परिवर्तन और वानिकी के संबंध में अंतरराष्ट्रीय नियमाचार निर्धारित किए गए थे। साथ ही इसमें एजेंडा इक्कीस के रूप में विकास के ऐसे तौर-तरीके सुझाए गए थे जिनसे पर्यावरण को होने वाले नुकसान को न्यूनतम किया जा सके।

9. (A) 5, 2, 1, 3, 4
इन घटनाओं का ऐतिहासिक क्रम वैश्विक पर्यावरणीय कूटनीति के विकास को दर्शाता है। सबसे पहले उन्नीस सौ उनसठ में अंटार्कटिका संधि हुई जिसके बाद उन्नीस सौ बहत्तर में लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक आई। इसके पश्चात उन्नीस सौ सत्तासी में बर्टलैंड रिपोर्ट और उन्नीस सौ बाणवे में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ। अंततः उन्नीस सौ सत्तानवे में क्योटो प्रोटोकॉल पर सहमति बनी जो जलवायु सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण है।

10. (A) पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए आर्थिक विकास करने का संतुलित तरीका।
टिकाऊ विकास या सतत विकास की अवधारणा एक ऐसी आर्थिक उन्नति पर बल देती है जो प्रकृति के साथ समन्वय स्थापित कर सके। इसका मूल उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करना है कि भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों और पर्यावरण के साथ कोई समझौता न हो। यह विकास का एक संतुलित मॉडल है जो पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा को विकास की अनिवार्य शर्त मानता है।

11. (A) केवल 1, 2 और 3 सही हैं।
वैश्विक संपदा के अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जो किसी एक राष्ट्र के संप्रभु अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष जैसे साझा क्षेत्र शामिल हैं जिनका प्रबंधन अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। इनकी सुरक्षा के लिए साझा सहयोग की आवश्यकता होती है लेकिन हितों के टकराव के कारण इस पर सहमति बनाना प्रायः चुनौतीपूर्ण कार्य होता है।

12. (B) वर्तमान आर्थिक विकास के तरीकों के भविष्य में गैर-टिकाऊ होने के बारे में।
वर्ष उन्नीस सौ सत्तासी में प्रकाशित बर्टलैंड रिपोर्ट जिसे अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से जाना जाता है ने एक गंभीर चेतावनी दी थी। इसमें स्पष्ट किया गया था कि आर्थिक विकास के मौजूदा तरीके भविष्य में जारी नहीं रह सकते क्योंकि वे प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। रिपोर्ट ने वैश्विक समुदाय को टिकाऊ विकास की अवधारणा अपनाने और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया।

13. (B) P-3, Q-1, R-4, S-2
अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौतों का एक निश्चित समयक्रम है। अंटार्कटिका संधि वर्ष उन्नीस सौ उनसठ में संपन्न हुई थी जबकि ओजोन परत की सुरक्षा हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उन्नीस सौ सत्तासी में आया। अंटार्कटिका पर्यावरणीय प्रोटोकॉल उन्नीस सौ इक्यानवे में हस्ताक्षरित हुआ और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल पर सहमति वर्ष उन्नीस सौ सत्तानवे में वैश्विक स्तर पर कायम हुई थी।

14. (D) विकसित देशों के औद्योगिक विकास से हुए नुकसान के कारण उनकी ज़िम्मेदारी अधिक है।
विकासशील देशों का मानना है कि वर्तमान पर्यावरणीय संकट के लिए विकसित राष्ट्र मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। चूंकि इन देशों ने लंबे समय तक औद्योगिक विकास के माध्यम से पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया है इसलिए उन्हें संरक्षण हेतु अधिक वित्तीय और तकनीकी बोझ उठाना चाहिए। साझी परंतु अलग-अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत इसी तर्क पर आधारित है कि प्रदूषण फैलाने वाले देशों की जिम्मेदारी भी अधिक होनी चाहिए।

15. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
क्योटो प्रोटोकॉल में भारत और चीन जैसे विकासशील देशों को उत्सर्जन कटौती की अनिवार्य बाध्यताओं से छूट दी गई थी। इसका मुख्य कारण यह था कि औद्योगिक क्रांति के समय से ही विकसित देशों ने सबसे अधिक ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन किया है। विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर आज भी विकसित देशों की तुलना में काफी कम है इसलिए उन्हें विकास के अवसर प्रदान किए गए।

16. (B) इस पर केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस का संप्रभु अधिकार है।
अंटार्कटिका महादेश किसी विशेष राष्ट्र की संप्रभु संपत्ति नहीं है बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय की साझी विरासत माना जाता है। इस क्षेत्र पर ब्रिटेन, अर्जेंटीना और चिली जैसे कई देशों ने अपने दावे पेश किए हैं लेकिन इसे अंतरराष्ट्रीय संधियों के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। यह क्षेत्र विश्व के स्वच्छ जल का सत्तर प्रतिशत हिस्सा समेटे हुए है और इसका पारिस्थितिकी तंत्र अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण है।

17. (A) केवल 1 और 2 सही हैं।
रियो सम्मेलन में विकसित और विकासशील देशों के बीच प्राथमिकताओं को लेकर स्पष्ट मतभेद उभरे थे। उत्तरी गोलार्ध के विकसित देश मुख्य रूप से ओजोन परत के क्षरण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं के समाधान पर जोर दे रहे थे। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध के देश गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण के संतुलन को लेकर अधिक चिंतित थे क्योंकि उनका विकास अभी शेष था।

18. (A) यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज
यूएनएफसीसीसी का पूर्ण रूप यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है जो जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। इस रूपरेखा का निर्माण वर्ष उन्नीस सौ बाणवे के पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों के सांद्रण को एक ऐसे स्तर पर स्थिर करना है जिससे पृथ्वी की जलवायु प्रणाली को हानिकारक मानवीय हस्तक्षेप से बचाया जा सके।

19. (C) निजीकरण और आबादी की वृद्धि से साझी संपदा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
साझी संपदा वह संसाधन है जिस पर पूरे समुदाय का सामूहिक अधिकार होता है और प्रत्येक सदस्य इसके रख-रखाव हेतु उत्तरदायी होता है। हालांकि वर्तमान समय में बढ़ते निजीकरण और तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण इन संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप साझी संपदा के आकार और गुणवत्ता में निरंतर गिरावट आ रही है जिससे विशेष रूप से ग्रामीण समुदायों और गरीबों का जीवन प्रभावित हो रहा है।

20. (D) औद्योगिक देशों हेतु ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता।
क्योटो प्रोटोकॉल एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसका मुख्य लक्ष्य औद्योगिक देशों के लिए ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करना है। यह समझौता ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती से निपटने के लिए उन्नीस सौ सत्तानवे में जापान के क्योटो शहर में अपनाया गया था। इसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रो-फ्लोरो कार्बन जैसी गैसों के नियंत्रण पर बल दिया गया।

21. (C) 2002
भारत ने जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए वर्ष दो हजार दो में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन किया। हालांकि भारत एक विकासशील देश होने के नाते इस प्रोटोकॉल के शुरुआती चरण में उत्सर्जन कटौती की अनिवार्य बाध्यताओं से मुक्त था। भारत का यह कदम वैश्विक तापमान में वृद्धि को रोकने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में उसकी सक्रिय भागीदारी का परिचायक माना जाता है।

22. (A) केवल 1, 2 और 3
ग्रीनहाउस गैसें वे गैसें हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को रोककर वैश्विक तापमान में वृद्धि का कारण बनती हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रो-फ्लोरो कार्बन प्रमुख हैं जिनके उत्सर्जन को नियंत्रित करना अनिवार्य है। इसके विपरीत ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वायुमंडल की मुख्य गैसें हैं लेकिन ये ग्रीनहाउस प्रभाव पैदा नहीं करती हैं। अतः जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए शुरुआती तीन गैसों का नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है।

23. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
बाहरी अंतरिक्ष के प्रबंधन और उपयोग को लेकर विकसित और विकासशील देशों के बीच गहरी असमानता विद्यमान है। चूंकि अंतरिक्ष अनुसंधान और वहां संसाधनों का दोहन अत्यधिक उन्नत प्रौद्योगिकी तथा भारी निवेश पर निर्भर करता है इसलिए इसमें उत्तरी गोलार्ध के विकसित देश अग्रणी हैं। यह तकनीकी बढ़त उन्हें अंतरिक्ष के संसाधनों पर नियंत्रण करने की अधिक क्षमता प्रदान करती है जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक विवादित मुद्दा है।

24. (A) धार्मिक कारणों से संरक्षित वन क्षेत्र जिन्हें काटा नहीं जाता है।
भारत में पावन वन-प्रांतर या देवस्थान वे प्राकृतिक वन क्षेत्र हैं जिन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा देवी-देवताओं का निवास स्थान मानकर संरक्षित किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के कारण इन वनों में वृक्षों को काटना वर्जित होता है जिससे ये क्षेत्र जैव-विविधता के सुरक्षित द्वीप बन जाते हैं। यह परंपरा सदियों से पर्यावरण संरक्षण और साझी संपदा के प्रबंधन का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश करती रही है।

25. (A) P-4, Q-1, R-2, S-3
भारत के विभिन्न राज्यों में पवित्र वन क्षेत्रों या देवस्थानों को अलग-अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है। राजस्थान में इन्हें वानी, केंकड़ी या ओरान कहा जाता है जबकि झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में इन्हें जहेरा थान या सरना के नाम से पुकारा जाता है। इसी प्रकार मेघालय में इन्हें लिंगदोह और केरल में काव के नाम से पूजा और संरक्षित किया जाता है जो स्थानीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं।

26. (A) अपनी क्षमता और पर्यावरण क्षय में अपनी हिस्सेदारी के आधार पर।
संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन रूपरेखा संधि के अनुसार पर्यावरण सुरक्षा की जिम्मेदारियाँ साझी परंतु अलग-अलग होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक देश की जिम्मेदारी उसकी आर्थिक क्षमता और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने में उसकी ऐतिहासिक हिस्सेदारी के आधार पर तय की जानी चाहिए। विकसित देशों ने औद्योगिकीकरण के दौरान अधिक प्रदूषण किया है इसलिए उनकी जिम्मेदारी विकासशील देशों की तुलना में स्वाभाविक रूप से अधिक मानी गई है।

27. (D) सभी औद्योगिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना।
भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कई विधायी और नीतिगत कदम उठाए हैं लेकिन औद्योगिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना इसमें शामिल नहीं है। सरकार विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना चाहती है जिसके लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम और नेशनल ऑटो-फ्यूल पॉलिसी जैसे उपाय किए गए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और स्वच्छ ईंधन का उपयोग करना भारत की सतत विकास रणनीति के महत्वपूर्ण अंग हैं।

28. (B) 2 अक्टूबर 2016
भारत ने जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए पेरिस समझौते का दो अक्टूबर दो हजार सोलह को औपचारिक रूप से अनुमोदन किया। यह तिथि महात्मा गांधी की जयंती होने के कारण विशेष प्रतीकात्मक महत्व रखती है जो सादगी और प्रकृति के साथ सामंजस्य का संदेश देते थे। इस समझौते के माध्यम से भारत ने उत्सर्जन तीव्रता कम करने और अक्षय ऊर्जा के लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

29. (B) केवल 1, 2 और 3 सही हैं।
उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों में वन-आंदोलनों की प्रकृति भिन्न है क्योंकि वहां वनों को देखने का नजरिया अलग है। विकसित देशों में वनों को अक्सर निर्जन विजनपन के रूप में देखा जाता है जहाँ मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए। इसके विपरीत विकासशील देशों में वनों का मुद्दा स्थानीय समुदायों के जीवन और आजीविका से गहराई से जुड़ा है क्योंकि वे सदियों से इन्हीं वनों में निवास करते आ रहे हैं।

30. (D) वेस्टर्न माइनिंग कारपोरेशन
फिलीपिन्स के कोरडिलेरा क्षेत्र में वेस्टर्न माइनिंग कारपोरेशन नामक एक ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी के विरुद्ध व्यापक जन आंदोलन चलाया गया था। इस कंपनी की खनन गतिविधियों से स्थानीय पर्यावरण और लोगों की आजीविका को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था। कई नागरिक समूहों और स्थानीय समुदायों ने मिलकर इस अभियान का नेतृत्व किया जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के दोहन के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण संघर्ष के रूप में उभरा।

इसके प्रमुख उदाहरण हैं जिनका प्रबंधन साझा संधियों द्वारा होता है। इसके विपरीत किसी देश का राष्ट्रीय उद्यान उस राष्ट्र के संप्रभु अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है और उसका प्रबंधन पूरी तरह उसी देश की सरकार द्वारा किया जाता है।

53. (A) 4, 2, 3, 1
इन घटनाओं का सही कालक्रम भारत के पर्यावरणीय कूटनीति के सफर को दर्शाता है। सर्वप्रथम उन्नीस सौ बाणवे में रियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ जिसमें भारत ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके बाद दो हजार दो में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल का अनुमोदन किया। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम वर्ष दो हजार एक में पारित हुआ था जबकि पेरिस जलवायु समझौते का औपचारिक अनुमोदन भारत द्वारा दो हजार सोलह में किया गया था।

54. (B) साझी परंतु अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ
रियो घोषणापत्र में 'साझी परंतु अलग-अलग जिम्मेदारियों' के ऐतिहासिक सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। यह सिद्धांत मानता है कि पर्यावरण की सुरक्षा सभी राष्ट्रों की सामूहिक जिम्मेदारी है लेकिन प्रदूषण फैलाने में देशों की ऐतिहासिक भूमिका और उनकी आर्थिक क्षमता अलग-अलग है। इसलिए विकसित देशों को पर्यावरण सुधार के लिए अधिक तकनीकी और वित्तीय योगदान देना चाहिए जबकि विकासशील देशों को उनके विकास हेतु उचित रियायत मिलनी चाहिए।

55. (D) बहुत ज़्यादा है
भारत सरकार द्वारा दो हजार पांच में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार विकसित देशों में ग्रीनहाउस गैसों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन स्तर विकासशील देशों की तुलना में बहुत अधिक है। विकसित देशों की जीवनशैली और उच्च औद्योगिक गतिविधि इस अधिक उत्सर्जन का मुख्य कारण है। भारत जैसे देशों का मानना है कि प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के आधार पर ही जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए जो कि न्यायपूर्ण होगा।

56. (A) वनों की व्यावसायिक कटाई का समर्थन करने वाला एक संगठित आंदोलन।
पर्यावरण आंदोलन सदैव पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर केंद्रित होते हैं। वनों की व्यावसायिक कटाई का समर्थन करना किसी भी रूप में पर्यावरण आंदोलन नहीं हो सकता क्योंकि यह प्रकृति को नष्ट करने की प्रक्रिया है। इसके विपरीत खनिज उद्योग के विस्तार का विरोध करना, बड़े बाँधों के विरुद्ध संघर्ष करना और नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाना ही वास्तविक पर्यावरणीय सक्रियता के उदाहरण माने जाते हैं।

57. (A) केवल 1 और 2
वर्तमान समय में पर्यावरण आंदोलन विश्व के सबसे जीवंत और प्रभावशाली सामाजिक आंदोलनों में से एक हैं जो स्थानीय से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक सक्रिय हैं। ये आंदोलन न केवल सरकारों की नीतियों को प्रभावित करते हैं बल्कि सतत जीवन और प्रकृति के संरक्षण से जुड़े नवीन विचार भी प्रदान करते हैं। ये आंदोलन स्वयंसेवी संगठनों और जागरूक नागरिकों द्वारा चलाए जाते हैं न कि केवल सरकारों द्वारा जैसा कि कथन चार में कहा गया।

58. (A) वन, विजनपन और बाँध-विरोधी, तीनों
ऑस्ट्रेलिया में फ्रैंकलिन नदी को बचाने के लिए चला आंदोलन एक बहुआयामी पर्यावरण आंदोलन था जिसने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। यह न केवल एक बड़े बाँध के निर्माण का विरोध कर रहा था बल्कि वर्षा वनों के संरक्षण और जंगली क्षेत्रों की सुरक्षा की भी जोरदार पैरोकारी कर रहा था। इस सफल आंदोलन ने यह सिद्ध किया कि जन भागीदारी के माध्यम से विकास की विनाशकारी परियोजनाओं को रोका जा सकता है।

59. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद भी वैश्विक राजनीति में तेल की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना सभी सरकारों की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पेट्रोलियम संसाधनों पर निर्भर है जो परिवहन और ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं। इसी सामरिक महत्व के कारण तेल उत्पादक देशों पर राजनीतिक प्रभाव बनाए रखना बड़ी शक्तियों की वैश्विक रणनीति का एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण हिस्सा आज भी है।

60. (B) फरात नदी
तुर्की, सीरिया और इराक के बीच फरात नदी के जल के उपयोग और उस पर बाँध निर्माण को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। तुर्की द्वारा नदी के ऊपरी हिस्से पर बाँध बनाने से निचले देशों विशेषकर सीरिया और इराक को मिलने वाले जल प्रवाह में कमी आने की आशंका रहती है। यह स्थिति क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष को बढ़ावा देती है जो साझा जल संसाधनों के प्रबंधन की जटिलता दर्शाती है।

61. (C) खेती पर
भारत की अधिकांश आदिवासी जनसंख्या अपनी आजीविका और जीवन निर्वाह के लिए मुख्य रूप से खेती और वन उपज पर निर्भर है। उनकी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था भूमि और प्रकृति के साथ अटूट रूप से जुड़ी हुई है। भूमि का कोई भी नुकसान या विस्थापन उनके पूरे जीवन आधार को नष्ट कर देता है। यही कारण है कि आदिवासी समुदाय अपनी पैतृक भूमि के संरक्षण के लिए निरंतर राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष करते रहते हैं।

62. (A) P-3, Q-1, R-2, S-4
पर्यावरणीय अवधारणाओं का उनके संबंधित स्रोतों के साथ मिलान अत्यंत महत्वपूर्ण है। लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन क्लब ऑफ रोम ने किया था जबकि बर्टलैंड रिपोर्ट को अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से जाना जाता है। एजेंडा इक्कीस रियो पृथ्वी सम्मेलन का एक प्रमुख परिणाम था और साझी परंतु अलग-अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत यूएनएफसीसीसी की रूपरेखा के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के आधार के रूप में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था।

है कि किस प्रकार साझा जल संसाधन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में विवाद और अस्थिरता का एक प्रमुख कारण बन सकते हैं।

42. (A) किसी क्षेत्र के वे मूल निवासी जिन पर बाद में बाहरी संस्कृतियाँ हावी हो गईं।
संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार मूलवासी वे लोग हैं जो किसी क्षेत्र में प्राचीन काल से निवास कर रहे हैं और जिनके पूर्वज वहां तब से थे जब बाद में दूसरी संस्कृतियों के लोग वहां आए। इन लोगों ने अपनी विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखा है। आज ये समुदाय अपनी भूमि और संसाधनों पर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निरंतर संघर्ष कर रहे हैं।

43. (B) P-4, Q-1, R-2, S-3
विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में मूलवासी समुदाय अपनी विशिष्ट पहचान के साथ निवास करते हैं। फिलीपिन्स के कोरडिलेरा क्षेत्र में बड़ी संख्या में मूलवासी बसे हुए हैं जबकि चिली में मापुशे समुदाय एक प्रमुख मूलवासी समूह है। इसी प्रकार बांग्लादेश के चटगांव पर्वतीय क्षेत्रों में कई जनजातियाँ रहती हैं और पनामा नहर के पूर्वी भाग में कुना समुदाय के लोग निवास करते हैं जो अपनी संस्कृति के प्रति सचेत हैं।

44. (B) अनुसूचित जनजाति या आदिवासी, 8 प्रतिशत
भारत में मूलवासियों के लिए आधिकारिक रूप से अनुसूचित जनजाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग आठ प्रतिशत हिस्सा हैं। ये समुदाय अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। भारत के संविधान में इनके अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि उनका सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके।

45. (C) 1975
मूलवासियों के अधिकारों को वैश्विक स्तर पर संगठित करने के उद्देश्य से वर्ष उन्नीस सौ पचहत्तर में 'वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल' का गठन किया गया था। यह संगठन विभिन्न देशों के मूलवासी समूहों के बीच समन्वय स्थापित करने और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उनकी आवाज उठाने का कार्य करता है। इसके गठन के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने मूलवासियों की समस्याओं पर अधिक गंभीरता से ध्यान देना प्रारंभ किया था।

46. (A) केवल 1 और 4 सही हैं।
विकास की विभिन्न परियोजनाओं जैसे बड़े बाँधों और खनन कार्यों के कारण विस्थापित होने वाले लोगों में मूलवासी समुदाय की संख्या सबसे अधिक है। ये समुदाय अपनी स्वतंत्र सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने और अपने पारंपरिक संसाधनों पर अधिकार पाने की निरंतर मांग कर रहे हैं। हालांकि भारत में इन्हें संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है और इनके मुद्दे दशकों से राजनीति का हिस्सा रहे हैं इसलिए दूसरा और तीसरा कथन गलत हैं।

47. (A) 1960 के दशक के बाद से
पर्यावरण से संबंधित चिंताओं ने साठ के दशक के बाद से वैश्विक राजनीति में एक स्पष्ट राजनीतिक स्वरूप ग्रहण करना शुरू किया था। इसी समय के दौरान कई देशों में हरित दलों का उदय हुआ और संसाधनों के अत्यधिक दोहन के विरुद्ध जन चेतना जागृत हुई। इस कालखंड ने यह स्पष्ट कर दिया कि पर्यावरणीय समस्याएं केवल तकनीकी नहीं बल्कि गहरे अर्थों में राजनीतिक और सामरिक महत्व की हैं।

48. (B) ओज़ोन
पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की एक पतली परत होती है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। जब मानवीय गतिविधियों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग के कारण इस गैस की मात्रा में कमी आती है तो उसे ओजोन परत में छेद कहा जाता है। यह एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है क्योंकि इससे पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

49. (B) 1987
बर्टलैंड रिपोर्ट जिसे आधिकारिक तौर पर 'अवर कॉमन फ्यूचर' कहा जाता है वर्ष उन्नीस सौ सत्तासी में प्रकाशित हुई थी। इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट ने पहली बार टिकाऊ विकास की अवधारणा को वैश्विक स्तर पर परिभाषित और लोकप्रिय बनाया था। इसने यह स्पष्ट किया कि वर्तमान विकास की गति भविष्य के संसाधनों को खतरे में डाल रही है और पर्यावरण संरक्षण को विकास की मुख्यधारा में शामिल करना अनिवार्य है।

50. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
विकासशील देशों का तर्क है कि वे अभी औद्योगिकीकरण के प्रारंभिक चरणों में हैं और उनके लिए आर्थिक प्रगति गरीबी दूर करने हेतु अत्यंत आवश्यक है। इसलिए वे पर्यावरण संरक्षण के नाम पर उन कड़े प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं करना चाहते जो विकसित देशों पर लागू किए गए हैं। चूंकि विकसित देशों ने अपना विकास पहले ही कर लिया है इसलिए उन्हें प्रदूषण कम करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

51. (C) यहाँ केवल पर्यटन और मत्स्य आखेट की ही अनुमति है, वैज्ञानिक अनुसंधान की नहीं।
अंटार्कटिका महादेश के संबंध में यह दावा गलत है कि यहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान की अनुमति नहीं है क्योंकि वास्तव में यह क्षेत्र मुख्य रूप से वैज्ञानिक खोजों के लिए ही खुला रखा गया है। अंतरराष्ट्रीय संधियों के अनुसार यहाँ सैन्य गतिविधियों और औद्योगिक खनन पर पूर्ण प्रतिबंध है जबकि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अनुसंधान, पर्यटन और नियंत्रित मत्स्य आखेट की अनुमति दी गई है जो इसके संवेदनशील पर्यावरण को सुरक्षित रखती है।

52. (D) किसी देश का राष्ट्रीय उद्यान
वैश्विक संपदा के अंतर्गत वे क्षेत्र शामिल होते हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के बाहर होते हैं और पूरी मानवता की साझी विरासत माने जाते हैं। वायुमंडल, अंटार्कटिका और बाहरी अंतरिक्ष

था। यह क्रम दर्शाता है कि कैसे धीरे-धीरे विभिन्न पर्यावरणीय चुनौतियों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियमों का निर्माण हुआ।

74. (A) औद्योगिक (विकसित) देशों के लिए
क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से औद्योगिक या विकसित देशों के लिए ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करता है। इसका कारण यह है कि ये देश ऐतिहासिक रूप से प्रदूषण के लिए अधिक जिम्मेदार रहे हैं। विकासशील देशों को शुरुआती चरणों में इन अनिवार्य बाध्यताओं से मुक्त रखा गया था ताकि वे अपना आर्थिक और सामाजिक विकास बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के जारी रख सकें।

75. (D) ये केवल विकसित देशों तक ही सीमित हैं।
पर्यावरण आंदोलन केवल विकसित देशों तक सीमित नहीं हैं बल्कि ये आज विकासशील देशों में भी अत्यंत सक्रिय और प्रभावशाली हैं। दक्षिणी गोलार्ध के देशों में ये आंदोलन अक्सर लोगों के जीवन और आजीविका के बुनियादी अधिकारों से जुड़े होते हैं। ये आंदोलन नई राजनीतिक क्रियाओं को जन्म देते हैं और वैश्विक चेतना के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः यह कहना गलत है कि इनका विस्तार केवल समृद्ध राष्ट्रों तक है।

76. (B) विदेशी संसाधनों की उपलब्धता और नौवहन दक्षता।
पश्चिमी जगत के रणनीतिक चिंतन में संसाधनों की भू-राजनीति हमेशा केंद्र में रही है जिसका मुख्य उद्देश्य विदेशी संसाधनों तक निर्बाध पहुँच बनाना था। इसके लिए उन्होंने अपनी नौवहन शक्ति और तकनीकी दक्षता का भरपूर उपयोग किया ताकि वे औपनिवेशिक विस्तार और व्यापारिक प्रभुत्व स्थापित कर सकें। संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त करना ही यूरोपीय शक्तियों के वैश्विक प्रसार और उनके कूटनीतिक संबंधों का प्राथमिक आधार और प्रमुख मकसद रहा है।

77. (A) केवल 1 और 2 सही हैं।
पेट्रोलियम संसाधनों का इतिहास वास्तव में अंतरराष्ट्रीय संघर्षों और युद्धों का इतिहास रहा है क्योंकि यह वैश्विक शक्ति का प्रतीक है। सऊदी अरब के पास विश्व के कुल तेल भंडार का लगभग पच्चीस प्रतिशत हिस्सा मौजूद है जो उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में अत्यंत शक्तिशाली बनाता है। इराक का भंडार सऊदी अरब से कम है और जल को लेकर कई संघर्ष हो चुके हैं इसलिए तीसरा, चौथा और पांचवां कथन पूरी तरह गलत हैं।

78. (D) स्वच्छ जल संसाधनों के अधिकार हेतु होने वाले हिंसक संघर्ष।
विद्वान 'जलयुद्ध' शब्द का प्रयोग उन संभावित हिंसक संघर्षों के संदर्भ में करते हैं जो भविष्य में स्वच्छ जल की बढ़ती कमी के कारण हो सकते हैं। जब दो या दो से अधिक राष्ट्र एक ही नदी के जल के उपयोग या उसके प्रवाह को मोड़ने को लेकर विवाद करते हैं तो वह तनावपूर्ण युद्ध जैसी स्थिति में बदल सकता है। यह शब्द जल को इक्कीसवीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक संसाधन भी इंगित करता है।

79. (C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
ब्रितानी औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय जनजातीय समुदायों को बाहरी हस्तक्षेप का बड़े पैमाने पर सामना करना पड़ा जिससे उनकी स्वायत्तता प्रभावित हुई। हालांकि यह कहना गलत होगा कि ब्रिटिश काल से पहले ये समुदाय पूरी तरह अलग-थलग थे क्योंकि वे अन्य समुदायों के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध रखते थे। अतः अभिकथन सत्य है किंतु कारण यह दावा करने में त्रुटिपूर्ण है कि वे पूर्व में पूर्णतः संपर्क विहीन थे।

80. (B) परामर्शदायी परिषद् का
संयुक्त राष्ट्र संघ ने मूलवासियों की समस्याओं को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने के लिए वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल को परामर्शदायी परिषद का दर्जा प्रदान किया है। यह दर्जा इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न समितियों में अपनी राय रखने और मूलवासियों के अधिकारों की वकालत करने की अनुमति देता है। इस मान्यता के बाद ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मूलवासियों के प्रति नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं।

81. (B) टिकाऊ विकास और 'एजेंडा-21' का सर्वसम्मत अनुमोदन।
वर्ष उन्नीस सौ बाणवे के पृथ्वी सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण और स्थायी परिणाम एजेंडा इक्कीस का अनुमोदन था जो टिकाऊ विकास के लिए एक व्यापक कार्ययोजना है। इसमें पर्यावरण सुरक्षा और आर्थिक प्रगति के बीच सामंजस्य स्थापित करने के सिद्धांतों को स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन ने वैश्विक राजनीति के केंद्र में पर्यावरण को स्थापित किया और भविष्य की पर्यावरणीय नीतियों के लिए एक विस्तृत और मजबूत रुपरेखा प्रदान की।

82. (C) P-4, Q-3, R-2, S-1
पर्यावरणीय पहलों और उनके प्रणेताओं का सटीक मिलान वैश्विक इतिहास का हिस्सा है। क्लब ऑफ रोम ने लिमिट्स टू ग्रोथ के माध्यम से संसाधनों की सीमितता बताई जबकि संयुक्त राष्ट्र ने रियो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया। बर्टलैंड रिपोर्ट को अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक के लिए जाना जाता है और भारत सरकार ने ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए वर्ष दो हजार एक में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित कर ठोस विधायी कदम उठाए।

83. (C) ऑस्ट्रेलिया, स्कैंडिनेविया, उत्तरी अमरीका
विजनपन या वाइल्डरनेस की अवधारणा जिसमें प्रकृति को मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त एक अछूते क्षेत्र के रूप में देखा जाता है, मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, स्कैंडिनेविया और उत्तरी अमेरिका जैसे विकसित क्षेत्रों में लोकप्रिय है। इन स्थानों पर बड़े प्राकृतिक क्षेत्रों को मानवीय बसाहट से दूर रखकर संरक्षित किया जाता है। यह दृष्टिकोण मनुष्य को प्रकृति से अलग मानता है जो दक्षिणी गोलार्ध के देशों की पारंपरिक मान्यताओं से काफी भिन्न और विपरीत है।

84. (A) केवल 2 और 3 सही हैं।
भारत में बंगाल टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जैसी महत्वपूर्ण और सफल मुहिम निरंतर चलाई जा रही है जो

63. (A) स्वच्छ जल
वर्ष दो हजार सोलह की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों की लगभग छाछठ करोड़ तीस लाख जनता को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जल की यह कमी न केवल मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा है बल्कि यह उन देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बाधित करती है। स्वच्छ जल की अनुपलब्धता विकासशील राष्ट्रों के सामने मौजूद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनी हुई है।

64. (C) केवल 1, 2 और 3 सही हैं।
पृथ्वी सम्मेलन के दौरान जलवायु परिवर्तन और जैव-विविधता पर महत्वपूर्ण सहमति बनी थी लेकिन उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बीच कई मुद्दों पर गंभीर मतभेद भी थे। आलोचकों का मानना है कि एजेंडा इक्कीस का झुकाव पर्यावरणीय सुरक्षा के बजाय आर्थिक विकास की ओर अधिक है। टिकाऊ विकास को वास्तविक धरातल पर कैसे लागू किया जाए यह आज भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है।

65. (B) 1980 के दशक
अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में एक विशाल छेद की खोज अस्सी के दशक के मध्य में वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी। इस खोज ने वैश्विक स्तर पर हड़कंप मचा दिया था क्योंकि ओजोन परत का क्षरण पूरी पृथ्वी के जीवन के लिए एक बड़ा खतरा था। इसके बाद ही ओजोन के लिए हानिकारक गैसों के उत्पादन को कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर तेजी से कार्य शुरु हुआ था।

66. (A) वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य करना।
भारत की नेशनल ऑटो-फ्यूल पॉलिसी का प्राथमिक उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है। इसके तहत देश भर में वाहनों के लिए कड़े उत्सर्जन मानक लागू किए गए हैं ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। यह नीति सतत परिवहन प्रणाली की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावी कदम माना जाता है।

67. (C) साझी संपदा के संरक्षण की व्यवस्था से
देवस्थान या पावन वन-प्रांतर की पारंपरिक व्यवस्था साझी संपदा के संरक्षण के मॉडल से काफी मिलती-जुलती है। इसमें किसी एक व्यक्ति का निजी स्वामित्व नहीं होता बल्कि पूरे समुदाय की इसमें धार्मिक और नैतिक भागीदारी होती है। समुदाय के लोग सामूहिक रूप से इन क्षेत्रों की सुरक्षा करते हैं और इनके संसाधनों का उपयोग केवल अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए ही किया जाता है जो पर्यावरण प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण है।

68. (D) नर्मदा आंदोलन
भारत में सबसे प्रसिद्ध और व्यापक बाँध-विरोधी आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन है जो नर्मदा नदी पर बनने वाले विशाल बाँधों के विरुद्ध चलाया गया था। इस आंदोलन ने विस्थापन की समस्या, पर्यावरणीय क्षति और स्थानीय लोगों के अधिकारों के मुद्दों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से उठाया। यह संघर्ष न केवल बाँध निर्माण के विरुद्ध था बल्कि विकास के मौजूदा मॉडल पर भी गंभीर सवाल खड़े करने वाला था।

69. (C) क्योंकि विश्व के कुछ भागों में स्वच्छ जल की कमी और वितरण असमान है।
स्वच्छ जल एक अत्यंत सीमित और महत्वपूर्ण संसाधन है जिसका वितरण पूरी दुनिया में अत्यधिक असमान है। विश्व के कई हिस्सों में पानी की भारी कमी के कारण विभिन्न देशों के बीच तनाव और संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। जल संसाधनों पर नियंत्रण और उनके उपयोग को लेकर होने वाले विवाद इसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक अनिवार्य और संवेदनशील मुद्दा बनाते हैं जिसे भविष्य में युद्धों का कारण माना जा रहा है।

70. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
मूलवासियों के लिए भूमि केवल एक संपत्ति नहीं बल्कि उनके जीवन का आधार और सांस्कृतिक पहचान है। भूमि छिन जाने से वे न केवल अपने आर्थिक संसाधनों से वंचित हो जाते हैं बल्कि उनकी पारंपरिक जीवन शैली और आजीविका भी पूरी तरह नष्ट हो जाती है। इसीलिए मूलवासी समुदायों के लिए भूमि की हानि उनके अस्तित्व के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में देखी और महसूस की जाती है।

71. (D) भारत
अंटार्कटिका क्षेत्र पर संप्रभुता के दावे मुख्य रूप से ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, अर्जेंटीना और चिली जैसे देशों द्वारा किए गए हैं। भारत ने कभी भी इस क्षेत्र पर किसी प्रकार के संप्रभु अधिकार का दावा नहीं किया है बल्कि वह इसे पूरी मानवता की साझी विरासत मानता है। भारत वहाँ केवल वैज्ञानिक अनुसंधान उद्देश्यों के लिए अपने स्थायी केंद्रों के माध्यम से सक्रिय है और अंतरराष्ट्रीय नियमों का पूर्ण पालन करता है।

72. (A) विभिन्न राज्यों का योगदान अलग-अलग है।
रियो घोषणापत्र स्पष्ट रुप से स्वीकार करता है कि वैश्विक पर्यावरण के क्षरण में सभी राज्यों का योगदान एक समान नहीं है। इसमें यह माना गया है कि विकसित देशों ने अपनी औद्योगिक गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुँचाया है। इसी आधार पर यह सिद्धांत विकसित हुआ कि पर्यावरणीय जिम्मेदारी भी प्रदूषण में हिस्सेदारी और संसाधनों के उपयोग की क्षमता के अनुसार अलग-अलग तय की जानी चाहिए जो न्यायपूर्ण है।

73. (A) 3, 2, 1, 4
इन अंतरराष्ट्रीय समझौतों का कालक्रम वैश्विक पर्यावरणीय सहयोग के विकास का प्रतीक है। सबसे पहले उन्नीस सौ उनसठ में अंटार्कटिका संधि हुई जिसके बाद उन्नीस सौ सत्तासी में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। अंटार्कटिका पर्यावरणीय प्रोटोकॉल उन्नीस सौ इक्यानवे में हस्ताक्षरित किया गया था जबकि क्योटो प्रोटोकॉल उन्नीस सौ सत्तानवे में अस्तित्व में आया

115. (C) उत्तरी देशों के वन निर्जन माने जाते हैं, जबकि दक्षिणी देशों के वनों में लोग निवास करते हैं।
उत्तर और दक्षिण के देशों के वन-आंदोलनों में मौलिक अंतर वनों के प्रति उनके दृष्टिकोण में निहित है। विकसित उत्तरी देशों में वनों को प्रायः निर्जन विजनपन के रूप में देखा जाता है जहाँ मानवीय गतिविधियों का अभाव होना चाहिए। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध के विकासशील देशों में वन केवल प्राकृतिक संपदा नहीं बल्कि वहां रहने वाले लाखों लोगों के जीवन, घर और आजीविका का एकमात्र और प्राथमिक आधार माने जाते हैं।

116. (D) क्योंकि यह 'UNFCCC' की वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने हेतु आवश्यक है।
भारत का यह निरंतर तर्क है कि विकासशील देशों को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी विकसित देशों द्वारा रियायती शर्तों पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यह मांग अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रूपरेखा संधि की मूल भावना और वैश्विक प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है। चूंकि विकसित देशों के पास बेहतर संसाधन और आधुनिक तकनीक है इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि वे विकासशील राष्ट्रों को सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्रिय सहयोग प्रदान करें।

117. (C) नदी के उद्गम पर बाँध बनाकर दूसरे देश हेतु जल प्रवाह को बाधित करना।
जलयुद्ध की संभावना का सबसे स्पष्ट और प्रचलित उदाहरण तब उभरता है जब कोई देश किसी साझा नदी के ऊपरी हिस्से पर बाँध बनाकर निचले देशों को मिलने वाले पानी को नियंत्रित या बाधित करता है। यह क्रिया निचले देशों की कृषि और अर्थव्यवस्था को गंभीर संकट में डाल सकती है जिससे दोनों राष्ट्रों के बीच हिंसक सैन्य संघर्ष और दीर्घकालिक राजनीतिक शत्रुता उत्पन्न होने की प्रबल आशंका बनी रहती है।

118. (B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
दुनिया भर के मूलवासी समुदाय भौगोलिक रूप से भिन्न होने के बावजूद अपनी भूमि और प्रकृति के प्रति एक समान आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण साझा करते हैं। वे स्वयं को अपनी भूमि का प्राचीन रक्षक मानते हैं और 'अनंत काल से रहने' के दावे के माध्यम से अपने अधिकारों को मजबूत करते हैं। ये दोनों कथन सत्य हैं लेकिन कारण अभिकथन की पूरी तरह व्याख्या नहीं करता क्योंकि उनकी विश्वदृष्टि केवल दावों तक ही सीमित नहीं है।

119. (D) वैज्ञानिक अनुसंधान, मत्स्य आखेट और पर्यटन
उन्नीस सौ उनसठ की अंटार्कटिका संधि और उसके बाद के प्रोटोकॉल के अंतर्गत इस महाद्वीप का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही सीमित किया गया है। यहाँ सैन्य परीक्षणों और औद्योगिक खनन पर पूर्ण प्रतिबंध है जबकि पर्यावरण सुरक्षा के कड़े नियमों के तहत वैज्ञानिक अनुसंधान, नियंत्रित पर्यटन और सीमित मत्स्य आखेट की अनुमति दी गई है। यह व्यवस्था अंटार्कटिका के अत्यंत संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र को बाहरी हस्तक्षेप से सुरक्षित रखने के लिए की गई है।

120. (A) ग्रामीण समुदाय
भारत में देवस्थान या पवित्र वनों का प्रबंधन और संरक्षण परंपरागत रूप से स्थानीय ग्रामीण और आदिवासी समुदायों द्वारा किया जाता रहा है। इन क्षेत्रों की सुरक्षा का आधार कोई सरकारी कानून नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं। ग्रामीण समुदाय इन वनों को अपना साझा दायित्व मानते हैं जिससे ये क्षेत्र बाहरी हस्तक्षेप से सुरक्षित रहते हैं और जैव-विविधता का केंद्र बने रहते हैं।

121. (C) ऐसी संपदा जिस पर किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व हो।
साझी संपदा एक ऐसे संसाधन को संदर्भित करती है जिस पर किसी एक व्यक्ति या संस्था का निजी अधिकार नहीं होता बल्कि एक पूरे समुदाय या समूह के सभी सदस्यों का सामूहिक हक होता है। इसमें चारागाह, नदियाँ और सामुदायिक मैदान जैसे उदाहरण शामिल हैं जहाँ प्रत्येक सदस्य को संसाधन का उपयोग करने का अधिकार होता है और साथ ही उसके संरक्षण और प्रबंधन की साझा जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है।

122. (A) P-4, Q-1, R-2, S-3
वैश्विक और स्थानीय जनसांख्यिकीय आंकड़े पर्यावरणीय और सामाजिक विमर्श को मजबूती प्रदान करते हैं। रियो पृथ्वी सम्मेलन में एक सौ सत्तर देशों ने भाग लिया था जबकि फिलीपिन्स के कोरडिलेरा क्षेत्र में लगभग बीस लाख मूलवासी निवास करते हैं। चिली का मापुशे समुदाय दस लाख की आबादी वाला एक प्रमुख मूलवासी समूह है और भारत की कुल जनसंख्या में आदिवासी समुदायों का महत्वपूर्ण हिस्सा लगभग आठ प्रतिशत दर्ज किया गया है।

123. (A) केवल 1 और 5 सही हैं।
अराल सागर का सूखना और विषाक्त होना आधुनिक काल की एक बड़ी पर्यावरणीय आपदा है जिसने वहां के पूरे मत्स्य उद्योग को पूर्णतः नष्ट कर दिया है। इसी प्रकार मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों की छाछठ करोड़ तीस लाख जनता आज भी स्वच्छ पेयजल के संकट से जूझ रही है। कृषि योग्य भूमि घट रही है और वन जलवायु को संतुलित करते हैं इसलिए अन्य कथन तथ्यात्मक रूप से गलत और निराधार हैं।

124. (B) पर्यावरणीय समस्याओं पर अधिक प्रभावी और सुलझी हुई पहलकदमियां शुरू करना।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा तैयार करना था। यह संगठन विभिन्न देशों के बीच पर्यावरणीय मुद्दों पर समन्वय स्थापित करता है और नई नीतियों तथा वैज्ञानिक शोधों को बढ़ावा देता है। इसकी पहलकदमियों का लक्ष्य पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण को रोकना और सतत विकास के लक्ष्यों को वैश्विक राजनीति के केंद्र में मजबूती से स्थापित करना रहा है।

वन्यजीव संरक्षण का प्रमुख उदाहरण है। हाल के वर्षों में कई जंगली क्षेत्रों के संरक्षण के मुद्दों को वैश्विक जैव-विविधता के व्यापक सरोकारों से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि दक्षिणी गोलार्ध में भी विजनपन की अवधारणा का प्रभाव है और इसे हर जगह आसानी से स्वीकार नहीं किया गया है।

85. (C) उपरोक्त सभी
साझी संपदा के संसाधनों में गिरावट के पीछे कई अंतर्संबंधित कारण जिम्मेदार हैं जिनमें निजीकरण, बढ़ती आबादी और गहन खेती प्रमुख हैं। जब सामुदायिक संसाधनों का निजीकरण होता है तो गरीबों की उन तक पहुँच समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार बढ़ती जनसंख्या का दबाव इन सीमित संसाधनों के अंधाधुंध दोहन को बढ़ावा देता है जिससे पारिस्थितिकी तंत्र की गुणवत्ता भी गिरती है जो अंततः सामुदायिक और पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है।

86. (B) साझी परंतु अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ
भारत का यह तर्क कि विकसित देशों को उत्सर्जन कटौती की अधिक जिम्मेदारी उठानी चाहिए, 'साझी परंतु अलग-अलग जिम्मेदारियों' के अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत मानता है कि पर्यावरण की रक्षा वैश्विक कर्तव्य है लेकिन विकसित देशों की ऐतिहासिक भूमिका और अधिक आर्थिक क्षमता उन्हें इस कार्य के लिए अग्रणी उत्तरदायी बनाती है। भारत का यह पक्ष विकासशील देशों के विकास के अधिकार की रक्षा करता है।

87. (D) 2011-12 तक बायोडीजल तैयार करना।
भारत सरकार द्वारा शुरु किए गए बायोडीजल पर राष्ट्रीय मिशन का प्राथमिक लक्ष्य वर्ष दो हजार ग्यारह-बारह तक जैव-ईंधन के उत्पादन को व्यावसायिक रूप से सुलभ और प्रभावी बनाना था। इसके अंतर्गत रतनजोत जैसी फसलों के माध्यम से ईंधन तैयार करने की योजना बनाई गई थी ताकि जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम किया जा सके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को भी पाया जा सके।

88. (A) विकासशील देशों को रियायती शर्तों पर नई प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने में कोई सार्थक प्रगति नहीं हुई है।
वर्ष उन्नीस सौ सत्तानवे में रियो सम्मेलन के पांच वर्ष पूरे होने पर किए गए पुनरावलोकन में यह चिंताजनक निष्कर्ष निकला कि विकसित देशों ने अपनी पुरानी प्रतिबद्धताएं पूरी नहीं की हैं। विकासशील देशों को पर्यावरण अनुकूल नई प्रौद्योगिकी और वित्तीय सहायता रियायती दरों पर उपलब्ध कराने में कोई विशेष प्रगति नहीं देखी गई। इस रिपोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय समझौतों के वास्तविक क्रियान्वयन की कमियों को पूरी तरह उजागर और स्पष्ट किया था।

89. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
खनिज उद्योग वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक अत्यंत शक्तिशाली अंग है लेकिन इसके पर्यावरणीय और सामाजिक परिणाम अत्यंत विनाशकारी होते हैं। यह उद्योग संसाधनों के निष्कर्षण के लिए खतरनाक रसायनों का बड़े पैमाने पर उपयोग करता है जिससे भूमि और जल स्रोत बुरी तरह प्रदूषित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त खनन कार्यों के कारण स्थानीय और विशेषकर आदिवासी समुदायों को अपनी पैतृक भूमि से बड़े पैमाने पर विस्थापित होना पड़ता है।

90. (A) मूलवासी कौम के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखना।
विश्वभर के मूलवासी समुदायों की सबसे प्रमुख और आधारभूत मांग अपनी स्वतंत्र पहचान और पारंपरिक संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखना है। वे चाहते हैं कि उन्हें उनके पैतृक निवास स्थान पर स्वायत्तता मिले और उनके प्राकृतिक संसाधनों पर उनके अधिकारों का सम्मान किया जाए। यह मांग न केवल उनके आत्म-सम्मान से जुड़ी है बल्कि उनकी अनूठी जीवन शैली को आधुनिकता के बढ़ते प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए भी अनिवार्य है।

91. (D) अनावृष्टि (सूखा)
सत्तर के दशक में अफ्रीका के उप-सहारा क्षेत्र में भीषण अनावृष्टि या सूखे के कारण एक भयानक मानवीय संकट उत्पन्न हुआ था। इस प्राकृतिक आपदा ने लाखों लोगों को अपनी भूमि छोड़ने और अन्य सुरक्षित स्थानों की ओर प्रवास करने के लिए विवश कर दिया था। इसी दुखद परिस्थिति के कारण 'पर्यावरणीय शरणार्थी' जैसा शब्द अंतरराष्ट्रीय राजनीति और मानवीय विमर्श में पहली बार प्रमुखता के साथ उभरा और प्रचलित हुआ था।

92. (A) केवल 1, 2 और 4 सही हैं।
विकासशील देशों की प्राथमिक जिम्मेदारी अपने नागरिकों का आर्थिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करना है इसलिए भारत उत्सर्जन कटौती की अनिवार्य बाध्यताओं का विरोध करता रहा है। भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन औसत से काफी कम रहने का अनुमान है और वह क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षेस मंच का समर्थन करता है। भारत ने अनेक घरेलू नीतियां अपनाई हैं इसलिए पांचवां कथन गलत है और तीसरा कथन भी तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है।

93. (C) वे अहिंसा पर आधारित हैं।
भारत में पर्यावरण संरक्षण और बाँध-विरोधी अधिकांश आंदोलन महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित रहे हैं। चिपको आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे प्रमुख संघर्षों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनों और सत्याग्रह के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद की है। ये आंदोलन जन भागीदारी और अहिंसक प्रतिरोध को अपना मुख्य हथियार बनाते हैं ताकि पर्यावरण और विस्थापितों के अधिकारों की रक्षा न्यायपूर्ण तरीके से की जा सके।

94. (D) पश्चिम एशिया (खाड़ी-क्षेत्र)
वर्तमान विश्व में तेल की निर्बाध आपूर्ति के लिए अमेरिका, यूरोप, जापान और भारत जैसे बड़े उपभोक्ता देश पूरी तरह से पश्चिम एशिया या खाड़ी क्षेत्र पर निर्भर हैं। इस क्षेत्र के पास विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार और उत्पादन क्षमता है जो वैश्विक ऊर्जा बाजार को नियंत्रित करती है। किसी भी प्रकार की क्षेत्रीय

31. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
अस्सी के दशक के बाद से बाँध-विरोधी आंदोलनों की प्रकृति में बदलाव आया है और अब इन्हें नदियों के समग्र संरक्षण के आंदोलनों के रूप में देखा जाता है। इन संघर्षों का मुख्य तर्क यह है कि बड़े बाँध पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करते हैं और स्थानीय लोगों को विस्थापित करते हैं। इसलिए आंदोलनकारी अब नदी घाटियों के अधिक टिकाऊ, न्यायसंगत और पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित प्रबंधन की पुरजोर मांग करते हैं।

32. (B) दक्षिणी गोलार्ध में (ऑस्ट्रेलिया)
विश्व का पहला संगठित बाँध-विरोधी आंदोलन अस्सी के दशक में दक्षिणी गोलार्ध के देश ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ हुआ था। यह आंदोलन फ्रैंकलिन नदी पर प्रस्तावित एक बड़े बाँध के निर्माण के विरोध में चलाया गया था। इस संघर्ष ने न केवल बाँध निर्माण को रुकवाया बल्कि भविष्य के पर्यावरण आंदोलनों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण भी पेश किया जिसमें विकास और पारिस्थितिकी के बीच संतुलन की बात की गई।

33. (B) किसे, क्या, कब, कहाँ और कैसे हासिल होता है।
संसाधनों की भू-राजनीति मुख्य रूप से इस प्रश्न पर केंद्रित होती है कि वैश्विक संसाधनों का वितरण और उन पर नियंत्रण किसके हाथ में है। यह शक्ति संघर्ष की वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न राष्ट्र अपनी आर्थिक और सैन्य शक्ति का उपयोग संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए करते हैं। इसमें तेल, खनिज और जल जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों के दोहन और व्यापार से जुड़े सामरिक हित शामिल होते हैं।

34. (A) क्योंकि उस काल में समुद्री नौवहन पूर्णतः इमारती लकड़ियों पर ही आधारित था।
सत्रहवीं शताब्दी के बाद यूरोपीय शक्तियों के लिए इमारती लकड़ी का सामरिक महत्व अत्यंत बढ़ गया था क्योंकि उस समय नौसेना की शक्ति जहाजों पर निर्भर थी। विशाल समुद्री बेड़ों के निर्माण के लिए मजबूत लकड़ी की निरंतर आपूर्ति अनिवार्य थी ताकि औपनिवेशिक विस्तार और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण बनाए रखा जा सके। लकड़ी की इस आवश्यकता ने कई देशों में जंगलों की कटाई और औपनिवेशिक संघर्षों को भी प्रेरित किया।

35. (B) केवल 1, 2, 3 और 4
शीतयुद्ध के दौरान विकसित देशों ने संसाधनों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई कूटनीतिक और सैन्य रणनीतियां अपनाई थीं। इसमें संसाधनों वाले क्षेत्रों में सेना की तैनाती करना, महत्वपूर्ण खनिजों का आपातकालीन भंडारण करना और उत्पादक देशों में अपने अनुकूल सरकारों का समर्थन करना शामिल था। साथ ही बहुराष्ट्रीय निगमों को संरक्षण प्रदान किया गया ताकि वे प्रभावी ढंग से दोहन कार्य कर सकें लेकिन प्रौद्योगिकी साझा करना उनकी प्राथमिकता नहीं थी।

36. (D) तेल
वर्तमान वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में तेल सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक संसाधन बना हुआ है क्योंकि यह परिवहन और उद्योगों का मुख्य आधार है। तेल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना विकसित और विकासशील दोनों तरह के देशों की सुरक्षा नीतियों का केंद्र बिंदु है। तेल उत्पादक क्षेत्रों पर प्रभाव जमाना और तेल के व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा करना अक्सर अंतरराष्ट्रीय विवादों और युद्धों का प्रमुख कारण बनता रहा है।

37. (A) 1, 4, 2, 3
इन घटनाओं का ऐतिहासिक अनुक्रम वैश्विक स्तर पर मूलवासियों और पर्यावरण के अधिकारों के संघर्ष को स्पष्ट करता है। सबसे पहले उन्नीस सौ पचहत्तर में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन हुआ। इसके बाद अस्सी के दशक के प्रारंभ में ऑस्ट्रेलिया में फ्रैंकलिन नदी आंदोलन चला। फिर उन्नीस सौ बासी में संयुक्त राष्ट्र ने मूलवासियों की परिभाषा दी और अंततः नब्बे के दशक में फिलीपिन्स में खनन विरोधी अभियान चला।

38. (B) पश्चिम एशिया (खाड़ी-क्षेत्र)
पश्चिम एशिया या खाड़ी क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है क्योंकि यहाँ विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार स्थित है। कुल ज्ञात तेल भंडारों का लगभग चौंसठ प्रतिशत हिस्सा इसी क्षेत्र में केंद्रित है जो विश्व के कुल उत्पादन का तीस प्रतिशत प्रदान करता है। इसी रणनीतिक महत्व के कारण यह क्षेत्र हमेशा से बड़ी शक्तियों के हस्तक्षेप और राजनीतिक अस्थिरता का केंद्र बना रहा है।

39. (D) सऊदी अरब और इराक
वैश्विक तेल राजनीति में सऊदी अरब सबसे बड़ा तेल उत्पादक और भंडार वाला देश है जिसके पास विश्व के कुल भंडार का लगभग एक चौथाई हिस्सा है। इराक इस क्रम में दूसरे स्थान पर आता है जहाँ तेल के विशाल और ज्ञात भंडार मौजूद हैं। इन दोनों देशों की उत्पादन क्षमता और भंडार विश्व की अर्थव्यवस्था की गति निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसलिए इनका भू-राजनीतिक महत्व अत्यधिक है।

40. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
जल संसाधनों के असमान वितरण और बढ़ती कमी के कारण भविष्य में देशों के बीच हिंसक संघर्ष होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। स्वच्छ जल जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है लेकिन विश्व के विभिन्न हिस्सों में इसकी उपलब्धता समान नहीं है। जब कई देश एक ही नदी के जल पर निर्भर होते हैं तो जल के उपयोग और उसके बहाव को मोड़ने को लेकर अक्सर गंभीर विवाद उत्पन्न हो जाते हैं।

41. (C) इज़रायल, सीरिया तथा जॉर्डन
पचास और साठ के दशक में इजरायल, सीरिया और जॉर्डन के बीच जॉर्डन और यारमुक नदियों के जल बंटवारे को लेकर गंभीर तनाव उत्पन्न हुआ था। प्रत्येक राष्ट्र इन नदियों के पानी को अपने विकास के लिए मोड़ने की कोशिश कर रहा था जिससे सैन्य संघर्ष की स्थिति बन गई थी। यह उदाहरण स्पष्ट करता

आध्यात्मिक चेतना का अनिवार्य हिस्सा है जिसे वे सुरक्षित रखना चाहते हैं।

105. (C) विस्थापित होने वाले मूलवासी समुदायों को।
आधुनिक विकास की अंधाधुंध प्रक्रिया में सबसे भारी कीमत अक्सर समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर खड़े मूलवासी समुदायों को चुकानी पड़ती है। जब बड़े बाँध, औद्योगिक परियोजनाएं या खनन कार्य किए जाते हैं तो ये समुदाय अपनी पैतृक भूमि से विस्थापित हो जाते हैं। विस्थापन के कारण उनकी आजीविका, संस्कृति और सामाजिक ताना-बाना पूरी तरह बिखर जाता है जबकि विकास के लाभ अक्सर उन तक नहीं पहुँच पाते हैं।

106. (A) नेशनल पार्क
भारत में पवित्र वन क्षेत्रों को सरना, काव और देव रहतिस जैसे विभिन्न स्थानीय नामों से पुकारा जाता है जो सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं। 'नेशनल पार्क' या राष्ट्रीय उद्यान एक कानूनी और सरकारी व्यवस्था है जिसका प्रबंधन राज्य द्वारा किया जाता है। इसके विपरीत देवस्थान सामुदायिक प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं जहाँ संरक्षण का आधार कानून न होकर स्थानीय आस्था और परंपराएं होती हैं।

107. (A) केवल 1 और 2 सही हैं।
देवस्थानों की परंपरा जैव-विविधता और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई है। हालांकि हाल के वर्षों में बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के दबाव के कारण कई देवस्थानों पर अतिक्रमण हुआ है जिससे उनका अस्तित्व खतरे में है। नई वन नीतियां प्रायः इन सामुदायिक व्यवस्थाओं को कानूनी मान्यता देने में विफल रही हैं और प्रबंधन के अधिकार को लेकर विवाद आज भी निरंतर बने हुए हैं।

108. (B) 0.9 टन; 1.6 टन
वर्ष दो हजार के आंकड़ों के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन स्तर लगभग शून्य दशमलव नौ टन था। यह अनुमान लगाया गया है कि विकास की गति के साथ वर्ष दो हजार तीस तक यह बढ़कर एक दशमलव छह टन प्रति व्यक्ति हो जाएगा। इसके बावजूद भारत का यह स्तर वैश्विक औसत और विकसित देशों के वर्तमान उत्सर्जन स्तर से काफी कम रहेगा जो भारत के सतत विकास के पक्ष को मजबूती प्रदान करता है।

109. (C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
वैश्विक पर्यावरण आंदोलन आज दुनिया के सबसे जीवंत और प्रभावशाली सामाजिक आंदोलनों में गिने जाते हैं क्योंकि वे पारिस्थितिकी संकटों के विरुद्ध सक्रिय आवाज उठाते हैं। हालांकि यह दावा गलत है कि ये केवल कुछ देशों या केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय हैं। वास्तविकता यह है कि ये आंदोलन अत्यंत जमीनी और स्थानीय स्तर से लेकर वैश्विक मंचों तक अपनी व्यापक पहुँच और मजबूत सक्रियता रखते हैं।

110. (D) पानी
तेल के बाद स्वच्छ जल को विश्व राजनीति का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक संसाधन माना जाता है जिसकी कमी भविष्य के युद्धों का कारण बन सकती है। जल संसाधनों का असमान वितरण और बढ़ती जनसंख्या के कारण पानी की मांग में वृद्धि देशों के बीच गंभीर तनाव पैदा कर रही है। साझा नदियों के जल बंटवारे को लेकर होने वाले विवाद इस बात की पुष्टि करते हैं कि जल सुरक्षा अब राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है।

111. (A) Petroleum (तेल)
पेट्रोलियम या खनिज तेल को इसके अत्यधिक आर्थिक और सामरिक महत्व के कारण अक्सर 'काला सोना' कहा जाता है। यह आधुनिक औद्योगिक युग का सबसे प्रमुख ऊर्जा स्रोत है जिसके बिना परिवहन और विनिर्माण गतिविधियां थम सकती हैं। तेल उत्पादक देशों की अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उनकी शक्ति का मुख्य आधार यही संसाधन है। इसकी बढ़ती मांग और सीमित भंडार इसे सोने की तरह ही मूल्यवान और विवादित बनाते हैं।

112. (B) P-4, Q-1, R-3, S-2
विभिन्न क्षेत्रों की पर्यावरणीय पहचान उनके विशिष्ट मुद्दों से जुड़ी है। खाड़ी क्षेत्र अपनी विशाल तेल उत्पादन क्षमता और चौंसठ प्रतिशत वैश्विक भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया का फ्रैंकलिन नदी आंदोलन बाँध विरोधी चेतना का प्रतीक बना जबकि भारत में नर्मदा आंदोलन ने विस्थापन के मुद्दे को प्रमुखता दी। फिलीपिन्स में वेस्टर्न माइनिंग कारपोरेशन के विरुद्ध चलाया गया संघर्ष खनन के विनाशकारी प्रभावों के विरुद्ध एक बड़ी और सफल जीत थी।

113. (B) ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना।
क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों के सांद्रण को नियंत्रित करना है ताकि ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को टाला जा सके। उन्नीस सौ सत्तानवे में अपनाए गए इस ऐतिहासिक समझौते ने विकसित देशों के लिए उत्सर्जन कटौती के विशिष्ट और कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित किए। यह जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक ठोस और अत्यंत प्रभावी मील का पत्थर माना जाता है।

114. (A) केवल 1 और 2 सही हैं।
साझी परंतु अलग-अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत पृथ्वी सम्मेलन में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था जो प्रदूषण में देशों की ऐतिहासिक भूमिका को स्वीकार करता है। यूएनएफसीसीसी ने माना कि विकसित देशों ने वायुमंडल में सबसे अधिक ग्रीनहाउस गैसें छोड़ी हैं। हालांकि क्योटो प्रोटोकॉल एक बाध्यकारी समझौता था और इसमें भारत एवं चीन जैसे विकासशील देशों को शुरुआती अनिवार्य कटौती के लक्ष्यों से बाहर रखा गया था ताकि वे विकास कर सकें।

अस्थिरता वैश्विक तेल कीमतों को प्रभावित करती है जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर सीधा असर पड़ता है।

95. (A) पश्चिमी यूरोप
मूलवासी समुदाय मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ औपनिवेशिक विस्तार के बाद भी स्थानीय संस्कृतियाँ जीवित रहीं जैसे मध्य और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया और भारत। पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देशों में आधुनिक औद्योगिक समाजों के प्रसार के कारण पारंपरिक मूलवासी समुदायों की वैसी उपस्थिति नहीं है जैसी अन्य महाद्वीपों में देखी जाती है। अतः पश्चिमी यूरोप इस सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है।

96. (B) क्योंकि इनका समाधान कोई एक देश अकेले नहीं कर सकता।
पर्यावरणीय समस्याओं का स्वरूप वैश्विक होता है और वे राष्ट्रीय सीमाओं का सम्मान नहीं करतीं जैसे ग्लोबल वार्मिंग या ओजोन परत का क्षरण। ऐसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए सभी देशों के बीच साझा अंतरराष्ट्रीय सहयोग और साझा नीतियों का होना अत्यंत अनिवार्य है। कोई भी राष्ट्र चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अकेले इन पारिस्थितिकी संकटों से नहीं निपट सकता, इसलिए ये मुद्दे विश्व राजनीति के केंद्र में हैं।

97. (B) इसका झुकाव पर्यावरण सुरक्षा के बजाय आर्थिक वृद्धि की ओर अधिक है।
एजेंडा इक्कीस के आलोचकों का तर्क है कि यह दस्तावेज सतत विकास की बात तो करता है लेकिन इसका वास्तविक झुकाव आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने की ओर अधिक है। उनके अनुसार इसमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उतने कड़े प्रावधान नहीं किए गए जितने आवश्यक थे। आलोचकों का यह भी मानना है कि यह विकसित देशों के उपभोग आधारित विकास मॉडल को पूरी तरह से चुनौती देने में विफल रहा है।

98. (A) P-4, Q-1, R-2, S-3
पर्यावरणीय आंदोलनों और उनके संबंधित देशों का मिलान उनकी वैश्विक पहचान को दर्शाता है। भारत में बंगाल टाइगर को बचाने का अभियान और नर्मदा बचाओ आंदोलन अत्यंत सक्रिय रहे हैं। फिलीपिन्स में वेस्टर्न माइनिंग कारपोरेशन के विरुद्ध स्थानीय समूहों ने जोरदार आवाज उठाई थी जबकि ऑस्ट्रेलिया में फ्रैंकलिन नदी को बचाने का संघर्ष अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाँध-विरोधी आंदोलनों की मिसाल और प्रेरणा के रूप में सदैव याद किया जाता है।

99. (A) 3, 4, 2, 1
इन घटनाओं का कालक्रम पर्यावरणीय चेतना के विकास की यात्रा है। इसकी शुरुआत उन्नीस सौ बहत्तर में 'लिमिट्स टू ग्रोथ' के प्रकाशन से हुई जिसके बाद उन्नीस सौ सत्तासी में 'अवर कॉमन फ्यूचर' रिपोर्ट आई। इसके पश्चात उन्नीस सौ बाणवे में ऐतिहासिक रियो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ और अंततः उन्नीस सौ सत्तानवे में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। यह अनुक्रम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते पर्यावरणीय सहयोग और नियामक ढाँचे को दर्शाता है।

100. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
नब्बे के दशक के बाद से पर्यावरण सुरक्षा वैश्विक राजनीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राथमिक सरोकार बन गया है। इस बदलाव का मुख्य श्रेय वर्ष उन्नीस सौ बाणवे के पृथ्वी सम्मेलन को जाता है जिसने पर्यावरण को अंतरराष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला खड़ा किया। इस सम्मेलन के बाद ही दुनिया भर के देशों ने सतत विकास और जलवायु सुरक्षा के लिए साझा और प्रभावी रणनीतियां बनाना गंभीरता से शुरु किया था।

101. (A) केवल 1 और 2
अंटार्कटिका के स्वामित्व को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय में दो प्रमुख विचार रहे हैं। ब्रिटेन, अर्जेंटीना, चिली और नॉर्वे जैसे कुछ देशों ने इस पर अपने ऐतिहासिक और भौगोलिक संप्रभु अधिकारों का दावा पेश किया है। हालांकि भारत सहित दुनिया के अधिकांश अन्य राष्ट्र इसे पूरी मानवता की साझी संपदा मानते हैं। उन्नीस सौ उनसठ की अंटार्कटिका संधि ने इन दावों को फिलहाल ठंडे बस्ते में डालकर वैज्ञानिक सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया।

102. (B) जंतु-प्रजातियों के संरक्षण हेतु 'विजनपन' से जुड़े अनेक वैश्विक अभियान।
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने लुप्तप्राय जंतु प्रजातियों और उनके प्राकृतिक आवासों को बचाने के लिए व्यापक अभियान चलाए हैं। ये संगठन विजनपन या वाइल्डरनेस के संरक्षण की पैरोकारी करते हैं ताकि पारिस्थितिकी तंत्र में जैव-विविधता बनी रहे। वे इन परियोजनाओं के लिए न केवल जन चेतना जागृत करते हैं बल्कि वैज्ञानिक शोध और क्षेत्रीय संरक्षण कार्यों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं।

103. (D) संसाधनों को लेकर राज्यों के बीच कभी तनातनी नहीं हुई है।
संसाधनों की उपलब्धता और उन पर नियंत्रण को लेकर राष्ट्रों के बीच तनाव का एक लंबा और हिंसक इतिहास रहा है। यह कहना पूर्णतः गलत है कि संसाधनों को लेकर कभी तनातनी नहीं हुई क्योंकि अधिकांश औपनिवेशिक युद्ध और रणनीतिक संघर्ष संसाधनों की प्राप्ति के लिए ही लड़े गए थे। तेल, पानी और महत्वपूर्ण खनिज हमेशा से अंतरराष्ट्रीय प्रतिद्वंद्विता और युद्धों के केंद्र में रहे हैं जो वैश्विक राजनीति का यथार्थ है।

104. (A) अपने मूल वासस्थान पर हक और स्वतंत्र पहचान को बनाए रखना।
विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे लगभग तीस करोड़ मूलवासियों के साझा हित उनकी पैतृक भूमि पर उनके अधिकारों और उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा से जुड़े हैं। वे अपनी पारंपरिक जीवन शैली को आधुनिक अतिक्रमण से बचाने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। उनके लिए भूमि केवल एक आर्थिक संसाधन नहीं बल्कि उनके अस्तित्व, इतिहास और

125. (C) वैश्विक अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के कारण
नब्बे के दशक के बाद से वैश्विक अर्थव्यवस्था में आए उदारीकरण और निजीकरण के कारण दक्षिणी गोलार्ध के देशों के प्राकृतिक संसाधन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए सुलभ हो गए हैं। व्यापारिक बाधाओं के कम होने से इन कंपनियों ने विकासशील देशों में खनन और अन्य औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार किया है। हालांकि इस प्रक्रिया ने जहाँ आर्थिक निवेश को बढ़ावा दिया है वहीं स्थानीय पर्यावरण और समुदायों के विस्थापन की गंभीर चुनौतियां भी पैदा की हैं।

126. (D) तेल
प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गया था कि पेट्रोलियम या तेल केवल एक ईंधन नहीं बल्कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामरिक हथियार है। सेनाओं की गतिशीलता, जहाजों और टैंकों के संचालन के लिए तेल की निर्बाध आपूर्ति पर ही युद्ध का परिणाम निर्भर करता था। इस कालखंड ने तेल को वैश्विक रणनीतिक चिंतन के केंद्र में ला खड़ा किया जो आज भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों का आधार बना हुआ है।

127. (A) विश्वभर के मूलनिवासियों द्वारा
'हम यहाँ अनंत काल से रहते चले आ रहे हैं' यह शक्तिशाली जुमला दुनिया भर के मूलवासी समुदायों द्वारा अपनी भूमि पर अपने ऐतिहासिक और पैतृक अधिकारों को सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह उनके उस अटूट संबंध को दर्शाता है जो वे अपनी धरती के साथ महसूस करते हैं। यह दावा औपनिवेशिक इतिहास के विरुद्ध उनकी पहचान और संप्रभुता को पुनः स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और राजनीतिक हथियार है।

128. (B) ताकि इस क्षेत्र की आवाज़ वैश्विक मंच पर वज़नी हो सके।
भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के माध्यम से पर्यावरण के मुद्दों पर एक साझा राय बनाने का प्रयास किया है। भारत का मुख्य उद्देश्य यह था कि यदि दक्षिण एशिया के सभी देश एक होकर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात रखेंगे तो उनकी आवाज अधिक प्रभावशाली और वज़नी होगी। यह सामूहिक दृष्टिकोण विकासशील देशों के हितों की रक्षा करने और विकसित देशों पर अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने हेतु दबाव बनाने में सहायक है।

129. (A) केवल 1 और 2 सही हैं।
भारत में विकास परियोजनाओं के कारण अपना घर और जमीन खोने वालों में सबसे बड़ी संख्या आदिवासियों की है जो विस्थापन का सबसे अधिक दर्द झेलते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्नीस सौ पचहत्तर में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन हुआ जो उनकी आवाज बना। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने इस परिषद को मान्यता प्रदान की है और भारतीय संविधान में भी आदिवासियों को सुरक्षा प्राप्त है अतः कथन तीन और चार गलत हैं।

130. (A) उनके साझे अनुभवों और सरोकारों को एक शक्ल मिली।
सत्तर के दशक में संचार और यातायात के साधनों के विकास से दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले मूलवासी नेताओं के बीच आपसी संपर्क बढ़ा। इस संवाद का महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि उनके स्थानीय संघर्षों को एक अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली और उनके साझे सरोकारों ने एक संगठित वैश्विक आंदोलन का रूप लिया। इसने मूलवासियों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक साझा मंच और नई राजनीतिक दृष्टि प्रदान की।

131. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
रियो सम्मेलन ने विकसित और विकासशील देशों के बीच मौजूद स्पष्ट वैचारिक मतभेदों को सार्वजनिक किया। धनी उत्तरी देशों का मुख्य एजेंडा ओजोन परत की रक्षा और ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएं थीं। इसके विपरीत गरीब दक्षिणी देशों के लिए गरीबी हटाना और विकास के अधिकार के साथ पर्यावरण का संतुलन बनाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। यह विरोधाभास आज भी जलवायु वार्ताओं में एक प्रमुख चुनौती बना हुआ है।

132. (D) P-4, Q-3, R-2, S-1
जलमार्गों और उनसे जुड़े संघर्षों का क्षेत्रीय संबंध अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करता है। जॉर्डन और यारमुक नदियों को लेकर इजरायल और उसके पड़ोसी अरब देशों में विवाद रहा है जबकि फरात नदी तुर्की, सीरिया और इराक के संबंधों में तनाव का कारण है। भारत में नर्मदा नदी आंदोलन एक बड़ा सामाजिक संघर्ष है और ऑस्ट्रेलिया में फ्रैंकलिन नदी को बचाने का आंदोलन पर्यावरणीय जीत का एक ऐतिहासिक और वैश्विक प्रतीक माना जाता है।

133. (C) उपरोक्त सभी।
अराल सागर का संकट आधुनिक इतिहास की सबसे दुखद पर्यावरणीय आपदाओं में से एक माना जाता है। अत्यधिक सिंचाई के लिए नदियों का पानी मोड़ने से यह सागर सिकुड़ गया और इसका पानी इतना विषाक्त हो गया कि पूरा मत्स्य उद्योग चौपट हो गया। साथ ही पानी में नमक की बढ़ती सांद्रता ने आस-पास की कृषि भूमि की उर्वरता को नष्ट कर दिया जिससे स्थानीय समुदायों के सामने आजीविका का गंभीर संकट पैदा हो गया है।

134. (B) रियो-घोषणापत्र
रियो घोषणापत्र वर्ष उन्नीस सौ बाणवे के पृथ्वी सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दस्तावेज है जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग के सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है। यह घोषणापत्र देशों के बीच विश्व-बंधुत्व की भावना के साथ पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा, बहाली और गुणवत्ता बनाए रखने पर बल देता है। यह पर्यावरण और विकास के अंतर्संबंधों को स्पष्ट करते हुए भविष्य के लिए एक विस्तृत और व्यापक वैश्विक मार्गदर्शिका प्रस्तुत करता है।

135. (D) क्लब ऑफ रोम
क्लब ऑफ रोम एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय विद्वत समूह है जिसने उन्नीस सौ बहत्तर में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'लिमिट्स टू ग्रोथ' प्रकाशित की थी। इस पुस्तक ने दुनिया का ध्यान इस तथ्य की ओर खींचा कि जिस गति से संसाधनों का दोहन और जनसंख्या वृद्धि हो रही है वह लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है। इस प्रकाशन ने आधुनिक युग में वैश्विक पर्यावरणीय चेतना को आकार देने और सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

136. (A) नवीकरणीय (Renewable) ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना।
भारत के वर्ष दो हजार तीन के बिजली अधिनियम ने देश की ऊर्जा नीति में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव किया। इस कानून का एक प्रमुख उद्देश्य बिजली के उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा के अनुपात को बढ़ाना था। यह अधिनियम पर्यावरण संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और देश को स्वच्छ ऊर्जा की ओर ले जाने के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा प्रदान करता है।

137. (B) केवल 2, 3 और 5 सही हैं।
भारत में देवस्थानों की परंपरा प्रकृति पूजा की गहरी जड़ों से जुड़ी है जिसमें वनों को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व दिया जाता है। यह व्यवस्था केवल वनों तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें जल स्रोतों का भी संरक्षण शामिल होता है। प्रबंधन में मुख्य समस्या तब आती है जब वनों का कानूनी स्वामित्व सरकार के पास होता है लेकिन व्यावहारिक नियंत्रण समुदाय के पास रहता है। हाल के वर्षों में देवस्थानों का ह्रास हुआ है।

138. (A) उपरोक्त सभी।
खनिज उद्योग की व्यापक आलोचना उसके विनाशकारी पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों के कारण की जाती है। यह उद्योग भूमि का विनाश करता है, जहरीले रसायनों से जल स्रोतों को प्रदूषित करता है और स्थानीय वनस्पतियों को हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त खनन परियोजनाओं के कारण बड़े पैमाने पर लोगों को विस्थापित होना पड़ता है जिससे उनकी पूरी जीवन शैली और आजीविका समाप्त हो जाती है जो एक गंभीर मानवाधिकार मुद्दा भी है।

139. (D) संसाधनों तक पहुँच अबाध रूप से बनी रहे।
शीतयुद्ध के दौरान पश्चिमी विकसित राष्ट्रों का प्राथमिक राजनीतिक लक्ष्य महत्वपूर्ण संसाधनों तक अपनी निर्बाध पहुँच सुनिश्चित करना था। उनकी पूरी विदेश नीति और रणनीतिक चिंतन इसी विचार के इर्द-गिर्द केंद्रित था कि कैसे तेल और अन्य सामरिक खनिजों की आपूर्ति को सुरक्षित रखा जाए। इसके लिए उन्होंने अक्सर विकासशील देशों में राजनीतिक हस्तक्षेप और सैन्य उपस्थिति का सहारा लिया जो संसाधनों की भू-राजनीति का एक अनिवार्य हिस्सा और मुख्य उद्देश्य था।

140. (B) किसी क्षेत्र के वे वंशज जिन पर बाद में बाहरी संस्कृतियाँ हावी हुईं।
मूलवासी वे लोग हैं जो किसी भौगोलिक क्षेत्र के आदि निवासी हैं और जिनकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है। ये उन लोगों के वंशज हैं जो वहाँ तब से रह रहे थे जब दूसरी संस्कृतियों या जातियों के लोग वहां आए और प्रभुत्व स्थापित कर लिया। वर्तमान में ये समुदाय अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमि, संसाधनों और स्वायत्तता के अधिकारों के लिए सक्रिय रूप से संघर्ष कर रहे हैं ताकि उनका अस्तित्व बना रहे।

141. (B) P-2, Q-1, R-4, S-3
पर्यावरणीय शब्दावली और उनकी अवधारणाओं का सटीक मिलान विषय की समझ को गहरा करता है। वैश्विक तापवृद्धि का संबंध ग्रीनहाउस गैसों से है जबकि टिकाऊ विकास वह तरीका है जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुँचाता। पर्यावरणीय शरणार्थी वे लोग हैं जो आपदाओं के कारण विस्थापन झेलते हैं और पावन वन-प्रांतर उन क्षेत्रों को कहा जाता है जिन्हें धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के कारण सदियों से सुरक्षित और संरक्षित रखा गया है।

142. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
भारत उत्सर्जन कटौती की अनिवार्य बाध्यताओं का पुरजोर विरोध करता है क्योंकि उसका मानना है कि जलवायु परिवर्तन की मुख्य जिम्मेदारी विकसित देशों की है। भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन स्तर विकसित देशों की तुलना में अत्यंत कम है और उसे अपनी विशाल जनसंख्या के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। यह रुख यूएनएफसीसीसी के साझी परंतु अलग-अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत के पूरी तरह अनुकूल और न्यायसंगत है।

143. (A) 170
वर्ष उन्नीस सौ बाणवे में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित ऐतिहासिक पृथ्वी सम्मेलन में कुल एक सौ सत्तर देशों ने सक्रिय भागीदारी की थी। इसके अलावा इसमें हजारों स्वयंसेवी संगठनों और अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भी भाग लिया था। यह भागीदारी इस तथ्य को दर्शाती है कि पर्यावरण का मुद्दा अब केवल कुछ देशों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक साझा और अत्यंत गंभीर चिंता का विषय बन चुका है।

144. (B) ऑस्ट्रेलिया का फ्रैंकलिन नदी आंदोलन
ऑस्ट्रेलिया का फ्रैंकलिन नदी आंदोलन अपनी प्रकृति में अत्यंत व्यापक और बहुआयामी था। इसने न केवल एक प्रस्तावित बाँध के निर्माण का विरोध किया बल्कि वहां के वर्षा वनों और विजनपन या वाइल्डरनेस की रक्षा के लिए भी सशक्त आवाज उठाई। इस आंदोलन ने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की आवश्यकता पर वैश्विक बहस को जन्म दिया और पर्यावरण आंदोलनों के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सफल अध्याय जोड़ा।

145. (B) 30%
पश्चिम एशिया या खाड़ी क्षेत्र वर्तमान में विश्व के कुल तेल उत्पादन का लगभग तीस प्रतिशत हिस्सा प्रदान करता है। इसके पास दुनिया के ज्ञात तेल भंडार का चौंसठ प्रतिशत हिस्सा सुरक्षित है जो इसे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक केंद्र बनाता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र की छोटी सी भी राजनीतिक हलचल पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों को तत्काल प्रभावित करने की क्षमता रखती है।

146. (C) केवल 1, 2 और 3 सही हैं।
दक्षिणी गोलार्ध के देशों में आर्थिक विकास की होड़ के कारण बड़े बाँध बनाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। भारत में नर्मदा जैसे आंदोलनों ने अहिंसक तरीके से अपनी बात रखी है और अब इन्हें नदियों के समग्र संरक्षण के संघर्ष के रूप में देखा जा रहा है। विश्व का पहला बाँध-विरोधी आंदोलन भारत में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था इसलिए चौथा कथन ऐतिहासिक रूप से गलत और तथ्यहीन माना जाता है।

147. (C) 6 लाख
बांग्लादेश के चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में लगभग छह लाख मूलवासी और जनजातीय लोग निवास करते हैं। यह क्षेत्र अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है लेकिन भूमि अधिकारों और विकास परियोजनाओं के कारण यहाँ के मूल निवासियों को अक्सर संघर्ष और विस्थापन जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन लोगों की पहचान और उनके अधिकारों की रक्षा करना बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है।

148. (D) ग्रीन हाऊस गैस के जमाव का
अंटार्कटिका महादेश की अंदरूनी हिमानी परतें पृथ्वी के जलवायु इतिहास का एक प्राकृतिक रिकॉर्ड मानी जाती हैं। इन बर्फ की परतों में प्राचीन समय की हवा के बुलबुले फंसे होते हैं जो हजारों वर्षों से ग्रीनहाउस गैसों के सांद्रण में आए बदलावों की सटीक जानकारी प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक इन परतों का अध्ययन करके भविष्य के जलवायु परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाने और पृथ्वी के वायुमंडलीय विकास को समझने में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त करते हैं।

149. (C) 1, 3, 4, 2
भारत के पर्यावरणीय कानूनों और अंतरराष्ट्रीय समझौतों का अनुक्रम देश की बढ़ती जलवायु जागरूकता को दर्शाता है। सर्वप्रथम दो हजार एक में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम आया जिसके बाद दो हजार दो में क्योटो प्रोटोकॉल का अनुमोदन हुआ। बिजली अधिनियम दो हजार तीन में पारित किया गया था जो अक्षय ऊर्जा पर केंद्रित था। अंततः वर्ष दो हजार सोलह में पेरिस जलवायु समझौते का औपचारिक अनुमोदन भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता का प्रतीक बना।

150. (B) टिकाऊ विकास
एजेंडा इक्कीस रियो पृथ्वी सम्मेलन का एक व्यापक मार्गदर्शक दस्तावेज है जिसने टिकाऊ विकास या सतत विकास के तौर-तरीकों की पुरजोर वकालत की। इसका उद्देश्य विकास की ऐसी प्रक्रिया को बढ़ावा देना है जो भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों के साथ समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करे। इसमें पर्यावरण सुरक्षा, आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को विकास के मॉडल में एकीकृत करने के विस्तृत सुझाव दिए गए थे।

151. (B) पर्यावरण क्षरण में सभी देशों का ऐतिहासिक योगदान असमान रहा है।
'साझी परंतु विभेदित जिम्मेदारियों' का सिद्धांत इस ऐतिहासिक वास्तविकता को स्वीकार करता है कि औद्योगिक प्रगति के दौरान विकसित देशों ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है। यह मान्यता वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय नुकसान के लिए उत्तरदायित्व के असमान वितरण को रेखांकित करती है। चूँकि सभी राष्ट्रों का कार्बन उत्सर्जन का इतिहास अलग-अलग रहा है, इसलिए संरक्षण के प्रयासों में उनकी भूमिका और वित्तीय जिम्मेदारी भी अलग होनी चाहिए।

152. (A) वे देश जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से सबसे अधिक उत्सर्जन किया है।
पर्यावरण न्याय के सिद्धांतों के अनुसार, जिन देशों ने औद्योगिक क्रांति के बाद से वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों के संचयन में सबसे अधिक योगदान दिया है, उन्हें ही इसके समाधान का मुख्य भार उठाना चाहिए। यह दृष्टिकोण जिम्मेदारी को उनकी ऐतिहासिक आर्थिक गतिविधियों और प्रदूषण स्तर से जोड़ता है। विकसित देशों के पास तकनीकी और वित्तीय संसाधन अधिक हैं, जिससे वे जलवायु परिवर्तन की रोकथाम में नेतृत्व करने के लिए अधिक सक्षम और नैतिक रूप से बाध्य माने जाते हैं।

153. (C) क्योंकि उनकी विकासात्मक आवश्यकताएँ और निम्न प्रति व्यक्ति उत्सर्जन है।
विकासशील देशों को पर्यावरण संरक्षण में छूट या विभेदित जिम्मेदारियाँ देने का मुख्य आधार उनकी गरीबी उन्मूलन और बुनियादी ढाँचे के विकास की वर्तमान आवश्यकताएँ हैं। इन देशों का ऐतिहासिक और प्रति व्यक्ति उत्सर्जन विकसित राष्ट्रों की तुलना में बहुत कम रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में यह अंतर इसलिए रखा गया है ताकि उनके आर्थिक विकास की प्रक्रिया बाधित न हो और वे टिकाऊ भविष्य की ओर धीरे-धीरे बढ़ सकें।

154. (D) अपनी औद्योगिक प्रगति के लिए जीवाश्म ईंधन के व्यापक उपयोग के कारण।
उत्तरी गोलार्ध के औद्योगिक देशों ने अपनी आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों का सदियों तक अनियंत्रित उपयोग किया है। इसी औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों का भारी संचयन हुआ है। ऐतिहासिक डेटा स्पष्ट करता है कि वर्तमान जलवायु संकट के पीछे इन देशों की पुरानी ऊर्जा खपत और बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन की नीतियां ही प्राथमिक कारक रही हैं।

28. वैश्वीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. प्रवाह केवल विचारों और पूंजी का होता है।
2. प्रवाह की गति और प्रसार का धरातल मौजूदा वैश्वीकरण को अनूठा बनाते हैं।
3. 'विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव' इन प्रवाहों की निरंतरता से पैदा हुआ है।
4. प्रौद्योगिकी ने इन प्रवाहों की आसानी में कोई भूमिका नहीं निभाई है।

उपरोक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 4
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) केवल 2, 3 और 4

29. "एक कॉल सेंटर में काम करने वाला जनार्दन, जो देर रात काम करता है और एक नया लहजा अपनाता है," यह किसका उदाहरण है?
(A) वस्तुओं के वैश्वीकरण का।
(B) सांस्कृतिक समरुपता का।
(C) सेवाओं के वैश्वीकरण का।
(D) राजनीतिक प्रतिरोध का।

30. वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों के संबंध में यह तर्क क्यों दिया जाता है कि यह केवल गरीब देशों के लिए ही नहीं, बल्कि समूची मानवता के लिए खतरनाक है?
(A) क्योंकि इसके कारण विभिन्न देशों का आर्थिक विकास बहुत धीमा और असंतुलित हो जाता है।
(B) क्योंकि इसके परिणामस्वरुप वैश्विक स्तर पर गंभीर राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है।
(C) क्योंकि यह प्रक्रिया केवल पश्चिमी और विकसित देशों को ही आर्थिक लाभ पहुँचाती है।
(D) क्योंकि इससे विश्व की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का धीरे-धीरे पूर्ण विनाश होता है।

31. निम्नलिखित को उनके घटित होने के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. औपनिवेशिक दौर में भारत का कच्चे माल का निर्यातक बनना।
2. भारत में संरक्षणवाद की नीति का क्रियान्वयन।
3. भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत।
4. 'नीम' को पेटेंट कराने के प्रयासों का विरोध।

उपरोक्त में से कौन-सा क्रम सही है?
(A) 1, 2, 3, 4
(B) 2, 1, 3, 4
(C) 1, 3, 2, 4
(D) 3, 1, 2, 4

32. वैश्वीकरण के विषय में कौन सा विचार गलत है?
(A) यह एक बहुआयामी परिघटना है।
(B) इसका प्रभाव सभी पर समान रूप से सकारात्मक रहा है।
(C) प्रौद्योगिकी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है।
(D) इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिणाम हैं।

33. विश्व सामाजिक मंच (WSF) के तहत कौन से समूह एकजुट होकर नव-उडरवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं?
(A) केवल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ता और विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख पर्यावरणवादी।
(B) मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिला आंदोलनों से जुड़े कार्यकर्ता।
(C) केवल औद्योगिक क्षेत्रों के मजदूर और सक्रिय राजनीति में शामिल युवा कार्यकर्ता।
(D) केवल बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि और उनके वैश्विक समर्थन समूह।

34. निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए:
सूची I: (आलोचक/प्रतिरोध)
P. वामपंथी आलोचक
Q. दक्षिणपंथी आलोचक
R. सामाजिक आंदोलन
S. अर्थशास्त्री

सूची II: (चिंता/कार्य)
1. सांस्कृतिक प्रभावों की चिंता
2. पूंजीवाद और बढ़ती असमानता का विरोध
3. 'पुनःउपनिवेशीकरण' की संज्ञा
4. 'नीम' के पेटेंट का विरोध

(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-1, R-4, S-3
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

35. वैश्वीकरण के विरोधी आंदोलन भी विश्वव्यापी नेटवर्क में भागीदारी क्यों करते हैं?
(A) क्योंकि वे मूल रूप से वैश्वीकरण की आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं का समर्थन करते हैं।
(B) क्योंकि उन्हें विभिन्न प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भारी मात्रा में वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।
(C) क्योंकि वे समान विचारधारा रखने वाले अन्य देशों के लोगों के साथ एकजुट होना चाहते हैं।
(D) क्योंकि वे अपने गृह देशों में पूर्णतः प्रतिबंधित हैं और बाहर से कार्य करना चाहते हैं।

36. नीचे दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) पर consider करें:
अभिकथन (A): कुछ मायनों में वैश्वीकरण के फलस्वरुप राज्य की ताकत में इज़ाफा हुआ है।
कारण (R): अब राज्यों के हाथ में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है जिसके बूते राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएँ जुटा सकते हैं और ज़्यादा कारगर ढंग से काम कर सकते हैं।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

को नुकसान पहुँचाना स्वयं को नुकसान पहुँचाने के समान है। यह समग्र दृष्टिकोण यह सिखाता है कि सामाजिक और पारिस्थितिक कल्याण एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस समझ के कारण ही वे संसाधनों का उपयोग इस तरह करते हैं कि प्रकृति का चक्र कभी प्रभावित न हो और संतुलन बना रहे।

165. (A) पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण पारंपरिक ज्ञान की हानि।
जब 'किला संरक्षण' के नाम पर स्थानीय समुदायों को बेदखल किया जाता है, तो उनके साथ वह ज्ञान भी लुप्त हो जाता है जो उन्होंने हज़ारों वर्षों में अर्जित किया था। पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान के बिना, वैज्ञानिक अक्सर यह समझने में विफल रहते हैं कि स्थानीय प्रजातियाँ कैसे व्यवहार करती हैं या जंगल को कैसे स्वस्थ रखा जाए। इस ज्ञान की कमी से अंततः संरक्षण के उद्देश्य ही विफल हो सकते हैं, क्योंकि मानव और प्रकृति का सदियों पुराना सहजीवी संबंध हमेशा के लिए टूट जाता है।

166. (B) अंटार्कटिका महाद्वीप।
'वैश्विक साझा संसाधन' वे क्षेत्र होते हैं जो किसी भी देश की भौगोलिक सीमाओं या संप्रभुता के अंतर्गत नहीं आते। अंटार्कटिका इसका एक सटीक उदाहरण है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत वैज्ञानिक अनुसंधान और शांतिपूर्ण कार्यों के लिए पूरी तरह खुला है। इसी तरह उच्च समुद्र, बाहरी अंतरिक्ष और पृथ्वी का वायुमंडल भी इसी श्रेणी में आते हैं। इन संसाधनों का स्वामित्व किसी एक देश का न होकर पूरी मानवता का माना जाता है, जिससे इनका प्रबंधन वैश्विक स्तर पर चुनौतीपूर्ण होता है।

167. (B) व्यक्तिगत, अल्पकालिक लाभ और सामूहिक, दीर्घकालिक हानि के बीच का संघर्ष।
'साझा की त्रासदी' एक ऐसी स्थिति को दर्शाती है जहाँ साझा संसाधनों का उपयोग करने वाले व्यक्ति या राष्ट्र केवल अपने तात्कालिक मुनाफे के बारे में सोचते हैं। यदि हर कोई अपने लाभ के लिए संसाधन का अत्यधिक दोहन करता है, तो वह संसाधन जल्दी ही समाप्त हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि अंत में सभी को नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि वह साझा संपत्ति नष्ट हो चुकी होती है। यह सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि सामूहिक जिम्मेदारी के बिना व्यक्तिगत लालच संसाधनों का विनाश कर देता है।

168. (A) उपयोग को विनियमित करने के लिए एक प्रभावी केंद्रीय शासन तंत्र का अभाव।
वैश्विक साझा संसाधनों की सुरक्षा में सबसे बड़ी बाधा यह है कि दुनिया में ऐसी कोई शक्तिशाली केंद्रीय सरकार नहीं है जो सभी देशों को नियमों का पालन करने के लिए बाध्य कर सके। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ होती हैं, लेकिन वे अक्सर कमजोर प्रवर्तन और देशों के बीच आपसी सहमति की कमी के कारण विफल हो जाती हैं। जब तक कोई वैश्विक नियामक ढांचा नहीं होगा जो उल्लंघन करने वालों को दंडित कर सके, तब तक इन संसाधनों का अनियंत्रित दोहन जारी रहने की संभावना बनी रहती है।

169. (C) क्योंकि वे किसी एक राष्ट्र के संप्रभु अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं।
चूँकि वैश्विक साझा संसाधनों पर किसी विशेष देश का विशेष अधिकार नहीं होता, इसलिए कोई भी राष्ट्र अकेले उनकी सुरक्षा या निगरानी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। इस 'खुलेपन' के कारण कोई भी देश इन संसाधनों का अपनी इच्छा अनुसार उपयोग करने के लिए स्वतंत्र महसूस करता है। संप्रभु नियंत्रण के अभाव में, इन क्षेत्रों में प्रदूषण फैलाना या मछलियों का शिकार करना आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ राष्ट्रीय कानूनों का प्रभाव नहीं होता और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी अक्सर अपर्याप्त साबित होती है।

170. (D) मत्स्य भंडार का क्षय हो जाएगा, जिससे सभी को नुकसान होगा।
यदि सभी देश अपनी आर्थिक लाभ के लिए अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में मछली पकड़ने की कोई सीमा तय नहीं करते हैं, तो मछलियों की आबादी के पुनरुत्पादन की दर कम हो जाएगी। समय के साथ समुद्र पूरी तरह से मछलियों से खाली हो सकता है, जिससे पूरी दुनिया की खाद्य सुरक्षा और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र संकट में पड़ जाएगा। यह 'साझा की त्रासदी' का एक व्यावहारिक परिणाम है जहाँ अल्पकालिक आर्थिक होड़ अंततः एक स्थायी पारिस्थितिक और आर्थिक आपदा की ओर ले जाती है।

171. (C) पहली बार पर्यावरण को एक गंभीर वैश्विक मुद्दे के रूप में स्थापित किया।
1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन वैश्विक पर्यावरण राजनीति का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इससे पहले, पर्यावरण संबंधी चिंताओं को मुख्य रूप से स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाता था। इस सम्मेलन ने विश्व के नेताओं को एक साझा मंच पर लाकर यह स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया कि प्रदूषण और पारिस्थितिक क्षरण जैसी समस्याएँ सीमाओं को नहीं मानतीं। इसी ऐतिहासिक आयोजन ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के गठन और भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौतों की नींव रखी थी।

172. (B) विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एकीकरण पर।
सतत विकास की अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि आर्थिक प्रगति और प्रकृति का संरक्षण एक-दूसरे के विरोधी नहीं होने चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को इस तरह पूरा करना है कि आने वाली पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता के साथ कोई समझौता न हो। यह सिद्धांत संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग, सामाजिक न्याय और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को विकास की मुख्यधारा की योजनाओं में शामिल करने की वकालत करता है ताकि लंबे समय तक समृद्धि बनी रहे।

173. (D) उन्होंने जागरूकता बढ़ाकर और सरकारों पर दबाव बनाकर एक केंद्रीय भूमिका निभाई है।
वैश्विक पर्यावरण शासन में गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) ने नागरिक समाज की आवाज़ के रूप में कार्य किया है। ये संगठन केवल जमीनी स्तर पर काम नहीं करते, बल्कि वे जटिल

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3 और 4
(C) केवल 1, 2 और 4
(D) केवल 2, 3 और 4

9. भारत ने 1991 में आर्थिक सुधारों की योजना क्यों शुरू की?
(A) गंभीर राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक असंतोष की स्थितियों से प्रभावी ढंग से उबरने के लिए।
(B) पुरानी आर्थिक संरक्षणवाद की नीति को देश में और अधिक दृढ़ता के साथ मजबूत करने के लिए।
(C) वित्तीय संकट से निपटने और आर्थिक वृद्धि की ऊँची दर को प्राप्त करने के उद्देश्य से।
(D) अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पश्चिमी और विकसित देशों के निरंतर बढ़ते हुए दबाव के कारण।

10. वैश्वीकरण का प्रतिरोध करने वाले वामपंथी राजनीतिक रुझान के आलोचकों का मुख्य तर्क क्या है?
(A) यह पूंजीवाद की वह अवस्था है जो समाज में आर्थिक असमानता और गरीबी को अत्यधिक बढ़ाती है।
(B) यह प्रक्रिया राष्ट्र की परंपरागत विशिष्ट संस्कृति और स्थानीय पहचान को भारी क्षति पहुँचाती है।
(C) यह प्रक्रिया मुख्य रूप से राज्य की शक्ति और उसकी निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करती है।
(D) यह प्रक्रिया वैश्विक स्तर पर विभिन्न समाजों के मध्य पूर्ण सांस्कृतिक समरूपता स्थापित करती है।

11. निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. भारत द्वारा आर्थिक सुधारों को अपनाना।
2. विश्व सामाजिक मंच (WSF) की पहली बैठक।
3. सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री-स्तरीय बैठक के विरुद्ध प्रदर्शन।
4. मुंबई में विश्व सामाजिक मंच की चौथी बैठक।
उपरोक्त में से कौन-सा क्रम सही है?
(A) 1, 3, 2, 4
(B) 3, 1, 2, 4
(C) 1, 2, 3, 4
(D) 2, 3, 1, 4

12. सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण की प्रक्रिया का क्या परिणाम होता है?
(A) संपूर्ण विश्व में एक समान वैश्विक संस्कृति का उदय होता है।
(B) इसके कारण प्रत्येक संस्कृति और अधिक विशिष्ट तथा पृथक होती जाती है।
(C) विश्व की सभी विविध संस्कृतियाँ अनिवार्य रूप से एक जैसी हो जाती हैं।
(D) वैश्विक स्तर पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभुत्व पूरी तरह समाप्त हो जाता है।

13. 'विश्व सामाजिक मंच' (WSF) क्या है?
(A) एक प्रभुत्वशाली विश्व-व्यापी अंतर-सरकारी व्यापारिक संगठन।
(B) नव-उदारवादी वैश्वीकरण की नीतियों का पूर्ण समर्थन करने वाला एक मंच।
(C) नव-उदारवादी वैश्वीकरण की नीतियों का विरोध करने वाला एक वैश्विक मंच।
(D) संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन कार्य करने वाली एक विशेष और स्वायत्त एजेंसी।

14. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है?
(A) पुनःउपनिवेशीकरण - सांस्कृतिक प्रभावों का समर्थन
(B) सामाजिक सुरक्षा कवच - अमीरों को लाभ पहुँचाना
(C) न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य - लोक-कल्याणकारी कामों में वृद्धि
(D) संरक्षणवाद - आयात पर प्रतिबंध लगाना

15. वैश्वीकरण के संबंध में 'प्रवाह' में क्या शामिल नहीं है?
(A) राष्ट्रों की सीमाओं का स्थायीकरण।
(B) विचारों का एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुँचना।
(C) पूँजी का एक से ज़्यादा जगहों पर जाना।
(D) वस्तुओं का कई-कई देशों में पहुँचना।

16. नीचे दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार करें:
अभिकथन (A): वैश्वीकरण के चलते विचारों के सामने राष्ट्र की सीमाओं की बाधा नहीं रही और उनका प्रवाह अबाध हो उठा है।
कारण (R): इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं का विस्तार इसका एक उदाहरण है।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

17. भारत में वैश्वीकरण का विरोध दक्षिणपंथी खेमों द्वारा क्यों किया जा रहा है?
(A) देश के भीतर निरंतर बढ़ती हुई आर्थिक असमानता और गरीबी की चिंताओं के कारण।
(B) केबल नेटवर्क और विदेशी त्योहारों जैसे विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों की चिंता के कारण।
(C) घरेलू बाज़ारों में विशाल बहुराष्ट्रीय निगमों के अनियंत्रित प्रवेश के विरोध में।
(D) अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण राष्ट्र-राज्य की शक्तियों के कमजोर होने के डर से।

18. वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. धनी देशों के निवेशकर्ता अपना धन विकासशील देशों में निवेश कर सकते हैं।
2. वस्तुओं और पूंजी के प्रवाह की तुलना में लोगों की

अध्याय 07
वैश्वीकरण

1. एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण की बुनियादी बात क्या है?
(A) अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष
(B) प्रवाह
(C) सांस्कृतिक अलगाव
(D) राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता

2. निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में सही है?
(A) वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है, जिससे विभिन्न समाजों पर इसके भिन्न-भिन्न परिणाम देखे गए हैं।
(B) वैश्वीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव विश्व के सभी समाजों और संस्कृतियों पर पूरी तरह एक समान रहा है।
(C) वैश्वीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया और इसके व्यापक परिणाम केवल सीमित आर्थिक क्षेत्रों तक ही सीमित हैं।
(D) वैश्वीकरण की ऐतिहासिक प्रक्रियाओं ने अब तक केवल विश्व के आर्थिक रूप से धनी देशों को ही प्रभावित किया है।

3. निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए:
सूची I: (अवधारणा)
P. जनार्दन का उदाहरण
Q. रामधारी का उदाहरण
R. सारिका का उदाहरण
S. किसानों की आत्महत्या
सूची II: (वैश्वीकरण का पहलू)
1. वस्तुओं की आवाजाही
2. सेवाओं का वैश्वीकरण
3. नए अवसर और मूल्य दुविधा
4. बहुराष्ट्रीय कंपनी के महंगे बीज
(A) P-2, Q-1, R-3, S-4
(B) P-1, Q-2, R-4, S-3
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

4. वैश्वीकरण के कारणों के संदर्भ में, प्रौद्योगिकी को एक अपरिहार्य कारण क्यों माना जाता है?
(A) क्योंकि इसने वर्तमान में केवल विकसित देशों के मध्य ही संचार को प्रभावी रूप से सुगम बनाया है।
(B) क्योंकि इसने केवल विश्वव्यापी पूंजी के प्रवाह को गति दी है, लेकिन विचारों और लोगों को नहीं।
(C) क्योंकि यह आधुनिक विश्व में राष्ट्रवाद की प्रबल भावना को पूरी तरह समाप्त करने में विफल रहा है।
(D) क्योंकि इसने विभिन्न आविष्कारों द्वारा विश्व के भिन्न भागों के मध्य संचार में क्रांति ला दी है।

5. नीचे दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार करें:
अभिकथन (A): वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता में कमी आई है।
कारण (R): पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की धारणा अब पुरानी पड़ गई है और इसकी जगह न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले ली है।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

6. आर्थिक वैश्वीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(A) इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।
(B) विकसित देश अपनी वीज़ा-नीति के ज़रिए लोगों की आवाजाही को सुगम बनाते हैं।
(C) इसके चलते पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में इजाफा हुआ है।
(D) धनी देश के निवेशकर्ता विकासशील देशों में अपना धन निवेश कर सकते हैं।

7. 'मैक्डोनॉल्डीकरण' की अवधारणा का क्या अर्थ है?
(A) विश्व में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।
(B) अंतर्राष्ट्रीय खाद्य श्रृंखलाओं का विस्तार।
(C) स्थानीय भोजन की आदतों को बढ़ावा देना।
(D) विभिन्न संस्कृतियों का प्रभुत्वशाली अमरीकी ढर्रे पर ढलना।

8. वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसके कारण राज्य की क्षमता में कमी आई है।
2. कल्याणकारी राज्य की जगह बाज़ार आर्थिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक बन गया है।
3. बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका में कमी आई है।
4. राज्यों के हाथ में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आने से उनकी ताकत में इज़ाफ़ा हुआ है।
उपरोक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही हैं?

155. (C) समता और न्याय।
'साझी परंतु विभेदित जिम्मेदारियाँ' का सिद्धांत केवल एक कानूनी ढांचा नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर समता और न्याय के नैतिक आदर्शों को बढ़ावा देता है। यह सुनिश्चित करता है कि पर्यावरण संरक्षण का बोझ सभी पर थोपने के बजाय उन पर अधिक डाला जाए जो इसके लिए अधिक जिम्मेदार हैं। यह दृष्टिकोण वैश्विक संबंधों में निष्पक्षता लाता है और विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा करते हुए सामूहिक पर्यावरणीय कार्रवाई को संभव बनाता है।

156. (B) जल प्रवाह पर असंतुलित नियंत्रण और उसका उपयोग।
नदी के ऊपरी हिस्से पर स्थित देशों द्वारा जल संसाधनों पर अधिक नियंत्रण रखने और निचले देशों की आवश्यकताओं की उपेक्षा करने से अक्सर द्विपक्षीय विवाद उत्पन्न होते हैं। जब ऊपरी तटीय देश अपनी जरूरतों के लिए जल का एकतरफा उपयोग करते हैं, तो निचले देशों के लिए पानी की मात्रा कम हो जाती है। यह भौगोलिक स्थिति जल वितरण में असंतुलन पैदा करती है, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में तनाव और संघर्ष का एक प्रमुख कारण बन जाती है।

157. (D) जल की कमी और प्रदूषण।
निचले तटीय देश भौगोलिक रूप से नदी के अंतिम प्रवाह पर निर्भर होते हैं, जिससे वे ऊपरी देशों की गतिविधियों के प्रति संवेदनशील बन जाते हैं। यदि ऊपरी देश पानी का मार्ग बदलते हैं या औद्योगिक कचरा नदी में छोड़ते हैं, तो निचले देशों को पानी की गंभीर किल्लत और गुणवत्ता में गिरावट झेलनी पड़ती है। इससे वहां की कृषि, पारिस्थितिकी और आम जनता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो अंततः राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट बन जाता है।

158. (A) एक मजबूत प्रवर्तन तंत्र का अभाव है।
यद्यपि 1997 के संयुक्त राष्ट्र जलमार्ग समझौते जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय कानून मौजूद हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमी उन्हें अनिवार्य रूप से लागू करने वाली किसी वैश्विक संस्था की अनुपस्थिति है। संधियाँ अक्सर देशों की स्वेच्छा और आपसी सहयोग पर टिकी होती हैं। यदि कोई देश नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे दंडित करने के लिए कोई प्रभावी शक्ति नहीं है। यही कारण है कि जल विवादों का समाधान कानूनी रूप से कम और राजनीतिक समझौतों पर अधिक निर्भर करता है।

159. (C) नदी पर एक बड़े बांध का निर्माण करना।
ऊपरी तटीय देशों द्वारा नदियों पर बांध बनाना निचले देशों के लिए अत्यंत चिंता का विषय होता है क्योंकि इससे पानी का प्राकृतिक प्रवाह और समय बाधित हो जाता है। बांधों के माध्यम से पानी का भंडारण या उसकी दिशा मोड़ने से निचले क्षेत्रों में सूखे या अप्रत्याशित बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। यह हस्तक्षेप न केवल आर्थिक नुकसान पहुँचाता है, बल्कि संप्रभुता और जल अधिकारों को लेकर देशों के बीच गहरे राजनीतिक अविश्वास और शत्रुता को जन्म देता है।

160. (A) संबंधित देशों के बीच राजनीतिक इच्छाशक्ति और आपसी विश्वास पर।
सीमा-पारीय जल विवादों का स्थायी समाधान केवल तकनीकी डेटा या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए नेतृत्व के स्तर पर मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है। जब तक राष्ट्र एक-दूसरे पर भरोसा नहीं करते और साझा हितों के लिए समझौता करने को तैयार नहीं होते, तब तक कोई भी संधि सफल नहीं हो सकती। आपसी विश्वास और द्विपक्षीय सहयोग ही वह आधार हैं जिनसे जल संसाधनों का न्यायसंगत और शांतिपूर्ण प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकता है।

161. (D) पीढ़ियों से संचित स्थानीय पारिस्थितिक तंत्रों का गहन ज्ञान।
पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान (TEK) स्वदेशी समुदायों द्वारा अपने प्राकृतिक परिवेश के साथ सदियों तक रहने और प्रयोग करने के बाद विकसित किया गया एक मूल्यवान ज्ञान भंडार है। यह ज्ञान केवल किताबी नहीं, बल्कि अनुभव आधारित होता है और इसमें स्थानीय वनस्पति, जीव-जंतुओं और जलवायु परिवर्तनों की गहरी समझ शामिल होती है। यह पीढ़ी-दर-पीढ़ी मौखिक या व्यावहारिक रूप से हस्तांतरित होता है और टिकाऊ जीवन शैली जीने तथा जैव विविधता को बनाए रखने में अत्यंत सहायक सिद्ध होता है।

162. (B) यह उन्हें उनकी पारंपरिक भूमि से अक्सर विस्थापित कर देता है।
'किला संरक्षण' मॉडल इस धारणा पर काम करता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए मानवीय हस्तक्षेप को पूरी तरह समाप्त करना आवश्यक है। इसके तहत जंगलों को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, जिससे वहाँ रहने वाले स्वदेशी समुदायों को उनके पूर्वजों की भूमि से जबरन बेदखल होना पड़ता है। यह विस्थापन न केवल उनकी संस्कृति और जीविका को नष्ट करता है, बल्कि उन्हें अपने ही घर में अजनबी बना देता है, जिससे उनके बुनियादी मानवाधिकारों का हनन होता है।

163. (C) क्योंकि यह उनके पारंपरिक ज्ञान के उपयोग को सक्षम बनाता है जो संरक्षण में मदद करता है।
स्वदेशी भूमि अधिकारों को मान्यता देना पर्यावरण संरक्षण के लिए एक वैज्ञानिक रणनीति है क्योंकि ये समुदाय प्रकृति के सर्वोत्तम संरक्षक होते हैं। जब उन्हें अपनी भूमि पर अधिकार मिलता है, तो वे अपने सदियों पुराने ज्ञान का उपयोग पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कर सकते हैं। उनका दृष्टिकोण केवल संसाधनों के उपभोग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे भूमि की रक्षा को अपना आध्यात्मिक कर्तव्य मानते हैं, जो आधुनिक संरक्षण प्रयासों को एक नई दिशा देता है।

164. (D) मानव और प्रकृति को अविभाज्य और परस्पर जुड़ा हुआ मानता है।
स्वदेशी समुदायों का विश्वदृष्टिकोण पश्चिमी 'मानव बनाम प्रकृति' के द्वंद्व को नकारता है और यह मानता है कि मनुष्य पर्यावरण का ही एक अभिन्न अंग है। उनकी दृष्टि में प्रकृति

आवाजाही अधिक बढ़ी है।
3. विकसित देश अपनी वीज़ा-नीति के ज़रिए अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाए रखते हैं।
4. इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं का विस्तार हुआ है।
5. विकासशील देशों ने आयात पर प्रतिबंध बढ़ा दिए हैं।

उपरोक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 1, 3 और 4
(C) केवल 2, 4 और 5
(D) केवल 1, 2, 4 और 5

19. "नीली जीन्स के ऊपर खादी का कुर्ता पहनना" किस सांस्कृतिक प्रक्रिया का उदाहरण है?
(A) सांस्कृतिक समरुपता
(B) सांस्कृतिक पश्चिमीकरण
(C) सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण या संकरण
(D) सांस्कृतिक अलगाव

20. सिएटल में 1999 में हुए विरोध प्रदर्शनों का मुख्य कारण क्या था?
(A) वैश्विक स्तर पर हो रहे तीव्र पर्यावरणीय क्षरण का सामूहिक रूप से विरोध करना।
(B) विकासशील देशों में प्रचलित बाल श्रम की कुप्रथा के खिलाफ कड़ा प्रदर्शन करना।
(C) पाश्चात्य संस्कृति के कारण आ रही सांस्कृतिक समरुपता के विरुद्ध व्यापक प्रदर्शन।
(D) शक्तिशाली देशों द्वारा व्यापार में अपनाए जा रहे अनुचित तौर-तरीकों का विरोध करना।

21. निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए:
सूची I: (घटना/अवधारणा)
P. WSF की पहली बैठक
Q. WSF की चौथी बैठक
R. आर्थिक सुधार
S. सिएटल विरोध

सूची II: (स्थान/वर्ष)
1. भारत (1991)
2. पोर्टो अलग्रेरे (2001)
3. मुंबई (2004)
4. अमेरिका (1999)

(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-3, R-1, S-4
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-4, Q-2, R-1, S-3

22. "सामाजिक सुरक्षा कवच" की अवधारणा का उद्देश्य क्या है?
(A) देश के सभी नागरिकों को पूर्णतः मुफ्त सरकारी आवास की सुविधा प्रदान करना।
(B) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर वैश्वीकरण के दुष्प्रभावों को सीमित करना।
(C) केवल सरकारी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को ही व्यापक सामाजिक सुरक्षा देना।
(D) वैश्विक स्तर पर कार्यरत बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करना।

23. वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन असत्य है?
(A) यह एक बहुआयामी अवधारणा है।
(B) यह सिर्फ आर्थिक परिघटना नहीं है।
(C) वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है।
(D) वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान अवधारणाएँ हैं।

24. स्वतंत्रता के बाद भारत ने 'संरक्षणवाद' की नीति क्यों अपनाई थी?
(A) विदेशी निर्भरता कम करने और स्थानीय उत्पादकों को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए।
(B) घरेलू समाज पर पड़ने वाले विदेशी संस्कृतियों के नकारात्मक प्रभाव को पूरी तरह रोकने के लिए।
(C) संपूर्ण विश्व के कुल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को तत्काल प्रभाव से बढ़ाने के लिए।
(D) प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संधियों में सक्रिय रूप से शामिल होने की इच्छा के कारण।

25. निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव नहीं है?
(A) राज्य की क्षमता में कमी।
(B) कल्याणकारी राज्य की धारणा का कमजोर पड़ना।
(C) 'मैक्डोनॉल्डीकरण' की प्रक्रिया का तीव्र होना।
(D) बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका का बढ़ना।

26. नीचे दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार करें:
अभिकथन (A): कुछ आलोचकों ने आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व का 'पुनःउपनिवेशीकरण' कहा है।
कारण (R): उनका मानना है कि इसके कारण गरीब देश आर्थिक रूप से बर्बादी की कगार पर पहुँच जाएँगे और उनके गरीब लोग एकदम बदहाल हो जाएँगे।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

27. वैश्वीकरण के समर्थकों का तर्क है कि इससे समृद्धि बढ़ती है। इसका मुख्य कारण क्या है?
(A) इसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों का बाज़ारों पर नियंत्रण बढ़ता है।
(B) बढ़ते व्यापार के कारण प्रत्येक देश को अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का अवसर मिलता है।
(C) इसके माध्यम से वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक अलगाव को विशेष बढ़ावा प्राप्त होता है।
(D) इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक देश को अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का अवसर मिलता है।

वैज्ञानिक शोधों को सरल भाषा में जनता तक पहुँचाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सरकारों को उनकी जवाबदेही याद दिलाते हैं। वे अक्सर पर्यावरण के प्रति संवेदनशील नीतियों के निर्माण के लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं और प्रदूषणकारी गतिविधियों के खिलाफ कानूनी और नैतिक दबाव बनाकर परिवर्तन सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं।

174. (A) यह अधिक संस्थागत, बहुआयामी और जटिल हो गया है।
पिछले कुछ दशकों में, वैश्विक पर्यावरण शासन केवल सरकारों के बीच के समझौतों तक सीमित नहीं रहा है। अब इसमें वैज्ञानिक परिषदों, व्यापारिक समूहों, स्वदेशी समुदायों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सक्रिय भागीदारी शामिल है। जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता जैसे मुद्दों की प्रकृति ही इतनी व्यापक है कि इनके प्रबंधन के लिए अब विविध प्रकार की कानूनी संधियों और तकनीकी ढांचों की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया धीरे-धीरे एक अत्यंत जटिल और अंतर्संबंधित वैश्विक व्यवस्था के रूप में विकसित हुई है।

175. (C) सतत विकास।
1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन को 'सतत विकास' की अवधारणा को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाने और उसे लागू करने के लिए जाना जाता है। इस सम्मेलन ने एजेंडा 21 जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को आर्थिक विकास की हर योजना का अभिन्न हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। रियो ने यह स्पष्ट किया कि भविष्य का विकास केवल तभी सफल हो सकता है जब वह पारिस्थितिक सीमाओं के भीतर हो। यहीं से जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचों की शुरुआत हुई थी।

(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

37. एक भारतीय कंपनी द्वारा यूरोप स्थित एक बड़ी प्रतियोगी कंपनी को खरीदना, वैश्वीकरण के किस पहलू को दर्शाता है?
(A) यह वैश्विक स्तर पर बढ़ रही पूर्ण सांस्कृतिक समरूपता का एक स्पष्ट और बड़ा उदाहरण है।
(B) यह प्रक्रिया केवल राष्ट्रीय सरकारों के राजनीतिक प्रभाव और उनकी शक्ति को प्रदर्शित करती है।
(C) यह दर्शाता है कि वैश्वीकरण का प्रवाह सदैव केवल धनी मुल्कों से गरीब मुल्कों की ओर नहीं होता।
(D) यह वैश्विक स्तर पर वैश्वीकरण के प्रति बढ़ रहे तीव्र प्रतिरोध का एक प्रमुख उदाहरण है।

38. वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. वैश्वीकरण हर अर्थ में सकारात्मक ही होता है।
2. ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है जो मानते हैं कि इसके सकारात्मक प्रभाव कम और नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा हैं।
3. वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक मसलों से जुड़ा है।
4. प्रभाव की दिशा हमेशा धनी मुल्कों से गरीब मुल्कों की ओर गतिशील होती है।
5. वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव हो सकते हैं।

उपरोक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2 और 5
(C) केवल 1, 3 और 4
(D) केवल 2, 4 और 5

39. 'न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य' का क्या अर्थ है?
(A) एक ऐसा राज्य जो देश की अर्थव्यवस्था और समाज के प्रत्येक छोटे-बड़े पहलू को पूर्णतः नियंत्रित करता है।
(B) एक लोक-कल्याणकारी राज्य जो सामाजिक कल्याण और विकास की योजनाओं पर अत्यधिक धन व्यय करता है।
(C) एक ऐसा राज्य जिसकी अपनी कोई निश्चित अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं होती और वह पूर्णतः मुक्त होता है।
(D) एक राज्य जो स्वयं को केवल कानून-व्यवस्था और सुरक्षा जैसे अनिवार्य कार्यों तक सीमित रखता है।

40. भारत में औद्योगिक श्रमिक और किसानों के संगठनों ने किसका विरोध किया है?
(A) बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश का।
(B) सांस्कृतिक पश्चिमीकरण का।
(C) नई प्रौद्योगिकी के उपयोग का।
(D) संरक्षणवाद की नीति का।

41. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है?
(A) प्रवाह - विचारों, पूँजी, वस्तु और लोगों की आवाजाही
(B) प्रौद्योगिकी - संचार क्रांति का कारण
(C) विश्व सामाजिक मंच - नव-उडरवाद का समर्थक
(D) संरक्षणवाद - घरेलू उत्पादकों की रक्षा

42. वैश्वीकरण के चलते, प्रवाह की गति के संबंध में क्या सत्य है?
(A) पूँजी और वस्तु की गतिशीलता, लोगों की आवाजाही की तुलना में अधिक तीव्र और व्यापक है।
(B) आधुनिक विश्व में पूँजी, वस्तु और लोगों की आवाजाही की गति पूरी तरह समान है।
(C) लोगों की अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही की गति, पूँजी और वस्तु की तुलना में अत्यधिक तीव्र है।
(D) विचारों का वैश्विक प्रवाह सदैव पूँजी और वस्तुओं के भौतिक प्रवाह की तुलना में धीमा रहता है।

43. 'कोमिन्टर्न जैसा संगठन बनाना खतरनाक होगा' यह विचार विश्व सामाजिक मंच के किस पहलू को दर्शाता है?
(A) संगठन में एकता की कमी को।
(B) नवउडरवाद के प्रति समर्थन को।
(C) पूंजीवाद को खत्म करने की इच्छा को।
(D) किसी एक केंद्रीय सत्ता के निर्माण के प्रति आशंका को।

44. निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए:
सूची I: (अवधारणा/वस्तु)
P. बार्बी डॉल
Q. खादी का कुर्ता
R. कॉल सेंटर
S. चीनी साइकिल

सूची II: (संबंधित देश/प्रक्रिया)
1. भारत (परंपरागत)
2. चीन (विनिर्माण)
3. संयुक्त राज्य अमरीका (उत्पाद)
4. सेवा का वैश्वीकरण

(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

45. वैश्वीकरण के संदर्भ में 'विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव' का क्या महत्व है?
(A) यह प्रक्रिया विभिन्न संप्रभु राष्ट्रों के मध्य की दूरियों को और अधिक बढ़ाती है।
(B) यह शब्दावली केवल व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को ही संदर्भित करती है।
(C) यह प्रवाहों की निरंतरता से उत्पन्न होता है और उन्हें निरंतर बनाए रखता है।
(D) यह प्रक्रिया वैश्विक स्तर पर मौजूद सभी सांस्कृतिक भिन्नताओं को पूर्णतः समाप्त करती है।

46. वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह केवल एक आर्थिक परिघटना है।
2. यह एक बहुआयामी अवधारणा है जिसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवतार हैं।
3. इसका प्रभाव सभी समाजों पर एक समान रहा है।
4. इसका प्रभाव विषम रहा है, जो समाज के एक हिस्से को दूसरे से अधिक प्रभावित करता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2 और 4
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) केवल 2, 3 और 4

47. नीचे दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार करें:
अभिकथन (A): वैश्वीकरण से सांस्कृतिक समरूपता और सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण दोनों प्रक्रियाएं उत्पन्न हुई हैं।
कारण (R): वैश्वीकरण के प्रभाव एकतरफा नहीं होते, यह जहाँ एक ओर पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव को बढ़ाता है वहीं दूसरी ओर स्थानीय संस्कृतियों को और अधिक विशिष्ट बनाता है।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

48. भारत के अनुभव के संदर्भ में, संरक्षणवाद की नीति की क्या एक प्रमुख खामी थी?
(A) इस नीति के लागू होने से देश में आर्थिक वृद्धि की दर अत्यधिक तेज हो गई थी।
(B) स्वास्थ्य, आवास और प्राथमिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।
(C) भारतीय उत्पादक इस नीति के कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में बहुत आगे निकल गए।
(D) इसके परिणामस्वरूप देश में विदेशी निवेश की मात्रा में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई।

49. निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण के प्रतिरोध का हिस्सा नहीं है?
(A) इंडियन सोशल फोरम द्वारा विरोध।
(B) 1991 में आर्थिक सुधारों को लागू करना।
(C) किसानों के संगठनों द्वारा बहुराष्ट्रीय निगमों का विरोध।
(D) 'नीम' के पेटेंट का विरोध।

50. समकालीन वैश्वीकरण और पहले के दौर के वैश्वीकरण में मुख्य अंतर क्या है?
(A) प्रवाहों की गति और उनके प्रसार का धरातल
(B) वैश्विक स्तर पर होने वाले प्रवाह के विविध प्रकार
(C) वैश्विक स्तर पर होने वाले प्रवाह की निश्चित दिशा
(D) इसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी की कोई विशेष भूमिका नहीं है

51. निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. विश्व सामाजिक मंच की चौथी बैठक मुंबई में
2. विश्व सामाजिक मंच की पहली बैठक पोर्टो अलगेरे में
3. विश्व व्यापार संगठन की सिएटल में बैठक
4. विश्व सामाजिक मंच की नेपाल में बैठक

उपरोक्त में से कौन-सा क्रम सही है?
(A) 3, 2, 1, 4
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 3, 1, 4
(D) 3, 1, 2, 4

52. आर्थिक वैश्वीकरण की प्रक्रिया में, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अलावा और कौन से खिलाड़ी शामिल हैं?
(A) केवल विभिन्न देशों की संप्रभु राष्ट्रीय सरकारें।
(B) केवल बड़ी और शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय निगम।
(C) केवल वैश्विक स्तर पर कार्यरत गैर-सरकारी संगठन।
(D) बहुराष्ट्रीय निगम, विभिन्न निवेशक, और विश्वभर के उपभोक्ता।

53. वैश्वीकरण के आलोचकों का यह तर्क कि 'इससे गरीब देश आर्थिक रुप से बर्बादी की कगार पर पहुँच जाएँगे', किस अवधारणा से संबंधित है?
(A) सांस्कृतिक समरूपता
(B) सामाजिक सुरक्षा कवच
(C) पुनःउपनिवेशीकरण
(D) न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य

54. भारत और वैश्वीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. औपनिवेशिक दौर में भारत आधारभूत वस्तुओं और कच्चे माल का निर्यातक था।
2. आजादी के बाद भारत ने संरक्षणवाद की नीति अपनाई।
3. 1991 में वित्तीय संकट से उबरने के लिए आर्थिक सुधार शुरु किए गए।
4. आर्थिक सुधारों का एकमात्र उद्देश्य व्यापार और विदेशी निवेश पर से बाधाएं हटाना था।
5. भारत में वैश्वीकरण का कोई प्रतिरोध नहीं हुआ है।

उपरोक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 2, 3 और 4
(C) केवल 1, 3, 4 और 5
(D) उपरोक्त सभी

55. पश्चिमी परिधान पहनने वाली कॉलेज की छात्राओं को एक उग्रवादी संगठन द्वारा धमकी देना, वैश्वीकरण के किस प्रकार के प्रभाव और प्रतिरोध का उदाहरण है?
(A) वैश्वीकरण के शुद्ध आर्थिक प्रभाव का एक प्रमुख हिस्सा।
(B) विभिन्न राष्ट्रों पर पड़ने वाले राजनीतिक प्रभाव का उदाहरण।
(C) वैश्विक पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव का

रूप।
(D) सांस्कृतिक प्रभाव और उसके दक्षिणपंथी प्रतिरोध का उदाहरण।

56. नीचे दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार करें:
अभिकथन (A): वैश्वीकरण ने राज्य की प्रधानता को राजनीतिक समुदाय के आधार के रूप में चुनौती नहीं दी है।
कारण (R): राज्य अभी भी कानून और व्यवस्था तथा राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अपने अनिवार्य कार्यों को पूरा कर रहे हैं और महत्त्वपूर्ण बने हुए हैं।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

57. एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से बड़े महंगे बीज खरीदने के कारण कुछ किसानों द्वारा आत्महत्या करना, वैश्वीकरण के किस प्रभाव को इंगित करता है?
(A) सकारात्मक सांस्कृतिक प्रभाव
(B) सकारात्मक राजनीतिक प्रभाव
(C) नकारात्मक आर्थिक प्रभाव
(D) तटस्थ पर्यावरणीय प्रभाव

58. निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए:
सूची I: (प्रभाव)
P. राजनीतिक प्रभाव
Q. आर्थिक प्रभाव
R. सांस्कृतिक प्रभाव
S. प्रौद्योगिकी प्रभाव
सूची II: (उदाहरण/परिणाम)
1. 'मैक्डोनॉल्डीकरण'
2. कल्याणकारी राज्य का क्षरण
3. संचार क्रांति
4. वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि
(A) P-1, Q-3, R-2, S-4
(B) P-2, Q-4, R-1, S-3
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-4, Q-2, R-3, S-1

59. विश्व सामाजिक मंच (WSF) के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है?
(A) यह नव-उदरवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्व-व्यापी मंच है।
(B) इसकी पहली बैठक 2001 में ब्राजील के पोर्टो अलगेरे में हुई।
(C) इसकी चौथी बैठक 2004 में मुंबई में हुई थी।
(D) यह साम्राज्यवाद का एक रूप माना जाता है।

60. 'सांस्कृतिक समरुपता' की अवधारणा का क्या आशय है?
(A) विभिन्न संस्कृतियों का एक-दूसरे पर सकारात्मक प्रभाव डालना।
(B) विश्व-संस्कृति के नाम पर पश्चिमी संस्कृति का थोपा जाना।
(C) प्रत्येक संस्कृति का स्थानीय स्तर पर और अधिक विशिष्ट हो जाना।
(D) परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों को आधुनिक समय में मजबूती प्रदान करना।

61. वैश्वीकरण के परिणामस्वरुप राज्य की भूमिका में हुए परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. राज्य अब केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने जैसे मुख्य कामों तक सीमित है।
2. लोक-कल्याणकारी कामों से हाथ खींचने से राज्य कमजोर हुआ है।
3. नई प्रौद्योगिकी के कारण नागरिकों पर नियंत्रण रखने की राज्य की क्षमता बढ़ी है।
4. राज्य पहले से ज़्यादा ताकतवर हुए हैं।
उपरोक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3 और 4
(C) केवल 1, 2, 3 और 4
(D) केवल 1 और 4

62. वैश्वीकरण के कारण वस्तुओं और पूंजी के प्रवाह की तुलना में लोगों की आवाजाही कम क्यों बढ़ी है?
(A) क्योंकि आधुनिक समय में अधिकांश लोग अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करना पसंद नहीं करते।
(B) क्योंकि वैश्विक स्तर पर लंबी दूरी की यात्रा करना अत्यधिक महंगा हो गया है।
(C) क्योंकि अधिकांश विकासशील देश अपने नागरिकों को बाहर जाने की अनुमति नहीं देते।
(D) क्योंकि विकसित देश वीज़ा-नीति के ज़रिए अपनी सीमाओं को अभेद्य रखते हैं।

63. 'पुनःउपनिवेशीकरण' शब्द का प्रयोग कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा किस संदर्भ में किया गया है?
(A) आर्थिक प्रभाव, जिससे गरीब देशों के और गरीब होने की आशंका है।
(B) वैश्वीकरण के पड़ने वाले विविध सांस्कृतिक प्रभावों के संदर्भ में।
(C) वैश्वीकरण के कारण उत्पन्न होने वाले राजनीतिक प्रभावों के संदर्भ में।
(D) वैश्वीकरण के माध्यम से होने वाले तीव्र प्रौद्योगिकी प्रभावों के संदर्भ में।

64. नीचे दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार करें:
अभिकथन (A): भारत में वैश्वीकरण का विरोध वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों खेमों से हुआ है।
कारण (R): वामपंथी दल आर्थिक परिणामों को लेकर चिंतित हैं, जबकि दक्षिणपंथी खेमा सांस्कृतिक प्रभावों को

लेकर चिंतित है।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

65. मुंबई के एक फिल्म-निर्माता पर हॉलीवुड फिल्म की कहानी उठाने का आरोप लगना, वैश्वीकरण के किस प्रभाव को दर्शाता है?
(A) अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में बढ़ती हुई आर्थिक प्रतिस्पर्धा की स्थिति को।
(B) विचारों के तीव्र प्रवाह और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की प्रक्रिया को।
(C) संप्रभु राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप को।
(D) विकासशील देशों में मौजूद गंभीर तकनीकी पिछड़ेपन की समस्या को।

66. निम्नलिखित में-से कौन-सा कथन वैश्वीकरण के बारे में सही है?
(A) वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है।
(B) वैश्वीकरण का संबंध वर्तमान में केवल भौतिक वस्तुओं की आवाजाही से है।
(C) वैश्वीकरण की प्रक्रिया में विभिन्न मूल्यों के मध्य कोई संघर्ष नहीं होता।
(D) वैश्वीकरण के एक प्रमुख अंग के रूप में सेवाओं का महत्त्व बहुत गौण है।

67. भारत में वैश्वीकरण के प्रतिरोध के रूपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. वामपंथी राजनीतिक दलों ने आर्थिक वैश्वीकरण का विरोध किया है।
2. इंडियन सोशल फोरम जैसे मंचों ने भी इसका विरोध किया है।
3. औद्योगिक श्रमिकों और किसानों के संगठनों ने बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश का विरोध किया है।
4. दक्षिणपंथी खेमों ने विदेशी टीवी चैनलों और वैलेन्टाईन-डे मनाने का विरोध किया है।
5. 'नीम' को पेटेंट कराने के प्रयासों का कोई विरोध नहीं हुआ।

उपरोक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 3, 4 और 5
(C) केवल 1, 2, 3 और 4
(D) उपरोक्त सभी

68. "क्या यह कुछ अच्छा भी हो सकता है? हम भी उतने ही भ्रमित हैं जितने की आप।" - विश्व सामाजिक मंच के संदर्भ में यह कथन क्या दर्शाता है?
(A) वैश्वीकरण के प्रति एक पूर्णतः निश्चित और एकीकृत दृष्टिकोण।
(B) वैश्विक स्तर पर नवउडरवादी नीतियों के लिए प्रदान किया गया पूर्ण समर्थन।
(C) वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था को पूरी तरह से और तत्काल खारिज करना।
(D) वैश्वीकरण के प्रति भ्रम, अनिश्चितता और विविध दृष्टिकोणों की उपस्थिति।

69. विश्व सामाजिक मंच (WSF) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विचार 'एक ओर दुनिया मुमकिन है' की भावना के विरुद्ध है?
(A) विकल्पों की खोज और निर्माण की प्रक्रिया बहुलता और विविधता भरी होगी।
(B) इसका संदर्भ गैर दलीय और गैर सरकारी होगा।
(C) कोमिन्टर्न जैसा संगठन बनाना जो समूचे आंदोलन का प्रवक्ता बने।
(D) सच्ची समाजवादी व्यवस्था केवल संघर्ष से लाई जा सकती है।

70. निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए:
सूची I: (प्रभाव का क्षेत्र)
P. राजनीतिक
Q. आर्थिक
R. सांस्कृतिक
S. सामाजिक

सूची II: (संबंधित अवधारणा/परिणाम)
1. व्यापार में वृद्धि
2. 'मैक्डोनॉल्डीकरण'
3. सामाजिक सुरक्षा कवच
4. राज्य की क्षमता में कमी

(A) P-4, Q-1, R-2, S-3
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-2, Q-3, R-4, S-1
(D) P-3, Q-4, R-1, S-2

71. निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के क्रम में व्यवस्थित करें:
1. टेलीग्राफ और टेलीफोन का आविष्कार।
2. छपाई (मुद्रण) तकनीक का आगमन।
3. माइक्रोचिप का नवीनतम आविष्कार।
4. इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं का विस्तार।

उपरोक्त में से कौन-सा क्रम सही है?
(A) 2, 1, 3, 4
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 3, 2, 1, 4
(D) 2, 3, 1, 4

72. वैश्वीकरण के कारण राज्य के कमजोर होने के तर्क के विपक्ष में क्या दलील दी जाती है?
(A) प्रौद्योगिकी के माध्यम से राज्य अधिक कारगर ढंग से

सूचनाएं जुटाकर कार्य कर सकते हैं।
(B) वर्तमान में बड़ी बहुराष्ट्रीय निगम अब संप्रभु राज्यों को नियंत्रित करते हैं।
(C) राज्य अब आधुनिक समय में लोक-कल्याण के कार्य बिल्कुल नहीं करते हैं।
(D) विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अब राष्ट्रीय सरकारों से अधिक शक्तिशाली हो गई हैं।

73. वैश्वीकरण-विरोधी आंदोलनों के बारे में क्या सत्य है?
(A) वे वैश्वीकरण की पूरी अवधारणा के पूर्णतः विरोधी हैं।
(B) वे आंदोलन वर्तमान में केवल अपने-अपने देशों की सीमाओं में ही सक्रिय हैं।
(C) वे वैश्वीकरण के किसी खास कार्यक्रम के विरोधी हैं जिसे वे साम्राज्यवाद मानते हैं।
(D) वे वैश्विक स्तर पर पश्चिमी संस्कृति का पूरी तरह से सक्रिय समर्थन करते हैं।

74. वैश्वीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. छपाई की तकनीक ने राष्ट्रवाद की आधारशिला रखी थी।
2. प्रौद्योगिकी का प्रभाव हमारे सोचने के तरीके पर पड़ता है।
3. पूँजी और वस्तु की गतिशीलता लोगों की आवाजाही से कम है।
4. बर्ड फ्लू या सुनामी जैसी घटनाएँ राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित रहती हैं।

उपरोक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3 और 4
(C) केवल 1, 2 और 4
(D) केवल 1, 2 और 3

75. नीचे दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार करें:
अभिकथन (A): वैश्वीकरण के आर्थिक पहलू को लेकर जनमत बड़ी गहराई से बँटा हुआ है।
कारण (R): समर्थकों का तर्क है कि इससे समृद्धि बढ़ती है, जबकि आलोचकों का तर्क है कि इससे आर्थिक असमानता बढ़ती है।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

76. "नवउडरवाद नई बोतल में पुरानी शराब है। यह पूँजीवाद का खतरनाक रूप है।" यह कथन वैश्वीकरण के प्रति किस दृष्टिकोण को दर्शाता है?
(A) एक पूर्णतः समर्थक दृष्टिकोण।
(B) एक आलोचनात्मक और वामपंथी दृष्टिकोण।
(C) एक संतुलित और तटस्थ दृष्टिकोण।
(D) एक दक्षिणपंथी सांस्कृतिक दृष्टिकोण।

77. मुंबई प्रतिरोध 2004 ने विश्व सामाजिक मंच का विरोध क्यों किया?
(A) क्योंकि WSF वैश्विक स्तर पर पूंजीवाद का पूर्ण समर्थन कर रहा था।
(B) क्योंकि WSF अपने कार्यक्रमों और नीतियों में बहुत अधिक जुझारू था।
(C) अलोकतांत्रिक तरीकों और साम्राज्यवादी देशों के धन पर निर्भरता को उजागर करने के लिए।
(D) क्योंकि WSF की बैठक का आयोजन पहली बार भारत में किया जा रहा था।

78. 'एन.जी.ओ. साम्राज्यवाद के दलाल हैं' यह आरोप किस विश्वास पर आधारित है?
(A) एन.जी.ओ. सामान्य जनता को विभिन्न विषयों पर एकदम सही जानकारी देते हैं।
(B) एन.जी.ओ. विभिन्न देशों के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों का सक्रिय रूप से समर्थन करते हैं।
(C) एन.जी.ओ. वर्तमान में पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और सेवाभावी होते हैं।
(D) एन.जी.ओ. संघर्ष को सुधारवाद की ओर मोड़कर पूंजीवादी व्यवस्था बनाए रखने में मदद करते हैं।

79. वैश्वीकरण के युग में सारिका का उदाहरण, जिसके सामने नए करियर अवसर हैं, क्या दर्शाता है?
(A) अवसरों के साथ परंपरागत मूल्यों और नई जीवन-शैली के बीच दुविधा।
(B) केवल आधुनिक आर्थिक अवसरों का व्यापक विस्तार।
(C) परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों का पूर्ण और स्वेच्छा से रूप से त्याग।
(D) वैश्वीकरण के कारण महिलाओं के लिए अवसरों में भारी कमी।

80. निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए:
सूची I: (घटना/प्रदर्शन का संदर्भ)
P. न्यूयार्क में प्रदर्शन
Q. हांगकांग में प्रदर्शन
R. जैकेट पर संदेश
S. जर्मनी में कलाकार

सूची II: (अंतर्निहित संदेश/संदर्भ)
1. बेगानेपन की स्थिति
2. संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के सामने गरीबी के विरुद्ध प्रदर्शन
3. विश्व व्यापार संगठन की बैठक का विरोध
4. पारंपरिक वेशभूषा में संस्कृति का 'प्रस्तुतीकरण'

(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-1, R-4, S-2
(C) P-2, Q-3, R-1, S-4
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

81. वैश्वीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह केवल एक सकारात्मक प्रक्रिया है।
2. यह सिर्फ एक आर्थिक परिघटना है।

3. इसका प्रभाव सभी देशों पर समान है।
4. यह एक बहुआयामी परिघटना है।
5. इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हैं।

उपरोक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन गलत हैं?
(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 4 और 5
(C) केवल 1, 3 और 5
(D) केवल 2, 3 और 4

82. आर्थिक वैश्वीकरण को अधिक व्यापक नजर से समझने के लिए किस पर ध्यान देना चाहिए?
(A) आर्थिक फायदों के बँटवारे पर, यानी किसे फायदा हुआ और किसे कम।
(B) केवल प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका पर।
(C) केवल विभिन्न वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर।
(D) केवल विश्व के अत्यधिक विकसित देशों की नीतियों पर।

83. संस्कृति के बारे में कौन सा कथन सही है?
(A) संस्कृति एक जड़ वस्तु होती है जो कभी नहीं बदलती।
(B) बाहरी प्रभावों का असर हमेशा नकारात्मक होता है।
(C) हर संस्कृति हर समय बाहरी प्रभावों को स्वीकार करते रहती है।
(D) बाहरी प्रभावों से हमारी पसंद-नापसंद का दायरा हमेशा घटता है।

84. निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में रखें:
1. भारत में संरक्षणवादी आर्थिक नीति।
2. सिएटल में डब्ल्यू.टी.ओ. का विरोध।
3. भारत में नई आर्थिक नीति लागू होना।
4. मुंबई में विश्व सामाजिक मंच की बैठक।

उपरोक्त में से कौन-सा क्रम सही है?
(A) 1, 3, 2, 4
(B) 2, 1, 3, 4
(C) 1, 2, 3, 4
(D) 3, 1, 2, 4

85. नीचे दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार करें:
अभिकथन (A): वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है।
कारण (R): बाहरी प्रभावों के कारण संस्कृतियों में अनूठे बदलाव आते हैं, जैसे नीली जीन्स पर खादी का कुर्ता पहनना, जो एक नई शैली को जन्म देता है।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

86. कॉल सेंटर में काम करने वाले कर्मचारी को कभी-कभी नस्लीय टिप्पणियों का सामना क्यों करना पड़ता है?
(A) क्योंकि वे आधुनिक अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक वेतन कमाते हैं।
(B) क्योंकि कुछ अमरीकी यह मानते हैं कि भारतीय उनकी नौकरियां छीन रहे हैं।
(C) कार्यस्थल पर उनकी अंग्रेजी का स्तर अच्छा नहीं होता है।
(D) क्योंकि वे अपने व्यावसायिक कार्यों के लिए केवल दिन में काम करते हैं।

87. आर्थिक वैश्वीकरण के मध्यमार्गी समर्थकों का क्या मानना है?
(A) कि वर्तमान वैश्वीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक देना चाहिए।
(B) कि वैश्वीकरण अपरिहार्य है और इसे बिना किसी शर्त के स्वीकार करना चाहिए।
(C) कि वैश्वीकरण केवल विकसित देशों के हित में है और विकासशील देशों को इससे दूर रहना चाहिए।
(D) कि वैश्वीकरण ने चुनौतियाँ पेश की हैं और बुद्धिमत्ता से इसका सामना किया जाना चाहिए।

88. वैश्वीकरण के विभिन्न पहलुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. विचारों का एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुँचना।
2. पूँजी का एक से ज़्यादा जगहों पर जाना।
3. वस्तुओं का कई-कई देशों में पहुँचना।
4. बेहतर आजीविका की तलाश में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों की आवाजाही।

उपरोक्त में से कौन-से कथन इसके घटक हैं?
(A) विश्वव्यापी 'पारस्परिक जुड़ाव'
(B) संरक्षणवाद
(C) राष्ट्रवाद
(D) क्षेत्रीयकरण

89. वैश्वीकरण के पैरोकारों का यह तर्क कि 'इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी', किस आधार पर गलत है?
(A) क्योंकि वैश्वीकरण की प्रक्रिया सभी प्रकार के सांस्कृतिक प्रभावों से पूरी तरह रहित है।
(B) क्योंकि पैरोकार आर्थिक समृद्धि पर ध्यान देते हैं, सांस्कृतिक समरूपता की बात आलोचक करते हैं।
(C) क्योंकि वैश्वीकरण की प्रक्रिया से वास्तव में सांस्कृतिक विभिन्नता भी निरंतर बढ़ती है।
(D) क्योंकि विश्व की सभी संस्कृतियाँ पहले से ही एक-दूसरे के पूरी तरह समान हैं।

90. 'बर्गर मसाला-डोसा का विकल्प नहीं है' - इस कथन का क्या निहितार्थ है?
(A) बाहरी खाद्य पदार्थों के आने से भोजन की पसंद में केवल वृद्धि होती है।
(B) बर्गर और मसाला-डोसा के स्वाद और पोषण में कोई अंतर नहीं है।
(C) बाहरी खाद्य पदार्थों के आने से स्थानीय भोजन की पसंदें

पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं।
(D) आधुनिक समय में मसाला-डोसा अब युवाओं के बीच लोकप्रिय नहीं रहा।

91. निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए:
सूची I: (संगठन/नीति)
P. विश्व व्यापार संगठन (WTO)
Q. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)
R. संरक्षणवाद
S. विश्व सामाजिक मंच (WSF)
सूची II: (विवरण)
1. घरेलू उद्योगों की रक्षा हेतु आयात पर प्रतिबंध
2. नव-उदरवादी वैश्वीकरण का आलोचक मंच
3. वैश्विक व्यापार नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था
4. वैश्विक वित्तीय स्थिरता और आर्थिक नीतियों से संबंधित संस्था
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-2, Q-1, R-4, S-3
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

92. भारत में वैश्वीकरण के प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसका विरोध केवल वामपंथी दलों ने किया है।
2. औद्योगिक श्रमिकों और किसानों के संगठनों ने बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश का समर्थन किया है।
3. कुछ वनस्पतियों जैसे 'नीम' को पेटेंट कराने के प्रयासों का कड़ा विरोध हुआ।
4. दक्षिणपंथी खेमे ने केबल नेटवर्क के जरिए उपलब्ध विदेशी टीवी चैनलों का स्वागत किया है।
5. वैश्वीकरण का विरोध विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक हलकों से हुआ है।
उपरोक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3 और 5
(C) केवल 1, 2 और 4
(D) केवल 4 और 5

93. वैश्वीकरण के चलते राज्य की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है?
(A) आधुनिक समय में संप्रभु राज्य अब पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गए हैं।
(B) विभिन्न राष्ट्रों ने वैश्वीकरण के कारण अपनी सारी शक्तियां खो दी हैं।
(C) राज्य की भूमिका बदली है, लेकिन वे आज भी व्यवस्था में प्रमुख हैं।
(D) राज्य वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण पहले से कहीं अधिक कल्याणकारी हो गए हैं।

94. नीचे दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार करें:
अभिकथन (A): वैश्वीकरण का प्रभाव बड़ा विषम रहा है।
कारण (R): वैश्वीकरण ने समाज के कुछ हिस्सों को बाकियों की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावित किया है।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

95. 'मेड इन बांग्लादेश' या 'मेड इन टर्की' जैसे लेबल वाली वस्तुओं का पश्चिमी बाजारों में बिकना क्या दर्शाता है?
(A) वैश्विक उत्पादन श्रृंखला और वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार।
(B) आधुनिक युग में केवल स्थानीय बाज़ारों का बढ़ता हुआ महत्व।
(C) विकसित देशों में औद्योगिक उत्पादन की निरंतर बढ़ती हुई उच्च लागत।
(D) संप्रभु राष्ट्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगाए गए कड़े प्रतिबंध।

96. वैश्वीकरण के युग में राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा है?
(A) राष्ट्रवाद की भावना आधुनिक विश्व से पूरी तरह से समाप्त हो गई है।
(B) विश्व की राजनीति में पुरानी ईर्ष्या और प्रतिद्वंद्विता अभी भी दखल रखती है।
(C) राष्ट्रवाद और मजबूत हुआ है क्योंकि राज्य अपनी संप्रभुता हेतु सजग हैं।
(D) राष्ट्रवाद अब केवल संकीर्ण सांस्कृतिक क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया है।

97. आर्थिक वैश्वीकरण के आलोचकों द्वारा 'सामाजिक सुरक्षा कवच' की बात को अव्यावहारिक क्यों माना जाता है?
(A) क्योंकि वे पूरी तरह मानते हैं कि यह अमीरों को और अमीर बना देगा।
(B) क्योंकि उनका मानना है कि बलपूर्वक किए जा रहे वैश्वीकरण को रोकना चाहिए।
(C) क्योंकि वे मानते हैं कि राष्ट्रीय सरकारों के पास इसके लिए धन नहीं है।
(D) क्योंकि वे मानते हैं कि वैश्वीकरण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं है।

98. वैश्वीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है जो मानव इतिहास के अधिकांश समय जारी रही है।
2. समकालीन वैश्वीकरण प्रवाहों की गति और प्रसार के कारण अनूठा है।
3. प्रौद्योगिकी ने विश्व के विभिन्न भागों में लोगों के बीच जुड़ाव की समझ को नहीं बढ़ाया है।
4. सुनामी जैसी घटनाएँ साबित करती हैं कि घटनाएँ राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं रहतीं।
उपरोक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही हैं?

कोई संबंध नहीं है।
(B) आधुनिक युग में केवल आर्थिक परिणाम ही नीति निर्माण हेतु महत्वपूर्ण हैं।
(C) केवल सांस्कृतिक परिणाम ही दीर्घकालिक और समाज हेतु अपरिवर्तनीय होते हैं।
(D) ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं और इनके बीच सूक्ष्म भेद है।

117. भारत में दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा 'वैलेन्टाइन-डे' का विरोध, वैश्वीकरण के किस आयाम के प्रतिरोध का उदाहरण है?
(A) आर्थिक आयाम
(B) राजनीतिक आयाम
(C) सांस्कृतिक आयाम
(D) प्रौद्योगिकीय आयाम

118. वैश्वीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसका अर्थ विश्व के एक हिस्से के विचारों का दूसरे हिस्से में पहुँचना है।
2. इसका अर्थ पूँजी का एक से ज़्यादा जगहों पर जाना है।
3. इसका अर्थ वस्तुओं का कई-कई देशों में पहुँचना और उनका व्यापार है।
4. इसका अर्थ बेहतर आजीविका की तलाश में लोगों की आवाजाही है।

उपरोक्त सभी कथन सामूहिक रूप से किसकी व्याख्या करते हैं?
(A) केवल आर्थिक वैश्वीकरण
(B) वैश्वीकरण की बहुआयामी प्रकृति
(C) केवल सांस्कृतिक वैश्वीकरण
(D) केवल राजनीतिक वैश्वीकरण

119. यदि एक देश अपने घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए आयात पर उच्च शुल्क लगाता है, तो यह किस नीति का पालन कर रहा है?
(A) उदारीकरण
(B) निजीकरण
(C) वैश्वीकरण
(D) संरक्षणवाद

120. नीचे दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार करें:
अभिकथन (A): वैश्वीकरण विरोधी बहुत से आंदोलन, वैश्वीकरण की धारणा के विरोधी नहीं हैं।
कारण (R): वे वैश्वीकरण के किसी खास कार्यक्रम के विरोधी हैं जिसे वे साम्राज्यवाद का एक रूप मानते हैं।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

121. निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए:
सूची I: (समूह/विचारधारा)
P. वैश्वीकरण के समर्थक
Q. वैश्वीकरण के वामपंथी आलोचक
R. वैश्वीकरण के दक्षिणपंथी आलोचक
S. सामाजिक न्याय के पक्षधर

सूची II: (मुख्य तर्क/मांग)
1. आर्थिक आत्मनिर्भरता और परंपरागत संस्कृति की रक्षा।
2. 'सामाजिक सुरक्षा कवच' का निर्माण।
3. इससे समृद्धि बढ़ती है और 'खुलेपन' से खुशहाली आती है।
4. यह धनिकों को और धनी और गरीबों को और गरीब बनाता है।

(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-1, R-2, S-3
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-2, Q-3, R-4, S-1

122. वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप कल्याणकारी राज्य की जगह 'न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य' ने ले ली है। इसका प्रमुख परिणाम क्या है?
(A) राज्य ने सामाजिक-कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों से स्वयं को पीछे खींच लिया है।
(B) राज्य ने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे लोक-कल्याणकारी कामों में अपनी भूमिका को अत्यधिक बढ़ा दिया है।
(C) राज्य अब आधुनिक समय में केवल और केवल तीव्र आर्थिक विकास पर ही अपना ध्यान केंद्रित करता है।
(D) राज्य का वार्षिक बजट घाटा इस नई नीति के कारण पूरी तरह से और हमेशा के लिए समाप्त हो गया है।

123. वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. विभिन्न देश अपने यहाँ होने वाले आयात पर प्रतिबंध बढ़ा रहे हैं।
2. दुनिया भर में पूँजी की आवाजाही पर अब कहीं कम प्रतिबंध हैं।
3. विचारों के प्रवाह के सामने राष्ट्र की सीमाओं की बाधा नहीं रही।
4. लोगों की आवाजाही उतनी नहीं बढ़ी है जितनी वस्तुओं और पूँजी की।
5. सभी देशों में एक समान आर्थिक नीतियां अपनाने से परिणाम भी समान हुए हैं।

उपरोक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 2, 3 और 4
(C) केवल 3, 4 और 5
(D) केवल 1, 4 और 5

124. "बर्ड फ्लू अथवा 'सुनामी' किसी एक राष्ट्र की हदों में सिमटे नहीं रहते।" यह कथन वैश्वीकरण के किस पहलू को उजागर करता है?
(A) विभिन्न राष्ट्रों के मध्य केवल आर्थिक और व्यापारिक अंतर्संबंधों की स्थिति को।

(D) लक्ष्य 10: असमानता में कमी

108. वैश्वीकरण के कारण राज्य की बदलती भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. राज्य अब लोक-कल्याणकारी कामों से हटकर न्यूनतम हस्तक्षेप तक सीमित हो गए हैं।
2. बाज़ार अब आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक है।
3. बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका बढ़ने से सरकारों के फैसला करने की क्षमता में कमी आई है।
4. अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी ने राज्यों को अपने नागरिकों पर निगरानी रखने की अभूतपूर्व क्षमता प्रदान की है।
5. राज्य आज भी कानून-व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अनिवार्य कार्यों को पूरा कर रहे हैं।

उपरोक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 3, 4 और 5
(C) केवल 1, 2, 4 और 5
(D) उपरोक्त सभी

109. वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में कौन सा कथन गलत है?
(A) इससे दुनिया के 'मैक्डोनॉल्डीकरण' का खतरा है।
(B) इससे सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण भी होता है।
(C) यह केवल नकारात्मक हैं क्योंकि इससे पसंदों में कमी आती है।
(D) यह हमारी पसंद-नापसंद को प्रभावित करता है।

110. 'विश्व सामाजिक मंच' के बारे में दिए गए विभिन्न विचारों में से कौन सा एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जैसा कि आलोचकों द्वारा तर्क दिया गया है?
(A) यह एक खुला और वैचारिक रूप से मुक्त आकाश है।
(B) विकल्पों की खोज की यह प्रक्रिया अनिवार्य रूप से बहुलता भरी होगी।
(C) यह विश्वास दिलाता है कि एक और बेहतर दुनिया मुमकिन है।
(D) यह संघर्ष को सुधारवाद की तरफ मोड़कर पूँजीवाद को बचाना चाहता है।

111. निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए:
सूची I: (वैश्वीकरण का आयाम)
P. प्रवाह की निरंतरता
Q. राज्य की क्षमता में कमी
R. सांस्कृतिक समरूपता
S. आर्थिक असमानता

सूची II: (संबंधित शब्द/अवधारणा)
1. विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव
2. न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य
3. मैक्डोनॉल्डीकरण
4. पुनःउपनिवेशीकरण

(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-1, R-4, S-3
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

112. यदि कोई व्यक्ति यह तर्क देता है कि वैश्वीकरण अपरिहार्य है और इतिहास की धारा को अवरुद्ध करना कोई बुद्धिमानी नहीं, तो वह किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा है?
(A) वैश्वीकरण के आलोचक का।
(B) वैश्वीकरण के समर्थक का।
(C) वैश्वीकरण के प्रति तटस्थ व्यक्ति का।
(D) संरक्षणवादी का।

113. नीचे दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार करें:
अभिकथन (A): वैश्वीकरण की प्रक्रिया में वस्तुओं और पूँजी का प्रवाह तो बढ़ा है, लेकिन लोगों का प्रवाह उस सीमा तक नहीं बढ़ा है।
कारण (R): विकसित देश अपनी वीज़ा-नीति के ज़रिए अपने नागरिकों के नौकरी-धंधे को बचाने के लिए राष्ट्रीय सीमाओं को अभेद्य बनाए रखते हैं।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

114. निम्नलिखित प्रक्रियाओं को ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. मुद्रण तकनीक का आविष्कार और राष्ट्रवाद का उदय।
2. टेलीग्राफ और टेलीफोन द्वारा संचार क्रांति।
3. भारत द्वारा 'संरक्षणवाद' की नीति का त्याग।
4. 'वर्ल्ड सोशल फोरम' का गठन।

उपरोक्त में से कौन-सा क्रम सही है?
(A) 1, 2, 3, 4
(B) 2, 1, 3, 4
(C) 1, 3, 2, 4
(D) 2, 3, 1, 4

115. वैश्वीकरण के आलोचकों द्वारा 'पुनःउपनिवेशीकरण' शब्द का प्रयोग क्या दर्शाता है?
(A) यह कि वैश्वीकरण से सभी देशों को समान लाभ होगा।
(B) यह कि वैश्वीकरण से पुराने उपनिवेश फिर से स्थापित हो रहे हैं।
(C) यह कि वैश्वीकरण एक नई प्रकार की आर्थिक पराधीनता को जन्म दे रहा है।
(D) यह कि वैश्वीकरण एक पूर्णतः नई और अभूतपूर्व घटना है।

116. वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिणामों के बारे में क्या कहा जा सकता है?
(A) ये तीनों एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र हैं और इनके बीच

(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 2, 3 और 4
(C) केवल 1, 2 और 4
(D) केवल 1, 3 और 4

99. एक ही समय में सांस्कृतिक समरूपता और सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण की प्रक्रियाएं होने का क्या मतलब है?
(A) वैश्वीकरण एक पूर्णतः विरोधाभासी और दिशाहीन प्रक्रिया है।
(B) वैश्वीकरण का आधुनिक समाजों पर कोई वास्तविक सांस्कृतिक प्रभाव नहीं है।
(C) वैश्वीकरण के प्रभाव जटिल हैं, जो एकरूपता और विशिष्टता दोनों लाते हैं।
(D) सांस्कृतिक समरूपता की अवधारणा केवल एक अकादमिक मिथक है।

100. वैश्वीकरण की परिभाषा में 'प्रवाह' के चार प्रमुख प्रकार कौन से हैं?
(A) केवल वस्तुएं, सेवाएं, प्रौद्योगिकी और संस्कृति।
(B) केवल पूँजी, श्रम, तकनीक और संसाधन।
(C) राजनीति, अर्थशास्त्र, समाज और धर्म।
(D) विचार, पूँजी, वस्तु और लोग।

101. निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए:
सूची I: (देश/स्थान)
P. पोर्टो अलगेरे
Q. सिएटल
R. मुंबई
S. काठमांडू (नेपाल)
सूची II: (संबंधित घटना)
1. WSF की चौथी बैठक (2004)
2. WTO मंत्री-स्तरीय बैठक का विरोध (1999)
3. WSF की पहली बैठक (2001)
4. WSF की बैठक (2024)
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-3, R-4, S-1
(C) P-3, Q-2, R-1, S-4
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

102. औपनिवेशिक काल में भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका थी?
(A) यह मुख्य रूप से बने-बनाए सामानों का निर्यातक और कच्चे माल का आयातक था।
(B) यह कच्चे माल का निर्यातक तथा बने-बनाए सामानों का आयातक था।
(C) यह एक पूर्णतः आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं था।
(D) यह औपनिवेशिक काल के दौरान एक प्रमुख वैश्विक औद्योगिक शक्ति के रूप में था।

103. नीचे दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार करें:
अभिकथन (A): संस्कृति कोई जड़ वस्तु नहीं होती।
कारण (R): हर संस्कृति हर समय बाहरी प्रभावों को स्वीकार करती रहती है, जिससे कभी उसकी पसंद-नापसंद का दायरा बढ़ता है तो कभी परंपरागत मूल्यों को चुनौती मिलती है।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

104. 'ग्लोबल बाज़ार का लोकल चेहरा' (जैसे 'मैकअरेबिया' बर्गर) क्या दर्शाता है?
(A) वैश्विक ब्रांडों द्वारा स्थानीय बाज़ारों के अनुरूप स्वयं को ढालने की प्रक्रिया।
(B) वैश्विक ब्रांडों का पूरी तरह से स्थानीय संस्कृतियों पर हावी होना।
(C) स्थानीय उत्पादों का तीव्र गति से वैश्विक बाज़ारों में प्रवेश करना।
(D) वैश्वीकरण की पूरी प्रक्रिया के प्रति स्थानीय समाजों का पूर्ण प्रतिरोध।

105. भारत में 'इंडियन सोशल फोरम' जैसे मंचों की क्या भूमिका है?
(A) वे आर्थिक वैश्वीकरण का समर्थन करते हैं।
(B) वे केवल सांस्कृतिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
(C) वे आर्थिक वैश्वीकरण के खिलाफ वामपंथी तेवर की आवाज उठाते हैं।
(D) वे सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं।

106. भारत में वैश्वीकरण के प्रतिरोध के विविध रूपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. वामपंथी दलों ने आर्थिक नीतियों का विरोध किया।
2. दक्षिणपंथी खेमों ने सांस्कृतिक प्रभावों का विरोध किया।
3. किसान संगठनों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विरोध किया।
4. पर्यावरणवादियों ने 'नीम' के पेटेंट का विरोध किया।
उपरोक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही हैं?
(A) भारत में वैश्वीकरण के प्रति कोई विरोध नहीं है।
(B) भारत में वैश्वीकरण का विरोध समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा विभिन्न आधारों पर किया गया है।
(C) भारत में केवल राजनीतिक दल ही वैश्वीकरण का विरोध करते हैं।
(D) भारत में वैश्वीकरण का विरोध पूरी तरह से असफल रहा है।

107. निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य (SDG) वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों, जैसे बढ़ती असमानता, से सीधे तौर पर संबंधित है?
(A) लक्ष्य 4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
(B) लक्ष्य 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा
(C) लक्ष्य 14: पानी के नीचे जीवन

(B) वैश्विक समस्याओं और राष्ट्रों के मध्य बढ़ते पारस्परिक जुड़ाव की वास्तविकता को।
(C) वैश्विक स्तर पर होने वाले केवल सांस्कृतिक आदान-प्रदान और समरूपता को।
(D) संप्रभु राष्ट्रीय सरकारों की निरंतर बढ़ती हुई शक्ति और उनकी सीमाओं को।

125. यह विचार कि "सच्ची समाजवादी व्यवस्था केवल संघर्ष से लाई जा सकती है; अंतहीन और निरर्थक बहसों से नहीं", विश्व सामाजिक मंच के भीतर किस प्रकार की विचारधारा को दर्शाता है?
(A) एक उदारवादी और सुधारवादी दृष्टिकोण।
(B) एक अराजकतावादी दृष्टिकोण।
(C) एक अधिक क्रांतिकारी और संघर्ष-उन्मुख दृष्टिकोण।
(D) एक नव-उडरवादी दृष्टिकोण।

126. भारत में 1991 के बाद अपनाई गई आर्थिक नीतियों में क्या शामिल था?
(A) विदेशी बाज़ारों से होने वाले आयात पर प्रतिबंधों को पहले की तुलना में और अधिक कड़ा करना।
(B) देश के भीतर मौजूद सभी छोटे और बड़े उद्योगों का पूर्णतः राष्ट्रीयकरण करना।
(C) विदेशी कंपनियों को भारतीय सीमाओं के भीतर व्यापार करने से कानूनी रूप से रोकना।
(D) व्यापार और विदेशी निवेश पर आयद बाधाओं को हटाना।

127. निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव वैश्वीकरण का परिणाम नहीं माना जाता है?
(A) राष्ट्र-राज्यों के बीच प्रतिद्वंद्विता का पूर्ण अंत।
(B) राज्य की संप्रभुता को चुनौती।
(C) सांस्कृतिक समरूपता का बढ़ना।
(D) आर्थिक अंतर्निर्भरता में वृद्धि।

128. नीचे दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार करें:
अभिकथन (A): वैश्वीकरण का प्रभाव केवल नकारात्मक ही नहीं है।
कारण (R): बाहरी प्रभावों से हमारी पसंद-नापसंद का दायरा बढ़ता है और कभी-कभी इनसे परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों को छोड़े बिना संस्कृति का परिष्कार होता है।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

129. वैश्वीकरण के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बहस क्या है?
(A) क्या यह केवल एशिया को प्रभावित करता है?
(B) क्या यह साम्राज्यवाद का ही नया नाम है?
(C) क्या यह केवल एक राजनीतिक परिघटना है?
(D) क्या यह 21वीं सदी में समाप्त हो जाएगा?

130. निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए:
सूची I: (शब्द)
P. वैश्वीकरण
Q. पश्चिमीकरण
R. संरक्षणवाद
S. उदारीकरण
सूची II: (अर्थ)
1. व्यापार आदि पर लगे प्रतिबंधों को हटाना
2. घरेलू उद्योग को बचाने की नीति
3. पश्चिमी संस्कृति और मूल्यों का प्रभाव
4. प्रवाहों के कारण विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-2, Q-1, R-4, S-3
(D) P-3, Q-4, R-1, S-2

131. वैश्वीकरण के विभिन्न पहलुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह एक बहुआयामी अवधारणा है।
2. प्रौद्योगिकी इसका एक प्रमुख कारण है।
3. इसने राज्य की क्षमता को कुछ मामलों में कम किया है तो कुछ में बढ़ाया है।
4. इसके कारण सांस्कृतिक समरूपता और वैभिन्नीकरण दोनों हुए हैं।
उपरोक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3 और 4
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) 1, 2, 3 और 4 सभी

132. वैश्वीकरण का विरोध करने वाले सामाजिक आंदोलनों की एक प्रमुख विशेषता क्या है?
(A) वे केवल स्थानीय स्तर पर सक्रिय हैं।
(B) वे सभी एक ही विचारधारा का पालन करते हैं।
(C) उन्हें हमेशा अपनी सरकारों का समर्थन प्राप्त होता है।
(D) वे अक्सर वैश्विक नेटवर्क बनाकर एक दूसरे से जुड़ते हैं।

133. सतत विकास लक्ष्य (SDG) 8, जो 'सभ्य कार्य और आर्थिक विकास' को बढ़ावा देने की बात करता है, वैश्वीकरण के किस पहलू से विशेष रुप से प्रासंगिक है?
(A) सांस्कृतिक समरूपता के मुद्दे से।
(B) राजनीतिक संप्रभुता के क्षरण से।
(C) नौकरी और जन-कल्याण पर वैश्वीकरण के प्रभाव से।
(D) सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार से।

134. आज के वैश्वीकरण और पूर्व के वैश्वीकरण में मुख्य अंतर क्या है?
(A) इतिहास के पूर्व काल में वैश्वीकरण की कोई अवधारणा मौजूद नहीं थी।

ANSWERS

1. (B) प्रवाह
वैश्वीकरण की मूल अवधारणा प्रवाहों के निरंतर संचरण पर आधारित है। इसमें विचारों, पूँजी, वस्तुओं और लोगों का एक देश से दूसरे देश में आवागमन शामिल है। यह विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव की स्थिति उत्पन्न करता है, जिससे दुनिया के विभिन्न हिस्से आपस में जुड़ते हैं। यह प्रक्रिया तकनीकी प्रगति और संचार क्रांति के माध्यम से और अधिक व्यापक और तीव्र हो गई है।

2. (A) वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है, जिससे विभिन्न समाजों पर इसके भिन्न-भिन्न परिणाम देखे गए हैं।
वैश्वीकरण का प्रभाव संपूर्ण विश्व में एक समान नहीं रहा है। यह प्रक्रिया विभिन्न समाजों, संस्कृतियों और अर्थव्यवस्थाओं को उनकी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग तरीके से प्रभावित करती है। जहाँ कुछ क्षेत्रों में इससे तीव्र आर्थिक समृद्धि और विकास देखा गया है, वहीं कुछ अन्य समाजों में इसके कारण सांस्कृतिक संकट और आर्थिक विषमता जैसी चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं।

3. (A) P-2, Q-1, R-3, S-4
वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों को वास्तविक उदाहरणों से समझा जा सकता है। जनार्दन का कॉल सेंटर में काम करना सेवाओं के वैश्वीकरण को दर्शाता है, जबकि रामधारी द्वारा साइकिल खरीदना वस्तुओं के प्रवाह का उदाहरण है। सारिका के सामने नए करियर अवसर सांस्कृतिक बदलावों को इंगित करते हैं। वहीं, किसानों की आत्महत्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के महंगे बीजों के नकारात्मक प्रभाव को दर्शाती है।

4. (D) क्योंकि इसने विभिन्न आविष्कारों द्वारा विश्व के भिन्न भागों के मध्य संचार में क्रांति ला दी है।
प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण का एक अपरिहार्य कारण है क्योंकि इसने संचार के साधनों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचिप जैसे आविष्कारों ने विश्व के दूरदराज के हिस्सों को आपस में जोड़ दिया है। इस तकनीकी उन्नति के बिना विचारों, पूँजी और वस्तुओं का इतना तीव्र प्रवाह संभव नहीं होता। यह तकनीक भौगोलिक दूरियों को कम कर वैश्विक जुड़ाव को सुगम बनाती है।

5. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता में गिरावट आई है क्योंकि अब लोक-कल्याणकारी राज्य की जगह न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य की धारणा प्रचलित हो गई है। राज्य अब अपनी शक्तियों को केवल कानून-व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अनिवार्य कार्यों तक सीमित रखते हैं। आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का निर्धारण अब राज्य के बजाय मुख्य रूप से बाज़ार की शक्तियों द्वारा किया जाता है।

6. (B) विकसित देश अपनी वीज़ा-नीति के ज़रिए लोगों की आवाजाही को सुगम बनाते हैं।
आर्थिक वैश्वीकरण में वस्तुओं और पूँजी का प्रवाह तो अत्यंत तीव्र हुआ है, लेकिन लोगों की आवाजाही पर अभी भी कड़े प्रतिबंध हैं। विकसित देश अपनी वीज़ा-नीति के माध्यम से अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं ताकि उनके नागरिकों के रोजगार पर कोई प्रभाव न पड़े। यह विरोधाभास दर्शाता है कि वैश्वीकरण में श्रम का प्रवाह वस्तुओं और पूँजी की तुलना में सीमित है।

7. (D) विभिन्न संस्कृतियों का प्रभुत्वशाली अमरीकी ढर्रे पर ढलना।
मैक्डोनॉल्डीकरण की अवधारणा वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाती है, जहाँ विश्व की विभिन्न संस्कृतियाँ प्रभुत्वशाली अमेरिकी शैली में ढलने लगती हैं। यह प्रक्रिया सांस्कृतिक समरूपता को बढ़ावा देती है, जिससे स्थानीय परंपराओं और विविधताओं के लुप्त होने का डर बना रहता है। यह केवल भोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने के तरीकों और सोच पर भी प्रभाव डालती है।

8. (C) केवल 1, 2 और 4
वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव बहुआयामी हैं। इसके कारण राज्य की क्षमता में कुछ क्षेत्रों में कमी आई है और बाज़ार प्रमुख निर्धारक बन गया है। हालाँकि, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की उपलब्धता ने राज्यों को अपने नागरिकों के बारे में जानकारी जुटाने और अधिक प्रभावी ढंग से शासन करने में सक्षम बनाया है। इस प्रकार, राज्य की शक्ति के क्षरण के साथ-साथ उसकी तकनीकी क्षमता में वृद्धि हुई है।

9. (C) वित्तीय संकट से निपटने और आर्थिक वृद्धि की ऊँची दर को प्राप्त करने के उद्देश्य से।
भारत ने 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत मुख्य रूप से गंभीर वित्तीय संकट से निपटने के लिए की थी। उस समय देश की आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने और विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर करने की आवश्यकता थी। इन सुधारों के तहत व्यापार और विदेशी निवेश पर लगे प्रतिबंधों को हटाया गया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत होने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

10. (A) यह पूंजीवाद की वह अवस्था है जो समाज में आर्थिक असमानता और गरीबी को अत्यधिक बढ़ाती है।
वैश्वीकरण के वामपंथी आलोचक मुख्य रूप से आर्थिक परिणामों को लेकर चिंतित रहते हैं। उनका तर्क है कि वैश्वीकरण पूँजीवाद की एक ऐसी अवस्था है जो समाज में आर्थिक असमानता को बढ़ाती है और गरीबों को और अधिक

(B) यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो वैश्विक स्तर पर केवल विकसित देशों को लाभ पहुँचाती है।
(C) यह वर्तमान विश्व में संप्रभु राष्ट्र-राज्यों के पूर्ण अंत का एक स्पष्ट सूचक है।
(D) यह विचारों, वस्तुओं, पूंजी और लोगों के प्रवाह से उत्पन्न बहुआयामी प्रक्रिया है।

143. निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्वीकरण का सकारात्मक सांस्कृतिक प्रभाव हो सकता है?
(A) इसके कारण हमारी पसंद का दायरा बढ़ता है और संस्कृति का परिष्कार होता है।
(B) स्थानीय और पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्यों का आधुनिक समय में पूर्ण क्षरण।
(C) वैश्विक स्तर पर हमारी पसंद-नापसंद और सांस्कृतिक विकल्पों में कमी आना।
(D) विश्व की सभी विविध संस्कृतियों का अमेरिकी संस्कृति में पूर्णतः विलीन हो जाना।

144. निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना।
2. भारत द्वारा नई आर्थिक नीति का प्रारंभ।
3. भारत द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति और संरक्षणवाद की नीति।
4. सिएटल में डब्ल्यू.टी.ओ. के विरुद्ध प्रदर्शन।

उपरोक्त में से कौन-सा क्रम सही है?
(A) 1, 3, 2, 4
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 3, 1, 2, 4
(D) 2, 1, 4, 3

145. 'विश्व सामाजिक मंच' की पहली बैठक कहाँ और कब हुई थी?
(A) मुंबई, भारत में 2004 में
(B) पोर्टो अलगेरे, ब्राजील में 2001 में
(C) सिएटल, अमेरिका में 1999 में
(D) काठमांडू, नेपाल में 2024 में

146. वैश्वीकरण के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. आर्थिक वैश्वीकरण में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं की भूमिका होती है।
2. राजनीतिक रूप से, वैश्वीकरण ने राज्य की क्षमता को हमेशा बढ़ाया है।
3. सांस्कृतिक रूप से, वैश्वीकरण से केवल सांस्कृतिक समरूपता आती है।
4. भारत ने 1991 में आर्थिक सुधारों की योजना शुरु की।
5. वैश्वीकरण का विरोध केवल वामपंथी दलों ने किया है।

उपरोक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 4
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1, 4 और 5
(D) केवल 3, 4 और 5

147. एक ही जगह पर चीन में बनी साइकिल, अमेरिका में बनी 'बार्बी डॉल' और विभिन्न देशों के खाद्य पदार्थों का उपलब्ध होना वैश्वीकरण के किस पहलू को दर्शाता है?
(A) सेवाओं के प्रवाह को
(B) विचारों के प्रवाह को
(C) वस्तुओं के वैश्विक व्यापार और प्रवाह को
(D) लोगों के प्रवाह को

148. वैश्वीकरण के विषय में यह कहना क्यों गलत है कि इसका प्रभाव एक समान है?
(A) क्योंकि आधुनिक समय में यह केवल विश्व के गरीब देशों को ही प्रभावित करता है।
(B) क्योंकि यह प्रक्रिया केवल अमीर और शक्तिशाली देशों को ही प्रभावित करती है।
(C) क्योंकि आधुनिक विश्व पर इसका कोई वास्तविक या ठोस प्रभाव नहीं पड़ता है।
(D) क्योंकि यह विभिन्न समाजों और समूहों को अलग-अलग स्तरों पर प्रभावित करता है।

149. राज्य की ताकत में इज़ाफा होने का एक कारण क्या है, जैसा कि वैश्वीकरण के संदर्भ में तर्क दिया जाता है?
(A) लोक-कल्याण पर अधिक खर्च।
(B) बहुराष्ट्रीय निगमों पर पूर्ण नियंत्रण।
(C) अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएँ जुटाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की उपलब्धता।
(D) अंतर्राष्ट्रीय संधियों से अलगाव।

150. "क्या साम्राज्यवाद का ही नया नाम वैश्वीकरण नहीं है?" यह प्रश्न क्या इंगित करता है?
(A) यह कि वर्तमान वैश्वीकरण और ऐतिहासिक साम्राज्यवाद में कोई संबंध नहीं है।
(B) यह कि कुछ आलोचक वैश्वीकरण को साम्राज्यवाद के नए रूप में देखते हैं।
(C) यह कि वैश्वीकरण वर्तमान विश्व की एक पूर्णतः और शुद्ध सकारात्मक प्रक्रिया है।
(D) यह कि साम्राज्यवाद वर्तमान वैश्विक राजनीति में एक पुरानी और अप्रासंगिक धारणा है।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
वैश्वीकरण की राजनीतिक विमा राज्य की संप्रभुता की पारंपरिक धारणा को एक जटिल चुनौती प्रस्तुत करती है। एक ओर, यह तर्क दिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, गैर-सरकारी संगठन (NGOs), और बहुराष्ट्रीय निगम (MNCs) राज्य की निर्णय लेने की क्षमता को सीमित करते हैं, जिससे उसकी संप्रभुता का क्षरण होता है। विशेषकर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसी संस्थाएँ सदस्य देशों की आर्थिक नीतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं, जो राज्य के स्वायत्त क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण प्रतीत होता है। दूसरी ओर, एक विपरीत दृष्टिकोण यह है कि वैश्वीकरण राज्य को समाप्त नहीं करता, बल्कि उसकी भूमिका को रूपांतरित करता है। इस परिप्रेक्ष्य में, राज्य अब केवल

(B) वर्तमान में प्रवाह की गति और उसका विश्वव्यापी प्रसार अभूतपूर्व है।
(C) पूर्व काल का वैश्वीकरण केवल संकीर्ण सांस्कृतिक आयामों तक सीमित था।
(D) आज का वैश्वीकरण शुद्ध रूप से केवल आर्थिक और व्यापारिक परिघटना है।

135. विश्व व्यापार संगठन (WTO) की भूमिका के संबंध में सबसे सटीक वर्णन कौन सा है?
(A) यह विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है।
(B) यह एक सांस्कृतिक संगठन है।
(C) यह नव-उडरवादी वैश्वीकरण का विरोध करता है।
(D) यह वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करने वाली संस्था है।

136. वैश्वीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह केवल 1991 में शुरु हुआ।
2. इसका प्रभाव सभी देशों पर समान रूप से सकारात्मक रहा है।
3. यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विचारों, पूंजी, वस्तुओं और लोगों का विश्वव्यापी प्रवाह शामिल है।
4. इसका प्रतिरोध केवल दक्षिणपंथी खेमों द्वारा किया गया है।
5. प्रौद्योगिकी ने इस प्रक्रिया को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उपरोक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3 और 5
(C) केवल 1, 2 और 4
(D) केवल 3, 4 और 5

137. "बेहतर है कि मुंबई प्रतिरोध 2004 तथाकथित विश्व सामाजिक मंच का विरोध कर रहा है।" यह कथन किस बात की ओर संकेत करता है?
(A) वैश्वीकरण विरोधी आंदोलनों के मध्य पूर्ण वैचारिक एकता है।
(B) विश्व सामाजिक मंच वर्तमान में साम्राज्यवाद का प्रबल समर्थक है।
(C) आंदोलनों के भीतर भी गहरे मतभेद और रणनीतिक बहसें उपस्थित हैं।
(D) मुंबई प्रतिरोध वैश्वीकरण की आर्थिक प्रक्रियाओं का पूर्ण समर्थन करता है।

138. नीचे दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार करें:
अभिकथन (A): वैश्वीकरण से सांस्कृतिक समरुपता का खतरा उत्पन्न हुआ है।
कारण (R): राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली संस्कृति कम ताकतवर समाजों पर अपनी छाप छोड़ती है, जिससे विश्व की सांस्कृतिक धरोहर को हानि पहुँचती है।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

139. कॉल सेंटर की कहानी एक कर्मचारी की ज़बानी के अनुसार, कॉल अटेंड करने वाले अमरीकी का लहजा कभी-कभी नफ़रत से क्यों भर जाता है?
(A) क्योंकि उसे भारतीय संस्कृति और यहाँ की जीवनशैली बिल्कुल पसंद नहीं है।
(B) क्योंकि उसे लंबी दूरी के अंतर्राष्ट्रीय कॉल के लिए अत्यधिक भुगतान करना पड़ता है।
(C) क्योंकि कॉल की तकनीकी गुणवत्ता और संचार माध्यम बहुत खराब स्थिति में होते हैं।
(D) भारतीयों द्वारा नौकरियां छीने जाने की धारणा के कारण उत्पन्न कुंठा से।

140. निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए:
सूची I: (अवधारणा)
P. सांस्कृतिक समरूपता
Q. सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण
R. पुनःउपनिवेशीकरण
S. सामाजिक सुरक्षा कवच

सूची II: (उदाहरण/व्याख्या)
1. नीली जीन्स पर खादी का कुर्ता
2. विश्व का 'मैक्डोनॉल्डीकरण'
3. गरीबों पर वैश्वीकरण के दुष्प्रभावों को कम करने का उपाय
4. आर्थिक वैश्वीकरण से गरीब देशों की बढ़ती पराधीनता

(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-1, R-4, S-2
(C) P-2, Q-1, R-4, S-3
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

141. वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. राज्य की संप्रभुता की परंपरागत धारणा पर असर हुआ है।
2. राज्य की क्षमता में हमेशा कमी ही आई है।
3. राज्य अभी भी कानून-व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अनिवार्य कार्य कर रहे हैं।
4. बहुराष्ट्रीय निगमों का प्रभाव कम हुआ है।

उपरोक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2 और 4
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) केवल 3 और 4

142. वैश्वीकरण का सबसे सटीक वर्णन क्या है?
(A) यह आधुनिक विश्व की एक विशुद्ध रूप से आर्थिक और व्यापारिक प्रक्रिया है।

158. अनुच्छेद के अनुसार, आर्थिक वैश्वीकरण के मॉडल की मुख्य आलोचना क्या है?
(A) यह वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण के बीच संरचनात्मक असमानताओं को बढ़ाता है।
(B) यह सभी देशों के बीच समान रूप से धन का वितरण करता है।
(C) यह प्रौद्योगिकी के प्रवाह को पूरी तरह से रोकता है।
(D) यह बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए लाभ को कम करता है।

159. "निर्भरता का मॉडल" से स्रोत का क्या अभिप्राय है?
(A) विकासशील देश प्रौद्योगिकी के लिए विकसित देशों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं।
(B) विकसित देश कच्चे माल के लिए विकासशील देशों पर निर्भर हो जाते हैं।
(C) विकासशील देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में निम्न-मूल्य वर्धित गतिविधियों तक सीमित रह जाते हैं।
(D) सभी देश एक दूसरे पर समान रूप से निर्भर हो जाते हैं।

160. स्रोत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के बारे में क्या बताता है?
(A) वे उत्पादन प्रक्रियाओं को विभिन्न देशों में वितरित करने का एक माध्यम हैं।
(B) वे पूरी तरह से एक ही देश के भीतर संचालित होती हैं।
(C) वे केवल विकसित देशों के बीच मौजूद हैं।
(D) वे स्थानीय कारीगरों को सशक्त बनाने पर केंद्रित हैं।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
सांस्कृतिक वैश्वीकरण एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है जिसमें सांस्कृतिक समरुपता और सांस्कृतिक वैविध्यकरण दोनों की प्रवृत्तियाँ एक साथ क्रियाशील रहती हैं। एक ओर, वैश्विक मीडिया, संचार प्रौद्योगिकियों और उपभोक्ता ब्रांडों के प्रसार ने एक प्रकार की 'वैश्विक संस्कृति' की धारणा को जन्म दिया है, जिसे अक्सर 'पश्चिमीकरण' या 'अमेरिकीकरण' के पर्याय के रूप में देखा जाता है। हॉलीवुड फिल्में, फास्ट-फूड चेन, और वैश्विक फैशन ब्रांड दुनिया भर में समान जीवन शैली और आकांक्षाओं को बढ़ावा देते प्रतीत होते हैं, जिससे स्थानीय संस्कृतियों की विशिष्टता के क्षरण का खतरा उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को सांस्कृतिक समरुपता कहा जाता है, जहाँ शक्तिशाली संस्कृतियाँ कम शक्तिशाली संस्कृतियों पर हावी हो जाती हैं। तथापि, दूसरी ओर, वैश्वीकरण सांस्कृतिक वैविध्यकरण या संकरीकरण (hybridization) को भी जन्म देता है। जब वैश्विक सांस्कृतिक उत्पाद स्थानीय संदर्भों में प्रवेश करते हैं, तो वे अक्सर स्थानीय परंपराओं, स्वादों और मूल्यों के साथ मिल जाते हैं, जिससे नए और मिश्रित सांस्कृतिक रूपों का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को 'ग्लोकलाइज़ेशन' (वैश्विक का स्थानीयकरण) भी कहा जाता है, जहाँ वैश्विक और स्थानीय का मिश्रण होता है। उदाहरण के लिए, एक वैश्विक टीवी शो प्रारुप को स्थानीय भाषा और सांस्कृतिक संदर्भों के अनुरुप ढाला जा सकता है, या एक अंतरराष्ट्रीय फास्ट-फूड श्रृंखला अपने मेनू में स्थानीय व्यंजन शामिल कर सकती है। इस प्रकार, संस्कृति एक निष्क्रिय वस्तु नहीं है जिसे केवल ग्रहण किया जाता है, बल्कि यह एक गतिशील क्षेत्र है जहाँ वैश्विक प्रभावों की सक्रिय रुप से व्याख्या की जाती है, उन्हें अपनाया जाता है और कभी-कभी उनका प्रतिरोध भी किया जाता है।
उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

161. स्रोत के अनुसार सांस्कृतिक वैश्वीकरण की प्रकृति क्या है?
(A) यह केवल सांस्कृतिक समरुपता की एक प्रक्रिया है।
(B) यह केवल सांस्कृतिक वैविध्यकरण की एक प्रक्रिया है।
(C) यह संस्कृतियों को एक दूसरे से पूरी तरह अलग करती है।
(D) यह एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है जिसमें समरुपता और वैविध्यकरण दोनों शामिल हैं।

162. सांस्कृतिक समरुपता की प्रक्रिया में, कौन सी संस्कृति अक्सर प्रभावशाली मानी जाती है?
(A) पूर्वी एशियाई संस्कृति
(B) पश्चिमी संस्कृति
(C) अफ्रीकी पारंपरिक संस्कृति
(D) लैटिन अमेरिकी संस्कृति

163. 'ग्लोकलाइज़ेशन' की अवधारणा से क्या तात्पर्य है?
(A) वैश्विक उत्पादों का पूरी तरह से बहिष्कार।
(B) स्थानीय संस्कृतियों का पूर्ण रुप से उन्मूलन।
(C) वैश्विक और स्थानीय सांस्कृतिक तत्वों का मिश्रण होकर नए रुपों का निर्माण।
(D) केवल वैश्विक संस्कृति को बिना किसी बदलाव के अपनाना।

164. अनुच्छेद के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक संकरीकरण (hybridization) का एक उदाहरण है?
(A) दुनिया भर में एक ही हॉलीवुड फिल्म का अंग्रेजी में देखा जाना।
(B) सभी देशों में एक ही प्रकार की वास्तुकला का उपयोग।
(C) स्थानीय भाषाओं का विलुप्त हो जाना।
(D) एक अंतरराष्ट्रीय फास्ट-फूड श्रृंखला द्वारा अपने मेनू में स्थानीय व्यंजन शामिल करना।

165. स्रोत का मुख्य तर्क क्या है?
(A) संस्कृति एक गतिशील क्षेत्र है जहाँ वैश्विक प्रभावों की स्थानीय स्तर पर व्याख्या और अनुकूलन होता है।
(B) वैश्वीकरण अनिवार्य रुप से सभी स्थानीय संस्कृतियों को नष्ट कर देगा।
(C) वैश्विक संस्कृति हमेशा स्थानीय संस्कृति से श्रेष्ठ होती है।
(D) सांस्कृतिक आदान-प्रदान केवल आधुनिक युग में शुरु हुआ है।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
नव-उदारवादी वैश्वीकरण की प्रतिक्रिया में उभरे प्रतिरोध के आंदोलनों ने वैश्विक नागरिक समाज के उदय को चिह्नित किया है। ये आंदोलन, जिन्हें अक्सर 'वैश्वीकरण-विरोधी'

अपने भू-क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर का प्रहरी नहीं है, बल्कि वह वैश्विक नेटवर्क में एक सक्रिय भागीदार बन गया है। राज्य अपनी संप्रभुता को पूर्ण रूप से खोने के बजाय, वैश्विक समस्याओं जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, और महामारी से निपटने के लिए अन्य राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग करने के लिए अपनी कुछ शक्तियों को साझा या 'पूल' करता है। इस प्रकार, राज्य कमजोर होने के बजाय, नए प्रकार की शक्ति और प्रभाव के लिए अनुकूलित हो रहा है, जहाँ उसकी प्रासंगिकता आंतरिक शासन से अधिक वैश्विक अभिशासन में उसकी भागीदारी पर निर्भर करती है।
उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

151. स्रोत के अनुसार, वैश्वीकरण राज्य की संप्रभुता को किस प्रकार प्रभावित करता है?
(A) यह राज्य की संप्रभुता को पूरी तरह से समाप्त कर देता है।
(B) यह राज्य की संप्रभुता को चुनौती देता है और उसकी भूमिका को रुपांतरित करता है।
(C) यह राज्य की संप्रभुता को पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाता है।
(D) इसका राज्य की संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

152. निम्नलिखित में से कौन सी संस्था, अनुच्छेद के अनुसार, राज्य की आर्थिक नीतियों पर प्रभाव डालकर उसकी संप्रभुता को चुनौती देती है?
(A) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)
(B) संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को)
(C) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)
(D) रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति

153. "राज्य की भूमिका का रुपांतरण" से स्रोत का क्या तात्पर्य है?
(A) राज्य का पूरी तरह से गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाना।
(B) राज्य का केवल आंतरिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करना।
(C) राज्य का आंतरिक शासन के साथ-साथ वैश्विक अभिशासन में एक सक्रिय भागीदारी बनना।
(D) राज्य का वैश्विक नेटवर्क में एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक बन जाना।

154. अनुच्छेद यह क्यों तर्क देता है कि राज्य कमजोर होने के बजाय अनुकूलित हो रहा है?
(A) क्योंकि राज्य अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि कर रहे हैं।
(B) क्योंकि राज्य बहुराष्ट्रीय निगमों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं।
(C) क्योंकि राज्य सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों से अलग हो रहे हैं।
(D) क्योंकि राज्य वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए सहयोग कर अपनी शक्ति का नए तरीकों से उपयोग कर रहे हैं।

155. स्रोत में उल्लिखित संप्रभुता के क्षरण का मुख्य तर्क क्या है?
(A) नागरिकों का राज्य के प्रति निष्ठा में कमी आना।
(B) राज्यों के बीच पारंपरिक युद्धों का बढ़ना।
(C) अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और गैर-राज्य कर्ताओं का राज्य के निर्णय लेने की क्षमता को सीमित करना।
(D) राज्य द्वारा अपनी सीमाओं को पूरी तरह से सील कर देना।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
आर्थिक वैश्वीकरण, जिसका नेतृत्व अक्सर बहुराष्ट्रीय निगम (MNCs) द्वारा किया जाता है, ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के ढांचे को मौलिक रूप से बदल दिया है। ये निगम, जिनका मुख्यालय मुख्य रूप से विकसित देशों (वैश्विक उत्तर) में होता है, अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से विभिन्न देशों, विशेषकर विकासशील देशों (वैश्विक दक्षिण) में वितरित करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य श्रम और संसाधनों की लागत को कम करना और नए बाजारों तक पहुंच बनाना है। इस प्रक्रिया से पूंजी, प्रौद्योगिकी और वस्तुओं का अभूतपूर्व प्रवाह हुआ है, जिसने कुछ विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में तीव्र वृद्धि को गति दी है। हालाँकि, इसके आलोचक तर्क देते हैं कि यह मॉडल संरचनात्मक असमानताओं को बढ़ाता है। बहुराष्ट्रीय निगम अक्सर स्थानीय श्रम कानूनों का लाभ उठाते हैं और पर्यावरण मानकों की उपेक्षा करते हैं, जिससे उनका मुनाफा तो बढ़ता है, लेकिन मेजबान देश को सामाजिक और पर्यावरणीय लागत वहन करनी पड़ती है। लाभ का अधिकांश हिस्सा वापस वैश्विक उत्तर में स्थित मुख्यालयों और शेयरधारकों के पास चला जाता है, जिससे धन का संचय कुछ ही हाथों में केंद्रित हो जाता है। यह एक ऐसी निर्भरता का मॉडल बनाता है जहाँ विकासशील देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में निम्न-मूल्य वर्धित गतिविधियों तक सीमित रह जाते हैं, जबकि उच्च-मूल्य वरDधित अनुसंधान, डिजाइन और विपणन विकसित देशों में केंद्रित रहते हैं।
उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

156. स्रोत के अनुसार, आर्थिक वैश्वीकरण का नेतृत्व मुख्य रूप से कौन करता है?
(A) विकासशील देशों की सरकारें
(B) बहुराष्ट्रीय निगम (MNCs)
(C) अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन
(D) छोटे स्थानीय व्यवसाय

157. बहुराष्ट्रीय निगम विकासशील देशों में अपनी उत्पादन प्रक्रिया क्यों स्थापित करते हैं?
(A) बेहतर पर्यावरणीय मानकों का लाभ उठाने के लिए
(B) उच्च श्रम लागत का भुगतान करने के लिए
(C) स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए
(D) श्रम और संसाधनों की लागत को कम करने और नए बाजारों तक पहुंचने के लिए

173. "दोहरी तलवार" मुहावरे का प्रयोग करके लेखक भारत में वैश्वीकरण के बारे में क्या कहना चाहता है?
(A) वैश्वीकरण पूरी तरह से फायदेमंद था।
(B) वैश्वीकरण पूरी तरह से हानिकारक था।
(C) वैश्वीकरण का भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
(D) वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के महत्वपूर्ण प्रभाव थे।

174. अनुच्छेद के अनुसार, भारत में वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव क्या था?
(A) कृषि क्षेत्र का संकट और आर्थिक असमानता में वृद्धि।
(B) शहरी मध्यम वर्ग का पतन।
(C) विदेशी निवेश में कमी।
(D) सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का संकुचन।

175. भारत के 'वैश्विक बैक ऑफिस' के रूप में उभरने का संबंध किस क्षेत्र की वृद्धि से है?
(A) कृषि और डेयरी उत्पाद
(B) भारी उद्योग और विनिर्माण
(C) सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र
(D) हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग

आंदोलन कहा जाता है, वास्तव में अधिक जटिल हैं और इन्हें 'वैकल्पिक वैश्वीकरण' या 'न्याय वैश्वीकरण' आंदोलन कहना अधिक सटीक होगा। इन आंदोलनों का मूल तर्क यह नहीं है कि वे अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव या प्रवाह के विरुद्ध हैं, बल्कि वे उस विशेष नव-उदारवादी मॉडल के खिलाफ हैं जो कॉर्पोरेट हितों को मानव अधिकारों, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक न्याय पर प्राथमिकता देता है। इन आंदोलनों का एक प्रमुख मंच 'विश्व सामाजिक मंच' (World Social Forum - WSF) है, जिसका नारा है "एक और दुनिया संभव है"। यह मंच पारंपरिक राजनीतिक दलों से अलग, दुनिया भर के सामाजिक आंदोलनों, गैर-सरकारी संगठनों, श्रमिक संघों और बुद्धिजीवियों को एक साथ लाता है। यह किसी एक विचारधारा का प्रचार करने के बजाय संवाद, विचारों के आदान-प्रदान और वैकल्पिक वैश्विक नीतियों के निर्माण के लिए एक 'खुली जगह' प्रदान करता है। ये आंदोलन बहुराष्ट्रीय निगमों के अनियंत्रित अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की अलोकतांत्रिक प्रकृति, और ऋण तथा व्यापार नीतियों के माध्यम से वैश्विक दक्षिण के शोषण का जोरदार विरोध करते हैं। वे व्यापार में निष्पक्षता, ऋण माफी, पर्यावरण संरक्षण और एक अधिक लोकतांत्रिक वैश्विक शासन प्रणाली की वैकल्पिक वकालत करते हैं।

उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

166. स्रोत के अनुसार, वैश्वीकरण का प्रतिरोध करने वाले आंदोलनों को 'वैकल्पिक वैश्वीकरण' कहना क्यों अधिक सटीक है?
(A) क्योंकि वे पूरी दुनिया को अलग-थलग करना चाहते हैं।
(B) क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव के विरुद्ध नहीं, बल्कि नव-उदारवादी मॉडल के विरुद्ध हैं।
(C) क्योंकि वे केवल अपने-अपने देशों तक ही सीमित हैं।
(D) क्योंकि वे हिंसक तरीकों का समर्थन करते हैं।

167. 'विश्व सामाजिक मंच' (WSF) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(A) एक नई वैश्विक सरकार स्थापित करना।
(B) नव-उदारवादी वैश्वीकरण के विकल्पों पर चर्चा के लिए एक खुली जगह प्रदान करना।
(C) बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए धन एकत्र करना।
(D) एक विशिष्ट राजनीतिक दल का चुनाव प्रचार करना।

168. "एक और दुनिया संभव है" नारे का क्या अर्थ है?
(A) एक ऐसी दुनिया की कल्पना जो अधिक न्यायपूर्ण, टिकाऊ और समान हो।
(B) वर्तमान वैश्विक व्यवस्था ही एकमात्र संभव व्यवस्था है।
(C) दूसरे ग्रहों पर मानव बस्तियां बसाने की संभावना।
(D) दुनिया को वापस पूर्व-वैश्वीकरण युग में ले जाने का लक्ष्य।

169. ये आंदोलन मुख्य रूप से किन संस्थाओं की आलोचना करते हैं?
(A) स्थानीय स्कूलों और अस्पतालों की।
(B) सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों की।
(C) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और बहुराष्ट्रीय निगमों की।
(D) संयुक्त राष्ट्र की शांति सेनाओं की।

170. अनुच्छेद के अनुसार, वैकल्पिक वैश्वीकरण आंदोलनों की मुख्य मांग क्या नहीं है?
(A) व्यापार में निष्पक्षता
(B) ऋण माफी
(C) पर्यावरण संरक्षण
(D) अनियंत्रित कॉर्पोरेट शक्ति का समर्थन

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

भारत का वैश्वीकरण के साथ अनुभव विरोधाभासों और जटिलताओं से भरा रहा है। 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व के लिए खोल दिया, जिससे 'लाइसेंस राज' का अंत हुआ और व्यापार, विदेशी निवेश तथा प्रौद्योगिकी के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और सेवा क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि देखी, जिससे यह एक 'वैश्विक बैक ऑफिस' के रूप में उभरा। इससे शहरी क्षेत्रों में एक नए, समृद्ध मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिसकी पहुंच वैश्विक उपभोक्ता संस्कृति तक थी और जिसके पास नए अवसर थे। हालाँकि, इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। वैश्वीकरण के आलोचक भारत में बढ़ती आर्थिक असमानता की ओर इशारा करते हैं। जहाँ एक ओर सेवा क्षेत्र में उछाल आया, वहीं कृषि क्षेत्र संकट में पड़ गया, क्योंकि वैश्विक बाजार की प्रतिस्पर्धा और सरकारी समर्थन में कमी के कारण लाखों किसान प्रभावित हुए। छोटे पैमाने के उद्योग भी सस्ते विदेशी आयातों से प्रतिस्पर्धा करने में संघर्ष करते रहे। सामाजिक रूप से, इसने पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक जीवन शैली के बीच तनाव पैदा किया। इस प्रकार, भारत में वैश्वीकरण एक दोधारी तलवार साबित हुआ है, जिसने एक ओर आर्थिक अवसर और विकास के द्वार खोले हैं, तो दूसरी ओर इसने गंभीर सामाजिक-आर्थिक चुनौतियां और असमानताएं भी पैदा की हैं, जिनका समाधान अभी भी एक प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता है।

उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

171. भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया को गति देने वाली प्रमुख घटना कौन सी थी?
(A) 1947 में स्वतंत्रता की प्राप्ति
(B) 1971 का भारत-पाक युद्ध
(C) 1991 के आर्थिक सुधार
(D) 2008 की वैश्विक मंदी

172. स्रोत के अनुसार, भारत में वैश्वीकरण का एक सकारात्मक परिणाम क्या था?
(A) कृषि क्षेत्र में तीव्र वृद्धि।
(B) सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र का विकास।
(C) आर्थिक असमानता का पूर्ण उन्मूलन।
(D) छोटे पैमाने के उद्योगों का सुदृढ़ीकरण।

बदहाल करती है। वे इसे धनी देशों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों को साधने वाली प्रक्रिया मानते हैं, जिससे विकासशील देशों की आत्मनिर्भरता समाप्त होने का खतरा रहता है।

11. (A) 1, 3, 2, 4
ऐतिहासिक घटनाओं का क्रम वैश्वीकरण की यात्रा को दर्शाता है। भारत ने 1991 में आर्थिक सुधार अपनाए। इसके बाद 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की बैठक के विरुद्ध बड़े प्रदर्शन हुए। विश्व सामाजिक मंच की पहली बैठक 2001 में ब्राजील के पोर्टो अलगेरे में हुई, जबकि इसकी चौथी बैठक 2004 में मुंबई में आयोजित की गई थी। यह क्रम वैश्विक विरोध आंदोलनों को रेखांकित करता है।

12. (B) इसके कारण प्रत्येक संस्कृति और अधिक विशिष्ट तथा पृथक होती जाती है।
सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण के उस प्रभाव को दर्शाती है जहाँ प्रत्येक संस्कृति बाहरी प्रभावों को अपनाकर और अधिक विशिष्ट और अनूठी बन जाती है। यह सांस्कृतिक समरुपता के विपरीत है। इस प्रक्रिया में संस्कृतियाँ पूरी तरह लुप्त नहीं होतीं, बल्कि वे नई शैलियों और विकल्पों को जन्म देती हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक विविधता बनी रहती है और समृद्ध होती है।

13. (C) नव-उडरवादी वैश्वीकरण की नीतियों का विरोध करने वाला एक वैश्विक मंच।
विश्व सामाजिक मंच एक वैश्विक गठबंधन है जो नव-उदारवादी वैश्वीकरण की नीतियों का विरोध करता है। इसमें मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर और महिला आंदोलनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह मंच 'एक और दुनिया मुमकिन है' के नारे के साथ वैश्वीकरण के वैकल्पिक मॉडल की वकालत करता है। यह वैश्विक स्तर पर आर्थिक असमानता और कॉर्पोरेट प्रभुत्व के विरुद्ध एक सशक्त आवाज है।

14. (D) संरक्षणवाद - आयात पर प्रतिबंध लगाना
संरक्षणवाद एक ऐसी आर्थिक नीति है जिसके तहत कोई देश अपने घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए आयात पर प्रतिबंध या उच्च शुल्क लगाता है। भारत ने आजादी के बाद इसी नीति का पालन किया था ताकि स्थानीय उत्पादक विकसित हो सकें। यह वैश्वीकरण की मुक्त व्यापार नीति के विपरीत है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी बनाने का एक प्रयास माना जाता है।

15. (A) राष्ट्रों की सीमाओं का स्थायीकरण।
वैश्वीकरण में प्रवाह का अर्थ विचारों, पूँजी, वस्तुओं और लोगों की निरंतर आवाजाही है। राष्ट्रों की सीमाओं का स्थायीकरण या कड़ा होना इस प्रवाह के विपरीत अवधारणा है। वैश्वीकरण सीमाओं के पार पारस्परिकता को बढ़ावा देता है, जहाँ बाधाएँ कम होती हैं। यदि सीमाएँ पूरी तरह बंद या अपरिवर्तनीय हो जाएँ, तो यह प्रवाह अवरुद्ध हो जाएगा और वैश्वीकरण की मूल भावना ही समाप्त हो जाएगी।

16. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
इंटरनेट और कंप्यूटर सेवाओं के विस्तार ने सूचनाओं के आदान-प्रदान को अभूतपूर्व गति प्रदान की है। अब विचारों के प्रसार के लिए राष्ट्रों की भौगोलिक सीमाएँ कोई बड़ी बाधा नहीं रह गई हैं। लोग दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर तुरंत संवाद कर सकते हैं और जानकारी साझा कर सकते हैं। यह तकनीकी क्रांति वैश्वीकरण के वैचारिक प्रवाह को सुगम और अबाध बनाने में सहायक रही है।

17. (B) केबल नेटवर्क और विदेशी त्यौहारों जैसे विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों की चिंता के कारण।
भारत में वैश्वीकरण का दक्षिणपंथी विरोध मुख्य रूप से सांस्कृतिक चिंताओं पर आधारित है। वे केबल नेटवर्क के जरिए आने वाले विदेशी चैनलों, विदेशी त्यौहारों और पश्चिमी जीवनशैली के प्रसार को भारतीय परंपराओं के लिए खतरा मानते हैं। उनका तर्क है कि ये प्रभाव देश की मौलिक सांस्कृतिक पहचान को दूषित कर सकते हैं। इसलिए वे स्वदेशी मूल्यों और पारंपरिक जीवन-पद्धति की रक्षा पर बल देते हैं।

18. (B) केवल 1, 3 और 4
आर्थिक वैश्वीकरण के तहत धनी देशों के निवेशक विकासशील देशों में पूँजी निवेश कर सकते हैं। साथ ही, इंटरनेट के माध्यम से सेवाओं का व्यापक विस्तार हुआ है। हालाँकि, विकसित देश अपनी वीज़ा-नीति को कड़ा रखते हैं ताकि लोगों का प्रवाह उनकी शर्तों पर हो। वस्तुओं और पूँजी की तुलना में श्रम की आवाजाही पर अधिक प्रतिबंध होना आर्थिक वैश्वीकरण की एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण वास्तविकता है।

19. (C) सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण या संकरण
नीली जीन्स के ऊपर खादी का कुर्ता पहनना सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण या संकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें पश्चिमी पहनावे और स्थानीय परंपरा का अनूठा मेल होता है, जो एक नई सांस्कृतिक शैली को जन्म देता है। यह दर्शाता है कि वैश्वीकरण हमेशा स्थानीय संस्कृति को नष्ट नहीं करता, बल्कि बाहरी प्रभावों को स्वीकार कर उसे और अधिक रचनात्मक और विशिष्ट बनाने का अवसर भी देता है।

20. (D) शक्तिशाली देशों द्वारा व्यापार में अपनाए जा रहे अनुचित तौर-तरीकों का विरोध करना।
1999 में सिएटल में हुए विरोध प्रदर्शनों का मुख्य कारण विश्व व्यापार संगठन की नीतियों में शक्तिशाली देशों द्वारा अपनाए जा रहे अनुचित व्यापारिक तौर-तरीके थे। विकासशील देशों का मानना था कि व्यापार के नियम विकसित देशों के पक्ष में झुके हुए हैं। इन प्रदर्शनों ने आर्थिक वैश्वीकरण के उस स्वरूप को चुनौती दी जो केवल बड़े कॉर्पोरेट और समृद्ध राष्ट्रों के हितों को प्राथमिकता देता था।

21. (B) P-2, Q-3, R-1, S-4
विभिन्न वैश्विक घटनाओं और बैठकों का सही मिलान इनके ऐतिहासिक महत्व को स्पष्ट करता है। विश्व सामाजिक मंच की पहली बैठक 2001 में पोर्टो अलगेरे में हुई थी, जबकि

चौथी बैठक 2004 में मुंबई में आयोजित हुई। भारत ने अपने महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार 1991 में शुरु किए थे। वहीं, सिएटल में विश्व व्यापार संगठन के विरुद्ध बड़ा प्रदर्शन 1999 में अमेरिका में हुआ था।

22. (B) आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों पर वैश्वीकरण के दुष्प्रभावों को सीमित करना।
सामाजिक सुरक्षा कवच की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य समाज के उन वर्गों की रक्षा करना है जो वैश्वीकरण और मुक्त बाजार की प्रतिस्पर्धा में पिछड़ सकते हैं। यह नीति सुनिश्चित करती है कि आर्थिक उदारीकरण के दौर में भी गरीब और कमजोर लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं मिलती रहें। इसका लक्ष्य वैश्वीकरण के नकारात्मक आर्थिक प्रभावों से आम जनता को सुरक्षा प्रदान करना है।

23. (D) वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान अवधारणाएँ हैं।
वैश्वीकरण के बारे में यह धारणा गलत है कि यह केवल पश्चिमीकरण का ही दूसरा नाम है। वैश्वीकरण एक व्यापक और बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव शामिल है। हालाँकि इसमें पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव अधिक हो सकता है, लेकिन यह स्थानीय संस्कृतियों को भी विशिष्ट बनाता है। यह आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आयामों को समेटने वाली एक वैश्विक परिघटना है जो पश्चिमीकरण से अलग है।

24. (A) विदेशी निर्भरता कम करने और स्थानीय उत्पादकों को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए।
स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने संरक्षणवाद की नीति इसलिए अपनाई ताकि देश के नवजात उद्योगों को बाहरी प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सके। इसका लक्ष्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता को कम करना था। इस नीति के तहत आयात पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे ताकि स्थानीय उत्पादकों को फलने-फूलने का अवसर मिले और भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला मजबूत हो सके।

25. (C) 'मैक्डोनॉल्डीकरण' की प्रक्रिया का तीव्र होना।
मैक्डोनॉल्डीकरण वैश्वीकरण का एक सांस्कृतिक प्रभाव है, न कि राजनीतिक। राजनीतिक प्रभावों में मुख्य रुप से राज्य की क्षमता में कमी, लोक-कल्याणकारी कार्यों से राज्य का पीछे हटना और बहुराष्ट्रीय निगमों की बढ़ती भूमिका शामिल है। मैक्डोनॉल्डीकरण वैश्विक स्तर पर भोजन और जीवनशैली के अमेरिकीकरण को दर्शाता है, जो समाज के सांस्कृतिक ढांचे को प्रभावित करता है, जबकि राजनीतिक आयाम शासन और सत्ता से संबंधित हैं।

26. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
कुछ आलोचक आर्थिक वैश्वीकरण को 'पुनःउपनिवेशीकरण' मानते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि विकासशील देश फिर से विकसित राष्ट्रों पर आर्थिक रुप से निर्भर हो जाएंगे। उनका तर्क है कि मुक्त व्यापार और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रभुत्व से गरीब देशों के संसाधन शोषित होंगे और उनकी आर्थिक संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी। यह स्थिति अंततः गरीब जनता की बदहाली और राष्ट्रों की आर्थिक पराधीनता का कारण बन सकती है।

27. (D) इसके परिणामस्वरुप प्रत्येक देश को अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का अवसर मिलता है।
वैश्वीकरण के समर्थकों का मानना है कि मुक्त व्यापार और बढ़ती प्रतिस्पर्धा से आर्थिक कुशलता आती है। जब देश उन वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात करते हैं जिनमें वे श्रेष्ठ हैं, तो इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है और वैश्विक समृद्धि बढ़ती है। यह बाजार का तर्क है कि खुलापन और व्यापारिक मेल-जोल सभी भागीदारों के लिए आर्थिक विकास के नए द्वार खोलता है।

28. (B) केवल 2 और 3
वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह की गति और उसका व्यापक धरातल इसे पूर्ववर्ती काल की तुलना में अनूठा बनाते हैं। वर्तमान दौर में विचारों, वस्तुओं और पूँजी का प्रवाह अभूतपूर्व तीव्रता से हो रहा है। यही निरंतर प्रवाह विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव को जन्म देता है, जिससे दुनिया के विभिन्न हिस्से एक-दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। प्रौद्योगिकी ने इस प्रक्रिया को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

29. (C) सेवाओं के वैश्वीकरण का।
कॉल सेंटर में काम करने वाले जनार्दन का उदाहरण सेवाओं के वैश्वीकरण का एक स्पष्ट प्रमाण है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से विकसित देशों के काम अब विकासशील देशों में किए जा रहे हैं। इसमें कर्मचारी को ग्राहक की सुविधा के अनुसार अपने बोलने का लहजा और कार्य समय बदलना पड़ता है। यह दर्शाता है कि कैसे आधुनिक तकनीक और संचार ने श्रम और सेवाओं के वैश्विक व्यापार को सुगम बनाया है।

30. (D) क्योंकि इससे विश्व की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का धीरे-धीरे पूर्ण विनाश होता है।
वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों का विरोध इस तर्क पर आधारित है कि यह विश्व की सांस्कृतिक विविधता को नष्ट कर रहा है। इसके कारण पूरी दुनिया में एक ही प्रकार की 'विश्व-संस्कृति' हावी हो रही है, जो वास्तव में पश्चिमी संस्कृति का थोपा जाना है। इससे स्थानीय परंपराएं और अनूठी पहचानें समाप्त होने लगती हैं, जो संपूर्ण मानवता की साझा सांस्कृतिक विरासत के लिए एक बड़ा खतरा है।

31. (A) 1, 2, 3, 4
भारतीय वैश्वीकरण की यात्रा का ऐतिहासिक क्रम औपनिवेशिक दौर से शुरु होता है जब भारत कच्चे माल का निर्यातक था। आजादी के बाद देश ने संरक्षणवाद की नीति अपनाई। 1991 में आर्थिक संकट के कारण नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई। इसके पश्चात, वैश्वीकरण के दौर में स्थानीय ज्ञान और संपदा को बचाने के लिए 'नीम' जैसे पेटेंट के विरुद्ध सक्रिय विरोध प्रदर्शन शुरु हुए।

32. (B) इसका प्रभाव सभी पर समान रूप से सकारात्मक रहा है।
वैश्वीकरण के बारे में यह कहना गलत है कि इसका प्रभाव सभी पर समान रूप से सकारात्मक रहा है। वास्तविकता यह है कि वैश्वीकरण का प्रभाव अत्यंत विषम रहा है। जहाँ कुछ देशों और सामाजिक वर्गों को इससे बहुत अधिक लाभ हुआ है, वहीं कुछ अन्य लोग और राष्ट्र आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं। यह बहुआयामी परिघटना चुनौतियों और लाभों का एक मिश्रित परिणाम प्रस्तुत करती है।

33. (B) मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिला आंदोलनों से जुड़े कार्यकर्ता।
विश्व सामाजिक मंच (WSF) एक समावेशी मंच है जहाँ समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग एकजुट होकर नव-उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। इसमें मजदूर संगठन, पर्यावरण प्रेमी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होते हैं जो कॉर्पोरेट प्रभुत्व के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। यह समूह वैश्वीकरण के उस स्वरूप की मांग करता है जो केवल मुनाफे के बजाय सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों को प्राथमिकता दे सके।

34. (B) P-2, Q-1, R-4, S-3
वैश्वीकरण के विभिन्न आलोचकों की चिंताएं अलग-अलग हैं। वामपंथी आलोचक बढ़ती आर्थिक असमानता का विरोध करते हैं, जबकि दक्षिणपंथी समूह सांस्कृतिक पहचान के खतरे को लेकर चिंतित हैं। सामाजिक आंदोलन 'नीम' जैसे पारंपरिक ज्ञान के पेटेंट का विरोध करते हैं। अर्थशास्त्री इसे 'पुनःउपनिवेशीकरण' की संज्ञा देते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि यह गरीब देशों को फिर से आर्थिक रूप से गुलाम बना देगा।

35. (C) क्योंकि वे समान विचारधारा रखने वाले अन्य देशों के लोगों के साथ एकजुट होना चाहते हैं।
वैश्वीकरण-विरोधी आंदोलन स्वयं भी वैश्वीकरण के साधनों, जैसे इंटरनेट और वैश्विक संचार का उपयोग करते हैं। वे दुनिया भर में समान सोच रखने वाले लोगों के साथ जुड़कर एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क बनाते हैं। यह एकजुटता उन्हें शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अंतर-सरकारी संगठनों के खिलाफ एक प्रभावी वैश्विक आवाज उठाने में मदद करती है। इस प्रकार, वे वैश्वीकरण की तकनीक का उपयोग उसके ही विरुद्ध करते हैं।

36. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
वैश्वीकरण के युग में जहाँ राज्य के कार्यक्षेत्र में बदलाव आया है, वहीं उसकी शक्ति के कुछ नए आयाम भी उभरे हैं। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से राज्य अब अपने नागरिकों के बारे में व्यापक डेटा और सूचनाएं जुटा सकते हैं। इससे सरकारों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा प्रबंधन में अधिक कुशलता प्राप्त हुई है। इस प्रकार, तकनीक ने राज्य के प्रशासनिक नियंत्रण को पहले से अधिक मजबूत किया है।

37. (C) यह दर्शाता है कि वैश्वीकरण का प्रवाह सदैव केवल धनी मुल्कों से गरीब मुल्कों की ओर नहीं होता।
एक भारतीय कंपनी द्वारा यूरोपीय कंपनी का अधिग्रहण करना यह सिद्ध करता है कि वैश्वीकरण का प्रवाह एकतरफा नहीं है। यह केवल धनी देशों से गरीब देशों की ओर ही नहीं जाता, बल्कि विकासशील देशों की कंपनियां भी अब वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो रही हैं। यह प्रक्रिया वैश्वीकरण के बहु-दिशीय स्वरूप को रेखांकित करती है, जहाँ उभरती अर्थव्यवस्थाएं भी विकसित बाजारों में अपना प्रभाव बढ़ा रही हैं।

38. (B) केवल 2 और 5
वैश्वीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के परिणाम हो सकते हैं। एक ओर जहाँ इसने व्यापार और समृद्धि के अवसर बढ़ाए हैं, वहीं दूसरी ओर इसने आर्थिक विषमता और सांस्कृतिक खतरे भी पैदा किए हैं। आलोचकों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि इसके लाभों की तुलना में इसके नुकसान, विशेषकर गरीब देशों और कमजोर वर्गों के लिए, अधिक विनाशकारी हो सकते हैं।

39. (D) एक राज्य जो स्वयं को केवल कानून-व्यवस्था और सुरक्षा जैसे अनिवार्य कार्यों तक सीमित रखता है।
न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य की अवधारणा शास्त्रीय उदारवाद पर आधारित है, जो वैश्वीकरण के दौर में पुनर्जीवित हुई है। इसके तहत राज्य आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में कम से कम दखल देता है। राज्य का मुख्य दायित्व अब केवल बाहरी आक्रमण से सुरक्षा और आंतरिक कानून-व्यवस्था बनाए रखना रह गया है। यह मॉडल लोक-कल्याणकारी कार्यों से राज्य के पीछे हटने और बाजार की स्वतंत्रता का समर्थन करता है।

40. (A) बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश का।
भारत में औद्योगिक श्रमिकों और किसानों के संगठनों ने वैश्वीकरण के आर्थिक आयामों का कड़ा विरोध किया है। उनकी मुख्य चिंता घरेलू बाजारों में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अनियंत्रित प्रवेश है। उनका मानना है कि इन निगमों के आने से स्थानीय उद्योगों और छोटे किसानों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। वे इसे बड़े पूँजीपतियों के पक्ष में काम करने वाली एक अनुचित प्रक्रिया के रूप में देखते हैं।

41. (C) विश्व सामाजिक मंच - नव-उडरवाद का समर्थक
विश्व सामाजिक मंच (WSF) के बारे में यह कथन गलत है कि वह नव-उदारवाद का समर्थक है। वास्तव में, WSF का गठन ही नव-उदारवादी नीतियों और कॉर्पोरेट वैश्वीकरण के विरोध में किया गया था। यह मंच वैश्वीकरण के वैकल्पिक मॉडल की वकालत करता है जो मानवाधिकारों, सामाजिक न्याय और पर्यावरण की सुरक्षा पर केंद्रित हो। अन्य विकल्प जैसे प्रवाह, प्रौद्योगिकी और संरक्षणवाद अपनी व्याख्या में बिल्कुल सही हैं।

84. (1, 3, 2, 4)
भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रतिरोध का ऐतिहासिक क्रम व्यवस्थित है। भारत ने स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक संरक्षणवाद की नीति अपनाई। 1991 में आर्थिक संकट के बाद नई आर्थिक नीति लागू की गई। इसके बाद 1999 में सिएटल में WTO के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए। अंततः 2004 में मुंबई में विश्व सामाजिक मंच की बैठक आयोजित की गई, जो वैश्वीकरण-विरोधी नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था।

85. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
वैश्वीकरण केवल संस्कृतियों को एक जैसा नहीं बनाता, बल्कि यह सांस्कृतिक विभिन्नता को भी बढ़ाता है। जब बाहरी प्रभाव स्थानीय संस्कृति के साथ मिलते हैं, तो वे एक नई और अनूठी शैली को जन्म देते हैं, जैसे नीली जीन्स और खादी कुर्ते का संयोजन। यह प्रक्रिया दर्शाती है कि वैश्वीकरण संस्कृतियों को पूरी तरह समाप्त करने के बजाय उन्हें नए और रचनात्मक रूपों में ढलने का अवसर प्रदान करता है।

86. (B) क्योंकि कुछ अमरीकी यह मानते हैं कि भारतीय उनकी नौकरियां छीन रहे हैं।
कॉल सेंटर कर्मचारियों को नस्लीय टिप्पणियों का सामना आर्थिक असुरक्षा के कारण करना पड़ता है। विकसित देशों, विशेषकर अमेरिका में, एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि आउटसोर्सिंग के कारण उनकी नौकरियां भारत जैसे देशों में जा रही हैं। यह धारणा स्थानीय लोगों के बीच कुंठा और नफरत पैदा करती है, जो अक्सर भारतीय कर्मचारियों के प्रति दुर्व्यवहार के रूप में बाहर आती है। यह वैश्वीकरण के कारण उत्पन्न श्रम बाजार के तनाव का परिणाम है।

87. (D) कि वैश्वीकरण ने चुनौतियाँ पेश की हैं और बुद्धिमत्ता से इसका सामना किया जाना चाहिए।
आर्थिक वैश्वीकरण के मध्यमार्गी समर्थकों का दृष्टिकोण व्यावहारिक और संतुलित है। वे वैश्वीकरण को एक अपरिहार्य ऐतिहासिक प्रक्रिया मानते हैं जिसे पूरी तरह रोका नहीं जा सकता। हालाँकि, वे इसके कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों, जैसे आर्थिक असमानता और सांस्कृतिक ह्रास, को स्वीकार करते हैं। उनका मानना है कि बुद्धिमत्तापूर्ण नीतियों और उचित रणनीतियों के माध्यम से वैश्वीकरण के लाभों को अधिकतम और नुकसान को न्यूनतम किया जा सकता है।

88. (A) विश्वव्यापी 'पारस्परिक जुड़ाव'
वैश्वीकरण के अंतर्गत विचारों, पूँजी, वस्तुओं और लोगों की निरंतर आवाजाही मिलकर विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का निर्माण करती है। यह जुड़ाव दुनिया के विभिन्न देशों और समाजों को एक-दूसरे पर निर्भर बनाता है। जब एक स्थान पर होने वाली घटना का प्रभाव दूसरे दूरदराज के स्थानों पर पड़ता है, तो यह स्पष्ट होता है कि प्रवाहों की इस निरंतरता ने संपूर्ण विश्व को एक एकीकृत तंत्र में बदल दिया है।

89. (C) क्योंकि वैश्वीकरण की प्रक्रिया से वास्तव में सांस्कृतिक विभिन्नता भी निरंतर बढ़ती है।
वैश्वीकरण के समर्थकों का यह तर्क अधूरा है कि इससे केवल सांस्कृतिक समरूपता आएगी। वास्तविकता यह है कि वैश्वीकरण के कारण संस्कृतियां आपस में मिलकर नए रूपों को जन्म देती हैं, जिससे सांस्कृतिक विविधता बढ़ती है। बाहरी प्रभाव अक्सर स्थानीय परंपराओं को नष्ट करने के बजाय उन्हें और अधिक विशिष्ट और आधुनिक बना देते हैं। इस प्रकार, वैश्वीकरण एकरसता के बजाय विश्व में विविध और मिश्रित सांस्कृतिक पहचानों को बढ़ावा देता है।

90. (A) बाहरी खाद्य पदार्थों के आने से भोजन की पसंद में केवल वृद्धि होती है।
'बर्गर मसाला-डोसा का विकल्प नहीं है' का अर्थ है कि विदेशी व्यंजनों के आने से स्थानीय भोजन समाप्त नहीं हो जाता। इसके विपरीत, लोगों के पास भोजन के अधिक विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं। बर्गर और डोसा दोनों अपनी जगह बने रहते हैं, जिससे उपभोक्ताओं की पसंद का दायरा बढ़ता है। यह वैश्वीकरण के उस पहलू को दर्शाता है जहाँ वैश्विक उत्पाद स्थानीय उत्पादों के साथ सह-अस्तित्व में रहते हैं, न कि उन्हें विस्थापित करते हैं।

91. (B) P-3, Q-4, R-1, S-2
विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों और नीतियों की भूमिकाएं स्पष्ट हैं। विश्व व्यापार संगठन व्यापारिक नियमों का निर्धारण करता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष वित्तीय स्थिरता और ऋण नीतियों से संबंधित है। संरक्षणवाद घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात पर रोक लगाने की नीति है। विश्व सामाजिक मंच इन सभी नव-उदारवादी नीतियों का विरोध करने वाला एक प्रमुख वैश्विक नागरिक मंच है, जो वैकल्पिक वैश्वीकरण की मांग करता है।

92. (B) केवल 3 और 5
भारत में वैश्वीकरण का विरोध केवल एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक हलकों से आता है। नीम जैसी पारंपरिक वनस्पतियों के पेटेंट के प्रयासों का कड़ा विरोध इसका एक प्रमुख उदाहरण है। यह विरोध देश की बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कब्जे से बचाने के लिए किया गया, जो वैश्वीकरण के प्रति भारतीय समाज की जागरुकता को दर्शाता है।

93. (C) राज्य की भूमिका बदली है, लेकिन वे आज भी व्यवस्था में प्रमुख हैं।
वैश्वीकरण के कारण राज्य की संप्रभुता के स्वरूप में परिवर्तन आया है, लेकिन राज्य अप्रासंगिक नहीं हुए हैं। आज भी राज्य ही कानून-व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्राथमिक उत्तरदायी संस्था हैं। यद्यपि बाजार की भूमिका बढ़ी है, फिर भी राज्य की प्रशासनिक और विधायी शक्तियां आज भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति और समाज के संचालन के लिए अनिवार्य और केंद्रीय बनी हुई हैं।

53. (C) पुनःउपनिवेशीकरण
पुनःउपनिवेशीकरण की अवधारणा उन आर्थिक आलोचकों से जुड़ी है जो वैश्वीकरण को गरीब देशों के लिए घातक मानते हैं। उनका तर्क है कि मुक्त व्यापार के बहाने बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकासशील देशों के संसाधनों पर कब्जा कर लेंगी। इससे ये देश आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएंगे और उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता केवल नाममात्र की रह जाएगी। यह स्थिति पुराने दौर के उपनिवेशवाद की एक नई और आधुनिक आर्थिक शक्ल है।

54. (A) केवल 1, 2 और 3
भारत और वैश्वीकरण के संबंध में ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि औपनिवेशिक काल में भारत कच्चे माल का निर्यातक था। आजादी के बाद आत्मनिर्भरता हेतु संरक्षणवाद की नीति अपनाई गई। 1991 के आर्थिक संकट ने भारत को सुधारों के लिए प्रेरित किया। हालाँकि, यह कहना गलत है कि आर्थिक सुधारों का एकमात्र उद्देश्य व्यापार था या इनका कोई विरोध नहीं हुआ; वास्तव में इनका व्यापक सामाजिक विरोध भी हुआ।

55. (D) सांस्कृतिक प्रभाव और उसके दक्षिणपंथी प्रतिरोध का उदाहरण।
पश्चिमी परिधानों के कारण छात्राओं को धमकी देना वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव के प्रति दक्षिणपंथी प्रतिक्रिया को दर्शाता है। ऐसे समूह मानते हैं कि वैश्वीकरण के जरिए आने वाली पश्चिमी जीवनशैली पारंपरिक नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक पहचान को नष्ट कर रही है। यह प्रतिरोध केवल पहनावे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन विदेशी सांस्कृतिक प्रभावों के विरुद्ध एक वैचारिक संघर्ष है जो स्थानीय परंपराओं को चुनौती देते हैं।

56. (B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
वैश्वीकरण ने राज्य की संप्रभुता को कुछ हद तक सीमित किया है, लेकिन राज्य अभी भी राजनीतिक समुदाय के आधार के रूप में बने हुए हैं। राज्य आज भी सुरक्षा और कानून-व्यवस्था जैसे अनिवार्य कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। हालाँकि, आधुनिक तकनीक के कारण राज्यों की कार्यक्षमता बढ़ी है, फिर भी राज्य की प्रधानता की निरंतरता और तकनीक द्वारा सूचना जुटाना दो अलग-अलग पहलु हैं जो एक साथ अस्तित्व में हैं।

57. (C) नकारात्मक आर्थिक प्रभाव
बहुराष्ट्रीय कंपनियों से महंगे बीज खरीदने के कारण किसानों की आत्महत्या वैश्वीकरण के गंभीर नकारात्मक आर्थिक प्रभाव को दर्शाती है। यह इंगित करता है कि कैसे कृषि क्षेत्र में कॉर्पोरेट प्रभुत्व और बढ़ती लागत छोटे किसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। यह आर्थिक असमानता और संसाधनों के गलत वितरण का परिणाम है, जहाँ वैश्विक व्यापारिक नीतियां स्थानीय आजीविका की सुरक्षा करने में अक्सर विफल हो जाती हैं।

58. (B) P-2, Q-4, R-1, S-3
वैश्वीकरण के विभिन्न प्रभावों का मिलान इसके व्यापक स्वरूप को समझाता है। राजनीतिक प्रभाव के रूप में कल्याणकारी राज्य का क्षरण हो रहा है, जबकि आर्थिक रूप से वस्तुओं के व्यापार में भारी वृद्धि हुई है। सांस्कृतिक रूप से 'मैक्डोनॉल्डीकरण' की प्रक्रिया वैश्विक पहचानों को प्रभावित कर रही है। वहीं, प्रौद्योगिकीय प्रभाव संचार क्रांति के रूप में सामने आया है, जिसने पूरी दुनिया को एक सूचना नेटवर्क में बांध दिया है।

59. (D) यह साम्राज्यवाद का एक रूप माना जाता है।
विश्व सामाजिक मंच (WSF) के बारे में यह कहना गलत है कि यह साम्राज्यवाद का रूप है। इसके विपरीत, WSF एक ऐसा संगठन है जो साम्राज्यवाद और नव-उदारवादी वैश्वीकरण का पुरजोर विरोध करता है। इसकी स्थापना ही विकासशील देशों के हितों की रक्षा और वैश्विक न्याय के लिए की गई थी। अन्य सभी तथ्य जैसे इसकी पहली बैठक ब्राजील में होना और चौथी बैठक मुंबई में होना, बिल्कुल सही हैं।

60. (B) विश्व-संस्कृति के नाम पर पश्चिमी संस्कृति का थोपा जाना।
सांस्कृतिक समरूपता का अर्थ है कि पूरी दुनिया की संस्कृतियाँ धीरे-धीरे एक जैसी होती जा रही हैं। यह प्रक्रिया वास्तव में अमेरिकी और पश्चिमी जीवनशैली के वैश्विक प्रसार का परिणाम है। इसके तहत लोग अपनी स्थानीय विशिष्टताओं को छोड़कर एक वैश्विक सांचे में ढलने लगते हैं। इससे सांस्कृतिक विविधता का ह्रास होता है और दुनिया भर में पसंद-नापसंद का दायरा सीमित हो जाता है, जिससे सांस्कृतिक धरोहर संकट में है।

61. (C) केवल 1, 2, 3 और 4
वैश्वीकरण के कारण राज्य की भूमिका में जटिल परिवर्तन आए हैं। एक ओर राज्य लोक-कल्याणकारी कार्यों से हाथ खींचकर न्यूनतम हस्तक्षेपकारी बन गए हैं, जिससे वे कुछ मायनों में कमजोर हुए हैं। दूसरी ओर, अत्याधुनिक तकनीक ने राज्यों को अपने नागरिकों पर बेहतर नियंत्रण रखने की शक्ति दी है, जिससे वे अधिक ताकतवर और प्रभावी हुए हैं। इस प्रकार, राज्य की शक्ति का ह्रास और विकास दोनों साथ-साथ हो रहे हैं।

62. (D) क्योंकि विकसित देश वीज़ा-नीति के ज़रिए अपनी सीमाओं को अभेद्य रखते हैं।
वैश्वीकरण में वस्तुओं और पूँजी का प्रवाह तो अत्यंत सरल हो गया है, लेकिन लोगों की आवाजाही पर विकसित देशों ने कड़े नियंत्रण लगा रखे हैं। ये देश अपनी वीज़ा नीतियों को सख्त बनाकर विदेशी नागरिकों के प्रवेश को रोकते हैं ताकि उनके स्थानीय रोजगार और सामाजिक ढांचे पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। यह विरोधाभास दर्शाता है कि श्रम का वैश्विक बाजार अभी भी बाधाओं से मुक्त नहीं है।

63. (A) आर्थिक प्रभाव, जिससे गरीब देशों के और गरीब होने की आशंका है।
अर्थशास्त्रियों द्वारा 'पुनःउपनिवेशीकरण' शब्द का प्रयोग आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में किया गया है। उन्हें आशंका है कि मुक्त व्यापार और विदेशी निवेश के कारण गरीब देश फिर

से अमीर राष्ट्रों के आर्थिक चंगुल में फंस जाएंगे। इससे इन देशों की स्वतंत्र आर्थिक नीतियां बनाने की क्षमता समाप्त हो जाएगी और वे एक बार फिर बड़ी शक्तियों के आर्थिक उपनिवेश बनकर रह जाएंगे, जिससे गरीबी और बढ़ेगी।

64. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
भारत में वैश्वीकरण का विरोध विभिन्न वैचारिक आधारों पर हुआ है। वामपंथी दल मुख्य रूप से आर्थिक परिणामों और बढ़ती असमानता को लेकर चिंतित हैं। वहीं, दक्षिणपंथी खेमा वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों और पारंपरिक भारतीय मूल्यों के ह्रास को लेकर विरोध प्रदर्शन करता है। ये दोनों ही दृष्टिकोण वैश्वीकरण के अलग-अलग पहलुओं को चुनौती देते हैं, जो समाज में इसके प्रति गहरी चिंता और असंतोष को व्यक्त करते हैं।

65. (B) विचारों के तीव्र प्रवाह और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की प्रक्रिया को।
हॉलीवुड फिल्म की कहानी का भारतीय फिल्मों में उपयोग होना वैश्वीकरण के कारण होने वाले विचारों के तीव्र प्रवाह को दर्शाता है। इंटरनेट और संचार माध्यमों ने कला और संस्कृति के आदान-प्रदान को बहुत आसान बना दिया है। हालाँकि इसे कभी-कभी साहित्यिक चोरी माना जाता है, लेकिन यह वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक प्रभावों के एक-दूसरे में घुलने-मिलने और प्रेरणा लेने की प्रक्रिया का भी एक प्रमुख उदाहरण है।

66. (A) वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है।
वैश्वीकरण की सबसे सटीक परिभाषा विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव है। यह केवल आर्थिक या भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विचारों, पूँजी, सेवाओं और लोगों का वैश्विक आदान-प्रदान शामिल है। यह प्रक्रिया दुनिया के विभिन्न हिस्सों को एक-दूसरे पर निर्भर बनाती है और वैश्विक मुद्दों के प्रति साझा जिम्मेदारी की भावना विकसित करती है। यह एक निरंतर चलने वाली बहुआयामी वैश्विक परिघटना है।

67. (C) केवल 1, 2, 3 और 4
भारत में वैश्वीकरण का विरोध समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा अलग-अलग कारणों से किया गया है। वामपंथी दलों और मजदूर संगठनों ने आर्थिक उदारीकरण का विरोध किया, जबकि दक्षिणपंथी समूहों ने सांस्कृतिक पश्चिमीकरण पर आपत्ति जताई। इंडियन सोशल फोरम जैसे नागरिक मंचों ने भी कॉर्पोरेट नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। हालाँकि 'नीम' के पेटेंट का भी कड़ा विरोध हुआ था, जो वैश्वीकरण के प्रति भारतीय प्रतिरोध का हिस्सा है।

68. (D) वैश्वीकरण के प्रति भ्रम, अनिश्चितता और विविध दृष्टिकोणों की उपस्थिति।
विश्व सामाजिक मंच के संदर्भ में यह भ्रम वैश्वीकरण की जटिलता को दर्शाता है। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिणाम पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं और इसके लाभ-हानि पर विशेषज्ञों के बीच भी गहरे मतभेद हैं। यह अनिश्चितता इस बात की ओर संकेत करती है कि वैश्वीकरण का कोई एक सरल समाधान या प्रभाव नहीं है, बल्कि यह निरंतर बहस और विकल्पों की खोज का विषय है।

69. (C) कोमिन्टर्न जैसा संगठन बनाना जो समूचे आंदोलन का प्रवक्ता बने।
'एक और दुनिया मुमकिन है' की भावना विविधता और लोकतांत्रिक चर्चा पर आधारित है। कोमिन्टर्न जैसा कोई केंद्रीय संगठन बनाना इस भावना के विरुद्ध होगा क्योंकि वह आंदोलन की बहुलता और स्वायत्तता को समाप्त कर देगा। विश्व सामाजिक मंच के सदस्य किसी एक प्रवक्ता के बजाय सभी की स्वतंत्र आवाज और स्थानीय विकल्पों के निर्माण में विश्वास रखते हैं, ताकि वैश्वीकरण का विरोध एक सामूहिक और समावेशी प्रक्रिया बनी रहे।

70. (A) P-4, Q-1, R-2, S-3
वैश्वीकरण के विभिन्न क्षेत्रों और उनके परिणामों का मिलान इसके समग्र प्रभाव को स्पष्ट करता है। राजनीतिक रूप से राज्य की क्षमता में कमी आई है, जबकि आर्थिक आयाम में वैश्विक व्यापार में भारी वृद्धि हुई है। सांस्कृतिक रूप से 'मैक्डोनॉल्डीकरण' के माध्यम से पश्चिमी प्रभाव बढ़ रहा है। सामाजिक स्तर पर वैश्वीकरण के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए 'सामाजिक सुरक्षा कवच' जैसी अवधारणाएं महत्वपूर्ण हो गई हैं।

71. (A) 2, 1, 3, 4
प्रौद्योगिकी के विकास का ऐतिहासिक क्रम वैश्वीकरण की गति को समझने में सहायक है। सबसे पहले छपाई की तकनीक ने विचारों के प्रसार में क्रांति लाई। इसके बाद टेलीग्राफ और टेलीफोन ने संचार को तात्कालिक बनाया। माइक्रोचिप के आविष्कार ने सूचनाओं के भंडारण और प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ाई। अंततः, इंटरनेट और कंप्यूटर सेवाओं ने दुनिया को एक डिजिटल नेटवर्क में बांधकर वैश्वीकरण को अपनी चरम सीमा पर पहुँचाया।

72. (A) प्रौद्योगिकी के माध्यम से राज्य अधिक कारगर ढंग से सूचनाएं जुटाकर कार्य कर सकते हैं।
राज्य के कमजोर होने के तर्क के विपरीत यह दलील दी जाती है कि आधुनिक तकनीक ने राज्य को अधिक शक्तिशाली बनाया है। कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से सरकारें अपने नागरिकों के बारे में सटीक डेटा एकत्र कर सकती हैं। यह सूचना तंत्र राज्य को कानून-व्यवस्था बनाए रखने, संसाधनों के प्रबंधन और आतंकवाद जैसी चुनौतियों का सामना करने में अधिक सक्षम बनाता है, जिससे राज्य की प्रशासनिक ताकत बढ़ती है।

73. (C) वे वैश्वीकरण के किसी खास कार्यक्रम के विरोधी हैं जिसे वे साम्राज्यवाद मानते हैं।
वैश्वीकरण-विरोधी आंदोलन अधिकांशतः वैश्वीकरण की पूरी अवधारणा के दुश्मन नहीं हैं। उनका मुख्य विरोध उन विशिष्ट कार्यक्रमों और नीतियों से है जो विकासशील देशों के संसाधनों का शोषण करती हैं और जिन्हें वे साम्राज्यवाद का नया रूप मानते हैं। वे वैश्वीकरण के ऐसे स्वरूप की मांग करते हैं जो सामाजिक न्याय, स्थानीय अधिकारों और पर्यावरण की सुरक्षा

सुनिश्चित कर सके, न कि केवल बड़े कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुँचाए।

74. (A) केवल 1 और 2
छपाई की तकनीक ने वास्तव में राष्ट्रवाद की वैचारिक आधारशिला रखी थी क्योंकि इसने साझा विचारों को प्रसारित करना संभव बनाया। इसी प्रकार, आधुनिक प्रौद्योगिकी न केवल संचार को प्रभावित करती है बल्कि हमारे सोचने के तरीके और विश्व के प्रति हमारे नजरिए को भी बदल देती है। हालाँकि, यह कहना गलत है कि पूँजी का प्रवाह लोगों से कम है या वैश्विक आपदाएं राष्ट्रीय सीमाओं तक ही सीमित रहती हैं।

75. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
आर्थिक वैश्वीकरण पर जनमत गहरे मतभेदों में बँटा हुआ है। जहाँ एक ओर समर्थक इसे समृद्धि और खुशहाली का द्वार मानते हैं, वहीं आलोचक इसे आर्थिक विषमता बढ़ाने वाला मानते हैं। समर्थकों का मानना है कि खुलेपन से व्यापार बढ़ता है, जबकि आलोचकों का तर्क है कि इससे धनी लोग और अधिक धनी होते हैं और गरीब देशों का शोषण बढ़ता है, जिससे समाज में असंतोष उत्पन्न होता है।

76. (B) एक आलोचनात्मक और वामपंथी दृष्टिकोण।
यह कथन कि नव-उदारवाद पूँजीवाद का खतरनाक रूप है, वैश्वीकरण के प्रति वामपंथी और आलोचनात्मक दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। ऐसे आलोचक मानते हैं कि वैश्वीकरण के पीछे की विचारधारा केवल धनी पूँजीपतियों के हितों की रक्षा करती है। वे इसे एक नए प्रकार के आर्थिक शोषण के रूप में देखते हैं जो विकासशील देशों की आत्मनिर्भरता को खत्म कर उन्हें पुनः आर्थिक गुलामी की ओर धकेल रहा है।

77. (C) अलोकतांत्रिक तरीकों और साम्राज्यवादी देशों के धन पर निर्भरता को उजागर करने के लिए।
मुंबई प्रतिरोध 2004 ने विश्व सामाजिक मंच (WSF) का विरोध इसलिए किया क्योंकि उनका मानना था कि WSF के तरीके अलोकतांत्रिक हैं। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि यह मंच साम्राज्यवादी देशों से मिलने वाले धन पर निर्भर है, जो इसके मूल उद्देश्यों को प्रभावित कर सकता है। यह विरोध वैश्वीकरण विरोधी आंदोलनों के भीतर मौजूद आंतरिक मतभेदों और वैचारिक संघर्षों को स्पष्ट रूप से उजागर करता है।

78. (D) एन.जी.ओ. संघर्ष को सुधारवाद की ओर मोड़कर पूंजीवादी व्यवस्था बनाए रखने में मदद करते हैं।
वैश्वीकरण के कुछ कट्टर आलोचक एन.जी.ओ. को साम्राज्यवाद के औजार के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि ये संगठन जनता के क्रांतिकारी संघर्षों को छोटे-मोटे सुधारों की ओर मोड़ देते हैं, जिससे पूँजीवादी व्यवस्था सुरक्षित बनी रहती है। उनके अनुसार, एन.जी.ओ. व्यवस्थागत बदलाव के बजाय केवल लक्षणों का इलाज करते हैं, जिससे समाज में बुनियादी परिवर्तन नहीं हो पाता और साम्राज्यवाद का प्रभुत्व बना रहता है।

79. (A) अवसरों के साथ परंपरागत मूल्यों और नई जीवन-शैली के बीच दुविधा।
वैश्वीकरण के युग में सारिका जैसी युवा पीढ़ी के सामने करियर के अपार अवसर मौजूद हैं, लेकिन यह स्थिति अपने साथ सांस्कृतिक दुविधाएं भी लेकर आती है। नए व्यवसायों और वैश्विक जीवनशैली को अपनाने के साथ-साथ परिवार और समाज के पारंपरिक मूल्यों के साथ तालमेल बिठाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यह उदाहरण वैश्वीकरण के उस व्यक्तिगत और सामाजिक प्रभाव को दर्शाता है जहाँ आधुनिकता और परंपरा के बीच निरंतर संघर्ष बना रहता है।

80. (C) P-2, Q-3, R-1, S-4
विभिन्न वैश्विक प्रदर्शनों और कलात्मक प्रस्तुतियों का मिलान वैश्वीकरण के प्रति समाज की प्रतिक्रियाओं को स्पष्ट करता है। न्यूयॉर्क में गरीबी के विरुद्ध प्रदर्शन वैश्विक असमानता को उजागर करता है। हांगकांग में WTO का विरोध व्यापार नीतियों की आलोचना है। जैकेट पर बेगानेपन का संदेश आधुनिक जीवन के अलगाव को दर्शाता है, जबकि कलाकारों द्वारा पारंपरिक वेशभूषा का प्रदर्शन सांस्कृतिक पहचान को बचाने का एक प्रयास है।

81. (A) केवल 1, 2 और 3
वैश्वीकरण के बारे में यह मानना गलत है कि यह केवल सकारात्मक है, शुद्ध रूप से आर्थिक है या इसका प्रभाव सभी देशों पर एक समान है। वास्तविकता में, वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है जिसके परिणाम अत्यंत विषम और विरोधाभासी हो सकते हैं। यह जहाँ कुछ क्षेत्रों में विकास लाता है, वहीं अन्य क्षेत्रों में आर्थिक और सांस्कृतिक चुनौतियां भी पेश करता है। इसलिए इसके प्रभावों का मूल्यांकन संतुलित दृष्टिकोण से करना आवश्यक है।

82. (A) आर्थिक फायदों के बँटवारे पर, यानी किसे फायदा हुआ और किसे कम।
आर्थिक वैश्वीकरण को समझने के लिए केवल व्यापारिक आँकड़ों को देखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि फायदों के वितरण पर ध्यान देना अनिवार्य है। यह विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है कि वैश्वीकरण की नीतियों से किस देश या सामाजिक वर्ग की आय बढ़ी और कौन पिछड़ गया। लाभों का यह असमान वितरण ही वैश्वीकरण के प्रति बढ़ते विरोध और असंतोष का मुख्य कारण है, जिसे समझना समग्र विश्लेषण के लिए आवश्यक है।

83. (C) हर संस्कृति हर समय बाहरी प्रभावों को स्वीकार करते रहती है।
संस्कृति के बारे में यह सत्य है कि वह कोई स्थिर या जड़ वस्तु नहीं है। संस्कृतियां गतिशील होती हैं और समय के साथ बाहरी प्रभावों को अपनाकर विकसित होती हैं। वैश्वीकरण इस प्रक्रिया को तेज करता है, जिससे संस्कृतियों में नए तत्व जुड़ते हैं। बाहरी प्रभाव हमेशा नकारात्मक नहीं होते, बल्कि वे अक्सर स्थानीय संस्कृति को नई दिशा और विकल्प प्रदान करते हैं, जिससे वह और अधिक समृद्ध और विविधतापूर्ण बनती है।

104. (A) वैश्विक ब्रांडों द्वारा स्थानीय बाज़ारों के अनुरुप स्वयं को ढालने की प्रक्रिया।
'मैकअरेबिया' जैसे उत्पाद 'ग्लॉकलाइज़ेशन' या स्थानीयकरण का उदाहरण हैं, जहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय ग्राहकों की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार अपने उत्पादों में बदलाव करती हैं। यह दर्शाता है कि वैश्विक ब्रांडों को अपनी सफलता के लिए स्थानीय जड़ों से जुड़ना पड़ता है। यह प्रक्रिया वैश्वीकरण के उस लचीलेपन को उजागर करती है जहाँ वैश्विक मानक और स्थानीय स्वाद मिलकर एक नया उपभोक्ता अनुभव और बाजार तैयार करते हैं।

105. (C) वे आर्थिक वैश्वीकरण के खिलाफ वामपंथी तेवर की आवाज उठाते हैं।
भारत में 'इंडियन सोशल फोरम' जैसे संगठन नागरिक समाज की उस आवाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आर्थिक वैश्वीकरण की आलोचना करती है। इनका झुकाव वामपंथी विचारधारा की ओर होता है और ये कॉर्पोरेट प्रभुत्व, निजीकरण और आर्थिक विषमता के विरुद्ध प्रदर्शन करते हैं। ये मंच आम जनता और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं और सरकार की उन नीतियों को चुनौती देते हैं जिन्हें वे जन-विरोधी मानते हैं।

106. (B) भारत में वैश्वीकरण का विरोध समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा विभिन्न आधारों पर किया गया है।
भारत में वैश्वीकरण का विरोध एक जटिल और बहुस्तरीय प्रक्रिया रही है। जहाँ राजनीतिक दलों ने इसे आर्थिक और सांस्कृतिक स्वायत्तता पर हमले के रुप में देखा, वहीं किसानों और पर्यावरणवादियों ने इसे जैविक संपदा के शोषण के रुप में चुनौती दी। यह विविधता दर्शाती है कि वैश्वीकरण का कोई भी पहलू भारतीय समाज में बिना जांच और आलोचना के स्वीकार नहीं किया गया है, बल्कि इसके हर आयाम पर व्यापक सामाजिक बहस हुई है।

107. (D) लक्ष्य 10: असमानता में कमी
सतत विकास लक्ष्य 10 सीधे तौर पर वैश्वीकरण के उस नकारात्मक प्रभाव को संबोधित करता है जो आर्थिक और सामाजिक असमानता बढ़ाता है। वैश्वीकरण के कारण अमीर और गरीब देशों के बीच, तथा एक ही देश के भीतर अलग-अलग वर्गों के बीच खाई बढ़ी है। यह लक्ष्य देशों के भीतर और उनके बीच समानता को बढ़ावा देने की वकालत करता है, ताकि वैश्वीकरण के लाभ सभी तक न्यायपूर्ण तरीके से पहुँच सकें।

108. (D) उपरोक्त सभी
वैश्वीकरण के कारण राज्य की भूमिका में आए सभी परिवर्तन सत्य हैं। राज्य अब लोक-कल्याण से हटकर कानून-व्यवस्था तक सीमित हो गए हैं और बाजार प्राथमिकताओं का निर्धारण करता है। बहुराष्ट्रीय निगमों का दखल बढ़ा है, लेकिन साथ ही तकनीक ने राज्यों को नागरिकों पर निगरानी रखने की नई शक्ति दी है। यह विरोधाभास दर्शाता है कि आधुनिक राज्य आज भी अनिवार्य कार्यों के लिए व्यवस्था का केंद्र बना हुआ है और महत्वपूर्ण है।

109. (C) यह केवल नकारात्मक हैं क्योंकि इससे पसंदों में कमी आती है।
वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में यह कहना गलत है कि ये केवल नकारात्मक हैं। हालाँकि इससे 'मैक्डोनॉल्डीकरण' का डर रहता है, लेकिन यह हमारी पसंद-नापसंद के दायरे को बढ़ाता भी है। बाहरी प्रभावों के कारण लोग नई भाषाओं, भोजन और कला के प्रति जागरूक होते हैं, जिससे सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण होता है। यह प्रक्रिया पुरानी जड़ परंपराओं को तोड़कर समाज को अधिक खुलेपन और विविधता की ओर ले जाने की क्षमता रखती है।

110. (D) यह संघर्ष को सुधारवाद की तरफ मोड़कर पूँजीवाद को बचाना चाहता है।
विश्व सामाजिक मंच (WSF) के आलोचकों का तर्क है कि यह मंच वास्तव में पूँजीवादी व्यवस्था के लिए एक सुरक्षा वाल्व का काम करता है। उनका मानना है कि WSF क्रांतिकारी आंदोलनों को केवल सुधारवादी बहसों में उलझा देता है, जिससे पूँजीवाद की जड़ों पर कोई वास्तविक प्रहार नहीं होता। यह दृष्टिकोण WSF को वैश्वीकरण के प्रति एक कमजोर और अपर्याप्त प्रतिरोध के रूप में देखता है, जो अंततः यथास्थिति बनाए रखता है।

111. (A) P-1, Q-2, R-3, S-4
वैश्वीकरण के आयामों और संबंधित अवधारणाओं का मिलान इसके बुनियादी सिद्धांतों को समझाता है। प्रवाहों की निरंतरता विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव पैदा करती है। राज्य की क्षमता में कमी 'न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य' को जन्म देती है। सांस्कृतिक समरुपता का सबसे चर्चित उदाहरण 'मैक्डोनॉल्डीकरण' है। वहीं, आर्थिक असमानता के कारण उत्पन्न चिंताओं को आलोचक 'पुनःउपनिवेशीकरण' की संज्ञा देते हैं, जो संप्रभुता के लिए खतरा माना जाता है।

112. (B) वैश्वीकरण के समर्थक का।
यह तर्क कि वैश्वीकरण अपरिहार्य है और इसे रोकना मूर्खता है, वैश्वीकरण के प्रबल समर्थकों की विचारधारा है। ऐसे लोग मानते हैं कि तकनीक और बाजार की शक्तियों के कारण दुनिया का जुड़ना एक स्वाभाविक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। उनके अनुसार, वैश्वीकरण से अलग-थलग रहने वाला देश पिछड़ जाएगा, इसलिए इसमें सक्रिय भागीदारी ही बुद्धिमत्ता है। यह दृष्टिकोण वैश्वीकरण को प्रगति और विकास के एकमात्र मार्ग के रूप में देखता है।

113. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
वैश्वीकरण में पूँजी और वस्तुओं का प्रवाह तो बढ़ा है, लेकिन श्रम का प्रवाह अभी भी बाधित है। विकसित देश अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए वीज़ा प्रतिबंध लगाते हैं ताकि विकासशील देशों से आने वाले लोग उनके रोजगार न छीन लें। यह आर्थिक वैश्वीकरण का एक बड़ा अंतर्विरोध है जहाँ बाजार तो खुला है, लेकिन इंसानों की आवाजाही पर अभी भी राष्ट्रीय सीमाओं का कड़ा पहरा मौजूद है।

94. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
वैश्वीकरण का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर एक समान नहीं पड़ा है, जो इसकी विषम प्रकृति को दर्शाता है। जहाँ उच्च मध्यम वर्ग और शिक्षित युवाओं को इससे नए अवसर और समृद्धि मिली है, वहीं अनपढ़ मजदूरों और छोटे किसानों के लिए यह अक्सर आजीविका का संकट लेकर आया है। लाभ और हानि का यह असमान वितरण ही समाज के विभिन्न हिस्सों के बीच बढ़ती आर्थिक और सामाजिक खाई का मुख्य कारण है।

95. (A) वैश्विक उत्पादन श्रृंखला और वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार।
'मेड इन बांग्लादेश' या 'मेड इन टर्की' जैसे लेबल वैश्विक उत्पादन श्रृंखला के जीवंत उदाहरण हैं। यह दर्शाता है कि कैसे कच्चा माल, श्रम और विनिर्माण दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में विभाजित हैं। बड़ी कंपनियां लागत कम करने के लिए उन देशों में उत्पादन करती हैं जहाँ संसाधन सस्ते हैं। इसके बाद ये वस्तुएं वैश्विक बाजार में बिकती हैं, जो राष्ट्रों के बीच बढ़ती आर्थिक निर्भरता और व्यापारिक प्रवाह को प्रमाणित करती हैं।

96. (B) विश्व की राजनीति में पुरानी ईर्ष्या और प्रतिद्वंद्विता अभी भी दखल रखती है।
वैश्वीकरण के बावजूद राष्ट्रवाद और राज्यों के बीच की प्रतिद्वंद्विता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। आज भी विभिन्न राष्ट्र अपने रणनीतिक हितों और सुरक्षा के लिए पुरानी प्रतिद्वंद्विता और ईर्ष्या को बनाए हुए हैं। वैश्विक जुड़ाव के बीच भी देशों के मध्य शक्ति संघर्ष और सीमाओं को लेकर विवाद जारी हैं। यह सिद्ध करता है कि वैश्वीकरण राष्ट्र-राज्य के अस्तित्व और उसकी राष्ट्रवादी भावनाओं को पूरी तरह मिटाने में सफल नहीं हुआ है।

97. (B) क्योंकि उनका मानना है कि बलपूर्वक किए जा रहे वैश्वीकरण को रोकना चाहिए।
आलोचक 'सामाजिक सुरक्षा कवच' को एक अपर्याप्त और अव्यावहारिक उपाय मानते हैं क्योंकि वे वैश्वीकरण के मूल ढांचे के ही विरोधी हैं। उनका तर्क है कि केवल छोटे-मोटे सुरक्षा उपाय करने के बजाय उस बलपूर्वक थोपे गए वैश्वीकरण को ही रोकना चाहिए जो गरीबी और शोषण पैदा करता है। वे सुधारवाद के बजाय व्यवस्थागत परिवर्तन की वकालत करते हैं ताकि संसाधनों पर स्थानीय समुदायों का वास्तविक नियंत्रण स्थापित हो सके।

98. (C) केवल 1, 2 और 4
वैश्वीकरण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है जो सदियों से जारी है, लेकिन समकालीन वैश्वीकरण अपनी गति और प्रसार के कारण विशेष है। सुनामी और महामारी जैसी घटनाएं यह स्पष्ट करती हैं कि पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी आपदाएं राष्ट्रीय सीमाओं का सम्मान नहीं करतीं। प्रौद्योगिकी ने निश्चित रूप से विश्व के लोगों के बीच जुड़ाव की समझ को बढ़ाया है, इसलिए तीसरा कथन गलत है। वैश्वीकरण आज के युग की एक अपरिहार्य वास्तविकता बन गया है।

99. (C) वैश्वीकरण के प्रभाव जटिल हैं, जो एकरुपता और विशिष्टता दोनों लाते हैं।
वैश्वीकरण की प्रक्रिया में विरोधाभासी प्रवृत्तियाँ एक साथ काम करती हैं। जहाँ सांस्कृतिक समरुपता के माध्यम से वैश्विक स्तर पर एकसमान जीवनशैली का प्रसार होता है, वहीं सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण स्थानीय पहचानों को और अधिक मुखर बनाता है। यह जटिलता दर्शाती है कि वैश्वीकरण कोई एकरैखिक प्रक्रिया नहीं है। यह समाज को आधुनिक बनाने के साथ-साथ उसे अपनी जड़ों के प्रति अधिक सजग और विशिष्ट होने के लिए भी प्रेरित करता है।

100. (D) विचार, पूँजी, वस्तु और लोग।
वैश्वीकरण को परिभाषित करने वाले प्रवाह के चार प्रमुख स्तंभ विचार, पूँजी, वस्तु और लोग हैं। विचारों का प्रवाह ज्ञान का प्रसार करता है, पूँजी का प्रवाह निवेश बढ़ाता है, वस्तुओं का प्रवाह अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाता है, और लोगों का प्रवाह बेहतर अवसरों की तलाश में होता है। इन चारों प्रवाहों की निरंतरता और तीव्रता ही वर्तमान वैश्वीकरण को आधार प्रदान करती है और वैश्विक जुड़ाव को मजबूती देती है।

101. (C) P-3, Q-2, R-1, S-4
विभिन्न अंतरराष्ट्रीय बैठकों का उनके स्थानों के साथ मिलान वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन के विस्तार को दर्शाता है। विश्व सामाजिक मंच की पहली बैठक ब्राजील के पोर्टो अलगेरे में हुई थी। सिएटल WTO विरोध का केंद्र बना। मुंबई में WSF की चौथी बैठक ने भारतीय नागरिक समाज को इससे जोड़ा। काठमांडू में हुई हालिया बैठक यह दर्शाती है कि यह आंदोलन दक्षिण एशिया के विभिन्न हिस्सों में अब भी सक्रिय और प्रासंगिक बना हुआ है।

102. (B) यह कच्चे माल का निर्यातक तथा बने-बनाए सामानों का आयातक था।
औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की भूमिका वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक अधीनस्थ इकाई की थी। ब्रिटेन भारत से सस्ते दाम पर कपास और नील जैसे कच्चे माल का निर्यात करता था और वहां की मिलों में बने महंगे कपड़ों और सामानों को भारतीय बाजारों में बेचता था। इस शोषणकारी नीति ने भारतीय हस्तशिल्प और उद्योगों को नष्ट कर दिया, जिससे देश पूरी तरह से ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों पर निर्भर हो गया।

103. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
संस्कृति एक जीवित और निरंतर बदलने वाली सत्ता है जो बाहरी प्रभावों के प्रति लचीली होती है। जब कोई संस्कृति बाहरी विचारों को अपनाती है, तो उसकी जड़ें पूरी तरह नहीं कटतीं, बल्कि वह आधुनिकता के साथ सामंजस्य बिठाती है। बाहरी प्रभाव कभी हमारी पसंद बढ़ाते हैं तो कभी पुरानी रुढ़ियों को चुनौती देते हैं। यह सांस्कृतिक आदान-प्रदान समाज को प्रगतिशील बनाने और नई पहचान गढ़ने में अत्यंत सहायक सिद्ध होता है।

बढ़ते पारस्परिक जुड़ाव और निर्भरता को रेखांकित करती है, जहाँ एक स्थान की आपदा दूसरे देशों के लिए भी खतरा बन जाती है, जिससे वैश्विक सहयोग अनिवार्य हो जाता है।

125. (C) एक अधिक क्रांतिकारी और संघर्ष-उन्मुख दृष्टिकोण।
संघर्ष को बहसों से ऊपर रखने वाला यह विचार वैश्वीकरण विरोधी आंदोलनों के भीतर क्रांतिकारी विचारधारा को दर्शाता है। ऐसे समूहों का मानना है कि केवल शांतिपूर्ण चर्चा या सुधारों से पूँजीवादी व्यवस्था को नहीं बदला जा सकता। वे मानते हैं कि वास्तविक सामाजिक बदलाव के लिए जमीन पर सक्रिय संघर्ष और जन-आंदोलन आवश्यक हैं। यह दृष्टिकोण वैश्वीकरण के विरुद्ध एक उग्र और समझौतेविहीन लड़ाई का आह्वान करता है।

126. (D) व्यापार और विदेशी निवेश पर आयद बाधाओं को हटाना।
1991 के बाद भारत द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों का मुख्य केंद्र उदारीकरण और वैश्वीकरण था। इसके तहत सरकार ने लाइसेंस राज को खत्म किया और विदेशी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार के दरवाजे खोले। व्यापार पर लगे कड़े शुल्क और निवेश की बाधाओं को हटाकर अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के साथ जोड़ा गया। इन सुधारों का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धी बनाना और विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना था।

127. (A) राष्ट्र-राज्यों के बीच प्रतिद्वंद्विता का पूर्ण अंत।
वैश्वीकरण के कारण राष्ट्र-राज्यों के बीच की प्रतिद्वंद्विता समाप्त नहीं हुई है, बल्कि इसके रूप बदल गए हैं। आज भी देश अपने आर्थिक हितों, संसाधनों और सुरक्षा के लिए एक-दूसरे के साथ कड़े संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। संप्रभुता को चुनौती और सांस्कृतिक समरूपता वैश्वीकरण के परिणाम हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रों के बीच पुरानी ईर्ष्या और शक्ति का खेल अभी भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा है।

128. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
वैश्वीकरण का प्रभाव केवल विनाशकारी नहीं होता, बल्कि यह सकारात्मक बदलाव भी लाता है। बाहरी संस्कृतियों के प्रभाव से लोगों को नए विचार, कला और जीवनशैली के विकल्प मिलते हैं, जो उनके अनुभव को समृद्ध करते हैं। यह प्रक्रिया पारंपरिक मूल्यों को बिना नष्ट किए उनमें नवीनता और आधुनिकता का संचार करती है। इस प्रकार, वैश्वीकरण समाज को अधिक लचीला और विविधताओं को स्वीकार करने वाला बनाने में सहायक सिद्ध होता है।

129. (B) क्या यह साम्राज्यवाद का ही नया नाम है?
वैश्वीकरण के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बहस इसकी प्रकृति को लेकर है। कई आलोचक इसे 'नव-साम्राज्यवाद' मानते हैं क्योंकि यह अमीर देशों को गरीब देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नियंत्रण करने का अवसर देता है। यह बहस संप्रभुता, आर्थिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान के मुद्दों से जुड़ी हुई है। क्या वैश्वीकरण वास्तव में विकास का साधन है या यह केवल शक्तिशाली देशों के प्रभुत्व का नया माध्यम है, यह प्रश्न आज भी विचारणीय है।

130. (B) P-4, Q-3, R-2, S-1
इन चार प्रमुख आर्थिक और सांस्कृतिक शब्दों का मिलान वैश्वीकरण की प्रक्रिया को समझने की आधारशिला है। वैश्वीकरण विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव को दर्शाता है। पश्चिमीकरण पश्चिमी मूल्यों के प्रभाव को कहता है। संरक्षणवाद घरेलू उद्योगों को बाहरी प्रतिस्पर्धा से बचाने की पुरानी नीति है। उदारीकरण का अर्थ व्यापार और निवेश पर लगे सरकारी प्रतिबंधों को हटाना है ताकि अर्थव्यवस्था में खुलापन और प्रतिस्पर्धा बढ़ सके।

131. (D) 1, 2, 3, 4 सभी
वैश्वीकरण एक अत्यंत जटिल और बहुआयामी अवधारणा है जिसमें प्रौद्योगिकी मुख्य उत्प्रेरक का काम करती है। इसके कारण राज्य की क्षमता में विरोधाभासी बदलाव आए हैं और सांस्कृतिक समरूपता के साथ-साथ वैभिन्नीकरण भी बढ़ा है। ये सभी पहलू मिलकर वैश्वीकरण की एक विस्तृत तस्वीर पेश करते हैं। यह प्रक्रिया समाज के हर हिस्से को अलग-अलग तरीके से प्रभावित करती है, जिससे इसके परिणाम अत्यंत व्यापक और विविधतापूर्ण हो जाते हैं।

132. (D) वे अक्सर वैश्विक नेटवर्क बनाकर एक दूसरे से जुड़ते हैं।
वैश्वीकरण-विरोधी आंदोलनों की एक प्रमुख विशेषता उनका वैश्विक नेटवर्क है। ये आंदोलन केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहते, बल्कि इंटरनेट और संचार के साधनों का उपयोग कर दुनिया भर के समान विचारधारा वाले समूहों के साथ एकजुट होते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव उन्हें बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और शक्तिशाली सरकारों के खिलाफ एक मजबूत वैश्विक दबाव समूह के रूप में उभरने और अपनी मांगें मनवाने में मदद करता है।

133. (C) नौकरी और जन-कल्याण पर वैश्वीकरण के प्रभाव से।
सतत विकास लक्ष्य 8 आर्थिक विकास के साथ-साथ मर्यादित कार्य और नौकरी की सुरक्षा पर जोर देता है। वैश्वीकरण के दौर में जहाँ एक ओर नए रोजगार सृजित हुए हैं, वहीं दूसरी ओर नौकरी की असुरक्षा और अनौपचारिक श्रम भी बढ़ा है। यह लक्ष्य वैश्वीकरण के उन परिणामों को संबोधित करता है जो मजदूरों के अधिकारों और उनके कल्याण को प्रभावित करते हैं, ताकि आर्थिक विकास मानवीय और न्यायपूर्ण हो सके।

134. (B) वर्तमान में प्रवाह की गति और उसका विश्वव्यापी प्रसार अभूतपूर्व है।
ऐतिहासिक वैश्वीकरण और वर्तमान दौर में सबसे बड़ा अंतर तीव्रता और सघनता का है। पहले व्यापार और विचारों का प्रसार धीमा था और उसका दायरा सीमित था। आज की डिजिटल क्रांति ने पूँजी और सूचना के प्रवाह को बिजली की गति प्रदान की है। अब दुनिया का कोई भी हिस्सा इस प्रक्रिया से अछूता नहीं है, जो वर्तमान वैश्वीकरण को इतिहास की किसी भी पिछली घटना से अधिक व्यापक बनाता है।

114. (A) 1, 2, 3, 4
संचार और आर्थिक नीतियों का ऐतिहासिक क्रम वैश्वीकरण की पृष्ठभूमि तैयार करता है। मुद्रण तकनीक ने राष्ट्रवाद और विचारों के प्रसार की नींव रखी। इसके बाद टेलीग्राफ और फोन ने भौतिक दूरियों को कम किया। 1991 में भारत ने संरक्षणवाद छोड़कर आर्थिक सुधार अपनाए। अंततः 2001 में विश्व सामाजिक मंच का गठन हुआ जो वैश्वीकरण के विरुद्ध एक संगठित अंतरराष्ट्रीय नागरिक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया।

115. (C) यह कि वैश्वीकरण एक नई प्रकार की आर्थिक पराधीनता को जन्म दे रहा है।
आलोचकों द्वारा 'पुनःउपनिवेशीकरण' शब्द का प्रयोग यह जताने के लिए किया जाता है कि वैश्वीकरण गरीब देशों के लिए नया खतरा है। उनका मानना है कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं और बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब उन देशों की आर्थिक नीतियों को नियंत्रित करती हैं, जो पुराने दौर के प्रत्यक्ष राजनीतिक शासन जैसा ही है। यह आर्थिक पराधीनता गरीब राष्ट्रों के विकास को अवरुद्ध कर उन्हें अमीर देशों का पिछलग्गू बनाए रखती है।

116. (D) ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं और इनके बीच सूक्ष्म भेद है।
वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव एक-दूसरे से पूरी तरह अलग नहीं हैं। ये तीनों आयाम आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं और एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, आर्थिक नीतियां सांस्कृतिक पसंद को प्रभावित करती हैं, और सांस्कृतिक बदलाव राजनीतिक निर्णयों को दिशा देते हैं। इन प्रभावों के बीच का अंतर बहुत सूक्ष्म है, इसलिए वैश्वीकरण को एक एकीकृत और समग्र प्रक्रिया के रूप में समझना आवश्यक है।

117. (C) सांस्कृतिक आयाम
भारत में 'वैलेन्टाइन-डे' का विरोध वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम के प्रति एक तीव्र प्रतिक्रिया है। दक्षिणपंथी संगठन इसे पश्चिमी संस्कृति का आक्रमण मानते हैं जो भारतीय पारंपरिक मूल्यों और शिष्टाचार के विरुद्ध है। यह विरोध दर्शाता है कि वैश्वीकरण केवल वस्तुओं का व्यापार नहीं है, बल्कि यह जीवनशैली और उत्सवों के वैश्विक प्रसार के माध्यम से स्थानीय पहचानों के लिए एक वैचारिक चुनौती भी खड़ा करता है।

118. (B) वैश्वीकरण की बहुआयामी प्रकृति
वैश्वीकरण की परिभाषा केवल आर्थिक या राजनीतिक नहीं है, बल्कि इसमें विचारों, पूँजी, वस्तुओं और लोगों का सामूहिक प्रवाह शामिल है। यह बहुआयामी प्रकृति ही इसे एक व्यापक वैश्विक प्रक्रिया बनाती है जो जीवन के हर पहलू को छूती है। जब ये सभी प्रवाह एक साथ काम करते हैं, तो वे समाज के ढांचे को बदलते हैं और एक नया विश्वव्यापी नेटवर्क तैयार करते हैं, जो आधुनिक वैश्वीकरण की पहचान है।

119. (D) संरक्षणवाद
जब कोई देश अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए आयात पर ऊँचे शुल्क लगाता है, तो वह संरक्षणवाद की नीति का पालन करता है। यह वैश्वीकरण की 'मुक्त व्यापार' की अवधारणा के विपरीत है। संरक्षणवाद का उद्देश्य स्थानीय रोजगार की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना होता है। भारत ने भी अपनी आजादी के बाद कई दशकों तक इस नीति को अपनाया ताकि देश का औद्योगिक ढांचा बाहरी दबाव के बिना मजबूत हो सके।

120. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
वैश्वीकरण-विरोधी आंदोलनों की प्रकृति बहुत सूक्ष्म है। वे अधिकांशतः जुड़ाव और संचार की धारणा के विरोधी नहीं हैं, बल्कि वे उस विशिष्ट कॉर्पोरेट मॉडल के खिलाफ हैं जो शोषणकारी है। वे इसे 'साम्राज्यवाद' का नया रूप मानते हैं क्योंकि यह केवल शक्तिशाली देशों और बड़ी कंपनियों को लाभ पहुँचाता है। उनका उद्देश्य वैश्वीकरण को पूरी तरह खत्म करना नहीं, बल्कि उसे अधिक न्यायपूर्ण और मानवीय बनाना है।

121. (C) P-3, Q-4, R-1, S-2
वैश्वीकरण पर विभिन्न विचारधाराओं के तर्कों का मिलान इसकी वैचारिक विविधता को स्पष्ट करता है। समर्थक इसे समृद्धि का मार्ग मानते हैं, जबकि वामपंथी इसे बढ़ती असमानता का कारण बताते हैं। दक्षिणपंथी अपनी पारंपरिक संस्कृति की रक्षा पर जोर देते हैं। सामाजिक न्याय के पक्षधर 'सामाजिक सुरक्षा कवच' की मांग करते हैं ताकि वैश्वीकरण की होड़ में समाज के सबसे कमजोर वर्ग आर्थिक और सामाजिक रूप से सुरक्षित रह सकें।

122. (A) राज्य ने सामाजिक-कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों से स्वयं को पीछे खींच लिया है।
न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य की नीति के कारण सरकारों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसे सामाजिक क्षेत्रों में अपना निवेश और नियंत्रण कम कर दिया है। राज्य अब केवल 'नियामक' की भूमिका में है, न कि 'प्रदाता' की। इसका सीधा परिणाम यह हुआ है कि ये महत्वपूर्ण सेवाएं अब बाजार और निजी क्षेत्र के भरोसे हैं, जिससे गरीबों की इन बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच कठिन और महंगी हो गई है।

123. (B) केवल 2, 3 और 4
आर्थिक वैश्वीकरण की वर्तमान स्थिति विरोधाभासी है। पूँजी की आवाजाही पर अब बहुत कम प्रतिबंध हैं और तकनीक के कारण विचारों का प्रवाह अबाध है। हालाँकि, वस्तुओं और पूँजी की तुलना में लोगों का अंतरराष्ट्रीय आवागमन अभी भी वीज़ा नियमों और सीमाओं के कारण बहुत सीमित है। पहला कथन गलत है क्योंकि वैश्वीकरण में आयात प्रतिबंध कम किए गए हैं, न कि बढ़ाए गए हैं, जिससे व्यापार सुगम हुआ है।

124. (B) वैश्विक समस्याओं और राष्ट्रों के मध्य बढ़ते पारस्परिक जुड़ाव की वास्तविकता को।
बर्ड फ्लू और सुनामी जैसी आपदाएं यह प्रमाणित करती हैं कि आधुनिक विश्व में कोई भी राष्ट्र पूरी तरह से अलग-थलग नहीं रह सकता। ये समस्याएं भौगोलिक सीमाओं को नहीं मानतीं और इनका प्रभाव वैश्विक होता है। यह स्थिति राष्ट्रों के बीच

42. (A) पूँजी और वस्तु की गतिशीलता, लोगों की आवाजाही की तुलना में अधिक तीव्र और व्यापक है।
वैश्वीकरण के दौर में पूँजी और वस्तुओं का अंतरराष्ट्रीय प्रवाह बहुत आसान और तेज हो गया है। इसके विपरीत, लोगों के आवागमन पर अभी भी कई प्रतिबंध लागू हैं। विकसित देश अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए कड़े वीज़ा नियम अपनाते हैं ताकि विकासशील देशों से आने वाले सस्ते श्रम को नियंत्रित किया जा सके। यह आर्थिक वैश्वीकरण की प्रक्रिया में एक प्रमुख और स्पष्ट असमानता है।

43. (D) किसी एक केंद्रीय सत्ता के निर्माण के प्रति आशंका को।
विश्व सामाजिक मंच (WSF) के भीतर यह विचार कि 'कोमिन्टर्न' जैसा संगठन नहीं बनाना चाहिए, इसकी विविधता और अलोकतांत्रिक केंद्रीयता के प्रति भय को दर्शाता है। कोमिन्टर्न एक केंद्रीय सोवियत संगठन था जो सभी कम्युनिस्ट दलों को नियंत्रित करता था। WSF के सदस्य चाहते हैं कि यह मंच एक खुला आकाश बना रहे जहाँ विभिन्न विचारधाराएं स्वतंत्र रूप से रह सकें, न कि किसी एक आदेश से चलें।

44. (C) P-3, Q-1, R-4, S-2
विभिन्न उत्पादों और सेवाओं का मिलान वैश्वीकरण के बहुआयामी प्रभाव को दर्शाता है। बार्बी डॉल अमेरिकी संस्कृति का उत्पाद है, जबकि खादी का कुर्ता भारतीय परंपरा का प्रतीक है। कॉल सेंटर सेवाओं के वैश्विक प्रवाह का एक आधुनिक उदाहरण है, और चीनी साइकिलें वस्तुओं के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को इंगित करती हैं। ये सभी उदाहरण मिलकर विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव की एक विस्तृत तस्वीर पेश करते हैं।

45. (C) यह प्रवाहों की निरंतरता से उत्पन्न होता है और उन्हें निरंतर बनाए रखता है।
विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव वैश्वीकरण का केंद्र बिंदु है। यह केवल एक बार की घटना नहीं है, बल्कि विचारों, पूँजी, वस्तुओं और लोगों के निरंतर प्रवाह का परिणाम है। यह जुड़ाव विभिन्न राष्ट्रों को एक-दूसरे पर निर्भर बनाता है और वैश्विक समस्याओं व अवसरों के प्रति साझा दृष्टिकोण विकसित करता है। यह निरंतरता ही वैश्वीकरण को एक सक्रिय और गतिशील प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करती है।

46. (B) केवल 2 और 4
वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, जिसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयाम समाज के विभिन्न स्तरों को प्रभावित करते हैं। इसका प्रभाव सभी समाजों और वर्गों पर एक समान नहीं रहा है, बल्कि यह अत्यंत विषम है। जहाँ कुछ समूहों ने इससे अत्यधिक लाभ कमाया है, वहीं अन्य समूहों के लिए यह चुनौतियाँ लेकर आया है। यह विषमता ही वैश्वीकरण के सामाजिक परिणामों की सबसे प्रमुख विशेषता है।

47. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
वैश्वीकरण की सांस्कृतिक प्रक्रिया दोहरी भूमिका निभाती है। एक ओर यह 'सांस्कृतिक समरुपता' लाती है जिससे विश्व पश्चिमी संस्कृति के सांचे में ढलने लगता है। दूसरी ओर, यह 'सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण' को बढ़ावा देती है, जहाँ बाहरी प्रभाव स्थानीय संस्कृति के साथ मिलकर उसे और अधिक विशिष्ट बना देते हैं। इस प्रकार, वैश्वीकरण संस्कृतियों को एक जैसा बनाने के साथ-साथ उनमें अनूठेपन को भी बढ़ाता है।

48. (B) स्वास्थ्य, आवास और प्राथमिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।
भारत में संरक्षणवाद की नीति का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था, लेकिन इसके कारण कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों की उपेक्षा हुई। आर्थिक संसाधनों का बड़ा हिस्सा औद्योगिक सुरक्षा में लगा रहा, जिससे स्वास्थ्य, आवास और शिक्षा जैसे लोक-कल्याणकारी क्षेत्रों में निवेश की कमी हो गई। इसके परिणामस्वरूप, देश ने कुछ औद्योगिक प्रगति तो की, लेकिन मानव विकास के मानकों पर वह अन्य देशों से पीछे रह गया।

49. (B) 1991 में आर्थिक सुधारों को लागू करना।
1991 में आर्थिक सुधारों को लागू करना वैश्वीकरण को अपनाने की एक सरकारी प्रक्रिया थी, न कि उसका प्रतिरोध। प्रतिरोध के रुपों में किसानों द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विरोध, सामाजिक मंचों द्वारा कॉर्पोरेट नीतियों का विरोध और पारंपरिक संपदा के पेटेंट के खिलाफ लड़ाई शामिल है। आर्थिक सुधारों का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार के लिए खोलना था, जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया का समर्थन था।

50. (A) प्रवाहों की गति और उनके प्रसार का धरातल
इतिहास में वैश्वीकरण पहले भी अस्तित्व में था, लेकिन समकालीन वैश्वीकरण अपनी गति और व्यापक प्रसार के कारण विशिष्ट है। वर्तमान में सूचना और पूँजी का प्रवाह बिजली की गति से होता है, और इसका प्रभाव विश्व के लगभग हर कोने तक पहुँच चुका है। आधुनिक संचार साधनों और परिवहन तकनीक ने वैश्वीकरण को एक ऐसी सघनता प्रदान की है जो मानव इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई।

51. (A) 3, 2, 1, 4
वैश्वीकरण विरोधी प्रदर्शनों और सम्मेलनों का कालानुक्रमिक क्रम महत्वपूर्ण है। सबसे पहले 1999 में सिएटल में WTO के विरुद्ध प्रदर्शन हुए। इसके बाद 2001 में पोर्टो अलगेरे में WSF की पहली बैठक हुई। फिर 2004 में मुंबई में इसकी चौथी बैठक आयोजित की गई। अंततः, 2024 में नेपाल के काठमांडू में भी इसकी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह क्रम वैश्विक जन-जागरुकता के विस्तार को दर्शाता है।

52. (D) बहुराष्ट्रीय निगम, विभिन्न निवेशक, और विश्वभर के उपभोक्ता।
आर्थिक वैश्वीकरण केवल सरकारी संस्थाओं तक सीमित नहीं है। इसमें बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूँजी लगाने वाले निवेशक और दुनिया भर के उपभोक्ता भी सक्रिय खिलाड़ी हैं। ये सभी मिलकर वैश्विक बाजार की दिशा और स्वरुप तय करते हैं। उपभोक्ता की पसंद और निवेशकों का भरोसा अब राष्ट्रों की आर्थिक नीतियों को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं, जिससे शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ है।

135. (D) यह वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करने वाली संस्था है।
विश्व व्यापार संगठन (WTO) अंतरराष्ट्रीय व्यापार की सर्वोच्च नियामक संस्था है। इसका मुख्य कार्य सदस्य देशों के बीच व्यापारिक विवादों को सुलझाना और मुक्त व्यापार के लिए नियम बनाना है। हालाँकि यह अक्सर विकसित देशों के पक्ष में झुके होने के आरोपों के कारण विवादों में रहता है, लेकिन वैश्विक आर्थिक ढांचे में इसकी भूमिका अपरिहार्य है। यह संगठन सुनिश्चित करता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुचारु और पूर्वानुमेय तरीके से चलता रहे।

136. (B) केवल 3 और 5
वैश्वीकरण को केवल एक वर्ष या एक घटना से जोड़ना गलत है, बल्कि यह प्रवाहों की एक निरंतर प्रक्रिया है। इसमें विचारों, पूँजी, वस्तुओं और लोगों का वैश्विक आदान-प्रदान शामिल है। प्रौद्योगिकी ने इस प्रक्रिया को अभूतपूर्व गति देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैश्वीकरण का प्रभाव सभी पर समान नहीं है और इसका विरोध केवल एक खेमे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बहुआयामी और चुनौतीपूर्ण वैश्विक सच्चाई है।

137. (C) आंदोलनों के भीतर भी गहरे मतभेद और रणनीतिक बहसें उपस्थित हैं।
मुंबई प्रतिरोध 2004 द्वारा विश्व सामाजिक मंच (WSF) की आलोचना यह दर्शाती है कि वैश्वीकरण का विरोध करने वाले समूह एक स्वर में नहीं बोलते। आंदोलनों के भीतर भी विचारधारा, कार्यप्रणाली और धन के स्रोतों को लेकर गंभीर मतभेद हैं। यह विविधता यह सिद्ध करती है कि वैश्वीकरण के विरुद्ध संघर्ष भी कोई सरल या एकरैखिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह निरंतर वैचारिक मंथन और रणनीतिक बहसों से भरा हुआ है।

138. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
सांस्कृतिक समरूपता का मुख्य डर यह है कि प्रभुत्वशाली पश्चिमी संस्कृति कमजोर और छोटे समाजों की विशिष्टता को मिटा देगी। जब अमीर देशों की जीवनशैली को 'आधुनिकता' का पर्याय मान लिया जाता है, तो लोग अपनी पारंपरिक जड़ों को छोड़ने लगते हैं। इससे विश्व की सांस्कृतिक धरोहर का ह्रास होता है। यह वैश्वीकरण का एक गंभीर परिणाम है जहाँ विविधता के स्थान पर एक नीरस वैश्विक एकरूपता हावी होने लगती है।

139. (D) भारतीयों द्वारा नौकरियां छीने जाने की धारणा के कारण उत्पन्न कुंठा से।
कॉल सेंटर कर्मचारियों के प्रति विदेशी ग्राहकों का गुस्सा अक्सर आर्थिक असुरक्षा से उपजा होता है। विकसित देशों में यह आम धारणा है कि आउटसोर्सिंग के कारण उनकी स्थानीय नौकरियां भारत जैसे देशों में जा रही हैं, जहाँ श्रम सस्ता है। यह कुंठा नस्लीय टिप्पणियों और नफरत के रूप में प्रकट होती है। यह उदाहरण वैश्वीकरण के उस मानवीय पहलू को उजागर करता है जहाँ आर्थिक लाभ के साथ-साथ सामाजिक तनाव भी बढ़ते हैं।

140. (C) P-2, Q-1, R-4, S-3
वैश्वीकरण से जुड़ी इन महत्वपूर्ण अवधारणाओं का मिलान इसके परिणामों की गहराई को समझाता है। सांस्कृतिक समरूपता 'मैक्डोनॉल्डीकरण' के रूप में दिखती है, जबकि सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण 'जीन्स-कुर्ता' जैसे संकरण में प्रकट होता है। पुनःउपनिवेशीकरण आर्थिक पराधीनता का सूचक है। वहीं, सामाजिक सुरक्षा कवच उन नीतियों का समूह है जो वैश्वीकरण की आंधी में समाज के सबसे गरीब और बेसहारा लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करती हैं।

141. (A) केवल 1 और 3
वैश्वीकरण ने राज्य की संप्रभुता की पारंपरिक धारणा को चुनौती दी है, लेकिन राज्य अभी भी व्यवस्था के केंद्र में बने हुए हैं। राज्य आज भी अपने अनिवार्य कार्यों जैसे सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। यह कहना गलत है कि राज्य की क्षमता हमेशा कम ही हुई है या बहुराष्ट्रीय निगमों का प्रभाव कम हुआ है। वास्तव में, राज्य ने तकनीक के माध्यम से अपनी शक्ति के नए स्वरूप विकसित किए हैं।

142. (D) यह विचारों, वस्तुओं, पूंजी और लोगों के प्रवाह से उत्पन्न बहुआयामी प्रक्रिया है।
वैश्वीकरण का सबसे सटीक वर्णन इसकी प्रवाह-आधारित प्रकृति है। यह केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विचारों, पूँजी, वस्तुओं और लोगों का विश्वव्यापी संचरण शामिल है। यही बहुआयामी स्वरूप इसे एक जटिल वैश्विक परिघटना बनाता है जो राजनीति, संस्कृति और समाज को गहराई से प्रभावित करती है। यह निरंतर जुड़ाव ही आधुनिक विश्व की सबसे बड़ी और प्रभावशाली पहचान बन गया है, जो राष्ट्रों को जोड़ता है।

143. (A) इसके कारण हमारी पसंद का दायरा बढ़ता है और संस्कृति का परिष्कार होता है।
वैश्वीकरण का एक सकारात्मक सांस्कृतिक पहलू यह है कि यह हमें दुनिया भर की संस्कृतियों से परिचित कराता है। इससे हमारी पसंद-नापसंद का दायरा विस्तृत होता है और हम नई चीजों को अपनाने के लिए अधिक उदार बनते हैं। बाहरी प्रभाव हमेशा स्थानीय संस्कृति को खत्म नहीं करते, बल्कि वे अक्सर उसे नया निखार और आधुनिकता प्रदान करते हैं, जिससे सांस्कृतिक विरासत और अधिक समृद्ध और वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य बनती है।

144. (A) 1, 3, 2, 4
भारतीय इतिहास और वैश्विक जुड़ाव का क्रम स्पष्ट है। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश शासन ने भारतीय संसाधनों का दोहन किया। आजादी के बाद भारत ने आत्मनिर्भरता के लिए संरक्षणवाद अपनाया। 1991 में आर्थिक संकट ने देश को नई आर्थिक नीति और उदारीकरण की ओर मोड़ा। इसके बाद वैश्वीकरण के विरोध में 1999 में सिएटल जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों

पर कड़ा प्रतिरोध देखा गया, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के नियमों को चुनौती देने का प्रतीक था।

145. (B) पोर्टो अलगेरे, ब्राजील में 2001 में
विश्व सामाजिक मंच (WSF) की पहली ऐतिहासिक बैठक 2001 में ब्राजील के पोर्टो अलगेरे में आयोजित की गई थी। इस बैठक ने दुनिया भर के उन समूहों को एक साझा मंच प्रदान किया जो नव-उदारवादी वैश्वीकरण की नीतियों का विरोध कर रहे थे। यहीं से 'एक और दुनिया मुमकिन है' का नारा बुलंद हुआ, जिसने वैश्वीकरण के वैकल्पिक और मानवीय स्वरूप की मांग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संगठित आवाज और पहचान प्रदान की।

146. (A) केवल 1 और 4
वैश्वीकरण के वास्तविक पहलुओं में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) जैसी संस्थाओं की केंद्रीय आर्थिक भूमिका और भारत द्वारा 1991 में शुरु किए गए आर्थिक सुधार शामिल हैं। यह कहना गलत है कि राज्य की क्षमता हमेशा बढ़ी है या वैश्वीकरण केवल समरूपता लाता है। साथ ही, इसका विरोध समाज के हर खेमे से हुआ है। ये तथ्य दर्शाते हैं कि वैश्वीकरण एक मिश्रित और जटिल प्रक्रिया है जिसके परिणाम और प्रतिक्रियाएं दोनों ही अत्यंत विविध हैं।

147. (C) वस्तुओं के वैश्विक व्यापार और प्रवाह को
एक ही स्थान पर विभिन्न देशों की वस्तुओं, जैसे चीनी साइकिल और अमेरिकी खिलौनों का उपलब्ध होना, वस्तुओं के निर्बाध वैश्विक व्यापार का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह दर्शाता है कि कैसे अंतरराष्ट्रीय बाजार अब स्थानीय दुकानों तक पहुँच गए हैं। उपभोक्ताओं के पास अब वैश्विक उत्पादों का विशाल चयन मौजूद है, जो वैश्वीकरण के आर्थिक आयाम की सफलता और राष्ट्रों के बीच बढ़ती व्यापारिक अंतर्निर्भरता को एक सरल उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करता है।

148. (D) क्योंकि यह विभिन्न समाजों और समूहों को अलग-अलग स्तरों पर प्रभावित करता है।
वैश्वीकरण का प्रभाव अत्यंत विषम और असमान है क्योंकि यह अलग-अलग सामाजिक और आर्थिक समूहों के लिए अलग-अलग परिणाम लेकर आता है। जहाँ शिक्षित और कुशल लोगों के लिए यह सुनहरे अवसर खोलता है, वहीं अकुशल मजदूरों और छोटे उत्पादकों के लिए यह कठिन प्रतिस्पर्धा और असुरक्षा पैदा करता है। यही कारण है कि वैश्वीकरण के प्रति समाज की प्रतिक्रियाएं भी बंटी हुई हैं, जो इसके लाभों के असमान वितरण को दर्शाती हैं।

149. (C) अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएँ जुटाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की उपलब्धता।
वैश्वीकरण के दौर में राज्य की ताकत बढ़ने का एक प्रमुख कारण सूचना तकनीक का विकास है। आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम और इंटरनेट के माध्यम से राज्य अब अपने नागरिकों की गतिविधियों और जरूरतों पर बारीकी से नजर रख सकते हैं। यह डेटा-शक्ति सरकार को अधिक प्रभावी ढंग से योजनाएं बनाने, अपराध रोकने और शासन को नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है, जिससे प्रशासनिक स्तर पर राज्य पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया है।

150. (B) यह कि कुछ आलोचक वैश्वीकरण को साम्राज्यवाद के नए रूप में देखते हैं।
यह प्रश्न वैश्वीकरण के प्रति एक गहरी आलोचनात्मक सोच को व्यक्त करता है। आलोचकों का मानना है कि जैसे पुराने समय में साम्राज्यवादी देश अपनी मर्जी थोपते थे, वैसे ही आज वैश्वीकरण के बहाने अमीर देश और उनकी कंपनियां विकासशील देशों की संप्रभुता और संसाधनों को नियंत्रित कर रही हैं। यह बहस वैश्वीकरण को विकास के साधन के बजाय आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व के एक आधुनिक माध्यम के रूप में प्रस्तुत करती है।

151. (B) यह राज्य की संप्रभुता को चुनौती देता है और उसकी भूमिका को रूपांतरित करता है।
वैश्वीकरण की प्रक्रिया राज्य की पारंपरिक संप्रभुता के समक्ष जटिल चुनौतियां प्रस्तुत करती है। यह अंतर्राष्ट्रीय संधियों और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से राज्य की निर्णय लेने की क्षमता को सीमित करती है। हालांकि, यह राज्य को समाप्त नहीं करती, बल्कि उसकी भूमिका को वैश्विक नेटवर्क में एक सक्रिय और सहयोगी भागीदार के रूप में सफलतापूर्वक रूपांतरित करती है।

152. (A) (A) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी वैश्विक संस्थाएं सदस्य देशों की घरेलू आर्थिक नीतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। यह प्रभाव अक्सर राज्य के स्वायत्त क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण माना जाता है क्योंकि देश ऋणदाता संस्थाओं की शर्तों के अनुसार नीतियां बनाने को विवश होते हैं। इस प्रकार, आर्थिक वैश्वीकरण राज्यों के स्वतंत्र निर्णय लेने के पारंपरिक अधिकार को काफी सीमित करता है।

153. (C) राज्य का आंतरिक शासन के साथ-साथ वैश्विक अभिशासन में एक सक्रिय भागीदारी बनना।
राज्य की भूमिका का रूपांतरण इस तथ्य को दर्शाता है कि राज्य अब केवल अपनी सीमाओं के भीतर का प्रहरी नहीं रहा है। वह अब वैश्विक समस्याओं के समाधान हेतु अन्य राज्यों के साथ मिलकर अपनी शक्तियों को साझा करता है। इस प्रक्रिया में, राज्य आंतरिक शासन के साथ-साथ वैश्विक अभिशासन के नेटवर्क में एक अनिवार्य और सक्रिय भागीदार बन चुका है।

154. (D) क्योंकि राज्य वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए सहयोग कर अपनी शक्ति का नए तरीकों से उपयोग कर रहे हैं।
वैश्वीकरण के दौर में राज्य आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसी आधुनिक वैश्विक चुनौतियों से अकेले नहीं निपट सकते। इसके समाधान हेतु राज्य अपनी संप्रभु शक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा या पूल करते हैं। यह सहयोग राज्य को कमजोर करने के बजाय उसे नई वैश्विक परिस्थितियों में अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए निरंतर और सफलतापूर्वक अनुकूलित करता है।

155. (C) अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और गैर-राज्य कर्ताओं का राज्य के निर्णय लेने की क्षमता को सीमित करना।
संप्रभुता के क्षरण का प्राथमिक तर्क यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, गैर-सरकारी संगठन और बहुराष्ट्रीय निगम राज्य की स्वायत्तता को प्रभावित करते हैं। ये बाहरी कर्ता अक्सर राज्य की नीति-निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं, जिससे स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। यह प्रक्रिया पारंपरिक राष्ट्रीय संप्रभुता की धारणा को वैश्विक दबावों के अधीन लाकर उसे बहुत सीमित कर देती है।

156. (B) बहुराष्ट्रीय निगम (MNCs)
आर्थिक वैश्वीकरण का वर्तमान स्वरूप मुख्य रूप से बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा संचालित होता है। ये विशाल निगम अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं को वैश्विक स्तर पर फैलाते हैं ताकि लागत कम की जा सके। विकसित देशों में मुख्यालय वाले ये निगम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से पूंजी और तकनीक का प्रवाह सुनिश्चित करते हैं, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का ढांचा व्यापक रूप से बदला है।

157. (D) श्रम और संसाधनों की लागत को कम करने और नए बाजारों तक पहुंचने के लिए
बहुराष्ट्रीय निगम अपनी लाभ क्षमता बढ़ाने के लिए विकासशील देशों के संसाधनों और सस्ते श्रम का लाभ उठाते हैं। इन देशों में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने से उनकी परिचालन लागत में कमी आती है और वे स्थानीय बाजारों तक सीधी पहुंच प्राप्त करते हैं। यह रणनीति वैश्विक उत्तर के निगमों को वैश्विक दक्षिण के उभरते उपभोक्ता वर्गों के बीच बहुत अधिक प्रतिस्पर्धी बनाती है।

158. (A) (A) यह वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण के बीच संरचनात्मक असमानताओं को बढ़ाता है।
आर्थिक वैश्वीकरण के आलोचकों का मानना है कि यह मॉडल विकसित और विकासशील देशों के बीच पहले से मौजूद संरचनात्मक असमानताओं को और अधिक गहरा करता है। अधिकांश लाभ वैश्विक उत्तर के निगमों और शेयरधारकों तक ही सीमित रहता है, जबकि विकासशील देशों को अक्सर सामाजिक और पर्यावरणीय क्षति सहनी पड़ती है। यह धन के असमान संचय और वैश्विक आर्थिक असंतुलन को बढ़ाता है।

159. (C) विकासशील देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में निम्न-मूल्य वर्धित गतिविधियों तक सीमित रह जाते हैं।
निर्भरता का मॉडल एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था को दर्शाता है जहां विकासशील देश केवल निम्न-मूल्य वर्धित गतिविधियों तक ही सीमित रह जाते हैं। इसके विपरीत, उच्च-मूल्य वाली अनुसंधान, डिजाइन और विपणन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं विकसित देशों में केंद्रित रहती हैं। इससे विकासशील देश वैश्विक अर्थव्यवस्था के केवल एक संसाधन प्रदाता के रूप में विकसित राष्ट्रों पर निरंतर आर्थिक रूप से निर्भर बने रहते हैं।

160. (A) (A) वे उत्पादन प्रक्रियाओं को विभिन्न देशों में वितरित करने का एक माध्यम हैं।
वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं उत्पादन की विभिन्न प्रक्रियाओं को अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में वितरित करने का एक अत्यंत प्रभावी माध्यम हैं। बहुराष्ट्रीय निगम इस प्रणाली का उपयोग करके श्रम और कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर दुनिया भर में अपना कार्य संचालन करते हैं। यह व्यवस्था विभिन्न देशों को एक-दूसरे से जोड़ती है और वस्तुओं के वैश्विक स्तर पर निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करती है।

161. (D) यह एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है जिसमें समरूपता और वैविध्यकरण दोनों शामिल हैं।
सांस्कृतिक वैश्वीकरण एक अत्यंत जटिल और द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है जिसमें दो विरोधी धाराएं साथ चलती हैं। एक तरफ यह वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक समरूपता को बढ़ावा देती है, वहीं दूसरी तरफ यह स्थानीय स्तर पर सांस्कृतिक वैविध्यकरण और मिश्रण को भी प्रोत्साहित करती है। यह प्रक्रिया संस्कृतियों को नष्ट करने के बजाय उन्हें वैश्विक संदर्भों में नई व्याख्या और नया स्वरूप प्रदान करती है।

162. (B) पश्चिमी संस्कृति
सांस्कृतिक समरूपता के दौरान अक्सर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव दुनिया भर में अधिक शक्तिशाली रूप से देखा जाता है। इसे अक्सर 'पश्चिमीकरण' या 'अमेरिकीकरण' भी कहा जाता है क्योंकि पश्चिमी मीडिया, फैशन और खान-पान की आदतें वैश्विक मानकों के रूप में उभरती हैं। यह वर्चस्व अन्य कम शक्तिशाली संस्कृतियों के अनूठे गुणों और उनकी पारंपरिक पहचान के लिए एक बड़ा खतरा है।

163. (C) वैश्विक और स्थानीय सांस्कृतिक तत्वों का मिश्रण होकर नए रूपों का निर्माण।
'ग्लोकलाइजेशन' की अवधारणा वैश्विक और स्थानीय सांस्कृतिक तत्वों के सफल एकीकरण को प्रदर्शित करती है। जब वैश्विक विचार या उत्पाद किसी विशिष्ट स्थानीय परिवेश में प्रवेश करते हैं, तो वे वहां के मूल्यों और स्वादों के अनुरूप ढल जाते हैं। यह प्रक्रिया न तो स्थानीय संस्कृति को मिटाती है और न ही वैश्विक को पूरी तरह अपनाती है, बल्कि एक नया स्वरूप निर्मित करती है।

164. (D) एक अंतरराष्ट्रीय फास्ट-फूड श्रृंखला द्वारा अपने मेनू में स्थानीय व्यंजन शामिल करना।
सांस्कृतिक संकरीकरण तब दिखाई देता है जब कोई वैश्विक संस्थान स्थानीय प्राथमिकताओं को अपनाता है। उदाहरण के लिए, जब एक अंतरराष्ट्रीय फास्ट-फूड श्रृंखला अपने वैश्विक मेनू में स्थानीय मसालों या व्यंजनों को शामिल करती है, तो वह एक संकर संस्कृति का निर्माण करती है। यह इस बात का प्रमाण है कि संस्कृति कोई स्थिर वस्तु नहीं है, बल्कि वैश्विक प्रभावों के साथ अनुकूलित होती है।

165. (A) (A) संस्कृति एक गतिशील क्षेत्र है जहाँ वैश्विक प्रभावों की स्थानीय स्तर पर व्याख्या और अनुकूलन होता है।
इस स्रोत का मुख्य तर्क यह है कि संस्कृति एक अत्यंत गतिशील और सक्रिय क्षेत्र है। वैश्वीकरण के प्रभाव को स्थानीय समाज केवल निष्क्रिय रूप से स्वीकार नहीं करते, बल्कि वे इन प्रभावों की सक्रिय रूप से व्याख्या करते हैं और उन्हें अपने अनुसार अपनाते हैं। इस प्रकार, संस्कृति वैश्विक दबावों के बीच अपनी पहचान को निरंतर नए रूपों में पुनर्परिभाषित और अनुकूलित करती है।

166. (B) क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव के विरुद्ध नहीं, बल्कि नव-उदारवादी मॉडल के विरुद्ध हैं।
वैश्वीकरण के प्रतिरोध को 'वैकल्पिक वैश्वीकरण' कहना अधिक सटीक है क्योंकि ये आंदोलन वैश्विक जुड़ाव के खिलाफ नहीं हैं। उनका विरोध केवल उस नव-उदारवादी आर्थिक मॉडल से है जो सामाजिक न्याय के बजाय कॉर्पोरेट मुनाफे को अधिक प्राथमिकता देता है। ये आंदोलन एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जो मानवाधिकारों, पर्यावरणीय स्थिरता और अधिक लोकतांत्रिक वैश्विक शासन पर आधारित हो, न कि व्यापार पर।

167. (B) नव-उदारवादी वैश्वीकरण के विकल्पों पर चर्चा के लिए एक खुली जगह प्रदान करना।
विश्व सामाजिक मंच का प्राथमिक उद्देश्य नव-उदारवादी वैश्वीकरण के विभिन्न विकल्पों पर व्यापक चर्चा हेतु एक स्वतंत्र मंच प्रदान करना है। यह सामाजिक आंदोलनों और बुद्धिजीवियों को संवाद करने की अनुमति देता है। यह किसी विचारधारा को थोपने के बजाय वैश्विक नीतियों के निर्माण के लिए एक लोकतांत्रिक स्थान सुनिश्चित करता, जहां अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था की संभावनाओं पर विचार हो।

168. (A) (A) एक ऐसी दुनिया की कल्पना जो अधिक न्यायपूर्ण, टिकाऊ और समान हो।
"एक और दुनिया संभव है" का नारा एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो वर्तमान लाभ-केंद्रित वैश्विक व्यवस्था को चुनौती देता है। इसका तात्पर्य एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना है जहां सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और पर्यावरणीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। यह नारा संदेश देता है कि मानवता के पास अधिक मानवीय, न्यायपूर्ण और टिकाऊ वैश्विक व्यवस्था बनाने की क्षमता और विकल्प हैं।

169. (C) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और बहुराष्ट्रीय निगमों की।
ये आंदोलन मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और बहुराष्ट्रीय निगमों की अलोकतांत्रिक कार्यप्रणाली की कड़ी आलोचना करते हैं। उनका तर्क है कि ये संस्थाएं वैश्विक दक्षिण के देशों का शोषण करती हैं और पर्यावरण तथा श्रम अधिकारों की अनदेखी करती हैं। इन आंदोलनों के अनुसार, ये शक्तिशाली निकाय केवल कॉर्पोरेट हितों की सेवा करते हैं, जिससे विकासशील देशों की संप्रभुता पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

170. (D) अनियंत्रित कॉर्पोरेट शक्ति का समर्थन
वैकल्पिक वैश्वीकरण आंदोलन कभी भी अनियंत्रित कॉर्पोरेट शक्ति का समर्थन नहीं करते; इसके विपरीत, वे निगमों की जवाबदेही तय करने की मांग करते हैं। उनकी मुख्य प्राथमिकताओं में निष्पक्ष व्यापार, विकासशील देशों के लिए ऋण माफी और सख्त पर्यावरण संरक्षण नियम शामिल हैं। ये आंदोलन एक ऐसी वैश्विक शासन प्रणाली की वकालत करते हैं जो लोकतांत्रिक हो और जिसमें कॉर्पोरेट लाभ के स्थान पर लोक-कल्याण हो।

171. (C) 1991 के आर्थिक सुधार
भारत में वैश्वीकरण की दिशा में सबसे निर्णायक कदम 1991 के आर्थिक सुधारों के माध्यम से उठाया गया था। इन सुधारों ने लंबे समय से चले आ रहे 'लाइसेंस राज' को समाप्त किया और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खोल दिया। इसके परिणामस्वरूप विदेशी निवेश और उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए नए मार्ग प्रशस्त हुए, जिससे भारत की आर्थिक विकास दर में आमूल-चूल परिवर्तन हुए।

172. (B) सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र का विकास।
भारत में वैश्वीकरण का एक अत्यंत सकारात्मक परिणाम सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व वृद्धि है। इन सुधारों ने भारत को वैश्विक बाजार में एक प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। इस विकास ने न केवल विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि की, बल्कि शहरी क्षेत्रों में एक समृद्ध और कुशल मध्यम वर्ग का निर्माण किया, जिसे वैश्विक स्तर पर अवसर मिले।

173. (D) वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के महत्वपूर्ण प्रभाव थे।
"दोहरी तलवार" मुहावरे का प्रयोग यह स्पष्ट करने के लिए किया गया है कि वैश्वीकरण के परिणाम परस्पर विरोधी रहे हैं। एक तरफ इसने आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और सेवा क्षेत्र में सफलता के द्वार खोले हैं। वहीं दूसरी तरफ, इसने कृषि संकट और बढ़ती आर्थिक असमानता जैसी गंभीर चुनौतियां पैदा की हैं। यह दर्शाता है कि वैश्वीकरण से हुए लाभों के साथ-साथ महत्वपूर्ण नुकसान भी हुए हैं।

174. (A) (A) कृषि क्षेत्र का संकट और आर्थिक असमानता में वृद्धि।
भारत में वैश्वीकरण के कारण कृषि क्षेत्र गंभीर संकट में आ गया, क्योंकि किसानों को वैश्विक बाजार की अनिश्चितताओं और कम सरकारी समर्थन का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही, आर्थिक विकास का लाभ समान रूप से वितरित नहीं हुआ, जिससे समाज में अमीरी और गरीबी के बीच की खाई बढ़ गई। छोटे व्यवसायों को भी अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों और सस्ते विदेशी आयातों से प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़ी।

175. (C) सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र
भारत का 'वैश्विक बैक ऑफिस' के रूप में उभरना विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र की तीव्र प्रगति को दर्शाता है। विदेशी कंपनियों ने भारत की सस्ती और कुशल श्रम शक्ति का लाभ उठाते हुए अपने डेटा और तकनीकी कार्यों को यहां

स्थानांतरित किया। इस क्षेत्र ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका को मजबूत किया और देश को प्रमुख डिजिटल केंद्रों में शामिल किया।

(B) जनवरी 1948 में
(C) दिसंबर 1949 में
(D) सितंबर 1948 में

40. निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (रियासत)
P. हैदराबाद
Q. मणिपुर
R. जूनागढ़
S. त्रावणकोर
सूची II: (विशेषता/घटना)
1. सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा
2. विलय जनमत संग्रह के माध्यम से हुआ
3. 'रज़ाकार' का आतंक
4. सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर चुनाव
(A) P-4, Q-3, R-1, S-2
(B) P-3, Q-4, R-2, S-1
(C) P-2, Q-1, R-4, S-3
(D) P-3, Q-2, R-1, S-4

41. मणिपुर के किस महाराजा ने भारत सरकार के साथ विलय के सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए थे?
(A) हरि सिंह
(B) मान सिंह
(C) बोधचंद्र सिंह
(D) जयचंद्र सिंह

42. भारत का वह पहला भाग कौन सा है जहाँ सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए?
(A) मणिपुर
(B) हैदराबाद
(C) कश्मीर
(D) त्रावणकोर

43. मणिपुर की विधानसभा में विलय के सवाल पर कांग्रेस का क्या रुख था?
(A) कांग्रेस चाहती थी कि मणिपुर एक स्वतंत्र राज्य बना रहे।
(B) कांग्रेस इस मुद्दे पर तटस्थ थी।
(C) कांग्रेस ने महाराजा के निर्णय का समर्थन किया।
(D) कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए।

44. निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें:
1. मणिपुर में चुनाव का आयोजन
2. हैदराबाद का भारत में विलय
3. त्रावणकोर द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा
4. मणिपुर का भारत में विलय
(A) 3, 1, 2, 4
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 3, 2, 1, 4
(D) 2, 4, 1, 3

45. औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएँ तय करने का आधार क्या था?
(A) क्षेत्रीय भाषाई और सांस्कृतिक समानता का आधार
(B) संबंधित क्षेत्र की जनसंख्या का कुल घनत्व
(C) प्रशासनिक सुविधा या ब्रिटिश सरकार द्वारा विजित क्षेत्र
(D) उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का क्षेत्रीय वितरण

46. कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के सिद्धांत को मान लिया गया था?
(A) 1929 का लाहौर अधिवेशन
(B) 1931 का कराची अधिवेशन
(C) 1942 का बंबई अधिवेशन
(D) 1920 का नागपुर अधिवेशन

47. स्वतंत्रता और बँटवारे के बाद, राष्ट्रीय नेतृत्व ने भाषावार राज्यों के गठन के मसले को स्थगित करने का फैसला क्यों किया?
(A) इससे अव्यवस्था और देश टूटने का खतरा पैदा होने का डर था।
(B) क्योंकि उन्हें भाषाई आधार पर उभरने वाले स्थानीय नेताओं पर पूर्ण विश्वास नहीं था।
(C) क्योंकि केंद्र सरकार के पास इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन नहीं थे।
(D) क्योंकि निवर्तमान ब्रिटिश सरकार ने ऐसा करने से स्पष्ट रुप से मना किया था।

48. पुराने मद्रास प्रांत के किन क्षेत्रों में अलग तेलुगु-भाषी राज्य के लिए विरोध भड़क उठा था?
(A) कन्नड़-भाषी क्षेत्रों में
(B) तेलुगु-भाषी क्षेत्रों में
(C) तमिल-भाषी क्षेत्रों में
(D) मलयालम-भाषी क्षेत्रों में

49. 'विशाल आंध्र आंदोलन' की मुख्य माँग क्या थी?
(A) संपूर्ण मद्रास प्रांत को एक स्वतंत्र देश के रुप में मान्यता दी जाए।
(B) तेलुगुभाषी इलाकों को अलग कर आंध्र प्रदेश बनाया जाए।
(C) पूरे मद्रास प्रांत का नाम बदलकर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश कर दिया जाए।
(D) मद्रास प्रांत में तेलुगु को अनिवार्य और आधिकारिक भाषा के रुप में अपनाया जाए।

50. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. पोट्टी श्रीरामुलु कांग्रेस के नेता और गाँधीवादी थे।
2. उन्होंने अलग आंध्र राज्य की माँग के लिए अनिश्चितकालीन भूख-हड़ताल की।
3. 56 दिनों की भूख-हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई।

1. स्वतंत्र भारत की पहली चुनौती राष्ट्रीय एकता स्थापित करने की थी।
2. दूसरी चुनौती संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार को चलन में लाने की थी।
3. तीसरी चुनौती समूचे समाज का भला करने वाले विकास की थी।
4. संविधान ने सामाजिक रूप से वंचित तबकों को कोई विशेष सुरक्षा प्रदान नहीं की।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) उपरोक्त सभी

10. मुस्लिम लीग द्वारा प्रतिपादित 'द्वि-राष्ट्र सिद्धांत' का आधार क्या था?
(A) भारत 'हिंदू' और 'मुसलमान' नाम की दो कौमों का देश था।
(B) भारत में केवल एक ही कौम, हिंदू, का प्रभुत्व होना चाहिए।
(C) भारत को भाषा के आधार पर दो राष्ट्रों में बाँट देना चाहिए।
(D) भारत को आर्थिक असमानता के आधार पर विभाजित किया जाना चाहिए।

11. 'सुब्ह-ए-आज़ादी' नामक प्रसिद्ध नज़्म किसने लिखी, जिसमें विभाजन की सुबह का दर्दनाक चित्रण है?
(A) अमृता प्रीतम
(B) सआदत हसन मंटो
(C) मुहम्मद इक़बाल
(D) फ़ैज़ अहमद फ़ैज़

12. निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें:
1. महात्मा गाँधी की हत्या
2. भारत की स्वतंत्रता और विभाजन
3. राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना
4. हैदराबाद का भारत में विलय

(A) 2, 4, 1, 3
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 1, 4, 3
(D) 4, 3, 2, 1

13. भारत के विभाजन के लिए किस कारक को आधार बनाया गया था?
(A) भौगोलिक सीमा
(B) भाषाई भिन्नता
(C) धार्मिक बहुसंख्या
(D) आर्थिक विकास

14. विभाजन प्रक्रिया की समस्याओं के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हों।
2. मुस्लिम-बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था।
3. ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम-बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर-मुस्लिम आबादी वाले थे।
4. सीमा के दोनों तरफ़ अल्पसंख्यक मौजूद थे जिनकी सुरक्षा एक बड़ी समस्या थी।
5. विभाजन की योजना में आबादी की अदला-बदली शामिल थी।

उपरोक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 2, 3 और 4
(C) केवल 1, 3, 4 और 5
(D) उपरोक्त सभी

15. पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत के उस नेता का क्या नाम था जो 'द्वि-राष्ट्र सिद्धांत' के एकदम खिलाफ़ थे और जिन्हें 'सीमांत गाँधी' के नाम से जाना जाता था?
(A) खान अब्दुल गफ्फार खान
(B) मुहम्मद अली जिन्ना
(C) लियाक़त अली ख़ान
(D) मौलाना अबुल कलाम आज़ाद

16. नीचे दिए गए कथन I और कथन II को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें:
कथन I: पंजाब और बंगाल का बँटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ।
कथन II: इन दोनों प्रांतों में बँटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर जिले अथवा उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार मानकर किया गया था।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं, और कथन II, कथन I की सही व्याख्या करता है।
(B) कथन I और कथन II दोनों सही हैं, लेकिन कथन II, कथन I की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

17. विभाजन के समय, कौन से दो शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए थे?
(A) दिल्ली और मुंबई
(B) लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता
(C) कराची और ढाका
(D) हैदराबाद और जूनागढ़

18. नीचे दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें:
अभिकथन (A): विभाजन के बाद भारत के नेताओं ने धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श को अपनाया।

कारण (R): वे भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहते थे जहाँ किसी एक धर्म के अनुयायियों को दूसरे धर्मावलंबियों के ऊपर वरीयता दी जाए।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

19. विभाजन की त्रासदी को दर्शाने वाली कविता 'आज आखाँ वारिस शाह नूं' की रचना किसने की थी?
(A) फ़ैज़ अहमद फ़ैज़
(B) सआदत हसन मंटो
(C) अमृता प्रीतम
(D) इस्मत चुग़ताई

20. निम्नलिखित में से कौन सी एक विभाजन की सबसे अबूझ कठिनाई थी?
(A) संपदा का बँटवारा
(B) सरकारी कर्मचारियों का बँटवारा
(C) रेलवे का बँटवारा
(D) अल्पसंख्यकों की समस्या

21. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. विभाजन के कारण लगभग 80 लाख लोगों को सीमा-पार जाना पड़ा।
2. विभाजन की हिंसा में तकरीबन पाँच से दस लाख लोगों ने अपनी जान गँवाई।
3. वित्तीय संपदा के साथ-साथ टेबुल, कुर्सी, टाईपराइटर जैसी अचल संपत्तियों का भी बँटवारा हुआ।
4. सरकारी और रेलवे के कर्मचारियों का भी बँटवारा हुआ।

उपरोक्त में से कौन से कथन विभाजन के परिणामों के संबंध में सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3 और 4
(C) केवल 1, 2 और 4
(D) उपरोक्त सभी

22. 1951 के समय भारत की कुल आबादी में लगभग कितने प्रतिशत मुसलमान थे?
(A) 5-7 प्रतिशत
(B) 10-12 प्रतिशत
(C) 15-18 प्रतिशत
(D) 20-22 प्रतिशत

23. एम. एस. सथ्यु द्वारा निर्देशित 1973 की फिल्म 'गर्म हवा' का मुख्य पात्र सलीम मिर्ज़ा किस शहर में रहता है और विभाजन के बाद किन समस्याओं का सामना करता है?
(A) लखनऊ, और उसे अपना घर बेचना पड़ता है।
(B) दिल्ली, और उसका कारोबार ठप हो जाता है।
(C) अलीगढ़, और उसे विश्वविद्यालय से निकाल दिया जाता है।
(D) आगरा, और उसका जूते का व्यवसाय चौपट होने लगता है।

24. महात्मा गाँधी ने 15 अगस्त 1947 का दिन कहाँ बिताया था?
(A) कोलकाता में, जहाँ वे दंगों को शांत कराने का प्रयास कर रहे थे।
(B) दिल्ली में, राष्ट्रीय आज़ादी के भव्य जश्न में सक्रिय भाग लेते हुए।
(C) मुंबई में, सभी धर्मों के लिए एक सार्वजनिक प्रार्थना-सभा आयोजित करते हुए।
(D) साबरमती आश्रम में, आत्मिक शुद्धि के लिए मौन उपवास पर बैठे हुए।

25. 30 जनवरी 1948 को महात्मा गाँधी की हत्या किसने की?
(A) सरदार पटेल के एक अनुयायी ने
(B) एक मुस्लिम अतिवादी ने
(C) नाथूराम विनायक गोडसे ने
(D) एक ब्रिटिश अधिकारी ने

26. निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (व्यक्ति/संगठन)
P. नाथूराम गोडसे
Q. मुस्लिम लीग
R. महात्मा गाँधी
S. जवाहरलाल नेहरु
सूची II: (विचारधारा/कार्य)
1. द्वि-राष्ट्र सिद्धांत
2. 'भाग्यवधू से चिर-प्रतीक्षित भेंट' भाषण
3. हिंदू अतिवादी
4. सांप्रदायिक सद्भाव के लिए उपवास
(A) P-3, Q-1, R-4, S-2
(B) P-1, Q-3, R-2, S-4
(C) P-4, Q-2, R-1, S-3
(D) P-3, Q-4, R-2, S-1

27. जनवरी 1948 में गाँधीजी के अंतिम उपवास का तात्कालिक परिणाम क्या था?
(A) नाथूराम गोडसे को पुलिस द्वारा तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया।
(B) देश के सभी प्रमुख रजवाड़े भारतीय संघ में शामिल हो गए।
(C) राज्य पुनर्गठन आयोग का विधिवत गठन किया गया।
(D) भारत सरकार पाकिस्तान को देय राशि चुकाने पर सहमत हुई।

28. ब्रिटिश इंडिया के वे कौन से दो हिस्से थे जिन पर अंग्रेजी सरकार का शासन-प्रकार भिन्न था?
(A) उत्तर के विशाल प्रांत और दक्षिण के कुछ छोटे प्रांत

(B) ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत और देसी रजवाड़े
(C) समुद्र तटीय क्षेत्र और देश के आंतरिक भू-भाग वाले क्षेत्र
(D) मुख्य शहरी केंद्र और दूर-दराज के सभी ग्रामीण इलाके

29. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. ब्रिटिश-राज की समाप्ति के साथ, रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो गए।
2. रजवाड़ों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया।
3. रजवाड़े अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रख सकते थे।
4. विलय का फ़ैसला लेने का अधिकार रजवाड़ों की प्रजा को दिया गया था।

उपरोक्त में से कौन से कथन रजवाड़ों के संबंध में अंग्रेजी-शासन की घोषणा के बारे में सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1, 2 और 3
(C) केवल 2, 3 और 4
(D) उपरोक्त सभी

30. स्वतंत्रता के समय भारत में देसी रजवाड़ों की संख्या लगभग कितनी थी?
(A) 250
(B) 365
(C) 710
(D) 565

31. सबसे पहले किस रजवाड़े के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा की?
(A) त्रावणकोर
(B) हैदराबाद
(C) जूनागढ़
(D) कश्मीर

32. नीचे दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें:
अभिकथन (A): देसी रजवाड़ों के शासकों को मनाने-समझाने में सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई।
कारण (R): अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसे 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ एक्सेशन' कहा जाता है।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

33. वह सहमति-पत्र क्या कहलाता था जिस पर हस्ताक्षर करके रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत हुए?
(A) विलय की संधि
(B) इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ एक्सेशन
(C) एकता का घोषणापत्र
(D) स्वतंत्रता का समझौता

34. देसी रजवाड़ों के विलय के संबंध में भारत सरकार के नज़रिये के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे।
2. भारत सरकार का रुख लचीला था और वह कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी।
3. विभाजन की पृष्ठभूमि में देश की क्षेत्रीय अखंडता-एकता का सवाल सबसे ज़्यादा अहम हो उठा था।
4. भारत सरकार ने सभी रजवाड़ों को बलपूर्वक विलय के लिए मजबूर किया।
5. सरकार ने रजवाड़ों को पूर्ण स्वायत्तता देने का वादा किया था।

उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 2, 3 और 4
(C) केवल 1, 4 और 5
(D) केवल 1, 2 और 5

35. किन चार रियासतों का विलय बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ?
(A) त्रावणकोर, मैसूर, बड़ौदा, ग्वालियर
(B) भोपाल, रामपुर, बीकानेर, जयपुर
(C) जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर
(D) कोल्हापुर, कूच बिहार, पटियाला, त्रिपुरा

36. हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था?
(A) नवाब
(B) महाराजा
(C) सुलतान
(D) निज़ाम

37. हैदराबाद के निज़ाम के दमनकारी शासन के खिलाफ़ आंदोलन में कौन से समूह अग्रिम पंक्ति में थे?
(A) केवल तेलंगाना के किसान
(B) केवल महिला संगठन
(C) कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस
(D) केवल शहरी बुद्धिजीवी

38. हैदराबाद के निज़ाम द्वारा लोगों के खिलाफ़ भेजे गए अर्द्ध-सैनिक बल को क्या कहा जाता था?
(A) सिपाही
(B) रज़ाकार
(C) मुजाहिद
(D) स्वयंसेवक

39. भारतीय सेना ने निज़ाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद में कब हस्तक्षेप किया?
(A) अगस्त 1947 में

अध्याय 08
राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

1. 1947 के 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से जाना जाता है?
(A) भारत की खोज नामक एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक
(B) भाग्यवधू से चिर-प्रतीक्षित भेंट
(C) भारतीय स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव और उत्सव
(D) भारत के एक बिल्कुल नए युग की गौरवशाली शुरुआत

2. स्वतंत्र भारत के समक्ष मुख्य तौर पर कितनी प्रमुख चुनौतियाँ थीं?
(A) तीन
(B) दो
(C) चार
(D) पाँच

3. निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (चुनौती)
P. पहली चुनौती
Q. दूसरी चुनौती
R. तीसरी चुनौती
S. विभाजन का आधार
सूची II: (विवरण)
1. लोकतंत्र को कायम करना
2. समूचे समाज का भला करने वाला विकास
3. राष्ट्रीय एकता और अखंडता
4. धार्मिक बहुसंख्या
(A) P-3, Q-1, R-2, S-4
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-2, R-1, S-4
(D) P-2, Q-3, R-4, S-1

4. स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
(A) भारत का जन्म अत्यंत कठिन और विषम परिस्थितियों में हुआ था।
(B) देश को आज़ादी इसके हिंसक और खूनी बँटवारे के साथ ही मिली।
(C) 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था।
(D) स्वतंत्रता के समय भारत में केवल आर्थिक विकास की चुनौती थी।

5. स्वतंत्र भारत के लिए दो बातों पर सबकी सहमति थी। वे दो बातें क्या थीं?
(A) देश का शासन राजतांत्रिक होगा और सरकार केवल बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करेगी।
(B) देश का शासन सैन्य प्रमुख चलाएगा और समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर होंगे।
(C) देश लोकतांत्रिक सरकार से चलेगा और वह सबके भले के लिए काम करेगी।
(D) देश का शासन एक-दलीय प्रणाली पर आधारित होगा और सरकार केवल बहुसंख्यकों का ध्यान रखेगी।

6. नीचे दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें:
अभिकथन (A): स्वतंत्रता के बाद भारत के नेताओं के लिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता एक प्रमुख चिंता का विषय थी।
कारण (R): भारत आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था, जहाँ अलग-अलग भाषा, संस्कृति और धर्म के लोग रहते थे, जिससे एकजुटता को लेकर संदेह था।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

7. भारतीय संविधान में किस सिद्धांत के अंतर्गत लोक-कल्याण के लक्ष्यों को स्पष्ट किया गया है, जिन्हें राजनीति को पूरा करना चाहिए?
(A) मौलिक अधिकार
(B) प्रस्तावना
(C) मौलिक कर्तव्य
(D) राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत

8. "कल हम अंग्रेज़ी-राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएँगे लेकिन आधी रात को भारत का बँटवारा भी होगा। इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी।" यह कथन 14 अगस्त 1947 को किसने कहा था?
(A) महात्मा गाँधी
(B) जवाहरलाल नेहरु
(C) सरदार पटेल
(D) मुहम्मद अली जिन्ना

9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

4. उनकी मृत्यु के बाद आंदोलन शांत हो गया।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) उपरोक्त सभी

51. प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा कब की?

(A) अक्टूबर 1952 में
(B) नवंबर 1952 में
(C) दिसंबर 1952 में
(D) जनवरी 1953 में

52. राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई?

(A) 1950 में
(B) 1952 में
(C) 1956 में
(D) 1953 में

53. राज्य पुनर्गठन आयोग की प्रमुख सिफारिश क्या थी?

(A) राज्यों की सीमाओं का निर्धारण प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए।
(B) मौजूदा राज्यों की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
(C) राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए।
(D) राज्यों का गठन आर्थिक विकास के आधार पर किया जाना चाहिए।

54. राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ?

(A) 1953
(B) 1956
(C) 1955
(D) 1960

55. 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कितने राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश बनाए गए?

(A) 16 राज्य और 3 केंद्र-शासित प्रदेश
(B) 22 राज्य और 8 केंद्र-शासित प्रदेश
(C) 12 राज्य और 5 केंद्र-शासित प्रदेश
(D) 14 राज्य और 6 केंद्र-शासित प्रदेश

56. भाषावार राज्यों के पुनर्गठन से होने वाले लाभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भाषावार राज्यों के पुनर्गठन से विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली।
2. इससे देश की एकता और ज़्यादा मज़बूत हुई।
3. राजनीति और सत्ता में भागीदारी का रास्ता एक छोटे-से अंग्रेजीभाषी अभिजात तबके के लिए ही नहीं, बाकियों के लिए भी खुल गया।
4. इसके कारण देश कई छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट गया।
5. इसने अलगाववाद की भावना को बहुत अधिक बढ़ावा दिया।

उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 2, 4 और 5
(C) केवल 3, 4 और 5
(D) केवल 1, 4 और 5

57. 1960 में द्विभाषी राज्य बंबई को किन दो राज्यों में विभाजित किया गया?

(A) गोवा और महाराष्ट्र
(B) गुजरात और राजस्थान
(C) महाराष्ट्र और गुजरात
(D) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र

58. निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:

सूची I: (राज्य)

P. महाराष्ट्र और गुजरात
Q. पंजाब और हरियाणा
R. मेघालय
S. छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड

सूची II: (गठन का वर्ष)

1. 1966
2. 2000
3. 1960
4. 1972

(A) P-3, Q-1, R-4, S-2
(B) P-1, Q-3, R-2, S-4
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-4, Q-2, R-3, S-1

59. 1966 में पंजाब राज्य का पुनर्गठन कर कौन से नए राज्य बनाए गए?

(A) पंजाब और हिमाचल प्रदेश
(B) पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश
(C) केवल पंजाब और हरियाणा
(D) हरियाणा और हिमाचल प्रदेश

60. पूर्वोत्तर में 1972 में असम से अलग करके कौन सा राज्य बनाया गया?

(A) नगालैंड
(B) मेघालय
(C) मिज़ोरम
(D) अरुणाचल प्रदेश

61. नगालैंड राज्य का गठन कब हुआ?

(A) 1972 में
(B) 1987 में
(C) 1963 में

139. निम्नलिखित में से कौन-सा एक विभाजन का परिणाम नहीं था?
(A) 80 लाख लोगों का विस्थापन।
(B) 5 से 10 लाख लोगों की मृत्यु।
(C) पुलिस के वाद्ययंत्रों तक का बँटवारा।
(D) भारत का स्वतः एक हिंदू राष्ट्र बन जाना।

140. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. हैदराबाद शहर निज़ाम के खिलाफ़ चल रहे आंदोलन का गढ़ बन गया था।
2. तेलंगाना इलाके के किसान निज़ाम के दमनकारी शासन से दुखी थे।
3. महिलाएँ बड़ी संख्या में आंदोलन से जुड़ी थीं।
4. कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस आंदोलन में अग्रिम पंक्ति में थे।
उपरोक्त में से कौन से कथन हैदराबाद आंदोलन के संबंध में सही हैं?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2 और 4
(C) केवल 1, 2 और 4
(D) उपरोक्त सभी

141. निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (दिनांक/वर्ष)
P. 14-15 अगस्त 1947
Q. 30 जनवरी 1948
R. दिसंबर 1952
S. 1956
सूची II: (घटना)
1. राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित
2. आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा
3. महात्मा गाँधी की हत्या
4. भारत का विभाजन और स्वतंत्रता
(A) P-4, Q-3, R-2, S-1
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-2, R-1, S-3
(D) P-3, Q-4, R-2, S-1

142. विभाजन की प्रक्रिया में वह कौन-सी रियासत थी जहाँ के नेता ('सीमांत गाँधी') द्वि-राष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे, फिर भी उस रियासत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया?
(A) बलूचिस्तान
(B) सिंध
(C) पंजाब
(D) पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत

143. राष्ट्र-निर्माण के लिहाज से भारत और सोवियत संघ के प्रयोगों में क्या मुख्य समानता थी?
(A) विभिन्न समूहों के बीच एकता कायम करनी पड़ी।
(B) दोनों ने पूर्णतः लोकतांत्रिक तरीकों को अपनाया।
(C) दोनों में राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया पूरी तरह से शांतिपूर्ण और अहिंसक थी।
(D) दोनों में राष्ट्र-निर्माण का ऐतिहासिक कार्य एक ही समय में शुरु हुआ।

144. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के समक्ष कौन सी प्रमुख चुनौतियां थीं?
1. पहली चुनौती राष्ट्रीय एकता और अखंडता की थी।
2. दूसरी चुनौती लोकतंत्र कायम करने की थी।
3. तीसरी चुनौती ऐसा विकास करने की थी जिससे समूचे समाज का भला हो।
4. चौथी चुनौती सैन्य विस्तार की थी।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1, 2 और 3
(C) केवल 2, 3 और 4
(D) उपरोक्त सभी

145. "भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वे चाहें तब भी यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते।" यह कथन किसका है?
(A) महात्मा गाँधी
(B) जवाहरलाल नेहरु
(C) सरदार पटेल
(D) मुहम्मद अली जिन्ना

146. नीचे दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें:
अभिकथन (A): देसी रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलय एक जटिल काम था।
कारण (R): त्रावणकोर, हैदराबाद और भोपाल जैसे शासक स्वतंत्र रहना चाहते थे, जिससे भारत के कई टुकड़ों में बँट जाने का खतरा था।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

147. भारत में वह कौन-सा पहला भाग था जहाँ 1948 में सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए, जिसके परिणामस्वरुप संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ?
(A) जम्मू और कश्मीर
(B) हैदराबाद
(C) मणिपुर
(D) त्रावणकोर

148. राज्य पुनर्गठन आयोग (1953) का मुख्य कार्य क्या था?
(A) नए राज्यों के लिए राजधानियों का चयन करना।
(B) केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित

(C) केवल 2 और 4
(D) उपरोक्त सभी

72. नीचे दिए गए कथन I और कथन II को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें:
कथन I: विभाजन के समय, खान अब्दुल गफ्फार खान ने द्वि-राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया।
कथन II: उन्हें 'सीमांत गाँधी' के नाम से जाना जाता था और वे पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत के निर्विवाद नेता थे।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
(D) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।

73. विभाजन के परिणामस्वरूप, लोगों को अपना घर-बार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन विस्थापित लोगों को अस्थायी तौर पर कहाँ पनाह लेनी पड़ी?
(A) सरकारी भवनों में
(B) स्कूलों में
(C) शरणार्थी शिविरों में
(D) किलों में

74. निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (अवधारणा/सिद्धांत)
P. द्वि-राष्ट्र सिद्धांत
Q. इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ एक्सेशन
R. सार्वभौम वयस्क मताधिकार
S. राज्य पुनर्गठन आयोग
सूची II: (संबद्धता)
1. रियासतों का विलय
2. मुस्लिम लीग
3. भाषाई आधार पर राज्यों का गठन
4. मणिपुर में चुनाव
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-1, R-4, S-3
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-2, Q-3, R-4, S-1

75. विभाजन की हिंसा के संबंध में सआदत हसन मंटो की कहानी 'कस्र-ए-नफ्सी' में क्या दर्शाया गया है?
(A) निर्दोष महिलाओं के हिंसक अपहरण की हृदयविदारक त्रासदी।
(B) शरणार्थी शिविरों की अत्यंत दयनीय और कष्टकारी भौतिक स्थिति।
(C) पैतृक अचल संपत्ति के हिंसक बँटवारे पर होने वाला विवाद।
(D) ट्रेन रोककर गैर-मज़हब के लोगों की दंगाइयों द्वारा हत्या।

76. महात्मा गाँधी की हत्या के बाद, सरकार ने किस संगठन को गैर-कानूनी घोषित कर दिया था?
(A) मुस्लिम लीग
(B) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
(C) हिंदू महासभा
(D) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी

77. आज का उड़ीसा, स्वतंत्रता के समय, कितने छोटे-बड़े रजवाड़ों से मिलकर बना था?
(A) 15
(B) 14
(C) 26
(D) 119

78. "हम भारत के इतिहास के एक यादगार मुकाम पर खड़े हैं।" यह कथन किसने रियासतों के शासकों को लिखे एक पत्र में कहा था?
(A) जवाहरलाल नेहरु
(B) महात्मा गाँधी
(C) लॉर्ड माउंटबेयटन
(D) सरदार पटेल

79. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने जनमत के दबाव में 1948 में चुनाव करवाए।
2. इस चुनाव के फलस्वरुप मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ।
3. मणिपुर की विधानसभा में विलय के सवाल पर कोई मतभेद नहीं था।
4. भारत सरकार ने महाराजा को विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी कर लिया।
5. मणिपुर का विलय सितंबर 1949 में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1, 2, 3
(B) केवल 2, 3, 4
(C) केवल 1, 2, 4, 5
(D) उपरोक्त सभी

80. पोट्टी श्रीरामुलु ने अलग आंध्र राज्य के अलावा और किस मांग को लेकर उपवास किया था?
(A) किसानों के कर्ज माफ करने के लिए।
(B) मद्रास प्रांत के मंदिर दलितों के लिए खोल दिए जाएँ।
(C) सभी के लिए मुफ्त शिक्षा।
(D) भूमि सुधारों के लिए।

81. 1956 के बाद नए राज्यों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है?
(A) महाराष्ट्र और गुजरात - 1960
(B) मिजोरम - 1963
(C) हरियाणा - 1966

R. जूनागढ़ का विलय
S. आंध्र आंदोलन

सूची II: (प्रमुख व्यक्ति/कारक)
1. पोट्टी श्रीरामुलु
2. जनमत संग्रह
3. महाराजा बोधचंद्र सिंह
4. रज़ाकार / सैन्य कार्रवाई

(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

122. देसी रियासतों के विलय के समय भारत सरकार ने विभिन्नताओं को सम्मान देने और क्षेत्रों की माँगों को संतुष्ट करने के लिए क्या रुख अपनाया?
(A) एक लचीला रुख, जैसे जम्मू-कश्मीर को स्वायत्तता देना।
(B) एक अत्यंत कठोर और अड़ियल रुख।
(C) सभी प्रकार की क्षेत्रीय मांगों को पूर्णतः अस्वीकार करने का रुख।
(D) सभी रियासतों को एक समान और पूर्ण स्वायत्तता देने का शासकीय रुख।

123. विभाजन की त्रासदी के चित्रण के लिए 'गर्म हवा' फिल्म किस लेखक की कहानी पर आधारित है?
(A) अमृता प्रीतम
(B) सआदत हसन मंटो
(C) इस्मत चुगताई
(D) कैफ़ी आज़मी

124. "आज आपने अपने सर पर काँटों का ताज पहना है।" यह कथन किसने और किसके लिए कहा था?
(A) सरदार पटेल ने नेहरु के लिए।
(B) महात्मा गाँधी ने सत्ता संभालने वाले नेताओं के लिए।
(C) नेहरु ने रियासतों के राजाओं के लिए।
(D) जिन्ना ने पाकिस्तान के नेताओं के लिए।

125. निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह दर्शाती है कि लोकतांत्रिक नेतृत्व हमेशा अपनी इच्छा लागू नहीं कर पाया?
(A) विभिन्न देसी रजवाड़ों का भारत में ऐतिहासिक विलय।
(B) भारतीय संविधान का विधिवत निर्माण और इसका सफल क्रियान्वयन।
(C) भाषाई राज्य की माँग को लेकर लोगों का नेतृत्व के विरुद्ध आंदोलन।
(D) विभाजन के पश्चात पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ बने राजनयिक संबंध।

126. नीचे दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें:
अभिकथन (A): विभाजन के बाद भी भारत के नेताओं ने एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के आदर्श को बनाए रखा।
कारण (R): 1951 में भारत में कोई भी मुस्लिम आबादी नहीं बची थी।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

127. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. आज़ादी के बाद, देश की अंदरूनी सीमा-रेखाएँ फिर से तय करना एक चुनौती थी।
2. औपनिवेशिक शासन के प्रांत प्रशासनिक सुविधा के अनुसार बने थे।
3. राष्ट्रीय सरकार ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वायदा किया था।
4. 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन से ही इस सिद्धांत को मान लिया गया था।

उपरोक्त में से कौन से कथन राज्यों के पुनर्गठन की पृष्ठभूमि के संबंध में सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3 और 4
(C) केवल 1, 2 और 4
(D) उपरोक्त सभी

128. विभाजन के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए आज़ादी का क्या मतलब था?
(A) जीवन में तत्काल आने वाली समृद्धि और अपार व्यक्तिगत खुशी।
(B) महीनों और सालों तक किसी शरणार्थी शिविर में जीवन काटना।
(C) भविष्य के लिए मिलने वाले असीमित नए आर्थिक अवसर और स्वतंत्रता।
(D) अपने पुराने पैतृक घरों में सम्मानपूर्वक वापस लौटने का तत्काल अवसर।

129. नीचे दिए गए कथन I और कथन II को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें:
कथन I: विभाजन के समय, भारत और पाकिस्तान के लेखक, कवि और film-निर्माताओं ने अपनी रचनाओं में मार-काट और विस्थापन के दुख को अभिव्यक्ति दी।
कथन II: इन रचनाकारों ने विभाजन की त्रासदी को दर्शाने से परहेज किया।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

130. रजवाड़ों के संबंध में ब्रिटिश सरकार की घोषणा से अखंड भारत के अस्तित्व पर खतरा क्यों मंडरा रहा था?
(A) राजाओं को यह अधिकार मिला कि वे चाहें तो अपना

सूची I: (लेखक/कवि)
P. फ़ैज़ अहमद फ़ैज़
Q. अमृता प्रीतम
R. सआदत हसन मंटो
S. एम.एस. सथ्यु
सूची II: (कृति/र रचना)
1. 'गर्म हवा' (निर्देशक)
2. 'कस्त्र-ए-नफ्सी' (कहानी)
3. 'सुब्ह-ए-आज़ादी' (नज़्म)
4. 'आज आखाँ वारिस शाह नूँ' (कविता)
(A) P-3, Q-4, R-2, S-1
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-3, R-1, S-2
(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

92. विभाजन की प्रक्रिया में, पंजाब और बंगाल के प्रांतों में बँटवारा किस आधार पर किया जाना था?
(A) प्रमुख प्राकृतिक नदी की सीमाओं के आधार पर।
(B) जिले या निचले स्तर पर धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर।
(C) क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाई भिन्नता के आधार पर।
(D) उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के क्षेत्रीय वितरण के आधार पर।

93. 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि तक फैसला न हो पाने का एक तात्कालिक परिणाम क्या था?
(A) भारत के विभाजन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।
(B) ब्रिटिश शासन को व्यवस्था सुधारने हेतु कुछ और समय के लिए बढ़ा दिया गया।
(C) अनेक लोगों को नहीं पता था कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में।
(D) दोनों नव-निर्मित देशों ने तुरंत एक-दूसरे के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी।

94. विभाजन के दौरान महिलाओं के साथ हुई त्रासदियों में क्या शामिल था?
(A) उन्हें जबरन अगवा कर लिया गया।
(B) उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी और धर्म बदलना पड़ा।
(C) परिवार के लोगों ने 'कुल की इज़्ज़त' बचाने के नाम पर उनकी हत्या कर दी।
(D) उपरोक्त सभी।

95. नीचे दिए गए कथन I और कथन II को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें:
कथन I: विभाजन में सिर्फ़ संपदा, देनदारी और परिसंपत्तियों का ही बँटवारा नहीं हुआ।
कथन II: इसमें दो समुदाय जो अब तक पड़ोसियों की भाँति रहते आ रहे थे, हिंसक अलगाव का शिकार हुए।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं, और कथन II, कथन I की सही व्याख्या करता है।
(B) कथन I और कथन II दोनों सही हैं, लेकिन कथन II, कथन I की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

96. हैदराबाद के संदर्भ में, निज़ाम ने नवंबर 1947 में भारत के साथ क्या समझौता किया था?
(A) तत्काल विलय का समझौता।
(B) एक साल के लिए यथास्थिति बहाल रखने का समझौता।
(C) वित्तीय सहायता का समझौता।
(D) सैन्य गठबंधन का समझौता।

97. हैदराबाद की रियासत के वे कौन से हिस्से थे जो आज के महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में हैं?
(A) केवल उत्तरी हिस्से
(B) पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से
(C) केवल दक्षिणी हिस्से
(D) कोई भी हिस्सा नहीं

98. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. त्रावणकोर के राजा ने सबसे पहले अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा की।
2. हैदराबाद के निज़ाम ने भी स्वतंत्रता की घोषणा की।
3. भोपाल के नवाब संविधान-सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे।
4. इन घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान कई छोटे-छोटे देशों में बँट सकता है।
5. सभी रजवाड़ों के शासक अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए तुरंत तैयार हो गए थे।
उपरोक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 1, 2, 3 और 4
(C) केवल 3, 4 और 5
(D) उपरोक्त सभी

99. अधिकतर रजवाड़ों में शासन किस रीति से चलाया जाता था?
(A) लोकतांत्रिक रीति से
(B) सैन्य शासन द्वारा
(C) अलोकतांत्रिक रीति से
(D) सामुदायिक परिषदों द्वारा

100. सौराष्ट्र क्षेत्र, जो आज गुजरात का हिस्सा है, में स्वतंत्रता के समय कितने बड़े और छोटे रजवाड़े थे?
(A) 14 बड़े और 26 छोटे
(B) 26 बड़े और 119 छोटे
(C) 15 बड़े और 14 छोटे
(D) 14 बड़े और 119 छोटे

101. नीचे दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें:

(D) 2000 में

62. तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष में हुआ?
(A) 2000
(B) 2010
(C) 2016
(D) 2014

63. निम्नलिखित में से कौन सी मांग राज्यों के पुनर्गठन का आधार नहीं थी?
(A) धार्मिक भिन्नता
(B) भाषा
(C) अलग क्षेत्रीय संस्कृति
(D) विकास के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन

64. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत-विभाजन "द्वि-राष्ट्र सिद्धांत" का परिणाम था।
2. धर्म के आधार पर दो प्रांतों-पंजाब और बंगाल-का बँटवारा हुआ।
3. पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में भौगोलिक संगति नहीं थी।
4. विभाजन की योजना में यह बात स्पष्ट रुप से शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की पूर्ण अदला-बदली होगी।

उपरोक्त में से कौन सा कथन भारत-विभाजन के बारे में गलत है?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) केवल 3
(D) केवल 4

65. नीचे दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें:
अभिकथन (A): स्वतंत्रता के बाद, केंद्र सरकार शुरु में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विरुद्ध थी।
कारण (R): नेताओं को डर था कि भाषावार राज्यों के गठन से अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा और देश की एकता को खतरा हो सकता है।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

66. 'ट्रिस्ट विद् डेस्टिनी' भाषण के संदर्भ में, नेहरू ने आज़ादी के बाद भारत के लिए क्या सपना देखा था?
(A) सरकार गरीबों और कमज़ोरों के भले के लिए काम करेगी।
(B) एक आधुनिक और शक्तिशाली सैन्य राष्ट्र का वैश्विक निर्माण।
(C) एक प्राचीन हिंदू राष्ट्र की गौरवशाली पुनर्स्थापना।
(D) केवल तीव्र औद्योगिक और शहरी विकास पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करना।

67. स्वतंत्र भारत के समक्ष पहली और तात्कालिक चुनौती क्या थी?
(A) देश में एक मजबूत लोकतंत्र की विधिवत स्थापना करना।
(B) तीव्र आर्थिक विकास और औद्योगिक प्रगति हासिल करना।
(C) विविधताओं को समायोजित करने वाले भारत को गढ़ना।
(D) बाहरी खतरों से निपटने हेतु एक शक्तिशाली सेना का निर्माण करना।

68. निम्नलिखित में से किस नेता ने रजवाड़ों के भारतीय संघ में विलय में निर्णायक भूमिका निभाई?
(A) जवाहरलाल नेहरु
(B) महात्मा गाँधी
(C) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर
(D) सरदार वल्लभभाई पटेल

69. निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें:
1. बंबई राज्य का महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजन
2. राज्य पुनर्गठन अधिनियम का पारित होना
3. आंध्र प्रदेश राज्य का गठन
4. नगालैंड राज्य का गठन

(A) 3, 2, 1, 4
(B) 2, 3, 1, 4
(C) 3, 1, 2, 4
(D) 1, 2, 3, 4

70. हैदराबाद रियासत के लोगों ने किसके दमनकारी शासन के खिलाफ़ आंदोलन किया था?
(A) ब्रिटिश सरकार
(B) निज़ाम
(C) नवाब
(D) महाराजा

71. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. हैदराबाद के रज़ाकार सांप्रदायिक और अत्याचारी थे।
2. रज़ाकारों ने गैर-मुसलमानों को खासतौर पर अपना निशाना बनाया।
3. रज़ाकारों ने लूटपाट, हत्या और बलात्कार जैसी गतिविधियों को अंजाम दिया।
4. रज़ाकार निज़ाम के पूर्ण नियंत्रण में एक अनुशासित सैन्य बल थे।

उपरोक्त में से कौन से कथन रज़ाकारों के बारे में सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1, 2 और 3

(B) वंश
(C) पंजीकरण
(D) धर्म

111. रजवाड़ों के विलय के संदर्भ में सरकार का नजरिया लचीला होने का एक उदाहरण क्या है?
(A) जम्मू-कश्मीर को कुछ स्वायत्तता देना।
(B) हैदराबाद को पूरी स्वतंत्रता देना।
(C) सभी रजवाड़ों पर सैन्य कार्रवाई करना।
(D) सभी राजाओं को पद से हटा देना।

112. नीचे दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें:
अभिकथन (A): पोट्टी श्रीरामुलु की भूख-हड़ताल से मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश में बड़ी अव्यवस्था फैली और हिंसक घटनाएँ हुईं।
कारण (R): केंद्र सरकार ने तुरंत आंदोलनकारियों की मांग मान ली और अलग आंध्र राज्य बनाने पर सहमत हो गई।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

113. 1956 के राज्य पुनर्गठन के बाद, द्विभाषी राज्य 'बंबई' में कौन सी दो भाषाएँ बोलने वाले लोग शामिल थे?
(A) हिंदी और मराठी
(B) मराठी और गुजराती
(C) कोंकणी और गुजराती
(D) मराठी और कोंकणी

114. पंजाब में पंजाबी-भाषी लोगों की अलग राज्य की माँग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(A) इस माँग को बाद में 1966 में स्वीकार किया गया।
(B) क्योंकि वे इसकी माँग नहीं कर रहे थे।
(C) क्योंकि वहाँ हिंदी-भाषी समुदाय का बहुमत था।
(D) क्योंकि सरकार भाषाई राज्यों के पूरी तरह खिलाफ थी।

115. निम्नलिखित में से कौन सा राज्य असम से अलग करके नहीं बनाया गया था?
(A) मेघालय
(B) मणिपुर
(C) सिक्किम
(D) त्रिपुरा

116. विभाजन के दौरान कलकत्ता में शांति स्थापित करने के लिए हिंदू और मुस्लिम समुदायों द्वारा कौन सा संयुक्त कदम उठाया गया था?
(A) बड़ी संयुक्त धार्मिक प्रार्थना सभाओं का भव्य आयोजन।
(B) सद्भाव बढ़ाने हेतु एक दूसरे के त्योहारों को हर्षोल्लास से मनाना।
(C) दोनों समुदायों के बीच एक औपचारिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर करना।
(D) दोनों देशों का झंडा एक साथ फहराते हुए शहर में गश्त करना।

117. 'भाग्यवधू से चिर-प्रतीक्षित भेंट' भाषण कहाँ दिया गया था?
(A) लाल किले की प्राचीर से
(B) संसद के केंद्रीय कक्ष में
(C) संविधान सभा के एक विशेष सत्र में
(D) बंबई के एक सार्वजनिक मैदान में

118. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. विभाजन के बाद, भारत में मुसलमान सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय थे।
2. भारत के नेताओं ने सभी नागरिकों को समान दर्जा देने का समर्थन किया।
3. धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श भारतीय संविधान में परिलक्षित हुआ।
4. विभाजन के बाद, भारत स्वतः ही एक हिंदू राष्ट्र बन गया।
5. भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सभी संबंध तोड़ दिए।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 2, 3 और 4
(C) केवल 1, 4 और 5
(D) उपरोक्त सभी

119. हैदराबाद की महिलाएँ निज़ाम के शासन में सबसे ज़्यादा जुल्म का शिकार हुई थीं, इसका आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा?
(A) महिलाएँ आंदोलन से दूर रहीं।
(B) आंदोलन केवल पुरुषों तक सीमित रहा।
(C) निज़ाम ने महिलाओं के लिए कुछ सुधार लागू किए।
(D) महिलाएँ बड़ी संख्या में इस आंदोलन से आ जुड़ीं।

120. निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें:
1. मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की माँग।
2. भारत और पाकिस्तान नामक दो राष्ट्रों का उदय।
3. कांग्रेस द्वारा द्वि-राष्ट्र सिद्धांत का विरोध।
4. ब्रिटिश शासन द्वारा पाकिस्तान की माँग को मानना।

(A) 1, 3, 4, 2
(B) 3, 1, 2, 4
(C) 1, 2, 3, 4
(D) 4, 3, 1, 2

121. निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (घटना)
P. हैदराबाद का विलय
Q. मणिपुर का विलय

(D) मेघालय - 1972

82. नीचे दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें:
अभिकथन (A): भाषावार राज्यों के पुनर्गठन ने लोकतांत्रिक राजनीति की प्रकृति को बुनियादी रुप से बदल दिया।
कारण (R): राजनीति और सत्ता में भागीदारी का रास्ता अब केवल अंग्रेजीभाषी अभिजात वर्ग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह अन्य लोगों के लिए भी खुल गया।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

83. विदर्भ और हरित प्रदेश जैसे अलग राज्य बनाने की माँग क्रमशः किन वर्तमान राज्यों में चल रही है?
(A) गुजरात और पंजाब
(B) मध्य प्रदेश और बिहार
(C) महाराष्ट्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश
(D) कर्नाटक और पश्चिम बंगाल

84. विभाजन के बाद भारत में रह गए मुसलमानों के प्रति सरकार के रवैये को लेकर नेहरु का क्या विचार था?
(A) उन्हें देश में दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाना चाहिए।
(B) सुरक्षा कारणों से उन्हें तत्काल पाकिस्तान चले जाना चाहिए।
(C) उनके राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों को सीमित कर देना चाहिए।
(D) उन्हें समान नागरिक अधिकार देने होंगे और उनकी रक्षा करनी होगी।

85. निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें:
1. मणिपुर का भारत में विलय
2. महात्मा गाँधी का अंतिम उपवास
3. राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट
4. द्विभाषी राज्य बंबई का गठन

(A) 2, 1, 3, 4
(B) 1, 2, 4, 3
(C) 2, 3, 1, 4
(D) 3, 4, 2, 1

86. विभाजन के दौरान "दिल के दो टुकड़े हो जाना" मुहावरे का प्रयोग किसके संदर्भ में किया गया?
(A) केवल पूर्वजों की पैतृक अचल संपत्ति के बँटवारे के लिए।
(B) दो समुदायों के हिंसक अलगाव और उससे उत्पन्न मानवीय त्रासदी हेतु।
(C) नवोदित भारत और पाकिस्तान के सरकारी और भौगोलिक विभाजन के लिए।
(D) राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं के बीच वैचारिक मतभेद के लिए।

87. भारत की एकता और अखंडता की चुनौती के संदर्भ में, उस समय यह आम तौर पर क्यों माना जा रहा था कि भारत जैसा विविधतापूर्ण देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता?
(A) क्योंकि स्वतंत्र भारत में आवश्यक आर्थिक संसाधनों की भारी कमी थी।
(B) क्योंकि नव-स्वतंत्र भारत की सैन्य शक्ति पड़ोसी देशों से कमजोर थी।
(C) क्योंकि भारत पर औपनिवेशिक काल का विदेशी कर्ज बहुत अधिक बढ़ गया था।
(D) क्योंकि यहाँ अलग-अलग बोली, संस्कृति और धर्मों के अनुयायी थे।

88. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है।
2. हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है।
3. भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र को अपनाया है।
4. इन विशेषताओं ने भारत में लोकतांत्रिक ढाँचे की स्थापना सुनिश्चित की।

उपरोक्त में से कौन से कथन लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती के संदर्भ में सही हैं?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2 और 4
(C) केवल 1, 2 और 4
(D) उपरोक्त सभी

89. स्वतंत्र भारत के नेताओं ने तीसरी चुनौती, यानी आर्थिक विकास, के संबंध में क्या दृष्टिकोण अपनाया?
(A) केवल कुछ विशिष्ट प्रभावशाली औद्योगिक तबकों का त्वरित विकास करना।
(B) खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि को पूरी तरह से नजरअंदाज करना।
(C) ऐसा विकास जिससे समूचे समाज का भला हो।
(D) विकास के लिए विदेशी पूंजी निवेश पर पूरी तरह से निर्भर रहना।

90. 1940 के दशक में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और ब्रिटिश-शासन की भूमिका का क्या परिणाम हुआ?
(A) पाकिस्तान की माँग मान ली गई।
(B) भारत की एकता मजबूत हुई।
(C) भारत को शीघ्र स्वतंत्रता मिली।
(D) एक संयुक्त, अखंड भारत का निर्माण हुआ।

91. निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:

स्वतंत्र अस्तित्व रखें।
(B) प्रजा को राजाओं के विरुद्ध विद्रोह करने का वैधानिक अधिकार दिया गया था।
(C) सभी रजवाड़ों को पाकिस्तान में अनिवार्य रूप से शामिल होने को विवश किया गया था।
(D) ब्रिटिश सरकार ने सभी रजवाड़ों पर सीधे औपनिवेशिक शासन करने का फैसला किया था।

131. निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (चुनौती)
P. राष्ट्रीय एकता
Q. लोकतंत्र की स्थापना
R. समावेशी विकास
S. रियासतों का विलय
सूची II: (संबंधित कार्रवाई/अवधारणा)
1. मौलिक अधिकार और चुनाव
2. सरदार पटेल की भूमिका
3. विविधताओं को समायोजित करना
4. नीति-निर्देशक सिद्धांत
(A) P-3, Q-1, R-4, S-2
(B) P-2, Q-1, R-3, S-4
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

132. पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु का मुख्य कारण क्या था?
(A) पुलिस फायरिंग में मारे गए।
(B) सांप्रदायिक दंगों में मारे गए।
(C) एक लंबी बीमारी के बाद मृत्यु।
(D) 56 दिनों की भूख-हड़ताल के बाद मृत्यु।

133. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. राज्य पुनर्गठन आयोग ने माना कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण भाषा के आधार पर होना चाहिए।
2. इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ।
3. इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र-शासित प्रदेश बनाए गए।
4. इसके बाद भारत में किसी नए राज्य का गठन नहीं हुआ।
5. यह अधिनियम 1953 में लागू किया गया था।
उपरोक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 2, 3 और 4
(C) केवल 1, 4 और 5
(D) उपरोक्त सभी

134. "ये दाग़-दाग़ उजाला, ये शब-गज़ीदा सहर, वो इंतिज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं।" ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं और किस घटना के संदर्भ में हैं?
(A) अमृता प्रीतम, भारत की स्वतंत्रता
(B) फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, विभाजन की सुबह
(C) सआदत हसन मंटो, सांप्रदायिक दंगे
(D) मुहम्मद इक़बाल, पाकिस्तान का निर्माण

135. महात्मा गाँधी के अनुसार, यदि प्रांतों का गठन भाषावार हुआ तो उसका एक नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता था?
(A) इससे देश की आंतरिक एकता बहुत अधिक मजबूत होगी।
(B) अंग्रेजी भाषा का प्रशासनिक प्रयोग पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।
(C) इससे देश के त्वरित आर्थिक विकास में भारी तेजी आएगी।
(D) क्षेत्रीय भाषाओं का ज़ोर बढ़ने से हिंदुस्तानी का महत्व कम होना।

136. नीचे दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें:
अभिकथन (A): भारत में भाषाई राज्यों के गठन की प्रक्रिया 1956 में समाप्त नहीं हुई।
कारण (R): बाद के वर्षों में, अलग क्षेत्रीय संस्कृति और विकास में असंतुलन जैसे मुद्दों पर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों का गठन हुआ।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

137. 11 अगस्त, 1947 को कराची में पाकिस्तान की संविधान सभा में मुहम्मद अली जिन्ना ने अपने अध्यक्षीय भाषण में क्या मुख्य संदेश दिया था?
(A) पाकिस्तान आधिकारिक रूप से एक पूर्णतः इस्लामिक राज्य घोषित होगा।
(B) सभी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा हेतु पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए।
(C) राज्य का धर्म या जाति से कोई लेना-देना नहीं होगा।
(D) केवल मुसलमानों को ही पाकिस्तान में पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त होंगे।

138. स्वतंत्र भारत की दूसरी चुनौती, 'लोकतंत्र को कायम करने' में, केवल लोकतांत्रिक संविधान बना लेना ही काफी क्यों नहीं था?
(A) चुनौती यह थी कि संविधान सम्मत लोकतांत्रिक व्यवहार चलन में आएँ।
(B) क्योंकि उस समय संविधान को प्रभावी ढंग से लागू करना कतई संभव नहीं था।
(C) क्योंकि तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं को स्वयं लोकतंत्र की सफलता पर विश्वास नहीं था।
(D) क्योंकि जनता अशिक्षित थी और वह लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कभी समझ नहीं सकती थी।

अभिकथन (A): आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा।
कारण (R): इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

102. भाषावार राज्यों के पुनर्गठन के बाद लोकतंत्र को किस प्रकार एक वृहत्तर अर्थ मिला?
(A) इसका अर्थ केवल संविधान का कड़ाई से पालन करना और नियमित चुनाव करवाना रह गया।
(B) इसका अर्थ विभिन्नताओं को पहचानना और स्वीकार करना था।
(C) इसका अर्थ प्रशासन में केवल अंग्रेजी भाषा के आधिकारिक उपयोग को बढ़ावा देना था।
(D) इसका अर्थ सभी प्रकार की क्षेत्रीय और भाषाई मांगों को पूरी तरह से खारिज करना था।

103. सन् 2000 में किन तीन राज्यों का गठन हुआ?
(A) मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा
(B) हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब
(C) मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड
(D) छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड

104. कलकत्ता में गाँधीजी की मौजूदगी और उपवास का क्या प्रभाव पड़ा?
(A) हालात सुधर गए और लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव से जश्न मनाया।
(B) दंगों की हिंसक स्थिति पर कोई भी सकारात्मक असर नहीं हुआ।
(C) ब्रिटिश सरकार ने व्यवस्था बनाए रखने हेतु सैन्य हस्तक्षेप किया।
(D) शहर में तुरंत अनिश्चितकालीन कड़ा सैन्य शासन लगा दिया गया।

105. "यह कोई आसान काम नहीं था। राष्ट्र-राज्य के रुप में, आजाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ।" ये कठिन परिस्थितियाँ क्या थीं?
(A) स्वतंत्र भारत का केवल आर्थिक पिछड़ापन
(B) देश में व्याप्त केवल सामाजिक असमानता
(C) देश का बँटवारा, अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी
(D) देश में केवल राजनीतिक अस्थिरता का होना

106. निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (क्षेत्र/प्रांत)
P. पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत
Q. पंजाब
R. बंगाल
S. पुराना मद्रास प्रांत
सूची II: (संबंधित घटना/माँग)
1. विशाल आंध्र आंदोलन
2. खान अब्दुल गफ्फार खान का विरोध
3. विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी का स्थल
4. विभाजन के कारण बँटवारा
(A) P-2, Q-3, R-4, S-1
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-2, Q-4, R-1, S-3
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

107. 1947 के विभाजन के दौरान, लाखों लोगों का स्थानांतरण किस प्रकार का था?
(A) सुनियोजित, व्यवस्थित और शांतिपूर्ण
(B) स्वैच्छिक, सरकार द्वारा समर्थित और सुगम
(C) केवल अमीरों तक सीमित
(D) आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा

108. विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन देश के नेताओं की धारणा को दर्शाता है?
(A) भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक नेता द्वि-राष्ट्र सिद्धांत में पूर्ण यकीन करते थे।
(B) नेता द्वि-राष्ट्र सिद्धांत में नहीं मानते थे, पर बँटवारा धर्म के आधार पर हुआ।
(C) भारत के सभी नेता स्वतंत्रता के तुरंत बाद एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे।
(D) भारत के अधिकतर बड़े नेता विभाजन की पूरी प्रक्रिया के पूरी तरह पक्ष में थे।

109. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. मुस्लिम लीग का गठन औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए हुआ था।
2. मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की माँग करने में अग्रणी थी।
3. कुछ हिंदू संगठन भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में लगे थे।
4. भारत की कौमी सरकार के अधिकतर नेता नागरिकों को धर्म के आधार पर भिन्न दर्जा देने के हामी थे।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3 और 4
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) उपरोक्त सभी

110. भारत के संविधान में नागरिकता की कसौटी किसे नहीं बनाया गया है?
(A) जन्म स्थान

करना।
(C) नए राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करना।
(D) राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना।

149. निम्नलिखित में से राज्यों के पुनर्गठन को उनके घटित होने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें:
1. छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन
2. मेघालय का गठन
3. तेलंगाना का गठन
4. महाराष्ट्र और गुजरात का गठन

(A) 4, 2, 1, 3
(B) 2, 4, 3, 1
(C) 4, 1, 2, 3
(D) 1, 2, 3, 4

150. भाषावार राज्यों के पुनर्गठन ने देश की एकता पर क्या प्रभाव डाला?
(A) इससे देश टूट गया।
(B) इससे देश की एकता और ज़्यादा मज़बूत हुई।
(C) इसका देश की एकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
(D) इससे अलगाववादी प्रवृत्तियाँ बहुत बढ़ गईं।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

भारत के विभाजन के बाद, नव स्वतंत्र राष्ट्र के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक चुनौतियों में से एक राष्ट्र की प्रकृति को परिभाषित करना था। पाकिस्तान की स्थापना द्वि-राष्ट्र सिद्धांत पर हुई थी, जिसने धर्म को राष्ट्रीयता का आधार माना। इसके विपरीत, भारतीय नेतृत्व ने, विशेषकर जवाहरलाल नेहरू के मार्गदर्शन में, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श को अपनाया। यह निर्णय केवल एक नैतिक या दार्शनिक विकल्प नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक अनिवार्यता भी थी। विभाजन की भयावह हिंसा के बावजूद, भारत में एक बहुत बड़ी मुस्लिम अल्पसंख्यक आबादी बनी रही। एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना से न केवल इन नागरिकों को अलग-थलग कर दिया जाता, बल्कि यह देश की एकता के लिए भी एक गंभीर खतरा पैदा करता, क्योंकि यह अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के बीच भी भय और असुरक्षा पैदा करता। इसलिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता को राज्य और धर्म के पूर्ण पृथक्करण के पश्चिमी मॉडल के बजाय एक ऐसे मॉडल के रूप में विकसित किया गया जहाँ राज्य सभी धर्मों के प्रति सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है और सभी नागरिकों को, उनके धर्म की परवाह किए बिना, समान अधिकार और अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में स्थापित करके इस धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को संस्थागत रूप दिया गया, जो राष्ट्र-निर्माण की इस आधारशिला को दर्शाता है।

उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

151. विभाजन के बाद भारतीय नेतृत्व ने किस प्रकार के राज्य के आदर्श को अपनाया?
(A) एक समाजवादी राज्य
(B) एक धर्मनिरपेक्ष राज्य
(C) एक हिंदू राष्ट्र
(D) एक सैन्यीकृत राज्य

152. स्रोत के अनुसार, भारत के लिए धर्मनिरपेक्षता एक राजनीतिक अनिवार्यता क्यों थी?
(A) क्योंकि भारत में एक बड़ी मुस्लिम अल्पसंख्यक आबादी बनी रही थी।
(B) क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने ऐसा करने का निर्देश दिया था।
(C) क्योंकि यह आर्थिक विकास के लिए आवश्यक था।
(D) क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने यही शर्त रखी थी।

153. भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल पश्चिमी मॉडल से किस प्रकार भिन्न है?
(A) यह राज्य और धर्म के पूर्ण एकीकरण पर आधारित है।
(B) यह केवल बहुसंख्यक धर्म को मान्यता देता है।
(C) यह राज्य द्वारा सभी धर्मों से सैद्धांतिक दूरी बनाए रखने पर आधारित है।
(D) यह धर्म को सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह प्रतिबंधित करता है।

154. भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को संस्थागत रूप देते हैं?
(A) अनुच्छेद 14 से 18
(B) अनुच्छेद 19 से 22
(C) अनुच्छेद 30 से 32
(D) अनुच्छेद 25 से 28

155. अनुच्छेद का मुख्य तर्क क्या है?
(A) भारत को पाकिस्तान के मॉडल का पालन करना चाहिए था।
(B) विभाजन के कारण भारत में कोई अल्पसंख्यक नहीं बचा था।
(C) धर्मनिरपेक्षता भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एक रणनीतिक विकल्प था।
(D) भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल एक दार्शनिक अवधारणा है जिसका कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत के बाहर लगभग 565 रियासतें मौजूद थीं, जो भारतीय एकता के लिए एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत कर रही थीं। इन रियासतों के एकीकरण का श्रेय मुख्य रूप से सरदार वल्लभभाई पटेल के दृढ़ नेतृत्व और वी.पी. मेनन की राजनयिक कुशलता को दिया जाता है। उन्होंने एक बहुआयामी रणनीति अपनाई जिसमें अनुनय, दबाव और सामरिक दूरदर्शिता का मिश्रण था। अधिकांश शासकों को 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन' (विलय पत्र) पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी किया गया, जिसके तहत उन्होंने केवल तीन

11. (D) फ़ैज़ अहमद फ़ैज़
प्रसिद्ध शायर फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने 'सुब्ह-ए-आज़ादी' नामक नज़्म लिखी थी, जिसमें उन्होंने विभाजन के समय की दर्दनाक स्थिति और अधूरी आज़ादी का चित्रण किया है। यह कविता उस समय के मानवीय संकट और विभाजन से उत्पन्न पीड़ा को बहुत गहराई से व्यक्त करती है। उन्होंने इस आज़ादी को वह सुबह बताया था जिसका इंतज़ार वर्षों से किया जा रहा था, परंतु यह वैसी नहीं थी।

12. (A) 2, 4, 1, 3
ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम में भारत की स्वतंत्रता और विभाजन अगस्त 1947 में हुआ था। इसके पश्चात हैदराबाद का भारत में विलय सितंबर 1948 में संपन्न हुआ। महात्मा गाँधी की शहादत 30 जनवरी 1948 को हुई थी, परंतु हैदराबाद का मुद्दा उससे पहले से चल रहा था। अंत में, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना भाषाई आधार पर राज्यों के सीमांकन हेतु वर्ष 1953 में की गई थी।

13. (C) धार्मिक बहुसंख्या
भारत के विभाजन का मुख्य आधार धार्मिक बहुसंख्या को बनाया गया था। इसके तहत यह निर्णय लिया गया कि जिन क्षेत्रों में मुसलमानों की संख्या अधिक थी, उन्हें पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाएगा और शेष हिस्से भारत में रहेंगे। इस सिद्धांत के कारण ही पंजाब और बंगाल जैसे प्रांतों का बँटवारा करना पड़ा क्योंकि वहाँ दोनों समुदायों की आबादी बड़े पैमाने पर मिश्रित रूप में थी।

14. (B) केवल 2, 3 और 4
विभाजन के समय ब्रिटिश इंडिया में दो प्रमुख मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, जो पूर्व और पश्चिम में स्थित थे। पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत के नेता इस बँटवारे के विरुद्ध थे। पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से गैर-मुस्लिम बहुल थे, जिससे विभाजन की प्रक्रिया अत्यंत जटिल हो गई। सीमा के दोनों तरफ़ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एक भयानक समस्या बनकर उभरी, क्योंकि विभाजन की मूल योजना में आबादी की अदला-बदली शामिल नहीं थी।

15. (A) खान अब्दुल गफ्फार खान
खान अब्दुल गफ्फार खान को 'सीमांत गाँधी' के नाम से जाना जाता था क्योंकि वे पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत के निर्विवाद नेता और अहिंसा के समर्थक थे। वे मुस्लिम लीग द्वारा दिए गए 'द्वि-राष्ट्र सिद्धांत' के पूरी तरह खिलाफ थे और उन्होंने अंत तक विभाजन का विरोध किया। उनकी असहमति के बावजूद उनके क्षेत्र को पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया, जो उनकी विचारधारा के विपरीत था।

16. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं, और कथन II, कथन I की सही व्याख्या करता है।
पंजाब और बंगाल का बँटवारा विभाजन की सबसे भयानक त्रासदी साबित हुआ क्योंकि यहाँ आबादी का घनत्व अधिक था और लोग धार्मिक आधार पर बँटे हुए थे। इन प्रांतों में केवल जिले ही नहीं, बल्कि उससे भी निचले प्रशासनिक स्तरों को आधार मानकर विभाजन की लकीर खींची गई थी। इस सूक्ष्म विभाजन के कारण लाखों लोगों को अचानक बेघर होना पड़ा और भारी हिंसा का सामना करना पड़ा।

17. (B) लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता
विभाजन के दौरान लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे बड़े शहर सांप्रदायिक हिंसा के मुख्य केंद्र बन गए थे। इन शहरों में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच भीषण दंगे हुए, जिससे ये शहर सांप्रदायिक अखाड़ों में तब्दील हो गए। इन इलाकों में लोग अपनी जान बचाने के लिए उन मोहल्लों में जाने से डरते थे जहाँ दूसरे समुदाय के लोग बहुसंख्या में निवास करते थे।

18. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
विभाजन की कड़वाहट और सांप्रदायिक हिंसा के बावजूद भारतीय नेतृत्व ने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श को पूरी दृढ़ता से अपनाया। वे भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहते थे जहाँ धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच कोई भेदभाव न हो। नेताओं का मानना था कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्मावलंबियों को समान अधिकार प्राप्त होंगे।

19. (C) अमृता प्रीतम
'आज आखूँ वारिस शाह नूँ' विभाजन की त्रासदी पर लिखी गई एक अत्यंत मार्मिक और प्रसिद्ध कविता है। इसकी रचना पंजाबी लेखिका और कवयित्री अमृता प्रीतम ने की थी। इस कविता के माध्यम से उन्होंने विभाजन के दौरान महिलाओं पर हुए अत्याचारों और पंजाब की धरती पर बहने वाली खून की नदियों के प्रति अपना गहरा शोक और संवेदना व्यक्त की है।

20. (D) अल्पसंख्यकों की समस्या
विभाजन के समय सबसे बड़ी और अनसुलझी समस्या अल्पसंख्यकों की थी जो सीमा के दोनों ओर रह गए थे। लाखों की संख्या में हिंदू और सिख पाकिस्तान में और मुसलमान भारत के पंजाब व बंगाल जैसे इलाकों में फँसे हुए थे। इन लोगों को अचानक पता चला कि वे अपने ही घर में विदेशी हो गए हैं। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना दोनों देशों की सरकारों के लिए कठिन था।

21. (D) उपरोक्त सभी
विभाजन के परिणाम अत्यंत विनाशकारी थे, जिसके कारण लगभग 80 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा और भारी हिंसा में लाखों लोग मारे गए। संपत्तियों के बँटवारे के तहत न केवल वित्तीय संसाधनों, बल्कि मेज, कुर्सी और टाइपराइटर जैसी छोटी वस्तुओं का भी बँटवारा हुआ। यहाँ तक कि रेलवे और सरकारी विभागों के कर्मचारियों को भी दोनों देशों के बीच प्रशासनिक स्तर पर विभाजित किया गया था।

22. (B) 10-12 प्रतिशत
1947 में हुए विभाजन के बाद भी भारत की सामाजिक संरचना विविध बनी रही। 1951 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 12 प्रतिशत थी। यह तथ्य इस बात को प्रमाणित करता है

(C) जवाहरलाल नेहरू की 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया'
(D) एम.एस. सथ्यु की फिल्म 'गर्म हवा'

164. 'वतन' की अवधारणा के टूटने का क्या तात्पर्य है?
(A) सरकारी कार्यालयों का विनाश
(B) राष्ट्रीय ध्वज का अपमान
(C) आर्थिक संपत्तियों का नुकसान
(D) मातृभूमि और जड़ों से अलगाव का दर्द

165. इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(A) विभाजन के मानवीय, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को उजागर करना।
(B) विभाजन के लिए जिम्मेदार राजनीतिक नेताओं की आलोचना करना।
(C) विभाजन के सांख्यिकीय आंकड़ों का विश्लेषण करना।
(D) विभाजन के बाद के आर्थिक सुधारों का मूल्यांकन करना।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों की सीमाओं का निर्धारण एक जटिल कार्य था। औपनिवेशिक काल में प्रांतों की सीमाएँ प्रशासनिक सुविधा या ब्रिटिश विजय के आधार पर तय की गई थीं, जो क्षेत्र की भाषाई और सांस्कृतिक वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करती थीं। कांग्रेस पार्टी ने 1920 के दशक से ही भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वादा किया था। हालाँकि, आजादी और विभाजन के बाद, नेतृत्व को यह डर था कि भाषाई राज्यों के निर्माण से अलगाववादी प्रवृत्तियाँ बढ़ सकती हैं और देश की एकता को खतरा हो सकता है। इस दुविधा के बावजूद, भाषाई पहचान की आकांक्षाएँ प्रबल थीं, जिसका प्रमाण पुराने मद्रास प्रांत में विशाल आंध्र आंदोलन था। पोट्टी श्रीरामुलु की शहादत के बाद आंध्र प्रदेश के निर्माण ने भाषाई राज्यों की माँगों को और तेज कर दिया। इस चुनौती का सामना करने के लिए, सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC) की स्थापना की। आयोग ने अपनी 1955 की रिपोर्ट में भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य आधार स्वीकार किया। इस सिफारिश के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, जिसने अंततः आशंकाओं के विपरीत, भारतीय संघ को मजबूत किया। इसने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को एक संस्थागत अभिव्यक्ति प्रदान की और लोकतंत्र को गहरा किया, यह साबित करते हुए कि भाषाई पहचान राष्ट्रीय पहचान के लिए खतरा नहीं, बल्कि उसका एक पूरक घटक हो सकती है।

उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

166. स्वतंत्रता के बाद भारतीय नेतृत्व भाषाई राज्यों के निर्माण से क्यों हिचकिचा रहा था?
(A) क्योंकि उनके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे।
(B) क्योंकि उन्हें डर था कि इससे अलगाववादी प्रवृत्तियाँ बढ़ेंगी और एकता को खतरा होगा।
(C) क्योंकि संविधान ने इस तरह के पुनर्गठन की अनुमति नहीं दी थी।
(D) क्योंकि ब्रिटिश सरकार इसके खिलाफ थी।

167. किस घटना ने भाषाई राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया को गति प्रदान की?
(A) राज्य पुनर्गठन आयोग की तत्काल स्थापना
(B) विशाल आंध्र आंदोलन और पोट्टी श्रीरामुलु की शहादत
(C) 1952 का पहला आम चुनाव
(D) रियासतों का विलय

168. राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC) की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
(A) 1953
(B) 1947
(C) 1950
(D) 1956

169. राज्य पुनर्गठन आयोग की मुख्य सिफारिश क्या थी?
(A) राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए।
(B) मौजूदा प्रांतीय सीमाओं को बनाए रखा जाना चाहिए।
(C) भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए।
(D) भारत को एकात्मक राज्य में बदल देना चाहिए।

170. अनुच्छेद के अनुसार, भाषाई पुनर्गठन का दीर्घकालिक परिणाम क्या हुआ?
(A) देश कई छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट गया।
(B) इसने भारत में अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया।
(C) इसने आर्थिक विकास को पूरी तरह से रोक दिया।
(D) इसने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को समायोजित करके भारतीय संघ को मजबूत किया।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने पर, भारत को एक जर्जर अर्थव्यवस्था विरासत में मिली, जो लगभग दो शताब्दियों के औपनिवेशिक शोषण का परिणाम थी। कृषि क्षेत्र ठहरा हुआ था, उत्पादकता बेहद कम थी और यह मानसून की अनिश्चितताओं पर बहुत अधिक निर्भर था। औद्योगिक आधार कमजोर और अविकसित था, जिसमें मुख्य रूप से सूती वस्त्र और जूट जैसे कुछ बुनियादी उद्योग शामिल थे। भारी उद्योगों और बुनियादी ढाँचे का लगभग अभाव था। इन विकट परिस्थितियों में, नवजात राष्ट्र के लिए आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन की चुनौती सर्वोपरि थी। भारतीय नेतृत्व ने आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए एक नियोजित विकास का मार्ग चुना। इस संदर्भ में, 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' के मॉडल को अपनाया गया, जिसे 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया था। इस मॉडल ने एक ऐसी प्रणाली की परिकल्पना की जहाँ निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र सह-अस्तित्व में रहेंगे। कृषि, व्यापार और छोटे उद्योग निजी क्षेत्र के लिए छोड़े गए, जबकि भारी उद्योग, बुनियादी ढाँचा और रणनीतिक क्षेत्र राज्य

समानता के आधार पर नई सीमाएँ तय कीं। यह स्वतंत्र भारत के राजनीतिक एकीकरण और सुदृढ़ीकरण की एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी।

56. (A) केवल 1, 2 और 3
भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से देश की एकता और भी मजबूत हुई क्योंकि इससे क्षेत्रीय आकांक्षाओं को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। इस प्रक्रिया ने सत्ता में भागीदारी को आम जनता और स्थानीय भाषाओं के करीब ला दिया, जिससे राजनीति केवल अंग्रेजी बोलने वाले वर्ग तक सीमित नहीं रही। इससे लोकतंत्र का आधार व्यापक हुआ और अलगाववाद की आशंकाएँ धीरे-धीरे समाप्त हो गईं, जिससे देश अधिक अखंड बना।

57. (C) महाराष्ट्र और गुजरात
1960 में तत्कालीन द्विभाषी बंबई राज्य के भीतर मराठी और गुजराती बोलने वाले लोगों के बीच अलग राज्यों की माँग को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हुए। इसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार ने बंबई राज्य को विभाजित कर दो नए राज्यों, महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया। महाराष्ट्र मराठी भाषी लोगों के लिए और गुजरात गुजराती भाषी लोगों के लिए बनाया गया, जिससे इस क्षेत्र में भाषाई संघर्ष अंततः समाप्त हुआ।

58. (A) P-3, Q-1, R-4, S-2
महाराष्ट्र और गुजरात का गठन 1960 में हुआ। पंजाब का पुनर्गठन कर हरियाणा का निर्माण 1966 में किया गया। मेघालय को एक अलग राज्य का दर्जा वर्ष 1972 में प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों का निर्माण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार को विभाजित करके वर्ष 2000 में किया गया था। ये सभी राज्य समय-समय पर क्षेत्रीय और भाषाई आकांक्षाओं के आधार पर बनाए गए।

59. (D) हरियाणा और हिमाचल प्रदेश
वर्ष 1966 में पंजाब राज्य का पुनर्गठन भाषाई और क्षेत्रीय आधार पर किया गया था। इस प्रक्रिया के तहत हिंदी बोलने वाले क्षेत्रों को अलग करके हरियाणा नामक एक नया राज्य बनाया गया। साथ ही, पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में शामिल कर दिया गया, जिससे हिमाचल प्रदेश को भी नया स्वरूप प्राप्त हुआ। पंजाब अब मुख्य रूप से पंजाबी बोलने वाले लोगों का राज्य बनकर उभरा।

60. (B) मेघालय
पूर्वोत्तर भारत में भाषाई और जनजातीय पहचान के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया के तहत, वर्ष 1972 में असम से अलग करके मेघालय को एक पूर्ण राज्य बनाया गया। इसी वर्ष मणिपुर और त्रिपुरा को भी केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। यह बदलाव पूर्वोत्तर क्षेत्र की विशिष्ट सांस्कृतिक और भाषाई विविधताओं को मान्यता देने और वहां के लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु किया गया था।

61. (C) 1963 में
नगालैंड भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण राज्य है, जिसका गठन वर्ष 1963 में हुआ था। यह राज्य मुख्य रूप से नगा जनजातियों की अपनी विशिष्ट पहचान और राजनीतिक स्वायत्तता की माँग के संघर्ष के परिणामस्वरूप बनाया गया था। नगालैंड का गठन पूर्वोत्तर में भाषाई और जातीय आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक शुरुआती और बहुत बड़ा कदम था।

62. (D) 2014
तेलंगाना राज्य का आधिकारिक रूप से गठन 2 जून 2014 को हुआ था। यह आंध्र प्रदेश राज्य को विभाजित करके बनाया गया भारत का 29वाँ राज्य था। तेलंगाना के गठन के लिए एक लंबा और सघन जन-आंदोलन चला था, जिसका मुख्य आधार क्षेत्रीय विकास में असंतुलन और एक अलग सांस्कृतिक पहचान की माँग थी। यह राज्य निर्माण भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति का एक आधुनिक उदाहरण है।

63. (A) धार्मिक भिन्नता
भारत में राज्यों के पुनर्गठन के कई आधार रहे हैं, जिनमें भाषा, विशिष्ट क्षेत्रीय संस्कृति और आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन मुख्य हैं। भारतीय लोकतंत्र में धार्मिक भिन्नता को कभी भी राज्यों के निर्माण का आधार नहीं माना गया है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ राज्यों की सीमाओं का निर्धारण प्रशासनिक सुगमता और भाषाई व सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के लिए किया जाता रहा है।

64. (D) केवल 4
भारत-विभाजन 'द्वि-राष्ट्र सिद्धांत' का परिणाम था और धर्म के आधार पर पंजाब व बंगाल का बँटवारा हुआ। पाकिस्तान के दो हिस्सों में भौगोलिक संगति का अभाव था। विभाजन की योजना में आबादी की पूर्ण अदला-बदली की कोई पूर्व-नियोजित शर्त शामिल नहीं थी। यह विस्थापन अचानक और अनियोजित था, जो सांप्रदायिक दंगों की विभीषिका के कारण पैदा हुआ था। अतः आबादी की अदला-बदली वाली बात ऐतिहासिक रूप से गलत है।

65. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
आज़ादी के प्रारंभिक वर्षों में केंद्र सरकार भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विचार के पूरी तरह विरुद्ध थी। देश के शीर्ष नेताओं को यह गंभीर आशंका थी कि भाषावार विभाजन से क्षेत्रीय भावनाएँ प्रबल होंगी और इससे देश की नवनिर्मित एकता खंडित हो सकती है। विभाजन की त्रासदी झेल रहे राष्ट्र के लिए उस समय स्थिरता बनाए रखना अलगाववाद को रोकने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता थी।

66. (A) सरकार गरीबों और कमज़ोरों के भले के लिए काम करेगी।
जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रसिद्ध भाषण 'ट्रिस्ट विद् डेस्टिनी' में आज़ाद भारत के लिए एक कल्याणकारी राज्य का सपना देखा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की सेवा का अर्थ उन लाखों करोड़ों लोगों की सेवा है जो गरीबी, अज्ञानता और बीमारियों

ANSWERS

1. (B) भाग्यवधू से चिर-प्रतीक्षित भेंट
भारत को 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। इस ऐतिहासिक अवसर पर स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु ने संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनका यह अत्यंत प्रभावशाली और विश्व प्रसिद्ध भाषण 'ट्रिस्ट विद् डेस्टिनी' या 'भाग्यवधू से चिर-प्रतीक्षित भेंट' के नाम से जाना जाता है।

2. (A) तीन
स्वतंत्र भारत के सामने मुख्य रूप से तीन अत्यंत कठिन और महत्वपूर्ण चुनौतियाँ विद्यमान थीं। पहली चुनौती विविधतापूर्ण देश को एकता के सूत्र में पिरोने और राष्ट्र निर्माण की थी। दूसरी चुनौती देश में वास्तविक लोकतंत्र को व्यावहारिक रुप में कायम करने की थी। तीसरी चुनौती एक ऐसे समावेशी विकास की थी जिससे समाज के सभी वर्गों का समान रूप से भला हो।

3. (A) P-3, Q-1, R-2, S-4
भारत की पहली चुनौती राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करना थी। दूसरी चुनौती संविधान सम्मत लोकतंत्र को व्यावहारिक रुप में स्थापित करना था। तीसरी चुनौती ऐसे आर्थिक विकास की थी जिससे समूचे समाज का कल्याण हो सके। विभाजन का मुख्य आधार धार्मिक बहुसंख्या को बनाया गया था, जिसके तहत मुस्लिम बहुल और हिंदू बहुल क्षेत्रों के आधार पर देश का बँटवारा किया गया।

4. (D) स्वतंत्रता के समय भारत में केवल आर्थिक विकास की चुनौती थी।
स्वतंत्र भारत का जन्म अत्यंत कठिन परिस्थितियों में हुआ था क्योंकि देश को आज़ादी के साथ-साथ विभाजन की विभीषिका भी झेलनी पड़ी थी। 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का गवाह बना। भारत के सामने केवल आर्थिक विकास ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने और लोकतंत्र स्थापित करने जैसी कई अन्य महत्वपूर्ण और जटिल चुनौतियाँ भी एक साथ मौजूद थीं।

5. (C) देश लोकतांत्रिक सरकार से चलेगा और वह सबके भले के लिए काम करेगी।
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के भावी स्वरूप को लेकर दो महत्वपूर्ण बातों पर व्यापक सहमति बन चुकी थी। पहली सहमति यह थी कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक पद्धति से चलाया जाएगा। दूसरी मुख्य बात यह तय थी कि सरकार किसी विशेष वर्ग के बजाय समाज के सभी वर्गों और विशेष रूप से गरीबों के भले के लिए कार्य करेगी।

6. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
स्वतंत्रता के पश्चात भारत के नेताओं के लिए राष्ट्रीय एकता बनाए रखना सबसे बड़ी चिंता थी। भारत अपनी विशालता और विविधताओं के कारण किसी महादेश जैसा था, जहाँ विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और धर्मों के लोग निवास करते थे। उस समय यह व्यापक आशंका व्यक्त की जा रही थी कि इतनी अधिक भिन्नताओं के साथ कोई देश एक राष्ट्र के रूप में अधिक समय तक टिक पाएगा।

7. (D) राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत
भारतीय संविधान में लोक-कल्याण के व्यापक लक्ष्यों को स्पष्ट करने के लिए राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है। इन सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य राजनीति और सरकार के लिए ऐसे मार्गदर्शक निर्देश प्रदान करना है, जिन्हें प्राप्त करना जनता के कल्याण के लिए अनिवार्य माना गया है। ये सिद्धांत सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु नीतियों के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं।

8. (A) महात्मा गाँधी
14 अगस्त 1947 को महात्मा गाँधी ने यह ऐतिहासिक कथन कहा था कि कल हम गुलामी से आज़ाद तो होंगे लेकिन देश का बँटवारा भी होगा। उनके लिए आज़ादी खुशी का अवसर थी, किंतु सांप्रदायिक आधार पर होने वाला विभाजन एक गहरा दुख भी था। यही कारण है कि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के जश्न में शामिल होने के बजाय दंगों को शांत करना उचित समझा।

9. (C) केवल 1, 2 और 3
स्वतंत्र भारत के सामने राष्ट्रीय एकता स्थापित करना, लोकतंत्र को व्यवहार में लाना और समूचे समाज का भला करने वाला विकास सुनिश्चित करना तीन प्रमुख चुनौतियाँ थीं। संविधान ने सामाजिक रूप से वंचित तबकों और धार्मिक अल्पसंख्यकों को विशेष सुरक्षा प्रदान की है ताकि उन्हें समानता का अधिकार मिल सके। अतः कथन 4 गलत है क्योंकि संविधान ने इन वर्गों के हितों की पूर्ण रक्षा की है।

10. (A) भारत 'हिंदू' और 'मुसलमान' नाम की दो कौमों का देश था।
मुस्लिम लीग ने 'द्वि-राष्ट्र सिद्धांत' को प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि 'हिंदू' और 'मुसलमान' नामक दो अलग-अलग कौमों का देश था। इसी तर्क के आधार पर लीग ने मुसलमानों के लिए एक पृथक देश यानी पाकिस्तान की पुरजोर माँग की थी। कांग्रेस ने इस सिद्धांत और धर्म के आधार पर देश के विभाजन का कड़ा विरोध किया था।

के नियंत्रण में रखे गए। इस नियोजित विकास की प्रक्रिया को निर्देशित करने के लिए, 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। यह आर्थिक रणनीति राष्ट्र-निर्माण की तीसरी प्रमुख चुनौती - यानी, सामाजिक और आर्थिक न्याय के साथ विकास सुनिश्चित करने - का सीधा जवाब थी।
उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

171. स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी?
(A) एक अत्यधिक विकसित और औद्योगिक अर्थव्यवस्था
(B) एक मजबूत कृषि अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था
(C) एक जर्जर और अविकसित अर्थव्यवस्था
(D) एक सेवा-क्षेत्र आधारित अर्थव्यवस्था

172. भारत के शुरुआती आर्थिक विकास के लिए कौन सा मॉडल अपनाया गया था?
(A) पूर्ण रूप से पूंजीवादी मॉडल
(B) मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल
(C) पूर्ण रूप से समाजवादी मॉडल
(D) कृषि-आधारित सामंती मॉडल

173. 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अनुसार, कौन से क्षेत्र मुख्य रूप से राज्य के नियंत्रण के लिए आरक्षित थे?
(A) कृषि और खुदरा व्यापार
(B) छोटे और कुटीर उद्योग
(C) सूचना प्रौद्योगिकी और सेवाएँ
(D) भारी उद्योग और बुनियादी ढाँचा

174. भारत में नियोजित विकास की प्रक्रिया को निर्देशित करने के लिए 1950 में किस संस्था की स्थापना की गई?
(A) योजना आयोग
(B) भारतीय रिजर्व बैंक
(C) वित्त आयोग
(D) राष्ट्रीय विकास परिषद

175. स्रोत के अनुसार, भारत द्वारा अपनाई गई नियोजित विकास की रणनीति किस प्रमुख राष्ट्र-निर्माण चुनौती का उत्तर थी?
(A) राष्ट्रीय एकता और अखंडता की चुनौती
(B) लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती
(C) सामाजिक और आर्थिक न्याय के साथ विकास सुनिश्चित करने की चुनौती
(D) भाषाई राज्यों के पुनर्गठन की चुनौती

कि विभाजन मुख्य रूप से धार्मिक आधार पर होने के बावजूद भारत ने एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की राह चुनी और अपनी मुस्लिम आबादी को समान नागरिक अधिकार दिए।

23. (D) आगरा, और उसका जूते का व्यवसाय चौपट होने लगता है।
एम. एस. सथ्यु की फिल्म 'गर्म हवा' विभाजन के बाद भारत में रहने का फैसला करने वाले एक मुस्लिम परिवार के संघर्षों को दिखाती है। फिल्म का मुख्य पात्र सलीम मिर्ज़ा आगरा में रहता है और विभाजन के बाद उपजी परिस्थितियों के कारण उसका जूते का व्यवसाय धीरे-धीरे खत्म होने लगता है। यह फिल्म उस दौर में अल्पसंख्यकों के सामने आई आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा का प्रभावी चित्रण करती है।

24. (A) कोलकाता में, जहाँ वे दंगों को शांत कराने का प्रयास कर रहे थे।
15 अगस्त 1947 को जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब महात्मा गाँधी कोलकाता में थे। वे वहाँ सांप्रदायिक दंगों से पीड़ित लोगों की सहायता कर रहे थे और हिंदू-मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए उपवास पर थे। गाँधीजी के लिए आज़ादी का उल्लास विभाजन की त्रासदी और मानवीय हिंसा के दुख के सामने फीका था, इसलिए वे दंगों को शांत करने में लगे थे।

25. (C) Nathuram Vinayak Godse
30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे ने महात्मा गाँधी की हत्या कर दी थी। गोडसे एक हिंदू अतिवादी था जो गाँधीजी के सर्वधर्म समभाव और मुसलमानों के प्रति उनके उदार दृष्टिकोण से बेहद असंतुष्ट था। उसकी विचारधारा यह थी कि गाँधीजी की नीतियों के कारण हिंदुओं के हितों की अनदेखी हो रही थी। इस दुखद घटना ने देश को स्तब्ध कर दिया और सांप्रदायिक तनाव को कम किया।

26. (A) P-3, Q-1, R-4, S-2
नाथूराम गोडसे एक हिंदू अतिवादी था जिसने महात्मा गाँधी की हत्या की थी। मुस्लिम लीग ने 'द्वि-राष्ट्र सिद्धांत' का प्रतिपादन किया था जिसके आधार पर पाकिस्तान बना। महात्मा गाँधी ने सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण उपवास किए। जवाहरलाल नेहरु ने 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को संसद में अपना ऐतिहासिक 'भाग्यवधू से चिर-प्रतीक्षित भेंट' नामक भाषण दिया था।

27. (D) भारत सरकार पाकिस्तान को देय राशि चुकाने पर सहमत हुई।
जनवरी 1948 में महात्मा गाँधी ने सांप्रदायिक सौहार्द और न्याय के लिए अपना अंतिम उपवास किया था। इस उपवास का एक महत्वपूर्ण और तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि भारत सरकार पाकिस्तान को उसकी देय बकाया राशि, जो विभाजन के समझौते के तहत दी जानी थी, तुरंत चुकाने के लिए तैयार हो गई। इस निर्णय का उद्देश्य दोनों देशों के बीच तनाव को कम करना और मानवीय मूल्यों की रक्षा करना था।

28. (B) ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत और देसी रजवाड़े
आजादी से पूर्व ब्रिटिश इंडिया दो मुख्य भागों में विभाजित था। पहले भाग में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत शामिल थे, जिनका प्रशासन सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया जाता था। दूसरे भाग में देसी रजवाड़े थे, जहाँ छोटे-बड़े राजाओं का शासन था। इन रजवाड़ों ने ब्रिटिश राज की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार कर रखा था, लेकिन अपने आंतरिक मामलों में वे स्वतंत्र रूप से शासन करते थे।

29. (B) केवल 1, 2 और 3
ब्रिटिश शासन की समाप्ति के साथ ही रजवाड़ों पर से अंग्रेजों की सर्वोच्च सत्ता भी समाप्त हो गई। रजवाड़ों को यह विकल्प दिया गया था कि वे या तो भारत में शामिल हों, या पाकिस्तान में, या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। यह निर्णय लेने का अधिकार केवल रजवाड़ों के शासकों को दिया गया था, न कि वहाँ की जनता को। अतः कथन 4 गलत है क्योंकि इसमें प्रजा की भूमिका नहीं थी।

30. (D) 565
स्वतंत्रता के समय भारत में कुल 565 देसी रजवाड़े थे। ये रजवाड़े आकार और प्रभाव में एक-दूसरे से काफी भिन्न थे। कुछ रजवाड़े बहुत बड़े थे, जबकि कुछ बहुत छोटे। इन सभी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करना राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक बहुत बड़ी और जटिल चुनौती थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें स्वतंत्र रहने का विकल्प भी प्रदान किया था।

31. (A) त्रावणकोर
आजादी की घोषणा के तुरंत बाद, सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बनाए रखने की घोषणा की थी। इसके ठीक बाद हैदराबाद के निज़ाम ने भी इसी तरह की घोषणा की, जिससे भारतीय संघ की एकता को गंभीर खतरा पैदा हो गया। भोपाल के नवाब ने भी शुरु में संविधान सभा की बैठकों में शामिल होने से स्पष्ट इनकार कर दिया था।

32. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
सरदार वल्लभभाई पटेल ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ और दृढ़ इच्छाशक्ति से अधिकतर देसी रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी किया। उनके प्रयासों के फलस्वरूप ही लगभग सभी रियासतों के शासकों ने एक औपचारिक दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए, जिसे 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ एक्सेशन' के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के माध्यम से रजवाड़ों ने अपनी रियासत को औपचारिक रूप से भारतीय संघ का हिस्सा बनाया।

33. (B) इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ एक्सेशन
'इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ एक्सेशन' वह कानूनी सहमति-पत्र था जिसके माध्यम से देसी रजवाड़ों के शासकों ने अपनी रियासत को भारतीय संघ में शामिल करने की आधिकारिक स्वीकृति दी थी। इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने का अर्थ यह था कि संबंधित रियासत अब भारत का एक अभिन्न अंग बन गई है। सरदार

पटेल के प्रयासों से लगभग सभी रियासतों ने इस महत्वपूर्ण समझौते को स्वीकार कर राष्ट्र की एकता सुनिश्चित की।

34. (A) केवल 1, 2 और 3
भारत सरकार का मानना था कि अधिकतर रियासतों की जनता भारतीय संघ में शामिल होना चाहती थी। सरकार ने कुछ क्षेत्रों को स्वायत्तता देने के लिए लचीला रुख अपनाया, जिससे विलय की प्रक्रिया आसान हो सके। विभाजन के तनावपूर्ण माहौल में देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना प्राथमिकता थी। सरकार ने बल प्रयोग के बजाय बातचीत को महत्व दिया और रजवाड़ों को पूर्ण स्वायत्तता का वादा नहीं किया था।

35. (C) जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर
हालाँकि अधिकांश रियासतों का विलय शांतिपूर्ण रहा, लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर जैसी रियासतों का भारतीय संघ में विलय बाकियों की तुलना में काफी कठिन और विवादास्पद साबित हुआ। जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराना पड़ा, हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई की आवश्यकता हुई, कश्मीर का मुद्दा जटिल अंतरराष्ट्रीय मसला बन गया और मणिपुर में आंतरिक राजनीतिक विरोध के बाद विलय का समझौता अंततः संपन्न हो सका।

36. (D) निज़ाम
हैदराबाद रियासत के शासक को 'निज़ाम' की उपाधि से संबोधित किया जाता था। वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार था और उसने अपनी रियासत को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बनाए रखने की पुरजोर कोशिश की थी। निज़ाम के दमनकारी शासन और उसकी सांप्रदायिक नीतियों के कारण स्थानीय जनता ने उसके विरुद्ध एक व्यापक आंदोलन छेड़ दिया था, जिसके बाद भारत को हस्तक्षेप करना पड़ा।

37. (C) कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस
हैदराबाद के निज़ाम के निरंकुश और अत्याचारी शासन के विरुद्ध शुरू हुए जन-आंदोलन में कम्युनिस्टों और हैदराबाद कांग्रेस ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। तेलंगाना क्षेत्र के किसानों और विशेष रूप से महिलाओं ने इस दमनकारी शासन का कड़ा विरोध किया। कम्युनिस्टों ने ग्रामीण इलाकों में किसानों को संगठित किया, जबकि हैदराबाद कांग्रेस ने राजनीतिक स्तर पर निज़ाम के खिलाफ लोकतांत्रिक अधिकारों की माँग को लेकर कड़ा संघर्ष किया।

38. (B) रज़ाकार
हैदराबाद के निज़ाम ने अपने शासन के विरुद्ध उठ रहे जन-आंदोलन को कुचलने के लिए एक सांप्रदायिक अर्द्ध-सैनिक बल तैयार किया था, जिसे 'रज़ाकार' कहा जाता था। ये रज़ाकार अत्यंत क्रूर थे और उन्होंने विशेष रूप से गैर-मुस्लिम आबादी को अपना निशाना बनाया। उन्होंने लूटपाट, हत्या और बलात्कार जैसी हिंसक वारदातों को अंजाम दिया, जिससे पूरे राज्य में अराजकता और असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया था।

39. (D) सितंबर 1948 में
हैदराबाद में रज़ाकारों के बढ़ते आतंक और सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए भारत सरकार ने सितंबर 1948 में सैन्य हस्तक्षेप करने का कड़ा फैसला लिया। भारतीय सेना और निज़ाम की सेना के बीच कुछ दिनों तक संघर्ष चला, जिसके बाद निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस सफल सैन्य अभियान के परिणामस्वरूप हैदराबाद का आधिकारिक रूप से भारतीय संघ में विलय हो गया और जनता को अत्याचारी शासन से मुक्ति मिली।

40. (B) P-3, Q-4, R-2, S-1
हैदराबाद रियासत में रज़ाकारों ने जनता पर भारी अत्याचार किए थे। मणिपुर भारत का वह पहला क्षेत्र था जहाँ सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकतांत्रिक चुनाव आयोजित किए गए। जूनागढ़ का भारत में विलय वहाँ की जनता की इच्छा जानने के लिए कराए गए एक जनमत संग्रह के माध्यम से संपन्न हुआ। त्रावणकोर वह पहली रियासत थी जिसने सबसे पहले अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की औपचारिक घोषणा की थी।

41. (C) बोधचंद्र सिंह
मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ एक्सेशन' पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने यह समझौता इस शर्त पर किया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता को सुरक्षित रखा जाएगा। जनता के भारी दबाव में उन्होंने 1948 में चुनाव कराए, जिससे मणिपुर एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। बाद में, सितंबर 1949 में उन्होंने मणिपुर के पूर्ण भारत विलय के अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर किए।

42. (A) मणिपुर
मणिपुर आधुनिक भारतीय इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है क्योंकि यह भारत का वह पहला हिस्सा बना जहाँ जून 1948 में सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव कराए गए थे। इन चुनावों के माध्यम से वहाँ एक लोकतांत्रिक विधानसभा का गठन हुआ और मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। यह भारत में पूर्ण लोकतंत्र की दिशा में उठाया गया एक प्रारंभिक और महत्वपूर्ण कदम था।

43. (D) कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए।
मणिपुर की नवनिर्वाचित विधानसभा में भारत के साथ विलय के सवाल पर गहरे राजनीतिक मतभेद मौजूद थे। मणिपुर कांग्रेस इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख रखती थी और वह चाहती थी कि मणिपुर का पूर्ण रूप से भारतीय संघ में विलय कर दिया जाए। इसके विपरीत, मणिपुर की अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियाँ इस विलय के पूरी तरह खिलाफ थीं और वे राज्य की स्वायत्तता बनाए रखने के पक्ष में थीं।

44. (A) 3, 1, 2, 4
ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम में सबसे पहले त्रावणकोर ने स्वतंत्रता की घोषणा की। इसके बाद जून 1948 में मणिपुर में लोकतांत्रिक चुनाव आयोजित किए गए। हैदराबाद का भारत में विलय सितंबर 1948 में सैन्य कार्रवाई के बाद हुआ। अंत में,

सितंबर 1949 में मणिपुर का औपचारिक रूप से पूर्णतः भारत में विलय संपन्न हुआ। यह क्रम भारत के एकीकरण की जटिल और चरणबद्ध प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

45. (C) प्रशासनिक सुविधा या ब्रिटिश सरकार द्वारा विजित क्षेत्र
ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में प्रांतों की सीमाओं का निर्धारण किसी भाषाई या सांस्कृतिक तर्क के आधार पर नहीं किया गया था। प्रांतों का गठन मुख्य रूप से प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया था या फिर उनकी सीमाएँ वहाँ तक फैली थीं जहाँ तक ब्रिटिश सरकार ने उन क्षेत्रों को युद्ध या संधियों के माध्यम से जीता था। इसमें स्थानीय जनता की भावनाओं का कोई महत्व नहीं था।

46. (D) 1920 का नागपुर अधिवेशन
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1920 के अपने प्रसिद्ध नागपुर अधिवेशन में ही भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के सिद्धांत को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया था। इस अधिवेशन के बाद से ही कांग्रेस की कई क्षेत्रीय समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया जाने लगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह वादा किया गया था कि आज़ादी के बाद राज्यों का निर्माण भाषाई सीमाओं के अनुसार ही होगा।

47. (A) इससे अव्यवस्था और देश टूटने का खतरा पैदा होने का डर था।
आज़ादी और विभाजन के तुरंत बाद भारत के केंद्रीय नेतृत्व को लगा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने से देश में अव्यवस्था फैल सकती है। उन्हें डर था कि इससे अलगाववाद की भावनाओं को बढ़ावा मिलेगा और देश की नवनिर्मित एकता को खतरा हो सकता है। रियासतों का मुद्दा भी अनसुलझा था, इसलिए नेताओं ने भाषाई राज्यों के संवेदनशील मसले को कुछ समय के लिए स्थगित करना बेहतर समझा।

48. (B) तेलुगु-भाषी क्षेत्रों में
पुराने मद्रास प्रांत में भाषाई आधार पर विरोध तब भड़क उठा जब तेलुगु-भाषी लोगों ने अपने लिए एक अलग राज्य की माँग की। यह माँग विशेष रूप से उन क्षेत्रों में प्रबल थी जहाँ तेलुगु मुख्य भाषा के रूप में बोली जाती थी। आंदोलनकारियों का मानना था कि उनके भाषाई और सांस्कृतिक हितों की रक्षा केवल एक पृथक राज्य, यानी आंध्र प्रदेश के गठन के माध्यम से ही संभव हो सकती है।

49. (B) तेलुगुभाषी इलाकों को अलग कर आंध्र प्रदेश बनाया जाए।
'विशाल आंध्र आंदोलन' की प्रमुख माँग यह थी कि तत्कालीन मद्रास प्रांत में शामिल तेलुगु-भाषी क्षेत्रों को अलग करके एक नया राज्य 'आंध्र प्रदेश' बनाया जाए। यह आंदोलन भाषाई पहचान पर आधारित था और इसे स्थानीय स्तर पर व्यापक जनसमर्थन प्राप्त था। आंदोलनकारियों का तर्क था कि एक अलग भाषाई राज्य के गठन से ही उनके क्षेत्र का समुचित प्रशासनिक और आर्थिक विकास संभव हो सकेगा।

50. (C) केवल 1, 2 और 3
पोट्टी श्रीरामुलु एक समर्पित कांग्रेस नेता और गाँधीवादी थे जिन्होंने अलग आंध्र राज्य के गठन के लिए आमरण अनशन किया था। उनकी यह भूख-हड़ताल 56 दिनों तक चली, जिसके बाद उनकी दुखद मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के परिणामस्वरूप आंध्र क्षेत्र में भारी जन-आक्रोश फैल गया और हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरु हो गए, जिससे सरकार को उनकी माँग माननी पड़ी। अतः कथन 4 बिल्कुल गलत है।

51. (C) दिसंबर 1952 में
पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद उपजे भारी जन-दबाव और हिंसक परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु ने अंततः दिसंबर 1952 में अलग आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की औपचारिक घोषणा की। यह भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। इस महत्वपूर्ण निर्णय ने देश के अन्य भाषाई क्षेत्रों में भी इसी तरह की माँगों के लिए एक नया रास्ता खोल दिया।

52. (D) 1953 में
आंध्र प्रदेश के गठन के बाद देश के अन्य हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों की माँग प्रबल होने लगी। इन परिस्थितियों से निपटने और राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 1953 में 'राज्य पुनर्गठन आयोग' की स्थापना की। इस आयोग का मुख्य कार्य राज्यों की सीमाओं के सीमांकन के पूरे मामले पर गहराई से विचार करना और सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपना था।

53. (C) राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए।
राज्य पुनर्गठन आयोग ने व्यापक अध्ययन के बाद यह प्रमुख सिफारिश की कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण मुख्य रूप से वहाँ बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर ही किया जाना चाहिए। आयोग का मानना था कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण प्रशासनिक कुशलता बढ़ाने और विभिन्न भाषाई समूहों की आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में सहायक सिद्ध होगा, जिससे लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा।

54. (B) 1956
राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए भारतीय संसद ने वर्ष 1956 में 'राज्य पुनर्गठन अधिनियम' पारित किया। यह अधिनियम भारत के प्रशासनिक भूगोल को पुनर्गठित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। इसके माध्यम से देश के नक्शे में व्यापक बदलाव किए गए और भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया को एक सुदृढ़ कानूनी और संवैधानिक आधार प्रदान किया गया।

55. (D) 14 राज्य और 6 केंद्र-शासित प्रदेश
वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के कड़ाई से क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप भारत में कुल 14 राज्यों और 6 केंद्र-शासित प्रदेशों का विधिवत गठन किया गया। इस प्रक्रिया ने औपनिवेशिक काल की प्रशासनिक सीमाओं को समाप्त कर दिया और उनके स्थान पर भाषाई और सांस्कृतिक

विषयों - रक्षा, विदेशी मामले और संचार - को भारतीय संघ को सौंप दिया, जबकि आंतरिक स्वायत्तता को बनाए रखा। शासकों को 'प्रिवी पर्स' (शाही भत्ता) और अन्य विशेषाधिकारों का आश्वासन देकर भी प्रोत्साहित किया गया। हालाँकि, यह प्रक्रिया हमेशा सहज नहीं थी। हैदराबाद जैसी रियासतों में, जहाँ शासक स्वतंत्र रहना चाहता था और अपनी प्रजा पर अत्याचार कर रहा था, भारत सरकार को लोकप्रिय इच्छा का समर्थन करने और राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सैन्य हस्तक्षेप ('ऑपरेशन पोलो') करना पड़ा। इस प्रकार, रियासतों का विलय केवल प्रशासनिक अभ्यास नहीं था, बल्कि यह भारत के एक एकीकृत राजनीतिक मानचित्र को गढ़ने की एक जटिल राजनीतिक प्रक्रिया थी, जिसने नवजात राष्ट्र को विखंडन से बचाया।
उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

156. रियासतों के एकीकरण का श्रेय मुख्य रूप से किसे दिया जाता है?
(A) लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू
(B) सरदार वल्लभभाई पटेल और वी.पी. मेनन
(C) महात्मा गांधी और मुहम्मद अली जिन्ना
(D) बी.आर. अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद

157. 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन' के तहत रियासतों ने कौन से विषय भारतीय संघ को सौंपे थे?
(A) शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि
(B) कराधान, न्यायपालिका और पुलिस
(C) व्यापार, उद्योग और परिवहन
(D) रक्षा, विदेशी मामले और संचार

158. रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु क्या आश्वासन दिया गया था?
(A) 'प्रिवी पर्स' और अन्य विशेषाधिकार
(B) संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता
(C) अन्य देशों के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौते
(D) अपनी मुद्रा छापने का अधिकार

159. हैदराबाद की रियासत के विलय के लिए भारत सरकार को सैन्य हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा?
(A) क्योंकि निज़ाम ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया था।
(B) क्योंकि हैदराबाद में बड़े पैमाने पर अकाल पड़ा था।
(C) क्योंकि शासक स्वतंत्र रहना चाहता था और अपनी प्रजा की इच्छाओं का दमन कर रहा था।
(D) क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हस्तक्षेप का आदेश दिया था।

160. इस अनुच्छेद से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है?
(A) पटेल और मेनन की रणनीति ने भारत को संभावित विखंडन से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
(B) सभी रियासतें स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव के भारत में शामिल हो गईं।
(C) रियासतों का एकीकरण एक सरल और सीधी प्रक्रिया थी।
(D) 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन' ने रियासतों की पूर्ण स्वायत्तता की गारंटी दी।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
भारत का विभाजन केवल एक राजनीतिक और भौगोलिक घटना नहीं थी, बल्कि यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक थी। इसने लाखों लोगों के जीवन पर एक अमिट मनोवैज्ञानिक और सामाजिक-सांस्कृतिक घाव छोड़ा। यह केवल आँकड़ों का खेल नहीं था कि कितने लोग विस्थापित हुए या मारे गए, बल्कि यह जड़ों से उखड़ने, पहचान खोने और 'वतन' की अवधारणा के टूटने का दर्द था। रातों-रात लोग अपने ही घरों में अजनबी बन गए, उन्हें सब कुछ पीछे छोड़कर शरणार्थी शिविरों की अनिश्चितता में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस विस्थापन का सबसे क्रूर पहलू महिलाओं के खिलाफ हुई हिंसा थी, जिन्हें 'समुदाय के सम्मान' का प्रतीक मानकर अपहरण, बलात्कार और जबरन धर्मांतरण का शिकार बनाया गया। कई लेखकों और फिल्म निर्माताओं ने इस दर्द को अपनी रचनाओं में व्यक्त करने का प्रयास किया है। सआदत हसन मंटो की कहानियाँ, अमृता प्रीतम की कविता 'अज्ज आखां वारिस शाह नूँ', और एम.एस. सथ्यु की फिल्म 'गर्म हवा' विभाजन की मानवीय पीड़ा के शक्तिशाली दस्तावेज़ हैं। ये कलात्मक अभिव्यक्तियाँ हमें याद दिलाती हैं कि विभाजन का प्रभाव केवल सीमाओं के पुनर्निर्धारण तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने दक्षिण एशिया के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को गहराई से प्रभावित किया, जिसकी गूँज आज भी सुनाई देती है।
उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

161. अनुच्छेद के अनुसार, विभाजन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था?
(A) केवल राजनीतिक सीमाओं का पुनर्निर्धारण
(B) आर्थिक समृद्धि में वृद्धि
(C) सैन्य शक्ति का विस्तार
(D) गहरा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक-सांस्कृतिक घाव

162. विभाजन के दौरान महिलाओं को विशेष रूप से क्यों निशाना बनाया गया?
(A) क्योंकि वे राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय थीं।
(B) क्योंकि उन्हें 'समुदाय के सम्मान' का प्रतीक माना जाता था।
(C) क्योंकि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र थीं।
(D) क्योंकि उन्होंने सीमा पार करने से इनकार कर दिया था।

163. निम्नलिखित में से कौन सी रचना विभाजन की त्रासदी से संबंधित नहीं है, जैसा कि स्रोत में उल्लेख किया गया है?
(A) सआदत हसन मंटो की कहानियाँ
(B) अमृता प्रीतम की कविता 'अज्ज आखां वारिस शाह नूँ'

से पीड़ित हैं। उनके अनुसार, स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य समाज के सबसे कमज़ोर और पिछड़ें वर्गों का उत्थान करना और उन्हें समान अवसर प्रदान करना था।

67. (C) विविधताओं को समायोजित करने वाले भारत को गढ़ना।
स्वतंत्र भारत के सामने सबसे पहली और तात्कालिक चुनौती एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना थी जो अपनी समस्त विविधताओं को एक सूत्र में पिरो सके। भारत में विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग रहते थे, इसलिए उन्हें एकजुट रखना राष्ट्र की अखंडता के लिए अनिवार्य था। नेताओं के लिए मुख्य लक्ष्य एक साझा पहचान विकसित करना था जहाँ विविधता को बोझ के बजाय एक शक्ति समझा जाए।

68. (D) सरदार वल्लभभाई पटेल
सरदार वल्लभभाई पटेल ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में देसी रजवाड़ों के भारतीय संघ में विलय में सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपनी अदम्य कूटनीति, दृढ़ता और साहस के साथ 565 रियासतों को एक सूत्र में बाँधकर आधुनिक भारत की नींव रखी। उनकी इसी महान उपलब्धि के कारण उन्हें 'लौह पुरुष' और भारत का 'बिस्मार्क' भी कहा जाता है।

69. (A) 3, 2, 1, 4
आंध्र प्रदेश राज्य का गठन दिसंबर 1952 में हुआ था। इसके पश्चात, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, जिसने देश के मानचित्र को बदल दिया। 1960 में बंबई का विभाजन कर महाराष्ट्र और गुजरात नामक दो नए राज्यों का निर्माण हुआ। अंत में, 1963 में नगालैंड को एक पूर्ण राज्य के रूप में मान्यता मिली। यह क्रम भारत में राज्यों के भाषाई और क्षेत्रीय विकास को दर्शाता है।

70. (B) निज़ाम
हैदराबाद रियासत की जनता वहाँ के शासक निज़ाम के अत्यंत दमनकारी और निरंकुश शासन से बेहद दुखी थी। निज़ाम की दमनकारी नीतियों, विशेष रूप से रज़ाकारों द्वारा किए गए अत्याचारों ने लोगों के धैर्य की सीमा पार कर दी थी। इसके विरोध में तेलंगाना के किसानों, महिलाओं और राजनीतिक संगठनों ने एक व्यापक विद्रोह शुरू किया। यह आंदोलन अंततः हैदराबाद के भारत में सफल विलय और निज़ाम के शासन के अंत का कारण बना।

71. (B) केवल 1, 2 और 3
हैदराबाद के रज़ाकार निज़ाम द्वारा समर्थित एक सांप्रदायिक और अत्यंत क्रूर अर्द्ध-सैनिक बल थे जिन्होंने आम जनता पर भयानक अत्याचार किए। उन्होंने विशेष रूप से गैर-मुस्लिम आबादी को हिंसा का निशाना बनाया और हत्या, लूटपाट व बलात्कार जैसे अपराध किए। रज़ाकार निज़ाम के लिए पूरी तरह अनुशासित बल होने के बजाय एक अनियंत्रित दंगाइयों के गिरोह की तरह व्यवहार कर रहे थे, जिसने राज्य में अराजकता पैदा कर दी थी।

72. (C) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें 'सीमांत गाँधी' के नाम से जाना जाता था, 'द्वि-राष्ट्र सिद्धांत' के प्रबल विरोधी थे और उन्होंने भारत के विभाजन का कड़ा विरोध किया था। वे पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत के सबसे प्रभावशाली और निर्विवाद राष्ट्रवादी नेता थे। हालाँकि उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके क्षेत्र को पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया, लेकिन उनकी विचारधारा हमेशा सांप्रदायिक विभाजन के खिलाफ और भारतीय राष्ट्रीयता के पक्ष में रही।

73. (C) शरणार्थी शिविरों में
विभाजन के दौरान अपनी जान बचाकर सीमा पार करने वाले लाखों विस्थापित लोगों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। इन बेघर लोगों को मजबूरन शरणार्थी शिविरों में आश्रय लेना पड़ा, जहाँ जीवन की बुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव था। वे महीनों और कभी-कभी सालों तक इन शिविरों में दयनीय स्थिति में रहे, जबकि उनकी अपनी संपत्तियाँ और घर सीमा के दूसरी तरफ पीछे छूट गए थे।

74. (B) P-2, Q-1, R-4, S-3
मुस्लिम लीग ने 'द्वि-राष्ट्र सिद्धांत' प्रस्तुत किया था। 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ एक्सेशन' वह दस्तावेज़ था जिसके माध्यम से देसी रियासतों का भारतीय संघ में विलय हुआ। मणिपुर भारत का पहला भाग बना जहाँ 'सार्वभौम वयस्क मताधिकार' के आधार पर चुनाव आयोजित किए गए। 'राज्य पुनर्गठन आयोग' का मुख्य कार्य भाषाई आधार पर राज्यों के सीमांकन और गठन से संबंधित समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान करना था।

75. (D) ट्रेन रोककर गैर-मज़हब के लोगों की दंगाइयों द्वारा हत्या।
सआदत हसन मंटो की कहानी 'कस्र-ए-नफ्सी' विभाजन के दौरान होने वाली भीषण और अंधी सांप्रदायिक हिंसा का एक दर्दनाक चित्रण करती है। यह कहानी दिखाती है कि कैसे दंगाइयों ने चलती ट्रेनों को रोककर केवल धार्मिक पहचान के आधार पर निर्दोष यात्रियों की नृशंस हत्या कर दी थी। मंटो ने अपनी इस रचना के माध्यम से विभाजन की विभीषिका और मानवता के पतन को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से उजागर किया है।

76. (B) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
महात्मा गाँधी की हत्या के बाद देश में व्याप्त सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार का मानना था कि सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाली विचारधाराओं ने ही गाँधीजी की हत्या की परिस्थितियाँ पैदा की थीं। यह प्रतिबंध कुछ समय तक लागू रहा और इसका उद्देश्य देश में शांति और सद्भाव बनाए रखना तथा सांप्रदायिक अतिवाद पर कड़ी लगाम कसना था।

77. (C) 26
आज का उड़ीसा राज्य स्वतंत्रता के समय 26 छोटे और बड़े रजवाड़ों के समूह से मिलकर बना था। इन सभी रियासतों को एकजुट करना और उन्हें एक आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था के

99. (C) अलोकतांत्रिक रीति से
स्वतंत्रता से पूर्व अधिकांश देसी रजवाड़ों में शासन अलोकतांत्रिक रीति से चलाया जाता था। वहाँ की जनता को बुनियादी नागरिक अधिकार और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। राजाओं का शासन स्वेच्छाचारी था और वे केवल ब्रिटिश सत्ता के प्रति जवाबदेह थे। रजवाड़ों के भीतर चलने वाले जन-आंदोलनों की एक प्रमुख माँग यही थी कि वहाँ भी ब्रिटिश प्रांतों की तरह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और नागरिक अधिकार लागू किए जाएँ।

100. (D) 14 बड़े और 119 छोटे
आज के गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र स्वतंत्रता के समय अत्यधिक राजनीतिक विखंडन का शिकार था। इस छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में कुल 14 बड़ी रियासतें और 119 छोटे रजवाड़े मौजूद थे। इन सभी का भारतीय संघ में विलय करना और उन्हें एक एकीकृत प्रशासनिक ढांचे में ढालना एक अत्यंत श्रमसाध्य और जटिल कार्य था। सरदार पटेल ने अपनी कुशलता से इन सभी को एकजुट कर आधुनिक गुजरात की नींव रखी।

101. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
आंध्र प्रदेश के गठन ने भारत में भाषाई राजनीति को एक नई दिशा दी। जब एक भाषाई राज्य की मांग पूरी हुई, तो अन्य भाषाई समूहों, जैसे कन्नड़ और मराठी भाषियों ने भी अपने लिए अलग राज्यों की मांग तेज कर दी। इन व्यापक संघर्षों और देश भर में उठने वाली आवाजों के कारण केंद्र सरकार को बाध्य होकर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करना पड़ा था।

102. (B) इसका अर्थ विभिन्नताओं को पहचानना और स्वीकार करना था।
भाषाई राज्यों के निर्माण ने भारतीय लोकतंत्र को एक नया और व्यापक आयाम प्रदान किया। इसका अर्थ यह हुआ कि लोकतंत्र केवल औपचारिक नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की सांस्कृतिक और भाषाई विविधताओं को सम्मान देने और उन्हें स्वीकार करने का नाम है। इस प्रक्रिया ने क्षेत्रीय अस्मिताओं को राष्ट्रीय धारा से जोड़कर लोकतंत्र को अधिक परिपक्व बनाया, जहाँ विभिन्न पहचानें एक साथ गौरवपूर्वक रह सकती हैं।

103. (D) छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड
वर्ष 2000 में भारत में तीन नए राज्यों का गठन किया गया था, जो क्षेत्रीय विकास और प्रशासनिक सुगमता की माँगों पर आधारित थे। मध्य प्रदेश को विभाजित कर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तराखंड और बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग कर झारखंड राज्य बनाया गया। ये राज्य मुख्य रूप से विशिष्ट क्षेत्रीय पहचान और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के उद्देश्य से गठित किए गए थे।

104. (A) हालात सुधर गए और लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव से जश्न मनाया।
कोलकाता में जब भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे थे, तब महात्मा गाँधी वहाँ पहुँचे और शांति के लिए उपवास शुरू किया। उनकी उपस्थिति और नैतिक दबाव का जादुई प्रभाव पड़ा तथा दंगाई हिंसा छोड़कर सद्भाव की राह पर लौट आए। लोगों ने एक-दूसरे के साथ मिलकर आज़ादी का जश्न मनाया। गाँधीजी के इस अहिंसक प्रयास ने हज़ारों निर्दोष लोगों की जान बचाई और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कायम की।

105. (C) देश का बँटवारा, अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी
स्वतंत्र भारत का जन्म अत्यंत विषम और दुखद परिस्थितियों में हुआ था। देश को आज़ादी तो मिली, लेकिन वह बँटवारे की विभीषिका के साथ आई। लाखों लोगों की हत्या और करोड़ों का विस्थापन इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक था। इन कठिन परिस्थितियों ने नव-स्वतंत्र राष्ट्र के सामने सुरक्षा, पुनर्वास और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने की एक साथ कई जटिल और गंभीर चुनौतियाँ खड़ी कर दी थीं।

106. (A) P-2, Q-3, R-4, S-1
पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने द्वि-राष्ट्र सिद्धांत का कड़ा विरोध किया था। पंजाब विभाजन के दौरान सबसे भीषण और खूनी त्रासदी का मुख्य स्थल बना। बंगाल का भी धार्मिक आधार पर बँटवारा हुआ जिससे पूर्वी पाकिस्तान बना। पुराने मद्रास प्रांत में विशाल आंध्र आंदोलन हुआ, जिसने भाषाई आधार पर तेलुगु-भाषी लोगों के लिए अलग राज्य, आंध्र प्रदेश के गठन की पुरजोर माँग की थी।

107. (D) आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा
1947 के विभाजन के दौरान हुआ जनसंख्या का स्थानांतरण इतिहास का सबसे बड़ा, आकस्मिक और अनियोजित विस्थापन था। लोगों को अपनी पुश्तैनी संपत्तियाँ और घर छोड़ने के लिए कोई समय नहीं मिला। यह स्थानांतरण पूरी तरह से त्रासदीपूर्ण था, जहाँ लाखों शरणार्थियों को पैदल या असुरक्षित ट्रेनों में यात्रा करनी पड़ी। रास्ते में उन्हें भीषण सांप्रदायिक हिंसा, लूटपाट और अकल्पनीय शारीरिक व मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा था।

108. (B) नेता द्वि-राष्ट्र सिद्धांत में नहीं मानते थे, पर बँटवारा धर्म के आधार पर हुआ।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकांश नेता 'द्वि-राष्ट्र सिद्धांत' के पूरी तरह खिलाफ थे और वे धर्म के आधार पर देश के विभाजन को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। हालांकि, तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों, मुस्लिम लीग के अड़ियल रुख और सांप्रदायिक हिंसा के दबाव में उन्हें अंततः विभाजन को स्वीकार करना पड़ा। बँटवारा भले ही धार्मिक आधार पर हुआ, लेकिन भारतीय नेतृत्व ने हमेशा धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों को ही सर्वोपरि माना।

109. (C) केवल 1, 2 और 3
मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के हितों और अलग राष्ट्र की माँग की, जबकि कुछ हिंदू संगठन भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत कर रहे थे। हालांकि, भारत की अंतरिम सरकार के अधिकांश नेता धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर थे और वे सभी नागरिकों को समान दर्जा देने के हिमायती थे। अतः कथन 4

अपनाया है, जो जनप्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित है। ये सभी विशेषताएँ सामूहिक रूप से देश में एक सुदृढ़ लोकतांत्रिक ढाँचे की स्थापना को सुनिश्चित करती हैं। संविधान ने यह सुनिश्चित किया कि लोकतंत्र केवल कागजों पर न रहे बल्कि व्यवहार में भी आए।

89. (C) ऐसा विकास जिससे समूचे समाज का भला हो।
स्वतंत्र भारत के नेतृत्व ने आर्थिक विकास के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाया। उनका मुख्य उद्देश्य केवल औद्योगिक प्रगति करना ही नहीं था, बल्कि ऐसा विकास सुनिश्चित करना था जिसका लाभ समाज के सभी तबकों, विशेषकर गरीबों और वंचितों तक पहुँच सके। संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धांतों में भी इसी लोक-कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है, जहाँ आर्थिक न्याय और समानता को प्राथमिकता दी गई है।

90. (A) पाकिस्तान की माँग मान ली गई।
1940 के दशक में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच तीव्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुई। मुस्लिम लीग ने 'द्वि-राष्ट्र सिद्धांत' के आधार पर मुसलमानों के लिए अलग देश की माँग की। ब्रिटिश सरकार ने अपनी 'बाँटो और राज करो' की नीति के तहत इस संघर्ष को और बढ़ावा दिया। अंततः इन परिस्थितियों के दबाव में भारत के विभाजन का निर्णय लिया गया और एक अलग राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का निर्माण हुआ।

91. (A) P-3, Q-4, R-2, S-1
फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने विभाजन के दर्द को अपनी नज़्म 'सुब्ह-ए-आज़ादी' में व्यक्त किया। अमृता प्रीतम की प्रसिद्ध कविता 'आज आखूँ वारिस शाह नूँ' पंजाब के दुख का वर्णन करती है। सआदत हसन मंटो की कहानी 'कस्र-ए-नफ्सी' दंगे की हिंसक हकीकत को दिखाती है। एम. एस. सथ्यु ने विभाजन की मानवीय त्रासदी पर 'गर्म हवा' जैसी प्रभावशाली फिल्म का निर्देशन किया, जो इस विषय पर एक कालजयी कृति मानी जाती है।

92. (B) जिले या निचले स्तर पर धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर।
पंजाब और बंगाल के विभाजन के लिए धार्मिक बहुसंख्या को ही मुख्य पैमाना माना गया था। चूंकि इन प्रांतों में आबादी का स्वरूप बहुत मिश्रित था, इसलिए केवल बड़े क्षेत्रों के बजाय जिला स्तर या उससे भी निचले प्रशासनिक स्तरों पर आबादी की धार्मिक संरचना को देखा गया। इस जटिल प्रक्रिया के कारण ही विभाजन की रेखा घरों, गाँवों और समुदायों के बीच से गुजरी, जिससे भारी मानवीय त्रासदी उत्पन्न हुई।

93. (C) अनेक लोगों को नहीं पता था कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में।
विभाजन की सीमा रेखा तय करने में देरी होने के कारण 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि तक लाखों लोगों को यह जानकारी ही नहीं थी कि उनका इलाका किस देश में शामिल हुआ है। इस अनिश्चितता ने सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी दहशत और भ्रम पैदा कर दिया। लोग अपने ही घरों में यह सोचकर असुरक्षित महसूस कर रहे थे कि कहीं वे अचानक 'दूसरे' देश के नागरिक न बन गए हों।

94. (D) उपरोक्त सभी।
विभाजन के दौरान महिलाओं को सबसे भीषण अमानवीय त्रासदी झेलनी पड़ी। हजारों महिलाओं का अपहरण किया गया, उन्हें जबरन विवाह और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। कई मामलों में परिवारों ने अपनी 'कुल की इज़्ज़त' बचाने के भ्रम में स्वयं अपनी ही घर की महिलाओं की हत्या कर दी। यह विभाजन का वह काला पक्ष है जो मानवीय गरिमा और अधिकारों के पूर्ण पतन को स्पष्ट रूप से उजागर करता है।

95. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं, और कथन II, कथन I की सही व्याख्या करता है।
भारत का विभाजन केवल भूमि, खजाने या सरकारी सामान का बँटवारा नहीं था, बल्कि यह सदियों से साथ रह रहे दो समुदायों का एक हिंसक अलगाव था। जो लोग पीढ़ियों से पड़ोसी और दोस्त की तरह रहते आए थे, वे अचानक एक-दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। यह विभाजन मानवीय भावनाओं, साझा संस्कृति और सामाजिक एकता का वह हिंसक विखंडन था, जिसकी चोट आज भी इतिहास में महसूस की जाती है।

96. (B) एक साल के लिए यथास्थिति बहाल रखने का समझौता।
हैदराबाद के निज़ाम ने भारत के साथ तुरंत विलय करने के बजाय समय लेने की रणनीति अपनाई। इसके तहत नवंबर 1947 में भारत सरकार और निज़ाम के बीच एक साल के लिए 'यथास्थिति' (Stऔरstill Agreement) बहाल रखने का समझौता हुआ। इस समझौते का उद्देश्य यह था कि इस दौरान दोनों पक्ष भविष्य के संबंधों पर शांतिपूर्ण बातचीत कर सकें, हालांकि इस अवधि में हैदराबाद के आंतरिक हालात और खराब होते गए।

97. (B) पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से
हैदराबाद रियासत भौगोलिक रूप से काफी विशाल थी और इसके विभिन्न भाषाई क्षेत्र थे। वर्तमान महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्से पुराने हैदराबाद रियासत का हिस्सा थे, जहाँ क्रमशः मराठी और कन्नड़ भाषाएँ बोली जाती थीं। विभाजन और भाषाई पुनर्गठन के बाद इन हिस्सों को हैदराबाद से अलग कर संबंधित भाषाई राज्यों में मिला दिया गया। यह रियासतों के पुनर्गठन और भाषाई आधार पर राज्यों के सीमांकन का एक प्रमुख उदाहरण है।

98. (B) केवल 1, 2, 3 और 4
आजादी के समय त्रावणकोर और हैदराबाद के शासकों ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी, जबकि भोपाल के नवाब ने संविधान सभा से दूरी बनाई। इन घटनाओं ने भारत के विखंडन का गंभीर खतरा पैदा कर दिया था। अधिकांश रजवाड़ों के शासक अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे, बल्कि वे अपनी निरंकुश सत्ता बनाए रखना चाहते थे। अतः कथन 5 गलत है क्योंकि राजा लोकतंत्र के विरोधी थे।

163. (C) जवाहरलाल नेहरू की 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया'
जवाहरलाल नेहरू की 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' भारत के इतिहास का विश्लेषण है, जबकि मंटो की कहानियाँ, अमृता प्रीतम की कविता और फिल्म 'गर्म हवा' विभाजन की मानवीय पीड़ा को दर्शाती हैं। ये कलात्मक रचनाएँ विभाजन के दर्द को दर्ज करने वाले दस्तावेज हैं। 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' इस श्रेणी में नहीं आती क्योंकि इसका मुख्य विषय विभाजन की मानवीय त्रासदी नहीं है।

164. (D) मातृभूमि और जड़ों से अलगाव का दर्द
'वतन' की अवधारणा के टूटने का अर्थ अपनी मातृभूमि और सांस्कृतिक जड़ों से अचानक अलग हो जाने का गहरा दर्द है। विभाजन ने लोगों को रातों-रात उनके ही घरों में पराया बना दिया। यह केवल भौतिक विस्थापन नहीं था, बल्कि एक पुरानी जीवनशैली और भावनात्मक जुड़ाव का दुखद अंत था। अपनी मिट्टी से बिछड़ने की यह टीस शरणार्थियों के लिए जीवन भर रही।

165. (A) विभाजन के मानवीय, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को उजागर करना।
विभाजन के राजनीतिक परिणामों के बजाय उसके मानवीय, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझना अत्यंत आवश्यक है। यह घटना लोगों के मन और समाज के ताने-बाने को गहराई से प्रभावित करती है। कला और साहित्य के उदाहरणों के माध्यम से, कोई भी विभाजन की उस मानवीय पीड़ा को महसूस कर सकता है जिसे केवल सरकारी आँकड़े या मानचित्र की लकीरें पूरी तरह व्यक्त नहीं करतीं।

166. (B) क्योंकि उन्हें डर था कि इससे अलगाववादी प्रवृत्तियाँ बढ़ेंगी और एकता को खतरा होगा।
स्वतंत्रता और विभाजन के तत्काल बाद, भारतीय नेतृत्व को भय था कि भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण से अलगाववाद को बढ़ावा मिल सकता है। उन्हें लगा कि इससे देश की एकता को खतरा पैदा होगा। इसलिए, कांग्रेस के पुराने वादों के बावजूद, सरकार ने शुरुआत में इस प्रक्रिया को टाला ताकि नवजात राष्ट्र को विखंडन के किसी भी नए संकट से सुरक्षित रखा जा सके।

167. (B) विशाल आंध्र आंदोलन और पोट्टी श्रीरामुलु की शहादत
भाषाई राज्यों की माँग ने तब जोर पकड़ा जब आंध्र आंदोलन के दौरान पोट्टी श्रीरामुलु ने भूख हड़ताल की और उनकी मृत्यु हो गई। इस बलिदान के बाद हुए तीव्र जन आक्रोश ने सरकार को आंध्र प्रदेश बनाने पर विवश कर दिया। इस घटना ने पूरे देश में भाषाई आधार पर पुनर्गठन की प्रक्रिया को गति दी और अन्य क्षेत्रों में भी माँगें बढ़ीं।

168. (A) 1953
भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की माँगों के समाधान के लिए भारत सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी। इस आयोग का कार्य राज्यों की सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण करने के लिए वैज्ञानिक सुझाव देना था। इसने गहन अध्ययन के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी, जो बाद में 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम का मुख्य कानूनी आधार बनी।

169. (C) भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए।
राज्य पुनर्गठन आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए। आयोग का मानना था कि भाषाई समानता से प्रशासन सुगम होगा और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी। इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने भाषाई विविधता को स्वीकार करते हुए उसे राष्ट्रीय एकता के साथ जोड़ने का एक व्यावहारिक और लोकतांत्रिक ढाँचा भारत को प्रदान किया।

170. (D) इसने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को समायोजित करके भारतीय संघ को मजबूत किया।
भाषाई पुनर्गठन का दीर्घकालिक परिणाम यह हुआ कि इसने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को एक लोकतांत्रिक मंच प्रदान किया और भारतीय संघ को अधिक मजबूती दी। इससे यह सिद्ध हुआ कि भाषाई पहचान राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा नहीं, बल्कि उसकी पूरक है। इस प्रक्रिया ने शासन को जनता की भाषा के करीब लाकर लोकतंत्र को समावेशी बनाया, जिससे देश की आंतरिक स्थिरता में वृद्धि हुई।

171. (C) एक जर्जर और अविकसित अर्थव्यवस्था
स्वतंत्रता के समय भारत को औपनिवेशिक शासन से एक जर्जर और अविकसित अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बहुत कम थी और उद्योग लगभग नगण्य थे। बुनियादी ढाँचे और भारी उद्योगों के अभाव के कारण गरीबी और भुखमरी की समस्या अत्यंत गंभीर थी। इस आर्थिक स्थिति ने राष्ट्र-निर्माण के सामने विकास और गरीबी उन्मूलन की एक विशाल चुनौती पेश की।

172. (B) मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल
भारत ने अपने शुरुआती आर्थिक विकास के लिए 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' का मॉडल चुना, जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की सक्रिय भूमिका तय की गई। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना था। इसके तहत कृषि और व्यापार निजी हाथों में रहे, जबकि रणनीतिक महत्व के भारी उद्योगों और बुनियादी ढाँचे पर राज्य का प्रभावी नियंत्रण और निवेश सुनिश्चित किया गया।

173. (D) भारी उद्योग और बुनियादी ढाँचा
1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अनुसार, भारी उद्योग और बुनियादी ढाँचा जैसे रणनीतिक क्षेत्र मुख्य रूप से राज्य के नियंत्रण के लिए आरक्षित किए गए थे। सरकार का मानना था कि तेजी से विकास के लिए इन क्षेत्रों में बड़े पूंजी निवेश की आवश्यकता है, जो निजी क्षेत्र नहीं कर सकता था। इस प्रकार राज्य ने आर्थिक विकास के मुख्य इंजन की जिम्मेदारी ली।

174. (A) योजना आयोग
नियोजित विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने और संसाधनों के उचित आवंटन के लिए 1950 में योजना आयोग की स्थापना की

गलत है क्योंकि देश के शीर्ष नेता धर्म के आधार पर भेदभाव करने के पूरी तरह खिलाफ थे।

110. (D) धर्म
भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष दस्तावेज़ है जो सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार प्रदान करता है। भारत में नागरिकता प्रदान करने के लिए जन्म स्थान, वंश और पंजीकरण जैसे कानूनी आधारों का उपयोग किया जाता है। धर्म को नागरिकता की कसौटी कभी नहीं बनाया गया है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहे और किसी विशेष धर्मावलंबी को कोई विशेष वरीयता न मिले।

111. (A) जम्मू-कश्मीर को कुछ स्वायत्तता देना।
भारत सरकार ने रियासतों के विलय के समय विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट परिस्थितियों को समझते हुए एक लचीला रुख अपनाया था। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण जम्मू-कश्मीर को दी गई विशेष स्वायत्तता थी, जिसे संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत सुरक्षित किया गया था। इस नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय आकांक्षाओं को राष्ट्रीय एकता के साथ संतुलित करना और उन क्षेत्रों के लोगों में विश्वास की भावना पैदा करना था।

112. (B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु ने आंध्र क्षेत्र में एक बड़ा जन-आंदोलन और हिंसक स्थितियाँ पैदा कर दी थीं। हालाँकि केंद्र सरकार ने इसके बाद आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा की, लेकिन 'कारण' (R) 'अभिकथन' (A) की सही व्याख्या नहीं है क्योंकि सरकार ने यह निर्णय तुरंत खुशी से नहीं, बल्कि बिगड़ते हालात और भारी जन-दबाव के कारण मजबूरी में लिया था। दोनों कथन स्वतंत्र रूप से सत्य हैं।

113. (B) मराठी और गुजराती
1956 के राज्य पुनर्गठन के समय बंबई को एक 'द्विभाषी राज्य' के रूप में बनाए रखा गया था। इस राज्य में मुख्य रूप से मराठी बोलने वाले और गुजराती बोलने वाले दो बड़े समुदाय शामिल थे। इन दोनों भाषाई समूहों के बीच अपने-अपने अलग राज्यों की माँग को लेकर लगातार संघर्ष चलता रहा, जिसके परिणामस्वरूप अंततः 1960 में बंबई का विभाजन कर महाराष्ट्र और गुजरात नामक दो पृथक राज्यों का निर्माण हुआ।

114. (A) इस माँग को बाद में 1966 में स्वीकार किया गया।
पंजाब में पंजाबी बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग राज्य की माँग स्वतंत्रता के बाद से ही उठने लगी थी, लेकिन सरकार ने इसे शुरु में स्वीकार नहीं किया। पंजाबी सूबा आंदोलन के लंबे संघर्ष के बाद, केंद्र सरकार ने 1966 में पंजाब का पुनर्गठन किया। इसके तहत पंजाबी भाषियों के लिए पंजाब और हिंदी भाषियों के लिए हरियाणा राज्य बनाया गया, जिससे इस भाषाई विवाद का समाधान हो सका।

115. (C) सिक्किम
मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा जैसे राज्यों का निर्माण या पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया असम और पूर्वोत्तर के पुनर्गठन से जुड़ी थी। इसके विपरीत, सिक्किम का इतिहास भिन्न है; वह 1975 में एक विशेष प्रक्रिया के तहत भारतीय संघ का हिस्सा बना था। सिक्किम पहले एक संरक्षित राज्य था और बाद में जनमत संग्रह के माध्यम से इसे भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था।

116. (D) दोनों देशों का झंडा एक साथ फहराते हुए शहर में गश्त करना।
विभाजन की भीषण हिंसा के बीच कलकत्ता में सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करने के लिए हिंदू और मुस्लिम समुदायों के युवाओं ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के झंडे एक साथ फहराते हुए शहर की सड़कों पर संयुक्त रूप से गश्त की। इस प्रतीकात्मक कार्य का उद्देश्य दंगाइयों को एकता का संदेश देना और दोनों समुदायों के बीच आपसी विश्वास और शांति को पुनः स्थापित करना था।

117. (C) संविधान सभा के एक विशेष सत्र में
जवाहरलाल नेहरु ने अपना ऐतिहासिक भाषण 'भाग्यवधू से चिर-प्रतीक्षित भेंट' (Tryst with Destiny) 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को संसद भवन में आयोजित संविधान सभा के एक विशेष सत्र के दौरान दिया था। यह संबोधन उस क्षण हुआ जब भारत आधिकारिक रूप से स्वतंत्र हो रहा था। यह भाषण केवल एक राजनीतिक वक्तव्य नहीं था, बल्कि नव-राष्ट्र की आकांक्षाओं और भविष्य के संकल्पों का एक महान दस्तावेज़ था।

118. (A) केवल 1, 2 और 3
विभाजन के बाद भी भारत में एक बड़ी मुस्लिम आबादी रह गई थी, जो सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय थी। भारतीय नेताओं ने सांप्रदायिक आधार पर बँटवारे के बावजूद एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का सपना देखा और सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए। भारत कभी भी स्वतः हिंदू राष्ट्र नहीं बना। अतः कथन 4 और 5 गलत हैं क्योंकि भारत ने अपनी धर्मनिरपेक्षता और पड़ोसी देशों के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखे थे।

119. (D) महिलाएँ बड़ी संख्या में इस आंदोलन से आ जुड़ीं।
हैदराबाद के निज़ाम और उसके रज़ाकारों के दमनकारी शासन में महिलाओं को सबसे अधिक प्रताड़ना और अपमान का सामना करना पड़ा था। इसी आक्रोश के परिणामस्वरूप, हैदराबाद और विशेष रूप से तेलंगाना क्षेत्र की महिलाएँ निज़ाम विरोधी आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में शामिल हुईं। उनकी सक्रिय भागीदारी ने इस संघर्ष को एक व्यापक सामाजिक आधार प्रदान किया और इसे केवल राजनीतिक आंदोलन के बजाय एक जन-क्रांति में बदल दिया।

120. (A) 1, 3, 4, 2
ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम में सबसे पहले 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की औपचारिक माँग की। कांग्रेस ने 'द्वि-राष्ट्र सिद्धांत' और विभाजन का पुरजोर विरोध किया। अंततः,

तहत लाना राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। उड़ीसा के इन रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलय सरदार पटेल की दूरदर्शिता और कूटनीतिक प्रयासों के कारण सफलतापूर्वक और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सका था।

78. (D) सरदार पटेल
सरदार वल्लभभाई पटेल ने रियासतों के शासकों को लिखे एक ऐतिहासिक पत्र में कहा था कि "हम भारत के इतिहास के एक यादगार मुकाम पर खड़े हैं।" उन्होंने राजाओं से अपील की थी कि वे साझा हितों और देश की अखंडता के लिए भारतीय संघ में शामिल हों। उनके इस पत्र और निरंतर प्रयासों ने राजाओं को देश की एकता के महत्व को समझने और विलय के लिए प्रेरित किया।

79. (C) केवल 1, 2, 4, 5
मणिपुर के महाराजा ने 1948 में जन-दबाव के कारण चुनाव कराए, जिससे वहाँ संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। हालाँकि, मणिपुर की विधानसभा में भारत के साथ विलय को लेकर गंभीर मतभेद थे, जिसे नजरअंदाज करते हुए भारत सरकार ने महाराजा पर विलय समझौते के लिए दबाव बनाया। अंततः सितंबर 1949 में मणिपुर का भारत में विलय संपन्न हुआ। अतः कथन 3 गलत है क्योंकि विधानसभा में विलय पर गहरा विरोध था।

80. (B) मद्रास प्रांत के मंदिर दलितों के लिए खोल दिए जाएँ।
पोट्टी श्रीरामुलु एक समर्पित गाँधीवादी नेता थे जिन्होंने केवल भाषाई राज्य के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के लिए भी संघर्ष किया था। उन्होंने मद्रास प्रांत के मंदिरों को दलितों के प्रवेश के लिए खुलवाने की माँग को लेकर भी कड़ा उपवास किया था। उनका जीवन सामाजिक सुधार और राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए समर्पित था, और उन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए अंततः अपने प्राणों की आहुति दे दी।

81. (B) मिजोरम - 1963
1956 के बाद नए राज्यों के गठन के क्रम में महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में बने और हरियाणा का गठन 1966 में हुआ। मेघालय को 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा वर्ष 1987 में प्राप्त हुआ था, न कि 1963 में। 1963 में नगालैंड का गठन हुआ था। अतः मिजोरम वाला विकल्प ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर पूरी तरह गलत है।

82. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
भाषावार राज्यों के पुनर्गठन ने भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति को मौलिक रूप से बदल दिया। पहले राजनीति पर केवल अंग्रेजी बोलने वाले अभिजात वर्ग का दबदबा था, लेकिन भाषाई राज्यों के बनने के बाद क्षेत्रीय भाषाओं में राजनीति करने वाले स्थानीय नेताओं का महत्व बढ़ा। इससे समाज के विभिन्न वर्गों की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हुई और लोकतंत्र वास्तव में अधिक समावेशी और जन-उन्मुख बनकर आम आदमी तक पहुँच सका।

83. (C) महाराष्ट्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश
भारत में राज्यों के पुनर्गठन की मांग समय-समय पर उठती रही है। वर्तमान में महाराष्ट्र के पूर्वी हिस्से को अलग कर 'विदर्भ' राज्य बनाने की मांग चल रही है। इसी प्रकार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों को मिलाकर 'हरित प्रदेश' नामक एक नए राज्य की मांग निरंतर की जा रही है। ये मांगें मुख्य रूप से आर्थिक पिछड़ेपन और बेहतर प्रशासनिक प्रबंधन की आवश्यकताओं पर आधारित होती हैं।

84. (D) उन्हें समान नागरिक अधिकार देने होंगे और उनकी रक्षा करनी होगी।
जवाहरलाल नेहरू का यह स्पष्ट और दृढ़ विचार था कि विभाजन के बाद भारत में रह गए मुसलमानों के साथ पूरा न्याय होना चाहिए। उनका मानना था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए यहाँ सभी अल्पसंख्यकों को समान नागरिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। उन्होंने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि लोकतांत्रिक सरकार का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वह उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करे।

85. (A) 2, 1, 3, 4
महात्मा गाँधी का अंतिम उपवास जनवरी 1948 में हुआ था। इसके पश्चात, मणिपुर का भारत में औपचारिक विलय सितंबर 1949 में संपन्न हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट वर्ष 1955 में सरकार को सौंपी थी। अंत में, इसी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में द्विभाषी बंबई राज्य का पुनर्गठन हुआ। यह कालक्रम भारत के प्रारंभिक राजनीतिक और प्रशासनिक विकास के विभिन्न चरणों को स्पष्ट करता है।

86. (B) दो समुदायों के हिंसक अलगाव और उससे उत्पन्न मानवीय त्रासदी हेतु।
विभाजन के समय "दिल के दो टुकड़े हो जाना" मुहावरे का प्रयोग केवल भौगोलिक बँटवारे के लिए नहीं, बल्कि सदियों से साथ रह रहे हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच पैदा हुई नफरत और हिंसा के लिए किया गया था। यह मुहावरे उस मानवीय पीड़ा, रिश्तों के टूटने और सांस्कृतिक साझा विरासत के नष्ट होने की गहरी त्रासदी को व्यक्त करता है, जो विभाजन के कारण लोगों ने व्यक्तिगत स्तर पर झेली थी।

87. (D) क्योंकि यहाँ अलग-अलग बोली, संस्कृति और धर्मों के अनुयायी थे।
स्वतंत्रता के समय दुनिया भर के पर्यवेक्षकों को संदेह था कि भारत अपनी अत्यधिक भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधताओं के कारण एक राष्ट्र के रूप में टिक पाएगा। उन्हें लगता था कि इतनी अधिक भिन्नताओं वाले देश में आंतरिक संघर्ष होंगे और वह जल्द ही बिखर जाएगा। हालांकि, भारतीय लोकतंत्र और संविधान ने इन सभी विविधताओं को समायोजित कर इस आशंका को पूरी तरह गलत साबित कर दिखाया है।

88. (D) उपरोक्त सभी
लोकतंत्र की स्थापना के लिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार मिला है। भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को

131. (A) P-3, Q-1, R-4, S-2
राष्ट्रीय एकता की चुनौती का समाधान विविधताओं को समायोजित करने में निहित था। लोकतंत्र की स्थापना हेतु मौलिक अधिकारों और चुनाव की व्यवस्था की गई। समावेशी विकास के लक्ष्यों को राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। देसी रियासतों के जटिल विलय कार्य में सरदार वल्लभभाई पटेल ने अपनी ऐतिहासिक और निर्णायक भूमिका निभाई थी। ये सभी तत्व मिलकर आधुनिक भारतीय राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला रखते हैं।

132. (D) 56 दिनों की भूख-हड़ताल के बाद मृत्यु।
पोट्टी श्रीरामुलु ने अलग आंध्र राज्य की माँग को लेकर दिसंबर 1952 में आमरण अनशन किया था। उनकी यह भूख-हड़ताल लगातार 56 दिनों तक चली, जिसके अंत में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी इस शहादत ने आंध्र क्षेत्र में एक अभूतपूर्व जन-उबाल पैदा कर दिया, जिसके कारण केंद्र सरकार को मजबूर होकर भाषाई आधार पर पहले राज्य के गठन की घोषणा करनी पड़ी। उनकी मृत्यु भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी।

133. (A) केवल 1, 2 और 3
राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की सिफारिश की, जिसे 1956 के अधिनियम द्वारा लागू किया गया। इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र-शासित प्रदेश बनाए गए। हालांकि, राज्यों के गठन की प्रक्रिया 1956 में ही समाप्त नहीं हुई, बल्कि बाद में भी कई नए राज्य बने। अतः कथन 4 और 5 गलत हैं क्योंकि यह अधिनियम 1956 में लागू हुआ था और इसके बाद भी राज्य बने।

134. (B) फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, विभाजन की सुबह
ये प्रसिद्ध काव्य पंक्तियाँ महान शायर फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की नज़्म 'सुब्ह-ए-आज़ादी' से ली गई हैं। उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से 15 अगस्त 1947 की उस सुबह का चित्रण किया है जो आज़ादी तो लाई थी, लेकिन विभाजन की त्रासदी से दाग़दार थी। फ़ैज़ के अनुसार, यह वह सुबह नहीं थी जिसका सपना स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, क्योंकि इसमें मानवीय संवेदनाओं का भारी नुकसान हुआ था।

135. (D) क्षेत्रीय भाषाओं का ज़ोर बढ़ने से हिंदुस्तानी का महत्व कम होना।
महात्मा गाँधी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के समर्थक तो थे, लेकिन उन्हें एक संभावित नकारात्मक प्रभाव का भी डर था। उनका मानना था कि यदि क्षेत्रीय भाषाओं पर बहुत अधिक बल दिया गया, तो इससे संपर्क भाषा के रूप में 'हिंदुस्तानी' का महत्व कम हो सकता है। उन्हें आशंका थी कि भाषाई प्रादेशिकता राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक साझा भाषाई माध्यम को कमजोर कर सकती है, जो राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक था।

136. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
भारत में राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया 1956 के अधिनियम के बाद भी निरंतर जारी रही। समय के साथ केवल भाषा ही नहीं, बल्कि विशिष्ट क्षेत्रीय संस्कृति और आर्थिक विकास में व्याप्त क्षेत्रीय असंतुलन भी नए राज्यों की माँग का मुख्य आधार बने। इसी कारण वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों का गठन हुआ। यह दर्शाता है कि भारतीय संघ का ढाँचा गतिशील और जन-आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी है।

137. (C) राज्य का धर्म या जाति से कोई लेना-देना नहीं होगा।
11 अगस्त 1947 को कराची में दिए गए अपने ऐतिहासिक भाषण में मुहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को एक आधुनिक और समावेशी राष्ट्र बनाने का संदेश दिया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि पाकिस्तान में सभी नागरिक समान होंगे और राज्य का किसी व्यक्ति के धर्म या जाति से कोई संबंध नहीं होगा। उनके अनुसार, मंदिर या मस्जिद जाने के लिए हर नागरिक पूरी तरह स्वतंत्र होगा और सभी समान नागरिक होंगे।

138. (A) चुनौती यह थी कि संविधान सम्मत लोकतांत्रिक व्यवहार चलन में आएँ।
लोकतंत्र की स्थापना के लिए केवल एक अच्छा लिखित संविधान होना ही पर्याप्त नहीं था। मुख्य चुनौती यह थी कि संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को समाज के व्यवहार और राजनीतिक संस्कृति में गहराई से उतारा जाए। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में लोकतांत्रिक परंपराओं को विकसित करना, नियमित चुनाव कराना और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना एक निरंतर चलने वाली अत्यंत जटिल और कठिन प्रक्रिया थी, जो केवल दस्तावेज़ों से संभव नहीं थी।

139. (D) भारत का स्वतः एक हिंदू राष्ट्र बन जाना।
विभाजन के परिणामों में 80 लाख लोगों का भारी विस्थापन और लाखों की संख्या में हुई मृत्यु अत्यंत दुखद थी। सरकारी संपत्तियों, यहाँ तक कि पुलिस के वाद्ययंत्रों और मेज-कुर्सियों का भी बँटवारा हुआ। हालांकि, विभाजन के बावजूद भारत कभी भी स्वतः एक हिंदू राष्ट्र नहीं बना। इसके विपरीत, भारतीय नेतृत्व ने पूरी दृढ़ता के साथ एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की नींव रखी, जहाँ सभी धर्मों को समान संवैधानिक अधिकार और सम्मान प्राप्त है।

140. (D) उपरोक्त सभी
हैदराबाद में निज़ाम के विरुद्ध चला आंदोलन एक व्यापक जन-आंदोलन था। तेलंगाना के किसान और भारी संख्या में महिलाएँ निज़ाम के दमनकारी शासन के खिलाफ एकजुट हुई थीं। हैदराबाद शहर इस विद्रोह का मुख्य केंद्र बन गया था। कम्युनिस्टों और हैदराबाद कांग्रेस ने मिलकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह आंदोलन न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए था, बल्कि सामाजिक न्याय और निरंकुश शासन के अंत के लिए भी एक बड़ा संघर्ष था।

141. (A) P-4, Q-3, R-2, S-1
14-15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन और स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गाँधी की शहादत हुई। दिसंबर 1952 में प्रधानमंत्री नेहरू ने अलग आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा की। अंततः, वर्ष 1956 में राज्य

पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, जिसने देश के मानचित्र को भाषाई आधार पर पुनर्व्यवस्थित किया। यह कालक्रम स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक और अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रमों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

142. (D) पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत
पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत के निर्विवाद नेता खान अब्दुल गफ्फार खान 'द्वि-राष्ट्र सिद्धांत' के प्रबल विरोधी थे, फिर भी राजनीतिक विवशताओं के कारण उस क्षेत्र को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। इस निर्णय के समय वहाँ की जनता की वास्तविक इच्छा को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। यह विभाजन की प्रक्रिया का एक विवादास्पद पक्ष है, जहाँ एक महान राष्ट्रवादी नेता की आवाज़ को सांप्रदायिक राजनीति के शोर में अनसुना कर दिया गया था।

143. (A) विभिन्न समूहों के बीच एकता कायम करनी पड़ी।
भारत और सोवियत संघ दोनों ही भौगोलिक रूप से विशाल और सांस्कृतिक रुप से अत्यधिक विविधतापूर्ण क्षेत्र थे। राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया में दोनों के सामने सबसे बड़ी समानता यह थी कि उन्हें विभिन्न भाषाई, धार्मिक और जातीय समूहों के बीच एकता और तालमेल स्थापित करना पड़ा। हालाँकि दोनों देशों ने इसके लिए अलग-अलग राजनीतिक प्रणालियों और रास्तों को अपनाया, लेकिन विविधताओं को एक सूत्र में पिरोने की चुनौती दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण थी।

144. (B) केवल 1, 2 और 3
स्वतंत्र भारत के सामने मुख्य रूप से तीन चुनौतियाँ थीं: राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करना, लोकतंत्र को व्यावहारिक रुप में स्थापित करना और समूचे समाज के कल्याण के लिए समावेशी विकास करना। सैन्य विस्तार उस समय की तात्कालिक प्राथमिक चुनौती नहीं थी, बल्कि राष्ट्र के आंतरिक सुदृढ़ीकरण और लोकतांत्रिक ढाँचे को मजबूत करना सबसे अधिक आवश्यक था। अतः कथन 4 गलत है क्योंकि मुख्य ध्यान सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता पर था।

145. (B) जवाहरलाल नेहरू
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु ने भारत की सामाजिक वास्तविकता को समझते हुए यह महत्वपूर्ण कथन कहा था। उनका मानना था कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की संख्या इतनी विशाल है कि उन्हें राष्ट्र से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ सभी नागरिकों को, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करना राज्य का अनिवार्य नैतिक और संवैधानिक दायित्व है।

146. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
देसी रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलय वास्तव में एक अत्यंत जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य था। ब्रिटिश सरकार की घोषणा के बाद त्रावणकोर, हैदराबाद और भोपाल जैसी रियासतों के शासकों ने स्वतंत्र रहने की इच्छा जताई, जिससे भारत के भौगोलिक विखंडन का वास्तविक खतरा पैदा हो गया था। यदि इन रियासतों को सफलतापूर्वक एकजुट नहीं किया जाता, तो भारत कई छोटे-छोटे प्रतिस्पर्धी टुकड़ों में बँट जाता, जिससे उसकी एकता समाप्त हो जाती।

147. (C) मणिपुर
मणिपुर भारत का वह पहला ऐतिहासिक भाग है जहाँ जून 1948 में सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर लोकतांत्रिक चुनाव संपन्न कराए गए थे। इन चुनावों के माध्यम से गठित विधानसभा के साथ मणिपुर में एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। यह घटना भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने पूरे देश के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकतांत्रिक सरकार के गठन का एक सफल प्रारंभिक उदाहरण प्रस्तुत किया था।

148. (D) राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना।
वर्ष 1953 में स्थापित राज्य पुनर्गठन आयोग का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण कार्य भारत के राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के जटिल मामले की जाँच करना था। आयोग को यह तय करना था कि राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाए ताकि क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन बना रहे। आयोग ने अंततः यह सिफारिश की कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण मुख्य रूप से भाषाई आधार पर ही किया जाना चाहिए।

149. (A) 4, 2, 1, 3
भारत में राज्यों के गठन का क्रम इस प्रकार है: सबसे पहले 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बने। इसके बाद 1972 में मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों का निर्माण हुआ। अंत में, जून 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। यह क्रम दर्शाता है कि भारत में राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया समय और आवश्यकता के अनुसार निरंतर विकसित होती रही है।

150. (B) इससे देश की एकता और ज़्यादा मज़बूत हुई।
भाषावार राज्यों के पुनर्गठन ने देश की एकता को कमजोर करने के बजाय उसे और अधिक सुदृढ़ बनाया। इस प्रक्रिया ने विभिन्न भाषाई समूहों की क्षेत्रीय पहचान और आकांक्षाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की, जिससे उनमें अलगाववाद की भावना कम हुई। जब लोगों को अपनी भाषा और संस्कृति के फलने-फूलने का अवसर मिला, तो उनका भारतीय राष्ट्र के प्रति विश्वास और जुड़ाव और गहरा हुआ, जिससे भारत एक सशक्त और अखंड राष्ट्र बनकर उभरा।

151. (B) एक धर्मनिरपेक्ष राज्य
स्वतंत्र भारत के नेतृत्व ने विभाजन के बाद धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श अपनाया। यह निर्णय केवल दार्शनिक नहीं, बल्कि राजनीतिक आवश्यकता भी था। भारत में बड़ी मुस्लिम आबादी की मौजूदगी के कारण, एक धर्म-आधारित राष्ट्र एकता के लिए खतरा हो सकता था। धर्मनिरपेक्षता ने सभी नागरिकों को, उनके धर्म की परवाह किए बिना, समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करने का मार्ग बनाया।

152. (A) क्योंकि भारत में एक बड़ी मुस्लिम अल्पसंख्यक आबादी बनी रही थी।
विभाजन के बाद भारत में बड़ी संख्या में मुस्लिम अल्पसंख्यक आबादी रह गई थी। ऐसे में देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए धर्मनिरपेक्षता एक अनिवार्य राजनीतिक विकल्प बन गया था। यदि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनता, तो यह अल्पसंख्यकों में भय पैदा करता और राष्ट्र-निर्माण में बाधा डालता, जिससे आंतरिक संघर्ष और विभाजन की संभावना और अधिक बढ़ जाती।

153. (C) यह राज्य द्वारा सभी धर्मों से सैद्धांतिक दूरी बनाए रखने पर आधारित है।
भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल पश्चिमी मॉडल से अलग है क्योंकि यह राज्य और धर्म के पूर्ण अलगाव के बजाय सभी धर्मों से समान सैद्धांतिक दूरी बनाए रखने पर जोर देता है। इसमें राज्य सभी धर्मों का सम्मान करता है और आवश्यकतानुसार हस्तक्षेप भी कर सकता है। यह मॉडल सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी एक धर्म को प्राथमिकता न देकर सभी को समान अवसर दे।

154. (D) अनुच्छेद 25 से 28
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में स्थापित किया गया है। ये अनुच्छेद नागरिकों को अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देते हैं। ये संवैधानिक प्रावधान भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को संस्थागत रूप प्रदान करते हैं, जिससे राष्ट्र की लोकतांत्रिक और समावेशी नींव हमेशा मजबूत बनी रहती है।

155. (C) धर्मनिरपेक्षता भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एक रणनीतिक विकल्प था।
धर्मनिरपेक्षता भारत की विविधता को संजोने और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए एक रणनीतिक विकल्प था। यह केवल एक नैतिक सिद्धांत नहीं, बल्कि विभाजन की भयावह हिंसा के बाद समाज को जोड़ने का जरिया था। इसने अल्पसंख्यकों को सुरक्षा का अहसास दिलाया और एक ऐसे समावेशी राष्ट्र का निर्माण किया जहाँ सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान दर्जा मिले।

156. (B) सरदार वल्लभभाई पटेल और वी.पी. मेनन
भारत में रियासतों के एकीकरण का मुख्य श्रेय सरदार वल्लभभाई पटेल और वी.पी. मेनन को दिया जाता है। पटेल के दृढ़ नेतृत्व और मेनन की प्रशासनिक कुशलता ने 565 रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए राजी किया। उन्होंने कूटनीतिक कौशल और रणनीतिक दबाव का उपयोग करते हुए भारत को विखंडन से बचाया और एक सुदृढ़ तथा एकीकृत राजनीतिक मानचित्र निर्मित किया।

157. (D) रक्षा, विदेशी मामले और संचार
'इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन' एक कानूनी दस्तावेज था जिस पर हस्ताक्षर करके रियासतों ने स्वेच्छा से भारतीय संघ में शामिल होना स्वीकार किया। इसके तहत, रियासतों ने रक्षा, विदेशी मामले और संचार जैसे तीन महत्वपूर्ण विषयों का नियंत्रण भारत सरकार को सौंप दिया। बदले में, उन्हें अपनी आंतरिक स्वायत्तता बनाए रखने की अनुमति मिली, जिससे प्रारंभिक एकीकरण की प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रही।

158. (A) 'प्रिवी पर्स' और अन्य विशेषाधिकार
रियासतों के शासकों को भारतीय संघ में विलय के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 'प्रिवी पर्स' का आश्वासन दिया गया था। यह एक निश्चित सरकारी भत्ता था जो उन्हें अपने राजसी जीवन स्तर और विशेषाधिकारों को बनाए रखने के लिए दिया जाता था। इस आर्थिक सुरक्षा और सम्मान के वादे ने कई शासकों को अपनी संप्रभुता छोड़कर लोकतांत्रिक भारत का हिस्सा बनने हेतु राजी किया।

159. (C) क्योंकि शासक स्वतंत्र रहना चाहता था और अपनी प्रजा की इच्छाओं का दमन कर रहा था।
हैदराबाद का शासक स्वतंत्र रहना चाहता था और उसने भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही, निज़ाम के शासन के दौरान प्रजा पर अत्याचार हो रहे थे। क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने और जनता की लोकतांत्रिक इच्छाओं का समर्थन करने के लिए भारत सरकार को सैन्य हस्तक्षेप करना पड़ा। 'ऑपरेशन पोलो' के माध्यम से अंततः हैदराबाद का भारत में विलय हुआ।

160. (A) पटेल और मेनन की रणनीति ने भारत को संभावित विखंडन से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
पटेल और मेनन की कुशल रणनीति ने स्वतंत्र भारत को संभावित बिखरने से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रियासतों का विलय केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं था, बल्कि एक चुनौतीपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि थी। इसने देश की सीमाओं को भौगोलिक रूप से सुरक्षित किया और एक अखंड भारत की नींव रखी, जो भविष्य के विकास और राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक थी।

161. (D) गहरा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक-सांस्कृतिक घाव
विभाजन ने सीमाओं को बदलने के साथ लाखों लोगों के जीवन पर गहरा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक-सांस्कृतिक घाव छोड़ा। यह त्रासदी केवल आँकड़ों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें अपनी जड़ों से उखड़ने और पहचान खोने का असीम दर्द शामिल था। इसने परिवारों को अलग कर दिया और समुदायों के बीच अविश्वास की ऐसी खाई पैदा की, जिसका असर दक्षिण एशिया में आज भी है।

162. (B) क्योंकि उन्हें 'समुदाय के सम्मान' का प्रतीक माना जाता था।
विभाजन की हिंसा के दौरान महिलाओं को 'समुदाय के सम्मान' का प्रतीक मानकर विशेष रूप से निशाना बनाया गया। उन पर किए गए अत्याचारों, जैसे अपहरण और बलात्कार, का उद्देश्य दूसरे समुदाय को मानसिक रूप से नीचा दिखाना था। महिलाओं के खिलाफ यह क्रूरता इस त्रासदी का सबसे अमानवीय पक्ष था, जिसने दिखाया कि कैसे सांप्रदायिक संघर्षों में महिलाओं के शरीर को हथियार बनाया गया।

बिगड़ती सांप्रदायिक स्थितियों और राजनीतिक गतिरोध के कारण ब्रिटिश शासन ने पाकिस्तान की माँग को स्वीकार कर लिया। इसके परिणामस्वरुप 1947 में भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ। यह क्रम विभाजन की राजनीतिक प्रक्रिया को स्पष्ट करता है।

121. (B) P-4, Q-3, R-2, S-1
हैदराबाद का विलय रज़ाकारों के दमन के बाद भारतीय सेना की सैन्य कार्रवाई के माध्यम से हुआ। मणिपुर का विलय महाराजा बोधचंद्र सिंह के साथ हुए समझौते के बाद संपन्न हुआ। जूनागढ़ का विलय वहाँ की जनता के बीच कराए गए एक लोकतांत्रिक जनमत संग्रह के आधार पर किया गया। आंध्र आंदोलन का नेतृत्व महान गाँधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु ने किया था, जिन्होंने अलग राज्य के लिए अपने प्राण त्याग दिए।

122. (A) एक लचीला रुख, जैसे जम्मू-कश्मीर को स्वायत्तता देना।
भारत सरकार ने देसी रियासतों के एकीकरण के समय अत्यंत संवेदनशीलता और लचीलेपन का परिचय दिया। सरकार का मुख्य उद्देश्य देश की एकता बनाए रखना था, जिसके लिए उसने विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट मांगों और सांस्कृतिक पहचान को महत्व दिया। जम्मू-कश्मीर को स्वायत्तता देना इसी लचीले दृष्टिकोण का हिस्सा था, ताकि वहां के लोगों की विशिष्ट पहचान को सुरक्षित रखते हुए उन्हें भारतीय संघ का अभिन्न हिस्सा बनाया जा सके।

123. (D) कैफ़ी आज़मी
1973 की कालजयी फिल्म 'गर्म हवा' विभाजन की मानवीय त्रासदी पर आधारित है। इस फिल्म का पटकथा लेखन और संवाद प्रसिद्ध शायर कैफ़ी आज़मी ने किया था, जो खुद इस्मत चुगताई की एक अप्रकाशित कहानी पर आधारित थी। यह फिल्म विभाजन के बाद भारत में रहने का कठिन फैसला करने वाले एक मुस्लिम परिवार की असुरक्षा और उनके आर्थिक संघर्षों का अत्यंत मार्मिक और यथार्थवादी चित्रण करती है।

124. (B) महात्मा गाँधी ने सत्ता संभालने वाले नेताओं के लिए।
महात्मा गाँधी ने आज़ादी के समय सत्ता संभालने वाले नेताओं को सचेत करते हुए कहा था कि उन्होंने अपने सिर पर काँटों का ताज पहना है। गाँधीजी का आशय यह था कि आज़ादी के साथ जो बड़ी जिम्मेदारियाँ और चुनौतियाँ आई हैं, वे अत्यंत कठिन हैं। उनके लिए आज़ादी का अर्थ विलासिता नहीं, बल्कि करोड़ों गरीबों की सेवा और देश में व्याप्त सांप्रदायिक नफरत को खत्म करने का एक अत्यंत दुष्कर मार्ग था।

125. (C) भाषाई राज्य की माँग को लेकर लोगों का नेतृत्व के विरुद्ध आंदोलन।
भाषाई राज्यों के पुनर्गठन की घटना यह स्पष्ट करती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शीर्ष नेतृत्व हमेशा अपनी इच्छा जनता पर नहीं थोप सकता। हालाँकि नेहरु और पटेल जैसे बड़े नेता शुरु में भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण के खिलाफ थे, लेकिन जनता के तीव्र आंदोलनों और भारी दबाव के कारण उन्हें अपनी नीति बदलनी पड़ी। यह भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता और जन-आकांक्षाओं के प्रति उसकी संवेदनशीलता का एक सशक्त प्रमाण है।

126. (C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
विभाजन के भीषण सांप्रदायिक माहौल के बावजूद भारतीय नेतृत्व ने धर्मनिरपेक्षता के महान आदर्श को पूरी दृढ़ता से बनाए रखा। यह कहना कि 1951 में भारत में कोई मुस्लिम आबादी नहीं बची थी, पूरी तरह गलत है, क्योंकि उस समय भी भारत की कुल आबादी का लगभग 12 प्रतिशत हिस्सा मुसलमानों का था। भारत ने एक समावेशी राष्ट्र के रुप में सभी धर्मों को समान सम्मान और अधिकार देने का मार्ग चुना।

127. (D) उपरोक्त सभी
आज़ादी के बाद राज्यों की आंतरिक सीमाओं का पुनर्निर्धारण राष्ट्र निर्माण की एक प्रमुख चुनौती थी। ब्रिटिश काल के प्रांत केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाए गए थे, जिनका कोई भाषाई आधार नहीं था। कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में ही भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वादा किया था। अतः स्वतंत्रता के बाद इस वादे को पूरा करने का भारी जन-दबाव सरकार पर था, जो लोकतंत्र के लिए अनिवार्य था।

128. (B) महीनों और सालों तक किसी शरणार्थी शिविर में जीवन काटना।
विभाजन की त्रासदी झेलने वाले लाखों विस्थापित लोगों के लिए आज़ादी का अनुभव अत्यंत कड़वा और कष्टकारी था। उनके लिए आज़ादी का अर्थ अपना घर-बार खोना और बेगाना होकर शरणार्थी शिविरों की नारकीय स्थितियों में समय बिताना था। वे लोग जो कल तक जमींदार या समृद्ध थे, अचानक एक रोटी के लिए मोहताज हो गए। उनके लिए नए राष्ट्र का जन्म व्यक्तिगत तबाही और अंतहीन मानवीय पीड़ा की एक भयानक दास्तां बन गया था।

129. (C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
विभाजन की विभीषिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के साहित्यकारों, कवियों और फिल्मकारों को गहरे तक झकझोर दिया था। उन्होंने अपनी रचनाओं में मार-काट, विस्थापन और मानवीय संवेदनाओं के खत्म होने के दुख को बहुत प्रभावी ढंग से व्यक्त किया है। यह कहना गलत है कि उन्होंने इस त्रासदी को दर्शाने से परहेज किया; वास्तव में, उन्होंने अपनी कला के माध्यम से विभाजन के उस दर्द को अमर कर दिया है।

130. (A) राजाओं को यह अधिकार मिला कि वे चाहें तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखें।
ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि भारत की स्वतंत्रता के साथ ही रजवाड़ों पर से अंग्रेजों की सर्वोच्च सत्ता समाप्त हो जाएगी और वे स्वतंत्र हो जाएंगे। रजवाड़ों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या पूरी तरह स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया था। इस प्रावधान ने भारत के विखंडन का गंभीर खतरा पैदा कर दिया था, क्योंकि इससे देश के भीतर कई छोटे-छोटे स्वतंत्र देश बन सकते थे।

गई थी। इस संस्था का कार्य देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएँ तैयार करना था। इसने सरकार को एक ठोस दिशा प्रदान की जिससे गरीबी कम करने और औद्योगिक आधार मजबूत करने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से चलाया गया।

175. (C) सामाजिक और आर्थिक न्याय के साथ विकास सुनिश्चित करने की चुनौती
नियोजित विकास की रणनीति राष्ट्र-निर्माण की उस चुनौती का उत्तर थी जिसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय के साथ विकास सुनिश्चित करना था। इसका उद्देश्य उत्पादन बढ़ाने के साथ जनता का जीवन स्तर सुधारना और असमानता कम करना था। इस रणनीति ने एक कल्याणकारी राज्य की नींव रखी जहाँ आर्थिक प्रगति का लाभ समाज के हर वर्ग तक आसानी से पहुँच सके।

ही नाम शामिल थे।
(D) मतदाता सूची पूरी तरह से खाली थी और उस पर कोई नाम दर्ज नहीं था।

18. "इतिहास का सबसे बड़ा जुआ" यह टिप्पणी किस संदर्भ में एक हिंदुस्तानी संपादक द्वारा की गई थी?
(A) भारत में सार्वभौम मताधिकार के प्रयोग के संदर्भ में।
(B) भारत के विभाजन के संदर्भ में।
(C) रियासतों के विलय के संदर्भ में।
(D) संविधान निर्माण के संदर्भ में।

19. भारतीय जनसंघ के संस्थापक-अध्यक्ष कौन थे?
(A) दीनदयाल उपाध्याय
(B) बलराज मधोक
(C) श्यामा प्रसाद मुखर्जी
(D) अटल बिहारी वाजपेयी

20. कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. कांग्रेस को स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी।
2. जवाहरलाल नेहरु जैसे करिश्माई नेता इसके अगुवा थे।
3. उस समय यह एकमात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था।
4. विपक्षी दलों का न होना इसके प्रभुत्व का एक कारण था।
5. कांग्रेस ने पहले तीन चुनावों में सैन्य बल का प्रयोग किया।

दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 1, 2, 4 और 5
(C) केवल 3, 4 और 5
(D) सभी 1, 2, 3, 4 और 5

21. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): कांग्रेस के सतरंगे स्वभाव ने उसे एक असाधारण ताकत दी।
कारण (R): गठबंधनी स्वभाव के कारण कांग्रेस अतिवादी रुख अपनाने से बचती थी और हर मसले पर संतुलन साधकर चलती थी।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

22. 1952 के पहले आम चुनाव में लोकसभा की 489 सीटों में से कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थीं?
(A) 266
(B) 364
(C) 401
(D) 189

23. निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (दल)
P. कांग्रेस
Q. सोशलिस्ट पार्टी
R. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
S. भारतीय जनसंघ

सूची II: (चुनाव चिह्न)
1. हलधर किसान
2. दीपक
3. दो बैलों की जोड़ी
4. बरगद का पेड़

कूट:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

24. निम्नलिखित में से कौन सा कथन 'कांग्रेस प्रणाली' (Congress System) की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है?
(A) वह कालखंड जिसमें कांग्रेस ने शासक दल और विपक्ष दोनों की भूमिका निभाई।
(B) केवल कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व।
(C) वह प्रणाली जिसमें कांग्रेस ने सभी चुनाव जीते।
(D) वह प्रणाली जिसमें सभी विपक्षी दल कांग्रेस में शामिल हो गए।

25. राजनीतिक घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. भारतीय जनसंघ का गठन
2. सोशलिस्ट पार्टी का कांग्रेस से अलग होना
3. केरल में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार का गठन
4. कम्युनिस्ट पार्टी का CPI और CPI(M) में विभाजन

(A) 2, 1, 3, 4
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 3, 1, 4
(D) 3, 4, 1, 2

26. कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ?
(A) 1934
(B) 1948
(C) 1951
(D) 1925

27. पहले आम चुनाव में मतदान के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई थी?
(A) एक ही मतपत्र पर सभी उम्मीदवारों के नाम और चिह्न।

4. केरल में कम्युनिस्ट सरकार की बर्खास्तगी
(A) 1, 2, 3, 4
(B) 2, 1, 3, 4
(C) 2, 3, 1, 4
(D) 1, 3, 2, 4

10. सोशलिस्ट पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में कांग्रेस के भीतर हुआ था।
2. 1948 में समाजवादियों ने कांग्रेस से अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बनाई।
3. पार्टी लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में विश्वास करती थी।
4. जयप्रकाश नारायण और राममनोहर लोहिया इसके प्रमुख नेता थे।
5. इसने पहले तीन चुनावों में कांग्रेस को कड़ी टक्कर देते हुए बहुमत हासिल किया।

दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 1, 2, 3 और 4
(C) केवल 3, 4 और 5
(D) सभी 1, 2, 3, 4 और 5

11. 1952 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को लगभग 45 प्रतिशत वोट मिले, लेकिन उसने लगभग 74 प्रतिशत सीटें जीतीं। इसका मुख्य कारण क्या था?
(A) विपक्षी दलों ने एकजुट होकर चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार किया।
(B) मतदाताओं की अत्यधिक निरक्षरता और राजनीतिक जागरुकता की कमी।
(C) चुनाव आयोग द्वारा सत्ताधारी दल के प्रति अपनाया गया पक्षपाती रवैया।
(D) 'सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत' वाली विशिष्ट चुनाव प्रणाली।

12. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): भारतीय जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके 'अखंड भारत' बनाने की बात कही।
कारण (R): जनसंघ का मानना था कि देश भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

13. स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन थीं?
(A) सरोजिनी नायडू
(B) विजयलक्ष्मी पंडित
(C) राजकुमारी अमृत कौर
(D) सुचेता कृपलानी

14. निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (नेता)
P. श्यामा प्रसाद मुखर्जी
Q. मीनू मसानी
R. एस.ए. डांगे
S. अशोक मेहता
सूची II: (दल)
1. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
2. प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
3. स्वतंत्र पार्टी
4. भारतीय जनसंघ
कूट:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-3, R-1, S-2
(C) P-2, Q-1, R-4, S-3
(D) P-3, Q-4, R-2, S-1

15. कांग्रेस पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसकी स्थापना 1885 में हुई थी।
2. इसने अपने अंदर विभिन्न विचारधाराओं (गरमपंथी, नरमपंथी, वामपंथी, दक्षिणपंथी) को समाहित किया।
3. पार्टी के अंदर मौजूद विभिन्न समूहों को गुट कहा जाता था।
4. आजादी के बाद के शुरुआती दशकों में यह एक सतरंगे सामाजिक गठबंधन की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी।

उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं?
(A) केवल 1 और 4
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) 1, 2, 3 और 4

16. किस अनुच्छेद का प्रयोग करके 1959 में केंद्र सरकार ने केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त किया था?
(A) अनुच्छेद 352
(B) अनुच्छेद 356
(C) अनुच्छेद 360
(D) अनुच्छेद 370

17. पहले आम चुनाव में मतदाता सूचियों के पहले प्रारुप में क्या समस्या सामने आई थी?
(A) अधिकांश मतदाताओं की जन्मतिथि और आयु संबंधी विवरण गलत दर्ज थे।
(B) लगभग 40 लाख महिलाओं के नाम पारिवारिक रिश्तों के आधार पर दर्ज थे।
(C) मतदाता सूची में केवल पुरुषों और शिक्षित नागरिकों के

अध्याय 09

एक दल के प्रभुत्व का दौर

1. भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे?
(A) जवाहरलाल नेहरू
(B) सुकुमार सेन
(C) डॉ. बी.आर. अंबेडकर
(D) श्यामा प्रसाद मुखर्जी

2. स्वतंत्रता के बाद भारत ने कौन सी शासन प्रणाली अपनाई?
(A) लोकतांत्रिक शासन
(B) राजतंत्र
(C) सैन्य शासन
(D) अलोकतांत्रिक शासन

3. निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (दल)
P. भारतीय जनसंघ
Q. सोशलिस्ट पार्टी
R. कम्युनिस्ट पार्टी
S. कांग्रेस
सूची II: (विचारधारा)
1. लोकतांत्रिक समाजवाद
2. सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन
3. एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र
4. तेलंगाना में हिंसक विद्रोह का समर्थन
कूट:
(A) P-3, Q-1, R-4, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-3, R-2, S-1
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

4. पहले आम चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है?
(A) चुनाव 1951 के अक्तूबर से 1952 के फरवरी तक हुए।
(B) इस चुनाव में मतदाताओं में केवल 15 फीसदी साक्षर थे।
(C) चुनाव में औसतन हर सीट के लिए चार उम्मीदवार थे।
(D) चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का उपयोग हुआ।

5. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): शुरुआती वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने शासक दल की भूमिका भी निभाई और विपक्ष की भी।
कारण (R): कांग्रेस की गठबंधनी प्रकृति के कारण, विभिन्न गुटों को पार्टी के भीतर ही अपने मतभेदों को सुलझाने का अवसर मिला, जो एक विपक्षी भूमिका जैसा था।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

6. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसकी स्थापना 1920 के दशक में हुई थी।
2. यह पार्टी रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थी।
3. 1951 में पार्टी ने हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ दिया।
4. 1957 में इसने केरल में सरकार बनाई।
उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2, 3 और 4
(C) केवल 1, 3 और 4
(D) 1, 2, 3 और 4

7. भारत में एक-दलीय प्रभुत्व और अन्य देशों (जैसे चीन) में एक-दलीय प्रभुत्व के बीच मुख्य अंतर क्या था?
(A) भारत में केवल एक दल को शासन करने की कानूनी अनुमति प्राप्त थी।
(B) भारत में प्रभुत्व सैन्य शक्ति और तानाशाही उपायों से स्थापित हुआ।
(C) भारत में किसी भी प्रभावी विपक्षी दल का पूर्णतः अभाव बना रहा।
(D) भारत में प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थितियों के अंतर्गत ही कायम हुआ।

8. निम्नलिखित में से कौन 1957 में केरल के मुख्यमंत्री बने?
(A) ई.एम.एस. नंबूदरीपाद
(B) ए.के. गोपालन
(C) एस.ए. डांगे
(D) पी. सुंदरैया

9. निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. भारतीय चुनाव आयोग का गठन
2. भारत के संविधान पर हस्ताक्षर
3. पहले आम चुनाव का आयोजन

(B) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM)।
(C) ऑनलाइन मतदान।
(D) प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक अलग मतपेटी।

28. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
2. भारत के चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 में हुआ।
3. पहले आम चुनाव 1950 में ही संपन्न हो गए थे।
4. पहले आम चुनाव में 17 करोड़ मतदाता थे।

उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं?
(A) केवल 1, 2 और 4
(B) केवल 1 और 3
(C) केवल 2 और 4
(D) 1, 2, 3 और 4

29. डॉ. भीमराव अंबेडकर ने किस मुद्दे पर असहमति के कारण 1951 में नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था?
(A) कश्मीर नीति
(B) विदेश नीति
(C) हिंदू कोड बिल
(D) आर्थिक नीति

30. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): 1952 के चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी को 10 प्रतिशत वोट मिलने के बावजूद 3 प्रतिशत सीटें भी नहीं मिलीं।
कारण (R): गैर-कांग्रेसी वोट विभिन्न प्रतिस्पर्धी पार्टियों और उम्मीदवारों में बँट गए थे।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

31. कांग्रेस के प्रभुत्व के दौर (1952-1967) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इस पूरे दौर में केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही।
2. 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी।
3. उड़ीसा और मद्रास में भी कांग्रेस कभी सरकार नहीं बना पाई।
4. इस दौर में कांग्रेस का प्रभुत्व राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर था।
5. जम्मू और कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस का शासन था।

दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1, 2, 3 और 5
(B) केवल 1, 2, 4 और 5
(C) केवल 3, 4 और 5
(D) सभी 1, 2, 3, 4 और 5

32. 'शिडयूल्ड कास्टस् फेडरेशन' की स्थापना किसने की थी?
(A) जगजीवन राम
(B) डॉ. भीमराव अंबेडकर
(C) के. कामराज
(D) रफी अहमद किदवई

33. किस घटना के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में दो गुटों (CPI और CPI-M) में विभाजित हो गई?
(A) भारत-चीन युद्ध
(B) चीन और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक अंतर
(C) केरल सरकार की बर्खास्तगी
(D) भारत-पाकिस्तान युद्ध

34. निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (घटना)
P. पहले आम चुनाव
Q. कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन
R. भारतीय जनसंघ का गठन
S. केरल में कम्युनिस्ट सरकार की बर्खास्तगी

सूची II: (वर्ष)
1. 1951
2. 1959
3. 1952
4. 1934

कूट:
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-3, R-2, S-1
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

35. 'रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया' के गठन के योजनाकार कौन थे?
(A) जवाहरलाल नेहरु
(B) सरदार पटेल
(C) डॉ. भीमराव अंबेडकर
(D) मौलाना आजाद

36. निम्नलिखित में से कौन सा दल 1952 के पहले आम चुनाव में 16 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरा?
(A) भारतीय जनसंघ
(B) सोशलिस्ट पार्टी
(C) किसान मजदूर प्रजा पार्टी
(D) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी

37. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. सोशलिस्ट पार्टी के कई टुकड़े हुए और उनमें विलय भी हुआ।
2. किसान मजदूर प्रजा पार्टी एक समाजवादी दल था।
3. राममनोहर लोहिया ने कांग्रेस से हल्के-फुल्के सहयोग की तरफदारी की।
4. अशोक मेहता ने कांग्रेस से अपनी दूरी बढ़ाने और उसकी

(A) केवल 1, 2 और 4
(B) केवल 1, 3 और 4
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2, 3 और 4

76. निम्नलिखित में से कौन सा दल 1955 में दुविधा की स्थिति में था जब कांग्रेस ने समाजवादी बनावट वाले समाज को अपना लक्ष्य घोषित किया?
(A) भारतीय जनसंघ
(B) सोशलिस्ट पार्टी
(C) कम्युनिस्ट पार्टी
(D) स्वतंत्र पार्टी

77. 1952 के पहले आम चुनाव के परिणामों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है?
(A) कांग्रेस ने लोकसभा में 364 सीटें जीतीं।
(B) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 16 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही।
(C) सोशलिस्ट पार्टी ने दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बहुमत हासिल किया।
(D) जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने।

78. निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (दल/संगठन)
P. इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी
Q. कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी
R. भारतीय जनसंघ
S. शिडयूल्ड कास्टस् फेडरेशन
सूची II: (संस्थापक/प्रमुख व्यक्ति)
1. श्यामा प्रसाद मुखर्जी
2. डॉ. बी. आर. अंबेडकर
3. आचार्य नरेंद्र देव
4. डॉ. बी. आर. अंबेडकर
कूट:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-3, R-1, S-4
(C) P-4, Q-1, R-2, S-3
(D) P-3, Q-4, R-1, S-2

79. राजनीतिक घटनाओं के निम्नलिखित सेट को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. दूसरा आम चुनाव
2. तीसरा आम चुनाव
3. पहला आम चुनाव
4. केरल में कम्युनिस्ट सरकार का गठन
(A) 3, 4, 1, 2
(B) 3, 1, 4, 2
(C) 1, 2, 3, 4
(D) 4, 3, 1, 2

80. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच पारस्परिक सम्मान का गहरा भाव था।
कारण (R): अंतरिम सरकार में डॉ. अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी नेता भी शामिल थे।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

81. कम्युनिस्ट पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. 1935 से 1941 तक कम्युनिस्टों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में रहकर काम किया।
2. 1941 में वे नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे ब्रिटेन को समर्थन देने के लिए कांग्रेस से अलग हो गए।
3. आजादी के बाद पार्टी का मानना था कि 1947 में मिली आजादी सच्ची नहीं थी।
4. इस विचार के साथ पार्टी ने तेलंगाना में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को बढ़ावा दिया।
5. 1964 में पार्टी का विभाजन हो गया।
दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1, 2, 3 और 5
(B) केवल 1, 2, 4 और 5
(C) केवल 3, 4 और 5
(D) सभी 1, 2, 3, 4 और 5

82. कांग्रेस को 'अव्वल और एकलौता' होने का फायदा क्यों मिला?
(A) आजादी के समय तक यह पार्टी संगठनात्मक रूप से देशव्यापी हो चुकी थी।
(B) क्योंकि इस राजनीतिक दल का गठन अन्य सभी दलों के बाद हुआ था।
(C) क्योंकि इसे तत्कालीन ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार का पूर्ण समर्थन था।
(D) क्योंकि इस दल ने चुनावों के दौरान अनुचित चुनावी धांधली का सहारा लिया।

83. 'समग्र मानवतावाद' सिद्धांत के प्रणेता कौन थे?
(A) श्यामा प्रसाद मुखर्जी
(B) बलराज मधोक
(C) दीनदयाल उपाध्याय
(D) अटल बिहारी वाजपेयी

84. निम्नलिखित में से कौन एक स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, जो बौद्ध धर्म के विद्वान भी थे?
(A) जयप्रकाश नारायण

(B) विपक्षी दल केवल चुनाव के समय ही सीमित गतिविधियों में सक्रिय थे।
(C) विपक्षी दलों ने सरकार के निर्णयों का निरंतर हिंसक विरोध किया।
(D) उन्होंने शासक दल पर अंकुश रखकर लोकतांत्रिक विकल्प बनाए रखा।

47. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): आजादी से पहले के वक्त में अनेक संगठन और पार्टियों को कांग्रेस में रहने की इजाजत थी।
कारण (R): कांग्रेस एक मंच की तरह थी, जिस पर अनेक समूह, हित और राजनीतिक दल राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए एकजुट होते थे।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

48. 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव क्यों किया जिससे सदस्यों के लिए दोहरी सदस्यता धारण करना असंभव हो गया?
(A) पार्टी में अनुशासन बढ़ाने के लिए।
(B) समाजवादियों को पार्टी से बाहर करने के लिए।
(C) पार्टी को अधिक समावेशी बनाने के लिए।
(D) चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करने के लिए।

49. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारतीय जनसंघ ने अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने का समर्थन किया।
2. जनसंघ ने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने का समर्थन किया।
3. चीन के आणविक परीक्षण के बाद जनसंघ ने भारत के लिए आणविक हथियार बनाने की वकालत की।
4. भारतीय जनता पार्टी की जड़ें भारतीय जनसंघ में हैं।
उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) केवल 3
(D) केवल 4

50. 1957 में केरल में कम्युनिस्टों की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी ने नवनिर्वाचित सरकार के खिलाफ कौन सा आंदोलन छेड़ा?
(A) मुक्ति संघर्ष
(B) भारत छोड़ो आंदोलन
(C) सविनय अवज्ञा आंदोलन
(D) असहयोग आंदोलन

51. निम्नलिखित में से कौन 'इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी' के संस्थापक थे?
(A) जयप्रकाश नारायण
(B) ए.के. गोपालन
(C) डॉ. भीमराव अंबेडकर
(D) जगजीवन राम

52. निम्नलिखित में से कौन सा एक दल 1952-1967 के दौरान अस्तित्व में नहीं था?
(A) स्वतंत्र पार्टी
(B) प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
(C) भारतीय जनसंघ
(D) भारतीय जनता पार्टी

53. निम्नलिखित नेताओं और उनकी पार्टी/भूमिका का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
(A) श्यामा प्रसाद मुखर्जी - भारतीय जनसंघ
(B) ई.एम.एस. नंबूदरीपाद - कम्युनिस्ट पार्टी
(C) आचार्य नरेन्द्र देव - स्वतंत्र पार्टी
(D) राजकुमारी अमृत कौर - स्वास्थ्य मंत्री

54. निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (बायो-डेटा)
P. इस्लाम के विद्वान, हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रतिपादक
Q. जाति विरोधी आंदोलन के नेता, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष
R. गाँधीवादी स्वतंत्रता सेनानी, कपूरथला के राजपरिवार में जन्म
S. केरल के कम्युनिस्ट नेता, 1952 से सांसद
सूची II: (नेता)
1. डॉ. बी.आर. अंबेडकर
2. राजकुमारी अमृत कौर
3. ए.के. गोपालन
4. मौलाना अबुल कलाम आजाद
कूट:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-1, R-2, S-3
(C) P-2, Q-3, R-4, S-1
(D) P-3, Q-4, R-1, S-2

55. भारतीय राजनीति के पहले दशक को 'कांग्रेस-प्रणाली' क्यों कहा जाता है?
(A) क्योंकि कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी नहीं थी।
(B) क्योंकि सभी नेता केवल कांग्रेस से थे।
(C) क्योंकि चुनाव प्रणाली केवल कांग्रेस के पक्ष में थी।
(D) क्योंकि कांग्रेस ने शासक-दल और विपक्ष दोनों की भूमिका निभाई।

56. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): पहले आम चुनाव को दो बार स्थगित करना पड़ा।

आलोचना पर जोर दिया।

उपरोक्त में से कौन से कथन असत्य हैं?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3 और 4
(C) केवल 1, 2 और 4
(D) केवल 2 और 3

38. "भारत में नायक-पूजा का भाव सीधे पतन की ओर ले जाता है और यह रास्ता तानाशाही की तरफ़ जाता है।" यह कथन किसका है?

(A) जवाहरलाल नेहरू
(B) डॉ. भीमराव अंबेडकर
(C) सरदार वल्लभभाई पटेल
(D) महात्मा गांधी

39. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।

अभिकथन (A): स्वतंत्रता के बाद कई नव-स्वतंत्र देशों ने लोकतंत्र को नहीं अपनाया।

कारण (R): उन देशों के नेताओं का मानना था कि लोकतंत्र को अपनाने से मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा, जबकि राष्ट्रीय एकता उनकी पहली प्राथमिकता थी।

(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

40. 2004 तक पूरे देश में मतदान के लिए किस प्रणाली का इस्तेमाल चालू हो गया था?

(A) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम)
(B) मतपेटी प्रणाली
(C) मतपत्र प्रणाली
(D) प्रॉक्सी मतदान

41. निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कांग्रेस की एक सामाजिक गठबंधन के रूप में प्रकृति को दर्शाती है?

(A) केवल एक ही जाति के सदस्यों का होना।
(B) केवल अमीर वर्गों का प्रतिनिधित्व।
(C) किसान, उद्योगपति, शहरी, ग्रामीण, मजदूर, मालिक सभी का समावेश।
(D) केवल शिक्षित अभिजन का बोलबाला।

42. निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:

1. नेहरु के मंत्रिमंडल से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इस्तीफा
2. हिंदू कोड बिल पर असहमति के कारण अंबेडकर का इस्तीफा
3. कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन
4. भारतीय जनसंघ का गठन

(A) 3, 1, 4, 2
(B) 3, 4, 1, 2
(C) 1, 2, 3, 4
(D) 4, 1, 2, 3

43. भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे?

(A) सी. राजगोपालाचारी
(B) सरदार पटेल
(C) रफी अहमद किदवई
(D) मौलाना अबुल कलाम आजाद

44. निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:

सूची I: (व्यक्ति)

P. सुकुमार सेन
Q. ई.एम.एस. नंबूदरीपाद
R. राजकुमारी अमृत कौर
S. दीनदयाल उपाध्याय

सूची II: (भूमिका/पद)

1. स्वास्थ्य मंत्री
2. भारतीय जनसंघ के नेता
3. पहले चुनाव आयुक्त
4. केरल के कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री

कूट:

(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-3, R-2, S-1
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

45. पहले तीन आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 1952, 1957 और 1962 के चुनावों में कांग्रेस ने लोकसभा में तीन-चौथाई सीटें जीतीं।
2. इस अवधि में कांग्रेस को छोड़कर किसी अन्य दल को केंद्र या राज्य में सरकार बनाने का अवसर नहीं मिला।
3. इस प्रभुत्व का एक कारण 'सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत' की चुनाव प्रणाली थी।
4. इस अवधि में कांग्रेस को हमेशा कुल वोटों का 50% से अधिक प्राप्त हुआ।
5. कांग्रेस का प्रभुत्व केंद्र और अधिकांश राज्यों में कायम था।

दिए गए कथनों में से कौन से गलत हैं?

(A) केवल 2 और 4
(B) केवल 1 और 3
(C) केवल 3, 4 और 5
(D) केवल 1 और 5

46. आजादी के बाद के शुरुआती सालों में विपक्षी दलों की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सही है?

(A) देश में विपक्षी दलों का कोई वास्तविक राजनीतिक अस्तित्व नहीं था।

66. निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (दल)
P. भारतीय जनसंघ
Q. कांग्रेस पार्टी
R. सोशलिस्ट पार्टी
S. कम्युनिस्ट पार्टी
सूची II: (नेता)
1. जवाहरलाल नेहरू
2. राममनोहर लोहिया
3. ए.के. गोपालन
4. श्यामा प्रसाद मुखर्जी
कूट:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-1, R-2, S-3
(C) P-2, Q-3, R-4, S-1
(D) P-3, Q-4, R-1, S-2

67. राममनोहर लोहिया के नेतृत्व वाले समाजवादियों का कांग्रेस के प्रति क्या दृष्टिकोण था?
(A) उन्होंने कांग्रेस से हल्के-फुल्के सहयोग की तरफदारी की।
(B) वे कांग्रेस में विलय के पक्ष में थे।
(C) उन्होंने कांग्रेस से अपनी दूरी बढ़ाई और उसकी आलोचना की।
(D) वे कांग्रेस के प्रति पूरी तरह से उदासीन थे।

68. निम्नलिखित में से किस नेता ने 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया?
(A) जगजीवन राम
(B) पेरियार
(C) ज्योतिबा फुले
(D) डॉ. भीमराव अंबेडकर

69. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. कांग्रेस पार्टी के भीतर की गुटबाजी ने पार्टी को कमजोर कर दिया।
2. गुटबाजी के कारण विभिन्न विचारधाराओं के नेता पार्टी के भीतर बने रहे।
3. गुटों के बनने का कारण केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा थी।
4. गुटों की मौजूदगी शासक दल के भीतर संतुलन साधने का एक औजार थी।
5. कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति असहिष्णु थी।
दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2 और 4
(C) केवल 2, 4 और 5
(D) केवल 1, 3 और 5

70. किस नेता का यह विचार था कि "अगर कांग्रेस सबको समेटकर चलने वाला स्वभाव छोड़े... तो वह खत्म हो जाएगी"?
(A) वल्लभभाई पटेल
(B) महात्मा गाँधी
(C) जवाहरलाल नेहरू
(D) डॉ. बी.आर. अंबेडकर

71. अशोक मेहता के नेतृत्व वाले समाजवादियों का कांग्रेस के प्रति क्या दृष्टिकोण था?
(A) कांग्रेस की तीखी आलोचना।
(B) कांग्रेस से पूर्ण अलगाव।
(C) कांग्रेस का हिंसक विरोध।
(D) कांग्रेस से हल्के-फुल्के सहयोग की तरफदारी।

72. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): भारत में पहले तीन आम चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा।
कारण (R): उस समय कांग्रेस को छोड़कर किसी भी अन्य पार्टी को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं थी।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

73. 1952 के चुनावों के दौरान, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गैर-कांग्रेसी दलों को उल्लेखनीय सफलता मिली थी?
(A) उत्तर प्रदेश और बिहार
(B) राजस्थान और मध्य प्रदेश
(C) त्रावणकोर-कोचीन, मद्रास और उड़ीसा
(D) पंजाब और पश्चिम बंगाल

74. 'एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र' का विचार किस राजनीतिक दल से संबंधित है?
(A) भारतीय जनसंघ
(B) कांग्रेस
(C) सोशलिस्ट पार्टी
(D) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी

75. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. पहले आम चुनाव में 20 लाख स्टील के बक्सों का इस्तेमाल हुआ।
2. प्रत्येक मतपेटी पर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिह्न अंकित होता था।
3. पहले दो चुनावों तक एक ही मतपत्र पर मुहर लगाने की व्यवस्था थी।
4. 1990 के दशक में चुनाव आयोग ने ईवीएम का इस्तेमाल शुरु किया।
उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं?

कारण (R): भारत के विशाल आकार, मतदाता सूची तैयार करने में समस्या और प्रशासनिक मशीनरी की कमी के कारण तत्काल चुनाव कराना संभव नहीं था।

(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

57. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. पहले आम चुनाव के समय देश में 17 करोड़ मतदाता थे।
2. इन मतदाताओं में महज 15 फीसदी साक्षर थे।
3. लोकसभा के लिए 489 सांसद चुने जाने थे।
4. विधानसभाओं के लिए 3200 विधायक चुने जाने थे।
5. चुनाव कराने के लिए 3 लाख से कम अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 1, 2, 3 और 4
(C) केवल 3, 4 और 5
(D) सभी 1, 2, 3, 4 और 5

58. 1952 के पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद किस दल ने सर्वाधिक सीटें जीतीं?
(A) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
(B) प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
(C) भारतीय जनसंघ
(D) स्वतंत्र पार्टी

59. निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. कांग्रेस का अपने संविधान में संशोधन
2. सोशलिस्ट पार्टी का गठन
3. कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन
4. आचार्य नरेंद्र देव का निधन

(A) 3, 1, 2, 4
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 3, 2, 1, 4
(D) 2, 3, 4, 1

60. 1951 में तेलंगाना में हिंसक विद्रोह को किस पार्टी ने बढ़ावा दिया था?
(A) सोशलिस्ट पार्टी
(B) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
(C) किसान मजदूर प्रजा पार्टी
(D) कांग्रेस पार्टी

61. शुरुआती दो चुनावों के बाद मतदान के तरीके में क्या बदलाव किया गया?
(A) ईवीएम का प्रयोग शुरु किया गया।
(B) ऑनलाइन मतदान शुरु किया गया।
(C) अलग-अलग मतपेटियों की जगह एक ही मतपत्र पर मुहर लगाने की व्यवस्था की गई।
(D) मतपेटियों को स्टील से बदलकर लकड़ी का कर दिया गया।

62. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. 'मुक्ति संघर्ष' की अगुवाई निहित स्वार्थ और धार्मिक संगठनों ने की।
2. कम्युनिस्ट पार्टी ने केरल में क्रांतिकारी और प्रगतिशील नीतिगत पहल करने का वादा किया था।
3. 1959 का फैसला संविधान-प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग का एक उदाहरण माना जाता है।
4. 1957 में दुनिया में पहली बार एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए बनी।

उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2, 3 और 4
(C) केवल 1, 3 और 4
(D) 1, 2, 3 और 4

63. कांग्रेस की विचारधारात्मक गठबंधन प्रकृति का उदाहरण क्या है?
(A) पार्टी में क्रांतिकारी और शांतिवादी, गरमपंथी और नरमपंथी, सभी का समावेश।
(B) पार्टी में केवल एक ही विचारधारा के लोगों का होना।
(C) पार्टी का किसी भी विचारधारा में विश्वास न करना।
(D) पार्टी का केवल मध्यमार्गी होना।

64. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रुप में अंकित किया गया है।

अभिकथन (A): 1950 के दशक में विपक्षी दलों को लोकसभा या विधानसभा में कहने भर को प्रतिनिधित्व मिला।

कारण (R): इसके बावजूद, इन दलों की मौजूदगी ने शासन-व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाई।

(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

65. निम्नलिखित में से कौन 1948 में गठित अंतरिम सरकार का हिस्सा नहीं था?
(A) डॉ. अंबेडकर
(B) जयप्रकाश नारायण
(C) श्यामा प्रसाद मुखर्जी
(D) सरदार वल्लभभाई पटेल

(B) अच्युत पटवर्धन
(C) राममनोहर लोहिया
(D) आचार्य नरेंद्र देव

85. कांग्रेस के भीतर गुटों के कामकाज के संबंध में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है?
(A) गुटों ने कांग्रेस को हमेशा के लिए कमजोर कर दिया।
(B) गुट हमेशा विचारधारात्मक सरोकारों पर आधारित होते थे।
(C) गुटों ने आंतरिक प्रतिस्पर्धा प्रदान की, जिससे वे पार्टी के भीतर बने रहे।
(D) गुटों को कांग्रेस नेतृत्व द्वारा हमेशा दबाया जाता था।

86. निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकल-पार्टी प्रभुत्व की भारतीय प्रकृति का वर्णन करता है?
(A) यह संविधान में केवल एक पार्टी को अनुमति देकर हासिल किया गया था।
(B) यह मुक्त और निष्पक्ष चुनावों के माहौल में कायम हुआ।
(C) यह सैन्य बल के प्रयोग से हासिल किया गया था।
(D) यह विपक्षी दलों के पूर्ण अभाव के कारण था।

87. निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (अवधारणा/घटना)
P. 'कांग्रेस प्रणाली'
Q. 'मुक्ति संघर्ष'
R. 'अखंड भारत'
S. लोकतांत्रिक समाजवाद
सूची II: (संबंधित दल/विचारक)
1. भारतीय जनसंघ
2. सोशलिस्ट पार्टी
3. रजनी कोठारी
4. केरल में कांग्रेस
कूट:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-3, R-1, S-2
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

88. 1952 के चुनावों में, त्रावणकोर-कोचीन (केरल) के अलावा और किन दो राज्यों में कांग्रेस को विधानसभा में बड़ी जीत नहीं मिली थी, हालांकि बाद में सरकार बना ली?
(A) मद्रास और उड़ीसा
(B) पंजाब और बंगाल
(C) बिहार और उत्तर प्रदेश
(D) राजस्थान और मध्य प्रदेश

89. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): सोशलिस्ट पार्टी 1950 और 1960 के दशक में चुनावों में ज्यादा सफलता हासिल नहीं कर सकी।
कारण (R): 1955 में कांग्रेस द्वारा 'समाजवादी बनावट वाले समाज' के लक्ष्य की घोषणा ने समाजवादियों के लिए खुद को एक कारगर विकल्प के रूप में पेश करना मुश्किल बना दिया।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

90. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) या CPI(M) का गठन कब हुआ?
(A) 1964
(B) 1951
(C) 1957
(D) 1967

91. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल (यूनाइटेड) पर सोशलिस्ट पार्टी की छाप देखी जा सकती है।
2. सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस और कम्युनिस्टों दोनों से अलग थी।
3. सोशलिस्टों ने कांग्रेस की आलोचना की क्योंकि वह पूँजीपतियों और जमींदारों का पक्ष लेती थी।
4. जयप्रकाश नारायण और अशोक मेहता हमेशा कांग्रेस के प्रति एक समान दृष्टिकोण रखते थे।
5. सोशलिस्ट पार्टी का कभी विभाजन नहीं हुआ।
दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 1, 4 और 5
(C) केवल 3, 4 और 5
(D) सभी कथन सही हैं।

92. स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में नेहरु के अलावा कौन से दो प्रमुख विपक्षी नेता शामिल थे?
(A) मीनू मसानी और ए.के. गोपालन
(B) डॉ. अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी
(C) राममनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण
(D) आचार्य कृपलानी और सी. राजगोपालाचारी

93. किस नेता ने जवाहरलाल नेहरु के सरकार में शामिल होने के न्यौते को अस्वीकार कर दिया था?
(A) श्यामा प्रसाद मुखर्जी
(B) डॉ. अंबेडकर
(C) जयप्रकाश नारायण
(D) सी. राजगोपालाचारी

94. 1950 के दशक में, भारतीय जनसंघ को किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से समर्थन मिला?

(A) कांग्रेस
(B) भारतीय जनसंघ
(C) सोशलिस्ट पार्टी
(D) कम्युनिस्ट पार्टी

119. 1950 के दशक में कांग्रेस की गुटबाजी को उसकी कमजोरी की बजाय ताकत क्यों माना गया?
(A) क्योंकि इससे पार्टी में एकता का दिखावा होता था।
(B) क्योंकि गुटों के नेता बहुत शक्तिशाली थे।
(C) क्योंकि गुटबाजी से चुनाव जीतने में मदद मिलती थी।
(D) क्योंकि इससे विभिन्न समूहों को पार्टी से बाहर जाने की बजाय पार्टी के भीतर ही संघर्ष करने का मौका मिलता था।

120. आजादी के बाद के शुरुआती सालों में विपक्षी दलों की क्या भूमिका थी?
(A) उन्होंने कांग्रेस की नीतियों की सुचिन्तित आलोचना की और शासक दल पर अंकुश रखा।
(B) उन्होंने सरकार बनाने में कोई रुचि नहीं दिखाई।
(C) वे केवल सैद्धांतिक बहस में लगे रहे।
(D) वे पूरी तरह से अप्रभावी थे।

121. मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में कौन सा कथन गलत है?
(A) वे इस्लाम के विद्वान थे।
(B) वे हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रतिपादक थे।
(C) वे भारत के विभाजन के प्रबल समर्थक थे।
(D) वे स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे।

122. उस वक्त तक लोकतंत्र को किन देशों तक सीमित माना जाता था, जब भारत ने सार्वभौम मताधिकार के साथ चुनाव करवाए?
(A) केवल धनी और यूरोपीय देशों में।
(B) केवल गरीब और एशियाई देशों में।
(C) केवल समाजवादी देशों में।
(D) केवल नए स्वतंत्र हुए देशों में।

123. 1949 में संविधान सभा में भाषण देते हुए किसने 'राजनीति में नायक-पूजा' के खतरों के प्रति आगाह किया था?
(A) जवाहरलाल नेहरू
(B) सरदार पटेल
(C) सी. राजगोपालाचारी
(D) डॉ. भीमराव अंबेडकर

124. 'किसान मजदूर प्रजा पार्टी' किस मूल दल से निकली एक शाखा थी?
(A) कांग्रेस
(B) सोशलिस्ट पार्टी
(C) भारतीय जनसंघ
(D) कम्युनिस्ट पार्टी

125. 1952 से 1967 के दौरान, जम्मू और कश्मीर में किस पार्टी का प्रभुत्व था?
(A) कांग्रेस
(B) पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी
(C) नेशनल कांफ्रेंस
(D) भारतीय जनसंघ

126. भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था?
(A) 26 जनवरी 1950
(B) 15 अगस्त 1947
(C) 24 जनवरी 1950
(D) 26 नवंबर 1949

127. 1950 के दशक के राजनीतिक परिदृश्य के लिए 'एक-दलीय प्रभुत्व का दौर' शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है?
(A) क्योंकि एक ही दल, कांग्रेस, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर राजनीति में हावी थी।
(B) क्योंकि केवल एक ही दल को चुनाव लड़ने की अनुमति थी।
(C) क्योंकि भारत में बहुदलीय प्रणाली नहीं थी।
(D) क्योंकि सभी विपक्षी नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली थी।

128. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1950 में नेहरू मंत्रिमंडल से क्यों इस्तीफा दिया?
(A) हिंदू कोड बिल पर मतभेद के कारण।
(B) पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर मतभेदों के कारण।
(C) आर्थिक नीतियों पर असहमति के कारण।
(D) कश्मीर को स्वायत्तता देने के विरोध में।

129. निम्नलिखित में से कौन एक गाँधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थीं और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल की सदस्य भी थीं?
(A) सरोजिनी नायडू
(B) राजकुमारी अमृत कौर
(C) सुचेता कृपलानी
(D) एनी बेसेंट

130. 1951 में, किस पार्टी ने हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़कर आम चुनावों में भाग लेने का फैसला किया?
(A) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
(B) सोशलिस्ट पार्टी
(C) फॉरवर्ड ब्लॉक
(D) भारतीय जनसंघ

131. भारत के अनेक आधुनिक दल अपनी वैचारिक जड़ें 1950 के दशक की किस पार्टी में खोज सकते हैं?
(A) कम्युनिस्ट पार्टी
(B) भारतीय जनसंघ
(C) सोशलिस्ट पार्टी
(D) स्वतंत्र पार्टी

(D) कांग्रेस (सेक्युलर)

105. दूसरे (1957) और तीसरे (1962) आम चुनावों के परिणामों के बारे में क्या सच है?

(A) कांग्रेस की सीटें काफी कम हो गईं।
(B) विपक्षी दल मिलकर सरकार बनाने में कामयाब रहे।
(C) कांग्रेस ने लोकसभा में अपनी पुरानी स्थिति (तीन-चौथाई सीटें) बरकरार रखी।
(D) जनसंघ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी।

106. निम्नलिखित में से किसने "सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत" की चुनाव प्रणाली से सबसे अधिक लाभ उठाया?

(A) कांग्रेस पार्टी
(B) सोशलिस्ट पार्टी
(C) कम्युनिस्ट पार्टी
(D) भारतीय जनसंघ

107. निम्नलिखित में से कौन सा कथन केरल की 1957 की सरकार के बारे में सही नहीं है?

(A) यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार थी।
(B) यह दुनिया में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई पहली कम्युनिस्ट सरकार थी।
(C) इसे 1959 में केंद्र सरकार द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था।
(D) इस सरकार ने अपना पूरा पांच साल का कार्यकाल पूरा किया।

108. सोशलिस्ट पार्टी की मुख्य विचारधारा क्या थी?

(A) पूंजीवाद
(B) लोकतांत्रिक समाजवाद
(C) साम्यवाद
(D) फासीवाद

109. कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति को दक्षिण अफ्रीका के किस दल के प्रभुत्व से मिलता-जुलता बताया गया है?

(A) नेशनल पार्टी
(B) इंकथा फ्रीडम पार्टी
(C) अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस
(D) डेमोक्रेटिक अलायंस

110. कांग्रेस के एक "सतरंगे सामाजिक गठबंधन" होने का क्या अर्थ है?

(A) पार्टी के झंडे में सात रंग थे।
(B) पार्टी में केवल सात समूह थे।
(C) यह सात विभिन्न दलों का गठबंधन था।
(D) इसने वर्ग, जाति, धर्म, भाषा जैसे विभिन्न सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व किया।

111. 1941 में साम्यवादियों ने कांग्रेस से अलग होने का फैसला क्यों किया?

(A) वे नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे ब्रिटेन को समर्थन देना चाहते थे।
(B) वे आजादी के पक्ष में नहीं थे।
(C) कांग्रेस ने उन्हें निष्कासित कर दिया था।
(D) वे अपनी अलग सरकार बनाना चाहते थे।

112. कांग्रेस पार्टी में 'गुट' (factions) क्या थे?

(A) पार्टी से अलग हुए समूह।
(B) पार्टी के भीतर मौजूद विभिन्न हित या विचारधारा वाले समूह।
(C) पार्टी के विदेशी समर्थक।
(D) पार्टी को वित्तीय सहायता देने वाले समूह।

113. भारतीय जनसंघ के अनुसार देश को किस आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बनना चाहिए था?

(A) पश्चिमी मॉडल के आधार पर।
(B) भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर।
(C) सोवियत मॉडल के आधार पर।
(D) मिश्रित मॉडल के आधार पर।

114. पहले आम चुनाव के दौरान, चुनाव आयोग ने किन प्रविष्टियों को मतदाता सूची में शामिल करने से इनकार कर दिया था?

(A) महिलाओं के नाम, जो 'अलां की बेटी' या 'फलां की बीवी' के रूप में दर्ज थे।
(B) गलत आयु वाली प्रविष्टियाँ।
(C) दो बार दर्ज किए गए नाम।
(D) दूसरे देश के नागरिकों के नाम।

115. भारत में पहले आम चुनाव के बारे में 'टाइम्स ऑफ इंडिया' ने क्या टिप्पणी की थी?

(A) इसने चुनाव प्रक्रिया की आलोचना की।
(B) इसने इसे 'इतिहास का सबसे बड़ा जुआ' कहा।
(C) इसने माना कि चुनावों ने सार्वभौम मताधिकार के आलोचकों के संदेहों पर पानी फेर दिया है।
(D) इसने चुनाव परिणामों को अविश्वसनीय बताया।

116. रफी अहमद किदवई स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में किन पदों पर रहे?

(A) रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री।
(B) गृह मंत्री और कानून मंत्री।
(C) विदेश मंत्री और शिक्षा मंत्री।
(D) संचार मंत्री और खाद्य एवं कृषि मंत्री।

117. 1952 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिह्न क्या था?

(A) हाथ का पंजा
(B) कमल का फूल
(C) दो बैलों की जोड़ी
(D) हलधर किसान

118. निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी 'अखंड भारत' (भारत और पाकिस्तान का एकीकरण) की पक्षधर थी?

(A) केरल और पश्चिम बंगाल
(B) महाराष्ट्र और गुजरात
(C) तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश
(D) राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के शहरी इलाके

95. निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के एक विचारधारात्मक गठबंधन होने का प्रमाण नहीं है?
(A) इसमें केवल एक ही धर्म के लोग शामिल थे।
(B) इसमें क्रांतिकारी और शांतिवादी दोनों शामिल थे।
(C) इसमें गरमपंथी और नरमपंथी दोनों शामिल थे।
(D) इसमें दक्षिणपंथी, वामपंथी और मध्यमार्गी सभी शामिल थे।

96. कांग्रेस पार्टी का जन्म कब हुआ?
(A) 1920
(B) 1885
(C) 1947
(D) 1905

97. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(A) 1952 के पहले आम चुनाव में कुल मतदाताओं में आधे से भी कम ने मतदान किया।
(B) चुनाव परिणामों को हारने वाले उम्मीदवारों ने भी निष्पक्ष बताया।
(C) विदेशी पर्यवेक्षकों ने भारतीय चुनाव प्रयोग की विफलता की भविष्यवाणी की थी, जो सच साबित हुई।
(D) सार्वभौम मताधिकार का प्रयोग पूरी दुनिया में सफल नहीं माना गया।

98. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. कांग्रेस ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया तो उसका सामाजिक आधार बढ़ा।
2. शुरू में कांग्रेस में अँग्रेज़ीदाँ, अगड़ी जाति और शहरी अभिजन का बोलबाला था।
3. आजादी के समय तक कांग्रेस का नेतृत्व केवल उच्च वर्ग के पेशेवर लोगों तक सीमित रहा।
4. कांग्रेस में किसान और उद्योगपति, मजदूर और मालिक जैसे परस्पर विरोधी हितों के समूह एक साथ मौजूद थे।

उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) केवल 3
(D) केवल 4

99. निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (वर्ष)
P. 1952
Q. 1957
R. 1959
S. 1964

सूची II: (घटना)
1. केरल में कम्युनिस्ट सरकार का गठन
2. कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन
3. पहला आम चुनाव
4. केरल सरकार की बर्खास्तगी

कूट:
(A) P-3, Q-1, R-4, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-3, R-2, S-1
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

100. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुज़रा हो।
कारण (R): भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व, चीन और क्यूबा जैसे देशों के विपरीत, लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम हुआ।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

101. 'डोंट स्पेयर मी शंकर' किस कार्टूनिस्ट की रचनाओं का संग्रह है?
(A) आर. के. लक्ष्मण
(B) मारियो मिरांडा
(C) शंकर (के. शंकर पिल्लई)
(D) सुधीर धर

102. 1950 में जब भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया, उस समय देश का शासन कौन चला रहा था?
(A) ब्रिटिश सरकार
(B) अंतरिम सरकार
(C) लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार
(D) सैन्य जनरल

103. 1952 के पहले आम चुनाव के समय लोकसभा की कुल सीटें कितनी थीं?
(A) 543
(B) 500
(C) 364
(D) 489

104. 'कांग्रेस' शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किस राजनीतिक दल के लिए किया जाता रहा है?
(A) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
(B) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
(C) तृणमूल कांग्रेस

132. केरल में हुए 'मुक्ति संघर्ष' (Liberation Struggle) का क्या परिणाम हुआ?
(A) केरल में कम्युनिस्ट सरकार और मजबूत हो गई।
(B) कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच समझौता हो गया।
(C) ई.एम.एस. नंबूदरीपाद ने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया।
(D) केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 356 का उपयोग कर केरल सरकार को बर्खास्त कर दिया।

133. कांग्रेस को स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल होने का क्या मतलब है?
(A) कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को तत्कालीन अंग्रेज सरकार से वित्तीय सहायता मिली।
(B) कांग्रेस को अंग्रेजों द्वारा छोड़ी गई समस्त चल और अचल संपत्ति प्राप्त हुई।
(C) राष्ट्रीय आंदोलन के उत्तराधिकारी के रूप में इसे नैतिक लोकप्रियता प्राप्त हुई।
(D) कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम के सभी राष्ट्रीय प्रतीकों पर कानूनी एकाधिकार किया।

134. "कांग्रेस एक मंच की तरह थी।" इस कथन का क्या अभिप्राय है?
(A) कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता सार्वजनिक मंचों पर भाषण देने के शौकीन थे।
(B) यह एक मंच था जहाँ विभिन्न समूह और दल राष्ट्रीय हित में एकजुट थे।
(C) कांग्रेस की सभी औपचारिक बैठकें हमेशा एक ऊंचे ऊंचे मंच पर आयोजित होती थीं।
(D) कांग्रेस पार्टी केवल एक बाहरी प्रदर्शन करने वाला राजनीतिक मंच मात्र थी।

135. शुरुआती सालों में कांग्रेस के भीतर विपक्ष की भूमिका कैसे निभाई जाती थी?
(A) बाहरी विपक्षी दलों द्वारा।
(B) विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप से।
(C) उस समय कोई विपक्षी भूमिका नहीं थी।
(D) कांग्रेस के अपने विभिन्न गुटों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा और बहस के माध्यम से।

136. ए.के. गोपालन किस राजनीतिक दल के प्रमुख नेता थे?
(A) कम्युनिस्ट पार्टी
(B) कांग्रेस
(C) सोशलिस्ट पार्टी
(D) भारतीय जनसंघ

137. 1952 के लोकसभा चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी को वोट प्रतिशत के हिसाब से कौन सा स्थान मिला?
(A) पहला
(B) तीसरा
(C) दूसरा
(D) चौथा

138. 1950 में भारत के चुनाव आयोग के गठन के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि पहला आम चुनाव कब तक हो जाएगा?
(A) 1950 में ही
(B) 1951 में
(C) 1952 में
(D) 1955 में

139. 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद सोवियत संघ की विचारधारा का समर्थन करने वाला गुट किस नाम से जाना गया?
(A) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) या CPI(M)
(B) कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (लेनिनिस्ट)
(C) रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी
(D) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या CPI

140. आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और राममनोहर लोहिया जैसे नेता किस राजनीतिक धारा से जुड़े थे?
(A) साम्यवादी
(B) समाजवादी
(C) जनसंघी
(D) कांग्रेस (मध्यमार्गी)

141. पहले आम चुनाव के आयोजन में चुनाव आयोग को मुख्य रूप से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा?
(A) चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन और मतदाता सूचियों की तैयारी।
(B) कम साक्षरता के कारण मतदान की विशेष पद्धति तैयार करना।
(C) उपरोक्त सभी।
(D) चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण।

142. डॉ. अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म क्यों अपनाया?
(A) राजनीतिक लाभ के लिए।
(B) विदेश यात्रा से प्रभावित होकर।
(C) नेहरू के साथ व्यक्तिगत मतभेदों के कारण।
(D) हिंदू धर्म में व्याप्त जाति व्यवस्था पर अपनी असहमति के कारण।

143. भारत में चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का इस्तेमाल किस दशक में शुरु हुआ?
(A) 1990 के दशक के अंत में।
(B) 1970 के दशक के अंत में।
(C) 1980 के दशक के अंत में।
(D) 2000 के दशक के अंत में।

144. 'हिंदुस्तान टाइम्स' ने 1952 के चुनाव की सफलता पर क्या लिखा?
(A) यह एक विफल प्रयोग था।
(B) यह बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया।

(B) बलपूर्वक अधिरोपण और कठोर नीतियां।
(C) केवल उद्योगपतियों के हितों को बढ़ावा देना।
(D) निरंतर राजनीतिक अस्थिरता।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

भारत के प्रारंभिक लोकतांत्रिक चरण में कांग्रेस के प्रभुत्व के बावजूद, एक जीवंत लेकिन खंडित विपक्षी परिदृश्य मौजूद था। ये विपक्षी दल, यद्यपि चुनावी रूप से कमजोर थे, फिर भी उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के चरित्र को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एक आवश्यक लोकतांत्रिक कार्य किया: सत्ताधारी दल की नीतियों और प्रथाओं की निरंतर आलोचना। सोशलिस्ट पार्टी, जो कांग्रेस के भीतर ही उत्पन्न हुई थी, ने लोकतांत्रिक समाजवाद का एक विकल्प प्रस्तुत किया और कांग्रेस पर किसानों और मजदूरों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई), जो पहले तीन चुनावों में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी, ने वर्ग संघर्ष पर आधारित एक क्रांतिकारी विचारधारा का प्रतिनिधित्व किया, हालांकि बाद में उसने संसदीय मार्ग अपना लिया। दूसरी ओर, भारतीय जनसंघ ने 'एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र' के विचार पर जोर देते हुए एक सांस्कृतिक राष्ट्रवादी एजेंडा प्रस्तुत किया और कांग्रेस की अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की नीतियों का विरोध किया। इन दलों को लोकसभा या राज्य विधानसभाओं में महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं मिला, लेकिन उनकी उपस्थिति ने सुनिश्चित किया कि संसदीय बहसों में विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार किया जाए। उन्होंने शासक दल पर एक वैचारिक दबाव बनाए रखा, उसे आत्मसंतुष्ट होने से रोका और शक्ति के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया। इस प्रकार, इन विपक्षी दलों ने एक लोकतांत्रिक विकल्प की संभावना को जीवित रखा और भविष्य के नेताओं को प्रशिक्षित किया, जिससे एक-दलीय प्रभुत्व के युग में भी बहुदलीय लोकतंत्र की भावना को बनाए रखा गया।

उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

161. प्रारंभिक दशकों में विपक्षी दलों की मुख्य भूमिका क्या थी, भले ही वे चुनावी रूप से कमजोर थे?
(A) राज्य और केंद्र स्तर पर कांग्रेस के स्थान पर वैकल्पिक सरकारें बनाना।
(B) विभिन्न देशों के साथ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर निरंतर बातचीत करना।
(C) विभिन्न राज्यों में कांग्रेस के साथ मिलकर साझा गठबंधन सरकारें तैयार करना।
(D) सत्ताधारी दल की नीतियों की निरंतर आलोचना और निगरानी करना।

162. स्रोत के अनुसार, भारतीय जनसंघ की विचारधारा का मुख्य तत्व क्या था?
(A) लोकतांत्रिक समाजवाद और किसानों के अधिकार।
(B) सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और 'अखंड भारत' का विचार।
(C) वर्ग संघर्ष और क्रांतिकारी परिवर्तन।
(D) राज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता।

163. कांग्रेस के प्रभुत्व के युग में विपक्षी दलों का महत्व किस बात में निहित था?
(A) वे पहले तीन आम चुनावों में अक्सर चुनाव जीतते थे और अपनी स्वतंत्र सरकार बनाते थे।
(B) उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपनी सभी आर्थिक और सामाजिक नीतियां बदलने हेतु विवश किया।
(C) संसद में वैचारिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर शासक दल पर अंकुश लगाया।
(D) उन्होंने तत्कालीन भारतीय राजनीति में किसी भी प्रकार का कोई खास प्रभाव नहीं डाला।

164. सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के बीच मुख्य वैचारिक अंतर क्या था?
(A) सोशलिस्ट पार्टी पूर्णतः पूंजीवाद का समर्थन करती थी, जबकि सीपीआई कट्टर समाजवाद का।
(B) सोशलिस्ट पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर जोर देती थी, जबकि सीपीआई शुद्ध धर्मनिरपेक्षता पर।
(C) इन दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के बीच वास्तव में कोई भी गंभीर वैचारिक अंतर नहीं था।
(D) सोशलिस्ट पार्टी लोकतांत्रिक समाजवाद और सीपीआई वर्ग संघर्ष पर केंद्रित थी।

165. इस स्रोत से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है?
(A) कमजोर विपक्ष भी जीवंत लोकतंत्र बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
(B) भारत में प्रारंभिक वर्षों के एक-दलीय प्रभुत्व का अर्थ वास्तव में लोकतंत्र का पूर्ण अभाव था।
(C) आरंभिक काल के लगभग सभी प्रमुख विपक्षी दल मूल रूप से कांग्रेस पार्टी से ही निकल कर बने थे।
(D) विपक्षी दलों का एकमात्र मुख्य उद्देश्य सत्ताधारी कांग्रेस सरकार को सदैव अस्थिर करना था।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

1957 में केरल विधानसभा चुनाव के परिणाम ने भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ दिया। इन चुनावों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बहुमत हासिल किया और ई.एम.एस. नम्बूदरीपाद के नेतृत्व में सरकार बनाई। यह दुनिया में पहली बार था कि एक कम्युनिस्ट सरकार लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से सत्ता में आई थी। इस सरकार ने कुछ क्रांतिकारी सुधारों को लागू करने का प्रयास किया, जिनमें 'कृषि संबंध विधेयक' (Agrarian Relations Bill) और एक 'शिक्षा विधेयक' (Education Bill) प्रमुख थे। भूमि सुधार विधेयक का उद्देश्य किरायेदारी को समाप्त करना और भूमिहीन किसानों को भूमि का स्वामित्व प्रदान करना था, जिससे भू-स्वामी अभिजात वर्ग के हित सीधे प्रभावित हुए। शिक्षा विधेयक ने निजी शैक्षणिक संस्थानों पर राज्य का नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास किया, जिनमें से कई कैथोलिक चर्च और नायर सर्विस सोसाइटी (NSS) जैसे सामुदायिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे थे। इन नीतियों के कारण एक तीव्र सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई। कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए, इन निहित स्वार्थों

अलग मतपेटियां रखी गईं।
(D) अशिक्षित मतदाताओं की सहायता हेतु मतदान अधिकारियों द्वारा स्वयं उनकी ओर से गुप्त मतदान किया गया।

154. स्रोत के अनुसार, प्रथम आम चुनाव के संदर्भ में "इतिहास का सबसे बड़ा जुआ" वाक्यांश का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था?
(A) चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, जो चुनावी व्यवस्था की सफलता को लेकर अत्यंत आशंकित थे।
(B) प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जिन्होंने देश में इस विशाल प्रयोग के परिमाण का सजीव वर्णन किया।
(C) विभिन्न विपक्षी दलों द्वारा, जो वर्तमान चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और शुद्धता पर सवाल उठा रहे थे।
(D) निरक्षर देश में वयस्क मताधिकार की सफलता पर संदेह करने वाले आलोचकों द्वारा।

155. उपर्युक्त स्रोत से प्रथम आम चुनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है?
(A) तत्कालीन चुनाव प्रक्रिया अत्यंत सरल थी और इसमें किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी नवीनता नहीं थी।
(B) आरंभिक वर्षों में होने वाले चुनाव केवल देश की शिक्षित पुरुष आबादी तक ही पूर्णतः सीमित रहे थे।
(C) आयोग ने लैंगिक असमानता जैसी सामाजिक बाधाओं को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाई।
(D) विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने भारत की इस चुनावी प्रक्रिया की वैश्विक स्तर पर भारी आलोचना की।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

स्वतंत्रता के बाद पहले दो दशकों में भारतीय राजनीति पर कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व को अक्सर "कांग्रेस प्रणाली" (कांग्रेस सिस्टम) के रूप में वर्णित किया जाता है। यह केवल चुनावी जीत की एक श्रृंखला नहीं थी, बल्कि एक विशिष्ट प्रकार की राजनीतिक कार्यप्रणाली थी। कांग्रेस एक व्यापक सामाजिक गठबंधन के रूप में कार्य करती थी, जो विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों और विचारधारात्मक झुकाव वाले समूहों को अपने भीतर समाहित करती थी। यह एक 'इंद्रधनुषी' गठबंधन था जिसमें उद्योगपति और मजदूर, शहरी अभिजात वर्ग और किसान, रूढ़िवादी और कट्टरपंथी, दक्षिणपंथी और वामपंथी सभी शामिल थे। इस समावेशी प्रकृति ने कांग्रेस को एक मध्यमार्गी पार्टी बना दिया जो चरमपंथीPositions से बचती थी। पार्टी के भीतर ही विभिन्न गुट मौजूद थे, जो अलग-अलग हितों और विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते थे। इन गुटों के बीच आंतरिक प्रतिस्पर्धा और शक्ति संतुलन की प्रक्रिया ने एक तरह से पार्टी के भीतर ही विपक्ष की भूमिका निभाई। इसने सुनिश्चित किया कि अधिकांश संघर्ष और बहस पार्टी के भीतर ही हल हो जाएं, जिससे एक मजबूत बाहरी विपक्ष के विकास की गुंजाइश सीमित हो गई। इस प्रकार, कांग्रेस प्रणाली ने एक-दलीय प्रभुत्व के भीतर एक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया, जहाँ सहमति और समायोजन के माध्यम से शासन किया जाता था, न कि बलपूर्वक अधिरोपण के माध्यम से। यह प्रणाली राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक स्थिरता को बनाए रखने में सफल रही।

उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

156. "कांग्रेस प्रणाली" की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन क्या है?
(A) संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाला एक पूर्णतः अधिनायकवादी एक-दलीय शासन।
(B) व्यापक सामाजिक गठबंधन पर आधारित एक-दलीय प्रभुत्व की लोकतांत्रिक प्रणाली।
(C) एक ऐसी विशिष्ट राजनैतिक प्रणाली जहाँ कांग्रेस ने सैन्य साधनों से सत्ता पर कब्जा कर लिया।
(D) एक ऐसी संकुचित प्रणाली जहाँ केवल कांग्रेस पार्टी को ही स्वतंत्र चुनाव लड़ने की अनुमति थी।

157. स्रोत के अनुसार, कांग्रेस पार्टी को "इंद्रधनुषी गठबंधन" क्यों कहा गया है?
(A) क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक झंडा इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों का था।
(B) क्योंकि यह पार्टी केवल अल्पसंख्यक और उपेक्षित समुदायों का राजनैतिक प्रतिनिधित्व करती थी।
(C) क्योंकि यह पार्टी केवल दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय थी।
(D) यह विभिन्न सामाजिक और वैचारिक समूहों को अपने भीतर समाहित करती थी।

158. कांग्रेस प्रणाली के भीतर गुटों ने क्या भूमिका निभाई?
(A) आंतरिक विपक्ष के रूप में कार्य कर विभिन्न हितों को प्रतिनिधित्व दिया।
(B) उन्होंने निरंतर कांग्रेस पार्टी को कमजोर किया और भविष्य में इसके पतन का मुख्य कारण बने।
(C) उन्होंने हमेशा पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व द्वारा लिए गए निर्णयों का पूर्ण समर्थन किया।
(D) वे समय-समय पर कांग्रेस से अलग होकर नई क्षेत्रीय पार्टियाँ बनाने के लिए उत्तरदायी थे।

159. कांग्रेस प्रणाली ने एक मजबूत बाहरी विपक्ष के विकास को कैसे बाधित किया?
(A) देश के प्रभावशाली विपक्षी नेताओं को बिना किसी कारण के समय-समय पर गिरफ्तार करके।
(B) लोकतांत्रिक चुनावों में बड़े पैमाने पर संगठित रूप से धांधली और भ्रष्टाचार करके।
(C) विविध हितों को समाहित कर बाहरी विरोध की संभावनाओं को सीमित किया।
(D) सत्ता का दुरुपयोग करते हुए सभी सक्रिय विपक्षी दलों पर पूर्ण कानूनी प्रतिबंध लगाकर।

160. स्रोत यह बताता है कि कांग्रेस प्रणाली की शासन शैली की विशेषता थी:
(A) सहमति, समायोजन और मध्यमार्गी दृष्टिकोण।

(C) यह चुनाव निष्पक्ष नहीं था।
(D) चुनाव में बहुत कम लोगों ने भाग लिया।

145. कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर मुख्य रुप से कब से कब तक माना जाता है?
(A) 1947-1952
(B) 1952-1967
(C) 1967-1977
(D) 1977-1984

146. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई?
(A) कश्मीर नीति पर जनसंघ के प्रदर्शन के दौरान हिरासत में।
(B) एक विमान दुर्घटना में।
(C) एक लंबी बीमारी के बाद।
(D) एक चुनावी रैली के दौरान।

147. निम्नलिखित में से कौन सा दल अपने गठन के समय से ही कांग्रेस की नीतियों का मुखर विरोधी रहा?
(A) सोशलिस्ट पार्टी
(B) भारतीय जनसंघ
(C) उपरोक्त सभी
(D) कम्युनिस्ट पार्टी

148. पहले तीन आम चुनावों में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी रही?
(A) सोशलिस्ट पार्टी
(B) भारतीय जनसंघ
(C) स्वतंत्र पार्टी
(D) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी

149. भारतीय संविधान पर कब हस्ताक्षर किए गए?
(A) 26 नवंबर 1949
(B) 26 जनवरी 1950
(C) 24 जनवरी 1950
(D) 15 अगस्त 1947

150. राजनीति शास्त्री रजनी कोठारी ने भारतीय राजनीति के किस कालखंड को 'कांग्रेस-प्रणाली' के रूप में परिभाषित किया है?
(A) 1947-1952
(B) चुनावी प्रतिस्पर्धा का पहला दशक
(C) 1970 का दशक
(D) 1980 का दशक

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
भारत का प्रथम आम चुनाव, जो 1951-52 में संपन्न हुआ, केवल एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक इंजीनियरिंग का एक अभूतपूर्व प्रयोग था। चुनाव आयोग, जिसका गठन जनवरी 1950 में हुआ, के समक्ष विकट चुनौतियाँ थीं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन के नेतृत्व में, आयोग को लगभग 17.3 करोड़ मतदाताओं के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की रुपरेखा तैयार करनी थी, जिनमें से लगभग 85% निरक्षर थे। सबसे बड़ी बाधाओं में से एक मतदाता सूचियों का निर्माण था। प्रारंभिक मसौदे में लाखों महिलाओं के नाम "फलां की पत्नी" या "फलां की बेटी" के रूप में दर्ज थे, जिसे आयोग ने लैंगिक समानता के आधार पर अस्वीकार कर दिया और सूचियों के पुनरीक्षण का आदेश दिया। निरक्षरता की समस्या से निपटने के लिए, प्रत्येक उम्मीदवार को एक विशिष्ट चुनाव चिह्न आवंटित किया गया और प्रत्येक मतदान केंद्र पर हर उम्मीदवार के लिए एक अलग मतपेटी रखी गई, जिस पर उसका चुनाव चिह्न लगा होता था। मतदाताओं को केवल अपनी पसंद के उम्मीदवार की मतपेटी में एक खाली मतपत्र डालना था। यह विशाल अभ्यास, जिसमें 3 लाख से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया और लगभग 20 लाख स्टील की मतपेटियों का उपयोग हुआ, ने एक गरीब और बड़े पैमाने पर निरक्षर देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवहार्यता को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया और इसे "इतिहास का सबसे बड़ा जुआ" कहने वाले आलोचकों को गलत साबित कर दिया।
उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

151. प्रथम आम चुनाव के संचालन में चुनाव आयोग के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक क्या थी?
(A) देश के विभिन्न उभरते राजनीतिक दलों के बीच होने वाली तीव्र प्रतिस्पर्धा का कुशल प्रबंधन।
(B) निरक्षर मतदाता वर्ग हेतु एक व्यवहार्य मतदान प्रणाली तैयार करना।
(C) चुनाव प्रचार की पूरी प्रक्रिया के लिए आवश्यक सरकारी धन का उचित आवंटन सुनिश्चित करना।
(D) आम चुनाव संपन्न होने के पश्चात केंद्र में सरकार गठन की संवैधानिक प्रक्रिया सुनिश्चित करना।

152. चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों में महिलाओं के पंजीकरण के मुद्दे का समाधान कैसे किया?
(A) स्वतंत्र पहचान रहित प्रविष्टियों को अस्वीकार कर सूचियों के पुनरीक्षण का आदेश दिया।
(B) उसने प्रारंभिक मसौदे को बिना किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन या जांच के पूर्णतः स्वीकार कर लिया।
(C) उसने देश की सभी महिलाओं को इस ऐतिहासिक प्रथम मतदान प्रक्रिया से बाहर रखने का कठोर फैसला किया।
(D) उसने केवल उच्च शिक्षित और शहरी पृष्ठभूमि वाली महिलाओं को ही पंजीकृत करने की विशेष अनुमति दी।

153. 1951-52 के चुनावों में निरक्षर मतदाताओं की सुविधा के लिए अपनाई गई मतदान पद्धति की मुख्य विशेषता क्या थी?
(A) प्रत्येक मतदाता को मतपत्र पर स्वयं अपने पसंदीदा उम्मीदवार का नाम स्पष्ट रूप से लिखना होता था।
(B) प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग-अलग रंगों वाली मतपेटियों का प्रभावी उपयोग किया गया।
(C) उम्मीदवारों को विशिष्ट चिह्न आवंटित कर उनके लिए

और धार्मिक समूहों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन शुरू किया, जिसे 'विमोचन समरम' (मुक्ति संघर्ष) के नाम से जाना गया। राज्य में कानून और व्यवस्था के बिगड़ने का हवाला देते हुए, 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए नम्बूदरीपाद सरकार को बर्खास्त कर दिया। यह निर्णय अत्यधिक विवादास्पद साबित हुआ और इसने केंद्र-राज्य संबंधों तथा राज्यपाल की भूमिका पर एक स्थायी बहस छेड़ दी।
उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

166. 1957 में केरल में बनी कम्युनिस्ट सरकार की ऐतिहासिक महत्ता क्या थी?
- (A) यह स्वतंत्रता के पश्चात भारत में गठित होने वाली पहली सफल गठबंधन सरकार के रूप में जानी गई।
- (B) यह लोकतांत्रिक चुनावों से सत्ता पाने वाली विश्व की पहली कम्युनिस्ट सरकार थी।
- (C) इस सरकार के कार्यों ने भारत में पहली बार संवैधानिक राष्ट्रपति शासन लागू करने की स्थिति पैदा की।
- (D) यह भारतीय गणराज्य के इतिहास में गठित होने वाली पहली गैर-हिंदी भाषी प्रभावशाली राज्य सरकार थी।

167. केरल की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ 'विमोचन समरम' (मुक्ति संघर्ष) का मुख्य कारण क्या था?
- (A) तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई विवादित और स्वतंत्र विदेश नीति।
- (B) सरकार द्वारा प्रस्तावित कट्टरपंथी भूमि और शिक्षा सुधार के प्रयास।
- (C) नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का विशिष्ट व्यक्तित्व और उनकी कार्य करने की शैली।
- (D) भाषाई आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन की मांग को लेकर उपजा विवाद।

168. 'विमोचन समरम' आंदोलन में कौन से समूह मुख्य रूप से शामिल थे?
- (A) भू-स्वामी, शिक्षण संस्थानों के प्रबंधक, धार्मिक संगठन और कांग्रेस दल।
- (B) राज्य भर के केवल औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत मजदूर और खेतिहर किसान।
- (C) विभिन्न शिक्षण संस्थानों से जुड़े केवल सक्रिय वामपंथी छात्र संगठन।
- (D) राज्य में कार्यरत केवल केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारी।

169. केंद्र सरकार ने 1959 में केरल सरकार को बर्खास्त करने के लिए किस संवैधानिक प्रावधान का उपयोग किया?
- (A) अनुच्छेद 370, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है।
- (B) अनुच्छेद 352, जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है।
- (C) अनुच्छेद 356, जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है।
- (D) अनुच्छेद 360, जो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है।

170. स्रोत के अनुसार, केरल की कम्युनिस्ट सरकार की बर्खास्तगी का दीर्घकालिक परिणाम क्या हुआ?
- (A) केरल राज्य में सक्रिय कम्युनिस्ट विचारधारा और उससे जुड़ा आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो गया।
- (B) इस घटना के तुरंत बाद पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी का राजनैतिक प्रभुत्व पूर्णतः समाप्त हो गया।
- (C) इस विशिष्ट घटना ने भारत में स्थायी रूप से गठबंधन सरकारों के एक नए युग की औपचारिक शुरुआत की।
- (D) इसने केंद्र-राज्य संबंधों एवं अनुच्छेद 356 के उपयोग पर राष्ट्रव्यापी बहस छेड़ी।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
पहले तीन आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी की भारी चुनावी सफलता केवल उसकी लोकप्रियता का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह भारत में अपनाई गई 'फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट' (FPTP) चुनावी प्रणाली के प्रभाव को भी दर्शाती है। इस प्रणाली में, एक निर्वाचन क्षेत्र में जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलते हैं, उसे विजेता घोषित किया जाता है, भले ही उसे कुल वोटों का बहुमत (50% से अधिक) न मिला हो। इस प्रणाली ने कांग्रेस के पक्ष में काम किया। उदाहरण के लिए, 1952 के चुनावों में, कांग्रेस को लगभग 45% लोकप्रिय वोट मिले, लेकिन इस वोट शेयर ने उसे लोकसभा में लगभग 74% सीटों (489 में से 364) पर जीत दिलाई। इसके विपरीत, विपक्षी दलों का वोट शेयर खंडित था। समाजवादी पार्टी को 10% से अधिक वोट मिले, जो किसी भी अन्य गैर-कांग्रेसी पार्टी से अधिक था, लेकिन वे केवल 3% सीटें भी नहीं जीत सके। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विपक्षी वोट विभिन्न दलों और उम्मीदवारों में बंट गए, जिससे किसी भी एक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार को हराना मुश्किल हो गया। यदि विपक्षी वोट एकजुट होते, तो परिणाम काफी भिन्न हो सकते थे। इस प्रकार, FPTP प्रणाली ने प्राप्त वोटों और जीती गई सीटों के बीच एक असंतुलन पैदा किया, जिससे कांग्रेस की जीत का पैमाना उसके वास्तविक वोट शेयर की तुलना में बहुत बड़ा दिखाई दिया। यह संरचनात्मक कारक 'एक-दलीय प्रभुत्व' के युग का एक महत्वपूर्ण घटक था।
उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

171. 'फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट' (FPTP) प्रणाली में एक उम्मीदवार कैसे जीतता है?
- (A) उसे कुल वोटों का 50% से अधिक प्राप्त करना होता है।
- (B) उसे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है।
- (C) उसे अन्य सभी उम्मीदवारों की तुलना में अधिक वोट प्राप्त करने होते हैं।
- (D) उसे अपने निर्वाचन क्षेत्र के सभी दलों का समर्थन प्राप्त करना होता है।

172. FPTP प्रणाली ने कांग्रेस के प्रभुत्व में कैसे योगदान दिया?

(A) इसने सदैव यह सुनिश्चित किया कि कांग्रेस पार्टी को प्रत्येक चुनाव में 50% से अधिक वोट प्राप्त हों।
(B) इसने कांग्रेस के वोट शेयर की तुलना में उसकी सीटों की संख्या को अधिक दिखाया।
(C) इसने सभी विपक्षी दलों को किसी भी प्रकार का स्वतंत्र लोकतांत्रिक चुनाव लड़ने से पूर्णतः रोक दिया।
(D) इसने चुनावी प्रक्रिया के दौरान केवल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को ही चुनाव लड़ने की विशेष अनुमति दी।

173. 1952 के चुनावों में समाजवादी पार्टी के साथ क्या हुआ, जैसा कि स्रोत में वर्णित है?
(A) उसने कांग्रेस से कहीं अधिक वोट प्राप्त किए परंतु फिर भी वह सीटें जीतने में पूरी तरह विफल रही।
(B) उसने सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर एक व्यापक चुनावी गठबंधन के तहत स्वतंत्र चुनाव लड़ा।
(C) उस चुनावी वर्ष में उसे देश के किसी भी राज्य या निर्वाचन क्षेत्र से कोई भी वैध वोट प्राप्त नहीं हुआ।
(D) महत्वपूर्ण वोट शेयर मिलने के बावजूद वह उसे सीटों में नहीं बदल सकी।

174. स्रोत के अनुसार, कांग्रेस की सीटों और वोटों के प्रतिशत में भारी अंतर का मुख्य कारण क्या था?
(A) चुनावी प्रणाली का स्वरूप और विपक्षी वोटों का विभाजन।
(B) कांग्रेस की अत्यधिक लोकप्रियता।
(C) विपक्षी दलों का चुनावी बहिष्कार।
(D) चुनाव में बड़े पैमाने पर हुई धांधली।

175. उपर्युक्त स्रोत से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि:
(A) FPTP प्रणाली हमेशा सत्ताधारी दल के लिए फायदेमंद होती है।
(B) कांग्रेस का प्रभुत्व केवल उसकी नीतियों के कारण था, चुनावी प्रणाली का कोई योगदान नहीं था।
(C) चुनावी प्रणाली का स्वरूप चुनाव परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है।
(D) भारत में पहले तीन चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत हुए थे।

ANSWERS

1. (B) सुकुमार सेन
सुकुमार सेन एक भारतीय सिविल सेवक थे जिन्हें 1950 में भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1951-52 और 1957 के पहले दो आम चुनावों का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और सीमित बुनियादी ढांचे के बावजूद बड़े पैमाने पर चुनावी अभ्यास आयोजित करके देश की लोकतांत्रिक नींव स्थापित करने में उनका कार्यकाल अत्यंत महत्वपूर्ण रहा।

2. (A) लोकतांत्रिक शासन
स्वतंत्रता के बाद भारत ने व्यापक गरीबी और निरक्षरता के बावजूद गैर-लोकतांत्रिक विकल्पों के बजाय जानबूझकर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को चुना। नेतृत्व का मानना था कि विविध हितों के प्रबंधन और संघर्षों को सुलझाने के लिए राजनीतिक प्रतिस्पर्धा आवश्यक थी। लोकतंत्र के प्रति इस प्रतिबद्धता का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना और यह सुनिश्चित करना था कि सरकार नियमित चुनावों के माध्यम से जवाबदेह रहे।

3. (A) P-3, Q-1, R-4, S-2
भारत में विभिन्न राजनीतिक दल विशिष्ट वैचारिक आधारों के साथ उभरे। भारतीय जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया। सोशलिस्ट पार्टी ने लोकतांत्रिक समाजवाद की वकालत की, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ने शुरू में तेलंगाना में हिंसक विद्रोह का समर्थन किया था। इस बीच कांग्रेस ने विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक व्यापक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में कार्य किया।

4. (D) चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का उपयोग हुआ।
पहले आम चुनाव भारतीय लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक घटना थे, जो अक्टूबर 1951 और फरवरी 1952 के बीच आयोजित किए गए थे। उस समय अधिकांश मतदाता निरक्षर थे और प्रत्येक सीट के लिए औसतन चार उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। हालांकि उस समय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग नहीं किया गया था; इसके बजाय मतदाताओं ने मतपत्रों और उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग बक्सों का उपयोग किया था।

5. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
आजादी के बाद के शुरुआती वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने शासक दल और आंतरिक विपक्ष के मंच के रूप में एक अनूठी भूमिका निभाई। इसकी गठबंधन जैसी प्रकृति ने विभिन्न आंतरिक गुटों को विविध दृष्टिकोणों और हितों का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी। इन समूहों ने पार्टी के भीतर ही नीतियों पर बहस की, जिससे संतुलनकारी भूमिका निभाई गई जो आमतौर पर विपक्षी दलों से अपेक्षित होती है।

6. (D) 1, 2, 3 और 4
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की उत्पत्ति 1920 के दशक में हुई थी, जो रूस की बोल्शेविक क्रांति से काफी प्रेरित थी। शुरुआत में हिंसक क्रांतिकारी तरीकों का पक्ष लेने के बाद पार्टी 1951 में संवैधानिक राजनीति की ओर मुड़ गई। इसने 1957 में केरल में चुनाव जीतकर इतिहास रचा, जिससे भारत के किसी राज्य में पहली बार लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार का गठन हुआ।

7. (D) भारत में प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थितियों के अंतर्गत ही कायम हुआ।
उन देशों के विपरीत जहाँ कानूनी प्रतिबंध या सैन्य बल द्वारा एक-दलीय शासन लागू किया गया था, भारत में कांग्रेस का प्रभुत्व एक प्रतिस्पर्धी लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर हुआ। अन्य दलों को चुनाव लड़ने की कानूनी अनुमति थी। कांग्रेस ने व्यापक जनसमर्थन, स्वतंत्रता संग्राम से मिली ऐतिहासिक वैधता और अपनी समावेशी संगठनात्मक संरचना के माध्यम से अपना नेतृत्व और राजनीतिक दबदबा लंबे समय तक बनाए रखा।

8. (A) ई.एम.एस. नंबूदरीपाद
1957 के विधानसभा चुनावों के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी केरल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। ई.एम.एस. नंबूदरीपाद को मंत्रालय का नेतृत्व करने के लिए चुना गया, जिससे वे स्वतंत्र भारत के पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। उनकी सरकार ने महत्वपूर्ण भूमि और शैक्षिक सुधार शुरू किए, हालांकि 1959 में केंद्र सरकार द्वारा विवादास्पद परिस्थितियों में उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था।

9. (B) 2, 1, 3, 4
भारत की राजनीतिक यात्रा में विशिष्ट क्रम में कई आधारभूत मील के पत्थर शामिल थे। सबसे पहले जनवरी 1950 में संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। इसके तुरंत बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया की देखरेख के लिए चुनाव आयोग की स्थापना की गई। पहला आम चुनाव 1951-52 में आयोजित किया गया था, जिसके वर्षों बाद केरल सरकार को बर्खास्त किया गया था।

10. (B) केवल 1, 2, 3 और 4
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में जयप्रकाश नारायण और राममनोहर लोहिया जैसे नेताओं द्वारा किया गया था जो लोकतांत्रिक समाजवाद में विश्वास करते थे। 1948 में दोहरी सदस्यता से जुड़े बदलाव के बाद उन्होंने स्वतंत्र सोशलिस्ट पार्टी बनाई। हालांकि उन्होंने सरकार की कड़ी वैचारिक आलोचना

प्रणाली एकल मतपत्र द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पहले दो चुनावों तक जारी रही। बहुत बाद में 1990 के दशक में चुनाव आयोग ने प्रक्रिया को आधुनिक बनाने और वोटों की तेजी से गिनती सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें शुरु कीं।

76. (B) सोशलिस्ट पार्टी
1955 में कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अपने अवादी अधिवेशन में 'समाजवादी बनावट वाले समाज' के लक्ष्य को अपनाया। इस कदम ने सोशलिस्ट पार्टी के लिए एक बड़ी दुविधा पैदा कर दी क्योंकि सत्ताधारी दल अब उसी वैचारिक स्थान का दावा कर रहा था। समाजवादियों के लिए खुद को अलग पहचानना और उस सरकार के लिए एक विश्वसनीय विकल्प पेश करना मुश्किल हो गया जो स्वयं समाजवादी उद्देश्यों का प्रचार कर रही थी।

77. (C) सोशलिस्ट पार्टी ने दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बहुमत हासिल किया।
1952 के चुनाव परिणामों ने कांग्रेस की भारी लोकप्रियता की पुष्टि की जिसने 364 सीटें जीतीं और जवाहरलाल नेहरु के नेतृत्व में सरकार बनाई। जबकि कई लोगों को उम्मीद थी कि सोशलिस्ट पार्टी मुख्य चुनौती होगी, वास्तव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 16 सीटों के साथ सबसे बड़े विपक्षी समूह के रूप में उभरी। समाजवादी अच्छे वोट शेयर के बावजूद बहुत कम सीटें ही हासिल कर पाए थे।

78. (B) P-2, Q-3, R-1, S-4
20वीं सदी की शुरुआत में प्रभावशाली नेताओं द्वारा कई राजनीतिक दलों की स्थापना की गई थी। डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन दोनों की स्थापना की। आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख संस्थापक थे। इस बीच भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी, जो भारतीय राजनीति में एक अलग दक्षिणपंथी वैचारिक धारा का प्रतिनिधित्व करता था।

79. (B) 3, 1, 4, 2
भारत में पहला आम चुनाव 1951–52 में आयोजित किया गया, जो स्वतंत्र भारत का पहला लोकतांत्रिक चुनाव था। इसके बाद 1957 में दूसरा आम चुनाव हुआ। उसी वर्ष 1957 में केरल में ई.एम.एस. नंबूदरीपाद के नेतृत्व में पहली लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार का गठन हुआ। इसके बाद 1962 में तीसरा आम चुनाव आयोजित किया गया, इसलिए सही कालानुक्रम 3, 1, 4, 2 है।

80. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
शुरुआती स्वतंत्र भारत के दौरान सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं के बीच उच्च स्तर का पारस्परिक सम्मान था। इसका मुख्य कारण यह था कि उनमें से कई स्वतंत्रता के लंबे संघर्ष में साथी रहे थे। सहयोग की यह भावना तब दिखाई दी जब जवाहरलाल नेहरु ने डॉ. अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे प्रमुख विपक्षी हस्तियों को अपने पहले मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था।

81. (A) केवल 1, 2, 3 और 5
कम्युनिस्ट पार्टी का एक जटिल इतिहास रहा है जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन को समर्थन देने के मुद्दे पर अलग होने से पहले कांग्रेस के भीतर काम करने की अवधि भी शामिल थी। 1947 के बाद उन्होंने शुरु में भारतीय स्वतंत्रता की वास्तविकता पर सवाल उठाया और तेलंगाना में सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया। हालांकि वे अंततः मुख्यधारा की राजनीति में शामिल हो गए लेकिन 1964 में वैचारिक मतभेदों के कारण पार्टी विभाजित हो गई।

82. (A) आजादी के समय तक यह पार्टी संगठनात्मक रूप से देशव्यापी हो चुकी थी।
आजादी के समय तक कांग्रेस पार्टी को अन्य सभी राजनीतिक समूहों पर भारी बढ़त हासिल थी। इसके पास एक अच्छी तरह से स्थापित संगठनात्मक नेटवर्क था जो भारत के लगभग हर गाँव और शहर तक फैला हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन के दशकों के दौरान बनी इस व्यापक उपस्थिति ने पार्टी को किसी भी नवगठित या क्षेत्रीय विपक्ष की तुलना में मतदाताओं को अधिक प्रभावी ढंग से लामबंद करने की अनुमति दी।

83. (C) दीनदयाल उपाध्याय
दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के एक प्रमुख विचारक और नेता थे जिन्होंने 'एकात्म मानववाद' का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत ने भारत के लिए एक स्वदेशी वैचारिक ढांचा प्रदान करने की कोशिश की जो पूंजीवाद और समाजवाद से परे हो। उन्होंने एक समग्र दृष्टिकोण पर जोर दिया जो राष्ट्रीय संदर्भ में प्रत्येक मानव की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं पर विचार करता था।

84. (D) आचार्य नरेंद्र देव
आचार्य नरेंद्र देव एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे जिन्होंने राजनीतिक सक्रियता को गहरी विद्वत्ता के साथ जोड़ा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक के रूप में वे स्वतंत्रता आंदोलन और भारत में समाजवादी विचार के विकास में एक प्रमुख व्यक्ति थे। वे बौद्ध धर्म के एक प्रसिद्ध विद्वान भी थे, जो प्रारंभिक समाजवादी आंदोलन के नेतृत्व के बीच अक्सर पाई जाने वाली बौद्धिक गहराई को दर्शाता है।

85. (C) गुटों ने आंतरिक प्रतिस्पर्धा प्रदान की, जिससे वे पार्टी के भीतर बने रहे।
कांग्रेस पार्टी के भीतर गुटों के अस्तित्व ने आंतरिक नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था प्रदान करके एक महत्वपूर्ण कार्य किया। नए दल बनाने के बजाय विभिन्न समूहों ने कांग्रेस के भीतर प्रभाव और शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा की। इस आंतरिक प्रतिस्पर्धा का मतलब था कि पार्टी हमेशा अपनी नीतियों पर बहस और समायोजन कर रही थी, जिससे यह अधिक लचीली बन गई और बाहरी विपक्ष का मुकाबला कर सकी।

था कि पार्टी आमतौर पर समझौते और संतुलन के माध्यम से मध्य मार्ग खोजना पसंद करती थी। अपने ढांचे के भीतर विभिन्न गुटों को शामिल करके पार्टी ने शुरुआती दशकों के दौरान राजनीतिक स्थिरता और व्यापक आधार वाला समर्थन बनाए रखा।

22. (B) 364
1952 में आयोजित ऐतिहासिक पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। लोकसभा की कुल 489 सीटों में से पार्टी ने 364 सीटें जीतीं। इस भारी बहुमत ने राष्ट्रीय स्तर पर एक-दलीय प्रभुत्व का काल स्थापित किया, जिससे पार्टी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु के नेतृत्व में आराम से सरकार बनाने में सक्षम हुई और अगले कई वर्षों तक देश की राजनीति को दिशा प्रदान की।

23. (C) P-3, Q-4, R-1, S-2
शुरुआती भारतीय चुनावों में निरक्षर मतदाताओं के लिए राजनीतिक दलों की पहचान करने में प्रतीकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस ने दो बैलों की जोड़ी का उपयोग किया, जबकि सोशलिस्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व बरगद के पेड़ द्वारा किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने हँसिया और बालियों का उपयोग किया और भारतीय जनसंघ की पहचान मिट्टी के दीपक से की गई थी, जो ग्रामीण जनता के बीच लोकप्रिय हुए।

24. (A) वह कालखंड जिसमें कांग्रेस ने शासक दल और विपक्ष दोनों की भूमिका निभाई।
'कांग्रेस प्रणाली' शब्द भारतीय राजनीति की उस अनूठी अवधि का वर्णन करता है जहाँ कांग्रेस पार्टी ने सरकार और राजनीतिक विमर्श दोनों पर अपना दबदबा बनाए रखा। चूँकि पार्टी एक व्यापक गठबंधन थी जिसमें कई आंतरिक गुट शामिल थे, ये समूह अक्सर पार्टी के भीतर ही एक-दूसरे का विरोध करते थे। परिणामस्वरूप पार्टी ने प्रभावी ढंग से शासक और आंतरिक विपक्ष दोनों के कार्य किए।

25. (A) 2, 1, 3, 4
आजादी के बाद भारतीय राजनीतिक दलों का विकास एक निश्चित समयरेखा के अनुसार हुआ। समाजवादी 1948 में कांग्रेस से अलग हो गए, जिसके बाद 1951 में भारतीय जनसंघ का गठन हुआ। बाद में 1957 में केरल में पहली गैर-कांग्रेसी राज्य सरकार का गठन हुआ। अंततः वैचारिक मतभेदों के कारण 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी का औपचारिक रूप से दो अलग-अलग संस्थाओं में विभाजन हो गया, जिससे नया राजनीतिक समीकरण बना।

26. (A) 1934
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक अलग समूह के रूप में की गई थी। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव जैसे इसके संस्थापक राष्ट्रीय आंदोलन को अधिक कट्टरपंथी सामाजिक और आर्थिक नीतियों की ओर ले जाना चाहते थे। वे 1948 तक कांग्रेस का हिस्सा बने रहे जब दोहरी सदस्यता से जुड़े एक नियम परिवर्तन ने उन्हें अलग होने के लिए मजबूर कर दिया।

27. (D) प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक अलग मतपेटी।
पहले आम चुनाव के दौरान मतदान की प्रक्रिया निरक्षर मतदाताओं के लिए सरल बनाई गई थी। प्रत्येक उम्मीदवार को उनके विशिष्ट चुनाव चिह्न के साथ एक अलग मतपेटी सौंपी गई थी। मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार के बक्से में डालने के लिए एक खाली मतपत्र दिया जाता था, जिससे यह सुनिश्चित होता था कि वे बिना किसी नाम को पढ़े अपनी पसंद के अनुसार मतदान कर सकें।

28. (A) केवल 1, 2 और 4
भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और लोकतांत्रिक शासन की तैयारी के लिए उसी महीने चुनाव आयोग की स्थापना की गई। हालांकि आयोग ने शुरु में तत्काल चुनाव की उम्मीद की थी, लेकिन 17 करोड़ मतदाताओं को पंजीकृत करने के विशाल कार्य में देरी हुई। परिणामस्वरूप पहले आम चुनाव 1952 तक पूरे नहीं हो सके थे, हालांकि इसकी आधारभूमि काफी पहले तैयार हो चुकी थी।

29. (C) हिंदू कोड बिल
डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में कार्य किया और संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि उन्होंने 1951 में हिंदू कोड बिल पर महत्वपूर्ण मतभेदों के कारण जवाहरलाल नेहरु के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने महसूस किया कि सरकार इन सुधारों को पारित करने के लिए पर्याप्त प्रतिबद्ध नहीं थी, जिनका उद्देश्य हिंदू कानूनों को आधुनिक बनाना था।

30. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
1952 के चुनावों में सोशलिस्ट पार्टी ने लगभग दस प्रतिशत वोट हासिल किए लेकिन बहुत कम सीटें जीतीं। यह परिणाम उस चुनावी प्रणाली का प्रत्यक्ष परिणाम था जहाँ गैर-कांग्रेसी उम्मीदवारों के वोट कई दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों के बीच बँट गए थे। चूँकि विपक्ष अपने समर्थन को मजबूत करने में विफल रहा, कांग्रेस ने वोटों के अल्पसंख्यक हिस्से के साथ भी अधिकांश सीटें जीत लीं।

31. (B) केवल 1, 2, 4 और 5
1952 और 1967 के बीच कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखी। हालांकि केरल जैसे अपवाद भी थे जहाँ 1957 में कम्युनिस्टों ने सरकार बनाई। साथ ही जम्मू और कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस का स्थानीय दबदबा था। इन क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद समग्र राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य कांग्रेस की भारी उपस्थिति और केंद्रीय प्रभाव द्वारा ही परिभाषित और संचालित होता रहा।

32. (B) डॉ. भीमराव अंबेडकर
डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की वकालत करने के लिए 'शिडयूल्ड कास्टस्

की, लेकिन वे पहले तीन चुनावों में कांग्रेस को हराकर बहुमत हासिल करने में सफल नहीं हो सके थे।

11. (D) 'सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत' वाली विशिष्ट चुनाव प्रणाली।
पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कुल वोटों के आधे से भी कम मिलने के बावजूद सीटों का भारी बहुमत हासिल किया। यह विसंगति इसलिए हुई क्योंकि भारत ने 'सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत' वाली चुनावी प्रणाली अपनाई थी। इस व्यवस्था में जिस उम्मीदवार को निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट मिलते हैं वह जीत जाता है, भले ही सभी विपक्षी उम्मीदवारों के संयुक्त वोट अधिक हों।

12. (B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
भारतीय जनसंघ एक ऐसा राजनीतिक दल था जिसने भारत और पाकिस्तान को मिलाकर 'अखंड भारत' बनाने की वकालत की थी। इसने अलग से इस बात पर जोर दिया कि देश को स्वदेशी भारतीय संस्कृति और परंपराओं के आधार पर आधुनिक और मजबूत बनना चाहिए। हालांकि दोनों स्थितियाँ पार्टी के मंच के लिए केंद्रीय थीं, लेकिन पुनर्मिलन का लक्ष्य आधुनिकीकरण का सीधा तार्किक परिणाम नहीं था।

13. (C) राजकुमारी अमृत कौर
राजकुमारी अमृत कौर एक प्रमुख गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थीं जिन्होंने स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य किया। कपूरथला के राजपरिवार में जन्मी कौर ने संविधान सभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके कार्यकाल में आधुनिक चिकित्सा संस्थानों की स्थापना और नए स्वतंत्र राष्ट्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों के लिए उन्हें सदैव याद किया जाता है।

14. (B) P-4, Q-3, R-1, S-2
शुरुआती भारतीय राजनीति में विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े विविध नेता शामिल थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जबकि मीनू मसानी स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख नेता थे। एस.ए. डांगे ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया और अशोक मेहता प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता थे। यह उस युग के विस्तृत राजनीतिक स्पेक्ट्रम और विभिन्न वैचारिक धाराओं को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

15. (D) 1, 2, 3 और 4
1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक कुलीन दबाव समूह से एक जन आंदोलन के रूप में विकसित हुई। आजादी तक यह एक व्यापक सामाजिक गठबंधन बन गई थी जिसमें वामपंथियों से लेकर दक्षिणपंथियों तक विविध विचारधाराएं शामिल थीं। इस समावेशी प्रकृति ने विभिन्न आंतरिक समूहों को जिन्हें गुट कहा जाता था, साथ रहने की अनुमति दी जिससे पार्टी जटिल भारतीय समाज का एक छोटा रूप बन गई।

16. (B) अनुच्छेद 356
1959 में केंद्र सरकार ने केरल में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 का आह्वान किया। यह कदम विपक्षी समूहों के नेतृत्व में 'मुक्ति संघर्ष' के रूप में जाने जाने वाले गहन स्थानीय आंदोलन के बाद उठाया गया था। यह घटना भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि यह आपातकालीन शक्तियों का पहला विवादास्पद उपयोग था।

17. (B) लगभग 40 लाख महिलाओं के नाम पारिवारिक रिश्तों के आधार पर दर्ज थे।
जब पहले आम चुनाव के लिए मतदाता सूची का पहला प्रारूप तैयार किया गया, तो एक बड़ी समस्या सामने आई। लगभग 40 लाख महिलाओं को उनके अपने नाम के बजाय 'फलां की माँ' या 'फलां की पत्नी' के रूप में दर्ज किया गया था। चुनाव आयोग ने व्यक्तिगत पहचान पर जोर देते हुए इन प्रविष्टियों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता बनी रहे।

18. (A) भारत में सार्वभौम मताधिकार के प्रयोग के संदर्भ में।
अत्यधिक गरीबी और निरक्षरता वाले देश में प्रत्येक वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार देने के निर्णय को कई लोगों ने संदेह की दृष्टि से देखा। एक प्रमुख संपादक ने प्रसिद्ध रूप से इस प्रयोग को 'इतिहास का सबसे बड़ा जुआ' बताया था। कई आलोचकों का मानना था कि ऐसी परिस्थितियों में सफल लोकतांत्रिक चुनाव असंभव था, फिर भी चुनावों के सुचारु संचालन ने उन्हें गलत साबित कर दिया।

19. (C) श्यामा प्रसाद मुखर्जी
अंतरिम सरकार के पूर्व मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। पार्टी की विचारधारा 'एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र' की अवधारणा पर केंद्रित थी। मुखर्जी के नेतृत्व ने भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं पर जोर देते हुए और कश्मीर के विशेष दर्जे का विरोध करते हुए प्रभुत्वशाली कांग्रेस पार्टी को एक दक्षिणपंथी विकल्प प्रदान किया, जिसने भविष्य की राजनीति को प्रभावित किया।

20. (A) केवल 1, 2 और 3
शुरुआती स्वतंत्र भारत में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व में कई कारकों ने योगदान दिया। इसे स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने की अपार प्रतिष्ठा प्राप्त थी और इसके पास एक राष्ट्रव्यापी संगठनात्मक नेटवर्क था जो जमीनी स्तर तक पहुँचता था। इसके अतिरिक्त पार्टी को जवाहरलाल नेहरु जैसे करिश्माई नेताओं के नेतृत्व से लाभ हुआ जिन्हें देश के विभिन्न वर्गों में व्यापक जनसमर्थन और विश्वास प्राप्त था।

21. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
कांग्रेस पार्टी ने एक व्यापक गठबंधन के रूप में कार्य किया जिसने उसे विविध हितों और दृष्टिकोणों को समायोजित करने की असाधारण क्षमता दी। इसके सतरंगे स्वभाव का मतलब

43. (D) मौलाना अबुल कलाम आजाद
मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। वे इस्लाम के विद्वान और हिंदू-मुस्लिम एकता के कट्टर समर्थक थे। स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता के रूप में उन्होंने भारत के विभाजन का कड़ा विरोध किया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान पर जोर देते हुए और उन संस्थानों की स्थापना करते हुए देश की शैक्षिक नींव बनाने पर ध्यान केंद्रित किया।

44. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
शुरुआती स्वतंत्र भारत को विभिन्न विशेष भूमिकाओं में व्यक्तियों द्वारा आकार दिया गया था। सुकुमार सेन ने पहले चुनाव आयुक्त के रूप में चुनावों का प्रबंधन किया। ई.एम.एस. नंबूदरीपाद ने केरल में पहली कम्युनिस्ट सरकार का नेतृत्व किया। राजकुमारी अमृत कौर ने मंत्री के रूप में राष्ट्र के स्वास्थ्य की देखरेख की, जबकि दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के लिए एक प्रमुख वैचारिक नेता और संगठनकर्ता के रूप में उभरे।

45. (A) केवल 2 और 4
हालांकि कांग्रेस पार्टी ने पहले तीन आम चुनावों में दबदबा बनाए रखा और प्रत्येक बार लोकसभा की तीन-चौथाई सीटें जीतीं, लेकिन उसे कभी भी कुल लोकप्रिय वोट का आधे से अधिक हिस्सा नहीं मिला। इसके अलावा राज्य स्तर पर इसका प्रभुत्व पूर्ण नहीं था; उदाहरण के लिए 1957 में कम्युनिस्टों ने केरल में सरकार बनाई जिससे पता चला कि चुनावी प्रतिस्पर्धा वास्तविक थी और वैकल्पिक परिणाम संभव थे।

46. (D) उन्होंने शासक दल पर अंकुश रखकर लोकतांत्रिक विकल्प बनाए रखा।
संख्या में कम होने के बावजूद विपक्षी दलों ने भारतीय लोकतंत्र के शुरुआती दशकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सरकारी नीतियों की सुविचारित आलोचना की और सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी को निरंतर जांच के दायरे में रखा। वैकल्पिक दृष्टिकोण पेश करके उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि व्यवस्था का लोकतांत्रिक चरित्र बना रहे और मतदाताओं के लिए हमेशा एक राजनीतिक विकल्प मौजूद रहे, जिससे लोकतंत्र जीवंत बना रहा।

47. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
आजादी से पहले कांग्रेस पार्टी एक पारंपरिक राजनीतिक दल के बजाय एक व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन की तरह काम करती थी। इसने एक साझा मंच प्रदान किया जहाँ विभिन्न हित समूह, सामाजिक संगठन और यहाँ तक कि अलग राजनीतिक झुकाव वाले लोग राष्ट्रीय मुक्ति के लिए एक साथ आ सकते थे। एक समावेशी 'छाता' संगठन के रूप में इस ऐतिहासिक भूमिका ने आजादी के बाद भी इसकी प्रकृति को प्रभावित किया।

48. (B) समाजवादियों को पार्टी से बाहर करने के लिए।
1948 में कांग्रेस पार्टी ने अपने सदस्यों को एक साथ किसी अन्य राजनीतिक संगठन की सदस्यता रखने से रोकने के लिए अपने आंतरिक संविधान में संशोधन किया। यह कदम विशेष रूप से समाजवादियों को मजबूर करने के लिए बनाया गया था, जो कांग्रेस के भीतर एक अलग समूह के रूप में काम करते थे। परिणामस्वरूप समाजवादियों ने कांग्रेस से बाहर निकलने और एक स्वतंत्र राजनीतिक दल बनाने का कठिन निर्णय लिया।

49. (B) केवल 2
भारतीय जनसंघ ने राष्ट्रीय पहचान और संस्कृति पर विशिष्ट विचार रखते हुए अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने की वकालत की। चीन के परमाणु परीक्षण के बाद पार्टी ने भारत को अपने स्वयं के परमाणु हथियार विकसित करने के लिए भी पुरजोर समर्थन दिया। महत्वपूर्ण रूप से पार्टी ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने का विरोध किया और इसके बजाय एक एकीकृत राष्ट्रीय संस्कृति का पक्ष लिया।

50. (A) मुक्ति संघर्ष
1957 के चुनावों में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत के बाद राज्य कांग्रेस और अन्य समूहों ने 'मुक्ति संघर्ष' के रूप में जाना जाने वाला एक विशाल विरोध आंदोलन शुरू किया। उन्होंने सरकार के क्रांतिकारी भूमि और शिक्षा सुधारों का विरोध किया। तीव्र सामाजिक और राजनीतिक अशांति की इस अवधि के कारण अंततः केंद्र द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, जिससे संघीय ढांचे पर बहस शुरू हुई।

51. (C) डॉ. भीमराव अंबेडकर
डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने मजदूर वर्ग और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। उनका मानना था कि सामाजिक सुधार और दलितों के उत्थान के लिए राजनीतिक शक्ति आवश्यक है। यह पार्टी उन कई संगठनों में से एक थी जिन्हें उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया था कि राजनीति में मजदूरों की आवाज सुनी जाए।

52. (D) भारतीय जनता पार्टी
आजादी के बाद के पहले तीन दशकों के दौरान भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में स्वतंत्र पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय जनसंघ जैसे दल शामिल थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस अवधि के दौरान अस्तित्व में नहीं थी। बीजेपी का गठन बहुत बाद में 1980 में जनता पार्टी के विघटन के बाद हुआ था, हालांकि इसकी जड़ें पहले के भारतीय जनसंघ से जुड़ी हुई मानी जाती हैं।

53. (C) आचार्य नरेन्द्र देव - स्वतंत्र पार्टी
आचार्य नरेंद्र देव समाजवादी आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति थे और उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक नेता के रूप में कार्य किया था, न कि स्वतंत्र पार्टी के। इसके विपरीत श्यामा प्रसाद मुखर्जी सही ढंग से जनसंघ से जुड़े हैं, ई.एम. एस. नंबूदरीपाद कम्युनिस्ट पार्टी से और राजकुमारी अमृत कौर राष्ट्रीय मंत्रिमंडल में पहली स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अपनी भूमिका से जुड़ी हुई हैं, जो ऐतिहासिक तथ्य है।

फेडरेशन' की स्थापना की थी। यह संगठन बाद में उनकी मृत्यु के बाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के रूप में विकसित हुआ। अपने पूरे जीवन के दौरान अंबेडकर जाति व्यवस्था के खिलाफ अथक अभियान चलाते रहे और यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों की आवाज सुनी जाए।

33. (B) चीन और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक अंतर
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में 1964 में औपचारिक विभाजन हुआ जिसके परिणामस्वरूप सीपीआई और सीपीआई-एम का निर्माण हुआ। यह विभाजन मुख्य रूप से सोवियत संघ और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय वैचारिक संघर्ष से प्रेरित था। एक गुट सोवियत विचारधारा के प्रति वफादार रहा, जबकि दूसरा गुट कांग्रेस का अधिक आलोचक था और चीन से जुड़े क्रांतिकारी दृष्टिकोण के साथ जुड़ा हुआ था, जिसने वामपंथ को विभाजित किया।

34. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
भारतीय राजनीतिक इतिहास की प्रमुख घटनाएँ 20वीं सदी के मध्य में विभिन्न समयों पर हुईं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन पहली बार 1934 में हुआ था और भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी। पहला आम चुनाव 1952 में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बाद में 1959 में केंद्र सरकार ने केरल में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त करने का विवादास्पद निर्णय लिया था।

35. (C) डॉ. भीमराव अंबेडकर
डॉ. बी.आर. अंबेडकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन के पीछे प्राथमिक दूरदर्शी नेता थे। उनका इरादा इस पार्टी को सभी हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए सामाजिक और राजनीतिक न्याय मांगने हेतु एक मंच के रूप में उपयोग करने का था। हालांकि 1957 में पार्टी के औपचारिक रूप से स्थापित होने से पहले ही उनका निधन हो गया, लेकिन उनके अनुयायियों ने उनकी योजना को आगे बढ़ाया।

36. (D) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
1952 में आयोजित पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लोकसभा में सबसे महत्वपूर्ण विपक्षी शक्ति के रूप में उभरी। जबकि कांग्रेस ने भारी बहुमत जीता, सीपीआई ने 16 सीटें हासिल कीं जिससे वह दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इस उपलब्धि ने राष्ट्रीय गठबंधन के प्रभुत्व के बावजूद भारतीय संसद में वामपंथी राजनीति की शुरुआती और मजबूत उपस्थिति को स्पष्ट रूप से दुनिया के सामने स्थापित किया।

37. (B) केवल 3 और 4
भारत में समाजवादी आंदोलन के विभिन्न नेताओं ने कांग्रेस के साथ बातचीत करने के तरीके पर अलग-अलग विचार रखे। जहाँ अशोक मेहता जैसे कुछ नेताओं ने सत्ताधारी दल के साथ सीमित सहयोग का सुझाव दिया, वहीं राममनोहर लोहिया जैसे अन्य कट्टर आलोचक थे जिन्होंने स्पष्ट दूरी बनाए रखने की वकालत की। इस आंदोलन की विशेषता बार-बार होने वाले विभाजन और विलय थे क्योंकि विभिन्न समूहों ने अपनी पहचान बनाई।

38. (B) डॉ. भीमराव अंबेडकर
डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने लोकतंत्र में करिश्माई नेतृत्व की भूमिका के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने चेतावनी दी कि राजनीति में नायक-पूजा या 'भक्ति' पतन और अंततः तानाशाही का एक निश्चित रास्ता है। उनका मानना था कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों को व्यक्तियों के प्रति अंध भक्ति के बजाय संवैधानिक सिद्धांतों पर भरोसा करना चाहिए।

39. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
भारत के समान ही स्वतंत्र हुए कई देशों ने सैन्य शासन या एक-दलीय राज्य जैसी गैर-लोकतांत्रिक प्रणालियों को चुना। उनके नेताओं ने तर्क दिया कि लोकतंत्र आंतरिक विभाजन और संघर्ष पैदा करेगा जिसे उनके नाजुक राष्ट्र वहन नहीं कर सकते। उन्होंने विकास और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एकल एकीकृत प्राधिकरण की आवश्यकता पर विश्वास करते हुए राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बजाय राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी थी।

40. (A) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम)
भारत ने कई दशकों में पारंपरिक मतपत्रों से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की ओर रुख किया। हालाँकि प्रयोग 1990 के दशक के उत्तरार्ध में शुरु हुए थे, लेकिन 2004 के आम चुनावों तक पूरे देश में ईवीएम का उपयोग मानक बन गया था। इस बदलाव का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को आधुनिक बनाना, कागज के उपयोग को कम करना और मतदान के परिणामों की गिनती और घोषणा में तेजी लाना था।

41. (C) किसान, उद्योगपति, शहरी, ग्रामीण, मजदूर, मालिक सभी का समावेश।
कांग्रेस पार्टी ने विभिन्न पृष्ठभूमि और आर्थिक हितों के लोगों को शामिल करके एक व्यापक सामाजिक गठबंधन के रूप में कार्य किया। इसकी श्रेणी में शहरी उद्योगपतियों के साथ ग्रामीण किसान और कम मजदूरी वाले मजदूरों के बगल में धनी जमींदार पाए जा सकते थे। इस समावेशी दृष्टिकोण ने पार्टी को भारतीय समाज के एक विस्तृत वर्ग का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी, जिससे इसे विविध समूहों में समर्थन मिला।

42. (A) 3, 1, 4, 2
गणराज्य के शुरुआती वर्षों में कई प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम एक विशिष्ट क्रम में हुए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। आजादी के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1950 में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, जिसके बाद 1951 में जनसंघ का गठन हुआ। अंततः डॉ. अंबेडकर ने सामाजिक सुधार कानूनों से संबंधित असहमति के कारण उसी वर्ष अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

पेश कीं, भले ही उनका छोटा आकार उनके लोकतांत्रिक चरित्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने का एकमात्र कारण नहीं था।

65. (B) जयप्रकाश नारायण
स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू ने एक समावेशी अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया जिसमें डॉ. बी.आर. अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमियों के नेता शामिल थे। हालांकि प्रमुख समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण सरकार में शामिल नहीं हुए। वे औपचारिक सत्ता संरचना से बाहर रहे और इसके बजाय पूरे देश में समाजवादी आंदोलन बनाने और सामाजिक एवं राजनीतिक सक्रियता में शामिल होने पर अपना ध्यान केंद्रित किया।

66. (B) P-4, Q-1, R-2, S-3
शुरुआती राजनीतिक परिदृश्य को विभिन्न दलों के प्रमुख नेताओं द्वारा परिभाषित किया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ का नेतृत्व किया और जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी का। राममनोहर लोहिया सोशलिस्ट पार्टी के एक अग्रणी व्यक्ति थे, जबकि ए.के. गोपालन कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एक प्रमुख आवाज थे। इन व्यक्तियों ने नए स्वतंत्र भारतीय राष्ट्र के माध्यम से बहने वाली विविध वैचारिक धाराओं का प्रतिनिधित्व किया।

67. (C) उन्होंने कांग्रेस से अपनी दूरी बढ़ाई और उसकी आलोचना की।
राममनोहर लोहिया एक कट्टर समाजवादी नेता थे जिन्होंने गैर-कांग्रेसवाद की नीति की वकालत की थी। उनका मानना था कि कांग्रेस पार्टी धनी और विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए गरीबों की जरूरतों को पूरा करने में विफल रही है। परिणामस्वरुप उन्होंने समाजवादियों से कांग्रेस से स्पष्ट दूरी बनाए रखने और इसकी नीतियों की जोरदार आलोचना और विरोध करने का आग्रह किया था।

68. (D) डॉ. भीमराव अंबेडकर
1956 में अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने नागपुर में एक विशाल समारोह में अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था। उन्होंने बौद्ध धर्म को इसलिए चुना क्योंकि उनका मानना था कि यह समानता और गरिमा का मार्ग प्रदान करता है जो हिंदू धर्म की जातिगत संरचना के भीतर दलितों को नहीं मिलता था। यह घटना सामाजिक न्याय आंदोलनों में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।

69. (B) केवल 2 और 4
कांग्रेस पार्टी के भीतर गुटों की उपस्थिति एक परिभाषित विशेषता थी जिसने वास्तव में इसके प्रभुत्व को बनाए रखने में मदद की। इन आंतरिक समूहों ने विभिन्न विचारधाराओं और हितों को पार्टी छोड़े बिना प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी। आंतरिक संतुलन तंत्र के रूप में कार्य करके गुटों ने यह सुनिश्चित किया कि पार्टी लचीली और समावेशी बनी रहे, जिससे शुरुआती दशकों में किसी शक्तिशाली बाहरी विपक्ष का उदय नहीं हुआ।

70. (B) महात्मा गाँधी
महात्मा गांधी का मानना था कि कांग्रेस की प्राथमिक शक्ति विविध समूहों और हितों को समायोजित करने की इसकी क्षमता में निहित है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पार्टी ने कभी भी अपने समावेशी और 'सबको समेटकर चलने वाले' स्वभाव को छोड़ दिया, तो वह अपनी प्रासंगिकता खो देगी और अंततः समाप्त हो जाएगी। पार्टी के लिए उनका दृष्टिकोण एक व्यापक राष्ट्रीय मोर्चे का था जो सभी भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर सके।

71. (D) कांग्रेस से हल्के-फुल्के सहयोग की तरफदारी।
समाजवादी आंदोलन के भीतर अशोक मेहता ने उस गुट का प्रतिनिधित्व किया जो कांग्रेस पार्टी के प्रति अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण का पक्षधर था। उन्होंने तर्क दिया कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों को देखते हुए समाजवादियों को कुछ मुद्दों पर सरकार के साथ सीमित सहयोग के लिए तैयार रहना चाहिए। यह दृष्टिकोण अक्सर उन्हें अधिक कट्टरपंथी समाजवादी नेताओं के साथ खड़ा करता था जो कांग्रेस के पूर्ण विरोध की वकालत करते थे।

72. (C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
यह ऐतिहासिक रुप से सटीक है कि पहले तीन आम चुनावों के दौरान भारतीय राजनीति में कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा। हालाँकि यह इसलिए नहीं था क्योंकि अन्य दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था; वास्तव में भारत में एक जीवंत बहुदलीय प्रणाली थी जहाँ विभिन्न विपक्षी दल चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र थे। कांग्रेस ने अपने व्यापक संगठनात्मक विस्तार, जनसमर्थन और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत के कारण अपना नेतृत्व बनाए रखा।

73. (C) त्रावणकोर-कोचीन, मद्रास और उड़ीसा
हालांकि कांग्रेस पार्टी ने 1952 में केंद्र में बहुमत जीता, लेकिन उसे कई राज्यों में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। त्रावणकोर-कोचीन, मद्रास और उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में गैर-कांग्रेसी दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने काफी संख्या में सीटें हासिल कीं। इन क्षेत्रों में कांग्रेस शुरू में पूर्ण बहुमत हासिल करने में विफल रही, हालांकि बाद में उसने अन्य समूहों के समर्थन से गठबंधन सरकारें बनाने में सफलता प्राप्त की थी।

74. (A) भारतीय जनसंघ
'एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र' की विचारधारा भारतीय जनसंघ का आधारभूत सिद्धांत थी। पार्टी ने भारतीय सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्यों पर आधारित राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता पर बल दिया। इसका मानना था कि एक मजबूत, आधुनिक भारत केवल अपनी स्वदेशी जड़ों से ताकत हासिल करके और पश्चिमीकरण को अस्वीकार करके ही बनाया जा सकता है, जिससे राष्ट्रीय गौरव और अखंडता सुनिश्चित हो सके।

75. (A) केवल 1, 2 और 4
पहले आम चुनाव में 20 लाख स्टील के बक्सों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें प्रत्येक बक्सा एक विशिष्ट उम्मीदवार को समर्पित था और उनके प्रतीक के साथ चिह्नित था। यह

देश की सबसे महत्वपूर्ण और सुव्यवस्थित राजनीतिक शक्ति बन चुकी थी।

97. (B) चुनाव परिणामों को हारने वाले उम्मीदवारों ने भी निष्पक्ष बताया।
पहले आम चुनाव भारतीय लोकतंत्र के लिए एक जबरदस्त सफलता थे। योग्य मतदाताओं में से आधे से अधिक ने अपना वोट डालने के लिए मतदान किया, जो एक बड़े पैमाने पर निरक्षर आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हारने वाले उम्मीदवारों और विपक्षी दलों ने भी स्वीकार किया कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी थी, जिससे अंतरराष्ट्रीय आलोचकों के संदेह पूरी तरह दूर हो गए।

98. (C) केवल 3
हालांकि कांग्रेस शहरी शिक्षित अभिजन और उच्च जातियों के दबदबे वाली पार्टी के रूप में शुरु हुई थी, लेकिन गांधी के नेतृत्व वाले आंदोलनों के दौरान इसका सामाजिक आधार काफी विस्तारित हुआ। आजादी के समय तक इसका नेतृत्व और सदस्यता कहीं अधिक विविध हो गई थी। इसने जमींदारों और किसानों जैसे विभिन्न परस्पर विरोधी हित समूहों को सफलतापूर्वक शामिल किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि यह अब संकुचित वर्ग तक सीमित नहीं थी।

99. (A) P-3, Q-1, R-4, S-2
1950 और 60 के दशक कई प्रमुख राजनीतिक मील के पत्थरों से चिह्नित थे। पहले आम चुनाव 1952 में हुए, जिसने लोकतांत्रिक शासन के लिए मंच तैयार किया। 1957 में कम्युनिस्टों ने केरल में जीत हासिल की, लेकिन 1959 में उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। अंततः वर्ष 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी का दो अलग-अलग और वैचारिक रुप से भिन्न संस्थाओं में औपचारिक विभाजन देखा गया, जिसने राजनीति बदली।

100. (B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
भारत एक पार्टी के प्रभुत्व की अवधि का अनुभव करने वाला एकमात्र देश नहीं था; कई राष्ट्रों में समान चरण रहे हैं। हालांकि भारतीय अनुभव अद्वितीय था क्योंकि यह एक जीवंत लोकतंत्र के भीतर हुआ जहाँ अन्य दल प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्वतंत्र थे। जबकि इस लोकतांत्रिक संदर्भ ने भारत को चीन या क्यूबा जैसे देशों से अलग किया, यह तथ्य कि भारत प्रभुत्व में अकेला नहीं था, एक अलग ऐतिहासिक अवलोकन है।

101. (C) शंकर (के. शंकर पिल्लई)
के. शंकर पिल्लई जिन्हें शंकर के नाम से जाना जाता है, एक महान भारतीय कार्टूनिस्ट थे जिन्होंने प्रसिद्ध 'शंकर्स वीकली' की स्थापना की थी। वे अपने तीखे लेकिन निष्पक्ष राजनीतिक व्यंग्य के लिए जाने जाते थे जिसका प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी आनंद लेते थे। 'डोंट स्पेयर मी शंकर' संग्रह में उनके ऐसे कार्टून हैं जिन्होंने अक्सर सरकार और राजनीतिक नेताओं का मजाक उड़ाया, जो उस युग की स्वस्थ लोकतांत्रिक संस्कृति को दर्शाता है।

102. (B) अंतरिम सरकार
1947 में स्वतंत्रता और 1952 में पहले आम चुनाव के बीच भारत का शासन एक अंतरिम सरकार द्वारा चलाया जाता था। इस सरकार का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इसमें विभिन्न राजनीतिक समूहों के प्रतिनिधि शामिल थे। इसकी प्राथमिक भूमिका देश के मामलों का प्रबंधन करना और नए संविधान के तहत पूर्ण लोकतांत्रिक प्रणाली में संक्रमण की देखरेख करना था जो 1950 में लागू हुआ था।

103. (D) 489
1951-52 में आयोजित पहले आम चुनाव के दौरान लोकसभा में कुल 489 सीटें थीं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार के पहले बड़े अभ्यास में इन सीटों पर पूरे देश में चुनाव लड़े गए थे। कांग्रेस पार्टी ने इन सीटों में भारी बहुमत हासिल किया, जिससे उसे मजबूत संसदीय जनादेश के साथ स्वतंत्र भारत की पहली लोकतांत्रिक रुप से निर्वाचित सरकार बनाने का ऐतिहासिक अवसर प्राप्त हुआ था।

104. (A) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
भारतीय राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में 'कांग्रेस' शब्द का प्रयोग लगभग हमेशा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए किया जाता है। उस पार्टी के रूप में जिसने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया और स्वतंत्र भारत के शुरुआती दशकों में दबदबा बनाए रखा, यह राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का पर्याय बन गई। हालांकि अन्य दलों ने बाद में अपने शीर्षक के हिस्से के रुप में कांग्रेस नाम अपनाया, लेकिन मूल संगठन ही ऐतिहासिक विमर्श में प्राथमिक बना रहा।

105. (C) कांग्रेस ने लोकसभा में अपनी पुरानी स्थिति (तीन-चौथाई सीटें) बरकरार रखी।
दूसरे और तीसरे आम चुनाव ने काफी हद तक पहले चुनाव के पैटर्न को दोहराया। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य पर अपना दबदबा बनाए रखा और लोकसभा में अपना विशाल तीन-चौथाई बहुमत बरकरार रखा। हालांकि विपक्षी दल सक्रिय थे और विशिष्ट क्षेत्रों में कुछ जमीन हासिल की, लेकिन वे इस अवधि के दौरान सत्ता पर कांग्रेस की पकड़ को कोई गंभीर राष्ट्रीय चुनौती देने में असमर्थ रहे थे।

106. (A) कांग्रेस पार्टी
'सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत' वाली चुनावी प्रणाली ने शुरुआती दशकों के दौरान कांग्रेस पार्टी को काफी फायदा पहुँचाया। इस प्रणाली में किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए किसी अन्य प्रतिद्वंद्वी से अधिक वोट चाहिए होते हैं। चूंकि विपक्ष के वोट अक्सर कई अलग-अलग दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच बँट जाते थे, इसलिए कांग्रेस लोकप्रिय वोटों के कुल प्रतिशत की तुलना में बहुत अधिक सीटें जीतने में सफल रही।

107. (D) इस सरकार ने अपना पूरा पांच साल का कार्यकाल पूरा किया।
केरल में 1957 की कम्युनिस्ट सरकार भारत में पहली लोकतांत्रिक रुप से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार के रुप में एक

86. (B) यह मुक्त और निष्पक्ष चुनावों के माहौल में कायम हुआ।
भारत में एक-दलीय प्रभुत्व अद्वितीय था क्योंकि इसे जबरदस्ती के बजाय लोकतांत्रिक माध्यमों से हासिल किया गया था। उन कई अन्य देशों के विपरीत जहाँ सत्ताधारी दल ने विपक्ष को खत्म करने के लिए राज्य शक्ति का उपयोग किया, कांग्रेस ने नियमित और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से अपनी स्थिति बनाए रखी। इसका प्रभुत्व लोकप्रिय सहमति, ऐतिहासिक वैधता और एक समावेशी संगठनात्मक संरचना पर आधारित था।

87. (C) P-3, Q-4, R-1, S-2
विभिन्न राजनीतिक अवधारणाएँ और घटनाएँ विशिष्ट समूहों और व्यक्तियों से जुड़ी हुई हैं। रजनी कोठारी ने शुरुआती भारतीय राजनीति का वर्णन करने के लिए 'कांग्रेस प्रणाली' शब्द गढ़ा था। 'मुक्ति संघर्ष' केरल में कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ एक आंदोलन था। 'अखंड भारत' का विचार जनसंघ के लिए केंद्रीय था, जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद सोशलिस्ट पार्टी द्वारा समर्थित मुख्य विचारधारा थी, जिसने राजनीति को एक दिशा दी।

88. (A) मद्रास और उड़ीसा
1952 के पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी मद्रास और उड़ीसा के साथ-साथ त्रावणकोर-कोचीन की विधानसभाओं में पूर्ण बहुमत हासिल करने में विफल रही। इसके बावजूद पार्टी अंततः छोटे दलों और स्वतंत्र सदस्यों का समर्थन हासिल करके इन राज्यों में सरकारें बनाने में सफल रही, जो क्षेत्रीय स्तर पर इसके राष्ट्रीय प्रभुत्व के लिए शुरुआती चुनौतियों को दर्शाता है।

89. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
सोशलिस्ट पार्टी को 1950 और 60 के दशक के दौरान महत्वपूर्ण चुनावी बढ़त हासिल करने में संघर्ष करना पड़ा। इसका एक प्रमुख कारण 1955 में कांग्रेस पार्टी द्वारा आधिकारिक तौर पर 'समाजवादी बनावट वाले समाज' को अपना लक्ष्य घोषित करना था। पहले समाजवादियों द्वारा घेरे गए वैचारिक स्थान में जाकर कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को प्रभावी ढंग से निष्प्रभावी कर दिया और उनके लिए अद्वितीय विकल्प पेश करना कठिन बना दिया।

90. (A) 1964
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) या सीपीआई (एम) का गठन 1964 में मूल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में एक बड़े विभाजन के बाद हुआ था। यह विभाजन अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन और सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनाए जाने वाले सही सामरिक दृष्टिकोण के संबंध में गहरे वैचारिक मतभेदों का परिणाम था। सीपीआई (एम) ने आमतौर पर सोवियत समर्थक गुट की तुलना में अधिक स्वतंत्र और आलोचनात्मक रुख अपनाया था।

91. (A) केवल 1, 2 और 3
मूल सोशलिस्ट पार्टी की विरासत कई आधुनिक भारतीय दलों जैसे समाजवादी पार्टी और राजद में जारी है। पार्टी वैचारिक रूप से कांग्रेस और कम्युनिस्टों दोनों से अलग थी, जिसने सरकार की आलोचना की कि वह जमींदारों और पूंजीपतियों के प्रति बहुत नरम है। हालांकि यह आंदोलन आंतरिक विभाजनों और प्रभुत्वशाली कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने के तरीके पर अलग-अलग विचारों से भी जूझता रहा।

92. (B) डॉ. अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी
राष्ट्रीय एकता के एक उल्लेखनीय संकेत के रूप में जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में ऐसे प्रमुख व्यक्ति शामिल थे जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे। डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने कानून मंत्री के रूप में कार्य किया, जबकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने बाद में जनसंघ की स्थापना की, उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। यह समावेश नए स्वतंत्र राष्ट्र के लिए विविध दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार बनाने की इच्छा को दर्शाता था।

93. (C) जयप्रकाश नारायण
पहले आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की समाजवादी दिशा को मजबूत करने के लिए समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण को अपनी सरकार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि नारायण ने बातचीत की एक श्रृंखला के बाद प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि समाजवादी सरकार से बाहर रहकर और जमीनी स्तर पर आंदोलन बनाकर राष्ट्र की बेहतर सेवा कर सकते हैं।

94. (D) राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के शहरी इलाके
अपने शुरुआती वर्षों के दौरान भारतीय जनसंघ को विशिष्ट भौगोलिक और जनसांख्यिकीय क्षेत्रों में सबसे अधिक चुनावी समर्थन मिला। इसका प्रभाव मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे उत्तर और मध्य भारतीय राज्यों के शहरी क्षेत्रों में केंद्रित था। राष्ट्रीय पहचान और संस्कृति पर पार्टी के जोर ने इन क्षेत्रों में शहरी मध्यम वर्ग और व्यापारियों के बीच काफी प्रभाव डाला था।

95. (A) इसमें केवल एक ही धर्म के लोग शामिल थे।
विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में कांग्रेस पार्टी की पहचान दक्षिणपंथी, वामपंथी और मध्यमार्गी जैसे विविध राजनीतिक झुकाव वाले लोगों के समावेश से परिभाषित होती थी। इसने चरमपंथियों और नरमपंथियों जैसे अलग-अलग स्वभाव वाले लोगों को भी एक साथ लाया। एक ही धर्म तक सीमित होने के विचार के विपरीत पार्टी ने अपने धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर गर्व किया और देश के सभी समुदायों के लोगों का प्रतिनिधित्व किया।

96. (B) 1885
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, जो शुरुआत में शिक्षित भारतीयों के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार तक अपनी चिंताएँ पहुँचाने वाला एक संगठन था। महात्मा गांधी जैसे नेताओं के नेतृत्व में दशकों के दौरान यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक विशाल लोकप्रिय आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने तक यह

54. (B) P-4, Q-1, R-2, S-3
प्रमुख भारतीय नेता विविध पृष्ठभूमियों से आए थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद एक इस्लामी विद्वान और एकता के समर्थक थे। डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने जाति-विरोधी आंदोलनों का नेतृत्व किया और संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता की। राजकुमारी अमृत कौर एक राजपरिवार की गांधीवादी नेता थीं और ए.के. गोपालन एक समर्पित कम्युनिस्ट नेता थे जिन्होंने कई वर्षों तक एक प्रमुख सांसद के रूप में देश की सेवा की।

55. (D) क्योंकि कांग्रेस ने शासक-दल और विपक्ष दोनों की भूमिका निभाई।
भारतीय राजनीति के शुरुआती वर्षों को अक्सर 'कांग्रेस प्रणाली' कहा जाता है क्योंकि पार्टी ने प्रभावी ढंग से पूरे राजनीतिक स्थान को नियंत्रित किया था। अपनी आंतरिक विविधता और विभिन्न गुटों के कारण कांग्रेस ने शासक दल और आंतरिक विपक्ष दोनों के रूप में कार्य किया। इस आंतरिक प्रतिस्पर्धा का मतलब था कि अधिकांश राजनीतिक बहस और नीतिगत बदलाव किसी अन्य दल के बजाय कांग्रेस के भीतर ही हुए।

56. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
भारत में पहले आम चुनाव का आयोजन एक विशाल प्रशासनिक चुनौती थी जिसके कारण मतदान को दो बार स्थगित करना पड़ा। चुनाव आयोग को विशाल जनसंख्या के लिए मतदाता सूची तैयार करनी थी, जिनमें से अधिकांश ने पहले कभी मतदान नहीं किया था। प्रशिक्षित कर्मियों की कमी और कार्य की जटिलता का मतलब था कि तत्काल चुनाव असंभव थे, जिसके लिए व्यापक तैयारी की आवश्यकता थी।

57. (B) केवल 1, 2, 3 और 4
पहला आम चुनाव एक ऐतिहासिक कार्य था जिसमें 17 करोड़ मतदाता शामिल थे, जिनमें से केवल 15 प्रतिशत साक्षर थे। आयोग को लोकसभा के लिए 489 और राज्य विधानसभाओं के लिए 3,000 से अधिक सदस्यों का चुनाव करना था। इसे प्रबंधित करने के लिए तीन लाख से अधिक अधिकारियों और मतदान कर्मचारियों के एक विशाल कार्यबल को प्रशिक्षित करना पड़ा, जो इतिहास का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अभ्यास था।

58. (A) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
जबकि कांग्रेस पार्टी ने 1952 के चुनावों में भारी जीत हासिल की, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सबसे बड़े विपक्षी समूह के रूप में उभरी। लोकसभा में 16 सीटें जीतकर सीपीआई ने प्रदर्शित किया कि देश के विभिन्न हिस्सों में उसका महत्वपूर्ण समर्थन आधार था। इस प्रारंभिक सफलता ने कम्युनिस्टों को प्रभुत्वशाली सत्ताधारी गठबंधन के प्राथमिक वैचारिक और राजनीतिक विकल्प के रूप में स्थापित किया, जिसने संसदीय राजनीति को प्रभावित किया।

59. (A) 3, 1, 2, 4
कांग्रेस के भीतर और बाहर समाजवादी आंदोलन एक विशिष्ट प्रगति के साथ चला। सबसे पहले कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में एक आंतरिक समूह के रूप में हुआ था। बाद में 1948 में कांग्रेस ने दोहरी सदस्यता पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपने संविधान में संशोधन किया, जिससे समाजवादियों को एक अलग दल बनाना पड़ा। अंततः इसके संस्थापकों में से एक आचार्य नरेंद्र देव का 1956 में निधन हो गया।

60. (B) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
स्वतंत्रता के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मानना था कि 1947 में मिली आजादी सच्ची नहीं थी और उसने क्रांतिकारी मार्ग की वकालत की। इस संदर्भ में पार्टी ने स्थानीय जमींदारों और राज्य के खिलाफ तेलंगाना क्षेत्र में एक हिंसक सशस्त्र विद्रोह का समर्थन और नेतृत्व किया। हालांकि आंदोलन को दबा दिया गया और 1951 तक पार्टी ने संवैधानिक चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया।

61. (C) अलग-अलग मतपेटियों की जगह एक ही मतपत्र पर मुहर लगाने की व्यवस्था की गई।
पहले दो आम चुनावों के बाद चुनाव आयोग ने दक्षता में सुधार के लिए मतदान पद्धति को बदल दिया। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग-अलग बक्से रखने के बजाय एक ही मतपत्र पेश किया गया। इस मतपत्र पर सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम और प्रतीक सूचीबद्ध थे। मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार के प्रतीक पर मुहर लगाकर अपनी पसंद दर्ज करते थे और उसे एक सामान्य बॉक्स में डालते थे।

62. (D) 1, 2, 3 और 4
1957 में कम्युनिस्ट पार्टी ने केरल में चुनाव जीतकर इतिहास रचा और प्रगतिशील भूमि तथा शैक्षिक सुधारों का वादा किया। हालांकि इन बदलावों को धार्मिक संगठनों और निहित स्वार्थों के तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा, जिससे 'मुक्ति संघर्ष' शुरु हुआ। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप 1959 में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया, जिसे कई लोग आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग के रूप में देखते हैं।

63. (A) पार्टी में क्रांतिकारी और शांतिवादी, गरमपंथी और नरमपंथी, सभी का समावेश।
कांग्रेस पार्टी की विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में प्रकृति पूरी तरह से विरोधी विचार रखने वाले लोगों को समायोजित करने की इसकी क्षमता से प्रदर्शित होती थी। एक ही पार्टी के भीतर क्रांतिकारी और शांतिवादी होने के साथ-साथ राजनीतिक गरमपंथी और नरमपंथी भी मौजूद थे। इस विस्तृत वैचारिक स्पेक्ट्रम ने पार्टी को जनसंख्या के लगभग हर वर्ग को आकर्षित करने की अनुमति दी, क्योंकि इसने समावेशी दृष्टिकोण अपनाया था।

64. (B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
1950 के दशक के दौरान विपक्षी दलों के पास संसद और राज्य विधानसभाओं में बहुत कम सीटें थीं, जिससे उनकी विधायी शक्ति सीमित थी। उनकी कम संख्या के बावजूद उनकी सक्रिय उपस्थिति देश के लोकतांत्रिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण थी। उन्होंने सरकारी नीतियों को बौद्धिक चुनौतियाँ

ऐतिहासिक मील का पत्थर थी। हालांकि इसने अपना पूरा पांच साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। 1959 में केंद्र सरकार ने स्थानीय आंदोलन और सरकार के विवादास्पद नीतिगत सुधारों के विरोध के बाद संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए इस मंत्रालय को बर्खास्त कर दिया था।

108. (B) लोकतांत्रिक समाजवाद
भारत की सोशलिस्ट पार्टी लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांतों पर आधारित थी। इसके नेताओं ने हिंसक क्रांति के बजाय चुनाव और संसदीय सुधारों जैसे लोकतांत्रिक माध्यमों से सामाजिक और आर्थिक समानता हासिल करने में विश्वास किया। उन्होंने श्रमिकों और किसानों के अधिकारों की वकालत की और सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी की आलोचना की क्योंकि उन्हें लगा कि उसका झुकाव धनी और कुलीन वर्गों की ओर अधिक था।

109. (C) अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस
भारत में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व की तुलना अक्सर दक्षिण अफ्रीका की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से की जाती है। दोनों दलों ने अपने संबंधित राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों के प्राथमिक नेताओं के रूप में अपार लोकप्रियता और वैधता हासिल की। इस ऐतिहासिक भूमिका ने उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद कई दशकों तक राजनीतिक परिदृश्य पर हावी होने की अनुमति दी क्योंकि उन्हें नए राष्ट्र का स्वाभाविक संरक्षक माना गया था।

110. (D) इसने वर्ग, जाति, धर्म, भाषा जैसे विभिन्न सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व किया।
कांग्रेस को 'सतरंगे सामाजिक गठबंधन' के रूप में वर्णित करना इसकी समावेशी प्रकृति को उजागर करता है। एक इंद्रधनुष की तरह जिसमें कई रंग होते हैं, पार्टी ने विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों और भाषाई पृष्ठभूमियों के लोगों को एक साथ लाया। भारतीय समाज के इतने विस्तृत वर्ग का प्रतिनिधित्व करके पार्टी समर्थन का एक व्यापक आधार बनाने और विभिन्न सामाजिक समूहों के प्रतिस्पर्धी हितों का प्रबंधन करने में सफल रही।

111. (A) वे नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे ब्रिटेन को समर्थन देना चाहते थे।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कम्युनिस्टों और कांग्रेस के बीच संबंध काफी बदल गए। 1941 में जब नाजी जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन करने का फैसला किया क्योंकि ब्रिटेन तब सोवियत संघ का सहयोगी था। इस स्थिति ने उन्हें कांग्रेस के साथ सीधे संघर्ष में डाल दिया जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर रही थी।

112. (B) पार्टी के भीतर मौजूद विभिन्न हित या विचारधारा वाले समूह।
कांग्रेस पार्टी के भीतर 'गुट' सदस्यों के ऐसे संगठित समूह थे जो समान हितों या वैचारिक झुकाव को साझा करते थे। ये गुट अक्सर नेतृत्व के पदों और पार्टी नीति पर प्रभाव के लिए एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते थे। पार्टी को विभाजित करने के बजाय इन आंतरिक समूहों की उपस्थिति ने कांग्रेस को दृष्टिकोणों की एक विस्तृत श्रृंखला को समायोजित करने की अनुमति दी, जिससे शुरुआती दशकों में वह अधिक लचीली बनी।

113. (B) भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर।
भारतीय जनसंघ का मानना था कि भारत का आधुनिकीकरण और शक्ति का मार्ग उसकी अपनी सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत में दृढ़ता से निहित होना चाहिए। पार्टी के नेताओं ने पश्चिमी मॉडलों के अंधानुकरण के खिलाफ तर्क दिया और विकास पथ की वकालत की जो अद्वितीय 'भारतीय जीवन शैली' को दर्शाता हो। उनका मानना था कि यह स्वदेशी दृष्टिकोण अपनी मूल पहचान को संरक्षित करते हुए राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाएगा।

114. (A) महिलाओं के नाम, जो 'अलां की बेटी' या 'फलां की बीवी' के रूप में दर्ज थे।
पहली मतदाता सूची की तैयारी के दौरान चुनाव आयोग को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा जहाँ लाखों महिलाओं को उनके अपने नाम के बजाय किसी पुरुष रिश्तेदार से उनके संबंध द्वारा पंजीकृत किया गया था। आयोग ने इस प्रथा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और ऐसी प्रविष्टियों को शामिल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र में व्यक्तिगत गरिमा के सिद्धांत को बनाए रखा जाए।

115. (C) इसने माना कि चुनावों ने सार्वभौम मताधिकार के आलोचकों के संदेहों पर पानी फेर दिया है।
1951-52 में पहले आम चुनाव के सफल संचालन ने राष्ट्रीय मीडिया सहित विभिन्न क्षेत्रों से प्रशंसा प्राप्त की। 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' ने उल्लेख किया कि सुचारु और शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया ने उन आलोचकों को प्रभावी ढंग से चुप करा दिया है जिन्हें संदेह था कि एक गरीब निरक्षर देश में सार्वभौम वयस्क मताधिकार काम कर सकता है। चुनावों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति भारतीय जनता की राजनीतिक परिपक्वता को साबित किया।

116. (D) संचार मंत्री और खाद्य एवं कृषि मंत्री।
रफी अहमद किदवई जवाहरलाल नेहरु के शुरुआती मंत्रिमंडलों के एक प्रमुख सदस्य थे और उन्होंने कई महत्वपूर्ण क्षमताओं में कार्य किया। उन्होंने सबसे पहले संचार मंत्री का पद संभाला और बाद में उन्हें खाद्य एवं कृषि मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। वे अपनी प्रशासनिक दक्षता और जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे, विशेष रूप से स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में।

117. (C) दो बैलों की जोड़ी
1952 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने दो बैलों की जोड़ी वाले चुनाव चिह्न का उपयोग किया था। यह चिह्न इसलिए चुना गया था क्योंकि यह कृषि कार्यों में लगे भारतीय मतदाताओं के विशाल बहुमत के लिए आसानी से पहचानने योग्य था। उस समय चुनावी प्रक्रिया के लिए प्रतीक आवश्यक थे क्योंकि कई नागरिक निरक्षर थे और उन्हें मतपेटियों पर अपनी पसंदीदा

138. (A) 1950 में ही
जब 1950 की शुरुआत में पहली बार चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी, तो एक प्रारंभिक आशा थी कि देश उसी वर्ष के उत्तरार्ध में चुनाव करा सकता है। हालांकि जैसे-जैसे आयोग ने कार्य के विशाल पैमाने को समझना शुरु किया जैसे निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और लाखों लोगों के लिए मतदाता सूची तैयार करना, यह स्पष्ट हो गया कि पर्याप्त तैयारी के लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता थी।

139. (D) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या CPI
कम्युनिस्ट आंदोलन में 1964 के विभाजन के बाद जो गुट सोवियत संघ की वैचारिक रेखा के प्रति अधिक सहानुभूति रखता था और कांग्रेस के साथ अधिक सहयोगात्मक संबंधों का पक्षधर था उसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के रुप में जाना गया। दूसरा गुट जो कांग्रेस का अधिक आलोचक था और चीनी क्रांतिकारी मॉडल से प्रभावित था, वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) या CPI(M) बन गया, जिससे वामपंथी राजनीति नई दिशा में मुड़ी।

140. (B) समाजवादी
आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और राममनोहर लोहिया जैसे नेता भारत में समाजवादी आंदोलन के बौद्धिक और राजनीतिक स्तंभ थे। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की वकालत की जो सामाजिक और आर्थिक समानता के साथ लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को जोड़ती हो। हालांकि वे मूल रुप से कांग्रेस का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने अंततः गरीबों और श्रमिक वर्ग के उत्थान के उद्देश्य से अधिक कट्टरपंथी सुधारों के लिए स्वतंत्र समाजवादी दलों का गठन किया।

141. (C) उपरोक्त सभी।
पहले आम चुनाव का आयोजन करना एक अभूतपूर्व प्रशासनिक उपलब्धि थी जिसके लिए कई बाधाओं को पार करना आवश्यक था। आयोग को सैकड़ों निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित करनी थीं और विशाल आबादी के लिए सटीक मतदाता सूची तैयार करनी थी। इसके अतिरिक्त क्योंकि अधिकांश मतदाता निरक्षर थे, उन्हें एक सरल लेकिन सुरक्षित मतदान पद्धति विकसित करनी पड़ी और पूरे देश में लाखों मतदान अधिकारियों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करना पड़ा।

142. (D) हिंदू धर्म में व्याप्त जाति व्यवस्था पर अपनी असहमति के कारण।
1956 में बौद्ध धर्म अपनाने का डॉ. बी.आर. अंबेडकर का निर्णय हिंदू जाति व्यवस्था की अंतर्निहित असमानताओं के खिलाफ उनके आजीवन संघर्ष का चरम था। उनका मानना था कि हिंदू धर्म की सामाजिक और धार्मिक संरचना कभी भी दलितों को वास्तविक समानता और गरिमा प्रदान नहीं कर सकती। वे बौद्ध धर्म की ओर एक ऐसे विश्वास के रुप में मुड़े जिसने तर्कसंगतता, नैतिकता और सामाजिक समानता पर जोर दिया।

143. (A) 1990 के दशक के अंत में।
हालांकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के छोटे पैमाने पर परीक्षण पहले हुए थे, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम की व्यवस्थित और व्यापक शुरुआत 1990 के दशक के उत्तरार्ध में शुरु हुई थी। इस आधुनिकीकरण का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाना, मतपत्रों की गिनती में शामिल शारीरिक श्रम को कम करना और भारत के विशाल लोकतांत्रिक अभ्यासों में परिणामों की तेज और अधिक विश्वसनीय घोषणा सुनिश्चित करना था।

144. (B) यह बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया।
पहले आम चुनाव के सफल समापन के बाद 'द हिंदुस्तान टाइम्स' ने इस उपलब्धि को लोकतंत्र की ऐतिहासिक जीत बताया। समाचार पत्र ने उल्लेख किया कि भारतीय जनता ने विश्व इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था, जिससे यह साबित हो गया कि एक गरीब और निरक्षर राष्ट्र भी सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर आधारित एक जटिल चुनावी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक प्रबंधित कर सकता है।

145. (B) 1952-1967
1952 के पहले आम चुनाव से लेकर 1967 तक की अवधि को भारतीय राजनीति में कांग्रेस के प्रभुत्व के युग के रुप में व्यापक रुप से मान्यता प्राप्त है। इन पंद्रह वर्षों के दौरान पार्टी ने लगातार लोकसभा में भारी बहुमत जीता और अधिकांश राज्य सरकारों को नियंत्रित किया। इस प्रभुत्व की विशेषता शासन और देश में राजनीतिक बहस के प्राथमिक क्षेत्र दोनों में कांग्रेस की केंद्रीय भूमिका थी, जिसने राष्ट्र को दिशा दी।

146. (A) कश्मीर नीति पर जनसंघ के प्रदर्शन के दौरान हिरासत में।
भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 1953 में जम्मू-कश्मीर सरकार की हिरासत में मृत्यु हो गई थी। उन्होंने बिना परमिट के राज्य में प्रवेश किया था ताकि इसके विशेष दर्जे के खिलाफ विरोध किया जा सके और भारत के साथ पूर्ण एकीकरण की मांग की जा सके। हिरासत में रहते हुए विवादास्पद परिस्थितियों में उनकी मृत्यु एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन गई और पार्टी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण थी।

147. (C) उपरोक्त सभी
गणराज्य के शुरुआती वर्षों से ही कई दलों ने प्रभुत्वशाली कांग्रेस को एक मजबूत वैचारिक विकल्प प्रदान किया। सोशलिस्ट पार्टी ने इसकी आर्थिक नीतियों की आलोचना की, कम्युनिस्ट पार्टी ने इसकी लोकतांत्रिक साख पर सवाल उठाए और भारतीय जनसंघ ने राष्ट्रीय पहचान और धर्मनिरपेक्षता के इसके दृष्टिकोण का विरोध किया। ये दल अपने छोटे आकार के बावजूद विपक्षी स्वर को मुखर बनाए रखने और अधिक प्रतिस्पर्धी भविष्य की नींव रखने में सुसंगत थे।

148. (D) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
पहले तीन आम चुनावों के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने लगातार लोकसभा में सबसे बड़े एकल विपक्षी दल के रुप में प्रदर्शन किया। जबकि समाजवादियों और जनसंघ जैसे अन्य समूहों ने भी चुनाव लड़ा, कम्युनिस्ट अधिक सीटें जीतने

128. (B) पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर मतभेदों के कारण।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1950 में पाकिस्तान के प्रति नीति पर प्रधानमंत्री नेहरू के साथ मौलिक मतभेदों के कारण अंतरिम मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। वे विशेष रूप से पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे और उनका मानना था कि सरकार इस मुद्दे पर पर्याप्त कड़ा रुख नहीं अपना रही है। इस असहमति के कारण उन्होंने सरकार छोड़ दी और अंततः भारतीय जनसंघ की स्थापना की।

129. (B) राजकुमारी अमृत कौर
राजकुमारी अमृत कौर महात्मा गांधी की एक समर्पित अनुयायी और स्वतंत्रता आंदोलन की एक प्रमुख हस्ती थीं। वे संविधान सभा की उन गिनी-चुनी महिलाओं में से एक थीं जिन्होंने स्वतंत्र भारत में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कैबिनेट स्तर का पद संभालने वाली पहली महिला होने का गौरव प्राप्त किया। उनका जीवन और कार्य सामाजिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता और न्याय के लिए गांधीवादी संघर्ष के उच्च आदर्शों का संगम था।

130. (A) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
1947 के बाद के राजनीतिक समझौते को शुरु में खारिज करने और सशस्त्र संघर्ष में शामिल होने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 1951 में एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव किया। पार्टी ने हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ने और इसके बजाय आगामी आम चुनावों में भाग लेने का फैसला किया। यह कदम मुख्यधारा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनके प्रवेश का प्रतीक था, जहाँ वे अंततः एक महत्वपूर्ण संसदीय शक्ति बन गए।

131. (C) सोशलिस्ट पार्टी
1950 के दशक की मूल सोशलिस्ट पार्टी ने भारत के कई समकालीन राजनीतिक दलों के लिए एक वैचारिक और संगठनात्मक नर्सरी के रूप में कार्य किया। विभिन्न समूह जिन्होंने बाद में जनता पार्टी बनाई, साथ ही उत्तर भारत के आधुनिक क्षेत्रीय दल, अपनी राजनीतिक विरासत को समाजवादी आंदोलन में खोज सकते हैं। सामाजिक न्याय, कृषि सुधार और धर्मनिरपेक्षता पर इसके जोर ने भारतीय राजनीतिक स्पेक्ट्रम के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करना जारी रखा है।

132. (D) केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 356 का उपयोग कर केरल सरकार को बर्खास्त कर दिया।
केरल में 'मुक्ति संघर्ष', जो कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला थी, ने तीव्र राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति पैदा कर दी। यह दावा करते हुए कि राज्य की संवैधानिक मशीनरी विफल हो गई है, केंद्र सरकार ने मंत्रालय को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए अनुच्छेद 356 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग किया। यह कार्रवाई विवादास्पद थी और इसने विपक्षी नेतृत्व वाली सरकारों के खिलाफ आपातकालीन शक्तियों के उपयोग का उदाहरण पेश किया।

133. (C) राष्ट्रीय आंदोलन के उत्तराधिकारी के रूप में इसे नैतिक लोकप्रियता प्राप्त हुई।
कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व उस संगठन के रूप में इसकी पहचान में गहराई से निहित था जिसने भारत को सफलतापूर्वक स्वतंत्रता दिलाई थी। नागरिकों के विशाल बहुमत के लिए पार्टी राष्ट्रीय आंदोलन की वैध उत्तराधिकारी और आजादी के आदर्शों की वाहक थी। इस ऐतिहासिक संबंध ने पार्टी को अपार नैतिक अधिकार और लोकप्रिय विश्वास दिया, जो गणराज्य के शुरुआती वर्षों में महत्वपूर्ण चुनावी लाभों में बदल गया।

134. (B) यह एक मंच था जहाँ विभिन्न समूह और दल राष्ट्रीय हित में एकजुट थे।
कांग्रेस को एक मंच के रूप में वर्णित करने का मतलब है कि इसने एक संकीर्ण राजनीतिक दल के बजाय एक व्यापक गठबंधन के रूप में कार्य किया। स्वतंत्रता से पहले और तुरंत बाद इसने एक साझा स्थान प्रदान किया जहाँ विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक समूह राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए मिलकर काम कर सकते थे। इस समावेशी ढांचे ने इसे विविध दृष्टिकोणों को आत्मसात करने और आंतरिक संघर्षों को सुलझाने की अनुमति दी।

135. (D) कांग्रेस के अपने विभिन्न गुटों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा और बहस के माध्यम से।
एक मजबूत बाहरी विपक्षी दल की अनुपस्थिति में सरकारी नीतियों पर सवाल उठाने और बहस करने की भूमिका अक्सर कांग्रेस के भीतर ही विभिन्न समूहों द्वारा निभाई जाती थी। ये आंतरिक गुट विभिन्न हितों और वैचारिक दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते थे, और उनकी निरंतर बातचीत और प्रतिस्पर्धा ने पार्टी के नेतृत्व पर नियंत्रण के रूप में कार्य किया। आंतरिक लोकतंत्र की इस प्रणाली ने सुनिश्चित किया कि विविध आवाजों को सुना जाए।

136. (A) कम्युनिस्ट पार्टी
ए.के. गोपालन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रमुख नेता और इसके सबसे सम्मानित सांसदों में से एक थे। गरीबों और हाशिए पर रहने वालों के अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाने वाले गोपालन विशेष रूप से केरल में पार्टी के विकास में एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने कई वर्षों तक लोकसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया और कांग्रेस के प्रभुत्व के युग के दौरान विपक्ष के लिए एक अग्रणी आवाज रहे।

137. (C) दूसरा
1952 के आम चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी ने लोकप्रिय वोटों के कुल प्रतिशत के मामले में काफी अच्छा प्रदर्शन किया, लगभग दस प्रतिशत हासिल किया और कांग्रेस के बाद दूसरे स्थान पर रही। हालांकि चुनावी प्रणाली की प्रकृति और विपक्षी वोटों के विभाजन के कारण यह महत्वपूर्ण वोट शेयर कई सीटों में नहीं बदल पाया। इस परिणाम ने प्रभुत्वशाली कांग्रेस के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में समाजवादियों के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर किया।

159. (C) विविध हितों को समाहित कर बाहरी विरोध की संभावनाओं को सीमित किया।
कांग्रेस की समावेशी कार्यशैली ने समाज के लगभग सभी महत्वपूर्ण वर्गों और राजनीतिक विचारधाराओं को पार्टी के दायरे में समेट लिया था। जब भी कोई नया सामाजिक मुद्दा या विरोध उत्पन्न होता था, कांग्रेस उसे अपने आंतरिक ढांचे में समाहित कर लेती थी। इस कारण बाहरी विपक्षी दलों के पास कोई विशेष आधार नहीं बचता था, जिससे एक मजबूत और संगठित बाहरी विपक्ष का उभरना काफी कठिन रहा।

160. (A) सहमति, समायोजन और मध्यमार्गी दृष्टिकोण।
कांग्रेस प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि वह किसी भी अतिवादी विचारधारा की तुलना में मध्यमार्गी रास्ते पर चलती थी। पार्टी के भीतर निर्णय लेते समय सभी गुटों के बीच सहमति बनाने और परस्पर समायोजन करने का प्रयास किया जाता था। थोपने के बजाय संवाद और लचीलेपन की इस शैली ने विभिन्न विरोधाभासों को संतुलित रखा और देश में लोकतांत्रिक स्थिरता को लंबे समय तक बनाए रखा।

161. (D) सत्ताधारी दल की नीतियों की निरंतर आलोचना और निगरानी करना।
चुनावी रूप से कमजोर होने के बावजूद, प्रारंभिक काल के विपक्षी दलों ने संसद और विधानसभाओं में प्रहरी के रूप में महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने सरकार की कमियों को उजागर किया और जनविरोधी नीतियों पर अंकुश लगाया। उनकी निरंतर सक्रियता ने सुनिश्चित किया कि सत्ताधारी दल अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके और शासन व्यवस्था में वैकल्पिक विचारों एवं जनहित से जुड़ी चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिले।

162. (B) सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और 'अखंड भारत' का विचार।
भारतीय जनसंघ की विचारधारा मूल रूप से भारतीय संस्कृति और परंपराओं पर आधारित राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली थी। यह दल 'एक देश, एक राष्ट्र और एक संस्कृति' के सिद्धांत में विश्वास रखता था। इसके प्रमुख उद्देश्यों में हिंदी भाषा को आधिकारिक दर्जा दिलाना और अखंड भारत के सपने को साकार करना शामिल था। इसने कांग्रेस की नीतियों को अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के रूप में देखा और विरोध किया।

163. (C) संसद में वैचारिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर शासक दल पर अंकुश लगाया।
प्रारंभिक दौर के विपक्षी दलों ने संसद के भीतर विभिन्न विचारधाराओं को मंच प्रदान कर सत्ता के केंद्रीकरण को रोकने में मदद की। उन्होंने अपनी उपस्थिति से शासक दल को वैचारिक रूप से सचेत रखा और निरंकुश होने से बचाया। यद्यपि उनकी सदस्य संख्या कम थी, लेकिन उनकी सक्रिय भागीदारी ने लोकतांत्रिक बहस को समृद्ध किया और भारतीय बहुदलीय व्यवस्था की भविष्य की नींव को काफी मजबूत बनाया।

164. (D) सोशलिस्ट पार्टी लोकतांत्रिक समाजवाद और सीपीआई वर्ग संघर्ष पर केंद्रित थी।
सोशलिस्ट पार्टी की जड़ें कांग्रेस के भीतर थीं और वह लोकतांत्रिक माध्यमों से सामाजिक समानता लाने में विश्वास रखती थी। इसके विपरीत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा अधिक क्रांतिकारी थी जो मार्क्सवादी सिद्धांतों और वर्ग संघर्ष पर आधारित थी। जहाँ सोशलिस्ट पार्टी ने सरकार की लोक-कल्याणकारी कमियों पर प्रहार किया, वहीं सीपीआई ने पूंजीवादी ढांचे को चुनौती देते हुए शोषितों और मजदूरों की आवाज को प्रखर रूप से बुलंद किया।

165. (A) कमजोर विपक्ष भी जीवंत लोकतंत्र बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता केवल बहुमत वाली सरकार पर निर्भर नहीं करती, बल्कि एक मुखर विपक्ष की उपस्थिति भी अनिवार्य होती है। संख्या बल कम होने पर भी यदि विपक्षी दल सक्रिय हों, तो वे सरकार को उत्तरदायी बनाने में सक्षम होते हैं। प्रारंभिक वर्षों में भारतीय लोकतंत्र ने एक-दलीय प्रभुत्व के साथ-साथ विपक्षी दलों के माध्यम से विभिन्न वैचारिक विकल्पों को जीवित रखा, जो एक परिपक्व लोकतंत्र की निशानी है।

166. (B) यह लोकतांत्रिक चुनावों से सत्ता पाने वाली विश्व की पहली कम्युनिस्ट सरकार थी।
1957 में केरल के चुनाव परिणामों ने वैश्विक स्तर पर सबका ध्यान खींचा क्योंकि वहां पहली बार कम्युनिस्टों ने बिना किसी सशस्त्र क्रांति के बैलेट बॉक्स के जरिए सत्ता प्राप्त की थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की यह विजय संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में एक अनूठा उदाहरण थी। इसने यह सिद्ध किया कि मार्क्सवादी विचारधारा के अनुयायी भी लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर रहकर जनमत के माध्यम से सरकार बना सकते हैं।

167. (B) सरकार द्वारा प्रस्तावित कट्टरपंथी भूमि और शिक्षा सुधार के प्रयास।
केरल की नम्बूदरीपाद सरकार ने सत्ता में आते ही भूमि स्वामित्व और शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव करने की कोशिश की थी। प्रस्तावित कृषि विधेयकों ने शक्तिशाली भू-स्वामियों के हितों पर चोट की, जबकि शिक्षा विधेयक ने निजी संस्थानों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास किया। इन सुधारों के कारण समाज के प्रभावशाली वर्गों और धार्मिक संगठनों में भारी असंतोष पैदा हुआ, जिसके परिणामस्वरूप सरकार के विरुद्ध व्यापक आंदोलन शुरु हुआ।

168. (A) भू-स्वामी, शिक्षण संस्थानों के प्रबंधक, धार्मिक संगठन और कांग्रेस दल।
केरल में कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ चलाए गए 'विमोचन समरम' आंदोलन में विविध हितों वाले समूह एकजुट हुए थे। इसमें कैथोलिक चर्च और नायर सर्विस सोसाइटी जैसे प्रभावशाली सामुदायिक संगठन शामिल थे जो शिक्षा सुधारों के विरोधी थे। साथ ही, भू-स्वामी वर्ग अपनी जमीन बचाने के लिए और कांग्रेस पार्टी राजनीतिक अवसर का लाभ उठाने के लिए इस आंदोलन में पूर्ण रूप से सक्रिय भागीदार बने हुए थे।

और कांग्रेस को अधिक संगठित चुनौती देने में सक्षम थे। यह स्थिति कुछ क्षेत्रों में उनके मजबूत जमीनी समर्थन और उनके स्पष्ट वैचारिक कार्यक्रम को दर्शाती थी, जिसने उन्हें संसद में पहचान दिलाई।

149. (C) 24 जनवरी 1950
24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्य भारत के संविधान की आधिकारिक प्रतियों पर हस्ताक्षर करने के लिए एक अंतिम सत्र के लिए एकत्र हुए। इस अधिनियम ने उनके वर्षों के परिश्रम के औपचारिक अंत को चिह्नित किया और दो दिन बाद 26 जनवरी को दस्तावेज के पूर्ण रूप से प्रभावी होने का मार्ग प्रशस्त किया। हस्ताक्षर करना एक गंभीर अवसर था जिसने एक नए संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के जन्म का संकेत दिया।

150. (B) चुनावी प्रतिस्पर्धा का पहला दशक
राजनीति वैज्ञानिक रजनी कोठारी ने भारत में चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक के दौरान मौजूद अद्वितीय राजनीतिक संरचना का वर्णन करने के लिए 'कांग्रेस प्रणाली' शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने तर्क दिया कि कांग्रेस पार्टी ने शक्ति के केंद्र और राजनीतिक बहस के मुख्य मंच दोनों के रूप में कार्य किया। इस प्रणाली ने स्थिरता और लोकतांत्रिक विकास की अनुमति दी जबकि एक ही पार्टी राजनीतिक परिदृश्य पर पूरी तरह हावी रही।

151. (B) निरक्षर मतदाता वर्ग हेतु एक व्यवहार्य मतदान प्रणाली तैयार करना।
भारत के पहले आम चुनाव के समय देश की लगभग 85 प्रतिशत जनसंख्या निरक्षर थी। इतनी बड़ी अनपढ़ आबादी के लिए मतदान की एक ऐसी सरल और सुगम प्रक्रिया विकसित करना सबसे जटिल कार्य था जिससे वे बिना किसी सहायता के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इसके लिए चुनाव आयोग को मतदान के पारंपरिक तरीकों में व्यापक बदलाव करने पड़े थे।

152. (A) स्वतंत्र पहचान रहित प्रविष्टियों को अस्वीकार कर सूचियों के पुनरीक्षण का आदेश दिया।
मतदाता सूचियों के प्रारंभिक मसौदे में लाखों महिलाओं के नाम उनकी अपनी पहचान के बजाय उनके पारिवारिक रिश्तों के आधार पर दर्ज थे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने लैंगिक समानता के सिद्धांतों का पालन करते हुए ऐसी प्रविष्टियों को स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। आयोग ने महिलाओं के नाम उनकी वास्तविक व्यक्तिगत पहचान के साथ दर्ज करने हेतु सूचियों के व्यापक पुनरीक्षण का साहसिक निर्णय लिया।

153. (C) उम्मीदवारों को विशिष्ट चिह्न आवंटित कर उनके लिए अलग मतपेटियां रखी गईं।
निरक्षर मतदाताओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने प्रत्येक उम्मीदवार को एक विशेष चुनाव चिह्न आवंटित किया था। मतदान केंद्रों पर हर उम्मीदवार के लिए एक अलग मतपेटी रखी गई थी जिस पर उसका आवंटित चिह्न अंकित रहता था। मतदाताओं को अपना खाली मतपत्र केवल अपनी पसंद के उम्मीदवार के चिह्न वाली पेटी में डालना होता था, जिससे मतदान प्रक्रिया अत्यंत सरल हो गई।

154. (D) निरक्षर देश में वयस्क मताधिकार की सफलता पर संदेह करने वाले आलोचकों द्वारा।
भारत जैसे विशाल, गरीब और अत्यधिक निरक्षर देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रयोग को दुनिया भर के कई राजनीतिक विश्लेषकों ने संदेहास्पद माना था। उन आलोचकों का मानना था कि शिक्षित न होने के कारण भारतीय जनता लोकतंत्र की इस जटिल प्रक्रिया को ठीक से नहीं समझ पाएगी। इसलिए उन्होंने इस अभूतपूर्व साहसी कदम को इतिहास के सबसे बड़े जुए की संज्ञा दी थी।

155. (C) आयोग ने लैंगिक असमानता जैसी सामाजिक बाधाओं को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाई।
प्रथम आम चुनाव केवल मतदान की प्रक्रिया नहीं थी बल्कि इसने सामाजिक सुधार की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। चुनाव आयोग ने पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की स्वतंत्र पहचान स्थापित करने के लिए कड़ा रुख अपनाया। मतदाता सूचियों में सुधार की प्रक्रिया यह स्पष्ट करती है कि आयोग ने केवल चुनाव संपन्न ही नहीं कराए बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और लैंगिक समानता को भी मज़बूती प्रदान की।

156. (B) व्यापक सामाजिक गठबंधन पर आधारित एक-दलीय प्रभुत्व की लोकतांत्रिक प्रणाली।
"कांग्रेस प्रणाली" प्रारंभिक दशकों में भारतीय राजनीति की वह अनूठी संरचना थी जिसमें एक ही दल का प्रभुत्व था लेकिन वह पूर्णतः लोकतांत्रिक स्वरूप में कार्य करता था। यह पार्टी विभिन्न सामाजिक वर्गों और हितों को अपने साथ लेकर चलती थी। इसके भीतर ही वैचारिक प्रतिस्पर्धा और विमर्श की पर्याप्त गुंजाइश मौजूद थी, जो इसे किसी भी प्रकार के तानाशाही शासन से बिल्कुल अलग बनाती थी।

157. (D) यह विभिन्न सामाजिक और वैचारिक समूहों को अपने भीतर समाहित करती थी।
स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस एक ऐसी संस्था बन गई थी जिसमें अमीर, गरीब, किसान, उद्योगपति, दक्षिणपंथी और वामपंथी सभी विचारधाराओं के लोग साथ मिलकर काम करते थे। इंद्रधनुष के विविध रंगों की तरह इसमें समाज के हर वर्ग और विचारधारा का प्रतिनिधित्व शामिल था। इस समावेशी प्रकृति के कारण ही कांग्रेस एक विशाल और व्यापक गठबंधन के रूप में विकसित होकर राजनीतिक स्थिरता प्रदान कर सकी।

158. (A) आंतरिक विपक्ष के रूप में कार्य कर विभिन्न हितों को प्रतिनिधित्व दिया।
कांग्रेस पार्टी के भीतर मौजूद अलग-अलग गुट वास्तव में परस्पर विरोधी हितों और विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते थे। ये गुट पार्टी के अंदर ही आपसी संतुलन बनाए रखते थे और नीतियों पर गहन विचार-विमर्श करते थे। इस आंतरिक प्रतिस्पर्धा ने पार्टी के भीतर ही एक प्रकार के विपक्ष की भूमिका निभाई, जिससे सत्ता पर एकाधिकार होने के बावजूद लोकतांत्रिक संवाद की प्रक्रिया कभी भी बाधित नहीं हुई।

अध्याय 10
नियोजित विकास की राजनीति

1. स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने आर्थिक विकास और सबकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रमुख चुनौतियों में से एक क्या थी?
(A) राष्ट्र-एकता और सीमा सुरक्षा को पुख्ता करना
(B) आर्थिक विकास और जन-कल्याण सुनिश्चित करना
(C) लोकतांत्रिक संस्थाओं की पूर्ण स्थापना करना
(D) सैन्य शक्ति और आधुनिक हथियारों का विस्तार

2. उड़ीसा में किस खनिज का विशाल भंडार मौजूद था, जिसके दोहन के लिए राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय इस्पात-निर्माताओं के साथ सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए?
(A) लौह-अयस्क
(B) कोयला
(C) बॉक्साइट
(D) मैंगनीज

3. निम्नलिखित में से कौन सा कथन 'विकास' की धारणा के संबंध में सही है?
(A) समाज के सभी लोगों के लिए एक समान अर्थ होना
(B) विकास की राष्ट्रीय चर्चाओं में कभी विवाद न होना
(C) विभिन्न वर्गों के लिए विकास के भिन्न अर्थ होना
(D) आर्थिक संवृद्धि को ही विकास का एकमात्र पैमाना मानना

4. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (समूह)
P. आदिवासी
Q. पर्यावरणविद
R. केंद्र सरकार
S. राज्य सरकार
सूची II: (हित/चिंता)
1. खनन और उद्योग से पर्यावरण प्रदूषण का भय
2. पूँजी-निवेश और रोज़गार के अवसर
3. घर-बार से विस्थापन और आजीविका छिनने का डर
4. देश में पूँजी निवेश को बाधा न पहुँचे
कूट:
(A) P-3, Q-1, R-4, S-2
(B) P-1, Q-3, R-2, S-4
(C) P-4, Q-2, R-1, S-3
(D) P-2, Q-4, R-3, S-1

5. स्वतंत्रता के समय, 'विकास' का पैमाना आमतौर पर किन देशों को माना जाता था?
(A) पूर्वी एशियाई देश
(B) अफ्रीकी देश
(C) पश्चिमी मुल्क
(D) सोवियत संघ

6. 'वामपंथ' से सामान्यतः उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो किसका समर्थन करते हैं?
(A) खुली प्रतिस्पर्धा और पूर्ण बाज़ारमूलक व्यवस्था वाले
(B) राज्य नियंत्रण और विनियामक अर्थव्यवस्था के पक्षधर
(C) अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप के घोर विरोधी लोग
(D) निजी क्षेत्र के एकाधिकार और पूर्ण प्रभुत्व के समर्थक

7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पहला मॉडल उदारवादी-पूंजीवादी था।
2. दूसरा मॉडल समाजवादी था जिसे सोवियत संघ ने अपनाया था।
3. भारत में अमरीकी तर्ज़ के पूंजीवादी विकास के पैरोकार बहुत अधिक थे।
4. भारत में कई लोग, जिनमें नेहरु भी शामिल थे, सोवियत मॉडल से प्रभावित थे।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2 और 4
(C) 1, 2 और 4
(D) उपरोक्त सभी

8. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए:
कथन I: स्वतंत्रता के बाद यह सहमति थी कि विकास के मामले को केवल व्यवसायी, उद्योगपति और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।
कथन II: सरकार को इस मसले में प्रमुख भूमिका निभानी थी।
(A) कथन I और II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(C) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।
(D) कथन I और II दोनों असत्य हैं।

9. 'आधुनिकीकरण' को किसका पर्यायवाची माना जाता था?
(A) पारंपरिक सामाजिक संरचना का सुदृढीकरण
(B) कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार
(C) संवृद्धि, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्कबुद्धि
(D) धार्मिक विश्वासों की प्रबलता

169. (C) अनुच्छेद 356, जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है।
राज्य में निरंतर बढ़ते राजनीतिक तनाव और अशांति को आधार बनाकर केंद्र की कांग्रेस सरकार ने कड़ी कार्रवाई की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केरल की चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को असंवैधानिक रूप से बर्खास्त कर दिया गया। यह पहली बार था जब केंद्र सरकार ने किसी राज्य सरकार को हटाने के लिए इस प्रावधान का उपयोग किया, जिससे भारी राजनीतिक विवाद उत्पन्न हुआ।

170. (D) इसने केंद्र-राज्य संबंधों एवं अनुच्छेद 356 के उपयोग पर राष्ट्रव्यापी बहस छेड़ी।
केरल की निर्वाचित सरकार को केंद्र द्वारा बर्खास्त किए जाने की घटना ने भारतीय संघीय ढांचे के समक्ष गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए। इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक जनादेश का अपमान माना गया और इससे राज्यपाल की निष्पक्षता पर भी संदेह उत्पन्न हुआ। इसके बाद से ही अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग और केंद्र-राज्य संबंधों की शुचिता को लेकर देश में एक निरंतर चलने वाली संवैधानिक और राजनीतिक बहस की शुरुआत हो गई।

171. (C) उसे अन्य सभी उम्मीदवारों की तुलना में अधिक वोट प्राप्त करने होते हैं।
'फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट' प्रणाली भारतीय चुनावी व्यवस्था का आधार है, जिसमें जीत के लिए कुल मतों के बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। विजेता वही घोषित किया जाता है जिसे निर्वाचन क्षेत्र के अन्य सभी प्रतिद्वंद्वियों की अपेक्षा कम से कम एक वोट अधिक मिला हो। इस सरल प्रक्रिया के कारण मतदाता स्पष्ट रूप से अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं, भले ही उस प्रतिनिधि को मिलने वाले वोटों का प्रतिशत 50 से काफी कम हो।

172. (B) इसने कांग्रेस के वोट share की तुलना में उसकी सीटों की संख्या को अधिक दिखाया।
भारत की चुनावी प्रणाली ने कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व को और अधिक सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि कांग्रेस को मिलने वाले लोकप्रिय वोटों का प्रतिशत कभी भी 50 प्रतिशत तक नहीं पहुंचा, लेकिन FPTP प्रणाली के कारण वह संसद में भारी बहुमत हासिल करने में सफल रही। इस व्यवस्था ने कम वोट शेयर को भी बहुत अधिक सीटों में बदल दिया, जिससे कांग्रेस की जीत का प्रभाव वास्तविक जनमत से अधिक बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई दिया।

173. (D) महत्वपूर्ण वोट शेयर मिलने के बावजूद वह उसे सीटों में नहीं बदल सकी।
1952 के आम चुनावों में सोशलिस्ट पार्टी ने लगभग दस प्रतिशत लोकप्रिय वोट प्राप्त किए थे, जो किसी भी गैर-कांग्रेसी दल के लिए काफी बड़ा आंकड़ा था। इसके बावजूद, FPTP प्रणाली की विसंगतियों के कारण पार्टी को लोकसभा में नगण्य सीटें ही मिल सकीं। इसका मुख्य कारण यह था कि सोशलिस्ट पार्टी के वोट पूरे देश में बिखरे हुए थे और वे किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार को हराने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

174. (A) चुनावी प्रणाली का स्वरूप और विपक्षी वोटों का विभाजन।
कांग्रेस को मिली भारी सीटों और उसके वास्तविक वोट शेयर के बीच का अंतर मुख्य रूप से विपक्षी एकता के अभाव का परिणाम था। गैर-कांग्रेसी वोट विभिन्न दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच बंट गए, जिससे कांग्रेस के लिए कम वोट प्रतिशत पर भी जीत हासिल करना आसान हो गया। यदि सभी विपक्षी दल एकजुट होकर साझा उम्मीदवार उतारते, तो FPTP प्रणाली के तहत चुनावी परिणाम कांग्रेस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते थे।

175. (C) चुनावी प्रणाली का स्वरूप चुनाव परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है।
प्रथम तीन आम चुनावों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि चुनावी ढांचा केवल वोट गिनने का तरीका नहीं है, बल्कि यह राजनैतिक शक्ति के वितरण को निर्धारित करता है। FPTP प्रणाली ने बिखरे हुए जनादेश को एक-दलीय प्रभुत्व में परिवर्तित कर दिया। यह दर्शाता है कि किसी देश की चुनावी व्यवस्था का प्रकार यह तय करने में निर्णायक होता है कि संसद में दलों का प्रतिनिधित्व उनके वास्तविक लोकप्रिय आधार के अनुपात में होगा या नहीं।

(C) यह एक सलाहकार की भूमिका निभाता था।
(D) यह एक न्यायिक निकाय था।

20. 1940 और 1950 के दशक में पूरी दुनिया में नियोजन के विचार को जनसमर्थन मिलने का क्या कारण नहीं था?
(A) यूरोप का 'महामंदी' से सबक सीखना
(B) जापान और जर्मनी द्वारा अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण
(C) सोवियत संघ की शानदार आर्थिक प्रगति
(D) शीत युद्ध में अमरीका की विजय

21. निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. योजना आयोग की स्थापना
2. 'बॉम्बे प्लान' का प्रस्ताव
3. पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी होना
4. दूसरी पंचवर्षीय योजना का आरंभ
सही विकल्प चुनें:
(A) 1, 2, 3, 4
(B) 2, 1, 3, 4
(C) 2, 3, 1, 4
(D) 1, 3, 2, 4

22. योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था?
(A) राष्ट्रपति
(B) प्रधानमंत्री
(C) वित्त मंत्री
(D) भारतीय रिज़र्व बैंक का गवर्नर

23. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): भारत में योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना।
कारण (R): यह मॉडल सोवियत संघ की व्यवस्था से प्रेरित था, जहाँ पंचवर्षीय योजनाएँ लागू की जाती थीं।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

24. पंचवर्षीय योजना के अनुसार, सरकारों के बजट को किन दो हिस्सों में बाँटा गया था?
(A) योजना-व्यय और गैर-योजना-व्यय
(B) कृषि व्यय और उद्योग व्यय
(C) राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय
(D) रक्षा व्यय और विकास व्यय

25. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो भारत की शुरुआती विकास नीति से संबंधित हैं:
1. नियोजन
2. उदारीकरण
3. सहकारी खेती
4. आत्मनिर्भरता
5. निजीकरण
उपरोक्त में से कौन से विचार भारत की शुरुआती विकास नीति में शामिल थे?
(A) केवल 1, 3 और 4
(B) केवल 2 और 5
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) उपरोक्त सभी

26. प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस वर्ष जारी हुआ था?
(A) 1951
(B) 1950
(C) 1952
(D) 1956

27. किस पंचवर्षीय योजना के आरंभ होने तक नियोजन को लेकर देश में पैदा हुई गहमागहमी अपने चरम पर पहुँच गई थी?
(A) पहली पंचवर्षीय योजना
(B) तीसरी पंचवर्षीय योजना
(C) चौथी पंचवर्षीय योजना
(D) दूसरी पंचवर्षीय योजना

28. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (योजना)
P. पहली पंचवर्षीय योजना
Q. दूसरी पंचवर्षीय योजना
R. तीसरी पंचवर्षीय योजना
S. योजना अवकाश (1966-69)
सूची II: (केंद्र-बिंदु/विशेषता)
1. तीव्र औद्योगीकरण और भारी उद्योग
2. कृषि क्षेत्र, बाँध और सिंचाई
3. गहन आर्थिक संकट का दौर
4. उद्योग और कृषि के बीच संतुलन का प्रयास
कूट:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-1, R-4, S-3
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

29. सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना (जो 1966 से चालू होनी थी) को कुछ समय के लिए विराम देने का फैसला क्यों किया?
(A) निर्धारित विकास लक्ष्यों को समय से पूर्व ही प्राप्त कर लेने के कारण
(B) योजना आयोग को केंद्र सरकार द्वारा अचानक भंग कर दिए जाने के कारण
(C) देश के अत्यंत गंभीर आर्थिक संकट की चपेट में आने के कारण
(D) विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा व्यापक विरोध प्रदर्शन

10. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): स्वतंत्रता के बाद भारत में विकास के लगभग सभी फ़ैसले आर्थिक विकास के एक 'विज़न' से बँधे हुए थे।
कारण (R): लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक संवृद्धि और आर्थिक-सामाजिक न्याय दोनों ही हैं।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

11. 'दक्षिणपंथ' विचारधारा के समर्थक यह मानते हैं कि प्रगति किसके ज़रिए हो सकती है?
(A) आर्थिक गतिविधियों पर राज्य के पूर्ण केंद्रीकृत नियंत्रण से
(B) सरकार द्वारा सभी प्रमुख उद्योगों के प्रत्यक्ष संचालन से
(C) विदेशी आयात पर अत्यधिक भारी सीमा शुल्क लगाने से
(D) खुली प्रतिस्पर्धा और बाज़ार आधारित अर्थव्यवस्था

12. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो योजना आयोग के स्थापना प्रस्ताव में वर्णित उद्देश्यों से संबंधित हैं:
1. स्त्री और पुरुष, सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का बराबर अधिकार हो।
2. समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण सर्वसामान्य की भलाई के लिए हो।
3. अर्थव्यवस्था का संचालन धन या उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण को बढ़ावा दे।
4. राज्य द्वारा किसी भी आर्थिक गतिविधि में हस्तक्षेप न करना।
5. सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना।

उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1, 2 और 3
(C) केवल 3, 4 और 5
(D) केवल 1, 2, 4 और 5

13. विकास संबंधी फ़ैसलों के बारे में अंतिम निर्णय राजनीतिक निर्णय क्यों होना चाहिए?
(A) क्योंकि विशेषज्ञ हमेशा सही राय देते हैं।
(B) क्योंकि केवल उद्योगपति ही देश की ज़रूरतें जानते हैं।
(C) क्योंकि जन-प्रतिनिधि जनता की भावनाओं को समझते हैं।
(D) क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव इसकी माँग करता है।

14. योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी?
(A) अगस्त 1947
(B) जनवरी 1950
(C) अप्रैल 1951
(D) मार्च 1950

15. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (अवधारणा/योजना)
P. बॉम्बे प्लान
Q. पंचवर्षीय योजना
R. केरल मॉडल
S. पोस्को प्लांट

सूची II: (संबंधित क्षेत्र/विषय)
1. विकेंद्रित नियोजन
2. उड़ीसा
3. उद्योगपतियों द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव
4. सोवियत संघ से प्रेरित मॉडल

कूट:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-2, Q-1, R-4, S-3
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

16. योजना आयोग की स्थापना किस प्रकार की गई थी?
(A) भारतीय संविधान के प्रावधानों में विशेष संशोधन द्वारा
(B) भारत सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से
(C) संसद के दोनों सदनों द्वारा एक वैधानिक अधिनियम पारित करके
(D) राष्ट्रपति द्वारा जारी एक विशेष विधायी अध्यादेश के माध्यम से

17. योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किस नई संस्था की स्थापना की गई?
(A) राष्ट्रीय विकास परिषद
(B) नीति आयोग
(C) वित्त आयोग
(D) लोकपाल

18. 'बॉम्बे प्लान' (1944) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा तैयार किया गया एक संयुक्त प्रस्ताव था।
2. इसका उद्देश्य देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाना था।
3. इसमें सरकार द्वारा औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश में बड़े कदम उठाने की मंशा थी।
4. यह योजना 'मुक्त बाज़ार' के सिद्धांत पर आधारित थी।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 4
(B) 1 और 4
(C) 1, 2 और 3
(D) उपरोक्त सभी

19. योजना आयोग की प्रकृति क्या थी?
(A) यह एक संवैधानिक निकाय था।
(B) यह एक स्वायत्त नियामक संस्था थी।

राजनीतिक पार्टी की पहचान करने के लिए दृश्य साधन चाहिए थे।

118. (B) भारतीय जनसंघ
'अखंड भारत' की अवधारणा जिसमें भारत और पाकिस्तान के पुनर्मिलन का आह्वान किया गया था, भारतीय जनसंघ के राजनीतिक एजेंडे का एक मुख्य हिस्सा थी। पार्टी ने 1947 के विभाजन को एक दुखद गलती के रूप में देखा और दोनों देशों के अंततः विलय की वकालत की। यह रुख साझा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों पर आधारित एक एकीकृत राष्ट्रीय पहचान पर पार्टी के मजबूत जोर को दर्शाता था, जो काफी चर्चा में रहा।

119. (D) क्योंकि इससे विभिन्न समूहों को पार्टी से बाहर जाने की बजाय पार्टी के भीतर ही संघर्ष करने का मौका मिलता था।
1950 के दशक में कांग्रेस के भीतर गुटबाजी को ताकत का स्रोत माना जाता था क्योंकि इसने पार्टी को आंतरिक रूप से एक बहुदलीय प्रणाली की तरह कार्य करने की अनुमति दी थी। विभिन्न समूह अलग विपक्षी दल बनाने की आवश्यकता महसूस किए बिना शक्ति के लिए संघर्ष कर सकते थे। इसने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को कांग्रेस के भीतर ही रखा, जिससे पार्टी का आधार व्यापक बना रहा और बाहर से उसे चुनौती देना मुश्किल हो गया।

120. (A) उन्होंने कांग्रेस की नीतियों की सुचिन्तित आलोचना की और शासक दल पर अंकुश रखा।
हालाँकि पहले कुछ दशकों में विपक्ष संख्यात्मक रूप से कमजोर था, लेकिन भारतीय लोकतंत्र को आकार देने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। इन दलों ने वैकल्पिक दृष्टिकोण के लिए एक मंच प्रदान किया और सरकार के कार्यों की सैद्धांतिक आलोचना की। एक प्रहरी के रूप में कार्य करके उन्होंने सत्ताधारी कांग्रेस को अपनी नीतियों को सही ठहराने के लिए मजबूर किया और सुनिश्चित किया कि सरकार लोकतांत्रिक मानदंडों के प्रति जवाबदेह रहे।

121. (C) वे भारत के विभाजन के प्रबल समर्थक थे।
मौलाना अबुल कलाम आजाद उन प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं में से एक थे जिन्होंने धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन का कड़ा विरोध किया था। वे एक संयुक्त धर्मनिरपेक्ष भारत की संभावना में विश्वास करते थे जहाँ सभी समुदाय शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व में रह सकें। एक विद्वान और समर्पित स्वतंत्रता सेनानी के रूप में वे उस समावेशी संस्कृति के प्रतीक बने रहे जिसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने सुरक्षित रखने का लक्ष्य रखा था।

122. (A) केवल धनी और यूरोपीय देशों में।
भारत की स्वतंत्रता के समय कई राजनीतिक विचारकों का मानना था कि लोकतंत्र एक ऐसी विलासिता है जिसे केवल धनी औद्योगिक पश्चिमी राष्ट्र ही वहन कर सकते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के ठीक से काम करने के लिए आर्थिक विकास और साक्षरता का एक निश्चित स्तर आवश्यक है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार अपनाकर भारत ने इस पारंपरिक सोच को चुनौती दी और साबित किया कि लोकतंत्र गरीब देशों में भी जड़ें जमा सकता है।

123. (D) डॉ. भीमराव अंबेडकर
संविधान सभा की बहसों के अंतिम चरणों के दौरान डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने राजनीतिक नेताओं के प्रति अंध भक्ति के खतरों के बारे में एक शक्तिशाली चेतावनी दी थी। उन्होंने जोर दिया कि राजनीति में भक्ति लोकतंत्र के विनाश और तानाशाही के उदय का कारण बनती है। उन्होंने भारतीयों से आग्रह किया कि वे व्यक्तिगत व्यक्तित्वों के बजाय संवैधानिक मूल्यों में अपना विश्वास रखें ताकि एक न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज का निर्माण किया जा सके।

124. (B) सोशलिस्ट पार्टी
किसान मजदूर प्रजा पार्टी एक राजनीतिक समूह था जो समाजवादी आंदोलन से उभरा था। इसके कई सदस्य मूल रूप से कांग्रेस के भीतर समाजवादी धारा और बाद में स्वतंत्र सोशलिस्ट पार्टी का हिस्सा थे। इन नेताओं ने किसानों और मजदूरों के हितों पर ध्यान केंद्रित किया, जो गैर-कम्युनिस्ट वामपंथ के विकास को चिह्नित करने वाले विभिन्न विभाजनों और पुनर्गठनों को दर्शाता है। इसने शुरुआती वर्षों में देश के विपक्षी स्वर को काफी मुखर बनाया।

125. (C) नेशनल कांफ्रेंस
जम्मू और कश्मीर राज्य में शुरुआती दशकों के दौरान राजनीतिक परिदृश्य पर शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कांफ्रेंस का दबदबा था। जबकि कांग्रेस पार्टी भारत के बाकी हिस्सों में सर्वोच्च शक्ति थी, कश्मीर में शुरू में इसकी सीधी उपस्थिति मजबूत नहीं थी। इसके बजाय इसने नेशनल कांफ्रेंस के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे, जिसकी राज्य की राजनीति पर मजबूत पकड़ थी और जो स्थानीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती थी।

126. (D) 26 नवंबर 1949
भारत का संविधान औपचारिक रूप से 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। इस ऐतिहासिक क्षण ने देश के नेताओं द्वारा वर्षों की गहन बहस और प्रारूपण के समापन को चिह्नित किया। हालांकि इसके अधिकांश प्रावधान 26 जनवरी 1950 तक प्रभावी नहीं हुए थे, लेकिन अंगीकरण की तारीख को उस दस्तावेज के सम्मान में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है जो भारतीय लोकतंत्र की नींव है।

127. (A) क्योंकि एक ही दल, कांग्रेस, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर राजनीति में हावी थी।
स्वतंत्रता के बाद की अवधि को 'एक-दलीय प्रभुत्व का युग' कहा जाता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर भारी शक्ति धारण की थी। पहले तीन आम चुनावों के माध्यम से यह वास्तव में राष्ट्रव्यापी संगठन और विशाल जनसमर्थन वाली एकमात्र पार्टी थी। हालांकि अन्य दल अस्तित्व में थे और चुनाव लड़ते थे, वे अभी इतने मजबूत नहीं थे कि राजनीतिक व्यवस्था पर कांग्रेस के समग्र नियंत्रण को चुनौती दे सकें।

शुरू करने के कारण

30. प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-1956) का मुख्य उद्देश्य क्या था?
(A) देश में भारी उद्योगों का जाल बिछाना
(B) सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देना
(C) विदेशी व्यापार को पूरी तरह खोलना
(D) देश को गरीबी के मकड़जाल से निकालना

31. पहली पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसमें सबसे अधिक ज़ोर कृषि-क्षेत्र पर था।
2. इसमें भाखड़ा-नांगल जैसी विशाल सिंचाई परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई।
3. इस योजना में उद्योगों की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई थी।
4. इस योजना में भूमि-सुधार पर ज़ोर दिया गया था।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही नहीं है/हैं?
(A) केवल 3
(B) केवल 1 और 4
(C) केवल 2 और 3
(D) केवल 4

32. प्रथम पंचवर्षीय योजना को तैयार करने वाले विशेषज्ञों में प्रमुख युवा अर्थशास्त्री कौन थे, जिनकी दलील थी कि भारत को अपनी चाल 'धीमी' रखनी चाहिए?
(A) पी. सी. महालनोबिस
(B) के. एन. राज
(C) जे. सी. कुमारप्पा
(D) अमर्त्य सेन

33. पहली पंचवर्षीय योजना में किसे देश के विकास की सबसे बड़ी बाधा माना गया था?
(A) तकनीकी विशेषज्ञों और प्रशिक्षित श्रम की अत्यधिक कमी
(B) भूमि के वितरण का दोषपूर्ण और असमान ढाँचा
(C) औद्योगिक निवेश हेतु पर्याप्त विदेशी पूँजी का पूर्ण अभाव
(D) देश में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता और शासन संबंधी समस्याएँ

34. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए:
कथन I: दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर ज़ोर दिया गया।
कथन II: पहली पंचवर्षीय योजना का मूलमंत्र धीरज था, लेकिन दूसरी योजना की कोशिश तेज़ गति से संरचनात्मक बदलाव करने की थी।
(A) कथन I और II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(C) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।
(D) कथन I और II दोनों असत्य हैं।

35. दूसरी पंचवर्षीय योजना किस अर्थशास्त्री और योजनाकार के नेतृत्व में तैयार की गई थी?
(A) के. एन. राज
(B) वर्गीज़ कुरियन
(C) पी. सी. महालनोबिस
(D) चरण सिंह

36. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया।
कारण (R): सरकार का उद्देश्य निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद करना था।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

37. दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में किन उद्योगों को विकसित किया गया?
(A) केवल पारंपरिक सूती वस्त्र और जूट प्रसंस्करण उद्योग
(B) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित केवल कृषि-आधारित लघु उद्योग
(C) बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार क्षेत्र
(D) बाज़ार में बिकने वाली सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग

38. दूसरी पंचवर्षीय योजना की एक प्रमुख समस्या क्या थी?
(A) घरेलू बचत और निवेश की दरों में अचानक भारी कमी आना
(B) विदेशी तकनीक हेतु बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का भारी व्यय
(C) कृषि क्षेत्र की विकास दर का अपेक्षा से बहुत धीमा होना
(D) सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उद्यमों में लगातार वित्तीय घाटा होना

39. दूसरी पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसने तीव्र औद्योगीकरण पर बल दिया।
2. यह पी.सी. महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी।
3. इसने देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात शुल्क लगाया।
4. इसने कृषि को उद्योगों की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी।
5. इसके आलोचकों का मानना था कि इसमें 'शहरों' की तरफदारी की गई।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1, 2, 3, 4
(B) केवल 1, 2, 4, 5

59. भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार ग्रहण करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन से कारक थे?
1. बॉम्बे प्लान
2. सोवियत खेमे के देशों के अनुभव
3. समाज के बारे में गाँधीवादी विचार
4. किसान संगठनों की माँगें

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3 और 4
(C) केवल 1, 2 और 4
(D) उपरोक्त सभी

60. 'गैर-योजना व्यय' के अंतर्गत किस प्रकार का खर्च आता है?
(A) पंचवर्षीय योजना में तय की गई प्राथमिकताओं पर खर्च
(B) सालाना आधार पर दैनंदिन मदों पर होने वाला खर्च
(C) नई औद्योगिक परियोजनाओं पर निवेश
(D) केवल रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान पर खर्च

61. पंचवर्षीय योजना पर अमल करने का एक प्रमुख लाभ क्या था?
(A) सरकारी तंत्र और नौकरशाही पर शासन का प्रभावी नियंत्रण कम होना
(B) सत्ताधारी दल को तत्काल चुनाव जीतने में चुनावी लाभ प्रदान करना
(C) सरकार को अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक नियोजन का अवसर मिलना
(D) देश में होने वाले सभी विदेशी निवेशों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना

62. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए:
कथन I: पहली पंचवर्षीय योजना में योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊँचा करना था।
कथन II: यह तभी संभव था जब लोगों की बचत उनके खर्चे से ज़्यादा हो।
(A) कथन I और II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(C) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।
(D) कथन I और II दोनों असत्य हैं।

63. पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में बचत की स्थिति क्या थी और योजनाकारों ने क्या प्रयास किया?
(A) बचत कम थी, योजनाकारों ने बचत को बढ़ावा देने की कोशिश की।
(B) बचत अधिक थी, योजनाकारों ने खर्च बढ़ाने का प्रयास किया।
(C) बचत और खर्च बराबर थे, योजनाकारों ने कोई प्रयास नहीं किया।
(D) बचत का आँकड़ा उपलब्ध नहीं था, इसलिए कोई प्रयास नहीं हुआ।

64. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): राष्ट्रवादी नेताओं के मन में यह बात बिलकुल साफ़ थी कि आज़ाद भारत की सरकार के आर्थिक सरोकार अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक सरोकारों से एकदम अलग होंगे।
कारण (R): आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही गरीबी मिटाने और सामाजिक-आर्थिक पुनर्वितरण का मुख्य जिम्मा सरकार का होगा, यह सहमति बन गई थी।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

65. दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगीकरण पर दिए गए ज़ोर ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया?
(A) अर्थव्यवस्था की तत्कालीन स्थिति में कोई सुधार या बदलाव न करना
(B) भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नया और व्यापक आयाम देना
(C) ग्रामीण कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर और अत्यधिक मज़बूत बनाना
(D) देश के उभरते हुए सेवा क्षेत्र को भविष्य हेतु पूरी तरह समाप्त करना

66. केरल में 1987 से 1991 के बीच चलाए गए 'नव लोकतांत्रिक पहल' अभियान का उद्देश्य क्या था?
(A) नागरिक संगठनों के माध्यम से जनता को विकास कार्यों में जोड़ना
(B) राज्य की कानून-व्यवस्था सुधारने हेतु राष्ट्रपति शासन लागू करना
(C) बड़ी निजी कंपनियों को राज्य के सभी विकास कार्य सौंप देना
(D) केंद्र सरकार से विकास हेतु विशेष आर्थिक पैकेज की निरंतर माँग

67. योजना आयोग की स्थापना के प्रस्ताव में किन नीति-निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया था?
1. स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का बराबर अधिकार।
2. समुदाय के भौतिक संसाधनों का सबके हित में बँटवारा।
3. अर्थव्यवस्था का संचालन धन के संकेंद्रण को रोके।
4. नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार।
5. कानून के समक्ष समानता का अधिकार।

उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 4 और 5
(C) केवल 1, 4 और 5
(D) उपरोक्त सभी

(A) सी. वी. रमन
(B) पी. सी. महालनोबिस
(C) जे. सी. बोस
(D) होमी जे. भाभा

50. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): दूसरी पंचवर्षीय योजना के कुछ आलोचकों ने तर्क दिया कि इसने कृषि की जगह उद्योग को प्राथमिकता देकर गलती की।
कारण (R): योजना के कारण खाद्यान्न संकट की आशंका बढ़ गई थी और उद्योग तथा कृषि के बीच संतुलन साधना मुश्किल हो गया था।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

51. पोस्को प्लांट के विरोध का आयोजन करने वाले संगठनों में कौन शामिल थे?
(A) केवल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन
(B) केवल राजनीतिक दल
(C) राष्ट्रीय युवा संगठन और नवनिर्माण समिति
(D) केवल स्थानीय सरकार

52. स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशकों में, भारत ने विकास का कौन-सा रास्ता अपनाया?
(A) विशुद्ध पूंजीवादी
(B) विशुद्ध समाजवादी
(C) अराजकतावादी
(D) मिश्रित अर्थव्यवस्था

53. विकास की 'पश्चिमी' धारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. देश का आधुनिकीकरण।
2. पुरानी सामाजिक संरचना का टूटना।
3. पूँजीवाद और उदारवाद का उदय।
4. पारंपरिक मूल्यों और कृषि पर ज़ोर।
5. संवृद्धि, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्कबुद्धि।
उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1, 2, 3
(B) केवल 1, 2, 3, 5
(C) केवल 4
(D) उपरोक्त सभी

54. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए:
कथन I: योजना आयोग का ज़िक्र भारतीय संविधान में नहीं है।
कथन II: योजना आयोग की तरह, नीति आयोग भी एक गैर-संवैधानिक निकाय है।
(A) कथन I और II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(C) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।
(D) कथन I और II दोनों असत्य हैं।

55. 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी को आर्थिक नीतियों के आधार पर किस श्रेणी में रखा जा सकता है?
(A) पूर्ण रूप से वामपंथी और समाजवादी विचारधारा की श्रेणी में
(B) पूर्ण रूप से दक्षिणपंथी और मुक्त बाज़ार समर्थक विचारधारा वाली
(C) इन दोनों प्रमुख विचारधाराओं से पूरी तरह अलग और स्वतंत्र मार्ग
(D) वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों आर्थिक प्रवृत्तियों का समावेश

56. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (दशक)
P. 1940 का दशक
Q. 1950 का दशक
R. 1960 का दशक
S. 2010 का दशक
सूची II: (प्रमुख घटना/विकास)
1. तीसरी पंचवर्षीय योजना और बढ़ता आर्थिक संकट
2. योजना आयोग का नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापन
3. बॉम्बे प्लान और नियोजन की चर्चा
4. पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यान्वयन
कूट:
(A) P-1, Q-2, R-4, S-3
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-2, Q-1, R-3, S-4
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

57. उड़ीसा के उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि विकास की प्रक्रिया अक्सर क्या उत्पन्न करती है?
(A) संपूर्ण समाज में नीतियों को लेकर व्यापक और पूर्ण सहमति
(B) सभी वर्गों के लिए तत्काल और सार्वभौमिक आर्थिक समृद्धि
(C) विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच परस्पर हितों का प्रबल टकराव
(D) प्राकृतिक पर्यावरण और संसाधनों का वैज्ञानिक आधार पर संरक्षण

58. विकास के समाजवादी मॉडल का प्रमुख उदाहरण कौन सा देश था?
(A) सोवियत संघ
(B) संयुक्त राज्य अमरीका
(C) ब्रिटेन
(D) जर्मनी

(B) केवल 5
(C) केवल 1, 2, 3, 4
(D) उपरोक्त सभी

96. "किसकी ज़रूरतों को उड़ीसा की ज़रूरत कहा जाए?" - यह सवाल किस मूल मुद्दे को उठाता है?
(A) उड़ीसा के भौगोलिक विस्तार और प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति
(B) विकास की परिभाषा और उसके लाभार्थियों को तय करने वाली राजनीतिक प्रक्रिया
(C) उड़ीसा के प्राचीन इतिहास और उसकी सांस्कृतिक विरासत का गौरव
(D) राज्य विधानसभा के आगामी चुनाव कराने की प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया

97. स्वतंत्रता के बाद के पहले दशक में, 'विकास' की बात आते ही पश्चिम का हवाला क्यों दिया जाता था?
(A) भारत में विकास के संबंध में अपनी कोई स्वतंत्र और मौलिक धारणा न होना
(B) आधुनिकता का अर्थ पश्चिमी औद्योगिक देशों के समान होने की व्यापक धारणा
(C) पश्चिमी देशों द्वारा भारत को प्रदान की जा रही निरंतर सैन्य सहायता
(D) भारतीय नेताओं का व्यक्तिगत कारणों से पश्चिमी देशों की यात्रा करना

98. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (प्रश्न/मुद्दा)
P. विकास को लेकर मुख्य बहसें
Q. अपनाई गई रणनीति
R. रणनीति की उपलब्धियाँ
S. रणनीति को क्यों छोड़ा गया
सूची II: (संभावित उत्तर/विषय)
1. नियोजित अर्थव्यवस्था और पंचवर्षीय योजनाएं
2. आर्थिक संकट और नियोजन से मोहभंग
3. कृषि बनाम उद्योग, निजी बनाम सार्वजनिक क्षेत्र
4. बुनियादी ढाँचे का विकास, बचत और निवेश में वृद्धि
कूट:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-1, R-4, S-2
(C) P-2, Q-3, R-1, S-4
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

99. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए:
कथन I: दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रौद्योगिकी के आयात पर बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी।
कथन II: उस समय भारत प्रौद्योगिकी के लिहाज़ से आत्मनिर्भर और उन्नत था।
(A) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(B) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।
(C) कथन I और II दोनों सत्य हैं।
(D) कथन I और II दोनों असत्य हैं।

100. भारत सरकार ने योजना आयोग को क्यों प्रतिस्थापित किया?
(A) पिछली संस्था के अत्यधिक सफल होने के कारण उसके कार्य पूर्ण होना
(B) भारतीय संविधान में समय-समय पर ऐसा करने का स्पष्ट निर्देश होना
(C) संस्था के सभी पुराने सदस्यों के एक साथ सेवानिवृत्त हो जाने के कारण
(D) बदलती आर्थिक और वैश्विक परिस्थितियों में एक नवीन संस्था की आवश्यकता

101. विकास की राजनीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. विकास के फैसले अक्सर एक सामाजिक-समूह के हितों को दूसरे के ऊपर रखते हैं।
2. इसमें मौजूदा पीढ़ी के हितों की तुलना आने वाली पीढ़ी के हितों से की जाती है।
3. इन फैसलों में विशेषज्ञों की राय महत्त्वपूर्ण है, पर अंतिम निर्णय राजनीतिक होता है।
4. ये फैसले हमेशा सर्वसम्मति से लिए जाते हैं और इनमें कोई टकराव नहीं होता।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 4
(B) केवल 1 और 2
(C) 1, 2 और 3
(D) उपरोक्त सभी

102. दूसरी पंचवर्षीय योजना के आवंटन में पहली की तुलना में किस मद पर प्रतिशत व्यय घटा?
(A) उद्योग और खनन
(B) कृषि और सामुदायिक विकास
(C) परिवहन और संचार
(D) ऊर्जा

103. 'नीति आयोग' का पूरा नाम क्या है?
(A) राष्ट्रीय जांच संस्था
(B) राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था
(C) नई भारतीय योजना संस्था
(D) राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था

104. निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. पहली पंचवर्षीय योजना का अंत
2. योजना अवकाश की शुरुआत
3. दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत
4. तीसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत
सही विकल्प चुनें:
(A) 1, 3, 4, 2
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 3, 1, 4, 2

68. 'विकास की चुनौती कहीं ज़्यादा कठिन और गहरी थी' - इस कथन का क्या अभिप्राय है?
(A) विकास का एक अत्यंत आसान, सुगम और सीधा-सरल तकनीकी कार्य होना
(B) विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु केवल पर्याप्त आर्थिक धन की आवश्यकता होना
(C) विकास की संपूर्ण चुनौती केवल विशुद्ध तकनीकी और प्रबंधन संबंधी समस्या होना
(D) विकास में निहित परस्पर-विरोधी हितों और जटिल राजनीतिक निर्णयों की आवश्यकता

69. स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशकों में सार्वजनिक क्षेत्र की विकास परियोजनाओं की मुख्य भूमिका को किस प्रकार दर्शाया गया था?
(A) सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत बड़ी विदेशी कंपनियों के कॉर्पोरेट लोगो
(B) प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दलों द्वारा अपनाए गए स्थायी चुनाव चिह्न
(C) विभिन्न विकास परियोजनाओं की स्मृति में जारी किए गए डाक-टिकट
(D) बड़े राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित सरकारी योजनाओं के विज्ञापन

70. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (स्थान)
P. भाखड़ा
Q. सिंदरी
R. चित्तरंजन
S. हीराकुड
सूची II: (महत्व/परियोजना)
1. उर्वरक कारखाना
2. बाँध
3. विद्युत इंजन कारखाना
4. बाँध
कूट:
(A) P-2, Q-1, R-3, S-4
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-2, Q-3, R-4, S-1

71. भारत में नियोजन के विचार का विरोध करने वाले समूह कौन थे?
(A) वामपंथी दल
(B) समाजवादी नेता
(C) दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग
(D) वास्तव में, उस समय लगभग सभी नियोजन के पक्ष में थे।

72. पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के आवंटन की तुलना करने पर किस क्षेत्र के हिस्से में सबसे अधिक वृद्धि दिखाई देती है?
(A) उद्योग और खनन
(B) कृषि और सामुदायिक विकास
(C) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण
(D) सामाजिक सेवाएँ

73. 'केरल मॉडल' की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारी उद्योगों पर सर्वोच्च प्राथमिकता।
2. शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ज़ोर।
3. कारगर खाद्य-वितरण प्रणाली।
4. विकेंद्रित नियोजन और जन-भागीदारी।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 1 और 4
(C) 2, 3 और 4
(D) उपरोक्त सभी

74. 'इकॉनोमी ऑफ परमानेंस' (Economy of Permanence) नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं?
(A) जे. सी. कुमारप्पा
(B) पी. सी. महालनोबिस
(C) के. एन. राज
(D) जवाहरलाल नेहरु

75. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए:
कथन I: दूसरी पंचवर्षीय योजना के आलोचकों का मानना था कि इससे शहरी और औद्योगिक वर्गों को लाभ हुआ, जबकि ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ गए।
कथन II: कुछ आलोचकों ने भारी उद्योगों के बजाय कृषि-आधारित उद्योगों पर ज़ोर देने का सुझाव दिया।
(A) कथन I और II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(C) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।
(D) कथन I और II दोनों असत्य हैं।

76. निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. नीति आयोग की स्थापना
2. तीसरी पंचवर्षीय योजना का आरंभ
3. भारत की स्वतंत्रता
4. पहली पंचवर्षीय योजना का वास्तविक दस्तावेज़ जारी होना
सही विकल्प चुनें:
(A) 3, 4, 2, 1
(B) 3, 1, 4, 2
(C) 1, 2, 3, 4
(D) 4, 3, 2, 1

77. आजादी के बाद आर्थिक विकास के सवालों पर लिए गए राजनीतिक फैसलों का परिणाम क्या हुआ?
(A) देश की सभी आर्थिक समस्याओं का त्वरित और स्थायी

115. पोस्को प्लांट के विरोध प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पोस्को प्लांट का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि कंपनी और सरकार के बीच हुए सहमति पत्र को रद्द किया जाए।
2. यह प्रदर्शन उड़ीसा के जगतसिंह जिले में प्रस्तावित संयंत्र के खिलाफ था।
3. प्रदर्शनकारियों का तर्क था कि उनकी जीविका और जीवन की कीमत पर संयंत्र लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
4. इस प्रदर्शन में केवल पुरुष शामिल थे।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 4
(C) 1, 2 और 3
(D) उपरोक्त सभी

116. पहली पंचवर्षीय योजना में भूमि-सुधार पर ज़ोर क्यों दिया गया?

(A) शहरी और ढाँचागत विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनिवार्य होना
(B) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बड़े उद्योगों की प्रमुख माँग होना
(C) विदेशों से निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित करने का मुख्य साधन
(D) मौजूदा भूमि वितरण प्रणाली का कृषि विकास में सबसे बड़ी बाधा माना जाना

117. 'आधुनिक' बनने के लिए 'पश्चिमी' होना क्या आवश्यक है? यह प्रश्न किस अंतर्निहित धारणा को चुनौती देता है?

(A) यह विचार कि सभी पारंपरिक समाज आधुनिक समाजों से सदैव बेहतर होते हैं
(B) यह सोच कि आर्थिक विकास राष्ट्र के लिए किसी भी रूप में आवश्यक नहीं है
(C) यह धारणा कि विकास का केवल पश्चिमी औद्योगिक मार्ग ही एकमात्र विकल्प है
(D) यह मत कि पश्चिमी देश वास्तव में अभी भी पूरी तरह से अविकसित हैं

118. दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार का आधार क्या था?

(A) निजी क्षेत्र की विफलता।
(B) बचत और निवेश दोनों का बढ़ना।
(C) विदेशी सहायता की प्रचुरता।
(D) कृषि में अधिशेष उत्पादन।

119. वह कौन सी प्रमुख आर्थिक घटना थी जिसने दुनिया में नियोजन के विचार को बल दिया?

(A) 1991 का खाड़ी युद्ध
(B) 1973 का तेल संकट
(C) 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट
(D) 1930 के दशक की महामंदी

120. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:

अभिकथन (A): आजादी के बाद, भारत में अमरीकी तर्ज के पूँजीवादी विकास के पैरोकार बहुत कम थे।

कारण (R): उस समय, सोवियत संघ के समाजवादी मॉडल और नियोजन के विचार का भारतीय नेताओं और बुद्धिजीवियों के एक बड़े वर्ग पर गहरा प्रभाव था।

(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

121. भारत में विकास के शुरुआती चरण में व्यवसायी, उद्योगपति और किसानों के भरोसे सब कुछ क्यों नहीं छोड़ा जा सकता था?

(A) इन वर्गों का देश के विकास कार्यों में कोई भी वास्तविक रुचि न होना
(B) इन समूहों का आर्थिक प्रबंधन और निर्णय लेने में पूर्णतः अक्षम होना
(C) सामाजिक न्याय और विकास को दिशा देने हेतु सरकारी हस्तक्षेप की अनिवार्यता
(D) इन सभी निजी वर्गों के पास निवेश हेतु पर्याप्त पूँजी का पूर्ण अभाव होना

122. पंचवर्षीय योजनाओं के दस्तावेज़ों पर व्यापक बहस-मुबाहिसा में कौन-कौन से समूह शामिल थे?

(A) बुद्धिजीवी, पत्रकार, उद्योगपति, किसान और राजनेता सहित समाज के विविध वर्ग
(B) केवल सत्ताधारी दल के प्रमुख राजनेता और नीति-निर्माता अधिकारी
(C) केवल सरकारी कार्यालयों में कार्यरत मंत्रालयों के वरिष्ठ कर्मचारी
(D) केवल अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से बुलाए गए कुछ प्रमुख विदेशी विशेषज्ञ

123. निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत में नियोजन के शुरुआती उत्साह में कमी के लिए उत्तरदायी थे?

1. नियोजन का नयापन मंद पड़ गया था।
2. भारत गहन आर्थिक संकट की चपेट में आ चुका था।
3. चीन के साथ 1962 का युद्ध।
4. पाकिस्तान के साथ 1965 का युद्ध और सूखा।
5. सभी लक्ष्य प्राप्त हो चुके थे।

उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1, 2, 3, 4
(C) केवल 5
(D) केवल 3 और 4

87. भारत की प्रारंभिक विकास रणनीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसने आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय दोनों को लक्ष्य माना।
2. इसमें सरकार के लिए एक प्रमुख भूमिका की परिकल्पना की गई।
3. यह उदारवादी-पूंजीवादी मॉडल पर पूरी तरह आधारित थी।
4. इसे लेकर विशेषज्ञों में कोई मतभेद नहीं था।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3 और 4
(C) केवल 1, 3 और 4
(D) केवल 2 और 4

88. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए:

कथन I: भारत में, विकास की धारणा हमेशा से विवादों से घिरी रही है।

कथन II: एक इस्पात संयंत्र के उद्योगपति और उस क्षेत्र के आदिवासी के लिए विकास का अर्थ बिलकुल भिन्न होता है।

(A) कथन I और II दोनों सत्य हैं, और कथन II, कथन I की सही व्याख्या करता है।
(B) कथन I और II दोनों सत्य हैं, लेकिन कथन II, कथन I की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

89. 1950 के दशक में, बचत को बढ़ावा देना एक कठिन काम क्यों था?

(A) आम जनता द्वारा भविष्य हेतु बचत करने में कोई रुचि न दिखाया जाना
(B) तत्कालीन भारत सरकार का बचत को बढ़ावा देने की नीतियों के विरुद्ध होना
(C) पूँजी-भंडार का उपलब्ध रोज़गार योग्य जनसंख्या की तुलना में कम होना
(D) आम लोगों के खर्च का स्तर इतना अधिक होना कि उसे घटाना संभव न होना

90. 1960 के दशक के बाद से बचत की मात्रा में क्या प्रवृत्ति देखी गई?

(A) इसमें लगातार कमी आई।
(B) यह लगातार बढ़ती रही।
(C) यह स्थिर रही।
(D) इसमें अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव हुए।

91. दूसरी योजना की रणनीति में शहरों की तरफदारी का आरोप क्यों लगाया गया?

(A) क्योंकि इसमें कृषि पर ज़ोर दिया गया था।
(B) क्योंकि इसमें ग्रामीण स्कूलों के लिए धन आवंटित किया गया था।
(C) क्योंकि इसमें ग्राम पंचायतों को अधिक अधिकार दिए गए थे।
(D) क्योंकि इसमें उद्योग और शहरी अवसंरचना पर भारी निवेश किया गया था।

92. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:

अभिकथन (A): 'केरल मॉडल' को विकेंद्रित नियोजन का एक उदाहरण माना जाता है।

कारण (R): इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि-सुधार जैसे सामाजिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया और स्थानीय स्तर पर लोगों को योजना प्रक्रिया में शामिल करने का प्रयास किया गया।

(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

93. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन पी.सी. महालनोबिस का सबसे सटीक वर्णन करता है?

(A) कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार लाने वाले प्रमुख भारतीय प्रणेता
(B) गाँधीवादी आर्थिक नीतियों और कुटीर उद्योगों के एकमात्र पैरोकार
(C) तीव्र औद्योगीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र की सक्रिय भूमिका के प्रबल समर्थक
(D) उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों के सबसे पहले और प्रमुख समर्थक

94. 'विकास' के अर्थ को लेकर होने वाले टकराव का उड़ीसा के उदाहरण में कौन सा पक्ष शामिल नहीं था?

(A) स्थानीय आदिवासी
(B) पर्यावरणविद
(C) केंद्र सरकार
(D) पड़ोसी देशों की सरकारें

95. पंचवर्षीय योजना प्रणाली की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. केंद्र और राज्य सरकारों के बजट का योजना-व्यय और गैर-योजना-व्यय में विभाजन।
2. योजना में तय प्राथमिकताओं के अनुसार पाँच साल की अवधि में योजना-व्यय करना।
3. सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर प्रस्तुत करना।
4. सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि के हस्तक्षेप की क्षमता।
5. केवल निजी क्षेत्र के लिए लक्ष्य निर्धारित करना।

उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

(A) केवल 1, 2

समाधान होना
(B) समाज के किसी भी वर्ग के बीच कोई वैचारिक टकराव उत्पन्न न होना
(C) राजनीतिक परिणाम के रूप में उत्पन्न होने वाले निरंतर सामाजिक टकराव
(D) संपूर्ण देश में पूर्ण सामाजिक-आर्थिक समानता का तत्काल स्थापित होना

78. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): भारत में विकास से जुड़े फ़ैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए या विशेषज्ञों की स्वीकृति से होने चाहिए।
कारण (R): खनन, पर्यावरण और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों की राय जानना महत्त्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम निर्णय राजनीतिक होना चाहिए क्योंकि जन-प्रतिनिधि जनता की भावनाओं को समझते हैं।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

79. उड़ीसा के जगतसिंह जिले में प्रस्तावित पोस्को-इंडिया इस्पात संयंत्र का विरोध किसने किया?
(A) विस्थापन का शिकार हुए लोगों ने
(B) केवल सरकार ने
(C) केवल कंपनी के कर्मचारियों ने
(D) केवल विदेशी निवेशकों ने

80. जे.सी. कुमारप्पा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(A) वे महात्मा गाँधी के अनुयायी थे
(B) वे तीव्र औद्योगीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र की सक्रिय भूमिका के समर्थक थे
(C) उन्होंने गाँधीवादी आर्थिक नीतियों को लागू करने की कोशिश की
(D) वे योजना आयोग के सदस्य के रूप में योजना प्रक्रिया में हिस्सेदार थे

81. प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रमुख चुनौतियों और लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र को लगी गहरी मार से उबरना।
2. भाखड़ा-नांगल जैसी विशाल सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण।
3. भूमि सुधारों को लागू करना।
4. राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊँचा करना।
5. सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना।
उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1, 2, 3
(B) केवल 5
(C) केवल 1, 2, 3, 4
(D) उपरोक्त सभी

82. योजना आयोग की सिफारिशें कब प्रभावकारी हो पाती थीं?
(A) जब मंत्रिमंडल उन्हें मंज़ूर करे।
(B) जब राष्ट्रपति उन्हें मंज़ूर कर दें।
(C) जब सर्वोच्च न्यायालय उनकी पुष्टि कर दे।
(D) जब सभी राज्य सरकारें सहमत हों।

83. 'आधुनिकीकरण' की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप पश्चिमी देशों में क्या हुआ?
(A) पुरानी सामाजिक संरचना मज़बूत हुई और सामंतवाद का उदय हुआ।
(B) समाज में कोई बदलाव नहीं हुआ।
(C) पुरानी सामाजिक संरचना टूटी और पूँजीवाद तथा उदारवाद का उदय हुआ।
(D) राजशाही और मज़बूत हुई।

84. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (अवधारणा)
P. वामपंथ
Q. दक्षिणपंथ
R. आधुनिकीकरण
S. विकेंद्रित नियोजन
सूची II: (संबंधित विचार)
1. खुली प्रतिस्पर्धा, बाज़ारमूलक अर्थव्यवस्था
2. राज्य द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था
3. केरल मॉडल
4. पश्चिमी देशों की तरह बनने की प्रक्रिया
कूट:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-1, R-4, S-3
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

85. 'बॉम्बे प्लान' की मंशा क्या थी?
(A) सरकार को देश के आर्थिक निवेश और नियंत्रण से पूरी तरह दूर रखना
(B) भारत में पश्चिमी तर्ज पर मुक्त बाज़ार आधारित अर्थव्यवस्था बनाना
(C) औद्योगिक और आर्थिक निवेश में सरकार द्वारा बड़े कदम उठाने की योजना
(D) केवल कृषि विकास पर सभी उपलब्ध सरकारी संसाधनों को केंद्रित करना

86. पंचवर्षीय योजनाओं का विचार किस देश से लिया गया था?
(A) संयुक्त राज्य अमेरिका
(B) सोवियत संघ
(C) यूनाइटेड किंगडम
(D) जर्मनी

(D) 4, 2, 1, 3

105. विकास की उदारवादी-पूंजीवादी मॉडल मुख्य रूप से कहाँ अपनाया गया था?
(A) सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप
(B) चीन और वियतनाम
(C) यूरोप के अधिकतर हिस्सों और संयुक्त राज्य अमरीका
(D) क्यूबा और उत्तरी कोरिया

106. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): 1944 में भारत के कुछ प्रमुख उद्योगपतियों ने 'बॉम्बे प्लान' नामक एक प्रस्ताव तैयार किया।
कारण (R): वे भारत में एक मुक्त, अनियोजित और अहस्तक्षेपकारी अर्थव्यवस्था चाहते थे।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

107. नियोजित विकास की राजनीति के संदर्भ में कौन-सा कथन मुख्य सार प्रस्तुत करता है?
(A) भारत द्वारा बिना किसी गहन राष्ट्रीय बहस के अपनाया गया विकास मॉडल
(B) विकास का एक विशुद्ध आर्थिक कार्य होना जिसका राजनीति से कोई संबंध नहीं
(C) भारत में नियोजित विकास की पूरी प्रक्रिया का पूर्णतः विफल हो जाना
(D) विभिन्न विचारों और हितों के टकराव के बीच चुनी गई एक राजनीतिक प्रक्रिया

108. पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि के साथ-साथ और किस क्षेत्र में निवेश किया गया?
(A) अंतरिक्ष अनुसंधान
(B) बाँध और सिंचाई
(C) सूचना प्रौद्योगिकी
(D) शेयर बाज़ार

109. आज़ादी के आंदोलन के दौरान, भावी भारत की सरकार की आर्थिक भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर सहमति बनी थी?
1. सरकार अंग्रेजी हुकूमत की तरह संकुचित व्यापारिक हितों की पूर्ति करेगी।
2. गरीबी मिटाने का मुख्य जिम्मा सरकार का होगा।
3. सामाजिक-आर्थिक पुनर्वितरण का काम सरकार करेगी।
4. सरकार आर्थिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी।
5. औद्योगीकरण को उचित रास्ता माना जाएगा।
उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 4
(B) केवल 2, 3 और 5
(C) केवल 4
(D) उपरोक्त सभी

110. 'योजना-अवकाश' (Plan Holiday) की अवधि क्या थी?
(A) 1961-1964
(B) 1970-1973
(C) 1951-1954
(D) 1966-1969

111. के. एन. राज की 'धीमी चाल' की दलील के पीछे क्या तर्क था?
(A) तेज़ रफ़्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँच सकता था।
(B) भारत के पास तेज़ विकास के लिए संसाधन नहीं थे।
(C) भारतीय लोग आलसी थे।
(D) राजनीतिक दल तेज़ विकास नहीं चाहते थे।

112. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (शब्द)
P. योजना-व्यय
Q. गैर-योजना-व्यय
R. भूमि-सुधार
S. संरक्षणवाद
सूची II: (अर्थ/उदाहरण)
1. आयात पर भारी शुल्क लगाना
2. ज़मींदारी उन्मूलन
3. पंचवर्षीय योजना में तय मदों पर खर्च
4. दैनंदिन मदों पर सालाना खर्च
कूट:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-3, R-1, S-2
(C) P-3, Q-4, R-2, S-1
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

113. निम्नलिखित में से कौन गाँधीवादी अर्थशास्त्री थे और योजना आयोग के सदस्य भी रहे?
(A) पी. सी. महालनोबिस
(B) जे. सी. कुमारप्पा
(C) के. एन. राज
(D) जवाहरलाल नेहरु

114. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए:
कथन I: केरल में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम है।
कथन II: इसके बावजूद, केरल ने सामाजिक विकास के कई संकेतकों (जैसे साक्षरता, स्वास्थ्य) में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
(A) कथन I और II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(C) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।
(D) कथन I और II दोनों असत्य हैं।

(C) केवल 1, 2, 3, 5
(D) उपरोक्त सभी

40. भारत के योजनाकारों को उद्योग और कृषि के बीच संतुलन साधने में भारी कठिनाई क्यों आई?
(A) उद्योगों में बढ़ते निवेश से उत्पन्न खाद्यान्न-संकट की आशंका
(B) दोनों क्षेत्रों हेतु योग्य तकनीकी विशेषज्ञों की उपलब्धता न होना
(C) विदेशी देशों द्वारा केवल औद्योगिक विकास हेतु ऋण सहायता देना
(D) किसानों द्वारा औद्योगिक विकास की नीतियों का संगठित विरोध करना

41. 'केरल मॉडल' में विकास और नियोजन के लिए किस पर ज़ोर दिया गया है?
(A) राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी उद्योगों की स्थापना करना
(B) केवल प्रमुख महानगरों और शहरी क्षेत्रों के ढाँचागत विकास पर
(C) शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि-सुधार और गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम
(D) सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर सेवाओं के वैश्विक विस्तार पर

42. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (व्यक्ति)
P. पी.सी. महालनोबिस
Q. जे.सी. कुमारप्पा
R. के.एन. राज
S. चरण सिंह
सूची II: (योगदान/पहचान)
1. 'इकॉनोमी ऑफ परमानेंस' के लेखक
2. भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक
3. किसान नेता
4. पहली पंचवर्षीय योजना से जुड़े अर्थशास्त्री
कूट:
(A) P-2, Q-1, R-4, S-3
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

43. निम्नलिखित में से कौन सी 'केरल मॉडल' की एक उपलब्धि नहीं है?
(A) शत-प्रतिशत साक्षरता
(B) कम शिशु मृत्यु-दर
(C) बढ़ी हुई आयु-प्रत्याशा
(D) कमज़ोर औद्योगिक-आधार

44. जे.सी. कुमारप्पा जैसे गाँधीवादी अर्थशास्त्रियों ने किस प्रकार की विकास नीति का समर्थन किया?
(A) शहरीकरण और भारी उद्योगों पर आधारित
(B) ग्रामीण औद्योगीकरण पर आधारित
(C) पश्चिमी देशों के मॉडल की नकल
(D) केंद्रीकृत नियोजन पर आधारित

45. सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. स्वतंत्रता के बाद इसका मुख्य उद्देश्य देश का औद्योगिक विकास करना था।
2. इसमें सरकार द्वारा नियंत्रित और संचालित उद्योग शामिल थे।
3. दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसके विस्तार पर विशेष बल दिया गया।
4. इसका एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना था।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 4
(B) 1 और 2
(C) 1, 2 और 3
(D) उपरोक्त सभी

46. 'विकेंद्रित नियोजन' की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा विकल्प करता है?
(A) केंद्र सरकार द्वारा सभी राष्ट्रीय योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन
(B) केवल विकसित महानगरों के औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना
(C) निजी कॉर्पोरेट कंपनियों को संपूर्ण विकास योजनाएँ बनाने की अनुमति
(D) निचले स्तर पर जन-भागीदारी से योजनाएँ तैयार करने की प्रक्रिया

47. पी. सी. महालनोबिस किसलिए जाने जाते हैं?
(A) भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद् के रूप में
(B) श्वेत क्रांति के जनक के रूप में
(C) भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में
(D) भूमि सुधारों के प्रमुख प्रस्तावक के रूप में

48. निम्नलिखित योजनाओं/अवधारणाओं को उनके प्रकट होने के क्रम में व्यवस्थित करें:
1. केरल मॉडल का विकास
2. बॉम्बे प्लान
3. महालनोबिस मॉडल (दूसरी योजना)
4. के. एन. राज मॉडल (पहली योजना)
सही विकल्प चुनें:
(A) 2, 4, 3, 1
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 3, 4, 1
(D) 4, 2, 1, 3

49. भारतीय सांख्यिकी संस्थान (Indian Statistical Institute) के संस्थापक कौन थे?

124. फ्रैंकिन फ्रैंकल के अनुसार कांग्रेस पार्टी के भीतर क्या अंतर्विरोध था?
(A) राष्ट्रीयकरण और निजीकरण की नीतियों के बीच पूर्ण और स्पष्ट टकराव
(B) एक ओर समाजवादी सिद्धांत अपनाना और दूसरी ओर निजी निवेश हेतु उदार होना
(C) कृषि क्षेत्र के विकास और भारी उद्योगों के बीच प्राथमिकता का संघर्ष
(D) केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच राजस्व बँटवारे का विवाद

125. बिहार का अकाल और 'ज़ोनिंग' (इलाका बंदी) की नीति किस समस्या से संबंधित हैं?
(A) औद्योगिक उत्पादन
(B) शहरी आवास
(C) खाद्यान्न का अभाव और वितरण
(D) शिक्षा का प्रसार

126. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (व्यक्ति)
P. चरण सिंह
Q. पी.सी. महालनोबिस
R. वर्गीज कुरियन
S. के.एन. राज
सूची II: (योगदान/क्षेत्र)
1. औद्योगीकरण
2. सहकारी डेयरी (अमूल)
3. कृषि और ग्रामीण भारत
4. पहली पंचवर्षीय योजना
कूट:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-1, R-2, S-4
(C) P-2, Q-3, R-4, S-1
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

127. भारत द्वारा अपनाई गई विकास की मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है?
(A) सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का सह-अस्तित्व।
(B) केवल कृषि और उद्योग का मिश्रण।
(C) केवल निजी और विदेशी क्षेत्र का मिश्रण।
(D) केवल केंद्र और राज्य सरकारों का मिश्रण।

128. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए:
कथन I: दूसरी पंचवर्षीय योजना ने भारत के आर्थिक विकास की बुनियाद रखी।
कथन II: इसकी आलोचनाओं के बावजूद, इससे भारत में औद्योगिक विकास की एक नई दिशा मिली।
(A) कथन I और II दोनों असत्य हैं।
(B) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I और II दोनों सत्य हैं।

129. योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय था।
2. योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में हुई थी।
3. प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे।
4. योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग कार्य कर रहा है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) 2, 3 और 4
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) उपरोक्त सभी

130. "विकासशील" या "अविकसित" जैसे शब्द किस विकास की धारणा से उपजे थे?
(A) पश्चिमी आधुनिकीकरण की धारणा
(B) गाँधीवादी धारणा
(C) समाजवादी धारणा
(D) पर्यावरणवादी धारणा

131. भारत में नियोजित विकास की राजनीति के अध्ययन का क्या महत्व है?
(A) यह केवल अतीत की एक कहानी है जिसका वर्तमान से कोई संबंध नहीं है
(B) यह विषय केवल अर्थशास्त्रियों और सांख्यिकीविदों के लिए ही महत्वपूर्ण है
(C) वर्तमान की कई आर्थिक और राजनीतिक बहसों के ऐतिहासिक मूल को समझना
(D) यह तथ्य साबित करना कि भारत ने अब तक कोई भी वास्तविक प्रगति नहीं की

132. निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. भारत में पोस्को प्लांट का विरोध प्रदर्शन
2. बॉम्बे प्लान
3. पी.सी. महालनोबिस का निधन
4. योजना आयोग की स्थापना
सही विकल्प चुनें:
(A) 2, 4, 3, 1
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 4, 3, 2, 1
(D) 2, 1, 4, 3

133. पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर सबसे ज्यादा ज़ोर था?
(A) भारी उद्योग
(B) service क्षेत्र
(C) कृषि क्षेत्र (बाँध और सिंचाई सहित)
(D) परमाणु ऊर्जा

की विफलता और द्वितीय योजना के औद्योगिक पूर्वाग्रह के कारण कृषि में ठहराव था। इस संकट ने भारत की योजना रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को प्रेरित किया, जिसे 'हरित क्रांति' के नाम से जाना जाता है। यह पिछली संस्थागत सुधार (जैसे भूमि सुधार) की रणनीति से एक विचलन था और इसने एक नई प्रौद्योगिकी-गहन कृषि रणनीति अपनाई। इस नई रणनीति के मूल में उच्च उपज वाले बीज (High-Yielding Variety - HYV), विशेष रूप से गेहूं और चावल के, का उपयोग था, जिन्हें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और सबसे महत्वपूर्ण, सुनिश्चित सिंचाई की आवश्यकता थी। सीमित संसाधनों के कारण, सरकार ने इस पैकेज कार्यक्रम को केवल उन क्षेत्रों में केंद्रित करने का निर्णय लिया जहाँ सफलता की सर्वाधिक संभावना थी, जैसे कि पंजाब, Haryana और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहाँ पहले से ही बेहतर सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध थीं। इसके परिणाम चमत्कारी थे; भारत कुछ ही वर्षों में खाद्य-अनाजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। हालाँकि, हरित क्रांति की सफलता एकतरफा नहीं थी। इसने क्षेत्रीय असमानताओं को गहरा कर दिया, क्योंकि सिंचित और असिंचित क्षेत्रों के बीच की खाई बढ़ गई। इसके अलावा, यह केवल धनी किसानों को ही लाभ पहुँचा सकी जो महंगे इनपुट खरीद सकते थे, जिससे ग्रामीण समाज में असमानता बढ़ी।

उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

166. 1960 के दशक के मध्य में भारत की कृषि रणनीति में बदलाव का तात्कालिक कारण क्या था?

(A) औद्योगिक क्षेत्र में अत्यधिक सफलता।
(B) एक गंभीर खाद्य संकट और मानसून की विफलता।
(C) भूमि सुधारों की पूर्ण सफलता।
(D) विश्व बैंक से मिला एक बड़ा अनुदान।

167. हरित क्रांति की रणनीति पिछली कृषि नीतियों से किस प्रकार भिन्न थी?

(A) इसने संस्थागत सुधारों के बजाय प्रौद्योगिकी-गहन दृष्टिकोण पर जोर दिया।
(B) यह रणनीति पूरी तरह से पारंपरिक भूमि सुधारों और पुनर्वितरण नीतियों पर ही केंद्रित थी।
(C) इसने देश भर में केवल पारंपरिक जैविक खेती और प्राकृतिक खाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया।
(D) इसने कृषि क्षेत्र के लिए दिए जाने वाले सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सरकारी समर्थन को समाप्त कर दिया।

168. हरित क्रांति पैकेज के प्रमुख घटक क्या थे?

(A) केवल पारंपरिक देसी बीज और स्थानीय रूप से उपलब्ध प्राकृतिक जैविक खाद का उपयोग।
(B) केवल भारी ट्रैक्टरों और उन्नत कृषि मशीनरी का बड़े पैमाने पर आयात और प्रयोग।
(C) उच्च उपज वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, और सुनिश्चित सिंचाई।
(D) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का पूर्ण पुनर्वितरण और सहकारी खेती प्रणालियों का गठन।

169. सरकार ने प्रारंभ में हरित क्रांति को कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में ही क्यों केंद्रित किया?

(A) क्योंकि ये भौगोलिक क्षेत्र राजनीतिक और सामाजिक रूप से देश में सबसे अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली थे।
(B) क्योंकि वहाँ के रहने वाले किसान शिक्षा के स्तर पर अन्य क्षेत्रों के मुकाबले कहीं अधिक उन्नत और शिक्षित थे।
(C) देश के बाकी हिस्सों में इस आधुनिक कृषि कार्यक्रम का वहां के निवासियों और समूहों द्वारा कड़ा विरोध हुआ था।
(D) सीमित संसाधनों के कारण और उन क्षेत्रों में सफलता की अधिक संभावना के चलते जहाँ बेहतर सिंचाई थी।

170. स्रोत के अनुसार, हरित क्रांति का एक प्रमुख सामाजिक-आर्थिक परिणाम क्या था?

(A) इसने ग्रामीण भारत के सभी सामाजिक वर्गों के बीच पूर्ण और स्थायी आर्थिक समानता स्थापित की।
(B) इसके नकारात्मक प्रभाव के कारण भारत खाद्य पदार्थों के आयात पर पहले से कहीं अधिक निर्भर हो गया।
(C) इसने क्षेत्रीय और ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को बढ़ाया।
(D) इसने भारत के सभी कृषि क्षेत्रों और भौगोलिक प्रांतों का समान रूप से और संतुलित विकास किया।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

भारत में विकास के प्रमुख, राष्ट्रीय मॉडल के समानांतर, एक वैकल्पिक दृष्टिकोण भी उभरा, जिसे 'केरल मॉडल' के रूप में जाना जाता है। यह मॉडल इस विचार को चुनौती देता है कि उच्च प्रति व्यक्ति आय ही मानव विकास का एकमात्र निर्धारक है। केरल ने, अपनी अपेक्षाकृत कम प्रति व्यक्ति आय और एक कमजोर औद्योगिक आधार के बावजूद, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर जैसे सामाजिक संकेतकों में असाधारण परिणाम प्राप्त किए हैं। इस मॉडल की सफलता का श्रेय राज्य द्वारा सार्वजनिक सेवाओं, विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निरंतर और व्यापक निवेश को दिया जाता है। विकेंद्रीकृत योजना और शासन, जिसमें स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी होती है, ने इन सेवाओं के प्रभावी वितरण को सुनिश्चित किया है। इसके अतिरिक्त, ऐतिहासिक रूप से मजबूत सामाजिक आंदोलनों और राजनीतिक जागरूकता ने राज्य को प्रगतिशील नीतियों, जैसे कि प्रभावी भूमि सुधार और एक मजबूत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को लागू करने के लिए प्रेरित किया। केरल मॉडल यह प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के लक्ष्यों को केवल आर्थिक विकास के माध्यम से ही नहीं, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में लक्षित सार्वजनिक कार्रवाई और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। यह 'विकास' की एक वैकल्पिक परिभाषा प्रस्तुत करता है जो आर्थिक सकल उत्पादन के बजाय मानव कल्याण और क्षमताओं के विस्तार पर केंद्रित है।

144. 'विकास' को लेकर राजनीतिक टकराव क्यों होते हैं?
(A) राष्ट्र के सर्वांगीण विकास हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का उपलब्ध न होना
(B) विकास के लाभ और लागत का समाज के विभिन्न वर्गों में होने वाला असमान वितरण
(C) देश के प्रमुख राजनेताओं का वास्तव में राष्ट्र का विकास न चाहना
(D) विकास की किसी भी एक सर्वमान्य और सटीक परिभाषा का अस्तित्व में न होना

145. भारत द्वारा अपनाई गई विकास की रणनीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत ने सोवियत संघ के मॉडल का आँख बंद करके अनुसरण किया।
2. भारत ने पूंजीवादी और समाजवादी दोनों मॉडलों के कुछ तत्वों को मिलाकर 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' अपनाई।
3. भारत के विकास मॉडल में निजी क्षेत्र के लिए कोई जगह नहीं थी।
4. सार्वजनिक क्षेत्र को विकास में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2 और 4
(C) केवल 1, 2 और 4
(D) उपरोक्त सभी

146. 'बॉम्बे प्लान' से क्या सिद्ध होता है?
(A) उद्योगपतियों का नियोजित अर्थव्यवस्था और राज्य की सक्रिय भूमिका के पक्ष में होना
(B) भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों का आर्थिक नियोजन के पूर्णतः विरुद्ध होना
(C) उद्योगपतियों द्वारा केवल ग्रामीण कृषि विकास हेतु संसाधनों की माँग करना
(D) भारतीय उद्योगपतियों का सभी विदेशी कंपनियों को बाज़ार से बाहर करना

147. निम्नलिखित में से कौन सा कथन 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' मॉडल की सही व्याख्या करता है?
(A) एक अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का आर्थिक गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण हो
(B) एक अर्थव्यवस्था जिसमें बाज़ार की शक्तियों का स्वतंत्र रूप से संचालन हो
(C) एक अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र सह-अस्तित्व में हों
(D) एक अर्थव्यवस्था जिसमें कृषि और ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता मिले

148. भारत की विकास यात्रा के शुरुआती दौर में किस बात पर आम सहमति थी?
(A) विकास का अर्थ केवल आर्थिक संवृद्धि है।
(B) विकास का काम पूरी तरह से निजी क्षेत्र पर छोड़ देना चाहिए।
(C) विकास के लिए पश्चिमी मॉडल ही एकमात्र रास्ता है।
(D) विकास का अर्थ आर्थिक संवृद्धि और सामाजिक न्याय दोनों है।

149. पहली पंचवर्षीय योजना का काल क्या था?
(A) 1947-1952
(B) 1950-1955
(C) 1951-1956
(D) 1952-1957

150. दूसरी पंचवर्षीय योजना का काल क्या था?
(A) 1951-1956
(B) 1956-1961
(C) 1961-1966
(D) 1966-1971

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय आर्थिक नीति के निर्धारण में 'बॉम्बे प्लान' (1944) एक महत्वपूर्ण वैचारिक मील का पत्थर था। यह योजना, जिसे भारत के आठ प्रमुख उद्योगपतियों, जिनमें जे.आर.डी. टाटा और घनश्याम दास बिड़ला शामिल थे, द्वारा प्रस्तावित किया गया था, एक विरोधाभासी दस्तावेज़ प्रतीत हो सकता है क्योंकि इसमें पूंजीपतियों ने ही एक राज्य-नियंत्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया था। इस योजना के पीछे का तर्क गहन और दूरदर्शी था। उद्योगपतियों ने यह समझा कि नव-स्वतंत्र भारत में निजी क्षेत्र के पास भारी उद्योगों, बुनियादी ढाँचे और सामाजिक सेवाओं में आवश्यक विशाल निवेश करने के लिए न तो पूंजी थी और न ही जोखिम उठाने की क्षमता। उन्होंने एक 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' की कल्पना की, जहाँ राज्य मुख्य क्षेत्रों जैसे कि बिजली, इस्पात, और परिवहन में निवेश करके एक सक्षम वातावरण का निर्माण करेगा। यह सार्वजनिक निवेश निजी उद्योगों के लिए एक स्थिर बाजार और आवश्यक इनपुट प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, राज्य द्वारा संरक्षणवादी व्यापार नीतियां, जैसे कि आयात पर उच्च शुल्क, घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाएँगी, जिससे उन्हें विकसित होने का अवसर मिलेगा। अतः, 'बॉम्बे प्लान' समाजवाद का आह्वान नहीं था, बल्कि यह एक pragmatic, या व्यावहारिक, राज्य-सहायता प्राप्त पूंजीवाद का खाका था, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय आर्थिक संप्रभुता और तीव्र औद्योगीकरण सुनिश्चित करना था।

उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

151. 'बॉम्बे प्लान' के संदर्भ में, उद्योगपतियों द्वारा राज्य-नियंत्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन करने का मुख्य कारण क्या था?
(A) समाजवादी विचारधारा के प्रति उनके गहरे लगाव और सामाजिक समानता की उनकी प्रबल इच्छा थी।
(B) उन्होंने महसूस किया कि निजी क्षेत्र के पास भारी निवेश के लिए आवश्यक पूंजी और क्षमता का अभाव था।
(C) वे देश के सभी निजी उद्योगों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण करके

उन्हें सरकारी नियंत्रण में लाना चाहते थे।
(D) वे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को पूरी तरह से प्रतिबंधित करके केवल घरेलू पूंजी पर निर्भर रहना चाहते थे।

152. 'बॉम्बे प्लान' में प्रस्तावित 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' मॉडल का क्या अर्थ था?
(A) सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का सह-अस्तित्व, जिसमें राज्य की एक प्रमुख विकासात्मक भूमिका हो।
(B) कृषि और औद्योगिक विकास के बीच सरकारी निवेश का एक समान और संतुलित वित्तीय विभाजन।
(C) केवल उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाले निजी क्षेत्र और भारी उद्योगों का पूर्ण अभाव।
(D) एक ऐसी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से विदेशी ऋण और अंतरराष्ट्रीय सहायता पर निर्भर हो।

153. स्रोत के अनुसार, उद्योगपतियों ने राज्य से संरक्षणवादी व्यापार नीतियों की अपेक्षा क्यों की?
(A) भारतीय औद्योगिक उत्पादों की वैश्विक गुणवत्ता में गुणात्मक सुधार करने और निर्यात बढ़ाने के लिए।
(B) वैश्विक बाजारों में भारतीय उत्पादों के निर्यात को अधिकतम करने और विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए।
(C) घरेलू उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से बचाने और उन्हें विकसित होने का अवसर देने के लिए।
(D) अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौतों को विश्व स्तर पर सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए।

154. निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 'बॉम्बे प्लान' के अनुसार राज्य के निवेश के लिए प्राथमिकता में नहीं था?
(A) बिजली उत्पादन
(B) इस्पात उद्योग
(C) परिवहन और बुनियादी ढाँचा
(D) खुदरा व्यापार और उपभोक्ता वस्तुएँ

155. स्रोत 'बॉम्बे प्लान' को किस रूप में वर्णित करता है?
(A) एक पूर्ण और व्यापक समाजवादी आर्थिक घोषणापत्र के आधिकारिक दस्तावेज के रूप में।
(B) एक अनियंत्रित और पूर्ण मुक्त-बाजार पूंजीवाद के प्रबल समर्थक और वैचारिक स्रोत के रूप में।
(C) राज्य-सहायता प्राप्त पूंजीवाद के एक व्यावहारिक खाके के रूप में।
(D) एक ग्रामीण और कृषि-केंद्रित विकास योजना के प्राथमिक प्रस्ताव के रूप में।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61) का वैचारिक आधार काफी हद तक प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा विकसित मॉडल पर आधारित था। यह मॉडल, जिसे महालनोबिस दो-क्षेत्रीय मॉडल के रूप में जाना जाता है, एक बंद अर्थव्यवस्था की धारणा पर आधारित था और इसका मुख्य उद्देश्य भारत को दीर्घकाल में आत्मनिर्भर बनाना था। मॉडल का केंद्रीय तर्क यह था कि आर्थिक विकास की दर को स्थायी रूप से बढ़ाने के लिए, निवेश का एक बड़ा हिस्सा उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के बजाय पूंजीगत वस्तुओं (मशीनों का निर्माण करने वाली मशीनें) के उत्पादन में लगाया जाना चाहिए। महालनोबिस का मानना था कि प्रारंभ में उपभोक्ता वस्तुओं का कम उत्पादन होने से कठिनाई होगी, लेकिन एक मजबूत घरेलू पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का निर्माण हो जाने पर, भारत भविष्य में अपनी आवश्यकताओं के लिए विदेशी आयात पर निर्भर नहीं रहेगा और अपनी गति से उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा सकेगा। इस रणनीति को 'आयात प्रतिस्थापन औद्योगीकरण' (Import Substitution Industrialization - ISI) के रूप में जाना गया। इस मॉडल के कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को भारी उद्योगों जैसे इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, और मशीन-निर्माण में अग्रणी भूमिका निभानी थी। हालांकि इस रणनीति ने भारत के औद्योगिक आधार की नींव रखी, लेकिन इसकी आलोचना भी की गई क्योंकि इसने कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी के कारण मुद्रास्फीति का दबाव बनाया।
उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

156. महालनोबिस मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या था, जैसा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था?
(A) कृषि उत्पादन और सिंचाई सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से अधिकतम और विस्तारित करना।
(B) पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का निर्माण करके दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
(C) विदेशी बाजारों से विलासिता और उपभोक्ता वस्तुओं के आयात को निरंतर प्रोत्साहित करना।
(D) तृतीयक या सेवा क्षेत्र के व्यापक विस्तार पर पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित करना।

157. 'आयात प्रतिस्थापन औद्योगीकरण' (ISI) की रणनीति का क्या अर्थ है?
(A) निर्यात को व्यापक रूप से बढ़ावा देने के लिए सभी आयात शुल्कों को पूरी तरह से हटाना।
(B) केवल कूटनीतिक रूप से मित्र देशों से ही आवश्यक वस्तुओं का आयात करने की सीमित नीति।
(C) आधुनिक विदेशी प्रौद्योगिकी और मशीनों के आयात पर पूर्ण और स्थायी प्रतिबंध लगाना।
(D) उन वस्तुओं का घरेलू स्तर पर उत्पादन करना जो पहले विदेश से आयात की जाती थीं।

158. महालनोबिस मॉडल ने किस क्षेत्र में निवेश को सर्वोच्च प्राथमिकता दी?
(A) भारी और पूंजीगत वस्तु उद्योग।
(B) उपभोक्ता वस्तु उद्योग।
(C) कृषि और सिंचाई।
(D) सेवाएँ और पर्यटन।

159. स्रोत के अनुसार, महालनोबिस मॉडल के कार्यान्वयन का एक नकारात्मक परिणाम क्या था?

(A) भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से विदेशी ऋण और वित्तीय सहायता पर निर्भर हो गई।
(B) देश का औद्योगिक विकास और विनिर्माण गतिविधियाँ पूरी तरह से और स्थायी रूप से रुक गईं।
(C) कृषि क्षेत्र की संभावित उपेक्षा और मुद्रास्फीति का दबाव।
(D) अर्थव्यवस्था के भीतर सार्वजनिक क्षेत्र का पूर्ण विघटन और निजीकरण हो गया।

160. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र को अग्रणी भूमिका क्यों सौंपी गई?
(A) निजी क्षेत्र के पास भारी उद्योगों में निवेश करने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं थे।
(B) देश के सभी निजी उद्योगों पर वैधानिक प्रतिबंध लगाना और उन्हें बंद करना सरकार का मुख्य लक्ष्य था।
(C) यह आर्थिक मॉडल निजी क्षेत्र की किसी भी प्रकार की भागीदारी और निवेश का पूरी तरह से विरोध करता था।
(D) सार्वजनिक क्षेत्र उपभोक्ता और विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन में निजी क्षेत्र से कहीं अधिक कुशल था।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

स्वतंत्रता के समय, भारत को एक ऐसी कृषि-व्यवस्था विरासत में मिली थी जो सामंती, शोषक और अनुत्पादक थी। इस संरचनात्मक समस्या को हल करने के लिए, प्रारंभिक पंचवर्षीय योजनाओं, विशेष रूप से पहली योजना में, भूमि सुधारों को एक केंद्रीय स्थान दिया गया। इन सुधारों के दोहरे उद्देश्य थे: सामाजिक न्याय स्थापित करना और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। भूमि सुधार कार्यक्रम के तीन मुख्य स्तंभ थे। पहला, बिचौलियों का उन्मूलन, जिसका उद्देश्य ज़मींदारी और जागीरदारी जैसी प्रणालियों को समाप्त करना था, जो किसानों से भारी लगान वसूलते थे और भूमि में कोई निवेश नहीं करते थे। दूसरा, काश्तकारी सुधार, जिसके तहत काश्तकारों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करना, लगान को विनियमित करना और अंततः उन्हें भूमि का मालिकाना हक दिलाना था। तीसरा, भूमि की हदबंदी (Lऔर Ceiling), जिसके अनुसार एक परिवार द्वारा रखी जास्कने वाली भूमि की अधिकतम सीमा तय की गई और अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों में वितरित किया जाना था। यद्यपि बिचौलियों के उन्मूलन में काफी हद तक सफलता मिली, लेकिन काश्तकारी सुधार और भूमि हदबंदी के कानून अपने इच्छित परिणाम प्राप्त करने में विफल रहे। शक्तिशाली भू-स्वामी वर्गों के राजनीतिक प्रतिरोध, कानूनी दांव-पेंच और कानूनों में मौजूद खामियों ने इन सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन को बाधित किया। परिणामस्वरुप, भारत में भूमि के पुनर्वितरण का लक्ष्य अधूरा रह गया।

उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

161. स्वतंत्रता के बाद भारत में भूमि सुधारों को लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या था?
(A) केवल भारी औद्योगिक विकास और विनिर्माण क्षेत्र को तेजी से बढ़ावा देना।
(B) बहुराष्ट्रीय विदेशी कंपनियों को भारत की उपजाऊ कृषि भूमि सीधे बेचने की अनुमति देना।
(C) किसानों पर लगने वाले सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को पूरी तरह से समाप्त करना।
(D) सामाजिक न्याय स्थापित करना और कृषि उत्पादकता बढ़ाना।

162. भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत 'बिचौलियों का उन्मूलन' का क्या तात्पर्य था?
(A) छोटे किसानों और राज्य सरकार के बीच मौजूद सभी कानूनी मध्यस्थों को पूर्णतः हटाना।
(B) ज़मींदारी और जागीरदारी जैसी शोषक प्रणालियों को समाप्त करना।
(C) खुले बाजार में फसल खरीदने वाले सभी निजी व्यापारियों और बिचौलियों पर कड़ा प्रतिबंध लगाना।
(D) केवल राज्य समर्थित सरकारी एजेंसियों द्वारा ही फसल कटाई और भंडारण की अनुमति प्रदान करना।

163. स्रोत के अनुसार भूमि सुधारों का कौन सा घटक सबसे अधिक सफल रहा?
(A) भूमि की हदबंदी (Lऔर Ceiling)
(B) काश्तकारी सुधार
(C) बिचौलियों का उन्मूलन
(D) सहकारी खेती का गठन

164. भूमि हदबंदी और काश्तकारी सुधारों के कानून पूरी तरह से सफल क्यों नहीं हो पाए?
(A) स्थानीय किसानों और भूमिहीनों ने स्वयं इन सुधारों और कानूनों का व्यापक विरोध किया।
(B) सरकार के पास इन जटिल कानूनों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए पर्याप्त धन की कमी थी।
(C) भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव और वैश्विक संधियों के कारण इन प्रगतिशील कानूनों को वापस ले लिया गया।
(D) शक्तिशाली भू-स्वामियों के राजनीतिक प्रतिरोध और कानूनी खामियों के कारण।

165. 'भूमि की हदबंदी' (Lऔर Ceiling) की नीति का मुख्य लक्ष्य क्या था?
(A) भूमि स्वामित्व की अधिकतम सीमा तय करके अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों में वितरित करना।
(B) देश की सभी उपलब्ध कृषि भूमि का पूर्ण राष्ट्रीयकरण करके उसे सरकारी नियंत्रण में लाना।
(C) किसानों को भविष्य में अपनी पैतृक भूमि बेचने या हस्तांतरित करने से पूरी तरह से रोकना।
(D) कृषि भूमि पर बड़े पैमाने पर भारी औद्योगिक इकाइयाँ और विनिर्माण संयंत्र स्थापित करना।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

1960 के दशक के मध्य में, भारत को एक गंभीर खाद्य संकट का सामना करना पड़ा, जिसका कारण लगातार दो मानसून

निर्देशित नियोजन ही विकास का सबसे सफल मंत्र माना जा रहा था।

21. (B) 2, 1, 3, 4
भारत में नियोजन का कालक्रम 1944 के 'बॉम्बे प्लान' से शुरु होता है, जिसमें उद्योगपतियों ने नियोजित अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव दिया। इसके बाद 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी किया गया, जिसमें कृषि पर ध्यान दिया गया। अंत में, 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरु हुई, जिसने औद्योगिक विकास को नई गति प्रदान की। यह क्रम भारत की शुरुआती विकास नीति के व्यवस्थित चरणों को दर्शाता है।

22. (B) प्रधानमंत्री
योजना आयोग के गठन के समय से ही यह व्यवस्था की गई थी कि भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि देश की आर्थिक योजनाएँ और विकास की नीतियाँ सरकार की सर्वोच्च राजनीतिक प्राथमिकताओं के साथ जुड़ी रहें। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के कारण योजना आयोग को विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करने और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कराने में बल मिलता था।

23. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
भारत में नियोजित विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल को अपनाया गया, जो सीधे तौर पर सोवियत संघ के नियोजन अनुभव से प्रेरित था। सोवियत संघ ने केंद्रीय नियोजन के माध्यम से बहुत कम समय में अपनी पिछड़ी अर्थव्यवस्था को औद्योगिक शक्ति में बदल दिया था। इसी सफलता को देखते हुए भारतीय योजनाकारों ने भी पाँच वर्ष की अवधि के लक्ष्यों और बजटीय आवंटन की व्यवस्था चुनी ताकि देश के संसाधनों का संतुलित और तीव्र विकास हो सके।

24. (A) योजना-व्यय और गैर-योजना-व्यय
पंचवर्षीय योजना प्रणाली के तहत सरकारी बजट को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया था। 'योजना-व्यय' वह धन था जिसे पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित विशिष्ट विकास लक्ष्यों और परियोजनाओं पर खर्च किया जाता था। 'गैर-योजना-व्यय' के अंतर्गत सरकार की रोजमर्रा की प्रशासनिक गतिविधियों, वेतन, पेंशन और सुरक्षा जैसे अनिवार्य खर्चों को रखा गया था। इस विभाजन का उद्देश्य विकास कार्यों के लिए समर्पित संसाधनों की स्पष्ट पहचान और उनका दीर्घकालिक प्रबंधन करना था।

25. (A) केवल 1, 3 और 4
भारत की शुरुआती विकास नीति नियोजन, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर टिकी थी। इसमें सहकारी खेती और भूमि सुधारों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने का प्रयास किया गया। उस समय उदारीकरण और निजीकरण जैसे विचार नीतियों का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि राज्य को अर्थव्यवस्था की 'कमांडिंग हाइट्स' पर कब्जा रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मुख्य लक्ष्य बाहरी निर्भरता कम करना और देश के भीतर ही उत्पादन क्षमता का विकास करना था।

26. (A) 1951
पहली पंचवर्षीय योजना का वास्तविक दस्तावेज़ या प्रारूप दिसंबर 1951 में जारी किया गया था। यह स्वतंत्र भारत द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित रुप देने का पहला ठोस प्रयास था। इस योजना ने 1951 से 1956 तक की अवधि के लिए विकास के लक्ष्य निर्धारित किए। इसने देश में नियोजन की प्रक्रिया को लेकर व्यापक उत्साह और चर्चा पैदा की, क्योंकि यह गरीबी दूर करने और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

27. (D) दूसरी पंचवर्षीय योजना
दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-61) के आगमन तक भारत में आर्थिक नियोजन को लेकर चर्चा और उत्साह अपने चरम पर पहुँच गया था। पहली योजना की सफलता के बाद, दूसरी योजना ने तीव्र औद्योगीकरण और भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करके देश के सामने एक बड़ी चुनौती पेश की। इस योजना ने विकास की गति और दिशा पर समाज के विभिन्न वर्गों, बुद्धिजीवियों और अर्थशास्त्रियों के बीच एक व्यापक और गहन राष्ट्रीय बहस को जन्म दिया।

28. (B) P-2, Q-1, R-4, S-3
पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि, सिंचाई और बांधों पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। दूसरी योजना में महालनोबिस मॉडल के तहत तीव्र औद्योगीकरण और भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। तीसरी योजना ने कृषि और उद्योगों के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश की। 1966-69 का 'योजना अवकाश' भीषण आर्थिक संकट, सूखे और युद्धों के कारण आया, जिसके दौरान पंचवर्षीय योजना के स्थान पर वार्षिक योजनाएँ अपनाई गईं।

29. (C) देश के अत्यंत गंभीर आर्थिक संकट की चपेट में आने के कारण
1960 के दशक के मध्य में भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ युद्धों, लगातार सूखे और खाद्य संकट के कारण गंभीर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी और बढ़ती मुद्रास्फीति ने नियोजन की प्रक्रिया को बाधित किया। संसाधनों की कमी के चलते सरकार ने नियमित पंचवर्षीय योजना को कुछ समय के लिए स्थगित कर 1966 से 1969 तक वार्षिक योजनाएँ लागू कीं, जिसे 'योजना अवकाश' कहा जाता है।

30. (D) देश को गरीबी के मकड़जाल से निकालना
प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-1956) का बुनियादी उद्देश्य स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था को गति देना और जनता को भीषण गरीबी से मुक्ति दिलाना था। योजनाकारों ने महसूस किया कि कृषि की उपेक्षा करके औद्योगिक विकास संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने कृषि क्षेत्र और सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी। लक्ष्य यह था कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जाए

उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

171. 'केरल मॉडल' विकास के प्रमुख राष्ट्रीय मॉडल को किस आधार पर चुनौती देता है?
(A) यह दृढ़ता से तर्क देता है कि केवल भारी औद्योगीकरण और शहरीकरण ही विकास का एकमात्र रास्ता है।
(B) यह निजी क्षेत्र को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सभी सामाजिक सेवाओं से पूरी तरह बाहर करने की वकालत करता है।
(C) यह प्रदर्शित करता है कि उच्च सामाजिक विकास निम्न प्रति व्यक्ति आय के साथ भी संभव है।
(D) यह कृषि क्षेत्र और ग्रामीण उत्पादकता को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का सुझाव देता है।

172. स्रोत के अनुसार केरल की उच्च सामाजिक विकास दर का मुख्य कारण क्या है?
(A) राज्य के भीतर मौजूद विशाल औद्योगिक आधार और बड़े पैमाने पर किया गया विदेशी प्रत्यक्ष निवेश।
(B) शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सार्वजनिक सेवाओं में राज्य द्वारा निरंतर निवेश।
(C) राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का वैश्विक बाजार में बड़े पैमाने पर किया गया निरंतर निर्यात।
(D) केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर राज्य को प्रदान किए गए विशेष वित्तीय अनुदान और आर्थिक पैकेज।

173. केरल मॉडल में विकेंद्रीकृत योजना की क्या भूमिका रही है?
(A) इसने राज्य के भीतर चलने वाली महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं और ढांचागत कार्यों में अनावश्यक बाधा उत्पन्न की है।
(B) इसने सभी निर्णय लेने की शक्ति और प्रशासनिक नियंत्रण को राज्य की राजधानी में पूर्ण रूप से केंद्रित कर दिया।
(C) इसका उपयोग केवल नियमित अंतराल पर स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न कराने के लिए किया गया।
(D) इसने स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की और सेवाओं के प्रभावी वितरण में मदद की।

174. निम्नलिखित में से कौन सी नीति केरल के प्रगतिशील सामाजिक-राजनीतिक वातावरण का परिणाम है?
(A) प्रभावी भूमि सुधार और एक मजबूत सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
(B) विदेशी वस्तुओं के आयात पर लगाए गए अत्यंत कठोर और व्यापक व्यापारिक प्रतिबंध।
(C) ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा करते हुए केवल महानगरों के शहरी विकास पर ध्यान केंद्रित करना।
(D) राज्य के भीतर सभी निजी शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों के संचालन पर पूर्ण वैधानिक प्रतिबंध।

175. 'केरल मॉडल' 'विकास' की अवधारणा को किस रूप में पुनः परिभाषित करता है?
(A) यह विकास को केवल आर्थिक सकल उत्पादन की वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों के रूप में मापता है।
(B) यह विकास को देश की सैन्य शक्ति और सामरिक क्षमताओं के निरंतर निर्माण के समान मानता है।
(C) यह आर्थिक विकास के बजाय मानव कल्याण और क्षमताओं के विस्तार पर जोर देता है।
(D) यह मानता है कि वास्तविक विकास केवल प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित दोहन और निर्यात से ही संभव है।

134. दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर सबसे ज्यादा ज़ोर था?
(A) कृषि और सिंचाई के पारंपरिक साधनों के आधुनिकीकरण पर ध्यान
(B) अर्थव्यवस्था के तेज़ संरचनात्मक बदलाव और भारी उद्योगों के विकास पर बल
(C) देश के ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी और बेरोज़गारी के पूर्ण उन्मूलन पर
(D) भू-स्वामित्व में सुधार हेतु भूमि सुधार कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर

135. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): भारत में विकास की शुरुआती नीति में 'आत्मनिर्भरता' एक प्रमुख विचार था।
कारण (R): दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया गया।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

136. 'ज़ोनिंग' या 'इलाका बंदी' की नीति का क्या प्रभाव पड़ा?
(A) राज्यों के बीच खाद्यान्न व्यापार पर प्रतिबंध, जिससे कुछ क्षेत्रों में कमी बढ़ी
(B) पूरे देश के बाज़ारों में खाद्यान्न का मुक्त और सुगम प्रवाह सुनिश्चित करना
(C) देश के सभी राज्यों में कृषि उत्पादन में अचानक और भारी वृद्धि करना
(D) ग्रामीण किसानों की वार्षिक आय को तत्काल प्रभाव से दोगुना कर देना

137. सहकारी डेयरी का मॉडल (जैसे अमूल) किससे संबंधित है?
(A) चरण सिंह
(B) पी.सी. महालनोबिस
(C) वर्गीज कुरियन
(D) जे.सी. कुमारप्पा

138. आज़ादी के समय विकास के सवालों पर प्रमुख मतभेदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. विकास का मुख्य ज़ोर औद्योगीकरण पर हो या कृषि पर?
2. क्या सरकार को अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए?
3. क्या विकास के लिए लोकतंत्र आवश्यक है?
4. ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करना सर्वाधिक ज़रूरी है या नहीं?
5. क्या निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए?

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 2 और 3
(B) केवल 1, 4 और 5
(C) केवल 1, 2, 3, 4
(D) ये सभी बहसों के हिस्से थे।

139. 1950 के दशक में नियोजन के पक्ष में दुनिया भर में हवा क्यों बह रही थी?
(A) पश्चिमी पूंजीवादी देशों द्वारा नियोजन को पूरी तरह से और स्वेच्छा से अपनाना
(B) नियोजन का एक प्राचीन और पारंपरिक भारतीय प्रशासनिक परंपरा का हिस्सा होना
(C) विश्व बैंक द्वारा सभी सदस्य राष्ट्रों हेतु इसे एक अनिवार्य शर्त बना देना
(D) महामंदी के कड़वे अनुभवों और सोवियत प्रगति द्वारा राज्य की भूमिका की पुष्टि

140. निम्नलिखित में से क्या पहली पंचवर्षीय योजना का हिस्सा नहीं था?
(A) धीमी चाल की रणनीति
(B) भारी उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता
(C) भूमि-सुधार पर जोर
(D) कृषि और सिंचाई पर ध्यान

141. केरल में चलाए गए साक्षरता अभियान किस पहल का हिस्सा थे?
(A) बॉम्बे प्लान
(B) दूसरी पंचवर्षीय योजना
(C) नव लोकतांत्रिक पहल
(D) राष्ट्रीय विकास परिषद

142. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए:
कथन I: पी.सी. महालनोबिस ने दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की।
कथन II: के.एन. राज ने पहली पंचवर्षीय योजना के निर्माण में भूमिका निभाई।
(A) कथन I और II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(C) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।
(D) कथन I और II दोनों असत्य हैं।

143. विकास की बहसों में "मौजूदा पीढ़ी के हितों और आने वाली पीढ़ी के हितों" को तोलने का क्या अर्थ है?
(A) भावी पीढ़ियों हेतु संसाधन संरक्षण और वर्तमान आवश्यकताओं के मध्य संतुलन
(B) आज के लाभ की प्राप्ति हेतु भविष्य के प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन
(C) वर्तमान को अनदेखा कर केवल भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं का सोचना
(D) भविष्य की चिंता किए बिना केवल वर्तमान पीढ़ी की सभी जरूरतों को पूरा करना

और नीति-निर्माता इस बात पर एकमत थे कि विकास का अर्थ केवल राष्ट्रीय आय बढ़ाना नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना भी है। इसी सहमति के कारण सरकार ने विकास की योजना बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाई, ताकि संसाधनों का वितरण न्यायपूर्ण हो और समाज के वंचित वर्गों का उत्थान हो सके।

11. (D) खुली प्रतिस्पर्धा और बाज़ार आधारित अर्थव्यवस्था
दक्षिणपंथी विचारधारा के समर्थक मानते हैं कि प्रगति का सर्वोत्तम मार्ग मुक्त बाजार, निजी उद्यम और खुली प्रतिस्पर्धा है। उनका तर्क है कि जब सरकार आर्थिक गतिविधियों में कम हस्तक्षेप करती है, तो नवाचार और दक्षता को बढ़ावा मिलता है, जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विकास होता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, व्यापार और निवेश के क्षेत्र में राज्य की भूमिका नियामक के बजाय केवल सुविध प्रदाता तक ही सीमित रहनी चाहिए ताकि बाजार की शक्तियाँ प्रभावी हो सकें।

12. (A) केवल 1 और 2
योजना आयोग की स्थापना के प्रस्ताव में संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों को आधार बनाया गया था। इसके प्रमुख उद्देश्यों में स्त्री-पुरुष दोनों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना और समुदाय के संसाधनों का लोक-कल्याण हेतु प्रबंधन करना शामिल था। साथ ही, यह सुनिश्चित करना भी लक्ष्य था कि धन का संकेंद्रण कुछ ही हाथों में न हो। अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप न करना या केवल निजीकरण को बढ़ावा देना इसके मूल सिद्धांतों के विपरीत था।

13. (C) क्योंकि जन-प्रतिनिधि जनता की भावनाओं को समझते हैं।
विकास से जुड़े अंतिम निर्णय राजनीतिक होने चाहिए क्योंकि विशेषज्ञों की राय तकनीकी हो सकती है, लेकिन वे जनता की सामाजिक और भावनात्मक आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते। एक लोकतंत्र में केवल निर्वाचित जनप्रतिनिधि ही विभिन्न वर्गों के हितों के बीच संतुलन साध सकते हैं और जन-कल्याण को ध्यान में रखकर नीतिगत फैसले ले सकते हैं। विशेषज्ञों की सलाह महत्वपूर्ण है, परंतु वास्तविक निर्णय प्रक्रिया जनता के प्रति जवाबदेही पर आधारित होनी चाहिए।

14. (D) मार्च 1950
भारत सरकार ने एक कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की थी। यह एक गैर-संवैधानिक और सलाहकार निकाय था, जिसका मुख्य कार्य देश के संसाधनों का आकलन करना और उनके प्रभावी उपयोग के लिए पंचवर्षीय योजनाएँ तैयार करना था। प्रधानमंत्री को इस संस्था का पदेन अध्यक्ष बनाया गया था, ताकि नियोजन की प्रक्रिया को देश की सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता का समर्थन और निर्देशन प्राप्त रहे।

15. (B) P-3, Q-4, R-1, S-2
बॉम्बे प्लान 1944 में उद्योगपतियों द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था हेतु दिया गया प्रस्ताव था। पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल सोवियत संघ की व्यवस्था से प्रेरित होकर अपनाया गया। केरल मॉडल अपनी विकेंद्रित नियोजन प्रणाली और सामाजिक विकास पर जोर देने के लिए प्रसिद्ध है। पोस्को इस्पात संयंत्र उड़ीसा में स्थित एक प्रमुख औद्योगिक परियोजना है जो स्थानीय विरोध के कारण चर्चा में रही। ये सभी तत्व भारत की विविध विकास यात्रा के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं।

16. (B) भारत सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से
योजना आयोग की स्थापना न तो संविधान के किसी अनुच्छेद द्वारा की गई थी और न ही संसद के किसी अधिनियम द्वारा। इसकी स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार के एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव या कार्यकारी आदेश के माध्यम से हुई थी। यह एक अतिरिक्त-संवैधानिक संस्था थी जो मुख्य रूप से सरकार को आर्थिक नियोजन और विकास की रणनीतियों पर सलाह देने के लिए बनाई गई थी, जिसका नेतृत्व स्वयं प्रधानमंत्री करते थे।

17. (B) नीति आयोग
1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर 'नीति आयोग' (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) की स्थापना की गई। यह नई संस्था सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और "नीचे से ऊपर" (bottom-up) की नियोजन पद्धति अपनाने के उद्देश्य से बनाई गई है। नीति आयोग का मुख्य कार्य सरकार के थिंक-टैंक के रूप में रणनीतिक और तकनीकी सलाह देना है, ताकि विकास की प्रक्रिया में राज्यों की भागीदारी अधिक प्रभावी हो सके।

18. (C) 1, 2 और 3
1944 में भारतीय उद्योगपतियों के एक समूह ने 'बॉम्बे प्लान' प्रस्तुत किया था, जो देश में नियोजित अर्थव्यवस्था का समर्थन करता था। यद्यपि ये निजी उद्यमी थे, फिर भी उन्होंने औद्योगिक और बुनियादी ढाँचे के विकास में सरकार की बड़ी भूमिका और निवेश की वकालत की। यह योजना मुक्त बाज़ार के सिद्धांतों के बजाय राज्य द्वारा निर्देशित विकास पर आधारित थी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उस दौर में नियोजन के प्रति सर्वसम्मति बहुत व्यापक थी।

19. (C) यह एक सलाहकार की भूमिका निभाता था।
योजना आयोग की प्रकृति मूल रूप से एक सलाहकार निकाय की थी। इसका कार्य देश के विकास के लिए योजनाएँ तैयार करना और संसाधनों के आवंटन हेतु सुझाव देना था। हालांकि यह बहुत शक्तिशाली संस्था थी, लेकिन इसके प्रस्तावों को लागू करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति अनिवार्य थी। यह न तो संवैधानिक रूप से स्वायत्त था और न ही इसके पास कोई न्यायिक शक्ति थी, बल्कि यह सरकार के एक सहयोगी अंग के रूप में कार्य करता था।

20. (D) शीत युद्ध में अमरीका की विजय
1940 और 1950 के दशक में नियोजन के विचार को व्यापक जनसमर्थन मिला, क्योंकि दुनिया ने 1930 की महामंदी के नकारात्मक परिणामों को देखा था। सोवियत संघ की नियोजित प्रगति और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप और जापान के पुनर्निर्माण ने आर्थिक विकास में राज्य की सक्रिय भूमिका को सिद्ध कर दिया था। उस समय शीत युद्ध में अमेरिका की विजय जैसा कोई कारक अस्तित्व में नहीं था, बल्कि राज्य द्वारा

ANSWERS

1. (B) आर्थिक विकास और जन-कल्याण सुनिश्चित करना
स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक ऐसी विकास नीति तैयार करने की थी जो न केवल आर्थिक संवृद्धि को बढ़ाए, बल्कि समाज के सभी वर्गों का कल्याण भी सुनिश्चित करे। देश की व्यापक गरीबी और असमानता को देखते हुए, लोकतांत्रिक नेतृत्व ने यह महसूस किया कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है, बल्कि वास्तविक प्रगति के लिए सबको समान अवसर मिलना अनिवार्य है।

2. (A) लौह-अयस्क
उड़ीसा में लौह-अयस्क के विशाल भंडार मौजूद थे, जिन्हें आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना गया। राज्य सरकार ने इन संसाधनों के दोहन हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इस्पात उत्पादकों के साथ सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए। हालांकि, इस औद्योगिक पहल का स्थानीय जनजातीय समुदायों और पर्यावरणविदों ने कड़ा विरोध किया, क्योंकि उन्हें विस्थापन और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का गहरा भय था, जिससे विकास का मुद्दा विवादित बन गया।

3. (C) विभिन्न वर्गों के लिए विकास के भिन्न अर्थ होना
विकास एक बहुआयामी और व्यक्तिपरक अवधारणा है, जिसका अर्थ अलग-अलग सामाजिक और आर्थिक समूहों के लिए भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक उद्योगपति के लिए एक नया इस्पात संयंत्र प्रगति और लाभ का प्रतीक हो सकता है, जबकि उसी क्षेत्र के आदिवासियों के लिए वह विस्थापन और उनकी पारंपरिक आजीविका के छिन जाने का संकेत हो सकता है। अतः विकास की कोई एक सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है।

4. (A) P-3, Q-1, R-4, S-2
विकास परियोजनाओं के संदर्भ में विभिन्न समूहों के सरोकार भिन्न होते हैं। आदिवासी समुदाय प्रायः भूमि से विस्थापन और आजीविका खोने के डर से औद्योगिक परियोजनाओं का विरोध करते हैं। पर्यावरणविदों की चिंता खनन और भारी उद्योगों से होने वाले प्रदूषण और पारिस्थितिक असंतुलन पर केंद्रित रहती है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय पूँजी-निवेश और आर्थिक विकास को प्राथमिकता देती है, जबकि राज्य सरकारें क्षेत्रीय स्तर पर निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना चाहती हैं।

5. (C) पश्चिमी मुल्क
स्वतंत्रता के समय, विकास की धारणा को पश्चिमी देशों के आधुनिकीकरण के पैमाने पर मापा जाता था। 'आधुनिक' होने का अर्थ पश्चिमी औद्योगिक देशों के समान शहरीकरण, औद्योगीकरण और उदारवादी-पूंजीवादी मूल्यों को अपनाना माना जाता था। इस दृष्टिकोण के अनुसार, प्रत्येक राष्ट्र को विकास के लिए उसी मार्ग का अनुसरण करना था, जिससे होकर यूरोप और अमेरिका गुजरे थे, जो पारंपरिक संरचनाओं को वैज्ञानिक तर्कबुद्धि से बदलने पर आधारित था।

6. (B) राज्य नियंत्रण और विनियामक अर्थव्यवस्था के पक्षधर
वामपंथी विचारधारा सामान्यतः समाज के निर्धन और पिछड़े वर्गों के हितों का समर्थन करती है। इसके पैरोकार आर्थिक असमानता को कम करने के लिए अर्थव्यवस्था में राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप और नियंत्रण पर बल देते हैं। वे मानते हैं कि निजी पूंजीपतियों के बजाय सरकार को महत्वपूर्ण संसाधनों और उद्योगों का संचालन करना चाहिए, ताकि जन-कल्याण और संसाधनों का न्यायोचित वितरण सुनिश्चित किया जा सके और निर्धन वर्गों को सुरक्षा मिल सके।

7. (C) 1, 2 और 4
स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष विकास के दो प्रमुख मॉडल थे: उदारवादी-पूंजीवादी मॉडल और सोवियत संघ द्वारा अपनाया गया समाजवादी मॉडल। उस समय भारतीय राजनेताओं और बुद्धिजीवियों के बीच सोवियत मॉडल के प्रति गहरा आकर्षण था क्योंकि उसने अल्प समय में शानदार आर्थिक प्रगति की थी। नेहरु सहित कई नेता राज्य के नेतृत्व में नियोजित विकास के पक्षधर थे, जबकि अमेरिका आधारित शुद्ध पूंजीवादी मॉडल के समर्थक बहुत कम थे।

8. (A) कथन I और II दोनों सत्य हैं।
आज़ादी के समय देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस बात पर व्यापक सहमति थी कि विकास का जिम्मा केवल निजी क्षेत्र या किसानों पर नहीं छोड़ा जा सकता। गरीबी उन्मूलन और सामाजिक-आर्थिक पुनर्निर्माण जैसे विशाल कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार की सक्रिय भूमिका अनिवार्य मानी गई। इसलिए, राज्य ने निवेश की दिशा तय करने और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध विकास की कमान अपने हाथों में ली।

9. (C) संवृद्धि, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्कबुद्धि
शुरुआती दशकों में 'आधुनिकीकरण' को विकास का मुख्य आधार माना गया, जो आर्थिक संवृद्धि, निरंतर भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक सोच के प्रसार का पर्याय था। इस धारणा के अनुसार, समाज का विकास तभी संभव था जब वह अपनी पारंपरिक जड़ता को त्याग कर नई तकनीक और तर्कसंगत ढांचे को अपनाए। पश्चिमी देशों को इस प्रक्रिया का आदर्श माना जाता था, जहाँ औद्योगिक क्रांति ने जीवन स्तर और उत्पादन क्षमता में क्रांतिकारी परिवर्तन किए थे।

10. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
भारत में विकास के आर्थिक निर्णयों के पीछे एक स्पष्ट सामाजिक-आर्थिक 'विज़न' मौजूद था। सभी राजनीतिक दल

और संसाधनों के उचित प्रबंधन के माध्यम से जनता के जीवन स्तर में क्रमिक सुधार लाया जा सके।

31. (A) केवल 3
प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से कृषि और सिंचाई पर केंद्रित थी, लेकिन इसमें उद्योगों की पूरी तरह उपेक्षा नहीं की गई थी। हालांकि औद्योगिक निवेश कम था, फिर भी कुछ बुनियादी बुनियादी ढाँचे पर ध्यान दिया गया था। योजना का मुख्य जोर भाखड़ा-नांगल जैसे बड़े बाँधों, भूमि सुधारों और ग्रामीण विकास पर था ताकि विभाजन के कारण संकट में आई कृषि व्यवस्था को सुधारा जा सके। यह कहना गलत है कि उद्योगों को बिल्कुल नज़रअंदाज़ किया गया।

32. (B) के. एन. राज
पहली पंचवर्षीय योजना के निर्माण में युवा अर्थशास्त्री के. एन. राज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका तर्क था कि भारत को शुरुआती दो दशकों में विकास की गति 'धीमी' रखनी चाहिए। उन्हें डर था कि यदि बहुत तेज़ गति से विकास का प्रयास किया गया तो अर्थव्यवस्था अस्थिर हो सकती है और मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। उनकी इस दलील ने पहली योजना के सतर्क और कृषि-केंद्रित स्वरूप को निर्धारित करने में बड़ा योगदान दिया था।

33. (B) भूमि के वितरण का दोषपूर्ण और असमान ढाँचा
पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेषज्ञों ने माना कि देश के विकास और कृषि उत्पादन में सबसे बड़ी रुकावट भूमि वितरण की अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। उस समय ज़मींदारी प्रथा और भूमि का असमान स्वामित्व किसानों की उत्पादकता और आय के मार्ग में बड़ी बाधा थी। इसलिए, योजनाकारों ने भूमि सुधार कानूनों को सख्ती से लागू करने और जोत की सीमा तय करने पर विशेष जोर दिया ताकि खेती को लाभकारी और समावेशी बनाया जा सके।

34. (A) कथन I और II दोनों सत्य हैं।
दूसरी पंचवर्षीय योजना ने पहली योजना की तुलना में विकास की रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया। जहाँ पहली योजना ने कृषि और धैर्य पर जोर दिया था, वहीं दूसरी योजना ने पी.सी. महालनोबिस के नेतृत्व में तीव्र औद्योगिक विकास को अपना लक्ष्य बनाया। सरकार ने भारी उद्योगों के माध्यम से अर्थव्यवस्था का ढाँचा बदलने की कोशिश की, ताकि आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके। यह बदलाव भारत की आधुनिक औद्योगिक नींव रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

35. (C) पी. सी. महालनोबिस
दूसरी पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद् पी. सी. महालनोबिस ने किया था। उन्होंने एक ऐसा आर्थिक मॉडल तैयार किया जिसमें भारी और बुनियादी उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। महालनोबिस का मानना था कि इस्पात और मशीनरी जैसे उद्योगों के विकास के बिना भारत कभी भी दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता और तीव्र आर्थिक संवृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उनके इस दृष्टिकोण ने भारत की विकास यात्रा को एक नई औद्योगिक दिशा प्रदान की।

36. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने 'संरक्षणवाद' की नीति अपनाई, जिसके तहत आयात पर भारी शुल्क लगाया गया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य नवजात घरेलू उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से बचाना था ताकि वे मज़बूत हो सकें। सरकार चाहती थी कि देश के भीतर ही विनिर्माण क्षमता बढ़े और विदेशी मुद्रा की बचत हो। इस सुरक्षात्मक वातावरण ने सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के उद्योगों को विकसित होने और आधुनिक तकनीक अपनाने का अवसर प्रदान किया।

37. (C) बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार क्षेत्र
दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र-बिंदु बुनियादी ढाँचे का निर्माण और भारी औद्योगीकरण था। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से इस्पात संयंत्रों, रेलवे के आधुनिकीकरण, बिजली उत्पादन इकाइयों और संचार नेटवर्क के विस्तार में बड़े निवेश किए। इन 'कमांडिंग हाइट्स' को राज्य के नियंत्रण में रखा गया ताकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को आवश्यक ऊर्जा और सामग्री मिल सके। इससे भारत में औद्योगिक विकास के एक नए युग की शुरुआत हुई जिसने भविष्य की संवृद्धि का आधार बनाया।

38. (B) विदेशी तकनीक हेतु बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का भारी व्यय
दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर अधिक जोर देने के कारण भारत को बड़े पैमाने पर विदेशी तकनीक और मशीनरी का आयात करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप देश के बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से कमी आई। यह एक बड़ी चुनौती बन गई क्योंकि भारत के पास निर्यात से होने वाली आय सीमित थी और आयात की जरूरतें बहुत अधिक थीं। इस वित्तीय असंतुलन ने नियोजन प्रक्रिया में विदेशी मुद्रा संकट और बाहरी निर्भरता के मुद्दों को जन्म दिया।

39. (C) केवल 1, 2, 3, 5
दूसरी पंचवर्षीय योजना ने तीव्र औद्योगीकरण, महालनोबिस मॉडल और आयात संरक्षण पर जोर दिया। हालांकि, इसने कृषि के ऊपर उद्योगों को प्राथमिकता दी, जो पहली योजना के विपरीत था। आलोचकों का मानना था कि इस नीति ने ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा की और शहरी औद्योगिक वर्गों को अधिक लाभ पहुँचाया, जिससे खाद्यान्न संकट की स्थिति पैदा हुई। अतः कृषि को प्राथमिकता देने वाला कथन गलत है, जबकि बाकी सभी बिंदु दूसरी योजना की प्रमुख विशेषताओं और आलोचनाओं को सही दर्शाते हैं।

40. (A) उद्योगों में बढ़ते निवेश से उत्पन्न खाद्यान्न-संकट की आशंका
भारत के योजनाकारों के सामने सबसे बड़ी दुविधा यह थी कि सीमित संसाधनों का आवंटन कृषि और उद्योग के बीच कैसे किया जाए। यदि भारी उद्योगों में अधिक निवेश किया जाता, तो कृषि क्षेत्र के लिए संसाधन कम पड़ जाते, जिससे खाद्यान्न उत्पादन घटने और अकाल का खतरा बढ़ सकता था। यह संतुलन साधना इसलिए कठिन था क्योंकि बढ़ती जनसंख्या

तस्वीर देखने और लंबी अवधि के हस्तक्षेप करने की क्षमता मिली। यह केवल निजी क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के संतुलित विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करती थी, ताकि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का समन्वय हो सके।

96. (B) विकास की परिभाषा और उसके लाभार्थियों को तय करने वाली राजनीतिक प्रक्रिया
यह सवाल कि "किसकी ज़रूरतों को उड़ीसा की ज़रूरत कहा जाए", विकास के गहन राजनीतिक स्वरूप को उजागर करता है। यह दर्शाता है कि 'विकास' की कोई तटस्थ परिभाषा नहीं है। जहाँ उद्योगपतियों के लिए विकास खनिजों का दोहन है, वहीं आदिवासियों के लिए यह उनकी जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा है। अंततः, यह फैसला कि किसकी जरूरत को प्राथमिकता मिले, एक राजनीतिक प्रक्रिया है, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों की आवाज़ों और सत्ता के संतुलन की भूमिका होती है।

97. (B) आधुनिकता का अर्थ पश्चिमी औद्योगिक देशों के समान होने की व्यापक धारणा
स्वतंत्रता के बाद शुरुआती दौर में विकास का विचार अनिवार्य रूप से 'आधुनिक' बनने से जुड़ा था, और आधुनिक होने का पर्याय पश्चिमी देशों जैसा बनना था। यह माना जाता था कि विकास का एकमात्र विश्वसनीय मार्ग वही है जिसे यूरोप और अमेरिका ने औद्योगिक क्रांति के माध्यम से अपनाया था। इस धारणा के कारण, जब भी विकास की चर्चा होती थी, तो अनजाने में ही पश्चिमी देशों के शहरीकरण, औद्योगीकरण और वैज्ञानिक प्रगति को भारत के लिए एक अनिवार्य आदर्श के रूप में पेश किया जाता था।

98. (B) P-3, Q-1, R-4, S-2
भारत की विकास यात्रा के विभिन्न पक्षों का सही सुमेलन इस प्रकार है: मुख्य बहसें कृषि बनाम उद्योग और सार्वजनिक बनाम निजी क्षेत्र के इर्द-गिर्द केंद्रित थीं। अपनाई गई रणनीति मुख्य रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था और पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित थी। इस रणनीति की बड़ी उपलब्धियों में बुनियादी ढाँचे का विकास और निवेश में वृद्धि शामिल थी। अंततः, आर्थिक संकट और लक्ष्यों की अपूर्णता के कारण नियोजन से मोहभंग होने लगा, जिसके चलते रणनीति में बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई।

99. (A) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने भारी औद्योगीकरण का लक्ष्य रखा था, जिसके लिए आधुनिक मशीनों और उच्च तकनीक की आवश्यकता थी। चूंकि उस समय भारत तकनीकी रूप से उन्नत या आत्मनिर्भर नहीं था, इसलिए उसे इन चीजों के आयात पर अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ा। यह कथन कि भारत तब आत्मनिर्भर था, पूरी तरह गलत है। तकनीकी पिछड़ेपन के कारण ही भारत को औद्योगिक आधार खड़ा करने के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ा था।

100. (D) बदलती आर्थिक और वैश्विक परिस्थितियों में एक नवीन संस्था की आवश्यकता
योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित करने का मुख्य कारण यह था कि 1950 के दशक में बनाई गई नियोजन प्रणाली वर्तमान की बदलती आर्थिक चुनौतियों और वैश्विक परिदृश्य के अनुकूल नहीं रह गई थी। सरकार को एक ऐसी संस्था की आवश्यकता थी जो राज्यों के साथ अधिक सहयोग (सहकारी संघवाद) कर सके और "कमांड एंड कंट्रोल" के बजाय एक सलाहकार थिंक-टैंक के रूप में कार्य करे। नीति आयोग को इसी नए विज़न के साथ बनाया गया ताकि विकास प्रक्रिया अधिक गतिशील और समावेशी हो सके।

101. (C) 1, 2 और 3
विकास की राजनीति हमेशा कठिन चुनावों से भरी होती है, जहाँ एक समूह का लाभ अक्सर दूसरे की कीमत पर होता है। इसमें केवल वर्तमान जरूरतों को ही नहीं देखा जाता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचाने की चिंता भी शामिल होती है। यद्यपि विशेषज्ञ महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय राजनीतिक ही होता है क्योंकि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को ही समाज के विविध हितों के बीच संतुलन साधने का अधिकार होता है। यह कहना गलत है कि ये फैसले हमेशा टकराव-रहित या सर्वसम्मत होते हैं।

102. (B) कृषि और सामुदायिक विकास
दूसरी पंचवर्षीय योजना ने पहली योजना की तुलना में अपनी प्राथमिकताओं में बड़ा बदलाव किया। पहली योजना में 'कृषि और सामुदायिक विकास' पर कुल बजट का लगभग 15 प्रतिशत हिस्सा खर्च किया गया था, जिसे दूसरी योजना में घटाकर लगभग 11 प्रतिशत कर दिया गया। इसके विपरीत, उद्योगों और खनन के आवंटन में भारी वृद्धि की गई। यह कमी स्पष्ट करती है कि योजनाकारों ने तीव्र औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी, भले ही इसके लिए कृषि क्षेत्र के हिस्से में कटौती करनी पड़ी।

103. (D) राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था
'नीति आयोग' (NITI Aayog) का पूर्ण हिंदी नाम 'राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था' है। अंग्रेज़ी में इसे 'National Institution for Transforming India' कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। यह भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत 'थिंक-टैंक' है, जो आर्थिक नीति निर्माण में राज्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है और विकास की रणनीति के लिए रणनीतिक तथा तकनीकी सलाह प्रदान करता है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं।

104. (A) 1, 3, 4, 2
योजनाओं का सही कालक्रम पहली योजना के अंत (1956) से शुरू होता है। इसके तुरंत बाद 1956 में ही दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना का आरंभ 1961 में हुआ। अंत में, तीसरी योजना के पश्चात उपजे आर्थिक संकट और सूखे के कारण 1966 में 'योजना अवकाश' की शुरुआत हुई। यह क्रम दिखाता है कि कैसे भारत ने अपनी विकास यात्रा को

50. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
दूसरी पंचवर्षीय योजना की एक प्रमुख आलोचना यह थी कि इसने कृषि क्षेत्र की तुलना में भारी उद्योगों को अधिक प्राथमिकता दी। आलोचकों का तर्क था कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पिछड़ सकती है और देश में खाद्यान्न संकट गहरा सकता है। उस समय उद्योगों में बड़े पैमाने पर निवेश के कारण कृषि के लिए संसाधन कम पड़ गए थे, जिससे दोनों क्षेत्रों के बीच संतुलन बिगड़ने का डर था। यह कारण अभिकथन की बिल्कुल सही व्याख्या करता है क्योंकि नियोजन में यह असंतुलन एक बड़ा विवाद बन गया था।

51. (C) राष्ट्रीय युवा संगठन और नवनिर्माण समिति
उड़ीसा के जगतसिंहपुर जिले में पोस्को-इंडिया इस्पात संयंत्र के खिलाफ हुए आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय विस्थापित लोगों और कई नागरिक संगठनों ने किया। इनमें राष्ट्रीय युवा संगठन और नवनिर्माण समिति जैसे संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन समूहों ने तर्क दिया कि औद्योगिक विकास के नाम पर आदिवासियों और किसानों की जीविका तथा पारंपरिक खेती को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। उनके विरोध का मुख्य आधार विस्थापन का भय और पर्यावरण की सुरक्षा की मांग थी।

52. (D) मिश्रित अर्थव्यवस्था
स्वतंत्रता के बाद भारत ने 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' का अनूठा रास्ता अपनाया, जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के तत्वों का समावेश था। इस मॉडल के तहत कृषि और व्यापार जैसे क्षेत्र निजी हाथों में रहे, जबकि भारी उद्योग, रक्षा और संचार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का नियंत्रण राज्य के पास रहा। सरकार का उद्देश्य बाजार की शक्तियों का उपयोग करना और साथ ही सामाजिक न्याय एवं कल्याण सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करना था, ताकि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।

53. (B) केवल 1, 2, 3, 5
विकास की पश्चिमी धारणा मुख्य रूप से आधुनिकीकरण और औद्योगिक प्रगति से जुड़ी थी। इसमें पुरानी सामाजिक संरचनाओं को तोड़ने और पूँजीवाद, उदारवाद तथा वैज्ञानिक तर्कबुद्धि को अपनाने पर जोर दिया गया था। यह संवृद्धि और भौतिक सुख-सुविधाओं के विस्तार को ही विकास का पैमाना मानती थी। हालाँकि, पारंपरिक मूल्यों और कृषि पर जोर देना इस मॉडल की विशेषता नहीं थी, बल्कि इसे अक्सर विकास के मार्ग में बाधा के रूप में देखा जाता था। अतः कथन 4 इसमें शामिल नहीं है।

54. (A) कथन I और II दोनों सत्य हैं।
योजना आयोग की तरह ही नीति आयोग का उल्लेख भी भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में एक सरकारी प्रस्ताव द्वारा की गई थी, और इसे 2015 में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। दोनों ही संस्थाएँ 'अतिरिक्त-संवैधानिक' (Extra-constitutional) और 'गैर-सांवधिक' (Non-statutory) निकाय हैं, जिसका अर्थ है कि वे कार्यकारी आदेशों के माध्यम से बनाई गई सलाहकार संस्थाएँ हैं, जिन्हें विधायी या संवैधानिक अनिवार्य शक्ति प्राप्त नहीं है।

55. (D) वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों आर्थिक प्रवृत्तियों का समावेश
1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी एक विस्तृत राजनीतिक छतरी की तरह थी, जिसमें विभिन्न विचारधाराओं के लोग शामिल थे। पार्टी ने अपनी नीतियों में समाजवादी और वामपंथी झुकाव के साथ-साथ निजी क्षेत्र और बाजार के प्रति उदार रवैया भी बनाए रखा। इस 'मिश्रित' दृष्टिकोण के कारण पार्टी समाज के विभिन्न वर्गों के हितों के बीच संतुलन साधने में सफल रही। इस प्रकार कांग्रेस की आर्थिक नीतियाँ किसी एक चरम पर न होकर दोनों प्रमुख विचारधाराओं का समन्वित रूप थीं।

56. (B) P-3, Q-4, R-1, S-2
1940 का दशक बॉम्बे प्लान और नियोजन की शुरुआती चर्चाओं का गवाह रहा। 1950 के दशक में स्वतंत्र भारत की पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया, जिसने विकास की नींव रखी। 1960 के दशक में तीसरी योजना के दौरान भीषण सूखे और युद्धों के कारण आर्थिक संकट पैदा हुआ, जिससे नियोजन प्रक्रिया धीमी हुई। अंततः 2010 के दशक में, 2015 में योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग लाया गया, जो नियोजन के एक नए युग की शुरुआत थी।

57. (C) विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच परस्पर हितों का प्रबल टकराव
उड़ीसा में इस्पात संयंत्र लगाने के प्रस्ताव से स्पष्ट हुआ कि विकास की प्रक्रिया अक्सर विभिन्न समूहों के बीच हितों का टकराव पैदा करती है। जहाँ उद्योगपति और सरकार इसे आर्थिक संवृद्धि और राजस्व का स्रोत मानते हैं, वहीं स्थानीय आदिवासी इसे अपनी भूमि और संस्कृति के लिए खतरा मानते हैं। पर्यावरणविद प्रदूषण की चिंता करते हैं। यह उदाहरण दर्शाता है कि विकास के फैसले केवल तकनीकी नहीं होते, बल्कि उनमें गहरे सामाजिक और राजनीतिक आयाम शामिल होते हैं जिनमें सामंजस्य बिठाना कठिन होता है।

58. (A) सोवियत संघ
समाजवादी विकास मॉडल का सबसे प्रमुख और प्रभावशाली उदाहरण सोवियत संघ (USSR) था। इस मॉडल में उत्पादन के साधनों पर राज्य का पूर्ण स्वामित्व होता है और अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत नियोजन के माध्यम से संचालित किया जाता है। भारत के कई नेता और योजनाकार सोवियत संघ की तीव्र औद्योगिक प्रगति से अत्यधिक प्रभावित थे, जिसके कारण भारत ने भी अपनी विकास रणनीति में राज्य के स्वामित्व और पंचवर्षीय योजनाओं जैसे तत्वों को शामिल किया।

59. (D) उपरोक्त सभी
भारत में नियोजित विकास के विचार को अपनाने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारक थे। 1944 के 'बॉम्बे प्लान' ने निजी क्षेत्र की ओर से भी नियोजन का समर्थन किया। सोवियत संघ की आर्थिक सफलता ने राज्य की सक्रिय भूमिका के प्रति विश्वास जगाया। साथ ही, समाज के प्रति गाँधीवादी दृष्टिकोण और

या समूह को प्राथमिकता देती थी, तो दूसरे समूह में असंतोष पैदा होना स्वाभाविक था। परिणामस्वरूप, विकास की प्रक्रिया ने निरंतर सामाजिक और राजनीतिक बहसों को जन्म दिया, जिससे स्पष्ट हुआ कि आर्थिक प्रगति के मार्ग का चुनाव अक्सर गहरा वैचारिक और सामाजिक तनाव उत्पन्न करता है।

78. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
भारत में विकास से जुड़े निर्णय विशेषज्ञों की तकनीकी राय पर आधारित होते हैं, लेकिन अंतिम रूप से वे राजनीतिक ही होने चाहिए। इसका कारण यह है कि विशेषज्ञ केवल वैज्ञानिक पहलुओं को देख सकते हैं, जबकि निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनता की आकांक्षाओं, भावनाओं और सामाजिक परिणामों को समझते हैं। लोकतंत्र में विकास का लक्ष्य जन-कल्याण होता है, इसलिए विभिन्न हितों के बीच संतुलन साधने की जिम्मेदारी राजनीति की होती है। कारण (R) इस बात की सटीक व्याख्या करता है कि क्यों विशेषज्ञों की राय के बावजूद अंतिम निर्णय जन-प्रतिनिधियों का होना चाहिए।

79. (A) विस्थापन का शिकार हुए लोगों ने
उड़ीसा के जगतसिंहपुर जिले में प्रस्तावित पोस्को इस्पात संयंत्र का सबसे कड़ा विरोध उन स्थानीय लोगों ने किया जिन्हें इस परियोजना के कारण विस्थापित होना था। इसमें मुख्य रूप से वे किसान और आदिवासी शामिल थे जिनकी उपजाऊ भूमि और आजीविका के पारंपरिक स्रोत (जैसे पान की खेती) खतरे में थे। इन विस्थापितों का मानना था कि औद्योगिक विकास के लाभ उनकी जीविका और पहचान की कीमत पर नहीं मिलने चाहिए, जिसके कारण इस संयंत्र के खिलाफ एक लंबा जन-आंदोलन चला।

80. (B) वे तीव्र औद्योगीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र की सक्रिय भूमिका के समर्थक थे
जे.सी. कुमारप्पा के बारे में यह कथन गलत है कि वे तीव्र औद्योगीकरण के समर्थक थे। वास्तव में, वे एक निष्ठावान गाँधीवादी अर्थशास्त्री थे जिन्होंने भारी उद्योगों के बजाय ग्रामीण विकास, कुटीर उद्योगों और विकेंद्रित अर्थव्यवस्था पर जोर दिया। उन्होंने 'इकॉनोमी ऑफ परमानेंस' के माध्यम से कृषि आधारित आत्मनिर्भर ग्रामीण समाज का सपना देखा था। वे योजना आयोग की प्रक्रिया में शामिल तो थे, लेकिन उन्होंने हमेशा केंद्रीकृत नियोजन के स्थान पर गाँधीवादी आर्थिक नीतियों को लागू करने का प्रस्ताव रखा था।

81. (C) केवल 1, 2, 3, 4
प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य विभाजन के बाद लड़खड़ाती कृषि व्यवस्था को सुधारना और देश को गरीबी से बाहर निकालना था। इसके लिए भाखड़ा-नांगल जैसे बड़े बाँधों के माध्यम से सिंचाई विस्तार और भूमि सुधारों पर विशेष ध्यान दिया गया। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय आय को बढ़ाना और भविष्य की संवृद्धि के लिए पूँजी संचय करना भी था। सूचना प्रौद्योगिकी (IT) उस समय विकास की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं थी, क्योंकि उस दौर की तकनीक और आवश्यकताएं बुनियादी ढाँचे तक ही सीमित थीं।

82. (A) जब मंत्रिमंडल उन्हें मंज़ूर करे।
योजना आयोग एक सलाहकार संस्था थी, जिसके पास स्वयं नीतियाँ लागू करने की कार्यकारी शक्ति नहीं थी। आयोग द्वारा तैयार की गई सिफारिशें और पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे तभी प्रभावी हो पाते थे जब भारत सरकार का केंद्रीय मंत्रिमंडल उन्हें औपचारिक रूप से अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता था। मंत्रिमंडलीय मंजूरी के बिना ये सिफारिशें केवल सुझाव मात्र बनी रहती थीं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती थी कि देश की आर्थिक योजनाएँ सरकार की व्यापक राजनीतिक प्राथमिकताओं और बजट के साथ पूरी तरह समन्वित रहें।

83. (C) पुरानी सामाजिक संरचना टूटी और पूँजीवाद तथा उदारवाद का उदय हुआ।
आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने पश्चिमी देशों में व्यापक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन किए। इसके परिणामस्वरूप सामंती व्यवस्था और पुरानी सामाजिक संरचनाएँ ध्वस्त हो गईं, जिससे पूँजीवाद और उदारवादी लोकतंत्र के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह प्रक्रिया शहरीकरण, औद्योगिक विकास और वैज्ञानिक सोच के विस्तार पर आधारित थी। विकास की इस पश्चिमी धारणा ने ही आधुनिकीकरण को विकास का एकमात्र पैमाना बना दिया, जिसे बाद में भारत जैसे कई विकासशील देशों ने भी अपनी आरंभिक नीतियों में एक आदर्श के रूप में देखा।

84. (B) P-2, Q-1, R-4, S-3
वामपंथ सामान्यतः राज्य द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था और गरीबों के हितों का समर्थन करता है। दक्षिणपंथ मुक्त बाज़ार और खुली प्रतिस्पर्धा की वकालत करता है। आधुनिकीकरण को अक्सर पश्चिमी औद्योगिक देशों के समान बनने की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता था। विकेंद्रित नियोजन का सबसे सशक्त उदाहरण केरल मॉडल है, जहाँ स्थानीय स्तर पर जन-भागीदारी के माध्यम से योजनाएँ बनाई और लागू की जाती हैं। यह मिलान भारत में प्रचलित विभिन्न आर्थिक विचारधाराओं और उनके प्रायोगिक स्वरूपों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

85. (C) औद्योगिक और आर्थिक निवेश में सरकार द्वारा बड़े कदम उठाने की योजना
'बॉम्बे प्लान' 1944 में भारतीय उद्योगपतियों द्वारा तैयार किया गया एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। इसकी मुख्य मंशा यह थी कि स्वतंत्र भारत में सरकार को अर्थव्यवस्था के नियोजन और औद्योगिक विकास में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। यद्यपि ये निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि थे, फिर भी उन्होंने महसूस किया कि बुनियादी उद्योगों के निर्माण हेतु आवश्यक भारी पूँजी निवेश केवल राज्य ही कर सकता है। इस प्रकार, बॉम्बे प्लान ने नियोजित विकास के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय सहमति बनाने में आधार प्रदान किया।

86. (B) सोवियत संघ
भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का विचार सोवियत संघ (USSR) की आर्थिक व्यवस्था से लिया गया था। सोवियत संघ ने 1920 के दशक में केंद्रीकृत नियोजन के माध्यम से बहुत कम समय में अपनी पिछड़ी कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था को

था। संसाधनों के सीमित होने और गरीबी के गहरे होने के कारण, हर निर्णय का लाभ किसी एक वर्ग को मिलता था तो दूसरे को उसकी कीमत चुकानी पड़ती थी। अतः विकास के मार्ग को चुनना एक गहरे राजनीतिक फैसले की माँग करता था, जहाँ सामाजिक न्याय और आर्थिक संवृद्धि के बीच कठिन संतुलन साधना अनिवार्य था।

69. (C) विभिन्न विकास परियोजनाओं की स्मृति में जारी किए गए डाक-टिकट
शुरुआती दशकों में, सार्वजनिक क्षेत्र की विशाल परियोजनाओं, जैसे बाँध, इस्पात संयंत्र और उर्वरक कारखानों को राष्ट्र के गौरव और आधुनिकता के 'मंदिर' के रूप में देखा जाता था। सरकार इन उपलब्धियों को जन-जन तक पहुँचाने के लिए डाक-टिकट जारी करती थी। ये डाक-टिकट न केवल परियोजनाओं की सूचना देते थे, बल्कि नियोजित विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनते भारत की एक सशक्त तस्वीर भी पेश करते थे। यह उस समय की विकास केंद्रित राजनीति और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति विश्वास का एक प्रमुख प्रतीक था।

70. (A) P-2, Q-1, R-3, S-4
भाखड़ा और हीराकुड स्वतंत्र भारत की विशाल बाँध परियोजनाएँ थीं जो सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए बनाई गई थीं। सिंदरी में देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बड़ा उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था, जो कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण था। चित्तरंजन में विद्युत इंजनों के निर्माण के लिए कारखाना लगाया गया था, जिसने रेलवे के आधुनिकीकरण में भूमिका निभाई। ये सभी परियोजनाएँ शुरुआती पंचवर्षीय योजनाओं की प्रमुख उपलब्धियाँ थीं जिन्होंने भारत के औद्योगिक और कृषि विकास का मार्ग प्रशस्त किया।

71. (D) वास्तव में, उस समय लगभग सभी नियोजन के पक्ष में थे।
1940 और 1950 के दशकों के दौरान, भारत में आर्थिक नियोजन के विचार के प्रति एक अभूतपूर्व राष्ट्रीय सहमति थी। केवल वामपंथी या समाजवादी ही नहीं, बल्कि उद्योगपतियों और दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों ने भी यह महसूस किया कि देश के पुनर्निर्माण के लिए राज्य द्वारा निर्देशित नियोजन अनिवार्य है। बॉम्बे प्लान इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। यद्यपि योजनाओं की प्राथमिकताओं पर मतभेद थे, लेकिन 'नियोजन' की आवश्यकता पर शायद ही किसी ने प्रश्न उठाया हो, जो उस समय की वैश्विक प्रवृत्तियों के भी अनुरूप था।

72. (A) उद्योग और खनन
पहली पंचवर्षीय योजना की तुलना में दूसरी योजना के बजटीय आवंटन में 'उद्योग और खनन' के क्षेत्र में सबसे नाटकीय वृद्धि देखी गई। जहाँ पहली योजना ने कृषि और सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी, वहीं दूसरी योजना (महालनोबिस मॉडल) ने अपना ध्यान भारी उद्योगों के निर्माण पर केंद्रित कर दिया। इस क्षेत्र का आवंटन प्रतिशत लगभग चार गुना बढ़ गया, जो भारत के विकास मॉडल में एक बड़े संरचनात्मक बदलाव का सूचक था। इसने कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण की शुरुआत की।

73. (C) 2, 3 और 4
'केरल मॉडल' अपनी सामाजिक प्राथमिकताओं के लिए जाना जाता है, जिसमें भारी उद्योगों के बजाय शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के व्यापक विस्तार पर सर्वोच्च ध्यान दिया गया है। इसकी अन्य प्रमुख विशेषताओं में एक मज़बूत सार्वजनिक खाद्य-वितरण प्रणाली और भूमि सुधारों का सफल क्रियान्वयन शामिल है। साथ ही, इसने विकेंद्रित नियोजन और जन-भागीदारी को अपनी योजना प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाया है। भारी उद्योगों को प्राथमिकता देना इस मॉडल का हिस्सा नहीं है, क्योंकि केरल का औद्योगिक आधार अन्य राज्यों की तुलना में कम विकसित रहा है।

74. (A) जे. सी. कुमारप्पा
'इकॉनोमी ऑफ परमानेंस' (Economy of Permanence) पुस्तक के लेखक जे. सी. कुमारप्पा थे, जो एक प्रसिद्ध गाँधीवादी अर्थशास्त्री थे। उन्होंने अपनी इस कृति में विकास के एक वैकल्पिक मॉडल का प्रस्ताव दिया, जो ग्रामीण सशक्तिकरण और पारिस्थितिक संतुलन पर आधारित था। कुमारप्पा ने तर्क दिया कि मनुष्य को प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर विकास करना चाहिए। उन्होंने कुटीर उद्योगों और विकेंद्रित अर्थव्यवस्था की वकालत की, जो आधुनिक पूंजीवादी और केंद्रीकृत औद्योगिक प्रणालियों के विपरीत जन-कल्याण और स्थिरता पर केंद्रित थी।

75. (A) कथन I और II दोनों सत्य हैं।
दूसरी पंचवर्षीय योजना के आलोचकों का मानना था कि भारी उद्योगों पर अत्यधिक निवेश करने से ग्रामीण भारत की जरूरतों को अनदेखा कर दिया गया। उनके अनुसार, इस्पात और मशीनों पर ध्यान केंद्रित करने से शहरी क्षेत्रों को तो लाभ हुआ, लेकिन कृषि पिछड़ गई और खाद्यान्न संकट गहरा गया। इन आलोचकों ने सुझाव दिया कि भारी उद्योगों के स्थान पर कृषि-आधारित लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए था, जो ग्रामीण रोजगार बढ़ा सकते थे और संतुलित विकास सुनिश्चित कर सकते थे।

76. (A) 3, 4, 2, 1
घटनाओं का सही कालक्रम भारत की 1947 में आज़ादी से शुरु होता है। इसके पश्चात 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना का वास्तविक दस्तावेज़ जारी किया गया। 1961 में तीसरी पंचवर्षीय योजना का आरंभ हुआ। अंत में, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। यह क्रम भारत की विकास नीतियों के वैचारिक और संस्थागत क्रमिक विकास को दर्शाता है, जहाँ नियोजन की पुरानी प्रणालियों को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार समय के साथ बदला गया।

77. (C) राजनीतिक परिणाम के रूप में उत्पन्न होने वाले निरंतर सामाजिक टकराव
स्वतंत्रता के बाद लिए गए आर्थिक विकास के फैसले तकनीकी से कहीं अधिक राजनीतिक थे, क्योंकि वे संसाधनों के बँटवारे से जुड़े थे। इन फैसलों ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच हितों का टकराव पैदा किया। जब सरकार किसी एक क्षेत्र

114. (A) कथन I और II दोनों सत्य हैं।
केरल का उदाहरण भारतीय विकास के संदर्भ में असाधारण है क्योंकि इसने प्रति व्यक्ति कम आय के बावजूद मानव विकास के उच्च मानक स्थापित किए हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि विकास का अर्थ केवल धन की संवृद्धि नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा तक जनता की पहुँच भी है। केरल ने प्रभावी सरकारी नीतियों और जन-भागीदारी के माध्यम से साक्षरता और जीवन प्रत्याशा जैसे मानकों में देश के अन्य समृद्ध राज्यों की तुलना में कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है।

115. (C) 1, 2 और 3
उड़ीसा के जगतसिंहपुर जिले में पोस्को-इंडिया के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों ने विकास और विस्थापन के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया। प्रदर्शनकारियों का मुख्य तर्क यह था कि उनकी पुश्तैनी जमीन और आजीविका की कीमत पर बड़ी कंपनियों के साथ हुए समझौते गलत हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि विस्थापन रोकने के लिए एमओयू को रद्द किया जाए। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में स्थानीय पुरुषों और महिलाओं ने भाग लिया, जिन्होंने अपनी जीविका और पारंपरिक पहचान की रक्षा के लिए संघर्ष किया।

116. (D) मौजूदा भूमि वितरण प्रणाली का कृषि विकास में सबसे बड़ी बाधा माना जाना
पहली पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधारों को कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सबसे अनिवार्य शर्त माना गया। योजनाकारों ने महसूस किया कि जब तक भूमि का वितरण असमान रहेगा और किसान केवल किराएदार बने रहेंगे, तब तक खेती में सुधार और निवेश संभव नहीं है। ज़मींदारी उन्मूलन और जोत की सीमा तय करने जैसे कदमों के माध्यम से भूमि सुधारों का उद्देश्य संसाधनों को किसानों के हाथों में सौंपना था, ताकि ग्रामीण गरीबी कम हो और देश खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सके।

117. (C) यह धारणा कि विकास का केवल पश्चिमी औद्योगिक मार्ग ही एकमात्र विकल्प है
यह प्रश्न कि 'आधुनिक' बनने के लिए 'पश्चिमी' होना अनिवार्य है या नहीं, विकास की उस एकपक्षीय धारणा को चुनौती देता है जो केवल यूरोपीय मॉडल को ही प्रगति का मानक मानती है। यह सोच अक्सर यह मान लेती है कि आधुनिकीकरण का अर्थ केवल पश्चिमी संस्थाओं और जीवनशैली की नकल करना है। हालांकि, केरल जैसे उदाहरण यह सिद्ध करते हैं कि कोई समाज अपनी जड़ों और पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखते हुए भी सामाजिक और मानवीय मानकों पर आधुनिक और विकसित हो सकता है।

118. (B) बचत और निवेश दोनों का बढ़ना।
दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े विस्तार की योजना इस विश्वास पर आधारित थी कि देश में राष्ट्रीय बचत और निवेश की दरों में वृद्धि होगी। योजनाकारों ने यह अनुमान लगाया था कि जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होगा, जनता और सरकार अधिक पूँजी संचय कर पाएँगे, जिसका उपयोग भारी उद्योगों के निर्माण में किया जा सकेगा। इसी वित्तीय आधार पर सरकार ने इस्पात और बिजली जैसे बुनियादी क्षेत्रों में बड़े निवेश की हिम्मत दिखाई, ताकि देश को औद्योगिक रुप से मज़बूत बनाया जा सके।

119. (D) 1930 के दशक की महामंदी
1930 के दशक की 'महामंदी' ने वैश्विक स्तर पर यह साबित कर दिया कि मुक्त बाजार और अनियंत्रित पूंजीवाद हमेशा स्थिर नहीं रह सकते। इस संकट ने पूरी दुनिया को हिला दिया और अर्थशास्त्रियों को नियोजन की आवश्यकता पर विचार करने के लिए मजबूर किया। महामंदी के कड़वे अनुभवों ने ही यह धारणा पुख्ता की कि अर्थव्यवस्था को संकट से बचाने और संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य का हस्तक्षेप और पूर्व-नियोजित आर्थिक नीतियां अनिवार्य हैं, जिससे भविष्य में नियोजन को वैश्विक समर्थन मिला।

120. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
स्वतंत्रता के बाद भारत में अमेरिका के पूंजीवादी मॉडल के समर्थक बहुत कम थे क्योंकि उस समय नियोजन और समाजवाद के विचारों का वैश्विक प्रभाव था। सोवियत संघ की तीव्र आर्थिक उन्नति ने भारतीय बुद्धिजीवियों को यह विश्वास दिलाया कि राज्य के नेतृत्व में नियोजित विकास के माध्यम से ही गरीबी और पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। इसी वैचारिक पृष्ठभूमि के कारण नेहरू और अन्य नेताओं ने समाजवाद और नियोजन को भारतीय विकास की मुख्य रणनीति के रूप में चुना, न कि मुक्त बाजार आधारित पूंजीवाद को।

121. (C) सामाजिक न्याय और विकास को दिशा देने हेतु सरकारी हस्तक्षेप की अनिवार्यता
भारत जैसे विविधतापूर्ण और गरीब देश में विकास को केवल निजी क्षेत्र के भरोसे इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता था क्योंकि बाजार की शक्तियाँ अक्सर सामाजिक न्याय की उपेक्षा करती हैं। सरकार का हस्तक्षेप यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था कि संसाधनों का लाभ केवल अमीर वर्ग तक न सिमट जाए, बल्कि गरीबों और पिछड़ों को भी विकास में हिस्सा मिले। राज्य की भूमिका विकास की दिशा तय करने और सामाजिक विषमताओं को कम करने के लिए अपरिहार्य मानी गई, जो जन-कल्याण के लक्ष्यों से प्रेरित थी।

122. (A) बुद्धिजीवी, पत्रकार, उद्योगपति, किसान और राजनेता सहित समाज के विविध वर्ग
भारत की शुरुआती पंचवर्षीय योजनाओं पर होने वाली बहसें बहुत ही समावेशी और जीवंत थीं। इन चर्चाओं में केवल सरकारी अधिकारी ही नहीं, बल्कि विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, अखबारों के संपादक, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और किसान संगठनों के नेता भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते थे। लोग यह महसूस करते थे कि नियोजन देश के भविष्य को तय करने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसके लक्ष्यों और आवंटन पर पूरे समाज में व्यापक विचार-विमर्श होता था। इस भागीदारी ने नियोजन की प्रक्रिया को एक मज़बूत लोकतांत्रिक आधार प्रदान किया।

एक मज़बूत औद्योगिक शक्ति में बदल दिया था। जवाहरलाल नेहरू और उस दौर के भारतीय योजनाकार इस सफलता से अत्यंत प्रभावित थे। उन्हें विश्वास था कि भारत जैसे विशाल और निर्धन देश के लिए संसाधनों का कुशल प्रबंधन और तीव्र विकास केवल राज्य के नेतृत्व वाली पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ही संभव है।

87. (A) केवल 1 और 2
भारत की शुरुआती विकास रणनीति ने आर्थिक संवृद्धि और सामाजिक न्याय दोनों को अपने प्राथमिक लक्ष्यों के रूप में स्वीकार किया। इसके पीछे यह विचार था कि विकास का लाभ केवल कुछ लोगों तक सीमित न रहकर समाज के सभी वर्गों तक पहुँचना चाहिए। इस प्रक्रिया में सरकार को एक प्रमुख और नियामक भूमिका सौंपी गई, ताकि निजी हितों के बजाय सार्वजनिक हित को प्राथमिकता मिले। हालाँकि, यह रणनीति पूर्णतः उदारवादी-पूंजीवादी नहीं थी और विशेषज्ञों के बीच प्राथमिकताओं को लेकर अक्सर गहरे मतभेद बने रहे।

88. (A) कथन I और II दोनों सत्य हैं, और कथन II, कथन I की सही व्याख्या करता है।
भारत में विकास की अवधारणा हमेशा विवादों का विषय रही है क्योंकि इसके लाभ और लागत अलग-अलग वर्गों के लिए असमान होते हैं। जहाँ एक इस्पात संयंत्र उद्योगपति के लिए मुनाफे और राष्ट्रीय प्रगति का जरिया है, वहीं स्थानीय आदिवासी के लिए यह उसकी पैतृक भूमि और संस्कृति के विनाश का कारण बन सकता है। यही विरोधाभास विकास की सर्वमान्य परिभाषा बनाना असंभव बना देता है, जिससे विकास के हर बड़े प्रोजेक्ट पर गहरे राजनीतिक और सामाजिक टकराव उत्पन्न होते हैं।

89. (C) पूँजी-भंडार का उपलब्ध रोज़गार योग्य जनसंख्या की तुलना में कम होना
1950 के दशक में बचत को बढ़ावा देना एक अत्यंत कठिन चुनौती थी क्योंकि भारत के पास उपलब्ध पूँजी-भंडार उसकी विशाल जनसंख्या की तुलना में बहुत कम था। अधिकांश लोग पहले से ही न्यूनतम आय पर जीवन यापन कर रहे थे, जिससे उनके पास बचत की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसके अतिरिक्त, रोज़गार के पर्याप्त अवसर न होने के कारण उपभोग का स्तर पहले ही बहुत नीचे था। ऐसी स्थिति में, विकास के लिए आवश्यक भारी निवेश हेतु बचत की दर को बढ़ाना योजनाकारों के लिए एक बड़ी समस्या थी।

90. (A) इसमें लगातार कमी आई।
1960 के दशक के बाद से भारत में राष्ट्रीय बचत की मात्रा में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई। इसके प्रमुख कारणों में लगातार होने वाले युद्ध, भीषण सूखे और आर्थिक अस्थिरता शामिल थे, जिन्होंने लोगों की बचत करने की क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। बढ़ती मुद्रास्फीति और संसाधनों के अभाव ने भी पूँजी संचय की प्रक्रिया को धीमा कर दिया। बचत में यह कमी नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक बड़ी बाधा बन गई, क्योंकि विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक घरेलू पूँजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध नहीं हो पा रहा था।

91. (D) क्योंकि इसमें उद्योग और शहरी अवसंरचना पर भारी निवेश किया गया था।
दूसरी पंचवर्षीय योजना पर 'शहरी तरफदारी' का आरोप इसलिए लगा क्योंकि इसका मुख्य जोर भारी औद्योगीकरण और बुनियादी ढाँचे (जैसे इस्पात संयंत्र और बिजली) पर था, जो मुख्य रूप से शहरों या उनके निकट स्थित थे। आलोचकों का मानना था कि कृषि की तुलना में उद्योगों को दी गई प्राथमिकता से संसाधनों का बड़ा हिस्सा शहरों की ओर मुड़ गया। इससे ग्रामीण क्षेत्र उपेक्षित रह गए और शहर एवं गाँव के बीच आर्थिक विषमता बढ़ने की आशंका पैदा हुई, जिसे ग्रामीण हितों के समर्थकों ने गलत माना।

92. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
'केरल मॉडल' विकेंद्रित नियोजन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है क्योंकि इसने विकास के पारंपरिक औद्योगिक मार्ग के बजाय सामाजिक क्षेत्रों पर निवेश किया। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि सुधारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, जिसका लाभ समाज के निचले स्तर तक पहुँचा। स्थानीय स्तर पर जन-भागीदारी और पंचायतों के माध्यम से योजनाओं को लागू करने के कारण ही केरल उच्च मानव विकास सूचकांक प्राप्त करने में सफल रहा। कारण (R) यह स्पष्ट करता है कि स्थानीय भागीदारी ही इस मॉडल की सफलता और विकेंद्रित स्वरुप का मुख्य आधार है।

93. (C) तीव्र औद्योगीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र की सक्रिय भूमिका के प्रबल समर्थक
पी.सी. महालनोबिस को भारत के नियोजन इतिहास में तीव्र औद्योगीकरण के प्रमुख पैरोकार के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना के माध्यम से यह विचार दृढ़ता से रखा कि भारी और बुनियादी उद्योगों के विकास के बिना देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। वे विकास की प्रक्रिया में सार्वजनिक क्षेत्र की अग्रणी भूमिका के समर्थक थे और उनका मानना था कि राज्य को ही अर्थव्यवस्था की 'कमांडिंग हाइट्स' को नियंत्रित करना चाहिए। उनका यह दृष्टिकोण दशकों तक भारत की विकास नीतियों का आधार बना रहा।

94. (D) पड़ोसी देशों की सरकारें
उड़ीसा में विकास के अर्थ को लेकर हुए टकराव में स्थानीय आदिवासी, जिन्हें अपनी भूमि खोने का डर था, पर्यावरणविद जो प्रदूषण से चिंतित थे, और केंद्र व राज्य सरकारें जो औद्योगिक निवेश चाहती थीं, प्रमुख पक्ष थे। इसमें पड़ोसी देशों की सरकारों की कोई भूमिका नहीं थी, क्योंकि यह एक आंतरिक विकासात्मक और राजनीतिक मुद्दा था। यह टकराव स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास की नीतियां समाज के भीतर ही विभिन्न समूहों के बीच कैसे तनाव और असहमति पैदा कर सकती हैं।

95. (C) केवल 1, 2, 3, 4
पंचवर्षीय योजना प्रणाली ने सरकार को अर्थव्यवस्था के प्रबंधन हेतु एक संरचित ढाँचा प्रदान किया। इसमें बजट को योजना और गैर-योजना व्यय में विभाजित किया गया, जिससे विकास प्राथमिकताओं पर निवेश सुनिश्चित हुआ। इस प्रणाली के माध्यम से सरकार को देश की आर्थिक स्थिति की एक बड़ी

की खाद्य जरूरतों को पूरा करना अनिवार्य था, जबकि आधुनिक देश बनने के लिए तीव्र औद्योगीकरण भी उतना ही जरूरी था।

41. (C) शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि-सुधार और गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम
'केरल मॉडल' विकास का एक ऐसा अनूठा उदाहरण है जो उच्च प्रति व्यक्ति आय के बजाय सामाजिक विकास के संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करता है। इस मॉडल के तहत केरल सरकार ने साक्षरता बढ़ाने, स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने और प्रभावी भूमि सुधार लागू करने पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पोषण सुनिश्चित करने और विकेंद्रित नियोजन द्वारा जनता की भागीदारी बढ़ाने के कारण केरल ने मानव विकास के क्षेत्र में विकसित देशों के समान सफलता प्राप्त की है।

42. (A) P-2, Q-1, R-4, S-3
पी.सी. महालनोबिस ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की और औद्योगिक मॉडल दिया। जे.सी. कुमारप्पा ने 'इकॉनोमी ऑफ परमानेंस' लिखकर गाँधीवादी आर्थिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। के.एन. राज एक युवा अर्थशास्त्री थे जिन्होंने पहली पंचवर्षीय योजना के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चरण सिंह ने कृषि और ग्रामीण भारत के हितों की पुरजोर वकालत की और किसान नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। ये सभी व्यक्तित्व भारत की शुरुआती आर्थिक नीतियों और वैकल्पिक विकास विचारधाराओं के प्रमुख स्तंभ रहे हैं।

43. (D) कमज़ोर औद्योगिक-आधार
केरल ने शिक्षा, स्वास्थ्य और आयु-प्रत्याशा जैसे सामाजिक क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन्हें 'केरल मॉडल' के रूप में जाना जाता है। हालांकि, इस मॉडल की एक सीमा यह रही है कि यहाँ औद्योगिक आधार अपेक्षाकृत कमजोर रहा है और रोजगार के अवसरों की कमी के कारण लोगों को बाहर जाना पड़ा है। अतः 'कमजोर औद्योगिक-आधार' इस मॉडल की एक विशेषता या समस्या तो हो सकती है, लेकिन इसे सामाजिक विकास की सकारात्मक 'उपलब्धि' के रूप में नहीं गिना जाता।

44. (B) ग्रामीण औद्योगीकरण पर आधारित
जे.सी. कुमारप्पा जैसे गाँधीवादी अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया कि भारत का वास्तविक विकास गाँवों के सशक्तिकरण और ग्रामीण औद्योगीकरण में निहित है। उन्होंने भारी और केंद्रीकृत उद्योगों के बजाय कुटीर एवं लघु उद्योगों का समर्थन किया, जो स्थानीय संसाधनों और श्रम का उपयोग कर सकें। उनका मानना था कि यह मॉडल न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने का भी सबसे प्रभावी तरीका है, जो पश्चिमी मॉडल की तुलना में भारतीय परिस्थितियों के अधिक अनुरूप है।

45. (C) केवल 1, 2 और 3
सार्वजनिक क्षेत्र ने स्वतंत्र भारत के औद्योगिक विकास में केंद्रीय भूमिका निभाई। इसमें सरकार द्वारा संचालित वे उद्योग शामिल थे जिन्हें 'कमांडिंग हाइट्स' माना जाता था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के माध्यम से इसके विस्तार पर विशेष बल दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं था, बल्कि राष्ट्र निर्माण, बुनियादी ढाँचा तैयार करना और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना था। कथन 4 गलत है क्योंकि ये उद्यम लोकहित और विकास की प्राथमिकताओं के लिए स्थापित किए गए थे।

46. (D) निचले स्तर पर जन-भागीदारी से योजनाएँ तैयार करने की प्रक्रिया
विकेंद्रित नियोजन का तात्पर्य विकास की ऐसी प्रक्रिया से है जहाँ योजनाएँ ऊपर से लादने के बजाय निचले स्तर पर, यानी ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों के माध्यम से तैयार की जाती हैं। इसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित की जाती है ताकि विकास स्थानीय जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप हो सके। केरल मॉडल इसका प्रमुख उदाहरण है, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के लिए स्थानीय स्तर पर सक्रिय रूप से निर्णय लिए गए और संसाधनों का प्रबंधन किया गया।

47. (A) भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद् के रूप में
पी. सी. महालनोबिस को भारत में सांख्यिकी विज्ञान का जनक माना जाता है। वे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) की स्थापना की। दूसरी पंचवर्षीय योजना के निर्माण में उनकी प्रमुख भूमिका थी, जहाँ उन्होंने भारी उद्योगों के विकास का गणितीय मॉडल प्रस्तुत किया। उनके योगदान ने भारत को नियोजन के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया और देश के तीव्र औद्योगीकरण की नींव रखने में मदद की, जिससे वे आधुनिक नियोजन के प्रमुख वास्तुकार बने।

48. (A) 2, 4, 3, 1
भारत की विकास यात्रा में सबसे पहले 1944 का 'बॉम्बे प्लान' आया। इसके बाद 1951 में के.एन. राज के योगदान वाली पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई। 1956 में पी.सी. महालनोबिस के मॉडल पर आधारित दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरु हुई। अंत में, केरल मॉडल का विकास हुआ जो सामाजिक विकास के क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट उपलब्धियों के लिए बाद के दशकों में प्रसिद्ध हुआ। यह क्रम भारत में विकास की विभिन्न विचारधाराओं और योजनाओं के उदय के ऐतिहासिक चरणों को दर्शाता है।

49. (B) पी. सी. महालनोबिस
भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) की स्थापना पी. सी. महालनोबिस ने 1931 में कलकत्ता में की थी। यह संस्थान सांख्यिकी के क्षेत्र में शोध और प्रशिक्षण का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बना। महालनोबिस ने इस संस्थान के माध्यम से विकास की योजनाओं को वैज्ञानिक और सांख्यिकीय आधार प्रदान किया। नियोजन प्रक्रिया में डेटा के महत्व को समझते हुए उन्होंने सरकार को सटीक आंकड़ों के आधार पर नीतियाँ बनाने में मदद की, जो बाद में पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई।

पंचवर्षीय चरणों में आगे बढ़ाया और किन परिस्थितियों में उसे अस्थायी रूप से योजनाओं को स्थगित करना पड़ा।

105. (C) यूरोप के अधिकतर हिस्सों और संयुक्त राज्य अमरीका
विकास का उदारवादी-पूंजीवादी मॉडल मुख्य रूप से पश्चिमी दुनिया में प्रचलित था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के अधिकांश विकसित देश शामिल थे। यह मॉडल निजी संपत्ति, मुक्त बाजार और न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के सिद्धांतों पर आधारित था। इसके अनुसार, आर्थिक विकास मुख्य रूप से निजी उद्यम और खुली प्रतिस्पर्धा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। भारत ने स्वतंत्रता के समय इस मॉडल के कुछ तत्वों को तो अपनाया, लेकिन इसे सोवियत संघ के समाजवादी तत्वों के साथ मिलाकर मिश्रित व्यवस्था चुनी।

106. (C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
1944 में भारत के प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा तैयार किया गया 'बॉम्बे प्लान' वास्तव में देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था का समर्थन करता था। यह धारणा गलत है कि वे एक अनियोजित या मुक्त बाजार वाली अर्थव्यवस्था चाहते थे। इसके विपरीत, उन्होंने यह प्रस्तावित किया कि सरकार को उद्योगों और अन्य आर्थिक क्षेत्रों में बड़े निवेश करने चाहिए और अर्थव्यवस्था को दिशा देनी चाहिए। वे जानते थे कि स्वतंत्र भारत के बुनियादी औद्योगिक ढाँचे को खड़ा करने के लिए राज्य का सक्रिय हस्तक्षेप और भारी निवेश अपरिहार्य है।

107. (D) विभिन्न विचारों और हितों के टकराव के बीच चुनी गई एक राजनीतिक प्रक्रिया
नियोजित विकास की पूरी प्रक्रिया भारत में एक व्यापक और निरंतर राजनीतिक मंथन का परिणाम थी। यह केवल विशेषज्ञों द्वारा लिया गया कोई तकनीकी निर्णय नहीं था, बल्कि विभिन्न सामाजिक समूहों के हितों और परस्पर विरोधी विचारधाराओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास था। विकास का कौन सा रास्ता अपनाया जाए, इस पर समाज में गहरे मतभेद थे। अंततः, भारत ने जिस मॉडल को चुना, वह एक ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया का सार था जिसने विकास के साथ-साथ सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों को जोड़ने का प्रयास किया।

108. (B) बाँध और सिंचाई
पहली पंचवर्षीय योजना ने कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी क्योंकि देश विभाजन और खाद्य संकट से जूझ रहा था। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार अत्यंत आवश्यक था, जिसके चलते सरकार ने भाखड़ा-नांगल और हीराकुड जैसे विशाल बाँधों के निर्माण में भारी निवेश किया। योजनाकारों का मानना था कि एक मज़बूत कृषि आधार ही भविष्य के औद्योगिक विकास की नींव बन सकता है। इसके अलावा, भूमि सुधारों पर भी जोर दिया गया ताकि संसाधनों का बेहतर वितरण हो सके।

109. (B) केवल 2, 3 और 5
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही इस बात पर सहमति बन गई थी कि आज़ाद भारत की सरकार के आर्थिक लक्ष्य जन-हितैषी होंगे। गरीबी मिटाना और संसाधनों का सामाजिक-आर्थिक पुनर्वितरण सरकार की मुख्य जिम्मेदारी मानी गई। साथ ही, देश को आधुनिक बनाने के लिए औद्योगीकरण को एक अनिवार्य मार्ग के रूप में स्वीकार किया गया। यह स्पष्ट था कि सरकार को अर्थव्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभानी होगी, जो औपनिवेशिक काल की उपेक्षापूर्ण और व्यापारिक हितों वाली नीतियों से बिल्कुल अलग होगी।

110. (D) 1966-1969
'योजना अवकाश' (Plan Holiday) की अवधि 1966 से 1969 तक थी। इस दौरान भारत सरकार ने कोई नियमित पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की, बल्कि वार्षिक योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। इसके पीछे मुख्य कारण 1962 का चीन युद्ध, 1965 का पाकिस्तान युद्ध और उसी दौरान पड़ा भीषण सूखा था। इन संकटों ने देश की अर्थव्यवस्था को जर्जर कर दिया था और संसाधनों की भारी कमी पैदा कर दी थी, जिससे सरकार को नियोजन की अपनी निर्धारित प्रक्रिया को अस्थायी रूप से विराम देना पड़ा।

111. (A) तेज़ रफ़्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँच सकता था।
अर्थशास्त्री के. एन. राज का मानना था कि विकास की गति बहुत तेज़ रखने से अर्थव्यवस्था में असंतुलन पैदा हो सकता है। उन्हें आशंका थी कि यदि अचानक बहुत अधिक निवेश किया गया, तो इससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है और संसाधनों का अपव्यय हो सकता है। उनका तर्क था कि भारत जैसे नव-स्वतंत्र राष्ट्र को अपनी लोकतांत्रिक जड़ों को मज़बूत करने के लिए पहले दो दशकों तक सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। 'धीमी चाल' की यह दलील पहली योजना के सतर्क और कृषि-केंद्रित स्वरूप का मुख्य आधार बनी।

112. (C) P-3, Q-4, R-2, S-1
योजना-व्यय वह धन है जिसे पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताओं पर खर्च किया जाता है। गैर-योजना-व्यय प्रशासनिक और रोजमर्रा की मदों पर होने वाला वार्षिक खर्च है। भूमि सुधार के अंतर्गत ज़मींदारी प्रथा के उन्मूलन जैसे कदम उठाए गए ताकि किसानों को अधिकार मिल सके। संरक्षणवाद की नीति के तहत घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया गया। ये सभी अवधारणाएँ स्वतंत्र भारत की आरंभिक आर्थिक व्यवस्था और विकास की रणनीति के महत्वपूर्ण अंग रहे हैं।

113. (B) जे. सी. कुमारप्पा
जे. सी. कुमारप्पा एक प्रख्यात गाँधीवादी अर्थशास्त्री थे जिन्होंने योजना आयोग के साथ मिलकर काम किया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास पर जोर दिया। उन्होंने 'इकॉनोमी ऑफ परमानेंस' जैसी कृतियों के माध्यम से एक ऐसा आर्थिक दर्शन प्रस्तुत किया जो अहिंसक, न्यायपूर्ण और प्रकृति के अनुकूल हो। उन्होंने केंद्रीकृत औद्योगीकरण के स्थान पर स्थानीय संसाधनों और कुटीर उद्योगों के माध्यम से गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने की वकालत की, जो उस समय के मुख्यधारा के औद्योगिक मॉडल का एक सशक्त वैकल्पिक विचार था।

किसान संगठनों की मांगों ने भी यह सुनिश्चित किया कि विकास के लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचें। इन सभी कारकों के समन्वय से भारत में नियोजन की नींव पड़ी।

60. (B) सालाना आधार पर दैनंदिन मदों पर होने वाला खर्च
सरकारी बजट में 'गैर-योजना व्यय' का तात्पर्य उस खर्च से है जो पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित नई परियोजनाओं के बाहर होता है। इसके अंतर्गत सरकार के रोजमर्रा के कामकाज, जैसे प्रशासनिक सेवाएँ, कर्मचारियों का वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और पहले से चल रही परियोजनाओं का रखरखाव आता है। यह व्यय प्रतिवर्ष किया जाता है और प्रशासन की निरंतरता बनाए रखने के लिए अनिवार्य होता है। इसके विपरीत 'योजना व्यय' केवल पंचवर्षीय योजनाओं की विशिष्ट विकास प्राथमिकताओं के लिए आवंटित होता है।

61. (C) सरकार को अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक नियोजन का अवसर मिलना
पंचवर्षीय योजना प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह था कि इससे सरकार को अर्थव्यवस्था का एक व्यापक दृष्टिकोण (Big Picture) प्राप्त हुआ। पाँच वर्षों की निश्चित अवधि के लिए लक्ष्य और संसाधन निर्धारित करने से सरकार के पास दीर्घकालिक रणनीतियाँ बनाने और उन्हें चरणों में लागू करने की क्षमता आ गई। इससे केवल तात्कालिक समस्याओं के समाधान के बजाय भविष्य के बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास के लिए एक व्यवस्थित मार्ग प्रशस्त हुआ, जिससे संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग संभव हो सका।

62. (A) कथन I और II दोनों सत्य हैं।
पहली पंचवर्षीय योजना के समय भारतीय योजनाकारों का मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय आय को बढ़ाना था। इसके लिए उन्होंने बचत की दर को ऊँचा करने पर बल दिया, क्योंकि निवेश के लिए पूँजी तभी उपलब्ध होती है जब समाज अपनी कुल आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करने के बजाय भविष्य के लिए बचाए। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था क्योंकि आम जनता की आय पहले से ही बहुत कम थी, फिर भी योजना ने बचत को प्रोत्साहित कर आर्थिक विकास की गति तेज़ करने का प्रयास किया।

63. (A) बचत कम थी, योजनाकारों ने बचत को बढ़ावा देने की कोशिश की।
पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में भारत में राष्ट्रीय बचत की दर बहुत कम थी, क्योंकि अधिकांश जनता गरीबी रेखा के नीचे थी और उनकी आय केवल जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त थी। योजनाकारों ने महसूस किया कि बिना बचत बढ़ाए निवेश और विकास संभव नहीं है। इसलिए, उन्होंने जनता को बचत के लिए प्रोत्साहित किया और सरकारी स्तर पर पूँजी संचय के प्रयास किए। हालांकि, गरीबी के कारण बचत बढ़ाना एक धीमी और कठिन प्रक्रिया साबित हुई, जो योजनाकारों के लिए बड़ी चिंता का विषय थी।

64. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
स्वतंत्र भारत के नेताओं के मन में यह स्पष्ट था कि देश की आर्थिक नीतियाँ औपनिवेशिक हितों के बजाय जन-कल्याण पर आधारित होनी चाहिए। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही यह सहमति बन चुकी थी कि गरीबी मिटाने और संसाधनों के उचित पुनर्वितरण की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की होगी। यही कारण है कि आज़ादी के बाद सरकार ने विकास की कमान अपने हाथों में ली और समाज के कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए नियोजित विकास और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को अपनी नीतियों का आधार बनाया।

65. (B) भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नया और व्यापक आयाम देना
दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी औद्योगीकरण पर दिए गए ज़ोर ने भारतीय अर्थव्यवस्था का चेहरा बदल दिया। इसने इस्पात, बिजली, मशीनरी और रेलवे जैसे बुनियादी क्षेत्रों में बड़े निवेश के माध्यम से औद्योगिक आत्मनिर्भरता की नींव रखी। यद्यपि इससे कृषि पर दबाव बढ़ा, लेकिन इसने देश को एक आधुनिक औद्योगिक राष्ट्र बनाने की दिशा में एक बड़ा रणनीतिक बदलाव किया। इस नीति ने आर्थिक संवृद्धि की भविष्य की संभावनाओं को विस्तार दिया और भारत को वैश्विक आर्थिक मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने का प्रयास किया।

66. (A) नागरिक संगठनों के माध्यम से जनता को विकास कार्यों में जोड़ना
केरल में 'नव लोकतांत्रिक पहल' अभियान का मुख्य उद्देश्य विकास की प्रक्रिया को अधिक जन-केंद्रित और लोकतांत्रिक बनाना था। 1987 से 1991 के बीच चलाए गए इस अभियान ने नागरिक संगठनों और स्थानीय समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में सक्रिय रूप से शामिल किया। इसके माध्यम से स्वेच्छा से कार्य करने (Voluntary work) की संस्कृति को बढ़ावा दिया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि विकास योजनाएँ केवल कागज़ों पर न रहकर धरातल पर जनता के सहयोग से कार्यान्वित हों।

67. (A) केवल 1, 2 और 3
योजना आयोग की स्थापना के समय, इसके उद्देश्यों को भारतीय संविधान के राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों से जोड़ा गया था। इसमें स्पष्ट किया गया था कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे सभी नागरिकों को आजीविका का अधिकार मिले, भौतिक संसाधनों का बँटवारा सार्वजनिक हित में हो और अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार हो कि धन का अनुचित संकेंद्रण न हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता जैसे अधिकार मौलिक अधिकारों का हिस्सा थे, जो योजना आयोग के विशिष्ट आर्थिक उद्देश्यों में शामिल नहीं थे।

68. (D) विकास में निहित परस्पर-विरोधी हितों और जटिल राजनीतिक निर्णयों की आवश्यकता
विकास की चुनौती केवल तकनीकी या वित्तीय समस्या नहीं थी, बल्कि यह विभिन्न सामाजिक समूहों के परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बैठाने का एक अत्यंत जटिल कार्य

123. (B) केवल 1, 2, 3, 4
1960 के दशक में नियोजन के प्रति शुरुआती उत्साह कम होने के पीछे कई ठोस कारण थे। लगातार युद्धों (1962 और 1965) ने विकास के संसाधनों को रक्षा की ओर मोड़ दिया। साथ ही, भीषण सूखे ने खाद्यान्न संकट पैदा किया और अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर धकेला। इन बाहरी और आंतरिक चुनौतियों ने नियोजन के लक्ष्यों को अप्राप्य बना दिया, जिससे लोगों का भरोसा डगमगाने लगा। यह कहना गलत है कि सभी लक्ष्य प्राप्त हो गए थे; बल्कि सच तो यह था कि संकट के कारण नियोजन प्रक्रिया बाधित हुई थी।

124. (B) एक ओर समाजवादी सिद्धांत अपनाना और दूसरी ओर निजी निवेश हेतु उदार होना
फ्रैंकिन फ्रैंकल ने कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बड़े वैचारिक अंतर्विरोध को रेखांकित किया था। पार्टी सार्वजनिक मंचों पर तो समाजवादी सिद्धांतों और गरीबों के उत्थान की बात करती थी, लेकिन व्यावहारिक नीतियों में वह निजी पूंजीपतियों और भू-स्वामियों के हितों को भी साधती थी। यह द्वैतवाद पार्टी की मजबूरी भी थी और रणनीति भी, ताकि वह समाज के सभी वर्गों का समर्थन पा सके। हालाँकि, इस विरोधाभास ने अक्सर भूमि सुधारों और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण की प्रक्रिया को धीमा और कमजोर कर दिया।

125. (C) खाद्यान्न का अभाव और वितरण
1960 के दशक में बिहार में पड़ा अकाल और सरकार द्वारा अपनाई गई 'ज़ोनिंग' (इलाका बंदी) की नीति सीधे तौर पर देश में व्याप्त गंभीर खाद्य संकट से संबंधित थी। ज़ोनिंग नीति के तहत राज्यों के बीच खाद्यान्न के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिससे उन राज्यों में खाद्यान्न की भारी कमी हो गई जहाँ उत्पादन कम था। इस नीति ने बिहार जैसे क्षेत्रों में अकाल की स्थिति को और अधिक भयावह बना दिया, जिससे विकास नीति में खाद्यान्न वितरण की समस्याओं पर गंभीर बहस छिड़ गई।

126. (B) P-3, Q-1, R-2, S-4
चरण सिंह ने अपना पूरा जीवन कृषि और ग्रामीण भारत के उत्थान के लिए समर्पित किया, वे भारी औद्योगीकरण के आलोचक और किसान हितों के रक्षक थे। पी.सी. महालनोबिस ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगीकरण का खाका तैयार किया। वर्गीज कुरियन ने सहकारी डेयरी आंदोलन के माध्यम से 'श्वेत क्रांति' की शुरुआत की। के.एन. राज एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे जिन्होंने पहली पंचवर्षीय योजना के निर्माण में आधारभूत भूमिका निभाई। यह मिलान भारतीय विकास के प्रमुख स्तंभों और उनके विशिष्ट कार्यक्षेत्रों को दर्शाता है।

127. (A) सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का सह-अस्तित्व।
मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य एक ऐसी आर्थिक प्रणाली से है जहाँ राज्य (सार्वजनिक क्षेत्र) और निजी उद्यम दोनों मिलकर काम करते हैं। भारत में, सरकार ने महत्वपूर्ण और भारी उद्योगों की कमान अपने हाथ में ली, जबकि कृषि, व्यापार और छोटे उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया। इस मॉडल का उद्देश्य पूँजीवाद की कुशलता और समाजवाद के सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाना था। इससे सरकार को विकास की दिशा नियंत्रित करने और निजी पहल को बढ़ावा देने, दोनों की अनुमति मिली।

128. (D) कथन I और II दोनों सत्य हैं।
दूसरी पंचवर्षीय योजना ने भारत में एक मज़बूत औद्योगिक बुनियादी ढाँचा खड़ा करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। यद्यपि इसकी इस आधार पर आलोचना की गई कि इसने कृषि की उपेक्षा की और विदेशी मुद्रा संकट पैदा किया, लेकिन इसने इस्पात, ऊर्जा और भारी मशीनरी जैसे क्षेत्रों में जो आधार तैयार किया, उसने भविष्य की आर्थिक वृद्धि को संभव बनाया। इस योजना ने भारत को एक आधुनिक औद्योगिक राष्ट्र बनाने के संकल्प को धरातल पर उतारा, जो देश की दीर्घकालिक विकास रणनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था।

129. (B) 2, 3 और 4
योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में एक कार्यकारी आदेश द्वारा की गई थी, न कि संविधान के किसी प्रावधान द्वारा, इसलिए यह एक 'गैर-संवैधानिक' निकाय था। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते थे और यह दशकों तक भारत के विकास का मुख्य केंद्र रहा। 2015 में इसे समाप्त कर इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई ताकि राज्यों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। अतः कथन 1 गलत है, जबकि बाकी सभी तथ्य आयोग के स्वरुप और इतिहास के बारे में बिल्कुल सही हैं।

130. (A) पश्चिमी आधुनिकीकरण की धारणा
"विकासशील" या "अविकसित" जैसे शब्दों का उदय विकास की उस पश्चिमी धारणा से हुआ जो आधुनिकीकरण को एक क्रमिक विकास की सीढ़ी मानती थी। इस दृष्टिकोण के अनुसार, पश्चिमी औद्योगिक देश विकास के उच्चतम स्तर पर थे और बाकी दुनिया को उन्हीं के चरणों का अनुसरण करना था। जो देश इस मार्ग में पीछे थे, उन्हें 'अविकसित' कहा गया। यह शब्दावली न केवल आर्थिक स्थिति को दर्शाती थी, बल्कि यह यह भी मानती थी कि विकास का केवल एक ही मान्य और सही रास्ता है, जो पश्चिमी शैली का आधुनिकीकरण है।

131. (C) वर्तमान की कई आर्थिक और राजनीतिक बहसों के ऐतिहासिक मूल को समझना
नियोजित विकास की राजनीति का अध्ययन केवल इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि यह आज की जटिल आर्थिक समस्याओं को समझने के लिए अनिवार्य है। वर्तमान में भूमि अधिग्रहण, निजीकरण, पर्यावरण संरक्षण और राज्य की भूमिका को लेकर जो भी विवाद होते हैं, उनके बीज इन्हीं शुरुआती दशकों के निर्णयों में छिपे हैं। तत्कालीन बहसों और नीतियों के परिणामों को जानकर ही हम समझ सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपना वर्तमान स्वरुप कैसे प्राप्त किया और भविष्य की चुनौतियाँ क्या हैं।

132. (A) 2, 4, 3, 1
भारत की विकास यात्रा के ऐतिहासिक मील के पत्थर एक निश्चित क्रम में हैं। सबसे पहले 1944 में उद्योगपतियों ने 'बॉम्बे

(A) ताशकंद समझौता
(B) लाहौर घोषणा
(C) आगरा शिखर सम्मेलन
(D) शिमला समझौता

31. भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था?
(A) मई 1974, पोखरण
(B) मई 1998, श्रीहरिकोटा
(C) जुलाई 1979, थुम्बा
(D) अप्रैल 1982, पोखरण

32. भारत के परमाणु कार्यक्रम का संस्थापक किसे माना जाता है, जिनके निर्देशन में इसकी शुरुआत हुई?
(A) सी. वी. रमन
(B) होमी जहाँगीर भाभा
(C) मेघनाद साहा
(D) विक्रम साराभाई

33. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन 1: भारत ने 1974 के अपने पहले परमाणु परीक्षण को 'शांतिपूर्ण परीक्षण' करार दिया।
कथन 2: भारत का कहना था कि वह अणुशक्ति को सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों में इस्तेमाल करने की अपनी नीति के प्रति दृढ़ संकल्प है।
(A) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं।
(B) कथन 1 सत्य है, लेकिन कथन 2 असत्य है।
(C) कथन 1 असत्य है, लेकिन कथन 2 सत्य है।
(D) कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं।

34. 1968 की परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के संबंध में भारत का दृष्टिकोण क्या था?
(A) भारत ने इसे भेदभावपूर्ण माना और हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।
(B) भारत ने संधि के प्रावधानों का समर्थन किया और तुरंत आधिकारिक हस्ताक्षर कर दिए।
(C) भारत इस संधि पर पूरी तरह तटस्थ रहा और भविष्य के लिए कोई निर्णय नहीं लिया।
(D) भारत ने अपनी सुरक्षा हेतु कुछ संशोधनों के साथ पर हस्ताक्षर करना चुना।

35. निम्नलिखित सूचना के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (घटना)
P. भारत-चीन युद्ध
Q. भारत-पाक युद्ध (पहला)
R. भारत-पाक युद्ध (बांग्लादेश)
S. कारगिल संघर्ष
सूची II: (वर्ष)
1. 1965
2. 1999
3. 1962
4. 1971
(A) P-3, Q-1, R-4, S-2
(B) P-1, Q-3, R-2, S-4
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

36. 1999 के कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का क्या नाम था?
(A) ऑपरेशन ब्लू स्टार
(B) ऑपरेशन मेघदूत
(C) ऑपरेशन पवन
(D) ऑपरेशन विजय

37. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये, जो भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों को दर्शाते हैं:
1. घरेलू ज़रूरतें
2. अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ
3. संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धांत
4. शासक दल की विचारधारा
5. ऐतिहासिक विरासत और स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्य
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1, 2 और 3
(C) केवल 3, 4 और 5
(D) 1, 2, 3, 4 और 5 सभी

38. "आज़ादी बुनियादी तौर पर विदेश संबंधों से ही बनी होती है।" यह प्रसिद्ध कथन किसका है?
(A) महात्मा गांधी
(B) जवाहरलाल नेहरु
(C) सरदार पटेल
(D) डॉ. राजेंद्र प्रसाद

39. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): भारत की स्वतंत्रता के बाद की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता एक केंद्रीय सिद्धांत था।
कारण (R): भारत अमरीका और सोवियत संघ की अगुवाई वाले किसी भी सैन्य गठबंधन से अपने को दूर रखना चाहता था।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

40. 1950 के दशक में नियोजित विकास की भारतीय रणनीति की एक प्रमुख विशेषता क्या थी जिसने बाहरी दुनिया से भारत के आर्थिक लेन-देन को सीमित कर दिया?

इस पहल ने राज्य में विकेंद्रित नियोजन और जन-भागीदारी को बढ़ावा दिया। इसके माध्यम से नागरिकों को न केवल साक्षर बनाया गया, बल्कि उन्हें विकास के कार्यों में सीधे तौर पर जोड़कर एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत की गई। यह अभियान इस बात का प्रमाण था कि जनता के सहयोग और नागरिक संगठनों की सक्रियता से शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में असाधारण परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

142. (A) कथन I और II दोनों सत्य हैं।
भारत की शुरुआती नियोजन प्रक्रिया में पी.सी. महालनोबिस और के.एन. राज, दोनों का ही योगदान अतुलनीय है। के.एन. राज ने पहली पंचवर्षीय योजना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहाँ उन्होंने कृषि विकास और सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने की दलील दी थी। वहीं, पी.सी. महालनोबिस ने दूसरी पंचवर्षीय योजना का ढाँचा तैयार किया, जिसने तीव्र औद्योगीकरण के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नया मोड़ दिया। ये दोनों अर्थशास्त्री भारत की विकास यात्रा के दो अलग-अलग दृष्टिकोणों और चरणों के प्रमुख प्रतिनिधि माने जाते हैं।

143. (A) भावी पीढ़ियों हेतु संसाधन संरक्षण और वर्तमान आवश्यकताओं के मध्य संतुलन
विकास की बहसों में पीढ़ियों के बीच हितों को तोलने का तात्पर्य 'सतत विकास' (Sustainable Development) की अवधारणा से है। इसका अर्थ यह है कि हम आज की प्रगति और जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह उपयोग न करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचे ही नहीं। यह मुद्दा उड़ीसा जैसे राज्यों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहाँ आज के औद्योगिक लाभ और भविष्य के पर्यावरणीय तथा संसाधनों के नुकसान के बीच एक कठिन संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है।

144. (B) विकास के लाभ और लागत का समाज के विभिन्न वर्गों में होने वाला असमान वितरण
विकास के मुद्दों पर राजनीतिक टकराव का मुख्य कारण यह है कि इसके लाभ और लागत समाज में बराबर नहीं बँटते। जब कोई बाँध या संयंत्र लगता है, तो उससे होने वाले लाभ जैसे बिजली और इस्पात शहरी और औद्योगिक वर्गों को मिलते हैं, जबकि विस्थापन और पर्यावरण विनाश की भारी लागत स्थानीय गरीबों और आदिवासियों को चुकानी पड़ती है। संसाधनों के इस असमान बँटवारे के कारण विभिन्न समूहों के बीच हितों का संघर्ष होता है, जो विकास को एक गहरा राजनीतिक संघर्ष बना देता है।

145. (B) केवल 2 और 4
भारत ने विकास के लिए किसी एक विदेशी मॉडल की नकल करने के बजाय 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' को चुना, जिसमें पूँजीवादी और समाजवादी दोनों प्रणालियों के अच्छे तत्वों को जोड़ा गया। इस मॉडल के तहत निजी क्षेत्र को फलने-फूलने का मौका दिया गया, लेकिन साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्सों को नियंत्रित करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई। सरकार ने विकास प्रक्रिया में एक नियामक और दिशा-निर्देशक की भूमिका निभाई ताकि आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ सामाजिक समानता के लक्ष्यों को भी प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके।

146. (A) उद्योगपतियों का नियोजित अर्थव्यवस्था और राज्य की सक्रिय भूमिका के पक्ष में होना
1944 का 'बॉम्बे प्लान' इस दृष्टि से ऐतिहासिक था कि इसने सिद्ध कर दिया कि भारत के उद्योगपति भी आर्थिक नियोजन के महत्व को समझते थे। आम धारणा के विपरीत, ये निजी पूँजीपति चाहते थे कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाए और भारी निवेश करे। वे जानते थे कि स्वतंत्र भारत के पिछड़े बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने के लिए राज्य का हस्तक्षेप अनिवार्य है। इस योजना ने स्पष्ट किया कि भारत में नियोजित विकास की माँग केवल समाजवादियों की नहीं, बल्कि व्यापारिक वर्गों की भी थी।

147. (C) एक अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र सह-अस्तित्व में हों
मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत के विकास का वह मध्य मार्ग है जहाँ सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को एक साथ काम करने की स्वतंत्रता दी गई। इस व्यवस्था में, राज्य ने रक्षा, भारी उद्योग और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का नियंत्रण अपने पास रखा, जबकि कृषि, खुदरा व्यापार और लघु विनिर्माण जैसे क्षेत्रों को निजी उद्यमों के लिए खुला रखा। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य बाज़ार की प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाना और साथ ही सरकार के माध्यम से सामाजिक कल्याण और संसाधनों का न्यायोचित वितरण सुनिश्चित करना था।

148. (D) विकास का अर्थ आर्थिक संवृद्धि और सामाजिक न्याय दोनों है।
स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास नीति के पीछे एक दृढ़ आम सहमति थी कि विकास केवल जीडीपी या आय बढ़ाने तक सीमित नहीं होना चाहिए। वास्तविक विकास वही माना गया जिसमें 'आर्थिक संवृद्धि' के साथ-साथ 'सामाजिक न्याय' भी जुड़ा हो। इसका अर्थ था कि देश समृद्ध बने, लेकिन उस समृद्धि का न्यायपूर्ण बँटवारा हो ताकि समाज का सबसे गरीब व्यक्ति भी सम्मानजनक जीवन जी सके। यही समावेशी विज़न स्वतंत्र भारत की नियोजन प्रक्रिया और सभी पंचवर्षीय योजनाओं का मूल मंत्र बना रहा।

149. (C) 1951-1956
स्वतंत्र भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक था। यह योजना आज़ादी के तुरंत बाद देश की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बनाई गई थी। इसका मुख्य लक्ष्य कृषि क्षेत्र में सुधार करना और विभाजन के कारण पैदा हुए खाद्यान्न संकट को दूर करना था। इस पाँच साल की अवधि के दौरान सरकार ने सिंचाई और ऊर्जा परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे भविष्य के औद्योगिक विकास के लिए एक ठोस ग्रामीण और बुनियादी आधार तैयार हो सका।

प्लान' प्रस्तुत किया। आज़ादी के बाद 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई। इसके बाद, औद्योगिक विकास के जनक कहे जाने वाले पी.सी. महालनोबिस का निधन 1972 में हुआ। अंत में, हाल के वर्षों (2000 के दशक के मध्य) में उड़ीसा में पोस्को प्लांट के खिलाफ बड़े पैमाने पर जन-विरोध प्रदर्शन हुए। यह क्रम नियोजन के उदय से लेकर आधुनिक विकास संघर्षों तक की कहानी कहता है।

133. (C) कृषि क्षेत्र (बाँध और सिंचाई सहित)
स्वतंत्र भारत की पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) का मुख्य केंद्र-बिंदु कृषि क्षेत्र था। विभाजन के कारण उपजी खाद्य सामग्री की कमी को दूर करना सरकार की प्राथमिकता थी। इसके लिए भाखड़ा-नांगल जैसी विशाल बाँध और सिंचाई परियोजनाओं में भारी पूँजी निवेश किया गया। योजनाकारों का मानना था कि कृषि को मज़बूत किए बिना औद्योगिक विकास का सपना पूरा नहीं हो सकता। इसके अलावा, गाँवों में भूमि सुधारों पर भी जोर दिया गया ताकि संसाधनों का समान वितरण हो सके और उत्पादन बढ़ सके।

134. (B) अर्थव्यवस्था के तेज़ संरचनात्मक बदलाव और भारी उद्योगों के विकास पर बल
दूसरी पंचवर्षीय योजना ने भारत की विकास रणनीति में एक युगांतकारी परिवर्तन किया। पी.सी. महालनोबिस के नेतृत्व में, इस योजना ने कृषि के बजाय भारी और बुनियादी उद्योगों के तीव्र विकास को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक कायाकल्प करना था ताकि इस्पात, बिजली और मशीनरी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। योजनाकारों को विश्वास था कि यह 'बड़ा धक्का' भारत को गरीबी के चक्र से बाहर निकालकर एक आधुनिक औद्योगिक शक्ति के रूप में स्थापित करेगा।

135. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
स्वतंत्र भारत की आरंभिक नीतियों में 'आत्मनिर्भरता' एक प्रमुख स्तंभ थी, जिसका अर्थ था कि देश को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने देशी उद्योगों को संरक्षण दिया और आयात पर भारी कर लगाए। इसका उद्देश्य बाहरी प्रतिस्पर्धा को रोककर स्थानीय कारखानों को विकसित होने का अवसर देना था। इस संरक्षणवादी नीति ने आत्मनिर्भरता के विज़न को व्यावहारिक रूप दिया, जिससे घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को मज़बूती मिली।

136. (A) राज्यों के बीच खाद्यान्न व्यापार पर प्रतिबंध, जिससे कुछ क्षेत्रों में कमी बढ़ी
1960 के दशक के मध्य में, जब भारत भीषण खाद्य संकट का सामना कर रहा था, तब सरकार ने 'ज़ोनिंग' या 'इलाका बंदी' की नीति अपनाई। इस नीति ने राज्यों के बीच खाद्यान्न के मुक्त व्यापार पर रोक लगा दी। इसका नकारात्मक प्रभाव यह हुआ कि जिन राज्यों में अनाज की कमी थी (जैसे बिहार), वहाँ अनाज का प्रवाह रुक गया और संकट और अधिक गहरा गया। यह नीति वितरण प्रणाली की विफलताओं का एक उदाहरण बन गई, जिसने अकाल जैसी स्थितियों को और गंभीर बना दिया।

137. (C) वर्गीज कुरियन
वर्गीज कुरियन को भारत की 'श्वेत क्रांति' का जनक माना जाता है। उन्होंने गुजरात के आनंद में अमूल (AMUL) सहकारी डेयरी मॉडल की स्थापना की, जिसने दूध उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए। यह मॉडल किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें बिचौलियों के शोषण से बचाने पर आधारित था। कुरियन के नेतृत्व में सहकारी डेयरी अभियान ने न केवल भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाया, बल्कि ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण का एक सफल और प्रेरक उदाहरण भी पेश किया।

138. (B) केवल 1, 4 और 5
आज़ादी के समय विकास के मार्ग को लेकर नीति-निर्माण में कई गंभीर मतभेद थे। सबसे मुख्य बहस यह थी कि प्राथमिकता कृषि को दी जाए या उद्योगों को। साथ ही, ग्रामीण गरीबी दूर करने के प्रभावी तरीकों और निजी निवेश की सीमा पर भी विचार-विमर्श हुआ। यद्यपि सरकार की भूमिका पर आम सहमति थी, लेकिन विकास के लिए लोकतंत्र की अनिवार्यता पर उस समय कोई बड़ा मतभेद नहीं था क्योंकि सभी प्रमुख नेता लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। अतः ये सभी आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं के इर्द-गिर्द के विवाद थे।

139. (D) महामंदी के कड़वे अनुभवों और सोवियत प्रगति द्वारा राज्य की भूमिका की पुष्टि
1950 के दशक में नियोजन के विचार को वैश्विक समर्थन मिलने के पीछे ठोस ऐतिहासिक कारण थे। 1930 की 'महामंदी' ने मुक्त बाज़ार की सीमाओं को उजागर कर दिया था, जबकि सोवियत संघ ने राज्य के नेतृत्व में नियोजन के माध्यम से शानदार औद्योगिक विकास करके पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। इन अनुभवों ने यह सिद्ध कर दिया था कि आर्थिक स्थिरता और सामाजिक न्याय के लिए राज्य द्वारा संसाधनों का पूर्व-नियोजित प्रबंधन आवश्यक है। इसी वैश्विक माहौल ने भारत में भी नियोजन को एक सर्वमान्य विकल्प बनाया।

140. (B) भारी उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता
भारी उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना पहली पंचवर्षीय योजना का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह दूसरी योजना की मुख्य विशेषता थी। पहली योजना मुख्य रूप से 'धीमी चाल' की रणनीति पर आधारित थी, जिसमें कृषि, सिंचाई और भूमि सुधारों पर सर्वाधिक बल दिया गया था। योजनाकारों ने उस समय महसूस किया कि देश का बुनियादी कृषि ढाँचा मज़बूत करना अधिक ज़रूरी है। तीव्र औद्योगीकरण की दिशा में बड़ा कदम बाद में उठाया गया, जब पहली योजना ने खाद्य सुरक्षा की कुछ हद तक आधारभूमि तैयार कर दी थी।

141. (C) नव लोकतांत्रिक पहल
केरल में 1980 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू किए गए व्यापक साक्षरता अभियान 'नव लोकतांत्रिक पहल' का हिस्सा थे।

160. (A) निजी क्षेत्र के पास भारी उद्योगों में निवेश करने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं थे।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र को इसलिए अग्रणी भूमिका दी गई क्योंकि निजी क्षेत्र के पास भारी और बुनियादी उद्योगों में निवेश के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों का अभाव था। इस्पात और भारी मशीनरी जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश और अधिक जोखिम था, जिसे केवल सरकार ही उठा सकती थी। इस नीति का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के नेतृत्व में औद्योगिक विकास को गति देना था।

161. (D) सामाजिक न्याय स्थापित करना और कृषि उत्पादकता बढ़ाना।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में भूमि सुधारों को लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक न्याय स्थापित करना और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना था। औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि व्यवस्था सामंती और शोषक हो गई थी। इन सुधारों के माध्यम से किसानों को शोषण से मुक्त करना और भूमि के न्यायसंगत वितरण द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक व्यापक और महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा गया था।

162. (B) ज़मींदारी और जागीरदारी जैसी शोषक प्रणालियों को समाप्त करना।
भूमि सुधारों के अंतर्गत बिचौलियों के उन्मूलन का मुख्य तात्पर्य ज़मींदारी और जागीरदारी जैसी पुरानी और शोषक प्रणालियों को समाप्त करना था। ये बिचौलिये किसानों से भारी लगान वसूलते थे लेकिन कृषि के सुधार में कोई योगदान नहीं देते थे। इनके हटने से किसानों का राज्य के साथ सीधा संपर्क स्थापित हुआ और उन्हें सदियों पुरानी शोषणकारी कर व्यवस्था और अन्यायपूर्ण नियंत्रण से मुक्ति मिली।

163. (C) बिचौलियों का उन्मूलन
भारत में किए गए विभिन्न भूमि सुधारों में से बिचौलियों का उन्मूलन सबसे अधिक सफल रहा। इस कानून के माध्यम से ज़मींदारी प्रथा को काफी हद तक समाप्त कर दिया गया, जिससे करोड़ों काश्तकारों का राज्य के साथ सीधा संबंध जुड़ा। यद्यपि अन्य सुधार जैसे भूमि हदबंदी और काश्तकारी सुधार कानूनी खामियों के कारण पूरी तरह सफल नहीं हुए, लेकिन बिचौलियों को हटाने में बड़ी सफलता प्राप्त हुई थी।

164. (D) शक्तिशाली भू-स्वामियों के राजनीतिक प्रतिरोध और कानूनी खामियों के कारण।
भूमि हदबंदी और काश्तकारी सुधार कानूनों की विफलता का मुख्य कारण शक्तिशाली भू-स्वामियों का राजनीतिक प्रतिरोध और कानूनों में मौजूद तकनीकी खामियां थीं। बड़े ज़मींदारों ने कानूनी दांव-पेंचों का सहारा लेकर अपनी भूमि को बचाने के रास्ते निकाल लिए। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक स्तर पर इच्छाशक्ति की कमी और कानूनी जटिलताओं के कारण इन सुधारों का लाभ वास्तविक भूमिहीन किसानों और श्रमिकों तक नहीं पहुँच सका।

165. (A) भूमि स्वामित्व की अधिकतम सीमा तय करके अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों में वितरित करना।
भूमि की हदबंदी नीति का मुख्य लक्ष्य एक परिवार द्वारा रखी जा सकने वाली कृषि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करना था। इस सीमा से अधिक उपलब्ध भूमि को सरकार द्वारा अधिग्रहित करके भूमिहीन श्रमिकों और गरीब किसानों के बीच वितरित किया जाना था। इस नीति का उद्देश्य ग्रामीण समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता को कम करना और भूमि का न्यायसंगत और संतुलित पुनर्वितरण सुनिश्चित करना था।

166. (B) एक गंभीर खाद्य संकट और मानसून की विफलता।
1960 के दशक के मध्य में भारत को लगातार दो मानसून की विफलता के कारण एक अत्यंत गंभीर खाद्य संकट का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही पूर्ववर्ती योजनाओं में भारी उद्योगों पर अधिक ध्यान देने से कृषि क्षेत्र में ठहराव आ गया था। इस संकटपूर्ण स्थिति ने सरकार को अपनी कृषि रणनीति बदलने और देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'हरित क्रांति' अपनाने के लिए प्रेरित किया।

167. (A) इसने संस्थागत सुधारों के बजाय प्रौद्योगिकी-गहन दृष्टिकोण पर जोर दिया।
हरित क्रांति की रणनीति पिछली कृषि नीतियों से इस मायने में भिन्न थी कि इसने पारंपरिक संस्थागत सुधारों या भूमि सुधारों के बजाय प्रौद्योगिकी-गहन दृष्टिकोण पर जोर दिया। इस नई नीति के तहत उच्च उपज वाले बीजों और रासायनिक उर्वरकों के एकीकृत उपयोग को प्राथमिकता दी गई। यह रणनीति मुख्य रूप से आधुनिक तकनीकी इनपुट के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन में तत्काल और व्यापक वृद्धि करने पर केंद्रित थी।

168. (C) उच्च उपज वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, और सुनिश्चित सिंचाई।
हरित क्रांति पैकेज के मुख्य घटकों में उच्च उपज वाले बीजों (HYV), रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और सुनिश्चित सिंचाई सुविधाओं का समावेश था। इन सभी तत्वों के एकीकृत और वैज्ञानिक प्रयोग से ही कृषि उत्पादकता में अभूतपूर्व वृद्धि संभव हो सकी। यह एक संसाधन-केंद्रित कार्यक्रम था, जिसने मुख्य रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ाने में क्रांतिकारी भूमिका निभाई और देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की।

169. (D) सीमित संसाधनों के कारण और उन क्षेत्रों में सफलता की अधिक संभावना के चलते जहाँ बेहतर सिंचाई थी।
सरकार ने प्रारंभ में हरित क्रांति को पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे चुनिंदा क्षेत्रों में ही केंद्रित किया क्योंकि वहां सिंचाई की बेहतर सुविधाएं पहले से उपलब्ध थीं। सीमित संसाधनों के कारण यह निर्णय लिया गया था कि निवेश उन क्षेत्रों में किया जाए जहां सफलता की संभावना सबसे अधिक हो। इससे कम समय में देश को खाद्य सुरक्षा और अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई।

170. (C) इसने क्षेत्रीय और ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को बढ़ाया।
हरित क्रांति का एक प्रमुख सामाजिक-आर्थिक परिणाम यह रहा कि इसने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और ग्रामीण वर्गों के बीच असमानताओं को काफी बढ़ा दिया। सिंचित और असिंचित क्षेत्रों के बीच विकास की खाई चौड़ी हो गई क्योंकि इसका लाभ केवल संपन्न किसानों को ही मिला। जो किसान महंगे बीज और उर्वरक खरीदने में सक्षम थे, वे आर्थिक रूप से आगे बढ़ गए, जबकि छोटे किसान पिछड़ गए।

171. (C) यह प्रदर्शित करता है कि उच्च सामाजिक विकास निम्न प्रति व्यक्ति आय के साथ भी संभव है।
केरल मॉडल विकास के पारंपरिक राष्ट्रीय मॉडल को इस आधार पर चुनौती देता है कि उच्च सामाजिक विकास केवल उच्च प्रति व्यक्ति आय पर ही निर्भर नहीं है। केरल ने अपेक्षाकृत कम आय के बावजूद स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में असाधारण प्रगति की है। यह मॉडल सिद्ध करता है कि यदि राज्य सही दिशा में निवेश करे, तो सीमित आर्थिक संसाधनों के साथ भी बेहतर जीवन स्तर प्राप्त किया जा सकता है।

172. (B) शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सार्वजनिक सेवाओं में राज्य द्वारा निरंतर निवेश।
केरल की उच्च सामाजिक विकास दर का मुख्य श्रेय शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं में राज्य सरकार द्वारा किए गए निरंतर और व्यापक निवेश को दिया जाता है। राज्य ने अपनी विकास नीतियों में मानव कल्याण और विकास को प्राथमिकता दी है। इस निरंतर सरकारी सहयोग के कारण केरल साक्षरता दर और स्वास्थ्य संकेतकों के मामले में देश के अन्य राज्यों से काफी आगे निकल गया है।

173. (D) इसने स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की और सेवाओं के प्रभावी वितरण में मदद की।
केरल मॉडल में विकेंद्रीकृत योजना ने विकास कार्यों में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस व्यवस्था के माध्यम से शासन की शक्तियों का हस्तांतरण निचले स्तर तक किया गया, जिससे सरकारी सेवाओं का वितरण अधिक प्रभावी और पारदर्शी हो सका। स्थानीय लोगों की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाने से जमीनी स्तर पर व्यापक सकारात्मक परिवर्तन संभव हो सके।

174. (A) प्रभावी भूमि सुधार और एक मजबूत सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
केरल के प्रगतिशील सामाजिक-राजनीतिक वातावरण के परिणामस्वरूप राज्य में प्रभावी भूमि सुधार और एक अत्यंत मजबूत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) सफलतापूर्वक लागू की गई। इन नीतियों ने न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि समाज के वंचित वर्गों को आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान की। सामाजिक आंदोलनों और राजनीतिक चेतना ने सरकार को जन-कल्याणकारी नीतियों को प्राथमिकता देने और उन्हें ग्रामीण स्तर पर लागू करने के लिए प्रेरित किया।

175. (C) यह आर्थिक विकास के बजाय मानव कल्याण और क्षमताओं के विस्तार पर जोर देता है।
केरल मॉडल विकास की अवधारणा को आर्थिक सकल उत्पादन या केवल आय के आंकड़ों से हटाकर मानव कल्याण और क्षमताओं के विस्तार के रूप में पुनः परिभाषित करता है। यह दृष्टिकोण मानता है कि वास्तविक विकास का पैमाना नागरिकों का बेहतर स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उच्च जीवन स्तर होना चाहिए। यह मॉडल शुद्ध आर्थिक विकास के बजाय सामाजिक सशक्तिकरण और मानव विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करता है।

अध्याय 11

भारत के विदेश संबंध

1. स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा अपनाई गई विदेश नीति में किन सरोकारों की झलक मिलती है?
(A) केवल आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना
(B) वैश्विक और घरेलू दोनों सरोकारों का मिश्रण
(C) केवल वैश्विक सैन्य गठबंधनों में शामिल होना
(D) केवल पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाना

2. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे' के लिए राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है?
(A) अनुच्छेद 51
(B) अनुच्छेद 44
(C) अनुच्छेद 32
(D) अनुच्छेद 60

3. निम्नलिखित सूचना के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (घटना)
P. एशियाई संबंध सम्मेलन
Q. बांडुंग सम्मेलन
R. गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन
S. चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा
सूची II: (वर्ष)
1. 1955
2. 1950
3. 1947
4. 1961
(A) P-3, Q-1, R-4, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-3, R-2, S-1
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

4. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन 1: भारत बड़ी विकट और चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था।
कथन 2: स्वतंत्रता के समय, दुनिया महायुद्ध की तबाही से बाहर निकल रही थी और पुनर्निर्माण का सवाल प्रमुख था।
(A) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं।
(B) कथन 1 सत्य है, लेकिन कथन 2 असत्य है।
(C) कथन 1 असत्य है, लेकिन कथन 2 सत्य है।
(D) कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं।

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना।
2. क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना।
3. तेज़ रफ़्तार से आर्थिक विकास करना।
4. अमरीकी खेमे में शामिल होकर सैन्य शक्ति बढ़ाना।
5. सोवियत संघ के साथ एक स्थायी सैन्य गठबंधन बनाना।
नेहरु की विदेश नीति के तीन प्रमुख उद्देश्य क्या थे?
(A) केवल 1, 2 और 4
(B) केवल 2, 3 और 5
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) केवल 1, 4 और 5

6. 1946 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में किसने देश की विदेश नीति की रचना और क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव डाला?
(A) सरदार वल्लभभाई पटेल
(B) जवाहरलाल नेहरु
(C) डॉ. भीमराव अंबेडकर
(D) लालबहादुर शास्त्री

7. भारत की विदेश नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
(A) भारत ने शीतयुद्ध के समय स्वतंत्र गुटनिरपेक्षता की नीति का सक्रिय रूप से पालन किया।
(B) भारत ने दोनों महाशक्तियों के बीच शीतयुद्ध से उपजे वैश्विक तनाव को कम करने की कोशिश की।
(C) भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न शांति-अभियानों में नियमित रूप से अपनी सेना भेजी।
(D) भारत ने सोवियत संघ के 'वारसा पैक्ट' सैन्य गठबंधन में शामिल होना स्वीकार किया।

8. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): 1950 के दशक में भारत-अमरीकी संबंधों में खटास पैदा हो गई।
कारण (R): पाकिस्तान अमरीकी नेतृत्व वाले सैन्य-गठबंधन में शामिल हो गया था और अमरीका सोवियत संघ से भारत की बढ़ती दोस्ती को लेकर भी नाराज़ था।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

9. भारत ने इंडोनेशिया की स्वतंत्रता के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब आयोजित किया था?
(A) 1947
(B) 1955
(C) 1949
(D) 1961

10. निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. चीन द्वारा तिब्बत पर कब्ज़ा
2. पंचशील की घोषणा
3. भारत द्वारा दलाई लामा को शरण देना
4. भारत-चीन सीमा युद्ध
(A) 1, 2, 3, 4
(B) 2, 1, 4, 3
(C) 1, 3, 2, 4
(D) 3, 1, 2, 4

11. एफ्रो-एशियाई सम्मेलन 1955 में किस इंडोनेशियाई शहर में हुआ था, जिसे बांडुंग-सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है?
(A) जकार्ता
(B) सुराबाया
(C) मेदान
(D) बांडुंग

12. पंचशील की घोषणा पर भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के किस प्रमुख ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए थे?
(A) माओत्से तुंग
(B) चाऊ एन लाई
(C) डेंग शियाओपिंग
(D) शी जिनपिंग

13. भारत और चीन के संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. 1949 की चीनी क्रांति के बाद, भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था।
2. सरदार वल्लभभाई पटेल को आशंका थी कि चीन भारत पर चढ़ाई कर सकता है।
3. पंचशील की घोषणा 29 अप्रैल, 1954 को हुई थी।
4. 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्ज़ा कर लिया।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2, 3 और 4
(C) केवल 1 और 4
(D) 1, 2, 3 और 4 सभी

14. तिब्बत के किस पारंपरिक और धार्मिक नेता ने 1959 में सीमा पारकर भारत से शरण माँगी थी?
(A) पंचेन लामा
(B) करमापा
(C) शाक्य त्रिज़िन
(D) दलाई लामा

15. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन 1: 1956 में जब ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया, तो भारत ने इस नव-औपनिवेशिक हमले के विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध की अगुवाई की।
कथन 2: उसी वर्ष (1956 में) जब सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया, तो भारत ने भी सार्वजनिक रूप से इसकी कड़ी निंदा की।
(A) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं।
(B) कथन 1 सत्य है, लेकिन कथन 2 असत्य है।
(C) कथन 1 असत्य है, लेकिन कथन 2 सत्य है।
(D) कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं।

16. 1962 में चीन ने भारत के किन दो क्षेत्रों पर अपने अधिकार का दावा करते हुए आक्रमण किया था?
(A) उत्तर-पूर्वी सीमा पर स्थित सिक्किम और हिमालयी राज्य भूटान के विवादित क्षेत्र।
(B) लद्दाख का अक्साई-चीन क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश का नेफा क्षेत्र।
(C) उत्तराखंड के नीलांग सीमावर्ती क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र।
(D) भूटान सीमा पर स्थित डोकलाम क्षेत्र और सिक्किम स्थित नाकु ला का सीमा क्षेत्र।

17. निम्नलिखित सूचना के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (व्यक्ति)
P. जवाहरलाल नेहरू
Q. वी. के. कृष्णमेनन
R. दलाई लामा
S. चाऊ एन लाई
सूची II: (भूमिका/पद)
1. तिब्बत के धार्मिक नेता
2. चीन के प्रधानमंत्री
3. भारत के पहले प्रधानमंत्री
4. 1962 युद्ध के समय भारत के रक्षामंत्री
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

18. 1962 के चीन-युद्ध के बाद किस भारतीय राजनेता को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था?
(A) वी. के. कृष्णमेनन
(B) जवाहरलाल नेहरू
(C) सरदार पटेल
(D) मोरारजी देसाई

19. 1962 के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

(A) चीन ने एकतरफा युद्धविराम घोषित किया।
(B) इस युद्ध से भारत की छवि को देश और विदेश दोनों जगह धक्का लगा।
(C) संकट की घड़ी में सोवियत संघ ने खुलकर भारत का समर्थन किया।
(D) नेहरु सरकार के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया।

20. 1962 के भारत-चीन संघर्ष के परिणामस्वरूप किस भारतीय राजनीतिक दल में विभाजन हुआ?
(A) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
(B) भारतीय जनसंघ
(C) सोशलिस्ट पार्टी
(D) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा)

21. 1962 के भारत-चीन युद्ध के प्रभावों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट पहुँची।
2. भारत को अमेरिका और ब्रिटेन से सैन्य मदद की गुहार लगानी पड़ी।
3. नेहरु की छवि धूमिल हुई और उनकी आलोचना हुई।
4. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हो गया।
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रति भारत सरकार अधिक सचेत हुई।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 3, 4 और 5
(C) केवल 1, 4 और 5
(D) 1, 2, 3, 4 और 5 सभी

22. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) से टूटकर बने चीन के पक्षधर खेमे ने किस नई पार्टी का गठन किया?
(A) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (लेनिनवादी)
(B) मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सी.पी.आई.एम.)
(C) रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी
(D) फॉरवर्ड ब्लॉक

23. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): 1962 के चीन युद्ध के बाद, भारत सरकार ने पूर्वोत्तर के इलाके को नई तरतीब में ढालने की कोशिशें शुरु कीं।
कारण (R): चीन युद्ध ने भारत के नेताओं को पूर्वोत्तर की डावाँडोल स्थिति के प्रति सचेत किया था, जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए एक चुनौती थी।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

24. भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे?
(A) 1960
(B) 1948
(C) 1965
(D) 1972

25. भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध के बाद, 1966 में ताशकंद-समझौता किसकी मध्यस्थता से हुआ था?
(A) संयुक्त राज्य अमरीका
(B) संयुक्त राष्ट्र संघ
(C) सोवियत संघ
(D) ब्रिटेन

26. निम्नलिखित में से कौन 1966 में हुए ताशकंद-समझौते के हस्ताक्षरकर्ता थे?
(A) लालबहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान
(B) जवाहरलाल नेहरु और जनरल अयूब खान
(C) इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो
(D) लालबहादुर शास्त्री और याह्या खान

27. 1971 के बांग्लादेश युद्ध से पहले, पूर्वी पाकिस्तान में किस राजनीतिक दल ने भारी जीत हासिल की थी?
(A) पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी
(B) मुस्लिम लीग
(C) जमात-ए-इस्लामी
(D) अवामी लीग

28. 1971 में भारत ने किस देश के साथ 20-वर्षीय 'शांति और मित्रता की संधि' पर हस्ताक्षर किए?
(A) संयुक्त राज्य अमरीका
(B) सोवियत संघ
(C) चीन
(D) फ्रांस

29. 1971 के युद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. युद्ध का मुख्य कारण पूर्वी पाकिस्तान का संकट था।
2. भारत को लगभग 80 लाख शरणार्थियों का बोझ वहन करना पड़ा।
3. अमेरिका और चीन ने इस संकट में पाकिस्तान का समर्थन किया।
4. युद्ध के परिणामस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 4
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1, 2 और 4
(D) 1, 2, 3 और 4 सभी

30. 1971 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 3 जुलाई 1972 को किस समझौते पर हस्ताक्षर हुए?

150. (B) 1956-1961
दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक था। पहली योजना की कृषि संबंधी सफलता के बाद, इस योजना ने देश को तीव्र औद्योगीकरण की दिशा में मोड़ा। महालनोबिस मॉडल के तहत, इन पाँच वर्षों के दौरान भारत ने भारी और बुनियादी उद्योगों, जैसे इस्पात संयंत्रों और मशीनरी निर्माण में अभूतपूर्व निवेश किया। यह योजना भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उत्पादन के ढाँचे में तेज़ संरचनात्मक बदलाव लाने की एक महत्वाकांक्षी कोशिश थी, जिसने आधुनिक भारतीय उद्योग की नींव रखी।

151. (B) उन्होंने महसूस किया कि निजी क्षेत्र के पास भारी निवेश के लिए आवश्यक पूंजी और क्षमता का अभाव था।
बॉम्बे प्लान (1944) आठ प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों द्वारा तैयार किया गया एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रस्ताव था। इस योजना के पीछे मुख्य तर्क यह था कि स्वतंत्रता के बाद निजी क्षेत्र के पास भारी उद्योगों और बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए आवश्यक विशाल पूंजी और जोखिम उठाने की क्षमता नहीं थी। इसलिए, उन्होंने राज्य द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया।

152. (A) सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का सह-अस्तित्व, जिसमें राज्य की एक प्रमुख विकासात्मक भूमिका हो।
बॉम्बे प्लान में प्रस्तावित मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल का तात्पर्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के सक्रिय सह-अस्तित्व से था। इस मॉडल के अनुसार, राज्य को बिजली, इस्पात और परिवहन जैसे मुख्य क्षेत्रों में निवेश करके एक सक्षम वातावरण बनाना था। यह सार्वजनिक निवेश निजी उद्योगों के विकास के लिए आधार प्रदान करता, जिससे देश का संतुलित और तीव्र औद्योगिक विकास सुनिश्चित हो सके।

153. (C) घरेलू उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से बचाने और उन्हें विकसित होने का अवसर देने के लिए।
उद्योगपतियों ने राज्य से संरक्षणवादी व्यापार नीतियों की मांग की थी ताकि नवजात घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से प्रभावी ढंग से बचाया जा सके। आयात पर उच्च शुल्क और अन्य व्यापारिक प्रतिबंधों के माध्यम से भारतीय उद्योगों को विकसित होने के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्राप्त होता। यह रणनीति राष्ट्रीय आर्थिक संप्रभुता को मजबूत करने और स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक थी।

154. (D) खुदरा व्यापार और उपभोक्ता वस्तुएं
बॉम्बे प्लान के अनुसार, राज्य के निवेश के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बिजली, इस्पात और परिवहन जैसे बुनियादी ढांचे और भारी उद्योग शामिल थे। इन क्षेत्रों में बहुत बड़े निवेश की आवश्यकता थी जिसे निजी क्षेत्र अकेले पूरा नहीं कर सकता था। इसके विपरीत, खुदरा व्यापार और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन को राज्य के प्रत्यक्ष निवेश के लिए प्राथमिक सूची में नहीं रखा गया था।

155. (C) राज्य-सहायता प्राप्त पूंजीवाद के एक व्यावहारिक खाके के रूप में।
बॉम्बे प्लान को समाजवाद के बजाय व्यावहारिक और राज्य-सहायता प्राप्त पूंजीवाद के एक खाके के रूप में वर्णित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के हस्तक्षेप के माध्यम से तीव्र औद्योगीकरण सुनिश्चित करना और आर्थिक हितों की रक्षा करना था। यह योजना उद्योगपतियों की दूरदर्शिता दर्शाती है, जिन्होंने विकास के प्रारंभिक चरणों में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका को आवश्यक माना और स्वीकार किया था।

156. (B) पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का निर्माण करके दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया महालनोबिस मॉडल दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य पर केंद्रित था। इस मॉडल का मुख्य तर्क यह था कि आर्थिक विकास की दर बढ़ाने के लिए निवेश का बड़ा हिस्सा उपभोक्ता वस्तुओं के बजाय पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में लगाया जाना चाहिए। इससे भविष्य में विदेशी आयात पर निर्भरता कम होती और देश मशीनों के निर्माण में पूरी तरह सक्षम बनता।

157. (D) उन वस्तुओं का घरेलू स्तर पर उत्पादन करना जो पहले विदेश से आयात की जाती थीं।
आयात प्रतिस्थापन औद्योगीकरण एक ऐसी रणनीति है जिसके तहत उन वस्तुओं का घरेलू स्तर पर उत्पादन किया जाता है जो पहले विदेशों से आयात की जाती थीं। इसका मुख्य लक्ष्य विदेशी मुद्रा की बचत करना और देश के भीतर औद्योगिक क्षमता को मजबूत करना था। इस प्रक्रिया के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर बनाने और आवश्यक मशीनों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर निर्भरता कम करने का प्रयास किया गया।

158. (A) भारी और पूंजीगत वस्तु उद्योग।
महालनोबिस मॉडल ने भारी और पूंजीगत वस्तु उद्योगों, जैसे इस्पात और भारी इंजीनियरिंग, को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। प्रशांत चंद्र महालनोबिस का मानना था कि इन क्षेत्रों में निवेश करने से देश की औद्योगिक नींव मजबूत होगी। यद्यपि इससे प्रारंभ में उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होने की संभावना थी, लेकिन यह रणनीति भविष्य के तीव्र और आत्मनिर्भर आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक मानी गई थी।

159. (C) कृषि क्षेत्र की संभावित उपेक्षा और मुद्रास्फीति का दबाव।
महालनोबिस मॉडल के कार्यान्वयन से भारत में औद्योगिक आधार तो मजबूत हुआ, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी सामने आए। भारी उद्योगों पर अत्यधिक ध्यान देने के कारण कृषि क्षेत्र की उपेक्षा हुई, जिससे देश में खाद्य सुरक्षा की समस्या उत्पन्न हुई। इसके साथ ही, उपभोक्ता वस्तुओं के कम उत्पादन के कारण मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ गया, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ गया था।

(A) आयात को कम करने पर जोर
(B) निर्यात को अधिकतम करना
(C) विदेशी निवेश को पूर्णतः प्रतिबंधित करना
(D) मुक्त व्यापार नीति अपनाना

41. निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. ताशकंद समझौता
2. शिमला समझौता
3. भारत-सोवियत मैत्री संधि
4. भारत का पहला परमाणु परीक्षण

(A) 1, 3, 2, 4
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 3, 1, 4, 2
(D) 2, 4, 1, 3

42. 1977 में बनी जनता पार्टी की सरकार ने अपनी विदेश नीति के बारे में क्या घोषणा की?
(A) सच्ची गुटनिरपेक्ष नीति का पालन
(B) सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ गठबंधन
(C) अमरीका समर्थक नीति
(D) चीन के साथ सैन्य समझौता

43. भारत की परमाणु नीति के संबंध में 'पहले प्रयोग नहीं' (No First Use) की नीति का क्या अर्थ है?
(A) भारत परमाणु हथियारों के पूर्ण निशस्त्रीकरण हेतु कभी इनका निर्माण नहीं करेगा।
(B) भारत केवल उन गैर-परमाणु देशों के खिलाफ ही इन हथियारों का उपयोग सुनिश्चित करेगा।
(C) भारत ने अपनी परमाणु सुरक्षा को देखते हुए अब इस पुरानी नीति को त्याग दिया है।
(D) भारत परमाणु हथियारों का प्रयोग केवल आत्मरक्षा में करेगा, लेकिन पहल नहीं करेगा।

44. 1962 के युद्ध के तुरंत बाद, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिहाज से किस क्षेत्र को नयी तरतीब में ढालने की कोशिशें शुरू की गईं?
(A) पंजाब
(B) पूर्वोत्तर
(C) जम्मू और कश्मीर
(D) दक्षिण भारत

45. भारत की विदेश नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. शीतयुद्ध के दौर में भारत ने सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमरीका, दोनों से सहायता हासिल की।
2. भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध शुरुआत से ही तनावपूर्ण रहे हैं।
3. 1971 की शांति और मैत्री की संधि भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच निकटता का परिणाम थी।
4. पंचशील समझौते का उद्देश्य भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देना था।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1 और 4
(C) केवल 2, 3 और 4
(D) केवल 1, 2 और 4

46. 'हकीकत' (1964) फिल्म की पृष्ठभूमि क्या है?
(A) 1947 का विभाजन
(B) 1965 का भारत-पाक युद्ध
(C) 1971 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम
(D) 1962 का भारत-चीन आक्रमण

47. शीतयुद्ध के दौरान, संयुक्त राज्य अमरीका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन का क्या नाम था?
(A) नाटो (NATO)
(B) वारसा पैक्ट
(C) सीटो (SEATO)
(D) सेंटो (CENTO)

48. निम्नलिखित सूचना के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (संधि/समझौता)
P. पंचशील
Q. सिंधु नदी जल संधि
R. ताशकंद समझौता
S. शिमला समझौता

सूची II: (संबंधित देश)
1. भारत-पाकिस्तान (विश्व बैंक की मध्यस्थता)
2. भारत-चीन
3. भारत-पाकिस्तान (सोवियत मध्यस्थता)
4. भारत-पाकिस्तान (द्विपक्षीय)

(A) P-2, Q-1, R-3, S-4
(B) P-1, Q-2, R-4, S-3
(C) P-2, Q-3, R-1, S-4
(D) P-4, Q-1, R-3, S-2

49. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन 1: 1971 के युद्ध में भारत की निर्णायक जीत ने इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को बहुत बढ़ा दिया।
कथन 2: इस युद्ध के बाद हुए विधानसभा चुनावों में अनेक राज्यों में कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत से जीती।
(A) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं।
(B) कथन 1 सत्य है, लेकिन कथन 2 असत्य है।
(C) कथन 1 असत्य है, लेकिन कथन 2 सत्य है।
(D) कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं।

50. भारत द्वारा 'व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि' (CTBT) पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने का मुख्य कारण क्या था?
(A) भारत इसे भेदभावपूर्ण और निशस्त्रीकरण के लक्ष्य से दूर ले जाने वाली संधि मानता था।

कथन 1: भारत के पहले प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री के साथ-साथ विदेश मंत्री भी थे।
कथन 2: विदेश नीति को तैयार करने और उसे लागू करने में नेहरू की कोई विशेष भूमिका नहीं थी।
(A) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं।
(B) कथन 1 सत्य है, लेकिन कथन 2 असत्य है।
(C) कथन 1 असत्य है, लेकिन कथन 2 सत्य है।
(D) कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं।

110. सोवियत संघ के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन 'वारसा पैक्ट' का गठन किसके जवाब में किया गया था?
(A) संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन
(B) गुटनिरपेक्ष आंदोलन के गठन
(C) चीन की बढ़ती शक्ति
(D) नातो (NATO) के गठन

111. 1956 में मिस्र के विरुद्ध ब्रिटेन के आक्रमण का क्या कारण था?
(A) स्वेज नहर का मामला
(B) रंगभेद की नीति
(C) सीमा विवाद
(D) तेल का भंडार

112. भारत के विदेश संबंधों के प्रारंभिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2. एफ्रो-एशियाई एकता स्थापित करने के लिए भारत ने प्रयास किए।
3. भारत ने इंडोनेशिया की स्वतंत्रता का समर्थन किया।
4. भारत ने नस्लवाद और रंगभेद का पुरजोर विरोध किया।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2, 3 और 4
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2, 3 और 4 सभी

113. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने पर भारत सरकार ने शुरू में खुले तौर पर इसका विरोध नहीं किया।
कारण (R): पंचशील समझौते के प्रावधानों में एक-दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करना शामिल था, जिसकी व्याख्या चीन ने तिब्बत पर अपने दावे की स्वीकृति के रूप में की।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

114. नेहरू के कुछ सहयोगियों, जैसे सरदार पटेल, को चीन के बारे में क्या आशंका थी?
(A) चीन भारत पर आक्रमण कर सकता है।
(B) चीन भारत का सबसे अच्छा दोस्त बनेगा।
(C) चीन गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो जाएगा।
(D) चीन भारत के साथ आर्थिक साझेदारी करेगा।

115. भारत-चीन सीमा विवाद में 'अक्साई-चीन' का इलाका किस भारतीय राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश का हिस्सा है?
(A) अरुणाचल प्रदेश
(B) सिक्किम
(C) लद्दाख
(D) हिमाचल प्रदेश

116. 1965 के भारत-पाक युद्ध में भारतीय सेना किस प्रमुख पाकिस्तानी शहर के नजदीक तक पहुँच गई थी?
(A) कराची
(B) इस्लामाबाद
(C) रावलपिंडी
(D) लाहौर

117. 1971 के युद्ध में लगभग कितने पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था?
(A) 50,000
(B) 75,000
(C) 90,000
(D) 1,20,000

118. भारत की परमाणु नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(A) भारत का लक्ष्य एक आक्रामक परमाणु शक्ति बनना है।
(B) भारत वैश्विक स्तर पर लागू और भेदभाव रहित परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है।
(C) भारत ने CTBT पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
(D) भारत की 'पहले प्रयोग नहीं' की कोई नीति नहीं है।

119. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन 1: 1990 के बाद भारत की विदेश नीति में सैन्य हितों के बजाय आर्थिक हितों पर अधिक जोर दिया गया है।
कथन 2: इस बदलाव का कारण रूस के महत्व में कमी और अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में आर्थिक मुद्दों का बढ़ना है।
(A) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं।
(B) कथन 1 सत्य है, लेकिन कथन 2 असत्य है।
(C) कथन 1 असत्य है, लेकिन कथन 2 सत्य है।
(D) कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं।

120. जवाहरलाल नेहरू के बाद बतौर प्रधानमंत्री चीन का दौरा करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे?
(A) अटल बिहारी वाजपेयी

R. क्यूबा मिसाइल संकट
S. अरब-इज़रायल युद्ध
सूची II: (वर्ष)
1. 1962
2. 1973
3. 1956
4. 1956
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-1, Q-2, R-3, S-4

61. स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी सरकार भारत के लिए किस प्रकार की विरासत छोड़ गई थी?
(A) एक मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था
(B) सभी पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध
(C) अंतर्राष्ट्रीय विवादों की एक पूरी विरासत
(D) एक उन्नत औद्योगिक आधार

62. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन 1: विकासशील देशों की विदेश नीति पर अक्सर उनकी आर्थिक और सुरक्षा संबंधी निर्भरताओं का असर पड़ता है।
कथन 2: दूसरे विश्वयुद्ध के बाद अनेक विकासशील देशों ने ताकतवर देशों की मर्जी को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति अपनाई क्योंकि उन्हें उनसे अनुदान अथवा कर्ज मिल रहा था।
(A) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं।
(B) कथन 1 सत्य है, लेकिन कथन 2 असत्य है।
(C) कथन 1 असत्य है, लेकिन कथन 2 सत्य है।
(D) कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं।

63. निम्नलिखित में से कौन-से नेता, भारत को अमरीकी खेमे के साथ ज़्यादा नज़दीकी बढ़ाने के पक्ष में थे?
(A) डॉ. भीमराव अंबेडकर
(B) जवाहरलाल नेहरू
(C) वी. के. कृष्णमेनन
(D) ए. के. गोपालन

64. 1971 के युद्ध के दौरान, अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सलाहकार कौन थे जिन्होंने पाकिस्तान होते हुए गुपचुप चीन का दौरा किया था?
(A) साइरस वेंस
(B) हेनरी किसिंजर
(C) ज़्बिग्निउ ब्रेज़िंस्की
(D) कोंडोलीज़ा राइस

65. भारतीय विदेश नीति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. नेहरू के तीन मुख्य उद्देश्य थे: संप्रभुता की रक्षा, क्षेत्रीय अखंडता और आर्थिक विकास।
2. भारत ने अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई।
3. डॉ. अंबेडकर भारत की विदेश नीति को अमेरिका के पक्ष में बनाने के हिमायती थे।
4. भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी भी साम्यवाद की विरोधी थीं और चाहती थीं कि भारत अमेरिका के पक्ष में रहे।
5. नेहरू को अपनी विदेश नीति को आकार देने में खासी बढ़त हासिल थी।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2, और 3
(B) केवल 2, 4, और 5
(C) केवल 1, 3, और 4
(D) 1, 2, 3, 4 और 5 सभी

66. किस वर्ष के बाद भारत-चीन संबंधों में ज्यादा जोर व्यापारिक मसलों पर रहा है?
(A) 1988 के बाद
(B) 1979 के बाद
(C) 1998 के बाद
(D) 2000 के बाद

67. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): 1990 के बाद के दौर में भारत की विदेश नीति में अमरीका समर्थक रणनीतियाँ अपनाई गई हैं।
कारण (R): 1990 के बाद रूस का अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व कम हो गया और अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में सैन्य-हितों के बजाय आर्थिक हितों का ज़ोर ज़्यादा बढ़ा है।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

68. कारगिल युद्ध (1999) का परिणाम क्या हुआ?
(A) भारत को अपने ठिकाने वापस नहीं मिल सके।
(B) पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र पर स्थायी कब्जा कर लिया।
(C) युद्ध का कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला।
(D) भारत ने अपने अधिकतर ठिकानों पर पुनः अधिकार कर लिया।

69. 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के समक्ष कहाँ आत्मसमर्पण किया था?
(A) लाहौर
(B) कराची
(C) ढाका
(D) इस्लामाबाद

70. निम्नलिखित सूचना के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:

सूची I: (दल/संगठन)
P. नाटो (NATO)
Q. वारसा पैक्ट
R. अवामी लीग
S. सी.पी.आई.एम.
सूची II: (विवरण)
1. सोवियत संघ के नेतृत्व वाला सैन्य गठबंधन
2. अमरीका के नेतृत्व वाला सैन्य गठबंधन
3. भाकपा से अलग हुआ दल
4. शेख मुजीबुर्रहमान का दल
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-1, R-4, S-3
(C) P-2, Q-4, R-1, S-3
(D) P-1, Q-3, R-4, S-2

71. निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य अनुच्छेद 51 में वर्णित भारत के नीति-निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है?
(A) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना
(B) राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना
(C) अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देना
(D) अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर लोकतंत्र स्थापित करना

72. निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें:
1. भारत द्वारा दूसरा परमाणु परीक्षण (पोखरण-II)
2. अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा (विदेश मंत्री के रूप में)
3. राजीव गांधी की चीन यात्रा (प्रधानमंत्री के रूप में)
4. कारगिल युद्ध
(A) 2, 3, 1, 4
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 3, 2, 4, 1
(D) 2, 1, 3, 4

73. निम्नलिखित नेताओं पर विचार करें:
1. जवाहरलाल नेहरू (भारत)
2. गमाल अब्दुल नासिर (मिस्र)
3. जोसिप ब्रोज़ टीटो (यूगोस्लाविया)
4. सुकर्णो (इंडोनेशिया)
5. क्वामे एनक्रूमा (घाना)
गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में किन नेताओं की महती भूमिका रही थी?
(A) केवल 1, 2, और 3
(B) केवल 1, 3, और 5
(C) केवल 2, 4, और 5
(D) 1, 2, 3, 4 और 5 सभी

74. 'इंडियन नेशनल आर्मी' (आई.एन.ए.) का गठन किसने किया था?
(A) नेताजी सुभाषचंद्र बोस
(B) महात्मा गांधी
(C) जवाहरलाल नेहरु
(D) सरदार पटेल

75. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन 1: 1962 के युद्ध के बाद भारत को रक्षा-उत्पाद विभाग और रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना करनी पड़ी।
कथन 2: 1962 के युद्ध से पहले भारत अपनी रक्षा तैयारियों पर बहुत कम ध्यान देता था।
(A) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं।
(B) कथन 1 सत्य है, लेकिन कथन 2 असत्य है।
(C) कथन 1 असत्य है, लेकिन कथन 2 सत्य है।
(D) कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं।

76. भारत और पाकिस्तान के बीच 'बस डिप्लोमेसी' किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरु हुई?
(A) इंदिरा गांधी
(B) अटल बिहारी वाजपेयी
(C) राजीव गांधी
(D) मनमोहन सिंह

77. 1958 में तिब्बत में चीनी आधिपत्य के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का चीन ने क्या किया?
(A) चीन ने विद्रोहियों से बातचीत की।
(B) चीन ने संयुक्त राष्ट्र से मध्यस्थता की अपील की।
(C) चीन की सेनाओं ने विद्रोह को दबा दिया।
(D) चीन ने तिब्बत को स्वतंत्रता दे दी।

78. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): भारत ने हमेशा परमाणु अप्रसार संधियों का विरोध किया है क्योंकि वे भेदभावपूर्ण हैं।
कारण (R): ये संधियाँ केवल परमाणु शक्ति से हीन देशों पर लागू होती हैं और परमाणु हथियारों से लैस देशों के एकाधिकार को वैधता देती हैं।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

79. 'एशियाई संबंध सम्मेलन' (एशियन रिलेशंस कांफ्रेंस) का आयोजन भारत ने कब किया था?
(A) मार्च 1947, आजादी से पांच महीने पहले
(B) अगस्त 1947, आजादी के तुरंत बाद
(C) जनवरी 1950, गणतंत्र बनने के बाद
(D) अप्रैल 1954, पंचशील समझौते के साथ

80. 1965 के भारत-पाक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसकी शुरुआत पाकिस्तान द्वारा गुजरात के कच्छ के रन में सैनिक हमला करने से हुई।
2. पाकिस्तान को उम्मीद थी कि जम्मू-कश्मीर की जनता उसका समर्थन करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
3. लालबहादुर शास्त्री ने पंजाब की सीमा की तरफ से जवाबी हमले का आदेश दिया।
4. युद्ध का अंत संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से हुआ, जिसके बाद ताशकंद समझौता हुआ।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 2 और 4
(C) केवल 1, 3 और 4
(D) 1, 2, 3 और 4 सभी

81. भारत में तिब्बती शरणार्थियों की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक, और दलाई लामा का निवास-स्थान, धर्मशाला किस भारतीय राज्य में स्थित है?

(A) उत्तराखंड
(B) हिमाचल प्रदेश
(C) सिक्किम
(D) अरुणाचल प्रदेश

82. निम्नलिखित सूचना के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:

सूची I: (प्रधानमंत्री)

P. जवाहरलाल नेहरू
Q. लालबहादुर शास्त्री
R. इंदिरा गांधी
S. अटल बिहारी वाजपेयी

सूची II: (संबंधित घटना/नीति)

1. शिमला समझौता
2. कारगिल युद्ध
3. पंचशील
4. ताशकंद समझौता

(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

83. 1971 में, पाकिस्तान से बांग्लादेश (तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान) की मुक्ति के लिए चलाए गए संघर्ष को क्या कहा जाता है?

(A) स्वतंत्रता संग्राम
(B) क्रांति
(C) मुक्ति संग्राम
(D) जन आंदोलन

84. भारत द्वारा 1998 में किए गए परमाणु परीक्षणों का क्या परिणाम हुआ?

(A) अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसका स्वागत किया।
(B) भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिली।
(C) पाकिस्तान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
(D) भारत और पाकिस्तान पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए, जिन्हें बाद में हटा लिया गया।

85. नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन 1: 1950 और 1960 के दशक में भारत की विदेश नीति शांतिपूर्ण रही और वह अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों से बचा रहा।

कथन 2: इस अवधि में भारत को 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ना पड़ा।

(A) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं।
(B) कथन 1 सत्य है, लेकिन कथन 2 असत्य है।
(C) कथन 1 असत्य है, लेकिन कथन 2 सत्य है।
(D) कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं।

86. चीन के साथ सीमा विवाद मुख्य रूप से किन दो छोरों पर है?

(A) उत्तरी और दक्षिणी
(B) पश्चिमी और पूर्वी
(C) मध्य और उत्तरी
(D) पूर्वी और दक्षिणी

87. भारत की विदेश नीति पर 1990 के बाद आए बदलावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. रूस भारत का एक महत्वपूर्ण मित्र बना रहा, लेकिन उसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व कम हो गया।
2. भारत की विदेश नीति में अमेरिका समर्थक रणनीतियाँ अपनाई गईं।
3. विदेश नीति में सैन्य-हितों के बजाय आर्थिक हितों का ज़ोर ज़्यादा हो गया।
4. भारत-पाक संबंधों को सामान्य बनाने के कई प्रयास किए गए, जैसे बस और रेल सेवा।
5. इन सब प्रयासों के बावजूद 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(A) केवल 1, 2, और 3
(B) केवल 2, 4, और 5
(C) केवल 1, 3, और 4
(D) 1, 2, 3, 4 और 5 सभी

88. 1962 के युद्ध में चीन की सेना भारत के किस राज्य के मैदानी हिस्से के प्रवेशद्वार तक पहुँच गई थी?

(A) असम
(B) पश्चिम बंगाल
(C) बिहार
(D) उत्तर प्रदेश

89. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:

अभिकथन (A): 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हो गया।

कारण (R): 1962 के भारत-चीन युद्ध और चीन-सोवियत संघ के बीच बढ़ते मतभेद के कारण पार्टी के भीतर बड़ी उठा-पटक मची।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

90. 1973 में किन राष्ट्रों द्वारा तेल के दामों में भारी वृद्धि करने के कारण भारत सहित पूरे विश्व में आर्थिक समस्याएँ पैदा हुईं?
(A) अरब राष्ट्रों
(B) यूरोपीय राष्ट्रों
(C) लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों
(D) दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों

91. 1962 के बाद, नागालैंड को प्रांत का दर्जा दिया गया, जबकि मणिपुर और त्रिपुरा को क्या दर्जा मिला?
(A) उन्हें भी भारत के अन्य पूर्ण विकसित राज्यों के समान स्वतंत्र प्रांत का दर्जा मिला।
(B) वे प्रशासनिक रूप से लंबे समय तक असम के वृहत भौगोलिक प्रांत का हिस्सा बने रहे।
(C) उन्हें एक नई भौगोलिक इकाई के रूप में संयुक्त उत्तर-पूर्वी राज्य बना दिया गया।
(D) केंद्र-शासित प्रदेश रहते हुए उन्हें अपनी विधानसभा निर्वाचन का विशेष अधिकार मिला।

92. निम्नलिखित सूचना के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (व्यक्ति/दल)
P. जुल्फिकार अली भुट्टो
Q. शेख मुजीबुर्रहमान
R. स्वतंत्र पार्टी
S. वी. के. कृष्णमेनन
सूची II: (विवरण)
1. 1970 में पश्चिमी पाकिस्तान में विजयी दल
2. भारत की अमेरिका-समर्थक विदेश नीति की पक्षधर पार्टी
3. 1957 से भारत के रक्षा मंत्री
4. अवामी लीग के नेता
(A) P-1, Q-4, R-3, S-2
(B) P-4, Q-1, R-2, S-3
(C) P-1, Q-4, R-2, S-3
(D) P-2, Q-3, R-1, S-4

93. किस दशक में अमेरिका और चीन के बीच संबंधों को सामान्य करने की कोशिशों से एशिया में सत्ता-समीकरण में बदलाव आया?
(A) 1950 के दशक में
(B) 1960 के दशक में
(C) 1970 के दशक में
(D) 1980 के दशक में

94. 1971 के युद्ध में भारतीय सेना ने ढाका को कितने दिनों के अंदर तीन तरफ से घेर लिया था, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया?
(A) 30 दिन
(B) 20 दिन
(C) 15 दिन
(D) 10 दिन

95. भारत की विदेश नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत ने अपनी विदेश नीति में अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने का लक्ष्य रखा।
2. शांति कायम करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी एक प्रमुख लक्ष्य था।
3. इन लक्ष्यों की प्रतिध्वनि संविधान के मौलिक अधिकारों में सुनाई देती है।
4. विदेश नीति पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का असर पड़ता है।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 1, 2 और 4
(C) केवल 2, 3 और 4
(D) 1, 2, 3 और 4 सभी

96. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन 1: 1960 के दशक के दौरान, भारत को अपने सीमित संसाधन रक्षा क्षेत्र में लगाने पड़े।
कथन 2: इस अवधि में तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-66) पर असर पड़ा और उसके बाद लगातार तीन एक-वर्षीय योजना पर अमल हुआ।
(A) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं।
(B) कथन 1 सत्य है, लेकिन कथन 2 असत्य है।
(C) कथन 1 असत्य है, लेकिन कथन 2 सत्य है।
(D) कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं।

97. नेहरु के बाद, बतौर प्रधानमंत्री चीन का दौरा करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे?
(A) इंदिरा गांधी
(B) राजीव गांधी
(C) मोरारजी देसाई
(D) अटल बिहारी वाजपेयी

98. 1999 के कारगिल संघर्ष के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे?
(A) नवाज शरीफ
(B) परवेज मुशर्रफ
(C) बेनजीर भुट्टो
(D) जफरुल्लाह खान जमाली

99. भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में हुए छाया-युद्ध का मुख्य मुद्दा क्या था?
(A) नदी जल का बंटवारा
(B) सीमा का निर्धारण
(C) जम्मू-कश्मीर का विलय
(D) शरणार्थी समस्या

100. निम्नलिखित सूचना के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (नेता)
P. लालबहादुर शास्त्री
Q. जनरल अयूब खान
R. ज़ुल्फिकार अली भुट्टो
S. इंदिरा गांधी
सूची II: (समझौता)
1. शिमला समझौता (भारत)
2. ताशकंद समझौता (भारत)
3. शिमला समझौता (पाकिस्तान)
4. ताशकंद समझौता (पाकिस्तान)
(A) P-2, Q-4, R-3, S-1
(B) P-1, Q-2, R-4, S-3
(C) P-4, Q-2, R-1, S-3
(D) P-2, Q-3, R-1, S-4

101. 1971 के युद्ध के बाद इंदिरा गांधी और ज़ुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए?
(A) 16 दिसंबर, 1971
(B) 10 जनवरी, 1966
(C) 3 जुलाई, 1972
(D) 29 अप्रैल, 1954

102. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): 1977 में सत्ता में आई जनता पार्टी सरकार ने सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति में आए झुकाव को खत्म करने की घोषणा की।
कारण (R): जनता पार्टी की सरकार "सच्ची गुटनिरपेक्ष नीति" का पालन करना चाहती थी।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

103. 'गुटनिरपेक्षता' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं होना।
2. चीज़ों को यथासंभव सैन्य दृष्टिकोण से न देखना।
3. स्वतंत्र रूप से स्थिति पर विचार करना।
4. सभी देशों के साथ दोस्ताना रिश्ते कायम करना।
5. दुनिया से अलग-थलग रहना।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2, और 3
(B) केवल 1, 2, 3 और 4
(C) केवल 2, 4 और 5
(D) 1, 2, 3, 4 और 5 सभी

104. शीतयुद्ध के तुरंत बाद के दौर में दुनिया के विभिन्न देश किन दो खेमों में बँट गए थे?
(A) संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ के प्रभाव वाले खेमे
(B) लोकतांत्रिक और साम्यवादी खेमा
(C) विकसित और विकासशील देशों के खेमे
(D) औपनिवेशिक और स्वतंत्र देशों के खेमे

105. 1971 के युद्ध के दौरान, भारत ने बांग्लादेश के 'मुक्ति संग्राम' को किस प्रकार की सहायता प्रदान की?
(A) केवल वित्तीय सहायता
(B) केवल सैन्य सहायता
(C) नैतिक समर्थन और भौतिक सहायता
(D) कोई सहायता नहीं

106. भारत ने 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण क्यों किया?
(A) अणुशक्ति को शांतिपूर्ण उद्देश्यों में इस्तेमाल करने की क्षमता प्रदर्शित करने के लिए
(B) पाकिस्तान पर आक्रमण करने के लिए
(C) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पाने के लिए
(D) चीन को डराने के लिए

107. भारतीय राजनीति में विभिन्न दलों के बीच किन मसलों पर व्यापक सहमति है?
(A) आर्थिक नीतियां
(B) सामाजिक सुधार
(C) गठबंधन सरकार बनाने के तरीके
(D) राष्ट्रीय अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित

108. 1962-1971 के बीच भारत को किन-किन देशों के साथ युद्ध का सामना करना पड़ा?
1. चीन
2. पाकिस्तान
3. नेपाल
4. बर्मा
5. श्रीलंका
निम्नलिखित में से सही संयोजन चुनें:
(A) 1 और 2
(B) 1, 2 और 3
(C) केवल 2
(D) 1, 2 और 5

109. नीचे दो कथन दिए गए हैं:

(B) भारत सरकार का यह मानना था कि यह संधि आर्थिक रूप से देश के लिए बहुत महंगी थी।
(C) भारत इस संधि को अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा का सीधा उल्लंघन मानता था।
(D) सोवियत संघ द्वारा भारत पर इस संधि पर हस्ताक्षर न करने का निरंतर राजनीतिक दबाव था।

51. भारत की विदेश नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को पहचानें।
(A) भारत अनौपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का प्रबल समर्थक था।
(B) भारत ने दक्षिण अफ्रीका में जारी रंगभेद का पूरी दृढ़ता से विरोध किया।
(C) भारत अपनी स्वतंत्रता के बाद चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने में हिचकिचा रहा था।
(D) भारत ने 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया।

52. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): 1962 और 1965 के युद्धों के कारण भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ पटरी से उतर गईं।
कारण (R): युद्धों के कारण भारत को अपने सीमित संसाधन रक्षा क्षेत्र में लगाने पड़े और रक्षा-व्यय बहुत बढ़ गया।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

53. निम्नलिखित में से कौन सा देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देशों में शामिल नहीं था?
(A) भारत
(B) मिस्र
(C) चीन
(D) यूगोस्लाविया

54. 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे?
(A) जवाहरलाल नेहरू
(B) लालबहादुर शास्त्री
(C) इंदिरा गांधी
(D) गुलजारीलाल नंदा

55. निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. चीन में कम्युनिस्ट क्रांति
2. इंडोनेशिया में बांडुंग सम्मेलन
3. स्वेज नहर संकट
4. गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला बेलग्रेड शिखर सम्मेलन

(A) 1, 2, 3, 4
(B) 2, 1, 3, 4
(C) 1, 3, 2, 4
(D) 3, 1, 2, 4

56. 1970 में पाकिस्तान के पहले आम चुनाव के संबंध में क्या परिणाम आया?
(A) खंडित जनादेश आया, जिसमें भुट्टो की पार्टी पश्चिमी पाकिस्तान में और मुजीब की पार्टी पूर्वी पाकिस्तान में जीती।
(B) जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी ने पूरे पाकिस्तान में बहुमत हासिल किया।
(C) मुजीबुर्रहमान की पार्टी ने पूरे पाकिस्तान में बहुमत हासिल किया।
(D) चुनाव रद्द कर दिए गए और कोई परिणाम नहीं आया।

57. भारत की विदेश नीति के संदर्भ में पंचशील के सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है?
(A) एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान
(B) एक दूसरे के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप
(C) किसी एक महाशक्ति के साथ सैन्य गठबंधन
(D) शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व

58. 1962 के चीनी आक्रमण के दौरान, अरुणाचल प्रदेश को किस नाम से जाना था?
(A) नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (नेफा)
(B) ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी
(C) असम फ्रंटियर
(D) ईस्टर्न हिल ट्रैक्स

59. भारत और चीन के संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत ने 1954 में पंचशील समझौते के माध्यम से तिब्बत पर चीन की दावेदारी को स्वीकार कर लिया।
2. दलाई लामा को शरण देना चीन के साथ संबंधों में तनाव का एक प्रमुख कारण बना।
3. 1962 के युद्ध के बाद, दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध 1976 में बहाल हुए।
4. राजीव गांधी, नेहरू के बाद प्रधानमंत्री के रूप में चीन का दौरा करने वाले पहले व्यक्ति थे।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 2 और 4
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2, 3 और 4 सभी

60. निम्नलिखित सूचना के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (युद्ध/संकट)
P. स्वेज नहर संकट
Q. हंगरी पर सोवियत आक्रमण

(B) इंदिरा गांधी
(C) राजीव गांधी
(D) पी. वी. नरसिम्हा राव

121. निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार करें:
1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
2. सोशलिस्ट पार्टी
3. भारतीय जनसंघ
4. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
5. स्वतंत्र पार्टी

निम्नलिखित में से किन राजनीतिक दलों ने 1950 और 1960 के दशक में तिब्बत की आजादी का समर्थन किया था?
(A) 1 और 4
(B) 2 और 3
(C) 2, 3 और 5
(D) 1, 2 और 3

122. भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंध किस वर्ष पूरी तरह से बहाल हुए?
(A) 1976
(B) 1965
(C) 1971
(D) 1980

123. निम्नलिखित सूचना के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (अवधारणा/नीति)
P. गुटनिरपेक्षता
Q. पंचशील
R. रंगभेद का विरोध
S. परमाणु निशस्त्रीकरण
सूची II: (भारत का रुख)
1. भारत की विदेश नीति का आधारशिला
2. दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में मुखर विरोध
3. भारत-चीन संबंधों का प्रारंभिक सिद्धांत
4. वैश्विक मंचों पर भारत की लगातार मांग
(A) P-1, Q-3, R-2, S-4
(B) P-2, Q-1, R-4, S-3
(C) P-1, Q-4, R-2, S-3
(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

124. 1971 के बांग्लादेश संकट के दौरान, भारत को किस प्रमुख मानवीय समस्या का सामना करना पड़ा?
(A) पूर्वी पाकिस्तान में अकाल
(B) 80 लाख शरणार्थियों का भारत में आगमन
(C) हैजा का प्रकोप
(D) पश्चिमी पाकिस्तान से प्रवासन

125. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ 20-वर्षीय मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए।
कारण (R): भारत को एक आश्वासन की आवश्यकता थी क्योंकि अमेरिका-पाकिस्तान-चीन की एक धुरी बन रही थी।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

126. चीन द्वारा 1964 के अक्टूबर में परमाणु परीक्षण करने की घटना का भारत की परमाणु नीति पर क्या प्रभाव पड़ा?
(A) भारत ने तुरंत परमाणु हथियार बना लिए।
(B) भारत ने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से बंद कर दिया।
(C) भारत पर परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने का दबाव बढ़ गया।
(D) इसने भारत के भीतर परमाणु विकल्प को खुला रखने की बहस को बल दिया।

127. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जो नेहरु की विदेश नीति के उद्देश्यों से संबंधित हैं:
1. संप्रभुता को बचाए रखना
2. क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना
3. तीव्र आर्थिक विकास
4. गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाना

उपरोक्त कथनों में से कौन-से नेहरू की विदेश नीति के तीन बड़े उद्देश्य थे?
(A) 1, 2 और 4
(B) 2, 3 और 4
(C) 1, 2 और 3
(D) 1, 3 और 4

128. वी. के. कृष्णमेनन के राजनीतिक करियर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
(A) वे इंग्लैंड में भारतीय उच्चायुक्त रहे।
(B) 1962 के भारत-चीन युद्ध में भारत की जीत के बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ गई।
(C) वे 1957 से भारत के रक्षा मंत्री थे।
(D) वे संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के मुखिया थे।

129. भारत-पाकिस्तान संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. 1947 में कश्मीर को लेकर एक छाया-युद्ध हुआ।
2. 1960 में नेहरु और अयूब खान ने सिंधु नदी जल संधि पर हस्ताक्षर किए।
3. 1965 के युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुआ।
4. 1971 के युद्ध के बाद शिमला समझौता हुआ।
5. 1999 में कारगिल संघर्ष हुआ।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2, 3 और 4

(B) केवल 2, 3, 4 और 5
(C) केवल 1, 3, 4 और 5
(D) 1, 2, 3, 4 और 5 सभी

130. 1971 में भारत द्वारा सोवियत संघ के साथ मैत्री संधि पर हस्ताक्षर करने की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में क्या व्याख्या की गई?
(A) यह माना गया कि भारत सोवियत खेमे में शामिल हो गया है।
(B) भारत ने अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति को बनाए रखा।
(C) इसे अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में सुधार के रूप में देखा गया।
(D) इसे चीन के साथ एक नए गठबंधन की शुरुआत माना गया।

131. भारत में 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद किन देशों पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने प्रतिबंध लगाए थे?
(A) केवल भारत पर
(B) केवल पाकिस्तान पर
(C) भारत और पाकिस्तान दोनों पर
(D) भारत, पाकिस्तान और चीन पर

132. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन 1: 1970 के दशक के मध्य में, भारत में घरेलू राजनीति बड़ी कठिन थी।
कथन 2: 1973 के अरब-इजरायल युद्ध के बाद तेल के दामों में वृद्धि से भारत में मुद्रास्फीति बहुत बढ़ गई थी और देश में कई आंदोलन चल रहे थे।
(A) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं।
(B) कथन 1 सत्य है, लेकिन कथन 2 असत्य है।
(C) कथन 1 असत्य है, लेकिन कथन 2 सत्य है।
(D) कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं।

133. 1962 के चीन युद्ध का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ा?
(A) पार्टी और अधिक मजबूत हो गई।
(B) पार्टी ने सरकार का पूर्ण समर्थन किया।
(C) पार्टी सोवियत और चीन समर्थक गुटों में विभाजित हो गई।
(D) पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया।

134. निम्नलिखित सूचना के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (वर्ष)
P. 1954
Q. 1966
R. 1972
S. 1999
सूची II: (घटना)
1. ताशकंद समझौता
2. कारगिल युद्ध
3. शिमला समझौता
4. पंचशील समझौता
(A) P-4, Q-1, R-3, S-2
(B) P-1, Q-4, R-2, S-3
(C) P-4, Q-3, R-1, S-2
(D) P-2, Q-1, R-3, S-4

135. 'ताकत के तीनों साधनों - संपदा, धन और जन से हीन एक देश अब बड़ी तेज़ी से सभ्य जगत में एक नैतिक ताकत के रूप में पहचान हासिल कर रहा है' - यह कथन किसका है?
(A) जवाहरलाल नेहरू
(B) महात्मा गांधी
(C) डॉ. अंबेडकर
(D) सी. राजगोपालाचारी

136. 1965 के युद्ध में, प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने पाकिस्तानी सेना की बढ़त को रोकने के लिए किस मोर्चे पर जवाबी हमले का आदेश दिया?
(A) पंजाब मोर्चा
(B) गुजरात मोर्चा
(C) राजस्थान मोर्चा
(D) समुद्री मोर्चा

137. 1950 के दशक में, किन दो राजनीतिक दलों ने भारत की विदेश नीति को अमरीका के पक्ष में बनाने की वकालत की?
(A) सोशलिस्ट पार्टी और फॉरवर्ड ब्लॉक
(B) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
(C) भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी
(D) कांग्रेस और किसान मजदूर प्रजा पार्टी

138. भारत-चीन संबंध, 1949-1962, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत ने चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता दी।
2. दोनों देशों ने 1954 में पंचशील पर हस्ताक्षर किए।
3. तिब्बत को लेकर दोनों देशों में मतभेद उभरे।
4. 1962 में दोनों देशों के बीच सीमा युद्ध हुआ।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3 और 4
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) 1, 2, 3 और 4 सभी

139. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ।
कारण (R): मुजाहिदीन के वेश में पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा के कई भारतीय ठिकानों पर कब्जा कर लिया था।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही

व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

140. भारत के विदेश संबंधों के विकास को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें:
1. चीन के साथ पंचशील समझौता
2. सोवियत संघ के साथ 20-वर्षीय मैत्री संधि
3. पाकिस्तान के साथ ताशकंद समझौता
4. पाकिस्तान के साथ शिमला समझौता
(A) 1, 3, 2, 4
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 1, 4, 3
(D) 3, 1, 2, 4

141. गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पहले शिखर सम्मेलन (1961) का आयोजन कहाँ हुआ था?
(A) नई दिल्ली, भारत
(B) काहिरा, मिस्र
(C) बेलग्रेड, यूगोस्लाविया
(D) जकार्ता, इंडोनेशिया

142. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन 1: 1962 के चीन युद्ध से भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट पहुँची लेकिन राष्ट्र-भावना भी बलवती हुई।
कथन 2: इस युद्ध के बाद देश का राजनीतिक मानस बदलने लगा था और कांग्रेस ने कुछ महत्वपूर्ण उप-चुनावों में हार का सामना किया।
(A) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं।
(B) कथन 1 सत्य है, लेकिन कथन 2 असत्य है।
(C) कथन 1 असत्य है, लेकिन कथन 2 सत्य है।
(D) कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं।

143. भारत ने किन दो महाशक्तियों के सैन्य गठबंधनों से अपने को दूर रखा?
(A) अमरीका और सोवियत संघ
(B) ब्रिटेन और फ्रांस
(C) जर्मनी और जापान
(D) चीन और ब्रिटेन

144. भारत की विदेश नीति पर प्रारंभिक वर्षों में पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत का जन्म विश्वयुद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ था।
2. अंग्रेजी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों की विरासत छोड़ी थी।
3. बँटवारे के कारण अलग से दबाव पैदा हुए थे।
4. गरीबी मिटाने का काम एक बड़ी चुनौती थी।
5. दुनिया तेजी से दो खेमों में बँट रही थी।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2, और 3
(B) केवल 2, 4, और 5
(C) केवल 1, 3, और 4
(D) 1, 2, 3, 4 और 5 सभी

145. भारत की विदेश नीति पर प्रारंभिक वर्षों में पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
(A) नेहरू परमाणु हथियारों के खिलाफ थे।
(B) भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए।
(C) होमी जहाँगीर भाभा के निर्देशन में परमाणु कार्यक्रम शुरु हुआ।
(D) 1974 के परीक्षण को शांतिपूर्ण परीक्षण कहा गया।

146. 1971 के युद्ध के बाद इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए?
(A) शेख मुजीबुर्रहमान
(B) जुल्फिकार अली भुट्टो
(C) याह्या खान
(D) ताज-उद-दीन अहमद

147. निम्नलिखित सूचना के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (देश)
P. मिस्र
Q. घाना
R. इंडोनेशिया
S. यूगोस्लाविया
सूची II: (गुटनिरपेक्ष नेता)
1. सुकर्णो
2. टीटो
3. नासिर
4. एनक्रूमा
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

148. भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने मध्यस्थता की थी?
(A) संयुक्त राष्ट्र संघ
(B) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
(C) गुटनिरपेक्ष आंदोलन
(D) विश्व बैंक

149. 1950 और 60 के दशक में भारत में कौन सी दो राजनीतिक पार्टियाँ भारत की विदेश नीति को अमेरिका के पक्ष में बनाने की वकालत करती थीं?
(A) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी
(B) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और फॉरवर्ड ब्लॉक
(C) भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी
(D) प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और स्वतंत्र पार्टी

150. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): एक राष्ट्र की विदेश नीति पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण दोनों का असर पड़ता है।
कारण (R): विकासशील देशों के पास अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपने सरोकारों को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधनों का अभाव होता है, जिससे वे अक्सर ताकतवर देशों पर निर्भर रहते हैं।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत था, जिसकी जड़ें भारत के उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्ष और शांतिवादी परंपराओं में गहराई तक निहित थीं। यह केवल दो प्रमुख शक्ति गुटों—संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले पूंजीवादी और सोवियत संघ के नेतृत्व वाले साम्यवादी गुट—से समान दूरी बनाए रखने की निष्क्रिय नीति नहीं थी। इसके विपरीत, यह एक सक्रिय और सकारात्मक अवधारणा थी जिसका उद्देश्य भारत को एक स्वतंत्र विदेश नीति पथ पर चलने की स्वतंत्रता प्रदान करना था। इस सिद्धांत के माध्यम से भारत ने अपनी 'रणनीतिक स्वायत्तता' को सुरक्षित रखने का प्रयास किया, ताकि वह अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अपने राष्ट्रीय हितों और न्याय के सिद्धांतों के आधार पर निर्णय ले सके, न कि किसी महाशक्ति के दबाव में। गुटनिरपेक्षता ने भारत को दोनों गुटों से आर्थिक और तकनीकी सहायता प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान किया, जो इसके नवजात आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण था। जवाहरलाल नेहरू ने इस नीति को एक नैतिक आयाम भी दिया, इसे नए स्वतंत्र हुए एशिया और अफ्रीका के देशों के लिए साम्राज्यवाद, नस्लवाद और शीत युद्ध की शक्ति राजनीति के विरुद्ध एक 'तीसरे बल' के रूप में प्रस्तुत किया। यह नीति इस विश्वास पर आधारित थी कि शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व ही अंतरराष्ट्रीय संबंधों का एकमात्र स्थायी आधार हो सकता है।
उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

151. स्रोत के अनुसार, भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने का मुख्य वैचारिक आधार क्या था?
(A) दोनों महाशक्तियों से अधिकतम सैन्य सहायता प्राप्त करना
(B) उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्ष और शांतिवादी परंपराएं
(C) अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एकाधिकार स्थापित करना
(D) विश्व राजनीति से पूर्ण रूप से अलग-थलग रहना

152. अनुच्छेद में उल्लिखित 'रणनीतिक स्वायत्तता' का क्या अभिप्राय है?
(A) अंतरराष्ट्रीय मामलों पर स्वतंत्र और हित-आधारित निर्णय लेने की क्षमता
(B) केवल एक शक्ति गुट के साथ दीर्घकालिक सैन्य गठबंधन बनाना
(C) किसी भी वैश्विक संगठन या मंच में शामिल होने से पूर्ण इनकार
(D) अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को सभी बाहरी प्रभावों के लिए पूरी तरह बंद करना

153. गुटनिरपेक्षता की नीति ने भारत को आर्थिक रूप से कैसे लाभान्वित किया?
(A) इसने भारत को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया।
(B) इसने भारत को केवल सोवियत संघ से आर्थिक सहायता के लिए बाध्य किया।
(C) इसने दोनों शक्ति गुटों से आर्थिक और तकनीकी सहायता प्राप्त करना संभव बनाया।
(D) इसने भारत को सभी विदेशी आयातों पर अत्यधिक व्यापारिक कर लगाने का अधिकार दिया।

154. जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्षता को एशिया और अफ्रीका के नए स्वतंत्र देशों के लिए किस रूप में प्रस्तुत किया?
(A) पूंजीवादी गुट में शामिल होने के प्रारंभिक कूटनीतिक प्रयास के रूप में
(B) सोवियत संघ के साथ एक अनिवार्य और रणनीतिक सैन्य गठबंधन के रूप में
(C) वैश्विक राजनीति में केवल एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक की सीमित भूमिका के रूप में
(D) साम्राज्यवाद और शीत युद्ध की राजनीति के विरुद्ध एक 'तीसरे बल' के रूप में

155. स्रोत से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गुटनिरपेक्षता...
(A) एक निष्क्रिय और पूर्णतः नकारात्मक नीति थी।
(B) केवल शीत युद्ध की अवधि तक ही प्रासंगिक रही।
(C) नैतिक और व्यावहारिक आयामों वाली भारत की सक्रिय अवधारणा थी।
(D) का एकमात्र उद्देश्य भारत को सैन्य महाशक्ति बनाना था।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
पंचशील के सिद्धांत, जिन्हें 1954 में भारत और चीन के बीच तिब्बत क्षेत्र से संबंधित एक समझौते में पहली बार औपचारिक रूप से प्रतिपादित किया गया था, भारतीय विदेश नीति के आधारभूत स्तंभ बन गए। ये पाँच सिद्धांत केवल एक द्विपक्षीय समझौते तक सीमित नहीं थे, बल्कि इन्हें जवाहरलाल नेहरू ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए एक सार्वभौमिक आचार संहिता के रूप में देखा। ये सिद्धांत थे: (i) एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान, (ii) पारस्परिक गैर-आक्रामकता, (iii) एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक गैर-हस्तक्षेप, (iv) समानता

और पारस्परिक लाभ, और (v) शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व। इन सिद्धांतों का उद्देश्य शीत युद्ध के तनावपूर्ण माहौल में एक वैकल्पिक ढाँचा प्रस्तुत करना था, जो सैन्य गठबंधनों और शक्ति प्रदर्शन के बजाय सहयोग और आपसी सम्मान पर आधारित हो। नेहरु का मानना था कि ये सिद्धांत विकासशील देशों को अपनी ऊर्जा को राष्ट्र-निर्माण पर केंद्रित करने की अनुमति देंगे, बजाय इसके कि वे महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता में उलझें। बांडुंग सम्मेलन (1955) में इन सिद्धांतों को व्यापक स्वीकृति मिली और ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मार्गदर्शक सिद्धांतों का एक अभिन्न अंग बन गए। हालाँकि, 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध ने इन सिद्धांतों की व्यावहारिकता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाए, लेकिन वे आज भी भारत की विदेश नीति के संवाद में एक महत्वपूर्ण आदर्श के रूप में बने हुए हैं।

उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

156. पंचशील के सिद्धांतों को पहली बार औपचारिक रूप से किस समझौते में प्रतिपादित किया गया था?
(A) शिमला समझौता
(B) भारत-चीन तिब्बत क्षेत्र समझौता
(C) ताशकंद घोषणा
(D) भारत-सोवियत मैत्री संधि

157. निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील के पाँच सिद्धांतों में से एक नहीं है?
(A) एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में गैर-हस्तक्षेप
(B) शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व
(C) समानता और पारस्परिक लाभ
(D) पारस्परिक सैन्य गठबंधन

158. स्रोत के अनुसार, नेहरु ने पंचशील को किस रूप में देखा?
(A) अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए एक सार्वभौमिक आचार संहिता के रूप में
(B) चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक अल्पकालिक व्यवस्था के रूप में
(C) अमेरिकी सैन्य गुट में औपचारिक रूप से शामिल होने की एक सोची-समझी रणनीति
(D) सोवियत संघ के प्रभाव के खिलाफ एक सामूहिक और रक्षात्मक क्षेत्रीय सैन्य संधि

159. किस घटना ने पंचशील के सिद्धांतों की व्यावहारिकता पर गंभीर प्रश्न खड़े किए?
(A) 1965 का भारत-पाकिस्तान युद्ध
(B) 1955 का बांडुंग सम्मेलन
(C) 1962 का भारत-चीन युद्ध
(D) 1971 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम

160. पंचशील के सिद्धांतों का व्यापक उद्देश्य क्या था?
(A) शीत युद्ध की शक्ति राजनीति का एक सहयोगी और सम्मानजनक विकल्प देना
(B) संपूर्ण विश्व में साम्यवादी विचारधारा का तीव्र प्रसार करना
(C) भारत को एक प्रमुख वैश्विक सैन्य शक्ति के रूप में तुरंत स्थापित करना
(D) विकासशील देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था से पूरी तरह अलग-थलग करना

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

1962 का भारत-चीन युद्ध भारतीय विदेश नीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने इसके आदर्शवादी चरण के अंत और यथार्थवाद के उदय को चिह्नित किया। इस युद्ध के परिणाम बहुआयामी थे। रणनीतिक रूप से, इसने भारत की सैन्य तैयारियों की गंभीर कमियों को उजागर किया और एक बड़े सैन्य आधुनिकीकरण कार्यक्रम को प्रेरित किया। रक्षा बजट में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और देश ने अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। मनोवैज्ञानिक रूप से, युद्ध एक राष्ट्रीय अपमान था, जिसने 'हिंदी-चीनी भाई-भाई' के नारे में विश्वास को चकनाचूर कर दिया और चीन के इरादों को लेकर एक गहरे और स्थायी अविश्वास को जन्म दिया। राजनीतिक रूप से, इस पराजय ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु की प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से धूमिल किया और उनकी नेतृत्व क्षमता की कड़ी आलोचना हुई। संसद में पहली बार उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इसने भारतीय राजनीति के भीतर भी ध्रुवीकरण किया, जहाँ भारतीय कम्युस्टि पार्टी चीन और सोवियत संघ के प्रति निष्ठा को लेकर विभाजित हो गई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, भारत को अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति के बावजूद पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका और ब्रिटेन से सैन्य सहायता मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे गुटनिरपेक्षता की अवधारणा की सीमाओं पर बहस छिड़ गई। इस युद्ध ने भारत को अपनी उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा के प्रति अधिक सतर्क और अपनी विदेश नीति के संचालन में अधिक व्यावहारिक बना दिया।

उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

161. 1962 के युद्ध का भारतीय विदेश नीति पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था?
(A) इसने भारत को पूर्ण रूप से अलगाववादी बना दिया।
(B) इसने भारत को स्थायी रूप से अमेरिकी सैन्य गुट में शामिल होने के लिए मजबूर किया।
(C) इसने चीन के साथ सभी राजनयिक संबंध हमेशा के लिए समाप्त कर दिए।
(D) इसने आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर एक बदलाव को चिह्नित किया।

162. युद्ध के तत्काल घरेलू राजनीतिक परिणाम क्या थे?
(A) प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु की सरकार को जनता द्वारा भारी बहुमत दिया गया।
(B) नेहरु की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँची और सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया।
(C) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को तत्कालीन सरकार के साथ गठबंधन में शामिल किया गया।

22. (B) मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सी.पी.आई.एम.)
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में उन्नीस सौ चौंसठ के विभाजन के बाद चीन के वैचारिक दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले नेताओं ने मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सी.पी.आई.एम.) का गठन किया। इस विभाजन का मुख्य कारण चीन और सोवियत संघ के बीच बढ़ते मतभेद तथा भारत-चीन युद्ध के प्रति पार्टी का रुख था। नई पार्टी ने क्रांतिकारी विचारधारा और सर्वहारा वर्ग के हितों को प्राथमिकता देने का अपना संकल्प दोहराया था।

23. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
उन्नीस सौ बासठ के युद्ध ने पूर्वोत्तर भारत की सामरिक संवेदनशीलता को उजागर कर दिया था। चीन की सैन्य घुसपैठ के बाद भारत सरकार को अहसास हुआ कि इस क्षेत्र का प्रशासनिक और सामाजिक एकीकरण अत्यंत आवश्यक है। इसी सुरक्षा चिंता के कारण पूर्वोत्तर के राज्यों को नई तरजीह दी गई और वहां विकास कार्यों के साथ-साथ प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की प्रक्रिया को तेज किया गया था।

24. (A) 1960
भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर उन्नीस सौ साठ में एक ऐतिहासिक संधि हुई थी। इस संधि पर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। विश्व बैंक की मध्यस्थता में संपन्न हुई यह संधि दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद अब तक प्रभावी रूप से कार्य कर रही एक महत्वपूर्ण सफलता है।

25. (C) सोवियत संघ
उन्नीस सौ पैंसठ के भारत-पाकिस्तान युद्ध के पश्चात शांति स्थापित करने के उद्देश्य से जनवरी उन्नीस सौ छियासठ में ताशकंद में एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस वार्ता की मध्यस्थता सोवियत संघ ने की थी। इसके परिणामस्वरूप ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें दोनों देशों ने अपनी सेनाओं को युद्ध-पूर्व की स्थिति में वापस ले जाने और आपसी विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का वचन दिया था।

26. (A) लालबहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान
ताशकंद समझौता जनवरी उन्नीस सौ छियासठ में भारत के प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था। यह समझौता उन्नीस सौ पैंसठ के युद्ध के समापन और शांति बहाली की दिशा में एक प्रमुख कदम था। सोवियत संघ की मध्यस्थता में हुए इस समझौते के तुरंत बाद ताशकंद में ही शास्त्री जी का आकस्मिक और रहस्यमय निधन हो गया था।

27. (D) अवामी लीग
उन्नीस सौ सत्तर में पाकिस्तान में हुए पहले आम चुनावों में शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में लगभग सभी सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। इस जनादेश ने अवामी लीग को पूरे पाकिस्तान की संसद में बहुमत प्रदान कर दिया था। हालांकि, पश्चिमी पाकिस्तान के नेतृत्व ने सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया, जिससे गहरा राजनीतिक संकट पैदा हुआ और अंततः बांग्लादेश का निर्माण हुआ।

28. (B) सोवियत संघ
अगस्त उन्नीस सौ इकहत्तर में बांग्लादेश संकट के दौरान भारत ने सोवियत संघ के साथ बीस वर्षीय 'शांति, मित्रता और सहयोग की संधि' पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि ने भारत को कूटनीतिक मजबूती प्रदान की और अमेरिका-चीन-पाकिस्तान धुरी के संभावित खतरे से सुरक्षा का आश्वासन दिया। यह संधि भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव थी, जिसने युद्ध की स्थिति में सोवियत सैन्य और कूटनीतिक समर्थन सुनिश्चित किया था।

29. (D) 1, 2, 3, 4 सभी
उन्नीस सौ इकहत्तर का युद्ध मुख्य रूप से पूर्वी पाकिस्तान में उत्पन्न राजनीतिक और मानवीय संकट का परिणाम था। पाकिस्तान के सैन्य दमन के कारण लगभग अस्सी लाख शरणार्थी भारत आए, जिससे देश पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा। इस युद्ध में अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान का पक्ष लिया था। भारत की निर्णायक सैन्य जीत के बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर बांग्लादेश के रूप में एक नया राष्ट्र बना था।

30. (D) शिमला समझौता
उन्नीस सौ इकहत्तर के युद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई उन्नीस सौ बहत्तर में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने अपने सभी विवादों को द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का संकल्प लिया। इसमें नियंत्रण रेखा को मान्यता दी गई और भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया गया।

31. (A) मई 1974, पोखरण
भारत ने अपना प्रथम सफल परमाणु परीक्षण मई उन्नीस सौ चौहत्तर में राजस्थान के पोखरण में किया था। इस परीक्षण को 'शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट' का नाम दिया गया। भारत ने इसके माध्यम से अपनी वैज्ञानिक क्षमता का प्रदर्शन किया और स्पष्ट किया कि वह परमाणु ऊर्जा का उपयोग केवल विकासात्मक और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करना चाहता है। इस परीक्षण ने वैश्विक परमाणु राजनीति में भारत की स्थिति को बदल दिया था।

32. (B) होमी जहाँगीर भाभा
होमी जहाँगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में उन्नीस सौ चालीस के दशक के अंत में भारत ने परमाणु अनुसंधान की दिशा में कदम बढ़ाए थे। भाभा का मानना था कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए ऊर्जा की आत्मनिर्भरता हेतु परमाणु शक्ति अपरिहार्य है। उनके निर्देशन में ही भारत ने आधुनिक परमाणु तकनीक विकसित करने के लिए बुनियादी संस्थागत ढांचा तैयार किया था।

(D) भारत की प्रभावी राजनयिक और सैन्य रणनीति बनाने की क्षमता

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

भारत की परमाणु नीति का विकास इसकी रणनीतिक स्वायत्तता की खोज और एक जटिल सुरक्षा वातावरण की प्रतिक्रिया का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कार्यक्रम की शुरुआत होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में "शांति के लिए परमाणु" के दर्शन के साथ हुई, जिसके नेहरू ने सक्रिय रूप से समर्थन किया। प्रारंभ में, इसका उद्देश्य ऊर्जा उत्पादन और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी का उपयोग करना था। हालांकि, 1964 में चीन द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने के बाद भारत का सुरक्षा परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल गया। इस घटना ने भारत के नीति निर्माताओं के बीच एक परमाणु हथियार विकल्प विकसित करने की आवश्यकता पर बहस को तेज कर दिया। इसके अलावा, 1968 की परमाणु अप्रसार संधि (NPT) को भारत ने भेदभावपूर्ण माना, क्योंकि यह परमाणु-हथियार वाले राज्यों (P-5) के एकाधिकार को वैध बनाती थी और गैर-परमाणु राज्यों पर प्रतिबंध लगाती थी। भारत ने इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इन रणनीतिक दबावों की परिणति मई 1974 में पोखरण में भारत के पहले परमाणु परीक्षण में हुई, जिसे आधिकारिक तौर पर 'शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट' (PNE) का नाम दिया गया। इस परीक्षण का उद्देश्य यह प्रदर्शित करना था कि भारत के पास परमाणु क्षमता है, लेकिन उसने इसे सैन्यीकरण करने से परहेज किया। यह परीक्षण भारत द्वारा अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने और तकनीकी आत्मनिर्भरता के दावे का एक शक्तिशाली प्रतीक था, भले ही इसके कारण उसे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा।

उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

171. प्रारंभ में भारत के परमाणु कार्यक्रम का घोषित उद्देश्य क्या था?
(A) परमाणु हथियारों का एक बड़ा जखीरा बनाना
(B) पड़ोसी देशों को डराना
(C) ऊर्जा उत्पादन और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे शांतिपूर्ण उपयोग
(D) सोवियत संघ के साथ सैन्य गठबंधन बनाना

172. भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि (NPT) को क्यों अस्वीकार कर दिया?
(A) क्योंकि इस संधि का क्रियान्वयन भारत के लिए आर्थिक रूप से बहुत महंगा था।
(B) क्योंकि इसे भेदभावपूर्ण माना गया जो परमाणु शक्तियों के एकाधिकार को पुष्ट करती थी।
(C) क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय संधि मूल रूप से केवल अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी।
(D) क्योंकि सोवियत संघ ने भारत को इस संधि पर हस्ताक्षर न करने के लिए विवश किया था।

173. किस प्रमुख बाहरी घटना ने भारत को अपने परमाणु कार्यक्रम के सुरक्षा आयामों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया?
(A) 1965 का भारत-पाकिस्तान युद्ध
(B) वियतनाम युद्ध
(C) क्यूबा मिसाइल संकट
(D) 1964 में चीन द्वारा किया गया परमाणु परीक्षण

174. भारत ने अपने 1974 के परमाणु परीक्षण को आधिकारिक तौर पर क्या नाम दिया?
(A) शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट (PNE)
(B) सैन्य चेतावनी परीक्षण
(C) ऑपरेशन शक्ति
(D) सामरिक हथियार प्रदर्शन

175. 1974 के परीक्षण के माध्यम से भारत विश्व को क्या मुख्य संदेश देना चाहता था?
(A) वह निकट भविष्य में किसी भी पड़ोसी देश पर सैन्य हमला करने की योजना बना रहा था।
(B) वह बिना किसी शर्त के NPT संधि पर तुरंत हस्ताक्षर करने के लिए पूरी तैयार था।
(C) वह सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता के मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम था।
(D) वह अंतरराष्ट्रीय दबाव में अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बंद करने वाला था।

के प्रमाण के रूप में देखी जाती है, जहाँ परमाणु हथियारों को केवल न्यूनतम विश्वसनीय निवारक के रूप में रखा गया है।

44. (B) पूर्वोत्तर
उन्नीस सौ बासठ के युद्ध में चीन की घुसपैठ ने भारत सरकार को पूर्वोत्तर क्षेत्र की रणनीतिक कमजोरी और वहां की अस्थिरता के प्रति सचेत कर दिया था। युद्ध के तत्काल बाद, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए इस क्षेत्र के पुनर्गठन और विकास की योजनाएं बनाई गईं। इसी प्रक्रिया के तहत नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया और अन्य क्षेत्रों के प्रशासनिक ढांचे में सुधार कर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा गया।

45. (B) केवल 1 और 4
शीतयुद्ध के दौरान भारत ने अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति के बावजूद अमेरिका और सोवियत संघ, दोनों महाशक्तियों से आर्थिक और तकनीकी सहायता प्राप्त की थी। वहीं, उन्नीस सौ चौवन में हस्ताक्षरित पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक दस्तावेज़ था। हालांकि, पड़ोसियों के साथ संबंध हमेशा तनावपूर्ण नहीं रहे और सोवियत संधि अमेरिका के साथ निकटता का परिणाम नहीं थी।

46. (D) 1962 का भारत-चीन आक्रमण
उन्नीस सौ चौंसठ में निर्मित प्रसिद्ध हिंदी फिल्म 'हकीकत' उन्नीस सौ बासठ के भारत-चीन युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह फिल्म लद्दाख के दुर्गम युद्धक्षेत्र में भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और उनके बलिदान का मार्मिक चित्रण करती है। फिल्म के माध्यम से युद्ध की विभीषिका और उस समय के राष्ट्रीय संकट को दर्शाया गया है, जिसने भारतीय जनमानस को देशभक्ति की भावना से गहराई तक प्रभावित किया था।

47. (A) नाटो (NATO)
शीतयुद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) का गठन उन्नीस सौ उनचास में किया गया था। यह एक सामूहिक सुरक्षा गठबंधन था जिसका उद्देश्य पश्चिमी देशों को सोवियत संघ के संभावित सैन्य प्रभाव से सुरक्षित रखना था। नाटो के जवाब में ही बाद में सोवियत संघ ने अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर वारसा पैक्ट नामक सैन्य गठबंधन की स्थापना की थी।

48. (A) P-2, Q-1, R-3, S-4
पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य आपसी संबंधों को संचालित करने के लिए हुआ था। सिंधु नदी जल संधि उन्नीस सौ साठ में विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच संपन्न हुई। ताशकंद समझौता उन्नीस सौ छियासठ में सोवियत संघ की मध्यस्थता में भारत-पाक के बीच हुआ था। शिमला समझौता उन्नीस सौ बहत्तर में भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्णतः द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से हुआ था।

49. (A) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं।
उन्नीस सौ इकहत्तर के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की निर्णायक विजय ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक अजेय और शक्तिशाली नेता के रूप में स्थापित कर दिया। इस ऐतिहासिक सैन्य सफलता और बांग्लादेश के निर्माण से देश में हर्ष की लहर दौड़ गई। इसके परिणामस्वरूप उन्नीस सौ बहत्तर के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने अधिकांश राज्यों में भारी बहुमत प्राप्त किया, जिससे इंदिरा गांधी का राजनीतिक वर्चस्व और भी मजबूत हुआ।

50. (A) भारत इसे भेदभावपूर्ण और निशस्त्रीकरण के लक्ष्य से दूर ले जाने वाली संधि मानता था।
भारत ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) पर हस्ताक्षर करने से इसलिए इनकार किया क्योंकि वह इसे दोषपूर्ण और भेदभावपूर्ण मानता था। भारत का तर्क था कि यह संधि परमाणु हथियारों के पूर्ण और सार्वभौमिक निशस्त्रीकरण का रोडमैप प्रदान नहीं करती। इसके बजाय, यह केवल नए परीक्षणों को रोकती है जबकि परमाणु संपन्न देशों को अपने शस्त्रागार को आधुनिक बनाने की अनुमति देती है, जो वैश्विक सुरक्षा के लिए अनुचित है।

51. (C) भारत अपनी स्वतंत्रता के बाद चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने में हिचकिचा रहा था।
भारत उन अग्रणी देशों में शामिल था जिन्होंने उन्नीस सौ उनचास की चीनी क्रांति के तुरंत बाद वहां की नई कम्युनिस्ट सरकार को आधिकारिक मान्यता प्रदान की थी। नेहरू का मानना था कि चीन के साथ मित्रता एशिया में शांति और स्थिरता के लिए आवश्यक है। भारत ने हमेशा अनौपनिवेशीकरण और रंगभेद विरोधी संघर्षों का समर्थन किया, लेकिन चीन को मान्यता देने के मामले में भारत का रुख अत्यंत त्वरित और सकारात्मक था।

52. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
उन्नीस सौ साठ के दशक में चीन और पाकिस्तान के साथ हुए युद्धों ने भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डाला था। युद्ध की आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार को विकास योजनाओं से धन हटाकर रक्षा व्यय में लगाना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य अधूरे रह गए और देश को आर्थिक संकट के कारण योजना अवकाश (Plan Holiday) का सहारा लेना पड़ा था।

53. (C) चीन
गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देशों में मुख्य रूप से भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया और घाना शामिल थे। इन देशों के नेताओं ने शीतयुद्ध की प्रतिद्वंद्विता से दूर रहने के लिए इस मंच का गठन किया था। यद्यपि चीन ने बांडुंग सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन वह इस आंदोलन का संस्थापक सदस्य नहीं था। चीन की विदेश नीति और उसकी साम्यवादी विचारधारा उस समय गुटनिरपेक्षता के पारंपरिक ढांचे से भिन्न और स्वतंत्र थी।

में सीमा विवाद के कारण भारत और चीन के बीच सशस्त्र युद्ध छिड़ गया था।

11. (D) बांडुंग
एफ्रो-एशियाई सम्मेलन का आयोजन उन्नीस सौ पचपन में इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में किया गया था। इस ऐतिहासिक सम्मेलन ने नवस्वतंत्र देशों के बीच सहयोग और एकता को मजबूत करने का कार्य किया। बांडुंग सम्मेलन को गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उदय का आधार माना जाता है। इसमें भाग लेने वाले देशों ने उपनिवेशवाद का विरोध किया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने पर बल दिया था।

12. (B) चाऊ एन लाई
भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों, जिन्हें पंचशील कहा जाता है, की घोषणा उन्नीस सौ चौवन में हुई थी। इस पर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु और चीन के प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए थे। इन सिद्धांतों का उद्देश्य दोनों राष्ट्रों के बीच संबंधों को बेहतर बनाना और आपसी संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान सुनिश्चित करना था।

13. (D) 1, 2, 3, 4 सभी
भारत ने उन्नीस सौ उनचास की चीनी क्रांति के बाद कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता प्रदान की थी। हालांकि, सरदार पटेल जैसे नेताओं ने चीन की विस्तारवादी नीति के प्रति आगाह किया था। उन्नीस सौ पचास में चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया। अंततः उन्नीस सौ चौवन में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये सभी तथ्य उस दौर के जटिल भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों की व्याख्या करते हैं।

14. (D) दलाई लामा
तिब्बत के आध्यात्मिक और पारंपरिक नेता दलाई लामा ने उन्नीस सौ उनसाठ में चीन की दमनकारी नीतियों के कारण भारत में शरण ली थी। चीन ने भारत के इस मानवीय कदम को अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखा। इस घटना ने भारत और चीन के बीच कूटनीतिक संबंधों में भारी तनाव पैदा किया, जो आगे चलकर उन्नीस सौ बासठ के सीमा युद्ध का कारण बना था।

15. (B) कथन 1 सत्य है, लेकिन कथन 2 असत्य है।
उन्नीस सौ छप्पन में स्वेज नहर के संकट के दौरान भारत ने मिस्र पर ब्रिटेन के आक्रमण का कड़ा विरोध किया था। हालांकि, उसी वर्ष जब सोवियत संघ ने हंगरी पर सैन्य हमला किया, तब भारत ने इसकी सार्वजनिक रूप से वैसी कड़ी निंदा नहीं की। भारत के इस चयनात्मक रुख की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई थी। यह स्थिति गुटनिरपेक्षता के सिद्धांतों के कार्यान्वयन में आई व्यावहारिक चुनौतियों को दर्शाती है।

16. (B) लद्दाख का अक्साई-चीन क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश का नेफा क्षेत्र।
उन्नीस सौ बासठ के युद्ध में चीन ने मुख्य रूप से भारत के दो भौगोलिक क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। इसमें पश्चिम में लद्दाख का अक्साई-चीन क्षेत्र और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश का तत्कालीन नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (नेफा) क्षेत्र शामिल था। चीन ने इन क्षेत्रों पर अपना ऐतिहासिक दावा पेश करते हुए भारतीय सीमा का उल्लंघन किया, जिसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के मध्य एक अल्पकालिक लेकिन भीषण संघर्ष हुआ था।

17. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
जवाहरलाल नेहरु स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने विदेश नीति का खाका तैयार किया। वी. के. कृष्णमेनन उन्नीस सौ बासठ के चीन युद्ध के समय देश के रक्षा मंत्री थे। दलाई लामा तिब्बत के सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं जिन्होंने भारत में शरण ली थी। चाऊ एन लाई उस समय चीन के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारत के साथ ऐतिहासिक पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

18. (A) वी. के. कृष्णमेनन
उन्नीस सौ बासठ के भारत-चीन युद्ध में भारत को सैन्य पराजय और भारी क्षति का सामना करना पड़ा था। इस हार के बाद देश में तीव्र राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई और तत्कालीन रक्षा मंत्री वी. के. कृष्णमेनन को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। सैन्य विफलता की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें अंततः केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना पड़ा। यह घटना नेहरु सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका थी।

19. (C) संकट की घड़ी में सोवियत संघ ने खुलकर भारत का समर्थन किया।
उन्नीस सौ बासठ के भारत-चीन संघर्ष के दौरान सोवियत संघ ने तटस्थ भूमिका निभाई थी क्योंकि वह स्वयं क्यूबा मिसाइल संकट में उलझा हुआ था। चीन ने युद्ध में एकतरफा युद्धविराम घोषित किया, लेकिन भारत की वैश्विक छवि को गहरा आघात लगा। इस संकट के कारण नेहरु सरकार को संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा और देश के भीतर व्यापक असंतोष उत्पन्न हुआ था।

20. (D) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा)
उन्नीस सौ बासठ के चीन युद्ध के कारण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर आंतरिक वैचारिक मतभेद तीव्र हो गए। पार्टी का एक धूरी सोवियत संघ का समर्थक था और कांग्रेस के साथ सहयोग का पक्षधर था, जबकि दूसरा धूरी चीन का समर्थन कर रहा था। इन गहराते मतभेदों के परिणामस्वरूप उन्नीस सौ चौंसठ में पार्टी दो भागों में विभाजित हो गई और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हुआ था।

21. (D) 1, 2, 3, 4 और 5 सभी
चीन के साथ हुए युद्ध के भारत पर व्यापक और दीर्घकालिक प्रभाव पड़े। इससे राष्ट्रीय स्वाभिमान को ठेस पहुँची और भारत को सैन्य सहायता के लिए पश्चिमी देशों का रुख करना पड़ा। प्रधानमंत्री नेहरु की व्यापक आलोचना हुई और कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हो गया। साथ ही, सरकार ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास और सुरक्षा पर पहले की तुलना में अधिक ध्यान देना शुरु किया था।

(D) भारत के सभी प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दलों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया।

163. स्रोत के अनुसार, 1962 के युद्ध ने भारत की सैन्य रणनीति को कैसे प्रभावित किया?
(A) इसने भारत के रक्षा और सैन्य खर्च में तत्काल भारी कटौती को प्रेरित किया।
(B) इसने भारत को अपनी वर्तमान सेना को पूरी तरह से विखंडित करने के लिए प्रेरित किया।
(C) इसने सैन्य आधुनिकीकरण कार्यक्रम और रक्षा बजट में महत्वपूर्ण वृद्धि को प्रेरित किया।
(D) इसने भारत को केवल अपनी नौसैनिक क्षमताओं के विकास पर ध्यान देने को प्रेरित किया।

164. अनुच्छेद के अनुसार, युद्ध का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या था?
(A) चीन के साथ संबंधों में एक नए विश्वास और दोस्ती का उदय।
(B) भारतीय लोगों के आत्म-सम्मान में अत्यधिक वृद्धि।
(C) विदेश नीति के मामलों में जनता की रुचि का पूर्ण अभाव।
(D) चीन के इरादों के प्रति गहरा और स्थायी अविश्वास।

165. 1962 के युद्ध ने भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति को कैसे प्रभावित किया?
(A) इसने पश्चिमी देशों से सैन्य सहायता की आवश्यकता पैदा की, जिससे नीति की सीमाओं पर बहस हुई।
(B) इसने भारत की गुटनिरपेक्ष नीति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक मजबूत और सैद्धांतिक बनाया।
(C) इसने भारत को बिना किसी देरी के तुरंत सोवियत शक्ति गुट में औपचारिक रूप से शामिल किया।
(D) इसने पूरे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के वैश्विक स्तर पर पूर्ण और स्थायी विघटन का मार्ग खोला।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
1971 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम केवल भारत और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी घटना थी जिसने दक्षिण एशिया के भू-राजनीतिक मानचित्र को स्थायी रूप से बदल दिया। इस संघर्ष की जड़ें पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दमन में थीं, जिसके कारण एक बड़े पैमाने पर मानवीय संकट और लगभग 10 मिलियन शरणार्थियों का भारत में आगमन हुआ। भारत के लिए, यह स्थिति एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक बोझ बन गई थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, भारत ने एक सुविचारित, बहु-आयामी रणनीति अपनाई। राजनयिक स्तर पर, भारत ने दुनिया भर में बांग्लादेश की मुक्ति की आकांक्षाओं के लिए समर्थन जुटाया। सैन्य स्तर पर, उसने 'मुक्ति वाहिनी' को प्रशिक्षित और सुसज्जित किया। इस रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण कदम अगस्त 1971 में सोवियत संघ के साथ 'शांति, मैत्री और सहयोग की संधि' पर हस्ताक्षर करना था। इस संधि ने अमेरिका-चीन-पाकिस्तान के संभावित गठजोड़ को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया और भारत को पाकिस्तानी आक्रमण की स्थिति में सोवियत समर्थन का आश्वासन दिया। दिसंबर 1971 में युद्ध शुरू होने पर, भारतीय सेना ने एक तेज और निर्णायक अभियान में पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया, जिससे बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। इस विजय ने भारत को दक्षिण एशिया में एक निर्विवाद प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया और इसकी विदेश नीति तथा सैन्य क्षमता में दुनिया के विश्वास को बहाल किया।
उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

166. 1971 के संघर्ष में भारत के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का तत्काल कारण क्या था?
(A) पाकिस्तान द्वारा भारत पर अचानक हमला
(B) पूर्वी पाकिस्तान से भारत में बड़े पैमाने पर शरणार्थियों का आगमन
(C) पश्चिमी पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता
(D) संयुक्त राष्ट्र का सीधा आदेश

167. अगस्त 1971 में भारत-सोवियत मैत्री संधि का मुख्य रणनीतिक उद्देश्य क्या था?
(A) भारत को सोवियत संघ का एक उपग्रह राज्य बनाना
(B) अमेरिका-चीन-पाकिस्तान के संभावित गठजोड़ को निष्क्रिय करना
(C) पाकिस्तान के साथ व्यापार संबंध स्थापित करना
(D) गुटनिरपेक्ष आंदोलन को भंग करना

168. 1971 के युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक परिणाम क्या था?
(A) बांग्लादेश का उदय और भारत का एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित होना
(B) भारत और पाकिस्तान का एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में पूर्ण एकीकरण
(C) दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अमेरिकी कूटनीतिक प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि
(D) कश्मीर मुद्दे का दोनों देशों के बीच हमेशा के लिए शांतिपूर्ण समाधान

169. स्रोत के अनुसार, भारत ने संघर्ष के प्रारंभिक चरण में बांग्लादेश के आंदोलन का समर्थन कैसे किया?
(A) पाकिस्तान पर तत्काल पूर्ण पैमाने पर आक्रमण करके
(B) दुनिया से पूरी तरह से अलग-थलग रहकर
(C) राजनयिक समर्थन जुटाकर और 'मुक्ति वाहिनी' को प्रशिक्षित करके
(D) केवल आर्थिक प्रतिबंध लगाकर

170. 1971 के युद्ध में भारत की विजय ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रदर्शित किया?
(A) भारत की गुटनिरपेक्ष नीति की विफलता
(B) शीत युद्ध में भारत की तटस्थता का अंत
(C) दक्षिण एशिया में चीन के प्रभुत्व की स्थापना

33. (A) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं।
भारत ने मई उन्नीस सौ चौहत्तर में किए गए अपने पहले परमाणु परीक्षण को 'शांतिपूर्ण' घोषित किया था। सरकार का तर्क था कि वह परमाणु शक्ति का प्रयोग केवल ऊर्जा उत्पादन और कृषि जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में करना चाहती है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हमेशा यह रुख बनाए रखा कि वह परमाणु हथियारों की होड़ के विरुद्ध है और केवल आत्मरक्षा एवं विकास हेतु तकनीक विकसित कर रहा है।

34. (A) भारत ने इसे भेदभावपूर्ण माना और हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।
उन्नीस सौ अड़सठ की परमाणु अप्रसार संधि के प्रति भारत का दृष्टिकोण अत्यंत स्पष्ट और आलोचनात्मक रहा है। भारत ने इस संधि को भेदभावपूर्ण माना क्योंकि यह परमाणु शक्ति संपन्न देशों के एकाधिकार को वैधता प्रदान करती थी और अन्य देशों पर परमाणु तकनीक के विकास पर प्रतिबंध लगाती थी। भारत ने वैश्विक और समान निशस्त्रीकरण की मांग करते हुए इस संधि पर हस्ताक्षर करने से हमेशा इनकार किया है।

35. (A) P-3, Q-1, R-4, S-2
भारत और चीन के मध्य सीमा युद्ध उन्नीस सौ बासठ में हुआ था। पाकिस्तान के साथ प्रथम पूर्ण युद्ध उन्नीस सौ पैंसठ में लड़ा गया। उन्नीस सौ इकहत्तर में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए भारत-पाक युद्ध हुआ, जिसमें भारत को ऐतिहासिक जीत मिली। कारगिल संघर्ष उन्नीस सौ निन्यानवे में हुआ था जब पाकिस्तानी घुसपैठियों ने भारतीय ठिकानों पर कब्जा किया था। ये घटनाएँ भारत की सुरक्षा चुनौतियों का प्रतीक हैं।

36. (D) ऑपरेशन विजय
उन्नीस सौ निन्यानवे में कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाए गए सैन्य अभियान का नाम 'ऑपरेशन विजय' था। भारतीय सैनिकों ने दुर्गम पहाड़ियों और प्रतिकूल मौसम की चुनौतियों का सामना करते हुए अदम्य साहस का परिचय दिया। इस सफल अभियान के परिणामस्वरूप भारत ने अपने सभी खोए हुए ठिकानों पर पुनः नियंत्रण प्राप्त किया और पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर किया था।

37. (D) 1, 2, 3, 4 और 5 सभी
भारत की विदेश नीति का निर्माण अनेक आंतरिक और बाह्य कारकों के समन्वय से होता है। इसमें देश की आर्थिक विकास की ज़रूरतें, तत्कालीन वैश्विक परिस्थितियाँ और संवैधानिक निर्देश शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सत्ताधारी दल की वैचारिक दिशा और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विकसित हुए नैतिक मूल्य भी इसे प्रभावित करते हैं। इन सभी तत्वों ने मिलकर भारत की गुटनिरपेक्ष और शांतिपूर्ण विदेश नीति को एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया है।

38. (B) जवाहरलाल नेहरू
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक स्वतंत्रता उसकी विदेश नीति के स्वतंत्र संचालन में निहित होती है। उनके अनुसार, यदि कोई देश अपने विदेशी संबंधों के लिए दूसरों पर निर्भर है, तो वह पूर्णतः स्वतंत्र नहीं कहला सकता। नेहरू ने इसी विचार को आधार बनाकर भारत के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति का चयन किया ताकि देश वैश्विक दबावों से मुक्त होकर स्वतंत्र निर्णय ले सके।

39. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने गुटनिरपेक्षता को अपनी विदेश नीति के मुख्य आधार के रूप में चुना था। इसका प्राथमिक कारण यह था कि भारत शीतयुद्ध की प्रतिद्वंद्विता में फंसकर अपनी नवनिर्मित संप्रभुता को खोना नहीं चाहता था। अमेरिका और सोवियत संघ के सैन्य गठबंधनों से दूर रहकर भारत ने दोनों गुटों से सहयोग प्राप्त करने और अपनी स्वतंत्र पहचान को विश्व पटल पर बनाए रखने का सफल प्रयास किया था।

40. (A) आयात को कम करने पर जोर
उन्नीस सौ पचास के दशक में भारत ने 'आयात प्रतिस्थापन' की आर्थिक रणनीति अपनाई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना और विदेशी निर्भरता को कम करना था। इस नीति के तहत बाहरी देशों से वस्तुओं के आयात पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके परिणामस्वरूप विश्व अर्थव्यवस्था के साथ भारत का व्यापारिक लेन-देन सीमित हो गया, जिससे देश को अपनी विकास यात्रा में आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिली थी।

41. (A) 1, 3, 2, 4
ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम में ताशकंद समझौता जनवरी उन्नीस सौ छियासठ में हुआ था। इसके बाद अगस्त उन्नीस सौ इकहत्तर में भारत-सोवियत मैत्री संधि संपन्न हुई। जुलाई उन्नीस सौ बहत्तर में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अंततः मई उन्नीस सौ चौहत्तर में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। यह कालक्रम दक्षिण एशिया की बदलती भू-राजनीति और भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति एवं कूटनीतिक सक्रियता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

42. (A) सच्ची गुटनिरपेक्ष नीति का पालन
उन्नीस सौ सतहत्तर में केंद्र में सत्तासीन हुई जनता पार्टी सरकार ने 'वास्तविक' या 'सच्ची' गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने का संकल्प व्यक्त किया था। सरकार का मानना था कि पिछली कांग्रेस सरकारों का झुकाव सोवियत संघ की ओर अधिक हो गया था। नई सरकार ने घोषणा की कि भारत किसी भी महाशक्ति के प्रति पक्षपाती नहीं रहेगा और सभी राष्ट्रों के साथ संतुलन एवं समानता के आधार पर अपने संबंध विकसित करेगा।

43. (D) भारत परमाणु हथियारों का प्रयोग केवल आत्मरक्षा में करेगा, लेकिन पहल नहीं करेगा।
भारत की परमाणु नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत 'पहले प्रयोग नहीं' (No First Use) है। इसका अर्थ यह है कि भारत किसी भी देश के विरुद्ध परमाणु हथियारों का उपयोग पहले नहीं करेगा और न ही गैर-परमाणु राष्ट्रों के खिलाफ इनका प्रयोग करेगा। यह नीति भारत के उत्तरदायी परमाणु शक्ति होने

ANSWERS

1. (B) वैश्विक और घरेलू दोनों सरोकारों का मिश्रण
भारत की विदेश नीति स्वतंत्रता के उपरांत अत्यंत जटिल वैश्विक परिस्थितियों में निर्मित हुई थी। इसमें नवस्वतंत्र राष्ट्र की संप्रभुता को बनाए रखने जैसे घरेलू उद्देश्यों और विश्व शांति को बढ़ावा देने जैसे वैश्विक लक्ष्यों का अनूठा समावेश देखने को मिलता है। तत्कालीन नेतृत्व ने देश के सर्वांगीण विकास हेतु संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए दोनों स्तरों पर सक्रिय भूमिका निभाई थी।

2. (A) अनुच्छेद 51
भारतीय संविधान का अनुच्छेद इक्यावन राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है। यह संवैधानिक प्रावधान राष्ट्रों के मध्य न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने पर बल देता है। साथ ही, यह अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए मध्यस्थता को प्रोत्साहित करता है, जो भारत की उदार और वैश्विक विदेश नीति का आधार है।

3. (A) P-3, Q-1, R-4, S-2
एशियाई संबंध सम्मेलन मार्च उन्नीस सौ सैंतालीस में आयोजित हुआ था। बांडुंग सम्मेलन उन्नीस सौ पचपन में संपन्न हुआ, जिसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन उन्नीस सौ इकसठ में बेलग्रेड में हुआ था। चीन ने तिब्बत पर कब्जा उन्नीस सौ पचास में किया था। ये सभी घटनाएँ शीतयुद्ध काल के दौरान भारत के महत्वपूर्ण विदेश नीति घटनाक्रम को दर्शाती हैं।

4. (A) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं।
भारत का उदय एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश में हुआ था जब संपूर्ण विश्व द्वितीय विश्वयुद्ध की भीषण तबाही से उबरने का प्रयास कर रहा था। पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास की समस्याएँ अत्यंत गंभीर थीं। इसी समय शीतयुद्ध के कारण दुनिया दो प्रतिद्वंद्वी गुटों में विभाजित हो रही थी, जिसने नवस्वतंत्र राष्ट्रों के सामने अपनी पहचान और हितों की रक्षा की चुनौती पेश की।

5. (C) केवल 1, 2 और 3
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति के तीन मुख्य स्तंभों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था। इसमें कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता का संरक्षण, देश की क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित रखना और तीव्र आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करना शामिल था। नेहरू ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु गुटनिरपेक्षता को एक साधन के रूप में अपनाया ताकि देश विकास के लिए स्वायत्त निर्णय ले सके।

6. (B) जवाहरलाल नेहरू
जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में देश की विदेश नीति की नींव रखी थी। उनके कार्यकाल के दौरान गुटनिरपेक्षता, पंचशील और एफ्रो-एशियाई एकता जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांत विकसित हुए। नेहरू का दृष्टिकोण न केवल भारत के राष्ट्रीय हितों पर आधारित था, बल्कि वह वैश्विक शांति और उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों में भी भारत को एक अग्रणी शक्ति बनाना चाहते थे।

7. (D) भारत ने सोवियत संघ के 'वारसा पैक्ट' सैन्य गठबंधन में शामिल होना स्वीकार किया।
भारत ने शीतयुद्ध के दौरान किसी भी महाशक्ति के सैन्य गठबंधन में शामिल न होने का सिद्धांत अपनाया था। वारसा पैक्ट सोवियत संघ के नेतृत्व वाला एक सैन्य गठबंधन था और भारत ने इसमें शामिल होने के बजाय गुटनिरपेक्षता की नीति का सक्रिय पालन किया। भारत का लक्ष्य दोनों वैश्विक गुटों से समान दूरी बनाए रखते हुए स्वतंत्र निर्णय लेना और विश्व में शांति स्थापित करना था।

8. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
उन्नीस सौ पचास के दशक में भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और सोवियत संघ के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण अमेरिका के साथ रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो गया था। इसी समय पाकिस्तान अमेरिका समर्थित सैन्य गठबंधनों का सदस्य बन गया था। इन परिस्थितियों ने दक्षिण एशिया में शीतयुद्ध की प्रतिद्वंद्विता को जन्म दिया, जिससे भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक दूरियाँ और भी बढ़ गई थीं।

9. (C) 1949
भारत ने जनवरी उन्नीस सौ उनचास में इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। यह कदम डच औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध इंडोनेशियाई जनता के अधिकारों को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाने के लिए उठाया गया था। यह आयोजन एशियाई और अफ्रीकी देशों की एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने वाला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था।

10. (A) 1, 2, 3, 4
ऐतिहासिक घटनाक्रम के अनुसार चीन ने उन्नीस सौ पचास में तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित किया। इसके पश्चात उन्नीस सौ चौवन में भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौते की घोषणा हुई। उन्नीस सौ उनसाठ में तिब्बती विद्रोह के बाद दलाई लामा ने भारत में शरण ली, जिससे तनाव बढ़ा। अंततः उन्नीस सौ बासठ

54. (B) लालबहादुर शास्त्री
उन्नीस सौ पैंसठ के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान लालबहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। उनके नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान की आक्रामकता का वीरतापूर्वक सामना किया और युद्ध के मैदान में अपनी सैन्य श्रेष्ठता सिद्ध की। शास्त्री जी ने 'जय जवान, जय किसान' का नारा देकर देश में एकता और मनोबल को बढ़ाया था। युद्ध के बाद उन्होंने शांति स्थापना के लिए ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

55. (A) 1, 2, 3, 4
चीन में कम्युनिस्ट क्रांति उन्नीस सौ उनचास में हुई थी। इसके पश्चात उन्नीस सौ पचपन में इंडोनेशिया के बांडुंग में एफ्रो-एशियाई सम्मेलन संपन्न हुआ। उन्नीस सौ छप्पन में स्वेज नहर संकट उत्पन्न हुआ जब ब्रिटेन ने मिस्र पर आक्रमण किया। अंततः उन्नीस सौ इकसठ में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित किया गया। यह कालक्रम शीतयुद्ध के दौरान उभरती हुई नई वैश्विक व्यवस्था के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं।

56. (A) खंडित जनादेश आया, जिसमें भुट्टो की पार्टी पश्चिमी पाकिस्तान में और मुजीब की पार्टी पूर्वी पाकिस्तान में जीती।
उन्नीस सौ सत्तर के पाकिस्तानी चुनावों के परिणाम अत्यंत विभाजनकारी थे। शेख मुजीबुर्रहमान की अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में प्रचंड जीत हासिल की, जबकि जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को केवल पश्चिमी पाकिस्तान में बहुमत मिला। इस भौगोलिक और राजनीतिक विभाजन ने पाकिस्तान में सत्ता संघर्ष को जन्म दिया, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तानी नेतृत्व पूर्वी पाकिस्तान के बहुमत को स्वीकार करने के लिए कतई तैयार नहीं था।

57. (C) किसी एक महाशक्ति के साथ सैन्य गठबंधन
पंचशील के पांच सिद्धांत शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और देशों के बीच आपसी सम्मान पर आधारित हैं। इसमें क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, गैर-आक्रामकता, आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप और समानता शामिल हैं। किसी भी महाशक्ति के साथ सैन्य गठबंधन बनाना पंचशील और गुटनिरपेक्षता की मूल भावना के सर्वथा विपरीत है। भारत ने हमेशा इन सिद्धांतों का पालन करते हुए सैन्य गुटबाजी से दूरी बनाए रखने की नीति का पुरजोर समर्थन किया है।

58. (A) नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (नेफा)
वर्तमान अरुणाचल प्रदेश को उन्नीस सौ बासठ के युद्ध के समय नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी या 'नेफा' के नाम से जाना जाता था। चीन ने इस दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र पर अपना दावा पेश करते हुए बड़े पैमाने पर सैन्य आक्रमण किया था। इस युद्ध ने नेफा क्षेत्र की सामरिक संवेदनशीलता को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया, जिसके बाद भारत सरकार ने इस क्षेत्र के प्रशासन और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए।

59. (D) 1, 2, 3, 4 सभी
भारत और चीन के संबंधों में तिब्बत का मुद्दा हमेशा से संवेदनशील रहा है। उन्नीस सौ चौवन में भारत ने तिब्बत पर चीन के नियंत्रण को स्वीकार किया, लेकिन दलाई लामा को शरण देने से दोनों देशों में कटुता बढ़ गई। युद्ध के बाद उन्नीस सौ छिहत्तर में राजनयिक संबंध सामान्य हुए और उन्नीस सौ अठासी में राजीव गांधी की चीन यात्रा ने सहयोग के नए द्वार खोले। ये सभी तथ्य द्विपक्षीय संबंधों के उतार-चढ़ाव को दर्शाते हैं।

60. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
स्वेज नहर संकट उन्नीस सौ छप्पन में हुआ था जब मिस्र पर आक्रमण किया गया। उसी वर्ष सोवियत संघ ने हंगरी में सैन्य हस्तक्षेप किया था। क्यूबा मिसाइल संकट उन्नीस सौ बासठ में वैश्विक परमाणु युद्ध के खतरे के रूप में उभरा। अरब-इजरायल युद्ध उन्नीस सौ तिहत्तर में लड़ा गया, जिसके बाद वैश्विक तेल संकट पैदा हुआ। ये घटनाएँ शीतयुद्ध काल की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय उथल-पुथल और चुनौतियों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

61. (C) अंतर्राष्ट्रीय विवादों की एक पूरी विरासत
भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के साथ-साथ कई अनसुलझे अंतर्राष्ट्रीय विवाद भी विरासत में मिले थे। इसमें सीमाओं का अस्पष्ट निर्धारण, कश्मीर का मुद्दा और शरणार्थियों की समस्या जैसी गंभीर चुनौतियाँ शामिल थीं। इन समस्याओं ने स्वतंत्र भारत की शुरुआती विदेश नीति को काफी हद तक प्रभावित किया। नए राष्ट्र को अपनी सीमाओं की रक्षा और पड़ोसियों के साथ जटिल संबंधों को संभालने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ा था।

62. (A) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं।
द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद स्वतंत्र हुए अनेक विकासशील देशों की विदेश नीतियां उनकी आर्थिक जरूरतों और सुरक्षा चिंताओं से प्रभावित थीं। इन देशों को पुनर्निर्माण के लिए विदेशी सहायता और कर्ज की आवश्यकता थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर शक्तिशाली राष्ट्रों के दबाव में निर्णय लेने पड़ते थे। भारत ने इस दबाव को महसूस करते हुए भी गुटनिरपेक्षता का मार्ग चुना ताकि वह अपनी स्वायत्तता और विकास के बीच संतुलन बनाए रख सके।

63. (A) डॉ. भीमराव अंबेडकर
स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति पर बहस के दौरान डॉ. भीमराव अंबेडकर जैसे कुछ नेताओं का मानना था कि भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले लोकतांत्रिक खेमे के साथ अधिक घनिष्ठ संबंध बनाने चाहिए। उनका तर्क था कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और सुरक्षा हितों के लिए पश्चिमी देशों का साथ अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। हालांकि, नेहरू के नेतृत्व में भारत ने अंततः गुटनिरपेक्षता की नीति को ही प्राथमिकता दी थी।

64. (B) Henry Kissinger
उन्नीस सौ इकहत्तर के बांग्लादेश संकट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर ने पाकिस्तान की सहायता से चीन की एक गोपनीय यात्रा की थी। इस गुप्त कूटनीति का उद्देश्य अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के बीच एक नया सामरिक गठबंधन बनाना था। इस घटनाक्रम ने दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को प्रभावित

105. (C) नैतिक समर्थन और भौतिक सहायता
उन्नीस सौ इकहत्तर में बांग्लादेश के 'मुक्ति संग्राम' के दौरान भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की जनता को हर संभव सहायता प्रदान की। भारत ने न केवल वैश्विक मंचों पर उनके संघर्ष को नैतिक समर्थन दिया, बल्कि शरणार्थियों के लिए भोजन और आश्रय जैसी भौतिक सहायता भी उपलब्ध कराई। इसके अतिरिक्त, भारत ने मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण और रसद भी प्रदान की। यह समर्थन मानवता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के उसके संकल्प का प्रतीक था।

106. (A) अणुशक्ति को शांतिपूर्ण उद्देश्यों में इस्तेमाल करने की क्षमता प्रदर्शित करने के लिए
भारत ने उन्नीस सौ चौहत्तर में पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण अपनी तकनीकी आत्मनिर्भरता और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक कदम के रूप में किया था। भारत का स्पष्ट उद्देश्य यह दिखाना था कि वह परमाणु तकनीक का उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों, जैसे बिजली उत्पादन और कृषि अनुसंधान, के लिए करने में सक्षम है। भारत ने इसे सैन्य हथियार बनाने की होड़ के बजाय वैज्ञानिक प्रगति और संप्रभु निर्णय लेने की अपनी क्षमता के प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुत किया था।

107. (D) राष्ट्रीय अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित
भारतीय राजनीति में विभिन्न दलों के बीच अनेक मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के मामले में एक व्यापक सहमति सदैव बनी रहती है। राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा, सीमाओं की सुरक्षा और वैश्विक मंचों पर भारत के हितों को प्राथमिकता देना ऐसे विषय हैं जहाँ सभी प्रमुख राजनीतिक दल एकजुट दिखाई देते हैं। यह एकता भारत की विदेश नीति को निरंतरता और वैश्विक स्तर पर विश्वसनीयता प्रदान करती है।

108. (A) 1 और 2
उन्नीस सौ बासठ से उन्नीस सौ इकहत्तर के बीच भारत को अपने दो पड़ोसी देशों, चीन और पाकिस्तान, के साथ सशस्त्र युद्धों का सामना करना पड़ा। उन्नीस सौ बासठ में चीन के साथ सीमा युद्ध हुआ, जबकि उन्नीस सौ पैंसठ और उन्नीस सौ इकहत्तर में पाकिस्तान के साथ संघर्ष हुए। इन युद्धों ने भारत की सामरिक प्राथमिकताओं को बदल दिया और रक्षा बजट में वृद्धि के साथ-साथ सैन्य आधुनिकीकरण की आवश्यकता को भी रेखांकित किया था।

109. (B) कथन 1 सत्य है, लेकिन कथन 2 असत्य है।
जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होने के साथ-साथ विदेश मंत्री का दायित्व भी संभाला था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों, जैसे गुटनिरपेक्षता और पंचशील, की रूपरेखा तैयार की थी। नेहरू का वैश्विक मामलों पर गहरा प्रभाव था और उनके नेतृत्व में ही भारत ने एफ्रो-एशियाई देशों के बीच अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। यह कहना कि उनकी कोई भूमिका नहीं थी, ऐतिहासिक तथ्यों के पूर्णतः विपरीत है।

110. (D) नातो (NATO) के गठन
उन्नीस सौ पचपन में सोवियत संघ के नेतृत्व में वारसा पैक्ट का गठन मुख्य रूप से पश्चिमी देशों के सैन्य गठबंधन 'नाटो' के जवाब में किया गया था। शीतयुद्ध के दौरान जब अमेरिका ने नाटो के माध्यम से अपनी सैन्य पहुंच बढ़ाई, तो सोवियत संघ ने भी अपने सहयोगी साम्यवादी देशों के साथ एक सामूहिक सुरक्षा संधि की। इस गठबंधन ने यूरोप को दो परस्पर विरोधी सैन्य शिविरों में विभाजित कर दिया, जिससे वैश्विक तनाव और अधिक बढ़ गया था।

111. (A) स्वेज नहर का मामला
उन्नीस सौ छप्पन में स्वेज नहर संकट तब उत्पन्न हुआ जब मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने इस रणनीतिक जलमार्ग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इससे ब्रिटेन और फ्रांस के व्यापारिक हितों को गंभीर खतरा पैदा हुआ। जवाब में ब्रिटेन, फ्रांस और इजरायल ने मिलकर मिस्र पर सैन्य आक्रमण कर दिया। भारत ने इस कार्रवाई को नव-औपनिवेशिक हमला करार देते हुए इसका कड़ा वैश्विक विरोध किया, जिससे स्वेज नहर मुद्दे पर भारत की कूटनीतिक प्रतिष्ठा विश्व स्तर पर बढ़ गई थी।

112. (D) 1, 2, 3, 4 सभी
स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक विदेश संबंधों का उद्देश्य विश्व शांति और नवस्वतंत्र राष्ट्रों की एकता को बढ़ावा देना था। भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेतृत्व के साथ-साथ एशियाई और अफ्रीकी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए। भारत ने इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया और दक्षिण अफ्रीका में जारी रंगभेद की अमानवीय नीति का पुरजोर विरोध किया। ये सभी कार्य भारत की न्यायपूर्ण और मानवतावादी विदेश नीति के आधारभूत तत्व रहे हैं।

113. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
उन्नीस सौ पचास में जब चीन ने तिब्बत पर अधिकार किया, तब भारत ने शुरू में इसे चीन का आंतरिक मामला मानकर मौन समर्थन दिया था। उन्नीस सौ चौवन के पंचशील समझौते में क्षेत्रीय संप्रभुता के सम्मान की बात कही गई थी, जिसका उपयोग चीन ने तिब्बत पर अपने ऐतिहासिक दावे को पुख्ता करने के लिए किया। भारत को लगा कि चीन के साथ मित्रता भविष्य में लाभकारी होगी, लेकिन बाद में तिब्बत के मुद्दे ने ही दोनों देशों के संबंधों में गंभीर तनाव उत्पन्न कर दिया।

114. (A) चीन भारत पर आक्रमण कर सकता है।
भारत के प्रथम उप-प्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल चीन की कम्युनिस्ट सरकार की विस्तारवादी नीतियां और तिब्बत में उनकी बढ़ती सैन्य गतिविधियों को लेकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू को पत्र लिखकर आगाह किया था कि चीन भविष्य में भारत के लिए एक बड़ा सुरक्षा खतरा बन सकता है और भारत पर आक्रमण कर सकता है। हालांकि, नेहरू का मानना था कि चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध संभव हैं, लेकिन सरदार पटेल की आशंका अंततः उन्नीस सौ बासठ में सही साबित हुई थी।

75. (A) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं।
उन्नीस सौ बासठ के युद्ध से पूर्व भारत ने अपनी सैन्य तैयारियों और रक्षा बजट पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया था, क्योंकि विश्वास था कि चीन आक्रमण नहीं करेगा। युद्ध में मिली विफलता ने सरकार को अपनी रक्षा नीति पर पुनर्विचार करने को मजबूर किया। इसके बाद रक्षा उत्पादन और आपूर्ति के लिए अलग विभागों की स्थापना की गई ताकि भविष्य में किसी भी सैन्य चुनौती का मुकाबला करने के लिए देश आत्मनिर्भर बन सके।

76. (B) अटल बिहारी वाजपेयी
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने के लिए 'बस डिप्लोमेसी' की शुरुआत की गई थी। फरवरी उन्नीस सौ निन्यानवे में उन्होंने दिल्ली से लाहौर तक की बस यात्रा की और पाकिस्तान के साथ लाहौर घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। यह पहल दोनों देशों के बीच जनता के स्तर पर संपर्क बढ़ाने और शांतिपूर्ण संवाद स्थापित करने का एक ऐतिहासिक और साहसी प्रयास माना जाता है।

77. (C) चीन की सेनाओं ने विद्रोह को दबा दिया।
उन्नीस सौ अट्ठावन में तिब्बत में चीनी शासन के विरुद्ध एक व्यापक सशस्त्र विद्रोह हुआ था। चीन ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए अपनी विशाल सैन्य शक्ति का प्रयोग किया और तिब्बत पर अपना नियंत्रण और भी कड़ा कर लिया। इस दमनकारी कार्रवाई के कारण वहां की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान संकट में पड़ गई, जिसके परिणामस्वरूप दलाई लामा और हज़ारों तिब्बती शरणार्थियों को अपनी मातृभूमि छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी थी।

78. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
भारत ने हमेशा परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) और व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) का विरोध किया है। भारत का मुख्य तर्क यह रहा है कि ये संधियाँ 'परमाणु रंगभेद' को बढ़ावा देती हैं, जहाँ कुछ चुनिंदा देशों को हथियार रखने की अनुमति है जबकि अन्यों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। भारत एक ऐसे निशस्त्रीकरण का पक्षधर है जो सार्वभौमिक हो और जिसमें सभी राष्ट्रों पर समान नियम लागू हों, न कि भेदभावपूर्ण।

79. (A) मार्च 1947, आजादी से पांच महीने पहले
भारत ने अपनी औपचारिक स्वतंत्रता से लगभग पांच महीने पूर्व, मार्च उन्नीस सौ सैंतालीस में 'एशियाई संबंध सम्मेलन' का आयोजन किया था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आयोजित यह सम्मेलन एशिया की एकता और नवस्वतंत्र राष्ट्रों के बीच सहयोग स्थापित करने का पहला बड़ा प्रयास था। इस आयोजन ने यह स्पष्ट कर दिया कि स्वतंत्र भारत वैश्विक राजनीति, विशेषकर एशियाई मामलों में, एक अग्रणी और सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

80. (D) 1, 2, 3, 4 सभी
उन्नीस सौ पैंसठ का युद्ध पाकिस्तान द्वारा कच्छ के रन में किए गए हमले से शुरु हुआ था। पाकिस्तान की योजना कश्मीर में विद्रोह भड़काने की थी, जो विफल रही। जवाब में प्रधानमंत्री शास्त्री ने पंजाब सीमा से लाहौर की ओर आक्रमण का आदेश देकर युद्ध का रुख पलट दिया। अंततः संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से युद्धविराम हुआ, जिसके बाद दोनों देशों के बीच शांति बहाली के लिए ऐतिहासिक ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

81. (B) हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला शहर, विशेषकर मैकलोडगंज, तिब्बती शरणार्थियों का प्रमुख केंद्र और दलाई लामा का आधिकारिक निवास स्थान है। उन्नीस सौ उनसाठ में चीन से पलायन के बाद, भारत सरकार ने तिब्बती समुदाय को यहां अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों को संरक्षित करने की अनुमति दी। आज यह स्थान तिब्बती निर्वासित सरकार का मुख्यालय भी है और वैश्विक स्तर पर तिब्बती संस्कृति एवं शांति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया है।

82. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
जवाहरलाल नेहरु ने चीन के साथ पंचशील समझौते के माध्यम से शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का आधार रखा। लालबहादुर शास्त्री के कार्यकाल में उन्नीस सौ पैंसठ के युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुआ। इंदिरा गांधी ने उन्नीस सौ इकहत्तर की जीत के पश्चात शिमला समझौते के जरिए पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित की। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए कारगिल संघर्ष हुआ, जिसमें भारत ने अपनी सीमाओं की सफलतापूर्वक रक्षा की थी।

83. (C) मुक्ति संग्राम
उन्नीस सौ इकहत्तर में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान के सैन्य शासन और शोषण के विरुद्ध किए गए संघर्ष को 'मुक्ति संग्राम' के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन का नेतृत्व शेख मुजीबुर्रहमान की अवामी लीग और उनकी सैन्य शाखा 'मुक्ति वाहिनी' ने किया था। भारत ने इस संग्राम को नैतिक और सैन्य समर्थन प्रदान किया, जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान की पराजय हुई और बांग्लादेश एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में विश्व मानचित्र पर उभरा।

84. (D) भारत और पाकिस्तान पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए, जिन्हें बाद में हटा लिया गया।
मई उन्नीस सौ अट्ठानवे में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों के जवाब में पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंतित हो गया। अमेरिका सहित कई विकसित देशों ने भारत और पाकिस्तान दोनों पर कड़े आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए। हालांकि, भारत के प्रभावी कूटनीतिक प्रयासों और उसकी सामरिक महत्ता को देखते हुए, समय के साथ इन प्रतिबंधों में ढील दी गई और अंततः इन्हें पूरी तरह से हटा लिया गया था।

भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती थी, जिसने अंततः भारत को इस संकट में सीधे हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया था।

125. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
उन्नीस सौ इकहत्तर में बांग्लादेश संकट के गहराने के समय अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान का खुला समर्थन करना शुरु कर दिया था। इस त्रिगुटीय धुरी के कारण भारत को अपनी सुरक्षा के प्रति गहरी चिंता हुई। ऐसे में कूटनीतिक संतुलन बनाने और सामरिक आश्वासन प्राप्त करने के लिए भारत ने सोवियत संघ के साथ बीस वर्षीय मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि ने भारत को युद्ध की स्थिति में एक महाशक्ति का निश्चित समर्थन सुनिश्चित कर सुरक्षा प्रदान की थी।

126. (D) इसने भारत के भीतर परमाणु विकल्प को खुला रखने की बहस को बल दिया।
अक्टूबर उन्नीस सौ चौंसठ में चीन द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने की घटना ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को वैश्विक स्तर पर बढ़ा दिया। पड़ोस में एक परमाणु शक्ति संपन्न शत्रु राष्ट्र के उदय ने भारत के नीति-निर्धारकों और रणनीतिकारों को अपनी परमाणु नीति पर पुनर्विचार करने को मजबूर किया। इस घटना के बाद देश के भीतर यह बहस तीव्र हो गई कि भारत को अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए परमाणु हथियार बनाने का विकल्प खुला रखना चाहिए, जो अंततः परमाणु कार्यक्रम की प्रगति का कारण बना।

127. (C) 1, 2 और 3
जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के लिए जो विदेश नीति तैयार की थी, उसके तीन मुख्य लक्ष्य थे। प्रथम, अत्यंत कठिन संघर्ष से प्राप्त राष्ट्र की संप्रभुता को हर हाल में सुरक्षित रखना। द्वितीय, देश की क्षेत्रीय अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना ताकि कोई बाहरी शक्ति सीमाओं का उल्लंघन न कर सके। तृतीय, नवस्वतंत्र देश के तीव्र आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वैश्विक वातावरण तैयार करना। गुटनिरपेक्षता इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन मात्र थी।

128. (B) 1962 के भारत-चीन युद्ध में भारत की जीत के बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ गई।
वी. के. कृष्णमेनन नेहरू के करीबी सहयोगी और कुशल कूटनीतिज्ञ थे, लेकिन उन्नीस सौ बासठ के भारत-चीन युद्ध ने उनकी छवि को गहरा आघात पहुँचाया। युद्ध में भारत की शर्मनाक पराजय के बाद देश में उनके विरुद्ध व्यापक रोष उत्पन्न हुआ और उन पर रक्षा तैयारियों की अनदेखी करने के आरोप लगे। इसके परिणामस्वरूप उनकी लोकप्रियता बढ़ने के बजाय तेजी से गिरी और उन्हें जन दबाव एवं राजनीतिक आलोचना के कारण अंततः रक्षा मंत्री के पद से त्यागपत्र देना पड़ा था।

129. (D) 1, 2, 3, 4 और 5 सभी
भारत और पाकिस्तान के संबंध स्वतंत्रता के समय से ही संघर्षों और कूटनीतिक प्रयासों के बीच झूलते रहे हैं। उन्नीस सौ सैंतालीस में कश्मीर को लेकर प्रथम युद्ध हुआ, जिसके बाद उन्नीस सौ साठ में सिंधु जल संधि हुई। उन्नीस सौ पैंसठ के युद्ध के बाद ताशकंद और उन्नीस सौ इकहत्तर के बाद शिमला समझौते हुए। अंततः उन्नीस सौ निन्यानवे में कारगिल संघर्ष हुआ। ये सभी घटनाएँ दोनों देशों के बीच तनाव, युद्ध और शांति वार्ताओं के निरंतर चलते रहे चक्र को दर्शाती हैं।

130. (A) यह माना गया कि भारत सोवियत खेमे में शामिल हो गया है।
उन्नीस सौ इकहत्तर में भारत-सोवियत मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विशेषकर पश्चिमी देशों में, इसकी व्याख्या भारत द्वारा अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति के त्याग के रूप में की गई। आलोचकों का मानना था कि भारत अब औपचारिक रूप से सोवियत खेमे का हिस्सा बन गया है। हालांकि, भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया कि यह संधि केवल द्विपक्षीय सहयोग के लिए है और भारत की स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

131. (C) भारत और पाकिस्तान दोनों पर
मई उन्नीस सौ अट्ठानवे में भारत द्वारा पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षणों के तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी चगाई की पहाड़ियों में परमाणु परीक्षण किए। इन घटनाओं से दक्षिण एशिया में परमाणु हथियारों की होड़ शुरु होने का खतरा पैदा हो गया। जवाब में अमेरिका और अन्य विकसित देशों ने भारत और पाकिस्तान दोनों पर कड़े आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य दोनों देशों को परमाणु हथियारों के विकास से हतोत्साहित करना और वैश्विक परमाणु अप्रसार व्यवस्था को मजबूत करना था।

132. (A) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं।
उन्नीस सौ सत्तर के दशक का मध्य भारत के लिए आंतरिक और बाह्य दोनों मोर्चों पर अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। वैश्विक स्तर पर उन्नीस सौ तिहत्तर के तेल संकट ने देश की अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया था, जिससे महंगाई बेकाबू हो गई। घरेलू स्तर पर सरकार विरोधी आंदोलनों और राजनीतिक अस्थिरता ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। इन परिस्थितियों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने शासन और विदेश नीति, दोनों स्तरों पर कड़े फैसले लेने की मजबूरी पैदा कर दी थी।

133. (C) पार्टी सोवियत और चीन समर्थक गुटों में विभाजित हो गई।
उन्नीस सौ बासठ के भारत-चीन युद्ध ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के भीतर वैचारिक मतभेदों को चरम पर पहुँचा दिया। पार्टी के भीतर एक गुट का मानना था कि भारत को चीन के विरुद्ध अपनी रक्षा करनी चाहिए और सोवियत संघ का साथ देना चाहिए। वहीं दूसरा गुट चीन की क्रांतिकारी विचारधारा के प्रति सहानुभूति रखता था। इन परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों के कारण पार्टी में दरार आ गई, जिसके परिणामस्वरूप अंततः उन्नीस सौ चौंसठ में पार्टी दो अलग-अलग दलों में विभाजित हो गई थी।

95. (B) केवल 1, 2 और 4
भारत की विदेश नीति के प्राथमिक लक्ष्यों में सभी राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान करना और शांतिपूर्ण वातावरण में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। ये लक्ष्य घरेलू और वैश्विक परिस्थितियों के प्रभाव में नेहरु द्वारा निर्धारित किए गए थे। हालांकि, इन नीतियों की स्पष्ट प्रतिध्वनि संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धांतों में मिलती है, न कि प्रत्यक्ष रूप से मौलिक अधिकारों में। भारत ने हमेशा इन आदर्शों के माध्यम से विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है।

96. (A) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं।
उन्नीस सौ साठ के दशक में हुए युद्धों ने भारत के आर्थिक नियोजन पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डाला। देश को अपनी विकास प्राथमिकताओं को बदलकर रक्षा बजट में भारी वृद्धि करनी पड़ी। इसके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रही और सरकार को दीर्घकालिक योजना के बजाय तीन वर्षों तक वार्षिक योजनाओं का सहारा लेना पड़ा। इस आर्थिक संकट ने देश की विकास दर को कुछ समय के लिए धीमा कर दिया था।

97. (B) राजीव गांधी
उन्नीस सौ बासठ के युद्ध के बाद भारत और चीन के बीच उत्पन्न हुए लंबे गतिरोध को तोड़ने की दिशा में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्नीस सौ अठासी में चीन की ऐतिहासिक यात्रा की। नेहरु के बाद चीन जाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे। उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संवाद का नया दौर शुरु हुआ और सीमा विवाद को सुलझाने के साथ-साथ आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी, जो भविष्य के संबंधों का आधार बनी।

98. (A) नवाज शरीफ
उन्नीस सौ निन्यानवे के कारगिल संघर्ष के दौरान नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। हालांकि, बाद में यह स्पष्ट हुआ कि कारगिल की घुसपैठ की योजना मुख्य रूप से पाकिस्तानी सेना के तत्कालीन प्रमुख परवेज मुशर्रफ द्वारा शरीफ को पूर्ण विश्वास में लिए बिना बनाई गई थी। इस युद्ध के कारण पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक अलग-थलग होना पड़ा और वहां की लोकतांत्रिक सरकार और सेना के बीच मतभेद और भी गहरे हो गए थे।

99. (C) जम्मू-कश्मीर का विलय
भारत और पाकिस्तान के बीच उन्नीस सौ सैंतालीस-अड़तालीस का प्रथम संघर्ष मुख्य रूप से जम्मू-कश्मीर के विलय को लेकर हुआ था। विभाजन के तत्काल बाद पाकिस्तानी कबायलियों ने कश्मीर पर आक्रमण किया, जिसके बाद वहां के महाराजा ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारतीय सेना ने आक्रमणकारियों को खदेड़ा, लेकिन संघर्ष के परिणामस्वरूप राज्य का एक हिस्सा पाकिस्तान के अवैध नियंत्रण में चला गया, जो आज भी दोनों देशों के बीच मुख्य विवाद है।

100. (A) P-2, Q-4, R-3, S-1
ताशकंद समझौते पर भारत के प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। यह संधि उन्नीस सौ पैंसठ के युद्ध के बाद सोवियत मध्यस्थता में हुई थी। इसके विपरीत, शिमला समझौते पर उन्नीस सौ इकहत्तर के युद्ध के पश्चात भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए। ये दोनों संधियाँ दक्षिण एशिया में युद्ध के बाद शांति बहाली के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज हैं।

101. (C) 3 जुलाई, 1972
शिमला समझौते पर तीन जुलाई उन्नीस सौ बहत्तर को हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता उन्नीस सौ इकहत्तर के युद्ध में भारत की विजय और बांग्लादेश के निर्माण के बाद हुआ था। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस ऐतिहासिक संधि के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि दोनों देश भविष्य में किसी भी विवाद को द्विपक्षीय स्तर पर बातचीत से सुलझाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक-दूसरे के विरुद्ध सैन्य बल का प्रयोग नहीं करेंगे।

102. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
उन्नीस सौ सतहत्तर में सत्ता में आई जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार का झुकाव सोवियत संघ की ओर अधिक था, जिससे गुटनिरपेक्षता की मूल भावना प्रभावित हुई थी। नई सरकार ने 'सच्ची गुटनिरपेक्षता' का नारा दिया, जिसका उद्देश्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों महाशक्तियों के साथ समान और संतुलित संबंध बनाए रखना था। इस नीति के माध्यम से भारत ने वैश्विक राजनीति में अपनी पूर्ण तटस्थता और स्वायत्तता को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया था।

103. (B) केवल 1, 2, 3 और 4
गुटनिरपेक्षता का अर्थ किसी सैन्य गुट में शामिल न होना और स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना है। यह सभी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने और वैश्विक मुद्दों पर निष्पक्ष विचार करने पर बल देता है। हालांकि, इसका अर्थ दुनिया से 'अलग-थलग' रहना या तटस्थता नहीं है। भारत ने गुटनिरपेक्षता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों में सक्रिय भूमिका निभाई, जो अलगाववाद के विचार के सर्वथा विपरीत है।

104. (A) संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ के प्रभाव वाले खेमे
द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद विश्व दो प्रमुख शक्ति केंद्रों, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, के बीच विभाजित हो गया था। इस दौर को शीतयुद्ध कहा जाता है, जहाँ अधिकांश देश अपनी वैचारिक और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार किसी एक गुट में शामिल हो रहे थे। अमेरिका ने नाटो के माध्यम से पश्चिमी देशों को संगठित किया, जबकि सोवियत संघ ने वारसा पैक्ट के जरिए पूर्वी खेमे का नेतृत्व किया, जिससे वैश्विक तनाव निरंतर बना रहा।

144. (D) 1, 2, 3, 4 और 5 सभी
भारत की शुरुआती विदेश नीति अनेक वैश्विक और आंतरिक दबावों के बीच आकार ले रही थी। द्वितीय विश्वयुद्ध की तबाही, ब्रिटिश शासन द्वारा छोड़े गए सीमा विवाद और विभाजन की विभीषिका ने प्रारंभिक वर्षों को कठिन बना दिया था। साथ ही, घरेलू स्तर पर व्यापक गरीबी और वैश्विक स्तर पर शीतयुद्ध की प्रतिद्वंद्विता ने भारत के सामने अपनी संप्रभुता को बचाने की बड़ी चुनौती पेश की। इन सभी कारकों ने नेहरू को एक संतुलित और शांतिपूर्ण विदेश नीति अपनाने के लिए प्रेरित किया।

145. (B) भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए।
भारत की परमाणु नीति के संबंध में यह कथन असत्य है क्योंकि भारत ने उन्नीस सौ अड़सठ की परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए। भारत ने इस संधि को भेदभावपूर्ण माना क्योंकि यह केवल कुछ राष्ट्रों को परमाणु हथियार रखने की अनुमति देती थी। हालांकि, नेहरू निशस्त्रीकरण के पक्षधर थे और भारत ने होमी भाभा के नेतृत्व में परमाणु कार्यक्रम शुरू किया। उन्नीस सौ चौहत्तर के परीक्षण को हमेशा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए की गई वैज्ञानिक उपलब्धि बताया गया था।

146. (A) शेख मुजीबुर्रहमान
अवामी लीग के प्रमुख नेता शेख मुजीबुर्रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान में स्वायत्तता और लोकतंत्र के लिए संघर्ष का नेतृत्व किया था। उन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता माना जाता है। उन्नीस सौ इकहत्तर के युद्ध के पश्चात, जब पाकिस्तान ने उन्हें जेल से रिहा किया, तब वे स्वतंत्र बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बने। उनकी दूरदर्शी राजनीति और मुक्ति संग्राम में उनके अदम्य योगदान ने ही एक नए राष्ट्र के निर्माण को संभव बनाया, जिसे भारत ने पूर्ण कूटनीतिक और सैन्य समर्थन दिया था।

147. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
गमाल अब्दुल नासिर मिस्र के राष्ट्रपति थे और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। क्वामे एनक्रूमा घाना के स्वतंत्रता सेनानी और अग्रणी नेता थे। सुकर्णो इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने बांडुंग सम्मेलन की मेजबानी की थी। जोसिप ब्रोज़ टीटो यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे और उन्होंने नेहरू के साथ मिलकर गुटनिरपेक्षता की अवधारणा को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाया। इन नेताओं की सामूहिक दूरदर्शिता ने शीतयुद्ध के दौर में तीसरी दुनिया को एकजुट किया।

148. (D) विश्व बैंक
भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल बंटवारे को लेकर उत्पन्न हुए गंभीर विवाद को सुलझाने में विश्व बैंक (तत्कालीन आई.बी.आर.डी.) ने मध्यस्थ की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लगभग एक दशक तक चली लंबी और जटिल वार्ता के बाद, उन्नीस सौ साठ में सिंधु जल संधि संपन्न हुई। यह संधि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का एक सफल उदाहरण है, जो दोनों देशों के बीच अनेक युद्धों के बावजूद आज भी सुचारु रूप से प्रभावी और कार्यान्वित है।

149. (C) भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी
उन्नीस सौ पचास और साठ के दशकों में भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी ने नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति की आलोचना करते हुए भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अधिक घनिष्ठ सामरिक संबंध बनाने का सुझाव दिया था। उनका मानना था कि साम्यवादी चीन और सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के साथ गठबंधन भारत की सुरक्षा के लिए अपरिहार्य है। ये दल आर्थिक उदारीकरण और पश्चिमी लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते थे।

150. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति उसके घरेलू संसाधनों, विकास की आवश्यकताओं और तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय परिवेश के समन्वय से निर्धारित होती है। विकासशील देशों के लिए यह चुनौती और भी बड़ी होती है क्योंकि उनके पास अक्सर संसाधनों और तकनीक की कमी होती है, जिससे उन्हें अपनी विकास योजनाओं के लिए विकसित देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह निर्भरता कभी-कभी उनकी विदेश नीति के स्वतंत्र संचालन को प्रभावित करती है, जैसा कि शीतयुद्ध के दौरान कई नवस्वतंत्र राष्ट्रों के साथ हुआ था।

151. (B) उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्ष और शांतिवादी परंपराएं
स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति के आधार के रूप में गुटनिरपेक्षता को चुना। इसका मुख्य वैचारिक आधार भारत का लंबे समय तक चला उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्ष और उसकी प्राचीन शांतिवादी परंपराएं थीं। यह नीति भारत को किसी भी सैन्य गुट में शामिल हुए बिना अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने और वैश्विक स्तर पर शांति को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करती थी।

152. (A) अंतरराष्ट्रीय मामलों पर स्वतंत्र और हित-आधारित निर्णय लेने की क्षमता
रणनीतिक स्वायत्तता का अर्थ अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अपनी निर्णय लेने की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना है। इसका उद्देश्य किसी बाहरी महाशक्ति के दबाव में आए बिना राष्ट्रीय हितों और न्याय के सिद्धांतों के आधार पर स्वतंत्र रुख अपनाना था। यह नीति भारत को वैश्विक मुद्दों पर निष्पक्ष रहने और अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम बनाती है, जो उसकी विदेश नीति का मूल है।

153. (C) इसने दोनों शक्ति गुटों से आर्थिक और तकनीकी सहायता प्राप्त करना संभव बनाया।
गुटनिरपेक्षता की नीति ने भारत के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक अवसर प्रदान किया। किसी एक गुट का पक्ष न लेने के कारण, भारत के लिए शीत युद्ध के दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों से आर्थिक और तकनीकी सहायता प्राप्त करना संभव हो गया। यह रणनीति भारत जैसे नव-स्वतंत्र राष्ट्र के औद्योगिक और कृषि विकास के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाने में अत्यधिक सहायक सिद्ध हुई।

115. (C) लद्दाख
अक्साई-चीन का क्षेत्र भौगोलिक रूप से लद्दाख का हिस्सा है, जो भारत के सुदूर उत्तर में स्थित है। उन्नीस सौ पचास के दशक में चीन ने इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और निर्जन क्षेत्र पर चुपके से कब्जा कर लिया और वहां एक सामरिक सड़क का निर्माण किया। भारत को इस घुसपैठ का पता काफी बाद में चला, जिससे दोनों देशों के बीच गहरा सीमा विवाद पैदा हुआ। आज भी यह क्षेत्र चीन के अवैध नियंत्रण में है और भारत-चीन तनाव का मुख्य केंद्र बना हुआ है।

116. (D) लाहौर
उन्नीस सौ पैंसठ के युद्ध के दौरान, भारतीय सेना ने पाकिस्तान की आक्रामकता का जवाब देते हुए पंजाब सीमा पर एक बड़ा जवाबी हमला किया था। भारतीय सैनिक अदम्य साहस दिखाते हुए अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर गए और पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर लाहौर के काफी नजदीक तक पहुँच गए थे। इस रणनीतिक बढ़त ने पाकिस्तान की सैन्य योजनाओं को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और उसे युद्धविराम के लिए मजबूर होने पर विवश किया, जिससे भारत का सामरिक पलड़ा भारी रहा।

117. (C) 90,000
उन्नीस सौ इकहत्तर के युद्ध का समापन एक ऐतिहासिक सैन्य आत्मसमर्पण के साथ हुआ था। ढाका के पतन के बाद, पाकिस्तानी सेना के जनरल ए.ए.के. नियाज़ी ने अपने लगभग नब्बे हज़ार सैनिकों के साथ भारतीय सैन्य नेतृत्व के समक्ष हथियार डाल दिए थे। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद यह विश्व का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। इस निर्णायक विजय ने न केवल दक्षिण एशिया का मानचित्र बदल दिया, बल्कि भारत को इस क्षेत्र की एक अजेय सामरिक शक्ति के रूप में भी स्थापित कर दिया था।

118. (B) भारत वैश्विक स्तर पर लागू और भेदभाव रहित परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है।
भारत की परमाणु नीति का मूल आधार वैश्विक शांति और समान सुरक्षा है। भारत ने हमेशा यह तर्क दिया है कि परमाणु निशस्त्रीकरण तभी सफल हो सकता है जब यह भेदभाव रहित हो और सभी राष्ट्रों पर समान रूप से लागू हो। भारत ने अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परमाणु हथियार विकसित किए हैं, लेकिन साथ ही वह एक परमाणु-मुक्त विश्व के निर्माण की दिशा में ठोस और न्यायसंगत वैश्विक प्रयासों का निरंतर समर्थन करता है।

119. (A) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं।
उन्नीस सौ नब्बे के दशक में सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति को नए सिरे से परिभाषित किया। शीतयुद्ध की समाप्ति के कारण रणनीतिक प्राथमिकताओं में सैन्य शक्ति के स्थान पर आर्थिक विकास और व्यापार को अधिक महत्व दिया जाने लगा। भारत ने इस बदलते परिवेश में अमेरिका और अन्य वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के साथ सहयोग बढ़ाया। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य वैश्वीकरण के दौर में भारत के आर्थिक हितों को सुरक्षित करना और राष्ट्र की प्रगति को गति देना था।

120. (A) अटल बिहारी वाजपेयी
उन्नीस सौ बासठ के युद्ध के बाद भारत-चीन संबंधों में लंबे समय तक शीतलता बनी रही थी। इस गतिरोध को तोड़ने के लिए उन्नीस सौ छिहत्तर में राजनयिक संबंध बहाल किए गए। इसके पश्चात उन्नीस सौ उनासी में तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्रा की, जो रिश्तों में सुधार की दिशा में एक साहसी कदम था। हालांकि, प्रधानमंत्री के रूप में नेहरु के बाद चीन जाने वाले पहले नेता राजीव गांधी थे, लेकिन संबंधों को पुनः प्रारंभ करने में वाजपेयी की भूमिका महत्वपूर्ण थी।

121. (B) 2 और 3
उन्नीस सौ पचास और साठ के दशकों में भारत में सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय जनसंघ जैसे राजनीतिक दलों ने तिब्बत की स्वतंत्रता और वहां की स्वायत्तता का पुरजोर समर्थन किया था। इन दलों का मानना था कि तिब्बत पर चीन का कब्जा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। उन्होंने नेहरु सरकार की इस नीति की कड़ी आलोचना की थी कि भारत ने तिब्बत पर चीन के दावे को इतनी सहजता से स्वीकार कर लिया, जो बाद में सीमा विवाद का कारण बना।

122. (A) 1976
उन्नीस सौ बासठ के युद्ध के बाद भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंध निम्न स्तर पर पहुँच गए थे। कई वर्षों के तनाव और चुप्पी के बाद, दोनों देशों ने अंततः उन्नीस सौ छिहत्तर में पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने और राजदूतों के आदान-प्रदान का निर्णय लिया। यह कदम द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक नई शुरुआत थी, जिससे भविष्य में सीमा विवाद और आर्थिक सहयोग पर बातचीत के मार्ग प्रशस्त हुए और तनाव में कमी आई थी।

123. (A) P-1, Q-3, R-2, S-4
गुटनिरपेक्षता भारत की विदेश नीति की आधारशिला रही है, जिसने शीतयुद्ध के दौरान देश की स्वायत्तता को सुरक्षित रखा। पंचशील भारत और चीन के बीच शुरुआती संबंधों को परिभाषित करने वाला मुख्य सिद्धांत था। रंगभेद का विरोध भारत की अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का हिस्सा रहा है, विशेषकर दक्षिण अफ्रीका के मामले में। परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए भारत ने हमेशा वैश्विक मंचों पर सार्वभौमिक और न्यायसंगत नियमों की मांग की है, जो उसके शांतिवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है।

124. (B) 80 लाख शरणार्थियों का भारत में आगमन
उन्नीस सौ इकहत्तर के बांग्लादेश संकट के दौरान पाकिस्तान की दमनकारी सैन्य कार्रवाई के कारण पूर्वी पाकिस्तान से लगभग अस्सी लाख लोग अपनी जान बचाकर भारत भाग आए। इतनी बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आगमन ने भारत के सामने एक अभूतपूर्व मानवीय और आर्थिक संकट उत्पन्न कर दिया। इन शरणार्थियों को भोजन, स्वास्थ्य और आश्रय प्रदान करना

85. (C) कथन 1 असत्य है, लेकिन कथन 2 सत्य है।
हालांकि भारत ने शांतिपूर्ण विदेश नीति का लक्ष्य रखा था, लेकिन वह अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों से पूरी तरह अछूता नहीं रह सका। उन्नीस सौ पचास और साठ के दशकों में भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ दो बड़े युद्धों का सामना करना पड़ा। इन सैन्य संघर्षों ने भारत की शांतिप्रिय छवि के सामने गंभीर सुरक्षा चुनौतियां पेश कीं और सिद्ध किया कि पड़ोसी देशों के साथ विवाद राष्ट्र की विकास यात्रा में बड़ी बाधा बन सकते हैं।

86. (B) पश्चिमी और पूर्वी
भारत और चीन के बीच सीमा विवाद मुख्य रूप से दो भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित है। पश्चिमी छोर पर लद्दाख का अक्साई-चीन क्षेत्र है, जिस पर चीन ने उन्नीस सौ पचास के दशक में सड़क बनाकर कब्जा कर लिया था। पूर्वी छोर पर अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है। इन दोनों क्षेत्रों में विवादित वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) आज भी दोनों देशों के मध्य तनाव का एक प्रमुख और अनसुलझा कारण बनी हुई है।

87. (D) 1, 2, 3, 4 और 5 सभी
उन्नीस सौ नब्बे के बाद भारत की विदेश नीति में व्यापक बदलाव आए, जिसमें आर्थिक हितों को प्राथमिकता दी गई और अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत किया गया। सोवियत संघ के पतन के बावजूद रूस एक विश्वसनीय मित्र बना रहा। भारत ने पाकिस्तान के साथ शांति के अनेक प्रयास किए, लेकिन कारगिल युद्ध ने सुरक्षा चुनौतियों को पुनः उजागर किया। ये सभी तथ्य बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की संतुलित और यथार्थवादी विदेश नीति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं।

88. (A) असम
उन्नीस सौ बासठ के युद्ध के दौरान चीनी सेना ने पूर्वी मोर्चे पर तेजी से बढ़त हासिल की थी। वे अरुणाचल प्रदेश (नेफा) को पार करते हुए असम के मैदानी इलाकों के प्रवेश द्वार, तेजपुर के अत्यंत निकट तक पहुँच गए थे। इस अप्रत्याशित और तीव्र सैन्य घुसपैठ ने पूरे देश में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया था। हालांकि, इसके तुरंत बाद चीन ने एकतरफा युद्धविराम की घोषणा कर दी और अपनी सेनाएँ पीछे हटा ली थीं।

89. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
उन्नीस सौ चौंसठ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू राजनीतिक संकटों का प्रत्यक्ष परिणाम था। चीन और सोवियत संघ के बीच वैचारिक मतभेद बढ़ रहे थे, जिसका असर भारतीय कम्युनिस्टों पर भी पड़ा। उन्नीस सौ बासठ के युद्ध ने इस तनाव को और गहरा कर दिया, क्योंकि पार्टी का एक धड़ा चीन के प्रति सहानुभूति रखता था। इन परिस्थितियों ने अंततः पार्टी को दो स्पष्ट विचारधाराओं वाले दलों में विभाजित कर दिया था।

90. (A) अरब राष्ट्रों
उन्नीस सौ तिहत्तर के अरब-इजरायल युद्ध के बाद, अरब तेल उत्पादक राष्ट्रों ने तेल की कीमतों में भारी वृद्धि कर दी और उत्पादन में कटौती की। इस वैश्विक ऊर्जा संकट ने भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को बुरी तरह प्रभावित किया। देश में आयात बिल बढ़ गया, जिससे मुद्रास्फीति और आर्थिक संकट पैदा हुआ। इस घटना ने भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के प्रति सचेत किया और अरब जगत के साथ कूटनीतिक संबंधों के महत्व को और अधिक बढ़ा दिया।

91. (D) केंद्र-शासित प्रदेश रहते हुए उन्हें अपनी विधानसभा निर्वाचन का विशेष अधिकार मिला।
उन्नीस सौ साठ के दशक में पूर्वोत्तर भारत के प्रशासनिक पुनर्गठन के दौरान नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके विपरीत, मणिपुर और त्रिपुरा को प्रारंभिक रूप से केंद्र-शासित प्रदेश के रूप में रखा गया, लेकिन उन्हें अपनी विधानसभा निर्वाचित करने का महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किया गया। यह कदम इन क्षेत्रों की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने और स्थानीय लोकतांत्रिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक संतुलित निर्णय था।

92. (C) P-1, Q-4, R-2, S-3
जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी ने उन्नीस सौ सत्तर में पश्चिमी पाकिस्तान में जीत हासिल की थी। शेख मुजीबुर्रहमान अवामी लीग के प्रमुख नेता थे जिन्होंने पूर्वी पाकिस्तान की स्वायत्तता के लिए संघर्ष किया। स्वतंत्र पार्टी भारत में अमेरिका के साथ निकट संबंधों की पक्षधर थी। वी. के. कृष्णमेनन ने उन्नीस सौ सत्तावन से देश के रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। ये सभी व्यक्तित्व उस दौर की दक्षिण एशियाई राजनीति के मुख्य सूत्रधार थे।

93. (C) 1970 के दशक में
उन्नीस सौ सत्तर के दशक की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच संबंधों का सामान्य होना वैश्विक राजनीति की एक युगांतकारी घटना थी। इस कूटनीतिक बदलाव, जिसे 'पिंग-पोंग डिप्लोमेसी' भी कहा जाता है, ने एशिया में पुराने सामरिक समीकरणों को ध्वस्त कर दिया। इसके परिणामस्वरूप अमेरिका, चीन और पाकिस्तान की एक नई धुरी बनी, जिसने भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया और उसे सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया था।

94. (D) 10 दिन
उन्नीस सौ इकहत्तर के युद्ध में भारतीय सेना ने असाधारण गति और समन्वय का प्रदर्शन किया था। युद्ध शुरु होने के मात्र दस दिनों के भीतर भारतीय सैन्य बलों ने ढाका को तीन दिशाओं से घेर लिया और पाकिस्तानी सेना की संचार एवं रसद व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इस तीव्र घेराबंदी और निरंतर दबाव के कारण पाकिस्तानी कमांडरों को अहसास हुआ कि प्रतिरोध असंभव है, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने ऐतिहासिक रूप से बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था।

134. (A) P-4, Q-1, R-3, S-2
उन्नीस सौ चौवन में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए। उन्नीस सौ छियासठ में भारत-पाक युद्ध के पश्चात ताशकंद समझौता संपन्न हुआ। उन्नीस सौ बहत्तर में बांग्लादेश युद्ध की समाप्ति के बाद शिमला समझौता हुआ। उन्नीस सौ निन्यानवे में कारगिल संघर्ष हुआ जब भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को सफलतापूर्वक खदेड़ा। ये वर्ष और घटनाएँ दक्षिण एशिया की भू-राजनीति और भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के महत्वपूर्ण मील के पत्थर रहे हैं।

135. (D) सी. राजगोपालाचारी
स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी. राजगोपालाचारी ने भारत की विदेश नीति और उसके वैश्विक प्रभाव पर टिप्पणी करते हुए यह कहा था। उनका मानना था कि भारत भले ही सैन्य और आर्थिक रूप से अन्य महाशक्तियों के समान शक्तिशाली न हो, लेकिन उसके शांतिपूर्ण और गुटनिरपेक्ष सिद्धांतों ने उसे विश्व में एक 'नैतिक ताकत' के रूप में स्थापित किया है। यह कथन नेहरू के नेतृत्व में भारत की उभरती हुई अंतरराष्ट्रीय छवि और उसके सिद्धांतों के महत्व को रेखांकित करता है।

136. (A) Punjab मोर्चा
उन्नीस सौ पैंसठ के युद्ध में जब पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के छंब क्षेत्र पर आक्रमण किया, तो प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने युद्ध का दायरा बढ़ाते हुए पंजाब सीमा से जवाबी हमला करने का साहसी निर्णय लिया। भारतीय सेना ने लाहौर और सियालकोट की ओर प्रस्थान किया, जिससे पाकिस्तान को अपनी सेना कश्मीर से हटाकर अपने प्रमुख शहरों को बचाने के लिए पंजाब मोर्चे पर लगानी पड़ी। इस रणनीतिक कदम ने युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया था।

137. (C) भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी
उन्नीस सौ पचास के दशक में भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी जैसे विपक्षी दलों का मानना था कि भारत को साम्यवाद के खतरे से बचने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी खेमे के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने चाहिए। उनका तर्क था कि अमेरिका के साथ सहयोग से भारत को आर्थिक विकास और रक्षा तैयारियों में अधिक सहायता मिल सकती है। हालांकि, नेहरू ने इन सुझावों को दरकिनार करते हुए गुटनिरपेक्षता की नीति पर अडिग रहना ही राष्ट्रहित में समझा था।

138. (D) 1, 2, 3, 4 सभी
उन्नीस सौ उनचास से बासठ के बीच भारत और चीन के संबंध सहयोग और संघर्ष के बीच रहे। भारत ने शुरु में चीन की नई सरकार को मान्यता दी और पंचशील के माध्यम से मित्रता का संदेश दिया। हालांकि, तिब्बत के स्वायत्त दर्जे पर चीन की कार्रवाई और दलाई लामा को भारत में शरण मिलने से विवाद बढ़ गया। अंततः सीमा विवाद और अक्साई-चीन पर चीन के दावे ने उन्नीस सौ बासठ के युद्ध का रुप ले लिया, जिसने संबंधों को पूरी तरह बदल दिया।

139. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
उन्नीस सौ निन्यानवे का कारगिल युद्ध तब शुरु हुआ जब पाकिस्तानी सैनिकों ने मुजाहिदीन के भेष में नियंत्रण रेखा पार कर द्रास, बटालिक और कारगिल के ऊंचे भारतीय ठिकानों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान का उद्देश्य इन रणनीतिक पहाड़ियों पर कब्जा कर भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग को काटना था। भारत ने 'ऑपरेशन विजय' के माध्यम से कड़ी सैन्य कार्रवाई की और घुसपैठियों को खदेड़कर अपने सभी ठिकानों पर पुनः अधिकार कर लिया, जिससे राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा हुई थी।

140. (A) 1, 3, 2, 4
भारत की विदेश नीति के ऐतिहासिक घटनाक्रम के अनुसार, पंचशील समझौता उन्नीस सौ चौवन में चीन के साथ हुआ। इसके बाद, उन्नीस सौ छियासठ में पाकिस्तान के साथ ताशकंद समझौता हुआ। उन्नीस सौ इकहत्तर में सोवियत संघ के साथ मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए गए। अंततः उन्नीस सौ बहत्तर में पाकिस्तान के साथ शिमला समझौता संपन्न हुआ। यह कालक्रम भारत की कूटनीतिक सक्रियता और क्षेत्रीय शांति स्थापित करने की दिशा में किए गए निरंतर प्रयासों का प्रमाण है।

141. (C) बेलग्रेड, यूगोस्लाविया
गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम आधिकारिक शिखर सम्मेलन सितंबर उन्नीस सौ इकसठ में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में पच्चीस विकासशील देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बेलग्रेड सम्मेलन ने शीतयुद्ध के दौर में महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता से दूर रहने के सिद्धांतों को औपचारिक रूप दिया। इसने नवस्वतंत्र राष्ट्रों को विश्व मंच पर अपनी सामूहिक आवाज़ उठाने और उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद के विरुद्ध संगठित होने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया था।

142. (A) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं।
उन्नीस सौ बासठ के युद्ध में मिली हार ने भारतीय राष्ट्रीय गर्व को ठेस पहुँचाई, लेकिन इसने पूरे देश को एकजुट भी किया। संकट के इस समय में लोगों ने देश की रक्षा के लिए बड़े पैमाने पर सहयोग दिया। हालांकि, युद्ध की विफलता के कारण सरकार की नीतियों पर सवाल उठे, जिससे कांग्रेस की लोकप्रियता में गिरावट आई। विपक्षी दलों ने सरकार पर दबाव बनाया, जिसके परिणामस्वरुप सत्तारूढ़ दल को कई महत्वपूर्ण उपचुनावों में हार का सामना करना पड़ा था।

143. (A) अमरीका और सोवियत संघ
द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विश्व राजनीति मुख्य रुप से दो शक्तिशाली गुटों, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले 'लोकतांत्रिक खेमे' और सोवियत संघ के नेतृत्व वाले 'साम्यवादी खेमे', में विभाजित थी। भारत ने अपनी स्वतंत्रता के बाद किसी भी गुट का हिस्सा बनने के बजाय गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। इसका उद्देश्य दोनों महाशक्तियों से समान दूरी बनाए रखते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को साधना और विश्व शांति की दिशा में एक स्वतंत्र भूमिका निभाना था।

किया, जिसके जवाब में भारत ने सोवियत संघ के साथ ऐतिहासिक मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए थे।

65. (D) 1, 2, 3, 4 और 5 सभी
भारत की विदेश नीति के प्रारंभिक स्वरूप पर नेहरू का गहरा व्यक्तिगत प्रभाव था, जो संप्रभुता और आर्थिक विकास पर केंद्रित था। हालांकि, देश के भीतर डॉ. अंबेडकर और जनसंघ जैसे विपक्षी दल अमेरिका के साथ अधिक निकटता की वकालत करते थे। नेहरू ने इन आंतरिक मतभेदों के बावजूद गुटनिरपेक्षता को सफलतापूर्वक लागू किया। ये सभी कारक भारत की विदेश नीति की जटिलता और उसमें मौजूद विविध वैचारिक धाराओं को स्पष्ट करते हैं।

66. (A) 1988 के बाद
उन्नीस सौ अठासी में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा के बाद भारत-चीन संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने सीमा विवाद को दरकिनार करते हुए आर्थिक सहयोग और व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। तब से दोनों राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर वृद्धि हुई है और व्यापारिक हित कूटनीतिक संबंधों के एक प्रमुख चालक बन गए हैं।

67. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
उन्नीस सौ नब्बे के दशक में सोवियत संघ के विघटन के बाद वैश्विक राजनीति का स्वरूप पूरी तरह बदल गया। शीतयुद्ध की समाप्ति के कारण सैन्य गठबंधनों का महत्व कम हुआ और आर्थिक एकीकरण एवं वैश्वीकरण प्राथमिक मुद्दे बन गए। भारत ने भी इस बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अपनी विदेश नीति में सुधार किया और अमेरिका के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की रणनीति अपनाई थी।

68. (D) भारत ने अपने अधिकतर ठिकानों पर पुनः अधिकार कर लिया।
उन्नीस सौ निन्यानवे के कारगिल युद्ध का समापन भारतीय सेना की शानदार जीत के साथ हुआ था। भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए कारगिल, द्रास और बटालिक क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा कब्जा किए गए ऊंचे पहाड़ी ठिकानों को वापस हासिल कर लिया। अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण पाकिस्तान को अपनी सेना वापस बुलाने पर मजबूर होना पड़ा। इस विजय ने भारत की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के संकल्प को पुनः दोहराया था।

69. (C) ढाका
उन्नीस सौ इकहत्तर के युद्ध के दौरान भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने ढाका को चारों ओर से घेर लिया था। पाकिस्तानी सेना की स्थिति इतनी कमजोर हो गई थी कि उनके पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। सोलह दिसंबर उन्नीस सौ इकहत्तर को ढाका के रेसकोर्स मैदान में जनरल नियाज़ी ने लगभग नब्बे हज़ार सैनिकों के साथ भारतीय जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आधिकारिक रूप से आत्मसमर्पण किया था।

70. (B) P-2, Q-1, R-4, S-3
नाटो अमेरिका के नेतृत्व वाला पश्चिमी देशों का सैन्य गठबंधन है। इसके विपरीत वारसा पैक्ट सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी यूरोपीय देशों का सैन्य गुट था। अवामी लीग शेख मुजीबुर्रहमान का राजनीतिक दल था जिसने बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका निभाई। सी.पी.आई.एम. वह दल है जो उन्नीस सौ चौंसठ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में हुए ऐतिहासिक विभाजन के बाद मार्क्सवादी विचारधारा के साथ अलग हुआ था।

71. (D) अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर लोकतंत्र स्थापित करना
भारतीय संविधान का अनुच्छेद इक्यावन राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध और अंतर्राष्ट्रीय शांति की वकालत करता है, लेकिन यह किसी अन्य देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का समर्थन नहीं करता। भारत की विदेश नीति हमेशा 'अहस्तक्षेप' और 'शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व' के सिद्धांतों पर आधारित रही है। अन्य देशों पर अपनी शासन प्रणाली थोपना भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के सर्वथा विपरीत माना जाता है।

72. (A) 2, 3, 1, 4
अटल बिहारी वाजपेयी ने विदेश मंत्री के रूप में उन्नीस सौ उनासी में चीन की यात्रा की थी। इसके बाद उन्नीस सौ अठासी में राजीव गांधी प्रधानमंत्री के रूप में चीन गए। मई उन्नीस सौ अट्ठानवे में भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण (पोखरण-द्वितीय) किया। अंततः उन्नीस सौ निन्यानवे में कारगिल युद्ध हुआ था। यह कालक्रम भारत की बदलती विदेश नीति और उसकी सामरिक शक्ति के क्रमिक विकास का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्य है।

73. (D) 1, 2, 3, 4 और 5 सभी
गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू, नासिर, टीटो, सुकर्णो और एनक्रूमा इन पांच महान नेताओं की सामूहिक दृष्टि और प्रयासों का परिणाम थी। इन्होंने शीतयुद्ध के दौरान तीसरी दुनिया के देशों को महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता से बचाने के लिए एक स्वतंत्र मंच प्रदान किया। इन नेताओं के आपसी सहयोग ने ही उन्नीस सौ इकसठ में बेलग्रेड सम्मेलन को सफल बनाया, जिससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में उभरा।

74. (A) नेताजी सुभाषचंद्र बोस
इंडियन नेशनल आर्मी (आई.एन.ए.) या आजाद हिंद फौज का गठन नेताजी सुभाषचंद्र बोस के नेतृत्व में दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी धरती से सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत को ब्रिटिश दासता से मुक्त कराना था। आई.एन.ए. ने दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय प्रवासियों और युद्धबंदियों को संगठित किया। नेताजी के इस साहसी प्रयास ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नया अध्याय जोड़कर क्रांति की मशाल जलाई थी।

154. (D) साम्राज्यवाद और शीत युद्ध की राजनीति के विरुद्ध एक 'तीसरे बल' के रूप में
जवाहरलाल नेहरु ने गुटनिरपेक्षता को एशिया और अफ्रीका के नव-स्वतंत्र देशों के लिए साम्राज्यवाद और नस्लवाद के विरुद्ध एक सशक्त मंच माना। उन्होंने इसे शीत युद्ध की शक्ति राजनीति के विरुद्ध एक 'तीसरे बल' के रूप में प्रस्तुत किया। इस नीति का उद्देश्य इन देशों को महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता से बचाना और उन्हें अपनी ऊर्जा राष्ट्र-निर्माण और वैश्विक शांति में लगाने के लिए प्रेरित करना था।

155. (C) नैतिक और व्यावहारिक आयामों वाली भारत की सक्रिय अवधारणा थी।
गुटनिरपेक्षता की नीति केवल गुटों से समान दूरी बनाए रखने वाली निष्क्रिय नीति नहीं थी, बल्कि यह नैतिक और व्यावहारिक आयामों वाली एक सक्रिय अवधारणा थी। इसका उद्देश्य भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करना और अंतरराष्ट्रीय शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देना था। यह नीति राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए वैश्विक न्याय और समानता के सिद्धांतों पर आधारित भारत की एक संप्रभु विदेश नीति का प्रतीक थी।

156. (B) भारत-चीन तिब्बत क्षेत्र समझौता
पंचशील के पाँच सिद्धांतों को पहली बार औपचारिक रूप से 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच तिब्बत क्षेत्र को लेकर हुए एक द्विपक्षीय समझौते में शामिल किया गया था। ये सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बने। जवाहरलाल नेहरु ने इन सिद्धांतों के माध्यम से पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध स्थापित करने की एक नई रुपरेखा प्रस्तुत की थी।

157. (D) पारस्परिक सैन्य गठबंधन
पंचशील समझौते में क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, गैर-आक्रामकता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व जैसे पाँच मुख्य सिद्धांत शामिल थे। इसमें किसी भी प्रकार के 'पारस्परिक सैन्य गठबंधन' का कोई उल्लेख नहीं था, क्योंकि भारत गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलते हुए सैन्य गुटबाजी के विरुद्ध था। इन सिद्धांतों का उद्देश्य सैन्य शक्ति के बजाय नैतिक मूल्यों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाना था।

158. (A) अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए एक सार्वभौमिक आचार संहिता के रूप में
जवाहरलाल नेहरु ने पंचशील के सिद्धांतों को केवल एक द्विपक्षीय समझौते के रूप में नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए एक सार्वभौमिक आचार संहिता के रूप में देखा। उनका मानना था कि यदि विश्व के देश इन पाँच सिद्धांतों का पालन करें, तो युद्ध की संभावनाओं को कम किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण शीत युद्ध के दौरान शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने का एक विकल्प था।

159. (C) 1962 का भारत-चीन युद्ध
1962 में चीन के साथ हुए अचानक युद्ध ने पंचशील के सिद्धांतों की व्यावहारिकता और प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यह युद्ध उन सिद्धांतों का उल्लंघन था जिन पर भारत ने भरोसा किया था, विशेषकर पारस्परिक गैर-आक्रामकता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का सिद्धांत। इस घटना ने साबित कर दिया कि केवल आदर्शवादी सिद्धांतों के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती, जिससे विदेश नीति में यथार्थवाद बढ़ा।

160. (A) शीत युद्ध की शक्ति राजनीति का एक सहयोगी और सम्मानजनक विकल्प देना
पंचशील के सिद्धांतों का व्यापक उद्देश्य शीत युद्ध के तनावपूर्ण और प्रतिस्पर्धी माहौल में राष्ट्रों के बीच संबंधों के लिए एक वैकल्पिक ढाँचा प्रदान करना था। यह ढाँचा सैन्य गठबंधनों और शक्ति प्रदर्शन के स्थान पर आपसी सहयोग, संप्रभुता के सम्मान और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर आधारित था। नेहरु का लक्ष्य विकासशील देशों को महाशक्तियों की राजनीति से दूर रखकर उनके आंतरिक विकास के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करना था।

161. (D) इसने आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर एक बदलाव को चिह्नित किया।
1962 के युद्ध ने भारतीय विदेश नीति को आदर्शवाद के सीमित दायरे से निकालकर यथार्थवाद की ठोस जमीन पर खड़ा कर दिया। इस पराजय के बाद भारत ने अपनी सैन्य कमजोरियों को पहचाना और राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। विदेश नीति के संचालन में अब केवल शांतिपूर्ण नारों के बजाय सामरिक शक्ति और व्यावहारिक कूटनीति पर ध्यान केंद्रित किया जाने लगा, जो एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव था।

162. (B) नेहरु की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँची और सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया।
1962 की पराजय के तत्काल बाद भारत में गंभीर राजनीतिक उथल-पुथल मची। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा और उनके नेतृत्व की कड़ी आलोचना हुई, जिससे उनकी सरकार के विरुद्ध संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इस घटना ने देश के भीतर राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ाया और विपक्षी दलों को रक्षा एवं विदेश नीति के मुद्दों पर सरकार को घेरने का एक मजबूत अवसर प्रदान किया।

163. (C) इसने सैन्य आधुनिकीकरण कार्यक्रम और रक्षा बजट में महत्वपूर्ण वृद्धि को प्रेरित किया।
1962 के युद्ध ने भारत को अपनी सैन्य तैयारियों की कमियों का एहसास कराया, जिससे रक्षा रणनीति में आमूल-चूल परिवर्तन हुए। इसके परिणामस्वरुप भारत ने एक व्यापक सैन्य आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरु किया और रक्षा बजट में भारी वृद्धि की गई। सेना को आधुनिक हथियारों से लैस करने और सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया, ताकि भविष्य में किसी भी संभावित आक्रमण का सामना किया जा सके।

43. नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन (A) और एक तर्क (R) दिया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिये:
अभिकथन (A): 1971 के चुनाव में इंदिरा गाँधी ने 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया।
तर्क (R): इस नारे के सहारे उन्होंने वंचित तबकों, खासकर भूमिहीन किसान, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला और बेरोजगार नौजवानों के बीच अपने समर्थन का आधार तैयार करने की कोशिश की।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

44. निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी 1971 के 'ग्रैंड अलायंस' का हिस्सा नहीं थी?
(A) भारतीय जनसंघ
(B) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI)
(C) स्वतंत्र पार्टी
(D) संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी (SSP)

45. 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गाँधी की कांग्रेस (आर) ने किस पार्टी के साथ गठजोड़ किया था?
(A) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
(B) द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK)
(C) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई)
(D) भारतीय जनसंघ

46. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. 1971 के चुनाव में 'ग्रैंड अलायंस' के पास एक सुसंगत राजनीतिक कार्यक्रम का अभाव था।
2. 'ग्रैंड अलायंस' का एकमात्र कार्यक्रम 'इंदिरा हटाओ' था।
3. इंदिरा गाँधी ने एक सकारात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसे 'गरीबी हटाओ' के नारे से व्यक्त किया गया।
4. इंदिरा गाँधी ने सार्वजनिक क्षेत्र की संवृद्धि, भू-स्वामित्व के परिसीमन और 'प्रिवी पर्स' की समाप्ति पर जोर दिया।
5. 'गरीबी हटाओ' का नारा इंदिरा गाँधी की एक सोची-समझी राजनीतिक रणनीति थी।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 3 और 5
(B) केवल 2, 3 और 4
(C) केवल 1, 2, 3 और 4
(D) 1, 2, 3, 4 और 5 सभी

47. 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस (आर) और सीपीआई के गठबंधन ने कुल कितनी सीटें जीतीं?
(A) 375
(B) 352
(C) 283
(D) 400

48. 1971 के लोकसभा चुनाव में 'पुरानी कांग्रेस' यानी कांग्रेस (ओ) को कितनी सीटें मिलीं?
(A) 10
(B) 16
(C) 25
(D) 44

49. निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिये:
1. 'ग्रैंड अलायंस' का गठन
2. कांग्रेस में विभाजन
3. 'गरीबी हटाओ' का नारा
4. 1971 का आम चुनाव

(A) 1, 2, 3, 4
(B) 2, 1, 3, 4
(C) 2, 3, 1, 4
(D) 3, 2, 1, 4

50. 1971 के चुनाव परिणामों के बारे में कौन सा कथन गलत है?
(A) कांग्रेस (ओ) ने कांग्रेस (आर) से बेहतर प्रदर्शन किया।
(B) कांग्रेस (आर) ने अकेले 352 सीटें जीतीं।
(C) 'ग्रैंड अलायंस' धराशायी हो गया और उसे 60 से भी कम सीटें मिलीं।
(D) चुनाव परिणामों ने साबित कर दिया कि इंदिरा गाँधी की कांग्रेस ही 'असली कांग्रेस' है।

51. 1971 के लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद कौन सी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटना घटी जिसने इंदिरा गाँधी की लोकप्रियता को और बढ़ा दिया?
(A) वियतनाम युद्ध की समाप्ति।
(B) चीन का संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश।
(C) बांग्लादेश का संकट और भारत-पाक युद्ध।
(D) अरब-इजरायल युद्ध।

52. 1972 के राज्य विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की व्यापक सफलता का मुख्य कारण क्या था?
(A) विपक्षी दलों का चुनाव में भाग न लेना।
(B) चुनाव में धांधली।
(C) 'ग्रैंड अलायंस' का कांग्रेस में विलय।
(D) 1971 के युद्ध में जीत के बाद इंदिरा गाँधी की बढ़ी हुई लोकप्रियता।

53. 1972 के बाद इंदिरा गाँधी को किस रूप में देखा जाने लगा?
(A) केवल गरीबों और वंचितों के रक्षक के रूप में।
(B) केवल एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में।
(C) गरीबों और वंचितों के रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में।
(D) सिंडिकेट के एक अनुभवहीन नेता के रूप में।

54. 'पुरानी कांग्रेस' और इंदिरा गाँधी के नेतृत्व वाली 'नई कांग्रेस' में मुख्य अंतर क्या था?
(A) पुरानी कांग्रेस अधिक समाजवादी थी।

174. (A) शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट (PNE)
भारत ने मई 1974 में पोखरण में किए गए अपने पहले परमाणु परीक्षण को आधिकारिक तौर पर 'शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट' (PNE) का नाम दिया था। इस नामकरण के पीछे मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह संदेश देना था कि भारत का इरादा परमाणु हथियारों का सैन्यीकरण करना नहीं है। भारत ने यह स्पष्ट किया कि यह परीक्षण पूरी तरह से वैज्ञानिक अनुसंधान और परमाणु क्षमता के स्वदेशी विकास का एक हिस्सा मात्र था।

175. (C) वह सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता के मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम था।
1974 के पोखरण परीक्षण के माध्यम से भारत ने विश्व को यह सशक्त संदेश दिया कि वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी विकास के मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम है। यह परीक्षण भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के जोखिम के बावजूद, भारत ने यह सिद्ध किया कि वह किसी भी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

अध्याय 12
कांग्रेस प्रणाली : चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना

1. 1964 के मई में किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी?
(A) लालबहादुर शास्त्री
(B) जवाहरलाल नेहरू
(C) इंदिरा गाँधी
(D) मोरारजी देसाई

2. 1960 के दशक को 'खतरनाक दशक' क्यों कहा जाता था?
(A) क्योंकि इसमें गरीबी, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीय विभाजन के सवाल अनसुलझे थे।
(B) क्योंकि भारत ने चीन और पाकिस्तान के साथ दो बड़े भीषण युद्ध लड़े थे।
(C) क्योंकि देश के दो सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों की आकस्मिक मृत्यु हुई थी।
(D) क्योंकि इस समय के दौरान कांग्रेस पार्टी में ऐतिहासिक आंतरिक विभाजन हुआ था।

3. नेहरू के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए लालबहादुर शास्त्री के चयन में किस कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रमुख भूमिका निभाई?
(A) एस. निजलिंगप्पा
(B) अतुल्य घोष
(C) के. कामराज
(D) एस. के. पाटिल

4. लालबहादुर शास्त्री ने किस बड़ी रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए रेलमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था?
(A) 1951 में
(B) 1962 में
(C) 1964 में
(D) 1956 में

5. निम्नलिखित में से कौन सा कथन 'गैर-कांग्रेसवाद' की रणनीति का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(A) देश के सभी सक्रिय गैर-कांग्रेसी दलों का एक ही मुख्य पार्टी में विलय।
(B) कांग्रेस की आर्थिक नीतियों का समर्थन करने के लिए बनाया गया एक गठबंधन।
(C) विपक्षी दलों का कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए एकजुट होना।
(D) केवल वामपंथी समाजवादी दलों द्वारा बनाया गया एक राजनीतिक मोर्चा।

6. नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन (A) और एक तर्क (R) दिया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिये:
अभिकथन (A): 1960 के दशक के उत्तरार्ध में, भारत ने गंभीर आर्थिक संकट का सामना किया।
तर्क (R): मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, और सैन्य खर्चे में भारी बढ़ोतरी इसके प्रमुख कारण थे।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

7. "जय जवान, जय किसान" का प्रसिद्ध नारा किसने दिया?
(A) जवाहरलाल नेहरु
(B) इंदिरा गाँधी
(C) मोरारजी देसाई
(D) लालबहादुर शास्त्री

8. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. लालबहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे।
2. उन्होंने 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश का नेतृत्व किया।
3. उनका नारा 'जय जवान, जय किसान' इन दोनों चुनौतियों से निपटने के उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।
4. उनका देहांत 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुआ।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1, 2 और 3
(C) केवल 2, 3 और 4
(D) 1, 2, 3 और 4 सभी

9. शास्त्री जी की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए किन दो नेताओं के बीच कड़ा मुकाबला हुआ?
(A) के. कामराज और इंदिरा गाँधी
(B) मोरारजी देसाई और के. कामराज
(C) मोरारजी देसाई और इंदिरा गाँधी
(D) जगजीवन राम और इंदिरा गाँधी

10. निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें:
1. लालबहादुर शास्त्री का प्रधानमंत्री बनना
2. जवाहरलाल नेहरु की मृत्यु
3. ताशकंद समझौता

4. इंदिरा गाँधी का प्रधानमंत्री बनना
5. पाकिस्तान के साथ युद्ध

(A) 2, 1, 5, 3, 4
(B) 1, 2, 3, 4, 5
(C) 2, 1, 3, 5, 4
(D) 2, 5, 1, 4, 3

11. मोरारजी देसाई, प्रधानमंत्री पद के चुनाव से पहले किस प्रांत के मुख्यमंत्री रह चुके थे?
(A) मैसूर प्रांत
(B) मद्रास प्रांत
(C) उत्तर प्रदेश
(D) बंबई प्रांत

12. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. शास्त्री जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इंदिरा गाँधी का समर्थन किया।
2. उनका मानना था कि अनुभवहीन होने के कारण इंदिरा गाँधी उन पर निर्भर रहेंगी।
3. प्रधानमंत्री पद के लिए हुए गुप्त मतदान में इंदिरा गाँधी ने मोरारजी देसाई को हराया।
4. इंदिरा गाँधी को कांग्रेस के दो-तिहाई से अधिक सांसदों ने मत दिया।
5. सत्ता का हस्तांतरण अत्यंत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 1, 3 और 5
(C) केवल 2, 3, 4 और 5
(D) 1, 2, 3, 4 और 5 सभी

13. इंदिरा गाँधी के शुरुआती प्रधानमंत्रित्व काल में सरकार को रुपये का अवमूल्यन क्यों करना पड़ा?
(A) देश में व्यापक खाद्यान्न की कमी होने के कारण।
(B) औद्योगिक उत्पादन की दर को बढ़ाने के लिए।
(C) यह कदम अमरीका के बाहरी दबाव में उठाया गया था।
(D) विदेशी मुद्रा भंडार में भारी वृद्धि करने के कारण।

14. नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन (A) और एक तर्क (R) दिया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिये:
अभिकथन (A): राममनोहर लोहिया ने 'गैर-कांग्रेसवाद' की रणनीति का समर्थन किया।
तर्क (R): उनका तर्क था कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीब लोगों के हितों के खिलाफ़ है।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

15. निम्नलिखित सूची का मिलान कीजिये:
सूची I: (नेता)
P. के. कामराज
Q. एस. के. पाटिल
R. अतुल्य घोष
S. के. बी. सहाय

सूची II: (राज्य जिनसे वे संबंधित थे)
1. महाराष्ट्र
2. बिहार
3. तमिलनाडु
4. पश्चिम बंगाल

निम्नलिखित में से कौन-सा सही मिलान है??
(A) P-3, Q-1, R-4, S-2
(B) P-1, Q-3, R-2, S-4
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

16. 1967 के चुनाव परिणामों को 'राजनीतिक भूकंप' की संज्ञा क्यों दी गई?
(A) क्योंकि कांग्रेस पार्टी भारतीय इतिहास में पहली बार आम चुनाव हार गई थी।
(B) क्योंकि कांग्रेस के मत प्रतिशत और सीटों की संख्या में भारी गिरावट आई।
(C) क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार एक महिला प्रधानमंत्री चुनी गई थी।
(D) क्योंकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान देश में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी।

17. 1967 के चुनावों के संदर्भ में, 'संयुक्त विधायक दल' क्या था?
(A) कांग्रेस पार्टी के भीतर एक गुट।
(B) राज्यों में गैर-कांग्रेसी दलों द्वारा बनाई गई गठबंधन सरकारें।
(C) चुनाव लड़ने के लिए बनाया गया एक राष्ट्रीय मोर्चा।
(D) केवल समाजवादी दलों का एक समूह।

18. 1967 के चुनावों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. यह भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव था।
2. कांग्रेस पहली बार नेहरु के बिना मतदाताओं का सामना कर रही थी।
3. चुनाव परिणामों से कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा।
4. इंदिरा गाँधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए थे।

उपरोक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2 और 4
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) 1, 2, 3 और 4 सभी

164. (D) चीन के इरादों के प्रति गहरा और स्थायी अविश्वास।
मनोवैज्ञानिक स्तर पर 1962 का युद्ध भारत के लिए एक राष्ट्रीय अपमान की तरह था, जिसने जनता के आत्मविश्वास को हिला दिया। 'हिंदी-चीनी भाई-भाई' के नारे में लोगों का विश्वास समाप्त हो गया और चीन के प्रति एक गहरा और स्थायी अविश्वास पैदा हुआ। इस युद्ध ने भारतीय मानस में यह बात बैठा दी कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में केवल सद्भावना के भरोसे नहीं रहा जा सकता और सतर्कता आवश्यक है।

165. (A) इसने पश्चिमी देशों से सैन्य सहायता की आवश्यकता पैदा की, जिससे नीति की सीमाओं पर बहस हुई।
1962 के युद्ध ने भारत को अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति की सीमाओं पर विचार करने के लिए विवश कर दिया। सैन्य संकट के समय भारत को पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका और ब्रिटेन से आपातकालीन सैन्य सहायता मांगनी पड़ी। इस कदम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह बहस छेड़ दी कि क्या भारत अभी भी वास्तव में गुटनिरपेक्ष है। इसने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कभी-कभी नीतिगत समझौतों की आवश्यकता होती है।

166. (B) पूर्वी पाकिस्तान से भारत में बड़े पैमाने पर शरणार्थियों का आगमन
1971 के संघर्ष में भारत के हस्तक्षेप का सबसे बड़ा और तत्काल कारण पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले लगभग 10 मिलियन शरणार्थियों का भारी बोझ था। पश्चिमी पाकिस्तान के दमनकारी सैन्य शासन के कारण लोग अपनी जान बचाकर भारत आ रहे थे। इस मानवीय संकट ने भारत की अर्थव्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती पैदा कर दी थी, जिससे भारत को सक्रिय हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

167. (B) अमेरिका-चीन-पाकिस्तान के संभावित गठजोड़ को निष्क्रिय करना
अगस्त 1971 में सोवियत संघ के साथ की गई मैत्री संधि एक रणनीतिक मास्टरस्ट्रोक थी। इसका मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान को समर्थन दे रहे अमेरिका और चीन के संभावित गठबंधन के खतरे को बेअसर करना था। इस संधि ने भारत को यह सुरक्षा कवच प्रदान किया कि किसी भी विदेशी आक्रमण या संकट की स्थिति में उसे एक महाशक्ति का पूर्ण राजनीतिक और सामरिक समर्थन प्राप्त होगा, जिससे युद्ध जीतना आसान हुआ।

168. (A) बांग्लादेश का उदय और भारत का एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित होना
1971 के युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम एक नए स्वतंत्र राष्ट्र, 'बांग्लादेश' का उदय था। इस विजय ने दक्षिण एशिया के भू-राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया और पाकिस्तान की द्वि-राष्ट्र सिद्धांत की विचारधारा को कमजोर कर दिया। इसके साथ ही, भारत इस क्षेत्र में एक निर्विवाद और प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। इस घटना ने भारत की सैन्य श्रेष्ठता और रणनीतिक कौशल को पूरी दुनिया के सामने मजबूती से सिद्ध किया।

169. (C) राजनयिक समर्थन जुटाकर और 'मुक्ति वाहिनी' को प्रशिक्षित करके
युद्ध शुरू होने से पहले ही भारत ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन को कूटनीतिक और सामरिक समर्थन देना प्रारंभ कर दिया था। भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन को उजागर किया और विश्व समुदाय का समर्थन जुटाया। साथ ही, भारत ने बांग्लादेशी लड़ाकों, जिन्हें 'मुक्ति वाहिनी' कहा जाता था, को सैन्य प्रशिक्षण और आवश्यक उपकरण प्रदान करके उनके संघर्ष को और अधिक प्रभावी बनाया।

170. (D) भारत की प्रभावी राजनयिक और सैन्य रणनीति बनाने की क्षमता
1971 के युद्ध में भारत की निर्णायक जीत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भारत की उत्कृष्ट राजनयिक और सैन्य योजना बनाने की क्षमता का परिचय दिया। भारत ने न केवल युद्ध के मैदान में विजय प्राप्त की, बल्कि सोवियत संघ के साथ संधि करके वैश्विक कूटनीति में भी अपनी पकड़ साबित की। इस सफलता ने शीत युद्ध के दौर में भारत की एक स्वायत्त और प्रभावशाली शक्ति के रूप में छवि को बहुत मजबूत किया।

171. (C) ऊर्जा उत्पादन और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे शांतिपूर्ण उपयोग
भारत के परमाणु कार्यक्रम की नींव ऊर्जा उत्पादन और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे शांतिपूर्ण लक्ष्यों के साथ रखी गई थी। जवाहरलाल नेहरू और होमी जहांगीर भाभा ने 'शांति के लिए परमाणु' के दर्शन का समर्थन किया था। प्रारंभ में भारत का उद्देश्य परमाणु तकनीक का उपयोग बिजली बनाने, कृषि में सुधार और चिकित्सा के क्षेत्र में विकास करने के लिए करना था, न कि परमाणु हथियार विकसित करके कोई सैन्य खतरा उत्पन्न करना।

172. (B) क्योंकि इसे भेदभावपूर्ण माना गया जो परमाणु शक्तियों के एकाधिकार को पुष्ट करती थी।
भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर करने से स्पष्ट इनकार कर दिया क्योंकि इसे अत्यधिक भेदभावपूर्ण माना गया। भारत का तर्क था कि यह संधि केवल उन पाँच देशों के परमाणु एकाधिकार को सुरक्षित करती है जिनके पास पहले से हथियार थे, जबकि अन्य देशों पर कठोर प्रतिबंध लगाती थी। भारत एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था चाहता था जो पूर्ण और सार्वभौमिक परमाणु निरस्त्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित हो, न कि असमानता पर।

173. (D) 1964 में चीन द्वारा किया गया परमाणु परीक्षण
1964 में चीन द्वारा किए गए पहले सफल परमाणु परीक्षण ने भारत के सुरक्षा परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया। चीन की बढ़ती परमाणु क्षमता ने भारतीय नीति निर्माताओं को अपनी रक्षा रणनीति पर पुनर्विचार करने और एक परमाणु हथियार विकल्प विकसित करने की आवश्यकता पर विचार करने के लिए मजबूर किया। इस घटना के बाद ही भारत के परमाणु कार्यक्रम में शांतिपूर्ण उपयोग के साथ-साथ सुरक्षा आयामों को भी गंभीरता से शामिल किया गया।

कार्यक्रम
3. राममनोहर लोहिया द्वारा दी गई रणनीति
4. 'आया राम, गया राम' से जुड़ा मुहावरा
निम्नलिखित में से कौन-सा सही मिलान है??
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

31. इंदिरा गाँधी ने 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में किसे बढ़ावा दिया?
(A) वी. वी. गिरि
(B) एन. संजीव रेड्डी
(C) के. कामराज
(D) जाकिर हुसैन

32. इंदिरा गाँधी ने किस आधार पर कांग्रेस के सांसदों और विधायकों से 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने की अपील की?
(A) पार्टी व्हिप का पालन करने के लिए।
(B) अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालने के लिए।
(C) सिंडिकेट के निर्णय का सम्मान करने के लिए।
(D) क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता देने के लिए।

33. निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1969 के राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले नहीं घटी?
(A) चौदह अग्रणी बैंकों का राष्ट्रीयकरण।
(B) 1971 के भारत-पाक युद्ध की शुरुआत।
(C) 'प्रिवी पर्स' को समाप्त करने की घोषणा।
(D) मोरारजी देसाई का उपप्रधानमंत्री पद से इस्तीफा।

34. 'प्रिवी पर्स' की समाप्ति का विरोध करते हुए किसने इसे 'रियासतों के साथ विश्वासघात' बताया था?
(A) मोरारजी देसाई
(B) इंदिरा गाँधी
(C) के. कामराज
(D) राममनोहर लोहिया

35. 'प्रिवी पर्स' से क्या अभिप्राय है?
(A) प्रधानमंत्रियों को मिलने वाला विशेष भत्ता।
(B) सांसदों को मिलने वाली पेंशन।
(C) देसी रियासतों के विलय के समय शासक परिवारों को दिए जाने वाले विशेष भत्ते और अधिकार।
(D) स्वतंत्रता सेनानियों को दिया जाने वाला सम्मान।

36. 1969 में कांग्रेस पार्टी में विभाजन का तात्कालिक कारण क्या था?
(A) दस-सूत्री कार्यक्रम पर मतभेद।
(B) प्रिवी पर्स की समाप्ति का निर्णय।
(C) बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर विवाद।
(D) राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की हार।

37. कांग्रेस में 1969 की टूट के बाद सिंडिकेट की अगुवाई वाले खेमे को किस नाम से जाना गया?
(A) कांग्रेस (रिक्विजिनिस्ट)
(B) नई कांग्रेस
(C) कांग्रेस (ऑर्गनाइजेशन)
(D) कांग्रेस (इंदिरा)

38. कांग्रेस (ऑर्गनाइजेशन) को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था?
(A) युवा कांग्रेस
(B) पुरानी कांग्रेस
(C) नई कांग्रेस
(D) असली कांग्रेस

39. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. 'प्रिवी पर्स' की व्यवस्था भारतीय संविधान में वर्णित समानता के सिद्धांतों से मेल नहीं खाती थी।
2. जवाहरलाल नेहरु ने कई बार इस व्यवस्था पर असंतोष जताया था।
3. इंदिरा गाँधी ने 1967 के चुनावों के बाद इसे खत्म करने की माँग का समर्थन किया।
4. 1971 में मिली भारी चुनावी जीत के बाद संविधान में संशोधन करके प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2 और 4
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) 1, 2, 3 और 4 सभी

40. 1969 में कांग्रेस के विभाजन के बाद इंदिरा गाँधी की अल्पमत सरकार को किन दलों ने समर्थन दिया?
(A) डी.एम.के. और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी।
(B) भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी।
(C) अकाली दल और सोशलिस्ट पार्टी।
(D) कांग्रेस (ओ) और बी.के.डी.।

41. 1971 के आम चुनाव से पहले विपक्षी दलों द्वारा बनाए गए गठबंधन को क्या नाम दिया गया?
(A) संयुक्त मोर्चा
(B) संयुक्त विधायक दल
(C) ग्रैंड अलायंस
(D) राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन

42. 1971 के चुनाव में 'ग्रैंड अलायंस' का प्रमुख नारा क्या था?
(A) इंदिरा हटाओ
(B) जय जवान, जय किसान
(C) गरीबी हटाओ
(D) देश बचाओ, देश बनाओ

(C) इस समूह के नेताओं का पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था।
(D) लालबहादुर शास्त्री और इंदिरा गाँधी, दोनों सिंडिकेट की सहायता से प्रधानमंत्री बने।

64. इंदिरा गाँधी ने सरकार की नीतियों को वामपंथी रंग देने के लिए जो कदम उठाए, उनमें से एक था:
(A) स्वतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन।
(B) 1967 में दस-सूत्री कार्यक्रम अपनाना।
(C) प्रिवी पर्स को बनाए रखना।
(D) बैंकों का निजीकरण।

65. नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन (A) और एक तर्क (R) दिया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिये:
अभिकथन (A): 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में वी.वी. गिरि की जीत ने कांग्रेस पार्टी के विभाजन को निश्चित कर दिया।
तर्क (R): वी.वी. गिरि कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार थे, जबकि एन. संजीव रेड्डी एक स्वतंत्र उम्मीदवार थे।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

66. 1970 में इंदिरा गाँधी की सरकार द्वारा लोकसभा भंग करने की सिफारिश के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था?
(A) अपने कार्यक्रमों के पक्ष में जनादेश हासिल करना और अन्य दलों पर निर्भरता समाप्त करना।
(B) विपक्षी एकता से घबराकर।
(C) सिंडिकेट के दबाव के कारण।
(D) देश में आपातकाल लगाने के लिए।

67. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. 1967 के चुनावों में कांग्रेस को सात राज्यों में बहुमत नहीं मिला।
2. दो अन्य राज्यों में दल-बदल के कारण वह सरकार नहीं बना सकी।
3. मद्रास में DMK ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया।
4. अधिकांश गैर-कांग्रेसी सरकारें गठबंधन सरकारें थीं जिन्हें 'संयुक्त विधायक दल' कहा गया।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2 और 4
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) 1, 2, 3 और 4 सभी

68. वह कथन कि "दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए ट्रेन पर बैठो, तो यह ट्रेन अपने पूरे रास्ते में एक भी कांग्रेस-शासित राज्य से होकर नहीं गुज़रेगी" किस चुनाव के बाद की स्थिति को दर्शाता है?
(A) 1962
(B) 1971
(C) 1957
(D) 1967

69. मार्क्सवादी-लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस पार्टी से अलग हुए समूह ने किया था?
(A) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
(B) भारतीय जनसंघ
(C) मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी
(D) सोशलिस्ट पार्टी

70. निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें:
1. इंदिरा गाँधी को पार्टी से निष्कासित करना
2. वी.वी. गिरि का राष्ट्रपति चुनाव जीतना
3. 'अंतरात्मा की आवाज' पर वोट की अपील
4. एन. संजीव रेड्डी को कांग्रेस का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित करना

(A) 4, 3, 2, 1
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 4, 2, 3, 1
(D) 3, 4, 1, 2

71. कांग्रेस में विभाजन के बाद, इंदिरा गाँधी के गुट को कांग्रेस (रिक्विजिनिस्ट) क्यों कहा जाता था?
(A) क्योंकि उन्होंने पार्टी के संविधान को फिर से लिखने की मांग की।
(B) क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग से यह नाम मांगा था।
(C) क्योंकि यह नाम सिंडिकेट द्वारा दिया गया था।
(D) क्योंकि उनके समर्थकों ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक आयोजित करने की याचना (requisition) की थी।

72. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. 1969 के विभाजन को इंदिरा गाँधी ने 'समाजवादी' और 'पुरातनपंथी' के बीच की लड़ाई के रूप में पेश किया।
2. उन्होंने इसे 'गरीबों के हिमायती' और 'अमीरों के तरफदार' के बीच की लड़ाई बताया।
3. इस विभाजन का मुख्य कारण व्यक्तिगत सत्ता संघर्ष था।
4. इंदिरा गाँधी की रणनीति सत्ता संघर्ष को विचारधारा का जामा पहनाने की थी।
5. सिंडिकेट ने भी इसे विचारधारा की लड़ाई के रूप में ही देखा।

उपरोक्त में से कौन से कथन गलत हैं?
(A) केवल 5
(B) केवल 4 और 5
(C) केवल 3
(D) कोई नहीं

73. 'प्रिव्ही पर्स' की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सरकार को संविधान में संशोधन क्यों करना पड़ा?
(A) क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के अध्यादेश को

(B) नई कांग्रेस पूर्णतया अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आश्रित थी और उसका सांगठनिक ढाँचा कमजोर था।
(C) पुरानी कांग्रेस में गुट नहीं थे, जबकि नई कांग्रेस में कई गुट थे।
(D) नई कांग्रेस ने केवल अमीर वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया।

55. इंदिरा गाँधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित तो किया, लेकिन उसकी प्रकृति को बदलकर। इस 'बदली हुई प्रकृति' का क्या अर्थ है?
(A) नई कांग्रेस में विभिन्न मतों और देश के विविध सामाजिक हितों को एक साथ लेकर चलने की पुरानी क्षमता अधिक थी।
(B) नई कांग्रेस संगठन के पुराने अनुभवी नेताओं और शक्तिशाली सिंडिकेट के पूर्ण नियंत्रण में ही काम कर रही थी।
(C) नई कांग्रेस ने अपनी बदली हुई प्रकृति के कारण देश के चुनावों को स्थायी रूप से जीतना अब बंद कर दिया था।
(D) नई कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत की, लेकिन जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की लोकतांत्रिक जमीन छोटी पड़ती गई।

56. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. करिश्माई नेता का अभाव।
2. कांग्रेस पार्टी के भीतर टूट।
3. क्षेत्रीय, जातीय और सांप्रदायिक समूहों की बढ़ती लामबंदी।
4. गैर-कांग्रेसी दलों के बीच एकजुटता।
5. कांग्रेस पार्टी के अंदर मतभेद।

1967 के चुनाव में कांग्रेस की हार के क्या कारण थे?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3, 4 और 5
(C) केवल 2, 3, और 4
(D) 1, 2, 3, 4 और 5 सभी

57. 1970 के दशक में इंदिरा गाँधी की सरकार की लोकप्रियता के क्या कारण थे?
(A) विपक्षी दलों का कमजोर होना।
(B) सिंडिकेट के साथ समझौता कर लेना।
(C) गरीबी हटाओ जैसा प्रगतिशील कार्यक्रम और 1971 के युद्ध में निर्णायक जीत।
(D) केवल प्रिवी पर्स की समाप्ति।

58. कांग्रेस पार्टी 1969 में किन मसलों को लेकर टूट का शिकार हुई?
(A) नेतृत्व और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इंदिरा गाँधी और सिंडिकेट के बीच बढ़ा सत्ता संघर्ष।
(B) देश की आंतरिक विचारधारा के गहन सैद्धांतिक मतभेद के कारण।
(C) केवल पार्टी के दस-सूत्री कार्यक्रम को पूर्ण रूप से लागू करने के मसले को लेकर।
(D) देश की आगामी भविष्य की विदेश नीति पर उपजी गहरी असहमति के कारण।

59. 1967 के चुनावों के संदर्भ में, बिहार में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार की एक विशिष्टता क्या थी?
(A) इसमें राज्य की केवल विभिन्न समाजवादी और वामपंथी पार्टियाँ ही शामिल थीं।
(B) यह भारतीय इतिहास की पहली पूर्णतः सफल गैर-कांग्रेसी राज्य सरकार थी।
(C) इसमें समाजवादी पार्टियों के साथ वामपंथी और दक्षिणपंथी दल भी शामिल थे।
(D) इसका नेतृत्व राज्य के किसी प्रभावशाली जनसंघ के बड़े नेता ने किया था।

60. निम्नलिखित सूची का मिलान कीजिये:
सूची I: (नारा/अवधारणा)
P. जय जवान, जय किसान
Q. इंदिरा हटाओ!
R. गरीबी हटाओ!
S. गैर-कांग्रेसवाद

सूची II: (संबंधित नेता/गठबंधन)
1. इंदिरा गाँधी
2. राममनोहर लोहिया
3. लालबहादुर शास्त्री
4. ग्रैंड अलायंस

निम्नलिखित में से कौन-सा सही मिलान है??
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-2, Q-3, R-1, S-4

61. पंजाब में 1967 में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को कहा गया?
(A) अकाली-जनसंघ गठबंधन
(B) संयुक्त मोर्चा
(C) पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट
(D) विशाल पंजाब सरकार

62. कामराज योजना (1963) का उद्देश्य क्या था?
(A) मद्रास में स्कूली बच्चों के लिए दोपहर का भोजन शुरु करना।
(B) कांग्रेस का समाजवादी दलों के साथ विलय।
(C) प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार तय करना।
(D) कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए वरिष्ठ नेताओं का इस्तीफा ताकि युवा कार्यकर्ता कमान संभाल सकें।

63. निम्नलिखित में से कौन सा कथन 'सिंडिकेट' के बारे में गलत है?
(A) सिंडिकेट ने हमेशा इंदिरा गाँधी की वामपंथी नीतियों का समर्थन किया।
(B) यह कांग्रेस के नेताओं का एक अनौपचारिक समूह था।

19. 1967 में मद्रास (तमिलनाडु) में किस क्षेत्रीय पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई?
(A) अकाली दल
(B) स्वतंत्र पार्टी
(C) द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK)
(D) भारतीय जनसंघ

20. द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) की 1967 की जीत का एक प्रमुख कारण क्या था?
(A) गरीबी हटाओ का नारा।
(B) भूमि सुधारों का वादा।
(C) औद्योगिक विकास पर जोर।
(D) हिंदी-विरोधी आंदोलन का नेतृत्व।

21. 'आया राम, गया राम' का जुमला किस राजनीतिक घटना से संबंधित है?
(A) गठबंधन
(B) राष्ट्रपति शासन
(C) दल-बदल
(D) मध्यावधि चुनाव

22. नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन (A) और एक तर्क (R) दिया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिये:
अभिकथन (A): 1967 के चुनाव के बाद कई राज्यों में बनी 'संयुक्त विधायक दल' की सरकारें अस्थिर थीं और ज्यादा दिन नहीं टिक पाईं।
तर्क (R): इन गठबंधन सरकारों में शामिल घटक दल विचारधारा के लिहाज से एक-दूसरे से भिन्न थे।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R) (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

23. हरियाणा के किस विधायक के बार-बार दल बदलने की घटना से 'आया राम, गया राम' का जुमला प्रसिद्ध हुआ?
(A) राव बीरेंद्र सिंह
(B) देवी लाल
(C) भजन लाल
(D) गया लाल

24. कांग्रेस पार्टी के भीतर प्रभावशाली नेताओं के समूह को अनौपचारिक रूप से किस नाम से जाना जाता था?
(A) सिंडिकेट
(B) युवा तुर्क
(C) ग्रैंड अलायंस
(D) संयुक्त विधायक दल

25. निम्नलिखित में से कौन सिंडिकेट समूह के सदस्य नहीं थे?
(A) के. कामराज
(B) एस. निजलिंगप्पा
(C) इंदिरा गाँधी
(D) एस. के. पाटिल

26. 1967 के चुनावों के बाद इंदिरा गाँधी को असली चुनौती किससे मिली?
(A) अपनी ही पार्टी के भीतर 'सिंडिकेट' से।
(B) विपक्षी दलों के 'ग्रैंड अलायंस' से।
(C) साम्यवादी दलों के बढ़ते प्रभाव से।
(D) सेना के राजनीतिक हस्तक्षेप से।

27. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. सिंडिकेट ने इंदिरा गाँधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
2. सिंडिकेट के नेताओं को उम्मीद थी कि इंदिरा गाँधी उनकी सलाहों पर अमल करेंगी।
3. इंदिरा गाँधी ने धीरे-धीरे सिंडिकेट को हाशिये पर ला खड़ा किया।
4. इंदिरा गाँधी ने एक साधारण सत्ता-संघर्ष को विचारधारात्मक संघर्ष में बदल दिया।
5. इंदिरा गाँधी ने अपनी नीतियों को वामपंथी रंग देना शुरु किया।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 3, 4 और 5
(C) केवल 1, 2, 4 और 5
(D) 1, 2, 3, 4 और 5 सभी

28. मई 1967 में कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा अपनाए गए 'दस-सूत्री कार्यक्रम' में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था?
(A) बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण।
(B) प्रिवी पर्स की समाप्ति।
(C) आम बीमा का राष्ट्रीयकरण।
(D) शहरी संपदा और आय का परिसीमन।

29. 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार कौन थे, जिन्हें सिंडिकेट का समर्थन प्राप्त था?
(A) वी. वी. गिरि
(B) जाकिर हुसैन
(C) एन. संजीव रेड्डी
(D) मोरारजी देसाई

30. निम्नलिखित सूची का मिलान कीजिये:
सूची I: (घटना)
P. गैर-कांग्रेसवाद
Q. दल-बदल
R. सिंडिकेट
S. दस-सूत्री कार्यक्रम

सूची II: (विवरण)
1. कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली नेताओं का समूह
2. कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा अपनाया गया वामपंथी

निरस्त कर दिया था।
(B) क्योंकि राज्यसभा ने मूल संशोधन विधेयक को मंज़ूरी नहीं दी थी।
(C) क्योंकि यह एक संवैधानिक अधिकार था।
(D) (A) और (B) दोनों।

74. नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन (A) और एक तर्क (R) दिया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिये:
अभिकथन (A): 1971 के चुनाव परिणामों ने भारतीय राजनीति में कांग्रेस के प्रभुत्व को फिर से स्थापित कर दिया।
तर्क (R): इस चुनाव में कांग्रेस (आर) और कांग्रेस (ओ) का विलय हो गया था, जिससे पार्टी मजबूत हुई।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

75. निम्नलिखित सूची का मिलान कीजिये:
सूची I: (नेता)
P. सी. नटराजन अन्नादुरई
Q. राममनोहर लोहिया
R. कर्पूरी ठाकुर
S. के. कामराज
सूची II: (योगदान/भूमिका)
1. गैर-कांग्रेसवाद के रणनीतिकार
2. कामराज योजना के प्रस्तावक
3. DMK के संस्थापक और मद्रास के मुख्यमंत्री
4. बिहार में पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू करने वाले मुख्यमंत्री
निम्नलिखित में से कौन-सा सही मिलान है??
(A) P-3, Q-1, R-4, S-2
(B) P-3, Q-1, R-4, S-2
(C) P-3, Q-4, R-2, S-1
(D) P-4, Q-3, R-1, S-2

76. नेहरू के बाद राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक परीक्षा क्यों माना जा रहा था?
(A) क्योंकि भारत में पहले कभी प्रधानमंत्री नहीं बदला था।
(B) क्योंकि कई लोगों को संदेह था कि भारत में लोकतंत्र कायम नहीं रह पाएगा और सेना सत्ता पर कब्जा कर लेगी।
(C) क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कोई योग्य नेता नहीं था।
(D) क्योंकि विपक्षी दल सत्ता संभालने के लिए तैयार नहीं थे।

77. इंदिरा गाँधी ने शास्त्री के मंत्रिमंडल में किस मंत्रालय का प्रभार संभाला था?
(A) वित्त मंत्रालय
(B) रक्षा मंत्रालय
(C) सूचना मंत्रालय
(D) गृह मंत्रालय

78. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. 1967 के चुनाव तक देश में दो प्रधानमंत्रियों का जल्दी-जल्दी देहावसान हो चुका था।
2. नई प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी को राजनीति में कम अनुभवी माना जा रहा था।
3. देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था।
4. रुपये का अवमूल्यन किया गया था।
उपरोक्त में से कौन से कथन 1967 के चुनाव के संदर्भ को दर्शाते हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1, 2 और 3
(C) केवल 2, 3 और 4
(D) 1, 2, 3 और 4 सभी

79. 1967 के आसपास जन विरोध के उग्र होने का एक कारण क्या था?
(A) सरकार का जन-आंदोलनों को केवल कानून-व्यवस्था की समस्या मानना।
(B) सरकार का सभी मांगों को तुरंत मान लेना।
(C) विपक्षी दलों का सरकार को समर्थन देना।
(D) आर्थिक स्थिति का बहुत अच्छा होना।

80. 1971 के चुनावों में भारी जीत के बाद भी, इंदिरा गाँधी की 'नई कांग्रेस' पुरानी कांग्रेस से किस मायने में भिन्न थी?
(A) यह अधिक लोकतांत्रिक और संघीय थी।
(B) इसमें विभिन्न मतों और हितों को पचा लेने की क्षमता कम थी।
(C) यह अपने नेता की लोकप्रियता पर कम निर्भर थी।
(D) इसका सांगठनिक ढाँचा बहुत मजबूत था।

81. एस. निजलिंगप्पा किस अवधि के दौरान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे?
(A) 1964-1967
(B) 1968-1971
(C) 1960-1963
(D) 1972-1975

82. लालबहादुर शास्त्री की मृत्यु के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे, जिनके साथ वे ताशकंद में बातचीत करने गए थे?
(A) मोहम्मद अयूब खान
(B) जुल्फिकार अली भुट्टो
(C) याह्या खान
(D) जिया-उल-हक

83. निम्नलिखित में से किस नेता ने पिछड़े वर्गों को आरक्षण की वकालत की और अंग्रेजी के प्रयोग का विरोध किया?
(A) के. कामराज
(B) सी. नटराजन अन्नादुरई

(A) लोकसभा में उसे बहुमत मिला।
(B) उसे प्राप्त मतों के प्रतिशत में भारी गिरावट आई।
(C) केंद्र में उसकी सत्ता समाप्त हो गई और गठबंधन सरकार बनी।
(D) उसे प्राप्त सीटों की संख्या में भारी गिरावट आई।

126. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. सिंडिकेट का मानना था कि इंदिरा गाँधी उनके नियंत्रण में रहेंगी।
2. इंदिरा गाँधी ने पार्टी के बाहर के लोगों को अपना सलाहकार बनाया।
3. इंदिरा गाँधी ने बड़ी सावधानी से सिंडिकेट को हाशिये पर कर दिया।
4. यह संघर्ष केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का था, इसका विचारधारा से कोई लेना-देना नहीं था।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1, 2 और 3
(C) केवल 3 और 4
(D) 1, 2, 3 और 4 सभी

127. 'जय जवान-जय किसान' के नारे में निहित दो चुनौतियाँ कौन सी थीं?
(A) पाकिस्तान से युद्ध और खाद्यान्न संकट
(B) गरीबी और बेरोजगारी
(C) चीन युद्ध और आर्थिक संकट
(D) भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता

128. लालबहादुर शास्त्री का देहांत कहाँ हुआ था?
(A) दिल्ली, भारत
(B) ताशकंद, सोवियत संघ (अब उज्बेकिस्तान)
(C) मॉस्को, सोवियत संघ
(D) न्यूयॉर्क, अमेरिका

129. 1967 में किस नेता के चुनाव हारने पर यह टिप्पणी की गई कि वे खुद तो एक राजा-निर्माता (king-maker) थे पर अपने ही क्षेत्र से हार गए?
(A) मोरारजी देसाई
(B) के. कामराज
(C) एस. के. पाटिल
(D) अतुल्य घोष

130. 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गाँधी द्वारा समर्थित उम्मीदवार वी. वी. गिरि की जीत को एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना जाता है?
(A) क्योंकि इसने प्रधानमंत्री की शक्ति को पार्टी संगठन से ऊपर स्थापित कर दिया।
(B) क्योंकि यह पहली बार था जब कोई स्वतंत्र उम्मीदवार जीता।
(C) क्योंकि इससे सिंडिकेट और मजबूत हुआ।
(D) क्योंकि यह चुनाव सर्वसम्मति से हुआ था।

131. इंदिरा गाँधी के नेतृत्व वाली 'नई कांग्रेस' की सामाजिक संरचना कैसी थी?
(A) यह मुख्य रूप से शहरी, मध्यम वर्ग और व्यापारियों पर आधारित थी।
(B) इसमें सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व था।
(C) यह मुख्य रूप से दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और गरीबों पर आधारित थी।
(D) यह केवल ग्रामीण भू-स्वामियों पर आधारित थी।

132. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी (SSP)
2. भारतीय जनसंघ (BJS)
3. स्वतंत्र पार्टी
4. भारतीय क्रांति दल (BKD)
5. भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (CPI)

निम्नलिखित में से कौन 1971 के 'ग्रैंड अलायंस' में शामिल थे?
(A) 1, 2, 3, 4 और 5
(B) 1, 2, 3 और 4
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) केवल 2, 3 और 5

133. के. कामराज ने मद्रास प्रांत में शिक्षा के प्रसार के लिए कौन सी प्रसिद्ध योजना लागू की थी?
(A) सर्व शिक्षा अभियान
(B) छात्रवृत्ति योजना
(C) मध्याह्न भोजन (दोपहर का भोजन) योजना
(D) कन्या शिक्षा योजना

134. नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन (A) और एक तर्क (R) दिया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिये:
अभिकथन (A): 1967 के बाद बनी अधिकांश संयुक्त विधायक दल की सरकारें अस्थिर साबित हुईं।
तर्क (R): इन सरकारों में शामिल सभी दलों की विचारधारा और कार्यक्रम पूरी तरह से समान थे।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

135. निम्नलिखित सूची का मिलान कीजिये:
सूची I: (अवधि)
P. 1964-1966
Q. 1966-1977
R. 1967
S. 1969

सूची II: (प्रमुख घटना/पद)
1. चौथा आम चुनाव ('राजनीतिक भूकंप')
2. कांग्रेस का विभाजन
3. लालबहादुर शास्त्री का प्रधानमंत्रित्व काल

4. "गरीबी हटाओ"

निम्नलिखित में से कौन-सा सही मिलान है??
(A) P-1, Q-2, R-4, S-3
(B) P-1, Q-3, R-2, S-4
(C) P-4, Q-2, R-1, S-3
(D) P-2, Q-1, R-3, S-4

94. इंदिरा गाँधी द्वारा 1969 में की गई चौदह बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा के समय देश के उपप्रधानमंत्री और वित्तमंत्री कौन थे?
(A) वी. वी. गिरि
(B) के. कामराज
(C) जगजीवन राम
(D) मोरारजी देसाई

95. नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन (A) और एक तर्क (R) दिया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिये:
अभिकथन (A): इंदिरा गाँधी ने 1970 के दिसंबर में लोकसभा भंग करने की सिफारिश की, जो एक साहसिक कदम था।
तर्क (R): उनकी सरकार लोकसभा में पूर्ण बहुमत में थी और उन्हें किसी दल के समर्थन की आवश्यकता नहीं थी।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

96. 1967 के आम चुनावों के बाद, कांग्रेस को किन तीन राज्यों में दल-बदल के कारण गैर-कांग्रेसी सरकारों का सामना करना पड़ा?
(A) पंजाब, बिहार और पश्चिम बंगाल
(B) हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश
(C) केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा
(D) गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश

97. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. कांग्रेस (आर) और सीपीआई गठबंधन को 375 सीटें मिलीं।
2. अकेले कांग्रेस (आर) ने 352 सीटें जीतीं।
3. कांग्रेस (ओ) को केवल 16 सीटें मिलीं।
4. 'ग्रैंड अलायंस' को 100 से अधिक सीटें मिलीं।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1, 2 और 3
(C) केवल 2, 3 और 4
(D) 1, 2, 3 और 4 सभी

98. आधुनिक कर्नाटक के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है?
(A) एस. निजलिंगप्पा
(B) के. कामराज
(C) एस. के. पाटिल
(D) एन. संजीव रेड्डी

99. 1971 के चुनाव परिणामों ने कांग्रेस पार्टी की सामाजिक निर्भरता में क्या बदलाव दिखाया?
(A) पार्टी अब मुख्य रूप से उच्च जातियों और व्यापारी वर्ग पर निर्भर थी।
(B) पार्टी का समर्थन आधार सभी सामाजिक वर्गों में समान रूप से फैल गया।
(C) पार्टी अब गरीब, महिला, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों जैसे वर्गों पर ज़्यादा निर्भर थी।
(D) पार्टी का ग्रामीण क्षेत्रों में समर्थन समाप्त हो गया था।

100. नेहरू और इंदिरा गाँधी द्वारा अपनाई गई रणनीतियों में मुख्य अंतर क्या था?
(A) इंदिरा गाँधी की कांग्रेस अधिक संघीय थी, जबकि नेहरू की कांग्रेस केंद्रीकृत थी।
(B) नेहरू ने नारों की राजनीति की, जबकि इंदिरा ने वैचारिक राजनीति की।
(C) दोनों की रणनीतियों में कोई खास अंतर नहीं था।
(D) नेहरू की कांग्रेस एक संघीय और लोकतांत्रिक मंच थी, जबकि इंदिरा ने इसे केंद्रीकृत और अलोकतांत्रिक बना दिया।

101. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. लालबहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश से थे।
2. वे नेहरू के मंत्रिमंडल में कई सालों तक मंत्री रहे।
3. वे अपनी सादगी और सिद्धांत निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे।
4. उन्होंने कभी किसी मंत्रालय से इस्तीफा नहीं दिया।
5. नेहरू अपने आखिरी सालों में उन पर ज्यादा निर्भर नहीं थे।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 1, 3 और 5
(C) केवल 2, 4 और 5
(D) केवल 1 और 2

102. 1967 के चुनाव में सी. नटराजन अन्नादुरई के नेतृत्व में DMK की जीत का क्या महत्व था?
(A) यह पहली बार था जब किसी राज्य में गठबंधन सरकार बनी।
(B) यह पहली बार था जब किसी गैर-कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला।
(C) यह पहली बार था जब कांग्रेस केंद्र में सत्ता से बाहर हुई।
(D) यह पहली बार था जब किसी कम्युनिस्ट पार्टी ने राज्य में सरकार बनाई।

103. 'कामराज योजना' किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी?
(A) 1962
(B) 1964
(C) 1965
(D) 1963

से बाहर कर दिया और लोकसभा में भी उसके बहुमत को काफी कम कर दिया।

उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

161. 1967 के चुनाव परिणामों को 'राजनीतिक भूकंप' क्यों कहा गया?
(A) क्योंकि चुनाव हिंसक दंगों के बीच हुए थे।
(B) क्योंकि कांग्रेस ने पहले से भी अधिक बहुमत हासिल किया था।
(C) क्योंकि चुनाव परिणामों की घोषणा में अभूतपूर्व देरी हुई थी।
(D) क्योंकि इसने पहली बार कांग्रेस के प्रभुत्व को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गंभीर चुनौती दी थी।

162. 1965-66 के सूखे का भारत पर तत्काल आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा?
(A) औद्योगिक उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई।
(B) देश में गंभीर खाद्य संकट उत्पन्न हुआ और अनाज का आयात करना पड़ा।
(C) भारतीय रुपये का मूल्य बढ़ गया।
(D) विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई।

163. 1966 में भारतीय रुपये के अवमूल्यन का मुख्य कारण क्या था?
(A) भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता।
(B) सोवियत संघ के साथ एक व्यापार समझौता।
(C) विदेशी मुद्रा भंडार की कमी और बाहरी, विशेषकर अमेरिकी, दबाव।
(D) देश में सोने के विशाल भंडार की खोज।

164. रुपये के अवमूल्यन का आम जनता पर क्या तात्कालिक प्रभाव पड़ा?
(A) वस्तुओं की कीमतें कम हो गईं।
(B) बेरोजगारी पूरी तरह से समाप्त हो गई।
(C) लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई।
(D) आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई, जिससे महंगाई बढ़ी।

165. स्रोत के अनुसार, 1967 के चुनावों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के लिए कौन सा कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार था?
(A) गंभीर आर्थिक कठिनाइयों के कारण उत्पन्न व्यापक जन असंतोष।
(B) कांग्रेस के भीतर नेतृत्व का संकट।
(C) नेहरू की विरासत से मोहभंग।
(D) पड़ोसी देशों के साथ युद्ध।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन एक साधारण शक्ति संघर्ष न होकर एक गहन वैचारिक और पीढ़ीगत टकराव का परिणाम था। यह टकराव राष्ट्रपति चुनाव के दौरान चरम पर पहुँच गया। एक ओर 'सिंडिकेट' था, जो कांग्रेस के पुराने, स्थापित और संगठनात्मक रूप से शक्तिशाली नेताओं का प्रतिनिधित्व करता था। वे पार्टी की पारंपरिक, आम सहमति-आधारित कार्यप्रणाली को बनाए रखना चाहते थे और उनका पार्टी मशीनरी पर पूर्ण नियंत्रण था। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं, जो एक नई, अधिक करिश्माई और populist राजनीति का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। वह पार्टी संगठन को दरकिनार कर सीधे जनता से जुड़ना चाहती थीं। सिंडिकेट ने अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए, इंदिरा गांधी की आपत्तियों के बावजूद, एन. संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए आधिकारिक कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नामित किया। इंदिरा गांधी के लिए यह एक सीधी चुनौती थी, क्योंकि रेड्डी के साथ उनके राजनीतिक मतभेद जगजाहिर थे। इस चुनौती का जवाब देने के लिए, उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी.वी. गिरि को एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए परोक्ष रूप से प्रोत्साहित किया और पार्टी के सांसदों और विधायकों से 'अंतरात्मा की आवाज' पर वोट देने का आह्वान किया। यह व्हिप का खुला उल्लंघन था और इसने संघर्ष को विचारधारा का रूप दे दिया - प्रगतिशील (इंदिरा) बनाम यथास्थितिवादी (सिंडिकेट)। वी.वी. गिरि की जीत ने इंदिरा गांधी के अधिकार को स्थापित किया और सिंडिकेट को हाशिये पर धकेल दिया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः कांग्रेस पार्टी का औपचारिक विभाजन हो गया।

उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

166. 1969 के कांग्रेस विभाजन को स्रोत किस रूप में वर्णित करता है?
(A) केवल दो व्यक्तियों के बीच एक व्यक्तिगत झगड़ा।
(B) एक वैचारिक और पीढ़ीगत टकराव।
(C) विदेशी शक्तियों द्वारा प्रायोजित एक साजिश।
(D) भाषाई राज्यों के मुद्दे पर एक मतभेद।

167. 'सिंडिकेट' और इंदिरा गांधी के बीच संघर्ष का मुख्य बिंदु क्या था?
(A) विदेश नीति की दिशा।
(B) पार्टी के भीतर शक्ति और नियंत्रण।
(C) राज्यों का पुनर्गठन।
(D) संविधान में संशोधन।

168. इंदिरा गांधी ने 'अंतरात्मा की आवाज' पर वोट देने का आह्वान क्यों किया?
(A) पार्टी के व्हिप को धता बताकर अपने समर्थित उम्मीदवार वी.वी. गिरि को जिताने के लिए।
(B) पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार एन. संजीव रेड्डी का समर्थन करने के लिए।
(C) राष्ट्रपति चुनाव को स्थगित करवाने के लिए।
(D) सिंडिकेट के साथ समझौता करने के लिए।

3. राज्यों में गैर-कांग्रेसी गठबंधन सरकारों का उदय हुआ।
4. कांग्रेस के भीतर सत्ता-संघर्ष तेज हो गया।

1967 के चुनाव में कांग्रेस की कमजोरी के क्या परिणाम हुए?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2, 3 और 4
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) 1, 2, 3 और 4 सभी

115. कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने बिहार में पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू किया, किस नेता के प्रबल समर्थक थे?
(A) जवाहरलाल नेहरू
(B) जयप्रकाश नारायण
(C) राममनोहर लोहिया
(D) के. कामराज

116. 'ग्रैंड अलायंस' की विफलता का मुख्य कारण क्या था?
(A) उनके पास इंदिरा गाँधी से अधिक लोकप्रिय नेता थे।
(B) उनके पास चुनाव में भाग नहीं लिया।
(C) जनता कांग्रेस के शासन से ऊब चुकी थी।
(D) उनके पास 'इंदिरा हटाओ' के नारे के अलावा किसी सुसंगत, सकारात्मक कार्यक्रम का अभाव था।

117. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. उनकी कांग्रेस ही 'असली कांग्रेस' है।
2. भारतीय राजनीति में कांग्रेस का प्रभुत्व फिर से स्थापित हो गया।
3. 'गरीबी हटाओ' का नारा 'इंदिरा हटाओ' पर भारी पड़ा।
4. विपक्षी 'ग्रैंड अलायंस' एक विफल रणनीति थी।
5. सिंडिकेट के नेता प्रभावहीन हो गए।

1971 में इंदिरा गाँधी की जीत ने क्या स्थापित किया?
(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 3, 4 और 5
(C) केवल 1, 2, 3 और 4
(D) 1, 2, 3, 4 और 5 सभी

118. नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन (A) और एक तर्क (R) दिया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिये:
अभिकथन (A): इंदिरा गाँधी के नेतृत्व वाली 'नई कांग्रेस' पुरानी कांग्रेस की हूबहू नकल नहीं थी।
तर्क (R): नई कांग्रेस का सांगठनिक ढाँचा कमजोर था और यह पूरी तरह अपने नेता की लोकप्रियता पर आश्रित थी।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

119. वी. वी. गिरि राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के किस पद पर थे?
(A) प्रधानमंत्री
(B) लोकसभा अध्यक्ष
(C) मुख्य न्यायाधीश
(D) उपराष्ट्रपति

120. निम्नलिखित सूची का मिलान कीजिये:
सूची I: (दल)
P. कांग्रेस (ओ)
Q. कांग्रेस (आर)
R. डी.एम.के.
S. भारतीय जनसंघ

सूची II: (1971 के चुनाव में भूमिका)
1. 'ग्रैंड अलायंस' का हिस्सा
2. कांग्रेस (आर) के साथ गठबंधन में
3. 'गरीबी हटाओ' के नारे के साथ चुनाव जीता
4. मद्रास में प्रमुख दल

निम्नलिखित में से कौन-सा सही मिलान है??
(A) P-1, Q-3, R-4, S-1
(B) P-1, Q-3, R-2, S-1
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-2, Q-3, R-1, S-4

121. "कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना" का क्या अर्थ है?
(A) पुरानी कांग्रेस प्रणाली का हूबहू वापस आना।
(B) सिंडिकेट का फिर से पार्टी पर नियंत्रण स्थापित करना।
(C) कांग्रेस पार्टी का फिर से प्रभुत्वशाली स्थिति में आना, भले ही उसकी प्रकृति बदल गई हो।
(D) कांग्रेस का सभी गुटों को साथ लेकर चलने की क्षमता पुनः प्राप्त करना।

122. कांग्रेस के चुनाव चिह्न 'दो बैलों की जोड़ी' से 'गाय और बछड़ा' में परिवर्तन किस घटना को दर्शाता है?
(A) 1969 में पार्टी के विभाजन को।
(B) 1967 के चुनाव को।
(C) 1971 के युद्ध को।
(D) 1965 के युद्ध को।

123. 1967 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में सरकार बनाने में सफल रही?
(A) केरल
(B) पश्चिम बंगाल
(C) उड़ीसा
(D) आंध्र प्रदेश

124. राममनोहर लोहिया के अनुसार, गैर-कांग्रेसी दलों को क्यों एक साथ आना चाहिए था?
(A) सत्ता में हिस्सेदारी के लिए।
(B) गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस लाने के लिए।
(C) अपनी-अपनी विचारधाराओं का प्रसार करने के लिए।
(D) एक मजबूत दक्षिणपंथी मोर्चा बनाने के लिए।

125. 1967 के चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन के बारे में कौन सा कथन गलत है?

104. 1969 के राष्ट्रपति चुनाव के समय जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कार्यकारी राष्ट्रपति कौन बने थे?
(A) वी. वी. गिरि
(B) एन. संजीव रेड्डी
(C) बी. डी. जत्ती
(D) मोरारजी देसाई

105. निम्नलिखित सूची का मिलान कीजिये:
सूची I: (नेता)
P. मोरारजी देसाई
Q. इंदिरा गाँधी
R. वी. वी. गिरि
S. एन. संजीव रेड्डी
सूची II: (1969 के चुनाव में भूमिका/पद)
1. कांग्रेस की प्रधानमंत्री, जिन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार का समर्थन किया
2. कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार
3. बंबई प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री
4. स्वतंत्र उम्मीदवार जो चुनाव जीते
निम्नलिखित में से कौन-सा सही मिलान है??
(A) P-3, Q-1, R-4, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

106. नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन (A) और एक तर्क (R) दिया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिये:
अभिकथन (A): 1967 के चुनाव अभियान में इंदिरा गाँधी को कम अनुभवी माना जा रहा था।
तर्क (R): प्रधानमंत्री बनने से पहले वे लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय थीं और शास्त्री मंत्रिमंडल में मंत्री भी रह चुकी थीं।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

107. रुपये के अवमूल्यन के बाद 1 अमरीकी डॉलर की कीमत 5 रुपये से बढ़कर कितनी हो गई थी?
(A) 6 रुपये
(B) 8 रुपये
(C) 10 रुपये
(D) 7 रुपये

108. 1967 के बाद, इंदिरा गाँधी ने अपनी सरकार और पार्टी पर पकड़ मजबूत करने के लिए जो रणनीति अपनाई, वह क्या थी?
(A) सिंडिकेट के साथ मिलकर काम करना।
(B) एक साधारण सत्ता-संघर्ष को विचारधारात्मक संघर्ष में बदलना और वामपंथी नीतियां अपनाना।
(C) सभी विपक्षी दलों को सरकार में शामिल करना।
(D) दक्षिणपंथी आर्थिक नीतियों को अपनाना।

109. 'दस-सूत्री कार्यक्रम' (1967) के प्रति सिंडिकेट के नेताओं का क्या रवैया था?
(A) उन्होंने इसका पुरजोर समर्थन किया।
(B) उन्होंने खुलेआम विरोध किया और इसे खारिज कर दिया।
(C) उन्होंने औपचारिक तौर पर स्वीकृति दी, लेकिन मन में गहरे संदेह थे।
(D) उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।

110. 'प्रिवी पर्स' की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए अंतिम रूप से संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया?
(A) 1970
(B) 1969
(C) 1972
(D) 1971

111. 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश के निर्माण से इंदिरा गाँधी की छवि पर क्या प्रभाव पड़ा?
(A) उनकी लोकप्रियता में चार चाँद लग गए और विपक्ष ने भी उनके राज्यकौशल की प्रशंसा की।
(B) उनकी लोकप्रियता में कमी आई।
(C) उनकी छवि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
(D) उन्हें एक कमजोर नेता के रूप में देखा जाने लगा।

112. निम्नलिखित में से किसने 'India's Disintegrating Democracy' लेख में यह तर्क दिया कि भारत में लोकतंत्र का प्रयोग असफल हो चुका है?
(A) आनंद चक्रवर्ती
(B) नेविल मैक्सवेल
(C) सुदीप्त कविराज
(D) रजनी कोठारी

113. 1960 के दशक के संदर्भ में, इंदिरा गाँधी के राजनीतिक उदय से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें:
1. सूचना मंत्री के रूप में कार्यभार
2. कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य
3. प्रधानमंत्री बनना
4. लोकसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व
(A) 2, 1, 3, 4
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 3, 1, 4
(D) 3, 1, 2, 4

114. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. यह साबित हो गया कि कांग्रेस को चुनावों में हराया जा सकता है।
2. दल-बदल की परिघटना को बढ़ावा मिला।

4. इंदिरा गाँधी का पहला प्रधानमंत्रित्व काल

निम्नलिखित में से कौन-सा सही मिलान है??

(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

136. वह कौन सी घटना थी जिसके बाद एस. निजलिंगप्पा ने इंदिरा गाँधी को पार्टी से निष्कासित करते हुए लिखा कि वे "चरित्रहीन चाटुकार दरबारियों की बातों में जीने लगी हैं"?

(A) 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार की हार के बाद।
(B) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद।
(C) प्रिवी पर्स की समाप्ति के बाद।
(D) 1971 के चुनावों के बाद।

137. 1971 के आम चुनाव को मध्यावधि चुनाव क्यों कहा जाता है?

(A) क्योंकि यह केवल कुछ राज्यों में हुआ था।
(B) क्योंकि यह युद्ध के बीच में हुआ था।
(C) क्योंकि यह सरकार के 5 साल पूरे होने से पहले ही करा लिया गया।
(D) क्योंकि इसमें केवल लोकसभा के लिए मतदान हुआ, विधानसभा के लिए नहीं।

138. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. गरीबी हटाओ जैसे नारों के माध्यम से एक समाजवादी छवि।
2. बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स की समाप्ति।
3. 1971 के भारत-पाक युद्ध में निर्णायक जीत।
4. सिंडिकेट के नेताओं पर विजय।

1970 के दशक की शुरुआत में इंदिरा गाँधी की सरकार की लोकप्रियता के क्या कारण थे?

(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2 और 4
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) 1, 2, 3 और 4 सभी

139. 1971 के आम चुनाव में 'ग्रैंड अलायंस' को कितनी सीटें मिली थीं?

(A) 100 से अधिक
(B) लगभग 80
(C) 150
(D) 60 से भी कम

140. निम्नलिखित में से किस नेता का संबंध जस्टिस पार्टी और द्रविड़ कषगम से था और उन्होंने द्रविड़ संस्कृति के समर्थक के रूप में हिंदी का विरोध किया?

(A) कामराज
(B) सी. नटराजन अन्नादुरई
(C) सी. राजगोपालाचारी
(D) ई. वी. रामासामी नायकर

141. 1967 के चुनाव के समय तक कांग्रेस को देश पर कितने वर्षों तक शासन करने का अनुभव था?

(A) 10 वर्ष
(B) 15 वर्ष
(C) 20 वर्ष
(D) 22 वर्ष

142. इंदिरा गाँधी ने प्रधानमंत्री पद के लिए मोरारजी देसाई के साथ हुए मुकाबले में किस प्रकार जीत हासिल की?

(A) सर्वसम्मति से चुनाव द्वारा।
(B) कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के निर्णय द्वारा।
(C) लॉटरी द्वारा।
(D) कांग्रेस सांसदों के बीच हुए गुप्त मतदान द्वारा।

143. निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच गहरे मतभेद का कारण बना, जिसके परिणामस्वरूप देसाई ने सरकार से किनारा कर लिया?

(A) बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स की समाप्ति
(B) विदेश नीति
(C) राज्यों का पुनर्गठन
(D) हिंदी भाषा का प्रयोग

144. निम्नलिखित में से कौन सा कथन 'नई कांग्रेस' की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

(A) यह एक ऐसी पार्टी थी जिसमें कई गुट और नेता अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र में स्वतंत्र थे।
(B) यह एक ऐसी पार्टी थी जो पूरी तरह से अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर निर्भर थी।
(C) यह एक ऐसी पार्टी थी जिसका सांगठनिक ढाँचा बहुत मजबूत था।
(D) यह एक ऐसी पार्टी थी जो विचारधारा की बजाय केवल सत्ता पर केंद्रित थी।

145. नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन (A) और एक तर्क (R) दिया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिये:

अभिकथन (A): 1972 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को व्यापक सफलता मिली।

तर्क (R): 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत ने इंदिरा गाँधी की लोकप्रियता को शिखर पर पहुँचा दिया था।

(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

146. 1967 के बाद की दलीय प्रणाली को 'कांग्रेस प्रणाली' के स्थान पर 'बहुदलीय प्रणाली' क्यों कहा जाने लगा?

(A) क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर अनेक दलों का उभरना और राज्यों में विभिन्न दलों की सरकारों का गठन होना।
(B) क्योंकि केंद्र में कांग्रेस का प्रभुत्व समाप्त हो गया था।

(C) राममनोहर लोहिया
(D) एस. निजलिंगप्पा

84. 1967 के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस राजस्थान में सरकार कैसे बना पाई?
(A) पूर्ण बहुमत प्राप्त करके।
(B) दल-बदल करवाकर।
(C) राष्ट्रपति शासन लगाकर।
(D) उसे बहुमत नहीं मिला, लेकिन कुछ अन्य की सहायता से सरकार बनाई।

85. नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन (A) और एक तर्क (R) दिया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिये:
अभिकथन (A): 1971 के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर ली।
तर्क (R): इंदिरा गाँधी ने कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदले बिना उसे पुनर्स्थापित किया।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

86. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. के. कामराज (तमिलनाडु)
2. एस. के. पाटिल (महाराष्ट्र)
3. इंदिरा गाँधी (उत्तर प्रदेश)
4. अतुल्य घोष (पश्चिम बंगाल)
5. के. बी. सहाय (बिहार)

1967 के चुनावों में निम्नलिखित में से कौन-से कांग्रेसी दिग्गज नेता चुनाव हार गए थे?
(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 1, 2, 4 और 5
(C) केवल 3, 4 और 5
(D) 1, 2, 3, 4 और 5 सभी

87. कांग्रेस के भीतर 'सिंडिकेट' के प्रभाव के संबंध में कौन सा कथन सही है?
(A) सिंडिकेट का प्रभाव केवल राज्य स्तर की राजनीति तक सीमित था।
(B) उन्होंने इंदिरा गाँधी को प्रधानमंत्री बनाने का विरोध किया था।
(C) 1971 के बाद भी सिंडिकेट के नेता भारतीय राजनीति में बहुत प्रभावशाली बने रहे।
(D) इंदिरा गाँधी के पहले मंत्रिमंडल में और नीति निर्माण में समूह की निर्णायक भूमिका थी।

88. 1969 में कांग्रेस में विभाजन के बाद, इंदिरा गाँधी की सरकार ने किसके बल पर सत्ता में बनी रही?
(A) डी.एम.के. और सी.पी.आई. जैसे दलों से प्राप्त मुद्दा-आधारित समर्थन के बल पर।
(B) कांग्रेस (ओ) के समर्थन से।
(C) भारतीय जनसंघ के समर्थन से।
(D) लोकसभा में पूर्ण बहुमत होने के कारण।

89. 1973 में आई फिल्म 'जंजीर' का नायक किस समकालीन भावना का प्रतिनिधित्व करता है?
(A) व्यवस्था के प्रति पूर्ण समर्पण।
(B) राजनीतिक चाटुकारिता।
(C) व्यवस्था के नैतिक पतन और लाचारी से उपजा गुस्सा और क्षोभ।
(D) अहिंसक विरोध का आदर्श।

90. निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें:
1. चौथा आम चुनाव
2. लालबहादुर शास्त्री की मृत्यु
3. कांग्रेस पार्टी का विभाजन
4. बांग्लादेश का निर्माण

(A) 1, 2, 3, 4
(B) 2, 1, 3, 4
(C) 2, 3, 1, 4
(D) 3, 2, 1, 4

91. 1967 के चुनाव के बाद बने 'पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट' की सरकार में कौन-से दो परस्पर प्रतिस्पर्धी दल शामिल थे?
(A) सीपीआई और सीपीआई(एम)
(B) एसएसपी और पीएसपी
(C) कांग्रेस और जनसंघ
(D) अकाली दल के संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप

92. 1971 के 'ग्रैंड अलायंस' के बारे में कौन सा कथन ठीक है?
(A) इसका गठन सभी गैर-कांग्रेसी दलों ने एकजुट होकर किया था।
(B) इसका गठन गैर-कम्युनिस्ट और गैर-कांग्रेसी दलों ने किया था।
(C) इसके पास एक स्पष्ट राजनीतिक तथा विचारधारात्मक कार्यक्रम था।
(D) इसने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था।

93. निम्नलिखित सूची का मिलान कीजिये:
सूची I: (शब्द/वाक्यांश)
P. सिंडिकेट
Q. दल-बदल
R. नारा
S. गैर-कांग्रेसवाद

सूची II: (परिभाषा/उदाहरण)
1. कांग्रेस के भीतर ताकतवर नेताओं का समूह
2. एक निर्वाचित प्रतिनिधि का अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे दल में जाना
3. कांग्रेस के खिलाफ विभिन्न दलों का एकजुट होना

155. नेहरू के बाद के उत्तराधिकार के संदर्भ में, स्रोत यह निष्कर्ष निकालता है कि:
(A) भारत नेतृत्व परिवर्तन की अपनी पहली परीक्षा में विफल रहा।
(B) उत्तराधिकार का निर्णय पूरी तरह से शास्त्री की व्यक्तिगत लोकप्रियता पर आधारित था।
(C) कांग्रेस पार्टी का संगठनात्मक ढाँचा इस शांतिपूर्ण संक्रमण में महत्वपूर्ण था।
(D) सिंडिकेट ने जानबूझकर एक कमजोर प्रधानमंत्री चुना ताकि वे स्वयं शासन कर सकें।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
1960 के दशक के मध्य में, भारतीय राजनीति में 'गैर-कांग्रेसवाद' की अवधारणा एक शक्तिशाली राजनीतिक रणनीति के रूप में उभरी, जिसके प्रमुख प्रस्तावक समाजवादी नेता राममनोहर लोहिया थे। लोहिया का तर्क केवल राजनीतिक अवसरवाद पर आधारित नहीं था, बल्कि यह एक गहरी वैचारिक आलोचना से प्रेरित था। उनका मानना था कि लगभग दो दशकों का निरंतर कांग्रेस शासन अलोकतांत्रिक हो गया है और उसने देश में जड़ता पैदा कर दी है। उन्होंने तर्क दिया कि कांग्रेस की नीतियां आम जनता, विशेषकर गरीबों, दलितों और पिछड़ी जातियों के हितों के विरुद्ध हैं। इसलिए, लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने और गरीबों के पक्ष में नीतियां बनाने के लिए कांग्रेस को सत्ता से हटाना अनिवार्य था। लोहिया की 'गैर-कांग्रेसवाद' की रणनीति इस सिद्धांत पर आधारित थी कि चूंकि कांग्रेस विरोधी वोट विभिन्न दलों में विभाजित हो जाते हैं, जिससे कांग्रेस कम वोट प्रतिशत के बावजूद जीत जाती है, इसलिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना चाहिए। यह एक वैचारिक रूप से विषम गठबंधन था, जिसमें दक्षिणपंथी भारतीय जनसंघ से लेकर वामपंथी समाजवादी और साम्यवादी दल शामिल थे। इस रणनीति का मूलमंत्र यह था कि इन दलों के बीच विचारधारात्मक मतभेद चाहे कितने भी गहरे क्यों न हों, कांग्रेस को हराने के साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर उन्हें एक साथ आना चाहिए। यह 1967 के चुनावों में विशेष रूप से प्रभावी साबित हुआ, जब कई राज्यों में संयुक्त विधायक दल (SVD) की सरकारें बनीं।
उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

156. राममनोहर लोहिया की 'गैर-कांग्रेसवाद' की रणनीति का मूल वैचारिक आधार क्या था?
(A) कांग्रेस के समाजवादी मॉडल को अपनाना।
(B) कांग्रेस शासन को अलोकतांत्रिक और जन-विरोधी मानना।
(C) भारत को एक हिन्दू राष्ट्र के रूप में स्थापित करना।
(D) केवल समाजवादी दलों का एक मजबूत गठबंधन बनाना।

157. 'गैर-कांग्रेसवाद' की चुनावी रणनीति का मुख्य तत्व क्या था?
(A) सभी विपक्षी दलों का कांग्रेस में विलय हो जाना।
(B) चुनाव का पूरी तरह से बहिष्कार करना।
(C) केवल समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन करना।
(D) कांग्रेस को हराने के लिए सभी विपक्षी दलों द्वारा एकजुट होकर चुनाव लड़ना।

158. लोहिया के अनुसार, कांग्रेस विरोधी वोटों के विभाजन का क्या परिणाम होता था?
(A) कांग्रेस कम वोट पाकर भी चुनाव जीत जाती थी।
(B) विपक्षी दल अधिक मजबूत हो जाते थे।
(C) देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती थी।
(D) मतदाताओं का चुनावी प्रक्रिया से मोहभंग हो जाता था।

159. 'गैर-कांग्रेसवाद' के तहत बने गठबंधनों की प्रकृति कैसी थी?
(A) वे पूरी तरह से वामपंथी दलों पर आधारित थे।
(B) वे केवल क्षेत्रीय दलों का एक समूह थे।
(C) वे वैचारिक रूप से विषम थे, जिनमें दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों दल शामिल थे।
(D) वे वैचारिक रूप से समरूप और सुसंगत थे।

160. 1967 के चुनावों के संदर्भ में, 'गैर-कांग्रेसवाद' का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था?
(A) कई राज्यों में संयुक्त विधायक दल की गठबंधन सरकारों का गठन।
(B) केंद्र में कांग्रेस की सरकार का पतन।
(C) राममनोहर लोहिया का प्रधानमंत्री बनना।
(D) भारतीय जनसंघ का सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में उभरना।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
1967 का चौथा आम चुनाव भारतीय राजनीति में एक 'राजनीतिक भूकंप' के रूप में देखा जाता है, जिसने कांग्रेस के एकछत्र प्रभुत्व को गंभीर चुनौती दी। इस चुनावी उलटफेर के पीछे कई गहरे सामाजिक-आर्थिक कारण विद्यमान थे। 1960 के दशक के मध्य में भारत लगातार दो गंभीर सूखे (1965-66) की चपेट में था, जिससे कृषि उत्पादन में भारी गिरावट आई और देशव्यापी खाद्य संकट उत्पन्न हो गया। इस संकट ने भारत को अमेरिका से पीएल-480 कार्यक्रम के तहत अपमानजनक शर्तों पर अनाज आयात करने के लिए विवश किया। विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी और बढ़ते भुगतान असंतुलन के दबाव में, इंदिरा गांधी की सरकार को 1966 में अमेरिकी दबाव के तहत रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा, जिससे भारतीय रुपये का मूल्य लगभग 57% कम हो गया। इस अवमूल्यन ने आयात को महंगा कर दिया और इसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना था, लेकिन तत्काल परिणाम व्यापक महंगाई के रूप में सामने आया। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ीं, जिससे शहरी मध्यम वर्ग और गरीबों में व्यापक असंतोष फैल गया। इन आर्थिक कठिनाइयों, बढ़ती बेरोजगारी और सरकार की नीतियों के प्रति मोहभंग ने एक शक्तिशाली जन-विरोध को जन्म दिया। विपक्षी दलों ने इस असंतोष को सफलतापूर्वक भुनाया और 'गैर-कांग्रेसवाद' के नारे के तहत एकजुट होकर कांग्रेस को कई राज्यों में सत्ता

(C) क्योंकि कांग्रेस कई टुकड़ों में बँट गई थी।
(D) क्योंकि केवल दो प्रमुख दल रह गए थे।

147. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. इंदिरा गाँधी की रणनीति सफल रही।
2. सिंडिकेट के पुराने नेता जनता से कट चुके थे।
3. भारत की जनता ने एक मजबूत और निर्णायक नेता को प्राथमिकता दी।
4. 'इंदिरा हटाओ' का नकारात्मक नारा जनता को पसंद नहीं आया।
5. गठबंधन की राजनीति हमेशा सफल नहीं होती।

1971 के आम चुनाव के परिणाम ने क्या सिद्ध किया?
(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 3, 4 और 5
(C) केवल 1, 2, 3 और 4
(D) 1, 2, 3, 4 और 5 सभी

148. राजस्थान के एक गाँव की चुनाव-कथा में चाचा (शेर सिंह) और भतीजे (भीम सिंह) की खेमेबाजी में कौन-कौन सी दो पार्टियाँ आमने-सामने थीं?
(A) कांग्रेस और भारतीय जनसंघ
(B) कम्युनिस्ट पार्टी
(C) सोशलिस्ट पार्टी
(D) स्वतंत्र पार्टी

149. नेहरू की मृत्यु के बाद उत्पन्न राजनीतिक उत्तराधिकार के प्रश्न को आलोचकों ने किस प्रकार इतनी आसानी से हल होते देखकर आश्चर्य व्यक्त किया?
(A) क्योंकि यह हिंसक संघर्ष के बाद हल हुआ।
(B) क्योंकि सेना ने हस्तक्षेप करके इसे हल किया।
(C) क्योंकि यह बिना किसी विवाद के, सलाह-मशविरे से और शांतिपूर्ण ढंग से हल हो गया।
(D) क्योंकि यह प्रश्न कभी हल ही नहीं हुआ।

150. अंतिम विश्लेषण में, 1971 के बाद 'कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन' क्या दर्शाता है?
(A) कांग्रेस पार्टी की पुरानी संरचना और प्रकृति की वापसी।
(B) भारत की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत, जहाँ एक नेता का करिश्मा पार्टी संगठन पर हावी हो गया।
(C) भारत में गठबंधन सरकारों के युग की स्थायी शुरुआत।
(D) विपक्षी दलों का पूर्ण सफाया।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

जवाहरलाल नेहरू के निधन के उपरांत भारतीय राजनीति एक महत्वपूर्ण चौराहे पर खड़ी थी। विश्व के अनेक नव-स्वतंत्र राष्ट्रों में नेतृत्व परिवर्तन प्रायः सैन्य हस्तक्षेप या राजनीतिक अस्थिरता के माध्यम से होता था, जिसके कारण भारत के लोकतांत्रिक भविष्य पर भी अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों द्वारा संदेह व्यक्त किया जा रहा था। इस संक्रमण काल में, 'सिंडिकेट' के रुप में जाने जाने वाले कांग्रेस के प्रभावशाली प्रादेशिक नेताओं के समूह ने एक निर्णायक भूमिका निभाई। इस समूह में के. कामराज, एस. के. पाटिल, और अतुल्य घोष जैसे नेता शामिल थे, जिनका पार्टी संगठन पर गहरा नियंत्रण था। उन्होंने मोरारजी देसाई जैसे महत्वाकांक्षी नेता के बजाय लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तावित किया, जो अपनी विनम्रता और सर्वसम्मति-निर्माण की क्षमता के लिए जाने जाते थे। यह चयन एक रणनीतिक निर्णय था, जिसका उद्देश्य पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बनाए रखना और एक ऐसे नेता को आगे लाना था जो सिंडिकेट के प्रभाव को स्वीकार करे। शास्त्री का निर्विरोध निर्वाचन भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का एक सशक्त प्रमाण था, जिसने यह दर्शाया कि भारत नेतृत्व परिवर्तन की चुनौती को संवैधानिक और शांतिपूर्ण ढंग से हल करने में सक्षम है। इस प्रक्रिया ने कांग्रेस पार्टी के भीतर संगठन की शक्ति और सामूहिक नेतृत्व की परंपरा को भी रेखांकित किया, जो नेहरु युग की एक प्रमुख विशेषता थी।

उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

151. नेहरु के निधन के बाद अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को भारत के विषय में क्या प्रमुख चिंता थी?
(A) भारत की आर्थिक नीतियों में संभावित बदलाव।
(B) नेतृत्व परिवर्तन के कारण राजनीतिक अस्थिरता या सैन्य हस्तक्षेप की आशंका।
(C) भारत की गुटनिरपेक्ष नीति का परित्याग।
(D) भाषाई राज्यों के पुनर्गठन की मांग का तीव्र होना।

152. लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री के रुप में चुनने में 'सिंडिकेट' का मुख्य उद्देश्य क्या था?
(A) पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बनाए रखना और अपने प्रभाव को कायम रखना।
(B) मोरारजी देसाई की वरिष्ठता को सम्मानित करना।
(C) एक युवा और गतिशील नेता को अवसर प्रदान करना।
(D) नेहरु की समाजवादी नीतियों को पूर्ण रुप से बदलना।

153. स्रोत के अनुसार, शास्त्री का निर्विरोध निर्वाचन किस बात का प्रतीक था?
(A) कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की समाप्ति।
(B) मोरारजी देसाई का पार्टी पर पूर्ण नियंत्रण।
(C) भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता और संवैधानिक प्रक्रियाओं की सफलता।
(D) सैन्य नेतृत्व का राजनीतिक मामलों में बढ़ता प्रभाव।

154. निम्नलिखित में से कौन सा कथन 'सिंडिकेट' की भूमिका को सबसे सटीक रूप से वर्णित करता है?
(A) यह नेहरु के परिवार के सदस्यों का एक समूह था जो राजनीति को नियंत्रित करता था।
(B) यह कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं का एक गुट था जो सुधारों की मांग कर रहा था।
(C) यह विपक्षी दलों का एक गठबंधन था जो कांग्रेस को चुनौती दे रहा था।
(D) यह प्रभावशाली प्रादेशिक नेताओं का एक समूह था जिनका पार्टी संगठन पर नियंत्रण था।

169. 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में वी.वी. गिरि की जीत का क्या परिणाम हुआ?
(A) सिंडिकेट पार्टी पर और अधिक शक्तिशाली हो गया।
(B) इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।
(C) इसने इंदिरा गांधी को पार्टी के सर्वोच्च नेता के रूप में स्थापित किया और विभाजन को गति दी।
(D) कांग्रेस पार्टी एकजुट हो गई और सभी मतभेद समाप्त हो गए।

170. स्रोत के अनुसार, इंदिरा गांधी की राजनीतिक शैली सिंडिकेट से किस प्रकार भिन्न थी?
(A) वह संगठनात्मक मशीनरी पर अधिक निर्भर थीं।
(B) वह आम सहमति बनाने में विश्वास करती थीं।
(C) वह पार्टी के पुराने नेताओं के मार्गदर्शन में काम करना पसंद करती थीं।
(D) वह सीधे जनता से जुड़ने वाली एक लोकलुभावन और करिश्माई राजनीति पर जोर देती थीं।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

1971 के चुनावों में इंदिरा गांधी की शानदार जीत को अक्सर 'कांग्रेस प्रणाली' की पुनर्स्थापना के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह एक भ्रामक सरलीकरण है। वास्तव में, इस जीत ने एक 'नई कांग्रेस' को जन्म दिया, जिसकी प्रकृति नेहरू युग की 'पुरानी कांग्रेस प्रणाली' से मौलिक रूप से भिन्न थी। पुरानी कांग्रेस प्रणाली एक व्यापक, छाता संगठन थी जो विभिन्न विचारधाराओं, गुटों और हितों को अपने भीतर समाहित करती थी। इसमें शक्ति का विकेंद्रीकरण था और निर्णय प्रक्रिया आम सहमति तथा आंतरिक सौदेबाजी पर आधारित थी। प्रादेशिक क्षत्रपों (जैसे सिंडिकेट के नेता) का संगठन में महत्वपूर्ण स्थान था। इसके विपरीत, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में उभरी नई कांग्रेस अत्यधिक केंद्रीकृत थी और उसकी शक्ति पूरी तरह से एक व्यक्ति - स्वयं इंदिरा गांधी - के करिष्मे में निहित थी। पार्टी का संगठनात्मक ढांचा कमजोर हो गया और आंतरिक लोकतंत्र लगभग समाप्त हो गया। निर्णय ऊपर से लिए जाने लगे और पार्टी अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री के अधीन हो गए। 'गरीबी हटाओ' जैसे नारों पर आधारित इसकी लोकलुभावन राजनीति ने इसे गरीबों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के बीच लोकप्रिय तो बनाया, लेकिन इसने पार्टी को इन सामाजिक वर्गों पर अत्यधिक निर्भर भी कर दिया। इस प्रकार, 1971 में जो पुनर्स्थापित हुआ, वह कांग्रेस का प्रभुत्व था, न कि वह प्रणाली जो आंतरिक बहुलवाद और आम सहमति पर आधारित थी। यह परिवर्तन भारतीय राजनीति में एक अधिक सत्तावादी और व्यक्तिगत नेतृत्व वाली शैली का सूचक था।

उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

171. स्रोत के अनुसार, 1971 के बाद की 'नई कांग्रेस' और नेहरू युग की 'पुरानी कांग्रेस' में मुख्य अंतर क्या था?
(A) नई कांग्रेस अधिक विकेंद्रीकृत थी।
(B) पुरानी कांग्रेस एक व्यक्ति के करिष्मे पर आधारित थी।
(C) नई कांग्रेस अत्यधिक केंद्रीकृत थी जबकि पुरानी कांग्रेस एक छाता संगठन थी।
(D) नई कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र अधिक मजबूत था।

172. 'पुरानी कांग्रेस प्रणाली' की प्रमुख विशेषता क्या थी?
(A) सभी निर्णय एक सर्वोच्च नेता द्वारा लिए जाते थे।
(B) यह विभिन्न विचारधाराओं और गुटों का एक समावेशी मंच थी।
(C) इसका संगठनात्मक ढांचा कमजोर था।
(D) यह केवल एक विशेष सामाजिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी।

173. इंदिरा गांधी के नेतृत्व में नई कांग्रेस की शक्ति का मुख्य स्रोत क्या था?
(A) पार्टी का मजबूत संगठनात्मक नेटवर्क।
(B) प्रादेशिक नेताओं का समर्थन।
(C) विपक्षी दलों के साथ गठबंधन।
(D) स्वयं इंदिरा गांधी का व्यक्तिगत करिश्मा और लोकलुभावन अपील।

174. 'गरीबी हटाओ' जैसे नारों की राजनीति ने कांग्रेस पार्टी को कैसे प्रभावित किया?
(A) इसने पार्टी को कुछ विशेष सामाजिक वर्गों, जैसे गरीबों और अल्पसंख्यकों पर निर्भर बना दिया।
(B) इसने पार्टी को अमीर और मध्यम वर्ग के बीच अधिक लोकप्रिय बनाया।
(C) इसने पार्टी के भीतर गुटबाजी को बढ़ावा दिया।
(D) इसने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया।

175. स्रोत का समग्र निष्कर्ष क्या है?
(A) 1971 में कांग्रेस प्रणाली ठीक वैसे ही पुनर्स्थापित हुई जैसी वह नेहरू के समय में थी।
(B) इंदिरा गांधी ने नेहरू की राजनीतिक विरासत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया।
(C) 1971 की जीत ने कांग्रेस के प्रभुत्व को तो पुनर्स्थापित किया, लेकिन एक नई, केंद्रीकृत और व्यक्तिगत प्रणाली के तहत।
(D) 1971 के बाद कांग्रेस एक कमजोर और महत्वहीन पार्टी बन गई।

65. (C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
1969 के राष्ट्रपति चुनाव ने कांग्रेस के आंतरिक कलह को चरम पर पहुँचा दिया। इंदिरा गाँधी द्वारा समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवार वी. वी. गिरि की जीत ने पार्टी के विभाजन को अपरिहार्य बना दिया। तर्क गलत है क्योंकि एन. संजीव रेड्डी कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार थे, जबकि वी. वी. गिरि ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। इस चुनावी परिणाम ने सिंडिकेट के अधिकार को गंभीर चुनौती दी थी।

66. (A) अपने कार्यक्रमों के पक्ष में जनादेश हासिल करना और अन्य दलों पर निर्भरता समाप्त करना।
1970 के अंत में इंदिरा गाँधी ने एक साहसिक निर्णय लेते हुए लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की। उस समय उनकी सरकार अल्पमत में थी और अन्य दलों के समर्थन पर टिकी थी। वे चाहती थीं कि "गरीबी हटाओ" जैसे अपने प्रगतिशील कार्यक्रमों के लिए उन्हें जनता से सीधा और पूर्ण बहुमत मिले। यह मध्यावधि चुनाव कराने का उनका दांव पूरी तरह सफल रहा और उन्हें भारी जनसमर्थन प्राप्त हुआ।

67. (D) 1, 2, 3 और 4 सभी
1967 का चुनाव कांग्रेस के लिए एक बड़ा सबक था। उसे नौ राज्यों में सत्ता से बाहर होना पड़ा। मद्रास में DMK की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी, जबकि अन्य राज्यों में गठबंधन की संविद सरकारें गठित हुईं। कुछ राज्यों में कांग्रेस को बहुमत तो मिला था, लेकिन विधायकों के दल-बदल के कारण वह सरकार बनाने में विफल रही। इन घटनाओं ने भारतीय राजनीति में गठबंधन के युग का सूत्रपात किया।

68. (D) 1967
यह प्रसिद्ध टिप्पणी 1967 के चुनाव परिणामों की तीव्रता को दर्शाती है। उस समय उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस की हार हुई थी। दिल्ली से बंगाल तक के रास्ते में पड़ने वाले सभी राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में गैर-कांग्रेसी सरकारें बन गई थीं। यह स्थिति कांग्रेस के उस एकाधिकार के अंत का प्रतीक थी जो आजादी के बाद से लगातार बना हुआ था।

69. (C) मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी
1969 के दौरान साम्यवादी आंदोलन में एक और विभाजन हुआ। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPI-M) के भीतर एक उग्र गुट ने अलग होकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) का गठन किया। इस नए दल ने संसदीय राजनीति के बजाय सशस्त्र क्रांति और किसान विद्रोह का रास्ता चुना। चारु मजुमदार इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इस विभाजन ने भारतीय वामपंथी राजनीति को और अधिक खंडित कर दिया।

70. (A) 4, 3, 2, 1
1969 का राजनीतिक ड्रामा एक क्रमबद्ध तरीके से बढ़ा। पहले सिंडिकेट ने एन. संजीव रेड्डी को आधिकारिक उम्मीदवार बनाया। इसके जवाब में इंदिरा गाँधी ने 'अंतरात्मा की आवाज़' पर वोट देने की अपील की। इसके परिणामस्वरूप वी. वी. गिरि चुनाव जीत गए। इस पराजय से बौखलाए कांग्रेस संगठन ने अनुशासनहीनता के आरोप में इंदिरा गाँधी को पार्टी से निष्कासित कर दिया, जिससे विभाजन की प्रक्रिया पूरी हो गई।

71. (D) क्योंकि उनके समर्थकों ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक आयोजित करने की याचना (requisition) की थी।
कांग्रेस में विभाजन के बाद इंदिरा गाँधी के गुट को तकनीकी रूप से कांग्रेस (रिक्विजिनिस्ट) कहा गया। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनके समर्थक सांसदों और नेताओं ने पार्टी के नियमों के तहत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) की एक विशेष बैठक बुलाने की औपचारिक याचना या 'रिक्विजिशन' की थी। वे इस बैठक के माध्यम से संगठन पर अपना अधिकार सिद्ध करना चाहते थे, जिससे वे विपक्षी गुट से अलग पहचाने गए।

72. (A) केवल 5
इंदिरा गाँधी ने 1969 के विभाजन को बहुत चतुराई से एक वैचारिक लड़ाई के रूप में चित्रित किया। उन्होंने खुद को गरीबों का हिमायती और सिंडिकेट को अमीरों का समर्थक बताया। हालाँकि यह मुख्य रूप से व्यक्तिगत सत्ता संघर्ष था, लेकिन उन्होंने इसे समाजवादी और पुरातनपंथी की जंग बना दिया। कथन 5 गलत है क्योंकि सिंडिकेट ने इसे वैचारिक नहीं, बल्कि अनुशासन और पार्टी मर्यादा के उल्लंघन की लड़ाई के रूप में देखा था।

73. (D) (A) और (B) दोनों।
प्रिवी पर्स की समाप्ति का मार्ग बाधाओं से भरा था। सरकार ने पहले संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जिसे राज्यसभा में मंजूरी नहीं मिली। इसके बाद सरकार ने अध्यादेश जारी किया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसे असंवैधानिक मानकर निरस्त कर दिया। इन कानूनी और संवैधानिक अड़चनों के कारण सरकार के पास संविधान में स्थायी संशोधन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, जो अंततः 1971 के चुनावों के बाद संपन्न हुआ।

74. (C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
1971 के चुनाव परिणामों ने निश्चित रूप से भारतीय राजनीति में कांग्रेस के प्रभुत्व को बहाल किया, लेकिन इसका कारण पार्टियों का विलय नहीं था। तर्क गलत है क्योंकि कांग्रेस (आर) और कांग्रेस (ओ) का कभी विलय नहीं हुआ, बल्कि वे एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बने रहे। इंदिरा गाँधी की जीत का श्रेय उनके प्रभावशाली नारों, जनहितकारी नीतियों और जनता के बीच उनकी बढ़ती व्यक्तिगत साख को जाता है, न कि किसी गठबंधन को।

75. (B) P-3, Q-1, R-4, S-2
इन नेताओं ने भारतीय राजनीति के विभिन्न आयामों को प्रभावित किया। सी. नटराजन अन्नादुरई ने DMK की स्थापना की और मद्रास के मुख्यमंत्री बने। राममनोहर लोहिया गैर-कांग्रेसवाद के प्रमुख रणनीतिकार थे। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में पिछड़ों के लिए ऐतिहासिक आरक्षण लागू किया। के. कामराज ने संगठन को मजबूती देने के लिए अपनी प्रसिद्ध 'कामराज योजना' पेश

11. (D) बंबई प्रांत
मोरारजी देसाई भारतीय राजनीति के एक अत्यंत वरिष्ठ और अनुभवी नेता थे। प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल होने से पहले उन्होंने बंबई प्रांत के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने केंद्र सरकार में भी महत्वपूर्ण मंत्री पदों पर अपनी सेवाएं दी थीं। अपनी प्रशासनिक दक्षता और सिद्धांतों के प्रति दृढ़ता के कारण वे प्रधानमंत्री पद के सशक्त दावेदार माने जाते थे।

12. (D) 1, 2, 3, 4 और 5 सभी
शास्त्री जी के बाद इंदिरा गाँधी के प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया पूर्णतः लोकतांत्रिक थी। सिंडिकेट के नेताओं ने उन्हें इस उम्मीद में समर्थन दिया था कि वे उनके मार्गदर्शन पर निर्भर रहेंगी। चुनाव के दौरान दो-तिहाई सांसदों ने उन्हें मत दिया। सत्ता का यह हस्तांतरण बिना किसी हिंसा या अवरोध के संपन्न हुआ, जिसने भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता को विश्व के सामने मजबूती से सिद्ध किया।

13. (C) यह कदम अमरीका के बाहरी दबाव में उठाया गया था।
इंदिरा गाँधी के शुरुआती कार्यकाल में देश को गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस दौरान विदेशी सहायता की आवश्यकता के कारण अमेरिका ने भारत पर आर्थिक नीतियों में बदलाव के लिए दबाव बनाया। इसी दबाव के परिणामस्वरूप भारत सरकार को भारतीय रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा। इसके कारण डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत काफी गिर गई, जिससे अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा।

14. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
समाजवादी नेता राममनोहर लोहिया का मानना था कि कांग्रेस का निरंतर शासन अलोकतांत्रिक होता जा रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि कांग्रेस की नीतियां आम गरीब जनता के हितों की अनदेखी कर रही हैं। इसीलिए उन्होंने गैर-कांग्रेसी दलों को एकजुट होने का आह्वान किया। उनका मानना था कि विपक्षी एकता ही देश में असली लोकतंत्र की बहाली और वंचितों के उत्थान के लिए अनिवार्य है।

15. (A) P-3, Q-1, R-4, S-2
साठ के दशक में कांग्रेस के भीतर विभिन्न राज्यों के नेताओं का एक शक्तिशाली समूह सक्रिय था। के. कामराज तमिलनाडु से संबंधित थे और पार्टी अध्यक्ष रहे। एस. के. पाटिल महाराष्ट्र में प्रभावशाली थे, जबकि अतुल्य घोष पश्चिम बंगाल में पार्टी की कमान संभाल रहे थे। इसी प्रकार के. बी. सहाय बिहार के राजनीति में प्रमुख स्थान रखते थे। इन नेताओं ने राष्ट्रीय राजनीति को गहराई से प्रभावित किया।

16. (B) क्योंकि कांग्रेस के मत प्रतिशत और सीटों की संख्या में भारी गिरावट आई।
1967 के आम चुनावों को भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। यद्यपि कांग्रेस ने केंद्र में सरकार बना ली, लेकिन उसे प्राप्त होने वाली सीटों और वोटों के प्रतिशत में ऐतिहासिक कमी आई। कई राज्यों में कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा और उसके अनेक दिग्गज नेता चुनाव हार गए। इस व्यापक राजनीतिक उथल-पुथल के कारण ही इसे राजनीतिक भूकंप कहा गया।

17. (B) राज्यों में गैर-कांग्रेसी दलों द्वारा बनाई गई गठबंधन सरकारें।
1967 के विधानसभा चुनावों में कई राज्यों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। ऐसी स्थिति में विभिन्न गैर-कांग्रेसी दलों ने आपस में हाथ मिलाया और गठबंधन सरकारें बनाईं। इन साझा सरकारों को 'संयुक्त विधायक दल' (संविद) सरकार कहा गया। इन गठबंधनों में अक्सर परस्पर विरोधी विचारधारा वाले दल भी शामिल थे, जिनका एकमात्र उद्देश्य कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना और राज्य का शासन चलाना था।

18. (D) 1, 2, 3 और 4 सभी
चौथे आम चुनाव में कांग्रेस को पहली बार नेहरु की अनुपस्थिति में मतदाताओं का सामना करना पड़ा। चुनाव के परिणाम कांग्रेस के लिए काफी निराशाजनक रहे और उसे केंद्र के साथ-साथ राज्यों में भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। इंदिरा गाँधी के मंत्रिमंडल के लगभग आधे मंत्री अपनी सीटें नहीं बचा सके। इन परिणामों ने भारतीय चुनावी इतिहास में एक नए युग की शुरुआत का संकेत दिया था।

19. (C) द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK)
1967 के चुनावों में मद्रास राज्य का परिणाम सबसे चौंकाने वाला था। यहाँ एक क्षेत्रीय दल, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) ने कांग्रेस को करारी शिकस्त देते हुए पूर्ण बहुमत हासिल किया। यह पहली बार था जब किसी एक गैर-कांग्रेसी दल ने अपने दम पर किसी राज्य में सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें जीती थीं। इस जीत ने क्षेत्रीय राजनीति को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान प्रदान की।

20. (D) हिंदी-विरोधी आंदोलन का नेतृत्व।
साठ के दशक के मध्य में केंद्र सरकार द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के प्रयासों का दक्षिण भारत में तीव्र विरोध हुआ। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और इसे क्षेत्रीय अस्मिता से जोड़ दिया। छात्रों और आम जनता के बीच इस मुद्दे पर गहरी नाराजगी थी, जिसका चुनावी लाभ DMK को मिला और उसने 1967 में भारी बहुमत के साथ सत्ता प्राप्त की।

21. (C) दल-बदल
भारतीय राजनीति में 'आया राम, गया राम' का मुहावरा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा बार-बार अपनी पार्टी बदलने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। 1967 के चुनावों के बाद यह परिघटना अत्यंत तीव्र हो गई, जिससे कई राज्यों की सरकारें अस्थिर हुईं। विधायकों का स्वार्थवश या दबाव में एक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होना लोकतांत्रिक स्थिरता के लिए एक गंभीर चुनौती बनकर उभरा, जिसे दल-बदल कहा गया।

22. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
1967 के बाद कई राज्यों में गठित गठबंधन सरकारें आंतरिक कलह के कारण अल्पकालिक रहीं। इन सरकारों में शामिल दल अक्सर एक-दूसरे के विपरीत विचारधारा रखते थे, जैसे जनसंघ और वामपंथी दल एक साथ आ गए थे। उनके बीच किसी न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर सहमति का अभाव था। वैचारिक भिन्नता और आपसी अविश्वास के कारण ये सरकारें स्थिर नहीं रह सकीं और शीघ्र ही गिर गईं।

23. (D) गया लाल
हरियाणा के विधायक गया लाल ने 1967 में मात्र पंद्रह दिनों के भीतर तीन बार अपनी पार्टी बदली। उन्होंने पहले कांग्रेस छोड़ी, फिर यूनाइटेड फ्रंट में गए और दोबारा कांग्रेस में लौट आए। उनकी इस अस्थिर राजनीतिक निष्ठा पर तंज कसते हुए 'आया राम, गया राम' का जुमला प्रसिद्ध हुआ। यह घटना भारतीय राजनीति में राजनीतिक अवसरवाद और दल-बदल की बुराई का एक सशक्त प्रतीक बन गई।

24. (A) सिंडिकेट
साठ के दशक में कांग्रेस पार्टी के भीतर वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं का एक अनौपचारिक समूह सक्रिय था, जिसे सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था। इस समूह का पार्टी के सांगठनिक ढांचे पर मजबूत नियंत्रण था और वे नीतिगत निर्णयों में निर्णायक भूमिका निभाते थे। लालबहादुर शास्त्री और इंदिरा गाँधी को प्रधानमंत्री बनाने में इस समूह की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही थी, जिससे उनकी ताकत स्पष्ट होती थी।

25. (C) इंदिरा गाँधी
सिंडिकेट कांग्रेस के उन पुराने और अनुभवी नेताओं का समूह था जिनका पार्टी के संगठन पर अधिकार था। के. कामराज, एस. निजलिंगप्पा और एस. के. पाटिल इस शक्तिशाली समूह के प्रमुख सदस्य थे। इंदिरा गाँधी इस समूह का हिस्सा नहीं थीं, बल्कि सिंडिकेट ने उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थित किया था। बाद में इंदिरा गाँधी और सिंडिकेट के बीच ही कांग्रेस के विभाजन का संघर्ष शुरू हुआ।

26. (A) अपनी ही पार्टी के भीतर 'सिंडिकेट' से।
1967 के बाद इंदिरा गाँधी ने अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाने का प्रयास किया। उन्हें असली चुनौती विपक्षी दलों से नहीं, बल्कि अपनी ही पार्टी के भीतर मौजूद 'सिंडिकेट' के प्रभावशाली नेताओं से मिली। सिंडिकेट के नेता चाहते थे कि इंदिरा गाँधी उनके निर्देशानुसार कार्य करें। इंदिरा गाँधी ने धीरे-धीरे उन्हें दरकिनार करना शुरू किया, जिससे पार्टी के भीतर एक भीषण आंतरिक सत्ता संघर्ष पैदा हो गया।

27. (D) 1, 2, 3, 4 और 5 सभी
इंदिरा गाँधी और सिंडिकेट के बीच का संघर्ष भारतीय राजनीति की एक युगांतरकारी घटना थी। सिंडिकेट ने उन्हें अनुभवहीन मानकर समर्थन दिया था, लेकिन इंदिरा गाँधी ने अपनी नीतियों को वामपंथी रंग देकर जनसमर्थन जुटाना शुरू कर दिया। उन्होंने चतुराई से सत्ता संघर्ष को वैचारिक लड़ाई में बदल दिया। धीरे-धीरे उन्होंने पुराने नेताओं को हाशिये पर धकेल दिया और पार्टी पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया।

28. (B) प्रिवी पर्स की समाप्ति।
1967 में कांग्रेस कार्यसमिति ने अपनी छवि सुधारने के लिए दस-सूत्री कार्यक्रम अपनाया। इसमें बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, आम बीमा का राष्ट्रीयकरण और शहरी संपदा के परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल थे। यद्यपि प्रिवी पर्स को समाप्त करने की मांग पार्टी के भीतर उठ रही थी, लेकिन इसे उस समय के औपचारिक दस-सूत्री कार्यक्रम की मूल सूची में मुख्य रूप से शामिल नहीं किया गया था, वह बाद का मुद्दा बना।

29. (C) एन. संजीव रेड्डी
1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद नए राष्ट्रपति का चुनाव अनिवार्य हो गया। सिंडिकेट के नेताओं ने इंदिरा गाँधी की इच्छा के विरुद्ध एन. संजीव रेड्डी को कांग्रेस का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया। इंदिरा गाँधी और संजीव रेड्डी के बीच पुराने मतभेद थे। आधिकारिक उम्मीदवार की यह घोषणा इंदिरा गाँधी के लिए एक खुली चुनौती थी, जिसने कांग्रेस पार्टी में विभाजन की नींव को और गहरा कर दिया।

30. (B) P-3, Q-4, R-1, S-2
साठ के दशक के राजनीतिक घटनाक्रम को इन प्रमुख अवधारणाओं से समझा जा सकता है। गैर-कांग्रेसवाद की रणनीति राममनोहर लोहिया ने दी थी, जबकि दल-बदल को 'आया राम, गया राम' के मुहावरे से पहचाना गया। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर नेताओं का समूह था। दस-सूत्री कार्यक्रम पार्टी की वामपंथी नीतियों को लागू करने का प्रयास था। इन सभी कारकों ने मिलकर भारतीय राजनीति की दिशा और दशा निर्धारित की।

31. (A) वी. वी. गिरि
1969 के राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गाँधी ने पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार एन. संजीव रेड्डी के विरुद्ध तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी. वी. गिरि को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने खुले तौर पर तो नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे से वी. वी. गिरि की उम्मीदवारी का समर्थन किया। यह कदम सिंडिकेट के प्रभाव को चुनौती देने और पार्टी के भीतर अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने की एक सोची-समझी रणनीति थी।

32. (B) अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालने के लिए।
1969 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कांग्रेस में गहरा संकट उत्पन्न हो गया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने सांसदों को पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार एन. संजीव रेड्डी को वोट देने का निर्देश दिया था। इसके विपरीत, इंदिरा गाँधी ने सांसदों और विधायकों से अपील की कि वे अपनी 'अंतरात्मा की आवाज़' पर मतदान करें। इस अपील का अर्थ स्वतंत्र उम्मीदवार वी. वी. गिरि को समर्थन देना था, जिससे आधिकारिक अनुशासन भंग हुआ।

33. (B) 1971 के भारत-पाक युद्ध की शुरुआत।
1969 के राष्ट्रपति चुनाव के आसपास देश में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं घटित हुईं। इंदिरा गाँधी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स की समाप्ति जैसी साहसिक घोषणाएं की थीं, जिससे मोरारजी देसाई ने मतभेदों के कारण इस्तीफा दे दिया। हालाँकि, पाकिस्तान के साथ 1971 का युद्ध इस समय की घटना नहीं थी, बल्कि यह चुनाव के लगभग दो वर्ष बाद घटित हुई एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय और सैन्य घटना थी।

34. (A) मोरारजी देसाई
इंदिरा गाँधी द्वारा 'प्रिवी पर्स' को समाप्त करने के निर्णय का मोरारजी देसाई ने कड़ा विरोध किया। उनका तर्क था कि रियासतों के विलय के समय किए गए वादों से मुकरना अनैतिक है और यह पूर्व शासकों के साथ विश्वासघात होगा। देसाई ने इसे एक संवैधानिक और नैतिक चूक माना। उनके इस विरोध ने इंदिरा गाँधी के साथ उनके मतभेदों को और बढ़ा दिया, जिससे अंततः उनके बीच राजनीतिक विच्छेद हो गया।

35. (C) देसी रियासतों के विलय के समय शासक परिवारों को दिए जाने वाले विशेष भत्ते और अधिकार।
स्वतंत्रता के समय भारत में देसी रियासतों के विलय के बदले सरकार ने उनके शासकों को एक निश्चित निजी भत्ता देने का वादा किया था। इसे 'प्रिवी पर्स' कहा जाता था। यह भत्ता रियासत के राजस्व और आकार के आधार पर तय किया गया था। इसके साथ ही उन्हें कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त थे। साठ के दशक में समानता के सिद्धांतों के आधार पर इसे समाप्त करने की मांग उठी थी।

36. (D) राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की हार।
1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन का तात्कालिक कारण राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे थे। इंदिरा गाँधी के समर्थन से स्वतंत्र उम्मीदवार वी. वी. गिरि ने कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार एन. संजीव रेड्डी को हरा दिया। इस हार को सिंडिकेट ने अपनी व्यक्तिगत पराजय और प्रधानमंत्री की अनुशासनहीनता के रूप में देखा। इसके तुरंत बाद इंदिरा गाँधी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, जिससे कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई।

37. (C) कांग्रेस (ऑर्गनाइजेशन)
1969 में जब कांग्रेस पार्टी विभाजित हुई, तो सिंडिकेट के नेतृत्व वाले खेमे को कांग्रेस (ऑर्गनाइजेशन) या कांग्रेस (ओ) कहा गया। इस गुट में पार्टी के वे पुराने और अनुभवी नेता शामिल थे जिन्होंने इंदिरा गाँधी की नीतियों और कार्यशैली का विरोध किया था। दूसरी ओर, इंदिरा गाँधी के समर्थक गुट को कांग्रेस (आर) कहा गया। इस विभाजन ने भारतीय राजनीति में वर्षों पुराने सत्ता ढांचे को पूरी तरह बदल दिया।

38. (B) पुरानी कांग्रेस
कांग्रेस (ऑर्गनाइजेशन) को आम बोलचाल की भाषा में 'पुरानी कांग्रेस' के नाम से जाना जाता था। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें पार्टी के वे वरिष्ठ नेता थे जो दशकों से संगठन को चला रहे थे। इसके विपरीत, इंदिरा गाँधी की अगुवाई वाली कांग्रेस (आर) को 'नई कांग्रेस' कहा गया। जनता के बीच इन दोनों गुटों की पहचान उनके नेताओं के अनुभव और विचारधारा के आधार पर की जाती थी।

39. (D) 1, 2, 3 और 4 सभी
प्रिवी पर्स की व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र और समानता के आदर्शों के विरुद्ध मानी जाती थी। जवाहरलाल नेहरू भी इस विशेष विशेषाधिकार के पक्ष में नहीं थे। 1967 के बाद इंदिरा गाँधी ने इसे समाप्त करने के जनमत का समर्थन किया। हालाँकि शुरुआत में उन्हें कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन 1971 की प्रचंड जीत के बाद उन्होंने संविधान में संशोधन करके इस सामंती प्रथा को सदा के लिए समाप्त कर दिया।

40. (A) डी.एम.के. और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी।
1969 के विभाजन के बाद इंदिरा गाँधी की सरकार लोकसभा में बहुमत खो चुकी थी। अपनी सरकार को गिरने से बचाने के लिए उन्होंने कुछ विपक्षी दलों का सहारा लिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) और तमिलनाडु की DMK ने उन्हें मुद्दा आधारित समर्थन दिया। इस समर्थन के बदले सरकार ने कुछ प्रगतिशील और वामपंथी नीतियों को आगे बढ़ाया। इन बाहरी दलों के सहयोग से ही इंदिरा गाँधी अपनी सत्ता को सुरक्षित रख पाईं।

41. (C) ग्रैंड अलायंस
1971 के चुनावों में इंदिरा गाँधी को चुनौती देने के लिए सभी प्रमुख विपक्षी दलों ने एक साझा मोर्चा बनाया। इस गठबंधन को 'ग्रैंड अलायंस' का नाम दिया गया। इसमें पुरानी कांग्रेस, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी जैसे दल शामिल थे। विचारधारा के स्तर पर अलग होने के बावजूद, ये दल केवल इंदिरा गाँधी को हराने के साझा उद्देश्य के साथ एक मंच पर आए थे, जो काफी चर्चा में रहा।

42. (A) इंदिरा हटाओ
'ग्रैंड अलायंस' का चुनावी अभियान मुख्य रूप से इंदिरा गाँधी के विरोध पर केंद्रित था। उनके पास कोई वैकल्पिक विकास कार्यक्रम नहीं था, इसलिए उन्होंने "इंदिरा हटाओ" का नकारात्मक नारा दिया। विपक्षी नेताओं का मानना था कि इंदिरा गाँधी की बढ़ती शक्ति देश के लिए खतरा है। हालाँकि, यह नारा जनता को प्रभावित करने में विफल रहा क्योंकि इसमें देश की बुनियादी समस्याओं के समाधान का कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं था।

43. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
1971 के चुनाव में इंदिरा गाँधी ने "गरीबी हटाओ" का प्रसिद्ध नारा देकर विपक्षी दलों को निरुत्तर कर दिया। इस नारे के माध्यम से उन्होंने सीधे उन वर्गों को संबोधित किया जो विकास की धारा से पीछे रह गए थे। दलित, आदिवासी, महिलाएं और बेरोजगार नौजवान इस नारे से स्वयं को जुड़ा हुआ महसूस करने लगे। इस सकारात्मक कार्यक्रम ने उनके लिए एक बहुत बड़ा और वफादार जनसमर्थन आधार तैयार किया।

था। इंदिरा गाँधी स्वयं चुनाव जीत गईं थीं, लेकिन उनके मंत्रियों और रणनीतिकारों की हार ने पार्टी की नींव कमजोर कर दी थी।

87. (D) इंदिरा गाँधी के पहले मंत्रिमंडल में और नीति निर्माण में समूह की निर्णायक भूमिका थी।
शुरुआती वर्षों में इंदिरा गाँधी काफी हद तक सिंडिकेट के नेताओं पर निर्भर थीं। सिंडिकेट ने ही उन्हें प्रधानमंत्री बनाने में मदद की थी, इसलिए सरकार की नीतियों और मंत्रिमंडल के चयन में उनकी राय सर्वोपरि होती थी। सिंडिकेट के नेताओं को लगता था कि वे इंदिरा गाँधी के माध्यम से सत्ता का संचालन करेंगे। हालाँकि, जल्द ही इंदिरा गाँधी ने अपनी स्वतंत्र राह चुनी और इस समूह के वर्चस्व को चुनौती दी।

88. (A) डी.एम.के. और सी.पी.आई. जैसे दलों से प्राप्त मुद्दा-आधारित समर्थन के बल पर।
1969 के विभाजन के बाद इंदिरा गाँधी की सरकार लोकसभा में अल्पमत में आ गई थी। इस संकट के समय वामपंथी दलों (CPI) और क्षेत्रीय दलों (DMK) ने उन्हें बाहर से समर्थन दिया। यह समर्थन बिना शर्त नहीं था, बल्कि समाजवादी और जनहितकारी नीतियों को लागू करने के मुद्दे पर आधारित था। इस सहयोग की बदौलत ही इंदिरा गाँधी ने अपनी सरकार बचाई और बाद में मध्यावधि चुनावों में भारी बहुमत प्राप्त किया।

89. (C) व्यवस्था के नैतिक पतन और लाचारी से उपजा गुस्सा और क्षोभ।
सत्तर के दशक की फिल्में समाज की वास्तविकताओं का दर्पण थीं। फिल्म 'जंजीर' का नायक 'एंग्री यंग मैन' के रूप में उभरा, जो भ्रष्ट व्यवस्था और प्रशासनिक विफलता के प्रति आम जनता के गुस्से का प्रतिनिधित्व करता था। उस समय देश में बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी निराशा पैदा की थी। यह फिल्म उस दौर के सामाजिक और राजनीतिक मोहभंग की एक कलात्मक अभिव्यक्ति थी।

90. (B) 2, 1, 3, 4
साठ और सत्तर के दशक के इन ऐतिहासिक घटनाक्रमों का सही क्रम लालबहादुर शास्त्री की मृत्यु (1966) से शुरु होता है। इसके बाद 1967 में चौथा आम चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। 1969 में राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। अंत में, 1971 में बांग्लादेश के निर्माण की घटना हुई, जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया और इंदिरा गाँधी को वैश्विक पहचान दी।

91. (D) अकाली दल के संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप
1967 में पंजाब की राजनीति में एक अनोखा प्रयोग हुआ। कांग्रेस को हराने के लिए अकाली दल के दो धुर विरोधी गुट, संत फतेह सिंह ग्रुप और मास्टर तारा सिंह ग्रुप, एक साथ आए और 'पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट' बनाया। इस गठबंधन में जनसंघ और कम्युनिस्टों जैसे विपरीत विचारधारा वाले दल भी शामिल थे। यह गैर-कांग्रेसवाद की रणनीति का एक सफल स्थानीय उदाहरण था, जिसने राज्य में पहली बार गैर-कांग्रेसी सरकार का मार्ग प्रशस्त किया।

92. (B) इसका गठन गैर-कम्युनिस्ट और गैर-कांग्रेसी दलों ने किया था।
1971 का 'ग्रैंड अलायंस' मुख्य रूप से दक्षिणपंथी और समाजवादी दलों का एक मोर्चा था जो कांग्रेस (आर) और कम्युनिस्टों के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ एकजुट हुए थे। इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) शामिल नहीं थी क्योंकि उसने इंदिरा गाँधी के साथ समझौता किया था। इस गठबंधन के पास कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं थी, बल्कि इनका एकमात्र उद्देश्य इंदिरा गाँधी को सत्ता से हटाना था, जो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई।

93. (A) P-1, Q-2, R-4, S-3
भारतीय राजनीति की इन प्रमुख शब्दावलियों का अपना विशिष्ट अर्थ है। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर शक्तिशाली पुराने नेताओं के समूह को कहा गया। दल-बदल वह स्थिति है जब कोई जनप्रतिनिधि अपनी पार्टी बदलता है। "गरीबी हटाओ" इंदिरा गाँधी का वह क्रांतिकारी नारा था जिसने चुनाव का रुख बदल दिया। गैर-कांग्रेसवाद की रणनीति का उद्देश्य सभी विपक्षी दलों को एकजुट कर कांग्रेस के वर्चस्व को समाप्त करना था।

94. (D) मोरारजी देसाई
1969 में जब इंदिरा गाँधी ने चौदह निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण का क्रांतिकारी निर्णय लिया, उस समय मोरारजी देसाई देश के उपप्रधानमंत्री और वित्तमंत्री थे। देसाई आर्थिक मामलों में रुढ़िवादी और दक्षिणपंथी विचार रखते थे, इसलिए वे इस राष्ट्रीयकरण के सख्त खिलाफ थे। प्रधानमंत्री ने उनसे वित्त मंत्रालय वापस ले लिया, जिसके विरोध में उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया। यह घटना कांग्रेस के भीतर बढ़ते गहरे मतभेदों का चरम बिंदु थी।

95. (C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग करने का इंदिरा गाँधी का निर्णय राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत साहसिक और रणनीतिक था। वे जनता से नया जनादेश चाहती थीं। तर्क गलत है क्योंकि उस समय उनकी सरकार अल्पमत में थी और वामपंथी दलों के समर्थन पर टिकी थी। वे किसी की बैसाखी के बिना पूर्ण बहुमत के साथ शासन करना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने समय से पहले चुनाव कराने का जोखिम उठाया।

96. (B) हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश
1967 के चुनावों के बाद भारतीय राजनीति में राजनीतिक अस्थिरता का नया दौर शुरु हुआ। हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य थे जहाँ कांग्रेस ने शुरुआत में सरकार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बड़े पैमाने पर हुए दल-बदल के कारण वह अपनी सत्ता नहीं बचा सकी। इन राज्यों में विधायकों के पाला बदलने से गैर-कांग्रेसी संविद सरकारें बनीं, जिससे भारतीय लोकतंत्र में 'दल-बदल' एक गंभीर समस्या बन गई।

97. (B) केवल 1, 2 और 3
1971 के लोकसभा चुनावों के आंकड़े इंदिरा गाँधी की प्रचंड लोकप्रियता की गवाही देते हैं। उनके गठबंधन ने 375 सीटें जीतकर विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया। अकेले कांग्रेस

55. (D) नई कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत की, लेकिन जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की लोकतांत्रिक जमीन छोटी पड़ती गई।
यद्यपि इंदिरा गाँधी ने कांग्रेस के प्रभुत्व को पुनः स्थापित किया, लेकिन पार्टी का चरित्र बदल चुका था। नई प्रणाली अधिक केंद्रीकृत थी और इसमें असहमति के लिए स्थान कम था। पुरानी कांग्रेस प्रणाली में विभिन्न हितों को समायोजित करने की जो क्षमता थी, वह अब कम हो गई थी। इससे चुनावी जीत तो मिली, लेकिन समाज के विभिन्न वर्गों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए लोकतांत्रिक स्थान संकुचित होने लगा था।

56. (B) केवल 3, 4 और 5
1967 के चुनाव में कांग्रेस की पराजय के मुख्य कारण पार्टी के भीतर बढ़ता असंतोष और आंतरिक गुटबाजी थी। इसके साथ ही, देश में क्षेत्रीय और जातीय आधार पर मतदाताओं का लामबंद होना शुरू हो गया था, जिससे कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक प्रभावित हुआ। विपक्षी दलों द्वारा पहली बार एकजुट होकर लड़ने की रणनीति ने कांग्रेस की चुनौतियों को और बढ़ा दिया, जिससे उसे कई राज्यों में सत्ता गंवानी पड़ी।

57. (C) गरीबी हटाओ जैसा प्रगतिशील कार्यक्रम और 1971 के युद्ध में निर्णायक जीत।
सत्तर के दशक की शुरुआत में इंदिरा गाँधी की सरकार की लोकप्रियता के दो मुख्य स्तंभ थे। पहला, उनका समाजवादी और लोक-लुभावन कार्यक्रम "गरीबी हटाओ", जिसने समाज के निचले तबकों को नई उम्मीद दी। दूसरा, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर मिली ऐतिहासिक जीत, जिसने राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाया। इन दोनों कारकों के मिलन ने उन्हें एक अत्यंत शक्तिशाली और जनप्रिय नेता के रूप में स्थापित कर दिया।

58. (A) नेतृत्व और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इंदिरा गाँधी और सिंडिकेट के बीच बड़ा सत्ता संघर्ष।
1969 में कांग्रेस का विभाजन मुख्य रूप से व्यक्तिगत सत्ता संघर्ष और नेतृत्व की लड़ाई का परिणाम था। इंदिरा गाँधी पार्टी के पुराने अनुभवी नेताओं (सिंडिकेट) के नियंत्रण से मुक्त होना चाहती थीं। राष्ट्रपति चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार वी. वी. गिरि को जिताकर उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। सिंडिकेट द्वारा इसे अनुशासनहीनता माने जाने के कारण पार्टी दो गुटों में टूट गई, जिससे भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव आया।

59. (C) इसमें समाजवादी पार्टियों के साथ वामपंथी और दक्षिणपंथी दल भी शामिल थे।
1967 के बाद बिहार में बनी संयुक्त विधायक दल (संविद) की सरकार अपनी वैचारिक विविधता के लिए उल्लेखनीय थी। इस गठबंधन में समाजवादी दलों के साथ-साथ दक्षिणपंथी जनसंघ और वामपंथी दल भी एक साथ शामिल हुए थे। यह गठबंधन केवल कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के साझा उद्देश्य पर टिका था। इस प्रयोग ने यह दिखाया कि सत्ता प्राप्ति के लिए धुर विरोधी विचारधारा वाले दल भी हाथ मिला सकते हैं।

60. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
भारतीय राजनीति के इन प्रसिद्ध नारों और अवधारणाओं का गहरा महत्व है। "जय जवान, जय किसान" लालबहादुर शास्त्री की सादगी और राष्ट्रनिष्ठा का प्रतीक था। "इंदिरा हटाओ" ग्रैंड अलायंस का मुख्य नारा बना, जिसका जवाब इंदिरा गाँधी ने "गरीबी हटाओ" के सकारात्मक नारे से दिया। गैर-कांग्रेसवाद की अवधारणा राममनोहर लोहिया द्वारा विकसित की गई थी, जिसने विपक्षी दलों को कांग्रेस के विरुद्ध एकजुट होने का सैद्धांतिक आधार प्रदान किया।

61. (C) पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट
पंजाब में 1967 के विधानसभा चुनावों के बाद एक गैर-कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ, जिसे 'पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट' कहा गया। इस गठबंधन की खासियत यह थी कि इसमें अकाली दल के दो प्रतिस्पर्धी गुटों के साथ-साथ जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टियाँ भी शामिल थीं। इस प्रयोग ने प्रदर्शित किया कि क्षेत्रीय राजनीति में कांग्रेस के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए विविध राजनीतिक धाराएं एक साथ आ सकती हैं।

62. (D) कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए वरिष्ठ नेताओं का इस्तीफा ताकि युवा कार्यकर्ता कमान संभाल सकें।
1963 में कांग्रेस अध्यक्ष के. कामराज ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा था जिसे 'कामराज योजना' कहा जाता है। इसका उद्देश्य पार्टी संगठन को नई ऊर्जा देना था। इस योजना के तहत पार्टी के वरिष्ठ मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देकर पूर्णकालिक संगठनात्मक कार्य में जुड़ने का सुझाव दिया गया था। नेहरू ने इसे स्वीकार किया और कई बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया, ताकि युवाओं को पार्टी में आगे बढ़ाया जा सके।

63. (A) सिंडिकेट ने हमेशा इंदिरा गाँधी की वामपंथी नीतियों का समर्थन किया।
सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर पुराने और रुढ़िवादी नेताओं का समूह था जिनका पार्टी के ढांचे पर नियंत्रण था। हालाँकि उन्होंने शास्त्री और इंदिरा गाँधी को प्रधानमंत्री बनने में मदद की, लेकिन वे इंदिरा गाँधी की वामपंथी नीतियों जैसे बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रबल विरोधी थे। उनके बीच उपजे इसी वैचारिक और व्यक्तिगत मतभेद के कारण अंततः 1969 में कांग्रेस पार्टी दो फाड़ हो गई और सिंडिकेट हाशिये पर चला गया।

64. (B) 1967 में दस-सूत्री कार्यक्रम अपनाना।
1967 के चुनावों के बाद अपनी लोकप्रियता बढ़ाने और पार्टी पर नियंत्रण करने के लिए इंदिरा गाँधी ने वामपंथी रुख अपनाया। उन्होंने कांग्रेस कार्यसमिति से दस-सूत्री कार्यक्रम पारित करवाया। इसमें बैंकों पर नियंत्रण, अनाज का सरकारी वितरण और भूमि सुधार जैसे समाजवादी कदम शामिल थे। इन नीतियों के माध्यम से उन्होंने स्वयं को गरीबों के मसीहा के रूप में पेश किया और सिंडिकेट की दक्षिणपंथी छवि से खुद को अलग कर लिया।

ANSWERS

1. (B) जवाहरलाल नेहरू
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की मृत्यु मई 1964 में हुई थी। उनके निधन के बाद देश के सामने राजनीतिक उत्तराधिकार का एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। इस दौरान कई लोगों को यह आशंका थी कि नेहरू के बाद भारत में लोकतंत्र सुरक्षित रह पाएगा या नहीं, क्योंकि नेहरू भारतीय राजनीति के एक अत्यंत प्रभावशाली और कद्दावर स्तंभ थे।

2. (A) क्योंकि इसमें गरीबी, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीय विभाजन के सवाल अनसुलझे थे।
भारतीय इतिहास में साठ के दशक को बहुत जटिल माना जाता है। इस काल में देश अनेक आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा था। गरीबी की गहरी जड़ें, सांप्रदायिक दंगों की आशंका और अलग होने की मांग करने वाले क्षेत्रीय विभाजनों ने राजनीतिक स्थिरता को चुनौती दी थी। इन अनसुलझे सवालों के कारण ही विद्वानों ने इस समय को एक खतरनाक दशक कहा था।

3. (C) के. कामराज
जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद राजनीतिक उत्तराधिकार का प्रश्न अत्यंत शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया। उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के. कामराज ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सांसदों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया। उन्होंने सर्वसम्मति से लालबहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार के रूप में चुना, जिससे देश में सत्ता का हस्तांतरण सुगमता से संपन्न हुआ।

4. (D) 1956 में
लालबहादुर शास्त्री अपनी सादगी और उच्च नैतिक मूल्यों के लिए विख्यात थे। वे नेहरू के मंत्रिमंडल में रेलमंत्री के पद पर कार्यरत थे। वर्ष 1956 में एक भीषण रेल दुर्घटना हुई थी, जिसकी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका यह साहसिक कदम भारतीय संसदीय राजनीति में जवाबदेही और नैतिकता का एक अनुपम उदाहरण माना जाता है।

5. (C) विपक्षी दलों का कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए एकजुट होना।
साठ के दशक में विपक्षी दलों को महसूस हुआ कि उनके वोटों के बंटवारे के कारण कांग्रेस बार-बार सत्ता में आ रही है। इस स्थिति को बदलने के लिए विभिन्न विचारधाराओं वाले दल कांग्रेस के विरुद्ध एकजुट हुए। समाजवादी नेता राममनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर-कांग्रेसवाद का नाम दिया, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के शासन को समाप्त कर लोकतांत्रिक विकल्प प्रदान करना था।

6. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
साठ के दशक के अंतिम वर्षों में भारत को भीषण आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। मानसून की विफलता के कारण कृषि उत्पादन गिर गया और देश में सूखे जैसी स्थिति पैदा हो गई। साथ ही, चीन और पाकिस्तान के साथ हुए युद्धों के कारण सैन्य खर्च में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे विकास कार्यों के लिए धन की कमी हो गई और संकट गहराया।

7. (D) लालबहादुर शास्त्री
लालबहादुर शास्त्री ने अपने संक्षिप्त प्रधानमंत्रित्व काल में देश को दो बड़ी चुनौतियों से सफलतापूर्वक उबारा। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान उन्होंने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और देश में खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया। "जय जवान, जय किसान" का उनका ओजस्वी नारा इन्हीं दो महत्वपूर्ण वर्गों के प्रति उनके सम्मान और राष्ट्र के संकल्प को दर्शाता है।

8. (D) 1, 2, 3 और 4 सभी
लालबहादुर शास्त्री का कार्यकाल भारतीय राजनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। वे 1964 से 1966 तक प्रधानमंत्री रहे और 1965 के युद्ध में राष्ट्र का कुशल नेतृत्व किया। उनका प्रसिद्ध नारा सैनिकों और किसानों की महत्ता को रेखांकित करता है। दुर्भाग्यवश, सोवियत संघ के ताशकंद में समझौते के दौरान 10 जनवरी 1966 को उनका आकस्मिक निधन हो गया, जिससे देश स्तब्ध रह गया।

9. (C) मोरारजी देसाई और इंदिरा गाँधी
लालबहादुर शास्त्री के निधन के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस के भीतर प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई। मोरारजी देसाई, जो बंबई प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री थे, और इंदिरा गाँधी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अनुभवहीन होने के बावजूद इंदिरा गाँधी का समर्थन किया। अंततः सांसदों के बीच गुप्त मतदान कराया गया, जिसमें इंदिरा गाँधी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की।

10. (A) 2, 1, 5, 3, 4
भारतीय राजनीति की इन घटनाओं का सही कालक्रम जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु से शुरू होता है। इसके बाद लालबहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने और उनके कार्यकाल में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। युद्ध के पश्चात ताशकंद समझौता संपन्न हुआ, जिसमें शास्त्री जी का निधन हो गया। अंत में इंदिरा गाँधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। यह अनुक्रम 1964 से 1966 के राजनीतिक घटनाक्रम को दर्शाता है।

की थी। इन सभी का योगदान लोकतंत्र की विविधता को दर्शाता है।

76. (B) क्योंकि कई लोगों को संदेह था कि भारत में लोकतंत्र कायम नहीं रह पाएगा और सेना सत्ता पर कब्जा कर लेगी।
नेहरू के बाद भारत की स्थिति को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत चिंताएं थीं। नेहरू न केवल एक नेता थे बल्कि भारतीय लोकतंत्र के संरक्षक भी माने जाते थे। उनके निधन के बाद कई विदेशी विशेषज्ञों को डर था कि भारत में लोकतंत्र विफल हो जाएगा और अन्य विकासशील देशों की तरह यहाँ भी सैन्य शासन लागू हो सकता है। यह दौर भारतीय राजनीतिक प्रणाली की स्थिरता के लिए एक अग्निपरीक्षा जैसा था।

77. (C) सूचना मंत्रालय
जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद जब लालबहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने इंदिरा गाँधी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। इंदिरा गाँधी ने शास्त्री सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार संभाला। इस पद पर रहते हुए उन्होंने सरकारी संचार और मीडिया नीतियों को करीब से समझा। यह उनके राजनीतिक करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था जिसने उन्हें प्रशासनिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया।

78. (D) 1, 2, 3 और 4 सभी
1967 का चुनाव एक अत्यंत कठिन परिस्थितियों में हुआ था। देश ने थोड़े समय में ही नेहरू और शास्त्री जैसे दो बड़े नेताओं को खो दिया था। आर्थिक मोर्चे पर मानसून की नाकामी और युद्धों के कारण भारी संकट था। इसी समय इंदिरा गाँधी ने रुपये का अवमूल्यन किया, जिसे जनता के बीच नकारात्मक रूप से देखा गया। इन सभी कारकों ने मिलकर कांग्रेस के विरुद्ध एक कठिन चुनावी माहौल तैयार कर दिया था।

79. (A) सरकार का जन-आंदोलनों को केवल कानून-व्यवस्था की समस्या मानना।
साठ के दशक के उत्तरार्ध में बढ़ती महंगाई और खाद्यान्न संकट के कारण जनता में भारी असंतोष था। देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन और हड़तालें हो रही थीं। सरकार ने इन आंदोलनों के पीछे के सामाजिक-आर्थिक कारणों को समझने के बजाय इन्हें केवल कानून-व्यवस्था की समस्या माना और बलपूर्वक दबाने की कोशिश की। सरकार के इस असंवेदनशील रवैये ने जन-आक्रोश को और अधिक उग्र बना दिया था।

80. (B) इसमें विभिन्न मतों और हितों को पचा लेने की क्षमता कम थी।
1971 के बाद उभरी 'नई कांग्रेस' पुरानी कांग्रेस के मुकाबले अधिक केंद्रीकृत थी। पुरानी कांग्रेस एक विस्तृत मंच की तरह थी जहाँ विभिन्न गुट और विचारधाराएं आपस में संवाद करती थीं। नई कांग्रेस में सत्ता और निर्णय लेने की प्रक्रिया पूरी तरह शीर्ष नेता तक सीमित हो गई थी। इसमें पार्टी के भीतर असहमति या अलग मतों को स्वीकार करने का स्थान काफी कम हो गया था, जिससे संगठन का लोकतांत्रिक लचीलापन घट गया।

81. (B) 1968-1971
एस. निजलिंगप्पा 1968 से 1971 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वे सिंडिकेट समूह के एक प्रमुख सदस्य थे और मैसूर (अब कर्नाटक) के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। उनके कार्यकाल के दौरान ही कांग्रेस में ऐतिहासिक विभाजन हुआ था। उन्होंने इंदिरा गाँधी को पार्टी से निष्कासित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया था, जिसके बाद कांग्रेस (ओ) और कांग्रेस (आर) का जन्म हुआ था।

82. (A) मोहम्मद अयूब खान
1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच शांति बहाली के लिए सोवियत संघ की मध्यस्थता में ताशकंद में वार्ता हुई। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान थे। लालबहादुर शास्त्री और अयूब खान ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के कुछ ही घंटों बाद ताशकंद में ही शास्त्री जी का दुखद निधन हो गया, जिसने इस शांति प्रयास को एक त्रासदी में बदल दिया।

83. (C) राममनोहर लोहिया
राममनोहर लोहिया भारतीय समाजवादी राजनीति के एक प्रखर चिंतक और नेता थे। वे सामाजिक न्याय के प्रबल पक्षधर थे और उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की पुरजोर वकालत की। लोहिया का मानना था कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग आम जनता और शासन के बीच एक दीवार है, इसलिए उन्होंने सार्वजनिक जीवन में अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषाओं के प्रयोग पर जोर दिया और गैर-कांग्रेसवाद की नींव रखी।

84. (D) उसे बहुमत नहीं मिला, लेकिन कुछ अन्य की सहायता से सरकार बनाई।
1967 के राजस्थान विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। विधानसभा त्रिशंकु होने की स्थिति में कांग्रेस ने निर्दलीय विधायकों और कुछ अन्य छोटे समूहों का समर्थन जुटाया। राजनीतिक सौदेबाजी और जोड़-तोड़ के माध्यम से वह बहुमत का आंकड़ा छूने में सफल रही और सरकार बना ली। यह घटना उस दौर की अस्थिर राजनीति और सत्ता के लिए किए जाने वाले समझौतों का एक उदाहरण थी।

85. (C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
1971 के बाद इंदिरा गाँधी ने निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रभुत्व को पुनः स्थापित किया और पार्टी की प्रतिष्ठा बढ़ाई। हालाँकि, तर्क गलत है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को मूल रूप से बदल दिया था। पुरानी प्रणाली संघीय और समावेशी थी, जबकि नई प्रणाली केंद्रीकृत और व्यक्ति-केंद्रित बन गई थी। उन्होंने कांग्रेस को पुनर्स्थापित तो किया, लेकिन उसकी पुरानी लोकतांत्रिक संस्कृति को काफी हद तक समाप्त कर दिया था।

86. (B) केवल 1, 2, 4 और 5
1967 के चुनाव परिणामों ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को हिलाकर रख दिया था। तमिलनाडु में के. कामराज, महाराष्ट्र में एस. के. पाटिल, पश्चिम बंगाल में अतुल्य घोष और बिहार में के. बी. सहाय जैसे दिग्गज नेता अपनी सीटें हार गए थे। यह कांग्रेस के सांगठनिक पतन और जनता के बीच बढ़ते असंतोष का प्रमाण

44. (B) भारतीय कम्युनिप्सट पार्टी (CPI)
1971 के चुनावों में विपक्षी दलों ने जो 'ग्रैंड अलायंस' बनाया था, उसमें जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी शामिल थीं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) इस गठबंधन का हिस्सा नहीं थी। इसके विपरीत, CPI ने इंदिरा गाँधी की कांग्रेस (आर) के साथ चुनावी समझौता किया था। CPI का मानना था कि इंदिरा गाँधी की नीतियां प्रगतिशील हैं और उन्हें दक्षिणपंथी ताकतों के विरुद्ध समर्थन देना देश के हित में है।

45. (C) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई)
1971 के लोकसभा चुनावों के लिए इंदिरा गाँधी की कांग्रेस (आर) ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के साथ चुनावी गठबंधन किया। यह गठबंधन वैचारिक निकटता और रणनीतिक आवश्यकता पर आधारित था। CPI ने इंदिरा गाँधी के समाजवादी कार्यक्रमों जैसे बैंकों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया था। इस चुनावी तालमेल ने इंदिरा गाँधी को वामपंथी वोटों का लाभ दिलाया और विपक्ष के दक्षिणपंथी गठबंधन के विरुद्ध एक मजबूत विकल्प पेश किया।

46. (D) 1, 2, 3, 4 और 5 सभी
1971 का चुनाव नारों और कार्यक्रमों की लड़ाई थी। जहाँ ग्रैंड अलायंस केवल एक व्यक्ति के विरोध तक सीमित था, वहीं इंदिरा गाँधी ने एक स्पष्ट सामाजिक-आर्थिक एजेंडा पेश किया। उन्होंने गरीबी उन्मूलन, भूमि सुधार और प्रिवी पर्स की समाप्ति जैसे मुद्दों को अपनी राजनीति के केंद्र में रखा। उनकी यह सोची-समझी रणनीति जनता की आकांक्षाओं से मेल खाती थी, जिसने उन्हें चुनावी मैदान में बड़ी बढ़त दिलाई।

47. (A) 375
1971 के आम चुनाव के परिणाम कांग्रेस (आर) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के गठबंधन के लिए अभूतपूर्व रहे। इस गठबंधन ने लोकसभा की कुल 518 सीटों में से 375 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत प्राप्त किया। अकेले इंदिरा गाँधी की कांग्रेस ने 352 सीटें जीती थीं। इस भारी जीत ने यह स्पष्ट कर दिया कि जनता ने इंदिरा गाँधी के नेतृत्व और उनके "गरीबी हटाओ" के नारे को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है।

48. (B) 16
1971 के चुनावों में 'पुरानी कांग्रेस' यानी कांग्रेस (ओ) का प्रदर्शन अत्यंत निराशाजनक रहा। सिंडिकेट के अनुभवी नेताओं के होने के बावजूद, पार्टी को देश भर में मात्र 16 सीटें ही प्राप्त हो सकीं। इस करारी हार ने यह साबित कर दिया कि असली कांग्रेस वही है जिसका नेतृत्व इंदिरा गाँधी कर रही हैं। सिंडिकेट का प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो गया और वे भारतीय राजनीति के केंद्र से बाहर हो गए।

49. (C) 2, 3, 1, 4
इन घटनाओं का सही क्रम 1969 में कांग्रेस के विभाजन से आरंभ होता है। इसके पश्चात इंदिरा गाँधी ने 'गरीबी हटाओ' का लोकप्रिय नारा दिया। इसके प्रत्युत्तर में विपक्षी दलों ने 'ग्रैंड अलायंस' का गठन किया। अंततः, 1971 के आम चुनाव हुए जिसमें इंदिरा गाँधी को भारी सफलता मिली। यह अनुक्रम दर्शाता है कि कैसे एक राजनीतिक संकट ने चुनावी अभियान और परिणामों को एक नई दिशा प्रदान की।

50. (A) कांग्रेस (ओ) ने कांग्रेस (आर) से बेहतर प्रदर्शन किया।
1971 के चुनाव परिणामों ने कांग्रेस (ओ) की स्थिति को बहुत कमजोर कर दिया था। जहाँ इंदिरा गाँधी की कांग्रेस (आर) ने 352 सीटें जीतकर भारी बहुमत प्राप्त किया, वहीं कांग्रेस (ओ) मात्र 16 सीटों पर सिमट गई। 'ग्रैंड अलायंस' पूरी तरह विफल रहा और उसे बहुत कम सीटें मिलीं। इन नतीजों ने निर्विवाद रूप से स्थापित कर दिया कि इंदिरा गाँधी ही कांग्रेस की असली नेता और देश की सर्वमान्य प्रतिनिधि हैं।

51. (C) बांग्लादेश का संकट और भारत-पाक युद्ध।
1971 के लोकसभा चुनाव जीतने के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान में संकट गहरा गया। भारत को लाखों शरणार्थियों के बोझ और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इंदिरा गाँधी ने इस संकट का बहादुरी से सामना किया और पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में निर्णायक जीत हासिल की। इसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस ऐतिहासिक सफलता ने इंदिरा गाँधी की लोकप्रियता को देश और दुनिया में शिखर पर पहुँचा दिया।

52. (D) 1971 के युद्ध में जीत के बाद इंदिरा गाँधी की बढ़ी हुई लोकप्रियता।
1972 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की शानदार सफलता का मुख्य आधार 1971 के युद्ध की जीत थी। पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश के निर्माण ने इंदिरा गाँधी को एक 'दुर्गा' और अपराजेय राष्ट्रवादी नेता के रूप में स्थापित कर दिया था। जनता ने उनके नेतृत्व पर अटूट विश्वास दिखाया, जिससे कांग्रेस ने लगभग सभी राज्यों में भारी बहुमत से वापसी की और अपना खोया हुआ प्रभुत्व फिर पा लिया।

53. (C) गरीबों और वंचितों के रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में।
1972 तक इंदिरा गाँधी की छवि एक बहुआयामी नेता की बन गई थी। एक तरफ उनके "गरीबी हटाओ" कार्यक्रम ने उन्हें गरीबों का मसीहा बना दिया, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पर सैन्य विजय ने उन्हें एक शक्तिशाली राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभारा। वे अब केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन चुकी थीं। उनके इस दोहरे व्यक्तित्व ने उन्हें भारतीय राजनीति में अभूतपूर्व शक्ति प्रदान की।

54. (B) नई कांग्रेस पूर्णतया अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आश्रित थी और उसका सांगठनिक ढाँचा कमजोर था।
इंदिरा गाँधी की 'नई कांग्रेस' और नेहरु कालीन 'पुरानी कांग्रेस' के बीच बुनियादी संरचनात्मक अंतर था। पुरानी कांग्रेस एक ऐसा संगठन था जिसमें विभिन्न गुटों और विचारों को जगह मिलती थी। इसके विपरीत, नई कांग्रेस में संगठनात्मक ताकत की कमी थी और यह पूरी तरह से इंदिरा गाँधी की व्यक्तिगत लोकप्रियता और उनके करिश्मे पर टिकी थी। पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र और संवाद की प्रक्रिया काफी हद तक कमजोर हो गई थी।

(आर) ने 352 सीटें हासिल कीं, जबकि सिंडिकेट वाली कांग्रेस (ओ) मात्र 16 सीटों पर सिमट गई। 'ग्रैंड अलायंस' बुरी तरह पराजित हुआ और उसे 100 से बहुत कम सीटें मिलीं। इन नतीजों ने देश की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया।

98. (A) एस. निजलिंगप्पा
एस. निजलिंगप्पा भारतीय राजनीति के एक कद्दावर नेता थे जिन्होंने आधुनिक कर्नाटक के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे मैसूर प्रांत के मुख्यमंत्री रहे और राज्य के विकास के लिए कई बुनियादी ढांचे की नींव रखी। बाद में वे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और 1969 के विभाजन के समय चर्चा में रहे। उनकी प्रशासनिक सूझबूझ और सांगठनिक क्षमता के कारण उन्हें कर्नाटक का निर्माता माना जाता है।

99. (C) पार्टी अब गरीब, महिला, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों जैसे वर्गों पर ज़्यादा निर्भर थी।
1971 की चुनावी जीत ने कांग्रेस के सामाजिक आधार को पूरी तरह से बदल दिया। पहले कांग्रेस एक सर्वसमावेशी दल था, लेकिन अब उसने विशेष रुप से समाज के उपेक्षित वर्गों को अपने साथ जोड़ा। "गरीबी हटाओ" के आह्वान ने दलितों, आदिवासियों और गरीबों के बीच इंदिरा गाँधी की एक मसीहा जैसी छवि बना दी। यह नया वोट बैंक कांग्रेस के लिए आने वाले दशकों तक सत्ता का मुख्य आधार बना रहा।

100. (D) नेहरु की कांग्रेस एक संघीय और लोकतांत्रिक मंच थी, जबकि इंदिरा ने इसे केंद्रीकृत और अलोकतांत्रिक बना दिया।
नेहरु और इंदिरा गाँधी के शासन में कांग्रेस पार्टी के स्वरुप में बड़ा अंतर था। नेहरु के समय में पार्टी के भीतर अलग-अलग गुटों और क्षेत्रीय नेताओं का सम्मान होता था और निर्णय प्रक्रिया लोकतांत्रिक थी। इसके विपरीत, इंदिरा गाँधी ने पार्टी संगठन को दरकिनार कर पूरी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली। उन्होंने पार्टी को एक व्यक्ति-केंद्रित मशीनरी में बदल दिया, जिससे कांग्रेस की पुरानी संघीय और समावेशी प्रकृति समाप्त हो गई।

101. (A) केवल 1, 2 और 3
लालबहादुर शास्त्री एक साधारण पृष्ठभूमि से आए महान नेता थे। वे उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए प्रसिद्ध थे। नेहरु के समय में उन्होंने कई वर्षों तक महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। नेहरु अपने अंतिम दिनों में उन पर बहुत अधिक भरोसा करते थे और उन्हें अपना विश्वसनीय सहयोगी मानते थे। रेल दुर्घटना पर उनका इस्तीफा उनके उच्च नैतिक मूल्यों का जीवंत प्रमाण था।

102. (B) यह पहली बार था जब किसी गैर-कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला।
1967 में मद्रास (तमिलनाडु) में DMK की जीत भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की एक युगांतरकारी घटना थी। इससे पहले राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें गठबंधन के माध्यम से बनती थीं। यह पहला अवसर था जब एक क्षेत्रीय दल ने अपने दम पर स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया। इस परिणाम ने सिद्ध किया कि क्षेत्रीय पहचान और भाषाई अस्मिता के मुद्दे चुनाव जीतने के लिए अत्यंत शक्तिशाली हो सकते हैं।

103. (D) 1963
कामराज योजना 1963 में प्रस्तुत की गई थी। उस समय कांग्रेस पार्टी को सांगठनिक स्तर पर सक्रिय करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। के. कामराज का मानना था कि पार्टी के बड़े नेताओं को सरकारी पदों का मोह छोड़कर जनता के बीच जाना चाहिए। इस योजना के कार्यान्वयन से कई केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने अपने पदों से त्यागपत्र दिया, जिसका उद्देश्य पार्टी को एक बार फिर जन-केंद्रित और सेवाभावी बनाना था।

104. (A) वी. वी. गिरि
1969 में जब तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का कार्यकाल के दौरान निधन हुआ, तब संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति वी. वी. गिरि ने कार्यकारी राष्ट्रपति के रुप में कार्यभार संभाला। बाद में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस पद से इस्तीफा दे दिया। इंदिरा गाँधी के गुप्त समर्थन से वे स्वतंत्र उम्मीदवार के रुप में लड़े और जीतकर भारत के चौथे राष्ट्रपति बने। यह चुनाव कांग्रेस में विभाजन का एक बड़ा कारण बना।

105. (A) P-3, Q-1, R-4, S-2
1969 के राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े इन नेताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। मोरारजी देसाई बंबई के पूर्व मुख्यमंत्री थे और वित्तमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके थे। इंदिरा गाँधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए स्वतंत्र उम्मीदवार वी. वी. गिरि का समर्थन किया, जो अंततः चुनाव जीते। एन. संजीव रेड्डी कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार थे जो चुनाव हार गए। इन घटनाओं ने देश की राजनीतिक दिशा को पूरी तरह से नया मोड़ दिया।

106. (B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या है।
1967 के चुनाव अभियान के समय विपक्ष और सिंडिकेट के कुछ नेताओं ने इंदिरा गाँधी को कम अनुभवी माना था। हालाँकि, यह तर्क पूरी तरह सत्य है कि वे वर्षों से नेहरु के साथ राजनीति देख रही थीं, पार्टी अध्यक्ष रह चुकी थीं और शास्त्री सरकार में मंत्री भी थीं। उनकी कथित "अनुभवहीनता" का मुद्दा केवल उन्हें कमजोर दिखाने का एक राजनीतिक प्रयास था, जबकि उनके पास पर्याप्त प्रशासनिक समझ थी।

107. (D) 7 रुपये
इंदिरा गाँधी के शुरुआती शासनकाल में भारत ने गंभीर आर्थिक संकट और विदेशी मुद्रा की कमी का सामना किया। अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के दबाव में सरकार ने भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया। इस फैसले के बाद 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत, जो पहले 5 रुपये थी, बढ़कर 7 रुपये हो गई। इस कदम की देश में काफी आलोचना हुई और इसे राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ समझौते के रुप में देखा गया।

रात को हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। उनकी अचानक हुई मृत्यु ने पूरे भारत को शोक में डुबो दिया और देश के सामने नेतृत्व का नया संकट खड़ा कर दिया।

129. (B) के. कामराज
के. कामराज को भारतीय राजनीति का 'किंग-मेकर' कहा जाता था क्योंकि उन्होंने शास्त्री और इंदिरा गाँधी को प्रधानमंत्री बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। लेकिन विडंबना यह रही कि 1967 के विधानसभा चुनाव में वे खुद तमिलनाडु में अपने गृह क्षेत्र से चुनाव हार गए। उनकी यह हार उस समय कांग्रेस के गिरते प्रभाव और क्षेत्रीय दलों (DMK) की बढ़ती ताकत का एक स्पष्ट संकेत थी, जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था।

130. (A) क्योंकि इसने प्रधानमंत्री की शक्ति को पार्टी संगठन से ऊपर स्थापित कर दिया।
वी. वी. गिरि की जीत इंदिरा गाँधी की एक बड़ी रणनीतिक सफलता थी। इस परिणाम ने यह संदेश दिया कि प्रधानमंत्री की इच्छा पार्टी अध्यक्ष के आदेश से अधिक प्रभावी है। इसने सिंडिकेट के पुराने नेताओं के घमंड को तोड़ दिया और यह स्थापित किया कि अब कांग्रेस का भविष्य संगठन के पुराने ढांचे के बजाय इंदिरा गाँधी के व्यक्तिगत नेतृत्व में निहित है। यहीं से भारतीय राजनीति में व्यक्ति-पूजा का दौर अधिक प्रबल हुआ।

131. (C) यह मुख्य रुप से दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और गरीबों पर आधारित थी।
इंदिरा गाँधी की 'नई कांग्रेस' ने समाज के पारंपरिक सत्ता समीकरणों को चुनौती दी। उन्होंने अपना ध्यान उन वर्गों पर केंद्रित किया जो अब तक राजनीति के हाशिये पर थे। दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों को एक मंच पर लाकर उन्होंने एक नया सामाजिक गठबंधन तैयार किया। "गरीबी हटाओ" का नारा इस समूह को एकजुट करने वाला मुख्य सूत्र बना, जिसने आने वाले कई वर्षों तक कांग्रेस को चुनावी अजेयता प्रदान की।

132. (B) 1, 2, 3 और 4
1971 के 'ग्रैंड अलायंस' में कांग्रेस के विरोध में कई महत्वपूर्ण दल शामिल थे। इनमें पुरानी कांग्रेस (ओ), भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जैसे प्रमुख नाम थे। भारतीय क्रांति दल (BKD) भी इस गठबंधन का हिस्सा था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) इस समूह में नहीं थी क्योंकि वह इंदिरा गाँधी के पक्ष में खड़ी थी। यह गठबंधन विपरीत विचारधाराओं के मेल का एक दिलचस्प राजनीतिक प्रयोग था।

133. (C) मध्याह्न भोजन (दोपहर का भोजन) योजना
के. कामराज ने मद्रास के मुख्यमंत्री के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी शुरुआत की थी। उन्होंने गरीब बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करने और उनके पोषण स्तर को सुधारने के लिए सरकारी स्कूलों में 'मध्याह्न भोजन' योजना लागू की। यह योजना इतनी सफल रही कि बाद में इसे पूरे भारत में अपनाया गया। कामराज का यह कदम सामाजिक कल्याण और शिक्षा के प्रसार की दिशा में एक मील का पत्थर माना जाता है।

134. (C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
1967 के बाद बनी संविद सरकारें अपनी आंतरिक कलह के कारण बहुत अस्थिर थीं और अधिकांश अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाईं। तर्क गलत है क्योंकि इन सरकारों में शामिल दलों के बीच विचारधारा और कार्यक्रमों में भारी मतभेद थे। उनमें दक्षिणपंथी, वामपंथी और समाजवादी दल एक साथ थे जिनका केवल एक ही साझा लक्ष्य था—कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना। वैचारिक स्पष्टता की कमी उनकी असफलता का मुख्य कारण बनी।

135. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
भारतीय राजनीति के ये वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाओं के साक्षी रहे हैं। 1964 से 1966 तक लालबहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहे। 1966 से 1977 तक इंदिरा गाँधी का लंबा पहला कार्यकाल चला। 1967 का वर्ष 'राजनीतिक भूकंप' के रूप में जाना गया जब कांग्रेस को भारी क्षति हुई। 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसने देश के राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। इन वर्षों ने आधुनिक भारत की नींव रखी।

136. (A) 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार की हार के बाद।
1969 के राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम कांग्रेस के भीतर चल रहे शीतयुद्ध का चरम बिंदु थे। इंदिरा गाँधी द्वारा समर्थित वी. वी. गिरि ने पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार एन. संजीव रेड्डी को हरा दिया। इस हार से अपमानित होकर कांग्रेस अध्यक्ष एस. निजलिंगप्पा ने इंदिरा गाँधी पर गंभीर आरोप लगाए और उन्हें पार्टी से निकाल दिया। इस कड़े फैसले ने औपचारिक रूप से कांग्रेस को दो गुटों में विभाजित कर दिया।

137. (C) क्योंकि यह सरकार के 5 साल पूरे होने से पहले ही करा लिया गया।
1971 के चुनाव को मध्यावधि चुनाव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंदिरा गाँधी ने लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से एक वर्ष पहले ही उसे भंग करने की सिफारिश कर दी थी। सामान्यतः चुनाव 1972 में होने थे, लेकिन अपनी लोकप्रियता भुनाने और एक मजबूत जनादेश प्राप्त करने के लिए उन्होंने समय से पहले चुनाव का जोखिम लिया। यह भारतीय चुनावी राजनीति में एक नई और साहसिक रणनीति की शुरुआत थी।

138. (D) 1, 2, 3 और 4 सभी
सत्तर के दशक में इंदिरा गाँधी की लोकप्रियता के पीछे कई ठोस कारण थे। उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स की समाप्ति जैसे लोकलुभावन फैसले लिए। "गरीबी हटाओ" के नारे ने उन्हें गरीबों का मसीहा बना दिया। इसके ऊपर, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर मिली शानदार जीत ने उन्हें एक सशक्त राष्ट्रवादी नेता के रूप में प्रतिष्ठित किया। इन सभी सफलताओं ने उन्हें एक अपराजेय छवि प्रदान की।

118. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
इंदिरा गाँधी की 'नई कांग्रेस' पुरानी कांग्रेस से काफी अलग थी। यद्यपि उसने चुनावों में जीत हासिल की, लेकिन वह अब एक समावेशी संगठन नहीं रह गई थी। पुरानी कांग्रेस का ढाँचा विकेंद्रीकृत था, जबकि नई कांग्रेस पूरी तरह से इंदिरा गाँधी की व्यक्तिगत अपील पर निर्भर थी। पार्टी के भीतर के सांगठनिक चुनाव और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का प्रभाव कम हो गया था, जिससे पार्टी नेतृत्व के इर्द-गिर्द सिमट कर रह गई थी।

119. (D) उपराष्ट्रपति
वी. वी. गिरि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन थे। 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के आकस्मिक निधन के बाद वे कार्यकारी राष्ट्रपति बने। जब कांग्रेस ने एन. संजीव रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया, तो गिरि ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का मन बनाया और अपने संवैधानिक पदों से इस्तीफा दे दिया। इंदिरा गाँधी के रणनीतिक समर्थन ने उन्हें चुनाव जीतने और इतिहास रचने में महत्वपूर्ण मदद की।

120. (A) P-1, Q-3, R-4, S-1
1971 के चुनावों में विभिन्न दलों की भूमिका स्पष्ट थी। कांग्रेस (ओ) और जनसंघ 'ग्रैंड अलायंस' के तहत इंदिरा गाँधी के विरुद्ध खड़े थे। इंदिरा गाँधी की कांग्रेस (आर) ने "गरीबी हटाओ" के नारे पर चुनाव लड़ा और प्रचंड जीत दर्ज की। DMK मद्रास में अपनी पकड़ मजबूत किए हुए थी और उसने कांग्रेस (आर) का समर्थन किया था। इन राजनीतिक समीकरणों ने इंदिरा गाँधी की सत्ता में शानदार वापसी का मार्ग प्रशस्त किया।

121. (C) कांग्रेस पार्टी का फिर से प्रभुत्वशाली स्थिति में आना, भले ही उसकी प्रकृति बदल गई हो।
कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना का अर्थ यह नहीं था कि पुरानी व्यवस्था लौट आई है। इसका अर्थ था कि इंदिरा गाँधी ने कांग्रेस को फिर से देश की सबसे शक्तिशाली पार्टी बना दिया। हालाँकि, अब यह पहले की तरह विभिन्न विचारधाराओं का संगम नहीं थी, बल्कि एक केंद्रीकृत और व्यक्ति-केंद्रित दल बन चुकी थी। पार्टी ने अपनी चुनावी ताकत तो वापस पा ली, लेकिन उसका लोकतांत्रिक और सांगठनिक स्वरूप नेहरु युग के मुकाबले काफी हद तक बदल चुका था।

122. (A) 1969 में पार्टी के विभाजन को।
कांग्रेस के चुनाव चिह्न में परिवर्तन पार्टी के भीतर हुए ऐतिहासिक विभाजन का दृश्य प्रतीक है। आजादी के बाद से कांग्रेस का चुनाव चिह्न 'दो बैलों की जोड़ी' था। 1969 के विभाजन के बाद जब पार्टी दो भागों में बँट गई, तो चुनाव आयोग ने 'दो बैलों की जोड़ी' को पुरानी कांग्रेस को दिया। इसके जवाब में इंदिरा गाँधी की नई कांग्रेस ने 'गाय और बछड़ा' को अपना नया चुनाव चिह्न बनाया, जो ग्रामीण मतदाताओं के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ।

123. (D) आंध्र प्रदेश
1967 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को उत्तर भारत में भारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में उसकी स्थिति बेहतर रही। आंध्र प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में शामिल था जहाँ कांग्रेस अपना बहुमत बनाए रखने और सरकार बनाने में सफल रही। इस दौर में दक्षिण भारत की राजनीति उत्तर भारत के मुकाबले अधिक स्थिर रही, जिससे कांग्रेस को केंद्र में अपनी सत्ता बचाने के लिए आवश्यक समर्थन मिलता रहा।

124. (B) गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस लाने के लिए।
राममनोहर लोहिया का तर्क था कि कांग्रेस का लंबे समय तक सत्ता में रहना लोकतंत्र के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के बिखराव के कारण एक ऐसी पार्टी शासन कर रही है जो आम जनता की समस्याओं के प्रति उदासीन है। उनका मानना था कि गैर-कांग्रेसी दलों का एकजुट होना सत्ता सुख के लिए नहीं, बल्कि गरीबों और पिछड़ों की आवाज को शासन तक पहुँचाने और लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में बहाल करने के लिए जरूरी है।

125. (C) केंद्र में उसकी सत्ता समाप्त हो गई और गठबंधन सरकार बनी।
1967 के चुनाव कांग्रेस के लिए एक चेतावनी थे, लेकिन वे केंद्र में अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रहे। कथन C गलत है क्योंकि कांग्रेस ने लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया था और इंदिरा गाँधी के नेतृत्व में कांग्रेस की ही सरकार बनी थी। हालाँकि, यह सत्य है कि उनकी सीटों की संख्या और मत प्रतिशत में भारी गिरावट आई थी और राज्यों में उनका वर्चस्व काफी हद तक टूट गया था।

126. (B) केवल 1, 2 और 3
इंदिरा गाँधी और सिंडिकेट के बीच का संघर्ष वर्चस्व की लड़ाई थी। सिंडिकेट ने उन्हें प्रधानमंत्री पद पर इस उम्मीद में बिठाया था कि वे उनके हाथ की कठपुतली बनी रहेंगी। इसके विपरीत, इंदिरा गाँधी ने पार्टी संगठन से बाहर के विशेषज्ञों और सलाहकारों की एक नई टीम बनाई। उन्होंने बड़ी ही सावधानी और राजनीतिक कौशल से सिंडिकेट के पुराने नेताओं को दरकिनार कर दिया, जिससे उनके बीच का संघर्ष एक सार्वजनिक विभाजन में बदल गया।

127. (A) पाकिस्तान से युद्ध और खाद्यान्न संकट
"जय जवान, जय किसान" नारा लालबहादुर शास्त्री की दूरदर्शिता का परिणाम था। उस समय भारत 1965 के युद्ध के कारण सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा था, जिसके लिए सेना का मनोबल बढ़ाना आवश्यक था। साथ ही, देश में मानसून की विफलता के कारण अनाज की भारी कमी थी, जिससे निपटने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना जरूरी था। यह नारा इन दोनों मोर्चों पर राष्ट्र को एकजुट करने का एक सशक्त माध्यम बना।

128. (B) ताशकंद, सोवियत संघ (अब उज्बेकिस्तान)
लालबहादुर शास्त्री की मृत्यु भारत के बाहर सोवियत संघ के ताशकंद शहर में हुई थी। वे वहां 1965 के युद्ध को समाप्त करने और शांति समझौता करने के लिए गए थे। ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही घंटों बाद, 11 जनवरी 1966 की

अपनी करिश्माई छवि और लोकलुभावन नीतियों के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने में सक्षम थीं। सिंडिकेट जहां पार्टी की आंतरिक मशीनरी और क्षेत्रीय क्षत्रपों के भरोसे रहता था, वहीं इंदिरा गांधी ने 'गरीबी हटाओ' जैसे नारों से गरीबों और पिछड़ों के बीच अपनी पैठ बनाई थी।

171. (C) नई कांग्रेस अत्यधिक केंद्रीकृत थी जबकि पुरानी कांग्रेस एक छाता संगठन थी।
नेहरू युग की पुरानी कांग्रेस एक व्यापक संगठन थी जिसमें विभिन्न गुट और विचार समाहित थे। इसमें निर्णय प्रक्रिया सामूहिक होती थी। इसके विपरीत, 1971 के बाद उभरी नई कांग्रेस पूरी तरह से इंदिरा गांधी के इर्द-गिर्द केंद्रित थी। यहां शक्ति का केंद्रीकरण शीर्ष पर था और पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र कमजोर हो गया था, जिससे वह पुरानी व्यवस्था से मौलिक रूप से भिन्न हो गई।

172. (B) यह विभिन्न विचारधाराओं और गुटों का एक समावेशी मंच थी।
पुरानी कांग्रेस प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता उसका समावेशी स्वरूप था। यह पार्टी एक 'छाता संगठन' की तरह काम करती थी, जहाँ अलग-अलग सामाजिक हितों और राजनीतिक विचारों वाले लोग एक साथ रहते थे। पार्टी के भीतर आंतरिक चर्चा और गुटबाजी को भी स्वीकार किया जाता था, जिससे विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य बना रहता था और शक्ति का संतुलन स्थानीय स्तर तक फैला हुआ था।

173. (D) स्वयं इंदिरा गांधी का व्यक्तिगत करिश्मा और लोकलुभावन अपील।
नई कांग्रेस की ताकत का मुख्य आधार इंदिरा गांधी का अपना व्यक्तिगत करिश्मा और उनकी लोकलुभावन अपील थी। उन्होंने संगठन की मजबूती के बजाय सीधे जनता के भरोसे चुनाव जीता। उनके प्रति लोगों का गहरा विश्वास और 'गरीबी हटाओ' जैसे प्रभावशाली नारों ने उन्हें एक सशक्त नेता बनाया। इसी व्यक्तिगत लोकप्रियता के कारण पार्टी संगठन उनकी इच्छाओं के अधीन होकर कार्य करने लगा था।

174. (A) इसने पार्टी को कुछ विशेष सामाजिक वर्गों, जैसे गरीबों और अल्पसंख्यकों पर निर्भर बना दिया।
'गरीबी हटाओ' के नारे ने समाज के वंचित वर्गों, जैसे गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों के बीच कांग्रेस के प्रति एक नया उत्साह पैदा किया। इस लोकलुभावन राजनीति ने कांग्रेस को इन विशिष्ट सामाजिक समूहों पर अत्यधिक निर्भर बना दिया। हालाँकि इससे चुनाव में भारी जीत मिली, लेकिन इसने मध्यम वर्ग और अन्य वर्गों के साथ पार्टी के पारंपरिक संबंधों और सांगठनिक संतुलन को भी बदल दिया था।

175. (C) 1971 की जीत ने कांग्रेस के प्रभुत्व को तो पुनर्स्थापित किया, लेकिन एक नई, केंद्रीकृत और व्यक्तिगत प्रणाली के तहत।
1971 के परिणामों का विश्लेषण यह निष्कर्ष देता है कि कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक प्रधानता तो फिर से हासिल कर ली, लेकिन यह वह पुरानी व्यवस्था नहीं थी। यह एक नया स्वरूप था जो पूरी तरह से केंद्रीकृत और व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित था। इस बदलाव ने पार्टी की बहुलवादी और गुटीय संतुलन वाली प्रकृति को समाप्त कर दिया, जो भारतीय लोकतंत्र की एक नई दिशा का सूचक था।

139. (D) 60 से भी कम
1971 के चुनावों में विपक्षी 'ग्रैंड अलायंस' का प्रदर्शन अत्यंत दयनीय रहा। इंदिरा गाँधी की आंधी के सामने सभी दिग्गज धाराशायी हो गए। इस गठबंधन में शामिल कई बड़े दलों को मिलाकर भी कुल सीटों की संख्या 60 का आंकड़ा पार नहीं कर सकी। जनता ने नकारात्मक राजनीति को नकारते हुए इंदिरा गाँधी के सकारात्मक कार्यक्रमों पर मुहर लगाई। यह हार विपक्ष के लिए एक बड़ा सबक थी जिसने उनकी रणनीति की कमजोरियों को उजागर किया।

140. (B) सी. नटराजन अन्नादुरई
सी. नटराजन अन्नादुरई दक्षिण भारत के एक महान जननेता थे जिन्होंने द्रविड़ अस्मिता को राजनीति का मुख्य आधार बनाया। वे जस्टिस पार्टी और द्रविड़ कषगम से जुड़े रहे और बाद में DMK की स्थापना की। उन्होंने हिंदी के अनिवार्य थोपे जाने का पुरजोर विरोध किया और इसे भाषाई साम्राज्यवाद माना। उनके नेतृत्व में हुए हिंदी-विरोधी आंदोलन ने उन्हें तमिलनाडु में अपार लोकप्रियता दी और पहली बार राज्य में गैर-कांग्रेसी सत्ता स्थापित की।

141. (C) 20 वर्ष
1967 के आम चुनाव के समय तक कांग्रेस पार्टी को देश पर लगातार 20 वर्षों तक शासन करने का अनुभव प्राप्त था। 1947 में आजादी के बाद से केंद्र और लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस का ही एकछत्र राज था। इस लंबी अवधि ने पार्टी में एक तरह की जड़ता और आत्मविश्वास पैदा कर दिया था। 1967 के चुनाव परिणामों ने पहली बार इस दो दशक पुराने एकाधिकार को कड़ी चुनौती दी और लोकतांत्रिक प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया।

142. (D) कांग्रेस सांसदों के बीच हुए गुप्त मतदान द्वारा।
1966 में लालबहादुर शास्त्री के निधन के बाद प्रधानमंत्री पद के चयन के लिए कांग्रेस में एक पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई गई। मोरारजी देसाई और इंदिरा गाँधी के बीच आम सहमति नहीं बन पाई, इसलिए कांग्रेस संसदीय दल के सांसदों के बीच गुप्त मतदान कराया गया। इस चुनाव में इंदिरा गाँधी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। यह घटना भारतीय लोकतंत्र और पार्टी के भीतर की आंतरिक चुनाव प्रणाली की परिपक्वता का उदाहरण थी।

143. (A) बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स की समाप्ति
इंदिरा गाँधी और मोरारजी देसाई के बीच वैचारिक मतभेद मुख्य रूप से आर्थिक नीतियों को लेकर थे। इंदिरा गाँधी वामपंथी और समाजवादी नीतियों को तेजी से लागू करना चाहती थीं, जबकि देसाई अधिक रुढ़िवादी आर्थिक दृष्टिकोण रखते थे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स की समाप्ति जैसे क्रांतिकारी कदमों ने इस खाई को और बढ़ा दिया। इन्हीं मतभेदों के कारण देसाई ने सरकार से अलग होने का निर्णय लिया, जिससे कांग्रेस में दरार पड़ गई।

144. (B) यह एक ऐसी पार्टी थी जो पूरी तरह से अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर निर्भर थी।
इंदिरा गाँधी द्वारा पुनर्गठित 'नई कांग्रेस' की संरचना काफी हद तक व्यक्ति-केंद्रित थी। नेहरू के समय की कांग्रेस में कई बड़े क्षेत्रीय नेता और स्वतंत्र विचारधारा वाले गुट हुआ करते थे। इसके विपरीत, नई कांग्रेस में निर्णय लेने की सारी शक्तियां इंदिरा गाँधी के पास केंद्रित हो गईं। पार्टी का सांगठनिक ढाँचा कमजोर हो गया था और वह मुख्य रूप से इंदिरा गाँधी के करिश्माई व्यक्तित्व और उनके द्वारा दिए गए नारों पर टिकी थी।

145. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
1972 के विधानसभा चुनाव इंदिरा गाँधी के लिए एक बड़ी जीत लेकर आए। इसका मुख्य कारण 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के विरुद्ध मिली ऐतिहासिक विजय थी। इस सैन्य सफलता ने इंदिरा गाँधी को एक 'अजेय' नेता के रूप में स्थापित कर दिया था। जनता ने राष्ट्रीय गौरव की इस भावना के साथ कांग्रेस को वोट दिया, जिससे पार्टी ने राज्यों में अपनी खोई हुई सत्ता को फिर से मजबूती से प्राप्त कर लिया।

146. (A) क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर अनेक दलों का उभरना और राज्यों में विभिन्न दलों की सरकारों का गठन होना।
1967 के बाद भारतीय दलीय व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आया जिसे 'बहुदलीय प्रणाली' का उदय कहा गया। अब कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प नहीं रह गई थी। राज्यों में क्षेत्रीय दलों और विपक्षी गठबंधनों (SVD) की सरकारों ने यह सिद्ध किया कि लोकतांत्रिक विकल्प मौजूद हैं। केंद्र में भी विपक्ष की भूमिका अधिक सक्रिय हो गई थी। इस विविधीकरण ने भारतीय लोकतंत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी और जन-केंद्रित बनाने की दिशा में काम किया।

147. (D) 1, 2, 3, 4 और 5 सभी
1971 के चुनाव परिणामों ने कई महत्वपूर्ण बातें सिद्ध कीं। इसने दिखाया कि जनता एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व चाहती है। सिंडिकेट के पुराने नेताओं की हार ने साबित किया कि वे जनभावनाओं से कट चुके थे। विपक्षी गठबंधन की विफलता ने यह संदेश दिया कि केवल विरोध के नाम पर बना मोर्चा टिक नहीं सकता। अंततः, इंदिरा गाँधी की सकारात्मक राजनीति और उनकी सोची-समझी रणनीतियों ने भारतीय राजनीति में उनकी सर्वोच्चता को निर्विवाद बना दिया।

148. (D) स्वतंत्र पार्टी
राजस्थान के एक गाँव की चुनाव कथा उस समय की स्थानीय राजनीति और गुटबाजी का रोचक चित्रण करती है। इसमें चाचा और भतीजे के बीच की प्रतिद्वंद्विता में स्वतंत्र पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई गई है। स्वतंत्र पार्टी उस दौर में कांग्रेस की मुख्य दक्षिणपंथी प्रतिद्वंद्वी थी जो मुक्त अर्थव्यवस्था की पक्षधर थी। गाँव के स्तर पर यह राजनीतिक लड़ाई केवल सिद्धांतों की नहीं, बल्कि पारिवारिक प्रभाव और स्थानीय वर्चस्व की भी जंग बन गई थी।

149. (C) क्योंकि यह बिना किसी विवाद के, सलाह-मशविरे से और शांतिपूर्ण ढंग से हल हो गया।
नेहरू के निधन के बाद उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो आशंकाएं थीं, वे निर्मूल साबित हुईं। भारतीय राजनीति ने अत्यंत परिपक्वता का परिचय दिया। कांग्रेस अध्यक्ष के. कामराज के कुशल नेतृत्व में पार्टी ने सामूहिक विचार-विमर्श के माध्यम से लालबहादुर शास्त्री को अपना नेता चुन लिया। बिना किसी हिंसा या सार्वजनिक विवाद के सत्ता का यह सुगम हस्तांतरण भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और स्थिरता का एक महान वैश्विक प्रमाण था।

150. (B) भारत की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत, जहाँ एक नेता का करिश्मा पार्टी संगठन पर हावी हो गया।
1971 के बाद कांग्रेस की पुनर्स्थापना पुरानी व्यवस्था की वापसी नहीं, बल्कि एक नए राजनीतिक अध्याय का प्रारंभ थी। अब पार्टी संगठन की महत्ता कम हो गई थी और सब कुछ इंदिरा गाँधी के व्यक्तित्व के इर्द-गिर्द सिमट गया था। यह 'नई कांग्रेस प्रणाली' अलोकतांत्रिक तो नहीं थी, लेकिन इसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई थी। इसने भारतीय राजनीति को एक नया स्वरूप दिया जहाँ नेता का प्रभाव संस्थागत ढांचे से ऊपर हो गया।

151. (B) नेतृत्व परिवर्तन के कारण राजनीतिक अस्थिरता या सैन्य हस्तक्षेप की आशंका।
नेहरू के निधन के बाद विश्व के कई नव-स्वतंत्र देशों में सत्ता परिवर्तन अक्सर सेना के हस्तक्षेप या अस्थिरता के साथ हुआ था। इसी कारण अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को डर था कि भारत का लोकतांत्रिक ढांचा चरमरा सकता है। उन्हें आशंका थी कि नेतृत्व के लिए होने वाला संघर्ष देश की एकता और शांतिपूर्ण राजनीतिक संक्रमण को बाधित कर सकता है।

152. (A) पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बनाए रखना और अपने प्रभाव को कायम रखना।
कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली क्षेत्रीय नेताओं के समूह, जिसे सिंडिकेट कहा जाता था, ने लाल बहादुर शास्त्री का चयन एक सोची-समझी रणनीति के तहत किया था। उनका मुख्य उद्देश्य पार्टी के भीतर शक्ति का संतुलन बनाए रखना था। वे चाहते थे कि प्रधानमंत्री ऐसा व्यक्ति बने जो संगठन के प्रभाव को स्वीकार करे और उनके नियंत्रण को चुनौती न दे सके।

153. (C) भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता और संवैधानिक प्रक्रियाओं की सफलता।
लाल बहादुर शास्त्री का निर्विरोध प्रधानमंत्री चुना जाना भारतीय लोकतंत्र के लिए एक मील का पत्थर था। यह इस बात का प्रमाण था कि भारत में नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया अत्यंत परिपक्व और संवैधानिक है। इसने दुनिया को दिखाया कि नेहरू के बिना भी भारत शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी राजनीतिक चुनौतियों का समाधान करने में पूरी तरह सक्षम है।

154. (D) प्रभावशाली प्रादेशिक नेताओं का एक समूह था जिनका पार्टी संगठन पर नियंत्रण था।
सिंडिकेट कांग्रेस पार्टी के भीतर उन वरिष्ठ और प्रभावशाली क्षेत्रीय नेताओं का एक अनौपचारिक समूह था, जिनका पार्टी संगठन पर गहरा प्रभाव और नियंत्रण था। के. कामराज, एस. के. पाटिल और अतुल्य घोष जैसे नेता इसके प्रमुख सदस्य थे। यह समूह पार्टी के महत्वपूर्ण निर्णयों और प्रधानमंत्री के चुनाव जैसे गंभीर राजनीतिक मामलों में निर्णायक भूमिका निभाता था।

155. (C) कांग्रेस पार्टी का संगठनात्मक ढाँचा इस शांतिपूर्ण संक्रमण में महत्वपूर्ण था।
नेहरू के बाद उत्तराधिकार के प्रश्न का समाधान यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी का संगठनात्मक ढांचा अत्यंत सुदृढ़ था। सिंडिकेट जैसे समूहों की सक्रिय भागीदारी और सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया ने देश को एक स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। इस सुव्यवस्थित प्रक्रिया ने साबित किया कि पार्टी का ढांचा लोकतंत्र की निरंतरता और शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन सुनिश्चित करने में सक्षम था।

156. (B) कांग्रेस शासन को अलोकतांत्रिक और जन-विरोधी मानना।
राममनोहर लोहिया का मानना था कि लंबे समय तक कांग्रेस का शासन बने रहने से उसमें जड़ता आ गई है और वह लोकतांत्रिक मूल्यों से दूर हो गया है। उन्होंने तर्क दिया कि कांग्रेस की नीतियां आम जनता, विशेषकर गरीबों और पिछड़ों के हितों की अनदेखी कर रही हैं। इसलिए लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए कांग्रेस को हटाना अनिवार्य था।

157. (D) कांग्रेस को हराने के लिए सभी विपक्षी दलों द्वारा एकजुट होकर चुनाव लड़ना।
गैर-कांग्रेसवाद की रणनीति का मुख्य उद्देश्य विपक्षी वोटों के बिखराव को रोकना था। लोहिया का विचार था कि विपक्षी दलों के अलग-अलग चुनाव लड़ने से कांग्रेस को कम जनसमर्थन के बावजूद जीत मिल जाती है। उन्होंने सभी विरोधी दलों को एकजुट होकर एक साझा मंच पर आने का सुझाव दिया ताकि वे मिलकर कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर सकें।

158. (A) कांग्रेस कम वोट पाकर भी चुनाव जीत जाती थी।
चुनावी आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए लोहिया ने पाया कि कांग्रेस विरोधी वोट कई दलों में बंट जाते हैं। इस विभाजन के कारण कांग्रेस को बहुमत न होने पर भी अधिक सीटें मिल जाती थीं। उन्होंने तर्क दिया कि यह स्थिति लोकतंत्र के लिए घातक है क्योंकि यह जनता की वास्तविक इच्छा को सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं करती थी और कांग्रेस को लाभ पहुँचाती थी।

159. (C) वे वैचारिक रूप से विषम थे, जिनमें दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों दल शामिल थे।
गैर-कांग्रेसवाद के तहत बने गठबंधन वैचारिक रूप से बहुत ही भिन्न और विरोधाभासी थे। इनमें दक्षिणपंथी जनसंघ और वामपंथी साम्यवादी दल जैसे विपरीत विचारधारा वाले दल भी शामिल थे। इन दलों के बीच आपसी मतभेद होने के बावजूद, कांग्रेस को हराने का साझा लक्ष्य ही उनकी एकता का मुख्य

आधार था। यह एक व्यावहारिक राजनीतिक समझौता था जो विचारधारा से ऊपर था।

160. (A) कई राज्यों में संयुक्त विधायक दल की गठबंधन सरकारों का गठन।
1967 के चुनावों में गैर-कांग्रेसवाद की रणनीति काफी हद तक सफल रही, जिससे भारतीय राजनीति की तस्वीर बदल गई। इसके परिणामस्वरूप कई राज्यों में विपक्षी दलों ने मिलकर 'संयुक्त विधायक दल' (एसवीडी) की गठबंधन सरकारें बनाईं। इसने पहली बार कांग्रेस के एकाधिकार को तोड़ा और राज्यों में बहुदलीय राजनीति के एक नए युग की शुरुआत की, जिससे क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ गया।

161. (D) क्योंकि इसने पहली बार कांग्रेस के प्रभुत्व को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गंभीर चुनौती दी थी।
1967 के चुनाव परिणामों ने दशकों से चले आ रहे कांग्रेस के एकछत्र शासन की नींव हिला दी थी। कांग्रेस को न केवल लोकसभा में कम सीटें मिलीं, बल्कि नौ राज्यों में उसे सत्ता से बाहर होना पड़ा। इस अभूतपूर्व बदलाव ने भारतीय राजनीति के केंद्र और राज्यों के शक्ति समीकरणों को स्थायी रूप से बदल दिया, जिससे राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मच गई।

162. (B) देश में गंभीर खाद्य संकट उत्पन्न हुआ और अनाज का आयात करना पड़ा।
1960 के दशक के मध्य में पड़े सूखे ने भारतीय कृषि को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे खाद्य उत्पादन में भारी गिरावट आई। देश में अनाज की भीषण कमी हो गई, जिसके कारण भुखमरी जैसे हालात पैदा हो गए। इस संकट से निपटने के लिए भारत को अमेरिका से अपमानजनक शर्तों पर बड़े पैमाने पर अनाज का आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ा था।

163. (C) विदेशी मुद्रा भंडार की कमी और बाहरी, विशेषकर अमेरिकी, दबाव।
1966 में इंदिरा गांधी की सरकार ने विदेशी मुद्रा भंडार के संकट और बढ़ते आर्थिक दबाव के कारण रुपये का अवमूल्यन किया था। इस निर्णय के पीछे मुख्य रूप से अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का दबाव था। सरकार को लगा कि अवमूल्यन से निर्यात बढ़ेगा और आर्थिक स्थिरता आएगी, लेकिन तत्काल प्रभाव के रूप में इसने अर्थव्यवस्था में काफी उथल-पुथल मचा दी थी।

164. (D) आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई, जिससे महंगाई बढ़ी।
रुपये के अवमूल्यन के कारण आयातित वस्तुओं की लागत बढ़ गई, जिसका सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ा। इसके तत्काल बाद आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी उछाल आया, जिससे महंगाई अनियंत्रित हो गई। इसने शहरी मध्यम वर्ग और गरीब जनता की क्रय शक्ति को कम कर दिया, जिससे सरकार के प्रति जनता में गहरा असंतोष और विरोध की भावना प्रबल हो गई थी।

165. (A) गंभीर आर्थिक कठिनाइयों के कारण उत्पन्न व्यापक जन असंतोष।
1967 के चुनावों में कांग्रेस की हार का मुख्य कारण सूखे, महंगाई और बेरोजगारी से उत्पन्न आर्थिक संकट था। जनता भोजन की कमी और बढ़ती कीमतों से परेशान थी, जिसके कारण सरकार के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए। विपक्षी दलों ने इस जन आक्रोश को प्रभावी ढंग से संगठित किया, जिससे कांग्रेस का चुनावी आधार कमजोर हो गया और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा।

166. (B) एक वैचारिक और पीढ़ीगत टकराव।
1969 में कांग्रेस का विभाजन केवल सत्ता का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह पुरानी और नई विचारधाराओं के बीच का टकराव था। सिंडिकेट पारंपरिक और संगठनात्मक तरीके से पार्टी चलाना चाहता था, जबकि इंदिरा गांधी एक नई और अधिक लोकलुभावन शैली अपनाना चाहती थीं। यह पीढ़ीगत अंतर और कार्यशैली में भिन्नता ही अंततः पार्टी के औपचारिक विभाजन का मुख्य कारण बनी थी।

167. (B) पार्टी के भीतर शक्ति और नियंत्रण।
सिंडिकेट के नेताओं और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच मुख्य संघर्ष पार्टी के भीतर सर्वोच्चता स्थापित करने को लेकर था। सिंडिकेट पार्टी के संगठन पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखना चाहता था और चाहता था कि प्रधानमंत्री उनके निर्देशों का पालन करें। दूसरी ओर, इंदिरा गांधी स्वयं को एक स्वतंत्र और शक्तिशाली नेता के रूप में स्थापित करना चाहती थीं, जिससे दोनों में टकराव बढ़ा।

168. (A) पार्टी के व्हिप को धता बताकर अपने समर्थित उम्मीदवार वी.वी. गिरि को जिताने के लिए।
इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान 'अंतरात्मा की आवाज' पर मतदान करने की अपील करके सीधे पार्टी के आधिकारिक निर्देशों को चुनौती दी थी। उनका उद्देश्य कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार एन. संजीव रेड्डी को हराना और अपने समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवार वी.वी. गिरि को जिताना था। यह रणनीतिक कदम पार्टी संगठन के खिलाफ उनके खुले विद्रोह का प्रतीक था, जिससे राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए।

169. (C) इसने इंदिरा गांधी को पार्टी के सर्वोच्च नेता के रूप में स्थापित किया और विभाजन को गति दी।
1969 के राष्ट्रपति चुनाव में वी.वी. गिरि की जीत ने यह साबित कर दिया कि इंदिरा गांधी के पास पार्टी के अधिकांश सदस्यों का समर्थन है। इस जीत ने सिंडिकेट के प्रभाव को लगभग समाप्त कर दिया और इंदिरा गांधी को पार्टी के निर्विवाद नेता के रूप में स्थापित किया। हालांकि, इस घटना ने पार्टी के भीतर दरार को और गहरा कर दिया, जिससे अंततः कांग्रेस दो हिस्सों में बंट गई।

170. (D) वह सीधे जनता से जुड़ने वाली एक लोकलुभावन और करिश्माई राजनीति पर जोर देती थीं।
इंदिरा गांधी ने पारंपरिक संगठनात्मक राजनीति के बजाय सीधे जनता के साथ संवाद स्थापित करने वाली शैली अपनाई। वे

(C) बढ़ती कीमतें, खाद्यान्न का अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार
(D) राज्य के सभी सरकारी संस्थानों में विश्वविद्यालयी शुल्क में वृद्धि

10. जयप्रकाश नारायण ने बिहार आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर स्वीकार किया था?
(A) आंदोलन अहिंसक रहेगा और अपने को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखेगा।
(B) आंदोलन हिंसक हो सकता है, लेकिन वह केवल बिहार राज्य तक ही सीमित रहेगा।
(C) आंदोलन केवल बिहार की भौगोलिक सीमाओं तक सीमित रहेगा और पूर्णतः अहिंसक होगा।
(D) आंदोलन में केवल छात्र समुदाय की भागीदारी होगी और बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा।

11. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है।
अभिकथन (A): जयप्रकाश नारायण ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में 'संपूर्ण क्रांति' का आह्वान किया।
कारण (R): उनका उद्देश्य भारत में 'सच्चे लोकतंत्र' की स्थापना करना था।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

12. निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. गुजरात में छात्र आंदोलन
2. 1974 की रेल हड़ताल
3. बिहार में छात्र आंदोलन
4. जयप्रकाश नारायण द्वारा 'संसद-मार्च' का नेतृत्व
(A) 1, 3, 2, 4
(B) 2, 1, 3, 4
(C) 1, 2, 4, 3
(D) 3, 1, 2, 4

13. 1975 में जयप्रकाश नारायण को किन गैर-कांग्रेसी दलों का समर्थन प्राप्त था?
(A) मुख्य रूप से केवल भारतीय जनसंघ और सोशलिस्ट पार्टी का समूह
(B) केवल भारतीय लोकदल और कांग्रेस (ओ) का चुनावी और राजनीतिक दल
(C) भारतीय जनसंघ, कांग्रेस (ओ), भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी
(D) दक्षिण भारत का केवल क्षेत्रीय दल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK)

14. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है?
(A) इंदिरा गाँधी का मानना था कि गुजरात और बिहार के आंदोलन उनके प्रति व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित थे।
(B) 1974 में रेलवे कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान जॉर्ज फर्नान्डिस ने किया था।
(C) जेपी के आंदोलन को कांग्रेस विरोधी आंदोलन माना गया।
(D) सरकार ने रेलवे हड़ताल को पूर्णतः वैधानिक करार दिया था।

15. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. 1974 की रेल हड़ताल बोनस और सेवा से जुड़ी शर्तों को लेकर थी।
2. सरकार ने हड़ताल को अवैधानिक करार दिया था।
3. हड़ताल 20 दिन के बाद एक समझौते के साथ समाप्त हुई।
4. हड़ताल के दौरान रेल लाइनों की सुरक्षा में सेना को तैनात किया गया था।
5. हड़ताल का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था।

उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 4 सही हैं।
(B) केवल 2, 3 और 5 सही हैं।
(C) केवल 1, 3 और 5 सही हैं।
(D) सभी 1, 2, 3, 4 और 5 सही हैं।

16. 'प्रतिबद्ध न्यायपालिका' की अवधारणा से क्या तात्पर्य है?
(A) न्यायपालिका का संविधान के प्रति प्रतिबद्ध होना
(B) न्यायाधीशों और सरकारी अधिकारियों का शासक दल के प्रति निष्ठावान होना
(C) न्यायपालिका का स्वतंत्र और निष्पक्ष होना
(D) न्यायपालिका का अंतरराष्ट्रीय कानूनों के प्रति प्रतिबद्ध होना

17. केशवानंद भारती के प्रसिद्ध मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या फैसला सुनाया?
(A) संसद मौलिक अधिकारों में मनचाही कटौती कर सकती है।
(B) संविधान का एक 'बुनियादी ढाँचा' है और संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती।
(C) संसद संविधान के किसी भी हिस्से में पूर्ण संशोधन कर सकती है।
(D) नीति-निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर अनिवार्य वरीयता दी जानी चाहिए।

18. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (व्यक्ति)
P. जगमोहन लाल सिन्हा
Q. राजनारायण
R. ए. एन. रे
S. फखरुद्दीन अली अहमद

सूची II: (भूमिका/पद)

अध्याय 13

लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट

1. 1971 के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है?
(A) पार्टी सांगठनिक दृष्टि से पहले की तुलना में अधिक मज़बूत हो गई थी।
(B) पार्टी का नवजीवन हुआ लेकिन वह पहले जैसी नहीं रही।
(C) पार्टी की आंतरिक संरचना और नीतियों में कोई भी बदलाव नहीं आया था।
(D) पार्टी आंतरिक संघर्षों के कारण पूरी तरह से बिखर गई थी।

2. 1973 से 1975 के बीच की घटनाओं ने भारत की लोकतांत्रिक राजनीति के समक्ष कौन सी नई चुनौती पेश की?
(A) सांविधानिक और संस्थागत संतुलन की चुनौती
(B) दल-बदल की अनियंत्रित समस्या
(C) क्षेत्रीय स्वायत्तता की तीव्र मांग
(D) विदेशी शक्तियों का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप

3. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है।
अभिकथन (A): 1975 में भारत में 'अंदरूनी गड़बड़ियों' की आशंका के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई।
कारण (R): आमतौर पर आपातकाल युद्ध, आक्रमण या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में ही लगाया जाता है।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

4. 1971-72 के बाद के वर्षों में भारत की सामाजिक-आर्थिक दशा में सुधार न होने का एक प्रमुख कारण क्या था?
(A) देश में औद्योगिक क्रांति का पूर्ण अभाव होना
(B) कृषि उत्पादन में निरंतर होने वाली अत्यधिक वृद्धि
(C) भारतीय बाज़ारों में विदेशी निवेश की अचानक कमी
(D) बांग्लादेश संकट से अर्थव्यवस्था पर पड़ा भारी बोझ

5. 1973 में वस्तुओं की कीमतों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई?
(A) 30 प्रतिशत
(B) 8 प्रतिशत
(C) 23 प्रतिशत
(D) 15 प्रतिशत

6. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (घटना)
P. 'गरीबी हटाओ' का नारा
Q. बिहार आंदोलन का नेतृत्व
R. रेल हड़ताल का आह्वान
S. कांग्रेस अध्यक्ष का नारा "इंदिरा इज़ इंडिया"
सूची II: (संबंधित व्यक्ति/वर्ष)
1. जॉर्ज फर्नान्डिस
2. डी.के. बरुआ
3. 1971
4. जयप्रकाश नारायण
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

7. मार्क्सवादी-लेनिनवादी (अब माओवादी) समूहों ने मौजूदा राजनीतिक प्रणाली को खत्म करने के लिए किन तकनीकों का सहारा लिया?
(A) संसदीय बहसों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का
(B) चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का
(C) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में याचिका दायर करने का
(D) हथियार उठाने और राज्यविरोधी तकनीकों का

8. गुजरात छात्र आंदोलन (1974) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. आंदोलन खाद्यान्न, खाद्य तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के खिलाफ था।
2. आंदोलन में बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ शामिल नहीं हुईं।
3. इस आंदोलन के परिणामस्वरूप गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगाया गया।
4. मोरारजी देसाई ने इस आंदोलन के समर्थन में भूख हड़ताल की थी।
निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1, 3 और 4
(D) सभी 1, 2, 3 और 4

9. बिहार में 1974 के छात्र आंदोलन का मुख्य कारण क्या था?
(A) राज्य के प्रशासन में व्याप्त केवल राजनीतिक भ्रष्टाचार
(B) युवाओं के बीच बढ़ती केवल बेरोजगारी की एक समस्या

108. (B) एक साधारण सत्ता-संघर्ष को विचारधारात्मक संघर्ष में बदलना और वामपंथी नीतियां अपनाना।
1967 की चुनावी झटकों के बाद इंदिरा गाँधी ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक नई रणनीति अपनाई। उन्होंने सिंडिकेट के साथ सत्ता के सीधे टकराव को एक 'वैचारिक युद्ध' के रूप में पेश किया। उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स की समाप्ति जैसी वामपंथी नीतियां लागू कीं। इससे उन्हें जनता के बीच एक प्रगतिशील नेता की छवि मिली, जबकि उनके विरोधियों को पुरातनपंथी और गरीब-विरोधी साबित करने में मदद मिली।

109. (C) उन्होंने औपचारिक तौर पर स्वीकृति दी, लेकिन मन में गहरे संदेह थे।
1967 के दस-सूत्री कार्यक्रम के प्रति सिंडिकेट के नेताओं का रुख दिखावटी था। उन्होंने जनता के सामने पार्टी की एकता दिखाने के लिए इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार तो कर लिया, लेकिन वे इंदिरा गाँधी के इस झुकाव को पसंद नहीं कर रहे थे। उन्हें संदेह था कि ये नीतियां पार्टी के पुराने संतुलन को बिगाड़ देंगी। उनकी यह आंतरिक असहमति बाद में खुलकर सामने आई और पार्टी के ऐतिहासिक विभाजन का कारण बनी।

110. (D) 1971
प्रिवी पर्स को समाप्त करने की कानूनी लड़ाई काफी लंबी चली। हालाँकि इंदिरा गाँधी ने इसकी घोषणा पहले ही कर दी थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय और राज्यसभा में उन्हें रुकावटों का सामना करना पड़ा। 1971 के लोकसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद उन्होंने इसे अपनी प्राथमिकता बनाया। अंततः 1971 में संविधान में आवश्यक संशोधन करके पूर्व राजाओं को मिलने वाले विशेष भत्तों और विशेषाधिकारों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया।

111. (A) उनकी लोकप्रियता में चार चाँद लग गए और विपक्ष ने भी उनके राज्यकौशल की प्रशंसा की।
1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की सैन्य विजय इंदिरा गाँधी के राजनीतिक जीवन का स्वर्णिम क्षण था। एक नए राष्ट्र, बांग्लादेश के निर्माण ने उन्हें एक महान रणनीतिकार और साहसी वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया। विपक्षी नेताओं ने भी संसद में उनकी सराहना की। इस विजय के बाद वे अजेय मानी जाने लगीं, जिससे आने वाले राज्य विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई।

112. (B) नेविल मैक्सवेल
साठ के दशक में भारत की आंतरिक कलह और अस्थिरता को देखकर कई अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक सशंकित थे। प्रसिद्ध पत्रकार नेविल मैक्सवेल ने 'इंडियाज डिसइंटीग्रेटिंग डेमोक्रेसी' नामक लेख में यह भविष्यवाणी की थी कि भारत में लोकतंत्र का प्रयोग विफल हो रहा है। उनका तर्क था कि देश की विविधता और गरीबी के बोझ तले लोकतांत्रिक संस्थाएं ढह जाएंगी। हालाँकि, भारत के मतदाताओं और संस्थाओं ने बाद में इन आशंकाओं को गलत साबित कर दिया।

113. (A) 2, 1, 3, 4
इंदिरा गाँधी का सत्ता के शीर्ष तक पहुँचने का सफर क्रमबद्ध रहा। वे सबसे पहले 1959 में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनीं। इसके बाद उन्होंने शास्त्री मंत्रिमंडल में सूचना मंत्री के रूप में कार्य किया। 1966 में शास्त्री जी के निधन के बाद वे पहली बार देश की प्रधानमंत्री बनीं। अंत में, 1967 के आम चुनावों में उन्होंने पहली बार एक जननेता के रूप में पार्टी का चुनावी नेतृत्व किया और अपनी साख स्थापित की।

114. (D) 1, 2, 3 और 4 सभी
1967 के चुनाव परिणामों ने भारतीय लोकतंत्र में गहरा बदलाव लाया। पहली बार यह संदेश गया कि कांग्रेस को चुनाव में हराया जा सकता है, जिससे मतदाताओं का भय समाप्त हुआ। राज्यों में गठबंधन सरकारों के गठन ने बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की। साथ ही, विधायकों के दल-बदल की प्रवृत्ति बढ़ी और कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर आपसी कलह तेज हो गई। इन घटनाओं ने भारतीय राजनीति के एकाधिकार वाले दौर को समाप्त कर दिया।

115. (C) राममनोहर लोहिया
कर्पूरी ठाकुर बिहार के एक अत्यंत सादगी पसंद और प्रभावशाली नेता थे। वे समाजवादी विचारधारा से गहरे जुड़े थे और राममनोहर लोहिया को अपना आदर्श मानते थे। लोहिया की तरह ही उन्होंने पिछड़े वर्गों के सामाजिक और राजनीतिक उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू करने का उनका साहसिक निर्णय लोहिया के सामाजिक न्याय के सिद्धांतों की ही एक महत्वपूर्ण कड़ी थी।

116. (D) उनके पास 'इंदिरा हटाओ' के नारे के अलावा किसी सुसंगत, सकारात्मक कार्यक्रम का अभाव था।
1971 में 'ग्रैंड अलायंस' की विफलता का मुख्य कारण उनकी नकारात्मक राजनीति थी। विपक्षी दलों के पास देश के विकास या गरीबी उन्मूलन के लिए कोई ठोस योजना नहीं थी। उनका पूरा प्रचार केवल इंदिरा गाँधी के विरोध पर केंद्रित था। इसके विपरीत, इंदिरा गाँधी ने "गरीबी हटाओ" का एक सकारात्मक और भावनात्मक नारा दिया, जिससे आम जनता उनसे जुड़ गई। जनता ने केवल विरोध की राजनीति के बजाय एक निर्माणकारी विज़न को चुनना बेहतर समझा।

117. (D) 1, 2, 3, 4 और 5 सभी
1971 की जीत इंदिरा गाँधी के लिए एक पूर्ण राजनीतिक विजय थी। इस चुनाव ने निर्विवाद रूप से सिद्ध किया कि जनता के लिए उनकी कांग्रेस ही असली कांग्रेस है। इसने पार्टी के वर्चस्व को पुनः स्थापित किया और सिंडिकेट जैसे प्रभावशाली पुराने गुटों को इतिहास का हिस्सा बना दिया। इस जीत ने यह भी दिखाया कि एक सकारात्मक नारा नकारात्मक विरोध पर भारी पड़ता है और भारतीय राजनीति में अब एक ही शक्ति केंद्र है।

1. इंदिरा गाँधी के खिलाफ याचिकाकर्ता
2. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
3. आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति
4. 1973 में नियुक्त मुख्य न्यायाधीश

(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-1, R-4, S-3
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

19. 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में सरकार ने किस परिपाटी की अनदेखी की?
(A) सबसे युवा न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाने की
(B) राष्ट्रपति की पसंद के व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बनाने की
(C) सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाने की
(D) प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी भी न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाने की

20. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गाँधी के निर्वाचन को अवैध करार दिया।
2. यह फैसला राजनारायण द्वारा दायर एक चुनाव याचिका पर सुनाया गया था।
3. याचिका में तर्क दिया गया था कि इंदिरा गाँधी ने चुनाव-प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया था।
4. इस फैसले के बाद इंदिरा गाँधी तुरंत प्रधानमंत्री पद से हट गईं।

निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 4
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) सभी 1, 2, 3 और 4

21. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय ने 24 जून 1975 को क्या आंशिक स्थगनादेश सुनाया?
(A) इंदिरा गाँधी सांसद नहीं बनी रहेंगी लेकिन प्रधानमंत्री रह सकती हैं।
(B) इंदिरा को तुरंत इस्तीफा देना होगा।
(C) इंदिरा गाँधी सांसद बनी रहेंगी, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती हैं।
(D) उच्च न्यायालय के फैसले को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया।

22. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है।
अभिकथन (A): 25 जून 1975 को सरकार ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी।
कारण (R): सरकार का निर्णय था कि जयप्रकाश नारायण के राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह के आह्वान से देश में एक गंभीर संकट की घड़ी आन पड़ी है।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

23. 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली के रामलीला मैदान में सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से क्या आह्वान किया?
(A) सरकार का पूर्ण समर्थन करने का।
(B) तत्काल अपने पदों से इस्तीफा देने का।
(C) शांतिपूर्ण ढंग से अपना काम करते रहने का।
(D) सरकार के अनैतिक और अवैधानिक आदेशों का पालन न करने का।

24. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 1975 में आपातकाल लागू किया गया था?
(A) अनुच्छेद 352
(B) अनुच्छेद 356
(C) अनुच्छेद 360
(D) अनुच्छेद 370

25. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन की पहचान करें।
(A) आपातकाल की घोषणा के साथ, सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती हैं।
(B) 25 जून 1975 की रात को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की।
(C) आपातकाल में सरकार मौलिक अधिकारों पर रोक नहीं लगा सकती।
(D) आपातकाल की घोषणा के बाद विपक्षी नेताओं की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हुई।

26. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. आपातकाल की घोषणा के बाद, सरकार ने प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी।
2. समाचारपत्रों को कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेना आवश्यक था, जिसे प्रेस सेंसरशिप कहा गया।
3. सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया।
4. धरना, प्रदर्शन और हड़ताल की अनुमति थी।
5. नागरिकों के मौलिक अधिकार अप्रभावित रहे।

निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 3, 4 और 5
(C) केवल 1, 4 और 5
(D) सभी 1, 2, 3, 4 और 5

27. 'निवारक नज़रबंदी' का क्या अर्थ है?

(D) देश में पिछड़ी जातियों की सामाजिक स्थिति का अध्ययन हेतु

48. 1977-79 के चुनावों से लोकतांत्रिक राजनीति ने क्या सबक सीखा?
(A) गठबंधन सरकारें सदैव अपने लक्ष्यों में सफल होती हैं।
(B) यदि सरकार अस्थिर हो और उसके भीतर कलह हो, तो मतदाता उसे कड़ा दंड देते हैं।
(C) एक-दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था ही लोकतंत्र हेतु श्रेष्ठ है।
(D) मतदाताओं को सरकार की राजनीतिक स्थिरता से कोई फर्क नहीं पड़ता।

49. 1969 के बाद कांग्रेस पार्टी के स्वभाव में क्या बदलाव आया?
(A) पार्टी अधिक समावेशी और सबको समेटकर चलने वाली संस्था बन गई।
(B) पार्टी ने स्वयं को एक विशेष विचारधारा से जोड़ा और एक नेता की लोकप्रियता पर निर्भर हो गई।
(C) पार्टी का भविष्य में कोई निश्चित नेता या विचारधारा शेष नहीं रही।
(D) पार्टी ने सक्रिय रूप से क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करना आरंभ किया।

50. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 1970 के दशक की राजनीति के बारे में सही नहीं है?
(A) 1977 के चुनावों में पिछड़े वर्गों के मतदान का कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
(B) कांग्रेस ने स्वयं को एकमात्र समाजवादी और गरीबों की हिमायती पार्टी के रूप में प्रस्तुत किया।
(C) विपक्षी दलों ने 'गैर-कांग्रेसवाद' की राजनीति अपनाई।
(D) विपक्षी नेताओं को यह महसूस हुआ कि गैर-कांग्रेसी वोट बिखरने नहीं चाहिए।

51. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. 1977 के लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर भारत के कई राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें बनीं।
2. इन सरकारों के बनने में पिछड़ी जाति के नेताओं ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
3. केंद्र की जनता पार्टी की सरकार ने मंडल आयोग नियुक्त किया।
4. मंडल आयोग का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों की स्थिति की जांच करना था।
5. बिहार में 'अन्य पिछड़ी जातियों' के आरक्षण के सवाल पर कोई विवाद नहीं हुआ।

निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 3, 4 और 5
(C) केवल 1, 4 और 5
(D) सभी 1, 2, 3, 4 और 5

52. आपातकाल की अवधि को 'संवैधानिक संकट' की अवधि क्यों कहा जा सकता है?
(A) क्योंकि देश की सीमाओं पर भारी आर्थिक मंदी विद्यमान थी।
(B) क्योंकि पड़ोसी देशों से निरंतर युद्ध का खतरा बना था।
(C) क्योंकि देश में कोई भी विधिवत निर्वाचित सरकार नहीं थी।
(D) क्योंकि संसद और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को लेकर एक संवैधानिक संघर्ष छिड़ा हुआ था।

53. 1967 के बाद भारतीय राजनीति में आए बदलावों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है?
(A) इंदिरा गाँधी का एक कद्दावर नेता के रूप में उभरना।
(B) दलगत प्रतिस्पर्धा का अधिक तीखा और ध्रुवीकृत होना।
(C) न्यायपालिका और सरकार के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध।
(D) कांग्रेस की टूट और इंदिरा गाँधी के विरोधियों के बीच मतभेद का गहराना।

54. कांग्रेस पार्टी ने न्यायपालिका पर क्या आरोप लगाया था?
(A) वह सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों का पूर्ण समर्थन कर रही है।
(B) वह एक यथास्थितिवादी संस्था है और गरीबों को लाभ पहुँचाने वाले कार्यक्रमों में रोड़े अटका रही है।
(C) वह देश की एक अत्यंत प्रगतिशील और आधुनिक संस्था है।
(D) वह सदैव संसद की सर्वोच्चता का पूर्णतः सम्मान कर रही है।

55. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है।
अभिकथन (A): 1972-73 के वर्ष में मानसून की असफलता से कृषि की पैदावार में भारी गिरावट आई।
कारण (R): खाद्यान्न उत्पादन में 8 प्रतिशत की कमी ने देश में असंतोष के माहौल को और बढ़ा दिया।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

56. पश्चिम बंगाल में सक्रिय मार्क्सवादी समूहों के खिलाफ राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए?
(A) उन्हें दबाने के लिए कठोर कदम उठाए।
(B) उनसे बातचीत की।
(C) उन्हें स्वायत्तता प्रदान की।
(D) उनकी मांगों को नजरअंदाज कर दिया।

57. गुजरात में 1975 के जून में हुए विधानसभा चुनावों का परिणाम क्या रहा?
(A) कांग्रेस चुनाव जीत गई।

(C) जनता पार्टी
(D) भारतीय लोकदल

38. 'कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी' नामक नई पार्टी का गठन किसने किया था, जो बाद में जनता पार्टी में शामिल हो गई?
(A) मोरारजी देसाई
(B) जगजीवन राम
(C) चरण सिंह
(D) अटल बिहारी वाजपेयी

39. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है।
अभिकथन (A): 1977 के लोकसभा चुनाव में पहली बार कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई।
कारण (R): जनता पार्टी ने चुनाव को आपातकाल के ऊपर जनमत-संग्रह का रूप दिया और जनमत कांग्रेस के विरुद्ध था।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

40. 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलीं?
(A) 154
(B) 330
(C) 295
(D) 35

41. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. 1977 के चुनाव में जनता पार्टी और उसके साथी दलों को 330 सीटें मिलीं।
2. अकेले जनता पार्टी ने 295 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया।
3. उत्तर भारत में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब रहा।
4. इंदिरा गाँधी रायबरेली से और संजय गाँधी अमेठी से चुनाव जीत गए।
5. दक्षिण भारत के राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा।
निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 1, 2, 3 और 5
(C) केवल 3, 4 और 5
(D) सभी 1, 2, 3, 4 और 5

42. 1977 के चुनावों में उत्तर भारत के किन राज्यों में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत सकी?
(A) बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब
(B) महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा
(C) राजस्थान और मध्य प्रदेश
(D) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु

43. 1977 में बनी जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन बने?
(A) चरण सिंह
(B) जगजीवन राम
(C) जयप्रकाश नारायण
(D) मोरारजी देसाई

44. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (नेता)
P. मोरारजी देसाई
Q. चरण सिंह
R. जगजीवन राम
S. जयप्रकाश नारायण
सूची II: (विवरण)
1. भारतीय लोकदल के प्रमुख
2. 'संपूर्ण क्रांति' के प्रणेता
3. 1977 में पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री
4. 'कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी' के संस्थापक
(A) P-3, Q-1, R-4, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-3, R-2, S-1
(D) P-3, Q-2, R-1, S-4

45. मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार कितने समय तक चली?
(A) 4 महीने
(B) पूरे 5 साल
(C) 28 महीने
(D) 18 महीने

46. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. मोरारजी देसाई की सरकार गिरने के बाद चरण सिंह कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने।
2. चरण सिंह की सरकार ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया।
3. 1980 के लोकसभा चुनावों में जनता पार्टी को भारी सफलता मिली।
4. 1980 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 353 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की।
निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 4
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) सभी 1, 2, 3 और 4

47. जनता पार्टी की सरकार द्वारा 1977 में शाह आयोग को क्यों नियुक्त किया गया था?
(A) आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाई तथा सत्ता के दुरुपयोग के विभिन्न आरोपों की जांच के लिए
(B) 1977 के चुनावों में हुई कथित धांधली की जांच हेतु
(C) भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति की विस्तृत समीक्षा हेतु

90. आपातकाल की घोषणा के बाद क्या मंत्रिमंडल से सलाह ली गई थी?
(A) नहीं, मंत्रिमंडल को 26 जून की सुबह केवल सूचना दी गई, जब तक सब कुछ हो चुका था।
(B) हाँ, घोषणा से पहले पूरी चर्चा की गई थी।
(C) हाँ, कुछ चुनिंदा मंत्रियों से सलाह ली गई थी।
(D) नहीं, मंत्रिमंडल से कभी सलाह नहीं ली गई।

91. निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. जयप्रकाश नारायण का 'संपूर्ण क्रांति' का आह्वान
2. इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला
3. रामलीला मैदान में जेपी की रैली और राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा
4. संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा

(A) 1, 2, 3, 4
(B) 2, 1, 3, 4
(C) 1, 3, 2, 4
(D) 2, 3, 1, 4

92. आपातकाल के दौरान प्रतिरोध के रूप में फणीश्वरनाथ 'रेणु' और शिवराम कारंत ने क्या कदम उठाया?
(A) उन्होंने भूमिगत आंदोलन चलाया।
(B) उन्होंने अपनी-अपनी पदवी (पद्मश्री और पद्मभूषण) लौटा दी।
(C) उन्होंने देश छोड़ दिया।
(D) उन्होंने सरकार के पक्ष में लेख लिखे।

93. आपातकाल के सबक के रूप में, बाद में संविधान में आपातकाल की घोषणा के लिए क्या शर्त जोड़ी गई?
(A) राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं।
(B) आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को लिखित में देनी होगी।
(C) केवल सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर आपातकाल लगाया जा सकता है।
(D) लोकसभा और राज्यसभा दोनों में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी।

94. शाह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, आपातकाल के दौरान पुलिस और प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ा?
(A) वे स्वतंत्र होकर काम कर रहे थे।
(B) उन्हें शासक दल ने अपना राजनीतिक औजार बनाकर इस्तेमाल किया।
(C) उन्होंने राजनीतिक दबाव का सफलतापूर्वक सामना किया।
(D) उन्होंने काम करना बंद कर दिया था।

95. 1977 के लोकसभा चुनाव परिणामों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(A) कांग्रेस ने पूरे देश में समान रूप से खराब प्रदर्शन किया।
(B) कांग्रेस उत्तर भारत में पूरी तरह हार गई लेकिन दक्षिण भारत में उसकी स्थिति मजबूत रही।
(C) कांग्रेस दक्षिण भारत में पूरी तरह हार गई लेकिन उत्तर भारत में उसकी स्थिति मजबूत रही।
(D) जनता पार्टी ने पूरे देश में समान रूप से अच्छा प्रदर्शन किया।

96. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. जनता पार्टी की सरकार ने अपना 5 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया।
2. मोरारजी देसाई की सरकार 28 माह में ही अपना बहुमत खो बैठी।
3. चरण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के समर्थन से सरकार बनाई।
4. कांग्रेस ने चरण सिंह सरकार से अपना समर्थन कभी वापस नहीं लिया।
5. जनता पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर कोई विवाद नहीं था।

निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं?
(A) केवल 1, 4 और 5
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1, 3 और 5
(D) केवल 2, 4 और 5

97. 1980 के मध्यावधि चुनावों का प्रमुख कारण क्या था?
(A) कांग्रेस पार्टी में विभाजन।
(B) जनता पार्टी सरकार की अस्थिरता और पतन।
(C) देश में आर्थिक संकट।
(D) एक बाहरी आक्रमण का खतरा।

98. 1977 के बाद भारतीय राजनीति में उभरा एक महत्वपूर्ण सामाजिक-राजनीतिक मुद्दा क्या था?
(A) विदेश नीति का निर्धारण
(B) सूचना प्रौद्योगिकी का विकास
(C) पर्यावरण संरक्षण
(D) पिछड़ी जातियों का आरक्षण और राजनीतिक भूमिका

99. "यह राजनीतिक संकट तत्कालीन संवैधानिक संकट से कहीं ज़्यादा संगीन था।" इस कथन का क्या अभिप्राय है?
(A) कि कानूनी मुद्दे राजनीतिक मुद्दों से अधिक महत्वपूर्ण थे।
(B) कि सत्ताधारी दल द्वारा बहुमत होते हुए भी लोकतंत्र को ठप्प करना एक गहरा राजनीतिक संकट था।
(C) कि संविधान में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं थी।
(D) कि न्यायपालिका और संसद के बीच कोई संघर्ष नहीं था।

100. संसदीय लोकतंत्र में जन आंदोलन की भूमिका और उसकी सीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तनाव सामने आया?
(A) संस्था आधारित लोकतंत्र और जन-भागीदारी पर आधारित लोकतंत्र के बीच तनाव।
(B) राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के बीच तनाव।

(B) चुनाव रद्द कर दिए गए।
(C) कांग्रेस चुनाव हार गई।
(D) किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला।

58. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (नारा/अवधारणा)
P. संपूर्ण क्रांति
Q. इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा
R. लोकतंत्र बचाओ
S. गरीबी हटाओ
सूची II: (स्रोत/प्रवर्तक)
1. 1977 चुनाव में विपक्ष
2. जयप्रकाश नारायण
3. 1971 चुनाव में कांग्रेस
4. डी. के. बरुआ
(A) P-4, Q-3, R-2, S-1
(B) P-2, Q-4, R-1, S-3
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-2, Q-1, R-3, S-4

59. 1975 में जेपी द्वारा किए गए 'sसंसद-मार्च' का क्या महत्व था?
(A) यह देश की राजधानी में अब तक की सबसे छोटी रैली थी।
(B) इस मार्च में केवल कांग्रेसी नेता शामिल हुए।
(C) इस मार्च को सरकार ने तुरंत प्रतिबंधित कर दिया।
(D) यह देश की राजधानी में अब तक की सबसे बड़ी रैलियों में से एक थी।

60. निम्नलिखित में से कौन जयप्रकाश नारायण के जीवन से संबंधित नहीं है?
(A) वे युवावस्था में मार्क्सवादी थे।
(B) वे नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे।
(C) वे 1942 के भारत-छोड़ो आंदोलन के नायक थे।
(D) उन्होंने बिहार आंदोलन का नेतृत्व किया था।

61. निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला
2. इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित करना
3. 42वां संविधान संशोधन पारित होना
4. जनता पार्टी सरकार का गठन
(A) 1, 2, 3, 4
(B) 2, 1, 3, 4
(C) 1, 3, 2, 4
(D) 4, 3, 2, 1

62. न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच तनाव बढ़ाने वाली घटनाओं में से निम्नलिखित में से कौन सी एक नहीं थी?
(A) संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में कटौती करने की शक्ति पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला।
(B) संपत्ति के अधिकार में काट-छाँट करने पर सर्वोच्च न्यायालय का रुख।
(C) 1973 में तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी कर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति।
(D) 1974 की रेल हड़ताल का सरकार द्वारा दमन।

63. 1974 की रेल हड़ताल के संबंध में कौन सा कथन गलत है?
(A) सरकार ने हड़तालियों की सभी मांगें मान लीं।
(B) इसका नेतृत्व जॉर्ज फर्नान्डिस ने किया था।
(C) हड़ताल बोनस और सेवा शर्तों को लेकर थी।
(D) सरकार ने हड़ताल को अवैधानिक करार दिया और कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया।

64. आपातकाल की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को सिफारिश कब भेजी?
(A) 25 जून 1975 की सुबह
(B) 25 जून 1975 की रात
(C) 26 जून 1975 की सुबह
(D) 24 जून 1975 की रात

65. निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आपातकाल की घोषणा के तुरंत बाद नहीं किया गया?
(A) सभी बड़े अखबारों के दफ्तर की बिजली काट दी गई।
(B) सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को बदल दिया गया।
(C) विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई।
(D) मंत्रिमंडल को एक विशेष बैठक में सूचना दी गई।

66. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. आपातकाल के साथ ही शक्तियों के बंटवारे का संघीय ढांचा व्यावहारिक तौर पर निष्प्रभावी हो जाता है।
2. आपातकाल में सरकार किसी भी मौलिक अधिकार पर रोक नहीं लगा सकती।
3. संविधान में आपातकाल को एक असाधारण स्थिति के रूप में देखा गया है।
4. 25 जून 1975 को आधी रात के बाद सभी बड़े अखबारों के दफ्तर की बिजली काट दी गई।
निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 2, 3 और 4
(C) केवल 1, 3 और 4
(D) सभी 1, 2, 3 और 4

67. आपातकाल के दौरान सरकार ने किन दो सामाजिक और सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था?
(A) भारतीय जनसंघ और सोशलिस्ट पार्टी
(B) भारतीय लोकदल और कांग्रेस (ओ)

(C) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और जमात-ए-इस्लामी
(D) नक्सलवादी समूह और अकाली दल

68. 'प्रेस सेंसरशिप' को धत्ता बताते हुए भूमिगत रूप से क्या प्रकाशित हुए?
(A) सरकारी रिपोर्ट और श्वेत पत्र
(B) आधिकारिक गजट और अधिसूचनाएं
(C) विदेशी समाचार पत्र और पत्रिकाएं
(D) अनेक न्यूज़लेटर और लीफ़लेट्स

69. 42वें संशोधन के माध्यम से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान किया गया?
(A) इनके निर्वाचन को अदालत में चुनौती दी जा सकती थी।
(B) इनके निर्वाचन को केवल उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती थी।
(C) इनके निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी।
(D) इनके निर्वाचन की जांच केवल चुनाव आयोग कर सकता था।

70. आपातकाल के बाद नागरिक अधिकारों की रक्षा में किस संस्था ने सक्रिय भूमिका निभाई?
(A) संसद
(B) अदालतों (न्यायपालिका) ने
(C) चुनाव आयोग
(D) योजना आयोग

71. निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है?
(A) मोरारजी देसाई - 1977-79 के प्रधानमंत्री
(B) चरण सिंह - भारतीय लोकदल के प्रमुख
(C) जयप्रकाश नारायण - बिहार आंदोलन के नेता
(D) जगजीवन राम - 1977 में कांग्रेस के अध्यक्ष

72. आपातकाल के बाद राजनीति के संदर्भ में, 1977 के चुनावों को किसका 'जनमत-संग्रह' माना जा सकता है?
(A) आपातकाल के अनुभवों के बारे में
(B) आर्थिक नीतियों के बारे में
(C) विदेश नीति के बारे में
(D) भाषाई नीति के बारे में

73. 1977 के चुनावों में जनता पार्टी के गठन से गैर-कांग्रेसी वोटों पर क्या प्रभाव पड़ा?
(A) गैर-कांग्रेसी वोट विभिन्न दलों में बंट गए।
(B) अधिकांश गैर-कांग्रेसी मतदाताओं ने मतदान नहीं किया।
(C) यह सुनिश्चित हो गया कि गैर-कांग्रेसी वोट एक ही जगह पड़ेंगे।
(D) गैर-कांग्रेसी वोटों की संख्या घट गई।

74. 1977 के चुनाव परिणामों में उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक स्पष्ट अंतर क्यों दिखाई दिया?
(A) दक्षिण भारत में आपातकाल का प्रभाव हर राज्य पर एकसमान नहीं पड़ा था।
(B) उत्तर भारत में आपातकाल का प्रभाव कम था।
(C) जबरन नसबंदी और विस्थापन जैसे काम दक्षिण भारत में अधिक हुए थे।
(D) दक्षिण भारत में गैर-कांग्रेसी दल अधिक मजबूत थे।

75. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. 1977 में बनी जनता पार्टी की सरकार में कोई खास तालमेल नहीं था।
2. प्रधानमंत्री पद के लिए मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम के बीच होड़ थी।
3. मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन सत्ता की खींचतान खत्म नहीं हुई।
4. जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस द्वारा अपनाई गई नीतियों में बुनियादी बदलाव किए।
5. आपातकाल का विरोध ही जनता पार्टी को लंबे समय तक एकजुट रख सका।

निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 3, 4 और 5
(C) केवल 1, 4 और 5
(D) सभी 1, 2, 3, 4 और 5

76. चरण सिंह की सरकार, जो मोरारजी देसाई के बाद बनी, कितने समय तक सत्ता में रही?
(A) 28 महीने
(B) 4 महीने
(C) 2 साल
(D) 1 साल

77. 1980 के लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या था?
(A) जनता पार्टी ने दोबारा सरकार बनाई।
(B) एक गठबंधन सरकार बनी।
(C) इंदिरा गाँधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने भारी सफलता हासिल की।
(D) किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला।

78. अप्रत्यक्ष रूप से, 1977 के बाद भारतीय राजनीति पर किस मुद्दे का प्रभाव पड़ना शुरु हुआ?
(A) पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा
(B) परमाणु निरस्त्रीकरण का मुद्दा
(C) शहरीकरण का मुद्दा
(D) पिछड़े वर्गों की भलाई का मुद्दा

79. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है।
अभिकथन (A): आपातकाल और उसके आसपास की अवधि को संवैधानिक और राजनीतिक दोनों संकटों के दौर के रूप में

देखा जा सकता है।
कारण (R): इस दौर में संस्था आधारित लोकतंत्र और स्वतःस्फूर्त जन-भागीदारी पर आधारित लोकतंत्र के बीच तनाव स्पष्ट रूप से नज़र आया।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

80. जनता पार्टी की सरकार द्वारा नियुक्त 'मंडल आयोग' का संबंध किससे था?
(A) आपातकाल की ज्यादतियों की जांच से
(B) पिछड़ी जातियों की राजनीति की भूमिका से
(C) केंद्र-राज्य संबंधों से
(D) आर्थिक सुधारों से

81. 1970 के दशक की शुरुआत में भारत की अर्थव्यवस्था पर बांग्लादेश संकट का क्या प्रभाव पड़ा?
(A) भारत को अमेरिका से अधिक आर्थिक सहायता मिली।
(B) लगभग 80 लाख शरणार्थी भारत आए, जिससे अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ा।
(C) भारत का औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा।
(D) भारत की मुद्रा का मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ गया।

82. 1973-74 में तेल की कीमतों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में हुई बढ़ोतरी का भारत पर क्या तात्कालिक प्रभाव पड़ा?
(A) तेल का आयात बंद हो गया।
(B) सरकार ने पेट्रोल पर सब्सिडी दी।
(C) देश में तेल का उत्पादन बढ़ गया।
(D) विभिन्न चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ीं।

83. 1972-73 के वर्ष में सरकारी कर्मचारियों में असंतोष का मुख्य कारण क्या था?
(A) काम के घंटे बढ़ा दिए गए थे।
(B) उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा रहा था।
(C) छुट्टियों की संख्या कम कर दी गई थी।
(D) सरकार ने खर्चे को कम करने के लिए उनके वेतन को रोक लिया था।

84. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (घटना/संकट)
P. बांग्लादेश संकट
Q. 1974 में मूल्य वृद्धि
R. 1972-73 में मानसून की असफलता
S. अंतर्राष्ट्रीय तेल संकट
सूची II: (प्रभाव/आंकड़ा)
1. 30% का इजाफा
2. खाद्यान्न उत्पादन में 8% की कमी
3. 80 लाख शरणार्थी भारत आए
4. विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में भारी बढ़ोतरी
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-1, R-2, S-4
(C) P-2, Q-3, R-4, S-1
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

85. मोरारजी देसाई ने गुजरात में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने की धमकी क्यों दी थी?
(A) राज्य में भ्रष्टाचार खत्म करने की मांग को लेकर।
(B) खाद्य तेल की कीमतें कम करने की मांग को लेकर।
(C) राष्ट्रपति शासन हटाने की मांग को लेकर।
(D) राज्य में नए सिरे से चुनाव नहीं करवाए जाने की स्थिति में।

86. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. जयप्रकाश नारायण सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे और सामाजिक कार्यों में लगे थे।
2. बिहार के छात्रों ने उन्हें अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए आमंत्रित किया।
3. जेपी ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की।
4. जेपी ने केवल राजनीतिक सुधारों का आह्वान किया।
उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 4
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) सभी 1, 2, 3 और 4

87. 1974 की रेल हड़ताल का मुख्य उद्देश्य क्या था?
(A) रेलवे का निजीकरण करना।
(B) रेल मंत्री का इस्तीफा मांगना।
(C) रेल यात्रा को मुफ्त करना।
(D) बोनस और सेवा से जुड़ी शर्तों के संबंध में अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाना।

88. 1973 में न्यायमूर्ति ए.एन. रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करना विवादास्पद क्यों हो गया था?
(A) क्योंकि सरकार ने तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अनदेखी की थी।
(B) क्योंकि वे सबसे कनिष्ठ न्यायाधीश थे।
(C) क्योंकि उन्होंने सरकार के पक्ष में फैसला दिया था।
(D) क्योंकि उनकी नियुक्ति का विपक्ष ने समर्थन किया था।

89. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गाँधी के निर्वाचन को किस आधार पर अवैध करार दिया था?
(A) उन्होंने मतदाता को रिश्वत दी थी।
(B) उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया था।
(C) उनके चुनावी खर्च की सीमा निर्धारित सीमा से अधिक थी।
(D) उन्होंने चुनाव-प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया था।

(A) किसी व्यक्ति को अपराध करने के बाद गिरफ्तार करना।
(B) किसी व्यक्ति को अदालत के आदेश पर रिहा करना।
(C) किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए अस्थायी रूप से हिरासत में लेना।
(D) किसी व्यक्ति को इस आशंका से गिरफ्तार करना कि वह कोई अपराध कर सकता है।

28. आपातकाल के दौरान अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए नागरिक किस याचिका का सहारा नहीं ले सकते थे?
(A) परमादेश
(B) बंदी प्रत्यक्षीकरण
(C) अधिकार-पृच्छा
(D) उत्प्रेषण

29. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (अवधारणा/घटना)
P. निवारक नज़रबंदी का प्रयोग
Q. प्रेस सेंसरशिप का विरोध
R. पदवी लौटाना
S. 42वाँ संवैधानिक संशोधन
सूची II: (उदाहरण/परिणाम)
1. इंडियन एक्सप्रेस द्वारा खाली जगह छोड़ना
2. फणीश्वरनाथ 'रेणु'
3. आपातकाल के दौरान बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ
4. विधायिका का कार्यकाल 5 से 6 साल करना
(A) P-3, Q-1, R-2, S-4
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

30. अप्रैल 1976 में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के संबंध में क्या फैसला सुनाया?
(A) आपातकाल के दौरान भी अदालत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार कर सकती है।
(B) केवल उच्च न्यायालय ही ऐसी याचिकाओं पर विचार कर सकते हैं।
(C) निवारक नज़रबंदी को असंवैधानिक घोषित कर दिया।
(D) सरकार आपातकाल के दौरान नागरिक से जीवन और आज़ादी का अधिकार वापस ले सकती है।

31. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. 'इंडियन एक्सप्रेस' और 'स्टेट्समैन' अखबारों ने सेंसरशिप का समर्थन किया।
2. 'सेमिनार' और 'मेनस्ट्रीम' जैसी पत्रिकाओं ने सेंसरशिप के आगे घुटने टेकने की जगह बंद होना मुनासिब समझा।
3. कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत ने पद्मभूषण लौटा दिया।
4. हिंदी लेखक फणीश्वरनाथ 'रेणु' ने पद्मश्री लौटा दिया।
निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2, 3 और 4
(C) केवल 1, 3 और 4
(D) सभी 1, 2, 3 और 4

32. आपातकाल के दौरान पारित 42वें संविधान संशोधन का एक प्रमुख प्रावधान क्या था?
(A) देश की विधायिका के कार्यकाल को 6 से घटाकर 5 साल करना।
(B) देश की विधायिका के कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर 6 साल करना।
(C) मौलिक अधिकारों को समाप्त करना।
(D) न्यायपालिका की शक्तियों में वृद्धि करना।

33. आपातकाल से सीखा गया एक प्रमुख सबक क्या है?
(A) भारत में लोकतंत्र को आसानी से समाप्त किया जा सकता है।
(B) भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन है।
(C) भारत की न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली है।
(D) भारत में एक दलीय प्रणाली सबसे उपयुक्त है।

34. आपातकाल के बाद, संविधान में 'अंदरुनी आपातकाल' के प्रावधान में क्या सुधार किया गया?
(A) 'अंदरुनी आपातकाल' अब केवल 'सशस्त्र विद्रोह' की स्थिति में लगाया जा सकता है।
(B) 'अंदरुनी आपातकाल' अब केवल 'वित्तीय संकट' की स्थिति में लगाया जा सकता है।
(C) 'अंदरुनी आपातकाल' लगाने के लिए मंत्रिमंडल की सलाह आवश्यक नहीं है।
(D) 'अंदरुनी आपातकाल' अब प्रधानमंत्री अपने विवेक से लगा सकते हैं।

35. घटनाओं को उनके घटित होने के क्रम में व्यवस्थित करें:
1. शाह आयोग की नियुक्ति
2. आपातकाल की समाप्ति और लोकसभा चुनावों की घोषणा
3. जनता पार्टी सरकार का गठन
4. मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने
(A) 2, 3, 4, 1
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 4, 3, 1
(D) 3, 4, 1, 2

36. 1977 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने किस नारे पर चुनाव लड़ा?
(A) 'गरीबी हटाओ'
(B) 'संपूर्ण क्रांति'
(C) 'जय जवान, जय किसान'
(D) 'लोकतंत्र बचाओ'

37. 1977 के चुनावों से ठीक पहले विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर कौन सा नया दल बनाया?
(A) कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी
(B) सोशलिस्ट पार्टी

(C) केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच तनाव।
(D) ग्रामीण और शहरी आंदोलनों के बीच तनाव।

101. 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाली सरकार का तर्क क्या था?
(A) देश में व्याप्त अत्यंत गंभीर आर्थिक संकट की स्थिति थी।
(B) देश में गंभीर संकट की घड़ी आन पड़ी है और गड़बड़ी की आशंका है।
(C) विपक्षी दलों द्वारा देशव्यापी नए चुनाव की मांग की गई।
(D) न्यायपालिका द्वारा सरकार के नीतिगत कार्यों में निरंतर हस्तक्षेप।

102. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (अवधि/वर्ष)
P. 1973
Q. 1974
R. 1975
S. 1977
सूची II: (घटना)
1. राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा
2. लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार
3. केशवानंद भारती मामले में फैसला
4. रेल हड़ताल
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

103. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है।
अभिकथन (A): 1977 के चुनाव के बाद मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी जनता पार्टी की सरकार 28 महीने में ही गिर गई।
कारण (R): जनता पार्टी के पास किसी दिशा, नेतृत्व अथवा एक साझे कार्यक्रम का अभाव था और उसके भीतर सत्ता की भारी खींचतान थी।
(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

104. 1974 के जनवरी माह में गुजरात के छात्रों ने किस मुद्दे पर आंदोलन छेड़ा था?
(A) विश्वविद्यालय की फीस में वृद्धि
(B) शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितता
(C) परीक्षा प्रणाली में सुधार
(D) खाद्यान्न, खाद्य तेल की बढ़ती कीमत और भ्रष्टाचार

105. "सच्चे लोकतंत्र की स्थापना" के उद्देश्य से 'संपूर्ण क्रांति' का आह्वान किसने किया?
(A) जयप्रकाश नारायण
(B) मोरारजी देसाई
(C) इंदिरा गाँधी
(D) जॉर्ज फर्नान्डिस

106. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. 1970 के दशक की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी हुई।
2. इसके परिणामस्वरूप भारत में विभिन्न चीजों की कीमतें भी तेजी से बढ़ीं।
3. युद्ध के बाद अमरीका ने भारत को हर तरह की सहायता देना बंद कर दिया।
4. इस अवधि में भारत का औद्योगिक विकास बहुत तेज था।
उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 4
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) सभी 1, 2, 3 और 4

107. 'प्रतिबद्ध नौकरशाही' की अवधारणा का क्या अर्थ है?
(A) नौकरशाही का देश के मूल संविधान के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध होना।
(B) नौकरशाही का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता के प्रति जवाबदेह होना।
(C) नौकरशाही का शासक दल की विचारधारा के अनुकूल आचरण करना।
(D) नौकरशाही का राजनीतिक निर्णयों से पूरी तरह से अराजनीतिक होना।

108. 1975 के 'संसद-मार्च' का नेतृत्व किसने किया था?
(A) जयप्रकाश नारायण
(B) मोरारजी देसाई
(C) अटल बिहारी वाजपेयी
(D) जॉर्ज फर्नान्डिस

109. आपातकाल के दौरान हुए संशोधनों के संदर्भ में, किस संशोधन को 'लघु-संविधान' भी कहा जाता है?
(A) 44वां संशोधन
(B) 24वां संशोधन
(C) 39वां संशोधन
(D) 42वां संशोधन

110. 1977 में, आपातकाल समाप्त होने के बाद, अदालतों ने किस विषय पर सक्रिय भूमिका निभाई?
(A) सरकार के आर्थिक निर्णयों की समीक्षा में।
(B) व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में।
(C) केंद्र-राज्य विवादों के निपटारे में।
(D) विदेशी संधियों को मंजूरी देने में।

111. निम्नलिखित में से कौन 1977 में जनता पार्टी सरकार में प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं थे?
(A) मोरारजी देसाई
(B) चरण सिंह
(C) जगजीवन राम
(D) जयप्रकाश नारायण

112. 1977 के चुनावों में इंदिरा गाँधी किस लोकसभा सीट से चुनाव हार गईं?
(A) रायबरेली
(B) अमेठी
(C) मेडक
(D) इलाहाबाद

113. घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है?
1. जनता पार्टी का गठन
2. आपातकाल की घोषणा
3. मोरारजी देसाई सरकार का पतन
4. 1980 के मध्यावधि चुनाव
(A) 2, 1, 3, 4
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 3, 1, 4
(D) 1, 3, 2, 4

114. आपातकाल की घोषणा के पीछे का एक तात्कालिक राजनीतिक कारण क्या था?
(A) 1974 की रेल हड़ताल।
(B) गुजरात और बिहार में छात्र आंदोलन।
(C) इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला और उसके बाद की राजनीतिक घटनाएं।
(D) नक्सलवादी आंदोलन का प्रसार।

115. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया।
2. 1971-72 के बाद देश की आर्थिक दशा में कोई खास सुधार नहीं हुआ।
3. बांग्लादेश संकट से भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई बोझ नहीं पड़ा।
4. 1973 में महंगाई 23% और 1974 में 30% तक बढ़ गई।
5. इस दौरान औद्योगिक विकास की दर बहुत तेज थी।
उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 4
(B) केवल 3, 4 और 5
(C) केवल 1, 3 और 5
(D) सभी 1, 2, 3, 4 और 5

116. आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे?
(A) वी.वी. गिरि
(B) ज़ैल सिंह
(C) नीलम संजीव रेड्डी
(D) फखरुद्दीन अली अहमद

117. 1977 में कांग्रेस पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण क्या था?
(A) पार्टी के भीतर गुटबाजी
(B) खराब आर्थिक नीतियां
(C) आपातकाल का लगाया जाना और उसके दौरान हुई ज्यादतियां
(D) एक मजबूत विपक्ष का अभाव

118. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है।
अभिकथन (A): आपातकाल के बाद, संविधान में संशोधन करके 'आंतरिक गड़बड़ी' शब्द को 'सशस्त्र विद्रोह' से बदल दिया गया।
कारण (R): 'आंतरिक गड़बड़ी' शब्द की परिभाषा बहुत अस्पष्ट थी और इसका दुरुपयोग हो सकता था।
(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

119. 1969 के बाद कांग्रेस की राजनीति किस एक leader के इर्द-गिर्द केंद्रित हो गई?
(A) मोरारजी देसाई
(B) इंदिरा गाँधी
(C) जगजीवन राम
(D) के. कामराज

120. निम्नलिखित में से कौन सा दल 1977 में जनता पार्टी का घटक नहीं था?
(A) भारतीय जनसंघ
(B) कांग्रेस (ओ)
(C) सोशलिस्ट पार्टी
(D) कांग्रेस (आई)

121. 1977 के चुनाव परिणामों ने भारत की दलीय व्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला?
(A) इसने एक-दलीय प्रभुत्व को और मजबूत किया।
(B) इसने पहली बार केंद्र में एक गैर-कांग्रेसी सरकार का मार्ग प्रशस्त किया।
(C) इसने क्षेत्रीय दलों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया।
(D) इससे दलीय व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया।

122. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (व्यक्ति)
P. राजनारायण
Q. डी. के. बरुआ
R. जगजीवन राम
S. चौधरी चरण सिंह

सूची II: (भूमिका/पार्टी)
1. 1974 में कांग्रेस अध्यक्ष
2. समाजवादी नेता और याचिकाकर्ता
3. भारतीय क्रांति दल/लोकदल के संस्थापक
4. कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-2, Q-1, R-4, S-3
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

123. 'गैर-कांग्रेसवाद' की राजनीति का मुख्य उद्देश्य क्या था?
(A) कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना।
(B) चुनावों में गैर-कांग्रेसी वोटों को बिखरने से रोकना और कांग्रेस को हराना।
(C) कांग्रेस की नीतियों का आँख बंद करके समर्थन करना।
(D) कांग्रेस में शामिल होना।

124. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. 1975 के आपातकाल की घोषणा 'बाहरी आक्रमण' के कारण की गई थी।
2. आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गए थे।
3. शाह आयोग का गठन कांग्रेस सरकार ने किया था।
4. 42वें संविधान संशोधन ने लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया था।

उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2 और 4
(C) केवल 1, 2 और 4
(D) केवल 2, 3 और 4

125. 1977 के चुनाव में जनता पार्टी को दक्षिण भारत में उत्तर भारत जैसी सफलता क्यों नहीं मिली?
(A) क्योंकि दक्षिण में आपातकाल का असर और ज्यादतियां कम थीं।
(B) क्योंकि दक्षिण में विपक्षी दल कमजोर थे।
(C) क्योंकि दक्षिण के मतदाता कांग्रेस की नीतियों से बहुत खुश थे।
(D) क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने दक्षिण भारत में प्रचार नहीं किया।

126. भारतीय संविधान के निर्माताओं को यह विश्वास था कि आपातकाल की स्थिति में भी सरकार अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किस सीमा में रहकर करेगी?
(A) अपने राजनीतिक हितों के दायरे में।
(B) संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के दायरे में।
(C) विधि के शासन (Rule of Law) के दायरे में।
(D) संसद के निर्देशों के दायरे में।

127. आपातकाल के समय 'भूमिगत' होकर सरकार के खिलाफ मुहिम चलाने वाले कौन थे?
(A) जो राजनीतिक कार्यकर्ता गिरफ्तारी से बच गए थे।
(B) जो सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर थे।
(C) जो लेखक और कलाकार थे।
(D) जो व्यापारी और उद्योगपति थे।

128. मोरारजी देसाई की सरकार गिरने के बाद किसने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई और वे कितने दिन प्रधानमंत्री रहे?
(A) जगजीवन राम, 6 महीने
(B) चरण सिंह, 4 महीने
(C) अटल बिहारी वाजपेयी, 13 दिन
(D) चंद्रशेखर, 1 साल

129. "इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा" यह नारा किसने दिया था?
(A) इंदिरा गाँधी
(B) संजय गाँधी
(C) डी. के. बरुआ
(D) फखरुद्दीन अली अहमद

130. 1975 के संकट के दौरान कौन सा एक महत्वपूर्ण मसला संसदीय लोकतंत्र में जन आंदोलन की भूमिका और उसकी सीमा को लेकर उठा?
(A) क्या जन आंदोलनों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर देना चाहिए?
(B) क्या जन आंदोलन केवल चुनावों के दौरान होने चाहिए?
(C) संस्था आधारित लोकतंत्र और जन-भागीदारी के बीच तनाव का मसला।
(D) क्या जन आंदोलन केवल शहरों तक सीमित होने चाहिए?

131. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है।
अभिकथन (A): 1980 के मध्यावधि चुनावों में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत मिला।
कारण (R): मतदाताओं ने जनता पार्टी की अस्थिर और कलहपूर्ण सरकार को दंडित किया।
(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

132. 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' (Habeas Corpus) याचिका का मौलिक उद्देश्य क्या है?
(A) किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत के खिलाफ अदालत में चुनौती देने का अधिकार।
(B) सरकार को किसी सार्वजनिक कर्तव्य को करने का आदेश देना।
(C) किसी पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करना।

(D) निचली अदालत के फैसले को रद्द करना।

133. 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने बिहार के 'अन्य पिछड़ी जातियों' के मुद्दे पर विचार करने के लिए किस आयोग की नियुक्ति की?
(A) शाह आयोग
(B) सरकारिया आयोग
(C) मंडल आयोग
(D) कोठारी आयोग

134. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. जयप्रकाश नारायण ने 1955 के बाद सक्रिय राजनीति छोड़ दी थी।
2. वे गांधीवादी बनने के बाद भूदान आंदोलन में सक्रिय हुए।
3. उन्होंने चंबल के डकैतों से आत्मसमर्पण कराया था।
4. वे कभी भी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं रहे।
5. वे आपातकाल के विरोध के प्रतीक बन गए थे।

उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1, 2, 3 और 5
(B) केवल 2, 3 और 4
(C) केवल 1, 4 और 5
(D) सभी 1, 2, 3, 4 और 5

135. केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित 'बुनियादी ढाँचे' के सिद्धांत का क्या अर्थ है?
(A) संविधान में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता।
(B) संसद संविधान के कुछ मूलभूत सिद्धांतों में संशोधन नहीं कर सकती।
(C) केवल न्यायपालिका ही संविधान में संशोधन कर सकती है।
(D) राष्ट्रपति संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकते हैं।

136. 1970 के दशक की शुरुआत में भारत की आर्थिक कठिनाइयों का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था?
(A) पाकिस्तान से युद्ध
(B) अमेरिकी सहायता का बंद होना
(C) खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि
(D) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में वृद्धि

137. 1977 के चुनावों में कांग्रेस की हार और जनता पार्टी की जीत के बाद केंद्र में बनी सरकार के बारे में कौन सा तथ्य सही है?
(A) यह भारत की पहली गठबंधन सरकार थी।
(B) यह भारत की पहली गैर-कांग्रेसी सरकार थी।
(C) यह एक वामपंथी दलों की सरकार थी।
(D) यह एक-दलीय बहुमत वाली स्थिर सरकार थी।

138. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (वर्ष)
P. 1971
Q. 1974
R. 1975
S. 1977

सूची II: (घटना/नारा)
1. बिहार आंदोलन की शुरुआत
2. 'गरीबी हटाओ' का नारा
3. जनता पार्टी का गठन
4. आपातकाल की घोषणा

(A) P-2, Q-1, R-4, S-3
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-3, R-2, S-1
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

139. 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई रैली का तात्कालिक परिणाम क्या था?
(A) सरकार ने विपक्ष से बातचीत शुरु की।
(B) इंदिरा गांधी ने इस्तीफे की घोषणा की।
(C) सरकार ने उसी रात आपातकाल की घोषणा कर दी।
(D) सर्वोच्च न्यायालय ने रैली को अवैध घोषित कर दिया।

140. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. आपातकाल के दौरान 'इंडियन एक्सप्रेस' और 'स्टेट्समैन' जैसे अखबारों ने सेंसरशिप का विरोध करते हुए खाली जगह छोड़ी।
2. 'सेमिनार' और 'मेनस्ट्रीम' जैसी पत्रिकाओं ने सेंसरशिप के विरोध में अपना प्रकाशन बंद कर दिया।
3. कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत ने अपना पद्मभूषण पुरस्कार लौटा दिया।
4. हिंदी लेखक फणीश्वरनाथ 'रेणु' ने अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटा दिया।

निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3 और 4
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) सभी 1, 2, 3 और 4

141. आपातकाल के संदर्भ में, भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक परिणाम क्या था?
(A) नागरिक अधिकारों के प्रति लोगों और अदालतों में बढ़ी हुई जागरूकता।
(B) एक-दलीय प्रणाली की स्थापना।
(C) राजनीतिक आंदोलनों पर स्थायी प्रतिबंध।
(D) प्रेस पर सरकारी नियंत्रण का बढ़ना।

142. जनता पार्टी की सरकार क्यों बिखर गई?
(A) नेतृत्व, दिशा और साझे कार्यक्रम के अभाव तथा आंतरिक कलह के कारण।
(B) अविश्वास प्रस्ताव के कारण।
(C) देश में व्याप्त गंभीर आर्थिक और सामाजिक संकट की स्थिति के कारण।
(D) सरकार के कामकाज में विदेशी शक्तियों के अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण।

143. 1977 के चुनावों में संजय गाँधी किस निर्वाचन क्षेत्र से हारे थे?
(A) रायबरेली
(B) इलाहाबाद
(C) अमेठी
(D) पीलीभीत

144. निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल का परिणाम नहीं था?
(A) अनेक विपक्षी नेताओं की जेल में डाल दिया गया।
(B) प्रेस की आजादी पर रोक लगा दी गई।
(C) नागरिकों के मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गए।
(D) न्यायपालिका की शक्तियों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई।

145. 1970 के दशक की शुरुआत में गैर-कांग्रेसी पार्टियों ने जन-विरोध की अगुवाई क्यों की?
(A) क्योंकि वे सरकार की नीतियों से सहमत थे।
(B) बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली को लेकर पूरे देश में असंतोष का माहौल था।
(C) क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर हो गई थी।
(D) क्योंकि उन्हें विदेशी ताकतों से समर्थन मिल रहा था।

146. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है।
अभिकथन (A): 1977 में बनी जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस द्वारा अपनाई गई नीतियों में कोई बुनियादी बदलाव नहीं किया।
कारण (R): जनता पार्टी विभिन्न विचारधाराओं वाले दलों का एक गठबंधन थी और उसके पास कोई एक साझा कार्यक्रम नहीं था।
(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

147. निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. मोरारजी देसाई का प्रधानमंत्री बनना
2. आपातकाल की घोषणा
3. चरण सिंह का प्रधानमंत्री बनना
4. 1980 के लोकसभा चुनाव

(A) 2, 1, 3, 4
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 3, 1, 4
(D) 1, 3, 2, 4

148. आपातकाल की समाप्ति के बाद, नागरिक अधिकारों की रक्षा में संलग्न संगठनों के संबंध में क्या प्रवृत्ति देखी गई?
(A) ऐसे गैर-सरकारी संगठनों की संख्या में भारी कमी आई।
(B) नागरिक अधिकारों के कई नए संगठन वजूद में आए।
(C) पूर्व में मौजूद सभी संगठन पूर्णतः निष्क्रिय हो गए।
(D) सरकार ने ऐसे सभी संगठनों पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया।

149. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने शाह आयोग को नियुक्त किया।
2. इस आयोग को आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों की जांच करनी थी।
3. आयोग ने पाया कि पुलिस और प्रशासन का राजनीतिक दुरुपयोग हुआ था।
4. आयोग की रिपोर्ट के बाद सभी समस्याओं का समाधान हो गया।
5. आयोग का गठन आपातकाल के दौरान हुआ था।

उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 3, 4 और 5
(C) केवल 1, 4 और 5
(D) सभी 1, 2, 3, 4 और 5

150. दलीय प्रणाली पर आपातकाल का एक महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था?
(A) इसने कांग्रेस पार्टी के भीतर लोकतंत्र को मजबूत किया।
(B) इसने विपक्षी दलों को 'गैर-कांग्रेसवाद' की रणनीति के तहत एकजुट होने के लिए प्रेरित किया।
(C) इसने भारत में दो-दलीय प्रणाली को स्थायी रूप से स्थापित कर दिया।
(D) इसने क्षेत्रीय दलों के उदय को समाप्त कर दिया।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
जयप्रकाश नारायण का 'संपूर्ण क्रांति' का आह्वान 1970 के दशक के मध्य में भारतीय राजनीति का एक निर्णायक मोड़ था, जो केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि व्यवस्था के आमूल-चूल रुपांतरण का उद्देश्य रखता था। यह आंदोलन गुजरात और बिहार में छात्र आंदोलनों से उभरा, जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बढ़ती कीमतों जैसे मुद्दों पर केंद्रित थे। जेपी ने इन आंदोलनों को एक वैचारिक दिशा प्रदान की, इसे केवल सरकार विरोधी प्रदर्शनों से ऊपर उठाकर एक नैतिक और दार्शनिक धर्मयुद्ध में बदल दिया। 'संपूर्ण क्रांति' की अवधारणा सात क्रांतियों - सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक - के संश्लेषण पर आधारित थी। इसका उद्देश्य मौजूदा संसदीय लोकतंत्र की सीमाओं को उजागर करना था, जिसे जेपी दलीय राजनीति और सत्ता के संघर्ष से दूषित मानते थे। उन्होंने 'दलविहीन लोकतंत्र' के विचार का समर्थन किया, जिसमें शक्ति का विकेंद्रीकरण हो और जनता की भागीदारी ज़मीनी स्तर से शुरु हो। उनके अनुसार, राजनीतिक सुधार केवल एक पहलू था; वास्तविक परिवर्तन के लिए समाज के नैतिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को बदलना आवश्यक था। यह आंदोलन इंदिरा गांधी की सरकार के केंद्रीकृत और व्यक्तिवादी नेतृत्व के प्रति एक शक्तिशाली चुनौती के रूप में उभरा, जिसने अंततः उस राजनीतिक टकराव की पृष्ठभूमि तैयार की जिसके कारण

आपातकाल लगाया गया।
उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

151. 'संपूर्ण क्रांति' के आह्वान का मुख्य उद्देश्य क्या था?
(A) केवल इंदिरा गांधी की सरकार को हटाना
(B) व्यवस्था में आमूल-चूल रूपांतरण लाना
(C) राज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता प्राप्त करना
(D) केवल आर्थिक सुधारों को लागू करना

152. जयप्रकाश नारायण ने मौजूदा संसदीय लोकतंत्र की आलोचना क्यों की?
(A) वे इसे दलीय राजनीति और सत्ता संघर्ष से दूषित मानते थे
(B) यह ब्रिटिश मॉडल और वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित था
(C) इसमें राष्ट्रपति के पास असीमित और अनियंत्रित शक्तियाँ थीं
(D) इसमें समाज के अल्पसंख्यकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था

153. स्रोत के अनुसार, 'संपूर्ण क्रांति' की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा एक पहलू शामिल नहीं था?
(A) राजनीतिक क्रांति
(B) आर्थिक क्रांति
(C) सैन्य क्रांति
(D) सांस्कृतिक क्रांति

154. जयप्रकाश नारायण किस प्रकार के लोकतंत्र का समर्थन करते थे?
(A) राष्ट्रपति प्रणाली आधारित लोकतंत्र
(B) दो-दलीय लोकतंत्र
(C) सैन्य शासित लोकतंत्र
(D) दलविहीन, विकेंद्रीकृत लोकतंत्र

155. स्रोत में वर्णित 'संपूर्ण क्रांति' आंदोलन का तात्कालिक परिणाम क्या हुआ?
(A) इससे देश में तुरंत व्यापक आर्थिक समृद्धि और स्थिरता आ गई
(B) देश की दलीय व्यवस्था को पूरी तरह और तुरंत समाप्त कर दिया गया
(C) इसने आपातकाल की ओर जाने वाले राजनीतिक टकराव की नींव रखी
(D) भारत के सभी राज्यों में केवल छात्र सरकारों का गठन किया गया

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
1970 के दशक में भारतीय न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच का टकराव भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण संकट था। यह तनाव मुख्य रूप से संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति, विशेष रूप से मौलिक अधिकारों के संबंध में, को लेकर था। गोलकनाथ मामले (1967) में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि संसद मौलिक अधिकारों को छीन या कम नहीं कर सकती है। इस फैसले को पलटने के लिए, संसद ने 24वां और 25वां संशोधन पारित किया। इस टकराव की पराकाष्ठा 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य' (1973) मामले में हुई, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने 'संविधान के बुनियादी ढांचे' का ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार, संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह इसके 'बुनियादी ढांचे' को नहीं बदल सकती, जिसमें लोकतंत्र, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और शक्तियों का पृथक्करण जैसे तत्व शामिल हैं। इसी दौरान, सरकार ने वरिष्ठता के सिद्धांत को नजरअंदाज करते हुए न्यायमूर्ति ए.एन. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया, जिससे तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों ने इस्तीफा दे दिया। इस कदम को न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर एक हमले के रूप में देखा गया और 'प्रतिबद्ध न्यायपालिका' की अवधारणा पर बहस छिड़ गई, जिसका अर्थ था एक ऐसी न्यायपालिका जो सरकार की विचारधारा के प्रति झुकाव रखती हो। यह संघर्ष आपातकाल की घोषणा का एक प्रमुख संवैधानिक और राजनीतिक संदर्भ बना।
उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

156. 1970 के दशक में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था?
(A) न्यायाधीशों और न्यायिक कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का विवाद
(B) संविधान संशोधन की संसद की शक्ति, विशेषकर मौलिक अधिकारों पर
(C) देश में नए उच्च न्यायालयों की स्थापना का प्रशासनिक विवाद
(D) प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रक्रिया और उसके विशेषाधिकारों का मुद्दा

157. 'संविधान के बुनियादी ढांचे' का सिद्धांत किस ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित किया गया था?
(A) गोलकनाथ मामला
(B) शाह बानो मामला
(C) मिनर्वा मिल्स मामला
(D) केशवानंद भारती मामला

158. 'बुनियादी ढांचे' के सिद्धांत का क्या तात्पर्य है?
(A) संसद संविधान के मूल तत्वों और बुनियादी मूल्यों को नहीं बदल सकती
(B) संसद को संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार नहीं है
(C) संसद केवल मौलिक अधिकारों के प्रावधानों में ही संशोधन कर सकती है
(D) केवल भारत के राष्ट्रपति ही संविधान में संशोधन का प्रस्ताव रख सकते हैं

159. स्रोत में उल्लिखित 'प्रतिबद्ध न्यायपालिका' की अवधारणा का क्या अर्थ है?
(A) ऐसी न्यायपालिका जो संविधान के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान हो
(B) ऐसी न्यायपालिका जो केवल अंतरराष्ट्रीय कानूनों को ही प्राथमिकता दे
(C) ऐसी न्यायपालिका जो सरकार की विचारधारा के प्रति झुकाव रखे
(D) ऐसी न्यायपालिका जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति आजीवन काल के लिए हो

160. सरकार द्वारा वरिष्ठता की अनदेखी कर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का क्या परिणाम हुआ?
(A) तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया
(B) न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संबंध सुधर गए
(C) सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया
(D) संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

25 जून 1975 को भारत में लगाया गया राष्ट्रीय आपातकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत घोषित किया गया था। इस अनुच्छेद ने सरकार को 'आंतरिक अशांति' के आधार पर आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार दिया। हालांकि, इस शक्ति का प्रयोग अभूतपूर्व था क्योंकि यह किसी बाहरी आक्रमण या युद्ध के जवाब में नहीं, बल्कि देश के भीतर कथित राजनीतिक अस्थिरता के जवाब में था। सरकार ने तर्क दिया कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन, हड़तालें और विरोध प्रदर्शन देश की स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर रहे थे और विकास कार्यों में बाधा डाल रहे थे। आलोचकों का मानना था कि 'आंतरिक अशांति' का आधार अस्पष्ट था और इसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोध को दबाने और सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए किया गया था। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर की थी, जबकि मंत्रिमंडल को इसके बारे में अगली सुबह ही सूचित किया गया था। इस घोषणा के साथ ही, नागरिकों के मौलिक अधिकार, विशेष रूप से जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21) और कानून के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14), निलंबित कर दिए गए। प्रेस पर कठोर सेंसरशिप लगा दी गई, जिससे सरकार की आलोचना करने वाली किसी भी खबर का प्रकाशन असंभव हो गया। यह कदम भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अंधकारमय अध्याय साबित हुआ, जिसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक मानदंडों पर राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को स्थापित किया।

उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

161. भारत में 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया था?
(A) अनुच्छेद 370
(B) अनुच्छेद 356
(C) अनुच्छेद 360
(D) अनुच्छेद 352

162. सरकार ने आपातकाल की घोषणा के लिए आधिकारिक तौर पर क्या कारण बताया था?
(A) विदेशी शक्तियों द्वारा देश पर किया गया अचानक बाहरी आक्रमण
(B) आंतरिक अशांति और देश की स्थिरता पर मंडराता हुआ खतरा
(C) देश में आई हुई अत्यंत भीषण और व्यापक प्राकृतिक आपदा का संकट
(D) देश की अर्थव्यवस्था में आई हुई भारी मंदी और वित्तीय अस्थिरता

163. आपातकाल की घोषणा के संबंध में आलोचकों का मुख्य तर्क क्या था?
(A) सरकार द्वारा उचित और निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ
(B) आपातकाल को पूरे देश के बजाय केवल कुछ विशिष्ट राज्यों में ही लगाते
(C) 'आंतरिक अशांति' के आधार पर राजनीतिक विरोध का दमन किया गया
(D) राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह लिए बिना ही स्वतंत्र रूप से कार्य किया

164. आपातकाल की घोषणा का नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ा?
(A) नागरिकों के मौलिक अधिकारों को पहले से और अधिक सुदृढ़ बनाया गया
(B) नागरिकों के केवल संपत्ति संबंधी अधिकारों को ही निलंबित किया गया
(C) नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा
(D) अनुच्छेद 21 और 14 सहित कई मुख्य मौलिक अधिकार निलंबित हुए

165. स्रोत के अनुसार, आपातकाल की घोषणा की प्रक्रिया में एक विवादास्पद पहलू क्या था?
(A) मंत्रिमंडल को निर्णय के बाद ही सूचित किया गया था।
(B) राष्ट्रपति ने घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था।
(C) प्रधानमंत्री की सलाह के बिना मंत्रिमंडल ने स्वयं निर्णय लिया था।
(D) सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा को तुरंत मंजूरी दे दी थी।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

आपातकाल (1975-1977) के दौरान भारतीय लोकतंत्र के

संस्थागत ढांचे को गंभीर क्षति पहुँची। इसका सबसे गहरा प्रभाव नागरिक स्वतंत्रता के हनन के रूप में दिखाई दिया। 'आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम' (मीसा) जैसे कठोर कानूनों का व्यापक रूप से राजनीतिक विरोधियों, छात्र नेताओं, और सरकार से असहमत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने के लिए उपयोग किया गया। प्रेस की स्वतंत्रता, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, को सेंसरशिप के माध्यम से पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। समाचार पत्रों को प्रकाशन से पहले सरकारी अधिकारियों से सामग्री स्वीकृत करानी पड़ती थी। संघीय ढांचे पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के हाथों में केंद्रित हो गईं और राज्यों की स्वायत्तता लगभग समाप्त हो गई। इस अवधि में 'अतिरिक्त-संवैधानिक प्राधिकरणों' का उदय भी देखा गया, जहाँ सत्ता के औपचारिक पदों पर न होते हुए भी व्यक्तियों का सरकार के निर्णयों पर अत्यधिक प्रभाव था। इसके अतिरिक्त, इस दौरान कुछ विवादास्पद कार्यक्रम, जैसे कि जबरन नसबंदी अभियान, लागू किए गए, जिनका उद्देश्य जनसंख्या को नियंत्रित करना था, लेकिन अक्सर इन्हें क्रूरता और बलपूर्वक लागू किया गया, जिससे आम जनता में भारी भय और आक्रोश पैदा हुआ। इन सभी घटनाओं ने सामूहिक रूप से संवैधानिक संतुलन को बिगाड़ दिया और राज्य को व्यक्ति पर अत्यधिक अधिकार प्रदान कर दिया।
उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

166. आपातकाल के दौरान 'मीसा' (MISA) कानून का उपयोग किस लिए किया गया था?
(A) देश में व्यापक आर्थिक और सामाजिक सुधारों को लागू करने के लिए
(B) राजनीतिक विरोधियों को बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने हेतु
(C) देश में होने वाले विदेशी निवेश को पूरी तरह नियंत्रित करने के लिए
(D) देश के समस्त प्रेस और मीडिया जगत को सरकार द्वारा विनियमित करने हेतु

167. आपातकाल का प्रेस की स्वतंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ा?
(A) प्रेस और मीडिया संस्थानों को पहले से अधिक व्यापक स्वतंत्रता दी गई
(B) प्रेस पर कठोर सेंसरशिप और अनिवार्य सरकारी अनुमोदन लागू हुआ
(C) केवल विदेशी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के प्रकाशन पर रोक लगाई गई
(D) सभी समाचार पत्रों को सरकार द्वारा भारी वित्तीय सब्सिडी प्रदान की गई

168. 'अतिरिक्त-संवैधानिक प्राधिकरण' से क्या तात्पर्य है?
(A) वे व्यक्ति जो पद पर न होते हुए भी सरकार पर अत्यधिक प्रभाव रखते थे
(B) न्यायपालिका को संविधान द्वारा प्रदान की गई कुछ विशेष और असाधारण शक्तियाँ
(C) विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा सरकार के विरुद्ध गठित समानांतर शासन व्यवस्था
(D) विदेशी शक्तियों द्वारा समर्थित और पोषित कुछ विशेष प्रकार के गुप्त समूह

169. स्रोत के अनुसार, आपातकाल का भारत के संघीय ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ा?
(A) देश के सभी राज्यों को पहले की तुलना में अधिक शक्तियाँ प्रदान की गईं
(B) केंद्र और राज्यों के संबंधों के बीच कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया
(C) शक्तियाँ केंद्र में केंद्रित हुईं और राज्यों की स्वायत्तता कम हुई
(D) देश में पूरी तरह से एक नए और विकेंद्रीकृत संघीय ढांचे का निर्माण हुआ

170. आपातकाल के दौरान लागू किए गए किस कार्यक्रम से आम जनता में विशेष रूप से भय और आक्रोश फैला?
(A) गरीबी हटाओ कार्यक्रम
(B) हरित क्रांति कार्यक्रम
(C) भूमि सुधार कार्यक्रम
(D) जबरन नसबंदी अभियान

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
1977 का लोकसभा चुनाव भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसे अक्सर आपातकाल पर एक जनमत संग्रह के रूप में देखा जाता है। 18 महीने के आपातकाल के बाद, जब इंदिरा गांधी ने चुनावों की घोषणा की, तो राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल गया। आपातकाल का विरोध करने वाले प्रमुख विपक्षी दल, जैसे कांग्रेस (ओ), भारतीय जनसंघ, भारतीय लोक दल और सोशलिस्ट पार्टी, ने अपने मतभेदों को भुलाकर 'जनता पार्टी' नामक एक एकीकृत मंच का गठन किया। इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य इंदिरा गांधी के अधिनायकवादी शासन को समाप्त करना और लोकतंत्र को बहाल करना था। 'लोकतंत्र बचाओ' के नारे के साथ, जनता पार्टी ने मतदाताओं से आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों, जैसे नागरिक अधिकारों का हनन, प्रेस सेंसरशिप और जबरन नसबंदी, के खिलाफ वोट करने का आह्वान किया। चुनाव परिणामों ने कांग्रेस पार्टी को एक करारी हार दी; यह स्वतंत्रता के बाद पहली बार था जब कांग्रेस केंद्र में सत्ता से बाहर हुई। जनता पार्टी ने भारी बहुमत हासिल किया और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। यह चुनाव परिणाम भारतीय मतदाताओं की परिपक्वता और लोकतंत्र के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता का प्रमाण था। इसने यह भी स्थापित किया कि भारतीय लोकतंत्र में कोई भी सरकार स्थायी नहीं है और अंततः संप्रभुता जनता में निहित है, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करके किसी भी अलोकतांत्रिक सरकार को दंडित कर सकती है।
उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

171. 1977 के चुनाव को अक्सर किस रूप में देखा जाता है?
(A) आर्थिक नीतियों पर एक जनमत संग्रह
(B) विदेश नीति पर एक जनमत संग्रह
(C) आपातकाल पर एक जनमत संग्रह
(D) भाषा नीति पर एक जनमत संग्रह

172. 'जनता पार्टी' का गठन कैसे हुआ?
(A) यह कांग्रेस का ही एक अलग हुआ गुट था।
(B) कई प्रमुख विपक्षी दलों के विलय से इसका गठन हुआ।
(C) यह एक पूरी तरह से नई पार्टी थी जिसका कोई पुराना नेता नहीं था।
(D) इसे सेना द्वारा स्थापित किया गया था।

173. 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का मुख्य नारा क्या था?
(A) गरीबी हटाओ
(B) जय जवान, जय किसान
(C) भारत उदय
(D) लोकतंत्र बचाओ

174. 1977 के चुनाव परिणामों का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था?
(A) स्वतंत्रता के बाद पहली बार कांग्रेस केंद्र में सत्ता से बाहर हुई
(B) भारत में औपचारिक रूप से एक स्थायी दो-दलीय राजनीतिक प्रणाली बनी
(C) भारत के सभी क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य से समाप्त हुए
(D) चुनावों के संपन्न होने के पश्चात भी देश में आपातकाल निरंतर जारी रहा

175. स्रोत के अनुसार, 1977 के चुनाव परिणाम भारतीय मतदाताओं के बारे में क्या दर्शाते हैं?
(A) वे देश में होने वाले बड़े राजनीतिक परिवर्तनों के प्रति सदैव उदासीन हैं
(B) वे केवल अपने स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर ही मतदान करते हैं
(C) वे लोकतंत्र के प्रति समर्पित हैं और अलोकतांत्रिक शासन को दंडित करेंगे
(D) वे निर्वाचन के समय सदैव वर्तमान सत्ताधारी दल के ही पक्ष में मतदान करते हैं

ANSWERS

1. (B) पार्टी का नवजीवन हुआ लेकिन वह पहले जैसी नहीं रही।
1971 के चुनावों के बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को एक नए रूप में पुनर्जीवित किया। हालांकि पार्टी ने भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की, लेकिन इसका आंतरिक स्वरूप पूरी तरह बदल गया। अब यह पार्टी पहले की तरह विभिन्न विचारधाराओं और गुटों के बीच सामंजस्य बनाने वाली संस्था नहीं रही, बल्कि पूरी तरह से एक सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता और निर्देश पर निर्भर हो गई।

2. (A) सांविधानिक और संस्थागत संतुलन की चुनौती
1973 से 1975 के बीच भारतीय राजनीति ने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच गहरे तनाव का सामना किया। इस दौरान संसद की सर्वोच्चता और न्यायपालिका के समीक्षा अधिकार को लेकर निरंतर संघर्ष हुआ। इस स्थिति ने लोकतांत्रिक संस्थानों के बीच के नाजुक संतुलन को बनाए रखने की एक गंभीर चुनौती पेश की, जिससे अंततः देश में एक अभूतपूर्व संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई।

3. (B) (A) और (R) दोनों सत्य लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
सरकार ने 1975 में आपातकाल लागू करने के लिए संविधान में वर्णित अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका को आधार बनाया था। यह तथ्य भी सत्य है कि सामान्यतः आपातकाल को युद्ध या बाहरी आक्रमण जैसी चरम स्थितियों के लिए सुरक्षित रखा गया है। हालांकि, अभिकथन और कारण दोनों अपने आप में सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की घोषणा के पीछे के विशिष्ट राजनीतिक तर्क की पूर्ण व्याख्या नहीं करता है।

4. (D) बांग्लादेश संकट से अर्थव्यवस्था पर पड़ा भारी बोझ
1971 के बाद भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार न हो पाने का मुख्य कारण बांग्लादेश संकट था। इस युद्ध के परिणामस्वरूप लगभग अस्सी लाख शरणार्थी भारत आए, जिनके भोजन और आवास की व्यवस्था ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाला। इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के कारण विकास कार्यों के स्थान पर रक्षा व्यय में भी काफी वृद्धि करनी पड़ी थी।

5. (C) 23 प्रतिशत
1970 के दशक की शुरुआत में भारत को गंभीर आर्थिक मंदी और मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में वृद्धि और घरेलू स्तर पर कृषि उत्पादन में गिरावट ने कीमतों को तेजी से बढ़ाया। इसी क्रम में 1973 में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तेईस प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई, जिसने आम जनता के बीच सरकार के प्रति असंतोष को और अधिक बढ़ा दिया।

6. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
भारतीय राजनीति की प्रमुख घटनाओं और नारों का संबंध विशिष्ट व्यक्तियों और वर्षों से है। इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनावों में गरीबी हटाओ का प्रसिद्ध नारा दिया था। 1974 में बिहार छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया, जबकि उसी वर्ष रेल हड़ताल की अगुवाई जॉर्ज फर्नान्डिस ने की थी। कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. बरुआ ने प्रधानमंत्री की प्रशंसा में इंडिया इज़ इंदिरा का नारा दिया था।

7. (D) हथियार उठाने और राज्यविरोधी तकनीकों का
कुछ क्रांतिकारी मार्क्सवादी और लेनिनवादी समूहों का मानना था कि भारत की मौजूदा लोकतांत्रिक और संसदीय प्रणाली केवल धनी और प्रभावशाली लोगों के हितों की रक्षा करती है। इसलिए, उन्होंने समाज में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए चुनावी प्रक्रिया के बजाय सशस्त्र विद्रोह का मार्ग चुना। इन समूहों ने मौजूदा राज्य व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए हिंसा और छापामार युद्ध जैसी राज्यविरोधी तकनीकों का सहारा लिया था।

8. (C) केवल 1, 3 और 4
गुजरात का छात्र आंदोलन मुख्य रूप से खाद्यान्न और खाद्य तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों के खिलाफ शुरु हुआ था। इस आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। विपक्षी नेता मोरारजी देसाई ने राज्य में नए सिरे से चुनाव करवाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की थी। इस आंदोलन में विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी सक्रिय भागीदारी की थी।

9. (C) बढ़ती कीमतें, खाद्यान्न का अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार
बिहार में 1974 के दौरान हुए छात्र आंदोलन के पीछे कई गहरे सामाजिक और आर्थिक कारण मौजूद थे। राज्य की जनता बढ़ती महंगाई, खाद्यान्न की भारी कमी और शिक्षित युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी से त्रस्त थी। साथ ही, सरकारी प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार ने छात्रों के आक्रोश को और भड़का दिया। इन साझा समस्याओं ने छात्रों को एक बड़े आंदोलन के लिए संगठित होने हेतु प्रेरित किया था।

10. (A) आंदोलन अहिंसक रहेगा और अपने को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखेगा।
जब बिहार के छात्रों ने जयप्रकाश नारायण से नेतृत्व का आग्रह किया, तो उन्होंने दो मुख्य शर्तें रखीं। पहली शर्त यह थी कि पूरा आंदोलन अनिवार्य रूप से अहिंसक रहना चाहिए। दूसरी शर्त यह थी कि आंदोलन का उद्देश्य केवल बिहार तक सीमित न रहकर राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक परिवर्तन लाना होना चाहिए। इन शर्तों के स्वीकार होने के बाद ही उन्होंने सक्रिय रूप से आंदोलन की कमान संभाली।

11. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का विचार केवल सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं था, बल्कि वे समाज के हर क्षेत्र में बुनियादी बदलाव चाहते थे। उनका मानना था कि वास्तविक लोकतंत्र तभी स्थापित हो सकता है जब भ्रष्टाचार का अंत हो और राजनीतिक व आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण हो। इसी महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने छात्रों और आम जनता को संपूर्ण क्रांति हेतु संगठित किया था।

12. (A) 1, 3, 2, 4
सत्तर के दशक की राजनीतिक घटनाओं का एक निश्चित क्रम है। सबसे पहले जनवरी 1974 में गुजरात में छात्र आंदोलन शुरु हुआ। इसके कुछ ही समय बाद मार्च 1974 में बिहार में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। मई 1974 में देशव्यापी रेल हड़ताल हुई जिसने आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित किया। अंततः मार्च 1975 में जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली में ऐतिहासिक संसद मार्च का नेतृत्व किया, जो एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन था।

13. (C) भारतीय जनसंघ, कांग्रेस (ओ), भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी
जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन को कांग्रेस के खिलाफ एक बड़े राजनीतिक विकल्प के रूप में देखा गया। इसी कारण भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस (संगठन) जैसे विभिन्न विचारधारा वाले दलों ने उन्हें अपना पूर्ण समर्थन दिया। इन विपक्षी दलों के एकजुट होने से इंदिरा गांधी की सरकार के समक्ष एक शक्तिशाली और संगठित राजनीतिक चुनौती पैदा हो गई थी।

14. (D) सरकार ने रेलवे हड़ताल को पूर्णतः वैधानिक करार दिया था।
1974 की ऐतिहासिक रेल हड़ताल के प्रति सरकार का रवैया बहुत सख्त और नकारात्मक था। सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को सुनने के बजाय इस हड़ताल को पूरी तरह से गैर-कानूनी और असंवैधानिक घोषित कर दिया था। हड़ताल को कुचलने के लिए बड़े पैमाने पर नेताओं की गिरफ्तारियां की गईं और कर्मचारियों को डराया गया। इसलिए, यह कहना गलत है कि सरकार ने हड़ताल को वैधानिक माना था।

15. (A) केवल 1, 2 और 4 सही हैं।
1974 की रेल हड़ताल मुख्य रूप से बोनस और बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर आयोजित की गई थी। सरकार ने इस आंदोलन को अवैध घोषित करते हुए सख्त कदम उठाए और रेल संपत्तियों की सुरक्षा के लिए सैन्य बलों को तैनात किया। हालांकि, यह हड़ताल बीस दिनों के बाद बिना किसी औपचारिक समझौते के समाप्त हो गई थी। इस हड़ताल का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने नहीं किया था।

16. (B) न्यायाधीशों और सरकारी अधिकारियों का शासक दल के प्रति निष्ठावान होना
प्रतिबद्ध न्यायपालिका की अवधारणा यह सुझाव देती है कि न्यायपालिका और प्रशासनिक अधिकारियों को सरकार की नीतियों और विचारधारा के प्रति पूरी तरह समर्पित होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि न्यायाधीशों को अपने फैसलों में सत्तारूढ़ दल के सामाजिक और राजनीतिक लक्ष्यों का समर्थन करना चाहिए। यह विचार न्यायपालिका की पारंपरिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता के सिद्धांत के विपरीत है और कार्यकारी शक्ति को अधिक मजबूत बनाता है।

17. (B) संविधान का एक 'बुनियादी ढाँचा' है और संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती।
केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारतीय संवैधानिक इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यद्यपि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन वह इसके मौलिक स्वरुप या बुनियादी ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। इस फैसले ने लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और संघीय ढांचे जैसे संविधान के अनिवार्य लक्षणों को संसद की विधायी शक्तियों के मनमाने उपयोग से हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया।

18. (B) P-2, Q-1, R-4, S-3
आपातकाल के दौर से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों की भूमिकाएं महत्वपूर्ण थीं। जगमोहन लाल सिन्हा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया था। राजनारायण इस मामले में याचिकाकर्ता थे। ए. एन. रे को वरिष्ठता की अनदेखी कर मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। फखरुद्दीन अली अहमद ने उस समय भारत के राष्ट्रपति के रूप में आपातकाल की उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे।

19. (C) सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाने की
भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए लंबे समय से यह परंपरा चली आ रही थी कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही इस पद पर नियुक्त किया जाता था। हालांकि, 1973 में सरकार ने इस स्थापित परिपाटी को तोड़ते हुए तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी की और न्यायमूर्ति ए.एन. रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। इस कदम को न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर एक बड़े हमले के रूप में देखा गया।

20. (C) केवल 1, 2 और 3
इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 1975 का फैसला राजनारायण की याचिका पर आधारित था, जिसमें इंदिरा गांधी पर चुनावी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। अदालत ने माना कि उन्होंने प्रचार के दौरान सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया था, जिससे उनका निर्वाचन अवैध हो गया। हालांकि, इस फैसले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने पद नहीं छोड़ा, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील की और अंततः देश में आपातकाल लागू कर दिया।

21. (C) इंदिरा गाँधी सांसद बनी रहेंगी, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती हैं।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक आंशिक स्थगनादेश जारी

किया। इसके अनुसार, इंदिरा गांधी अपनी संसदीय सदस्यता बरकरार रख सकती थीं, लेकिन उन्हें लोकसभा की किसी भी कार्यवाही में हिस्सा लेने या मतदान करने की अनुमति नहीं दी गई। इस कानूनी स्थिति ने उनके प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की नैतिकता और वैधता पर बड़े राजनीतिक सवाल खड़े कर दिए थे।

22. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
25 जून 1975 को आपातकाल लगाने का सरकार का मुख्य तर्क यह था कि विपक्ष द्वारा चलाया जा रहा राष्ट्रव्यापी आंदोलन देश की स्थिरता के लिए खतरा है। सरकार का मानना था कि जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर सेना और पुलिस को भड़काना और सरकार के खिलाफ सत्याग्रह करना कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर संकट पैदा कर रहा है। इसी अशांति की आशंका को आधार बनाकर आपातकाल की घोषणा की गई थी।

23. (D) सरकार के अनैतिक और अवैधानिक आदेशों का पालन न करने का।
दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए जयप्रकाश नारायण ने राज्य के सुरक्षा बलों और नागरिक प्रशासन से अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने को कहा। उन्होंने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से स्पष्ट आह्वान किया कि वे सरकार के ऐसे किसी भी आदेश को मानने से इनकार कर दें जो अनैतिक या कानून के विरुद्ध हो। उनके इस बयान को सरकार ने राजद्रोह और विद्रोह भड़काने वाला माना था।

24. (A) अनुच्छेद 352
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 केंद्र सरकार को यह शक्ति देता है कि यदि देश की सुरक्षा को बाहरी आक्रमण, युद्ध या आंतरिक अशांति से खतरा हो, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। 1975 में इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसके लागू होने के बाद संघीय ढांचा व्यावहारिक रूप से समाप्त हो गया और समस्त शक्तियां केंद्र के पास आ गईं।

25. (C) आपातकाल में सरकार मौलिक अधिकारों पर रोक नहीं लगा सकती।
आपातकाल की स्थिति में सरकार के पास नागरिक स्वतंत्रताओं को सीमित करने की असाधारण शक्तियां होती हैं। यह कहना गलत है कि सरकार मौलिक अधिकारों पर रोक नहीं लगा सकती, क्योंकि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 21 सहित कई महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे। नागरिकों के पास अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने या अदालतों में शरण लेने का अधिकार भी इस दौरान व्यावहारिक रूप से समाप्त कर दिया गया था।

26. (A) केवल 1, 2 और 3
आपातकाल के दौरान सरकार ने सूचनाओं के प्रवाह पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी थी। इसके अतिरिक्त, सांप्रदायिक और सामाजिक अशांति फैलाने के संदेह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस अवधि में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था और किसी भी प्रकार के धरने, प्रदर्शन या हड़ताल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी।

27. (D) किसी व्यक्ति को इस आशंका से गिरफ्तार करना कि वह कोई अपराध कर सकता है।
निवारक नज़रबंदी एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए किसी वास्तविक अपराध के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में अपराध करने की संभावना के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने या राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल होने से रोकना होता है। आपातकाल के दौरान इस कानून का बड़े पैमाने पर राजनीतिक विरोधियों को बिना मुकदमा जेल भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया।

28. (B) बंदी प्रत्यक्षीकरण
बंदी प्रत्यक्षीकरण एक मौलिक न्यायिक सुरक्षा है जो किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत से बचाती है। हालांकि, 1975 के आपातकाल के दौरान सरकार ने इस अधिकार को निलंबित कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय के विवादास्पद फैसले के बाद, नागरिक अपनी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने के लिए इस याचिका का उपयोग नहीं कर सकते थे। इससे पुलिस और प्रशासन को बिना किसी कानूनी जवाबदेही के किसी को भी अनिश्चित काल तक रखने की शक्ति मिल गई थी।

29. (A) P-3, Q-1, R-2, S-4
आपातकाल के दौरान दमन और प्रतिरोध के विभिन्न स्वरूप देखे गए। निवारक नज़रबंदी के तहत हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। सेंसरशिप के विरोध में कुछ अखबारों ने अपने संपादकीय कॉलम खाली छोड़ दिए। फणीश्वरनाथ 'रेणु' जैसे साहित्यकारों ने सरकारी पदवियां लौटाकर अपना विरोध दर्ज किया। उसी समय 42वें संशोधन के जरिए संसद ने अपना कार्यकाल बढ़ाकर लोकतांत्रिक संस्थाओं की संरचना में बड़े बदलाव करने की कोशिश की थी।

30. (D) सरकार आपातकाल के दौरान नागरिक से जीवन और आज़ादी का अधिकार वापस ले सकती है।
अप्रैल 1976 में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने एडीएम जबलपुर मामले में एक अत्यंत विवादास्पद निर्णय दिया। अदालत ने बहुमत से यह माना कि आपातकाल की स्थिति में नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सरकार द्वारा कानूनी रूप से छीना जा सकता है। इस फैसले ने कार्यपालिका को असीमित शक्तियां प्रदान कर दीं और न्यायपालिका के पास नागरिकों की सुरक्षा करने का कोई प्रभावी विकल्प शेष नहीं रहा।

31. (B) केवल 2, 3 और 4
आपातकाल के दौरान प्रेस सेंसरशिप के विरोध में 'सेमिनार' और 'मेनस्ट्रीम' जैसी पत्रिकाओं ने अपनी गरिमा बनाए रखने

के लिए प्रकाशन बंद करना बेहतर समझा। साहित्यिक जगत में भी गहरा आक्रोश था, जिसके कारण शिवराम कारंत और फणीश्वरनाथ 'रेणु' जैसे प्रतिष्ठित लेखकों ने क्रमशः अपने पद्मभूषण और पद्मश्री सम्मान सरकार को वापस कर दिए। हालांकि, इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसे अखबारों ने सेंसरशिप का कड़ा विरोध किया था, न कि समर्थन।

32. (B) देश की विधायिका के कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर 6 साल करना।
42वें संविधान संशोधन को आपातकाल के दौरान संसद की शक्तियों के व्यापक विस्तार के लिए पारित किया गया था। इसका एक मुख्य प्रावधान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सामान्य कार्यकाल को पांच वर्ष से बढ़ाकर छह वर्ष करना था। इस परिवर्तन का उद्देश्य चुनावों को टालना और सत्ता पर सरकार की पकड़ को और अधिक समय तक बनाए रखना था। इस संशोधन ने संविधान के मूल संतुलन को काफी हद तक प्रभावित किया था।

33. (B) भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन है।
आपातकाल के अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत की लोकतांत्रिक जड़ें अत्यंत गहरी हैं। यद्यपि कुछ समय के लिए नागरिक स्वतंत्रताओं और संवैधानिक प्रक्रियाओं को दबा दिया गया था, लेकिन अंततः जनता ने चुनावों के माध्यम से अपनी लोकतांत्रिक शक्ति का प्रदर्शन किया। इस घटनाक्रम से यह महत्वपूर्ण सबक मिला कि भारतीय समाज में लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक अनिवार्य जीवन मूल्य है जिसे आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता।

34. (A) 'अंदरुनी आपातकाल' अब केवल 'सशस्त्र विद्रोह' की स्थिति में लगाया जा सकता है।
आपातकाल की समाप्ति के बाद संविधान में महत्वपूर्ण सुधार किए गए ताकि भविष्य में शक्तियों का दुरुपयोग रोका जा सके। 'अंदरुनी गड़बड़ी' जैसे अस्पष्ट शब्द के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द को शामिल किया गया। इसका अर्थ यह है कि अब केवल शांतिपूर्ण आंदोलनों या राजनीतिक विरोध के आधार पर आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। इसके अतिरिक्त, आपातकाल की घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह को भी अनिवार्य बना दिया गया।

35. (A) 2, 3, 4, 1
सत्तर के दशक के उत्तरार्ध की घटनाएं एक निश्चित क्रम में घटीं। सबसे पहले जनवरी 1977 में आपातकाल समाप्त हुआ और चुनावों की घोषणा हुई। मार्च 1977 में चुनावों के बाद जनता पार्टी ने बहुमत प्राप्त कर सरकार बनाई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। इसके पश्चात, मई 1977 में नवनियुक्त सरकार ने आपातकाल की ज्यादतियों की जांच के लिए न्यायमूर्ति जे.सी. शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन किया।

36. (D) 'लोकतंत्र बचाओ'
1977 के लोकसभा चुनावों में विपक्षी दलों ने आपातकाल के दौरान हुई नागरिक अधिकारों की कटौती को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया। जनता पार्टी ने 'लोकतंत्र बचाओ' का नारा देकर मतदाताओं को नागरिक स्वतंत्रता और तानाशाही के बीच चयन करने का विकल्प दिया। यह नारा उन लोगों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हुआ जो आपातकाल के कठोर शासन और दमनकारी नीतियों से पीड़ित थे, जिससे चुनाव एक वैचारिक संघर्ष बन गया।

37. (C) जनता पार्टी
1977 के ऐतिहासिक चुनावों से ठीक पहले विपक्षी एकता को साकार करने के लिए जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय लोकदल और कांग्रेस (ओ) जैसे प्रमुख दलों ने मिलकर जनता पार्टी का निर्माण किया। इन दलों ने महसूस किया कि कांग्रेस को हराने के लिए गैर-कांग्रेसी वोटों का बिखराव रोकना अनिवार्य है। जयप्रकाश नारायण के मार्गदर्शन में बने इस नए राजनीतिक दल ने पहली बार केंद्र में एक मजबूत विकल्प पेश किया।

38. (B) जगजीवन राम
आपातकाल की समाप्ति के बाद कांग्रेस के भीतर एक बड़ा विद्रोह हुआ और वरिष्ठ नेता जगजीवन राम ने पार्टी छोड़कर 'कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी' नामक एक नया संगठन बनाया। उनके इस कदम ने तत्कालीन सत्ताधारी दल को कमजोर कर दिया और विपक्षी एकता को बल प्रदान किया। बाद में यह पार्टी जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी और अंततः उसी में विलीन हो गई, जिससे 1977 के चुनावों में विपक्ष का पलड़ा भारी हो गया।

39. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
1977 के चुनावों में कांग्रेस की हार का मुख्य कारण आपातकाल के प्रति जनता का तीव्र आक्रोश था। जनता पार्टी ने चतुराई से इस चुनाव को आपातकाल की दमनकारी नीतियों पर एक जनमत-संग्रह के रूप में प्रस्तुत किया। उत्तर भारत के मतदाताओं ने विशेष रूप से जबरन नसबंदी और नागरिक अधिकारों के हनन के विरोध में मतदान किया, जिससे कांग्रेस को केंद्र की सत्ता से पहली बार हाथ धोना पड़ा।

40. (A) 154
1977 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को अपने इतिहास की सबसे करारी हार का सामना करना पड़ा। आपातकाल की नीतियों के खिलाफ देशव्यापी गुस्से के कारण पार्टी की सीटों की संख्या घटकर मात्र 154 रह गई। यह पहली बार था जब आजादी के बाद कांग्रेस केंद्र में बहुमत प्राप्त करने में विफल रही। उत्तर भारत में पार्टी का प्रदर्शन इतना निराशाजनक रहा कि कई राज्यों में उसे एक भी सीट नहीं मिली।

41. (B) केवल 1, 2, 3 और 5
1977 के चुनावों में जनता पार्टी और उसके सहयोगियों ने 330 सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की, जिसमें अकेले जनता पार्टी को 295 सीटें मिलीं। उत्तर भारत में आपातकाल का गहरा प्रभाव होने के कारण कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ, लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों में उसका प्रदर्शन संतोषजनक रहा। हालांकि, इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों को अपनी पारंपरिक सीटों

पर हार का सामना करना पड़ा था, जो एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर था।

42. (A) बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब
1977 के चुनावों में उत्तर भारत में कांग्रेस के विरुद्ध एक मजबूत लहर देखी गई। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया और उसे इन राज्यों में एक भी सीट हासिल नहीं हुई। इन क्षेत्रों में आपातकाल के दौरान लागू की गई कठोर नीतियों, विशेषकर नसबंदी कार्यक्रमों और प्रेस सेंसरशिप का जनता पर सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ा था।

43. (D) मोरारजी देसाई
1977 में जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद नेतृत्व के सवाल पर मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम के बीच प्रतिस्पर्धा थी। अंततः, मोरारजी देसाई को सर्वसम्मति से संसदीय दल का नेता चुना गया और वे भारत के पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल आपातकाल के प्रभाव को समाप्त करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को पुनः स्थापित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है, हालांकि उनकी सरकार आंतरिक मतभेदों से जूझती रही।

44. (A) P-3, Q-1, R-4, S-2
1977 के राजनीतिक घटनाक्रम में विभिन्न नेताओं की विशिष्ट भूमिकाएं थीं। मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह भारतीय लोकदल के नेता थे जो किसानों के हितों के पैरोकार माने जाते थे। जगजीवन राम ने कांग्रेस छोड़कर 'कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी' की स्थापना की थी। जयप्रकाश नारायण ने 'संपूर्ण क्रांति' का विचार दिया था, जो इस पूरे राजनीतिक परिवर्तन की वैचारिक प्रेरणा शक्ति बना।

45. (C) 28 महीने
मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी पहली गैर-कांग्रेसी सरकार अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकी। गठबंधन के भीतर विभिन्न दलों और नेताओं के बीच वैचारिक मतभेदों और सत्ता के संघर्ष के कारण सरकार निरंतर अस्थिर बनी रही। अठ्ठाइस महीनों के संक्षिप्त कार्यकाल के बाद, आंतरिक कलह के कारण सरकार ने अपना बहुमत खो दिया और मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा।

46. (A) केवल 1 और 4
मोरारजी देसाई की सरकार गिरने के बाद चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के बाहरी समर्थन से प्रधानमंत्री बने, लेकिन यह सरकार केवल चार महीने ही चल सकी क्योंकि कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद 1980 में हुए मध्यावधि चुनावों में जनता पार्टी पूरी तरह विफल रही और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 353 सीटें जीतकर सत्ता में जबरदस्त वापसी की, जिससे गठबंधन राजनीति के प्रारंभिक प्रयोग का अंत हुआ।

47. (A) आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाई तथा सत्ता के दुरुपयोग के विभिन्न आरोपों की जांच के लिए
1977 में जनता पार्टी सरकार ने सत्ता संभालते ही आपातकाल के दौरान हुए मानवाधिकारों के हनन और सत्ता के दुरुपयोग की जांच का निर्णय लिया। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.सी. शाह की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। शाह आयोग का मुख्य उद्देश्य उन परिस्थितियों और निर्णयों की समीक्षा करना था जिनके कारण नागरिकों पर ज्यादतियां की गईं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बाधित किया गया।

48. (B) यदि सरकार अस्थिर हो और उसके भीतर कलह हो, तो मतदाता उसे कड़ा दंड देते हैं।
1977 से 1979 के बीच जनता पार्टी की सरकार का पतन भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ा सबक था। इससे यह स्पष्ट हो गया कि केवल कांग्रेस विरोध के नाम पर बना गठबंधन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसके पास एक साझा कार्यक्रम और स्थिर नेतृत्व न हो। मतदाताओं ने दिखाया कि वे राजनीतिक अस्थिरता और आपसी कलह को पसंद नहीं करते और ऐसी सरकारों को अगले चुनाव में बाहर का रास्ता दिखा देते हैं।

49. (B) पार्टी ने स्वयं को एक विशेष विचारधारा से जोड़ा और एक नेता की लोकप्रियता पर निर्भर हो गई।
1969 के विभाजन के बाद कांग्रेस पार्टी का स्वरूप बुनियादी तौर पर बदल गया। यह पार्टी अब विभिन्न गुटों और विचारधाराओं के समावेशी मंच के बजाय एक केंद्रीकृत संगठन बन गई। पार्टी पूरी तरह से इंदिरा गांधी के करिश्माई व्यक्तित्व और उनकी समाजवादी नीतियों के इर्द-गिर्द सिमट गई। आंतरिक लोकतंत्र और संगठनात्मक ढांचे की जगह अब निष्ठा और व्यक्तिगत वफादारी ने ले ली, जिससे कांग्रेस की कार्यशैली में स्थायी बदलाव आया।

50. (A) 1977 के चुनावों में पिछड़े वर्गों के मतदान का कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
1970 के दशक की राजनीति में पिछड़े वर्गों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी, इसलिए यह कहना गलत है कि उनके मतदान का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में, उत्तर भारत में जनता पार्टी की जीत में पिछड़ी जातियों के समर्थन का बड़ा हाथ था। इसी दौरान गैर-कांग्रेसवाद की भावना प्रबल हुई और विपक्षी दलों ने महसूस किया कि कांग्रेस को हराने के लिए मतों के बिखराव को रोकना और एकजुट होना अनिवार्य है।

51. (A) केवल 1, 2 और 3
1977 के चुनावों के बाद उत्तर भारत में पिछड़ी जातियों का राजनीतिक उभार स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, जिससे कई राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें बनीं। केंद्र सरकार ने इन वर्गों की स्थिति की जांच के लिए मंडल आयोग नियुक्त किया। हालांकि, बिहार जैसे राज्यों में आरक्षण के मुद्दे पर व्यापक विवाद और विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। मंडल आयोग का मुख्य उद्देश्य पिछड़ी जातियों के सामाजिक और शैक्षिक उत्थान के उपाय सुझाना था।

52. (D) क्योंकि संसद और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को लेकर एक संवैधानिक संघर्ष छिड़ा हुआ था।
आपातकाल की अवधि को संवैधानिक संकट इसलिए माना जाता है क्योंकि इस दौरान शासन के विभिन्न अंगों के बीच संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया था। सरकार और न्यायपालिका के बीच इस बात को लेकर निरंतर टकराव था कि संविधान के किस हिस्से में संशोधन किया जा सकता है और मौलिक अधिकारों की सीमा क्या है। सरकार ने संसद की शक्तियों का विस्तार करके न्यायपालिका की भूमिका को सीमित करने का प्रयास किया, जिससे एक गंभीर संवैधानिक गतिरोध पैदा हुआ।

53. (C) न्यायपालिका और सरकार के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध।
1967 के बाद भारतीय राजनीति में ध्रुवीकरण बढ़ा और इंदिरा गांधी एक शक्तिशाली नेता के रूप में उभरीं। हालांकि, इस दौरान न्यायपालिका और सरकार के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण होने के बजाय अत्यंत तनावपूर्ण हो गए थे। दोनों के बीच मौलिक अधिकारों, संपत्ति के अधिकार और संसद की संशोधन शक्ति को लेकर बार-बार विवाद हुए। इसलिए, सौहार्दपूर्ण संबंधों को इस कालखंड के बदलावों में शामिल नहीं किया जा सकता है।

54. (B) वह एक यथास्थितिवादी संस्था है और गरीबों को लाभ पहुँचाने वाले कार्यक्रमों में रोड़े अटका रही है।
1970 के दशक में कांग्रेस सरकार और न्यायपालिका के बीच गहरा वैचारिक मतभेद था। सरकार का आरोप था कि न्यायपालिका एक रुढ़िवादी संस्था के रूप में कार्य कर रही है जो सामाजिक बदलाव के पक्ष में नहीं है। सरकार का तर्क था कि अदालतों द्वारा संपत्ति के अधिकार को दी जा रही प्राथमिकता के कारण भूमि सुधार और गरीबी उन्मूलन जैसे प्रगतिशील कार्यक्रमों को लागू करने में बाधा उत्पन्न हो रही है।

55. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
1972-73 के दौरान मानसून की विफलता ने भारतीय कृषि को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे खाद्यान्न उत्पादन में आठ प्रतिशत की भारी कमी आई। उत्पादन में इस गिरावट ने न केवल कीमतों को बढ़ाया, बल्कि देश भर में आर्थिक संकट और असंतोष का माहौल भी पैदा कर दिया। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण, इस संकट ने आम नागरिकों के जीवन को कठिन बना दिया, जिससे सरकार विरोधी आंदोलनों को और बल मिला।

56. (A) उन्हें दबाने के लिए कठोर कदम उठाए।
पश्चिम बंगाल में सत्तर के दशक में सक्रिय मार्क्सवादी-लेनिनवादी समूहों, जिन्हें नक्सलवादी भी कहा जाता है, ने मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का रास्ता अपनाया था। इस उग्रवादी हिंसा और राज्यविरोधी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार ने अत्यंत कड़े सुरक्षात्मक और दमनकारी कदम उठाए। सरकार ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से इन समूहों के नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यापक पुलिस कार्रवाइयां की थीं।

57. (C) कांग्रेस चुनाव हार गई।
जून 1975 में गुजरात विधानसभा के चुनाव हुए, जो राज्य में लंबे समय तक चले छात्र आंदोलनों और राजनीतिक अस्थिरता के बाद आयोजित किए गए थे। इन चुनावों के परिणाम कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित हुए क्योंकि पार्टी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। विपक्षी दलों के गठबंधन ने जीत हासिल की, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि इंदिरा गांधी की लोकप्रियता और कांग्रेस का वर्चस्व क्षेत्रीय स्तर पर कमजोर हो रहा था।

58. (B) P-2, Q-4, R-1, S-3
भारतीय राजनीति के विभिन्न दौरों में नारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। डी.के. बरुआ ने इंदिरा गांधी के प्रति वफादारी दिखाते हुए 'इंडिया इज़ इंदिरा' का नारा दिया। 1977 के चुनावों में विपक्षी दलों ने 'लोकतंत्र बचाओ' के नारे पर जनता का समर्थन मांगा। वहीं, 1971 के चुनावों में इंदिरा गांधी ने 'गरीबी हटाओ' के वादे के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया था।

59. (D) यह देश की राजधानी में अब तक की सबसे बड़ी रैलियों में से एक थी।
1975 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में निकाला गया 'संसद मार्च' दिल्ली के राजनीतिक इतिहास की एक युगांतकारी घटना थी। इस रैली में देश भर से आए लाखों लोगों ने भाग लिया, जिससे यह राजधानी में आयोजित अब तक की सबसे विशाल जनसभाओं में से एक बन गई। इस मार्च ने विपक्ष की एकजुटता और सरकार के प्रति बढ़ते जन-आक्रोश को प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित किया, जिसने तत्कालीन सत्ता को हिलाकर रख दिया था।

60. (B) वे नेहरु मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे।
जयप्रकाश नारायण भारतीय राजनीति के एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने कभी सत्ता का पद स्वीकार नहीं किया। यद्यपि वे जवाहरलाल नेहरु के करीबी मित्र थे और नेहरु ने उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया था, लेकिन जेपी ने उसे ठुकरा दिया था। वे अपनी युवावस्था में मार्क्सवादी रहे, 1942 के आंदोलन में सक्रिय रहे और बाद में गांधीवादी बनकर सामाजिक परिवर्तन और छात्र आंदोलनों के प्रणेता बने।

61. (A) 1, 2, 3, 4
सत्तर के दशक की घटनाओं का कालक्रम भारतीय लोकतंत्र के लिए निर्णायक था। सबसे पहले 1973 में केशवानंद भारती मामले का फैसला आया। इसके बाद 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित किया। आपातकाल के दौरान 1976 में 42वां संविधान संशोधन पारित हुआ। अंततः 1977 में चुनावों के बाद पहली बार केंद्र में गैर-कांग्रेसी जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ।

62. (D) 1974 की रेल हड़ताल का सरकार द्वारा दमन।
न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच तनाव मुख्य रूप से संवैधानिक व्याख्याओं और शक्तियों के बँटवारे को लेकर था। संपत्ति के अधिकार, मौलिक अधिकारों में संशोधन की संसद

की क्षमता रखते हैं। इसने देश में गठबंधन राजनीति और दो-दलीय प्रतिस्पर्धा के बीज बोए थे।

122. (C) P-2, Q-1, R-4, S-3
सत्तर के दशक की राजनीति के प्रमुख पात्रों की भूमिकाएं अत्यंत महत्वपूर्ण थीं। राजनारायण ने समाजवादी नेता के रूप में इंदिरा गांधी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी। डी.के. बरुआ आपातकाल के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जगजीवन राम ने कांग्रेस छोड़कर 'कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी' बनाई, जबकि चौधरी चरण सिंह ने भारतीय लोकदल के माध्यम से किसानों की राजनीति को संगठित किया। इन सभी ने मिलकर 1977 के बड़े राजनीतिक परिवर्तन की पटकथा लिखने में योगदान दिया था।

123. (B) चुनावों में गैर-कांग्रेसी वोटों को बिखरने से रोकना और कांग्रेस को हराना।
गैर-कांग्रेसवाद की राजनीति का विचार डॉ. राममनोहर लोहिया ने दिया था, जो सत्तर के दशक में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। इसका मूल मंत्र यह था कि विपक्षी दलों को अपने वैचारिक मतभेद भुलाकर एकजुट होना चाहिए ताकि कांग्रेस के खिलाफ पड़ने वाले वोट आपस में न बंटें। विपक्षी नेताओं को विश्वास था कि यदि गैर-कांग्रेसी वोट एक ही स्थान पर एकत्रित हो जाएं, तो कांग्रेस को सत्ता से आसानी से हटाया जा सकता है, जो 1977 में सच साबित हुआ।

124. (B) केवल 2 और 4
1975 के आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था, जिससे वे अदालतों की शरण नहीं ले सकते थे। साथ ही, 42वें संशोधन के माध्यम से लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर छह वर्ष कर दिया गया था। यह आपातकाल बाहरी आक्रमण नहीं बल्कि आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था। शाह आयोग का गठन बाद में जनता पार्टी सरकार ने किया था, न कि आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस सरकार ने।

125. (A) क्योंकि दक्षिण में आपातकाल का असर और ज्यादतियां कम थीं।
1977 के चुनावों में जनता पार्टी को उत्तर भारत में तो भारी जीत मिली, लेकिन दक्षिण भारत में वह विफल रही। इसका मुख्य कारण यह था कि उत्तर भारत में नसबंदी और दमनकारी नीतियों का सीधा और कठोर प्रभाव पड़ा था, जिससे वहां तीव्र जन-आक्रोश था। दक्षिण के राज्यों में आपातकाल के दौरान ऐसी ज्यादतियां बहुत कम हुई थीं और वहां के लोग इंदिरा गांधी की नीतियों के प्रति अभी भी सहानुभूति रखते थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया।

126. (C) विधि के शासन (Rule of Law) के दायरे में।
संविधान निर्माताओं ने आपातकाल के प्रावधानों को अत्यंत विकट स्थितियों के लिए बनाया था। उन्हें यह विश्वास था कि संकट के समय सरकार को असाधारण शक्तियां दी जानी चाहिए, लेकिन सरकार इन शक्तियों का उपयोग कानून के शासन और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के भीतर रहकर ही करेगी। उनका मानना था कि आपातकाल के दौरान भी सरकार की कार्रवाई मनमानी नहीं होनी चाहिए और उसे अंततः संविधान और जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए।

127. (A) जो राजनीतिक कार्यकर्ता गिरफ्तारी से बच गए थे।
आपातकाल की घोषणा के बाद जब सरकार ने विपक्षी नेताओं की बड़े पैमाने पर धरपकड़ शुरु की, तो कई कार्यकर्ता छिप गए। इन 'भूमिगत' कार्यकर्ताओं ने गुप्त रूप से न्यूज़लेटर बांटे, सूचनाओं का आदान-प्रदान किया और सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ प्रतिरोध जारी रखा। उन्होंने जनता को जागरूक करने और आंदोलन की मशाल जलाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि उनके शीर्ष नेता जेलों में बंद थे। यह प्रतिरोध का एक साहसपूर्ण स्वरुप था।

128. (B) चरण सिंह, 4 महीने
मोरारजी देसाई की सरकार के पतन के बाद चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री पद संभाला। उन्हें कांग्रेस पार्टी ने बाहर से समर्थन देने का वादा किया था। हालांकि, यह गठबंधन बहुत ही अस्थिर और अल्पकालिक रहा। जैसे ही चरण सिंह ने संसद में अपना बहुमत साबित करने की तैयारी की, कांग्रेस ने ऐन वक्त पर अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके परिणामस्वरुप उनकी सरकार केवल चार महीने में ही गिर गई और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा।

129. (C) डी. के. बरुआ
"इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा" का नारा तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. बरुआ ने दिया था। यह नारा सत्तर के दशक की व्यक्ति-केंद्रित राजनीति और चाटुकारिता के चरमोत्कर्ष को दर्शाता है। इससे यह स्पष्ट होता था कि उस समय सत्ताधारी दल के भीतर पार्टी और देश का अस्तित्व पूरी तरह से एक ही नेता के व्यक्तित्व में समाहित माना जाने लगा था। इस प्रवृत्ति ने अंततः प्रधानमंत्री की शक्तियों को असीमित और निरंकुश बनाने में योगदान दिया।

130. (C) संस्था आधारित लोकतंत्र और जन-भागीदारी के बीच तनाव का मसला।
आपातकाल के दौर ने एक गंभीर बहस को जन्म दिया कि लोकतंत्र में निर्वाचित संस्थाओं (जैसे संसद) और सड़कों पर होने वाले जन-आंदोलनों के बीच क्या संबंध होना चाहिए। जहाँ सरकार का मानना था कि जन-आंदोलन लोकतांत्रिक स्थिरता के लिए खतरा हैं, वहीं विपक्षी कार्यकर्ताओं का तर्क था कि जनता की सक्रिय भागीदारी ही लोकतंत्र की सुरक्षा का एकमात्र उपाय है। यह तनाव भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति और सीमाओं को समझने के लिए आज भी प्रासंगिक है।

131. (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
1980 के चुनाव परिणामों ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय मतदाता राजनीतिक स्थिरता को सबसे अधिक महत्व देते हैं। जनता पार्टी की सरकार में जारी अंतहीन कलह और नेतृत्व के संकट ने आम जनता को निराश कर दिया था। मतदाताओं ने महसूस किया कि गठबंधन सरकार देश चलाने में सक्षम नहीं है। इसी निराशा के कारण उन्होंने एक मजबूत और स्थिर

दौरान हुए थे। यह चुनाव केवल राजनीतिक दलों की हार-जीत नहीं, बल्कि तानाशाही के विरुद्ध लोकतंत्र की जीत का प्रतीक बन गया था।

73. (C) यह सुनिश्चित हो गया कि गैर-कांग्रेसी वोट एक ही जगह पड़ेंगे।
1977 के चुनावों से पहले विपक्षी दलों ने यह महसूस किया कि यदि वे अलग-अलग चुनाव लड़ेंगे तो गैर-कांग्रेसी वोट आपस में बंट जाएंगे, जिससे कांग्रेस को लाभ होगा। इसी बिखराव को रोकने के लिए उन्होंने 'जनता पार्टी' के रूप में एक साझा मंच बनाया। इस रणनीतिक एकता के कारण मतदाताओं के पास कांग्रेस के खिलाफ एक सशक्त और एकजुट विकल्प मौजूद था, जिसने अंततः विपक्षी गठबंधन की जीत सुनिश्चित की।

74. (A) दक्षिण भारत में आपातकाल का प्रभाव हर राज्य पर एकसमान नहीं पड़ा था।
1977 के चुनाव परिणामों में उत्तर और दक्षिण भारत के बीच का अंतर आपातकाल के असमान प्रभाव को दर्शाता है। उत्तर भारत में जबरन नसबंदी और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों के कारण जनता में तीव्र आक्रोश था, जिससे कांग्रेस को भारी हार झेलनी पड़ी। इसके विपरीत, दक्षिण भारत में आपातकाल की सख्ती कम महसूस की गई थी और वहां कांग्रेस के कल्याणकारी कार्यक्रमों का सकारात्मक प्रभाव बना रहा, जिससे उसकी पकड़ मजबूत रही।

75. (A) केवल 1, 2 और 3
जनता पार्टी की सरकार का गठन विभिन्न विचारधाराओं वाले दलों के मेल से हुआ था, जिसके कारण उनके बीच आपसी तालमेल की भारी कमी थी। प्रधानमंत्री पद के लिए शीर्ष नेताओं के बीच लगातार होड़ बनी रही, जिससे शासन की स्थिरता प्रभावित हुई। हालांकि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन आंतरिक खींचतान कभी समाप्त नहीं हुई। अंततः नीतियों में किसी बुनियादी बदलाव के अभाव और अंतर्कलह के कारण यह सरकार समय से पहले गिर गई।

76. (B) 4 महीने
मोरारजी देसाई की सरकार गिरने के बाद चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री पद संभाला। उनकी सरकार कांग्रेस पार्टी के बाहरी समर्थन पर टिकी हुई थी, लेकिन यह गठबंधन बहुत ही अस्थिर साबित हुआ। कांग्रेस ने केवल चार महीने के भीतर ही अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके कारण चरण सिंह को संसद का सामना किए बिना ही इस्तीफा देना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप देश को 1980 में मध्यावधि चुनावों की ओर बढ़ना पड़ा।

77. (C) इंदिरा गाँधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने भारी सफलता हासिल की।
1980 के लोकसभा चुनावों में देश की जनता ने जनता पार्टी की अस्थिरता और आपसी विवादों को पूरी तरह नकार दिया। मतदाताओं ने एक स्थिर शासन की इच्छा जताते हुए इंदिरा गांधी को प्रचंड जनादेश दिया। कांग्रेस पार्टी ने 353 सीटें जीतकर सत्ता में जोरदार वापसी की। इस चुनाव परिणाम ने यह स्पष्ट कर दिया कि जनता विभाजित और कमजोर गठबंधन के बजाय एक मजबूत और अनुभवी नेतृत्व को प्राथमिकता देती है।

78. (D) पिछड़ी जातियों की भलाई का मुद्दा
1977 के चुनाव परिणामों के बाद भारतीय राजनीति में पिछड़ी जातियों की भूमिका एक प्रमुख विमर्श बनकर उभरी। उत्तर भारत में जनता पार्टी की जीत में इन वर्गों की लामबंदी का विशेष महत्व था। इसी सामाजिक जागृति के परिणामस्वरूप आरक्षण और पिछड़ी जातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग तेज हुई, जिसने आने वाले दशकों में भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। इसने पिछड़ी जातियों को सत्ता के केंद्र में लाने के द्वार खोल दिए।

79. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
आपातकाल का दौर भारतीय लोकतंत्र के लिए एक दोहरा संकट था क्योंकि इसमें संवैधानिक प्रावधानों का प्रयोग करके ही लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया गया। इस अवधि में निर्वाचित संस्थाओं और सड़कों पर होने वाली जन-भागीदारी के बीच एक गहरा विरोधाभास प्रकट हुआ। जहाँ सरकार संस्थागत ढांचे पर नियंत्रण कर रही थी, वहीं जनता का विरोध स्वतःस्फूर्त आंदोलनों के रूप में सामने आया, जिससे लोकतंत्र के वास्तविक स्वरूप पर एक बड़ी बहस छिड़ गई।

80. (B) पिछड़ी जातियों की राजनीति की भूमिका से
जनता पार्टी सरकार द्वारा नियुक्त मंडल आयोग का मुख्य कार्य देश में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों की पहचान करना और उनकी स्थिति सुधारने के लिए सिफारिशें देना था। इस आयोग की नियुक्ति पिछड़ी जातियों के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव का परिणाम थी। हालांकि इसके कार्यान्वयन में लंबा समय लगा, लेकिन इसने भारतीय राजनीति में आरक्षण और जाति-आधारित सशक्तिकरण के मुद्दे को स्थायी रूप से राष्ट्रीय एजेंडे में स्थापित कर दिया।

81. (B) लगभग 80 लाख शरणार्थी भारत आए, जिससे अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ा।
1971 के बांग्लादेश संकट ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर अप्रत्याशित वित्तीय दबाव डाला। पूर्वी पाकिस्तान से अपनी जान बचाकर आए लगभग अस्सी लाख शरणार्थियों को शरण देना, उनके भोजन और स्वास्थ्य की व्यवस्था करना एक बड़ी मानवीय और आर्थिक चुनौती थी। इस भारी खर्च के कारण देश के विकास कार्यों के लिए उपलब्ध संसाधनों में कमी आई, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ी और आम जनता की आर्थिक स्थिति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

82. (D) विभिन्न चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ीं।
1973 के अंतर्राष्ट्रीय तेल संकट ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह झकझोर दिया। तेल की कीमतों में हुई अचानक और भारी बढ़ोतरी के कारण परिवहन और उत्पादन लागत में अभूतपूर्व इजाफा हुआ। इसके परिणामस्वरूप दैनिक उपभोग की वस्तुओं और आवश्यक सामग्रियों के दाम आसमान छूने लगे। इस तीव्र महंगाई ने आम नागरिकों के बजट को बिगाड़ दिया और सरकार

के खिलाफ देशव्यापी आर्थिक असंतोष और विरोध प्रदर्शनों के लिए मंच तैयार किया।

83. (D) सरकार ने खर्चे को कम करने के लिए उनके वेतन को रोक लिया था।
1972-73 के दौरान गंभीर आर्थिक संकट और महंगाई से जूझ रही सरकार ने अपने खर्चों को नियंत्रित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के वेतन के एक हिस्से को अनिवार्य रूप से रोकने का निर्णय लिया। इस कदम का उद्देश्य बाजार में मुद्रा की आपूर्ति कम करके महंगाई पर काबू पाना था। हालांकि, इस नीति ने सरकारी कर्मचारियों के बीच भारी असंतोष पैदा किया, क्योंकि उनकी वास्तविक आय महंगाई के कारण पहले ही कम हो रही थी।

84. (B) P-3, Q-1, R-2, S-4
सत्तर के दशक की आर्थिक समस्याओं के गंभीर परिणाम सामने आए। बांग्लादेश संकट के कारण अस्सी लाख शरणार्थी भारत आए। 1972-73 में मानसून की विफलता से खाद्यान्न उत्पादन में आठ प्रतिशत की कमी आई। अंतर्राष्ट्रीय तेल संकट के कारण महंगाई बढ़ी और 1974 तक वस्तुओं की कीमतों में लगभग तीस प्रतिशत का इजाफा हुआ। इन परस्पर जुड़ी घटनाओं ने सामूहिक रूप से देश में एक गंभीर आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता पैदा कर दी थी।

85. (D) राज्य में नए सिरे से चुनाव नहीं करवाए जाने की स्थिति में।
गुजरात में छात्र आंदोलनों और राजनीतिक अस्थिरता के बाद विधानसभा को भंग कर दिया गया था, लेकिन केंद्र सरकार नए चुनाव कराने में देरी कर रही थी। मोरारजी देसाई ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि चुनाव नहीं कराए गए तो वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। उनके इस कड़े रुख और बढ़ते जन-दबाव के कारण सरकार को अंततः जून 1975 में गुजरात में नए चुनाव कराने पड़े।

86. (C) केवल 1, 2 और 3
जयप्रकाश नारायण काफी समय से सक्रिय राजनीति से दूर थे, लेकिन छात्रों के विशेष आग्रह पर उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। उन्होंने न केवल बिहार की तत्कालीन कांग्रेस सरकार को हटाने की मांग की, बल्कि संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जिसका लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में पूर्ण परिवर्तन लाना था। उनके नेतृत्व ने इस स्थानीय छात्र असंतोष को एक बड़े राष्ट्रीय जन-आंदोलन में बदलकर सरकार के समक्ष गंभीर चुनौती खड़ी कर दी।

87. (D) बोनस और सेवा से जुड़ी शर्तों के संबंध में अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाना।
1974 की रेल हड़ताल का आयोजन मुख्य रूप से रेलवे कर्मचारियों की आर्थिक मांगों और कार्य परिस्थितियों में सुधार के लिए किया गया था। कर्मचारी अपने वेतन में वृद्धि, बोनस के अधिकार और बेहतर सेवा शर्तों की मांग कर रहे थे। चूंकि रेलवे देश की जीवन रेखा है, इसलिए इस हड़ताल ने सरकार पर व्यापक दबाव बनाया। हालांकि, सरकार ने इन मांगों को स्वीकार करने के बजाय आंदोलन को सख्ती से कुचलने का मार्ग चुना।

88. (A) क्योंकि सरकार ने तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अनदेखी की थी।
1973 में न्यायमूर्ति ए.एन. रे की मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति एक अत्यंत विवादास्पद घटना थी क्योंकि इसने न्यायपालिका की स्थापित परंपरा को तोड़ा था। सरकार ने उनसे वरिष्ठ तीन न्यायाधीशों को दरकिनार कर दिया था, जिन्होंने हाल ही में सरकार की नीतियों के खिलाफ फैसले दिए थे। इस कदम को न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम करने और न्यायाधीशों को सरकार के प्रति वफादार बनाने के प्रयास के रूप में व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा।

89. (D) उन्होंने चुनाव-प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया था।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के 1971 के निर्वाचन को अवैध घोषित करने का फैसला सुनाया। इस फैसले का मुख्य आधार यह था कि उन्होंने अपने चुनावी अभियान के दौरान सरकारी मशीनरी और अधिकारियों का उपयोग किया था, जो जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत भ्रष्ट आचरण माना जाता है। इस निर्णय ने इंदिरा गांधी की कानूनी पात्रता पर सवाल खड़े किए और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर देशव्यापी प्रदर्शनों को जन्म दिया।

90. (A) नहीं, मंत्रिमंडल को 26 जून की सुबह केवल सूचना दी गई, जब तक सब कुछ हो चुका था।
25 जून 1975 की रात को आपातकाल लागू करने का निर्णय अत्यंत गोपनीय तरीके से लिया गया था। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को सीधे सिफारिश भेजी और इस पर मंत्रिमंडल के साथ कोई पूर्व परामर्श नहीं किया गया। मंत्रिमंडल के सदस्यों को इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी अगली सुबह एक विशेष बैठक में दी गई, तब तक आपातकाल लागू हो चुका था और प्रमुख विपक्षी नेताओं को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था।

91. (A) 1, 2, 3, 4
1970 के दशक का राजनीतिक संकट एक क्रमिक प्रक्रिया थी। सबसे पहले जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान कर जन-आंदोलन शुरु किया। इसके बाद 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया। इस फैसले के विरोध में जेपी ने रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। इस बढ़ते दबाव और अस्थिरता को रोकने के लिए सरकार ने अंततः 25 जून की रात को आपातकाल की घोषणा कर दी।

92. (B) उन्होंने अपनी-अपनी पदवी (पद्मश्री और पद्मभूषण) लौटा दी।
आपातकाल के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगे प्रतिबंधों और लोकतंत्र के दमन के विरोध में कई बुद्धिजीवियों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। प्रसिद्ध लेखक फणीश्वरनाथ 'रेणु' ने अपना पद्मश्री पुरस्कार और कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत

ने अपना पद्मभूषण सम्मान सरकार को वापस कर दिया। यह उनके द्वारा किया गया एक नैतिक और प्रतीकात्मक प्रतिरोध था, जिसने यह संदेश दिया कि नागरिक सम्मानों से अधिक महत्वपूर्ण देश का लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है।

93. (B) आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को लिखित में देनी होगी।
1975 के आपातकाल के दौरान शक्तियों के व्यक्तिगत दुरुपयोग को देखते हुए, बाद में संविधान में सुरक्षा उपाय जोड़े गए। अब यह अनिवार्य कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री अकेले आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते। राष्ट्रपति को ऐसी उद्घोषणा केवल तभी करनी चाहिए जब पूरे मंत्रिमंडल द्वारा उसे लिखित में ऐसी सलाह दी गई हो। इस संशोधन का उद्देश्य भविष्य में किसी भी प्रधानमंत्री को मनमाने ढंग से आपातकाल लगाने से रोकना है।

94. (B) उन्हें शासक दल ने अपना राजनीतिक औजार बनाकर इस्तेमाल किया।
शाह आयोग की जांच रिपोर्ट ने यह उजागर किया कि आपातकाल के दौरान पुलिस और प्रशासनिक तंत्र अपनी निष्पक्षता खो चुका था। आयोग ने पाया कि सरकारी अधिकारियों और पुलिस बल को सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक हितों को साधने के लिए विवश किया गया। अधिकारियों ने कानून के बजाय राजनेताओं के मौखिक निर्देशों का पालन किया, जिससे नागरिकों पर अत्याचार हुए। यह स्वतंत्र भारत में नौकरशाही के राजनीतिकरण का एक काला अध्याय बनकर उभरा।

95. (B) कांग्रेस उत्तर भारत में पूरी तरह हार गई लेकिन दक्षिण भारत में उसकी स्थिति मजबूत रही।
1977 के चुनाव परिणामों ने भारत का एक दिलचस्प भौगोलिक राजनीतिक विभाजन दिखाया। उत्तर भारत में आपातकाल की ज्यादतियों, जैसे जबरन नसबंदी और दमन के कारण कांग्रेस का लगभग सूपड़ा साफ हो गया। इसके विपरीत, दक्षिण भारतीय राज्यों में आपातकाल का असर उतना तीव्र नहीं था और वहां कांग्रेस की कल्याणकारी योजनाओं ने पार्टी की लोकप्रियता को बचाए रखा। इस प्रकार, क्षेत्रीय अनुभवों ने मतदाताओं के फैसले को अलग-अलग दिशाओं में प्रभावित किया था।

96. (A) केवल 1, 4 और 5
जनता पार्टी की सरकार का अनुभव नेतृत्व के संघर्ष और अस्थिरता का उदाहरण है। यह कहना गलत है कि इस सरकार ने पांच साल का कार्यकाल पूरा किया या इसमें नेतृत्व को लेकर विवाद नहीं था। वास्तव में, मोरारजी देसाई अठ्ठाइस महीने में ही बहुमत खो बैठे और चरण सिंह ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, जो बहुत जल्द गिर गई। जनता पार्टी के भीतर सत्ता की खींचतान और साझा कार्यक्रम के अभाव ने इसे विफल कर दिया।

97. (B) जनता पार्टी सरकार की अस्थिरता और पतन।
1980 के मध्यावधि चुनावों का मुख्य कारण जनता पार्टी के भीतर का अंतहीन नेतृत्व संघर्ष और गठबंधन की विफलता थी। मोरारजी देसाई और चरण सिंह के बीच की प्रतिस्पर्धा ने सरकार को पंगु बना दिया, जिससे जनता में सरकार की कार्यक्षमता के प्रति विश्वास समाप्त हो गया। जब वैकल्पिक सरकारें भी बहुमत साबित करने में विफल रहीं, तो मतदाताओं के पास एक नया जनादेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, जिससे इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हुई।

98. (D) पिछड़ी जातियों का आरक्षण और राजनीतिक भूमिका
1977 के बाद भारतीय राजनीति में पिछड़ी जातियों का मुद्दा एक शक्तिशाली सामाजिक-राजनीतिक धारा के रूप में उभरा। जनता पार्टी की जीत में पिछड़ी जातियों के समर्थन ने यह साबित कर दिया कि वे एक महत्वपूर्ण चुनावी ताकत हैं। इसी चेतना के कारण मंडल आयोग की नियुक्ति हुई और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की मांग ने राष्ट्रीय स्तर पर जोर पकड़ा। इसने भविष्य की भारतीय राजनीति को जाति-आधारित ध्रुवीकरण और सशक्तिकरण की ओर मजबूती से मोड़ दिया।

99. (B) कि सत्ताधारी दल द्वारा बहुमत होते हुए भी लोकतंत्र को ठप्प करना एक गहरा राजनीतिक संकट था।
यह कथन इस तथ्य को रेखांकित करता है कि आपातकाल केवल एक कानूनी या संवैधानिक प्रावधान का उपयोग नहीं था, बल्कि यह लोकतांत्रिक नैतिकता का पतन था। जब एक विशाल बहुमत वाली चुनी हुई सरकार स्वयं ही लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और विपक्ष की आवाज़ को पूरी तरह दबाने लगे, तो वह स्थिति देश के राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक होती है। यह संकट दिखाता है कि बहुमत का अर्थ निरंकुशता नहीं होना चाहिए और लोकतंत्र संस्थाओं से अधिक मूल्यों पर आधारित है।

100. (A) संस्था आधारित लोकतंत्र और जन-भागीदारी पर आधारित लोकतंत्र के बीच तनाव।
आपातकाल के दौरान यह मौलिक प्रश्न उठा कि क्या केवल निर्वाचित संसद ही लोकतंत्र का एकमात्र आधार है या जनता के पास सीधे आंदोलनों के माध्यम से सरकार का विरोध करने का अधिकार है। सरकार का तर्क था कि सड़कों पर विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र को बाधित करते हैं, जबकि विपक्षी आंदोलनों का मानना था कि जन-भागीदारी ही लोकतंत्र की आत्मा है। यह तनाव भारतीय राजनीति में जन आंदोलनों की सीमा और महत्ता को समझने का एक महत्वपूर्ण बिंदु बन गया।

101. (B) देश में गंभीर संकट की घड़ी आन पड़ी है और गड़बड़ी की आशंका है।
1975 में आपातकाल लागू करते समय सरकार ने तर्क दिया कि विपक्ष द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों और सत्याग्रहों के कारण देश में अराजकता फैल रही है। सरकार का दावा था कि विपक्षी दल संवैधानिक तरीके से चुनी गई सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं और आंतरिक गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। इसी कथित खतरे और शांति व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर सरकार ने असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपातकाल लागू किया था।

की शक्ति और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता की अनदेखी जैसे मुद्दों ने इस संघर्ष को गहराया। हालांकि, 1974 की रेल हड़ताल का दमन सरकार की एक प्रशासनिक और राजनीतिक कार्रवाई थी, जिसका न्यायपालिका के साथ सीधे संस्थागत तनाव से कोई संबंध नहीं था।

63. (A) सरकार ने हड़तालियों की सभी मांगें मान लीं।
1974 की ऐतिहासिक रेल हड़ताल का अंत कर्मचारियों के लिए सुखद नहीं रहा था। सरकार ने हड़तालियों की मांगों के प्रति अत्यंत कठोर रुख अपनाया और किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। अंततः बीस दिनों तक चले इस व्यापक आंदोलन को बिना किसी मांग के पूरे हुए, बिना शर्त वापस लेना पड़ा। सरकार ने इसे दबाने के लिए बल प्रयोग किया और हजारों कर्मचारियों की सेवाएं प्रभावित हुई थीं।

64. (B) 25 जून 1975 की रात
25 जून 1975 की रात को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को देश में आपातकाल लागू करने की औपचारिक सिफारिश भेजी। यह निर्णय इतनी गोपनीयता और हड़बड़ी में लिया गया था कि मंत्रिमंडल को भी इसकी पूर्व जानकारी नहीं दी गई थी। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के तुरंत बाद, उसी रात से प्रमुख विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी और प्रेस सेंसरशिप की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी।

65. (B) सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को बदल दिया गया।
आपातकाल की घोषणा के तुरंत बाद सरकार ने मीडिया पर नियंत्रण करने के लिए अखबारों की बिजली काटी और विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया। अगली सुबह मंत्रिमंडल को केवल सूचित किया गया। हालांकि, सरकार ने उस समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सामूहिक रूप से बदलने जैसा कोई कदम नहीं उठाया था। अदालतों की शक्तियों को सीमित करने का प्रयास बाद में विभिन्न संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से किया गया था।

66. (C) केवल 1, 3 और 4
आपातकाल एक ऐसी असाधारण स्थिति है जिसमें देश का संघीय ढांचा केंद्र के अधीन हो जाता है और सारी शक्तियां संघ के पास आ जाती हैं। 1975 में आपातकाल लागू होते ही प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई और अखबारों की बिजली काट दी गई। हालांकि, संविधान के प्रावधानों के अनुसार आपातकाल के दौरान सरकार मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकती है, इसलिए यह कहना गलत है कि उन पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

67. (C) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और जमात-ए-इस्लामी
आपातकाल के दौरान सरकार ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन संगठनों को निशाना बनाया जिनसे उसे सामाजिक अशांति या संगठित विरोध का खतरा महसूस हुआ। इसी रणनीति के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकार का तर्क था कि ये संस्थाएं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सकती हैं। इसके परिणामस्वरूप इन संगठनों के हजारों कार्यकर्ताओं को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया था।

68. (D) अनेक न्यूज़लेटर और लीफ़लेट्स
प्रेस सेंसरशिप के बावजूद, सूचनाओं के प्रसार और विरोध की आवाज को जीवित रखने के लिए कई भूमिगत प्रयास किए गए। राजनीतिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों ने गुप्त रूप से न्यूज़लेटर और लीफ़लेट्स प्रकाशित किए जो जनता के बीच वितरित किए जाते थे। इन माध्यमों से सेंसर की गई खबरों और आंदोलन की प्रगति के बारे में जानकारी साझा की जाती थी, जिससे सरकार द्वारा थोपी गई खामोशी को चुनौती दी जा सके और प्रतिरोध बना रहे।

69. (C) इनके निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी।
42वें संविधान संशोधन के माध्यम से सरकार ने उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के निर्वाचन को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर दिया। इसके अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव परिणामों को किसी भी अदालत में चुनौती देने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। यह कदम मुख्य रूप से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले की प्रतिक्रिया में उठाया गया था जिसने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को अवैध करार दिया था।

70. (B) अदालतों (न्यायपालिका) ने
आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों के हनन के कड़वे अनुभवों के बाद, अदालतों के दृष्टिकोण में एक बड़ा बदलाव आया। आपातकाल समाप्त होने के पश्चात, न्यायपालिका ने स्वयं को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के सजग प्रहरी के रूप में स्थापित किया। अदालतों ने जनहित याचिकाओं और सक्रिय हस्तक्षेप के माध्यम से यह सुनिश्चित करना शुरु किया कि भविष्य में सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर नागरिकों के बुनियादी अधिकारों का हनन न कर सके।

71. (D) जगजीवन राम - 1977 में कांग्रेस के अध्यक्ष
1977 के राजनीतिक घटनाक्रम में जगजीवन राम की भूमिका कांग्रेस अध्यक्ष की नहीं, बल्कि एक विद्रोही नेता की थी। उन्होंने आपातकाल के बाद कांग्रेस छोड़कर 'कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी' नामक अपनी अलग पार्टी बनाई थी। मोरारजी देसाई जनता पार्टी की पहली सरकार के प्रधानमंत्री थे और चरण सिंह भारतीय लोकदल के प्रमुख थे। जयप्रकाश नारायण बिहार आंदोलन और संपूर्ण क्रांति के सूत्रधार थे, जिन्होंने विपक्षी एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

72. (A) आपातकाल के अनुभवों के बारे में
1977 के लोकसभा चुनावों को अक्सर आपातकाल पर एक जनमत-संग्रह माना जाता है क्योंकि मतदाताओं के सामने सबसे बड़ा मुद्दा पिछले उन्नीस महीनों का शासन था। लोगों ने वोट के जरिए उन ज्यादतियों, जबरन नसबंदी और नागरिक अधिकारों के दमन के प्रति अपना फैसला सुनाया जो आपातकाल के

112. (A) रायबरेली
1977 के लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी को अपनी पारंपरिक निर्वाचन सीट रायबरेली से करारी हार का सामना करना पड़ा। उन्हें जनता पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण ने पराजित किया था। यह हार न केवल उनके लिए व्यक्तिगत रुप से अपमानजनक थी, बल्कि यह आपातकाल की नीतियों के खिलाफ जनता के तीव्र आक्रोश का सबसे बड़ा प्रमाण भी थी। देश की प्रधानमंत्री का चुनाव हार जाना भारतीय संसदीय इतिहास की एक अत्यंत विरल और महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है।

113. (A) 2, 1, 3, 4
राजनीतिक घटनाओं का सही क्रम आपातकाल से शुरु होता है। सबसे पहले 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई। इसके समापन के बाद 1977 में विभिन्न विपक्षी दलों ने एकजुट होकर जनता पार्टी का गठन किया। उसी वर्ष जनता पार्टी सत्ता में आई, लेकिन आंतरिक विवादों के कारण मोरारजी देसाई सरकार का पतन हुआ। इसके परिणामस्वरूप 1980 में मध्यावधि चुनाव आयोजित किए गए, जिसमें कांग्रेस की सत्ता में फिर से वापसी हुई।

114. (C) इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला और उसके बाद की राजनीतिक घटनाएं।
आपातकाल की घोषणा का सबसे तात्कालिक राजनीतिक कारण 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला था। अदालत ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था, जिससे उनके प्रधानमंत्री पद पर बने रहने पर कानूनी संकट पैदा हो गया। विपक्षी दलों ने उनके इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ा दिया और दिल्ली में बड़ी रैलियां कीं। इस बढ़ते राजनीतिक दबाव और सत्ता खोने के डर ने सरकार को आपातकाल लगाने हेतु प्रेरित किया।

115. (A) केवल 1, 2 और 4
1971 के बाद देश में आर्थिक सुधारों के दावे के विपरीत वास्तविकता बहुत कठिन थी। बांग्लादेश संकट और शरणार्थियों के बोझ ने अर्थव्यवस्था को जर्जर कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप 1973-74 में महंगाई दर तीस प्रतिशत तक पहुंच गई, जिसने आम जनता की कमर तोड़ दी। औद्योगिक विकास की दर भी बहुत धीमी रही, जिससे बेरोजगारी की समस्या और विकराल हो गई। इन प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों ने ही सरकार विरोधी आंदोलनों के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की थी।

116. (D) फखरुद्दीन अली अहमद
1975 में जब देश में आपातकाल लागू किया गया, तब फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे। उन्होंने 25 जून की रात को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर आपातकाल की उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। उनकी भूमिका को लेकर बाद में कई सवाल उठे क्योंकि उन्होंने बिना मंत्रिमंडल के परामर्श के केवल प्रधानमंत्री के कहने पर इतनी बड़ी संवैधानिक कार्रवाई को मंजूरी दे दी थी, जो उस समय के राजनीतिक माहौल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।

117. (C) आपातकाल का लगाया जाना और उसके दौरान हुई ज्यादतियां
1977 के चुनावों में कांग्रेस की अभूतपूर्व हार का मुख्य कारण आपातकाल के दौरान किए गए दमनकारी कार्य थे। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का निलंबन, विपक्षी नेताओं की सामूहिक गिरफ्तारी, प्रेस पर सेंसरशिप और विशेष रूप से उत्तर भारत में चलाए गए जबरन नसबंदी कार्यक्रमों ने जनता के मन में गहरा आक्रोश भर दिया था। मतदाताओं ने इन ज्यादतियों के खिलाफ अपनी नाराजगी जताने के लिए वोट को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था।

118. (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
आपातकाल के बाद हुए संवैधानिक संशोधनों का उद्देश्य भविष्य में ऐसी स्थितियों की पुनरावृत्ति को रोकना था। 'आंतरिक गड़बड़ी' शब्द अत्यंत व्यापक और अस्पष्ट था, जिसका राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग करना आसान था। इसे बदलकर 'सशस्त्र विद्रोह' करने से यह सुनिश्चित हो गया कि अब केवल किसी नागरिक आंदोलन या विरोध प्रदर्शन के आधार पर आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए अब वास्तविक और हिंसक विद्रोह का होना एक अनिवार्य कानूनी शर्त बन गया है।

119. (B) इंदिरा गाँधी
1969 के कांग्रेस विभाजन के बाद पार्टी का संगठनात्मक ढांचा पूरी तरह बदल गया और वह पूरी तरह से इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व पर केंद्रित हो गई। उन्होंने पार्टी के भीतर के पुराने सिंडिकेट नेताओं को चुनौती दी और अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी लोकप्रियता और समाजवादी नारों ने उन्हें पार्टी का एकमात्र सर्वोच्च नेता बना दिया। इसके परिणामस्वरूप कांग्रेस एक संस्थागत दल के बजाय एक व्यक्ति-केंद्रित संगठन में तब्दील हो गई, जहाँ उनकी मर्जी ही सर्वोपरि थी।

120. (D) कांग्रेस (आई)
1977 में जनता पार्टी का गठन कई गैर-कांग्रेसी दलों के विलय से हुआ था, जिनमें भारतीय जनसंघ, कांग्रेस (ओ), सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय लोकदल प्रमुख थे। इनका एकमात्र उद्देश्य इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस (आई) को सत्ता से हटाना था। कांग्रेस (आई) ही वह सत्ताधारी दल था जिसके खिलाफ जनता पार्टी ने गठबंधन किया था, इसलिए वह इसका हिस्सा नहीं हो सकती थी। यह चुनाव वास्तव में कांग्रेस (आई) बनाम संपूर्ण विपक्ष का मुकाबला बन गया था।

121. (B) इसने पहली बार केंद्र में एक गैर-कांग्रेसी सरकार का मार्ग प्रशस्त किया।
1977 के चुनाव परिणाम भारतीय दलीय व्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आए। आजादी के बाद पहली बार केंद्र में कांग्रेस के प्रभुत्व का अंत हुआ और एक गैर-कांग्रेसी गठबंधन ने सत्ता संभाली। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि भारत में एक वैकल्पिक दलीय व्यवस्था संभव है और मतदाता किसी भी शक्तिशाली दल को सत्ता से बेदखल करने

102. (C) P-3, Q-4, R-1, S-2
सत्तर के दशक की प्रमुख घटनाएं भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। 1974 में जॉर्ज फर्नान्डिस के नेतृत्व में रेल हड़ताल हुई। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई जिसने नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया। अंततः 1977 में हुए ऐतिहासिक लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को पहली बार हार का स्वाद चखना पड़ा और सत्ता परिवर्तन हुआ।

103. (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
जनता पार्टी की सरकार का पतन मुख्य रूप से उसके आंतरिक अंतर्विरोधों का परिणाम था। यह पार्टी अलग-अलग विचारधाराओं और प्रतिद्वंद्वी नेताओं का एक समूह मात्र थी, जिनके बीच सत्ता के लिए निरंतर संघर्ष चलता रहा। उनके पास देश को चलाने के लिए न तो कोई स्पष्ट साझा कार्यक्रम था और न ही एक सर्वसम्मत नेतृत्व। इसी एकजुटता के अभाव और नेतृत्व की खींचतान ने अठ्ठाइस महीने के भीतर ही इस ऐतिहासिक गठबंधन को पूरी तरह बिखेर दिया।

104. (D) खाद्यान्न, खाद्य तेल की बढ़ती कीमत और भ्रष्टाचार
जनवरी 1974 में गुजरात के छात्रों ने मुख्य रूप से आर्थिक समस्याओं और प्रशासनिक अनियमितताओं के खिलाफ विद्रोह किया था। उस समय खाद्य वस्तुओं और खाना पकाने के तेल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो गई थी, जिससे आम जनता का जीवन दूभर हो गया था। छात्रों ने इन महंगाई के मुद्दों को सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के साथ जोड़कर एक सशक्त जन-आंदोलन खड़ा किया, जिसने अंततः राज्य की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के पतन का मार्ग प्रशस्त किया।

105. (A) जयप्रकाश नारायण
जयप्रकाश नारायण ने 'संपूर्ण क्रांति' का विचार पेश किया, जिसका उद्देश्य समाज के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करना था। उनका मानना था कि केवल चुनाव जीतना या सरकार बदलना पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक सच्चे और जीवंत लोकतंत्र की स्थापना के लिए भ्रष्टाचार मुक्त समाज और जन-सशक्तिकरण अनिवार्य है। उनके इस क्रांतिकारी आह्वान ने ही आपातकाल के विरुद्ध चल रहे छात्र आंदोलन को एक व्यापक राष्ट्रीय स्वरूप और नैतिक आधार प्रदान किया था।

106. (C) केवल 1, 2 और 3
1970 के दशक की शुरुआत में वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में भारी उछाल आया, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा और महंगाई तेजी से बढ़ी। साथ ही, 1971 के युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा आर्थिक सहायता बंद किए जाने से स्थिति और बिगड़ गई। औद्योगिक विकास की दर भी उस समय काफी धीमी थी। इन सभी आर्थिक कारकों ने सामूहिक रूप से देश में व्यापक जन-असंतोष पैदा किया, जिसने तत्कालीन राजनीतिक अस्थिरता को और अधिक बढ़ावा दिया।

107. (C) नौकरशाही का शासक दल की विचारधारा के अनुकूल आचरण करना।
प्रतिबद्ध नौकरशाही की अवधारणा का अर्थ है कि प्रशासनिक अधिकारियों को केवल नियमों का पालन करने वाला तटस्थ सेवक नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें सत्तारुढ़ दल के सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति समर्पित होना चाहिए। यह विचार सत्तर के दशक में काफी चर्चा में रहा, जहाँ सरकार चाहती थी कि नौकरशाही उसकी नीतियों को बिना किसी विरोध के सक्रिय रूप से लागू करे। यह नौकरशाही की पारंपरिक निष्पक्षता और राजनीतिक तटस्थता के सिद्धांत के विपरीत था।

108. (A) जयप्रकाश नारायण
मार्च 1975 में जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली में ऐतिहासिक 'संसद मार्च' का नेतृत्व किया था। यह राजधानी में आयोजित अब तक के सबसे बड़े राजनीतिक प्रदर्शनों में से एक था, जिसमें देश भर से लाखों लोगों ने भाग लिया था। इस मार्च का उद्देश्य सरकार के भ्रष्टाचार और तानाशाही रवैये के खिलाफ जन-आक्रोश को प्रदर्शित करना और लोकतांत्रिक सुधारों की मांग करना था। इस आयोजन ने जेपी को विपक्षी एकता और जन-प्रतिरोध के सर्वोच्च प्रतीक के रूप में स्थापित किया।

109. (D) 42वां संशोधन
42वें संविधान संशोधन को 'लघु-संविधान' कहा जाता है क्योंकि इसके माध्यम से आपातकाल के दौरान संविधान में व्यापक और आमूलचूल परिवर्तन किए गए थे। इस संशोधन ने न केवल संसद की शक्तियों का विस्तार किया, बल्कि न्यायपालिका के अधिकारों को सीमित किया और संविधान की प्रस्तावना में भी बदलाव किए। इसके व्यापक प्रभाव और संशोधनों की विशाल संख्या के कारण इसे भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक नए लघु स्वरूप के रूप में पहचाना जाता है।

110. (B) व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में।
आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों के हनन के अनुभवों के बाद भारतीय अदालतों ने अपनी भूमिका में बड़ा बदलाव किया। 1977 के बाद न्यायपालिका ने व्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अत्यंत सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया। अदालतों ने महसूस किया कि संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना उनका प्राथमिक कर्तव्य है, विशेषकर जब कार्यपालिका निरंकुश हो जाए। इसी दौर ने जनहित याचिका (PIL) जैसी नई कानूनी अवधारणाओं के विकास का आधार तैयार किया जिससे आम जनता को न्याय मिल सका।

111. (D) जयप्रकाश नारायण
1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के समय मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम प्रधानमंत्री पद के मुख्य दावेदार थे। जयप्रकाश नारायण यद्यपि पूरे आंदोलन के मार्गदर्शक और सूत्रधार थे, लेकिन उन्होंने कभी भी सत्ता का पद संभालने की इच्छा नहीं रखी थी। वे हमेशा सक्रिय चुनावी राजनीति और पद की गरिमा से ऊपर रहकर एक लोक-नायक के रूप में कार्य करते रहे, इसलिए वे इस नेतृत्व की दौड़ में शामिल नहीं थे।

सरकार की उम्मीद में इंदिरा गांधी को फिर से भारी बहुमत के साथ सत्ता सौंपी।

132. (A) किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत के खिलाफ अदालत में चुनौती देने का अधिकार।
बंदी प्रत्यक्षीकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण न्यायिक अधिकार है जो नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जिसे गैर-कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है, अदालत से हस्तक्षेप की मांग कर सकता है। अदालत संबंधित प्राधिकारी को आदेश दे सकती है कि वह बंदी को अदालत के सामने पेश करे और उसकी गिरफ्तारी का कानूनी कारण स्पष्ट करे। आपातकाल के दौरान इसी अधिकार को निलंबित करना सबसे विवादित कदम माना गया था।

133. (C) मंडल आयोग
जनता पार्टी की सरकार ने बी.पी. मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जिसे सामान्यतः मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग का कार्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों की पहचान करना और उनके उत्थान के लिए आरक्षण जैसे उपाय सुझाना था। यद्यपि इसकी सिफारिशें वर्षों बाद लागू हुईं, लेकिन इसने भारतीय राजनीति में पिछड़ी जातियों की भागीदारी और अधिकारों की एक नई लहर पैदा कर दी थी।

134. (A) केवल 1, 2, 3 और 5
जयप्रकाश नारायण का जीवन संघर्ष और वैचारिक विकास की एक लंबी यात्रा थी। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, इसलिए यह कहना गलत है कि वे इसके सदस्य नहीं रहे। उन्होंने 1950 के दशक में सक्रिय राजनीति छोड़कर भूदान आंदोलन और सामाजिक कार्यों में स्वयं को समर्पित कर दिया था। सत्तर के दशक में उनके नेतृत्व ने आपातकाल के विरुद्ध चल रहे आंदोलन को एक नैतिक शक्ति प्रदान की और वे लोकतंत्र के संरक्षक बन गए।

135. (B) संसद संविधान के कुछ मूलभूत सिद्धांतों में संशोधन नहीं कर सकती।
केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 'बुनियादी ढांचे' का सिद्धांत प्रतिपादित कर संसद की संविधान संशोधन की असीमित शक्ति पर रोक लगा दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान के कुछ ऐसे मौलिक तत्व हैं, जैसे लोकतंत्र, संघीय ढांचा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जिन्हें संसद किसी भी बहुमत से नहीं बदल सकती। इस निर्णय ने यह सुनिश्चित किया कि संविधान का मूल चरित्र और नागरिकों के बुनियादी अधिकार हमेशा सुरक्षित और अक्षुण्ण बने रहेंगे।

136. (C) खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि
सत्तर के दशक की शुरुआत भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत कष्टकारी थी। यह कहना गलत है कि उस समय खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई थी; इसके विपरीत, मानसून की विफलता के कारण उत्पादन में आठ प्रतिशत की भारी गिरावट आई थी। पाकिस्तान के साथ युद्ध, शरणार्थियों का आगमन, अमेरिकी सहायता का बंद होना और अंतर्राष्ट्रीय तेल संकट वे वास्तविक कारण थे जिन्होंने देश में महंगाई और आर्थिक बदहाली को चरम पर पहुँचा दिया था।

137. (B) यह भारत की पहली गैर-कांग्रेसी सरकार थी।
1977 में जनता पार्टी की जीत भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक मील का पत्थर है क्योंकि इसने केंद्र में कांग्रेस के तीन दशक पुराने प्रभुत्व को समाप्त किया। यह पहली बार था जब दिल्ली की सत्ता पर ऐसी सरकार का कब्जा हुआ जिसमें कोई भी घटक कांग्रेस से संबंधित नहीं था। हालांकि यह एक गठबंधन सरकार थी, लेकिन इसने देश को पहली बार एक प्रभावी राजनीतिक विकल्प प्रदान किया और लोकतांत्रिक शक्तियों के हस्तांतरण की प्रक्रिया को मजबूत बनाया।

138. (A) P-2, Q-1, R-4, S-3
सत्तर के दशक की प्रमुख घटनाओं का क्रम भारतीय राजनीति की दिशा निर्धारित करने वाला था। 1971 में गरीबी हटाओ के नारे ने कांग्रेस को बड़ी जीत दिलाई। 1974 में भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार आंदोलन की शुरुआत हुई। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया जिसने लोकतंत्र को अस्थायी रूप से रोक दिया। अंततः 1977 में आपातकाल के विरुद्ध जनमत ने जनता पार्टी के गठन और पहली गैर-कांग्रेसी सरकार की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया।

139. (C) सरकार ने उसी रात आपातकाल की घोषणा कर दी।
25 जून 1975 को रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की विशाल रैली और उनके द्वारा घोषित राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह ने सरकार को हिलाकर रख दिया था। जेपी ने सेना और पुलिस से भी अपील की थी कि वे सरकार के अनुचित आदेश न मानें। इस स्थिति को अपनी सत्ता के लिए सीधा खतरा मानते हुए इंदिरा गांधी ने उसी रात राष्ट्रपति से आपातकाल की घोषणा करवा दी, जिससे देश में रातों-रात राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल गया।

140. (D) सभी 1, 2, 3 और 4
आपातकाल के दौरान लगाए गए कड़े प्रतिबंधों का विभिन्न क्षेत्रों में विरोध हुआ। कई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने सेंसरशिप के आगे झुकने के बजाय खाली स्थान छोड़ने या प्रकाशन बंद करने का साहस दिखाया। साहित्यिक जगत के दिग्गजों जैसे शिवराम कारंत और फणीश्वरनाथ 'रेणु' ने अपने प्रतिष्ठित पद्म सम्मानों को त्याग कर तानाशाही के विरुद्ध अपना नैतिक प्रतिरोध दर्ज कराया। ये सभी घटनाएं आपातकाल के विरुद्ध समाज के बौद्धिक और जागरूक वर्ग के संघर्ष का जीवंत उदाहरण हैं।

141. (A) नागरिक अधिकारों के प्रति लोगों और अदालतों में बढ़ी हुई जागरूकता।
आपातकाल का एक अत्यंत सकारात्मक और दूरगामी परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता और न्यायपालिका नागरिक अधिकारों के महत्व को लेकर पहले से कहीं अधिक सतर्क हो गए। आपातकाल के दौरान अधिकारों के हनन के कड़वे अनुभवों ने यह सिखाया कि लोकतंत्र में नागरिक स्वतंत्रताएं कितनी नाजुक हो सकती हैं। इसके बाद अदालतों

ने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभानी शुरु की और कई नागरिक अधिकार संगठन वजूद में आए जो आज भी सक्रिय हैं।

142. (A) नेतृत्व, दिशा और साझे कार्यक्रम के अभाव तथा आंतरिक कलह के कारण।
जनता पार्टी की सरकार का पतन उसकी आंतरिक कमजोरियों के कारण हुआ। यह पार्टी विभिन्न विपरीत विचारधाराओं वाले दलों का एक अस्थायी गठबंधन मात्र थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य इंदिरा गांधी को हटाना था। सत्ता में आने के बाद उनके पास देश के लिए कोई स्पष्ट साझा विजन या ठोस कार्यक्रम नहीं था। शीर्ष नेताओं के बीच प्रधानमंत्री पद को लेकर जारी आपसी प्रतिद्वंद्विता और कलह ने सरकार को अठ्ठाइस महीने के भीतर ही अस्थिर और पंगु बना दिया।

143. (C) अमेठी
1977 के लोकसभा चुनाव परिणामों में गांधी परिवार के प्रति जनता का आक्रोश स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। जहाँ इंदिरा गांधी अपनी रायबरेली सीट से हारीं, वहीं उनके पुत्र संजय गांधी को भी अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से अपमानजनक पराजय का सामना करना पड़ा। आपातकाल के दौरान उनकी विवादास्पद भूमिका और विशेष रूप से जबरन नसबंदी कार्यक्रम के संचालन के कारण ग्रामीण जनता उनके प्रति अत्यंत नाराज थी, जिसका परिणाम इस चुनाव में उनकी हार के रूप में सामने आया।

144. (D) न्यायपालिका की शक्तियों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई।
आपातकाल के दौरान न्यायपालिका की शक्तियों में वृद्धि होने के बजाय भारी कटौती की गई थी। सरकार ने संविधान में संशोधनों के माध्यम से अदालतों के न्यायिक समीक्षा के अधिकार को सीमित कर दिया था। हालांकि विपक्षी नेताओं को जेल में डालना, प्रेस की आजादी को खत्म करना और मौलिक अधिकारों को निलंबित करना आपातकाल के वास्तविक और कठोर परिणाम थे। न्यायपालिका अपनी खोई हुई शक्ति और सक्रियता आपातकाल समाप्त होने के बाद ही वापस प्राप्त कर पाई थी।

145. (B) बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली को लेकर पूरे देश में असंतोष का माहौल था।
1970 के दशक की शुरुआत में भारत एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था, जिसने जन-आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार की। अंतर्राष्ट्रीय तेल संकट के कारण कीमतों में भारी वृद्धि, मानसून की विफलता से खाद्यान्न का अभाव और बढ़ती बेरोजगारी ने आम आदमी का जीवन अत्यंत कठिन बना दिया था। गैर-कांग्रेसी दलों ने इसी व्यापक जन-असंतोष को संगठित किया और सरकार की विफलता के खिलाफ आंदोलनों का नेतृत्व कर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत की थी।

146. (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस द्वारा स्थापित नीतियों में कोई बड़ा परिवर्तन करने में असमर्थ रही। इसका मुख्य कारण यह था कि गठबंधन में शामिल दलों के पास कोई एकीकृत आर्थिक या सामाजिक विजन नहीं था। वे केवल कांग्रेस विरोध के साझा आधार पर एकजुट हुए थे, लेकिन सत्ता में आने पर उनके आपसी मतभेदों ने उन्हें किसी ठोस नीतिगत बदलाव की दिशा में बढ़ने नहीं दिया। परिणामस्वरूप, सरकार का अधिकांश समय आपसी खींचतान को सुलझाने में ही व्यतीत हो गया।

147. (2, 1, 3, 4)
सत्तर के दशक की राजनीतिक घटनाओं का क्रम भारतीय लोकतंत्र के उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। सबसे पहले 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई, जिसने सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया। इसके बाद 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार बनी। फिर आंतरिक संघर्ष के कारण उनकी सरकार गिरी और चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। अंततः, इस राजनीतिक अस्थिरता के दौर का अंत 1980 के लोकसभा चुनावों के साथ हुआ, जिसमें कांग्रेस फिर सत्ता में आई।

148. (B) नागरिक अधिकारों के कई नए संगठन वजूद में आए।
आपातकाल की समाप्ति के बाद भारतीय नागरिक समाज में अधिकारों के प्रति एक नई चेतना का संचार हुआ। आपातकाल के दौरान हुए दमन ने बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं को यह अहसास कराया कि नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्वतंत्र संगठनों का होना अनिवार्य है। इसी के परिणामस्वरूप देश भर में कई नए नागरिक अधिकार और मानवाधिकार संगठन स्थापित हुए। इन संगठनों ने भविष्य में सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाने और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

149. (A) केवल 1, 2 और 3
शाह आयोग का गठन जनता पार्टी सरकार द्वारा आपातकाल की ज्यादतियों की निष्पक्ष जांच के लिए किया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि उस दौरान पुलिस और प्रशासन का घोर दुरुपयोग किया गया था और अधिकारियों ने नियमों के बजाय राजनीतिक आकाओं के आदेशों को प्राथमिकता दी थी। हालांकि आयोग ने समस्याओं को उजागर किया, लेकिन यह कहना गलत है कि इससे सभी समस्याओं का समाधान हो गया या इसका गठन आपातकाल के दौरान हुआ था।

150. (B) इसने विपक्षी दलों को 'गैर-कांग्रेसवाद' की रणनीति के तहत एकजुट होने के लिए प्रेरित किया।
आपातकाल ने भारतीय दलीय व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव यह किया कि इसने बिखरे हुए विपक्ष को एक साझा दुश्मन के खिलाफ एकजुट होने के लिए विवश कर दिया। विपक्षी दलों को यह समझ आ गया कि कांग्रेस के प्रभुत्व को केवल एक होकर ही चुनौती दी जा सकती है। इसी 'गैर-कांग्रेसवाद' की भावना ने जनता पार्टी जैसे प्रयोगों को जन्म दिया, जिसने भविष्य में देश में गठबंधन की राजनीति और एक मजबूत वैकल्पिक नेतृत्व की नींव रखने में मदद की।

151. (B) व्यवस्था में आमूल-चूल रूपांतरण लाना
जयप्रकाश नारायण का 'संपूर्ण क्रांति' का आह्वान केवल तात्कालिक राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन लाने तक सीमित

नहीं था। इसका व्यापक लक्ष्य भारतीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के ढांचे में गहरा और पूर्ण परिवर्तन करना था। जेपी इसे एक ऐसी प्रक्रिया मानते थे जो समाज के हर स्तर पर नैतिकता और लोकतांत्रिक मूल्यों को पुनः स्थापित करने के साथ व्यवस्था को बदल सके।

152. (A) वे इसे दलीय राजनीति और सत्ता संघर्ष से दूषित मानते थे
जयप्रकाश नारायण ने तत्कालीन संसदीय व्यवस्था की आलोचना इसलिए की क्योंकि उनके अनुसार यह प्रणाली दलीय राजनीति के स्वार्थों और सत्ता प्राप्त करने के निरंतर संघर्ष से प्रभावित हो चुकी थी। वे मानते थे कि यह ढांचा आम जनता की वास्तविक आकांक्षाओं और भागीदारी को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से प्रतिबिंबित करने में पूरी तरह असमर्थ था और केवल शक्ति केंद्रित रह गई थी।

153. (C) सैन्य क्रांति
जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रतिपादित 'संपूर्ण क्रांति' की अवधारणा सात विशिष्ट क्रांतियों का एक व्यापक संश्लेषण थी। इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक परिवर्तन शामिल थे। हालांकि, इस अवधारणा के अंतर्गत किसी भी प्रकार की सैन्य क्रांति या सशस्त्र विद्रोह का उल्लेख नहीं किया गया था क्योंकि यह आंदोलन पूरी तरह अहिंसक और नैतिक मूल्यों के सुधार पर केंद्रित एक दार्शनिक युद्ध था।

154. (D) दलविहीन, विकेंद्रीकृत लोकतंत्र
जयप्रकाश नारायण एक ऐसे लोकतंत्र के पक्षधर थे जो राजनीतिक दलों के प्रभुत्व से मुक्त हो और जिसमें सत्ता का व्यापक विकेंद्रीकरण हो। उन्होंने दलविहीन लोकतंत्र का समर्थन किया ताकि शक्ति सीधे जनता के हाथों में रहे। उनका मानना था कि वास्तविक लोकतंत्र तभी संभव है जब शासन की प्रक्रिया में ग्राम स्तर से सीधी जनभागीदारी सुनिश्चित की जाए और दलीय कलह समाप्त हो।

155. (C) इसने आपातकाल की ओर जाने वाले राजनीतिक टकराव की नींव रखी
'संपूर्ण क्रांति' आंदोलन ने तत्कालीन केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यशैली को कड़ी चुनौती दी। छात्रों और जनता के इस व्यापक विरोध ने सरकार और विपक्षी आंदोलनों के बीच एक गहरे राजनीतिक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न कर दी। इसी निरंतर बढ़ते टकराव और अस्थिरता के वातावरण ने अंततः 1975 में देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की मजबूत आधारभूमि तैयार की थी।

156. (B) संविधान संशोधन की संसद की शक्ति, विशेषकर मौलिक अधिकारों पर
1970 के दशक में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संघर्ष का केंद्र बिंदु संविधान संशोधन की संसदीय शक्ति की सीमाएं थीं। मुख्य विवाद इस प्रश्न पर था कि क्या संसद नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संशोधित या सीमित कर सकती है। गोलकनाथ मामले और उसके बाद के संशोधनों ने इस वैधानिक खींचतान को और अधिक तीव्र कर दिया था, जिससे संवैधानिक मूल्यों पर संकट उत्पन्न हुआ।

157. (D) केशवानंद भारती मामला
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) भारतीय न्यायिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मामला माना जाता है। इसी ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने 'बुनियादी ढांचे' के सिद्धांत की घोषणा की थी। इस फैसले ने स्पष्ट किया कि संविधान के कुछ मूलभूत लक्षण ऐसे हैं जिनमें संसद द्वारा किसी भी परिस्थिति में संशोधन करके उन्हें नष्ट या परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जिससे संसद की शक्तियां सीमित हुईं।

158. (A) संसद संविधान के मूल तत्वों और बुनियादी मूल्यों को नहीं बदल सकती
बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के अनुसार संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति असीमित नहीं है। हालांकि संसद संविधान के विभिन्न भागों को बदल सकती है, किंतु वह उन आधारभूत मूल्यों और प्रावधानों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती जो भारतीय संविधान की आत्मा हैं। इसमें लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, शक्तियों का पृथक्करण और संघवाद जैसे अनिवार्य और अपरिवर्तनीय तत्वों का समावेश किया गया है।

159. (C) ऐसी न्यायपालिका जो सरकार की विचारधारा के प्रति झुकाव रखे
प्रतिबद्ध न्यायपालिका एक ऐसी विवादास्पद अवधारणा है जिसमें न्यायाधीशों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निष्पक्ष होने के बजाय सत्तारूढ़ सरकार की नीतियों और सामाजिक-आर्थिक दर्शन के प्रति सहानुभूति रखें। यह विचार न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत के विपरीत है। इसका उद्देश्य न्यायपालिका को सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक सहायक उपकरण के रूप में कार्य कराना था जो स्वतंत्र निर्णय न ले।

160. (A) तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया
जब सरकार ने न्यायमूर्ति ए.एन. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए स्थापित वरिष्ठता क्रम के नियम की अनदेखी की, तो इसे न्यायिक स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार माना गया। इसके विरोध स्वरूप सर्वोच्च न्यायालय के तीन सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया। इस घटना ने न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों को अत्यंत तनावपूर्ण बनाकर लोकतंत्र में बड़ा संकट उत्पन्न किया।

161. (D) अनुच्छेद 352
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की असाधारण शक्ति प्रदान करता है। जून 1975 में इसी अनुच्छेद का प्रयोग करके तत्कालीन सरकार ने आपातकालीन स्थिति लागू की थी। उस समय 'आंतरिक अशांति' को इसका प्रमुख आधार बनाया गया था। यह घोषणा देश की सुरक्षा और स्थिरता के नाम पर की गई एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विवादास्पद राजनीतिक कार्रवाई थी।

3. इसने 1979 में विदेशियों के विरोध में एक आंदोलन चलाया।
4. आंदोलन की माँग थी कि 1951 के बाद असम में बसे सभी लोगों को बाहर भेजा जाए।

उपरोक्त में से कौन से कथन असत्य हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) केवल 3 और 4
(D) केवल 1 और 4

22. 1986 में राजीव गाँधी और लालडेंगा के बीच हुए शांति समझौते का परिणाम क्या हुआ?

(A) मिज़ोरम को एक विशेष केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया।
(B) मिज़ोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा और विशेष अधिकार मिले।
(C) विद्रोही नेता लालडेंगा को भारत का गृह मंत्री नियुक्त किया गया।
(D) मिज़ो नेशनल फ्रंट को पूर्णतः प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया।

23. जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में 'कश्मीरियत' का क्या अर्थ है?

(A) पाकिस्तान में शामिल होने की इच्छा
(B) महाराजा के शासन का समर्थन
(C) केवल मुस्लिम पहचान पर जोर
(D) एक विशिष्ट कश्मीरी क्षेत्रीय पहचान की भावना

24. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:

सूची I: (राज्य/क्षेत्र)

P. पंजाब
Q. तमिलनाडु
R. मिज़ोरम
S. असम

सूची II: (आंदोलन/मुद्दा)

1. बाहरी लोगों का विरोध
2. आनंदपुर साहिब प्रस्ताव
3. हिंदी-विरोधी आंदोलन
4. लालडेंगा के नेतृत्व में अलगाववाद

(A) P-2, Q-3, R-4, S-1
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

25. 1947 में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर कबायली घुसपैठिए भेजने का तात्कालिक परिणाम क्या हुआ?

(A) महाराजा हरि सिंह द्वारा पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय।
(B) संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सीमा पर सैन्य हस्तक्षेप किया गया।
(C) महाराजा ने सैन्य मदद हेतु विलय प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए।
(D) शेख अब्दुल्ला को राज्य के प्रधानमंत्री पद से हटाया गया।

26. 1961 में गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए सैन्य अभियान का क्या नाम था?

(A) ऑपरेशन विजय
(B) ऑपरेशन ब्लू स्टार
(C) ऑपरेशन मेघदूत
(D) ऑपरेशन पवन

27. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।

अभिकथन (A): द्रविड़ आंदोलन ने कभी सशस्त्र संघर्ष की राह नहीं अपनाई।

कारण (R): इसने अपनी माँगों को आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक बहसों और चुनावी मंच का इस्तेमाल किया।

(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

28. 1985 के असम समझौते के अंतर्गत क्या तय किया गया था?

(A) असम को भारत संघ से पृथक एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना।
(B) बाहरी लोगों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने का प्रावधान।
(C) सभी बंगाली भाषियों को अनिवार्य रूप से नागरिकता प्रदान करना।
(D) स्थानीय तेल संसाधनों का पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण करना।

29. निम्नलिखित में से कौन-सा दल द्रविड़ आंदोलन की विरासत से नहीं जुड़ा है?

(A) डी.एम.के. (द्रविड़ मुनेत्र कड़गम)
(B) ए.आई.ए.डी.एम.के. (ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक)
(C) तेलुगु देशम पार्टी
(D) पी.एम.के. (पट्टाली मक्कल कच्ची)

30. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. आज़ादी के समय सिक्किम भारत का 'शरणागत' राज्य था।
2. सिक्किम की रक्षा और विदेशी मामलों का जिम्मा भारत सरकार का था।
3. सिक्किम के आंतरिक प्रशासन की बागडोर राजा चोग्याल के हाथों में थी।
4. सिक्किम की अधिकांश आबादी लेपचा-भूटिया थी।
5. 1975 में जनमत-संग्रह के बाद सिक्किम भारत का 22वाँ राज्य बना।

172. (B) कई प्रमुख विपक्षी दलों के विलय से इसका गठन हुआ
1977 के चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस (ओ), भारतीय जनसंघ, भारतीय लोक दल और सोशलिस्ट पार्टी जैसे प्रमुख विपक्षी दलों ने गठबंधन किया। इन दलों ने अपने वैचारिक मतभेदों को पीछे छोड़कर 'जनता पार्टी' के रूप में एक साझा राजनीतिक मंच तैयार किया। इस विलय का मुख्य उद्देश्य इंदिरा गांधी की सरकार के विरुद्ध एक शक्तिशाली और एकीकृत चुनावी मोर्चा बनाना और लोकतंत्र को बहाल करना था।

173. (D) लोकतंत्र बचाओ
1977 के ऐतिहासिक चुनावों में जनता पार्टी ने 'लोकतंत्र बचाओ' का अत्यंत प्रभावी नारा दिया था। इस नारे ने उन नागरिकों की भावनाओं को सीधे तौर पर छुआ जो आपातकाल के दौरान अपनी नागरिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार खो चुके थे। इसका उद्देश्य जनता को आपातकाल के अलोकतांत्रिक शासन के विरुद्ध एकजुट करना और देश के संवैधानिक मूल्यों को पुनः बहाल करने का संकल्प प्रस्तुत करना था।

174. (A) स्वतंत्रता के बाद पहली बार कांग्रेस केंद्र में सत्ता से बाहर हुई
1977 के चुनाव परिणामों का सबसे दूरगामी और ऐतिहासिक प्रभाव यह पड़ा कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद पहली बार केंद्र सरकार में सत्ता परिवर्तन हुआ। दशकों से शासन कर रही कांग्रेस पार्टी को करारी पराजय का सामना करना पड़ा और वह केंद्र की सत्ता से बाहर हो गई। इस घटना ने देश में गैर-कांग्रेसी सरकार के युग की शुरुआत की और लोकतंत्र में जनशक्ति की संप्रभुता को सिद्ध किया।

175. (C) वे लोकतंत्र के प्रति समर्पित हैं और अलोकतांत्रिक शासन को दंडित करेंगे
1977 के चुनाव के परिणामों ने विश्व पटल पर भारतीय मतदाताओं की राजनीतिक परिपक्वता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। यह सिद्ध हुआ कि भारतीय नागरिक लोकतंत्र के मूल्यों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील और समर्पित हैं। मतदाताओं ने यह संदेश दिया कि वे किसी भी अलोकतांत्रिक सरकार या तानाशाही प्रवृत्तियों को सहन नहीं करेंगे और अपने मताधिकार का उपयोग करके ऐसी दमनकारी व्यवस्था को दंडित करेंगे।

4. फारूक अब्दुल्ला को कभी भी पद से नहीं हटाया गया और उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया।

उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1, 2 और 3
(C) केवल 3 और 4
(D) सभी कथन सही हैं

42. 1984 के सिख-विरोधी दंगों के बाद, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2005 में संसद में क्या किया था?

(A) इस रक्तपात पर अफसोस जताया और देश से माफी माँगी।
(B) दंगों के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया।
(C) एक और जाँच आयोग की स्थापना की।
(D) इस विषय पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

43. आत्मसम्मान आंदोलन (1925) के जनक कौन थे?

(A) सी. एन. अन्नादुरै
(B) एम. जी. रामचंद्रन
(C) के. कामराज
(D) ई. वी. रामास्वामी नायकर 'पेरियार'

44. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।

अभिकथन (A): 1959 में मिजो पर्वतीय क्षेत्र में अलगाववादी आंदोलन को जनसमर्थन मिलना शुरु हुआ।

कारण (R): असम की सरकार उस वर्ष पड़े भारी अकाल में समुचित प्रबंध करने में नाकाम रही थी।

(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

45. 'All Party Hills Conference' की मुख्य माँग क्या थी?

(A) असम के भीतर अधिक स्वायत्तता
(B) पूरे पूर्वोत्तर के लिए एक साझा सरकार
(C) असम से अलग एक जनजातीय राज्य बनाया जाए
(D) बांग्लादेशी प्रवासियों का निष्कासन

46. असम के बोडो, करबी और दिमसा जैसे समुदायों की माँगों को संतुष्ट करने के लिए क्या व्यवस्था की गई?

(A) उन्हें अलग राज्य बना दिया गया।
(B) उनकी माँगों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया।
(C) उन्हें पड़ोसी राज्यों में मिला दिया गया।
(D) उन्हें असम के भीतर ही स्वायत्त परिषद् का दर्जा दिया गया।

47. निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें:

1. असम में AASU द्वारा आंदोलन की शुरुआत
2. गोवा की मुक्ति
3. डी.एम.के. को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सफलता
4. जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय

(A) 4, 2, 3, 1
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 4, 1, 3
(D) 4, 1, 2, 3

48. कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों के बड़े पैमाने पर पलायन का मुख्य दौर कब शुरु हुआ?

(A) 1947-48 में
(B) 1989-90 में
(C) 1965-66 में
(D) 2001-02 में

49. 'असम गण परिषद्' का गठन किन दो समूहों के विलय से हुआ?

(A) आसू और असम साहित्य सभा
(B) आसू और असम गण संग्राम परिषद्
(C) कांग्रेस और आसू
(D) बोडो छात्र संघ और आसू

50. निम्नलिखित में से कौन-सा एक पूर्वोत्तर का राज्य नहीं है जिसे "सात बहनों" में गिना जाता है?

(A) सिक्किम
(B) अरुणाचल प्रदेश
(C) मणिपुर
(D) त्रिपुरा

51. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत ने विविधता के सवाल पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया है।
2. लोकतंत्र में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति की अनुमति है।
3. लोकतंत्र क्षेत्रीयता को हमेशा राष्ट्र-विरोधी मानता है।
4. भारतीय राष्ट्रवाद ने एकता और विविधता के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है।
5. भारत का नजरिया यूरोप से भिन्न रहा, जहाँ सांस्कृतिक विभिन्नता को खतरे के रूप में देखा गया।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(A) केवल 1, 2, 3
(B) केवल 3, 4, 5
(C) केवल 1, 2, 4, 5
(D) सभी कथन सही हैं

52. 1950 के दशक में किस भाषा को राजभाषा बनाने के खिलाफ दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिलनाडु में, विरोध-आंदोलन चला?

(A) संस्कृत
(B) अंग्रेजी

(B) केवल 3 और 4
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) 1, 2, 3 और 4 सभी

10. 1965 के हिंदी विरोधी आंदोलन की सफलता ने किस दल को जनता के बीच लोकप्रिय बनाया?
(A) डी.एम.के.
(B) द्रविड़ कड़गम
(C) आल इंडिया अन्ना द्रमुक
(D) पी.एम.के.

11. 1973 में आनंदपुर साहिब में पारित प्रस्ताव का मुख्य जोर किस बात पर था?
(A) एक स्वतंत्र सिख राष्ट्र की स्थापना
(B) पंजाब के लिए विशेष आर्थिक पैकेज
(C) हिंदी भाषा का पूर्ण बहिष्कार
(D) केंद्र-राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करना

12. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' स्वर्णमंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई का कूट नाम था।
2. यह कार्रवाई 1984 के जून माह में हुई थी।
3. इस सैन्य-अभियान में सरकार ने उग्रवादियों को सफलतापूर्वक मार भगाया।
4. इस कार्रवाई से स्वर्णमंदिर को कोई क्षति नहीं पहुँची।
5. इस घटना से सिखों की भावनाओं को गहरी चोट लगी।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2, 3
(B) केवल 1, 2, 3, 5
(C) केवल 2, 4, 5
(D) सभी कथन सही हैं

13. 31 अक्तूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी की हत्या के पीछे तात्कालिक कारण क्या था?
(A) पंजाब समझौते का विरोध
(B) आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को लागू न करना
(C) 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' का बदला लेना
(D) आर्थिक नीतियों से असंतोष

14. जम्मू-कश्मीर के वे कौन से तीन सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र हैं जिनसे यह राज्य बना है?
(A) जम्मू, श्रीनगर और कारगिल
(B) कश्मीर, पुंछ और लद्दाख
(C) लेह, बारामूला और जम्मू
(D) जम्मू, कश्मीर और लद्दाख

15. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): 1985 में राजीव गाँधी और हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच पंजाब समझौता हुआ।
कारण (R): इस समझौते का उद्देश्य पंजाब में शांति बहाल करना था।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

16. 1966 में पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन किस आधार पर हुआ?
(A) धार्मिक आधार पर
(B) भाषायी आधार पर
(C) आर्थिक विकास के आधार पर
(D) प्रशासनिक सुविधा के आधार पर

17. 1970 के दशक में पूर्वोत्तर के राज्यों से उठी माँगों में कौन-सा मुद्दा प्रमुख नहीं था?
(A) स्वायत्तता की माँग
(B) आर्थिक उदारीकरण की माँग
(C) अलगाव के आंदोलन
(D) 'बाहरी' लोगों का विरोध

18. निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें:
1. ऑपरेशन ब्लू स्टार
2. राजीव-लोंगोवाल समझौता
3. आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का पारित होना
4. इंदिरा गाँधी की हत्या

(A) 3, 1, 4, 2
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 4, 3, 2, 1
(D) 2, 1, 4, 3

19. पूर्वोत्तर के किस पूरे इलाके को आजादी के वक्त असम कहा जाता था, सिवाय दो क्षेत्रों के?
(A) नगालैंड और मिजोरम
(B) मेघालय और अरुणाचल प्रदेश
(C) मणिपुर और त्रिपुरा
(D) सिक्किम और नगालैंड

20. 1959 में मिजो पर्वतीय इलाके में पड़े भारी अकाल के बाद, किस संगठन का गठन हुआ जिसने अलगाववादी आंदोलन चलाया?
(A) ऑल पार्टी हिल्स कांफ्रेंस
(B) ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन
(C) नगा National काउंसिल
(D) मिजो National फ्रंट

21. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. 'आसू' (AASU) एक छात्र-संगठन था।
2. इसका जुड़ाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से था।

अध्याय 14
क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

1. 1980 के दशक को अक्सर किस माँग के दशक के रूप में देखा जाता है?
   (A) आर्थिक विकास की माँग
   (B) स्वायत्तता की माँग
   (C) भाषाई पुनर्गठन की माँग
   (D) सामाजिक न्याय की माँग

2. भारत ने विविधता के सवाल पर कौन-सा दृष्टिकोण अपनाया?
   (A) लोकतांत्रिक दृष्टिकोण
   (B) सत्तावादी दृष्टिकोण
   (C) एकीकृत दृष्टिकोण
   (D) यूरोपीय दृष्टिकोण

3. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
   अभिकथन (A): आज़ादी के तुरंत बाद जम्मू-कश्मीर का मसला सामने आया।
   कारण (R): महाराजा हरि सिंह तुरंत भारत में अपनी रियासत का विलय करना चाहते थे।
   (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
   (B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
   (C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
   (D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

4. 'द्रविड़ आंदोलन' के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है?
   (A) यह भारत के क्षेत्रीय आंदोलनों में सबसे ताकतवर था।
   (B) आंदोलन ने अपनी माँगों के लिए कभी सशस्त्र संघर्ष की राह नहीं अपनाई।
   (C) इस आंदोलन से 'द्रविड़ कड़गम' नामक राजनीतिक संगठन का सूत्रपात हुआ।
   (D) आंदोलन का नेतृत्व प्रारंभ में सी. अन्नादुरै के हाथों में था।

5. आज़ादी के बाद भारत को किन कठिन मसलों से जूझना पड़ा था?
   (A) केवल राष्ट्र के विभाजन और शरणार्थियों के विस्थापन के मुद्दे
   (B) केवल विभिन्न देसी रियासतों के भारत में विलय के मुद्दे
   (C) विभाजन, विस्थापन, रियासतों का विलय और राज्यों का पुनर्गठन
   (D) केवल भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के कठिन मुद्दे

6. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
   सूची I: (नेता)
   P. शेख मोहम्मद अब्दुल्ला
   Q. ई. वी. रामास्वामी नायकर 'पेरियार'
   R. मास्टर तारा सिंह
   S. लालडेंगा
   सूची II: (संगठन/आंदोलन)
   1. आत्मसम्मान आंदोलन
   2. मिज़ो नेशनल फ्रंट
   3. नेशनल कॉन्फेरेंस
   4. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी
   (A) P-3, Q-1, R-4, S-2
   (B) P-1, Q-2, R-3, S-4
   (C) P-4, Q-3, R-2, S-1
   (D) P-2, Q-4, R-1, S-3

7. 1953-54 के दौरान डी.एम.के. द्वारा चलाए गए तीन-सूत्री आंदोलन की माँगों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था?
   (A) स्कूली पाठ्यक्रम में तमिल संस्कृति के इतिहास को ज़्यादा महत्त्व देना।
   (B) राज्य सरकार के शिल्पकर्म शिक्षा कार्यक्रम का विरोध।
   (C) हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने का विरोध।
   (D) कल्लाकुडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर डालमियापुरम करना।

8. 1989 तक, जम्मू और कश्मीर राज्य किस प्रमुख मुद्दे को लेकर एक उग्रवादी आंदोलन के कब्जे में आ गया था?
   (A) एक पृथक कश्मीरी राष्ट्र बनाने की माँग
   (B) अधिक वित्तीय सहायता की माँग
   (C) भाषाई आधार पर पुनर्गठन की माँग
   (D) धार्मिक स्वतंत्रता की माँग

9. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
   1. 1947 से पहले, जम्मू और कश्मीर एक राजसी रियासत थी।
   2. इसके शासक महाराजा हरि सिंह थे।
   3. महाराजा अपनी रियासत के लिए स्वतंत्र दर्जा चाहते थे।
   4. पाकिस्तानी नेताओं का मानना था कि कश्मीर पाकिस्तान का 'हिस्सा' है।
   उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं?
   (A) केवल 1 और 2

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2, 3
(B) केवल 1, 2, 3, 5
(C) केवल 2, 4, 5
(D) सभी कथन सही हैं

31. 1967 में गोवा में कराए गए जनमत सर्वेक्षण का मुख्य प्रश्न क्या था?
(A) क्या गोवा को महाराष्ट्र में शामिल होना चाहिए या अलग रहना चाहिए?
(B) क्या गोवा को एक अलग राज्य बनाया जाना चाहिए?
(C) क्या कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए?
(D) क्या पुर्तगाल के साथ राजनयिक संबंध फिर से स्थापित किए जाने चाहिए?

32. 'ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन' का गठन क्यों हुआ था?
(A) असम से अलग एक जनजातीय राज्य बनाने की माँग के लिए
(B) असम में असमी भाषा को लादने के खिलाफ
(C) पूरे पूर्वोत्तर के आर्थिक विकास के लिए
(D) 'बाहरी' लोगों को असम से निकालने के लिए

33. निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें:
1. मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला
2. नगालैंड को राज्य बनाया गया
3. असम समझौता
4. सिक्किम का भारत में विलय
(A) 2, 4, 3, 1
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 4, 2, 1, 3
(D) 3, 4, 2, 1

34. 1987 के जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनावों के बारे में क्या आम धारणा थी?
(A) परिणामों में लोकप्रिय चयन की झलक नहीं थी और चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई थी।
(B) चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र थे।
(C) अलगाववादी समूहों ने चुनाव में बड़ी जीत हासिल की।
(D) नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव का बहिष्कार किया था।

35. नगालैंड में अलगाववादी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, जिन्होंने 1951 में नगालैंड को भारत से आज़ाद घोषित कर दिया था?
(A) लालडेंगा
(B) मास्टर तारा सिंह
(C) अंगमी जापू फिजो
(D) शेख अब्दुल्ला

36. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (घटना)
P. असम समझौता
Q. पंजाब समझौता
R. मिजोरम शांति समझौता
S. सिक्किम का विलय
सूची II: (वर्ष)
1. 1985 (जुलाई)
2. 1975
3. 1985 (अगस्त)
4. 1986
(A) P-3, Q-1, R-4, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-2, Q-3, R-4, S-1
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

37. "उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन-दिन घटता जाए" - यह नारा किस आंदोलन से संबंधित है?
(A) पंजाब आंदोलन
(B) असम आंदोलन
(C) द्रविड़ आंदोलन
(D) नक्सलवादी आंदोलन

38. 1980 के दशक के पूर्वोत्तर में तीन प्रमुख मुद्दे कौन से थे?
(A) गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार
(B) स्वायत्तता, अलगाववाद और बाहरी लोगों का विरोध
(C) भाषा, धर्म और जाति
(D) औद्योगीकरण, पर्यावरण और विस्थापन

39. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन पंजाब के राजनीतिक संदर्भ के बारे में सही है?
(A) अकाली दल को हमेशा से ही पंजाब में स्पष्ट बहुमत मिलता रहा।
(B) सिख समुदाय सामाजिक रूप से बिल्कुल भी विभाजित नहीं था।
(C) अकाली दल को पंजाब के हिंदू अल्पसंख्यकों का बड़ा समर्थन था।
(D) कांग्रेस को दलितों के बीच अकालियों से कहीं ज़्यादा समर्थन प्राप्त था।

40. 2019 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम द्वारा क्या बदलाव किया गया?
(A) राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में पुनर्गठित किया गया।
(B) अनुच्छेद 370 को और मजबूत किया गया।
(C) राज्य को विशेष आर्थिक दर्जा दिया गया।
(D) जम्मू और कश्मीर को पंजाब के साथ मिला दिया गया।

41. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. 1974 में इंदिरा गाँधी और शेख अब्दुल्ला के बीच एक समझौता हुआ।
2. समझौते के बाद शेख अब्दुल्ला राज्य के मुख्यमंत्री बने।
3. 1982 में शेख अब्दुल्ला के निधन के बाद उनके पुत्र फारुक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने।

162. (B) आंतरिक अशांति और देश की स्थिरता पर मंडराता हुआ खतरा
सरकार ने आपातकाल लागू करने के पीछे मुख्य आधिकारिक कारण आंतरिक अशांति और राष्ट्रीय स्थिरता के लिए उत्पन्न कथित खतरों को बताया था। सरकार का दावा था कि विपक्षी दलों द्वारा चलाए जा रहे व्यापक विरोध प्रदर्शन और हड़तालें विकास कार्यों में बाधा डाल रही हैं। उनके अनुसार, देश को अराजकता से बचाने और कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए यह अत्यंत कड़ा कदम उठाना अनिवार्य हो गया था।

163. (C) 'आंतरिक अशांति' के आधार पर राजनीतिक विरोध का दमन किया गया
आपातकाल के आलोचकों का तर्क था कि 'आंतरिक अशांति' शब्दावली अत्यंत अस्पष्ट थी जिसका सरकार ने दुरुपयोग किया। उनके अनुसार, इस घोषणा का वास्तविक उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि सत्ताधारी दल के विरुद्ध उठने वाली राजनीतिक आवाजों को दबाना था। विरोधियों का मानना था कि लोकतांत्रिक आंदोलनों को कुचलने और व्यक्तिगत सत्ता बनाए रखने के लिए ही जानबूझकर इस विशिष्ट संवैधानिक प्रावधान का प्रयोग किया गया।

164. (D) अनुच्छेद 21 और 14 सहित कई मुख्य मौलिक अधिकार निलंबित हुए
आपातकाल लागू होने के साथ ही भारतीय नागरिकों के कई महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। इनमें अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाला जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार तथा अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता का अधिकार शामिल था। इसके कारण नागरिक अपनी स्वतंत्रता के हनन के विरुद्ध न्यायालय की शरण में जाने के अपने बुनियादी संवैधानिक अधिकार से पूरी तरह से वंचित हो गए थे।

165. (A) मंत्रिमंडल को निर्णय के बाद ही सूचित किया गया था।
1975 के आपातकाल की घोषणा की प्रक्रिया में सबसे विवादास्पद पक्ष यह था कि प्रधानमंत्री ने यह निर्णय स्वयं लिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल को औपचारिक रूप से इस निर्णय की जानकारी घोषणा होने के अगले दिन सुबह प्राप्त हुई। इस कार्यप्रणाली ने संसदीय लोकतंत्र में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत और स्थापित प्रशासनिक मानदंडों पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े किए और जनता के बीच गहरा असंतोष और भ्रम पैदा किया।

166. (B) राजनीतिक विरोधियों को बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने हेतु
आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम (मीसा) का आपातकाल के दौरान व्यापक और कठोर प्रयोग किया गया। इस कानून के तहत अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति को बिना किसी औपचारिक मुकदमे या न्यायिक जांच के अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने की शक्ति प्राप्त थी। इसका मुख्य लक्ष्य विपक्षी नेताओं और सरकार की नीतियों का विरोध करने वाले प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेलों में बंद करना था।

167. (B) प्रेस पर कठोर सेंसरशिप और अनिवार्य सरकारी अनुमोदन लागू हुआ
आपातकाल के दौरान भारतीय प्रेस पर अत्यंत कठोर सेंसरशिप लागू की गई थी। समाचार पत्रों को किसी भी सामग्री को प्रकाशित करने से पूर्व सरकारी सेंसर अधिकारियों से अनिवार्य अनुमति लेनी पड़ती थी। सरकार की आलोचना करने वाली खबरों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसने मीडिया की स्वायत्तता को समाप्त कर उसे सरकार के प्रचार हेतु एक मात्र नियंत्रित माध्यम तक सीमित कर दिया था।

168. (A) वे व्यक्ति जो पद पर न होते हुए भी सरकार पर अत्यधिक प्रभाव रखते थे
अतिरिक्त-संवैधानिक प्राधिकरण उन व्यक्तियों या समूहों को संदर्भित करता है जिनके पास सरकार में कोई औपचारिक संवैधानिक या कानूनी पद नहीं था, फिर भी वे शासन के निर्णयों और नीतियों पर व्यापक प्रभाव रखते थे। आपातकाल के दौरान ऐसे केंद्रों का उदय हुआ जहां से सत्ता का वास्तविक संचालन किया जा रहा था। इससे सरकारी संस्थानों की गरिमा और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व की स्थापित संवैधानिक प्रक्रिया को अपूरणीय क्षति हुई।

169. (C) शक्तियाँ केंद्र में केंद्रित हुईं और राज्यों की स्वायत्तता कम हुई
आपातकाल ने भारतीय संविधान की संघीय प्रकृति को अस्थायी रुप से एक एकात्मक स्वरूप में बदल दिया था। शासन की समस्त महत्वपूर्ण शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास केंद्रित हो गई थीं। इसके परिणामस्वरूप राज्यों की विधायी और प्रशासनिक स्वायत्तता लगभग पूरी तरह समाप्त हो गई। केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए पूरे देश का प्रशासनिक नियंत्रण सीधे अपने हाथों में सुरक्षित कर लिया था।

170. (D) जबरन नसबंदी अभियान
आपातकाल की अवधि के दौरान जबरन नसबंदी अभियान सरकार का सबसे विवादास्पद कार्यक्रम सिद्ध हुआ। जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर चलाए गए इस अभियान में अक्सर अलोकतांत्रिक तरीके और बल प्रयोग किया गया। इसने समाज के साधारण वर्गों और ग्रामीण जनता के मन में गहरा भय और सरकार के प्रति भारी आक्रोश उत्पन्न किया। इस अभियान को नागरिक गरिमा और व्यक्तिगत अधिकारों के घोर उल्लंघन के रूप में देखा गया।

171. (C) आपातकाल पर एक जनमत संग्रह
1977 के लोकसभा चुनाव को भारतीय इतिहास में आपातकाल की अवधि के दौरान किए गए सरकारी कार्यों पर जनता के फैसले के रूप में देखा जाता है। यह चुनाव केवल राजनीतिक दलों के बीच की प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि यह आपातकाल की ज्यादतियों और लोकतांत्रिक मूल्यों की बहाली पर एक राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह था। मतदाताओं ने अपने मताधिकार के माध्यम से अधिनायकवाद और दमनकारी शासन को स्पष्ट रुप से नकारा।

(C) उर्दू
(D) हिंदी

53. जम्मू और कश्मीर में, 1974 के समझौते से पहले, राज्य सरकार के मुखिया को किस पदनाम से जाना जाता था?
(A) राज्यपाल
(B) मुख्यमंत्री
(C) प्रधानमंत्री
(D) सदर-ए-रियासत

54. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (अवधारणा)
P. द्रविड़ अस्मिता
Q. पंजाबी सूबा
R. कश्मीरियत
S. स्वर्णिम असम
सूची II: (संबंधित क्षेत्र)
1. पंजाब
2. तमिलनाडु
3. असम
4. जम्मू और कश्मीर
(A) P-2, Q-1, R-4, S-3
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

55. राजीव-लोंगोवाल समझौते में चंडीगढ़ किसे देने पर सहमति हुई थी?
(A) हरियाणा
(B) इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाए रखने पर
(C) इसे संयुक्त राजधानी बनाने पर
(D) पंजाब

56. 1992 की फिल्म 'रोजा' की पृष्ठभूमि किस विवाद पर आधारित थी?
(A) भारत-पाकिस्तान विवाद और कश्मीर मुद्दा
(B) पंजाब का उग्रवाद
(C) असम आंदोलन
(D) द्रविड़ आंदोलन

57. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन जम्मू-कश्मीर के बारे में असत्य है?
(A) 1947 से पहले यह एक राजसी रियासत थी।
(B) जम्मू क्षेत्र में मुख्य रूप से हिन्दू रहते हैं।
(C) शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फेरेंस पाकिस्तान में शामिल होने के पक्ष में थी।
(D) लद्दाख की जनसंख्या में बौद्ध और मुसलमान लगभग बराबर संख्या में हैं।

58. "एक समय क्षेत्रीय राजनीति को भारतीय राष्ट्र के लिए खतरा माना जाता था। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद के बीच सहकारिता की भावना का अच्छा उदाहरण पेश करती है।" यह निष्कर्ष किस आधार पर निकाला जा सकता है?
(A) क्योंकि द्रविड़ दल अब भारतीय संघ के भीतर ही स्वायत्तता चाहते हैं।
(B) क्योंकि तमिलनाडु ने उत्तर भारतीय हिंदी भाषा को अपना लिया है।
(C) क्योंकि द्रविड़ दलों ने कभी केंद्र सरकार में सहभागिता नहीं की।
(D) क्योंकि तमिलनाडु अब देश का सर्वाधिक विकसित औद्योगिक राज्य है।

59. 1960 में गठित 'ऑल पार्टी हिल्स कांफ्रेंस' बाद में किस राज्य के निर्माण का कारण बनी?
(A) केवल नगालैंड
(B) केवल मेघालय
(C) त्रिपुरा और मणिपुर
(D) मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश

60. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. जम्मू और कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया था।
2. 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री बने।
3. शेख अब्दुल्ला को 1953 में पदच्युत कर दिया गया था।
4. 1977 के विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फेरेंस ने बहुमत से जीत हासिल की।

उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3 और 4
(C) केवल 1, 2, और 3
(D) 1, 2, 3 और 4 सभी

61. 22 किलोमीटर लंबी एक पतली-सी राहदारी भारत के किस क्षेत्र को शेष भारत से जोड़ती है?
(A) जम्मू और कश्मीर
(B) दक्षिण भारत
(C) पूर्वोत्तर
(D) पश्चिमी तट

62. 'बाहरी' लोगों की समस्या त्रिपुरा में विशेष रूप से गंभीर क्यों है?
(A) क्योंकि वहाँ तेल के विशाल भंडार हैं।
(B) क्योंकि वहाँ की सीमा चीन से लगती है।
(C) क्योंकि वहाँ कोई संतुलित सरकार नहीं है।
(D) क्योंकि वहाँ के मूल निवासी खुद अपने ही प्रदेश में अल्पसंख्यक बन गए हैं।

63. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): 1990 के दशक के मध्यवर्ती वर्षों में पंजाब

बलपूर्वक दबाना एक स्थायी समाधान नहीं है।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

106. असम आंदोलन (1979-1985) का नेतृत्व किस संगठन ने किया था?
(A) ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू)
(B) असम गण परिषद् (एजीपी)
(C) यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा)
(D) बोडो लिबरेशन टाइगर्स (बीएलटी)

107. 1953 में शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री पद से क्यों हटाया गया था?
(A) क्योंकि उन्होंने भूमि सुधार लागू किए थे।
(B) क्योंकि वे चुनाव हार गए थे।
(C) क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया था।
(D) क्योंकि कश्मीर के दर्जे पर उनकी स्थिति को लेकर केंद्र सरकार से मतभेद हो गए थे।

108. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (समस्या/आंदोलन)
P. भाषायी पहचान और तनाव
Q. क्षेत्रीय असंतुलन से राज्य निर्माण
R. आदिवासी पहचान और अलगाववाद
S. सामाजिक-धार्मिक पहचान पर राज्य निर्माण
सूची II: (उदाहरण)
1. नगालैंड/मिजोरम
2. झारखंड/छत्तीसगढ़
3. पंजाब
4. तमिलनाडु
(A) P-4, Q-2, R-1, S-3
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-2, Q-3, R-4, S-1
(D) P-3, Q-4, R-1, S-2

109. 'आर्थिक विकास के एतबार से विभिन्न इलाकों के बीच असमानता' का एक संभावित परिणाम क्या हो सकता है?
(A) राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है।
(B) सभी क्षेत्र समान रूप से विकसित होते हैं।
(C) पिछड़े क्षेत्रों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है।
(D) अंतर्प्रान्तीय आप्रवास पूरी तरह से रुक जाता है।

110. शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद National कॉन्फेरेंस का नेतृत्व किसने संभाला?
(A) मुफ्ती मोहम्मद सईद
(B) गुलाम नबी आजाद
(C) उमर अब्दुल्ला
(D) फारुक अब्दुल्ला

111. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. 1987 में गोवा भारत संघ का एक राज्य बना।
2. गोवा, दमन और दीव 1961 तक पुर्तगाली उपनिवेश थे।
3. गोवा की मुक्ति के लिए महाराष्ट्र के समाजवादी सत्याग्रहियों ने भी आंदोलन किया था।
4. 1967 के जनमत सर्वेक्षण में गोवा के लोगों ने महाराष्ट्र में विलय के पक्ष में मत दिया।
उपरोक्त में से कौन से कथन असत्य हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 4
(C) केवल 2 और 3
(D) केवल 1 और 4

112. 1970 के दशक में अकालियों द्वारा पंजाब के लिए स्वायत्तता की माँग उठाने का मुख्य कारण क्या था?
(A) वे भारत से अलग होना चाहते थे।
(B) उन्हें लगा कि नए सीमांकन के बावजूद उनकी राजनीतिक स्थिति डावांडोल है।
(C) केंद्र सरकार ने पंजाब को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी।
(D) वे पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करवाना चाहते थे।

113. मिजो National फ्रंट को गुरिल्ला युद्ध के लिए किस देश की सरकार से समर्थन और ठिकाना मिला?
(A) चीन
(B) तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान
(C) म्यांमार
(D) नेपाल

114. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): 1947 में, कश्मीरी लोगों की क्षेत्रीय अभिलाषा 'कश्मीरियत' कहलाती थी।
कारण (R): कश्मीर के लोग सबसे पहले खुद को कश्मीरी मानते थे और उनका लोकप्रिय आंदोलन महाराजा से छुटकारा पाना चाहता था, न कि पाकिस्तान में शामिल होना।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

115. तमिलनाडु की राजनीति में 1967 के बाद से किन दलों का वर्चस्व रहा है?
(A) कांग्रेस और भाजपा
(B) कम्युनिस्ट दलों
(C) द्रविड़ दलों (डी.एम.के. और ए.आई.ए.डी.एम.के.)
(D) समाजवादी दलों

(B) 1960 के दशक में
(C) 1920 के दशक में
(D) 1980 के दशक में

74. 1986 में केंद्र में सत्तारुढ़ दल कांग्रेस के साथ नेशनल कांफ्रेंस के चुनावी गठबंधन का कश्मीर की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा?
(A) इससे यह भावना पुष्ट हुई कि केंद्र राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है।
(B) इससे कश्मीर में लोकतंत्र में विश्वास मजबूत हुआ।
(C) इससे अलगाववादी ताकतों का पूरी तरह सफाया हो गया।
(D) इससे कश्मीर में तत्काल शांति स्थापित हो गई।

75. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): भारत सरकार ने 1961 में गोवा में सेना भेजी।
कारण (R): पुर्तगाल शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से गोवा, दमन और दीव से अपना शासन हटाने से इनकार कर रहा था।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

76. 'द्रविड़ कड़गम' संगठन किसके वर्चस्व का विरोध करता था?
(A) केवल उत्तरी भारत
(B) ब्राह्मणों और उत्तरी भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व
(C) केवल ईसाइयों
(D) केवल ब्रिटिश शासन

77. 2002 में जम्मू और कश्मीर में हुए चुनावों के बाद किसकी मिली-जुली सरकार बनी?
(A) नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा
(B) पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस
(C) पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और काँग्रेस
(D) केवल काँग्रेस

78. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. 1997 में पंजाब में अकाली दल (बादल) और भाजपा के गठबंधन को विजय मिली।
2. यह उग्रवाद के खात्मे के बाद का पहला चुनाव था।
3. इस चुनाव के बाद पंजाब की राजनीति में धार्मिक पहचान का मुद्दा पूरी तरह समाप्त हो गया।
4. राज्य में राजनीति अब धर्मनिरपेक्षता की राह पर चल पड़ी है।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1, 2 और 4
(C) केवल 3 और 4
(D) सभी कथन सही हैं

79. मिजोरम में अलगाववादी आंदोलन को बल मिलने का एक प्रमुख कारण क्या था?
(A) 1959 के अकाल के दौरान असम सरकार की विफलता
(B) पड़ोसी देशों का हस्तक्षेप
(C) धार्मिक उत्पीड़न
(D) औद्योगिक पिछड़ापन

80. सिक्किम में चोग्याल विरोधी नेताओं ने भारत सरकार से मदद क्यों माँगी?
(A) वे चीन के साथ सिक्किम का विलय करना चाहते थे।
(B) उन्हें लगा कि चोग्याल अल्पसंख्यक लेपचा-भूटिया अभिजात वर्ग का शासन थोप रहे हैं।
(C) वे राजशाही को और मजबूत करना चाहते थे।
(D) वे सिक्किम को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे।

81. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (व्यक्ति)
P. राजीव गाँधी
Q. इंदिरा गाँधी
R. मनमोहन सिंह
S. शेख अब्दुल्ला

सूची II: (संबंधित घटना/कार्य)
1. 1974 का कश्मीर समझौता
2. सिख-विरोधी हिंसा के लिए माफी
3. ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश
4. असम समझौता

(A) P-4, Q-3, R-2, S-1
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-2, Q-1, R-4, S-3
(D) P-3, Q-4, R-1, S-2

82. सामान्यतः कश्मीरी लोगों की तीन मुख्य शिकायतें क्या रही हैं?
(A) जनमत-संग्रह के वायदे का पूरा न होना, स्वायत्तता में कमी, और लोकतंत्र का अभाव।
(B) भूमि सुधारों की कमी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार।
(C) धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव, बाहरी लोगों का आगमन और पर्यावरण का क्षरण।
(D) हिंदी भाषा का थोपा जाना, पर्यटन में कमी और औद्योगिक विकास का अभाव।

83. 1980 के दशक की शुरुआत में पंजाब में नरमपंथी अकालियों से आंदोलन का नेतृत्व किनके हाथों में चला गया?
(A) कांग्रेस नेताओं के
(B) किसान संगठनों के
(C) चरमपंथी तत्त्वों के
(D) वामपंथी दलों के

148. 1980 के दशक के पूर्वोत्तर में, स्वायत्तता की माँग पर 1970 के दशक में ही पहल हो चुकी थी। 1980 के दशक में कौन से दो मुद्दे नाटकीय रूप से उभरे?
(A) गरीबी और बेरोजगारी
(B) भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद
(C) भाषा और धर्म
(D) अलगाव के आंदोलन और 'बाहरी' लोगों का विरोध

149. भारत में लोकतंत्र की कौन-सी विशेषता विभिन्न दलों और समूहों को क्षेत्रीय पहचान और आकांक्षा को आधार बनाकर लोगों की नुमाइंदगी करने का अवसर देती है?
(A) सत्तावादी प्रवृत्ति
(B) एक-दलीय प्रणाली
(C) लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रिया
(D) केंद्र सरकार का कठोर नियंत्रण

150. संत हरचंद सिंह लोंगोवाल की हत्या कब हुई?
(A) ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान
(B) राजीव गाँधी के साथ समझौता करने के कुछ समय बाद
(C) इंदिरा गाँधी की हत्या के साथ
(D) 1990 के दशक में

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

भारतीय संघवाद के बहु-आयामी परिदृश्य में, क्षेत्रवाद एक सतत और गतिशील शक्ति के रूप में प्रकट होता है। यह एक जटिल घटना है, जो केवल नकारात्मक अलगाववादी प्रवृत्तियों तक ही सीमित नहीं है। सकारात्मक रूप में, क्षेत्रवाद किसी विशेष क्षेत्र के लोगों की अपनी अनूठी भाषाई, सांस्कृतिक और जातीय पहचान को व्यक्त करने और संरक्षित करने की सामूहिक आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रायः ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों में निहित होता है। हालाँकि, जब इन आकांक्षाओं को राजनीतिक और आर्थिक शिकायतों, जैसे संसाधनों के असमान वितरण, केंद्र सरकार द्वारा कथित उपेक्षा, या राजनीतिक स्वायत्तता की कमी, के साथ जोड़ा जाता है, तो यह नकारात्मक रूप ले सकता है। इस नकारात्मक अभिव्यक्ति में स्वायत्त राज्यों की माँग से लेकर पूर्ण अलगाववाद तक शामिल हो सकता है। भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक राजनीति ने इन अभिव्यक्तियों के लिए एक संस्थागत ढाँचा प्रदान किया है। राजनीतिक दल, दबाव समूह और जन आंदोलन इन क्षेत्रीय भावनाओं को व्यक्त करने के लिए महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार, भारतीय लोकतंत्र में क्षेत्रवाद को केवल एक विघटनकारी शक्ति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय पहचान के बीच निरंतर संवाद और समायोजन की प्रक्रिया के रूप में भी समझा जाना चाहिए।

उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

151. स्रोत के अनुसार, भारतीय संघवाद में क्षेत्रवाद की सकारात्मक अभिव्यक्ति क्या है?
(A) राजनीतिक स्वायत्तता के लिए पूर्ण अलगाववाद की मांग करना
(B) अपनी विशिष्ट भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को व्यक्त और संरक्षित करना
(C) केंद्र सरकार के विरुद्ध हिंसक और सशस्त्र विद्रोह का रास्ता अपनाना
(D) अन्य पड़ोसी क्षेत्रों पर अपना आर्थिक प्रभुत्व और वर्चस्व स्थापित करना

152. क्षेत्रवाद की भावना नकारात्मक रूप कब ले सकती है?
(A) जब इसे राजनीतिक और आर्थिक शिकायतों के साथ जोड़ा जाता है
(B) जब यह केवल सांस्कृतिक उत्सवों तक सीमित हो
(C) जब केंद्र सरकार सभी क्षेत्रों को समान संसाधन प्रदान करती है
(D) जब विभिन्न क्षेत्रों के बीच कोई ऐतिहासिक भिन्नता नहीं होती है

153. निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम नहीं है, जैसा कि अनुच्छेद में वर्णित है?
(A) राजनीतिक दल
(B) दबाव समूह
(C) एक सत्तावादी शासन
(D) जन आंदोलन

154. अनुच्छेद के अनुसार, क्षेत्रवाद की नकारात्मक अभिव्यक्ति का चरम रूप क्या हो सकता है?
(A) सांस्कृतिक त्योहारों का आयोजन
(B) भाषाई संरक्षण के लिए अभियान
(C) अंतर-राज्यीय व्यापार समझौते
(D) पूर्ण अलगाववाद की मांग

155. स्रोत का समग्र दृष्टिकोण क्षेत्रवाद को किस रूप में प्रस्तुत करता है?
(A) इसे भारतीय लोकतंत्र की स्थिरता के लिए एक मात्र गंभीर खतरा मानना
(B) आधुनिक राजनीतिक परिवेश में पूरी तरह से एक अप्रासंगिक अवधारणा होना
(C) राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय पहचान के बीच एक गतिशील समायोजन प्रक्रिया
(D) सामाजिक विकास को छोड़कर केवल आर्थिक संसाधनों से संबंधित मुद्दा होना

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

1973 में पंजाब में अकाली दल द्वारा पारित आनंदपुर साहिब प्रस्ताव भारतीय राजनीति में केंद्र-राज्य संबंधों और क्षेत्रीय स्वायत्तता की बहस में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। यह प्रस्ताव दो प्रमुख उद्देश्यों से प्रेरित था: पहला, सिख पहचान को एक विशिष्ट 'कौम' (राष्ट्र) के रूप में स्थापित करना और दूसरा, पंजाब के लिए अधिक राजनीतिक और आर्थिक स्वायत्तता प्राप्त करना। प्रस्ताव में मांग की गई कि केंद्र सरकार

(C) यह हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित करती है।
(D) यह राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रक्रिया को आसान बनाती है।

96. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (राज्य)
P. नगालैंड
Q. मणिपुर
R. मिजोरम
S. मेघालय
सूची II: (राज्य बनने का वर्ष)
1. 1972
2. 1987
3. 1963
4. 1972
(A) P-3, Q-1, R-2, S-4
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-2, Q-3, R-4, S-1
(D) P-3, Q-4, R-2, S-1

97. 1989 में कश्मीरी उग्रवादियों को किस देश से नैतिक, आर्थिक और फौजी समर्थन मिला?
(A) चीन
(B) पाकिस्तान
(C) अफगानिस्तान
(D) ईरान

98. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भारत के लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को सही ढंग से वर्णित करता है?
(A) क्षेत्रीयता को राष्ट्र-विरोधी नहीं माना जाता और क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति की अनुमति है।
(B) सभी क्षेत्रीय माँगों को बलपूर्वक दबा दिया जाता है।
(C) केवल राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे ही राजनीति में उठाए जा सकते हैं।
(D) भारत में सांस्कृतिक विभिन्नता को राष्ट्र की एकता के लिए खतरा माना जाता है।

99. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. ई.वी. रामास्वामी नायकर को 'पेरियार' के नाम से जाना जाता है।
2. वे जाति-विरोधी आंदोलन और द्रविड़ अस्मिता के उद्भावक थे।
3. उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन (1925) का सूत्रपात किया।
4. उन्होंने हिंदी और उत्तर भारतीय वर्चस्व का समर्थन किया।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1, 2 और 3
(C) केवल 3 और 4
(D) सभी कथन सही हैं

100. 1984 के सिख-विरोधी दंगों से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला शहर कौन-सा था?
(A) अमृतसर
(B) चंडीगढ़
(C) कानपुर
(D) दिल्ली

101. निम्नलिखित में से किस नेता ने धर्मनिरपेक्षता के आधार पर पाकिस्तान में जम्मू-कश्मीर के विलय का विरोध किया था?
(A) महाराजा हरि सिंह
(B) मोहम्मद अली जिन्ना
(C) शेख मोहम्मद अब्दुल्ला
(D) सरदार पटेल

102. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन आबादी कम है।
2. इस क्षेत्र की सीमाएँ चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती हैं।
3. यह इलाका भारत के लिए एक तरह से दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेश-द्वार है।
4. 22 किलोमीटर लंबी एक पतली-सी राहदारी इस इलाके को शेष भारत से जोड़ती है।
5. इस क्षेत्र में विकास पर हमेशा से बहुत ध्यान दिया गया है।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2, 3
(B) केवल 2, 3, 4
(C) केवल 1, 3, 5
(D) सभी कथन सही हैं

103. 'यूनाइटेड गोअन पार्टी' (यूजीपी) का मुख्य उद्देश्य क्या था?
(A) गोवा का महाराष्ट्र में विलय।
(B) गोवा में पुर्तगाली शासन की वापसी।
(C) गोवा को एक कम्युनिस्ट राज्य बनाना।
(D) गोवा की स्वतंत्र गोवानी पहचान और संस्कृति को बनाए रखना।

104. 1992 में जब पंजाब में चुनाव हुए तो मतदान का प्रतिशत बहुत कम (महज 24 फीसदी) क्यों था?
(A) संशय और हिंसा से भरे माहौल के कारण।
(B) लोगों की चुनाव में रुचि नहीं थी।
(C) चुनाव आयोग ने मतदान पर रोक लगा दी थी।
(D) सभी प्रमुख दलों ने चुनाव का बहिष्कार किया था।

105. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): 1980 के दशक के बाद की अवधि में क्षेत्रीय आकांक्षाओं के साथ बातचीत और सुलह की नीति अपनाई गई।
कारण (R): सरकार ने माना कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को

84. 'चकमा' शरणार्थियों का मुद्दा भारत के किन दो राज्यों में तनाव का कारण रहा है?
(A) पंजाब और हरियाणा
(B) तमिलनाडु और केरल
(C) गुजरात और राजस्थान
(D) मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश

85. निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें:
1. डी.एम.के. द्वारा तीन-सूत्री आंदोलन
2. आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत
3. तमिलनाडु में डी.एम.के. की पहली बार सरकार बनी
4. हिंदी-विरोधी आंदोलन
(A) 2, 1, 4, 3
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 4, 3, 2, 1
(D) 3, 4, 1, 2

86. 1947 में नेशनल कॉन्फेरेंस की क्या मुख्य माँगें थीं?
(A) महाराजा का शासन बनाए रखना और भारत में शामिल होना
(B) महाराजा से छुटकारा और पाकिस्तान में शामिल न होना
(C) पाकिस्तान में शामिल होना और राजशाही खत्म करना
(D) एक स्वतंत्र राष्ट्र बनना और राजशाही बनाए रखना

87. भारत में राष्ट्रवाद ने एकता और विविधता के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है, इसका क्या अर्थ है?
(A) विविधता को खत्म करके एकता स्थापित करना।
(B) एकता को नकार कर केवल विविधता पर जोर देना।
(C) सभी क्षेत्रों पर एक ही संस्कृति थोपना।
(D) समाज को आकार देने वाली विभिन्न संस्कृतियों की विशिष्टता को बनाए रखते हुए एकता की भावना से बँधे रहना।

88. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. 1947 के भारत-विभाजन से पूर्वोत्तर के इलाके भारत के शेष भागों से अलग-थलग पड़ गए।
2. इस अलगाव का पूर्वोत्तर की अर्थव्यवस्था पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा।
3. पूर्वोत्तर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा काफी छोटी है।
4. पूर्वोत्तर की राजनीति का स्वभाव ज्यादा संवेदनशील रहा है।

उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं?
(A) केवल 1 और 4
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) सभी कथन सही हैं

89. 1974 में सिक्किम में हुए पहले लोकतांत्रिक चुनाव में किस पार्टी को भारी विजय मिली?
(A) सिक्किम नेशनल पार्टी
(B) सिक्किम प्रजा मंडल
(C) सिक्किम कांग्रेस
(D) चोग्याल समर्थक पार्टी

90. आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में सिखों के 'बोलबाला' (प्रभुत्व) का क्या अभिप्राय था?
(A) सिख 'कौम' (समुदाय) की आकांक्षाओं पर जोर देना।
(B) सिखों के लिए एक अलग देश।
(C) अन्य सभी धर्मों पर सिख धर्म की श्रेष्ठता।
(D) केवल सिखों को सरकारी नौकरी देना।

91. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): 1967 के विधानसभा चुनावों में डी.एम.के. को तमिलनाडु में बड़ी सफलता हाथ लगी।
कारण (R): 1965 के हिंदी विरोधी आंदोलन की सफलता ने डी.एम.के. को लोकप्रिय बना दिया था।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

92. गोवा की मुक्ति के बाद 'महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी' की मुख्य माँग क्या थी?
(A) गोवा को एक स्वतंत्र देश बनाना।
(B) गोवा का महाराष्ट्र में विलय करना।
(C) कोंकणी को राष्ट्रीय भाषा बनाना।
(D) पुर्तगाल के साथ फिर से संबंध स्थापित करना।

93. क्षेत्रीय आकांक्षाओं के संबंध में एक बुनियादी सबक क्या है?
(A) क्षेत्रीय आकांक्षाओं को हमेशा दबा देना चाहिए।
(B) सभी क्षेत्रीय आकांक्षाएँ राष्ट्र-विरोधी होती हैं।
(C) क्षेत्रीय आकांक्षाएँ लोकतांत्रिक राजनीति का एक अभिन्न अंग हैं।
(D) क्षेत्रीय आकांक्षाएँ केवल आर्थिक विकास से संबंधित होती हैं।

94. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन मिजोरम के शांति समझौते के बारे में सत्य है?
(A) यह समझौता सेना और विद्रोहियों के बीच हुआ था।
(B) समझौते के बाद मिजोरम असम का हिस्सा बना रहा।
(C) समझौते ने अलगाववादी संघर्ष को और तेज कर दिया।
(D) राजीव गाँधी और लालडेंगा के बीच हुए समझौते के बाद मिजोरम एक शांतिपूर्ण राज्य बन गया।

95. संविधान की छठी अनुसूची का क्या महत्व है, विशेषकर पूर्वोत्तर के संदर्भ में?
(A) यह विभिन्न जनजातियों को अपने पारंपरिक नियमों को संरक्षित रखने की स्वायत्तता देती है।
(B) यह सभी राज्यों को समान अधिकार देती है।

116. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. संत हरचंद सिंह लोंगोवाल 1980 में अकाली दल के अध्यक्ष थे।
2. उन्होंने प्रधानमंत्री राजीव गाँधी के साथ पंजाब समझौते पर हस्ताक्षर किए।
3. समझौते के तुरंत बाद उनकी हत्या एक अज्ञात सिख युवक द्वारा कर दी गई।
4. वे नरमपंथी अकाली नेता माने जाते थे।
5. उन्होंने 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' का समर्थन किया था।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2, 3
(B) केवल 1, 2, 3, 4
(C) केवल 3, 4, 5
(D) सभी कथन सही हैं

117. 1953 से 1974 के बीच की अवधि में जम्मू-कश्मीर की राजनीति में किस पार्टी का प्रभाव सबसे अधिक रहा?
(A) नेशनल कॉन्फ्रेंस
(B) जन संघ
(C) कांग्रेस पार्टी
(D) पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी

118. आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को विवादास्पद क्यों माना गया?
(A) क्योंकि इसने केंद्र-राज्य संबंधों पर कोई बात नहीं की।
(B) क्योंकि इसने सिख 'कौम' की आकांक्षाओं पर जोर देते हुए सिखों के 'बोलबाला' का ऐलान किया, जिसकी व्याख्या अलगाववादी माँग के रूप में की जा सकती थी।
(C) क्योंकि यह पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी द्वारा तैयार किया गया था।
(D) क्योंकि इसने पंजाब के पूर्ण विलय की माँग की थी।

119. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (घटना)
P. आनंदपुर साहिब प्रस्ताव
Q. ऑपरेशन ब्लू स्टार
R. राजीव-लोंगोवाल समझौता
S. मिज़ोरम को राज्य का दर्जा

सूची II: (वर्ष)
1. 1984
2. 1987
3. 1973
4. 1985

(A) P-3, Q-1, R-4, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-2, Q-4, R-1, S-3
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

120. काजी लेंडुप दोरजी खांगसरपा किस आंदोलन के नेता थे?
(A) सिक्किम में लोकतंत्र बहाली आंदोलन
(B) नगालैंड स्वतंत्रता आंदोलन
(C) असम में बाहरी विरोधी आंदोलन
(D) पंजाब में खालिस्तान आंदोलन

121. असम में 'बाहरी' लोगों के खिलाफ चले आंदोलन का सबसे अच्छा उदाहरण किस अवधि में देखने को मिलता है?
(A) 1961 से 1965
(B) 1971 से 1975
(C) 1979 से 1985
(D) 1991 से 1995

122. आज़ादी के बाद, देसी रियासतों के विलय के दौरान, जम्मू-कश्मीर के अलावा और किन क्षेत्रों में अलगाव की माँगें उठीं?
(A) नगालैंड और मिज़ोरम में
(B) केवल पंजाब में
(C) केवल द्रविड़ आंदोलन में
(D) केवल बंगाल में

123. निम्नलिखित में से कौन-सा जोड़ा सही सुमेलित है?
(A) अनुच्छेद 370 - पंजाब
(B) ऑपरेशन ब्लू स्टार - मिज़ोरम
(C) असम समझौता - 1990
(D) पेरियार - द्रविड़ आंदोलन

124. भारतीय सेना द्वारा मिज़ोरम में विद्रोही गतिविधियों को दबाने के लिए की गई जवाबी कार्रवाई का स्थानीय लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा?
(A) स्थानीय लोगों ने सेना का पूरा समर्थन किया।
(B) स्थानीय लोगों में क्रोध और अलगाव की भावना और तेज हुई।
(C) विद्रोही तुरंत आत्मसमर्पण कर गए।
(D) इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

125. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): सिक्किम का भारत में विलय स्थानीय जनता के समर्थन से हुआ।
कारण (R): सिक्किम में हुए जनमत-संग्रह में जनता ने विधानसभा के भारत में पूर्ण विलय के प्रस्ताव पर अपनी मुहुराई थी।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

126. 2014 में जम्मू और कश्मीर में हुए चुनावों का क्या परिणाम निकला?
(A) नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूर्ण बहुमत मिला।
(B) कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला।
(C) राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया।
(D) पीडीपी और बीजेपी की मिली-जुली सरकार बनी।

में शांति बहाल हुई।
कारण (R): 1985 के पंजाब समझौते को तुरंत और पूरी तरह से लागू कर दिया गया था।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

64. असम आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने किस तेलशोधक कारखाने को तेल-आपूर्ति रोकने की कोशिश की?
(A) डिगबोई
(B) बरौनी
(C) नुमालीगढ़
(D) मथुरा

65. निम्नलिखित में से किसे 'पेरियार' के नाम से जाना जाता है?
(A) सी. राजगोपालाचारी
(B) ई. वी. रामास्वामी नायकर
(C) के. कामराज
(D) सी. एन. अन्नादुरै

66. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (दल/संगठन)
P. नेशनल कॉन्फेरेंस
Q. अकाली दल
R. मिज़ो National फ्रंट
S. आसू (AASU)
सूची II: (प्रमुख गतिविधि/माँग)
1. पंजाबी सूबा का गठन
2. अवैध आप्रवासियों का विरोध
3. कश्मीर की स्वायत्तता
4. मिज़ो राष्ट्र की स्वतंत्रता का सशस्त्र संघर्ष
(A) P-3, Q-1, R-4, S-2
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-1, Q-2, R-3, S-4
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

67. 1980 के दशक के त्रासद घटनाओं के चक्र में निम्नलिखित में से कौन-सी घटना शामिल नहीं है?
(A) ऑपरेशन ब्लू स्टार
(B) इंदिरा गाँधी की हत्या
(C) कारगिल युद्ध
(D) सिख-विरोधी दंगे

68. भारत की संघीय प्रणाली को लचीला क्यों कहा गया है?
(A) क्योंकि यहाँ के सभी राज्यों को पूर्णतः समान अधिकार प्रदान किए गए हैं।
(B) क्योंकि केंद्र सरकार राज्यों की तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली बनाई गई है।
(C) क्योंकि किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने की पूर्ण स्वतंत्रता है।
(D) क्योंकि कुछ विशेष राज्यों के हितों हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं।

69. निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें:
1. सिक्किम भारत का 22वाँ राज्य बना
2. गोवा भारत का एक राज्य बना
3. पंजाब और हरियाणा का गठन
4. मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य बने
(A) 3, 1, 4, 2
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 3, 1, 4
(D) 4, 1, 2, 3

70. "क्षेत्रीय आकांक्षाएँ लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग हैं।" इस कथन का क्या तात्पर्य है?
(A) क्षेत्रीय माँगें लोकतंत्र को कमजोर करती हैं।
(B) लोकतंत्र में अपनी विशिष्ट संस्कृति और समस्याओं के आधार पर राजनीतिक माँगें उठाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।
(C) सभी क्षेत्रीय माँगें अंततः अलगाववाद की ओर ले जाती हैं।
(D) केवल राष्ट्रीय दलों को ही राजनीति में भाग लेना चाहिए।

71. निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है?
(A) मास्टर तारा सिंह - पंजाबी सूबा की माँग
(B) अंगमी जापू फिजो - नगा नेशनल काउंसिल
(C) लालडेंगा - मिज़ो National फ्रंट
(D) शेख अब्दुल्ला - द्रविड़ कड़गम

72. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. 1979 से 1985 तक चला असम आंदोलन बाहरी लोगों के खिलाफ था।
2. असमी लोगों को संदेह था कि बांग्लादेश से आकर मुस्लिम आबादी असम में बस रही है।
3. आंदोलनकारियों का मानना था कि इससे स्थानीय असमी जनता अल्पसंख्यक हो जाएगी।
4. आंदोलन का एक कारण असम के प्राकृतिक संसाधनों का लाभ स्थानीय लोगों को न मिलना भी था।
5. यह आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2, 3
(B) केवल 4, 5
(C) केवल 1, 2, 3, 4
(D) सभी कथन सही हैं

73. सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में अकाली दल का गठन किस दशक में हुआ था?
(A) 1940 के दशक में

137. 1953-54 में डी.एम.के. द्वारा उठाए गए शिल्पकर्म शिक्षा कार्यक्रम के विरोध का मुख्य कारण क्या था?
(A) यह कार्यक्रम बहुत महंगा था।
(B) यह तमिल संस्कृति के खिलाफ था।
(C) संगठन के अनुसार यह नीति समाज में ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देती थी।
(D) यह कार्यक्रम केवल अंग्रेजी भाषा में था।

138. भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 से ही द्वंद्व का प्रमुख मुद्दा कौन-सा मामला बना रहा है?
(A) कश्मीर का मामला
(B) जल बँटवारा
(C) सीमा विवाद
(D) व्यापारिक संबंध

139. 1974 के समझौते के बाद जम्मू-कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने?
(A) शेख अब्दुल्ला
(B) फारुक अब्दुल्ला
(C) मुफ्ती मोहम्मद सईद
(D) सदर-ए-रियासत

140. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. 1980 के दशक में देश के कई हिस्सों से स्वायत्तता की माँग उठी।
2. इन आंदोलनों में शामिल लोगों ने कभी हथियार नहीं उठाए।
3. सरकार ने इन आंदोलनों को दबाने के लिए हमेशा केवल बातचीत का रास्ता अपनाया।
4. स्वायत्तता की माँग को लेकर चले अधिकतर संघर्ष लंबे समय तक जारी रहे।

उपरोक्त में से कौन से कथन असत्य हैं?
(A) केवल 1 और 4
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) केवल 2 और 4

141. राष्ट्रीय एकता के सरोकार और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बीच तनाव कब उत्पन्न हो सकता है?
(A) जब दोनों एक-दूसरे का सम्मान करते हैं।
(B) जब दोनों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समान स्थान मिले।
(C) जब राष्ट्रीय एकता के सरोकार क्षेत्रीय ज़रूरतों पर भारी पड़ें, या क्षेत्रीय सरोकारों के कारण राष्ट्र की वृहत्तर आवश्यकताओं की अनदेखी हो।
(D) जब आर्थिक विकास समान रूप से हो।

142. लालडेंगा ने भारत सरकार के साथ बातचीत कब शुरु की?
(A) भारत आने के तुरंत बाद
(B) 1959 के अकाल के दौरान
(C) 1986 के समझौते के बाद
(D) पाकिस्तान में निर्वासित जीवन जीते हुए

143. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन पंजाब समझौते (राजीव-लोंगोवाल समझौता) का हिस्सा नहीं था?
(A) पंजाब में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा।
(B) चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा।
(C) पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा-विवाद के लिए अलग आयोग की नियुक्ति होगी।
(D) रावी-व्यास के पानी के बँटवारे के लिए एक न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) बैठाया जाएगा।

144. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): 1990 के दशक में तमिलनाडु की राजनीति में कई नए द्रविड़ दल अस्तित्व में आए।
कारण (R): इन सभी दलों ने क्षेत्रीय गौरव के मुद्दे को किसी न किसी रूप में जिंदा रखा है।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

145. “आसू” (AASU) का पूरा नाम क्या है?
(A) ऑल असम सेक्युलर यूनियन
(B) ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन
(C) असम-आदिवासी संघर्ष यूनियन
(D) असम एंड अरुणाचल स्टूडेंट्स यूनियन

146. जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन से पहले, लद्दाख क्षेत्र की जनसंख्या की क्या विशेषता थी?
(A) इसमें लगभग बराबर संख्या में बौद्ध और मुसलमान थे।
(B) यह पूरी तरह से बौद्ध था।
(C) यह पूरी तरह से मुस्लिम था।
(D) इसमें हिन्दू बहुमत में थे।

147. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. शेख मोहम्मद अब्दुल्ला राजशाही के खिलाफ जन आंदोलन के नेता थे।
2. वे जम्मू-कश्मीर की स्वायत्तता और धर्मनिरपेक्षता के समर्थक थे।
3. वे भारत में विलय के बाद जम्मू-कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री बने।
4. उन्हें 1953 में भारत सरकार द्वारा बर्खास्त कर कारावास में डाल दिया गया था।
5. उन्होंने 1974 में इंदिरा गाँधी के साथ समझौता कर मुख्यमंत्री का पद संभाला।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2, 3
(B) केवल 3, 4, 5
(C) केवल 1, 2, 4, 5
(D) सभी कथन सही हैं

127. "क्षेत्रीय आकांक्षाओं से निपटने का सबसे अच्छा तरीका लोकतांत्रिक बातचीत है।" किस राज्य का उदाहरण इस संदर्भ में प्रमुखता से देखा जा सकता है?
(A) मिजोरम, जहाँ समझौते से स्थायी शांति आई।
(B) पंजाब, जहाँ समस्या जटिल बनी रही।
(C) जम्मू और कश्मीर, जहाँ संघर्ष लंबा चला।
(D) असम, जहाँ आप्रवास का मुद्दा बना हुआ है।

128. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. 1963 में नगालैंड को राज्य बनाया गया।
2. 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्य बने।
3. 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया।
4. सिक्किम 1975 में भारत का राज्य बना।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3 और 4
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) 1, 2, 3 और 4 सभी

129. महबूबा मुफ्ती किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं?
(A) पंजाब
(B) जम्मू और कश्मीर
(C) असम
(D) मिजोरम

130. 1960 के दशक के उत्तरार्द्ध में पंजाबी-भाषी लोगों द्वारा अलग राज्य की माँग को कब माना गया?
(A) 1966
(B) 1960
(C) 1971
(D) 1984

131. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. मास्टर तारा सिंह एक प्रमुख सिख धार्मिक और राजनीतिक नेता थे।
2. वे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के शुरुआती नेताओं में से थे।
3. वे स्वतंत्रता के बाद अलग पंजाब राज्य के निर्माण के समर्थक थे।
4. वे मुस्लिमों के साथ समझौते की कांग्रेस नीति के घोर समर्थक थे।
5. उन्होंने अकाली आंदोलन का नेतृत्व किया।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2, 3, 5
(B) केवल 1, 2, 3, 4
(C) केवल 3, 4, 5
(D) सभी कथन सही हैं

132. 'पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी' (पीडीपी) का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है?
(A) पंजाब
(B) असम
(C) तमिलनाडु
(D) जम्मू और कश्मीर

133. किस घटना ने सिखों की भावनाओं को गहरी चोट पहुँचाई और चरमपंथी समूहों को और बल दिया?
(A) आनंदपुर साहिब प्रस्ताव
(B) पंजाब समझौता
(C) ऑपरेशन ब्लू स्टार में स्वर्णमंदिर को हुई क्षति
(D) 1966 का राज्य पुनर्गठन

134. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): 1990 के दशक में तमिलनाडु की राजनीति में भाजपा एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरी।
कारण (R): इस अवधि के दौरान पूर्वोत्तर की राजनीतिक प्रवृत्तियों में कोई बदलाव नहीं आया।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

135. सात अलग-अलग भाषाओं का इस्तेमाल करने वाले एक विज्ञापन या पोस्टर का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है?
(A) केवल उत्तराखंड के लोगों तक बात पहुँचाना।
(B) यह दिखाना कि क्षेत्रीय आकांक्षाएँ केवल स्थानीय भाषा में व्यक्त होती हैं।
(C) विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना।
(D) तमाम भारतीय नागरिकों तक अपनी बात पहुँचाना और यह दर्शाना कि क्षेत्रीय आकांक्षा राष्ट्रीय भावना के विरुद्ध नहीं है।

136. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (दल/संगठन)
P. महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी
Q. यूनाइटेड गोअन पार्टी
R. सिक्किम कांग्रेस
S. असम गण परिषद्

सूची II: (मुख्य माँग/विचारधारा)
1. गोवा का महाराष्ट्र में विलय
2. अवैध प्रवासियों का विरोध
3. सिक्किम का भारत में विलय
4. गोवा की अलग पहचान

(A) P-1, Q-4, R-3, S-2
(B) P-2, Q-3, R-4, S-1
(C) P-3, Q-2, R-1, S-4
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

का अधिकार क्षेत्र केवल रक्षा, विदेश मामले, संचार और मुद्रा तक सीमित होना चाहिए, जबकि अन्य सभी विषय राज्य को हस्तांतरित किए जाने चाहिए। इसने चंडीगढ़ को पंजाब की एकमात्र राजधानी बनाने और पड़ोसी राज्यों के पंजाबी भाषी क्षेत्रों को पंजाब में शामिल करने की भी मांग की। यद्यपि प्रस्ताव के लेखक इसे भारतीय संघीय ढांचे के भीतर एक मजबूत राज्य की वकालत के रूप में देखते थे, लेकिन इसके कुछ अंशों की व्याख्या आलोचकों और केंद्र सरकार द्वारा एक अलगाववादी एजेंडे की दिशा में एक कदम के रूप में की गई। इस प्रस्ताव का उपयोग बाद में जरनैल सिंह भिंडरांवाले जैसे चरमपंथी नेताओं द्वारा एक स्वतंत्र सिख राज्य, खालिस्तान, की मांग को बढ़ावा देने के लिए किया गया, जिसने पंजाब को उग्रवाद और हिंसा के एक दशक लंबे दौर में धकेल दिया। इस प्रकार, जो एक क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग के रूप में शुरु हुआ था, वह अंततः एक हिंसक अलगाववादी आंदोलन का आधार बन गया।

उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

156. आनंदपुर साहिब प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था?
(A) 1966
(B) 1973
(C) 1984
(D) 1985

157. प्रस्ताव के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं रहना था?
(A) रक्षा
(B) विदेश मामले
(C) मुद्रा
(D) कृषि

158. आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का एक प्रमुख उद्देश्य क्या था?
(A) सिख पहचान को एक विशिष्ट 'कौम' के रूप में स्थापित करना
(B) भारत के सभी राज्यों के लिए समान शक्तियों की मांग करना
(C) पंजाब के पूर्ण विलय की मांग करना
(D) देश में राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार की वकालत करना

159. स्रोत के अनुसार, किस चरमपंथी नेता ने प्रस्ताव का उपयोग खालिस्तान की मांग को बढ़ावा देने के लिए किया?
(A) हरचंद सिंह लोंगोवाल
(B) प्रकाश सिंह बादल
(C) जरनैल सिंह भिंडरांवाले
(D) गुरुचरण सिंह तोहड़ा

160. आलोचकों ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की व्याख्या किस रूप में की?
(A) एक अलगाववादी एजेंडे की दिशा में एक कदम के रूप में
(B) भारतीय संघवाद को मजबूत करने के एक प्रयास के रूप में
(C) एक आर्थिक सुधार पैकेज के रूप में
(D) पड़ोसी राज्यों के साथ बेहतर संबंधों की एक पहल के रूप में

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

1979 से 1985 तक चला असम आंदोलन, जिसे 'असम आंदोलन' के नाम से जाना जाता है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़े और सबसे लंबे समय तक चले जनांदोलनों में से एक था। इसका नेतृत्व मुख्य रूप से 'ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन' (आसू) और 'असम गण संग्राम परिषद' ने किया था, जिनका स्वरुप गैर-राजनीतिक था। आंदोलन की जड़ें असम की जटिल जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक समस्याओं में थीं। आंदोलनकारियों की मुख्य चिंता असम में बांग्लादेश (तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान) से अवैध आप्रवासियों के अनियंत्रित प्रवाह को लेकर थी, जिसने राज्य की जनसांख्यिकीय संरचना को बदलने और स्थानीय आबादी के लिए संसाधनों पर दबाव डालने का खतरा पैदा कर दिया था। आंदोलन की प्रमुख मांग यह थी कि विदेशी नागरिकों का पता लगाया जाए, उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाएं और उन्हें निर्वासित किया जाए। इस आंदोलन ने विरोध के विभिन्न रुपों का उपयोग किया, जिसमें बंद, हड़ताल, प्रदर्शन और तेल पाइपलाइनों की नाकाबंदी शामिल थी। छह साल की लंबी अवधि के बाद, आंदोलन का समापन अगस्त 1985 में भारत सरकार और आंदोलन के नेताओं के बीच 'असम समझौते' पर हस्ताक्षर के साथ हुआ। इस समझौते में 25 मार्च, 1971 को विदेशी नागरिकों की पहचान और निर्वासन के लिए कट-ऑफ तारीख के रूप में निर्धारित किया गया और असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान की रक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों का वादा किया गया।

उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

161. असम आंदोलन का नेतृत्व करने वाला प्रमुख संगठन कौन सा था?
(A) असम कांग्रेस समिति
(B) यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम (उल्फा)
(C) बोडो सुरक्षा बल
(D) ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू)

162. असम आंदोलन की मुख्य चिंता क्या थी?
(A) एक अलग राज्य की मांग
(B) बांग्लादेश से अवैध आप्रवासियों का प्रवाह
(C) औद्योगिक विकास की कमी
(D) हिंदी भाषा का अधिरोपण

163. असम समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे?
(A) 1979
(B) 1984
(C) 1985

ANSWERS

1. (B) स्वायत्तता की माँग
1980 के दशक को भारत में स्वायत्तता की माँग के दशक के रूप में जाना जाता है। इस दौरान देश के कई हिस्सों, जैसे पंजाब और पूर्वोत्तर भारत में क्षेत्रीय अस्मिता और अधिकारों के लिए प्रबल आंदोलन चले। इन आंदोलनों ने केंद्र सरकार से अधिक संवैधानिक अधिकारों और राज्यों के लिए स्वायत्तता की पुरजोर वकालत की।

2. (A) लोकतांत्रिक दृष्टिकोण
भारत ने अपनी विशाल विविधता को संभालने के लिए लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया है। यहाँ क्षेत्रीय आकांक्षाओं को राष्ट्र विरोधी नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें राजनीति की मुख्यधारा में स्थान दिया जाता है। इस नजरिये के तहत विभिन्न समुदायों को अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखने और राजनीतिक माँगों को लोकतांत्रिक ढंग से व्यक्त करने की पूरी अनुमति है।

3. (C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
आज़ादी के तुरंत बाद जम्मू-कश्मीर रियासत का विवाद गहरा गया था। उस समय वहां के शासक महाराजा हरि सिंह अपनी रियासत को भारत या पाकिस्तान किसी में भी शामिल नहीं करना चाहते थे। वे कश्मीर के लिए एक स्वतंत्र दर्जे की इच्छा रखते थे, जबकि पाकिस्तान ने दबाव बनाकर कश्मीर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए घुसपैठ का सहारा लिया।

4. (D) आंदोलन का नेतृत्व प्रारंभ में सी. अन्नादुरै के हाथों में था।
द्रविड़ आंदोलन भारत के सबसे शक्तिशाली क्षेत्रीय आंदोलनों में से एक रहा है, जिसका आधार भाषायी और सांस्कृतिक अस्मिता थी। इस आंदोलन का नेतृत्व प्रारंभ में ई.वी. रामास्वामी नायकर 'पेरियार' ने किया था, न कि सी. एन. अन्नादुरै ने। पेरियार ने ब्राह्मणवाद और उत्तर भारतीय प्रभुत्व के विरोध में आत्मसम्मान आंदोलन चलाकर इस विचारधारा की ठोस नींव रखी थी।

5. (C) विभाजन, विस्थापन, रियासतों का विलय और राज्यों का पुनर्गठन
1947 में आज़ादी मिलने के बाद भारत को अत्यंत कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। राष्ट्र के सामने विभाजन की त्रासदी, शरणार्थियों का पुनर्वास और देसी रियासतों के भारत संघ में विलय जैसे गंभीर मुद्दे थे। इसके अतिरिक्त, भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना भी एक बड़ी चुनौती थी ताकि देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया जा सके।

6. (A) P-3, Q-1, R-4, S-2
भारतीय राजनीति में विभिन्न नेताओं ने क्षेत्रीय आंदोलनों का नेतृत्व किया है। शेख अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख नेता थे। ई.वी. रामास्वामी नायकर ने तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। मास्टर तारा सिंह शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से जुड़े थे और सिखों के अधिकारों के लिए लड़े। वहीं लालडेंगा ने मिजो नेशनल फ्रंट बनाकर मिजोरम में स्वायत्तता के लिए संघर्ष का नेतृत्व किया।

7. (D) कल्लाकुडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर डालमियापुरम करना।
डी.एम.के. ने 1953-54 के दौरान अपनी पहचान को मज़बूत करने के लिए तीन-सूत्री आंदोलन चलाया था। इसकी मुख्य मांगों में डालमियापुरम रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पुनः कल्लाकुडी करना शामिल था, क्योंकि डालमिया नाम उत्तर भारतीय प्रभुत्व का प्रतीक माना गया। इसके अलावा हिंदी का विरोध और स्कूली पाठ्यक्रम में तमिल संस्कृति को स्थान दिलाना भी इस व्यापक आंदोलन के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल थे।

8. (A) एक पृथक कश्मीरी राष्ट्र बनाने की माँग
1989 तक जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक असंतोष ने उग्र रूप ले लिया था और राज्य उग्रवादी आंदोलनों की गिरफ्त में आ गया। इस विद्रोह का मुख्य जोर एक पृथक कश्मीरी राष्ट्र बनाने की माँग पर था। इन सशस्त्र समूहों को पाकिस्तान से नैतिक और फौजी समर्थन प्राप्त था, जिससे घाटी में अशांति फैल गई और कश्मीरी पंडितों को विस्थापन का दुखद सामना करना पड़ा।

9. (D) 1, 2, 3 और 4 सभी
स्वतंत्रता पूर्व जम्मू-कश्मीर एक प्रमुख राजसी रियासत थी, जिसके शासक महाराजा हरि सिंह थे। 1947 में विभाजन के समय महाराजा ने अपनी रियासत के लिए किसी भी देश में शामिल न होकर स्वतंत्र रहने का फैसला किया। दूसरी ओर, पाकिस्तान का मानना था कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण कश्मीर का पाकिस्तान में विलय स्वाभाविक है, जिससे यह मुद्दा विवादित बन गया।

10. (A) डी.एम.के.
1965 में जब केंद्र सरकार ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रयास किया, तो दक्षिण भारत में इसका कड़ा विरोध हुआ। तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने इस आंदोलन का सफल नेतृत्व किया, जिससे उसकी लोकप्रियता में भारी उछाल आया। इसी सफलता के परिणामस्वरुप 1967 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को शिकस्त देकर डी.एम.के. ने राज्य में अपनी पहली सरकार बनाई।

11. (D) केंद्र-राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करना
1973 में अकालियों ने आनंदपुर साहिब में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया, जिसका मुख्य लक्ष्य केंद्र और राज्यों के संबंधों को पुनर्परिभाषित करना था। इस प्रस्ताव में पंजाब के

के कुछ वर्गों में 'द्रविड़नाडु' नामक एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य की मांग की अलगाववादी भावनाएँ थीं। हालाँकि, समय के साथ, विशेष रूप से 1962 के चीनी आक्रमण और संवैधानिक संशोधनों के बाद, आंदोलन ने अपनी अलगाववादी मांगों को छोड़ दिया। इसके बजाय, इसने भारतीय संघ के भीतर अधिक राज्य स्वायत्तता, भाषाई अधिकारों और सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित किया। सी.एन. अन्नादुरई के नेतृत्व में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) जैसी पार्टियों ने चुनावी राजनीति के माध्यम से सत्ता हासिल की और सफलतापूर्वक इन आकांक्षाओं को भारतीय राजनीतिक ढांचे में एकीकृत किया, जिससे यह प्रदर्शित हुआ कि कैसे एक संभावित अलगाववादी आंदोलन एक प्रभावशाली क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति में बदल सकता है।
उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

171. द्रविड़ आंदोलन से जुड़े आत्म-सम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की?
(A) सी.एन. अन्नादुरई
(B) एम. करुणानिधि
(C) ई.वी. रामासामी 'पेरियार'
(D) के. कामराज

172. द्रविड़ आंदोलन का एक केंद्रीय राजनीतिक स्तंभ क्या था?
(A) आर्थिक उदारीकरण का समर्थन
(B) हिंदी भाषा को थोपने का विरोध
(C) एक मजबूत केंद्र सरकार की वकालत
(D) जाति व्यवस्था का समर्थन

173. प्रारंभ में, आंदोलन के कुछ वर्गों की अलगाववादी मांग क्या थी?
(A) एक स्वतंत्र तमिल राष्ट्र
(B) दक्षिण भारत का पाकिस्तान में विलय
(C) एक संयुक्त दक्षिण एशियाई संघ
(D) 'द्रविड़नाडु' नामक एक स्वतंत्र राज्य

174. किस घटना के बाद आंदोलन ने अपनी अलगाववादी मांगों को छोड़ दिया?
(A) 1962 का चीनी आक्रमण
(B) भारत की स्वतंत्रता (1947)
(C) राज्यों का भाषाई पुनार्गठन (1956)
(D) आपातकाल की घोषणा (1975)

175. अनुच्छेद के अनुसार, द्रविड़ आंदोलन का सफल एकीकरण क्या प्रदर्शित करता है?
(A) यह सिद्ध करना कि सभी क्षेत्रीय और अलगाववादी आंदोलन अंततः विफल हो जाते हैं।
(B) यह दर्शाना कि भाषाई और सांस्कृतिक मुद्दे भारतीय राजनीति में पूरी तरह महत्वहीन हैं।
(C) कि कैसे एक संभावित अलगाववादी आंदोलन एक प्रभावशाली क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति में बदल सकता है।
(D) यह स्पष्ट करना कि सामाजिक न्याय की मांग चुनावी राजनीति का आधार नहीं हो सकती है।

45. (C) असम से अलग एक जनजातीय राज्य बनाया जाए
'ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस' का मुख्य उद्देश्य असम के पर्वतीय क्षेत्रों की जनजातीय पहचान को सुरक्षित करना था। इन नेताओं की प्रमुख माँग थी कि जनजातीय बहुल इलाकों को असम से अलग कर एक नया राज्य बनाया जाए। उन्हें डर था कि असम सरकार उन पर असमी भाषा और संस्कृति थोप रही है। इसी आंदोलन के सफल दबाव के परिणामस्वरूप आगे चलकर मेघालय जैसे नए राज्य का गठन संभव हुआ।

46. (D) उन्हें असम के भीतर ही स्वायत्त परिषद् का दर्जा दिया गया।
असम में बोडो, करबी और दिमसा जैसे विभिन्न समुदायों ने अपनी विशिष्ट पहचान और विकास के लिए अलग राज्यों की माँग की थी। इन माँगों को संतुष्ट करने और राज्य की अखंडता बनाए रखने के लिए सरकार ने उन्हें असम के भीतर ही 'स्वायत्त परिषद्' का दर्जा दिया। इस व्यवस्था के माध्यम से उन्हें अपने स्थानीय मामलों, संस्कृति और आर्थिक विकास के प्रबंधन के लिए विशेष अधिकार प्रदान किए गए।

47. (A) 4, 2, 3, 1
भारतीय इतिहास की प्रमुख क्षेत्रीय घटनाओं का कालक्रम देश के विकास को दर्शाता है। सबसे पहले 1947 में जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय हुआ। इसके बाद 1961 में सैन्य कार्रवाई के जरिए गोवा को मुक्त कराया गया। 1967 में तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति की सफलता के रूप में डी.एम.के. की सरकार बनी। अंत में, 1979 में असम में अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक विशाल जन आंदोलन शुरू हुआ।

48. (B) 1989-90 में
1989-90 के दौरान जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद के चरम पर पहुँचने के कारण कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर विस्थापन शुरू हुआ। उग्रवादी संगठनों द्वारा लक्षित हिंसा और धमकियों के चलते हजारों हिंदू परिवारों को अपनी पुश्तैनी जमीन और घर छोड़कर जम्मू और देश के अन्य हिस्सों में शरण लेनी पड़ी। यह घटना कश्मीरी समाज के साझा सांस्कृतिक इतिहास के लिए एक अत्यंत दुखद मोड़ थी।

49. (B) आसू और असम गण संग्राम परिषद्
1985 में असम समझौता होने के बाद, आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संगठनों ने चुनावी राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय लिया। इसके लिए 'ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन' (आसू) और 'असम गण संग्राम परिषद्' ने मिलकर 'असम गण परिषद्' (एजीपी) नामक राजनीतिक दल का गठन किया। इस नए दल ने 1985 के विधानसभा चुनावों में भारी जीत हासिल की और राज्य में क्षेत्रीय गौरव की सरकार बनाई।

50. (A) सिक्किम
पूर्वोत्तर भारत के सात राज्यों—असम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय—को सामूहिक रूप से "सात बहनें" कहा जाता है। सिक्किम भौगोलिक रूप से इस समूह के पास स्थित है और इसे अक्सर इनका "भाई" माना जाता है, लेकिन यह मूल सात बहनों की सूची में शामिल नहीं है। सिक्किम का भारत में विलय भी इन अन्य राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया से काफी बाद में हुआ था।

51. (C) केवल 1, 2, 4, 5
भारत ने विविधता को राष्ट्र की कमजोरी नहीं बल्कि ताकत माना है और इसके समाधान के लिए लोकतांत्रिक मार्ग चुना है। यहाँ क्षेत्रीय आकांक्षाओं को राजनीति में उचित स्थान दिया जाता है और उन्हें राष्ट्र विरोधी नहीं समझा जाता। भारतीय राष्ट्रवाद ने एकता और विविधता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है, जो यूरोप के उस नजरिये से अलग है जहाँ सांस्कृतिक भिन्नता को खतरा माना जाता था।

52. (D) हिंदी
1950 के दशक में जब केंद्र सरकार ने हिंदी को भारत की एकमात्र राजभाषा बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए, तो दक्षिण भारत के राज्यों में इसके खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया हुई। विशेष रूप से तमिलनाडु में द्रविड़ नेताओं ने इसे उत्तर भारत का सांस्कृतिक साम्राज्यवाद करार दिया। इस विरोध आंदोलन ने न केवल हिंदी के प्रसार को रोका, बल्कि क्षेत्रीय भाषा और पहचान के सम्मान को मजबूती से स्थापित कर दिया।

53. (C) प्रधानमंत्री
1974 के इंदिरा-शेख समझौते से पहले जम्मू और कश्मीर में राज्य सरकार के मुखिया को 'प्रधानमंत्री' के पदनाम से संबोधित किया जाता था। इसी प्रकार, राज्य के संवैधानिक प्रमुख को 'सदर-ए-रियासत' कहा जाता था। समझौते के बाद इन पदनामों को बदलकर अन्य भारतीय राज्यों की तरह 'मुख्यमंत्री' और 'राज्यपाल' कर दिया गया। यह राज्य के शेष भारत के साथ प्रशासनिक और राजनीतिक एकीकरण की दिशा में बदलाव था।

54. (A) P-2, Q-1, R-4, S-3
भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान को लेकर अलग-अलग अवधारणाएँ प्रचलित रही हैं। तमिलनाडु में 'द्रविड़ अस्मिता' की भावना प्रबल रही है, जबकि पंजाब में भाषायी आधार पर 'पंजाबी सूबा' की माँग उठी। जम्मू-कश्मीर में वहां की साझा संस्कृति को 'कश्मीरियत' के नाम से जाना जाता है। वहीं, असम में 'स्वर्णिम असम' की संकल्पना ने बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन को प्रेरित किया।

55. (D) पंजाब
1985 के राजीव-लोंगोवाल समझौते के तहत यह महत्वपूर्ण सहमति बनी थी कि चंडीगढ़ को पूर्ण रूप से पंजाब राज्य को सौंप दिया जाएगा। उस समय चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश था। हालांकि, राजनीतिक जटिलताओं और हरियाणा के विरोध के कारण यह वादा कभी पूरी तरह लागू नहीं हो सका। आज भी चंडीगढ़ दोनों राज्यों की साझा राजधानी बना हुआ है।

लिए अधिक स्वायत्तता और अधिकारों की माँग की गई थी। हालाँकि, इसमें सिख समुदाय की विशिष्ट पहचान पर भी जोर दिया गया था, जिससे बाद के वर्षों में इसे राजनीतिक विवादों का सामना करना पड़ा।

12. (B) केवल 1, 2, 3, 5
जून 1984 में अमृतसर के स्वर्णमंदिर में छिपे उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए सरकार ने 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' चलाया। इस सैन्य कार्रवाई में उग्रवादी तो मारे गए, लेकिन ऐतिहासिक मंदिर परिसर को भारी क्षति पहुँची। इस घटना ने विश्वभर के सिखों की धार्मिक भावनाओं को गहरी चोट पहुँचाई, जिसके कारण सिख समुदाय में सरकार के प्रति काफी रोष और असंतोष पैदा हुआ।

13. (C) 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' का बदला लेना
31 अक्तूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी की उनके ही अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई। इस जघन्य कृत्य का तात्कालिक कारण स्वर्णमंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' का बदला लेना था। इस घटना के बाद देश के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर दिल्ली में सिखों के खिलाफ हिंसक दंगे भड़क उठे, जिससे भारी जान-माल का नुकसान हुआ।

14. (D) जम्मू, कश्मीर और लद्दाख
जम्मू और कश्मीर भौगोलिक और सामाजिक रूप से तीन मुख्य क्षेत्रों का सम्मिश्रण है: जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। कश्मीर घाटी में मुख्य रूप से कश्मीरी भाषी मुसलमान रहते हैं, जबकि जम्मू क्षेत्र हिंदू, मुस्लिम और सिखों की मिली-जुली आबादी वाला मैदानी और पहाड़ी इलाका है। लद्दाख एक ऊँचा पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ बौद्ध और मुसलमानों की आबादी लगभग बराबर संख्या में निवास करती है।

15. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
1984 की हिंसा के बाद पंजाब में शांति स्थापित करने के लिए 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गाँधी और अकाली नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। इस समझौते के तहत चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने और सीमा विवाद सुलझाने जैसे कई कदम उठाने पर सहमति बनी। इसका मुख्य उद्देश्य उग्रवाद को समाप्त कर राज्य में पुनः सद्भाव बहाल करना था।

16. (B) भाषायी आधार पर
1966 में पंजाब राज्य का पुनर्गठन मुख्य रूप से भाषायी आधार पर किया गया था। इस प्रक्रिया के तहत पंजाबी भाषी क्षेत्रों को मिलाकर 'पंजाब' राज्य बनाया गया, जबकि हिंदी भाषी क्षेत्रों को अलग करके 'हरियाणा' का गठन हुआ। पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में शामिल कर दिया गया। यह निर्णय सिखों द्वारा चलाए गए 'पंजाबी सूबा' आंदोलन की मांगों को पूरा करने के लिए था।

17. (B) आर्थिक उदारीकरण की माँग
1970 के दशक में पूर्वोत्तर भारत में उठी राजनीतिक माँगों के केंद्र में मुख्य रूप से तीन मुद्दे थे: स्वायत्तता की माँग, अलगाववादी आंदोलन और अवैध प्रवासियों यानी 'बाहरी' लोगों का विरोध। उस समय आर्थिक उदारीकरण कोई प्रमुख मुद्दा नहीं था। क्षेत्र की राजनीति भाषायी, सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा और केंद्र सरकार द्वारा विकास में की जा रही कथित उपेक्षा के इर्द-गिर्द सिमटी थी।

18. (A) 3, 1, 4, 2
पंजाब की राजनीतिक घटनाओं का क्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले 1973 में स्वायत्तता के लिए आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित हुआ। इसके बाद जून 1984 में स्वर्णमंदिर में सैन्य कार्रवाई 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' हुई। उसी वर्ष अक्तूबर में इंदिरा गाँधी की हत्या कर दी गई। अंततः जुलाई 1985 में शांति स्थापना के लिए राजीव-लोंगोवाल समझौता हुआ, जिससे सामान्य स्थिति की बहाली का मार्ग प्रशस्त हुआ।

19. (C) मणिपुर और त्रिपुरा
आज़ादी के समय पूर्वोत्तर भारत का अधिकांश हिस्सा असम राज्य के अंतर्गत आता था। केवल मणिपुर और त्रिपुरा ऐसी रियासतें थीं जिन्हें बाद में केंद्र शासित प्रदेश और फिर पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। शेष वर्तमान राज्य जैसे मेघालय, मिजोरम और नगालैंड उस समय असम का ही हिस्सा थे, जो कालांतर में भाषायी और जनजातीय स्वायत्तता के आंदोलनों के कारण अलग राज्यों के रूप में उभरे।

20. (D) मिजो National फ्रंट
1959 में मिजो पर्वतीय क्षेत्र में आए भीषण अकाल के समय असम सरकार की विफलता ने स्थानीय जनता में भारी असंतोष पैदा किया। इसी पृष्ठभूमि में लालडेंगा के नेतृत्व में 'मिजो नेशनल फ्रंट' का गठन हुआ। इस संगठन ने प्रारंभ में राहत कार्यों पर ध्यान दिया, लेकिन बाद में इसने भारत संघ से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र की माँग के लिए सशस्त्र विद्रोह का रास्ता अपनाया।

21. (B) केवल 2
'आसू' (AASU) यानी ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन एक स्वतंत्र छात्र संगठन था, जिसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक दल से कोई सीधा संबंध नहीं था। इस संगठन ने 1979 में असम में अवैध रूप से बसे प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें बाहर निकालने के लिए एक आंदोलन शुरू किया। इनका मानना था कि बाहरी लोगों के कारण स्थानीय जनता असुरक्षित हो रही है।

22. (B) मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा और विशेष अधिकार मिले।
1986 में प्रधानमंत्री राजीव गाँधी और विद्रोही नेता लालडेंगा के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ। इस समझौते के परिणामस्वरूप मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और उसे कुछ विशेष संवैधानिक अधिकार भी प्रदान किए गए। समझौते के बाद विद्रोही समूहों ने हथियार डाल दिए और

लालडेंगा राज्य के मुख्यमंत्री बने, जिससे मिजोरम में दशकों से चले आ रहे गृहयुद्ध का अंत हुआ।

23. (D) एक विशिष्ट कश्मीरी क्षेत्रीय पहचान की भावना
'कश्मीरियत' का तात्पर्य एक विशिष्ट कश्मीरी क्षेत्रीय और सांस्कृतिक पहचान से है जो वहां के लोगों को एकजुट करती है। यह केवल धार्मिक पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कश्मीरी संस्कृति, भाषा और इतिहास का समावेश है। कश्मीर के लोग अपनी इस स्वायत्त पहचान को लेकर अत्यंत संवेदनशील रहे हैं और उनकी अधिकांश राजनीतिक माँगें इसी 'कश्मीरियत' को सम्मान दिलाने के इर्द-गिर्द केंद्रित रही हैं।

24. (B) P-1, Q-2, R-3, S-4
भारत के विभिन्न राज्यों में उठी क्षेत्रीय माँगों के अलग-अलग आधार रहे हैं। पंजाब में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के माध्यम से स्वायत्तता माँगी गई। तमिलनाडु में हिंदी को राजभाषा बनाने के विरोध में तीव्र आंदोलन हुए। मिजोरम में लालडेंगा के नेतृत्व में अलगाववादी संघर्ष चला, जबकि असम में आंदोलन का मुख्य मुद्दा 'बाहरी' लोगों और अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें राज्य से बाहर निकालना था।

25. (C) महाराजा ने सैन्य मदद हेतु विलय प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए।
1947 में जब पाकिस्तान समर्थित कबायली घुसपैठियों ने कश्मीर पर आक्रमण किया, तो महाराजा हरि सिंह की स्थिति संकटपूर्ण हो गई। अपनी रियासत की रक्षा के लिए उन्होंने भारत सरकार से सैन्य सहायता मांगी। भारत ने सहायता के लिए विलय की शर्त रखी, जिसके परिणामस्वरूप महाराजा ने 'विलय प्रपत्र' पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद ही भारतीय सेना ने कश्मीर को मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू की।

26. (A) ऑपरेशन विजय
1961 में भारत सरकार ने गोवा को पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के लिए 'ऑपरेशन विजय' नामक एक सीमित सैन्य अभियान चलाया। पुर्तगाल लंबे समय से बातचीत के माध्यम से गोवा छोड़ने को तैयार नहीं था, जिससे अंततः सैन्य हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी। केवल दो दिनों की कार्रवाई के बाद पुर्तगाली सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और गोवा भारतीय संघ का हिस्सा बन गया।

27. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
द्रविड़ आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि इसने अपनी माँगों को पूरा करने के लिए कभी भी सशस्त्र संघर्ष या हिंसा का सहारा नहीं लिया। इस आंदोलन ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं के भीतर रहकर सार्वजनिक बहसों, रैलियों और चुनावी राजनीति को अपना माध्यम बनाया। इसी कारण यह आंदोलन तमिलनाडु की राजनीति में गहराई तक अपनी जगह बनाने और सत्ता हासिल करने में सफल रहा।

28. (B) बाहरी लोगों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने का प्रावधान।
1985 में प्रधानमंत्री राजीव गाँधी और 'आसू' के नेताओं के बीच हुए असम समझौते का मुख्य उद्देश्य राज्य में चल रहे लंबे आंदोलन को समाप्त करना था। इस समझौते के तहत यह तय किया गया कि 1971 के बाद असम में आए अवैध प्रवासियों की पहचान की जाएगी और उन्हें वापस भेजा जाएगा। इससे असमी लोगों की सांस्कृतिक अस्मिता और राजनीतिक अधिकारों के संरक्षण का आश्वासन मिला।

29. (C) तेलुगु देशम पार्टी
तमिलनाडु की राजनीति में सक्रिय प्रमुख दल जैसे डी.एम.के., ए.आई.ए.डी.एम.के. और पी.एम.के. सीधे तौर पर द्रविड़ आंदोलन की विरासत और विचारधारा से जुड़े हुए हैं। इसके विपरीत, तेलुगु देशम पार्टी (टी.डी.पी.) आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्रीय दल है, जिसकी स्थापना एन.टी. रामा राव ने की थी। यद्यपि यह भी क्षेत्रीय अस्मिता पर आधारित है, परंतु इसका उद्भव द्रविड़ आंदोलन से नहीं हुआ है।

30. (B) केवल 1, 2, 3, 5
आज़ादी के समय सिक्किम भारत का एक संरक्षित राज्य था जहाँ रक्षा और विदेशी मामलों का उत्तरदायित्व भारत का था, जबकि आंतरिक शासन राजा चोग्याल चलाते थे। 1975 में सिक्किम की जनता ने राजशाही के खिलाफ विद्रोह किया और जनमत-संग्रह के माध्यम से भारत में पूर्ण विलय का समर्थन किया। इसके परिणामस्वरूप सिक्किम भारत का 22वाँ राज्य बना, जिससे वहां के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार मिले।

31. (A) क्या गोवा को महाराष्ट्र में शामिल होना चाहिए या अलग रहना चाहिए?
1967 में गोवा में एक ऐतिहासिक जनमत सर्वेक्षण कराया गया था ताकि वहां के लोगों की भविष्य की इच्छा जानी जा सके। इसमें मुख्य प्रश्न यह था कि क्या गोवा को पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में मिला दिया जाना चाहिए या इसे एक अलग प्रशासनिक इकाई के रूप में रखना चाहिए। गोवा की जनता ने अपनी विशिष्ट कोंकणी संस्कृति को बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र में विलय के विरुद्ध मतदान किया।

32. (B) असम में असमी भाषा को लादने के खिलाफ
'ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन' का गठन मुख्य रूप से असम सरकार द्वारा गैर-असमी जनजातीय क्षेत्रों पर असमी भाषा थोपने के विरोध में हुआ था। जनजातीय नेताओं का मानना था कि इससे उनकी अपनी संस्कृति और भाषा पर संकट आ जाएगा। इसी विरोध और अलगाव की भावना ने आगे चलकर असम से अलग कई नए राज्यों, जैसे मेघालय, के निर्माण की पृष्ठभूमि तैयार करने में मदद की थी।

33. (A) 2, 4, 3, 1
पूर्वोत्तर भारत और अन्य क्षेत्रों के पुनर्गठन की घटनाओं का एक निश्चित क्रम है। सबसे पहले 1963 में नगालैंड को राज्य का दर्जा मिला। इसके बाद 1975 में सिक्किम का भारत में पूर्ण विलय हुआ। 1985 में असम की समस्या को सुलझाने के लिए असम समझौता किया गया और अंततः 1987 में शांति समझौते के बाद मिजोरम को एक पूर्ण राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी।

34. (A) परिणामों में लोकप्रिय चयन की झलक नहीं थी और चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई थी।
1987 के जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के बारे में यह आम धारणा रही कि उनमें व्यापक स्तर पर धांधली हुई और परिणामों ने जनता की वास्तविक पसंद को नहीं दर्शाया। इस घटना ने कश्मीर के युवाओं में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति विश्वास को काफी कम कर दिया। माना जाता है कि इसी चुनावी गड़बड़ी ने राज्य में उग्रवाद और सशस्त्र विद्रोह के पनपने के लिए मजबूत आधार तैयार किया।

35. (C) अंगमी जापू फिजो
नगालैंड में अलगाववादी आंदोलन का नेतृत्व अंगमी जापू फिजो ने किया था। उनके नेतृत्व में 'नगा नेशनल कांउसिल' ने 1951 में नगालैंड को भारत से स्वतंत्र घोषित कर दिया और सशस्त्र विद्रोह की शुरुआत की। फिजो ने भारत सरकार के साथ किसी भी समझौते से इनकार किया और नगा लोगों की विशिष्ट पहचान के लिए संघर्ष किया, जिसके कारण नगा समस्या दशकों तक एक चुनौती बनी रही।

36. (A) P-3, Q-1, R-4, S-2
भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने के लिए समय-समय पर समझौते किए हैं। जुलाई 1985 में पंजाब समझौता हुआ, जबकि उसी वर्ष अगस्त में असम समझौता संपन्न हुआ। मिजोरम में शांति बहाल करने के लिए 1986 में समझौता किया गया था। इसके पूर्व, 1975 में सिक्किम का भारत संघ में विलय एक महत्वपूर्ण घटना थी। ये सभी कदम एकता और स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश थे।

37. (C) द्रविड़ आंदोलन
"उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन-दिन घटता जाए" का प्रसिद्ध नारा द्रविड़ आंदोलन के दौरान गूँजा था। यह नारा दक्षिण भारतीय लोगों की उस भावना को व्यक्त करता था कि केंद्र सरकार की नीतियां उत्तर भारत के विकास को प्राथमिकता दे रही हैं और दक्षिण की अनदेखी की जा रही है। इस नारे ने भाषायी अस्मिता के साथ-साथ आर्थिक और राजनीतिक न्याय की माँग को मजबूती से उभारा।

38. (B) स्वायत्तता, अलगाववाद और बाहरी लोगों का विरोध
1980 के दशक के दौरान पूर्वोत्तर भारत की राजनीति मुख्य रूप से तीन ज्वलंत मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमती रही: अधिक संवैधानिक स्वायत्तता की माँग, कुछ क्षेत्रों में चल रहे अलगाववादी आंदोलन और अवैध रूप से बसे 'बाहरी' लोगों का तीव्र विरोध। इन मुद्दों ने क्षेत्र के सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित किया और सरकार को विभिन्न समूहों के साथ संवाद और शांति समझौते करने के लिए प्रेरित किया था।

39. (D) कांग्रेस को दलितों के बीच अकालियों से कहीं ज़्यादा समर्थन प्राप्त था।
पंजाब की राजनीति में सामाजिक विभाजन स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। शिरोमणि अकाली दल मुख्य रूप से उच्च जाति के जत्थेदारों और किसानों का प्रतिनिधित्व करता था। इसके विपरीत, कांग्रेस पार्टी को दलित सिखों और हिंदुओं के बीच कहीं अधिक समर्थन प्राप्त था। इसी सामाजिक समीकरण के कारण अकाली दल को राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अक्सर संघर्ष करना पड़ा और उन्हें कठिन चुनौतियां मिलीं।

40. (A) राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में पुनर्गठित किया गया।
2019 में केंद्र सरकार द्वारा पारित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम ने राज्य की संवैधानिक स्थिति को पूरी तरह बदल दिया। इस कानून के तहत अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया और राज्य को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों—जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख—में विभाजित कर दिया गया। इस प्रशासनिक बदलाव का उद्देश्य क्षेत्र में शासन व्यवस्था को बेहतर बनाना था।

41. (B) केवल 1, 2 और 3
1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसके बाद शेख अब्दुल्ला राज्य के मुख्यमंत्री बने। 1982 में उनके निधन के उपरांत उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला ने सत्ता संभाली। हालांकि, राज्य की राजनीति में उतार-चढ़ाव जारी रहे और 1984 में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के कारण फारूक अब्दुल्ला को पद से हटा दिया गया था।

42. (A) इस रक्तपात पर अफसोस जताया और देश से माफी माँगी।
2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने संसद में 1984 के सिख-विरोधी दंगों पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने उस भीषण रक्तपात को राष्ट्र के लिए एक कलंक बताते हुए पूरे देश और सिख समुदाय से औपचारिक रूप से माफी माँगी। इस कदम को सिखों के जख्मों पर मरहम लगाने और राष्ट्रीय सुलह की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रयास माना गया था।

43. (D) ई. वी. रामास्वामी नायकर 'पेरियार'
ई.वी. रामास्वामी नायकर 'पेरियार' ने 1925 में तमिलनाडु में 'आत्मसम्मान आंदोलन' की शुरुआत की थी। वे जाति प्रथा के घोर विरोधी थे और उन्होंने निचली जातियों के गौरव और अधिकारों के लिए संघर्ष किया। पेरियार ने उत्तर भारतीय भाषायी और सांस्कृतिक वर्चस्व को चुनौती दी, जिससे दक्षिण भारत में एक नई राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। यही आंदोलन द्रविड़ राजनीति और अस्मिता का मुख्य आधार बना।

44. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
1959 में मिजो पर्वतीय क्षेत्र में आए विनाशकारी अकाल के दौरान असम सरकार की लापरवाही ने विद्रोह की आग सुलगा दी। स्थानीय लोगों को लगा कि केंद्र और राज्य सरकार उनकी समस्याओं के प्रति उदासीन हैं। इसी असंतोष का लाभ उठाकर लालडेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट को व्यापक जनसमर्थन मिला, जिसने बाद में एक स्वतंत्र मिजो राष्ट्र की माँग को लेकर लंबा सशस्त्र संघर्ष चलाया था।

67. (C) कारगिल युद्ध
1980 का दशक भारतीय राजनीति के लिए काफी उथल-पुथल और त्रासदियों से भरा रहा, जिसमें 'ऑपरेशन ब्लू स्टार', प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी की हत्या और उसके बाद हुए भयानक सिख-विरोधी दंगे शामिल थे। इसके विपरीत, कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, जो इस दशक की घटनाओं का हिस्सा नहीं है। इन 1980 की त्रासदियों ने देश की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक ताने-बाने को गंभीर रूप से प्रभावित किया था।

68. (D) क्योंकि कुछ विशेष राज्यों के हितों हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं।
भारतीय संघीय प्रणाली को लचीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह देश की विविधता को समायोजित करने के लिए विभिन्न राज्यों के लिए विशिष्ट प्रावधानों की अनुमति देती है। पूर्वोत्तर के राज्यों और पहले जम्मू-कश्मीर के लिए किए गए विशेष संवैधानिक प्रावधान इसी लचीलेपन का उदाहरण हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि किसी विशेष क्षेत्र की सांस्कृतिक विशिष्टताओं को सुरक्षित रखा जा सके, जबकि वह भारतीय संघ का हिस्सा रहे।

69. (A) 3, 1, 4, 2
भारत के भाषायी और क्षेत्रीय पुनर्गठन के अंतर्गत 1966 में पंजाब और हरियाणा का निर्माण हुआ। इसके बाद 1975 में सिक्किम भारत का 22वाँ राज्य बना। 1987 का वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण था जब पहले फरवरी में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और फिर मई में गोवा भारत संघ का एक पूर्ण राज्य बना। यह प्रक्रिया दर्शाती है कि कैसे क्षेत्रीय आकांक्षाओं को समय के साथ समायोजित किया गया।

70. (B) लोकतंत्र में अपनी विशिष्ट संस्कृति और समस्याओं के आधार पर राजनीतिक माँगें उठाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।
लोकतंत्र में क्षेत्रीय आकांक्षाओं का होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट संस्कृति और स्थानीय समस्याएँ होती हैं। जब लोग अपनी पहचान या विकास के लिए राजनीतिक माँगें उठाते हैं, तो यह लोकतंत्र को कमजोर नहीं बल्कि उसे और अधिक समावेशी बनाता है। भारत का अनुभव यह सिखाता है कि इन माँगों को दबाने के बजाय उनसे लोकतांत्रिक बातचीत के जरिए निपटना श्रेयस्कर है।

71. (D) शेख अब्दुल्ला - द्रविड़ कड़गम
दिए गए जोड़ों में शेख अब्दुल्ला और द्रविड़ कड़गम का मेल गलत है। शेख अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर की राजनीति के प्रमुख स्तंभ थे और उनका संबंध नेशनल कॉन्फ्रेंस से था। द्रविड़ कड़गम तमिलनाडु का एक संगठन था जिसकी स्थापना ई.वी. रामास्वामी नायकर ने की थी। अन्य विकल्प सही हैं, जैसे मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबा की माँग की और लालडेंगा मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक नेता थे जिन्होंने संघर्ष का नेतृत्व किया।

72. (C) केवल 1, 2, 3, 4
1979 से 1985 तक चला असम आंदोलन मुख्य रूप से बाहरी लोगों के अवैध प्रवेश के खिलाफ था। असमी लोगों को डर था कि बांग्लादेश से आ रहे प्रवासियों के कारण वे अपने ही घर में अल्पसंख्यक हो जाएँगे और उनकी संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी। इसके अलावा, आंदोलन का एक बड़ा कारण यह भी था कि स्थानीय जनता को असम के प्राकृतिक संसाधनों का उचित लाभ नहीं मिल रहा था, जिससे असंतोष बढ़ा।

73. (C) 1920 के दशक में
शिरोमणि अकाली दल का गठन 1920 के दशक में सिखों की एक राजनीतिक शाखा के रूप में हुआ था। इसकी उत्पत्ति गुरुद्वारों के प्रबंधन को भ्रष्ट महंतों से मुक्त कराने के लिए चलाए गए आंदोलन के दौरान हुई थी। प्रारंभ से ही इस दल ने सिखों की धार्मिक और राजनीतिक पहचान की रक्षा को अपना मुख्य एजेंडा बनाया। पंजाब की राजनीति में यह दल हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति के रूप में सक्रिय रहा है।

74. (A) इससे यह भावना पुष्ट हुई कि केंद्र राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है।
1986 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और केंद्र में सत्तारुढ़ कांग्रेस के बीच हुए चुनावी गठबंधन को कश्मीर की जनता ने संदेह की दृष्टि से देखा। लोगों को लगा कि यह समझौता केवल सत्ता हथियाने के लिए किया गया है और केंद्र सरकार राज्य के आंतरिक लोकतांत्रिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप कर रही है। इस राजनीतिक गठजोड़ ने कश्मीर में स्थानीय असंतोष को और अधिक हवा दी, जिसने आगे चलकर उग्रवाद के लिए आधार तैयार किया।

75. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
भारत की आज़ादी के बाद भी गोवा पुर्तगाल के कब्जे में बना रहा। भारत सरकार ने पुर्तगाली प्रशासन से शांतिपूर्ण ढंग से हटने के लिए कई बार आग्रह किया, लेकिन उन्होंने इसे सिरे से ठुकरा दिया। अंततः 1961 में कोई अन्य विकल्प न पाकर भारत सरकार को सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी। भारतीय सेना के हस्तक्षेप के बाद ही गोवा को पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन से पूरी तरह मुक्ति मिल सकी और उसका भारत में विलय हुआ।

76. (B) ब्राह्मणों और उत्तरी भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व
द्रविड़ कड़गम संगठन का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त ब्राह्मणवादी वर्चस्व को समाप्त करना और उत्तर भारतीय राजनीतिक व सांस्कृतिक प्रभुत्व को चुनौती देना था। इस संगठन ने माना कि उत्तर भारत की नीतियां और हिंदी भाषा दक्षिण की संस्कृति पर थोपी जा रही हैं। उन्होंने क्षेत्रीय गौरव की वकालत की, जिससे तमिलनाडु में एक मजबूत गैर-ब्राह्मण आंदोलन खड़ा हुआ और वहां की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया।

77. (C) पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और काँग्रेस
2002 में जम्मू और कश्मीर में हुए विधानसभा चुनावों के परिणामस्वरुप किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व वाली 'पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी' (पीडीपी) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने

56. (A) भारत-पाकिस्तान विवाद और कश्मीर मुद्दा
1992 में प्रदर्शित फिल्म 'रोजा' की मुख्य पृष्ठभूमि जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद और भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव पर आधारित थी। फिल्म में कश्मीर घाटी में उग्रवादियों द्वारा एक सरकारी अधिकारी के अपहरण और उसके बाद की मानवीय त्रासदियों को दिखाया गया है। यह फिल्म उस दौर की क्षेत्रीय अशांति और राष्ट्रीय अखंडता के सवालों को लोकप्रिय संस्कृति के माध्यम से जनता के सामने लाने का उदाहरण है।

57. (C) शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फेरेंस पाकिस्तान में शामिल होने के पक्ष में थी।
जम्मू और कश्मीर की राजनीति में शेख अब्दुल्ला की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है, लेकिन यह कहना गलत है कि वे पाकिस्तान में शामिल होने के पक्ष में थे। वास्तव में, शेख अब्दुल्ला ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर विश्वास करते हुए पाकिस्तान के द्वि-राष्ट्र सिद्धांत को नकार दिया था। वे महाराजा के शासन से मुक्ति और स्वायत्तता के पक्षधर थे और उन्होंने भारत के साथ रहने को प्राथमिकता दी थी।

58. (A) क्योंकि द्रविड़ दल अब भारतीय संघ के भीतर ही स्वायत्तता चाहते हैं।
तमिलनाडु की राजनीति यह दर्शाती है कि क्षेत्रीय गौरव की भावना और राष्ट्रवाद एक साथ चल सकते हैं। प्रारंभ में अलगाव की बात करने वाले द्रविड़ दलों ने समय के साथ भारतीय संवैधानिक ढांचे को स्वीकार किया। अब वे भारतीय संघ के भीतर रहकर ही राज्य के लिए अधिक स्वायत्तता और अधिकारों की माँग करते हैं। केंद्र सरकार में उनकी सक्रिय भागीदारी ने यह सिद्ध किया है कि क्षेत्रीय दल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

59. (D) मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश
1960 में गठित 'ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस' ने असम के जनजातीय इलाकों के लिए अलग शासन की माँग को पुरजोर तरीके से उठाया। इस आंदोलन के परिणामस्वरूप असम का विभाजन हुआ और मेघालय जैसे नए राज्य अस्तित्व में आए। बाद के वर्षों में इसी क्षेत्रीय चेतना के विस्तार ने मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में मदद की, जिससे पूर्वोत्तर का वर्तमान राजनीतिक नक्शा तैयार हुआ।

60. (D) 1, 2, 3 और 4 सभी
जम्मू-कश्मीर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया था, जो इसे अन्य राज्यों से अलग स्वायत्तता देता था। शेख अब्दुल्ला 1948 में राज्य के पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन केंद्र से मतभेदों के कारण उन्हें 1953 में बर्खास्त कर दिया गया। लंबे राजनीतिक वनवास के बाद, 1977 के विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारी बहुमत हासिल किया, जो उनकी लोकप्रियता का प्रमाण था।

61. (C) पूर्वोत्तर
भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र शेष देश से भौगोलिक रूप से केवल 22 किलोमीटर चौड़ी एक पतली भूमि पट्टी के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जिसे 'सिलीगुड़ी कॉरिडोर' या 'चिकन नेक' कहा जाता है। यह गलियारा सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके चारों ओर चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमाएँ लगती हैं। इसी भौगोलिक अलगाव के कारण इस क्षेत्र में विकास और सुरक्षा की चुनौतियाँ काफी जटिल रही हैं।

62. (D) क्योंकि वहाँ के मूल निवासी खुद अपने ही प्रदेश में अल्पसंख्यक बन गए हैं।
त्रिपुरा में 'बाहरी' लोगों या प्रवासियों की समस्या सबसे अधिक गंभीर रही है क्योंकि यहाँ की जनसांख्यिकी में भारी बदलाव आया है। पड़ोसी देश बांग्लादेश से आए शरणार्थियों की बड़ी संख्या के कारण वहाँ के मूल निवासी जनजातीय लोग अपने ही प्रदेश में अल्पसंख्यक बनकर रह गए हैं। इस स्थिति ने स्थानीय जनता में अपनी राजनीतिक शक्ति और सांस्कृतिक पहचान खोने का गहरा भय पैदा किया है, जिससे संघर्ष भी हुए।

63. (C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
1990 के दशक के मध्य तक पंजाब में लंबे समय से चली आ रही उग्रवादी हिंसा पर नियंत्रण पा लिया गया और शांति बहाल हुई। हालांकि, इसका कारण 1985 के पंजाब समझौते का पूर्ण कार्यान्वयन नहीं था, क्योंकि उस समझौते की अधिकांश शर्तें अधूरी ही रह गई थीं। शांति बहाली का श्रेय सुरक्षा बलों की कार्रवाई, चरमपंथियों के प्रति जनता के मोहभंग और पुनः शुरु हुई लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दिया जाता है।

64. (B) बरौनी
असम आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने आर्थिक विरोध प्रकट करने के लिए बिहार स्थित 'बरौनी' तेलशोधक कारखाने को होने वाली कच्चे तेल की आपूर्ति ठप करने का प्रयास किया था। उनका तर्क था कि असम के प्राकृतिक संसाधनों का लाभ स्थानीय लोगों को मिलने के बजाय बाहर के क्षेत्रों को मिल रहा है। इस कदम का उद्देश्य केंद्र सरकार पर दबाव बनाना था ताकि वह असम के आर्थिक मुद्दों पर ध्यान दे सके।

65. (B) ई. वी. रामास्वामी नायकर
ई.वी. रामास्वामी नायकर को दक्षिण भारत में श्रद्धापूर्वक 'पेरियार' के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है 'महान आत्मा'। वे एक प्रखर समाज सुधारक थे जिन्होंने तर्कवाद और आत्मसम्मान के सिद्धांतों का प्रचार किया। पेरियार ने जातिगत भेदभाव और उत्तर भारतीय ब्राह्मणवादी परंपराओं का कड़ा विरोध किया। उनके विचारों ने तमिलनाडु की सामाजिक संरचना को बदलने और द्रविड़ राजनीति को दिशा देने में निर्णायक भूमिका निभाई।

66. (A) P-3, Q-1, R-4, S-2
भारत के क्षेत्रीय दलों ने विशिष्ट लक्ष्यों के लिए संघर्ष किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर की स्वायत्तता पर जोर दिया, जबकि अकाली दल ने भाषायी आधार पर 'पंजाबी सूबा' के गठन की लड़ाई लड़ी। मिजो नेशनल फ्रंट ने प्रारंभ में मिजो राष्ट्र की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र विद्रोह किया, वहीं 'आसू' ने असम में अवैध प्रवासियों की पहचान और उनके निष्कासन को अपना मुख्य सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बनाया था।

(D) 1990

164. असम समझौते के अनुसार, विदेशी नागरिकों की पहचान और निर्वासन के लिए कट-ऑफ तारीख क्या निर्धारित की गई थी?
(A) 15 अगस्त, 1947
(B) 26 जनवरी, 1950
(C) 16 दिसंबर, 1971
(D) 25 मार्च, 1971

165. निम्नलिखित में से कौन सा विरोध का तरीका असम आंदोलन के दौरान नहीं अपनाया गया था, जैसा कि अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है?
(A) सशस्त्र अलगाववादी विद्रोह
(B) बंद और हड़ताल
(C) तेल पाइपलाइनों की नाकाबंदी
(D) सार्वजनिक प्रदर्शन

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
भारत के पूर्वोत्तर में अलगाववादी आंदोलन जटिल और विविध रहे हैं, लेकिन नागा और मिज़ो मामले दो विपरीत प्रक्षेप पथ प्रस्तुत करते हैं। नागा आंदोलन, जो भारत के सबसे पुराने अलगाववादी संघर्षों में से एक है, का नेतृत्व अंगामी ज़ापू फिज़ो और नागा नेशनल काउंसिल (एनएनसी) ने किया था। उन्होंने 1951 में ही भारत से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और एक संप्रभु नागालैंड के लिए एक लंबा सशस्त्र संघर्ष चलाया। भारतीय राज्य की प्रतिक्रिया बल प्रयोग की थी, जिसके परिणामस्वरूप दशकों तक हिंसा चली। अंततः, 1963 में नागालैंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन यह एनएनसी के एक गुट को ही संतुष्ट कर सका और संघर्ष विभिन्न रूपों में जारी रहा। इसके विपरीत, मिज़ो आंदोलन, जो 1966 में मिज़ो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) और इसके नेता लालडेंगा के नेतृत्व में एक अलगाववादी विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, का एक अलग निष्कर्ष निकला। 1959 के अकाल के प्रति असम सरकार की अपर्याप्त प्रतिक्रिया से प्रेरित होकर, एमएनएफ ने सशस्त्र संघर्ष का रास्ता अपनाया। हालांकि, दो दशकों के संघर्ष के बाद, एमएनएफ और भारत सरकार बातचीत की मेज पर आए। इसका परिणाम 1986 में ऐतिहासिक मिज़ो शांति समझौते के रूप में हुआ। इस समझौते के तहत, एमएनएफ ने अलगाववाद छोड़ दिया, हथियार डाल दिए और बदले में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा और विशेष संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई। लालडेंगा मिजोरम के मुख्यमंत्री बने, जिसने पूर्व विद्रोहियों को सफलतापूर्वक मुख्यधारा की राजनीति में एकीकृत किया।
उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

166. नागा नेशनल काउंसिल (एनएनसी) के प्रमुख नेता कौन थे?
(A) लालडेंगा
(B) अंगामी ज़ापू फिज़ो
(C) मुफ्ती मोहम्मद सईद
(D) प्रफुल्ल कुमार महंत

167. मिज़ो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के अलगाववादी विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था?
(A) पड़ोसी राज्यों के साथ उत्पन्न भाषाई और गहरे सांस्कृतिक मतभेद
(B) 1959 के अकाल के प्रति सरकार की अपर्याप्त और उदासीन प्रतिक्रिया
(C) किसी बाहरी और शत्रु विदेशी शक्ति द्वारा अचानक किया गया आक्रमण
(D) राज्य प्रशासन द्वारा किया जाने वाला कथित व्यापक धार्मिक उत्पीड़न

168. ऐतिहासिक मिज़ो शांति समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे?
(A) 1986
(B) 1963
(C) 1975
(D) 1991

169. स्रोत के अनुसार, नागा और मिज़ो मामलों के बीच मुख्य अंतर क्या है?
(A) नागा आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक रहा, जबकि मिज़ो आंदोलन एक सशस्त्र संघर्ष था।
(B) नागा आंदोलन को व्यापक विदेशी समर्थन मिला, जबकि मिज़ो आंदोलन पूर्णतः स्थानीय था।
(C) मिज़ो आंदोलन शांति समझौते के साथ समाप्त हुआ, जबकि नागा संघर्ष काफी लंबा चला।
(D) मिज़ो आंदोलन छात्र संगठनों का प्रयास था, जबकि नागा आंदोलन राजनीतिक दलों द्वारा चला.

170. भारत सरकार ने नागा आंदोलन की प्रारंभिक मांगों पर कैसी प्रतिक्रिया दी?
(A) तत्काल राज्य का दर्जा प्रदान करके
(B) शांति समझौते के लिए बातचीत करके
(C) संयुक्त राष्ट्र में मामले को उठाकर
(D) बल प्रयोग के माध्यम से

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिलनाडु में, द्रविड़ आंदोलन 20वीं सदी की एक प्रमुख सामाजिक-राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा। इसकी जड़ें ई.वी. रामासामी 'पेरियार' द्वारा शुरू किए गए आत्म-सम्मान आंदोलन में थीं, जिसने ब्राह्मणवादी सामाजिक पदानुक्रम और जाति व्यवस्था को चुनौती दी। द्रविड़ आंदोलन का मूल सिद्धांत एक विशिष्ट द्रविड़ पहचान का दावा करना था, जो उत्तर भारत की कथित आर्य-संस्कृत संस्कृति से अलग और श्रेष्ठ थी। इसने उत्तर भारतीय राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का भी कड़ा विरोध किया। आंदोलन का एक केंद्रीय स्तंभ हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में थोपने का विरोध था। 1965 में हुए बड़े पैमाने पर हिंदी-विरोधी आंदोलन इस भावना की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति थे। प्रारंभ में, आंदोलन

मिलकर एक गठबंधन सरकार बनाई। इस चुनाव को राज्य में लोकतंत्र की बहाली की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया क्योंकि इसमें मतदाताओं की भागीदारी अच्छी रही और प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न हुई थी।

78. (B) केवल 1, 2 और 4
1997 के पंजाब चुनावों में अकाली दल (बादल) और भाजपा के गठबंधन की शानदार जीत हुई। यह उग्रवाद के काले दौर की समाप्ति के बाद का पहला महत्वपूर्ण चुनाव था जिसने राज्य में सामान्य स्थिति की वापसी की पुष्टि की। हालांकि, राजनीति में अब धर्मनिरपेक्ष मुद्दों और विकास पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा, लेकिन धार्मिक पहचान का प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। फिर भी, पंजाब शांति की राह पर लौट आया।

79. (A) 1959 के अकाल के दौरान असम सरकार की विफलता
मिजोरम में अलगाववादी आंदोलन के पनपने का सबसे प्रमुख कारण 1959 में आया भीषण अकाल था। उस संकट के समय असम सरकार की लापरवाही और राहत कार्यों में विफलता ने मिजो जनता को बुरी तरह आहत किया। उन्हें लगा कि राज्य सरकार उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील नहीं है। इसी आक्रोश ने 'मिजो नेशनल फ्रंट' को एक मजबूत आधार प्रदान किया, जिसने आगे चलकर भारत से अलग होने के लिए विद्रोह किया।

80. (B) उन्हें लगा कि चोग्याल अल्पसंख्यक लेपचा-भूटिया अभिजात वर्ग का शासन थोप रहे हैं।
सिक्किम की बहुसंख्यक आबादी नेपाली मूल की थी, जो वहां के राजा चोग्याल और अल्पसंख्यक लेपचा-भूटिया अभिजात वर्ग के शासन से असंतुष्ट थी। उन्हें लगता था कि चोग्याल उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन कर रहे हैं। इसी कारण सिक्किम कांग्रेस जैसे लोकतांत्रिक दलों ने भारत सरकार से हस्तक्षेप और मदद की अपील की। जनता के भारी समर्थन के कारण अंततः सिक्किम में राजशाही समाप्त हुई और भारत में विलय हुआ।

81. (A) P-4, Q-3, R-2, S-1
भारतीय राजनीति के विभिन्न शीर्ष नेताओं ने क्षेत्रीय मुद्दों पर निर्णायक कदम उठाए हैं। राजीव गाँधी ने असम की समस्या सुलझाने के लिए 1985 में ऐतिहासिक असम समझौता किया। इंदिरा गाँधी ने पंजाब में उग्रवाद को रोकने के लिए 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' का कड़ा फैसला लिया। डॉ. मनमोहन सिंह ने 1984 के दंगों के लिए राष्ट्र से माफी माँगी, जबकि शेख अब्दुल्ला ने 1974 में समझौता कर कश्मीर की मुख्यधारा की राजनीति में वापसी की थी।

82. (A) जनमत-संग्रह के वायदे का पूरा न होना, स्वायत्तता में कमी, और लोकतंत्र का अभाव।
जम्मू-कश्मीर के लोगों की तीन प्रमुख शिकायतें रही हैं जो वहां के राजनीतिक असंतोष का मूल कारण मानी जाती हैं। पहली, आज़ादी के समय जनमत-संग्रह के वायदे का पूरा न होना। दूसरी, अनुच्छेद 370 के बावजूद समय के साथ राज्य की स्वायत्तता में निरंतर कटौती किया जाना। और तीसरी, राज्य में निष्पक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और चुनावों का अभाव होना। इन मुद्दों ने समय-समय पर अलगाववादी भावनाओं को बल दिया है।

83. (C) चरमपंथी तत्त्वों के
1980 के दशक की शुरुआत में पंजाब की राजनीति में एक खतरनाक मोड़ आया जब आंदोलन का नेतृत्व नरमपंथी अकालियों के हाथों से निकलकर चरमपंथी तत्वों के पास चला गया। इन समूहों ने अधिक उग्र और कभी-कभी हिंसक मांगों को अपना समर्थन दिया। उन्होंने अमृतसर के स्वर्णमंदिर परिसर को अपना मुख्यालय बना लिया, जिससे राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई और अंततः सरकार को सैन्य कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

84. (D) मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश
'चकमा' शरणार्थियों का मुद्दा मुख्य रूप से पूर्वोत्तर के दो राज्यों, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में तनाव का एक बड़ा कारण बना हुआ है। ये चकमा लोग मूलतः बांग्लादेश के चित्तागोंग हिल ट्रैक्ट्स से आए बौद्ध धर्मावलंबी हैं। स्थानीय जनजातीय समुदायों को डर है कि इन शरणार्थियों के बसने से उनकी अपनी जनसांख्यिकी, संस्कृति और संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। इस मुद्दे पर अक्सर छात्र संगठनों द्वारा तीव्र विरोध किया जाता है।

85. (2, 1, 4, 3) (Wait, provided answer is A)
तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का विकास कई चरणों में हुआ। सबसे पहले 1925 में पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन शुरु किया। इसके दशकों बाद, 1953 में डी.एम.के. ने अपनी पहचान पुख्ता करने के लिए तीन-सूत्री आंदोलन चलाया। 1965 के दौरान हिंदी विरोधी आंदोलन ने इस राजनीति को चरम पर पहुँचाया। इन सभी जन आंदोलनों की परिणति 1967 के चुनाव में हुई, जब डी.एम.के. ने पहली बार राज्य में अपनी सरकार बनाई थी।

86. (B) महाराजा से छुटकारा और पाकिस्तान में शामिल न होना
1947 में शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस की दो स्पष्ट माँगें थीं। पहली यह कि वे कश्मीर में महाराजा हरि सिंह की राजशाही को समाप्त कर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे धर्म के आधार पर बने पाकिस्तान में शामिल होने के कड़े विरोधी थे। उनकी विचारधारा धर्मनिरपेक्ष थी, जिसके कारण उन्होंने मुस्लिम लीग के द्वि-राष्ट्र सिद्धांत को पूरी तरह नकार दिया था।

87. (D) समाज को आकार देने वाली विभिन्न संस्कृतियों की विशिष्टता को बनाए रखते हुए एकता की भावना से बँधे रहना।
भारतीय राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी विशेषता एकता और विविधता के बीच संतुलन साधना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि क्षेत्रीय विविधताओं को मिटाकर एकरूपता लाई जाए, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि विभिन्न भाषायी, धार्मिक और सांस्कृतिक पहचानों को फलने-फूलने का पूरा मौका दिया जाए। भारत एक ऐसे साझा मंच के रूप में विकसित हुआ है जहाँ सभी क्षेत्रों

था। आंदोलन की समाप्ति के बाद इसी संगठन की पृष्ठभूमि से निकले नेताओं ने 'असम गण परिषद्' बनाकर राज्य में पहली बार एक क्षेत्रीय सरकार का गठन किया था, जिसने असम की राजनीति को नई दिशा दी।

146. (A) इसमें लगभग बराबर संख्या में बौद्ध और मुसलमान थे।
जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन से पूर्व, लद्दाख क्षेत्र की जनसांख्यिकी एक विशेष संतुलन प्रदर्शित करती थी। यहाँ की कुल जनसंख्या में बौद्धों और मुसलमानों की संख्या लगभग बराबर थी। लद्दाख के लेह जिले में बौद्ध बहुमत में हैं, जबकि कारगिल जिले में मुस्लिम आबादी अधिक है। इस धार्मिक विविधता के बावजूद वहां के लोग अपनी साझा लद्दाखी पहचान को लेकर एकजुट रहे हैं और लंबे समय से लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की माँग करते रहे थे, जिसे 2019 में पूरा किया गया।

147. (D) सभी कथन सही हैं
शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के आधुनिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। उन्होंने राजशाही के खिलाफ जन आंदोलन चलाया और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर भारत के साथ विलय का समर्थन किया। वे राज्य के पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन बाद में केंद्र से मतभेदों के कारण उन्हें बर्खास्तगी और जेल का सामना करना पड़ा। अंततः 1974 में इंदिरा गाँधी के साथ समझौता कर उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यधारा की राजनीति में वापसी की और अपनी लोकप्रियता को पुनः सिद्ध किया, जो उनके कद को दर्शाता है।

148. (D) अलगाव के आंदोलन और 'बाहरी' लोगों का विरोध
1980 के दशक के दौरान पूर्वोत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति और अधिक जटिल हो गई। स्वायत्तता की माँग तो पहले से ही मौजूद थी, लेकिन इस दशक में दो नए और गंभीर मुद्दे नाटकीय रूप से उभरे: पहला, कुछ राज्यों में स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए चल रहे अलगाववादी सशस्त्र आंदोलन और दूसरा, असम जैसे राज्यों में 'बाहरी' लोगों के खिलाफ शुरू हुआ तीव्र विरोध। इन दोनों मुद्दों ने केंद्र सरकार को सुरक्षा और विकास की नीतियों पर पुनर्विचार करने और विभिन्न समूहों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए मजबूर किया था।

149. (C) लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रिया
भारत की लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रिया ही वह विशेषता है जो विभिन्न दलों और समूहों को अपनी क्षेत्रीय पहचान और आकांक्षाओं के आधार पर जनता का प्रतिनिधित्व करने का अवसर देती है। यहाँ चुनावी प्रतिस्पर्धा के माध्यम से छोटे और क्षेत्रीय समूह अपनी बात केंद्र तक पहुँचा सकते हैं और सत्ता में हिस्सेदारी प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि भारत में क्षेत्रीय दल न केवल राज्यों में बल्कि केंद्र सरकार के गठन में भी निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं, जो लोकतंत्र की सफलता का प्रमाण है।

150. (B) राजीव गाँधी के साथ समझौता करने के कुछ समय बाद
संत हरचंद सिंह लोंगोवाल की हत्या 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गाँधी के साथ 'पंजाब समझौते' पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही हफ्तों बाद कर दी गई थी। उन्हें चरमपंथी सिख गुटों के कोप का सामना करना पड़ा जो इस शांति समझौते को स्वीकार नहीं कर रहे थे और इसे सिखों के साथ विश्वासघात मानते थे। उनकी हत्या राज्य में शांति बहाली के प्रयासों के लिए एक बहुत बड़ा धक्का थी। हालांकि, उनके द्वारा शुरु की गई सुलह की प्रक्रिया ने अंततः पंजाब को उग्रवाद के काले दौर से बाहर निकालने में मदद की थी।

151. (B) अपनी विशिष्ट भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को व्यक्त और संरक्षित करना
भारतीय संघवाद में क्षेत्रवाद एक जटिल घटना है जिसे हमेशा नकारात्मक नहीं माना जाना चाहिए। इसका सकारात्मक पक्ष किसी विशेष क्षेत्र के निवासियों की अपनी विशिष्ट भाषाई, सांस्कृतिक और जातीय पहचान को प्रदर्शित करने और उसे सुरक्षित रखने की सामूहिक इच्छा को दर्शाता है। यह ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों से प्रभावित होकर क्षेत्रीय गौरव और अपनी जड़ों से जुड़ाव को बढ़ावा देता है।

152. (A) जब इसे राजनीतिक और आर्थिक शिकायतों के साथ जोड़ा जाता है
क्षेत्रवाद की भावना तब नकारात्मक मोड़ लेती है जब स्थानीय लोगों की आकांक्षाएं राजनीतिक और आर्थिक शिकायतों से जुड़ जाती हैं। संसाधनों के असमान वितरण, केंद्र सरकार द्वारा की गई कथित उपेक्षा या राजनीतिक स्वायत्तता की कमी जैसे कारक असंतोष को जन्म देते हैं। ऐसी स्थितियों में क्षेत्रीय पहचान का उपयोग अक्सर संकुचित हितों या अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।

153. (C) एक सत्तावादी शासन
भारतीय लोकतंत्र में क्षेत्रीय भावनाओं और मांगों को व्यक्त करने के लिए संस्थागत ढांचे उपलब्ध हैं। राजनीतिक दल, विभिन्न दबाव समूह और जन आंदोलन इन भावनाओं को सरकार तक पहुँचाने के प्रभावी माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। इसके विपरीत, एक सत्तावादी शासन लोकतांत्रिक मूल्यों और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने का प्रयास करता है, जिससे वह इन भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बन सकता है।

154. (D) पूर्ण अलगाववाद की मांग
जब क्षेत्रवाद नकारात्मक अभिव्यक्ति का रूप लेता है, तो इसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। इसकी शुरुआत स्वायत्त राज्यों की मांग से होती है, लेकिन चरम स्थिति में यह पूर्ण अलगाववाद में बदल सकता है। इसका अर्थ देश की मुख्यधारा से पूरी तरह अलग होकर एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र की स्थापना की मांग करना है, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए बड़ी चुनौती बनती है।

155. (C) राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय पहचान के बीच एक गतिशील समायोजन प्रक्रिया
भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में क्षेत्रवाद को केवल एक विघटनकारी शक्ति नहीं माना जाना चाहिए। यह वास्तव में राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय पहचान के बीच होने वाले निरंतर संवाद और समायोजन की एक गतिशील प्रक्रिया है। यह

में हिंसा और अस्थिरता का लंबा दौर शुरू हुआ। इस बाहरी हस्तक्षेप ने कश्मीर मुद्दे को और अधिक जटिल बना दिया और इसे एक द्विपक्षीय तनाव से अंतरराष्ट्रीय स्तर के संकट में बदल दिया।

98. (A) क्षेत्रीयता को राष्ट्र-विरोधी नहीं माना जाता और क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति की अनुमति है।
भारत का लोकतांत्रिक दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि क्षेत्रीयता और राष्ट्रवाद एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों को अपनी विशिष्ट समस्याओं और आकांक्षाओं को राजनीतिक रूप से व्यक्त करने की पूरी आजादी है। क्षेत्रीय दलों का उदय और उनकी सत्ता में भागीदारी इसी लोकतांत्रिक परिपक्वता का प्रमाण है। भारत सरकार ने हमेशा क्षेत्रीय माँगों को राष्ट्रीय एकता के भीतर समायोजित करने की कोशिश की है, जिससे लोकतंत्र मजबूत हुआ है।

99. (B) केवल 1, 2 और 3
ई.वी. रामास्वामी नायकर 'पेरियार' को आधुनिक तमिलनाडु का निर्माता और द्रविड़ अस्मिता का जनक माना जाता है। उन्होंने 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य निम्न जातियों को सामाजिक उत्पीड़न से मुक्त करना था। पेरियार ने हिंदी और उत्तर भारतीय वर्चस्व का कड़ा विरोध किया और तर्क दिया कि दक्षिण की संस्कृति और भाषा को संरक्षित रखा जाना चाहिए। उनके ये विचार आज भी दक्षिण भारतीय राजनीति की वैचारिक नींव हैं।

100. (D) दिल्ली
31 अक्तूबर 1984 को इंदिरा गाँधी की हत्या के बाद देश के कई शहरों में सिख समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़क उठी, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सबसे अधिक प्रभावित हुई। दिल्ली में हजारों निर्दोष सिखों को निशाना बनाया गया, उनके घरों और दुकानों को जला दिया गया। सरकारी आँकड़ों के अनुसार, इस हिंसा में अकेले दिल्ली में दो हजार से अधिक लोग मारे गए थे। यह घटना स्वतंत्र भारत के इतिहास में मानवाधिकारों के उल्लंघन का काला अध्याय है।

101. (C) शेख मोहम्मद अब्दुल्ला
शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के एक ऐसे दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने धर्म के आधार पर राष्ट्र निर्माण के विचार को पूरी तरह खारिज कर दिया था। उन्होंने पाकिस्तान में शामिल होने का पुरजोर विरोध किया क्योंकि उनकी विचारधारा धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पर आधारित थी। शेख अब्दुल्ला का मानना था कि कश्मीर की बहुलतावादी संस्कृति केवल एक धर्मनिरपेक्ष भारत में ही सुरक्षित रह सकती है। इसी सोच के कारण उन्होंने भारत के साथ राज्य के विलय का समर्थन किया था।

102. (B) केवल 2, 3, 4
भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी सीमाएँ चीन, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे देशों से लगती हैं, जो इसे भारत के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेश-द्वार बनाती हैं। यह क्षेत्र केवल 22 किलोमीटर लंबी एक पतली भूमि पट्टी के जरिए मुख्य भारत से जुड़ा है। सामरिक महत्व के बावजूद, लंबे समय तक इस क्षेत्र में विकास की गति धीमी रही, जिससे यहाँ कई क्षेत्रीय असंतोष उभरे और संवेदनशील स्थितियां बनीं।

103. (D) गोवा की स्वतंत्र गोवानी पहचान और संस्कृति को बनाए रखना।
गोवा की मुक्ति के बाद, 'यूनाइटेड गोअन पार्टी' (यूजीपी) का गठन उन लोगों द्वारा किया गया था जो गोवा की अपनी एक विशिष्ट पहचान और कोंकणी संस्कृति को बचाए रखना चाहते थे। इस पार्टी ने गोवा के महाराष्ट्र में विलय का कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि गोवा का अपना एक अलग इतिहास और सामाजिक ताना-बाना है जिसे पड़ोसी राज्य में मिलाकर खत्म नहीं किया जाना चाहिए। इसी विरोध के कारण 1967 में जनमत सर्वेक्षण की स्थिति उत्पन्न हुई थी।

104. (A) संशय और हिंसा से भरे माहौल के कारण।
1992 में जब पंजाब में विधानसभा चुनाव कराए गए, तो मतदान का प्रतिशत मात्र 24 फीसदी रहा, जो बेहद कम था। इसका मुख्य कारण राज्य में व्याप्त उग्रवाद और हिंसा का माहौल था। चरमपंथी संगठनों ने चुनाव के बहिष्कार का आह्वान किया था और मतदाताओं में सुरक्षा को लेकर गहरा भय था। हालांकि मतदान कम हुआ, लेकिन इन चुनावों ने राज्य में पुनः लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना और उग्रवाद के अंत की शुरुआत में प्रतीकात्मक भूमिका निभाई।

105. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
1980 के दशक के बाद भारत सरकार ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं से निपटने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव किया और बातचीत व सुलह की नीति अपनाई। सरकार ने यह महसूस किया कि केवल बल प्रयोग या दमन के माध्यम से क्षेत्रीय असंतोष को स्थायी रूप से हल नहीं किया जा सकता। इसी सोच के कारण पंजाब, असम और मिजोरम जैसे अशांत क्षेत्रों में ऐतिहासिक शांति समझौते किए गए, जिन्होंने अलगाववाद को कम करने और इन क्षेत्रों को मुख्यधारा में लाने में सफलता पाई।

106. (A) ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू)
1979 में शुरू हुए असम आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से 'ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन' (आसू) ने किया था। यह एक गैर-राजनीतिक छात्र संगठन था जिसने अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर पूरे राज्य में जबरदस्त जनसमर्थन जुटाया। आंदोलन का उद्देश्य उन विदेशी नागरिकों की पहचान करना और उन्हें मतदाता सूची से हटाकर राज्य से बाहर भेजना था जो 1951 के बाद असम में आए थे। छह साल तक चले इस तीव्र आंदोलन की समाप्ति 1985 के असम समझौते के साथ हुई थी।

107. (D) क्योंकि कश्मीर के दर्जे पर उनकी स्थिति को लेकर केंद्र सरकार से मतभेद हो गए थे।
1953 में शेख अब्दुल्ला को जम्मू-कश्मीर के प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त कर गिरफ्तार कर लिया गया था। इसका मुख्य कारण कश्मीर के स्वायत्त दर्जे और भविष्य की स्थिति को लेकर उनके और केंद्र सरकार के बीच बढ़ते मतभेद थे। केंद्र सरकार को

फिज़ो ने नागा पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर संगठित करने और सशस्त्र संघर्ष को दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

167. (B) 1959 के अकाल के प्रति सरकार की अपर्याप्त और उदासीन प्रतिक्रिया

मिज़ो आंदोलन की शुरुआत के पीछे 1959 में आया भीषण अकाल एक बड़ा कारण बना। उस समय की असम सरकार द्वारा अकाल राहत कार्यों में दिखाई गई उदासीनता और अपर्याप्त प्रतिक्रिया ने स्थानीय मिज़ो आबादी में गहरा असंतोष पैदा कर दिया। इस उपेक्षा ने लालडेंगा के नेतृत्व में मिज़ो नेशनल फ्रंट को सशस्त्र विद्रोह का मार्ग अपनाने और एक अलग राष्ट्र की मांग करने के लिए प्रेरित किया।

168. (A) 1986

मिज़ो हिल्स में लगभग दो दशकों तक चले सशस्त्र संघर्ष का अंत एक सफल शांति प्रक्रिया के माध्यम से हुआ। 1986 में भारत सरकार और मिज़ो नेशनल फ्रंट के बीच ऐतिहासिक मिज़ो शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते ने न केवल क्षेत्र में हिंसा को समाप्त किया, बल्कि मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा और विशेष संवैधानिक सुरक्षा भी प्रदान की, जिससे विकास का नया युग शुरू हुआ।

169. (C) मिज़ो आंदोलन शांति समझौते के साथ समाप्त हुआ, जबकि नागा संघर्ष काफी लंबा चला।

नागा और मिज़ो आंदोलनों के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर उनके समाधान की प्रक्रिया और परिणाम में निहित है। जहाँ मिज़ो आंदोलन 1986 के शांति समझौते के बाद मुख्यधारा की राजनीति में सफलतापूर्वक एकीकृत हो गया, वहीं नागा संघर्ष काफी लंबा और जटिल रहा। मिज़ो विद्रोहियों ने हथियार डालकर शांति का मार्ग चुना, जबकि नागालैंड में दशकों तक विभिन्न गुटों के बीच संघर्ष और हिंसा जारी रही।

170. (D) बल प्रयोग के माध्यम से

नागा आंदोलन द्वारा जब संप्रभुता और स्वतंत्रता की मांग की गई, तो भारत सरकार की प्रारंभिक प्रतिक्रिया बल प्रयोग की रही। सरकार ने विद्रोह को दबाने और राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए सेना का उपयोग किया। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में दशकों तक हिंसक संघर्ष जारी रहा। यद्यपि बाद में राजनीतिक समाधान के प्रयास किए गए, लेकिन शुरुआती दौर में सैन्य दृष्टिकोण ही प्रभावी बना रहा।

171. (C) ई.वी. रामासामी 'पेरियार'

दक्षिण भारत में सामाजिक सुधारों की नींव रखने वाले आत्म-सम्मान आंदोलन की शुरुआत ई.वी. रामासामी 'पेरियार' ने की थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवादी वर्चस्व और जाति आधारित भेदभाव को चुनौती देना था। उन्होंने निचली जातियों के आत्म-सम्मान को जागृत करने और उन्हें सामाजिक समानता दिलाने के लिए कड़ा संघर्ष किया, जो बाद में तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ आंदोलन का मुख्य आधार बना।

172. (B) हिंदी भाषा को थोपने का विरोध

द्रविड़ आंदोलन का एक प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तंभ उत्तर भारत की भाषाई प्रभुता का विरोध करना था। इसमें विशेष रूप से हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में थोपे जाने का कड़ा विरोध शामिल था। इस आंदोलन का मानना था कि हिंदी को अनिवार्य करना तमिल भाषा और संस्कृति की विशिष्टता के लिए खतरा है। 1965 के हिंदी-विरोधी आंदोलनों ने इस विरोध को एक शक्तिशाली जन आंदोलन बना दिया।

173. (D) 'द्रविड़नाडु' नामक एक स्वतंत्र राज्य

द्रविड़ आंदोलन के शुरुआती चरण में कुछ चरमपंथी वर्गों ने एक अलग और स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र की कल्पना की थी। इस प्रस्तावित स्वतंत्र राज्य को 'द्रविड़नाडु' का नाम दिया गया था, जो उत्तर भारतीय राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव से पूरी तरह मुक्त होता। यह मांग द्रविड़ पहचान को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की आकांक्षा पर आधारित थी, जिसने तत्कालीन राजनीति में काफी चर्चा बटोरी थी।

174. (A) 1962 का चीनी आक्रमण

द्रविड़ आंदोलन की दिशा में एक बड़ा बदलाव 1962 के चीनी आक्रमण के दौरान आया। राष्ट्रीय सुरक्षा के संकट और देश की अखंडता की आवश्यकता को देखते हुए आंदोलन के नेताओं ने अपनी अलगाववादी मांगों को त्यागने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त, संवैधानिक संशोधनों ने भी अलगाववाद की राजनीति को प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद आंदोलन ने भारतीय संघ के भीतर स्वायत्तता और भाषाई अधिकारों पर अधिक ध्यान दिया।

175. (C) कि कैसे एक संभावित अलगाववादी आंदोलन एक प्रभावशाली क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति में बदल सकता है।

द्रविड़ आंदोलन का भारतीय राजनीतिक ढांचे में सफल एकीकरण एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह दर्शाता है कि कैसे एक संभावित अलगाववादी आंदोलन सही लोकतांत्रिक संवाद के माध्यम से एक प्रभावशाली क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति के रूप में बदल सकता है। चुनावी राजनीति में डीएमके जैसी पार्टियों की भागीदारी ने यह सिद्ध किया कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को राष्ट्रीय एकता के साथ संतुलित किया जा सकता है, जो लोकतंत्र की शक्ति है।

रहा। इस अवधि के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई गुट कांग्रेस में मिल गए या उसके प्रभाव में रहे। केंद्र सरकार ने राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कांग्रेस की सरकारों को बढ़ावा दिया। हालांकि इस दौरान राज्य का भारत के साथ प्रशासनिक एकीकरण बढ़ा, लेकिन स्थानीय स्तर पर राजनीतिक असंतोष और स्वायत्तता की कमी की शिकायतें भी बनी रहीं।

118. (B) क्योंकि इसने सिख 'कौम' की आकांक्षाओं पर जोर देते हुए सिखों के 'बोलबाला' का ऐलान किया, जिसकी व्याख्या अलगाववादी माँग के रूप में की जा सकती थी।
आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को विवादास्पद इसलिए माना गया क्योंकि इसमें सिख 'कौम' की विशिष्ट पहचान पर अत्यधिक जोर दिया गया था। प्रस्ताव में प्रयुक्त 'बोलबाला' (प्रभुत्व) जैसे शब्दों की व्याख्या कुछ राजनीतिक हलकों में अलगाववादी माँग या एक अलग राष्ट्र की इच्छा के रूप में की गई। यद्यपि अकालियों का कहना था कि वे केवल संघीय ढांचे के भीतर अधिक अधिकारों की माँग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार और अन्य दलों ने इसे राष्ट्रीय एकता के लिए संभावित खतरे के रूप में देखा था।

119. (B) P-1, Q-2, R-3, S-4
पंजाब और मिजोरम के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं का एक निश्चित क्रम है। 1973 में स्वायत्तता के लिए आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आया। जून 1984 में स्वर्णमंदिर में सैन्य कार्रवाई 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' हुई। इसके बाद, जुलाई 1985 में शांति बहाली के लिए ऐतिहासिक राजीव-लोंगोवाल समझौता संपन्न हुआ। अंततः, 1987 में मिजोरम को एक पूर्ण राज्य के रूप में मान्यता दी गई। ये सभी घटनाएँ दर्शाती हैं कि किस प्रकार भारत ने क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना संवैधानिक और राजनीतिक माध्यमों से किया है।

120. (A) सिक्किम में लोकतंत्र बहाली आंदोलन
काजी लेंडुप दोरजी खांगसरपा सिक्किम में लोकतंत्र की बहाली और राजशाही के विरुद्ध चले आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता थे। उनके नेतृत्व में सिक्किम कांग्रेस ने राज्य की बहुसंख्यक जनता को एकजुट किया और चोग्याल के निरंकुश शासन को चुनौती दी। उन्होंने सिक्किम के भारत में पूर्ण विलय की पुरजोर वकालत की ताकि वहां के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार मिल सकें। 1975 में सिक्किम के भारत का 22वाँ राज्य बनने के बाद वे वहां के पहले मुख्यमंत्री बने।

121. (C) 1979 से 1985
असम में 'बाहरी' लोगों के खिलाफ चला आंदोलन 1979 से 1985 तक अपनी पूरी तीव्रता के साथ जारी रहा। इस छह साल की अवधि में राज्य ने व्यापक विरोध प्रदर्शनों, बंद और हिंसक झड़पों का सामना किया। आंदोलनकारियों की मुख्य शिकायत यह थी कि विदेशी प्रवासियों के कारण असम की जनसांख्यिकी और स्थानीय संस्कृति खतरे में है। इस संघर्ष का अंत 15 अगस्त 1985 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी और आंदोलनकारी नेताओं के बीच हुए 'असम समझौते' के साथ हुआ था।

122. (A) नगालैंड और मिज़ोरम में
आज़ादी के बाद जहाँ अधिकांश रियासतें भारत में शांतिपूर्ण ढंग से मिल गईं, वहीं कुछ क्षेत्रों में गंभीर अलगाववादी माँगें उठीं। जम्मू-कश्मीर के अलावा, पूर्वोत्तर भारत के नगालैंड और मिजोरम में भी भारत संघ से अलग होने के लिए लंबे समय तक सशस्त्र विद्रोह चले। नगालैंड में अंगमी जापू फिजो और मिजोरम में लालडेंगा के नेतृत्व में इन आंदोलनों ने भारतीय सुरक्षा बलों और केंद्र सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती पेश की, जिसे अंततः राजनीतिक समझौतों और स्वायत्तता के जरिए सुलझाया गया था।

123. (D) पेरियार - द्रविड़ आंदोलन
दिए गए जोड़ों में पेरियार और द्रविड़ आंदोलन का संबंध बिल्कुल सही है क्योंकि ई.वी. रामास्वामी नायकर 'पेरियार' ही इस आंदोलन के वैचारिक आधार स्तंभ थे। इसके विपरीत, अनुच्छेद 370 का संबंध पंजाब से नहीं बल्कि जम्मू-कश्मीर से था। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में पंजाब में हुआ था, मिजोरम में नहीं। असम समझौता 1985 में हुआ था, न कि 1990 में। अतः पेरियार वाला विकल्प ही ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से सटीक मेल प्रदर्शित करता है।

124. (B) स्थानीय लोगों में क्रोध और अलगाव की भावना और तेज हुई।
मिजोरम में विद्रोही गतिविधियों को कुचलने के लिए भारत सरकार ने सेना का सहारा लिया, जिसमें वायुसेना के इस्तेमाल जैसी कठोर कार्रवाइयां भी शामिल थीं। इस सैन्य कार्रवाई ने मिजो विद्रोहियों को तो पीछे हटने पर मजबूर किया, लेकिन आम स्थानीय जनता के मन में गहरे जख्म छोड़ दिए। इससे लोगों में भारत सरकार के प्रति क्रोध और अलगाव की भावना और अधिक प्रबल हो गई। यही कारण था कि वहां शांति स्थापित करने में दो दशकों का लंबा समय और राजनीतिक इच्छाशक्ति लगानी पड़ी थी।

125. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
सिक्किम का भारत में विलय केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं था, बल्कि इसे स्थानीय जनता का भारी समर्थन प्राप्त था। 1975 में सिक्किम की निर्वाचित विधानसभा ने राजशाही को समाप्त करने और भारत का हिस्सा बनने के लिए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया। इस निर्णय पर जनता की मुहर लगाने के लिए एक जनमत-संग्रह कराया गया, जिसमें सिक्किम के अधिकांश नागरिकों ने भारत में विलय के पक्ष में मतदान किया। इसी जनभावना के आधार पर सिक्किम को संवैधानिक रूप से भारत का राज्य बनाया गया था।

126. (D) पीडीपी और बीजेपी की मिली-जुली सरकार बनी।
2014 के जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनावों के परिणाम बहुत ही रोचक रहे क्योंकि किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिला। घाटी में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि जम्मू क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने बड़ी जीत हासिल की। अंततः, दो परस्पर विरोधी विचारधारा वाले दलों—पीडीपी और बीजेपी—ने मिलकर एक

गठबंधन सरकार बनाई। मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने। हालांकि, यह गठबंधन अधिक समय तक नहीं चल सका और 2018 में बीजेपी के समर्थन वापस लेने से सरकार गिर गई थी।

127. (A) मिजोरम, जहाँ समझौते से स्थायी शांति आई।
क्षेत्रीय आकांक्षाओं और संघर्षों को सुलझाने के लिए 'मिजोरम' को दुनिया भर में एक सफल उदाहरण के रूप में देखा जाता है। दो दशकों के हिंसक विद्रोह और सैन्य कार्रवाई के बाद, 1986 में भारत सरकार और लालडेंगा के बीच हुआ शांति समझौता एक बड़ी उपलब्धि थी। इस समझौते ने न केवल शांति बहाल की, बल्कि मिजोरम आज पूर्वोत्तर के सबसे शांत और साक्षर राज्यों में से एक है। यह दर्शाता है कि लोकतांत्रिक संवाद से घोर अलगाववाद को भी मुख्यधारा में बदला जा सकता है।

128. (D) 1, 2, 3 और 4 सभी
पूर्वोत्तर भारत के राज्यों का गठन एक क्रमिक प्रक्रिया रही है। 1963 में नगालैंड पहला ऐसा जनजातीय राज्य बना जो असम से अलग हुआ। इसके बाद 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य की मान्यता मिली। 1987 में शांति बहाली के प्रयासों के तहत मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य बने। वहीं, 1975 में सिक्किम का भारत में विलय हुआ। ये सभी वर्ष भारतीय लोकतंत्र द्वारा क्षेत्रीय अस्मिता और स्वायत्तता को संवैधानिक मान्यता देने के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं।

129. (B) जम्मू और कश्मीर
महबूबा मुफ्ती जम्मू और कश्मीर राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं। वे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की नेता हैं और उन्होंने 2016 में अपने पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद राज्य की कमान संभाली। उनका मुख्यमंत्री बनना कश्मीर की राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का एक महत्वपूर्ण संकेत था। हालांकि, उनके कार्यकाल के दौरान राज्य को सुरक्षा की गंभीर चुनौतियों और बाद में गठबंधन टूटने जैसी राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा था।

130. (A) 1966
स्वतंत्रता के बाद सिखों द्वारा चलाए गए 'पंजाबी सूबा' आंदोलन की माँग को भारत सरकार ने लंबे समय बाद 1966 में स्वीकार किया। इस निर्णय के तहत तत्कालीन पंजाब राज्य का भाषायी आधार पर पुनर्गठन किया गया। पंजाबी बोलने वाले क्षेत्रों को 'पंजाब' और हिंदी बोलने वाले क्षेत्रों को 'हरियाणा' राज्य के रूप में स्थापित किया गया। चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की साझा राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यह पुनर्गठन भाषायी अस्मिता के प्रति लोकतांत्रिक सम्मान का परिणाम था।

131. (A) केवल 1, 2, 3, 5
मास्टर तारा सिंह सिखों के एक अत्यंत प्रभावशाली धार्मिक और राजनीतिक नेता थे। उन्होंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के गठन और अकाली आंदोलन के नेतृत्व में केंद्रीय भूमिका निभाई। वे स्वतंत्रता के बाद भाषायी आधार पर अलग 'पंजाब' राज्य (पंजाबी सूबा) के निर्माण के सबसे प्रबल पैरोकार थे। यद्यपि वे धर्मनिरपेक्षता के विरोधी नहीं थे, लेकिन उन्होंने सिखों की विशिष्ट पहचान और उनके राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए अक्सर कांग्रेस सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना की थी।

132. (D) जम्मू और कश्मीर
'पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी' (पीडीपी) जम्मू और कश्मीर की एक प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। इसकी स्थापना 1999 में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने की थी। इस दल ने 'कश्मीरियत' और स्थानीय लोगों की समस्याओं को केंद्र में रखकर राजनीति की और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विकल्प के रूप में उभरा। पीडीपी ने राज्य में दो बार गठबंधन सरकारों का नेतृत्व किया है, जिससे वहां की द्वि-दलीय क्षेत्रीय राजनीति को एक नया आयाम मिला और स्थानीय आकांक्षाओं को स्वर मिला।

133. (C) ऑपरेशन ब्लू स्टार में स्वर्णमंदिर को हुई क्षति
जून 1984 में अमृतसर के स्वर्णमंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' ने सिख समुदाय को मानसिक और धार्मिक रूप से गहरा आघात पहुँचाया। सिखों के लिए स्वर्णमंदिर केवल एक इमारत नहीं, बल्कि उनकी आस्था का सर्वोच्च केंद्र है। सैन्य अभियान के दौरान मंदिर परिसर और अकाल तख्त को हुई क्षति ने न केवल उग्रवाद को बढ़ावा दिया, बल्कि सामान्य सिखों के मन में भी सरकार के प्रति अविश्वास और नाराजगी भर दी, जिसका असर दशकों तक सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य पर रहा।

134. (C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
1990 के दशक में तमिलनाडु की राजनीति में काफी बदलाव आया और डी.एम.के. व ए.आई.ए.डी.एम.के. से अलग होकर कई नए द्रविड़ दल जैसे एम.डी.एम.के. और पी.एम.के. अस्तित्व में आए। ये दल क्षेत्रीय अस्मिता को नए स्वरूप में पेश कर रहे थे। दूसरी ओर, यह कहना गलत होगा कि पूर्वोत्तर की राजनीति स्थिर रही; उसी दौरान पूर्वोत्तर के कई राज्यों में नए शांति समझौते हुए और क्षेत्रीय दलों की भूमिका केंद्र सरकार में भी पहले की तुलना में अधिक प्रभावी होकर उभरी थी।

135. (D) तमाम भारतीय नागरिकों तक अपनी बात पहुँचाना और यह दर्शाना कि क्षेत्रीय आकांक्षा राष्ट्रीय भावना के विरुद्ध नहीं है।
भारत जैसे बहुभाषी देश में सात या अधिक भाषाओं का उपयोग करने वाले विज्ञापनों का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता का संदेश देना होता है। यह दर्शाता है कि क्षेत्रीय भाषाएँ और आकांक्षाएं देश के लिए खतरा नहीं हैं, बल्कि वे भारतीयता के व्यापक दायरे का हिस्सा हैं। ऐसे विज्ञापनों के माध्यम से सरकार या संगठन यह बताना चाहते हैं कि राष्ट्र की प्रगति में हर क्षेत्र की भाषा और संस्कृति का समान महत्व है, जो अंततः एकता और विविधता के बीच संतुलन को पुष्ट करता है।

136. (A) P-1, Q-4, R-3, S-2
विभिन्न क्षेत्रीय दलों का गठन विशिष्ट मांगों को लेकर हुआ था। 'महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी' गोवा का महाराष्ट्र में विलय चाहती थी, जबकि 'यूनाइटेड गोअन पार्टी' उसकी अलग पहचान की पक्षधर थी। 'सिक्किम कांग्रेस' ने सिक्किम के भारत में पूर्ण विलय के लिए नेतृत्व प्रदान किया। वहीं 'असम गण परिषद'

का जन्म असम आंदोलन से हुआ, जिसका मुख्य लक्ष्य राज्य से अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालना और क्षेत्रीय हितों की रक्षा करना था।

137. (C) संगठन के अनुसार यह नीति समाज में ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देती थी।
1953-54 में तमिलनाडु की राजाजी सरकार द्वारा लाए गए 'शिल्पकर्म शिक्षा कार्यक्रम' का डी.एम.के. ने पुरजोर विरोध किया। इस दल का मानना था कि यह कार्यक्रम बच्चों को उनके पारिवारिक जातिगत व्यवसायों में ही बांधे रखेगा, जो ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था को और मजबूत करेगा। डी.एम.के. ने इसे पिछड़ी जातियों के आधुनिक विकास और शिक्षा के मार्ग में बाधा माना। इसी विरोध ने द्रविड़ राजनीति को सामाजिक न्याय के संघर्ष के रूप में जनता के बीच लोकप्रिय बनाया था।

138. (A) कश्मीर का मामला
1947 के विभाजन के समय से ही भारत और पाकिस्तान के बीच 'कश्मीर का मुद्दा' सबसे बड़ा और जटिल विवाद बना हुआ है। दोनों देश इस क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं, जिसके कारण अब तक कई युद्ध और निरंतर सीमावर्ती तनाव होते रहे हैं। भारत इसे अपना अभिन्न अंग मानता है जबकि पाकिस्तान इसे 'अधूरा विभाजन' कहता है। इस विवाद ने न केवल दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित किया है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की शांति और सुरक्षा के लिए चुनौती खड़ी की है।

139. (D) सदर-ए-रियासत
1974 के ऐतिहासिक समझौते के बाद जम्मू-कश्मीर की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने पुनः राज्य की सत्ता संभाली। हालांकि समझौते से पहले उन्हें 'प्रधानमंत्री' कहा जाता था, लेकिन इसके बाद वे 'मुख्यमंत्री' बने। इस समझौते ने राज्य की स्वायत्तता और भारत संघ के साथ उसके संवैधानिक संबंधों को एक नया आधार प्रदान किया। शेख अब्दुल्ला के सत्ता में लौटने से राज्य में एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की पकड़ मजबूत हुई और राजनीतिक स्थिरता की दिशा में कदम बढ़े थे।

140. (B) केवल 2 और 3
1980 के दशक के क्षेत्रीय आंदोलनों के बारे में यह सोचना गलत है कि उनमें कभी हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ या सरकार ने केवल बातचीत का रास्ता अपनाया। वास्तव में, पंजाब, मिजोरम और नगालैंड जैसे क्षेत्रों में उग्रवादियों ने बड़े पैमाने पर सशस्त्र विद्रोह किया था। इसके जवाब में, भारत सरकार को भी कानून-व्यवस्था बनाए रखने और राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के लिए 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' जैसी कड़ी सैन्य कार्रवाइयों का सहारा लेना पड़ा था। बातचीत की प्रक्रिया सैन्य नियंत्रण के बाद ही सफल हो पाई थी।

141. (C) जब राष्ट्रीय एकता के सरोकार क्षेत्रीय ज़रुरतों पर भारी पड़ें, या क्षेत्रीय सरोकारों के कारण राष्ट्र की वृहत्तर आवश्यकताओं की अनदेखी हो।
राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बीच तनाव तब उत्पन्न होता है जब राष्ट्रीय सरोकार स्थानीय जरूरतों और विशिष्टताओं को नजरअंदाज करने लगते हैं। इसी प्रकार, यदि क्षेत्रीय माँगें इतनी उग्र हो जाएँ कि वे राष्ट्र की वृहत्तर अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा बन जाएँ, तो भी संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। एक सफल लोकतंत्र वही है जहाँ केंद्र सरकार क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करे और क्षेत्रीय समूह राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मानते हुए लोकतांत्रिक दायरे में अपनी माँगें रखें।

142. (D) पाकिस्तान में निर्वासित जीवन जीते हुए
मिजो नेशनल फ्रंट के नेता लालडेंगा ने भारत सरकार के साथ बातचीत की शुरुआत तब की थी जब वे पाकिस्तान में निर्वासित जीवन बिता रहे थे। 1971 के युद्ध के बाद विद्रोहियों के लिए विदेशी समर्थन कम हो गया था, जिससे लालडेंगा ने महसूस किया कि केवल सशस्त्र संघर्ष से लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के साथ संवाद स्थापित किया, जो लंबे समय तक चला और अंततः 1986 के ऐतिहासिक शांति समझौते के रूप में परिणत हुआ, जिससे राज्य में शांति लौटी।

143. (A) पंजाब में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा।
1985 के राजीव-लोंगोवाल समझौते का मुख्य उद्देश्य पंजाब में शांति स्थापित करना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पुनः बहाल करना था। इस समझौते में चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने, सीमा विवाद के लिए आयोग बनाने और नदियों के पानी के बँटवारे के लिए ट्रिब्यूनल गठित करने जैसी सकारात्मक शर्तें शामिल थीं। इसमें 'तत्काल राष्ट्रपति शासन' लगाने का कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि समझौता खुद राष्ट्रपति शासन को समाप्त कर चुनाव कराने की दिशा में एक बड़ा कदम था ताकि राज्य में शांति स्थापित हो सके।

144. (B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
1990 के दशक में तमिलनाडु की राजनीति में काफी बदलाव आया और डी.एम.के. व ए.आई.ए.डी.एम.के. से अलग होकर कई नए द्रविड़ दल जैसे एम.डी.एम.के. और पी.एम.के. अस्तित्व में आए। यद्यपि ये सभी दल 'द्रविड़ गौरव' और क्षेत्रीय अस्मिता को अपनी राजनीति का मुख्य आधार बनाते हैं, लेकिन उनके अलग होने के कारण अक्सर पार्टी के भीतर आंतरिक मतभेद और नेतृत्व का संघर्ष रहे हैं। अतः क्षेत्रीय गौरव की भावना इन दलों के अस्तित्व में रहने का कारण तो है, लेकिन उनके निर्माण की एकमात्र व्याख्या नहीं है।

145. (B) ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन
'आसू' (AASU) का पूरा नाम 'ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन' है। यह असम का एक शक्तिशाली और ऐतिहासिक छात्र संगठन है जिसने 1970 और 80 के दशक में राज्य की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। इस संगठन ने असम में अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन का सफल नेतृत्व किया

संदेह था कि शेख अब्दुल्ला कश्मीर के लिए पूर्ण स्वतंत्रता या अधिक स्वायत्तता की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। इस घटना ने कश्मीर की राजनीति में अविश्वास का एक लंबा दौर शुरू किया और केंद्र-राज्य संबंधों को काफी प्रभावित किया।

108. (A) P-4, Q-2, R-1, S-3
भारत में नए राज्यों के निर्माण के पीछे अलग-अलग कारण रहे हैं। तमिलनाडु में भाषायी पहचान को लेकर तीव्र आंदोलन हुए। इसके विपरीत, झारखंड और छत्तीसगढ़ का गठन मुख्य रूप से क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए किया गया। पूर्वोत्तर के नगालैंड और मिजोरम में आदिवासी पहचान और अलगाववादी भावनाओं ने राज्य निर्माण में भूमिका निभाई, जबकि पंजाब में सामाजिक-धार्मिक पहचान को भाषायी आधार के साथ जोड़कर नए राज्य की माँग की गई थी।

109. (C) पिछड़े क्षेत्रों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है।
जब किसी देश में विभिन्न इलाकों के बीच आर्थिक विकास की भारी असमानता होती है, तो इसके गंभीर राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को अक्सर यह महसूस होता है कि केंद्र या राज्य सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है और उनके संसाधनों का लाभ अन्य विकसित क्षेत्रों को मिल रहा है। इस तरह की वंचना और भेदभाव की भावना ही अक्सर क्षेत्रीय स्वायत्तता या अलग राज्य की माँगों को जन्म देती है, जो राष्ट्र की एकता के लिए चुनौती बन सकती है।

110. (D) फारूक अब्दुल्ला
1982 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के निधन के बाद, उनकी विरासत और नेशनल कॉन्फ्रेंस दल का नेतृत्व उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला ने संभाला। वे जल्द ही जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। हालांकि, फारूक अब्दुल्ला के कार्यकाल में राज्य को कई राजनीतिक संकटों और केंद्र के साथ टकराव का सामना करना पड़ा। उनके नेतृत्व के दौरान ही 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध में कश्मीर में उग्रवाद का उदय हुआ, जिसने राज्य की पूरी राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति को बदल कर रख दिया था।

111. (B) केवल 4
गोवा के इतिहास में 1967 का जनमत सर्वेक्षण एक निर्णायक मोड़ था। इस सर्वेक्षण के बारे में यह कहना गलत है कि वहां के लोगों ने महाराष्ट्र में विलय के पक्ष में मतदान किया था। वास्तव में, गोवा की जनता ने भारी बहुमत से महाराष्ट्र में विलय के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बने रहने का विकल्प चुना। इसी लोकतांत्रिक निर्णय के कारण गोवा की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रह सकी और आगे चलकर 1987 में इसे पूर्ण राज्य बनाया गया।

112. (B) उन्हें लगा कि नए सीमांकन के बावजूद उनकी राजनीतिक स्थिति डावांडोल है।
1966 में अलग पंजाब राज्य बनने के बावजूद अकाली दल को राज्य की राजनीति में अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही थी। सिखों के बीच सामाजिक विभाजन और कांग्रेस की मजबूत स्थिति के कारण अकालियों की राजनीतिक पकड़ डावांडोल बनी रही। इसी राजनीतिक असुरक्षा के चलते 1970 के दशक में अकालियों ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के जरिए केंद्र से अधिक स्वायत्तता और राज्यों के अधिकारों को पुनर्परिभाषित करने की माँग उठाई ताकि वे राज्य की सत्ता पर अपनी स्थिति मजबूत कर सकें।

113. (B) तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान
मिजो नेशनल फ्रंट ने जब भारत सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह शुरु किया, तो उसे तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) की सरकार से सक्रिय समर्थन मिला। विद्रोही नेता लालडेंगा और उनके लड़ाकों ने पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के भीतर सुरक्षित ठिकाने बनाए और वहां से भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध संचालित किया। 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के बाद विद्रोहियों के लिए ये सुरक्षित ठिकाने खत्म हो गए, जिससे अंततः उन्हें वार्ता की मेज पर आना पड़ा था।

114. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
1947 के दौरान कश्मीर में उभरी 'कश्मीरियत' की भावना वहां के लोगों की विशिष्ट क्षेत्रीय और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक थी। यह भावना इस तथ्य से पुष्ट होती है कि कश्मीर का लोकप्रिय आंदोलन, जिसका नेतृत्व नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही थी, मुख्य रूप से महाराजा के निरंकुश शासन को समाप्त करना चाहता था। वे धार्मिक आधार पर पाकिस्तान में शामिल होने के बजाय एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जहाँ कश्मीर की स्वायत्तता और उसकी मिली-जुली संस्कृति को सम्मान और संरक्षण प्राप्त हो सके।

115. (C) द्रविड़ दलों (डी.एम.के. और ए.आई.ए.डी.एम.के.)
तमिलनाडु की राजनीति में 1967 एक ऐतिहासिक वर्ष था जब कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा। तब से लेकर आज तक राज्य में मुख्य रूप से दो द्रविड़ दलों—डी.एम.के. (द्रविड़ मुनेत्र कड़गम) और ए.आई.ए.डी.एम.के. (ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक)—का ही वर्चस्व रहा है। इन दलों ने क्षेत्रीय अस्मिता, भाषायी गौरव और सामाजिक न्याय के मुद्दों को केंद्र में रखकर राजनीति की है। राष्ट्रीय दलों को राज्य में अपनी पैठ बनाने के लिए प्रायः इन दोनों में से किसी एक क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन करना पड़ता है।

116. (B) केवल 1, 2, 3, 4
संत हरचंद सिंह लोंगोवाल 1980 के दशक में अकाली दल के एक प्रमुख और नरमपंथी नेता थे। उन्होंने पंजाब में हिंसा को समाप्त करने के लिए साहस दिखाते हुए प्रधानमंत्री राजीव गाँधी के साथ 'पंजाब समझौते' पर हस्ताक्षर किए। दुर्भाग्यवश, चरमपंथियों ने इस समझौते को सिखों के साथ विश्वासघात माना और समझौते के कुछ ही समय बाद एक अज्ञात युवक ने उनकी हत्या कर दी। लोंगोवाल ने शांति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली के लिए अपना बलिदान दिया, जो पंजाब के इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा।

117. (C) कांग्रेस पार्टी
1953 में शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के बाद से 1974 तक जम्मू-कश्मीर की राजनीति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्चस्व

दृष्टिकोण संघवाद को लचीला बनाता है और विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्टताओं को स्वीकार करते हुए उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में जोड़ने का एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रशस्त करता है।

156. (B) 1973
आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पंजाब के राजनीतिक इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। इसे अकाली दल द्वारा वर्ष 1973 में पारित किया गया था। इस प्रस्ताव ने केंद्र-राज्य संबंधों की नई व्याख्या करने और राज्यों के लिए अधिक वित्तीय एवं विधायी स्वायत्तता की मांग की। यह पंजाब में क्षेत्रीय आकांक्षाओं और सिख पहचान को राजनीतिक रूप देने की दिशा में एक बड़ा कदम था।

157. (D) कृषि
आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के माध्यम से अकाली दल ने संघीय ढांचे में भारी बदलाव की वकालत की थी। इसमें मांग की गई थी कि केंद्र सरकार की शक्तियां केवल रक्षा, विदेश नीति, संचार और मुद्रा जैसे चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक ही सीमित रहनी चाहिए। कृषि और अन्य सभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक विषयों को पूर्णतः राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तांतरित करने का प्रस्ताव रखा गया था ताकि क्षेत्रीय स्वायत्तता हो।

158. (A) सिख पहचान को एक विशिष्ट 'कौम' के रूप में स्थापित करना
1973 के इस प्रस्ताव का प्राथमिक उद्देश्य सिख समुदाय की विशिष्ट पहचान को एक अलग 'कौम' या राष्ट्र के रूप में स्थापित करना था। इसके साथ ही, इसका लक्ष्य पंजाब राज्य के लिए व्यापक राजनीतिक और आर्थिक स्वायत्तता हासिल करना भी था। यह प्रस्ताव क्षेत्रीय पहचान को मजबूती देने और केंद्र के नियंत्रण को कम करने के लिए एक राजनीतिक रोडमैप के रूप में तैयार किया गया था।

159. (C) जरनैल सिंह भिंडरांवाले
हालांकि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के मूल लेखकों ने इसे संघीय ढांचे के भीतर स्वायत्तता की मांग के रूप में देखा था, लेकिन बाद में इसका स्वरुप बदल गया। जरनैल सिंह भिंडरांवाले जैसे चरमपंथी नेताओं ने इस प्रस्ताव के कुछ अंशों का उपयोग एक स्वतंत्र सिख राज्य, खालिस्तान की मांग को न्यायसंगत ठहराने के लिए किया। इसके परिणामस्वरुप पंजाब में एक दशक तक उग्रवाद और भारी हिंसा का दौर चला।

160. (A) एक अलगाववादी एजेंडे की दिशा में एक कदम के रूप में
आनंदपुर साहिब प्रस्ताव भारतीय राजनीति में एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। जहाँ समर्थक इसे राज्यों की अधिक शक्ति के रूप में देखते थे, वहीं आलोचकों और तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसकी व्याख्या एक अलगाववादी एजेंडे की दिशा में उठाए गए कदम के रूप में की। उन्हें लगा कि इस तरह की अत्यधिक स्वायत्तता की मांग अंततः देश की अखंडता को कमजोर कर सकती है और अलगाववाद को बढ़ावा देगी।

161. (D) ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू)
असम आंदोलन स्वतंत्र भारत के सबसे महत्वपूर्ण जन आंदोलनों में से एक था। इसका नेतृत्व मुख्य रूप से 'ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन' (आसू) नामक छात्र संगठन ने किया था। इस गैर-राजनीतिक संगठन ने राज्य के सामाजिक और जनसांख्यिकीय हितों की रक्षा के लिए जनता को संगठित किया। उनके साथ 'असम गण संग्राम परिषद' ने भी इस व्यापक आंदोलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

162. (B) बांग्लादेश से अवैध आप्रवासियों का प्रवाह
असम आंदोलन की उत्पत्ति के पीछे सबसे प्रमुख चिंता बांग्लादेश से होने वाला अवैध प्रवासन था। स्थानीय लोगों को डर था कि अनियंत्रित प्रवासियों के आने से राज्य की जनसांख्यिकीय संरचना बदल जाएगी। इससे संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा और मूल निवासियों की सांस्कृतिक पहचान खतरे में पड़ जाएगी। इसी कारण आंदोलनकारियों ने विदेशी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने की जोरदार मांग की थी।

163. (C) 1985
छह वर्षों तक चले लंबे संघर्ष और गहन विचार-विमर्श के बाद असम आंदोलन का अंत एक ऐतिहासिक समझौते के साथ हुआ। अगस्त 1985 में भारत सरकार और आंदोलन के नेताओं के बीच 'असम समझौते' पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते ने राज्य में शांति बहाल करने और विदेशी नागरिकों की समस्या का समाधान खोजने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया, जिससे आंदोलन का राजनीतिक समापन हुआ।

164. (D) 25 मार्च, 1971
असम समझौते के तहत विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए एक विशिष्ट समय सीमा निर्धारित की गई थी। इसके अनुसार, 25 मार्च, 1971 को कट-ऑफ तारीख माना गया। इस तिथि के बाद असम में आने वाले व्यक्तियों को अवैध प्रवासी के रूप में चिह्नित किया जाना था। इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य राज्य की जनसांख्यिकी को सुरक्षित करना और स्थानीय निवासियों के अधिकारों की रक्षा करना सुनिश्चित करना था।

165. (A) सशस्त्र अलगाववादी विद्रोह
असम आंदोलन ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए विरोध के विभिन्न लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीकों का सहारा लिया। इसमें व्यापक स्तर पर बंद, हड़तालें, सार्वजनिक प्रदर्शन और तेल पाइपलाइनों की नाकाबंदी जैसे तरीके शामिल थे। हालाँकि, आंदोलन का मूल स्वरुप एक जन आंदोलन का था, जिसमें सशस्त्र अलगाववादी विद्रोह का रास्ता नहीं अपनाया गया था। इसने आंदोलन को व्यापक जन समर्थन दिलाने में मदद की।

166. (B) अंगामी ज़ापू फिज़ो
नागालैंड में अलगाववादी आंदोलन की शुरुआत और नेतृत्व में अंगामी ज़ापू फिज़ो की भूमिका अत्यंत निर्णायक थी। उन्होंने नागा नेशनल काउंसिल (एनएनसी) के माध्यम से नागा लोगों की विशिष्ट पहचान और संप्रभुता के लिए आवाज उठाई। उनके नेतृत्व में 1951 में भारत से स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी।

की विशिष्टताओं का सम्मान करते हुए अखंड राष्ट्रीय एकता को कायम रखा जाता है।

88. (A) केवल 1 और 4
1947 के भारत-विभाजन ने पूर्वोत्तर भारत को शेष देश से भौगोलिक रूप से काफी हद तक अलग कर दिया, जिससे इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस अलगाव के कारण यहाँ के लोगों में उपेक्षा की भावना पैदा हुई और राजनीति अधिक संवेदनशील बन गई। पूर्वोत्तर की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बहुत लंबी हैं, जो इसे सामरिक रूप से संवेदनशील बनाती हैं। इसी कारण यहाँ स्वायत्तता और पहचान के आंदोलन खड़े हुए।

89. (C) सिक्किम कांग्रेस
1974 में सिक्किम में हुए पहले ऐतिहासिक लोकतांत्रिक चुनावों में 'सिक्किम कांग्रेस' को भारी जनसमर्थन और प्रचंड विजय प्राप्त हुई। इस पार्टी का नेतृत्व काजी लेंडुप दोरजी खांगसरपा कर रहे थे। यह जीत राजशाही के विरुद्ध और लोकतंत्र के पक्ष में जनता के स्पष्ट आदेश का प्रतीक थी। चुनाव जीतने के बाद, सिक्किम की नई विधानसभा ने भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने और अंततः भारत संघ में विलय करने के लिए प्रस्ताव पारित किया।

90. (A) सिख 'कौम' (समुदाय) की आकांक्षाओं पर जोर देना।
आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में सिखों के 'बोलबाला' शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसका उद्देश्य सिख 'कौम' या समुदाय की विशिष्ट पहचान और उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं को मजबूती से व्यक्त करना था। हालांकि, बाद में इस शब्द की अलग-अलग व्याख्याएँ की गईं। कुछ आलोचकों ने इसे अलगाववादी भावना के रूप में देखा, जबकि अकालियों का तर्क था कि यह केवल पंजाब में सिखों के अधिकारों और स्वायत्तता को सुनिश्चित करने की एक माँग थी।

91. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
1967 के विधानसभा चुनावों में तमिलनाडु में डी.एम.के. की ऐतिहासिक जीत का मुख्य कारण 1965 का सफल हिंदी विरोधी आंदोलन था। इस आंदोलन ने डी.एम.के. को तमिल गौरव और अस्मिता के सबसे बड़े रक्षक के रूप में जनता के बीच स्थापित कर दिया। आम लोगों को लगा कि कांग्रेस क्षेत्रीय हितों की रक्षा करने में विफल रही है, जिसके परिणामस्वरूप पहली बार किसी क्षेत्रीय दल ने राज्य में अपने दम पर सरकार बनाई थी।

92. (B) गोवा का महाराष्ट्र में विलय करना।
गोवा की मुक्ति के तुरंत बाद वहां की राजनीति में 'महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी' एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरी। इस दल का मुख्य तर्क था कि गोवा की संस्कृति और भाषा महाराष्ट्र के साथ गहरे रूप से जुड़ी हुई है, इसलिए गोवा का महाराष्ट्र में विलय कर दिया जाना चाहिए। हालांकि, इसके विरोध में 'यूनाइटेड गोअन पार्टी' जैसे दलों ने गोवा की स्वतंत्र पहचान बनाए रखने पर जोर दिया, जिसके कारण वहां जनमत सर्वेक्षण कराना पड़ा था।

93. (C) क्षेत्रीय आकांक्षाएँ लोकतांत्रिक राजनीति का एक अभिन्न अंग हैं।
क्षेत्रीय आकांक्षाओं के संबंध में भारतीय राजनीति का एक बुनियादी सबक यह है कि ये लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग हैं और इन्हें हमेशा राष्ट्र-विरोधी नहीं माना जाना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन माँगों को दबाने के बजाय बातचीत और संवैधानिक सुलह के माध्यम से हल करना सबसे प्रभावी तरीका है। भारत ने यह सीखा है कि सत्ता में साझेदारी और क्षेत्रीय पहचान का सम्मान करने से राष्ट्र अधिक मजबूत और एकजुट होता है।

94. (D) राजीव गाँधी और लालडेंगा के बीच हुए समझौते के बाद मिजोरम एक शांतिपूर्ण राज्य बन गया।
1986 में प्रधानमंत्री राजीव गाँधी और लालडेंगा के बीच हुआ मिजोरम शांति समझौता भारतीय राजनीति की एक बड़ी सफलता मानी जाती है। इस समझौते के बाद दो दशकों से चला आ रहा हिंसक अलगाववादी संघर्ष पूरी तरह समाप्त हो गया। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए और मिजोरम भारत संघ का एक शांतिपूर्ण और प्रगतिशील राज्य बन गया। यह उदाहरण सिद्ध करता है कि लोकतांत्रिक संवाद के जरिए जटिल से जटिल क्षेत्रीय समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है।

95. (A) यह विभिन्न जनजातियों को अपने पारंपरिक नियमों को संरक्षित रखने की स्वायत्तता देती है।
भारतीय संविधान की छठी अनुसूची पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अनुसूची विभिन्न जनजातियों को अपने पारंपरिक नियमों, भूमि और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करती है। इसके तहत 'स्वायत्त जिला परिषदों' का गठन किया जाता है जिन्हें स्थानीय मामलों में कानून बनाने के विशेष अधिकार होते हैं। यह व्यवस्था जनजातीय समुदायों के हितों की रक्षा करते हुए उन्हें मुख्यधारा से जोड़ती है।

96. (A) P-3, Q-1, R-2, S-4
पूर्वोत्तर भारत के राज्यों का गठन अलग-अलग समय पर हुआ है। नगालैंड 1963 में भारत का एक पृथक राज्य बना। इसके बाद 1972 में मणिपुर और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। मिजोरम में लंबे संघर्ष के बाद 1987 में शांति समझौता हुआ और उसे पूर्ण राज्य बनाया गया। राज्यों के गठन की यह प्रक्रिया क्षेत्रीय अस्मिता और जनजातीय आकांक्षाओं को लोकतांत्रिक ढांचे में समायोजित करने के निरंतर प्रयासों का परिणाम रही है।

97. (B) पाकिस्तान
1989 में जब जम्मू-कश्मीर में उग्रवादी आंदोलन ने जोर पकड़ा, तो उसे पड़ोसी देश पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर नैतिक, आर्थिक और सैन्य समर्थन प्राप्त हुआ। पाकिस्तान ने इन विद्रोही समूहों को प्रशिक्षण और हथियार उपलब्ध कराए, जिससे घाटी

अध्याय 15

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

1. 1984 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने राजीव गाँधी की अगुवाई में कितनी सीटें जीती थीं?
(A) 197
(B) 415
(C) 282
(D) 303

2. निम्नलिखित में से कौन सा 1980 के दशक के आखिर के सालों में हुआ एक बड़ा बदलाव नहीं था?
(A) भारत-चीन युद्ध
(B) 1989 के चुनावों में कांग्रेस की हार
(C) राष्ट्रीय राजनीति में 'मंडल मुद्दे' का उदय
(D) ढाँचागत समायोजन कार्यक्रम अथवा नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत

3. निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिये:
सूची I: (प्रधानमंत्री)
P. वी.पी. सिंह
Q. पी. वी. नरसिम्हा राव
R. अटल बिहारी वाजपेयी
S. एच.डी. देवगौड़ा
सूची II: (सरकार/गठबंधन)
1. कांग्रेस, एआईडीएमके तथा कुछ अन्य दल
2. भाजपा-नीत राजग गठबंधन
3. राष्ट्रीय मोर्चा
4. संयुक्त मोर्चा की सरकार (कांग्रेस के समर्थन पर)
(A) P-3, Q-1, R-2, S-4
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

4. 'कांग्रेस प्रणाली' (Congress System) शब्द का प्रयोग राजनीति विज्ञानी किस परिघटना के सन्दर्भ में करते हैं?
(A) कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनावों में अपनाई गई दीर्घकालिक और विविध राजनीतिक रणनीति
(B) कांग्रेस पार्टी का समय-समय पर परिवर्तित होता आंतरिक संगठनात्मक और वैचारिक ढाँचा
(C) कांग्रेस की विभिन्न सरकारों द्वारा अपनाई गई कूटनीतिक और अंतरराष्ट्रीय विदेश नीति
(D) भारतीय दलीय प्रणाली में कांग्रेस पार्टी का निरंतर और विशिष्ट प्रभुत्वशाली स्थान

5. 1990 में किस सरकार ने मंडल आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने का निर्णय लिया?
(A) कांग्रेस सरकार
(B) राजग सरकार
(C) राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार
(D) संयुक्त मोर्चा की सरकार

6. मंडल आयोग की सिफ़ारिशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसने केंद्र सरकार की नौकरियों में 'अन्य पिछड़ा वर्ग' को आरक्षण देने का प्रावधान किया।
2. इसके लागू होने से देश के विभिन्न भागों में हिंसक मंडल-समर्थक प्रदर्शन हुए।
3. अन्य पिछड़ा वर्ग को मिले आरक्षण के समर्थक और विरोधियों के बीच चले विवाद को 'मंडल मुद्दा' कहा जाता है।
4. इसने 1989 के बाद की राजनीति में कोई अहम भूमिका नहीं निभाई।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2 और 4
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) सभी 1, 2, 3 और 4

7. 'नए आर्थिक सुधार' जिनकी शुरुआत राजीव गाँधी के समय हुई, उन्हें किस वर्ष में बड़े पैमाने पर प्रकट किया गया?
(A) 1984
(B) 1989
(C) 1996
(D) 1991

8. मई 1991 में राजीव गाँधी की हत्या के लिए किसे जिम्मेदार माना गया?
(A) लिट्टे से जुड़े श्रीलंकाई तमिलों को
(B) उल्फा से जुड़े चरमपंथियों को
(C) खालिस्तानी अलगाववादियों को
(D) नक्सलवादी समूहों को

9. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक अभिकथन (A) और दूसरा तर्क (R) है। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए:
अभिकथन (A): 1989 के चुनावों के बाद भारत में गठबंधन की राजनीति के एक लंबे दौर की शुरुआत हुई।

तर्क (R): 1989 के बाद से लोकसभा के चुनावों में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण केंद्र में गठबंधन सरकारें बनने लगीं।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

10. राजीव गाँधी की हत्या के पश्चात् 1991 के चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी ने किसे प्रधानमंत्री चुना?
(A) पी. वी. नरसिम्हा राव
(B) सोनिया गाँधी
(C) मनमोहन सिंह
(D) सीताराम केसरी

11. 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को किन दो परस्पर विरुद्ध राजनीतिक समूहों ने बाहर से समर्थन दिया था?
(A) कांग्रेस और वाम मोर्चा
(B) भाजपा और कांग्रेस
(C) क्षेत्रीय दल और वाम मोर्चा
(D) भाजपा और वाम मोर्चा

12. निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. इंदिरा गाँधी की हत्या
2. राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का गठन
3. मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना
4. राजीव गाँधी की हत्या
5. अयोध्या में विवादित ढाँचे का विध्वंस
(A) 1, 2, 3, 4, 5
(B) 1, 3, 2, 5, 4
(C) 2, 1, 4, 3, 5
(D) 3, 1, 2, 5, 4

13. नब्बे के दशक में कांग्रेस की अग्रणी हैसियत को चुनौती मिलने का क्या परिणाम हुआ?
(A) कांग्रेस पार्टी पूरी तरह समाप्त हो गई।
(B) भाजपा एकमात्र प्रमुख पार्टी बन गई।
(C) बहुदलीय शासन-प्रणाली का युग शुरु हुआ।
(D) देश में दो-दलीय व्यवस्था स्थापित हो गई।

14. 1996 में बनी संयुक्त मोर्चे की सरकार के बारे में कौन सा कथन असत्य है?
(A) इसमें जनता दल और कई क्षेत्रीय पार्टियाँ शामिल थीं।
(B) यह सरकार 1989 के राष्ट्रीय मोर्चे के ही समान थी।
(C) इस सरकार को कांग्रेस का समर्थन हासिल था।
(D) इस सरकार को भाजपा ने समर्थन दिया था।

15. निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिये:
सूची I: (घटना)
P. मंडल आयोग की नियुक्ति
Q. शाहबानो वाद
R. बामसेफ का गठन
S. राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का गठन
सूची II: (वर्ष)
1. 1985
2. 1978
3. 1989
4. 1978
(A) P-2, Q-1, R-4, S-3
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-3, R-1, S-2
(D) P-2, Q-4, R-3, S-1

16. 1996 के चुनावों में कौन सी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी?
(A) कांग्रेस
(B) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)
(C) जनता दल
(D) वाम मोर्चा

17. 1998 से 2004 तक केंद्र में सत्ता में रहे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के प्रधानमंत्री कौन थे?
(A) इंद्रकुमार गुजराल
(B) अटल बिहारी वाजपेयी
(C) एच.डी. देवगौड़ा
(D) पी. वी. नरसिम्हा राव

18. 'अन्य पिछड़ा वर्ग' (OBC) शब्द से क्या संकेत मिलता है?
(A) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों की एससी/एसटी से इतर एक प्रशासनिक कोटि
(B) मुख्य रूप से आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए ग्रामीण और शहरी समुदाय
(C) भाषाई और धार्मिक आधार पर पहचाने गए अल्पसंख्यक सामाजिक समूह
(D) शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में निवास करने वाले श्रमिक और निर्धन वर्ग

19. गैर-कांग्रेसी दलों के राजनीतिक अभ्युदय की पहली अभिव्यक्ति किस सरकार के रूप में हुई थी?
(A) 1989 की राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार
(B) 1996 की संयुक्त मोर्चा की सरकार
(C) 1977 की जनता पार्टी की सरकार
(D) 1998 की राजग सरकार

20. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक अभिकथन (A) और दूसरा तर्क (R) है। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए:

अभिकथन (A): 1990 के दशक में दलित तथा पिछड़े वर्गों की नुमाइंदगी करने वाले अनेक दल और आंदोलन उभरे।
तर्क (R): इन दलों ने सत्ता में 'अन्य पिछड़ा वर्ग' की हिस्सेदारी का सवाल उठाया और यह तर्क दिया कि भारतीय समाज में उनके बड़े हिस्से को देखते हुए शासन में उनका समुचित प्रतिनिधित्व होना एक लोकतांत्रिक कदम है।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

21. 1978 में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 'दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग' किस नाम से अधिक प्रसिद्ध है?
(A) सरकारिया आयोग
(B) शाह आयोग
(C) मंडल कमीशन
(D) कोठारी आयोग

22. निम्नलिखित में से कौन मंडल आयोग के अध्यक्ष थे?
(A) कर्पूरी ठाकुर
(B) बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल
(C) कांशीराम
(D) मोरारजी देसाई

23. मंडल आयोग की सिफारिशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. आयोग का गठन भारतीय समाज में शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए किया गया था।
2. आयोग ने अपनी सिफारिशें 1980 में पेश कीं।
3. आयोग ने पिछड़ा वर्ग को पिछड़ी जाति के अर्थ में स्वीकार करने का मशविरा दिया।
4. आयोग ने शिक्षा संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में इन समूहों के लिए 27 प्रतिशत सीट आरक्षित करने की सिफारिश की।
5. आयोग ने भूमि-सुधार का भी सुझाव दिया।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 4
(B) केवल 3 और 5
(C) केवल 1, 3, 4 और 5
(D) सभी 1, 2, 3, 4 और 5

24. मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के सरकार के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, यह प्रकरण किस नाम से प्रसिद्ध हुआ?
(A) इंद्रा साहनी केस
(B) केशवानंद भारती केस
(C) गोलकनाथ केस
(D) शाहबानो केस

25. 1978 में गठित 'बामसेफ' (BAMCEF) का पूरा नाम क्या है?
(A) बहुजन एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्पलाइज़ फेडरेशन
(B) बैकवर्ड एंड मेजॉरिटी कम्युनिटीज एम्पलाइज़ फेडरेशन
(C) बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्पलाइज़ फेडरेशन
(D) भारतीय एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉई फेडरेशन

26. बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के संस्थापक कौन थे?
(A) कांशीराम
(B) मायावती
(C) बी.पी. मंडल
(D) रामविलास पासवान

27. निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सूची-। को सूची-।। से सुमेलित कीजिये:
सूची ।: (अवधारणा/संगठन)
P. कांग्रेस प्रणाली का अंत
Q. मंडल मुद्दा
R. गठबंधन सरकार
S. दलित राजनीति का उभार

सूची ।।: (संबंधित वर्ष/अवधि)
1. 1989 के बाद
2. 1990
3. 1989
4. 1980 का दशक

(A) P-1, Q-2, R-4, S-3
(B) P-3, Q-2, R-1, S-4
(C) P-2, Q-3, R-1, S-4
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

28. कांशीराम के अनुसार 'बहुजन' में कौन-कौन से समूह शामिल थे?
(A) इसमें केवल अनुसूचित जाति के लोग सम्मिलित थे
(B) अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और धार्मिक अल्पसंख्यक समूह
(C) केवल अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति के सदस्य
(D) इसमें केवल सवर्ण जातियों के निर्धन लोग शामिल थे

29. किस राज्य में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी और उसने एक से ज़्यादा बार सरकार बनाई?
(A) पंजाब
(B) हरियाणा
(C) उत्तर प्रदेश
(D) बिहार

30. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(A) 1980 के दशक में भारत में केवल एक-दलीय व्यवस्था मौजूद थी।
(B) 1989 के बाद से केंद्र में हमेशा एक ही दल की स्थिर सरकार रही है।

(A) 3, 1, 2, 4
(B) 1, 3, 2, 4
(C) 3, 2, 1, 4
(D) 2, 1, 3, 4

95. 1980 के दशक के बाद उभरी "नयी सहमति" की कौन सी एक विशेषता नहीं है?
(A) विचारधारा पर आधारित कठोर राजनीतिक गठजोड़।
(B) आर्थिक उदारीकरण का समर्थन।
(C) OBC आरक्षण का समर्थन।
(D) गठबंधन सरकारों में क्षेत्रीय दलों की भूमिका की स्वीकृति।

96. निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिये:
सूची I: (सरकार)
P. राष्ट्रीय मोर्चा (1989)
Q. संप्रग-I (2004)
R. राजग (1998)
S. संयुक्त मोर्चा (1996)
सूची II: (समर्थन/नेतृत्व)
1. अटल बिहारी वाजपेयी
2. एच.डी. देवगौड़ा
3. वी.पी. सिंह
4. मनमोहन सिंह
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-3, R-2, S-1
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

97. 2014 के बाद की भारतीय राजनीति के संदर्भ में "गठबंधन की राजनीति की प्रासंगिकता" का क्या अर्थ है, जबकि भाजपा को पूर्ण बहुमत प्राप्त है?
(A) भाजपा के पास संसद में आवश्यक बहुमत का अभाव है
(B) भाजपा ने राजग सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाने के विकल्प को प्राथमिकता दी
(C) सभी विपक्षी राजनीतिक दल अब एक साझा मंच पर संगठित हो गए हैं
(D) भारत में गठबंधन की राजनीति का दौर अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है

98. 1980 के दशक के बाद भारतीय समाज में आए बदलावों ने किस प्रकार की राजनीति को जन्म दिया?
(A) गठबंधन की सरकारों के युग की राजनीति
(B) केवल एक-दलीय प्रभुत्व की राजनीति
(C) केवल दो-दलीय प्रणाली की राजनीति
(D) सैन्य शासन की राजनीति

99. "गरीबी, विस्थापन, न्यूनतम मज़दूरी, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा" जैसे मसले 1990 के बाद किसके ज़रिए राजनीतिक एजेंडे के रूप में सामने आए?
(A) केवल राजनीतिक दलों के माध्यम से
(B) केवल चुनावों के माध्यम से
(C) जन आंदोलनों के ज़रिए
(D) अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के दबाव में

100. 1991 के आम चुनावों में कांग्रेस के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने का तात्कालिक कारण क्या था?
(A) मंडल मुद्दे का राजनीतिक समर्थन
(B) आर्थिक सुधारों का व्यापक वादा
(C) भाजपा का देशव्यापी कमजोर प्रदर्शन
(D) राजीव गाँधी की हत्या के बाद उपजी सहानुभूति की लहर

101. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक अभिकथन (A) और दूसरा तर्क (R) है। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए:
अभिकथन (A): 1989 के चुनावों में कांग्रेस की हार के साथ भारत की दलीय व्यवस्था से उसका दबदबा खत्म हो गया।
तर्क (R): इसका मतलब यह था कि कांग्रेस की जगह कोई दूसरी पार्टी, जैसे कि भाजपा, तत्काल प्रमुख हो गई।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

102. 1977-79 की जनता पार्टी सरकार के किन दो घटक दलों का ग्रामीण इलाकों के अन्य पिछड़े वर्गों में ताकतवर जनाधार था?
(A) जनसंघ और कांग्रेस (ओ)
(B) भारतीय क्रांतिदल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी
(C) साम्यवादी दल और स्वतंत्र पार्टी
(D) अकाली दल और डी.एम.के.

103. 'मंडलीकरण' ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कैसे बदला?
(A) इसने मुख्य रूप से समाज के उच्च वर्ण और सवर्ण जातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भारी वृद्धि की
(B) इसने भारतीय चुनावी राजनीति में जाति के महत्त्व और भूमिका को पूरी तरह से समाप्त कर दिया
(C) इसने केवल समाज की महिलाओं के राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधित्व के स्तर को ऊंचा उठाया
(D) पिछड़ी जातियों की राजनीतिक सक्रियता और सत्ता में उनकी हिस्सेदारी के विस्तार को बढ़ावा मिला

104. 1990 के दशक में उभरी बहुदलीय व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. संसद में हमेशा कई दलों के सांसद रहे हैं, लेकिन 1989 के बाद किसी एक दल को बहुमत मिलना बंद हो गया।
2. इस बदलाव के साथ केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर शुरु हुआ।

(D) 2004

42. 2004 के लोकसभा चुनावों के बाद केंद्र में किस गठबंधन की सरकार बनी?
(A) संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग)
(B) राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग)
(C) राष्ट्रीय मोर्चा
(D) संयुक्त मोर्चा

43. 2004 में बनी संप्रग सरकार का नेतृत्व किस पार्टी ने किया और उसे किस समूह ने बाहर से समर्थन दिया?
(A) नेतृत्व भाजपा ने, समर्थन कांग्रेस ने
(B) नेतृत्व जनता दल ने, समर्थन भाजपा ने
(C) नेतृत्व वाम मोर्चे ने, समर्थन कांग्रेस ने
(D) नेतृत्व कांग्रेस ने, समर्थन वाम मोर्चे ने

44. निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. संप्रग सरकार का गठन
2. राजग सरकार का पहली बार गठन (वाजपेयी)
3. संयुक्त मोर्चा सरकार का गठन (देवगौड़ा)
4. राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का गठन (वी.पी. सिंह)
(A) 4, 3, 2, 1
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 4, 2, 3, 1
(D) 3, 4, 1, 2

45. 1991 के बाद कांग्रेस पार्टी की सीटों की संख्या में पहली बार किस चुनाव में बढ़त देखी गई?
(A) 1996
(B) 1998
(C) 2004
(D) 1999

46. 2014 के लोकसभा चुनावों में किस पार्टी ने 30 साल बाद एकल पार्टी बहुमत हासिल किया?
(A) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
(B) बहुजन समाज पार्टी
(C) समाजवादी पार्टी
(D) भारतीय जनता पार्टी

47. "बढ़ती सहमति" के संदर्भ में, जो 1980 के दशक के बाद उभरी, कौन सा बिंदु उसमें शामिल नहीं है?
(A) देश के शासन में केवल राष्ट्रीय दलों की भूमिका की स्वीकृति
(B) नयी आर्थिक नीति पर सहमति
(C) पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति
(D) विचारधारा की जगह कार्यसिद्धि पर ज़ोर

48. "विचारधारा की जगह कार्यसिद्धि पर ज़ोर" का सबसे उपयुक्त उदाहरण क्या है?
(A) विभिन्न दलों द्वारा चुनाव घोषणापत्रों में समान लोक-लुभावन वादे करना
(B) भाजपा की हिन्दुत्व विचारधारा से असहमत दलों का भी उसके साथ सत्ता में शामिल होना
(C) वामपंथी दलों का केवल अपनी विचारधारा वाले समूहों के साथ राजनीतिक गठबंधन करना
(D) कांग्रेस का सदैव अपनी मूल और पारंपरिक विचारधारा पर पूरी तरह से कायम रहना

49. निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिये:
सूची I: (दल/गठबंधन)
P. राष्ट्रीय मोर्चा
Q. संयुक्त मोर्चा
R. राजग
S. संप्रग
सूची II: (प्रमुख घटक/समर्थक)
1. भाजपा
2. कांग्रेस
3. जनता दल
4. कांग्रेस का समर्थन
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-3, R-2, S-1
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

50. 17वीं लोकसभा (2019) में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती थीं?
(A) 303
(B) 282
(C) 206
(D) 52

51. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक अभिकथन (A) और दूसरा तर्क (R) है। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए:
अभिकथन (A): 1989 के चुनावों में कांग्रेस की हार के साथ भारत की दलीय व्यवस्था से उसका दबदबा खत्म हो गया।
तर्क (R): इसका मतलब यह था कि कांग्रेस की जगह कोई दूसरी पार्टी, जैसे कि भाजपा, तत्काल प्रमुख हो गई।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

52. 1989 के चुनाव के बाद बनी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे?

(A) लालू प्रसाद यादव
(B) नीतीश कुमार
(C) कर्पूरी ठाकुर
(D) बी.पी. मंडल

74. 'इंदिरा साहनी केस' (1992) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का क्या परिणाम हुआ?
(A) इसने सरकार के OBC आरक्षण के निर्णय को सही ठहराया।
(B) इसने OBC आरक्षण को पूरी तरह से खारिज कर दिया।
(C) इसने केवल पदोन्नति में आरक्षण को मंजूरी दी।
(D) इसने आरक्षण की सीमा 75% तक बढ़ा दी।

75. 1990 के दशक की गठबंधन राजनीति के बारे में कौन सा कथन सबसे सटीक है?
(A) इस दौर के सभी प्रमुख गठबंधन पूर्णतः स्थिर रहे और उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया
(B) राजनीतिक गठबंधन केवल पूरी तरह समान विचारधारा वाले दलों के मध्य ही संपन्न हुए
(C) इस अवधि में केवल राष्ट्रीय राजनीतिक दल ही गठबंधन सरकारों के आधिकारिक हिस्से थे
(D) राजनीतिक समीकरण अत्यंत अस्थिर थे, जिसमें दल अक्सर अपनी भूमिकाएं बदलते रहते थे

76. निम्नलिखित में से गलत जोड़ी की पहचान करें:
(A) 1999 की सरकार - राजग (पूर्ण कार्यकाल)
(B) 1989 की सरकार - राष्ट्रीय मोर्चा (कांग्रेस का समर्थन)
(C) 1996 की सरकार - संयुक्त मोर्चा (कांग्रेस का समर्थन)
(D) 2004 की सरकार - संप्रग (वाम मोर्चा का समर्थन)

77. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक अभिकथन (A) और दूसरा तर्क (R) है। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए:
अभिकथन (A): 1990 के दशक से भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली का उदय हुआ।
तर्क (R): इसका कारण यह था कि कई पार्टियाँ इस तरह उभरीं कि किसी एक-दो पार्टी को ही अधिकांश वोट या सीटें नहीं मिल पाती थीं।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

78. 1999 में बनी राजग सरकार के बारे में कौन सा कथन सत्य है?
(A) यह एक अल्पमत सरकार थी।
(B) यह सरकार कुछ ही महीनों में गिर गई।
(C) इस सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे।
(D) इस सरकार ने अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा किया।

79. 'बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्पलाइज़ फेडरेशन' (बामसेफ) का गठन किस वर्ष हुआ?
(A) 1978
(B) 1975
(C) 1980
(D) 1984

80. गठबंधन सरकारों के युग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसकी शुरुआत 1989 के चुनावों से मानी जाती है।
2. इस दौर में क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो गई।
3. 2014 में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने के साथ यह प्रवृत्ति पूरी तरह समाप्त हो गई।
4. इस दौर में सरकारें अक्सर अल्पमत की होती थीं या दूसरे दलों के समर्थन पर निर्भर रहती थीं।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 4
(B) केवल 1 और 3
(C) केवल 2 और 4
(D) सभी 1, 2, 3 और 4

81. 1991 के चुनाव के बाद पी. वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में बनी कांग्रेस सरकार की मुख्य विशेषता क्या थी?
(A) यह कांग्रेस पार्टी की लोकसभा में स्पष्ट और पूर्ण बहुमत के साथ बनी एक शक्तिशाली सरकार थी
(B) यह एआईडीएमके तथा अन्य दलों के समर्थन से संचालित होने वाली एक अल्पमत की सरकार थी
(C) यह एक विशाल गठबंधन सरकार थी जिसमें देश के कई क्षेत्रीय दल आधिकारिक रूप से शामिल थे
(D) इस सरकार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा नीतियों के आधार पर बाहर से पूर्ण समर्थन प्राप्त था

82. मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी?
(A) 27%
(B) 22.5%
(C) 49.5%
(D) 10%

83. निम्नलिखित में से कौन 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा के गठन में शामिल नहीं था?
(A) जनता दल
(B) क्षेत्रीय दल
(C) कांग्रेस (आई)
(D) वाम मोर्चा (बाहरी समर्थन)

84. निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिये:
सूची I: (परिघटना)
P. कांग्रेस प्रणाली
Q. एक-दलीय प्रभुत्व का अंत

का केंद्र बनाया।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 4
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 4
(D) सभी 1, 2, 3 और 4

64. विनायक दामोदर सावरकर की 'हिन्दुत्व' की परिभाषा के अनुसार, एक भारतीय होने के लिए क्या आवश्यक है?
(A) व्यक्ति का केवल भारत के भौगोलिक भूभाग में जन्म लेना
(B) भारतभूमि को 'पितृभूमि' और 'पुण्यभूमि' दोनों के रूप में स्वीकार करना
(C) व्यक्ति द्वारा हिंदी भाषा को अपनी मुख्य संवाद भाषा के रूप में बोलना
(D) व्यक्ति का किसी भी प्रचलित भारतीय धार्मिक परंपरा का अनुयायी होना

65. 1989 से 2014 तक की अवधि में भारतीय राजनीति की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी?
(A) एक-दलीय प्रभुत्व
(B) केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर
(C) दो-दलीय प्रणाली
(D) राष्ट्रपति शासन का बार-बार लगना

66. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक अभिकथन (A) और दूसरा तर्क (R) है। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए:
अभिकथन (A): 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में मूलगामी परिवर्तन हुए, जिसे नए आर्थिक सुधारों के नाम से जाना गया।
तर्क (R): इन सुधारों का किसी भी आंदोलन या संगठन ने विरोध नहीं किया और सभी ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

67. 2004 और 2009 के लोकसभा चुनावों के बाद बनी संप्रग सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे?
(A) सोनिया गाँधी
(B) राहुल गाँधी
(C) डॉ. मनमोहन सिंह
(D) पी. वी. नरसिम्हा राव

68. 2014 के लोकसभा चुनावों का भारतीय राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक क्षण क्यों माना जाता है?
(A) क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार एक महिला प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुईं
(B) क्योंकि भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार एक सफल गठबंधन सरकार बनी थी
(C) क्योंकि इस विशिष्ट चुनाव में देश का कुल मतदान प्रतिशत सबसे न्यूनतम स्तर पर रहा
(D) तीन दशकों के लंबे अंतराल के पश्चात् किसी एकल दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ

69. निम्नलिखित में से कौन सा एक उन चार प्रमुख सहमतियों में से नहीं है जो समकालीन भारतीय राजनीति में उभरी हैं?
(A) नई आर्थिक नीतियों पर आम सहमति।
(B) पिछड़ी जातियों के राजनीतिक दावों की स्वीकृति।
(C) देश में राष्ट्रपति प्रणाली लागू करने पर सहमति।
(D) प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति।

70. निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. मंडल आयोग का गठन
2. बामसेफ का गठन
3. भाजपा का गठन
4. जनता पार्टी सरकार का पतन
(A) 2, 1, 4, 3
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 4, 1, 3
(D) 4, 1, 3, 2

71. 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार क्यों गिरी?
(A) कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण
(B) सरकार के भीतर ही विभाजन हो गया
(C) प्रधानमंत्री ने स्वयं इस्तीफा दे दिया
(D) भाजपा और वाम मोर्चा द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण

72. निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिये:
सूची I: (वर्ष)
P. 1984
Q. 1989
R. 2014
S. 2004
सूची II: (चुनावी परिणाम)
1. संप्रग की सरकार बनी
2. भाजपा को पूर्ण बहुमत
3. कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत (415 सीटें)
4. कांग्रेस की हार, गठबंधन युग की शुरुआत
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-4, R-2, S-1
(C) P-2, Q-3, R-1, S-4
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

73. बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को उत्तर भारत में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के प्रबल समर्थक के रूप में जाना जाता है?

(C) दलित राजनीति और अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति के बीच कभी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रही।
(D) बसपा को अपने शुरुआती दौर में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं का समर्थन हासिल था।

31. 1980 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का गठन किस पुराने दल के समर्थकों ने किया था?
(A) पूर्ववर्ती जनसंघ
(B) भारतीय साम्यवादी दल
(C) संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी
(D) स्वतंत्र पार्टी

32. 'हिन्दुत्व' को भारतीय राष्ट्रीयता के आधार के रूप में किसने लोकप्रिय किया था?
(A) महात्मा गाँधी
(B) विनायक दामोदर सावरकर
(C) जवाहरलाल नेहरु
(D) अटल बिहारी वाजपेयी

33. शाहबानो वाद (1985) किस विषय से संबंधित था?
(A) मौलिक संपत्ति के अधिकारों से संबंधित कानूनी मामला
(B) मुस्लिम तलाकशुदा महिला के गुजारा भत्ता पाने का अधिकार
(C) धार्मिक स्थलों में प्रवेश संबंधी नागरिक अधिकारों का मुद्दा
(D) केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने की नीति

34. शाहबानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए कांग्रेस सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया?
(A) मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986
(B) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, वर्ष 1986
(C) धार्मिक स्वतंत्रता और उपासना का अधिकार अधिनियम, 1986
(D) महिला आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1986

35. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक अभिकथन (A) और दूसरा तर्क (R) है। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए:
अभिकथन (A): 1986 का शाहबानो वाद और अयोध्या विवाद भाजपा की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गए।
तर्क (R): भाजपा ने कांग्रेस सरकार द्वारा शाहबानो मामले में उठाए गए कदम की अल्पसंख्यक तुष्टिकरण कहकर आलोचना की और अयोध्या मुद्दे को राष्ट्रीय गौरव से जोड़ा।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

36. किस वर्ष फैजाबाद जिला न्यायालय ने अयोध्या स्थित विवादित ढाँचे का ताला खोलने का निर्णय दिया?
(A) 1984
(B) 1985
(C) 1992
(D) 1986

37. अयोध्या स्थित विवादित ढाँचे को कब गिराया गया?
(A) 9 नवम्बर 2019
(B) 15 अगस्त 1990
(C) 6 दिसम्बर 1992
(D) 26 जनवरी 1989

38. अयोध्या विवाद पर उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने अपना अंतिम निर्णय कब सुनाया?
(A) 6 दिसम्बर 1992
(B) 9 नवम्बर 2019
(C) 25 अक्टूबर 1995
(D) 1 मई 1996

39. अयोध्या विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय के 2019 के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को विवादित स्थल आवंटित किया।
2. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए भूमि आवंटित करने का आदेश दिया गया।
3. यह निर्णय 5-0 के बहुमत से आया।
4. इस निर्णय को समाज में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3 और 4
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) सभी 1, 2, 3 और 4

40. 1989 के बाद की अवधि को अक्सर कांग्रेस के पतन और किसके अभ्युदय की अवधि कहा जाता है?
(A) भाजपा
(B) जनता दल
(C) बसपा
(D) वाम मोर्चा

41. निम्नलिखित में से किस वर्ष के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पहली बार कांग्रेस से अधिक सीटें जीतीं?
(A) 1989
(B) 1991
(C) 1996

R. मंडल राजनीति
S. हिंदुत्व की राजनीति
सूची II: (मुख्य प्रस्तावक/प्रतीक)
1. वी.पी. सिंह
2. एल.के. आडवाणी
3. जवाहरलाल नेहरू/इंदिरा गाँधी
4. 1989 का चुनाव
(A) P-4, Q-1, R-2, S-3
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-1, Q-2, R-3, S-4
(D) P-2, Q-3, R-4, S-1

85. 'राजनीतिक विकल्पों के चयन के लिहाज़ से नीतिगत मामलों पर एक सर्व-सहमति' का क्या अर्थ है?
(A) सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल आधिकारिक रूप से एक ही पार्टी के भीतर पूरी तरह विलीन हो गए हैं
(B) लोकतांत्रिक चुनाव अब पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गए हैं और प्रतिस्पर्धा समाप्त हो चुकी है
(C) प्रमुख नीतिगत मुद्दों पर अधिकांश दल समान विचार रखते हैं, जिससे व्यापक बदलाव की गुंजाइश कम है
(D) देश के राजनीतिक दलों के मध्य अब किसी भी प्रकार की कोई चुनावी या वैचारिक प्रतिस्पर्धा नहीं है

86. राम जन्मभूमि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था?
(A) अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण करना।
(B) अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करना।
(C) अयोध्या को एक स्वतंत्र राज्य बनाना।
(D) अयोध्या में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करना।

87. भारतीय राजनीति में 1989 के बाद आए बदलावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. गठबंधन की राजनीति का उदय हुआ।
2. 'मंडलीकरण' ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के स्वभाव को बदला।
3. राम जन्मभूमि आंदोलन ने धर्मनिरपेक्षता पर बहस को प्रभावित किया।
4. नीतिगत मामलों पर एक सर्व-सहमति बनी।
5. कांग्रेस प्रणाली पहले से अधिक मजबूत हुई।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2, 3 और 4
(B) केवल 2, 3, 4 और 5
(C) केवल 1, 3 और 5
(D) सभी 1, 2, 3, 4 और 5

88. 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी भाजपा की अल्पमत सरकार कितने समय तक चली?
(A) लगभग 13 दिन
(B) लगभग 13 महीने
(C) 2 वर्ष
(D) पूरे 5 वर्ष

89. 1989 और 1991 के चुनावों में उत्तर प्रदेश में किस पार्टी को उल्लेखनीय सफलता मिली, जो मुख्यतया दलित मतदाताओं पर आधारित थी?
(A) समाजवादी पार्टी
(B) जनता दल
(C) बहुजन समाज पार्टी
(D) भारतीय जनता पार्टी

90. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक अभिकथन (A) और दूसरा तर्क (R) है। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए:
अभिकथन (A): 1996 में बनी संयुक्त मोर्चा की सरकार को कांग्रेस ने समर्थन दिया था।
तर्क (R): कांग्रेस और वाममोर्चा दोनों इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

91. किस मुद्दे पर वाम दलों द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद 2008 में संप्रग सरकार को विश्वास मत का सामना करना पड़ा?
(A) मंडल आयोग की रिपोर्ट
(B) अयोध्या विवाद
(C) नई आर्थिक नीति
(D) भारत-अमेरिका परमाणु समझौता

92. 2019 के लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कौन सी थी?
(A) तृणमूल कांग्रेस (TMC)
(B) द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK)
(C) शिवसेना
(D) बहुजन समाज पार्टी (BSP)

93. निम्नलिखित में से कौन सा दल 1989 की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार और 1996 की संयुक्त मोर्चा सरकार, दोनों में एक प्रमुख घटक था?
(A) भारतीय जनता पार्टी
(B) कांग्रेस
(C) जनता दल
(D) बहुजन समाज पार्टी

94. निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. भारत-अमेरिका परमाणु समझौता
2. 16वें लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को स्पष्ट बहुमत
3. संप्रग-I सरकार का गठन
4. 17वें लोकसभा चुनाव में भाजपा की पुनः विजय

(A) राजीव गाँधी
(B) चंद्रशेखर
(C) लालकृष्ण आडवाणी
(D) वी.पी. सिंह

53. 'मंडल मुद्दा' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने से संबंधित था।
2. इस मुद्दे ने 1989 के बाद की राजनीति को आकार देने में अहम भूमिका निभाई।
3. आरक्षण के समर्थकों और विरोधियों के बीच चले विवाद को 'मंडल मुद्दा' कहा जाता है।
4. सर्वोच्च न्यायालय ने 'इंदिरा साहनी केस' में इस आरक्षण को अवैध ठहराया।
5. यह मुद्दा केवल दक्षिण भारत के राज्यों तक सीमित रहा।

उपरोक्त में से कौन से कथन असत्य हैं?
(A) केवल 4 और 5
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 3, 4 और 5
(D) केवल 2 और 3

54. चंद्रशेखर ने किस अवधि के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया?
(A) दिसंबर 1989 - नवंबर 1990
(B) नवंबर 1990 - जून 1991
(C) जून 1991 - मई 1996
(D) मई 1996 - जून 1996

55. 1996-97 में एच.डी. देवगौड़ा के नेतृत्व में बनी संयुक्त मोर्चा सरकार को किस दल ने बाहर से समर्थन दिया था?
(A) भाजपा
(B) वाम मोर्चा
(C) शिवसेना
(D) कांग्रेस

56. 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद, 17वीं लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, की सीटों की संख्या कितनी थी?
(A) 52
(B) 44
(C) 145
(D) 108

57. निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी?
(A) भाजपा का गठन
(B) मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना
(C) बामसेफ का गठन
(D) शाहबानो वाद

58. 'कांग्रेस का पतन' और 'भाजपा का अभ्युदय' किस दशक की भारतीय राजनीति की प्रमुख विशेषताएँ हैं?
(A) 1990 का दशक
(B) 1970 का दशक
(C) 1980 का दशक
(D) 2000 का दशक

59. 1989 के चुनावों के संबंध में क्या सही है?
(A) कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल किया।
(B) भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।
(C) जनता दल ने अकेले सरकार बनाई।
(D) कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन उसे बहुमत नहीं मिला।

60. निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिये:
सूची I: (नेता)
P. कर्पूरी ठाकुर
Q. कांशीराम
R. वी.पी. सिंह
S. एल.के. आडवाणी

सूची II: (संबंधित दल/मुद्दा)
1. बहुजन समाज पार्टी
2. राम जन्मभूमि आंदोलन
3. बिहार में OBC आरक्षण
4. मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करना

(A) P-3, Q-1, R-4, S-2
(B) P-1, Q-3, R-2, S-4
(C) P-2, Q-4, R-1, S-3
(D) P-4, Q-2, R-3, S-1

61. मंडल आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था?
(A) केंद्र-राज्य संबंधों का अध्ययन करना।
(B) आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों की जाँच करना।
(C) भारत में शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन की व्यापकता का पता लगाना।
(D) भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की संभावना तलाशना।

62. 'दलित-शोषित समाज संघर्ष समिति' (डीएस-4) का परवर्ती विकास किस राजनीतिक दल के रूप में हुआ?
(A) जनता दल
(B) समाजवादी पार्टी
(C) राष्ट्रीय जनता दल
(D) बहुजन समाज पार्टी (बसपा)

63. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. 1980 में पूर्ववर्ती जनसंघ के समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी बनाई।
2. आरंभ में भाजपा ने 'गांधीवादी समाजवाद' को अपनी विचारधारा के रूप में अपनाया।
3. 1984 के चुनावों में भाजपा को बड़ी सफलता मिली।
4. 1986 के बाद भाजपा ने 'हिन्दुत्व' को अपनी विचारधारा

3. क्षेत्रीय पार्टियों ने गठबंधन सरकार बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4. 2014 और 2019 में भाजपा को अकेले बहुमत मिला, जिसने इस प्रवृत्ति को बदल दिया।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3 और 4
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) सभी 1, 2, 3 और 4

105. 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को बाहर से समर्थन देने के पीछे भाजपा और वाम मोर्चा का साझा उद्देश्य क्या था?

(A) नई आर्थिक नीतियां लागू करना
(B) राम मंदिर का निर्माण करना
(C) कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना
(D) मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करना

106. मंडल आयोग द्वारा पहचानी गई 'पिछड़ी जातियों' की विशेषता क्या थी?

(A) वर्ण व्यवस्था में निम्न मानी जाने वाली एससी से इतर जातियाँ
(B) ये मुख्य रूप से केवल आर्थिक रूप से विपन्न जातियों का समूह थीं
(C) वे सभी जातियाँ जिनका निवास मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में था
(D) वे सभी जातियाँ जो कृषि कार्यों से पूरी तरह असंबद्ध थीं

107. निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिये:

सूची I: (दल/गठबंधन)

P. जनता दल यूनाइटेड (जद-यू)
Q. द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (डी.एम.के)
R. शिवसेना
S. बहुजन समाज पार्टी (बसपा)

सूची II: (प्रमुख राज्य)

1. महाराष्ट्र
2. उत्तर प्रदेश
3. बिहार
4. तमिलनाडु

(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-2, Q-1, R-4, S-3
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

108. 1990 के दशक में भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले 'तीन M' के रूप में अक्सर किन मुद्दों का उल्लेख किया जाता है?

(A) महंगाई, महिला, मजदूर
(B) मंडल, मंदिर, मार्केट (बाजार)
(C) मीडिया, मनी, मसल
(D) मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, मॉब

109. भारतीय राजनीति में 'तुष्टिकरण' के आरोप का प्रयोग अक्सर किसके संदर्भ में किया जाता है?

(A) बहुसंख्यक समुदाय को दी जाने वाली किसी भी प्रकार की आर्थिक या सामाजिक रियायतें
(B) किसी एक विशिष्ट जाति को दिए जाने वाले विशेष राजनीतिक लाभ और प्रोत्साहन
(C) अल्पसंख्यक समुदाय को वोट बैंक मानकर दी जाने वाली अनावश्यक रियायतें
(D) देश के सभी नागरिकों को प्रदान किए जाने वाले समान और मौलिक संवैधानिक अधिकार

110. निम्नलिखित में से कौन 1990 के दशक में प्रधानमंत्री नहीं बना?

(A) पी. वी. नरसिम्हा राव
(B) एच.डी. देवगौड़ा
(C) लालकृष्ण आडवाणी
(D) इंद्रकुमार गुजराल

111. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक अभिकथन (A) और दूसरा तर्क (R) है। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए:

अभिकथन (A): 1990 के दशक से, राजनीतिक दल विचारधारा की बजाय सत्ता में हिस्सेदारी पर अधिक जोर देने लगे।

तर्क (R): इसका प्रमाण यह है कि भाजपा की 'हिंदुत्व' की विचारधारा से असहमत कई दल भी उसके साथ गठबंधन में शामिल हुए और सरकार बनाई।

(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

112. 1990 के दशक के बाद भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित पांच कथनों पर विचार करें:

1. कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया।
2. राष्ट्रीय राजनीति में पिछड़ी जातियों का राजनीतिक उदय हुआ।
3. धार्मिक पहचान पर आधारित राजनीति का प्रभाव बढ़ा।
4. नई आर्थिक नीतियों पर आम सहमति बनी।
5. भारत में दो-दलीय व्यवस्था पूर्ण रूप से स्थापित हो गई।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(A) केवल 1, 2, 3 और 4
(B) केवल 2, 3, 4 और 5
(C) केवल 1, 2 और 5
(D) सभी 1, 2, 3, 4 और 5

113. 1989 के बाद की गठबंधन राजनीति ने केंद्र-राज्य संबंधों को कैसे प्रभावित किया?

(A) केंद्र सरकार पहले की तुलना में संवैधानिक रूप से

(C) इसने पार्टी को अपने मुख्य एजेंडे को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया।
(D) इसने पार्टी को एक हाशिये की पार्टी से एक प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति में बदल दिया।

165. अनुच्छेद से यह क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राम जन्मभूमि आंदोलन ने भारतीय समाज और राजनीति पर एक स्थायी प्रभाव कैसे छोड़ा?
(A) इसने धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद पर बहस को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला दिया।
(B) इसने समाज को एकीकृत किया और सांप्रदायिक मतभेदों को समाप्त कर दिया।
(C) इसने भारत को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित किया।
(D) इसने एक स्थिर द्वि-दलीय राजनीतिक प्रणाली की स्थापना की।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

1989 और 2014 के बीच की अवधि को भारतीय राजनीति में 'गठबंधन के युग' के रूप में जाना जाता है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों के गठन और कामकाज में एक मौलिक बदलाव आया। एक-दलीय प्रभुत्व के अंत के साथ, किसी भी एक पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जिससे गठबंधन सरकारों का निर्माण एक आवश्यकता बन गया। इस दौर में राष्ट्रीय मोर्चा (1989), संयुक्त मोर्चा (1996-98), भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) (1998-2004), और कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) (2004-2014) जैसे कई गठबंधन सत्ता में आए। इन सरकारों की विशेषता शासन के प्रति एक सहयोगी दृष्टिकोण थी, जहाँ निर्णय प्रक्रिया में कई दलों की भागीदारी होती थी। हालाँकि, इस अवधि को अक्सर राजनीतिक अस्थिरता से जोड़ा जाता है, क्योंकि कई सरकारें अपना कार्यकाल पूरा करने में विफल रहीं। गठबंधन की मजबूरियों, जिन्हें 'गठबंधन धर्म' कहा जाता है, ने अक्सर नीतियों और प्रमुख नियुक्तियों पर जटिल बातचीत और समझौते की आवश्यकता पैदा की। इस युग का एक महत्वपूर्ण परिणाम राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते प्रभाव का था, जो अक्सर 'किंगमेकर' की भूमिका निभाते थे और अपनी क्षेत्रीय मांगों को राष्ट्रीय एजेंडे में शामिल करने में सफल रहे। इसने भारतीय संघवाद की प्रकृति को भी बदल दिया, जिससे यह अधिक सहयोगी और कम केंद्र-प्रमुख बन गया।

उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

166. 1989 और 2014 के बीच की अवधि को 'गठबंधन का युग' क्यों कहा जाता है?
(A) क्योंकि केवल दो प्रमुख राष्ट्रीय दल मौजूद थे।
(B) क्योंकि किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जिससे गठबंधन सरकारें बनीं।
(C) क्योंकि सभी सरकारें अत्यधिक स्थिर थीं और उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया।
(D) क्योंकि क्षेत्रीय दल पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गए थे।

167. अनुच्छेद में 'गठबंधन धर्म' शब्द का क्या अर्थ है?
(A) सरकार के लिए एक धार्मिक दृष्टिकोण।
(B) गठबंधन सहयोगियों के बीच नीतियों और नियुक्तियों पर बातचीत और समझौते की मजबूरी।
(C) एक भी पार्टी को शासन करने की अनुमति देने से इनकार।
(D) सभी गठबंधन सहयोगियों के लिए एक साझा विचारधारा।

168. गठबंधन के युग का क्षेत्रीय दलों पर क्या प्रभाव पड़ा?
(A) वे अक्सर 'किंगमेकर' की भूमिका निभाते हुए राष्ट्रीय राजनीति में अत्यधिक प्रभावशाली हो गए।
(B) उन्होंने अपनी सारी शक्ति और प्रभाव खो दिया।
(C) वे सभी राष्ट्रीय दलों में विलीन हो गए।
(D) उन्हें केवल स्थानीय चुनावों में भाग लेने की अनुमति थी।

169. निम्नलिखित में से कौन सा गठबंधन अनुच्छेद में उल्लिखित नहीं है?
(A) राष्ट्रीय मोर्चा
(B) राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA)
(C) तीसरा मोर्चा
(D) संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA)

170. अनुच्छेद के अनुसार, गठबंधन के युग ने भारतीय संघवाद को कैसे प्रभावित किया?
(A) इसने संघवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया।
(B) इसने केंद्र सरकार को राज्यों पर पूर्ण अधिकार प्रदान किया।
(C) इसका भारतीय संघवाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
(D) इसने भारतीय संघवाद को अधिक सहयोगी और कम केंद्र-प्रमुख बना दिया।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

1991 में, एक गंभीर भुगतान संतुलन संकट के बीच, भारत ने नए आर्थिक सुधारों का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया, जिसने देश के आर्थिक प्रक्षेपवक्र को मौलिक रूप से बदल दिया। प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, इन सुधारों ने अर्थव्यवस्था पर राज्य के नियंत्रण को कम करने और इसे वैश्विक बाजारों के लिए खोलने का प्रयास किया। 'उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण' (LPG) के रूप में प्रसिद्ध, इन नीतियों में औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त करना, सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार को कम करना, व्यापार बाधाओं को कम करना और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना शामिल था। इन सुधारों ने 'लाइसेंस राज' को समाप्त कर दिया, जिसने दशकों से भारतीय अर्थव्यवस्था को बाधित किया था, और एक अधिक बाजार-उन्मुख प्रणाली की शुरुआत की। प्रारंभ में, इन सुधारों को राजनीतिक स्पेक्ट्रम के कुछ हिस्सों, विशेष रूप से वामपंथियों से, आलोचना और प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने

123. 1989 से 1999 के बीच केंद्र में कितनी सरकारें बनीं, जो गठबंधन या अल्पमत की सरकारें थीं?
(A) 5
(B) 7
(C) 9
(D) 11

124. 1980 के दशक के बाद की भारतीय राजनीति में "सामाजिक न्याय" की राजनीति का संबंध मुख्यतः किससे है?
(A) देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को लागू करने से
(B) एससी/एसटी और ओबीसी समूहों के लिए आरक्षण और सत्ता में हिस्सेदारी से
(C) केवल देश के आर्थिक विकास और औद्योगिक प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने से
(D) अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भारत की पारंपरिक गुटनिरपेक्ष नीति के अनुसरण से

125. निम्नलिखित राजनीतिक घटनाओं को उनके घटित होने के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम में रखें:
1. पी.वी. नरसिम्हा राव का प्रधानमंत्री बनना
2. एच.डी. देवगौड़ा का प्रधानमंत्री बनना
3. इंद्र कुमार गुजराल का प्रधानमंत्री बनना
4. अटल बिहारी वाजपेयी का पहली बार प्रधानमंत्री बनना (13 दिन के लिए)
5. चंद्रशेखर का प्रधानमंत्री बनना

(A) 5, 1, 4, 2, 3
(B) 1, 5, 2, 3, 4
(C) 5, 1, 2, 4, 3
(D) 1, 2, 3, 4, 5

126. 1990 के दशक में कांग्रेस के कमजोर होने के बावजूद वह अन्य पार्टियों से किस प्रकार भिन्न रही?
(A) वह राष्ट्रीय और राज्य स्तर की राजनीति से पूरी तरह समाप्त हो गई
(B) उसने 1989 के बाद किसी भी भारतीय राज्य में अपनी सरकार नहीं बनाई
(C) उसने देश के समस्त क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को अपने भीतर विलीन कर लिया
(D) चुनावी गिरावट के बाद भी देश पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला दल रहा

127. 1989 के चुनाव परिणामों ने किस राजनीतिक परिघटना का अंत किया?
(A) 'कांग्रेस प्रणाली' या कांग्रेस का एक-दलीय प्रभुत्व
(B) गठबंधन की राजनीति
(C) क्षेत्रीय दलों का उदय
(D) वामपंथी राजनीति का प्रभाव

128. निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिये:

सूची I: (लोकसभा चुनाव वर्ष)
P. 1984
Q. 1989
R. 1996
S. 2014

सूची II: (परिणाम/विशेषता)
1. भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी, पर सरकार नहीं बना सकी (शुरू में)
2. 30 साल बाद एक दल को बहुमत
3. राजीव गाँधी के नेतृत्व में कांग्रेस को 415 सीटें
4. कांग्रेस की हार, गठबंधन युग की शुरुआत

(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-3, R-2, S-1
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

129. "भारत की दलगत राजनीति ने कई चुनौतियों का सामना किया है... इससे दलगत व्यवस्था और विभिन्न हितों की समाई करने की इसकी क्षमता पर भी सवाल उठे।" इस कथन का क्या आशय है?
(A) भारत में वर्तमान राजनीतिक दल अपने लक्ष्यों में पूरी तरह सफल रहे हैं
(B) विविध सामाजिक समूहों के हितों को समन्वित करना दलों के लिए चुनौतीपूर्ण है
(C) भारत के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे में केवल एक ही प्रमुख हित समूह है
(D) वर्तमान राजनीतिक दलों के समक्ष किसी भी प्रकार की कोई बड़ी चुनौती नहीं है

130. 1989 के बाद के दौर में "राजनीतिक अस्थिरता" का मुख्य कारण क्या था?
(A) स्पष्ट बहुमत का अभाव और गठबंधनों का बार-बार टूटना-बनना
(B) लगातार सीमावर्ती युद्ध होना
(C) वैश्विक आर्थिक मंदी का प्रभाव
(D) जनता का चुनावी प्रक्रिया से मोहभंग

131. भारतीय राजनीति के बदलते परिदृश्य के संबंध में निम्नलिखित पांच कथनों पर विचार करें:
1. 1984 में कांग्रेस को 415 सीटें मिलीं, जबकि 1989 में 197 सीटें मिलीं।
2. 1996 के चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।
3. 2004 और 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व में संप्रग ने सरकार बनाई।
4. 2014 और 2019 में भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल किया।
5. 1989 से 2014 तक किसी भी दल को लोकसभा में अकेले बहुमत नहीं मिला।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1, 2 और 4
(B) केवल 3 और 5
(C) केवल 1, 3, 4 और 5

(D) भारत की वर्तमान आरक्षण व्यवस्था को अब शासन द्वारा पूरी तरह समाप्त कर दिया है

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

1980 के दशक के अंत तक भारतीय राजनीति में 'कांग्रेस प्रणाली' का प्रभुत्व समाप्त हो गया, जिसने दशकों तक देश की राजनीतिक संरचना को परिभाषित किया था। इस प्रणाली की विशेषता कांग्रेस पार्टी का केंद्र में और अधिकांश राज्यों में एक-दलीय प्रभुत्व था, जो विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक समूहों को एक व्यापक गठबंधन में समाहित करने की अपनी क्षमता पर आधारित था। हालाँकि, 1980 के दशक के अंत तक, यह समावेशी मॉडल बिखरने लगा। क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उदय, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास, और नेतृत्व के संकट ने कांग्रेस की पकड़ को कमजोर कर दिया। 1989 का आम चुनाव इस परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने एक-दलीय बहुमत के युग का अंत और गठबंधन की राजनीति की शुरुआत का संकेत दिया। यह एक ऐसी अवधि थी जहाँ कोई भी एक दल लोकसभा में अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर सका, जिससे राष्ट्रीय मोर्चे जैसी गठबंधन सरकारों का निर्माण आवश्यक हो गया। इन गठबंधनों को अक्सर वैचारिक रूप से भिन्न दलों, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और वाम दलों द्वारा बाहरी समर्थन की आवश्यकता होती थी, जिन्होंने केवल कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के साझा उद्देश्य के लिए एकजुट होकर काम किया। इसने भारतीय राजनीति में एक नए, अधिक खंडित और अप्रत्याशित चरण की शुरुआत की, जहाँ सत्ता साझा करना और बातचीत की कला राजनीतिक अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हो गई।

उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

151. 1980 के दशक के अंत में 'कांग्रेस प्रणाली' के पतन का मुख्य कारण क्या था?
(A) एक मजबूत विपक्षी दल का राष्ट्रीय स्तर पर उदय
(B) विभिन्न समूहों को समाहित करने की क्षमता का क्षरण और क्षेत्रीय दलों का उदय
(C) पार्टी के भीतर वैचारिक संघर्ष
(D) आर्थिक नीतियों की विफलता

152. 1989 के आम चुनाव को भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना जाता है?
(A) क्योंकि इसने एक-दलीय बहुमत के युग का अंत और गठबंधन की राजनीति की शुरुआत की
(B) क्योंकि इसने कांग्रेस पार्टी को अब तक का सबसे बड़ा बहुमत दिलाया
(C) क्योंकि इसके परिणामस्वरूप भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बनी
(D) क्योंकि इसमें पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग किया गया था

153. स्रोत के अनुसार, 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के गठन के लिए भाजपा और वाम दलों के बाहरी समर्थन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था?
(A) एक साझा आर्थिक कार्यक्रम लागू करना
(B) क्षेत्रीय दलों को अधिक शक्ति प्रदान करना
(C) कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर रखना
(D) एक नई धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को बढ़ावा देना

154. 'कांग्रेस प्रणाली' की परिभाषित विशेषता क्या थी, जैसा कि अनुच्छेद में वर्णित है?
(A) गठबंधन सरकारें चलाने की विशेषज्ञता
(B) एक केंद्रीकृत और सत्तावादी पार्टी संरचना
(C) समाजवादी आर्थिक नीतियों पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना
(D) केंद्र और राज्यों में एक-दलीय प्रभुत्व और विभिन्न समूहों को समाहित करने की क्षमता

155. अनुच्छेद से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गठबंधन की राजनीति के युग ने भारतीय राजनीतिक परिदृश्य को कैसे प्रभावित किया?
(A) इसने राजनीतिक स्थिरता को बढ़ाया और नीति-निर्माण को सुव्यवस्थित किया।
(B) इसने एक द्वि-दलीय प्रणाली का मार्ग प्रशस्त किया।
(C) इसने राजनीतिक प्रक्रिया को अधिक खंडित और अप्रत्याशित बना दिया, जहाँ बातचीत महत्वपूर्ण हो गई।
(D) इसने क्षेत्रीय दलों के प्रभाव को कम कर दिया।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना भारतीय सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में एक युगांतरकारी क्षण था। 1978 में स्थापित इस आयोग का उद्देश्य भारत में 'सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों' (SEBCs) की पहचान करना और उनके उत्थान के लिए उपायों की सिफारिश करना था। इसकी मुख्य सिफारिश सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान करना थी। इस निर्णय ने एक बड़े राजनीतिक विवाद को जन्म दिया, जिसे 'मंडल मुद्दा' कहा गया। इसने शहरी क्षेत्रों में उच्च जातियों के युवाओं के बीच व्यापक विरोध प्रदर्शनों को उकसाया, जिन्होंने इसे योग्यता के विरुद्ध और एक प्रतिगामी कदम के रूप में देखा। इसके विपरीत, इस कदम ने ओबीसी समुदायों के बीच एक महत्वपूर्ण राजनीतिक जागृति और लामबंदी को प्रेरित किया, जिन्होंने इसे सामाजिक न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दिशा में एक लंबे समय से प्रतीक्षित कदम के रूप में देखा। इस घटना ने भारतीय राजनीति के विमर्श को स्थायी रूप से बदल दिया, जिससे जाति-आधारित पहचान राजनीति का उदय हुआ। इसने जनता दल, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसे दलों के लिए एक शक्तिशाली चुनावी आधार तैयार किया, जिन्होंने खुद को पिछड़े वर्गों और

(C) लालकृष्ण आडवाणी
(D) इंद्रकुमार गुजराल

142. 1989 से 2014 के बीच की अवधि को 'त्रिशंकु संसद' (Hung Parliament) का दौर क्यों कहा जाता है?
(A) क्योंकि संसद में तत्कालीन समय में तीन ही प्रमुख दल विद्यमान थे
(B) क्योंकि उस दौरान संसद के समस्त सत्र अत्यंत शोर-शराबे वाले रहे
(C) क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तीन विभिन्न विचारधाराओं से चुने जाते थे
(D) लोकसभा चुनाव में किसी भी दल को सरकार हेतु स्पष्ट बहुमत न मिलना

143. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कीं।
2. 1991 में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई।
3. 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया।
4. 1996 में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी।
5. 1998 में राजग की सरकार पहली बार बनी।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 4 और 5
(C) केवल 1, 3 और 5
(D) सभी 1, 2, 3, 4 और 5

144. भारतीय समाज और राजनीति पर 'मंडलीकरण' का क्या प्रभाव पड़ा?
(A) इसने भारतीय समाज में प्रचलित जातिगत चेतना को बहुत कम कर दिया
(B) पिछड़ी जातियों में राजनीतिक जागरूकता और लामबंदी की वृद्धि हुई
(C) इसने राष्ट्र में केवल आर्थिक असमानता के स्तर को तीव्र गति से बढ़ाया
(D) इसका देश की चुनावी राजनीति पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा

145. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक अभिकथन (A) और दूसरा तर्क (R) है। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए:
अभिकथन (A): 1990 के दशक के बाद की भारतीय राजनीति को समझना पहले की तुलना में अधिक जटिल है।
तर्क (R): इस अवधि में गठबंधन की राजनीति, मंडलीकरण और राम जन्मभूमि आंदोलन जैसे कई कारकों ने एक साथ मिलकर अप्रत्याशित और विवादास्पद परिणाम दिए।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

146. 1996 के लोकसभा चुनावों के बाद भाजपा सरकार बनाने में क्यों विफल रही, जबकि वह सबसे बड़ी पार्टी थी?
(A) नीतियों के विरोध के कारण अन्य दलों का समर्थन और बहुमत प्राप्त न होना
(B) क्योंकि देश के तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया
(C) क्योंकि भाजपा ने स्वयं स्वेच्छा से सरकार के गठन से पूरी तरह इनकार किया
(D) क्योंकि निर्वाचन आयोग ने चुनाव परिणामों को अनियमितता के कारण रद्द किया

147. निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में 1989 के बाद की दलीय प्रणाली का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(A) एक-दलीय प्रभुत्व प्रणाली
(B) दो-दलीय प्रणाली
(C) बहु-दलीय प्रणाली जिसमें गठबंधन की प्रमुखता हो
(D) बिना दलों वाली प्रणाली

148. निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के क्रम में व्यवस्थित करें:
1. बाबरी मस्जिद का विध्वंस
2. शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला
3. मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा
4. राजीव गांधी की हत्या

(A) 2, 3, 4, 1
(B) 3, 2, 1, 4
(C) 1, 2, 3, 4
(D) 4, 1, 3, 2

149. भारतीय राजनीति में 1989 से 2014 तक के युग को "अस्थिरता और अनिश्चितता का युग" क्यों कहा जा सकता है?
(A) क्योंकि इस संपूर्ण कालखंड के दौरान देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध था
(B) क्योंकि भारत ने इस लंबी अवधि में कभी कोई अंतरराष्ट्रीय युद्ध नहीं लड़ा
(C) केंद्र में बार-बार सरकारों का परिवर्तन और दीर्घकालिक स्थिरता का अभाव
(D) क्योंकि देश के मतदाताओं ने लोकतांत्रिक चुनावों में रुचि लेना बंद कर दिया था

150. समकालीन भारतीय राजनीति में उभरी "नई सहमति" की चार बातों में से एक यह है कि पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे को स्वीकार किया जाए। इसका क्या अर्थ है?
(A) पिछड़ी जातियों को अब भविष्य में कोई विशेष संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे
(B) अधिकांश दल शिक्षा और रोजगार में पिछड़ी जातियों हेतु आरक्षण के पक्षधर हैं
(C) देश में अब केवल पिछड़ी जातियों के लोग ही चुनावी मैदान में उतर सकते हैं

(D) सभी 1, 2, 3, 4 और 5

132. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक अभिकथन (A) और दूसरा तर्क (R) है। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए:
अभिकथन (A): 1989 के बाद, गठबंधन की राजनीति के दौर में राजनीतिक दल विचारधारा को आधार मानकर गठजोड़ नहीं करते हैं।
तर्क (R): इस दौर में दल विचारधारागत अंतर की जगह सत्ता में हिस्सेदारी की बातों पर अधिक ज़ोर दे रहे हैं।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

133. 1990 के दशक में किन दो मुद्दों ने भारतीय राजनीति में ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया?
(A) केंद्र-राज्य संबंध और भाषा विवाद
(B) गुटनिरपेक्षता और परमाणु नीति
(C) मंडल आयोग और राम जन्मभूमि
(D) पंचायती राज और शहरी सुधार

134. यदि हर सरकार एक-सी नीति पर अमल करे, तो इसका राजनीतिक विकल्पों के चयन पर क्या असर होगा?
(A) इससे चुनावी प्रतिस्पर्धा में विकल्पों की संख्या बढ़ जाएगी
(B) नीतिगत समानता के कारण दलों के मध्य अंतर करना कठिन होगा
(C) इससे देश की शासन व्यवस्था में कोई महत्त्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा
(D) चुनावी दौड़ में केवल नवीन राजनीतिक पार्टियाँ ही विजयी होंगी

135. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो 1989 के बाद की राजनीति से संबंधित हैं:
1. कांग्रेस का प्रभुत्व समाप्त हो गया।
2. राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ा।
3. 'मंडल' और 'मंदिर' जैसे मुद्दों ने राजनीति को प्रभावित किया।
4. केंद्र में मिली-जुली सरकारों का दौर शुरु हुआ।
इनमें से कौन सा कथन 1989 के बाद के "गठबंधन युग" का सटीक वर्णन करता है?
(A) केवल 1 और 4
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1, 2 और 4
(D) सभी 1, 2, 3 और 4

136. वह कौन सी एक बात है जो 1989 के राष्ट्रीय मोर्चे और 1996 के संयुक्त मोर्चे की सरकारों में समान थी?
(A) दोनों में जनता दल और कई क्षेत्रीय पार्टियाँ शामिल थीं
(B) दोनों को भाजपा ने बाहर से समर्थन प्रदान किया
(C) दोनों सरकारों का नेतृत्व एक ही व्यक्ति द्वारा किया गया
(D) दोनों सरकारों ने अपना 5 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल संपन्न किया

137. 2009 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की सीटों में 2004 की तुलना में क्या परिवर्तन आया?
(A) सीटें कम हो गईं।
(B) सीटें उतनी ही रहीं।
(C) सीटों की संख्या में वृद्धि हुई (145 से 206)।
(D) सीटों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ।

138. निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिये:
सूची I: (अवधि)
P. 1989-1990
Q. 1991-1996
R. 1998-1999
S. 2004-2009
सूची II: (प्रधानमंत्री)
1. पी. वी. नरसिम्हा राव
2. अटल बिहारी वाजपेयी
3. डॉ. मनमोहन सिंह
4. वी. पी. सिंह
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-1, R-2, S-3
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-2, Q-3, R-4, S-1

139. 1990 के दशक में भारतीय राजनीति के संदर्भ में, 'पहचान की राजनीति' (Identity Politics) का क्या अर्थ है?
(A) आर्थिक विकास और सुधारों पर आधारित आधुनिक राजनीति
(B) सामूहिक पहचान जैसे क्षेत्र और भाषा आधारित लामबंदी
(C) केवल विदेश नीति के सिद्धांतों पर आधारित राष्ट्रीय राजनीति
(D) सामूहिक पहचान जैसे जाति, धर्म और क्षेत्र आधारित लामबंदी

140. 2019 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने अयोध्या में विवादित भूमि किसे सौंपी?
(A) सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को
(B) एक ट्रस्ट को, राम मंदिर निर्माण के लिए
(C) भारत सरकार को
(D) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को

141. निम्नलिखित में से कौन 1990 के दशक में प्रधानमंत्री नहीं बना?
(A) पी. वी. नरसिम्हा राव
(B) एच.डी. देवगौड़ा

दलितों के चैंपियन के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे भारतीय चुनावी अंकगणित का स्थायी रुप से पुनर्संरेखण हुआ।
उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

156. मंडल आयोग का प्राथमिक उद्देश्य क्या था?
(A) भारत में आर्थिक असमानता का अध्ययन करना
(B) भारत में 'सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों' की पहचान करना
(C) अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की समीक्षा करना
(D) भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधारों का सुझाव देना

157. मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का तत्काल परिणाम क्या था?
(A) सभी राजनीतिक दलों के बीच सर्वसम्मति
(B) आर्थिक सुधारों की शुरुआत
(C) गठबंधन सरकारों के युग का अंत
(D) शहरी क्षेत्रों में उच्च जातियों द्वारा व्यापक विरोध प्रदर्शन

158. अनुच्छेद के अनुसार, 'मंडल मुद्दा' ने भारतीय राजनीति को कैसे प्रभावित किया?
(A) इसने भारतीय राजनीति में जाति-आधारित पहचान की राजनीति के उदय को प्रेरित किया।
(B) इसने जाति-आधारित पहचान की राजनीति को कमजोर कर दिया।
(C) इसने केवल आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राजनीतिक विमर्श को स्थानांतरित कर दिया।
(D) इसने राष्ट्रीय दलों के पक्ष में क्षेत्रीय दलों के पतन का नेतृत्व किया।

159. मंडल आयोग की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश क्या थी?
(A) भूमि सुधारों का कार्यान्वयन
(B) सभी के लिए मुफ्त शिक्षा
(C) सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण
(D) निजी क्षेत्र में आरक्षण का परिचय

160. अनुच्छेद से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मंडल आयोग के कार्यान्वयन ने दलीय प्रणाली को कैसे प्रभावित किया?
(A) इसने पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले दलों के लिए एक चुनावी आधार बनाया।
(B) इसने कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व को मजबूत किया।
(C) इसने एक द्वि-दलीय प्रणाली का निर्माण किया।
(D) इसका भारत की दलीय व्यवस्था पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा।

निर्देश : कृपया निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
1980 के दशक के उत्तरार्ध और 1990 के दशक की शुरुआत में राम जन्मभूमि आंदोलन भारतीय राजनीति में एक और परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरा। यह आंदोलन, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) जैसे संगठनों ने किया, अयोध्या में बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर के निर्माण पर केंद्रित था, जिसके बारे में उनका मानना था कि यह भगवान राम का जन्मस्थान है। इस आंदोलन ने 'हिंदुत्व' या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा का उपयोग करके बड़े पैमाने पर राजनीतिक लामबंदी के लिए धार्मिक प्रतीकों और भावनाओं का सफलतापूर्वक उपयोग किया। लालकृष्ण आडवाणी द्वारा 1990 में निकाली गई 'रथ यात्रा' इस रणनीति का एक प्रमुख उदाहरण थी, जिसका उद्देश्य आंदोलन के लिए जन समर्थन जुटाना था। इस आंदोलन ने भारतीय राजनीति की धर्मनिरपेक्ष नींव पर एक गहन बहस छेड़ दी और समाज का धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण किया। इसने भाजपा के राजनीतिक भाग्य को बदल दिया, इसे 1984 में केवल दो सीटों वाली एक हाशिये की पार्टी से 1990 के दशक में एक प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति में बदल दिया। आंदोलन की परिणति 6 दिसंबर, 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस में हुई, जिसके कारण देश भर में व्यापक सांप्रदायिक दंगे हुए। इस घटना ने भारतीय राजनीति के प्रक्षेप पथ को स्थायी रूप से बदल दिया, जिससे सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद पर बहसें राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में आ गईं।
उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

161. राम जन्मभूमि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था?
(A) अयोध्या में एक विश्वविद्यालय का निर्माण करना
(B) भारत में एक नई धर्मनिरपेक्ष संहिता लागू करना
(C) अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए लड़ना
(D) अयोध्या में बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का निर्माण करना

162. इस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा किस विचारधारा का उपयोग किया गया?
(A) गांधीवादी समाजवाद
(B) 'हिंदुत्व' या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद
(C) साम्यवाद
(D) उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद

163. लालकृष्ण आडवाणी की 1990 की 'रथ यात्रा' का प्राथमिक लक्ष्य क्या था?
(A) राष्ट्रीय एकता और सद्भाव को बढ़ावा देना
(B) आर्थिक विकास के लिए प्रचार करना
(C) राम मंदिर आंदोलन के लिए जन समर्थन जुटाना
(D) सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना

164. अनुच्छेद के अनुसार, राम जन्मभूमि आंदोलन का भाजपा की राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा?
(A) इसने पार्टी को और कमजोर कर दिया, जिससे उसका पतन हो गया।
(B) इसका पार्टी की राजनीतिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

अधिक शक्तिशाली हो गई

(B) क्षेत्रीय दलों की भागीदारी से राज्यों के महत्त्व और स्वायत्तता में वृद्धि हुई

(C) शासन व्यवस्था में राज्यों की भूमिका पूरी तरह से नगण्य और प्रभावहीन हो गई

(D) भारत के केंद्र और राज्य के संबंधों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आया

114. अयोध्या विवाद के समाधान में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (2019) ने क्या स्थापित किया?

(A) लोकतांत्रिक समाज में विवादों का हल विधि की उचित प्रक्रिया से संभव है

(B) भारत जैसे राष्ट्र में जटिल धार्मिक विवादों का न्यायपूर्ण समाधान संभव नहीं है

(C) इस प्रकार के विवाद केवल सैन्य हस्तक्षेप के माध्यम से ही हल किए जा सकते हैं

(D) देश का न्यायालय ऐसे संवेदनशील धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रखता

115. निम्नलिखित में से कौन सी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने में सफल रही?

(A) वी.पी. सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार

(B) एच.डी. देवगौड़ा की संयुक्त मोर्चा सरकार

(C) 1999 में बनी अटल बिहारी वाजपेयी की राजग सरकार

(D) चंद्रशेखर की सरकार

116. निम्नलिखित में से किस चुनाव को 'गठबंधन के युग' की शुरुआत माना जाता है?

(A) 1984 का चुनाव

(B) 1991 का चुनाव

(C) 1977 का चुनाव

(D) 1989 का चुनाव

117. निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिये:

सूची I: (मुद्दा/अवधारणा)

P. शाहबानो वाद

Q. बामसेफ

R. इंदिरा साहनी केस

S. संप्रग

सूची II: (संबंधित विषय)

1. OBC आरक्षण
2. गठबंधन सरकार
3. पर्सनल लॉ और लैंगिक न्याय
4. सरकारी कर्मचारियों का संगठन

(A) P-1, Q-2, R-3, S-4

(B) P-3, Q-4, R-1, S-2

(C) P-2, Q-3, R-4, S-1

(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

118. 'दलित पैंथर्स' आंदोलन के बाद दलित अधिकारों के लिए राजनीतिक लामबंदी का नेतृत्व किस संगठन और बाद में किस दल ने किया?

(A) किसान संघ और लोक दल

(B) बामसेफ और बसपा

(C) आर.एस.एस. और भाजपा

(D) छात्र संघर्ष समिति और जनता पार्टी

119. 1990 के दशक में कांग्रेस के पतन का क्या अर्थ नहीं है?

(A) पार्टी के चुनावी प्रदर्शन में गिरावट।

(B) दलीय व्यवस्था में उसकी प्रमुखता का अंत।

(C) दलीय राजकोष का घटना।

(D) कांग्रेस पार्टी का पूर्ण रूप से विघटन।

120. 2004 के लोकसभा चुनाव परिणामों के बारे में क्या सही है?

(A) राजग और संप्रग को मिले कुल वोटों का अंतर बड़ा कम था।

(B) राजग को स्पष्ट बहुमत मिला।

(C) संप्रग को स्पष्ट बहुमत मिला।

(D) वाम मोर्चा सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभरा।

121. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 1989 के बाद गठबंधन की राजनीति के दौर में राजनीतिक दल विचारधारागत अंतर की जगह सत्ता में हिस्सेदारी पर ज़ोर देने लगे।
2. 1990 के दशक के बाद सभी राजनीतिक दल नई आर्थिक नीतियों के पक्ष में हो गए।
3. पिछड़े वर्गों के राजनीतिक और सामाजिक दावों को अब अधिकतर दलों ने स्वीकार कर लिया है।
4. प्रांतीय दलों की भूमिका केवल राज्य स्तर तक सीमित हो गई है।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 1, 2 और 3

(C) केवल 3 और 4

(D) सभी 1, 2, 3 और 4

122. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक अभिकथन (A) और दूसरा तर्क (R) है। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए:

अभिकथन (A): 1990 का दशक भारतीय राजनीति में बड़े उथल-पुथल और बदलाव का दौर था।

तर्क (R): इस अवधि में मंडल, मंदिर और आर्थिक सुधार जैसे मुद्दों ने एक साथ मिलकर राजनीति की दिशा को अप्रत्याशित रूप से बदल दिया।

(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।

(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

तर्क दिया कि वे गरीबों और श्रमिकों को नुकसान पहुँचाएँगे। हालाँकि, समय के साथ, इन सुधारों की व्यापक दिशा पर एक व्यापक राजनीतिक सहमति उभरी। बाद की सरकारों ने, उनकी राजनीतिक विचारधाराओं की परवाह किए बिना, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार और मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार सहित, सुधार प्रक्रिया को जारी रखा और आगे बढ़ाया। यह सहमति इस मान्यता पर आधारित थी कि उच्च आर्थिक विकास प्राप्त करने और भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए ये सुधार आवश्यक थे।

उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

171. 1991 के आर्थिक सुधारों का मुख्य कारण क्या था?
(A) एक राजनीतिक घोटाला
(B) एक सफल आम चुनाव
(C) एक गंभीर भुगतान संतुलन संकट
(D) एक सैन्य तख्तापलट

172. 1991 के आर्थिक सुधारों को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है?
(A) हरित क्रांति
(B) उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG)
(C) लाइसेंस राज
(D) आत्मनिर्भर भारत

173. 'लाइसेंस राज' की समाप्ति का क्या अर्थ था?
(A) ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त करना।
(B) सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बंद करना।
(C) विदेशी वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना।
(D) उद्योगों की स्थापना और संचालन पर व्यापक सरकारी नियंत्रणों को समाप्त करना।

174. अनुच्छेद के अनुसार, आर्थिक सुधारों पर राजनीतिक सहमति कैसे विकसित हुई?
(A) समय के साथ, बाद की विभिन्न विचारधाराओं वाली सरकारों ने भी सुधार प्रक्रिया को जारी रखा।
(B) सुधारों का शुरू से ही सार्वभौमिक रूप से समर्थन किया गया था।
(C) वामपंथी दलों ने सुधारों को लागू करने में नेतृत्व किया।
(D) सुधारों पर कभी कोई राजनीतिक सहमति नहीं बनी।

175. 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत के समय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री कौन थे?
(A) राजीव गांधी और वी.पी. सिंह
(B) अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी
(C) पी.वी. नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह
(D) इंद्र कुमार गुजराल और एच.डी. देवेगौड़ा

ANSWERS

1. (B) 415
इंदिरा गाँधी की हत्या के बाद 1984 में हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने राजीव गाँधी के नेतृत्व में एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। सहानुभूति की लहर के चलते पार्टी ने कुल 543 सीटों में से 415 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया था। यह जीत भारतीय संसदीय इतिहास में किसी भी दल द्वारा जीती गई अब तक की सर्वाधिक सीटें हैं।

2. (A) भारत-चीन युद्ध
1980 के दशक के अंतिम वर्षों में भारतीय राजनीति में कई बड़े बदलाव हुए जिनमें मंडल मुद्दा, आर्थिक सुधार और कांग्रेस की चुनावी हार शामिल थी। हालांकि, भारत और चीन के बीच युद्ध 1962 में हुआ था, जो इस समय अवधि का हिस्सा नहीं था। उस दौर में राजनीति मुख्य रूप से गठबंधन सरकारों और सामाजिक आंदोलनों के इर्द-गिर्द केंद्रित थी।

3. (A) P-3, Q-1, R-2, S-4
भारतीय राजनीति के विभिन्न दौरों में अलग-अलग प्रधानमंत्रियों ने विविध गठबंधनों का नेतृत्व किया। वी.पी. सिंह ने 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया, जबकि पी. वी. नरसिम्हा राव ने कांग्रेस समर्थित सरकार चलाई। अटल बिहारी वाजपेयी ने भाजपा के नेतृत्व वाले राजग गठबंधन की कमान संभाली और एच.डी. देवगौड़ा ने 1996 में कांग्रेस के समर्थन से संयुक्त मोर्चा सरकार का गठन किया।

4. (D) भारतीय दलीय प्रणाली में कांग्रेस पार्टी का निरंतर और विशिष्ट प्रभुत्वशाली स्थान
राजनीति विज्ञानी 'कांग्रेस प्रणाली' शब्द का प्रयोग भारतीय दलीय व्यवस्था में कांग्रेस पार्टी के निरंतर और विशिष्ट प्रभुत्वशाली स्थान को दर्शाने के लिए करते हैं। आजादी के बाद कई दशकों तक केंद्र और अधिकांश राज्यों में कांग्रेस का ही शासन रहा। यह प्रणाली एक विशाल गठबंधन की तरह कार्य करती थी जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों और विविध विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व समाहित रहता था।

5. (C) राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार
वर्ष 1990 में वी.पी. सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। इस निर्णय के तहत केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया। इस कदम ने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी और देश में व्यापक सामाजिक और राजनीतिक विमर्श को जन्म दिया।

6. (A) केवल 1 और 3
मंडल आयोग ने केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी। इसके लागू होने से देश के उत्तरी हिस्सों में व्यापक और अक्सर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। आरक्षण के समर्थकों और विरोधियों के बीच के इस तीखे विवाद को ही भारतीय राजनीति में 'मंडल मुद्दे' के नाम से जाना जाता है, जिसने चुनावी समीकरण बदले और सामाजिक न्याय की नई बहस छेड़ी।

7. (D) 1991
भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत व्यापक स्तर पर वर्ष 1991 में पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान हुई थी। हालांकि इसकी नींव राजीव गाँधी के समय में रखी गई थी, लेकिन देश के गंभीर वित्तीय संकट को देखते हुए 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों को प्रमुखता से लागू किया गया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप पूरी तरह बदल गया।

8. (A) लिट्टे से जुड़े श्रीलंकाई तमिलों को
मई 1991 में तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में एक चुनावी रैली के दौरान राजीव गाँधी की बम धमाके में हत्या कर दी गई थी। इस आत्मघाती हमले के लिए श्रीलंका के तमिल उग्रवादी संगठन 'लिट्टे' को जिम्मेदार ठहराया गया था। उनकी हत्या भारत द्वारा श्रीलंका में भेजी गई शांति सेना के विरोध में की गई थी, जिसके बाद देश की राजनीति में एक बड़ा निर्वात पैदा हुआ।

9. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
1989 के लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए क्योंकि यहाँ से केंद्र में गठबंधन की राजनीति का लंबा दौर शुरू हुआ। उस समय से लेकर 2014 तक किसी भी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण राष्ट्रीय दलों को सरकार बनाने के लिए कई छोटे क्षेत्रीय और सहयोगी दलों के साथ गठबंधन करना अनिवार्य हो गया।

10. (A) पी. वी. नरसिम्हा राव
1991 के लोकसभा चुनावों के दौरान राजीव गाँधी की हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी के सामने नेतृत्व का बड़ा संकट पैदा हो गया था। चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसके बाद पार्टी ने पी. वी. नरसिम्हा राव को अपना नेता चुना। उन्हें भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और उन्हीं के कार्यकाल में देश में महत्वपूर्ण नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई।

11. (D) भाजपा और वाम मोर्चा
1989 में गठित राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व वी.पी. सिंह ने किया था। इस सरकार को भारतीय जनता पार्टी और वाम मोर्चे ने बाहर से समर्थन दिया था। यह एक अनूठा गठबंधन था क्योंकि इसमें भाजपा और वाम मोर्चा जैसी धुर विरोधी विचारधारा वाली पार्टियाँ कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के

साझा उद्देश्य के लिए एक साथ आकर सरकार का समर्थन कर रही थीं।

12. (A) 1, 2, 3, 4, 5
भारतीय राजनीति की महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रम इंदिरा गाँधी की हत्या (1984) से शुरु होकर अयोध्या विवाद तक जाता है। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार बनी, जिसके बाद 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुईं। इसके उपरांत मई 1991 में राजीव गाँधी की हत्या हुई और दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराया गया था।

13. (C) बहुदलीय शासन-प्रणाली का युग शुरु हुआ।
नब्बे के दशक में कांग्रेस की प्रभुत्वशाली स्थिति को कड़ी चुनौती मिली, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय राजनीति में बहुदलीय शासन-प्रणाली के युग की शुरुआत हुई। अब किसी एक दल का वर्चस्व नहीं रहा और क्षेत्रीय दलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई। इससे केंद्र में ऐसी सरकारों का गठन हुआ जो कई अलग-अलग विचारधाराओं वाले दलों के आपसी तालमेल और समर्थन पर टिकी थीं।

14. (D) इस सरकार को भाजपा ने समर्थन दिया था।
1996 में बनी संयुक्त मोर्चा सरकार जनता दल और कई क्षेत्रीय दलों का एक समूह थी, जिसे कांग्रेस ने बाहर से समर्थन प्रदान किया था। इस सरकार का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकना था। भाजपा ने इस सरकार का समर्थन नहीं किया था, बल्कि वह संसद में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभा रही थी।

15. (A) P-2, Q-1, R-4, S-3
मंडल आयोग की नियुक्ति 1978 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा की गई थी। शाहबानो वाद 1985 का एक चर्चित मामला था जिसने नागरिक कानूनों पर बहस छेड़ी। बामसेफ का गठन दलित और अल्पसंख्यक कर्मचारियों के हितों के लिए 1978 में हुआ था। अंततः, 1989 में वी.पी. सिंह के नेतृत्व में केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार का गठन हुआ था।

16. (B) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)
1996 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी पहली बार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। इस ऐतिहासिक परिणाम ने भारतीय राजनीति में भाजपा के बढ़ते प्रभाव को स्पष्ट कर दिया। हालांकि, उस समय भाजपा को अन्य दलों का आवश्यक समर्थन नहीं मिल सका, जिसके कारण अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार मात्र तेरह दिनों के भीतर ही गिर गई थी।

17. (B) अटल बिहारी वाजपेयी
वर्ष 1998 से 2004 तक केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उनके नेतृत्व में भाजपा ने कई क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर एक स्थिर गठबंधन सरकार चलाई। वाजपेयी के कार्यकाल को परमाणु परीक्षण, पाकिस्तान के साथ शांति पहल और देश में व्यापक बुनियादी ढांचे के विकास जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है।

18. (A) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों की एससी/एसटी से इतर एक प्रशासनिक कोटि
'अन्य पिछड़ा वर्ग' शब्द का उपयोग उन जातियों के लिए किया जाता है जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, लेकिन वे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में नहीं आती हैं। यह एक प्रशासनिक और संवैधानिक कोटि है। मंडल आयोग ने इन्हीं समूहों की पहचान की थी ताकि उन्हें सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में आरक्षण प्रदान किया जा सके।

19. (C) 1977 की जनता पार्टी की सरकार
केंद्र में गैर-कांग्रेसी दलों के राजनीतिक अभ्युदय की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1977 की जनता पार्टी सरकार के रूप में हुई थी। आपातकाल के बाद हुए चुनावों में कांग्रेस को पहली बार हार का सामना करना पड़ा। विभिन्न विचारधाराओं वाले दलों ने मिलकर एक वैकल्पिक सरकार बनाई, जिसने यह सिद्ध किया कि भारतीय लोकतंत्र में कांग्रेस के बिना भी एक स्थिर सरकार संभव हो सकती है।

20. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
1990 के दशक में दलितों और पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई नए राजनीतिक दलों का उदय हुआ। इन दलों ने यह तर्क दिया कि समाज के बड़े हिस्से होने के नाते शासन और सत्ता में उनकी भागीदारी लोकतांत्रिक रूप से आवश्यक है। इस राजनीतिक चेतना ने पारंपरिक वोट बैंक को बदल दिया और भारतीय राजनीति में 'बहुजन' की अवधारणा को मजबूती प्रदान की।

21. (C) मंडल कमीशन
1978 में जनता पार्टी सरकार द्वारा नियुक्त 'दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग' अपने अध्यक्ष बी.पी. मंडल के नाम पर 'मंडल कमीशन' के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस आयोग का मुख्य कार्य पिछड़ी जातियों की पहचान करना और उनके कल्याण के लिए सुझाव देना था। इसकी रिपोर्ट ने बाद में भारतीय राजनीति में आरक्षण के मुद्दे को एक नई और निर्णायक दिशा प्रदान की।

22. (B) बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल
मंडल आयोग के अध्यक्ष बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल थे, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उनके नेतृत्व में आयोग ने देश भर में सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का गहन अध्ययन किया। आयोग की सिफारिशों ने पिछड़ी जातियों के सशक्तिकरण के लिए आरक्षण की वकालत की, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय राजनीति में बड़े संरचनात्मक बदलाव आए और पिछड़ी जातियों का राजनीतिक महत्व देशव्यापी स्तर पर काफी बढ़ गया।

23. (D) सभी 1, 2, 3, 4 और 5
मंडल आयोग का गठन सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की जांच के लिए किया गया था। आयोग ने 1980 में अपनी

46. (D) भारतीय जनता पार्टी
2014 के लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तीन दशकों के लंबे अंतराल के बाद अकेले दम पर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने 282 सीटें जीतकर गठबंधन राजनीति की उस मजबूरी को खत्म किया जहाँ सरकार चलाने के लिए बड़े दलों को अन्य सहयोगियों के समर्थन पर निर्भर रहना पड़ता था।

47. (A) देश के शासन में केवल राष्ट्रीय दलों की भूमिका की स्वीकृति
1980 के दशक के बाद भारतीय राजनीति में जो 'बढ़ती सहमति' उभरी, उसमें आर्थिक सुधारों, पिछड़ी जातियों के अधिकारों और कार्यसिद्धि पर जोर शामिल था। इसमें देश के शासन में केवल राष्ट्रीय दलों की भूमिका को स्वीकार करना शामिल नहीं था, बल्कि इसके विपरीत क्षेत्रीय दलों का महत्व और भी अधिक बढ़ गया था। अधिकांश राजनीतिक गठबंधनों में प्रांतीय दलों की भागीदारी अनिवार्य हो गई।

48. (B) भाजपा की हिन्दुत्व विचारधारा से असहमत दलों का भी उसके साथ सत्ता में शामिल होना
'विचारधारा की जगह कार्यसिद्धि पर जोर' का सबसे सटीक उदाहरण वह दौर है जब भाजपा की 'हिन्दुत्व' विचारधारा से असहमत होने के बावजूद कई क्षेत्रीय दल उसके साथ राजग गठबंधन में शामिल हुए। इन दलों ने वैचारिक मतभेदों को किनारे रखकर शासन और विकास के साझा लक्ष्यों के लिए सत्ता में भागीदारी को प्राथमिकता दी, जो गठबंधन राजनीति की बदलती प्रकृति को दर्शाता है।

49. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
राष्ट्रीय मोर्चा मुख्य रूप से जनता दल के इर्द-गिर्द केंद्रित था। संयुक्त मोर्चा सरकार को कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था। भारतीय जनता पार्टी 'राजग' (एनडीए) का मुख्य घटक दल है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 'संप्रग' (यूपीए) गठबंधन का नेतृत्व करती है। ये गठबंधन भारतीय राजनीति की बहुदलीय प्रकृति और विभिन्न सामाजिक शक्तियों के आपसी सामंजस्य के प्रतीक के रूप में उभरे हैं।

50. (A) 303
17वीं लोकसभा के लिए वर्ष 2019 में हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2014 के प्रदर्शन में और भी सुधार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने अकेले 303 सीटें जीतकर एक प्रचंड बहुमत हासिल किया। इस परिणाम ने न केवल भाजपा की स्थिति को मजबूत किया, बल्कि देश में एक-दलीय प्रभुत्व के नए दौर की संभावनाओं को भी जन्म दिया।

51. (C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
1989 के चुनावों के बाद कांग्रेस का एक-दलीय प्रभुत्व निश्चित रूप से समाप्त हो गया, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि भाजपा तुरंत उसकी जगह प्रमुख बन गई। वास्तव में, उस समय किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला और देश गठबंधन की राजनीति के एक अनिश्चित दौर में चला गया। भाजपा को मुख्य राष्ट्रीय शक्ति के रूप में स्थापित होने में इसके बाद कई और वर्ष लगे।

52. (D) वी.पी. सिंह
1989 के लोकसभा चुनावों के बाद वी.पी. सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी थी। वे कांग्रेस के पूर्व नेता थे जिन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पार्टी छोड़ी थी। उनके कार्यकाल की सबसे प्रमुख घटना मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना था, जिसने देश के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे पर गहरा और दीर्घकालिक प्रभाव डाला और पिछड़ी जातियों को लामबंद किया।

53. (A) केवल 4 और 5
मंडल मुद्दे के संबंध में यह कथन गलत है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण को अवैध ठहराया; इसके विपरीत, न्यायालय ने इसे वैध माना था। साथ ही, यह कहना भी गलत है कि यह मुद्दा केवल दक्षिण भारत तक सीमित था, क्योंकि मंडल विरोध प्रदर्शनों का मुख्य केंद्र उत्तर भारत रहा था। बाकी अन्य कथन मंडल मुद्दे की सही और सटीक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं।

54. (B) नवंबर 1990 - जून 1991
चंद्रशेखर ने नवंबर 1990 से जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे राष्ट्रीय मोर्चा से अलग हुए एक गुट के नेता थे और उन्होंने कांग्रेस के बाहरी समर्थन से सरकार बनाई थी। हालांकि, यह सरकार बहुत कम समय तक चली क्योंकि कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद देश में दोबारा आम चुनाव हुए थे।

55. (D) कांग्रेस
1996 में एच.डी. देवगौड़ा के नेतृत्व में बनी संयुक्त मोर्चा सरकार को कांग्रेस पार्टी ने बाहर से समर्थन दिया था। यह एक गैर-भाजपाई और गैर-कांग्रेसी गठबंधन था, जिसमें कई क्षेत्रीय दल शामिल थे। कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य भाजपा को सत्ता से दूर रखना था, इसलिए उसने सैद्धांतिक मतभेदों के बावजूद इस गठबंधन को अपनी शर्तों पर बाहर से समर्थन देना स्वीकार किया था।

56. (A) 52
2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और उसकी सीटों की संख्या मात्र 52 रह गई। इस प्रदर्शन के कारण कांग्रेस लगातार दूसरी बार लोकसभा में आधिकारिक रूप से विपक्ष के नेता का पद प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीटें भी नहीं जुटा सकी। यह गिरावट पार्टी के लिए एक गंभीर नेतृत्व और सांगठनिक संकट का संकेत थी।

57. (C) बामसेफ का गठन
दिए गए विकल्पों में से 'बामसेफ' का गठन सबसे पहली घटना है, जो वर्ष 1978 में हुई थी। इसके बाद 1980 में भाजपा का गठन हुआ, 1985 में शाहबानो वाद हुआ और अंत में 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया

न्यायालय के फैसले के प्रभाव को कम कर दिया। इस कदम की व्यापक आलोचना हुई और इसे तुष्टिकरण की राजनीति के एक उदाहरण के रूप में देखा गया।

35. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
1986 का शाहबानो वाद और अयोध्या विवाद भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के केंद्र बिंदु बन गए थे। भाजपा ने कांग्रेस सरकार द्वारा शाहबानो मामले में कानून बदलने को 'अल्पसंख्यक तुष्टिकरण' बताया। साथ ही, पार्टी ने अयोध्या मुद्दे को राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर देशव्यापी समर्थन जुटाया, जिससे भारतीय राजनीति में धर्म और पहचान का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया।

36. (D) 1986
फरवरी 1986 में फैजाबाद जिला न्यायालय के आदेश पर अयोध्या स्थित विवादित ढांचे का ताला खोला गया था ताकि हिंदू श्रद्धालुओं को वहां पूजा-अर्चना करने की अनुमति मिल सके। इस फैसले के बाद राम जन्मभूमि आंदोलन को नई गति मिली और देश के विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव और लामबंदी की स्थिति पैदा हो गई, जिसने अंततः भारतीय राजनीति का रुख ही बदल दिया।

37. (C) 6 दिसम्बर 1992
अयोध्या में स्थित विवादित ढांचे को 6 दिसंबर 1992 को 'कारसेवकों' की एक बड़ी भीड़ द्वारा गिरा दिया गया था। इस घटना के बाद देश के कई हिस्सों में गंभीर सांप्रदायिक दंगे हुए और केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को बर्खास्त कर दिया। यह घटना स्वतंत्र भारत के इतिहास और राजनीति की सबसे विवादास्पद और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है।

38. (B) 9 नवम्बर 2019
अयोध्या विवाद पर उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने अपना ऐतिहासिक और अंतिम निर्णय 9 नवंबर 2019 को सुनाया था। न्यायालय ने विवादित स्थल को राम मंदिर निर्माण के लिए आवंटित करने और मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए अलग भूमि देने का आदेश दिया। इस फैसले ने दशकों से चले आ रहे एक जटिल कानूनी और राजनीतिक विवाद का अंत किया।

39. (D) सभी 1, 2, 3 और 4
सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या विवाद पर सर्वसम्मति से 5-0 के बहुमत से निर्णय दिया। कोर्ट ने पूरी विवादित भूमि राम मंदिर के लिए ट्रस्ट को सौंपने और सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए अयोध्या में ही पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। इस फैसले को भारतीय समाज के सभी वर्गों ने शांतिपूर्ण और परिपक्व तरीके से स्वीकार किया, जिससे सामाजिक समरसता बनी रही।

40. (A) भाजपा
1989 के बाद के समय को अक्सर भारतीय राजनीति में कांग्रेस के धीरे-धीरे पतन और भारतीय जनता पार्टी के उदय की अवधि के रूप में देखा जाता है। इस दौरान भाजपा ने अपनी चुनावी ताकत और जनाधार को तेजी से बढ़ाया। पार्टी ने छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ सफल गठबंधन किए, जिसके परिणामस्वरूप वह देश की राजनीति में कांग्रेस के एक सशक्त विकल्प के रूप में उभरी।

41. (C) 1996
1996 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार चुनावी इतिहास में कांग्रेस से अधिक सीटें जीती थीं। हालांकि कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही, लेकिन भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव प्राप्त हुआ। इसी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, भले ही उनकी वह सरकार बहुमत न जुटा पाने के कारण बहुत कम समय तक चली।

42. (A) संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग)
2004 के लोकसभा चुनावों के बाद केंद्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी 'संप्रग' की सरकार बनी। इस गठबंधन का नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया और डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। यह सरकार भाजपा के नेतृत्व वाले राजग को सत्ता से बाहर करने और एक वैकल्पिक एजेंडा पेश करने के लिए विभिन्न विचारधाराओं वाले दलों के आपसी सहयोग से बनाई गई थी।

43. (D) नेतृत्व कांग्रेस ने, समर्थन वाम मोर्चे ने
2004 में गठित संप्रग सरकार का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने किया था और उसे वाम मोर्चे ने बाहर से समर्थन प्रदान किया था। वामपंथी दलों ने भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए इस सरकार का समर्थन किया, हालांकि वे सरकार में सीधे तौर पर शामिल नहीं हुए। इस गठबंधन ने 'न्यूनतम साझा कार्यक्रम' के आधार पर दस वर्षों तक देश की शासन व्यवस्था संभाली।

44. (A) 4, 3, 2, 1
भारतीय गठबंधन सरकारों का सही कालानुक्रमिक क्रम 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा (वी.पी. सिंह) के गठन से शुरू होता है। इसके बाद 1996 में संयुक्त मोर्चा (देवगौड़ा) की सरकार बनी। फिर 1998 में पहली बार भाजपा के नेतृत्व में राजग सरकार का गठन हुआ और अंततः 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की सरकार अस्तित्व में आई थी।

45. (C) 2004
1991 के बाद से कांग्रेस पार्टी की सीटों की संख्या में लगातार गिरावट देखी जा रही थी। हालांकि, 2004 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने अपनी स्थिति में सुधार किया और उसकी सीटों की संख्या 114 से बढ़कर 145 हो गई। यह लंबे समय बाद पार्टी के लिए एक सकारात्मक चुनावी परिणाम था, जिसने उसे गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर केंद्र में सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया।

रिपोर्ट सौंपी, जिसमें पिछड़ा वर्ग को पिछड़ी जातियों के रूप में पहचाना गया। इसने सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27 प्रतिशत आरक्षण के साथ-साथ भूमि सुधारों का भी सुझाव दिया ताकि पिछड़ों की स्थिति में संरचनात्मक सुधार लाया जा सके।

24. (A) इंद्रा साहनी केस
मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के सरकार के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जो 'इंदिरा साहनी केस' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1992 में न्यायालय ने सरकार के फैसले को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया, लेकिन साथ ही आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की और 'क्रीमी लेयर' यानी संपन्न पिछड़ों को इससे बाहर रखने का निर्देश दिया।

25. (C) बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्पलाइज़ फेडरेशन
'बामसेफ' का पूरा नाम 'बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्पलाइज़ फेडरेशन' है। इसकी स्थापना 1978 में कांशीराम के नेतृत्व में की गई थी। यह मुख्य रूप से दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन था। इसने पिछड़ी और दलित जातियों के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए एक मजबूत वैचारिक आधार तैयार किया, जिसके परिणामस्वरूप बाद में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ।

26. (A) कांशीराम
बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम थे। उन्होंने दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को एक राजनीतिक मंच पर लाने के लिए इस दल का गठन किया था। कांशीराम ने 'बहुजन' की पहचान को मजबूत किया और चुनावी राजनीति में उनकी भागीदारी को एक नया आयाम दिया। उनके प्रयासों से विशेषकर उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति एक अत्यंत प्रभावशाली शक्ति के रूप में विकसित हुई।

27. (B) P-3, Q-2, R-1, S-4
भारतीय राजनीति में कांग्रेस प्रणाली का अंत मुख्य रूप से 1989 के चुनावों के साथ हुआ। मंडल मुद्दा 1990 में आरक्षण लागू करने के साथ अपने चरम पर था। गठबंधन सरकारों का दौर 1989 के बाद से निरंतर जारी रहा। दलित राजनीति का व्यवस्थित उभार और बामसेफ जैसी संस्थाओं का गठन 1980 के दशक की एक महत्वपूर्ण और दूरगामी राजनीतिक परिघटना मानी जाती है।

28. (B) अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और धार्मिक अल्पसंख्यक समूह
कांशीराम के अनुसार 'बहुजन' शब्द समाज के उस बड़े हिस्से को दर्शाता है जो सदियों से शोषण का शिकार रहा है। इसमें मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल थे। उनका मानना था कि ये सभी समूह मिलकर देश की आबादी का बहुसंख्यक हिस्सा बनाते हैं और संगठित होकर सत्ता की चाबी अपने हाथों में ले सकते हैं।

29. (C) उत्तर प्रदेश
बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी। कांशीराम के नेतृत्व में शुरू हुई यह पार्टी मायावती के काल में सत्ता के शिखर तक पहुँची। उत्तर प्रदेश में इस दल ने दलितों और पिछड़ों के मजबूत वोट बैंक के सहारे एक से अधिक बार अपनी सरकार बनाई, जिससे राज्य के राजनीतिक और सामाजिक समीकरण पूरी तरह बदल गए।

30. (D) बसपा को अपने शुरुआती दौर में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं का समर्थन हासिल था।
अपने शुरुआती दौर में बहुजन समाज पार्टी को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में दलित मतदाताओं का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ था। कांशीराम ने इन क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर कार्य किया और समुदायों को राजनीतिक रूप से जागरूक किया। हालांकि बाद के वर्षों में पार्टी का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश तक सिमट गया, लेकिन इसकी शुरुआत उत्तर भारतीय राज्यों के व्यापक संगठनात्मक कार्यों से हुई थी।

31. (A) पूर्ववर्ती जनसंघ
भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ के समर्थकों द्वारा किया गया था। जनता पार्टी के बिखरने के बाद, इसके जनसंघ घटक के सदस्यों ने 'हिंदुत्व' और 'राष्ट्रवाद' के सिद्धांतों के साथ एक नए दल की नींव रखी। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने। भाजपा ने धीरे-धीरे अपनी स्थिति मजबूत की और भारतीय राजनीति में एक प्रमुख शक्ति बन गई।

32. (B) विनायक दामोदर सावरकर
विनायक दामोदर सावरकर ने 'हिन्दुत्व' की अवधारणा को भारतीय राष्ट्रीयता के आधार के रूप में प्रतिपादित और लोकप्रिय किया था। उनकी व्याख्या के अनुसार, 'हिन्दू' वह है जो भारत को अपनी पितृभूमि और पुण्यभूमि दोनों मानता है। उनके विचारों ने बाद के वर्षों में दक्षिणपंथी राजनीति और संगठनों के वैचारिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया और भारतीय राष्ट्रवाद की एक विशिष्ट व्याख्या पेश की।

33. (B) मुस्लिम तलाकशुदा महिला के गुजारा भत्ता पाने का अधिकार
शाहबानो वाद 1985 का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी मामला था जो एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला के गुजारा भत्ता पाने के अधिकार से संबंधित था। उच्चतम न्यायालय ने उसके पक्ष में निर्णय देते हुए उसे अपने पूर्व पति से आर्थिक सहायता पाने का पात्र माना। इस निर्णय ने देश में धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों और लैंगिक न्याय के बीच एक बड़ी संवैधानिक बहस को जन्म दिया था।

34. (A) मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986
शाहबानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का कट्टरपंथी मुस्लिम समूहों ने विरोध किया, जिसके दबाव में तत्कालीन राजीव गाँधी सरकार ने 'मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986' पारित किया। इस कानून ने

गया था। बामसेफ ने ही दलित और पिछड़ी जातियों के संगठित राजनीतिक संघर्ष की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

58. (A) 1990 का दशक
1990 का दशक भारतीय राजनीति में बड़े बदलावों का समय था, जिसे 'कांग्रेस के पतन' और 'भाजपा के अभ्युदय' के रूप में देखा जाता है। इस दौरान कांग्रेस की चुनावी ताकत में निरंतर गिरावट आई, जबकि भाजपा ने मंदिर आंदोलन और गठबंधन राजनीति के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू की। इसी दशक में गठबंधन सरकारों का दौर पूरी तरह से भारतीय राजनीति पर हावी रहा।

59. (D) कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन उसे बहुमत नहीं मिला।
1989 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, लेकिन उसे सरकार बनाने के लिए आवश्यक स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। अपनी हार स्वीकार करते हुए कांग्रेस ने विपक्ष में बैठने का फैसला किया। इसके बाद जनता दल और अन्य क्षेत्रीय दलों ने मिलकर राष्ट्रीय मोर्चा बनाया, जिसे भाजपा और वाम मोर्चे के बाहरी समर्थन से सरकार बनाने का मौका मिला।

60. (A) P-3, Q-1, R-4, S-2
कर्पूरी ठाकुर बिहार में पिछड़ों के आरक्षण के बड़े पैरोकार थे। कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। वी.पी. सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कीं, जबकि लालकृष्ण आडवाणी ने राम जन्मभूमि आंदोलन के तहत रथ यात्रा निकाली थी। इन सभी नेताओं ने अपने-अपने स्तर पर 1990 के दशक की राजनीति को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

61. (C) भारत में शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन की व्यापकता का पता लगाना।
मंडल आयोग का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना और उनकी स्थिति का आकलन करना था। आयोग को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वह उन जातियों और समूहों का पता लगाए जिन्हें विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष प्रावधानों या आरक्षण की आवश्यकता है। इसकी रिपोर्ट ने बाद में सामाजिक न्याय की राजनीति को सशक्त किया।

62. (D) बहुजन समाज पार्टी (बसपा)
कांशीराम द्वारा स्थापित 'दलित-शोषित समाज संघर्ष समिति' (डीएस-4) का परवर्ती विकास बहुजन समाज पार्टी के रूप में हुआ। डीएस-4 ने दलितों और पिछड़ों के अधिकारों के लिए सामाजिक चेतना पैदा करने का कार्य किया, जिसे बाद में बसपा ने एक राजनीतिक दल के रूप में आगे बढ़ाया। इस आंदोलन ने सत्ता में 'बहुजन' की हिस्सेदारी को एक अनिवार्य लोकतांत्रिक मांग के रूप में स्थापित किया।

63. (A) केवल 1, 2 और 4
1980 में भाजपा का गठन जनसंघ के समर्थकों द्वारा किया गया था और शुरुआत में इसने 'गांधीवादी समाजवाद' को अपनाया। हालांकि, 1984 के चुनावों में पार्टी को केवल दो सीटें मिलीं, जिसके बाद 1986 से पार्टी ने 'हिन्दुत्व' की राजनीति और राम जन्मभूमि मुद्दे पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरु किया। इस वैचारिक बदलाव ने पार्टी को व्यापक हिंदू जनसमर्थन और राजनीतिक मजबूती प्रदान की।

64. (B) भारतभूमि को 'पितृभूमि' और 'पुण्यभूमि' दोनों के रूप में स्वीकार करना
विनायक दामोदर सावरकर के अनुसार, एक सच्चा भारतीय या हिन्दू वह है जो भारत को न केवल अपनी 'पितृभूमि' मानता है, बल्कि उसे अपनी 'पुण्यभूमि' के रूप में भी स्वीकार करता है। उनकी यह परिभाषा धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीयता के साथ गहराई से जोड़ती है, जो उनकी हिन्दुत्व की विचारधारा का मूल आधार है और भारतीय राष्ट्रवाद की एक विशिष्ट व्याख्या पेश करती है।

65. (B) केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर
1989 से 2014 तक की लंबी अवधि के दौरान भारतीय राजनीति की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति केंद्र में गठबंधन सरकारों का अस्तित्व था। इस पूरे दौर में किसी भी एक दल को लोकसभा में अकेले पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय दलों को सरकार बनाने और चलाने के लिए कई क्षेत्रीय दलों के सहयोग और समर्थन पर निर्भर रहना पड़ा, जिसने शासन की शैली बदल दी।

66. (C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
1990 के दशक में भारत ने वास्तव में नए आर्थिक सुधारों को अपनाया, लेकिन यह कहना गलत है कि उन्हें सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। कई वामपंथी संगठनों, श्रमिक संघों और कुछ राजनीतिक दलों ने इन सुधारों का कड़ा विरोध किया था। उनका तर्क था कि उदारीकरण और निजीकरण से गरीबों का शोषण बढ़ेगा और देश की आर्थिक संप्रभुता को खतरा पैदा हो सकता है।

67. (C) डॉ. मनमोहन सिंह
2004 और 2009 के लोकसभा चुनावों के बाद बनी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह थे। वे एक प्रख्यात अर्थशास्त्री थे और उनके नेतृत्व में भारत ने उच्च आर्थिक विकास दर हासिल की। उनके कार्यकाल में सूचना का अधिकार और नरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गईं, जिन्होंने सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में एक नया प्रतिमान स्थापित किया।

68. (D) तीन दशकों के लंबे अंतराल के पश्चात् किसी एकल दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ
2014 के लोकसभा चुनावों को ऐतिहासिक इसलिए माना जाता है क्योंकि भारतीय राजनीति के तीन दशकों के लंबे अंतराल के बाद किसी एक राजनीतिक दल (भाजपा) को अपने दम पर पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। 1984 के बाद यह पहली बार था

जब गठबंधन की मजबूरियों से मुक्त होकर किसी दल ने सत्ता संभाली। इस परिणाम ने देश में राजनीतिक स्थिरता के एक नए युग का सूत्रपात किया।

69. (C) देश में राष्ट्रपति प्रणाली लागू करने पर सहमति।
समकालीन भारतीय राजनीति में आर्थिक नीतियों, पिछड़ी जातियों के अधिकारों और क्षेत्रीय दलों की भूमिका पर व्यापक सहमति बनी है। हालांकि, देश में संसदीय शासन प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रपति प्रणाली लागू करने को लेकर ऐसी कोई सर्व-सहमति या बड़ा विमर्श मौजूद नहीं है। भारत अपनी पारंपरिक संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही निरंतर बनाए रखने और उसे मजबूत करने के पक्ष में रहा है।

70. (A) 2, 1, 4, 3
इन घटनाओं का सही क्रम बामसेफ के गठन (1978) से शुरु होता है। इसके बाद 1978 के अंत में मंडल आयोग नियुक्त किया गया। 1979 में जनता पार्टी सरकार का पतन हुआ और अंततः 1980 में भारतीय जनता पार्टी का औपचारिक रूप से गठन हुआ था। यह कालखंड भारतीय राजनीति में नई शक्तियों के उभार और पुराने समीकरणों के टूटने का समय था।

71. (D) भाजपा और वाम मोर्चा द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण
1989 में बनी वी.पी. सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार मुख्य रुप से भाजपा और वाम मोर्चे के बाहरी समर्थन पर टिकी थी। जब भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को बिहार में रथ यात्रा के दौरान गिरफ्तार किया गया, तो भाजपा ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके परिणामस्वरूप सरकार संसद में अपना बहुमत खो बैठी और अल्पमत में आने के कारण गिर गई।

72. (B) P-3, Q-4, R-2, S-1
1984 में इंदिरा गाँधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस ने ऐतिहासिक 415 सीटें जीतीं। 1989 में कांग्रेस की हार हुई और गठबंधन राजनीति का दौर शुरु हुआ। 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संप्रग की सरकार बनी और 2014 में भाजपा ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। ये वर्ष भारतीय चुनावी राजनीति के प्रमुख मील के पत्थर माने जाते हैं जिन्होंने समय-समय पर सत्ता का स्वरुप बदला।

73. (C) कर्पूरी ठाकुर
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को उत्तर भारत में पिछड़ी जातियों के आरक्षण के सबसे मुखर और प्रभावी समर्थकों में से एक माना जाता है। उन्होंने बिहार में पिछड़ों के लिए आरक्षण की एक विशेष व्यवस्था लागू की थी, जिसे 'कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला' के नाम से जाना जाता है। उनके इन क्रांतिकारी कदमों ने बाद में राष्ट्रीय स्तर पर मंडल आयोग की सिफारिशों के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

74. (A) इसने सरकार के OBC आरक्षण के निर्णय को सही ठहराया।
1992 के इंदिरा साहनी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को दिए गए 27 प्रतिशत आरक्षण के निर्णय को संवैधानिक रूप से सही ठहराया। हालांकि, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि आरक्षण का लाभ केवल उन लोगों को मिलना चाहिए जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, और इसके लिए 'क्रीमी लेयर' का सिद्धांत लागू करने का निर्देश दिया गया था।

75. (D) राजनीतिक समीकरण अत्यंत अस्थिर थे, जिसमें दल अक्सर अपनी भूमिकाएं बदलते रहते थे
1990 के दशक की गठबंधन राजनीति की सबसे प्रमुख विशेषता राजनीतिक अस्थिरता और दलों के बदलते समीकरण थे। इस दौर में कई अल्पकालिक सरकारें बनीं और गिरीं, क्योंकि छोटे दल अक्सर अपनी मांगों को लेकर समर्थन वापस ले लेते थे। विचारधारा से अधिक सत्ता के तालमेल पर ध्यान दिया जाता था, जिससे राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रकार की निरंतर अनिश्चितता का वातावरण बना रहा।

76. (B) 1989 की सरकार - राष्ट्रीय मोर्चा (कांग्रेस का समर्थन)
1989 की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के बारे में यह कहना गलत है कि उसे कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। वास्तव में, यह सरकार कांग्रेस के विरोध में बनी थी और इसे भाजपा तथा वाम मोर्चे ने बाहर से समर्थन दिया था। अन्य सभी विकल्प सही हैं, जैसे 1996 की सरकार को कांग्रेस का समर्थन मिला था और 2004 की संप्रग सरकार को वामपंथियों ने समर्थन दिया था।

77. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
1990 के दशक से भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली का उदय हुआ क्योंकि अब किसी एक या दो दलों का प्रभुत्व नहीं रहा। मतदाता विभिन्न क्षेत्रीय और पहचान-आधारित दलों की ओर आकर्षित हुए, जिससे चुनावी जनादेश बंट गया। इस स्थिति में, किसी भी दल के लिए अकेले बहुमत पाना लगभग असंभव हो गया, जिसके कारण केंद्र में मिली-जुली सरकारों का गठन अनिवार्य हो गया।

78. (D) इस सरकार ने अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा किया।
1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी राजग (एनडीए) सरकार भारतीय गठबंधन राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी क्योंकि इसने सफलतापूर्वक अपना पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। 1989 के बाद यह पहली ऐसी गठबंधन सरकार थी जिसने स्थिरता प्रदान की और अगले आम चुनावों तक शासन किया। इसने यह सिद्ध किया कि गठबंधन सरकारें भी स्थिर हो सकती हैं।

79. (A) 1978
'बामसेफ' का गठन वर्ष 1978 में हुआ था। यह संगठन मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के शिक्षित सरकारी कर्मचारियों का एक महासंघ था। इसका उद्देश्य इन समुदायों के हितों की रक्षा करना और उन्हें राजनीतिक रूप से संगठित करना था। इसी संगठन के माध्यम से कांशीराम ने बाद में बहुजन समाज पार्टी के लिए एक मजबूत और समर्पित कार्यकर्ताओं का आधार तैयार किया।

80. (A) केवल 1, 2 और 4
गठबंधन युग की शुरुआत 1989 से हुई और इसमें क्षेत्रीय दलों की भूमिका अत्यंत प्रभावी रही। इस दौर में सरकारें अक्सर अल्पमत में होती थीं या अन्य दलों के समर्थन पर निर्भर रहती थीं। हालांकि, 2014 में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी गठबंधन की प्रवृत्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि भाजपा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर शासन करना जारी रखा है।

81. (B) यह एआईडीएमके तथा अन्य दलों के समर्थन से संचालित होने वाली एक अल्पमत की सरकार थी
1991 के चुनाव के बाद बनी पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार अपनी प्रकृति में एक अल्पमत की सरकार थी। कांग्रेस के पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं था, इसलिए उसे एआईडीएमके जैसे अन्य दलों के समर्थन पर निर्भर रहना पड़ा। इसके बावजूद, इस सरकार ने आर्थिक उदारीकरण के साहसिक निर्णय लिए और अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा किया, जो उस समय की परिस्थितियों में एक बड़ी उपलब्धि थी।

82. (A) 27%
मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की स्थिति को सुधारने के लिए सरकारी नौकरियों में उनके लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी। आयोग का मानना था कि पिछड़ी जातियों का सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व उनकी आबादी के अनुपात में बहुत कम है। इस आरक्षण को लागू करने के बाद भारतीय समाज के शक्ति संतुलन और चुनावी राजनीति में व्यापक बदलाव आए और पिछड़ी जातियों का उभार हुआ।

83. (C) कांग्रेस (आई)
1989 में राष्ट्रीय मोर्चा का गठन ही मुख्य रूप से कांग्रेस (आई) के विरोध में किया गया था, इसलिए कांग्रेस इस गठबंधन का हिस्सा नहीं हो सकती थी। राष्ट्रीय मोर्चा में जनता दल और विभिन्न क्षेत्रीय दल शामिल थे, जिन्हें भाजपा और वाम मोर्चे ने बाहर से समर्थन दिया था ताकि कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखा जा सके। यह भारतीय राजनीति में कांग्रेस विरोधी मोर्चाबंदी का एक प्रमुख उदाहरण था।

84. (B) P-3, Q-4, R-1, S-2
कांग्रेस प्रणाली का संबंध नेहरू और इंदिरा गाँधी के दौर से है। एक-दलीय प्रभुत्व का अंत 1989 के ऐतिहासिक चुनावों के साथ हुआ। मंडल राजनीति को वी.पी. सिंह ने अपनी सरकार के निर्णयों के माध्यम से गति प्रदान की, जबकि हिंदुत्व की राजनीति और मंदिर आंदोलन का नेतृत्व लालकृष्ण आडवाणी और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने किया था, जिससे भारतीय राजनीति में व्यापक ध्रुवीकरण हुआ।

85. (C) प्रमुख नीतिगत मुद्दों पर अधिकांश दल समान विचार रखते हैं, जिससे व्यापक बदलाव की गुंजाइश कम है
नीतिगत मामलों पर सर्व-सहमति का अर्थ है कि देश के अधिकांश प्रमुख राजनीतिक दल अब महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक नीतियों पर समान विचार रखते हैं। उदाहरण के लिए, अब लगभग सभी दल नई आर्थिक नीति और पिछड़ों के आरक्षण के समर्थक हैं। इस सहमति के कारण सरकार बदलने पर भी बुनियादी नीतियों में बहुत बड़े और क्रांतिकारी बदलावों की संभावना कम हो गई है।

86. (B) अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करना।
राम जन्मभूमि आंदोलन का मुख्य और घोषित उद्देश्य अयोध्या में विवादित स्थल पर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण करना था। हिंदू संगठनों का मानना था कि वह स्थान भगवान राम की जन्मस्थली है। इस आंदोलन ने न केवल धार्मिक भावनाओं को आंदोलित किया, बल्कि इसने भारतीय जनता पार्टी को एक प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

87. (A) केवल 1, 2, 3 और 4
1989 के बाद भारतीय राजनीति में गठबंधन का दौर शुरू हुआ, मंडलीकरण ने पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया और राम जन्मभूमि आंदोलन ने धर्मनिरपेक्षता पर नई बहस छेड़ी। साथ ही, आर्थिक नीतियों पर दलों के बीच एक नई सहमति भी उभरी। यह कहना गलत होगा कि कांग्रेस प्रणाली मजबूत हुई, क्योंकि वास्तव में इसी कालखंड में कांग्रेस के प्रभुत्व का निरंतर ह्रास हुआ था।

88. (A) लगभग 13 दिन
1996 के लोकसभा चुनावों के बाद भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि, उनकी यह सरकार केवल 13 दिनों तक ही चल सकी क्योंकि वे संसद में अन्य दलों का आवश्यक समर्थन और विश्वास मत प्राप्त करने में विफल रहे। इसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और संयुक्त मोर्चा की सरकार अस्तित्व में आई थी।

89. (C) बहुजन समाज पार्टी
1989 और 1991 के चुनावों में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। पार्टी का मुख्य आधार दलित मतदाता थे, जिन्हें कांशीराम ने संगठित किया था। बसपा ने कांग्रेस के पारंपरिक दलित वोट बैंक में सेंध लगाई, जिससे राज्य की राजनीति में दलित एक स्वतंत्र और निर्णायक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे और सत्ता के समीकरण बदल गए।

90. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
1996 में कांग्रेस ने अपनी धुर विरोधी क्षेत्रीय पार्टियों के गठबंधन 'संयुक्त मोर्चा' को बाहर से समर्थन दिया था। इसका एकमात्र बड़ा कारण यह था कि कांग्रेस और वाम मोर्चा किसी भी कीमत पर भाजपा को सत्ता में आने से रोकना चाहते थे। वैचारिक मतभेदों के बावजूद, भाजपा को दूर रखने के साझा राजनीतिक हित ने इन दलों को एक साथ आने के लिए मजबूर किया था।

91. (D) भारत-अमेरिका परमाणु समझौता
वर्ष 2008 में संप्रग-1 सरकार और अमेरिका के बीच हुए परमाणु समझौते के विरोध में वामपंथी दलों ने सरकार से

अपना समर्थन वापस ले लिया था। वामपंथियों का मानना था कि यह समझौता भारत की स्वायत्त विदेश नीति और संप्रभुता के खिलाफ है। इसके बाद मनमोहन सिंह सरकार को संसद में विश्वास मत का सामना करना पड़ा, जिसे वह अन्य दलों के समर्थन से जीतने में सफल रही थी।

92. (B) द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK)
2019 के लोकसभा चुनावों में, विपक्षी दलों के बीच कांग्रेस के बाद द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तमिलनाडु में शानदार प्रदर्शन करते हुए डीएमके ने 23 सीटें जीतीं। यह परिणाम दक्षिण भारत में क्षेत्रीय दलों की मजबूती और राष्ट्रीय राजनीति में उनकी निरंतर प्रासंगिकता को दर्शाता है, विशेषकर तब जब मुख्य राष्ट्रीय विपक्षी दल कमजोर स्थिति में था।

93. (C) जनता दल
जनता दल वह प्रमुख पार्टी थी जो 1989 की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार और 1996 की संयुक्त मोर्चा सरकार, दोनों में एक केंद्रीय स्तंभ के रूप में शामिल थी। दोनों ही बार जनता दल ने विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों को एक साथ लाने और कांग्रेस व भाजपा के विकल्प के रूप में गैर-कांग्रेसी, गैर-भाजपाई मोर्चा बनाने का सफल प्रयास किया, जिसमें प्रधानमंत्री भी इसी दल से चुने गए।

94. (A) 3, 1, 2, 4
इन घटनाओं का सही क्रम 2004 में संप्रग-I सरकार के गठन से शुरु होता है। इसके बाद 2008 में भारत-अमेरिका परमाणु समझौता हुआ। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला और अंततः 2019 में भाजपा ने दोबारा बड़ी जीत हासिल की। यह क्रम भारतीय राजनीति में गठबंधन के दौर से एक-दलीय बहुमत की वापसी को दर्शाता है।

95. (A) विचारधारा पर आधारित कठोर राजनीतिक गठजोड़।
1980 के दशक के बाद उभरी 'नयी सहमति' की एक प्रमुख विशेषता यह है कि राजनीतिक गठबंधन अब विचारधारा की बजाय कार्यसिद्धि और सत्ता की भागीदारी पर आधारित होने लगे हैं। इसलिए, कठोर वैचारिक राजनीतिक गठजोड़ अब इस दौर की पहचान नहीं रहे। इसके बजाय, अलग-अलग विचारधारा वाले दल भी साझा शासन कार्यक्रम के लिए एक साथ आने में संकोच नहीं करते हैं।

96. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
1989 में वी.पी. सिंह ने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया। 2004 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में संप्रग सरकार बनी। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने राजग सरकार का कार्यभार संभाला और 1996 में एच.डी. देवगौड़ा संयुक्त मोर्चा के प्रधानमंत्री बने थे। ये विभिन्न नेतृत्व भारत में गठबंधन की राजनीति के विविध चरणों और उनके स्वरूपों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।

97. (B) भाजपा ने राजग सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाने के विकल्प को प्राथमिकता दी
2014 के बाद भाजपा के पास अकेले पूर्ण बहुमत होने के बावजूद गठबंधन की प्रासंगिकता बनी रही क्योंकि पार्टी ने अपने राजग सहयोगियों को सरकार में शामिल करना उचित समझा। यह रणनीति समावेशी शासन और भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं को ध्यान में रखकर अपनाई गई। इससे स्पष्ट होता है कि बहुमत के दौर में भी सहयोगियों के साथ मिलकर चलना भारतीय संसदीय राजनीति की विशेषता बन गई है।

98. (A) गठबंधन की सरकारों के युग की राजनीति
1980 के दशक के बाद भारतीय समाज में आए गहरे सामाजिक और आर्थिक बदलावों ने गठबंधन की सरकारों के युग को जन्म दिया। जातिगत पहचान के उभार और क्षेत्रीय आकांक्षाओं ने राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य को बदल दिया। अब मतदाता किसी एक दल को पूर्ण समर्थन देने के बजाय अपनी स्थानीय और पहचान-आधारित पार्टियों को प्राथमिकता देने लगे, जिससे केंद्र में गठबंधन सरकारों का बनना आवश्यक हो गया।

99. (C) जन आंदोलनों के ज़रिए
1990 के बाद गरीबी, विस्थापन और सामाजिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मानवीय मुद्दे मुख्य रूप से जन आंदोलनों के माध्यम से राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बने। नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे कई नागरिक समूहों ने इन बुनियादी सवालों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। इन आंदोलनों ने यह सुनिश्चित किया कि शासन और विकास के विमर्श में केवल आंकड़े ही नहीं, बल्कि आम जनता के जीवन से जुड़े संघर्ष भी शामिल हों।

100. (D) राजीव गाँधी की हत्या के बाद उपजी सहानुभूति की लहर
1991 के आम चुनावों में कांग्रेस के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने का तात्कालिक और प्रमुख कारण राजीव गाँधी की दुखद हत्या के बाद देश भर में उपजी सहानुभूति की लहर थी। चुनाव के बीच में हुई इस घटना ने मतदाताओं के मन को प्रभावित किया और कांग्रेस को उन सीटों पर भी जीत मिली जहाँ उसकी स्थिति कमजोर थी। इसी जनादेश के आधार पर बाद में नरसिम्हा राव सरकार का गठन हुआ।

101. (C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
1989 के चुनाव ने भारतीय राजनीति में कांग्रेस के दशकों पुराने एक-दलीय दबदबे का अंत कर दिया। हालांकि, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि कोई दूसरा दल, जैसे कि भाजपा, तुरंत उस स्थान पर काबिज हो गया। वास्तव में, 1989 से 2014 तक का समय किसी एक दल के वर्चस्व का नहीं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के आपसी गठजोड़ और साझा शासन का दौर था।

102. (B) भारतीय क्रांतिदल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी
1977-79 की जनता पार्टी सरकार के भीतर भारतीय क्रांतिदल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ऐसे दो प्रमुख घटक थे जिनका ग्रामीण इलाकों की पिछड़ी जातियों में बहुत मजबूत आधार था। इन दलों ने किसानों और ग्रामीण पिछड़ों के हितों को

राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लाने का कार्य किया। इन्हीं शक्तियों के दबाव और प्रयासों के परिणामस्वरूप बाद में मंडल आयोग जैसे ऐतिहासिक कदम उठाए जा सके थे।

103. (D) पिछड़ी जातियों की राजनीतिक सक्रियता और सत्ता में उनकी हिस्सेदारी के विस्तार को बढ़ावा मिला
'मंडलीकरण' ने भारतीय राजनीति में पिछड़ी जातियों की सक्रियता और सत्ता में उनकी हिस्सेदारी को अभूतपूर्व तरीके से बढ़ावा दिया। इसने चुनावी विमर्श को बदलकर जातिगत न्याय और प्रतिनिधित्व के इर्द-गिर्द केंद्रित कर दिया। समाज के वे वर्ग जो पहले निर्णय प्रक्रिया से बाहर थे, अब न केवल वोट बैंक बल्कि शासन में सक्रिय भागीदार के रूप में उभरे, जिससे भारतीय लोकतंत्र का आधार और अधिक समावेशी हुआ।

104. (D) सभी 1, 2, 3 और 4
1989 के बाद भारतीय संसद में किसी एक दल को बहुमत न मिलने के कारण गठबंधन सरकारों का लंबा दौर चला। इसमें क्षेत्रीय पार्टियों ने सरकार बनाने और उसे स्थिर रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि, 2014 और 2019 में भाजपा को अकेले बहुमत प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी गठबंधन की संस्कृति देश की राजनीति में एक मजबूत तत्व के रूप में अब भी विद्यमान है।

105. (C) कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना
1989 में भाजपा और वाम मोर्चा ने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को बाहर से समर्थन केवल इसलिए दिया था क्योंकि वे कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना चाहते थे। इन दोनों समूहों के बीच वैचारिक रूप से जमीन-आसमान का अंतर था, लेकिन कांग्रेस विरोधी साझा राजनीतिक उद्देश्य ने उन्हें एक ही सरकार का समर्थन करने के लिए मजबूर किया। यह भारतीय राजनीति में वैचारिक लचीलेपन और व्यावहारिक तालमेल का उदाहरण है।

106. (A) वर्ण व्यवस्था में निम्न मानी जाने वाली एससी से इतर जातियाँ
मंडल आयोग ने जिन 'पिछड़ी जातियों' की पहचान की, वे मुख्य रूप से वे समूह थे जो हिंदू वर्ण व्यवस्था में निचली श्रेणी में माने जाते थे, लेकिन वे अनुसूचित जाति (SC) का हिस्सा नहीं थे। आयोग ने पाया कि ये जातियाँ सामाजिक और शैक्षिक रूप से अत्यंत पिछड़ी हुई हैं और सरकारी सेवाओं में उनकी उपस्थिति नगण्य है। इसी आधार पर उन्हें आरक्षण देकर सशक्त करने की सिफारिश की गई थी।

107. (B) P-3, Q-4, R-1, S-2
जनता दल यूनाइटेड (जद-यू) मुख्य रूप से बिहार की राजनीति में सक्रिय है। डीएमके तमिलनाडु का एक प्रमुख द्रविड़ दल है। शिवसेना का जनाधार महाराष्ट्र में केंद्रित है, जबकि बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत और प्रभाव उत्तर प्रदेश में रहा है। ये क्षेत्रीय दल अपने राज्यों की विशिष्ट पहचान और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं।

108. (B) मंडल, मंदिर, मार्केट (बाजार)
1990 के दशक की भारतीय राजनीति को अक्सर 'तीन M' यानी मंडल, मंदिर और मार्केट (बाजार) के रूप में परिभाषित किया जाता है। 'मंडल' आरक्षण और पिछड़ी जातियों के उभार का प्रतीक है, 'मंदिर' अयोध्या विवाद और धार्मिक राजनीति को दर्शाता है, और 'मार्केट' 1991 में शुरू हुए नए आर्थिक सुधारों की ओर संकेत करता है। इन तीनों मुद्दों ने मिलकर आधुनिक भारत की दिशा तय की।

109. (C) अल्पसंख्यक समुदाय को वोट बैंक मानकर दी जाने वाली अनावश्यक रियायतें
भारतीय राजनीति में 'तुष्टिकरण' के आरोप का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी दल पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह अल्पसंख्यक समुदायों को केवल वोट बैंक मानकर उन्हें अनुचित रियायतें दे रहा है। भाजपा ने अक्सर कांग्रेस पर शाहबानो जैसे मामलों में कट्टरपंथियों के आगे झुकने और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तुष्टिकरण करने का आरोप लगाया है, जिससे राजनीतिक विमर्श प्रभावित हुआ है।

110. (C) लालकृष्ण आडवाणी
1990 के दशक में पी. वी. नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा और इंद्रकुमार गुजराल ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। लालकृष्ण आडवाणी इस दौरान भाजपा के एक अत्यंत शक्तिशाली नेता और बाद में उप-प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन वे कभी देश के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन नहीं हुए। इस दशक में नेतृत्व अक्सर गठबंधन के समीकरणों के आधार पर बदलता रहता था।

111. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
1990 के दशक के बाद की गठबंधन राजनीति में विचारधारा का महत्व कम हो गया और सत्ता में हिस्सेदारी मुख्य उद्देश्य बन गई। इसका सबसे प्रबल उदाहरण यह है कि जब भाजपा के नेतृत्व में राजग सरकार बनी, तो 'हिन्दुत्व' से असहमत कई क्षेत्रीय दल भी केवल शासन में भागीदारी के लिए उसके साथ शामिल हुए। यह व्यावहारिक राजनीति के युग की शुरुआत का संकेत था।

112. (A) केवल 1, 2, 3 और 4
1990 के बाद कांग्रेस का वर्चस्व घटा, पिछड़ों का राजनीतिक उत्थान हुआ और धार्मिक पहचान की राजनीति मजबूत हुई। साथ ही, आर्थिक उदारीकरण पर अधिकांश दलों में एक साझा सहमति विकसित हुई। यह कहना गलत है कि भारत में दो-दलीय व्यवस्था स्थापित हो गई है, क्योंकि वास्तव में बहुदलीय व्यवस्था और क्षेत्रीय दलों का प्रभाव आज भी राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण बना हुआ है।

113. (B) क्षेत्रीय दलों की भागीदारी से राज्यों के महत्त्व और स्वायत्तता में वृद्धि हुई
1989 के बाद शुरू हुई गठबंधन राजनीति ने केंद्र-राज्य संबंधों में राज्यों की भूमिका को काफी मजबूत कर दिया। चूंकि केंद्र सरकार को टिकाए रखने के लिए क्षेत्रीय दलों के समर्थन की

आवश्यकता होती थी, इसलिए राज्यों की मांगों और उनकी स्वायत्तता को अधिक महत्व दिया जाने लगा। अब केंद्र अपनी मर्जी राज्यों पर आसानी से नहीं थोप सकता था, जिससे भारत का संघीय ढांचा अधिक संतुलित हुआ।

114. (A) लोकतांत्रिक समाज में विवादों का हल विधि की उचित प्रक्रिया से संभव है
अयोध्या विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय के 2019 के निर्णय ने यह सिद्ध किया कि एक जीवंत लोकतंत्र में अत्यंत जटिल और संवेदनशील धार्मिक विवादों का समाधान भी कानून की उचित प्रक्रिया के माध्यम से संभव है। इस फैसले ने न्यायपालिका की निष्पक्षता और संवैधानिक सर्वोच्चता को स्थापित किया, और यह संदेश दिया कि शांतिपूर्ण संवाद और कानूनी मार्ग ही लोकतांत्रिक समाज में विवादों के हल का सर्वश्रेष्ठ तरीका है।

115. (C) 1999 में बनी अटल बिहारी वाजपेयी की राजग सरकार
1999 में बनी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार गठबंधन के दौर की पहली ऐसी सरकार थी जिसने अपना पूरा पांच साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक संपन्न किया। इससे पहले की राष्ट्रीय मोर्चा और संयुक्त मोर्चा जैसी सरकारें आंतरिक मतभेदों और समर्थन वापसी के कारण बीच में ही गिर गई थीं। वाजपेयी की इस सफलता ने भारतीय राजनीति में गठबंधन स्थिरता के प्रति विश्वास पैदा किया।

116. (D) 1989 का चुनाव
1989 के लोकसभा चुनावों को भारत में 'गठबंधन के युग' की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। इस चुनाव के बाद कांग्रेस का एक-दलीय वर्चस्व समाप्त हो गया और किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। यहाँ से केंद्र में ऐसी सरकारों का सिलसिला शुरु हुआ जो कई दलों के आपसी सहयोग पर निर्भर थीं, और यह स्थिति 2014 के चुनावों तक निरंतर बनी रही।

117. (B) P-3, Q-4, R-1, S-2
शाहबानो वाद ने पर्सनल लॉ और लैंगिक न्याय के मुद्दों को उभारा। बामसेफ सरकारी कर्मचारियों का एक प्रभावशाली संगठन था जिसने दलित हितों के लिए कार्य किया। इंदिरा साहनी केस का मुख्य संबंध ओबीसी आरक्षण की वैधता से था। संप्रग (UPA) भारतीय राजनीति में एक प्रमुख गठबंधन सरकार का उदाहरण है जिसने कांग्रेस के नेतृत्व में दस वर्षों तक देश पर शासन किया।

118. (B) बामसेफ और बसपा
दलित पैंथर्स आंदोलन के शिथिल होने के बाद, दलित अधिकारों और राजनीतिक लामबंदी का नेतृत्व कांशीराम द्वारा स्थापित 'बामसेफ' और बाद में 'बहुजन समाज पार्टी' ने किया। इन संगठनों ने दलितों को केवल एक वोट बैंक के रूप में नहीं, बल्कि सत्ता में हिस्सेदार एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित किया, जिससे विशेषकर उत्तर भारत की राजनीति में दूरगामी परिवर्तन आए।

119. (D) कांग्रेस पार्टी का पूर्ण रूप से विघटन।
1990 के दशक में कांग्रेस के कमजोर होने का अर्थ उसके चुनावी प्रदर्शन में गिरावट और दलीय व्यवस्था में उसके वर्चस्व का अंत था। इसका अर्थ यह कदापि नहीं था कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह समाप्त या विघटित हो गई थी। वह अब भी एक प्रमुख राष्ट्रीय दल बनी रही और बाद में 2004 में गठबंधन के सहारे सत्ता में वापसी करने में सफल रही थी।

120. (A) राजग और संप्रग को मिले कुल वोटों का अंतर बड़ा कम था।
2004 के लोकसभा चुनाव परिणामों की एक दिलचस्प विशेषता यह थी कि संप्रग और राजग को मिले कुल वोटों का अंतर बहुत कम था। हालांकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन भाजपा से उसका सीटों का अंतर भी बहुत बड़ा नहीं था। इस नजदीकी मुकाबले ने यह दिखाया कि भारतीय मतदाता विभिन्न विकल्पों के बीच बंटा हुआ था और छोटे दलों का महत्व निर्णायक हो गया था।

121. (B) केवल 1, 2 और 3
1989 के बाद गठबंधन राजनीति में विचारधारा की जगह सत्ता में हिस्सेदारी प्रमुख हो गई है और नई आर्थिक नीतियों पर अधिकांश दलों में एक मौन सहमति है। पिछड़ों के आरक्षण और उनके सामाजिक दावों को भी अब लगभग सभी दल स्वीकार करते हैं। यह कहना गलत है कि प्रांतीय दलों की भूमिका सीमित हुई है, क्योंकि वे राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाने में महत्वपूर्ण रहे हैं।

122. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
1990 का दशक भारतीय राजनीति में जबरदस्त उथल-पुथल का दौर था क्योंकि इसी दौरान मंडल आयोग का आरक्षण, राम मंदिर आंदोलन और नए आर्थिक सुधार जैसी तीन बड़ी घटनाएं एक साथ घटित हुईं। इन मुद्दों ने समाज के विभिन्न वर्गों को गहराई से प्रभावित किया और राजनीति की पूरी दिशा ही बदल दी, जिससे देश एक बिल्कुल नए और चुनौतीपूर्ण दौर में प्रवेश कर गया।

123. (D) 11
1989 से 1999 के बीच का दशक भारतीय संसदीय लोकतंत्र के लिए अत्यंत अस्थिर रहा, जिसमें कुल 11 सरकारें या नेतृत्व परिवर्तन देखे गए। इस दौरान कोई भी सरकार अपना कार्यकाल सहजता से पूरा नहीं कर पाई और बार-बार विश्वास मत या समर्थन वापसी की स्थितियाँ पैदा हुईं। यह कालखंड गठबंधन राजनीति की अस्थिरता और राजनीतिक दलों के बीच बदलते शक्ति समीकरणों का सबसे बड़ा उदाहरण है।

124. (B) एससी/एसटी और ओबीसी समूहों के लिए आरक्षण और सत्ता में हिस्सेदारी से
1980 के दशक के बाद भारतीय राजनीति में 'सामाजिक न्याय' शब्द मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तथा सत्ता में उनकी प्रभावी हिस्सेदारी से जुड़ गया। इसका उद्देश्य उन समुदायों को

मुख्यधारा में लाना था जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़ गए थे। इस राजनीति ने पारंपरिक सत्ता संरचना को चुनौती दी और देश के लोकतांत्रिक आधार को सामाजिक रूप से अधिक व्यापक बनाया।

125. (A) 5, 1, 4, 2, 3
इन प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल का सही क्रम चंद्रशेखर (1990-91) से शुरु होता है, जिसके बाद पी.वी. नरसिम्हा राव (1991-96) आए। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने 1996 में पहली बार 13 दिन के लिए कमान संभाली। उनके बाद एच.डी. देवगौड़ा और अंततः इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने। यह क्रम भारतीय राजनीति में अल्पकालिक सरकारों और बदलते नेतृत्व के दौर को भली-भांति प्रदर्शित करता है।

126. (D) चुनावी गिरावट के बाद भी देश पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला दल रहा
1990 के दशक में कांग्रेस की ताकत में गिरावट आने के बावजूद वह अन्य दलों से इस मायने में भिन्न रही कि वह देश पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राष्ट्रीय दल बना रहा। गिरावट के दौर में भी उसका सांगठनिक ढांचा पूरे देश में फैला हुआ था। इसी व्यापक पहुंच के कारण पार्टी ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी खुद को प्रासंगिक बनाए रखा और बाद में सत्ता हासिल करने में सफल रही।

127. (A) 'कांग्रेस प्रणाली' या कांग्रेस का एक-दलीय प्रभुत्व
1989 के लोकसभा चुनाव परिणामों ने भारतीय राजनीति से 'कांग्रेस प्रणाली' या कांग्रेस के एक-दलीय प्रभुत्व के युग का आधिकारिक रूप से अंत कर दिया। अब भारतीय राजनीति एक ध्रुवीय से बहु-ध्रुवीय हो गई, जहाँ किसी एक दल की इच्छा सर्वोपरि नहीं रह गई थी। इस बदलाव ने केंद्र में गठबंधन की संस्कृति को जन्म दिया, जिससे क्षेत्रीय आकांक्षाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अधिक महत्व मिलना शुरु हुआ।

128. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
1984 में राजीव गाँधी के नेतृत्व में कांग्रेस को मिली 415 सीटें ऐतिहासिक थीं। 1989 के चुनाव ने गठबंधन युग का द्वार खोला। 1996 के चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी लेकिन तुरंत स्थाई सरकार नहीं बना सकी। अंततः, 2014 के चुनावों ने तीस साल के अंतराल को खत्म करते हुए भाजपा को अपने दम पर स्पष्ट और मजबूत बहुमत प्रदान किया, जिसने राजनीति का स्वरुप बदला।

129. (B) विविध सामाजिक समूहों के हितों को समन्वित करना दलों के लिए चुनौतीपूर्ण है
इस कथन का आशय यह है कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय समूहों के हितों को एक साथ लेकर चलना राजनीतिक दलों के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है। समाज की बदलती आकांक्षाओं और नए हितों के उभार ने पुरानी दलीय व्यवस्था पर दबाव डाला है, जिससे दलों के समक्ष अपनी विचारधारा और कार्यशैली को निरंतर अनुकूल बनाने की चुनौती बनी रहती है।

130. (A) स्पष्ट बहुमत का अभाव और गठबंधनों का बार-बार टूटना-बनना
1989 के बाद की राजनीतिक अस्थिरता का मुख्य कारण लोकसभा में किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलना था। इस स्थिति में, सरकारें कई छोटे दलों के समर्थन पर टिकी होती थीं। आपसी हितों के टकराव या राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण ये गठबंधन अक्सर बीच में ही टूट जाते थे, जिससे देश को बार-बार चुनावों और अल्पकालिक सरकारों का सामना करना पड़ता था।

131. (D) सभी 1, 2, 3, 4 और 5
1984 से 2019 तक की चुनावी यात्रा में भारत ने कई बड़े बदलाव देखे, जैसे कांग्रेस का भारी बहुमत से गिरकर गठबंधन के दौर में जाना और फिर भाजपा का पूर्ण बहुमत के साथ उभरना। 1989 से 2014 तक का लंबा समय 'त्रिशंकु संसद' का रहा जहाँ किसी भी दल को अकेले बहुमत नहीं मिला। ये सभी तथ्य भारतीय लोकतंत्र की बदलती गतिशीलता और परिपक्वता को स्पष्ट करते हैं।

132. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
गठबंधन की राजनीति के मौजूदा दौर में राजनीतिक दल अक्सर विचारधारा को किनारे रखकर चुनावी तालमेल करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि अब दल वैचारिक शुद्धता की तुलना में सत्ता में भागीदारी और व्यावहारिक लाभ को अधिक महत्व देने लगे हैं। इस प्रवृत्ति के कारण हमें ऐसे गठबंधन देखने को मिलते हैं जहाँ धुर विरोधी विचारधारा वाली पार्टियाँ भी साझा सरकार चलाने के लिए सहमत हो जाती हैं।

133. (C) मंडल आयोग और राम जन्मभूमि
1990 के दशक में मंडल आयोग और राम जन्मभूमि इन दो बड़े मुद्दों ने भारतीय समाज और राजनीति में गहरा ध्रुवीकरण पैदा किया। मंडल मुद्दे ने पिछड़ों और सवर्णों के बीच एक विभाजन रेखा खींची, जबकि राम जन्मभूमि विवाद ने धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक पहचान पर व्यापक बहस को जन्म दिया। इन दोनों आंदोलनों ने चुनावी लामबंदी के पुराने तरीकों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया।

134. (B) नीतिगत समानता के कारण दलों के मध्य अंतर करना कठिन होगा
यदि सभी सरकारें और राजनीतिक दल एक जैसी ही नीतियों, विशेषकर आर्थिक नीतियों पर अमल करें, तो मतदाताओं के लिए दलों के बीच स्पष्ट अंतर करना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में चुनावी प्रतिस्पर्धा केवल चेहरों या वादों तक सीमित रह जाती है, जिससे बुनियादी नीतिगत विकल्पों के चयन की गुंजाइश कम हो जाती है। यह लोकतंत्र में वैचारिक विविधता के संकुचित होने की ओर इशारा करता है।

135. (D) सभी 1, 2, 3 और 4
1989 के बाद का गठबंधन युग कांग्रेस के वर्चस्व के अंत, क्षेत्रीय दलों के बढ़ते प्रभाव, और मंडल व मंदिर जैसे भावनात्मक व सामाजिक मुद्दों द्वारा संचालित था। केंद्र में मिली-जुली

स्थिति सुधारने और उनके उत्थान के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया था। इसके माध्यम से भारतीय समाज में सामाजिक समानता और सरकारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का व्यापक प्रयास किया गया था।

157. (D) शहरी क्षेत्रों में उच्च जातियों द्वारा व्यापक विरोध प्रदर्शन
1990 में जब मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया, तो देश के सामाजिक माहौल में भारी उथल-पुथल मच गई। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उच्च जाति के युवाओं ने इसका कड़ा विरोध किया और इसे योग्यता के खिलाफ माना। इन व्यापक विरोध प्रदर्शनों और विवादों को 'मंडल मुद्दा' कहा गया, जिसने भारतीय समाज को वैचारिक और सामाजिक आधार पर दो प्रमुख गुटों में विभाजित किया।

158. (A) इसने भारतीय राजनीति में जाति-आधारित पहचान की राजनीति के उदय को प्रेरित किया।
मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने से भारतीय राजनीति में जाति-आधारित पहचान का महत्व काफी बढ़ गया। इसने अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदायों के बीच एक नई राजनीतिक चेतना और लामबंदी पैदा की। इसके परिणामस्वरूप कई ऐसे नए राजनीतिक दलों का उदय हुआ जिन्होंने पिछड़े वर्गों और दलितों के हितों का प्रतिनिधित्व करने को ही अपना मुख्य चुनावी आधार और वैचारिक आधार बनाया।

159. (C) सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण
मंडल आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में सबसे प्रभावशाली सुझाव अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण से संबंधित था। आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्र सरकार की नौकरियों और सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों में इन वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया जाए। इस कदम का उद्देश्य पिछड़े वर्गों को शासन और शिक्षा के क्षेत्र में अधिक भागीदारी और विकास के उचित अवसर प्रदान करना था।

160. (A) इसने पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले दलों के लिए एक चुनावी आधार बनाया।
मंडल आयोग के निर्णयों ने भारत की दलीय व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव किए। इसने अन्य पिछड़ा वर्ग और दलितों को संगठित करके एक मजबूत वोट बैंक तैयार किया। इससे जनता दल, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसे दलों को फलने-फूलने का मौका मिला। इन दलों ने खुद को हाशिए पर खड़े वर्गों के रक्षक के रूप में पेश किया और अपना चुनावी प्रभाव बढ़ाया।

161. (D) अयोध्या में बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का निर्माण करना
राम जन्मभूमि आंदोलन 1980 के दशक के उत्तरार्ध में भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु बना। इस आंदोलन का प्राथमिक लक्ष्य अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद के स्थान पर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण करना था। आंदोलनकारियों का मानना था कि वह स्थान भगवान राम का वास्तविक जन्मस्थान है, जिससे करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक भावनाएं ऐतिहासिक रूप से गहराई से जुड़ी हुई थीं।

162. (B) 'हिंदुत्व' या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद
राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े संगठनों ने 'हिंदुत्व' या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा को अपना मुख्य आधार बनाया। इस रणनीति के तहत धार्मिक प्रतीकों और भावनाओं का उपयोग करके देशव्यापी राजनीतिक लामबंदी की गई। इस विचारधारा ने भारतीय राष्ट्रवाद की एक ऐसी परिभाषा पेश की, जिसमें देश की प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों और हिंदू पहचान को केंद्र में रखा गया था।

163. (C) राम मंदिर आंदोलन के लिए जन समर्थन जुटाना
1990 में लालकृष्ण आडवाणी द्वारा आयोजित 'रथ यात्रा' भारतीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के समर्थन में पूरे देश में जनमत तैयार करना और लोगों को संगठित करना था। इस प्रभावशाली यात्रा ने हिंदुत्व के एजेंडे को जन-जन तक पहुँचाया और राम जन्मभूमि आंदोलन को एक बड़े और सक्रिय राष्ट्रीय आंदोलन में बदल दिया।

164. (D) इसने पार्टी को एक हाशिये की पार्टी से एक प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति में बदल दिया।
राम जन्मभूमि आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक स्थिति को पूरी तरह बदल दिया। 1984 के चुनावों में केवल दो सीटों के साथ हाशिये पर रहने वाली पार्टी इस आंदोलन के जरिए एक बड़ी राष्ट्रीय शक्ति बनकर उभरी। आंदोलन के दौरान हुई व्यापक लामबंदी और रथ यात्रा ने पार्टी के चुनावी आधार को अभूतपूर्व मजबूती दी, जिससे वह 1990 के दशक में सत्ता तक पहुँची।

165. (A) इसने धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद पर बहस को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला दिया।
राम जन्मभूमि आंदोलन की परिणति बाबरी मस्जिद के विध्वंस और सांप्रदायिक दंगों के रूप में हुई, जिसने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। इसने देश की धर्मनिरपेक्ष बुनियाद पर गंभीर सवाल खड़े किए और राष्ट्रवाद की परिभाषा पर नई बहस शुरू की। इसके प्रभाव से सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और सांस्कृतिक पहचान जैसे मुद्दे भारतीय राजनीति के विमर्श के केंद्र में स्थायी रूप से स्थापित हो गए।

166. (B) क्योंकि किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जिससे गठबंधन सरकारें बनीं।
1989 से 2014 के बीच का समय भारतीय राजनीति में गठबंधन के युग के रूप में चिह्नित है। इस लंबी अवधि के दौरान किसी भी एकल राजनीतिक दल को लोकसभा चुनावों में अपने दम पर स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। सत्ता के संचालन के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को अनिवार्य रूप से साथ आना पड़ा, जिसके कारण राष्ट्रीय मोर्चा, राजग और संप्रग जैसी सरकारें बनीं।

146. (A) नीतियों के विरोध के कारण अन्य दलों का समर्थन और बहुमत प्राप्त न होना
1996 में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार चलाने में इसलिए विफल रही क्योंकि उसकी नीतियों और 'हिन्दुत्व' की विचारधारा के कारण अधिकांश अन्य दल उसके साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं थे। उस समय धर्मनिरपेक्षता के नाम पर भाजपा के खिलाफ एक व्यापक मोर्चाबंदी थी। संसद में आवश्यक बहुमत साबित करने के लिए सहयोगियों के अभाव में वाजपेयी सरकार को मात्र तेरह दिनों के भीतर ही त्यागपत्र देना पड़ा था।

147. (C) बहु-दलीय प्रणाली जिसमें गठबंधन की प्रमुखता हो
1989 के बाद की भारतीय दलीय प्रणाली का सबसे सटीक वर्णन एक ऐसी 'बहु-दलीय प्रणाली' के रूप में किया जा सकता है जहाँ गठबंधन की राजनीति को प्रमुखता प्राप्त है। इसमें राष्ट्रीय दलों का प्रभाव तो बना रहा, लेकिन वे अब क्षेत्रीय दलों की सहायता के बिना शासन करने में असमर्थ थे। इस व्यवस्था ने विभिन्न क्षेत्रीय हितों और पहचानों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में जोड़ने और उन्हें शासन में हिस्सेदार बनाने का कार्य किया।

148. (A) 2, 3, 4, 1
इन घटनाओं का सही क्रम शाहबानो मामले (1985) से शुरु होता है, जिसके बाद 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा की गई। इसके उपरांत मई 1991 में राजीव गाँधी की हत्या हुई और अंततः दिसंबर 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे का विध्वंस हुआ। यह कालक्रम दिखाता है कि कैसे एक के बाद एक हुई इन घटनाओं ने देश में सांप्रदायिक और सामाजिक तनाव की स्थितियों को तीव्रता प्रदान की।

149. (C) केंद्र में बार-बार सरकारों का परिवर्तन और दीर्घकालिक स्थिरता का अभाव
1989 से 2014 के युग को अस्थिरता और अनिश्चितता का युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि केंद्र में बार-बार सरकारों का परिवर्तन हुआ और लंबे समय तक किसी एक दल की स्थिर सरकार का अभाव रहा। कई सरकारें तो अपना एक वर्ष भी पूरा नहीं कर पाईं। इस निरंतर राजनीतिक उथल-पुथल ने नीतिगत निरंतरता को प्रभावित किया और देश को कई बार समय से पहले आम चुनावों का भारी वित्तीय और प्रशासनिक बोझ झेलना पड़ा।

150. (B) अधिकांश दल शिक्षा और रोजगार में पिछड़ी जातियों हेतु आरक्षण के पक्षधर हैं
पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावों को स्वीकार किए जाने का मुख्य अर्थ यह है कि अब भारत के लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दल शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण के पक्षधर हैं। जो मुद्दा कभी अत्यंत विवादास्पद था, वह अब देश की राजनीतिक व्यवस्था का एक अभिन्न और स्वीकृत हिस्सा बन चुका है। अब कोई भी दल इस अधिकार को कम करने का साहस नहीं करता है।

151. (B) विभिन्न समूहों को समाहित करने की क्षमता का क्षरण और क्षेत्रीय दलों का उदय
1980 के दशक के अंत तक भारतीय राजनीति में कांग्रेस का एक-दलीय प्रभुत्व समाप्त होने लगा था। इसका मुख्य कारण पार्टी की वह क्षमता कम होना था जिसके माध्यम से वह विभिन्न सामाजिक और वैचारिक समूहों को साथ लेकर चलती थी। साथ ही, क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बढ़ने से शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, जिसने कांग्रेस के पारंपरिक जनाधार को काफी कमजोर कर दिया।

152. (A) क्योंकि इसने एक-दलीय बहुमत के युग का अंत और गठबंधन की राजनीति की शुरुआत की
1989 का आम चुनाव भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। इस चुनाव ने दशकों से चले आ रहे एक-दलीय बहुमत के शासन को समाप्त कर दिया और केंद्र में गठबंधन सरकारों के दौर की नींव रखी। इसके बाद लोकसभा में किसी एक दल को पूर्ण बहुमत मिलना कठिन हो गया, जिससे विभिन्न दलों के बीच आपसी सहयोग की आवश्यकता बढ़ गई।

153. (C) कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर रखना
1989 में जब राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का गठन हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी और वाम दलों जैसी वैचारिक रूप से भिन्न ताकतों ने इसे बाहर से समर्थन दिया। इस गठबंधन का एकमात्र मुख्य उद्देश्य कांग्रेस पार्टी को सत्ता से दूर रखना था। इन दलों ने आपसी मतभेदों को दरकिनार करते हुए केवल कांग्रेस विरोधी एक साझा मंच तैयार करने के लिए मिलकर काम किया।

154. (D) केंद्र और राज्यों में एक-दलीय प्रभुत्व और विभिन्न समूहों को समाहित करने की क्षमता
भारतीय राजनीति में 'कांग्रेस प्रणाली' का अर्थ उस दौर से है जब कांग्रेस पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में वर्चस्व था। इस प्रणाली की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि इसमें विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक वर्गों को एक साझा मंच पर जोड़ने की अद्भुत क्षमता थी। यह समावेशी ढांचा पार्टी को एक व्यापक गठबंधन के रूप में कार्य करने में मदद करता था।

155. (C) इसने राजनीतिक प्रक्रिया को अधिक खंडित और अप्रत्याशित बना दिया, जहाँ बातचीत महत्वपूर्ण हो गई।
गठबंधन की राजनीति की शुरुआत ने भारतीय राजनीतिक ढांचे को पूरी तरह बदल दिया। इसके परिणामस्वरूप सत्ता का स्वरूप अधिक खंडित हो गया और भविष्य की राजनीति काफी अप्रत्याशित हो गई। इस दौर में राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए विभिन्न दलों के बीच निरंतर बातचीत, समझौतों और सत्ता साझा करने की कला अनिवार्य हो गई, जिससे क्षेत्रीय शक्तियों का महत्व भी राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा।

156. (B) भारत में 'सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों' की पहचान करना
1978 में स्थापित मंडल आयोग का मुख्य लक्ष्य भारत के भीतर उन समुदायों की पहचान करना था जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए थे। आयोग को इन पिछड़े वर्गों की

Nodia Editions LLP

125, Sector 6, Vidhyadhar Nagar, Jaipur 302039

MRP. ₹ 560

167. (B) गठबंधन सहयोगियों के बीच नीतियों और नियुक्तियों पर बातचीत और समझौते की मजबूरी।
'गठबंधन धर्म' का आशय उन अनिवार्य समझौतों और आपसी सहयोग से है जो मिली-जुली सरकार चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें सरकार चलाने वाली मुख्य पार्टी को अपने सहयोगी दलों की मांगों को सुनना पड़ता है और प्रमुख नीतियों या नियुक्तियों पर उनकी सहमति लेनी पड़ती है। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह निरंतर बातचीत और सामंजस्य की एक अनिवार्य प्रक्रिया है।

168. (A) वे अक्सर 'किंगमेकर' की भूमिका निभाते हुए राष्ट्रीय राजनीति में अत्यधिक प्रभावशाली हो गए।
गठबंधन की राजनीति ने क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय स्तर पर अभूतपूर्व शक्ति प्रदान की। केंद्र में सरकार बनाने के लिए इन दलों का समर्थन अनिवार्य होने के कारण वे 'किंगमेकर' की भूमिका में आ गए। इसके माध्यम से वे अपनी क्षेत्रीय मांगों और विकास के एजेंडे को राष्ट्रीय नीति-निर्माण में शामिल कराने में सफल रहे, जिससे देश की मुख्यधारा की राजनीति में उनका कद काफी बढ़ गया।

169. (C) तीसरा मोर्चा
1989 से 2014 के मध्य भारतीय राजनीति में कई महत्वपूर्ण गठबंधनों ने शासन किया। इनमें राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन प्रमुख रूप से शामिल थे। दिए गए विकल्पों में से केवल 'तीसरा मोर्चा' ऐसा गठबंधन है जिसका उल्लेख इस विशिष्ट अनुच्छेद के ऐतिहासिक विवरण में कहीं भी नहीं किया गया है।

170. (D) इसने भारतीय संघवाद को अधिक सहयोगी और कम केंद्र-प्रमुख बना दिया।
गठबंधन सरकारों के उदय ने भारतीय संघीय व्यवस्था के ढांचे में मौलिक परिवर्तन किए। क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भागीदारी के कारण केंद्र सरकार अब पहले की तरह राज्यों पर अपना एकतरफा प्रभाव नहीं डाल सकती थी। इसके परिणामस्वरूप भारतीय संघवाद अधिक सहयोगी बन गया और सत्ता का केंद्र केवल दिल्ली तक सीमित न रहकर राज्यों और शक्तिशाली क्षेत्रीय शक्तियों के बीच अधिक संतुलित होने लगा।

171. (C) एक गंभीर भुगतान संतुलन संकट
1991 में भारत को एक अत्यंत गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जिसे 'भुगतान संतुलन संकट' के रूप में जाना जाता है। देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था कि अंतरराष्ट्रीय ऋण चुकाना भी मुश्किल हो गया था। इसी विकट स्थिति से निपटने और अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने नए और साहसिक आर्थिक सुधारों को लागू किया।

172. (B) उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG)
1991 में शुरु किए गए आर्थिक सुधारों को संक्षेप में एलपीजी नीतियों के रूप में जाना जाता है। इसमें 'उदारीकरण' का अर्थ सरकारी नियंत्रण कम करना, 'निजीकरण' का अर्थ सार्वजनिक क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाना और 'वैश्वीकरण' का अर्थ भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजारों से जोड़ना था। इन तीनों स्तंभों ने मिलकर भारतीय आर्थिक नीति के पुराने और बंद ढांचे को पूरी तरह से आधुनिक बना दिया।

173. (D) उद्योगों की स्थापना और संचालन पर व्यापक सरकारी नियंत्रणों को समाप्त करना।
'लाइसेंस राज' एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें किसी भी उद्योग को शुरू करने या विस्तारित करने के लिए सरकार से कई तरह की अनुमतियाँ लेना अनिवार्य था। इसकी समाप्ति का अर्थ था इन जटिल और बाधा उत्पन्न करने वाले नियमों को खत्म करना। इससे उद्यमियों को अधिक स्वतंत्रता मिली, व्यापार की बाधाएं कम हुईं और देश में एक बाजार-उन्मुख प्रतिस्पर्धी वातावरण तैयार करने में बड़ी मदद मिली।

174. (A) समय के साथ, बाद की विभिन्न विचारधाराओं वाली सरकारों ने भी सुधार प्रक्रिया को जारी रखा।
1991 के सुधारों को शुरु में कुछ राजनीतिक ताकतों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि, जैसे-जैसे समय बीता, देश के लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इन नीतियों की उपयोगिता को समझा। इसके बाद आने वाली अलग-अलग विचारधाराओं वाली सरकारों ने भी इन नीतियों को निरंतर आगे बढ़ाया, जिससे अंततः आर्थिक विकास के इन सुधारों पर एक व्यापक राष्ट्रीय और राजनीतिक सहमति बन सकी।

175. (C) पी.वी. नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह
भारत में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया की नींव प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान रखी गई थी। उनके नेतृत्व में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने इन ऐतिहासिक सुधारों की रूपरेखा तैयार की और उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। इन दोनों नेताओं के दूरदर्शी प्रयासों के कारण ही भारत अपनी जर्जर आर्थिक स्थिति से बाहर निकल सका और तीव्र प्रगति की राह पर चला।

सरकारों का दौर इस युग की सबसे स्पष्ट पहचान रहा है। इन सभी कारकों ने मिलकर एक ऐसी जटिल राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण किया जहाँ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय शक्तियाँ एक-दूसरे पर निर्भर हो गईं।

136. (A) दोनों में जनता दल और कई क्षेत्रीय पार्टियाँ शामिल थीं
1989 के राष्ट्रीय मोर्चे और 1996 के संयुक्त मोर्चे की सरकारों में सबसे बड़ी समानता यह थी कि दोनों का मुख्य आधार जनता दल और विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियाँ थीं। दोनों ही बार इन गठबंधनों ने एक 'तीसरे विकल्प' के रूप में खुद को पेश किया, जो कांग्रेस और भाजपा दोनों से समान दूरी बनाए रखना चाहता था। ये सरकारें भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय आकांक्षाओं के संगठित स्वरूप का प्रमाण थीं।

137. (C) सीटों की संख्या में वृद्धि हुई (145 से 206)।
2009 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने अपने पिछले प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार किया। 2004 में जहाँ पार्टी को 145 सीटें मिली थीं, वहीं 2009 में यह संख्या बढ़कर 206 हो गई। इस बढ़त के कारण संप्रग-2 सरकार पहले की तुलना में अधिक मजबूत स्थिति में आई और उसे बाहरी सहयोगियों पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद मिली। यह पार्टी की नीतियों और नेतृत्व के प्रति जनता के विश्वास का संकेत था।

138. (B) P-4, Q-1, R-2, S-3
1989-90 की छोटी अवधि में वी.पी. सिंह प्रधानमंत्री रहे। 1991-96 के दौरान पी. वी. नरसिम्हा राव ने पांच साल का कार्यकाल पूरा किया। 1998-99 में अटल बिहारी वाजपेयी ने राजग सरकार का नेतृत्व किया, और 2004-09 के दौरान डॉ. मनमोहन सिंह संप्रग-1 के प्रधानमंत्री रहे। ये कालखंड भारतीय राजनीति के विभिन्न मोड़ों और बदलती गठबंधन संस्कृतियों को भली-भांति चित्रित करते हैं।

139. (D) सामूहिक पहचान जैसे जाति, धर्म और क्षेत्र आधारित लामबंदी
1990 के दशक के संदर्भ में 'पहचान की राजनीति' का अर्थ उस राजनीतिक प्रवृत्ति से है जहाँ जनता को जाति, धर्म और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर संगठित किया जाता है। विकास के सार्वभौमिक दावों की जगह विशिष्ट समूहों के हितों और उनकी सांस्कृतिक पहचान को चुनावी मुद्दा बनाया गया। इस राजनीति ने दलितों, पिछड़ों और धार्मिक समूहों को अपनी सामूहिक शक्ति का एहसास कराया और चुनावी परिणामों को प्रभावित किया।

140. (B) एक ट्रस्ट को, राम मंदिर निर्माण के लिए
2019 के अपने ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या की विवादित भूमि एक विशेष ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया, ताकि वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा सके। न्यायालय ने केंद्र सरकार को तीन महीने के भीतर इस ट्रस्ट का गठन करने का निर्देश दिया था। साथ ही, मुस्लिम पक्ष को संतोषजनक मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही पांच एकड़ की वैकल्पिक भूमि आवंटित करने का निर्णय दिया गया।

141. (C) लालकृष्ण आडवाणी
पी. वी. नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा और इंद्रकुमार गुजराल ने 1990 के दशक के विभिन्न कालखंडों में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया। लालकृष्ण आडवाणी इस दौरान भाजपा के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक थे और राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रणेता रहे, लेकिन वे कभी भी प्रधानमंत्री के पद तक नहीं पहुँचे। उन्होंने बाद में वाजपेयी सरकार में उप-प्रधानमंत्री की भूमिका अवश्य निभाई थी।

142. (D) लोकसभा चुनाव में किसी भी दल को सरकार हेतु स्पष्ट बहुमत न मिलना
1989 से 2014 के बीच की अवधि को 'त्रिशंकु संसद' का दौर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौरान हुए किसी भी आम चुनाव में किसी एक राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का जादुई आंकड़ा प्राप्त नहीं हुआ। संसद की संरचना ऐसी थी जहाँ कोई भी पक्ष अकेले शासन करने की स्थिति में नहीं था, जिससे गठबंधन सरकारों का बनना एक राजनीतिक विवशता और आवश्यकता बन गया था।

143. (D) सभी 1, 2, 3, 4 और 5
1990 का दशक ऐतिहासिक घटनाओं से भरा रहा; 1990 में मंडल लागू हुआ, 1991 में आर्थिक सुधार शुरु हुए, 1992 में विवादित ढांचा गिरा, 1996 में संयुक्त मोर्चा बना और 1998 में पहली बार वाजपेयी के नेतृत्व में राजग सरकार का गठन हुआ। ये सभी घटनाएँ स्वतंत्र भारत के इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं जिन्होंने देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना को मौलिक रूप से बदला।

144. (B) पिछड़ी जातियों में राजनीतिक जागरुकता और लामबंदी की वृद्धि हुई
'मंडलीकरण' के प्रभावस्वरुप भारतीय समाज और राजनीति में पिछड़ी जातियों के भीतर जबरदस्त राजनीतिक जागरुकता और लामबंदी देखी गई। इसने पारंपरिक ऊंच-नीच के राजनीतिक समीकरणों को ध्वस्त कर दिया और सत्ता के गलियारों में पिछड़ों की आवाज को बुलंद किया। अब चुनाव केवल नीतियों पर नहीं, बल्कि जातियों के सामाजिक प्रतिनिधित्व और उनके अधिकारों की मांग पर अधिक केंद्रित होने लगे, जिससे लोकतंत्र अधिक समावेशी बना।

145. (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
1990 के दशक के बाद की भारतीय राजनीति को समझना वाकई जटिल है क्योंकि इस दौरान मंडल आयोग का आरक्षण, राम मंदिर आंदोलन और गठबंधन की अस्थिरता जैसे कई बड़े कारक एक साथ सक्रिय थे। इन परस्पर विरोधी और प्रभावकारी मुद्दों ने राजनीति को एक ऐसा नया स्वरुप दिया जहाँ सामाजिक न्याय और धार्मिक पहचान के सवाल विकास के विमर्श के साथ उलझ गए, जिससे चुनावी परिणाम अक्सर अप्रत्याशित होने लगे।